

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

अन्तराष्ट्रीय राजनीति को विचारभूमि

THEORY OF INTERNATIONAL POLITICS

★
U. G. C. TEXT BOOKS

Dr. Prabhu Dutt Sharma

M.A. (Pol. Sc. & History),

M.P.A. (Pub. Adm.) (U.S.A.) Ph.D. (U.S.A.),

Gold Medalist

Reader, Department of Political Science,

University of Rajasthan, JAIPUR

&

Harish Chandra Sharma M.A.

Department of Political Science,

Lal Bahadur Shastri College, JAIPUR

★

COLLEGE BOOK DEPOT
JAIPUR-2

Published by :
College Book Depot
JAIPUR-2

Revised Edition 1970-71
All Rights Reserved with the Publishers
Price Rs. 21/-

Printed at :
College Press
&
Chandrodaya Printers
JAIPUR

राष्ट्रनाया हिन्दी के अनन्य उपासक
एवं भारतीय संस्कृति और चिन्तन
के सजीव प्रतीक



डॉ० रामानन्द तिवारी

'भारतीनन्दन'

को

सादर

समर्पित

★

जिनके समात्मभाव से यह
रचना अनुप्राणित है

तीसरे संस्करण के तीन शब्द

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, संस्थाओं एवं विदेशी नीतियों की दुनिया में जो व्यापकता है, उसे देखते हुए किसी भी लेखक और प्रकाशक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने प्रकाशन को समीचीन एवं नवीन बनाए रखे । गत दो वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच एवं उसके नेपथ्य में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन एवं परिवर्तन प्रभुत्व हुई हैं उनके सदर्थ में यह अनिवार्य हो गया कि हम अपने इस प्रकाशन को नवीनतम सामग्री एवं विचार विस्तार से अलङ्कृत कर अपने हिन्दी माध्यम के पाठक के ज्ञान को इस क्षेत्र में पुराना न पड़ने दें । फलतः प्रभुत्व है हमारा यह तीसरा संस्करण, दूसरे से अधिक समृद्ध एवं अपने विविध स्वरूप में ।

अपने पाठकों के हम आभारी हैं जो इस पाठ्य पुस्तक के स्वागत द्वारा हमें प्रोत्साहित करते रहे हैं । हमें विश्वास है कि इस पाठ्य-पुस्तक के अनुशीलन से आज के विश्वविद्यालयों के हिन्दी माध्यम का विद्यार्थी जगत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अपने ज्ञान को उस स्तर तक बढ़ा सकेगा जहाँ से उसे आगे की ओर वैश्व स्तरीय प्रगति एवं सदर्थ पुस्तक सरलता से समझ में आने लगेगी ।

—लेखकगण

प्राक्कथन

प्रस्तुत पुस्तक 'अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारभूमि' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को शासित करने वाले कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्तों को बौद्धिक ढंग से विश्लेषित करने का एक नया प्रयास है। एक जमाना था जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का ज्ञान केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों और उनसे निर्देशित होने वाले युद्ध और शान्ति के प्रयासों तक ही सीमित था। आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम शोध ने यह सिद्ध कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति केवल घटनाओं का घटाटोप न होकर कुछ नियम विरोधों के अनुसार घेला जाने वाला एक खेल है, जिसके तिराडों-राष्ट्र व्यक्तियों की तरह निश्चित राष्ट्रीय हित रखते हैं। विश्व शान्ति जैसे गम्भीर और मर्यादक निष्कर्ष आज हमारी राष्ट्रीय हित की सम्पूर्ति एवं भ्रम्बद्धन में जन्म लेकर शक्ति-संतुलन, सामूहिक सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की समस्याओं को जटिल बनाते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के गम्भीर और बरिष्ट विचारविम्व में हिन्दी माध्यम द्वारा वह सब कुछ सरल और बोधगम्य ढंग से कहने का प्रयास किया गया है जिसके लिए अभी भी अग्रजों भाषा का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। पुस्तक की रचना में यथासम्भव प्राप्य सामग्री को मूल स्रोतों, पत्र-पत्रिकाओं और भाषिक ग्रन्थों से सजोकर सरलतम ढंग से विवेचित, विश्लेषित एवं प्रतिपादित किया गया है। आशा है, विद्यार्थीजगत हमारे इस प्रयास को उपयोगी एवं स्वागतव्य पायेगा।

अन्त में, धन्यवाद देना एक औपचारिकता हो गई है किन्तु अपने इस परिश्रम में यदि हम किसी का आभार मान सकते हैं तो केवल स्वयं का अपना तथा अपने उन प्रशानक बन्धुभा का, जिनके आपसी सहयोग एवं प्रेरणापूर्ण परेशानियों से यह रचना सम्भव हो सकी है।

अनुक्रम

①

PART I

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ	1
The Theories of International Politics)	

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति	1
✓ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का विकास	४
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र	5
वर्तमान विश्व राजनीति के परिवर्तनशील	
तत्व एवं नई दिशाएँ	14
अन्तर्राष्ट्रीय जगत की उनका	14
✓ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान के रूप में	24
विचारधारा का महत्त्व एवं योगदान	25
अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के प्रभाव के कारण	33
अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के निर्माण एवं	
स्वीकृति के मार्ग की बाधाएँ	34
✓ सिद्धान्तों के विकास की चार सीढ़ियाँ	42
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य विचारधारा	44
अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के प्रकार	45
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र सिद्धांत	48
पेल तथा सीदेनाजी का सिद्धांत	51
✓ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यापकवादी सिद्धान्त	54
2 राज्य व्यवस्था	63
(The State System)	
राज्य व्यवस्था का अर्थ	64
राज्यों का शक्ति-स्तर	66
राज्य व्यवस्था का विकास	68
प्रादेशिक राज्य का जन्म और अन्त	69

राष्ट्र राज्यो की स्थापना	८६
राज्य व्यवस्था की विशेषताएँ	९२
राष्ट्रवाद का सिद्धान्त	९३
'राष्ट्र' और राष्ट्रवाद	९५
राष्ट्रवाद का अर्थ एवं प्रवृत्ति	९६
राष्ट्रवाद की जड़	९६
राष्ट्रवाद के प्रकार	१०७
साम्यवाद और राष्ट्रवाद	११२
राष्ट्रवाद का नया रूप	११५
राष्ट्रवाद का मूलशक्ति	११८
राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त	१२१
सम्प्रभुता की मान्यता	१२४
सम्प्रभुता के कुछ रूप	१२८



PART II

राष्ट्रीय शक्ति का सामान्य विचार	१३७
----------------------------------	-----

(The Concept of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप	१४१
शक्ति के लिए सधन के आधार	१४४
शक्ति की राजनीति पर यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण	१४७
शक्ति मन्थन के रूप	१५२

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व भूगोल और प्राकृतिक स्रोत	१५४
--	-----

(The Elements of National Power Geography & Natural Resources)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल का योगदान	१५६
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भौगोलिक दृष्टिकोण	१६१
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव	१६७
भौगोलिक तत्व एवं विश्व राजनीति	१७०
प्राकृतिक स्रोत	१७६

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व जनसंख्या और तकनीकी (Elements of National Power - Population and Technology)	१८२
जनसंख्या	१८२
जनसंख्या का सख्यात्मक पहलू	१८५
जनसंख्या का गुणात्मक पहलू	१८६
जनसंख्या का वितरण	१८७
जनसंख्या का प्रसार एवं विनाम	१८८
जनसंख्या सम्बन्धी समस्याएँ	१८९
जन्मदर के विकास की वर्तमान प्रवृत्तियाँ (१)	१९५
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जनसंख्या का स्थान	१९७
बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करने के माग	१९८
राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तकनीकी	२०४
तकनीकी और राष्ट्रीय शक्ति	२०५
तकनीकी का प्रवृत्ति और प्रभाव	२१०
विश्व राजनीति और तकनीकी प्रगति	२१३
तकनीकी के मुख्य प्रकार व उनका महत्व	२२०
विज्ञान, तकनीकी एवं विदेश नीति	२२७
शक्ति और राष्ट्रीय शक्ति	२२८
तकनीकी विकास का माध्यम	२३०
राष्ट्रीय शक्ति के तत्व विचारधारा मोरल और नेतृत्व (Elements of National Power Ideology, Morale & Leadership)	२३४
विश्व राजनीति में विचारधारा	२३६
विचारधारा के प्रकार	२४१
साम्यवाद की विचारधाराएँ	२४५
साम्यवाद की विचारधाराएँ	२४७
अनारक्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएँ	२५०
प्रजातन्त्रवाद एवं साम्यवाद की विचारधाराएँ	२५२
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और दक्षिणोन्मुख ...	२६३
नेतृत्व और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ...	२६६
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के कार्य ...	२७१
मोरल ...	२७२

मनोवश के निर्माण के साधन	२७१
नेतृत्व	२७८
राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन	२८

③ PART III

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन	२८६
कूटनीति प्रचार और राजनीतिक युद्ध	
(Instruments for the promotion of National Interest Diplomacy Propaganda & Political Warfare)	
अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का बदलता रूप	२९१
राष्ट्रीय हित का अर्थ	२९५
राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित	२९८
कूटनीति	३००
कूटनीति का अर्थ और परिभाषाएँ	३०१
कूटनीति के विकास का इतिहास	३०३
कूटनीति का उद्देश्य	३०६
प्रासंगिक कूटनीति के अभिनता	३०७
कूटनीतिक विभागाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ	३१०
कूटनीतिक कार्यों का स्वरूप	३१२
कूटनीति के विभिन्न प्रकार	३२०
प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति	३२१
सर्वाधिकारवादी कूटनीति	३२३
सम्मेलनों द्वारा कूटनीति	३२४
व्यक्तिगत कूटनीति	३२७
युद्धप्रिय कूटनीति	३२८
गुप्त कूटनीति	३३१
प्रचार द्वारा कूटनीति	३३३
पुरानी और नई कूटनीति	३३४
कूटनीति पर प्रभाव डालने वाले कुछ नये विचार	३३६
संसदीय कूटनीति	३३८
सोवियत कूटनीति के कुछ रूप	३४०
मध्य कूटनीति के अर्थ	३४३

प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध ✓ ---	---	३४२
प्रचार का धर्म एवं परिभाषा	---	३४६
प्रचार के उद्देश्य	---	३४७
प्रचार के तरीके	---	३४८
प्रभावशाली प्रचार का आवश्यकताएँ		३४९
सूचना और प्रचार के रूप	---	३५०
मासिक समाचार का प्रचार-धर्म	---	३५३
मानविक सम्बन्ध और विदेश नीति		३५७
राजनीतिक युद्ध ✓		३७०
राजनीतिक युद्ध के साधन		३७२
राष्ट्रीय नीति की अभिवृद्धि के साधन		
धार्मिक साधन, साम्राज्यवाद-उत्पत्तिवाद एवं युद्ध		३७३
(Instruments for the Promotion of National Power : Economic Instruments, Imperialism Colonialism and War)		
धार्मिक साधन	---	३७६
धार्मिक साधनों का महत्व	---	३७७
धार्मिक साधनों का धर्म	---	३७८
अन्तराष्ट्रीय धार्मिक जीवन का प्रकृति		३८०
धार्मिक साधना के प्रकार	---	३८२
वैदेशिक धार्मिक साधना	---	३८३
साम्राज्यवाद		४००
साम्राज्यवाद-उत्पत्तिवाद ✓	---	४०१
साम्राज्यवाद, उत्पत्तिवाद और राष्ट्रवाद	---	४०६
साम्राज्यवाद की नींव के पथ		४०८
साम्राज्यवाद के रूप		४१४
साम्राज्यवाद का मूल्य	---	४१६
वैदेशिक उत्पत्तिवाद और साम्राज्यवाद	---	४२१
वैदेशिक साम्राज्यवाद	---	४२३
अन्तर्गत साम्राज्यवाद		४२६
युद्ध का धर्म	---	४३१
युद्ध के कारण	---	४३३
युद्ध के फल	---	४३७

युद्ध का विगत एवं वर्तमान स्वरूप	४४१
सम्पूर्ण युद्ध	४४१
सैनिक शक्ति की सम्भावनाएँ	४४२
युद्ध को रोकने का प्रयास	४४४

PART IV

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ - I	४६१
(Limitations of National Power)	
<u>शक्ति मनुष्य</u>	४६३
शक्ति संतुलन के अनेक अर्थ	४७०
शक्ति मनुष्य की स्थापना के तरीके	४७६
शक्ति संतुलन तथा राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले अनेक तत्व	४८१
शक्ति मनुष्य पर मार्गस्थानों के विचार	४८२
शक्ति संतुलन के सिद्धांतों का मूल्यांकन	४८४
<u>सामूहिक सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय भगडा का शांतिपूर्ण निपटारा</u>	४८३
सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रमंडल	४८६
नामू हक मुरा और संयुक्त राष्ट्रमंडल	५००
सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय मंडल	५०२
शांतिपूर्ण समझौते	५०७
शांतिपूर्ण समझौते के मान्य	५०६
क्षेत्रीय व्यवस्था और शांतिपूर्ण निपटारे	५११
राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ - II	५१३
(Limitations of National Power)	
अन्तर्राष्ट्रीय कानून	५१४
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कानून का स्थान	५१७
क्या अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक सत्य है ?	५२१
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोधित स्वरूप	५२३
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विमान	५२५
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास	५२५
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण	५२६
अन्तर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून	५३०
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रकार	५३१

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की नियमबद्ध करना	५३७
अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे दराव	५३८
अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन	५३९
विश्व सरकार की मान्यता का विक्षेपण	५४३
विश्व सरकार की उपयोगिता	५४८
विश्व सरकार के समतल और माघन	५५६
विश्व सरकार का मान्यता की धारणा	५६८
नि सम्प्रसारण	५७२
नि सम्प्रसारण का आवश्यकता एवं महत्व	५८२
नि सम्प्रसारण के प्रयत्न का इतिहास	५८६
मुक्त राष्ट्र मंच के बाद नि सम्प्रसारण के प्रयास	५९५
नि सम्प्रसारण के माग की बढताइया	६०६
राष्ट्रीय सक्ति का अन्य मोमाये	६११
अन्तर्राष्ट्रीय सक्ति	६१२
/ विश्व जनमत	६१६

PART V

[

हमारे समय की उभरती हुई प्रगतिशील एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका का जागरण	६२५
--	-----

(Contemporary Emerging Trends Resurgence
of Asia Africa and Latin America)

विश्व परिवर्तन के आधार	६२६
पश्चिमि विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाले तत्व	६२८
एशिया की जागृति	६३२
एशिया में स्वतन्त्र आन्दोलनों का सूत्रपात और अनिवेशवाद का दृष्टा	६३४
एशिया के प्रमुख राष्ट्रों में जागरण और उनके द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति	६४७
अफ्रीका की जागृति	६६६
मुख्य प्रमुख अफ्रीकन देश	६७४
स्वतन्त्र अफ्रीका महाद्वीप की समस्याएं	६७७
अफ्रीका में साम्यवाद	६८१

अमरीका के उन्नयन	---	---	७१४
अमरीकी नीति का विचार	---	--	७१६
अमरीकी निर्माण	---	---	७१७
अमरीकी पर्यटन	--	---	७१७
अमरीकी धर्म	---	---	७१८
द्वितीय विश्वयुद्ध और अमरीका	---	---	७२०
भारत और अमरीका	---	.	७२३
द्वितीय महायुद्ध और अमरीकी विदेश नीति	---	---	७२४
सुशासन का काल	---	---	७२६
महान दिगन्तरेण का काल	---	---	७२८
दूसरे सिद्धान्त	---	---	७२९
संसार की योजना	---	---	७३२
नारो : अमरीका की रण-नीति	---	---	७३७
सुने सपर का काल	---	---	७३८
बोत दृष्टि का काल	---	---	७४१
अधुनिक भारत-देश की सिद्धान्त	---	---	७४३
हृषिकेश का काल	---	--	७४८
विदेशी युग	---	---	७४८
भारत का युग	---	---	८०३
विदेशी निम्न की विदेश नीति	---	.	८१२
अमरीका की विदेश नीति का मूल्यांकन	---	---	८१४
गोत युद्ध	---	---	८१७
(Cold War)			
गोतयुद्ध का प्रारम्भ, भारत और सिद्धान्त	---	---	८१८
विश्व की पूर्ण के विरुद्ध सिद्धान्त	---	---	८१९
पूर्ण की विरुद्ध के विरुद्ध सिद्धान्त	---	---	८२७
१९४७ से वर्तमान समय तक के गोत-युद्ध पर एक दृष्टि	---	---	८३२
संयोजक सपर बनाम शक्ति राखनीति	---	--	८४३
१. यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन	---	---	८४८
(Rebuilding and Reorganization of Europe)			
शान्ति स्थापना के प्रयास	---	--	८५०
शान्ति की मुख्य-मुख्य कारण	---	---	८५३

प्रन्तराष्ट्रीय कानूनों का आधार एवं प्रवर्धन	१७१
संघ द्वारा मान्य अधिकारों की रक्षा	१७२
संयुक्त राष्ट्रमण की देख	१७४
वियतनाम और पश्चिम एशिया की समस्याएँ —	१८०
(Problems of Vietnam and West Asia)	
वियतनाम की समस्या	१८०
जेनेवा में युद्ध-विराम संधि और वियतनाम का विभाजन	१८१
युद्ध विराम की प्रसक्तता और वियतनाम का वर्तमान स्वरूप	१८४
मध्य-पूर्व की समस्या	१८४
इजरायल-पर्व युद्ध	१८४
Exercise	१००८
Suggested Readings	१०३३

PART I

Theories of International Politics , Realistic Theory,
scope of International Politics, a survey of new develop-
ments

अध्याय-१—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ
(The Theories of International Politics)

अध्याय-२—राज्य-प्रणाली
(State System)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ [THE THEORIES OF INTERNATIONAL POLITICS]

एक विचारणीय प्राणी होने के नाते व्यक्ति के प्रदेष्टे कार्य व पीछे विचारों की प्रेरणा एवं आधार रहता है। उसका कार्य चाहे व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, किसी भी क्षेत्र में किया जाये, उसे हम मानवीय कार्य तभी कहेंगे जबकि वह विचार एवं बुद्धि पर प्रभावित है। यही स्थिति आगे चल कर व्यक्तिगत क्षेत्र में नैतिक नियमों, सामाजिक क्षेत्र में रीति रिवाजों एवं परम्पराओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न परम्पराओं के विकास का कारण बनती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराएँ विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहार को इस प्रकार तय करती हैं कि वे अपने हितों का साधन बुद्धिपूर्ण तरीके से कर सकें।

— अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराओं के विश्लेषण से पूर्व यह उपयोगी होगा कि हम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच स्थित अन्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के विकास की जानकारी प्राप्त कर लें।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (National and International Politics)

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच सदैव ही एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना कठिन है, फिर भी दोनों के मध्य स्थित अन्तर के प्रति सजग रहना आवश्यक है। कई एक समस्याएँ ऊपर से देखने पर पूर्णतः

राष्ट्रीय व्यवस्था संघर्षाधीन प्रकृति की दिशाई देती है किन्तु समय में वे पूर्णतया ऐसी नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर लगे विदे जाते जाते धन की मात्रा कम करके समझ में देना होता है कि संघर्षाधीन व्यवस्था की स्थिति और उम्र कम उमर पर धन की मात्रा कम है। एक दूसरे उदाहरण में जब एक देश धन संकलन क्रम केवल नीति को धारण करता है उसका उम्र कम के निशानिधियों की प्राविष्ट स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इन धर्म में वह एक राष्ट्रीय समस्या की विधा हुई किन्तु उम्र केवल नीति का निर्माण के मुद्दों पर धर्मात् दन के संघर्षाधीन आधार पर जो प्रभाव पड़ता है वह इनका संघर्षाधीन प्रकृति है। इन प्रकार राष्ट्रीय एवं संघर्षाधीन प्रकृति का प्रसरण प्रतिरक्ष होता है। नतीजतन इनमें वह समझ विधा जाता है कि जो निष्ठाएँ तब विचारधारामें राष्ट्रीय जीवन पर लागू होती हैं उनका संघर्षाधीन जीवन पर भी लागू किया जा सकता है। इनका प्रभाव यह हुआ कि जिस लोगों की संघर्षाधीन राजनीति का प्रसरण अनुभव नहीं है वे लोग भी राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर अपनी तात्त्विक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं पर राष्ट्रीय एवं संघर्षाधीन राजनीति के बीच अनिष्ट सम्बन्ध एवं अनिराव की स्थिति होने के बाद भी यह एक तथ्य है कि राष्ट्रीय विशेषज्ञता का संघर्षाधीन पटनाओं में बहुत कम उपयोग रहता है, यही तब कि नतीजतन राष्ट्रीय राजनीति के निष्ठाओं की संघर्षाधीन राजनीति में लागू करने से सम्बन्धित गतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं।

जब हम दूसरे देश की राजनीति का अध्ययन करते हैं तब कुछ समस्याएँ हमारे सामने आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी सशक्ति का गहरा प्रभाव रहता है और ऐसी स्थिति में जो लोग अपने देश की राजनीति में साहिर होते हैं वे आवश्यक नहीं कि अन्य देशों की राजनीति को भी अपनी ही गहराई से समझ सकें, क्योंकि दूसरे देश के लोग भी उनकी सशक्ति एवं परम्पराओं में रगे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब एक व्यक्ति यह देखा है कि दूसरे देश के लोग उस सशक्ति एवं परम्परा में विश्वास नहीं करते जिसमें वह स्वयं करता है तो वे इसे एक अस्वाभाविक स्थिति कहते हैं। अपनी पृष्ठभूमि के भिन्न होने के कारण एक देश में रहने वाले विदेशी लोग उस देश के व्यवहार के सम्बन्ध में अनेक बार गलत निर्णय ले लेते हैं। व्यवहार में ऐसे भी उदाहरण देखने की मिलते हैं कि एक ही समस्या के बारे में देश के अन्दर रहने वाले और देश से बाहर रहने वाले लोगों के विचारों में विभिन्नता रहती है। एक ही स्थान पर रहने वाले देशी और विदेशी व्यक्तियों के दृष्टिकोणों के बीच अन्तर हो जाता है। यह अन्तर यह है कि

एक देश के नागरिक अपने देश के अपने मामलों में अधिक रुचि लेते हैं जबकि विदेशियों को उन देश की विदेश नीति के सम्बन्ध में अधिक रुचि रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या शीत-युद्ध (Cold-war) प्रारम्भ हुआ उसके पीछे मुख्य रूप से मीडलान्ड एव परम्परागत भेद कार्य कर रहे थे। मुख्यतः राज्य समूहों का यह मोहकन मध्य क्षेत्रों ही देशों के लोग अपनी नीति का प्रतिनिधि कहना थे या उनका नागरिकों की सम्मानित एव अधिक प्राप्ति की ओर सन्तानित थी किन्तु इनमें से प्रत्येक दूसरे का धृष्टता की दृष्टि में समता या ओर उनकी नीतियों को अन्तर्राष्ट्रीय नीति के लिए मानकर सम्मान था।

इस प्रकार यह बहुत सुविधा है कि दूसरे देश की स्थिति एवं नीति का मही रूप में सम्मान दिया जाए, मनुष्यों अन्तर्राष्ट्रीय समाज की सम्मानता की ओर नो कठिन है क्योंकि इस समाज का एक व्यक्ति नहीं होते बल्कि राज्य होते हैं। जब हम राज्य के बारे में विचार करते समते हैं तो उनका एक मानसिक संरचना न मान कर उन्हें बाह्यविक्रम स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार दो देशों के मध्य स्थित सम्बन्धों का ऐसे अध्ययन करते हैं मानो दो व्यक्तियों के मध्य स्थित सम्बन्धों का अध्ययन कर रहे हों। इस अध्ययन में हम उन सब बातों को ध्यान में रखते हैं जो स्थितितन सम्बन्धों की विशेषता मानती आती है। यही कारण है कि कभी-कभी दो देशों का उनके प्रतिनिधियों में वैयक्तिकरण कर दिया जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री या विदेशी मामलों के राज्य मन्त्रियों को उक्त देश का प्रतीक सम्मान दिया जाता है। राज्य की प्रकृति कृत्रिम एवं परम्परागत होती है तथा एक व्यक्ति जब पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है और उसमें जब वह अपने व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य करता है, उसमें पर्याप्त भेद रहता है। यदि हम इन बातों का ध्यान में न रखें तो भ्रम की गुंजाइश रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की प्रकृति के सम्बन्ध में उल्लेख होने वाले भ्रमों के प्रतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन में भी अनेक व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस मापा का प्रयोग किया जाता है उसकी उत्पत्ति राष्ट्रीय स्तर पर ही हुई है इसलिए यह स्वभाविक है कि प्रयुक्त किए गए शब्द अपने अर्थ के सम्बन्ध में भ्रम उत्पन्न कर दें। हम अन्तर्राष्ट्रीय समाज और अन्तर्राष्ट्रीय माण्डनों का अध्ययन ठीक इस प्रकार करना चाहते हैं मानो यह व्यक्तियों के समूह हों। हम अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी आतून और नैतिकता का अध्ययन करते हैं, राज्यों के अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विचार करते हैं। इसी प्रकार जब हम अन्तर्राष्ट्रीय

बेन्थम (Jeremy Bentham) ने घनराष्ट्रीय सम्बन्धों का नाम दिया है। ज्ञान की इस शाखा में न केवल विभिन्न देशों के विदेशी मामलों का नया घनराष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन किया जाता है बल्कि इसमें घनराष्ट्रीय समाज तथा उसकी समस्याओं का भी अध्ययन सम्मिलित है। शून्यतावाद, घनराष्ट्रीय बाह्य वेत्ताओं, आदि ने इन क्षेत्र में एक सामान्य माना स्थिति की है एवं कुछ मानान्यों परम्पराओं नाश की हैं जो घनराष्ट्रीय शक्ति में भी प्रयुक्त होती हैं। शक्ति समुत्पन्न आदि समस्याओं की उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है।

आहार, शक्ति, राष्ट्रीय परम्पराओं आदि ने विभिन्नान पूर्ण राष्ट्रों के घनराष्ट्रीय सम्बन्धों का बाह्य ऐसी विचारधारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती जा सामान्य रूप में स्वीकृत हो। यदि हम विश्व-समाज के १९४ वा अपने नौ आर्थिक राष्ट्रों के पारम्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ मानान्यों पर उल्टा चाहते हैं तो कान बनाने के लिए कोई परिचयना करना आवश्यक है।

एक परिचयना यह है कि मानव-जाति इन सम्बन्ध राष्ट्रों के घनराष्ट्रीय समाज में होने-बढ़ाने रूप में समर्थ है। इन सम्बन्ध राष्ट्रों के पारम्परिक सम्बन्ध मुक्त रूप से शक्ति (Power) पर निर्भर करते हैं। इन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कुछ पञ्चायिकाओं द्वारा किया जाता है जो अपने देश एवं घनराष्ट्रीय बाजारों के दबावों और मध्यस्थता प्रभावों की जटिलताओं में राष्ट्र की नीति को निर्धारित करते हैं। इन घनराष्ट्रीय समाज के मामले समझ-समझ पर मध्यस्थता करने हैं और कभी-कभी सम्बन्धों की सम्भावना उभर जाती है। दूसरी ओर राष्ट्रों के बीच घोर-घोर स्थिति होने वाला घनराष्ट्रीय सहयोगी नौ घनराष्ट्रीय शक्ति के लिए कुछ सामान्य प्रदान करता है। शक्ति पर आधारित इन परिचयना को न तो मौलिक बड़ा जा सकता है और न ही आधिकारिक रहन; किन्तु फिर भी यह अनोखी ओर मनीषी है। इसने द्वारा राष्ट्रों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक पदार्थशास्त्री दृष्टिकोण प्रदान किया जाता है। साथ ही यह शक्ति की राजनीति से प्रभावित होने वाले सम्बन्ध राष्ट्रों के वर्तमान विश्व और उनके बीच कन के सहयोग की सम्भावनाओं के बीच समन्वित करता है।

घनराष्ट्रीय संबंधों के प्रति शक्ति का दृष्टिकोण (Power Approach) परम्परागत है। राष्ट्रों के द्वारा विभिन्न तरीकों से शक्ति का प्रयोग किया जाता है और शक्ति पर जो घनराष्ट्रीय नियंत्रण रखा जाता

मीन मुठ प्रारम्भ होने से शक्ति पर घोर भी बन दिया जाता चाहिए। अन्तराष्ट्रीय हित की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाने लगा और आज यह अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में राजनीति के क्षेत्र में अन्वयन का एक वैश्वीय विषय बन गया। आज अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का विषय एक भयान अनुशासन के रूप में वर्णित महत्व प्राप्त कर चुका है। इस विषय पर बहुत बड़ी सभा में विद्वता पूर्ण पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित होने लगी हैं। अन्तराष्ट्रीय विज्ञान इस क्षेत्र में विनोदित बने हैं और कई नवीन प्रविश्यों तथा मान्यताओं विनिमित्त हुई हैं। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की सभा भी बढ़ती जा रही है।

वास्तव में आज की परिवर्तित परिस्थितियों में अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन परिभाषित महत्वपूर्ण होना जा रहा है। यह अध्ययन केवल विगत घटनाओं का समीक्षण मात्र नहीं है बल्कि अन्तराष्ट्रीय सामन्यविज्ञानों का सही निरूपण है। आज इस क्षेत्र में शक्ति के विचारों के प्रचलन के लिए अनेक माध्यम मिल गये हैं। अंतर्गत दृष्टि में अन्तराष्ट्रीय घटनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन भी आवश्यक समझा जाता है। अन्तराष्ट्रीय घटनाओं का विभिन्न पहलुओं को अन्य अनुशासनों द्वारा भी देखा जाता है—उदाहरणार्थ इतिहासकार कूटनीति पर इतिहास पर विचार करते हैं, अर्थशास्त्री अन्तराष्ट्रीय वित्त और व्यापार का हित करते हैं, तथा राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी अन्तराष्ट्रीय कानून, सगठन और राजनीति को पढ़ते हैं। धीरे-धीरे मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, जाति-शास्त्र, भूगोल, रसोई आदि विषय भी अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र की ओर अधिकाधिक आकर्षित हो रहे हैं।

अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण सम्पूर्ण अन्तराष्ट्रीय समाज को सामने रख कर चलता है और इकाइयों का इस व्यवस्था का भाग मानता है। इसी दृष्टि का मुख्य केन्द्र इकाइयों का पारस्परिक सम्बन्ध है। यह दृष्टिकोण अन्वयन से प्रेरित होता है। एक दूसरा दृष्टिकोण इकाइयों से प्रेरित हो सकता है। यहाँ मुख्य अर्थ का विषय इकाइयाँ एवं भाग होते हैं और उनके उद्देश्यों एवं योजनाओं के विनिर्माण पर अधिक जोर दिया जाता है। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की अधि-मात्र पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के देखने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दूसरे दृष्टिकोण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे दोनों ही दृष्टिकोणों की अपनी कमजोरियाँ एवं महत्त्व हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि व्यवस्था का दृष्टिकोण अन्तराष्ट्रीय कानून एवं सगठन तथा अन्तराष्ट्रीय आलावरण के महत्व का अधिक मूल्यवान् कर लेता है। इस दृष्टिकोण में राज्यों के अन्त-

मूल शान्ति गतिनीय शक्तियों को भुत्ता दिया जाता है। रज्यों को एक समान सम्बन्ध दिया जाता है जिसकी वजह से एक जैसी है तथा कथन आधार में ही आधार है। दूसरी ओर बाद बाद दृष्टिकोण आधारित बहुमुखी एवं राष्ट्रीय मध्यम पर अधिक और देता है और इन प्रकार अन्तर प्रक्रिया एवं इकाइयों के पारस्परिक सम्बन्धों की व्यवस्था हो जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधारा का विभाग कई एक उद्देश्यों को सामने रख कर होता है। विचारधारा (Theory) के द्वारा यह तय किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में क्या सम्बन्ध रखना वह अपने विदेश नीति को क्या रूप प्रदान करेगा तथा किन उद्देश्यों का वह अपने व्यवहार की प्रेरणा बनावेगा। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचारकों विद्वानों तथा सत्तार्यों का दृष्टिकोण इन समस्याओं के बारे में एक जैसा नहीं रहता, इसलिए अनेक विचारधाराओं का विकास हुआ है। यह विचारधारा वहीं वही ता एक दूसरे को पूरक प्रतीत होती है और वहीं इनके बीच परस्पर विरोध की प्रतीति होती है। पहले कोई भी देश जब दूसरे देश के साथ अपने सम्बन्धों का तय करेगा या तो उसने सामने कोई एक निश्चित मान नहीं होता या जिसके अनुसार वह अपने व्यवहार के रूप को ठानेगा। उस समय या कुछ भी राज्य के उम्मादिकारियों का दृष्टिकोण रहता या तथा जिस भी वे देश के हित में सम्बन्धित थे उनके अनुसार उस देश के विदेशी संबंध निश्चित हो जाते थे। किन्तु जब अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक पृथक् अनुशासन के रूप में विकसित हुआ तो अनेक निश्चित एवं विचारधाराएँ रूप ग्रहण करने लगी। इनके बाद यह समझा जाने लगा कि जब दूसरे देशों के साथ रहे जाने वाले संबंधों को निश्चित किया जाए तो इन विचारधाराओं का आधार बना दिया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में विचारधारा का महत्व कमजोर बढना जा रहा है और देश विदेश की बदलती हुई परिस्थितियों समस्याओं एवं नवीन विचारों के सामने नई-नई विचारधाराएँ जन्म लेती हैं, पूर्ण विचारधाराएँ मनोचित होती हैं तथा मध्यम का रूप निर्धारण करती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र

(The Scope of International Relations)

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का जब एक पृथक् अनुशासन के रूप में विकास हो गया, तो, राज्या, व्यवस्था, क्षेत्र, निश्चित, निम्न, अनेक, पर, भी, विचार, विचार, जाने लगा। मि० ग्रेसन जिक (Grayson Kirk), क्लास मोर (Klaus

Knorr), ई० एल० वुडवाड (E. L. Woodward) एवं वाल्डेमार गुरियो (Waldemar Gurian) आदि विचारकों ने एक उत्तर अध्ययन की शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति एवं क्षेत्र पर विचार प्रकट किए ।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन क्षेत्र (Scope) पर विचार करने से पूर्व यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि यह पद अत्यन्त ही अस्पष्ट है । अध्ययन क्षेत्र शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है उसकी कुछ निश्चित सीमाएँ हैं । अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में ऐसी कोई सीमा नहीं होती । ज्ञान के क्षेत्र का एक निश्चित प्रकार नहीं होता । इसके विभिन्न धाराएँ तथा तरीके जो एक समय विशेष पर कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपयोगी लगते हैं वे दूसरे समय अपना महार खो देने हैं । ज्ञान की एक शाखा द्वारा एक ही समय में विभिन्न निरीक्षणों के घनत्व-घनता पहलुओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है । ये पहलू निरीक्षण के लक्षण एवं दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं । जिन सीमाओं द्वारा ज्ञान के एक अनुशासन को दूसरे से अलग किया जाता है वे भी कोई ठोस दीवारों की भाँति नहीं होते । समय-समय पर इन अनुशासनों की रूढ़ि भी बदलती रहती है और इस प्रकार उनकी रूप-रचना में भी परिवर्तन या जाड़ा है । यह परिवर्तन अत्यन्त धीमी गति के साथ होता है क्योंकि मानविक घादों यही धीरे-धीरे बदलती हैं तथा बौद्धिक जगत के निहित स्वार्थ भी सामाजिक दुनिया में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करते हैं । यही कारण है कि एक अनुशासन लम्बे समय तक अपने पुराने रूप को ही बनाये रखा है ।

इन सभी बातों को ध्यान में रखने पर हम प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ना बटिन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एक पृथक् अनुशासन है अथवा स्थित विषयों से ही लिया गया एक मिला-जुला विषय है ? इसकी किसी नवीन शाखा का विकास होता है तो वह केवल तभी होता है जबकि कुछ नये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नये तरीकों की माँग की जाती है । इस प्रकार के विषय प्रारम्भ में तो मूल विषय के प्रकार मान ही प्रतीत होते हैं तथा ज्ञान की स्थित शाखाओं के साथ सलग्न रहते हैं किन्तु जब नवीन प्रश्नों की जटिलता बढ़ जाती है तथा उत्तर देने के लिए आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है तो कुछ छमाही मस्तिष्क नये मुन्नाव पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं । उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ज्ञान के एक विशेष विकास का जन्म होता है तथा जो भी कोई इस क्षेत्र के प्रश्नों का जवाब देना चाहे उसे इनका पूरा ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है । बढ़ते-बढ़ते एक दिन यह ज्ञान की नई

शाखा का रूप धारण कर लेता है। यही प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की भी घटना की गई। और उसके बाद ही ये ज्ञान की एक स्वतन्त्र शाखा के रूप में विकसित हो गये हैं।

विश्व के राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों के बारे में जो प्रश्न उठते हैं वे निश्चय ही महत्त्वपूर्ण एवं कठिन होते हैं। ये सम्बन्ध एक विशेष साम्राज्य से सम्बन्धित हैं जिसकी स्थापना इच्छाओं के बीच कोई ऐसी केन्द्रीय शक्ति नहीं होती जिसे कि शक्ति का एकाधिकार प्राप्त हो। वर्तमान ज्ञान की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रश्न इनके अतिरिक्त एक अन्तर-राष्ट्र है कि उन पर स्थित अनुमानों के एक भाग के रूप में विचार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हमें ज्ञान की एक नृपक्ष शाखा के रूप में विकसित करना परम आवश्यक था।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में जिन विषयों का अध्ययन किया जाता चाहिए तथा कौन से विषय हमारे अध्ययन क्षेत्र से बाहर हैं, यह ज्ञान तब करते समय हमका विभिन्न विचारकों के मतों को सामने रख कर चयन चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि ये मत पूर्ण रूप से मरने ही हों किन्तु फिर भी इनके मौलिक मूल्य की मांग तो की ही जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का जो क्षेत्र बताया जाता है उसे हम पूर्णतः साथ एवं अन्तिम नहीं मान सकते क्योंकि समय के विकास के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि ये वे सम्बन्ध होते हैं जो एक देश अपनी सीमाओं से बाहर निरक्षर कर अन्य देशों के साथ विकसित करता है। इन सम्बन्धों के बारे में जो ज्ञान का संप्रदाय है उसे भी हम हमकी परिधि में रख सकते हैं।

दूसरे, ज्ञान की शाखा के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अन्तर्गत विषय वस्तु एवं प्रश्नों पर विचार करने के लिए विशेषण के तरीके तथा तकनीकें भी समाहित रहती हैं। इसकी विषय वस्तु में किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले ज्ञान का संप्रदाय रहता है जो पुराने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने तथा नई समस्याओं को मुक्त करने में सहायता कर सके। इस विषय वस्तु में राजनैतिक समूहों या व्यक्तियों के व्यवहार से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान आता है तथा साथ ही नीति सम्बन्धी प्रश्नों या घटनाओं से सम्बन्धित विशेष सूचना भी सम्मिलित रहती है। जहाँ तक सामान्य ज्ञान

के प्रश्नों का सम्बन्ध है इनमें इन प्रश्नों की जांच करने के लिए या उन्हें ध्वस्वीकार करने के लिए परिवर्तनात्मक तक पहुँचने के तात्त्विक प्रयास भी रहते हैं। जहाँ तक व्यावहारिक प्रश्नों का संबंध है इनमें हम संलग्न प्रश्नों पर विचार करने के प्रयासों, मूल्य से सम्बन्धित सदस्यों के वर्गीकरण, प्राप्त कार्य के विधियों का उत्प्रेषण एवं उनके सम्भावित परिणामों, आदि को समाहित किया जाता है। इन विधियों में से उस विधय की प्रपना लिया जाता है जो इच्छित सदस्यों को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग प्रदान करें।

तीसरे, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विशेष प्रकार के प्रश्नों पर विचार करता है। इसमें सम्बन्ध उन प्रश्नों से है जो कि विश्व-व्यवस्था में स्वायत्त राजनैतिक समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों से प्रकट होते हैं। इस विश्व-व्यवस्था में किसी भी एक स्थान पर शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं होता।

चौथे, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का विन्नेपणकर्त्ता वह होता है जो राष्ट्रीय के पारस्परिक संबंधों पर विचार करने की विशेष योग्यता रखता हो। यह विन्नेपणकर्त्ता राष्ट्रीय नीतियों के संघर्ष, समायोजन और समझौतों में रुचि लेता है। यह सम्भव है कि वह जातिशास्त्र, समाजशास्त्र या जनसंख्या से सम्बन्धित विद्या आदि सलग्न विषयों में भी अपनी रुचि दिखाए, किन्तु ऐसा वह उभी माञ्जित करेगा जिस तक कि ये विषय अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रकाश डालते हों। ऐसी स्थिति में इन दोषों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विन्नेपणकर्त्ता की वह रुचि नहीं रहती जो एक समाजशास्त्री, जातिशास्त्री आदि की रह सकती है।

पाँचवें, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का तकनीकी ज्ञान एक राष्ट्रीय समुदाय के अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्धों के ज्ञान के व्यापक भौगोलिक स्तर का केवल प्रसार मात्र नहीं है। बरन् इसके अपने कुछ विशेष तत्व होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्बन्ध विशेष प्रकार के शक्ति सम्बन्धों से रहता है जिसका अस्तित्व एक केन्द्रीकृत सत्ताविहीन समाज में होता है। अन्तर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र उन व्यापारिक संबंधों पर विचार करता है जो राष्ट्रीय सीमाओं का प्रति-क्रमण करते हैं तथा जो सम्प्रभु राज्यों के अनिवार्यतः कार्यों के कारण जटिल हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून वह कानून होता है जो स्वतन्त्र राष्ट्रों की स्वेच्छाजनक स्वीकृति पर आधारित हो।

छठे, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों द्वारा जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है वे मुख्य रूप से सामाजिक संघर्षों एवं समायोजनों से सम्बन्धित होते हैं। अतः

के व्यवहार, विभिन्न स्थितियों के मापेदार मूल्य तथा कुछ सीमा तक राष्ट्रीय के वाहनी अधिकारों एवं वर्तमानों पर विचार करना होता है। किन्तु इन प्रकार के विषय अधिक नहीं होते और सामान्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को उस समय तक समझना असम्भव होता है जब तक उन स्थानीय तथ्यों एवं प्रभावों का उचित अध्ययन न कर लिया जाए जो राष्ट्रीय नीतियों की रचना पर प्रभाव डालते हैं।

नवें, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मानवीय व्यवहार (Human Behaviour) का अध्ययन भी अपना महत्त्व रखता है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नियंत्रण लेने की प्रक्रिया का पर्याप्त महत्त्व है। ये नियंत्रण ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा लिए जाते हैं जो पहचाने जा सकें।

दसवें, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक दृष्टि से सांस्कृतिक विषय कहा जा सकता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि कुलत्र नियंत्रणकर्ताओं को बाहर निकाल दिया जाए। इसके विपरीत यह जरूरी माना जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विद्यार्थियों को सामान्य क्षेत्र का परिषय प्रदान किया जाए और इनकी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए उचित तरीके बताए जाएं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की विषयवस्तु का एक सांस्कृतिक महत्त्व है क्योंकि इसके प्रतिक्षण से विद्यार्थी को प्रभावपूर्ण विचार करने के तरीकों का ज्ञान होता है तथा वह अपने वातावरण के इस महत्त्वपूर्ण भाग को समझने में समर्थ हो पाता है। एक प्रज्ञातत्र के नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति से यह भाषा की जाती है कि वह विदेशी मामलों से संबंधित प्रश्नों पर विचारपूर्वक अपना मत निश्चित करे।

जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अपना जीवन व्यवसाय प्रारम्भ करना चाहते हैं उन्हें व्यावसायिक प्रतिक्षण प्रदान किया जाता है। इस दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की पांच बर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय कानून और संगठन, कूटनीति, इतिहास और राजनैतिक भूगोल। इसके प्रतिरिक्त इसमें कुछ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक विषयों का भी अध्ययन किया जाता है; जैसे, समाज शास्त्र, जाति शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और नीति शास्त्र आदि। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विचारक को संबंधित विषयों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सम्पूर्ण प्रश्नों के बारे में प्रभावशील रूप से सोचने में सक्षम हो सके। यह भी आवश्यक है कि उसे कम से कम एक स्वीकृत अनुशासन का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह मूल बौद्धिक सदगुणों से परिचित हो

सबे । इस प्रकार के प्रतिक्षण के बाद ही यह विद्वता का उम्प स्तर प्राप्त कर लेगा और अंतर्राष्ट्रीय राजकार्यों के क्षेत्र में भी उपयोगी योगदान कर लेगा ।

वर्तमान विश्व राजनीति के परिवर्तनशील तथ्य एवं नई विभाषे
(Dynamic Elements of Contemporary World Politics
and New Dimensions)

विश्व राजनीति के घटन पर बीगबी शताब्दी की प्रारम्भिक दशाब्दियों से ही कुछ एक ऐसे विभागों ने जन्म लिया जो घागे बन कर अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण के तथ्य बन गए । इन विभागों की प्रकृति परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ इनमें व्यापकता समाप्त, परिवर्तन और परिवर्धन होता रहता है । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी ऐसी घने नई शक्तियाँ अथवा तथ्य सामने आए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था के कार्यों को तथा विश्व व्यवस्था की प्रकृति को प्रभावित किया । इन तथ्यों के रूप में होने वाले परिवर्तनों के बाद इस कथन की तथ्यता सामने आ जाती है कि सारा सारा एक रङ्गमंच की भांति है । जिस प्रकार नाटक के रङ्गमंच पर घटनाएँ घाती और आती रहती हैं उसी प्रकार विश्व व्यवस्था में भी हर कोई एवं घमिनेताओं का परिवर्तन होता रहता है । इस रङ्गमंच पर बड़ी तीव्रता से घटनाएँ घाती और आती रहती हैं । दुनियाँ में युद्ध हुए, गर हुए, प्रलय आई किन्तु बाद में फिर गृजन हुआ, सृष्टि पसी और शांति की गोद में मानव सम्पत्ता पनने लगी । प्रथम विश्वयुद्ध हुआ, भीषण गर गंधार के बाद रण-भेरी दही राष्ट्र सच ने युद्ध की सम्भावना को टालने का प्रयास किया किन्तु क्योंकि रणचही का तत्पर घमो भरा न था, राष्ट्र सच (League of Nations) गर गया और उसकी साज पर पुन लोपे गनगनाने लगी । मानव की दैवीय प्रवृत्तियों ने फिर जोर दिया और अब की बार शांति स्थापना का कार्य समुक्त राष्ट्र सच (United Nations Organisations) को सौरा गया । अस्त्र-शस्त्रों के युद्ध का स्थान शीत युद्ध ने ले लिया । सारा मुख्य रूप से दो भागों में बट गया । विचारधारा के आधार पर विभाजित ये दोनों ही भाग एक दूसरे के परम शत्रु बन गये । साम्यवादी गुट कहता है कि वह एक दिन सारे विश्व को ताल भडे के नीचे ला खडा करेगा जबकि धर्माध्य-वादी गुट वाले अपनी प्रजातन्त्रात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रतिवृद्धि के लिए अपना सब कुछ ग्योछावर करने को तैयार बैठे थे । इन दोनों के बीच एक तीसरा मधुसाय और भी बन गया जो दोनों से घलग गया दोनों के विरोधों

य मनुष्यों को बम बनाने का प्रयत्न करने लगा। यह अपने पास ही मनु-
लान राबर्ट्स का मुँह कहता है। यह गुट आवश्यक भी था क्योंकि यदि भीड़
मुँह बमों में परिवर्तित हो गया तो मनु शक्ति से युक्त इस युद्ध में
क्या शेष रह जायगा यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मनु शक्ति का
विकास न केवल विश्व-शांति के बल्कि मानवता के प्रतिस्व के लिए ही एक
साकार चुनौती बन गया।

साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद धीरे-धीरे मिटते चले गये। ब्रिटेन,
जिसके शासन में सभी सूर्य ही न छिपता था अब अपने क्षेत्र में ही सीमित
रह गया। साम्राज्यवाद का रूप बदला, वह अब रात्रिचित्र न रह कर घायिक
तथा सैनिक बन गया। विश्व के दोनों ही गुट एक दूसरे के प्रभाव को घटाने
के लिए सधि संगठनों का निर्माण करने लगे। छोटे राज्यों को भी इन दो
पाटों के बीच अपना सुरक्षा तंत्र बनाने लगा। गाँटो, सिण्टो, सेन्टो,
बगदाद पेंकट आदि सैनिक संधियाँ होने लगी। साम्यवाद के चारों ओर घेरा
बाल दिया गया। दूसरी ओर साम्यवाद ने भी इस बकभूह को तोड़ना
प्रारम्भ कर दिया। समय के अनुसार विभिन्न राज्यों की शक्ति-स्थिति में
अन्तर आने लगा। विदेशी पैसे से छूट कर अनेक नवोदित राष्ट्र विश्व रंगमंच
पर आकर अपना पाठ पढ़ा करने लगे। छोटे राष्ट्रों में अपना सघ बना कर
सामूहिक रूप से सुरक्षा एवं विकास के कार्यों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति का
विकास होने लगा। एशिया व अफ्रीका के देशों में चेतना जागी। दक्षिण
एशिया एक क्षेत्र के रूप में, दक्षिण पूर्वी एशिया एक क्षेत्र के रूप में, अरब
गणराज्यों का सघ, अफ्रीकी एशियाई सघ आदिको साकार करने की दिशाओं
में राजनीतिज्ञों के मस्तिष्कों की मुद्रा घूमने लगी।

यह है विश्व रंगमंच, जिसकी घटनाओं में नदी के जल का सा प्रवाह
और परिवर्तन है। इस प्रवाह में वर्तमान समय में जो नये मोड़ लिये हैं उनमें
से कुछ का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जा रहा है।

(१) विचारधाराओं का परिवर्तित रूप

(The Changing States of Ideologies)

साम्यवाद व पूँजीवाद के प्रतिनिधि के रूप में रूस तथा अमेरिका
के बीच पहले सैदान्तिक भेद इतना था कि इनको घुम्बक के दो प्रुवों की
भाँति गृहक एवं असातम माना जाता था। दोनों देशों के बीच विचारधारा
के मूल अन्तर अब भी वर्तमान हैं—एक पूर्णतावादी (Totalitarian) राज्य
है जबकि दूसरा नागरिक स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र मर्यादवस्था में अधिक विश्वास

रगता है। एक वा दावा है कि समानता पर आधारित हो के बारण्ड उनके राज्य की शासन प्रणाली सचवा प्रमाण्य है जबकि दूसरा उसे तात्काली वा ही एक दूसरा रूप कहता है। इन पर भी मात्र विश्व की बदली हुई परिस्थितियों में दोनों ही गुटों के बीच लड़ने की मांग विरोध और मध्यम का बातावरण नहीं रह गया है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर ये सब कुछ उत्तर दृष्टिकोण माने बनने जा रहे हैं। इनके अतिरिक्त माटो के देशों की एका विमर्शित होती जा रही है। पश्चिमी शक्तियों के बीच डी, एम, को लेकर काफी विवाद चलता रहा था। अमरीका ने मित्र नीति धारापर मीन के साम्यवाद के दूसरे बड़े देश साम्यवादी चीन को साम्यवाद दे दी है। अरब-इसरायल मध्य के समय मीन द्वारा अमरीका आदि देशों का समर्थन न करना इसी प्रवृत्ति का लक्षण है। इसी प्रकार साम्यवादी गुट में भी विभाजन हो गये हैं। कुछ राष्ट्र माटो के नेतृत्व में चीन की अग्रगण्य में आ गये हैं तथा दूसरे माटो को ही साम्यवाद का केन्द्रबिन्दु बनाने के पक्ष में हैं। इन दोनों भागों के सदस्यों के बीच लड़ने की कई स्तरों में लड़नी पड़ी जा रही है। चीन कम का सम्बन्ध इनका अतिरिक्त मध्यम होता जा रहा है कि कई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर ये एकरा नहीं है। भारत पर चीनी हमले के समय कम ने पुनी साथ ही और प्रायः न यह कह कर कुछ भी करने में अपनी मजबूरी प्रकट की कि 'एक उदासा माई है तो दूसरा उनका दोस्त'। चीन को स्पष्ट शर्तों में मोविमन कम को गुप्तारवादी (Revisionist) एक पुत्रीशियों का विटल कह कर आरोप लगाता है कि मोविमन कम सब मानने व सेनिन के सिद्धान्तों में विपुल हुआ रहा है। इन प्रकार दो विरोधी विचारधाराओं के बीच का अन्तर कम हो रहा है तथा एक ही मिडल के बीच शिपटन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को विचारधाराओं के इन परिवर्तित सदस्यों में देना जाना अनिवार्य रहेगा।

(२) दो गुटों का मात्र अस्तित्व नहीं रहा है

(Bipolar world does not exist today)

राष्ट्रपति साइजन होवर (Eisenhower) के समय विश्व दो गुटों में बंटा हुआ था किन्तु अब अन्तर्राष्ट्रीय अगाध में केवल दो ही प्रतिद्वन्द्वी ही यह मान नहीं है। मात्र विश्व का प्रत्येक देश मात्र आपकी एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट करने का प्रयास करता है। यदि ऐसा यह अस्तित्व कम से नहीं कर सकता तो एक क्षेत्रीय संगठन बनाकर विश्व समान पर अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। छोटे राष्ट्रों की प्रवृत्ति यह रहती थी कि किसी भी गुट के साथ मैनिफेस्ट सन्धि में सम्मिलित

घोर अपनी सुरक्षा की घोर से निश्चित हो जाय, किन्तु घाज की बदलती हुई परिस्थिति व दृष्टिकोणों के अनुसार ऐसा करना न कोई चाहता है, न यह आवश्यक है घोर न उपयोगी। पाकिस्तान पश्चिमी सैनिक सन्धिषों में बंधा हुआ होने पर भी चीन का 'हमदर्द' बना हुआ है। इस तथ्य के निरीक्षण द्वारा हम यह जान सकते हैं कि घाज विश्व में दो-गुटो की भावना एव अनीति की गाथा बन गई है।

(३) क्षेत्रीय संगठन के रूप एवं प्रकृति में अंतर

(Change in nature and forms of Regional organisation)

क्षेत्रीय संगठनों का आधार मूल तत्त्व राष्ट्रों की सुरक्षा थी। यह धाना की गई थी कि संगठन के किसी भी सदस्य-राष्ट्र पर विदेशी घातमाला हान की दशा में दूसरे सभी सदस्य घातमालाकारी का विरोध मिल कर करेंगे। किन्तु घाज की बदली हुई परिस्थितियों में क्षेत्रीय संगठनों पर जिस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है यह पाकिस्तान ने सन् १९६१ में भारत पर किए अपने घातमाला के समय जान लिया होगा।

(४) विभिन्न देशों के स्तरों में परिवर्तन

(Change in Status of different Nations)

एशिया घोर अफ्रीका के देशों की विश्व राजनीति में पहले अप्रिय महत्व नहीं दिया जाता था। इनमें से अधिकांश तो अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का प्रयोग करने में भी समयन न थे। उनका भाग्य किसी दूसरे साम्राज्य-वादी राष्ट्र के साथ बंधा हुआ था, किन्तु घाज के न केवल अपनी स्वतन्त्र विदेश नीति का ही प्रयोग कर सकते हैं बल्कि साथ ही उनका स्थान महत्वपूर्ण भी है। उनमें निम्नलिखित का विश्व राजनीति पर भारी प्रभाव पड़ता है। भारत ने तटस्थ या घमनघन राष्ट्रों का नेतृत्व करने, शीत युद्ध की बढ़ती को कम करने के लिए जो प्रयास किये हैं उनका महत्व समार के अधिकांश देश, जिनमें रूस व अमेरिका भी सम्मिलित हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं। चीन बड़ी शीघ्रता से विश्व की बड़ी शक्ति बनने की भाव उत्तापना ही रहा है। इसके लिए यह हिस्सा घोर युद्ध का भाग बनाने में भी नहीं हिचकिचाता। उसका यह विचार है कि पूंजीपति वर्ग से सत्ता लेने एवं मजदूर वर्ग का विश्व में शासन स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि युद्ध के लिए तैयार रहा जाय। साम्यवाद के चीनी व्याख्याकारों के मत में पश्चिमी पूंजीवादी राष्ट्र कागज के भेर (Paper Tiger) हैं। साम्यवादी राष्ट्रों के पास शक्ति की कमी नहीं है भव डरने का कोई कारण नहीं है। भव विश्व-

जाति के लिए समय आ गया है। इन प्रकार मात्र विश्व के राष्ट्रों का स्वर नमना बदलता जा रहा है। प्रत्येक देश को अपनी विदेश नीति का निर्माण करने समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखना होगा।

(२) विश्व सत्ता के प्रति परिवर्तित दृष्टि

(The attitude changing towards U.N.O.)

संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना त्रिम समय की गई थी तभी से मात्र तब हमने विश्व की घनत्व महत्वपूर्ण समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान किया है। विश्व जाति एवं महयोग बनाने के साथ साथ यह सत्ता प्राप्ति, सामूहिक एवं सामाजिक उत्पत्ति के लिए भी बल उठाती है। इन सत्ता की सफलता के लिए आवश्यक है कि विश्व के व्यक्ति से व्यक्ति देश इसके सदस्य होने तथा उनकी सहभागिता एवं सन्तुष्ट महयोग इन मिला रहे किन्तु मात्र विभिन्न राष्ट्रों का दृष्टि इनके प्रति उदासीन या दिखाई देने लगा है। विश्व सत्ता की राष्ट्रों ने विश्व जाति एवं वस्तुओं के सामान्य उन्हें न के नीचे उन्नाह कर राष्ट्रीय स्वायत्त की सोझी पर आ गया है। प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की अपने राष्ट्रीय स्वायत्त की निधि का माध्यम बनाता चाहता है। यदि संयुक्त राष्ट्रसंघ इन्डानेजिया की मलयेजिया दिशाने में सहायता नहीं करता तो इन्डानेजिया की इसकी सदस्यता में कोई मार नजर नहीं आता। पाकिस्तान ने भी घमकी दी थी कि या तो कश्मीर समस्या का हल उनकी जगहों के आधार पर कर दिया जाय करना नद भी उनकी सदस्यता छोड़ दगा।

विश्व में ऐसे राष्ट्र नमन बढ़ने जा रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनी समस्या का हल करने की अपेक्षा शक्ति का प्रयोग करके उसे सुलभाना अधिक उचित समझते हैं।

(३) अणु शक्ति के नये स्वामी

(New Owners of Atomic Power)

रोबर्ट्स (Henry L. Roberts) ने १९५६ में यह माना था कि विश्व में हलचल मचाने वाली सबसे बड़ी समस्याएँ हैं 'अणु' और 'सामूहिकतावाद'। विश्व के राष्ट्रों ने इस तथे को समझा है। अणु घसनों का निर्माण, रक्षा एवं प्रयोग तीनों ही अवस्थाएँ बड़ी गतिशील और भयानक परिणामों को उत्पन्न करने वाली है। जितना घन, समय और शक्ति इन कार्यों में व्यय होता है यदि वह दूसरे उपयोगी कार्यों में लगाया जाये तो विश्व काफी घाते बढ़ सकती है। अणु घसनों का निर्माण, जैसा कि प्रत्येक देश निर्माण करते

समय ही घोषित कर देता है, प्रयोग न करने के लिए ही किया जाता है। यह शक्ति एक प्रकार से प्रतिरोधात्मक रूप में कार्य करती है किन्तु मावावेग में कोई भी मानव समुदाय यदि इनके प्रयोग पर उतर आये तो हजारों वर्षों को यह मानवता घोर सस्कृति बिना अपना कोई बिन्दु छोड़े ही नष्ट हो जायगी। विश्व जनमत इसके खतरों को समझ कर इसे मीमित करने की घोर मुक्ता तथा इसके प्रयोग के सम्बन्ध में बड़ी शक्तियों एवं अन्य अनेक राष्ट्रों के बीच समझौता हुआ (Partial Test Ban Treaty) जिसके अनुसार धनु शक्ति के परीक्षण खुले प्राकाश में होना बन्द कर दिया गया। धनु शक्ति का प्रयोग दानियूण कार्यों में करने के लिए दबाव दिया जाने लगा। समुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ तथा अन्य कई एक राष्ट्रों ने मिलकर धनु शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए सन्धि (Non-Proliferation Treaty) की है। किन्तु मान जिते देन धनु शक्ति-सम्पन्न होने का मुकुट पदनने को चाहतुर हैं। चीन ने अक्टूबर १९६४ को एक धनु बम का परीक्षण कर मानव जाति के सहारकों की धरती में अपना नाम लिगा लिगा है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने के बाद से तो यह धनु शक्ति के क्षेत्र में पर्याप्त भागे बढ गया है। जागत के ऊपर भी अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबाव होते जा रहे हैं कि वह बम का निर्माण करे।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत की उत्तमर्ने (Tensions of International World)

① वर्तमान विश्व के परिवर्तित रूप में जो अनेक विकास समाहित हो गये हैं उनके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न उत्तमर्ने पैदा हुईं। एक दल जब अपने पक्षियों या दूरस्थ देशों के साथ सम्बन्ध विनिमित करने के लिये अग्रसर होता है, उसके सामने अनेक समस्याएं विकट रूप धारण कर उपस्थित होती हैं। उसे अनेक गतिरोधों, विरोधानाओं एवं प्रक्षामवस्तु पूर्ण स्थितियों में होकर गुजरना होता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्वानों को भी ऐसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना होता है। विरोधानाम पूर्ण स्थितियों एवं दो निम्न मामलों में से एक का चयन करना अत्यन्त कठिन बन जाता है। इस सम्बन्ध में प्रथम अन्तेस-नीय विरोधानाम यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में वस्तुगता भरती जाय अथवा विषयगतता। यह कहा जाता है कि वस्तुगता अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के लिये एक मात्र मार्ग है जिसे अपनाये बिना यह विश्व की प्रमुख समस्याओं को व्यापोजित रूप से विवेचित नहीं कर

सम्मान। यह सब होने हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विघटन हट्टिबोल पड़ाने मारने चलता है। एक समझ द्वारा ऐसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण बातों को समझें कि जो दूसरे समझ के विपरीत उद्देश्यों की ओर खींचे न हों। प्रदेवर विन्समी राईट (Quincy Wright) के कथनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की समस्या का मुख्य सूत्र यह है कि विभिन्न विघटनपूर्ण समस्याओं में किन्हीं विभिन्न समझों द्वारा स्वीकार किया जाता है और प्रदेवर द्वारा उन्हें समझना सत्य माना जाता है।¹ प्रदेवर देन के अर्थ में कुछ दुराग्रह एवं मायनाएँ होती हैं किन्तु यह न केवल अपने विपरीत वरन् दूसरे देन के विपरीत भी अन्तिम माय मान कर समझता है। कई बार इनकी प्रकृति के परिणामस्वरूप विभिन्न देनों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध पैदा हो जाते हैं और कभी कभी ये सम्बन्ध समयों का भी रूप धारण कर लेते हैं। उचित यह समझा जाता है कि एक देन को अग्रिम से अग्रिम वस्तुमान हट्टिबोल अन्तर्गत बाह्य तात्त्विक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वह माने पूर्वोक्तों से प्रत्यक्ष होकर देन के तथा उनके विपरीत में कठोर माय दण्डों की प्रवृत्ति कर सके। ऐसा करने में वह देन प्रजासत्तात्मक जीवन से सम्बन्धित सूत्रों एवं सिद्धांतों की भी अन्तर्गत रूप से समझता है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक दूसरे विरोधमान यथार्थवाद और आदर्शवाद के मागों का बीच है। बहुत पहले से ही दार्शनिक एवं व्यवहार कर्ता आदर्श और यथार्थ के विचलन में उलझे रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की देनसे समय रिस हट्टिबोल की अन्तर्गत जाय यह सन्देह समय में एक विवाद का विषय रहा है। विदेश नीति या राष्ट्रीय व्यवहार के सम्बन्ध में जो मत विभिन्नता पाई जाती है उसमें से अग्रिमता का आधार आदर्श और यथार्थ के विचलन हुआ है। जब एक देन अपने राष्ट्रीय हित पर विचार करने लगता है तो यथार्थ एवं आदर्श के अर्थों की परिभाषित करने की समस्या उत्पन्न होती है। इसमें पामर तथा पर्किंस (Palmer and Perkins) का यह कथन सही है कि-राष्ट्रीय-एवं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दोनों का बड़ा महत्व है और दोनों का बीच प्रसार की अपेक्षा मात्रा का अन्तर है।² यही कारण है कि आदर्शवादी विचारक भी आदर्शवाद की यथार्थता के सम्बन्ध में बात

1 Quincy Wright, The Study of International Relations, Appleton Century-Crafts 1955, p 20

2 Palmer and Perkins, International Relations, Scientific Book Agency, 2nd Edition, p XXVI.

करना पसन्द करते हैं और दूसरी ओर प्रत्येक पर्याप्तवादी यह दिखाना चाहता है कि वही सच्चा आदर्शवादी है। चूंकि यह माना जाता है कि विचारकों की दोनों ही प्रेरणाएँ कुछ सम्भावित सत्यों से युक्त हैं क्योंकि जब हम आदर्शवाद को उसके बंधन रूप में अपना लेते हैं तो वास्तविकताओं से दूर चले जाते हैं और बंदन यथार्थ पर जोर देने से अपनाई गई नीतियाँ और अनाकर्षक बन जाती हैं।

तीसरा विरोधामास राष्ट्रवाद और अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के बीच स्थित संधियों से प्रकट होता है। यदि एक दृष्टि से देखा जाये तो वैज्ञानिक प्रगति एवं तबनीकी विकास ने सारे विश्व का एक परिवार का रूप दे दिया है किन्तु दूसरी ओर यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि इस परिवार की इकाइयाँ वे स्वायत्ततामयी राज्य हैं जिनमें सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कई प्रकार के अन्तर वर्तमान हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रवाद एक प्रभावपूर्ण तत्व है और विशेष रूप से जो देश कुछ समय पूर्व ही साम्राज्यवाद के चंगुल से बाहर आये हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना प्रसरता के साथ है। इन देशों में राष्ट्रवाद का होना उपयोगी भी है क्योंकि ऐसा न होने पर उनका धार्मिक एवं सामाजिक विकास वांछित गति के साथ नहीं हो पाएगा। जिन देशों में धार्मिक भी साम्राज्यवादी शक्तियों का पजा गढ़ा हुआ है उनमें राष्ट्रियता की भावना का अस्तित्व उनके स्वयं के अस्तित्व की एक आवश्यक शर्त है। इनके पर भी अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के महत्व एवं आवश्यकता का भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि अणुशक्ति के विकास के कारण विश्व को विश्वस से बचाने के लिये यह जरूरी बन गया है कि विभिन्न राष्ट्र अपने आपकी राष्ट्रियता के मज़बूत आधारों से बाहर जाएँ और सहयोगपूर्ण-संघों के विकास के लिये सच्चे दिल से प्रयास करें। वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में राष्ट्रियता और अन्तर्राष्ट्रीय दो विरोधपूर्ण तत्व आवश्यक दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच समायोजन करना बहुत जरूरी है।

चौथे, अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर एक अन्य विरोधामास जो राष्ट्रियता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता के अस्तित्व के कारण पैदा होता है, यह यह है कि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच उपयुक्त समायोजन किस प्रकार किया जाए। जब तक राष्ट्रिय राज्य व्यवस्था राजनैतिक संगठन का मुख्य रूप रहती है उस समय तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा पर अधिक जोर दिया जाता रहेगा। चूंकि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बीच आवश्यक रूप से संधर्भ नहीं है क्योंकि एक की प्राप्ति करने के लिए जिन साधनों की अपेक्षा जाता है वे कभी कभी दूसरे की

प्राप्त करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गिज होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो घनत्व दीर्घीय संगठन बनाए गए तथा सैनिक शक्तियों की पूर्ति उनके परिष्कारमय विषय के देशों में सहयोग की भाषा बड़ी। इनके साथ यह भी सत्य है कि कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को इन माध्यमों के आधार पर दाब पर नहीं लगा सकता कि प्रत्येक देश अपने आसपास में दूसरे के साथ सहयोग करेगा। सैनिक शक्तियों के प्रयोग में यह बात गिज हा चुकी है। समुक्त राज्य अमेरिका ने टर्की से माठ बह दिया था कि वह सामाजिक शांतिपूर्ण की स्थिति में दक्षिण पूर्वी एशिया में सैनिक संगठन के आधार पर सैनिक महायुद्धों के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा का बरतन स्वयं ही रचना होगा है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी प्रयास करने होते हैं। जब विश्व के कई देश सैनिक रूप में एक दूसरे की सहयोग देने के लिए बचनबद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रीय-सुरक्षा की समस्या धीरे धीरे घटित होती जाती है क्योंकि पहले तो वेबन एक ही राष्ट्र के सामाजिक गति के लिए रक्षात्मक संघर्षों की जाती थी किन्तु अब एक समूह द्वारा दिये जाने वाले हमले के विरुद्ध रक्षा की संघर्ष करना आवश्यक बन जाता है।

पाँचवें, यह निश्चय करना एक समस्या है कि विश्व राजनीति के व्यवहार में शक्ति प्रयुक्त स्वीकृति में किस की महत्व प्रदान दिया जाये। यदि एक देश दूसरे देश से अपनी बात को स्वीकार करना चाहता है तो इसके लिए उसे शक्ति का प्रयोग करना चाहिए प्रयुक्त दूसरे राष्ट्र को समझा-बुझा कर उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। कई बार ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं कि शक्ति के मार्ग को अपनाते हैं कि लिए बाध्य होता पड़ता है। एक शक्तिप्रिय देश की भी शक्ति और स्वीकृति दोनों ही मार्ग अपनाकर चलना होता है। शक्ति का प्रयोग करना या न करना पूरी तरह से एक राष्ट्र की दृष्टि पर ही निर्भर नहीं होता बल्कि इनके लिए दूसरे राष्ट्र का व्यवहार भी पर्याप्त महत्व रखता है।

छठे, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह निर्धारित करना भी बड़ा कठिन है कि यहाँ सहयोग एक समय का सापेक्षिक महत्व क्या है। यह स्पष्ट है कि दोनों ही प्रवृत्तियों के घने उदाहरण प्रतिदिन सामने आते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में होने वाले सघर्षों के समाचार प्रायः अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं तथा ये शक्ति एक युद्ध जैसे मूल प्रश्नों को सझा कर देते हैं। इतने पर भी 'सहयोग', सघर्ष की अपेक्षा अधिक सामान्य है तथा मौलिक रूपों में इसे प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार ही प्रयास किये जाते हैं। मनोविज्ञान

एक समाज शास्त्र आदि विभिन्न अनुमानों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सघर्ष एक सहयोग के कारणों पर प्रकाश डाला जाता है।

सातवें, आज के जगत् में मनुष्य की आवश्यकताओं बहुत अधिक बढ़ गई हैं किन्तु साथ ही विज्ञान की प्रगति ने यह भी सम्भव बना दिया है कि अत्येक व्यक्ति को जीवन का एक सन्तोषजनक स्तर प्रदान किया जा सके। यहाँ विरोधामास यह है कि जिन देशों में मानवीय आवश्यकताओं तीव्रगति से बढ़ रही हैं वहाँ उनको सन्तुष्ट करने के साधनों की व्यवस्था नहीं है और जहाँ ये साधन उपलब्ध हैं वहाँ आवश्यकताओं की मात्रा इतनी अधिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका को यह चिन्ता रहती है कि वह मूल फसला के प्रति-रिक्त उत्पादन को बढ़ा सक्षि करे। इन प्रतिरिक्त फसलों को या तो गोदामों में भर दिया जाता है अथवा उनको नष्ट कर दिया जाता है किन्तु दूसरी ओर दुनिया के करोड़ों लोग भूखा, सूखा या बाढ़ के कारण भूखों मरते हैं। दुनिया के अधिकांश लोग ऐसे हैं जो दिना कुछ सामे ही सी जाते हैं। जब तक विश्व से इस अन्तर को दूर नहीं किया जाता तब तक यहाँ मानवीय व्यवस्था की मात्रा कम ही की जा सकती है।

आठवें, बीमवीं शताब्दी का एक विरोधामास यह है कि हमें एक ओर तो नैतिक स्तर एक सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हुआ है तथा मानव इतिहास में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव व्यवस्था के लिए प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु जब हम तस्वीर के दूसरे पक्ष को देखते हैं तो भारी निराशा होती है क्योंकि विश्व का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ कि मानव को अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। इस दृष्टि से साम्यवादी एवं पूँजीवादी दोनों ही व्यवस्थाओं बहुत कुछ समान रूप से दोषी हैं क्योंकि जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था की अमानवीयता जा रहा है वहाँ साम्यवादी का हर प्रकार से अमानवीय किया जा रहा है और दूसरी ओर जहाँ साम्यवाद का प्रभाव है वहाँ अतिक्रियावाद के नाम पर सामूहिक हत्याओं, अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, अज्ञानता आदि की जा रही है। एफाका महाद्वीप में जाति के नाम पर, महापूर्व में धर्म के नाम पर तथा विपक्षनाम में विचारधारा की खातिर जो विध्वंसनात्मक एवं अमानवीयपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं वे बीमवीं शताब्दी के रूप को महा ब्रवा देते हैं। अमानवीय व्यवस्था की कोई सीमा नहीं होती। यह सम्बन्ध के अन्त स्तर पर पहुँचे देशों में भी पाया जा सकता है। अन्त-हारा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नौषों लोगों की समस्या को लिया जा सकता है। विश्व के धर्मों को शिक्षाओं आज केवल नाम मात्र के लिए ही रह गई है। व्यावहारिक जगत् में उनका प्रभाव एवं महत्त्व नहीं के बराबर है।

पक्षों के अतिशय एवं सामूहिक व्यवहार पर एक अनुष्ठान का काम करना या तथा कानों प्रचार से उसे मानवता की परिधि में समाहित करना या विज्ञान विज्ञान की प्रगति से जब से धर्म के मूल्यों को गीत बनाया है तथा मनुष्य के विश्वास पर बुद्धिवादी किया है तभी से मनुष्य अतिरिक्त सभी अतिशय, योग्यता, मूढ़ता, टंग एवं अनादिक्युल्य बन गया है।

अब, विज्ञान की प्रगति से तथा तकनीकी विज्ञानों से मानव को एक ऐसे दो रास्ते पर लाकर मड़ा कर दिया है जहाँ से कि वह चाहे तो धरती पर स्वर्ग की अन्तरिक्ष करने की ओर बढ़ सकता है और यदि चाहे तो सब सब की सब मानव सम्पत्ति को अतीत की ऐसी कड़ानी बना सकता है जहाँ से कोई कड़ा पाया टोका है और न ही मूढ़ता वाला। मात्र मनुष्य के हाथों में अमीनिम मणि सा मई है। यह उम्मीद है कि वह इनका प्रयोग विज्ञान के लिए करे या रक्षा के लिए।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक विज्ञान के रूप में (Science of International Politics)

सात्र विज्ञान का युग है। प्रत्येक शास्त्र अपने-अपने अधिष्ठापित वैज्ञानिक स्वभाव के लिए प्रयत्न करता है। कारण यह है कि वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी प्रगति सामान्य होती है; वे निश्चित होते हैं क्योंकि उनकी गरिमा के बारे में सदेह या सम्भावना पर निर्भर नहीं रहता रहता। वैज्ञानिक अध्ययन एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है जिसमें मविष्यवाणियों की जा सकती है। वे मविष्यवाणियों प्रायः सब भी हो जाती हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सभी परिस्थितियों में प्रत्येक समय तथा स्थान पर एक समान रूप में प्रभावकारी होते हैं। इन सब गुणों के कारण ही प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की मति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में भी यह प्रश्न उठता है कि क्या इनका अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर किया जा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर पाने से पूर्व यह जानना उपयोगी एवं आवश्यक होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के वैज्ञानिक होने का अर्थ क्या है तथा किन विधि का अनुगीतन करके इनकी वैज्ञानिक बनाया जा सकता है।

वैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएँ

वैज्ञानिक विधि से जब हम किसी विषय की आवश्यकता करना चाहते हैं तो प्रारम्भ में सरसम्बन्धी परिकल्पनाएँ बनाई जाएँगी। उन परिकल्पनाओं

की सत्यता की जांचने के लिए पहले वस्तु-स्थिति का निरीक्षण करना होगा, उसके बाद प्रयोग। प्रयोग द्वारा जो चीजें हमारे अध्ययन से सम्बन्ध रखती हैं उनको रखा जायेगा तथा बाकी को छोड़ दिया जायेगा। ऐसे ऐसे विषयों का वर्गीकरण करना होगा। वर्गीकृत भागों का प्रापसी सम्बन्ध क्या है यह देखने के बाद तत्सम्बन्धी निष्कर्ष दिये जायेंगे। ये निष्कर्ष वैज्ञानिक होंगे, इस प्रकार के अध्ययन में पाई जाने वाली मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं—

(१) एक व्यावहारिक परिस्थिति में केवल थोड़े ही विकल्प हो सकते हैं प्रथवा उन विकल्पों के बीच गुणात्मक भिन्न होता है, इससे चारों में वैज्ञानिक सदेहनीय होता है। उसका यह प्रभाव रहता है कि चीजों के सभी भिन्नताओं को केवल गुणात्मक सीमा तक साफ़ रख दिया जाये।

(२) वैज्ञानिक अध्ययन की सबसे प्रमुख विशेषता यह मानी जाती है कि यह भविष्यवाणी करने तथा वस्तु स्थिति पर नियंत्रण रखने में समर्थ होता है। यदि किसी विधि का सर्व सही है, प्रस्तुतीकरण का वगैरह प्रभावकारी है तथा निष्कर्ष भी बुद्धिसमय है तो भी हम उसे तब तक वैज्ञानिक नहीं कह सकते जब तक वह व्यवहार में काम न करे। प्रयोग द्वारा यदि उन निष्कर्षों को सही सिद्ध नहीं किया जा सके तो उन्हें बदलना होगा। विज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। इससे अध्ययन में कारण-कार्य (Cause and Effect) का सम्बन्ध होता है तथा भविष्यवाणियों के गलत होने की सम्भावना कम रहती है।

(३) विज्ञान यह मानकर चलता है कि वास्तविकता का पता लगाने के लिए निरीक्षण (Observation) करना आवश्यक है। इसमें बुद्धि के आधार पर अनुमान भी किये जाते हैं किन्तु उनको सत्य तभी माना जाता है जब वे निरीक्षण व प्रयोग की नतीजों पर सही चरते हो।

(४) विज्ञान के निष्कर्षों के बीच तालमेल रहता है, वे परस्पर विरोधी नहीं होते। कोई भी निष्कर्ष वैज्ञानिक है या नहीं यह देखने के लिए हम दूसरे वैज्ञानिक निष्कर्षों से उसकी तुलना कर सकते हैं। यदि विरोध वर्तमान है तो हमारा निष्कर्ष सही नहीं माना जायगा।

(५) विज्ञान दर्शन से सम्बन्धित है, क्योंकि दर्शन-प्रदत्त तार्किक व्यवस्था का प्रयोग करता है। तर्कों को प्रमाणित करने के लिए यह कलात्मक तरीका अपनाता है अतः कला से सम्बन्धित है। यह इतिहास से सम्बन्ध रखता है क्योंकि इसके लिए प्रमाण व तथ्य इतिहास द्वारा दिये जाते हैं, किन्तु विज्ञान मानवीय विद्या नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की प्रकृति का

एक घन माता है। इस धर्म में समानवीय होने के कारण यह इतिहास, दर्शन व ज्ञान के मिश्र भी है।

विज्ञान की उक्त विशेषताओं को यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में प्रयोग कर सकें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिक मान्यता से है कि जैसा कि विष्णु राईट का मत है, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ऐसा क्षेत्र है जिसमें विज्ञान का प्रयोग बढ़ा बठिन है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। किर्क (Dr. Grayson Kirk) महोदय ने इन दृष्टिकोणों को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। किर्क महोदय का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है और इस दृष्टि से हम इतिहास की भाँति ऐतिहासिक तथ्यों का सफल बन रहे हैं। इस दृष्टिकोण में घटनाओं का वर्णन मान्यता दे दिया जाता है। दूसरा दृष्टिकोण वैधानिक (Legal) है। इसका धर्म यह है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कानूनी दृष्टि से देखकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तीसरे दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उसी रूप में देखा जाता है जिस रूप में वह पेट रही है। न तो उनको ऐतिहासिक सन्दर्भ में देखा जाता है और न ही किसी वैधानिक दृष्टि से बरतें, एक निष्पक्ष दण्ड के रूप में जैसी वे हैं उसी रूप में देगी जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखने के इन विभिन्न पहलुओं का वर्णन पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि सभी दृष्टिकोणों में वैज्ञानिक सत्यता अवश्य मौजूद है। समाप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी बौद्धिक व्यवस्था (Academic discipline) है जो वर्तमान इतिहास तथा नवीन घटनाओं के मिश्र है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राजनीति सुधारों से भी मिश्र है।¹ इस प्रकार ऐतिहासिक एवं वैधानिक दोनों ही दृष्टिकोण जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने में प्रयुक्त किये जाते हैं, अनुचित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना सम्भव नहीं है इससे कई कारण हैं। प्रथम एवं प्रमुख कारण तो यह है कि ये घटनाएँ स्थिर नहीं हैं बदलती रहती हैं। मानवीय क्रियाएँ होने के कारण यह अनुमान लगाना बठिन होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न हो जाएं तो फिर उनका परिणाम क्या होगा तथा एक देश विशेष की नीति पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। राज्य, राष्ट्र और सरकारों के व्यवहार को

समझने के लिए वैज्ञानिक तरीका केवल तभी अपनाया जा सकता है जबकि हम यह मान कर चलें कि ये मनुष्य एवं उनके दृष्टिकोणों का संयोग है या एक विश्व व्यवस्था का भाग है।¹

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को वैज्ञानिक रीति से जानने के मार्ग में दूसरी कठिनाई यह है कि वैज्ञानिक अध्ययन के निष्कर्षों से व्यक्ति प्रभावित हो सकते हैं। यह सम्भव है किसी जटिल चीज के बारे में, यदि भाव कोई बात कह दें तो उसका प्रभाव जटिल चीज पर न पड़े और यही कारण है कि वहाँ भाव अधिकवाहिया कर सकते हैं। किन्तु मनुष्य के बारे में यह सच नहीं है। उदाहरण के लिए किसी ने यह सामान्यीकरण (Generalization) किया कि 'एक पाकिस्तानी सैनिक तीन भारतीय सैनिकों के बराबर होता है।' एक सण के लिए मान लिया जाये कि सामान्यीकरण सच था। इसने भारतीय जवानों में प्रतिक्रिया की; उनका साहस बढ़ गया। वर्तमान भारत-पाक युद्ध में यह साबित हो गया कि उक्त कथन सही था, सच तो यह है कि एक भारतीय जवान तीन पाकिस्तानी जवानों के समान था। मनुष्य में स्वर्ण की गतिधियों को सुधारने की प्रवृत्ति होती है इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन करते समय निरीक्षण तथा विश्लेषण की प्रक्रिया मौखिक एवं प्राणीमात्र विज्ञानों से भलग ही तरह की होनी चाहिए।—

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के तथ्य बड़ी गीघ्रता से बदलते रहते हैं, तथा इसका विषय अनिश्चित (Ambiguous material) होता है इसलिए इनके बारे में अनिश्चितताग्रिमा करना सम्भव होता है।² अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति ऐसी है कि न तो इनमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग हो किया जा सकता है और न ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जिनको वैज्ञानिक कहा जा सके।

किन्तु राइट का मत इस सम्बन्ध में कुछ उदार है। उनका विचार है कि यद्यपि अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण कि हम इस विषय को विज्ञान का रूप पूरी तरह से नहीं दे सकते किन्तु फिर भी यह मानना गलत होगा कि वैज्ञानिक विधियाँ (निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण, सारणीकरण प्रयोग, निष्कर्ष आदि) का किसी भी स्तर पर प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन में नहीं किया जा सकता। विज्ञान की अनेक विशेषतायें जैसे वस्तुगतता

1. Quincy Wright, The Study of International Relation, P. 116.

2. Morgenthau, Hans J., Politics among Nations, P. 18

(Objectivity), निश्चितता (Accuracy), मात्राबोध (Quantification), तर्क (Logic) आदि का प्रयोग नागरिकों, नेताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अन्य कार्यकर्ताओं के दृष्टिकोणों का प्रभावित करने में दिया जा सकता है। धार्मिक युग में सभी व्यवस्थाओं को धार्मिक रूप में विज्ञान बन जाता है बाहे उनसे विज्ञान बनने के मार्ग में बिजुली हो जायावे वही न पाये।¹ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी समय की मांग के अनुसार विज्ञान बनाना ही होगा। इनका प्रारम्भ क्या या इतिहास के रूप में हुआ, बाद में वे दर्शन की माँति सामाज्यीकरण करने सके और यह समय है कि इनको वैज्ञानिक रूप दिया जाय।

विचारधारा का महत्व एवं योगदान (The Importance and Role of Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा का महत्व एवं योगदान उतना ही महत्वा एवं प्रभावपूर्ण है जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन व्यवस्था में विचारों का महत्व होता है। जीवन में सफलता प्रायः सभी प्राप्ति हो पाने है जबकि व्यक्ति कुछ मूल सिद्धान्तों को अपनाते हुए घूम रहे। इसी प्रकार एक राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता भी कुछ विचारधाराओं (Theories) से मार्ग दर्शन प्राप्त करता उससे सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का उपयोग एवं महत्त्व विश्व राजनीति में प्राप्त सम्पत्ति माना जाता है। उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं विचारक आज किसी न किसी रूप में अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर विचारधाराओं के महत्व को स्वीकार करके चलते हैं। इन प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के कुछ महत्त्व के सिद्धान्तों के विचारों का उल्लेख करना उपयुक्त है।

(१) थॉमसन (Kenneth W Thompson) के विचार

थॉमसन महोदय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के प्रयोगों की सीढ़ी कार्य करना होता है। एक ओर तो उसे ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स शीप-बर्ता मरीज से दूर रह कर कार्य नहीं कर सकता उसी प्रकार एक सिद्धान्त शास्त्री को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकताओं से घबरा दूर नहीं रहना चाहिए। उसे वर्तमान समय में स्थित वास्तविकताओं का वर्णन करना चाहिए और

दूसरी ओर नवविषय में उनका क्या रूप हो सकता है यह भी विनिर्दिष्ट करना चाहिए। वर्तमान को समझना तथा नवविषय को विनिर्दिष्ट करना अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के दो महत्वपूर्ण तथा परस्पर संबंधित कार्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत बुद्धि पर आधारित होते हैं और इन पर आधारित भ्रमों से प्रेरित कोई भी विदेश नीति बौद्धिक (Rational) आधारों से प्रेरित हो जायेगी। प्रतीत काल में राजनैतिक सिद्धांतों ने प्रचलित दोनों पक्षों को समुचित रूप से नहीं देखा और यही कारण है कि उनके निष्कर्ष वास्तविकता एवं लोकप्रियता प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे। उदाहरण के लिए उदार लोकतन्त्रवादी (Liberal Democrats) विचारकों ने इस बात पर जोर दिया कि जनसाधारण का विदेश नीति के निर्माण में भाग लेना चाहिए अर्थात् जब भी किसी एक देश अन्य देश के साथ अपने सम्बन्धों को ठीक करे तो वह उनकी उपयुक्तता के बारे में प्रत्यक्ष ही जनता की राय जान ले। देश के नागरिकों को इस बात का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाये कि वे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में अपनी प्रतिक्रिया से देश के कर्णधारों को परिचित करा सकें। 'विदेश नीति का रूप प्रजातन्त्रात्मक होना चाहिए' यह विचार सरकार तथा विदेश नीति की सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित था। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह कारगर रहेगा। दूसरे, इस व्यवस्था में वे लोग भी विदेश नीति जैसे विषयों में सक्रिय रुचि लेना प्रारम्भ कर देंगे जो अब तक इस ओर से उदासीन थे किन्तु यह मांगता व्यवहार करने पर सफल न हो सकी। अमेरिका में विदेश नीति से संबंधित निर्णय लेते समय जनमत स्पष्ट कराने की परम्परा ने अमेरिका की लाम पटुबाने की प्रेरणा कई बार पथ भ्रष्ट किया। उक्त सिद्धान्त का निर्माण करते समय यह भुला दिया गया था कि अमेरिका का प्रत्येक नागरिक पूरे देश के लिए उत्तरदायी नहीं है वह केवल अपने हिस्से के लिए उत्तरदायी है तथा प्रत्येक व्यक्ति इस विषय में विशेषज्ञ (Expert) न तो था और न हो सकता था। प्रजातन्त्र की मूल्यों का शासन कहने की भ्रमों की परम्परा ने विदेश नीति के विषयों में जनसाधारण के हस्तक्षेप को प्रासंगिक एवं अनुपयोगी बना दिया। विदेश नीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लेने का कार्य विशेषज्ञ ही कर सकते हैं।

थॉम्पसन (Thompson) के विचारानुसार जिन्हीं भी सैद्धांतिक मान्यताओं को उनके लक्ष्यों (Objectives), प्रेरणायों (Motivations) तथा राष्ट्र की नीतियों (Policies of nations) के आधार पर प्रासंगिक तथा अप्रासंगिक सिद्ध किया जा सकता है।

विश्व शांति की स्थापना के लिए सन्तुष्ट रूप से प्रयास करना अन्य राष्ट्रीय गिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। दोस्ताने महादय के विचारानुसार अधिवासी देशों की विदेश नीति का पीछे एक सदैव यह रहता है कि अधिकांश में अधिकांश राज्यों के साथ शांति की स्थापना का प्रयास किया जाय। शांति तथा यदि कोई एक दूसरे का समानार्थक समझा जाता है। यदि किसी देश का कार्य शांति का समर्थक है तो वह अवश्य ही युद्ध पूर्ण हाथों और यदि कोई देश युद्धपूर्वक व्यवहार कर रहा है तो वह अवश्य ही शांति की दिशा में ही प्रयत्नशील होगा। इस दृष्टि से कोई भी युद्धपूर्ण देश शांति के विरुद्ध किसी भी सदन की धरना आदेश नहीं बना सकता। बाबून की शांति और युद्ध का सापेक्ष माना जाता है। बाबून के अनुसार जब व्यवहार किया जाता है तो विचार से समर्थ एवं युद्ध का गहरा बहुत कुछ कम हो जाता है और इसलिए यह व्यवहार युद्धपूर्ण माना जा सकता है। इसी अर्थ में एक विचारक ने यह माना है कि किसी भी मानव समाज ने हिंसा के लिए कोई विवरण नहीं सोचा, सिवाय इसके कि बाबूनी तथा वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की जाना।

इस विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि इसके द्वारा भन्तराष्ट्रीय व्यवहारों को धोड़क बना दिया जाता है।

(२) मार्गेन्थो (Hans J. Morgenthau) के विचार

सिद्धान्तों का ऐतिहासिक तथ्यों से अनिष्ट सम्बन्ध रहता है। वैसे इतिहासकार एवं सिद्धान्त शास्त्रों के बीच एक गूढ़म अंतर की स्थिति रहती है। इतिहासकार घटनाओं को इतिहास नाम से वर्णित करता है तथा उनको स्पष्ट करने के लिए वहीं-वहीं पर सिद्धान्तों के प्रभाव को मान लेता है जबकि दूसरी ओर सिद्धान्तशास्त्री सिद्धान्तों का निर्माण करते हैं तथा ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग वे इतिहास के उद्घरणों को देकर करते हैं।

भन्तराष्ट्रीय सिद्धान्तों का मुख्य सदन न केवल भन्तराष्ट्रीय व्यवस्था एवं शांति के हित में भन्तराष्ट्रीय संबंधों की वैधानिकता एवं समुदायिक रूप प्रदान कर देना है बल्कि भन्तराष्ट्रीय संबंधों पर मविष्यवाणी करना तथा परिणामों को नियंत्रित करना भी है। मार्गेन्थो के मतानुसार भन्तराष्ट्रीय विचारधारा के पीछे यदि इतिहास के घटना-चक्र का सही विश्लेषण न हो तो वह राजनीतिज्ञ को एक सफल राजनीतिज्ञ कभी भी नहीं बनने देगा। केवल उपनिवेशवाद व आदेशवाद विचारों की नींव पर खड़ा सिद्धान्तों की स्थापना कर दें तथा राजनीतिज्ञों से उन सिद्धान्तों को व्यवहार

करने का अनुरोध करें तो इसके परिणाम उस देश की राजनीति के लिए पतित हो सकते हैं। प्रादुर्गो यर आधारित व्यवहार जिन कल्पनाओं के साथ माने बढ़ता है वे प्रायः यथार्थ जगत में तत्कार नहीं हो पानी। दूसरी ओर आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कुछ ऐसे सिद्धांत भी उपस्थित हैं जो वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं। वे सिद्धान्त एक प्रकार का भ्रम पैदा कर देते हैं। वे बताते हैं कि अस्त्रों से सुसज्जित सम्प्रभु राष्ट्रों से युक्त समाज आज भी अपनी विदेश नीति का संचालन बिना किसी पतरे की समाधान के कर सकते हैं क्योंकि प्राचीनकाल में ऐसा होता था; किन्तु ये सिद्धांत आज के प्रगु युग की बदली हुई परिस्थितियों को भुला देते हैं। और यदि इन सिद्धांतों को देव वाक्य मानकर इनके आधार पर आचरण किया गया तो ये राजनीतिज्ञ आज उसी प्रकार असफल रहेंगे जैसे कि युद्धों के बीच के काल से राजनीतिज्ञ उस समय के उन्नतिशील सिद्धांतों (Progressive theories) के अपनाने पर रहे थे।

मार्गेन्थो महोदय के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा का सिद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से महत्व है। इन दोनों क्षेत्रों में इसके उपयोगी कार्य निम्न प्रकार हैं —

(१) अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के सिद्धान्तिक (Theoretical) कार्य—
अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का मुख्य कार्य राजनीतिज्ञों को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में प्रथम प्रदर्शन करना है। विदेश नीति से संबंधित गतिधियों को सुलझाने में तथा समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक राष्ट्र के सम्मुख किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर हल अपनाने के कई विकल्प रहते हैं। उस देश का माध्य, विश्व की शांति, विदेश नीति की सफलता आदि सभी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं कि वह देश उन विकल्पों में से किसको अपनाना है। यहाँ अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का महत्व प्रारम्भ हो जाता है क्योंकि इन्हीं के आधार पर यह जाना जा सकता है कि एक विकल्प विशेष को अपनाने का क्या परिणाम हो सकता है तथा उन परिस्थितियों का भी उल्लेख कर सकता है जिनमें उस विकल्प को अपनाना उचित तथा सफल रहेगा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त एक देश को उन सभी दुष्परिणामों एवं खतरों से बचा लेते हैं जो एक गलत विकल्प को अपनाने पर हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के सिद्धांतिक कार्यों के प्रति-रिक्त कुछ व्यावहारिक कार्य भी हैं।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के व्यावहारिक (Practical) कार्य—
जैसा कि मार्गेन्थो (Morgenthau) महोदय का विचार है, उपरोक्त

संज्ञात्मक कार्य प्रायः सभी सामाजिक गिडानों द्वारा परिपूर्ण किये जाते हैं किन्तु इन पर अन्तराष्ट्रीय विचारधारा का एकाधिकार नहीं होता।^१ व्यावहारिक कार्यों का अनुमीलन अन्तराष्ट्रीय गिडानों की धानी विशेषता है। अन्तराष्ट्रीय गिडान्त तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों एवं अन्तराष्ट्रीय समस्याओं की उत्पत्ति होते हैं। इन गिडान्तों की रचना करने वाले विचारक चाहे वे कबरे में बैठ कर बौद्धिक विवेचनों में उमरें नहीं रहते, वे तो व्यावहारिक जगत में परिस्थितियों से प्रभावित विचारों को देग कर कुछ निष्कर्षों पर आते हैं। ऐसे में वेकर धात्र तब का गारा राजनीतिक दमन हमी प्रकिया का परिणाम है। जैसे कि राजनीतिक परिस्थितियों विचारधारा के निर्माण में कार्य करती है उसी प्रकार विचारधारा भी उन परिस्थितियों में अनेकालीय परिवर्तन करने के उद्देश से गतिम होता है।

राजनीतिक वातावरणों को चार विभिन्न दृष्टियों से देखने के कारण अन्तराष्ट्रीय गिडान्त चार प्रकार के विभिन्न व्यावहारिक कार्यों को सम्मिलित करते हैं। अन्तराष्ट्रीय गिडान्तों का सबसे पहला काम यह है कि राजनीतिकों द्वारा अपनाई गई नीतियों को यह बौद्धिक आधार एक सहमति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए १९४७ के बाद अमेरिकन विदेश नीति में कई नवीन नीतियों को अपनाया जैसे ट्रूमैन गिडान्त, माइंस योजना; अमेरिकन सप्लाय व्यवस्था आदि। इन नीतियों के पीछे किसी प्रकार का गिडान्त नहीं था। बाद में गिडान्त वास्तविकों द्वारा गिडान्त की रचना करके इन नीतियों को व्यापक-समस्त गिडान्त दिया गया।^२

गिडान्तों का दूसरा काम यह है कि विचारों की एक सामायोजित व्यवस्था का निर्माण किया जाय जो विदेश नीति को सबसे विचारधारा प्रदान कर सके। अन्तराष्ट्रीय विचारधाराओं द्वारा ऐसे मापदण्डों का निर्माण किया जाता है जिनके आधार पर विदेश नीतियों की आलोचना की जाती है अथवा उनको स्वीकार किया जाता है। अन्तराष्ट्रीय विचारधारा एक प्रकार से बौद्धिक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे में बिठा कर विदेश नीतियों को उचित ठहराया जाता है अथवा उनको विपरीत गिडान्त करके उन्हें छोड़ देने पर जोर दिया जाता है।^३ अन्तराष्ट्रीय के युग में यह धारणात्मक समझा जाता है कि शासन द्वारा अपनाई गई विदेश नीति पर सौजन्य की स्वीकृति होनी

1. Morgenthau, Hans J, Ibid, P. 105

2. Morgenthau, Hans J, Ibid. P. 113

3. Morgenthau, Ibid P. 114

चाहिए। सिद्धान्त शास्त्रियों को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी सिद्धान्त रहे जाय वे जनमत के अनुकूल होने चाहिए। लोकमत तथा घरेलू राजनीति के दबावों की परिधि में जो सिद्धान्त व्यवहार में लाये जा सकते हैं उन्हीं को राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाया जाता है।

विचारधाराओं का एक अन्य कार्य यह है कि उसे एक नवीन विश्व की रचना का आधार प्रस्तुत करना चाहिए। यह कार्य अन्य सबसे अधिक सौजन्यपूर्ण है। भाव जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सव्यों के रूप में एक तीव्र परिवर्तन दिया देता है, अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का यह कार्य करना चाहिए तथा वे इसे कर सकते हैं। इस नवीन विश्व में राष्ट्रीय राज्यों का प्राप्ति सव्य आज की भाँति ऐसा न होगा कि सशस्त्र सव्यों का रूप धारण कर ले। यह नया सवार इस प्रकार का होगा कि इसमें सभी देश अपने भाषों एक विश्व सरकार के रूप में संगठित कर लेंगे। १७८६ की फ्रांसीसी क्रांति के बाद से अब तक विश्व का झुकाव राजनैतिक संगठन की ओर काफी रहा है। किन्तु इसे सैद्धान्तिक विश्लेषण के आधार पर अनुस्यूत भी ठहराया जा सकता है। भाव अणु शक्ति के विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के रूप तथा दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। विद्वत् नीति के साधन तथा साध्य भी बदल गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में दो विचारधाराओं गतियों हैं—एक कल्पनाविही (Utopian) तथा दूसरी यथार्थवादी (Realist)। अणु शक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के रूप पर तथा एक देश ने घरेलू कार्यों पर उत्प्रेक्षणीय प्रभाव पड़ सकता है। भाव अन्तर्राष्ट्रीय विचार धाराओं का यह एक प्रमुख कार्य बन गया है कि इन प्रभावों को कम करे तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को उसी रूप में समझे जिस रूप में वे हैं। इन्हें चाहिए कि बौद्धिक राजनीति तथा सत्यागत उन सभी परिवर्तनों को एक बौद्धिक रूप प्रदान करें जिनको यह ज्ञानिजारी शक्ति (अणु शक्ति) स्वयं से प्रभावित करना चाहती है।

एक अन्य कार्य अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का यह है कि उनके द्वारा एक ऐसी ढाल का निर्माण कर देना चाहिए जो विचारणीय समुदाय (Academic Community) को राजनैतिक विश्व के साथ सम्बन्धित करने से रोक सके। कई बार ऐसा होता है कि विचारकों द्वारा राजनीतिज्ञों के प्रलोभनों में आकर जनता को बौद्धिक स्तर पर गुमराह किया जाता है तथा इस प्रकार राजनीतिज्ञों के तुच्छ स्वार्थों की पूति की जाती है। यह सब एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण सम्भव होता है। विचारणीय वर्ग द्वारा यह कार्य 'प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों व रूपों के निर्धारण' द्वारा सम्पन्न कर दिया जाता

है। इस प्रकार धर्म विचारक राजनीति विचार के मजबूती नहीं या गहने, उनमें व्यवस्था नहीं हो गयी तथा वे राजनीतियों में सम्मिलित नहीं हो पाये। बिना दिन प्रतिदिन की राजनीति के धर्म में कुछ बड़े ही विचारक इस प्रक्रिया द्वारा विद्वानों की सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्राप्त कर लेते हैं तथा उनको किसी प्रकार का राजनीति परिणाम भुगतने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ विचारकों ने इसे एक आवश्यक सुराई माना है। उनके अनुसार धर्मराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करते समय 'विद्वानों के विद्वानों' की जानकारी एक दुर्भाग्यपूर्ण आवश्यकता बन जाती है।¹ इस आवश्यकता का कारण यह है कि जब तक हम यह न जानें कि एक विचारधारा या विद्वान का आधार क्या है तब तक उनके गहरी स्वभाव का विवेचन करने में अपने आपकी समस्याएँ पाने हैं।

इस प्रकार राजनीतिक विद्वानों के कार्यों की माँगों में विद्वानिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों में विवेचना की है।

धर्मराष्ट्रीय विचारधाराओं के उपर्युक्त सम्बन्धों का धर्म के लिए यह आवश्यक है कि विद्वान शास्त्रियों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि धर्मराष्ट्रीय विद्वान को समय की समस्याओं से अपने आपकी सम्मिलित रखना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण विद्वान धर्म की कोठरी में बैठकर नहीं रखा जा सकता। रक्षिता के समस्याओं के वास्तविक एवं व्यावहारिक रूप में निश्चय का परिचय होना चाहिए। उन प्रतिदिन के विश्व की परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के उपर्युक्त होना चाहिए। केवल अवस्थानात्मक पर आधारित कोई भी विद्वान्त धर्म यात्री कीड़ी पर प्रभाव नहीं रख सकता। जो विद्वान्त समय के अनुकूल नहीं होता वह अनुयोगी एवं व्यावहारिक बन जाता है तथा उसे धर्मराष्ट्रीय पटल से हटा दिया जाता है। कोई भी दूर केवल उनी विचारधारा को अपनावण जो हमारे लिए व्यावहारिक दृष्टि से लाभप्रद है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्वान शास्त्री व्यावहारिक नैतिक गुणों से परिपूर्ण हो सर्वांगीण उत्तम सत्य की व्याख्या करने के लिए संचालित साहस होना चाहिए। उसे लोक महत्व के विषयों पर अपनी स्वतन्त्र राय प्रकट करने में कोई संकोच या डर नहीं करना चाहिए। उसे निष्ठा भाव से समय की समस्याओं पर विचार करना चाहिए। इस गुण से सम्पन्न

1 Kalaus Knoch & Sidney Verba (ed), The International System, P. 2.

संग कम होते हैं, यही कारण है कि दार्शनिक एवं सिद्धान्त शास्त्रियों की मध्या प्रत्येक युग में शृंगुलियों पर गिने जाने योग्य होती है। सिद्धान्त शास्त्री को अतीत काल में उसी समस्या के ऊपर अन्य विचारकों द्वारा किये गये प्रयासों से भी लाभ उठाना चाहिए। दुराग्रह एवं पूर्वाग्रह मदैव ही हानिप्रद होते हैं। उसे समस्या से सम्बन्धित सभी आवश्यक तथ्यों का संकलन करना चाहिए। उसे एक समस्या पर विचार करते समय एक देश विशेष से प्रारम्भ कर सम्पूर्ण विश्व को घेरने प्रसरण का विषय बना लेना चाहिए।

(५) तीसरे, सिद्धान्त-शास्त्री को घटनाओं का वेवल बर्णन करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उनका बौद्धिक विश्लेषण करके कुछ निष्कर्षों पर पहुँचना चाहिए। सिद्धान्तों का निर्माण करते समय इतिहास से भी यथाचित सहायता प्राप्त करनी चाहिए। पहली पीढ़ियों एवं शताब्दियों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान भी इस दृष्टि से अनुपयुक्त न रहेगा।

(६) अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की वर्तमान परिस्थितियों को समझने का कार्य करना चाहिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थित घटनाओं की व्याख्या करनी चाहिए तथा भविष्य के लिए तैयारी करने तथा भविष्यवाणी करने का कार्य करना चाहिए। यह सोचना अवधार्य होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सिद्धान्त भी उतनी निश्चित भविष्यवाणी का आधार बन जायेंगे जितना कि भौतिक विज्ञान होने हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों को भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाले परिवर्तनों को देखना चाहिए तथा उनके लिए मार्ग-दर्शन भी करना चाहिए।

आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो घनेक विचारधारायें देने को प्राप्त होनी हैं उनका जन्म आधुनिक काल की ही देन है। पहले इनका अस्तित्व नहीं था। इनके अभाव के लिए उत्तरदायी कई एक तरफ हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के अभाव के कारण (Reasons of the Lack of International Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सिद्धान्तों का प्रागमन इतने पीछे जाकर हुआ, इसके कई कारण हैं। वाइट महोदय (Wight) के विचारानुसार अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत बहुत कम हैं; गाय ही जो हैं उनमें बौद्धिकता और नैतिकता की मात्रा थोड़ी है। इसके कारण आन्तरिक हैं। अतीतकाल के सम्प्रभुता-सम्पन्न राज्यों में बुद्धि का जो स्तर तथा दिशा रह सकती थी उसमें केवल इसी प्रकार के सिद्धान्त सम्भव थे।

गिद्दाओं के प्रभाव का दूसरा माध्यम राज्य विचारकों में 'दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रधानता' था। जब विचारक धनराष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न समस्याओं एवं स्थितियों पर विचार करने से तो उनका निष्कर्ष एवं प्रक्रियाएँ सामाज्यीकरण के रूप में होते थे। धारा में कुछ समय पूर्व धनराष्ट्रीय समस्याओं पर कोई उत्तरागामी गिद्दाएँ नहीं थे और न ही किसी ने धनराष्ट्रीय समस्याओं की समस्या का अनुभव किया था। विभिन्न धनराष्ट्रीय समस्याओं के अन्तर्गत विभाग के लिए अनुष्ठान उत्पन्न भूमि उन समय भी बनाया भी। जिस तरह इतिहास के प्रारम्भ में ही धनराष्ट्रीय समस्याओं का अन्विष्ट है तथा विदेश नीति के लक्ष्य है उन्हीं तरह उन समय भी अन्विष्ट व सुरी विदेश नीति के अनुष्ठान परिणाम प्राप्त हुए थे। विदेश नीति की सफलता व असफलता करने वाले में महत्त्व रक्षती थी। इन स्थितियों के होने पर भी धनराष्ट्रीय गिद्दाओं की रचना नहीं की गई लेकिन हमने हमें यह निष्कर्ष नहीं निरालना चाहिए कि एन्टो, अरस्तू, हॉब्स या माकि सन्निहित दृष्टिकोण के थे और इसीलिए के इस कार्य को नहीं कर रहे। मार्गस्थो महोदय ने धनराष्ट्रीय गिद्दाओं की वर्तमान समय तक रचना न होने के कारणों का वर्णन किया है। वे दार्शनिक प्रकृति के प्रभाव को इसका एक मूल कारण मानते हैं। उनके विचारानुसार जब तक धनराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन इतिहास ही रहा उनके कोई गिद्दाएँ न बन गये—इसका प्रथम कारण यह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसका प्रभाव नेपोलियन-बुद्धों के अन्तर्गत रहा। उन समय तक राष्ट्रों के सम्बन्धों की एक सामाजिक तत्त्व माना जाता था जिसे परिवर्तित करना अनुष्ठान की शक्ति के बाहर है। यह समझा जाता था कि धनराष्ट्रीय सम्बन्ध होते ही होंगे जैसा कि किसी देश विशेष का इतिहास एवं उसकी परिस्थितियाँ उन्हें बनायेगी। य चीजें किसी विचारधारा से प्रभावित न होकर अनुष्ठान की प्रकृति से संचालित हानी हैं, इसलिए धनराष्ट्रीय विचारधारा की रचना की ओर ध्यान ही नहीं दिया गया। इस दृष्टिकोण का एक यह हुआ कि राजनैतिक विचारधाराओं को महत्त्व मिला। राजा के स्वयं एवं औपानिक स्थिति को रक्षित करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार धर्म की अहीम का रूप बनाने हुए मार्क्स ने कहा था कि जब मजदूर वर्ग अपने दुर्गों तथा भोवण का कारण अपने माध्य की ओर अपने छुटकारा दिवाने वाला ईश्वर को मान लेता है तब वे स्वयं प्रयत्नहीन बन जाते हैं, उनके मोचने की शक्ति खत्म जाती है। मार्क्स का यह कथन प्रसारण यही पर भी लागू हुआ। जब यह मोचा गया कि राष्ट्रों के सम्बन्ध अनुष्ठान की शक्ति से बाहर हैं, अनुष्ठान चाहे तो भी उनमें

सुधार नहीं कर सकता तो स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत जैसा विषय बौद्धिक विवेचनाओं के क्षेत्र में कोई स्थान न पा सता। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि यह न साबित जाय कि राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध किसी अन्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, बल्कि वे तो मनुष्य पर योनि जाते हैं, मनुष्य को उन्हें स्वीकार करना चाहिए तथा जहां तक हो सके उन्हें उनी रूप में सहन करना चाहिए। इसके विपरीत सोचना यह चाहिए कि राष्ट्रों के मध्यवर्ती सम्बन्ध मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं और इसलिए मनुष्य उन्हें अपनी इच्छा से ही संशोधित, परिवर्तित व परिवर्धित कर सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के द्वारा तो एक ऐसा भावार्थ प्रसार किया जाता है जिसे अपना कर एक देश आमानों से अपने हितों की प्राप्ति कर सके। यह व्यवहार का एक विकल्प प्रस्तुत करती है। किन्तु यदि कोई स्वतंत्र देश अपने परम्परागत व्यवहार को अपरिवर्तनीय मान कर इस विकल्प को ही महत्व न दे तो उसके लिए विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह जाता।

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के दौर से उदित होने का दूसरा कारण यह है कि १९वीं व २०वीं शताब्दी की प्रथम दशकाब्दी में सैद्धान्तिक विचारों के क्षेत्र में सुधारवादी प्रवृत्ति का जार था। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझने का प्रयास नहीं किया गया बल्कि बौद्धान्तिक सगठनों एवं संस्थाओं को स्थापना करके उन्हें दबाने का प्रयत्न किया गया। शक्ति राजनीति (Power Politics) को जो विदेश नीति का आधार स्वप्न है, धृष्टि से देखा जाता था और एक बुराई माना जाता था—जिसे समझने की अपेक्षा मिटा देना ही उचित था। उदाहरण के लिए, हम प्रथम विश्व युद्ध के समय व उसके बाद बुद्धिमान की स्थिति एवं उसके कार्यों को ले सकते हैं। हम देखेंगे कि विल्सन (Wilson) शक्ति संतुलन (Balance of Power) के प्रभावों को समझने में रुचि नहीं लेते थे वरन् उससे छुटकारा पाने की तलाश में अग्रिम थे। वे अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का इस रूप में सुधार करना चाहते थे कि किसी की शक्ति संतुलन पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही न रहे। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं विदेश नीति के क्षेत्र में एक नियो-घातमक दृष्टिकोण का बोझ डाला था। ऐसी स्थिति में बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की विषयगत तथा व्यवस्थित रूप में देखना असम्भव था।

एक तीसरा कारण भी था जिसने कि यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं (International Theories) के जन्म तथा विकास को पूर्णतः

असम्भव तो नहीं बनाया किन्तु इसके विनाश तथा उपयोग को सुरी तरह अवक दिया। यह कारण राजनीति का राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप में पाया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय समझ पर होने वाली प्रत्येक घटना को राजनीतिज्ञ यह दे दिया जाता है और इस प्रकार उनको किसी विचारधारा के आधार पर विश्लेषित करने या समझने का मार्ग रच जाता है। राजनीतिज्ञ बायीं में बौद्धिक तरव समाहित रहता है—इस कारण राजनीति सैद्धांतिक विश्लेषणों के प्रति सादर की दृष्टि से देगना प्रारम्भ कर देती है। इसके अनिश्चित राजनीतिज्ञ विचारों बहुत कुछ अनिश्चित एवं अस्थायी रूप में चलती रहती हैं। उनके बारे में किसी निश्चित की रचना करना बड़ा कठिन बन जाता है। जब राजनीतिज्ञ घटनाओं को देखता प्रतीत होता है कि वे पूर्णतः नवीन हैं तथा पहले कभी नहीं पड़ी थी और न पड़ेंगे। किन्तु दूसरी दृष्टि से वे समान हैं क्योंकि वे सामाजिक शक्तियों में प्रभावित होती हैं। सामाजिक शक्तियाँ अत्यन्त मानवीय प्रकृति का परिणाम हैं। इन समान परिस्थितियों में वे समान रूप में प्रभाव डालेंगी। किन्तु समस्या तो यह है कि इस सामान्यीकरण (Generalisation) एवं विशेषीकरण के बीच कोई विमात्रक रेखा खींचने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं है और इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निश्चित निष्कर्षों का निर्माण नहीं हो पाता। अन्तर्राष्ट्रीय निष्कर्ष परिस्थिति, समस्या विशेष तथा अन्य सामाजिक पहलुओं से मण्डित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के सामने काश्मीर की समस्या है। इसे सुलझाने के लिए मान लो हमारे पास चार विकल्प हैं। अन्तर्राष्ट्रीय निष्कर्ष भारत को यह मार्ग दर्शन करा सकते हैं कि एक विश्व विरोध को धरना देने के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, साथ ही वे उन परिस्थितियों को बता सकते हैं जिनमें एक विश्व विरोध का घटनावा जाना तथा सफलता प्राप्त करना सम्भव है। निष्कर्ष उन्हे यह भी बता सकते हैं कि किन्हीं विरोध परिस्थितियों में एक विश्व विरोध को दूर करने की प्रेरणा प्राप्ति-मिलना देनी चाहिए। किन्तु ये सभी सैद्धांतिक विश्लेषण या तो उन तत्वों पर निर्भर करते हैं जो हमारी जानकारी के बिना ही घटित होते हैं अथवा जो ऐसे परिणाम हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी न था। यही आधार-अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर सैद्धांतिक विचार विमर्श रच जाता है। विचार-धारा (Theory) विभिन्न विवरणों की ओर इशारा कर सकती है तथा उनकी आवश्यक पूर्व परिस्थितियाँ एवं उनके परिणामों को स्पष्ट कर सकती है। यह उन परिस्थितियों को बता सकती है जिनके होने पर विश्व अस्थिर पलटायी बन सकती है। किन्तु यह छोड़े बहुत निश्चय के साथ भी यह नहीं

बता सकती कि कौन सा विरूप सही है तथा वह निश्चय ही अपनाया जायेगा।^१

अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के निर्माण एवं स्वीकृति के मार्ग की बाधाएँ (Problems of Building and Confirmation of International Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के निर्माण के मार्ग में व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक अनेक समस्याएँ आती हैं। किसी भी विचारक के लिए यह एक अनम्भव कार्य होगा कि वह अपनी विचारधारा (Theory) के इतिहास में दुर्घटनाओं के कार्य, विशेष व्यक्तिगत सम्बन्धों का प्रभाव एक प्रभावशाली अक्ति-सम्पन्न विचारधारा (Ideology) का प्रभाव आदि बातों को भी समीक्षित कर सके। अनेकों सविनष्ट तत्व होते हैं, जिनकी ध्यान में रखकर ही एक पूर्ण तथा प्रभावशाली सिद्धान्त का निर्माण किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक जब कोई विचारधारा बनाने लगते हैं या किसी विचारधारा को स्वीकृत बनाने का प्रयास करते हैं तो उनके सामने अनेक समस्याएँ आती हैं जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं—

(१) सामान्यीकरण की समस्या

सामान्यीकरण किये बिना किसी प्रकार का बौद्धिक चिन्तन असम्भव होता है तथा जहाँ विषय सन्निष्ट होते हैं वहाँ चिन्तन का रूप स्वतः ही सिद्धान्त का रूप धारण कर लेता है। कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त उसने सत्य नहीं होने जितने कि भौतिक विज्ञानों के सिद्धान्त होने हैं। किन्तु ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भूगोलियों से लेकर गैलिलियो के समय तक भौतिक विज्ञान भी इतने निश्चित न थे जितने कि अब हैं। यह परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों के क्षेत्र में भी हो सकता है। भौतिक विज्ञानों में सुनिश्चितता की स्थापना करने वाले तत्व मुख्य रूप से दो हैं। प्रथम तो यह है कि वे साधारण समस्या को ही अपने अध्ययन का विषय बनाती हैं जिनका एक निश्चित तथा सीमित क्षेत्र होता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान ने केवल उन समस्याओं को अपने अध्ययन का विषय बनाया है जिनका समाधान करने के लिए उसके पास साधन मौजूद हैं। अपने अध्ययन के क्षेत्र की यदि आवश्यक हुआ तो यह कम भी कर सकता है। भौतिक

सङ्गठन भौतचारिक एवं स्थायी होते हैं। सिन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर राजनैतिक सङ्गठन मनोपचारिक होता है, उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सन्धिषो को लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वार्थ को ध्यान में रखकर जो समझौते, संधियाँ सौदेबाजियाँ आदि की जाती हैं वे केवल तभी तक स्थिर रहती हैं जब तक उन देशों का स्वार्थ उनसे पूरा होता रहे। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं अनुपयोगी होने पर इनको तुरन्त ही तोड़ दिया जाता है। कबन भौतचारिकता के नाम पर इनको बनाये रखने की परम्परा नहीं है।

(४) घटनातत्त्वों की समस्या

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाली घटनायें एकाकी नहीं होतीं उनके पीछे कारण के रूप में अनेक तत्त्व वर्तमान रहते हैं। उन तत्त्वों को समझे बिना उस घटना को भी समुचित रूप से नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए वर्तमान विश्व में स्थित शक्तियों में आपसी संघर्ष को यदि हम समझना चाहें तो यह आवश्यक है कि उन देशों की मूलिक सामर्थ्य, अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ, राजनैतिक सम्बन्ध, विश्व के अन्य राष्ट्रों की उनके प्रति भावनायें आदि बातों पर विचार किया जाय। उन देशों की आन्तरिक राजनीति को जानना भी आवश्यक होगा क्योंकि आन्तरिक राजनैतिक एवं आर्थिक आवश्यकताएँ एक राज्य की विदेश नीतियों को बहुत कुछ प्रभावित करती हैं।

(५) तुलनात्मक अध्ययन की समस्या

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इसमें विद्यार्थी को विभिन्न घटनाओं की एक ही समय में तुलना करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। आज की एक घटना का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमको भूतकाल में कोई वंसी ही घटना ढूँढनी पड़ेगी और यह आवश्यक भी नहीं है कि जो घटना हमें मिले उसके पीछे भी वही कारण हो जो प्रस्तुत घटना के पीछे है।

अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के पीछे उक्त समस्याओं एवं कठिनाइयों के होने पर हमें कैपलान (Kaplan) महोदय के शब्दों को दुहराते हुए कहना पड़ेगा कि 'अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान की भाँति नविष्पत्तियों या स्पष्टीकरण करने की शक्ति प्राप्त कर लेगी' यह आशा हम छोड़ देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विचारधाराओं का विकास अपने आप में एक क्रम रखता है। प्रारम्भ में विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के अध्ययन में इतना अधिक

महत्व नहीं दिया जाता था। थाम्पसन महोदय के कथनानुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चार विभिन्न स्तरों में होकर गुजरना पड़ा है।

सिद्धान्तों के विकास की चार सीढ़ियाँ (Four Steps of Theory Orientation)

थाम्पसन (Thompson) महोदय ने बतलाया है कि सबसे पहले स्तर में प्रथम विश्व युद्ध व उससे पहले इस क्षेत्र में किये गये अध्ययनों को समाहित किया जा सकता है। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कूटनीतिक इतिहास के रूप में लिखा जाता था। ऐतिहासिक अनुसंधान एवं प्रमाणों को अधिक महत्व दिया जाता था। घटनाओं का केवल वर्णन कर दिया जाता था, तथा इस बात को नहीं देखा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के सामान्य ढाँचे में वे किस प्रकार समायाजित होती हैं। घटनाओं के आधार पर सामान्य अथवा सार्वभौमिक सिद्धांत निकाले जा सकते हैं, यह विचार उस समय उपेक्षित था।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की दूसरी सीढ़ी दो विश्वयुद्धों के बीच के समय को माना जाता है। इस समय नवीन एवं तात्कालिक घटनाओं का अध्ययन करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। विचारक एवं अध्ययनकर्ता उन घटनाओं का तात्कालिक महत्व वर्णित करने में रुचि दिखाने लगे। युद्ध के बाद की समस्याओं की तुलना युद्ध से पूर्व ही उसी प्रकार की समस्याओं से की जाने की आदत को भुलाया जाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसा कोई स्थिर तथा सुनिश्चित आधार न रहा जिस पर वर्तमान काल की घटनाओं का इतिहास से संबंध जोड़ा जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में एक नया मोड़ तब आया जब उन्हें कानून और सङ्गठन के सहारे संस्थापक रूप देने का प्रयास किया जाने लगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना एवं शक्ति सन्तुलन के सिद्धांत के निरस्वार के साथ ही इस मान्यता को विशेष महत्व दिया जाने लगा। यह समझा जाने लगा कि विश्व संस्था बन जाने पर सभी समस्याओं और संघर्षों का स्वयं ही लोप हो जायेगा। इस प्रकार के विचारों ने विषयगत एवं बौद्धिक अध्ययन (Subjective and Rational Study) के विकास की धारा को प्रबल कर दिया। इस क्षेत्र में भावना एवं सुधारवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। इस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आशावाद तथा आदर्शवाद का बोलबाला था। बौद्धिक अनुसंधानों का मुख्य विषय अंतर्राष्ट्रीय कानून

तथा संगठन बना रहा। इसके प्रतिरिक्त इस समय अंतर्राष्ट्रीय सबंधों का अध्ययन करते समय अंतर्राष्ट्रीय सबंधों एवं नवीन उद्भावनाओं को नैतिकता की कसौटी पर कसा जाता था। एक सामान्य प्रवृत्ति इस काल के विचारकों की यह थी कि शांति एवं व्यवस्थापूर्ण विश्व की स्थापना के लिए ये विश्व सरकार की स्थापना में विश्वास करते थे। मार्गेंथो (Morgenthau, Hans, J) महोदय के दृष्टानुसार इस काल की विचारधाराओं का समय अंतर्राष्ट्रीय सबंधों की प्रवृत्ति को समझना नहीं था चरन् विवासशील कानूनी संस्थाओं व संगठनों से था। इस प्रकार तत्कालीन स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के प्रकारों को गौण बना दिया गया।

१९३० तक के अंतर्राष्ट्रीय सबंधों पर जिन विचारधाराओं का बोल-बाला था, उनमें वास्तविकता के कठोर सत्यो की अवहेलना करके विश्व सरकार, संगठन और कानून के महत्वपूर्ण प्रादशों पर जोर दिया गया। इस काल में किसी सुव्यवस्थित सामान्य सिद्धांत की उद्भावना का प्रयत्न ही नहीं उठा।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होने पर यह समझा जाने लगा कि अब विश्व एक प्रकार से कानून के प्रणीत हो गया है किंतु इस काल के अध्यापकों, शोध-कर्ताओं एवं कार्यकर्ताओं में अंतर्राष्ट्रीय सबंधों को देखने के दृष्टिकोण में अंतर आ गया। अब उनका दृष्टिकोण वैधानिक प्रणाली स्थापन होने की अपेक्षा राजनैतिक अधिक था। अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के अध्ययन की यह चोखी सीढ़ी है। इस काल में उन शक्तियों एवं प्रभावों का अध्ययन करना भी प्रारंभ हो गया जो राज्यों के वैदेशिक व्यवहार को प्रभावित एवं प्रभावित करते हैं। उन प्रवृत्तियों एवं साधनों को देखा जाने लगा जिनके द्वारा राज्य अपनी विदेश नीति का संचालन करता है। उन तरीकों एवं प्रक्रिया को खोजा जाने लगा जिनके द्वारा राष्ट्रो के मतभेदों एवं मनमुटावों को मिटाया अथवा समाधोजित किया जा सके।

इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सबंधों के अध्ययन का स्वरूप अब भावसंवाद न रहकर वास्तविकता के अधिक निकट आ गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक आदि तत्वों का भी अध्ययन किया जाने लगा। फिर भी राजनैतिक पहलू को महत्वपूर्ण माना गया। अंतर्राष्ट्रीय सबंधों पर एकीकृत सिद्धांतों (Integrated Theories) का निर्माण किया जाना प्रारंभ हो गया।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामान्य विचारधारा (General Theory in International Field)

सामान्य विचारधारा वह होती है जो समान परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर सभी देशों द्वारा अपनाई जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सामान्य सिद्धान्तों का परिमाण अधिक नहीं है। सम्भवतः इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों को सैद्धांतिक आधार पर समझना उतना समभव नहीं है जितना अन्य सामाजिक विज्ञानों में होता है। अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों के ऊपर समय-समय पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विचार प्रकट किये जाते हैं किंतु ये विचार इतने एक-पक्षीय तथा सीमित होते हैं कि इनके माध्यम से स्थिति के पूर्ण रूप को नहीं समझा जा सकता। इन एकपक्षीय सिद्धांतों में वह सामर्थ्य नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय सबंधों के वास्तविक व्यवहार का चित्र हमारे सामने रख सके। भूतकाल में इन सिद्धांतों का निर्माण एक विशेष हित रखने वाले समुदाय के लिए किया गया था जैसे सैनिक समुदाय, कूटनीतिज्ञ, न्यायिक (Jurist), शक्तिकारी राजनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी, साम्राज्यवादी, शक्तिवादी, शिल्पक तथा अन्य। किन्सी राइट के मतानुसार 'शक्तिकारी राजनीतिज्ञ के लिए रचे गये सिद्धांतों का शक्तिवादी व अन्तर्राष्ट्रीयतावादी लोगों के लिए कोई महत्व नहीं होगा। इन सिद्धांतों के निर्माता भी इतिहासकार, भूगोलशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, नीतिशास्त्री आदि थे। इन्होंने केवल विशेष तथा सकुचित दृष्टिकोण से ही वस्तुस्थिति को परखा और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सम्पूर्ण चित्र को अंकित करने में सफल न हो सके।

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सामान्य सिद्धान्त की आवश्यकता को कई दृष्टियों से स्वीकार किया जा रहा है। कहा जाता है कि सामान्य सिद्धान्त राजनीतिज्ञों की सहायता करेगा। जिन लोगों को विदेश नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेने होते हैं उनके पास प्रदर्शक के रूप में एक ऐसे सिद्धान्त का होना आवश्यक है जो उनके लक्ष्य तथा साधनों की समुचित व्याख्या कर सके। राजनीति अथवा निर्णयों के निर्माता (Decision maker) के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कूटनीतिज्ञों, सैनिकों, कानून वेत्ताओं, धर्म-शास्त्रियों, उपनिवेशीय प्रशासकों, अन्तर्राष्ट्रीय लोकसेवकों आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का कार्य है कि इन सभी को विशेषज्ञ परामर्श (Expert advice) प्रदान करे। इसके अतिरिक्त सामान्य सिद्धान्त (General Theory) का एक महत्वपूर्ण कार्य है नागरिकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का समुचित ज्ञान कराना। आज प्रजातन्त्र का

युग है तथा प्रत्येक व्यक्ति विदेश नीति के निर्णयों पर अपना प्रभाव डालना चाहता है। किन्तु कोई प्रभाव डालने से पूर्व आवश्यक है कि व्यक्ति को उक्त विषय का ज्ञान हो। सामान्य सिद्धान्तों का एक सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शोध कार्य को आसान बना देता है।

सामान्य सिद्धान्त का अर्थ व स्वरूप

सामान्य सिद्धान्त का अर्थ बताते हुए निम्नो राइट ने लिखा है कि यह ज्ञान का वह रूप है कि जो विस्तृत, समझने योग्य, सम्बद्ध तथा आत्म शोधक हो तथा साथ ही इससे जानकारी, मविष्यवाणी, मूल्योपान, विश्व के राज्यों के आपसी सम्बन्धों के तथा विश्व की परिस्थितियों के नियन्त्रण को कुछ योगदान मिल सके।¹ मि० राइट के विचारानुसार इन समस्त गुणों से युक्त सिद्धान्त को प्राप्त करना सर्वथा असम्भव है।

मि० राइट द्वारा दी गई उक्त परिभाषा में प्रकृति एवं उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य सिद्धान्त की जिन विशेषताओं की ओर निर्देश किया गया है वे निम्न प्रकार हैं—

सामान्य सिद्धान्त की प्रकृति एवं उद्देश्य

सामान्य सिद्धान्त में किसी एक विषय की ध्याख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए शक्तिपूर्ण एवं युद्ध-सम्बन्धी, सहकारिता पूर्ण व परस्पर विरोधी, सांविधिक तथा सैन्य, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इत्यादि। सामान्य सिद्धान्त उलझा हुआ व विस्तृत नहीं होना चाहिये। विस्तृत सिद्धान्त प्रायः उलझनपूर्ण होता है और उलझन के कारण वह अपने उन गुणों से वंचित रह जाता है जिनकी उससे भाषा की जाती है। यह ऐसे सामाजीकरणों में अभिषिक्त किया गया हो जो समझ में आने योग्य हों, संगठित हों तथा कम से कम हो। मूल बात को बड़ा-चड़ा कर कहने की अपेक्षा उसे उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया जाय। प्रत्यक्ष सत्त्व में कोई बार प्रसंगिता का कारण बन जाता है किन्तु फिर भी आवश्यकता से अधिक स्पष्टीकरण में विरोधाभास या असंगतियाँ पैदा होने का डर रहता है।)

1. Wright, Quincy, The study of International Relations, PP. 498 ff.

सामान्य सिद्धांत के निष्कर्ष एक तार्किक विश्लेषण के सहज व स्वाभाविक परिणाम होने चाहिए। इसका प्रत्येक भाग एक दूसरे से सम्बंधित तथा समायोजित हो तथा उनमें परस्पर विरोध न हो। इसके अतिरिक्त सामान्य सिद्धांत में स्वयं की कमियों को पूरा करने तथा स्वयं के दोषों को दूर करने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में किसी का यह सोचना गलत होगा कि उसके निष्कर्ष अन्तिम सत्य हैं तथा हमें गा ही रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि समय एवं परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ ही उनके रूप में यथोचित परिवर्तन कर दिये जाय।

सामान्य सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह जनता और राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में बहुत बाल पहले जन्मे हुए उन विचारों को सुरक्षित दे जिनका आज की परिस्थितियों में कोई महत्व नहीं रह गया है। इसके अध्ययन का रूप वस्तुगत (Objective) होना चाहिए क्योंकि सत्यता एवं तथ्यपूर्णता के लिए ऐसा होना जरूरी होता है। इस अर्थ में सामान्य सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वही कार्य है जो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में कापर्निकस ने किया था। सामान्य सिद्धांत को ऐसे मार्गों को प्रदर्शित करना चाहिए जिनमें भविष्य के शाश्वत तथा अध्ययनकर्ता अपने बड़ सके और इस क्षेत्र में अपना अनुदान प्रदान कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नवीन विचारों का स्वागत होना चाहिए क्योंकि वे भी उनमें ही मूल्यवान हैं जितने कि हमारे स्वयं के। नवीन विचारों के सदर्भ में यदि समय समय पर अपने मनों एवं धारणाओं को भी संशोधित कर लिया जाये तो उचित रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का दूसरा लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में भविष्यवाणी करने के कार्य को संभव बनाना है। इसके लिए यह जरूरी है कि कारण कार्य के सम्बन्ध को उचित रूप से बँटाया जाये। इसका स्वरूप वैज्ञानिक होना चाहिए। 'इन परिस्थितियों के होने पर यह कार्य होगा' अथवा 'ऐसा करिये ऐसा हो जायगा' आदि कहने की सामर्थ्य इनमें होनी चाहिए किंतु प्रायः यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में सम्भव नहीं हो पाता। इसके अनेक कारण हैं जैसे कि मानवीय व्यवहार एकसा नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तुलना नहीं की जा सकती, हम अपनी परिचल्पनाओं पर प्रयोग नहीं कर सकते आदि। फिर भी कुछ बातों पर कुछ मात्रा में भविष्यवाणी की जा सकती है और हमें अवश्य ही इस प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।¹

अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धांत का तीसरा सक्षय परिस्थिति का मूल्यांकन करना है। इसका यह कार्य है कि आवश्यकता के समय लोगों को केवल तथ्यों का ज्ञान कराने की प्रपेक्षा यह भी बताये कि उनके लिए भ्रष्टाचार क्या है। इसी धर्म में प्लेटो कहा करता था कि समय पर राजनीतिज्ञ को सज्जनतापूर्ण भूठ (Noble lies) भी बोल देनी चाहिए। इस दृष्टि से सत्य का मापदण्ड प्रमाण अथवा बुद्धि नहीं है बल्कि इसका व्यावहारिक प्रयोग है। हमें जनता से जो कराना है तथा जिन सिद्धान्तों को ग्रहण कराना है उनका उद्देश्य बताते समय कुटनीति से काम लेना आवश्यक बन जाता है। सामान्य जनता बालक-बुद्धि से काम करती है। यदि बालक से आप कहे कि 'वह अध्ययन में रुचि ले, इससे व्यक्तित्व का विकास होगा' तो इस कथन का व्यावहारिक प्रभाव इतना न होगा जितना कि यह कहने पर कि 'वह अध्ययन करेगा तो उसे मिठाई व खिलौने दिये जायेंगे।' यद्यपि दोनों परिस्थितियों में अध्ययन का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास ही है। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के अध्ययन का विषय है मनुष्य तथा उसके समुदाय। मनुष्यों के जीवन के कुछ मूल्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धान्तों को उन मूल्यों के समायोजन में ही अपने सक्षयों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए वरना मनुष्य जिन मूल्यों को महत्व देता है उनकी सुरक्षा के लिए यह सिद्धान्तों को तिलाजलि दे सकता है। कुछ विचारकों का मत है कि समाज विज्ञान शास्त्रियों को केवल तथ्यों व प्रमाणों से सम्बन्ध रखना चाहिए 'मूल्यों' से नहीं। किन्तु जैसा कि मि. राइट का मत है—सामाजिक विज्ञान 'मूल्यों' को अवहेलना नहीं कर सकते, यह तो इनका मूल सत्व होता है।

चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को यह बताना चाहिए कि क्या होने को है, यह बताना चाहिए कि क्या होना भ्रष्टाचार है तथा साथ ही सरकार व जनता को जो भ्रष्टाचार उसे बनाये रखने के लिए निर्णय लेने में सहायता देनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर सरकारें तब तक नियंत्रण नहीं रख सकती जब तक कि उन्हें साफ साफ यह पता न हो कि वे ऐसा क्यों करना चाहती हैं। कोई निरापेक्ष सेने से पूर्व हमारे सामने कुछ मूल्यों का रहना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार के मूल्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं।

पाचवें, अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण कार्य आज यह भी है कि विषम समुदाय की परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए वह प्रयास करे। आज का युग सम्प्रभु राष्ट्रीय राज्यों की स्थिति में परिवर्तन की मांग करता है। वह विश्व समाज तथा विश्व सरकार की स्थापना चाहता

है। सामान्य सिद्धांतों का यह कर्तव्य बन जाता है कि समय की इस आवश्यकता व युग की इस मांग को ध्यान में रख कर ही भागे बड़े।

ऊपर बताये गये उद्देश्य एवं तत्त्वों को अपने-प्राप में धारण करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत हो सकेगा ऐसी आशा नहीं है। उपर्युक्त सभी विशेषताएं एक आदर्श अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत का चित्रण करती हैं। सिद्धांत शास्त्रियों का यह प्रयास होना चाहिए कि वे अपने सिद्धांतों में इन विशेषताओं को अधिक से अधिक समाविष्ट कर सकें। कोई भी सिद्धांत इन विशेषताओं के जितना नजदीक होगा वह उतना ही उपयोगी, श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक माना जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के प्रकार (Types of International Theory)

जब से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन की ओर राजनीति के मनीषियों का ध्यान गया है तभी से इस क्षेत्र में सिद्धांतों की रचना का कार्य भी प्रारम्भ हो गया। शुरू में तो भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास आदि शास्त्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ चुने हुए विषयों का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का सकलन होने लगा। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का शुमारम्भ तब से माना जा सकता है जब से विचारकों ने सम्पूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में देखना प्रारम्भ किया है। जैसा कि किन्सी राइट (Quincy Wright) का मन है कि विश्व के सम्बन्ध में एक सामान्य धारणा का होना सिद्धांत-निर्माण के लिए अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि इसके माध्यम से ही तथ्यों का सकलन एवं सगठन किया जा सकता है। विश्व के सम्बन्ध में जिन ५ सामान्य धारणाओं को अब तक स्वीकार किया गया है वे किन्सी राइट (Quincy Wright) महाशय के अनुसार निम्न प्रकार हैं—

(१) विश्व एक विचार धारणा योजना के रूप में
(World as an Idea or Plan)

(२) विश्व : शक्ति सन्तुलन के रूप में
(World as Equilibrium or Balance of Power)

(३) विश्व : एक सगठन के रूप में
(World as an Organisation)

(४) विश्व समुदाय के रूप में

(World as a Community)

(५) विश्व : एक असलान क्षेत्र के रूप में

(World as an Uncommitted Field)

उक्त पाँच धारणायें काल-क्रम के अनुसार उस समय के विचारकों की प्रभावित करती रही हैं। प्रारम्भिक विचारक विश्व को ईश्वर का एक विचार मानते थे। उनका विश्वास था कि ससार एक नाटक की तरह है जिसका रचयिता एवं निर्देशक ईश्वर है। किस घटना के बाद वीनसी घटना अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर आनी चाहिए इसका निर्णय वही करेगा। बाद में बुद्धिवाद के उदय के साथ साथ यह माना जाने लगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दुनिया का निर्माण मनुष्य की बुद्धि से होता है। प्राकृतिक शक्तियों के बीच सन्तुलन का महत्व देख कर १७ वीं शताब्दी में लिसोलै (Lisola) तथा १८ वीं शताब्दी में डेविड ह्यूम (David Hume) द्वारा शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्तों की रचना की गई। तीसरी धारणा के अनुसार यह माना जाने लगा कि विश्व का ढाँचा पूर्ण निर्धारित नहीं है यह राजनीतिज्ञों की बुद्धि व जनता के मत (Opinion) के अनुसार घट्ठा या बुरा संगठित किया जा सकता है। चौथी धारणा में यह स्वीकार दिया गया कि विश्व के विभिन्न भाग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बंधे हुए हैं। विश्व के सभी मनुष्य पिता परमात्मा की सत्ता और इस प्रकार भाई भाई हैं। यह धारणा अनुभव की कसौटी पर सत्य न ठहर सके। पाँचवीं व अन्तिम धारणा विश्व को भलग-भलग क्षेत्रों (Fields) से युक्त मानती है। इस धारणा के प्राधार पर मि० राइट (Wright) ने पृथक से क्षेत्र सिद्धांत (Field Theory) की रचना की है अतः इसे विस्तार से देखना उपयोगी होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का क्षेत्र सिद्धांत

(The Field-Theory of International Relations)

इस सिद्धांत की विशद व्याख्या किंक्सी राइट (Quincy Wright) ने दी है।^१ यह सिद्धांत मानता है कि ससार विभिन्नताओं से पूर्ण है तथा अत्यन्त सश्लिष्ट (Complicated) है। एक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो

1. Quincy Wright: The Study of International Relations, Last chapter.

की मूल्य-व्यवस्था (Value System), सामाजिक संस्थाएँ (Social institutions) तथा सरकार के रूप (Forms of Govt) उनके अपने होने हैं जो दूसरे क्षेत्र में नहीं अपनाये जा सकते। इन क्षेत्रों में पाये जाने वाली मिश्रताओं को दूर करना न तो सम्भव है और न आवश्यक ही।

नीतियों को बनाने, निर्णयों को लेने तथा उनको व्यावहारिक रूप देने का काम किसी एक का नहीं होता। इस कार्य में राज्य, सरकार, राष्ट्र और जनता सभी का सहयोग रहता है। आवश्यक नहीं कि एक क्षेत्र की जनता का स्तर वही हो जो वहा सरकार का है। सरकार के अपने कुछ ऐसे मूल्य हो सकते हैं जो जनता के मूल्यों से भिन्न हों तथा जो उस देश की संस्कृति तथा राज्य के कानूनों में समाहित मूल्यों का प्रतिनिधित्व न कर सकें। इन दोनों मूल्यों के बीच संघर्ष होता है—देश में स्पष्टतः दो भाग बन जाते हैं। एक पक्ष में सरकार एवं प्रशासक रहते हैं और दूसरे पक्ष में जनता अथवा प्रशासित रहते हैं। यदि शासन व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक है तो जनता का पक्ष विजयी होगा और यदि तानाशाही है तो शासक या सरकार की मनमानी चलेगी अर्थात् जिसके हाथ में शक्ति है वह दूसरे के मूल्यों को कुचल देगा। क्षेत्र सिद्धांत वालों का दावा है कि उनका मिद्धांत दम दृष्टि से भ्रमलभन है और दूसरे सिद्धांत यह मानकर चलते हैं कि एक दिन सभी लोग एक प्रकार की विश्व व्यवस्था (World order) पर एकमत हो जायेंगे। क्षेत्र सिद्धांत यह मानता है कि एक 'क्षेत्र' (Field) है, जो हो सकता है भविष्य में सभी मतों (Opinions) के बीच एकता की षोड़ी बहुत स्थापना कर सके किन्तु अभी तो जैसे ही उसके कार्यों की व्यवस्था में तथा उनके आपसी सम्बन्धों में परिवर्तन होता है, इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। एक क्षेत्र के निवासियों के मूल्य, भावनाएँ एवं लक्ष्य आदि जब तक एक जैसे रहते हैं तब तक तो उनके मतों में भी सामंजस्यता रह सकती है किन्तु ज्यों ही उनके पारस्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन आता है त्यों ही उनके बीच मत भिन्नता भी स्थापित हो जाती है। हो सकता है कि 'क्षेत्र' भविष्य में एक समायोजित वैधानिक व्यवस्था बन जाये, एक स्थायी संतुलन या एक समर्थ संगठन बन जाये, या कोई सद्भावपूर्ण समुदाय बन जाये किन्तु सिद्धान्त इनमें से किसी को अपना लक्ष्य बना कर नहीं चलता। इस विचारधारा का उद्देश्य यह नहीं है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का दर्शन या उनके व्यवहार की कला का आदर्श (Model) प्रस्तुत करे किन्तु यह तो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास की व्याख्या करने अथवा उसे वैज्ञानिक रूप देने का प्रयास करती है।¹

1 Quincy Wright "Development of a general theory of International Relations," in the role of theory in International Relations, edited by Harrison, P. 40

प्रो० राइट का कहना है कि क्षेत्र सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत माना जा सकता है। साम्राज्यवादी युग में जिस विचारधारा का प्रभाव था; वह विश्व को एक योजना मान कर चलती थी। राष्ट्रीयतावाद के युग में आकर यह विचारधारा महत्वहीन बन गई तथा इसका स्थान शक्ति सन्तुलन को महत्व देने वाली विचारधारा ने ले लिया। अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के वर्तमान युग में शक्ति-सन्तुलन के विचार भी प्रसामयिक बन गये हैं और आज विश्व सगठन एवं विश्व सरकार की मान्यता को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रो० विन्स्टो राइट का विचार है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र सिद्धांत को अपना लिया गया तो यह कभी भी प्रसामयिक न बनेगा क्योंकि यह परिवर्तन का विरोध नहीं करता वरन् उसको मान कर चलता है तथा अनुकूल समायोजित होने का प्रयास करता है।

खेल तथा सौदेबाजी का सिद्धान्त (Games and Bargaining Theory)

इस सिद्धांत का प्रतिपादन तथा व्याख्या जिन तीन विद्वानों ने की है उनके नाम हैं—केपलन (Morton A. Kaplan), बर्न्स (Arthur Lee Burns) तथा क्वाउन्ट (Richard E. Quandt)। इन विद्वानों ने खेल सिद्धांत के आधार पर शक्ति सन्तुलन (Balance of Power) की सैद्धांतिक व्याख्या दी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इन विचारकों ने खेलों का माध्यम प्रयुक्त किया है। इस प्रणाली में अधिक समय, तथा शक्ति की आवश्यकता होती है, नहीं तो भवितव्य इसका काफी विकास हो गया होता।

यह सिद्धांत उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहते हैं, जो एक बौद्धिक सिद्धांत चाहते हैं, अथवा जो अपने विकल्पों की तुलनात्मक रूप से उपयोगिता देखना चाहते हैं। युद्ध कीमत के बारे में खेल सिद्धांत बहुत कुछ कहता है तथा एक व्यवस्थित रूप में कहता है। जहाँ यह सिद्धांत लागू हो जाता है वहाँ भूलें रहने की सम्भावना काफी कम हो जाती है। खेल सिद्धांत को यदि भण्डारी प्रकार समझ लिया जाय तो हम उन समस्याओं को भी जान सकते हैं जिन पर अभी खेल सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है।

एक खेल की भांति इस सिद्धांत में भी स्वयं के नियम (Rules), खिलाड़ी (Players), क्रियाएँ (Moves), युद्ध-कीमत (Strategies)

तथा शक्ति देना (Pay off) आदि होते हैं। यह खेल स्पर्धापूर्ण (Competitive) तथा सहकारितापूर्ण (Cooperative) दोनों ही प्रकार हो सकता है। खेल के संझौते पर विशेषण की इकड़ खिलाड़ी होता है। यह अभिनेता (Actor) होता है। अन्तर्राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ी दो भी हो सकते हैं तथा इससे अधिक भी। खिलाड़ी का अर्थ उससे है जो निर्णय लेता है। खिलाड़ी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए या प्रतिद्वन्द्वी की शक्ति को कम करने के लिए जिनसे संधिया करता है वे राष्ट्र खिलाड़ी नहीं माने जाते।

खेल के नियम होते हैं, इन नियमों के ऊपर खिलाड़ियों का बल नहीं रहता। जैसे शतरंज का नियम है कि पैदल मोहरा एक बार में एक या दो घर पार कर सकता है, इसी तरह अमरीकन शासन व्यवस्था में नियम है कि जिम स्मिथद्वारा को बहुमत प्राप्त हो जाय वही राष्ट्रपति बन जाता है। खेल निदान उन तत्वों को ध्यान में नहीं रखता जो अन्तर्राष्ट्रीय खेल पर प्रभाव नहीं रखते। खेल के नियम ही यह निर्णय करते हैं कि एक खिलाड़ी क्या बलम उठायेगा। अन्तर्राष्ट्रीय खेलों के सामाजिक नियम स्थिर होने की अपेक्षा सजीले होते हैं। जैसे कि 'शक्ति मनुष्य' के अनुसार यह धारा की जाती थी कि एक राष्ट्र उस पक्ष में नहीं मिलेगा जो पहले से ही शक्तिशाली है। किन्तु यह भी सम्भव है कि वह देश इसी पक्ष में मिल जाय।

सामान्य खेलों की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय सम्झौतों का खेल भी दो प्रकार का होता है—(१) जिसमें कि सभी विकल्पों तथा उनके परिणामों की सूचना खिलाड़ी को दे दी जाय। (२) जिसमें इस प्रकार की सूचना न दी जाय। सूचना पूरी तथा अपूर्ण दोनों ही प्रकार का हो सकती है। इस खेल में खिलाड़ी के सामने कुछ विकल्पों में से चुनाव करने की स्वतन्त्रता भी रहती है। एक बार डा० राधाकृष्णन् ने कहा था कि तांग के खेल में हमारे पास क्या पत्ते आयेंगे, यह हमारे अधिकार की बात नहीं है किन्तु जो पत्ते आयें हैं उनका प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे यह बहुत कुछ हमारी स्वतन्त्र निर्णय शक्ति पर आधारित है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ व स्थितियाँ किम करवट बँटती हैं यह एक राष्ट्र की शक्ति के बाहर की बात है किन्तु उन स्थितियों में यह किम विकल्प को चुनेगा यह उसी की दृष्टि पर है। एक विकल्प के चुनाव का परिणाम क्या होगा यह भी बहुत कुछ अनिश्चित हो जाता है क्योंकि 'परिणाम' पर दूसरे राष्ट्र द्वारा चुने गये विकल्पों का भी प्रभाव पड़ता है, जो अनिश्चित है।^१ खेल भी कई प्रकार के होते हैं जैसे—

1 Morton A Kaplan, System and Process in International Politics, P 174.

(१) Zero sum Games जिसमें कुछ खिलाड़ियों की हानियों (Losses) का अर्थ दूसरे खिलाड़ियों का लाभ (Gains) होता है।

(२) Constant Sum Games—इस खेल को समझने के लिए हम एक बाजार की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कुछ सामान एक निश्चित संख्या व कीमत में बिकते हैं। इस बाजार के प्रतिद्वन्द्वी जो लाभ प्राप्त करेंगे वह दूसरे को हानि देकर नहीं करेंगे। सभी को समान लाभ मिलेगा।

(३) Non Zero sum Games—यह खेल उक्त दोनों के बीच का है। इसमें प्रतिद्वन्द्वियों के बीच का संबंध सहयोगितापूर्ण भी रह सकता है और परस्पर विरोधी भी।

शक्ति के खेल का एक उदाहरण

(An Example of the Game of Power)

शक्ति का खेल विभिन्न राष्ट्रों द्वारा खेला जाता है। ये राष्ट्र एक मेज के चारों ओर बैठ जाते हैं और गोठियों के माध्यम से प्रतियोगिता करने लगते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के पास एक बोर्ड होता है। इस बोर्ड पर वे सीमाएँ प्रकट रहती हैं जिनका वह प्रत्येक अन्य प्रतियोगी के साथ हिस्सेदार है। साथ ही उसका स्वयं का प्रदेश भी प्रकट रहता है। गोठियाँ स्रोतों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिस देश के पास जितनी अधिक गोठियाँ हैं वह उतने ही अधिक स्रोतों का स्वामी माना जायेगा। कुछ गोठियाँ सुरक्षित सेनाओं (Reserved force) के रूप में भी रखी जा सकती हैं। जब इनको दूसरे देशों के विच्छेद सीमा पर लगा दिया जाता है तो ये विध्वंसक शक्ति के साथ बन जाती हैं। जिन स्रोतों को प्रयुक्त नहीं किया जाता अर्थात् जिनको न तो सीमाओं पर ही लगाया जाता है और न ही सुरक्षित सेना के रूप में रखा जाता है वे अनुरागिक भाषा में शायद कमाती हैं किन्तु यह अनुपात प्रत्येक बार अवसर के अनुसार बदलता रहता है।

चलने के लिये प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी बारी आनी है। यदि कोई चाहे तो वह अपनी बारी को छोड़ भी सकता है अथवा वह इसे स्वीकार करके अपनी शक्तियों को कार्यरत कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है या वापिस बुला सकता है अथवा जो सेनाएँ पहले से ही सीमा पर भेजी जा चुकी हैं उनके द्वारा युद्ध प्रारम्भ कर सकता है। यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाता है तो उस सीमा पर की गोठियाँ विरोधी पक्ष की गोठियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगी। प्रत्येक पक्ष उस समय तक गोठियों को सीमा पर भेजता रहेगा जब तक कि दूसरे पक्ष की सारी गोठियाँ समाप्त नहीं हो जायें। चलने की

नियमित बारी को उस समय तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक वह सपर्य भयवा युद्ध समाप्त न हो जाये भयवा जब तक किसी पक्ष के पास पुनः सेना भेजने तथा युद्ध को प्रारम्भ करने का अवसर है। इस खेल के खिलाड़ियों को यह विदित रहता है कि यह खेल या तो समाप्त होने तक खेला जायेगा भयवा कुछ विशेष बारियों के बाद समाप्त हो जायेगा। बारियों की सख्या गोटियों की सख्या पर निर्भर करती है।

सन्धि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में हो जानी है और जब सन्धि हो जानी है तो सम्बन्धित देश सामान्य सीमाओं पर से अपनी सेनाओं को हटा लेते हैं। जब एक देश दूसरे देश के विरुद्ध सीमा पर अपनी सेना को बढ़ाता जाता है तो वह दबाव डालने की स्थिति में हो जाता है। जिस देश का दबाव जितना अधिक होता है सीमा पर उसकी प्रभुता उतनी ही अधिक मानी जाती है।

शक्ति के इस खेल का उद्देश्य यह होता है कि खेल के अन्त तक यथा-सम्भव अधिक गोटिया प्राप्त की जायें। यदि खेल की समाप्ति के बाद एक खिलाड़ी के पास थोड़ी सी गोटिया ही बच जाती है तो वह एक हारा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। खेल से पूर्व ही खिलाड़ियों द्वारा जो मर्यादा तय कर दी गई थी, यदि उस मर्यादा से ही कम गोटिया किसी खिलाड़ी के पास बच पाती हैं तो उनको शून्य प्रदान किया जाता है तथा उनकी गोटियों को उन सभी खिलाड़ियों में बांट दिया जाता है जिनके पास कम से कम इतनी गोटियां हो जितनी के साथ उन्होंने खेलना प्रारम्भ किया है।

खिलाड़ियों द्वारा खेल प्रारम्भ करने से पूर्व ही यह तय कर लिया जाता है कि कितनी बारियों के बाद खेल की समाप्ति कर दिया जायेगा। जब दो से अधिक खिलाड़ी खेलते हैं और अपनी गोटियों से अधिक की मर्यादा तक की बारियों तक खेलते हैं तो वह खेल पर्याप्त उत्तेजक बन जाता है। खिलाड़ियों की मर्यादा जितनी कम होती है उनकी बारी घाने में उतना ही कम समय लगता है।

खेल के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में एक बड़े घाकार की मेज होनी चाहिए जिस पर दो २० x ३० इंच के दो नक्शे रखे जा सकें तथा उनके बीच कोई ऐसा प्रतिरोध लगाया जा सके कि खिलाड़ी एक दूसरे के नक्शों को तथा एक दूसरे के चेहरों को न देख सकें। उनका एक मानीटर होता है जो एक ही समय में दोनों नक्शों पर नजर रखता है। खिलाड़ी बैकल्पिक रूप से कमरे के दोनों ओर बंटाये जाते हैं। उनकी टेलीफोन पर

विचारों का आदान-प्रदान का अवसर दिया जाता है। जहाँ खेल व्यक्तियों की जगह टीम के बीच होता है वहाँ गोपनीयता की दृष्टि से दो कमरों की आवश्यकता होती है। यह खेल जिस रूप में खेला जाता है उसमें केवल कुछ घंटे ही लगते हैं। खिलाड़ी को खेल की तकनीक समझाने में ही लगभग एक घंटा व्यतीत हो जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी को ५२ सम्झा दिया जाता है कि वह सापेक्षिक रूप से अधिक नम्बर पाने के लिए नहीं बरन् सम्पूर्ण नम्बरों को पाने के लिए खेल रहा है। कुछ एक ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो खेल में विभिन्नता ला सकती हैं। उदाहरण के लिए 'राजरो' के मूल्य भ्रमण-भ्रमण हो सकते हैं। दो खिलाड़ियों की मूल्य व्यवस्था का पारस्परिक संबंध भ्रमण-भ्रमण हो सकता है। प्रत्येक खिलाड़ी को अपने प्रतिपक्षी के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त है उसकी मात्रा भी भ्रमण-भ्रमण हो सकती है। संचार व्यवस्था का रूप भ्रमण-भ्रमण हो सकता है। संचार व्यवस्था सीधी हो सकती है, यह प्रत्येक प्रकार की बात के लिए स्वतंत्र हो सकती है अथवा केवल कुछ प्रस्तावों एवं कथनों तक ही सीमित हो सकती है। इस प्रकार शक्ति के खेलों के बीच अनेक विभिन्नताएँ पाई जा सकती हैं।

ये खेल प्रायः उन सौदेबाजियों के प्रायोगिक अध्ययन होते हैं जो सीमित युद्ध अथवा अन्य सषर्णों में की जाती हैं। यह सौदेबाजी शब्दों के आधार पर की जाती है और कार्यों के आधार पर भी। इस सौदेबाजी में संचार व्यवस्था को कमजोर रखा जाता है, इसे कानूनी रूप में लागू करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। जब सौदेबाजी करने वाले भागीदार एक दूसरे से सम्पर्क करते हैं तो वे एक दूसरे के मूल्यांशों से प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं। वैसे उनके पास एक-दूसरे की नुकसान पहुँचाने के लिए पर्याप्त शक्ति रहती है। सौदेबाजी की इस स्थिति को खेल का रूप देकर उस पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान एवं सोचें की जाती हैं।

वर्तमान समय में प्रयोग के लिए जिन खेलों को अपनाया जाता है वे युद्ध के साथ सादृश्यता नहीं रखते। अनुसंधान हेतु आयोजित इन खेलों तथा परम्परागत युद्ध के खेलों के बीच अन्तर होता है। प्रथम अन्तर तो यह है कि प्रायः सभी युद्ध खेल पूर्ण रूप से जीरो-सम (Zero-Sum) खेल होते हैं। इनमें विरोधियों के साथ सहयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। विजेता केवल वही माना जाता है जो अपने प्रतिद्वन्दी को समाप्त कर सके अथवा उसका दबा सके। दूसरे, इस खेल को जो रूप दिया जाता है वह युद्ध जना नहीं होता। इसमें कम से कम तकनीकी जटिलता रहती है। इसे प्रशिक्षण की अपेक्षा शोध कार्य के लिए व्यवस्थित किया जाता है। इसका रूप अत्यन्त

सरल बनाया जाता है। इसमें सौदामनिक दृष्टि से मापन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि किया जा सकता है। कई बार खेल का आयोजन किया जा सके इसलिए इनको कम खर्चों पर बनाया जाता है। इसमें अधिक प्रसाधनों की आवश्यकता भी नहीं होती।

खेल सिद्धान्त की प्रक्रिया

(The Methodology of Game Theory)

प्रायोगिक खेल सिद्धान्त के द्वारा सौदेबाजी की प्रक्रिया का व्यावहारिक अध्ययन किया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि कोई भी औपचारिक सिद्धान्त या विचारधारा अपने आप में अपर्याप्त होती है। कम से कम सौदेबाजी के खेलों में यह आवश्यक रूप से अपर्याप्त होती है। इस प्रकार के खेलों में एक अनिश्चयता की मात्रा रहती है। खेल की मात्रात्मक बनावट द्वारा जो बाधाएँ प्रस्तुत की जाती हैं वे किसी भी मुझाव का निर्णय करने के लिए उसे अपर्याप्त बना देती हैं। यहाँ तब कि बुद्धिपूर्ण एवं आन्तरिक रूप से समायोजित पूर्ण खेल में भाग लेने वालों के व्यवहार की रणनीतियाँ भी कुछ उपयोगी नहीं बनतीं। इस प्रकार के किसी भी खेल में वस्तु स्थिति को समझने के लिए, अभिप्रायों को जानने एवं उनका अनुमान लगाने के लिए प्रत्येक की समायोजित आकांक्षाओं तक पहुँचने के लिए और एक भीमिष युद्ध में सीमा निर्धारित करने के लिए आवश्यक माध्यता, परम्परा एवं रोक विवसित करने के लिए कार्यों में एकीकरण की आवश्यकता होती है। एक खेल में भाग लेने वाले लोग एक दूसरे की आकांक्षाओं का ज्ञान कराने के लिए किम प्रकार की क्रिया-प्रतिक्रिया करेंगे, वे अपने अभिप्रायों को जानने के लिए बौद्धिक साधन अपनायेंगे तथा वे समुक्त रूप से जिन नियमों एवं परम्पराओं को जानेंगे तथा मानेंगे; ये सारी बातें पहले से ही तय नहीं की जा सकती। चाहे कोई खिलाड़ी कितना ही बौद्धिक क्यों न हो इनके बारे में पहले से ही कुछ तय नहीं कर सकता। खेल सिद्धांत में व्यावहारिक अध्ययन का आवश्यक उत्पन्न रहता है। बौद्धिक व्यवहार की विचारधारा द्वारा जो तरीका सुझाया जाता है उससे भिन्न रूप में भी एक खेल के खिलाड़ी व्यवहार कर सकते हैं। यह भिन्नता चुराई की अपेक्षा अच्युत की दिशा में भी अपसर हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में खिलाड़ी उससे भी अच्युत व्यवहार कर सकते हैं जैसा कि एक शुद्ध औपचारिक बौद्धिक व्यवहार की विचारधारा द्वारा सुझाया जाता है किन्तु ये खिलाड़ी अच्युत व्यवहार किस तरह कर सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका

सैद्धान्तिक विश्लेषण किया जा सकता है किन्तु अन्त में उसे व्यवहार के आधार पर ही प्रमाणित करना होता है। खेल सिद्धांत के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह किया जाता है कि इसके आधार पर हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं भयवा जिस वानावरण को देखते हैं क्या उसके आधार पर वास्तविक सघर्ष की स्थितियों का भयवा वास्तविक सीदेवाशी की प्रक्रियाओं का सामान्यीकरण किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि इस प्रकार का खेल वास्तविक सघर्ष को सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को सामने नहीं लाता। यह हमारे सामने कोई ऐसा मन्तुलित मॉडल नहीं रखता जिसमें सभी तत्वों का पर्याप्त महत्व प्राप्त हो। इसका मुख्य उद्देश्य समस्या के उन पहलुओं को सामने लाना है जो विश्लेषण के लिए सन्देह प्रदर्शित करते हैं भयवा प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों को सन्देह की नजर से देखने हैं। इस प्रकार के खेल द्वारा खिलाड़ियों की ज्ञान एवं सूचना सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जाता है, उनके भावनात्मक व्यवहार या व्यक्तिगत मूल्य व्यवस्था पर नहीं। जहाँ तक सम्भव होता है वहाँ तक खिलाड़ी की मूल्य व्यवस्था उसे खेल द्वारा ही प्रदान की जाती है। यदि हमारे रोकते हुए भी भावनात्मक पक्ष उभर आता है तो उसका स्तर उस मनमुटाव, जलन, ईर्ष्या आदि में मिश्र होता है जो वास्तविक सघर्ष एवं जीते जागते युद्ध की स्थिति में हो सकता है। इस प्रकार के खेल में व्यक्तियों के व्यवहारों एवं सगठनात्मक व्यवहार, नौकरशाही के व्यवहार सामूहिक राजनैतिक व्यवहार एवं अन्य संयुक्त निष्पन्न प्रक्रियाओं पर भाग लेने वाले व्यक्तियों की विशेषताओं एवं सामर्थ्य के द्वारा सीमाएँ लगाई जाती हैं।

इस प्रकार के खेल की इतनी सारी सीमाएँ होती हैं किन्तु फिर भी यह सीमित युद्ध तथा ऐसे साधनों के कुछ तत्वों को जानने के लिए एक प्राक्-पंक साधन प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास अनुभव-आत्मक रूप में वे वस्तु स्थिति का अध्ययन करने के लिए बहुत कम विकल्प हैं। खेल के आधार पर किए जाने वाले प्रयोगों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह यद्यपि पर्याप्त व्यापक या विश्वसनीय नहीं होता किन्तु दूसरे तरीकों से प्राप्त होने वाले ज्ञान की तुलना में यह अच्छा प्रतीत होता है। खेल सिद्धांत से प्राप्त निष्कर्षों या परिणामों का एक अन्य महत्व यह है कि यथार्थ जगत में भी वे कुछ उपयोगी सिद्ध होते हैं। सीमित युद्ध, औद्योगिक सघर्ष आदि के बारे में अनेक प्रस्ताव सामान्य रूप में रखे जाते हैं तथा उन्हें इतने सरल एवं सामान्य प्रमाणों या तर्कों पर आधारित किया जाता है कि वे उतनी सरल और बनावटी स्थिति पर लागू किये जा सकें जो खेल द्वारा

वर्णित की गई है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि यद्यपि खेल के निष्कर्षों की उपयोगिता एवं प्रमाणिकता सदिग्ध है, फिर भी किसी अन्य सिद्धान्त द्वारा इनको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रायोगिक खेलों की उपयोगिता को इस आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि हम सामान्य रूप से तर्क करने पर जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं उनको खेल की प्रक्रिया द्वारा असत्य मिट्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम खेल का आयोजन करते हैं। इस खेल में प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की मूल्य व्यवस्था के प्रति अनभिज्ञ है अथवा उसे यह जानकारी नहीं है कि दूसरे खिलाड़ी को चलने के कितने अवसर प्राप्त होंगे अथवा यह कितनी बार चल सकता है। ऐसी स्थिति में यदि हम यह प्रस्ताव करें कि प्रत्येक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी की मूल्य व्यवस्था का, उसकी चाल के अवसरों का तथा जितनी बार वह चल चुका है इसका ज्ञान करा दिया जाए तो दो खिलाड़ियों को इससे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? इस प्रश्न के सम्बन्ध में यदि बौद्धिक रूप से विचार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर आयोगे कि जिस खिलाड़ी को अपने विरोधी के सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त है, वह लाभ न रहेगा किन्तु जब हम इस बात को तर्कों के आधार पर नहीं बल्कि खेल के आधार पर जानने की चेष्टा करते हैं तो पाते हैं कि इससे दोनों ही खिलाड़ियों को लाभ हो सकता है अथवा दोनों को हानि हो सकती है। यदि वह खेल नान-जीरो-सम (Non-Zero-Sum) प्रकार का है तो प्रस्ताव को दूसरे रूप में रखा जा सकता है कि अन्य चीजें समान होने पर उस खिलाड़ी को अधिक प्राप्ति होगी अथवा अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा जिसे अपने विरोधी के सम्बन्ध में अधिक सूचना प्राप्त है। यह प्रस्ताव एक दोषपूर्ण तर्क प्रक्रिया पर आधारित है किन्तु यह बुद्धि-संगत प्रतीत होता है। यदि हम इसकी गलती को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो इसके लिए खेल का तरीका अपनाना होगा। जो लोग इस प्रकार के प्रस्ताव को मानते हैं उनकी मान्यता का आधार सामान्य गूँझ-गूँझ होती है। यह गूँझ-गूँझ इतनी सामान्य होती है कि यदि एक खेल द्वारा प्रस्ताव को दोषपूर्ण सिद्ध कर दिया गया तो इसमें विरोधाभास पैदा हो जाएगा।

इस उदाहरण के द्वारा खेल की प्रक्रिया का एक अन्य पहलू सामने आता है। खेल का प्रयोग इतना सरल होता है कि उसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके। जब यह खेल भाषा के विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है तो इन परिणामों से पीछे ऐसे कारण होते हैं जिनको आसानी से समझा जा सकता है। प्रयोगात्मक खेल द्वारा जिस निष्कर्ष पर पहुँचा

जाता है उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि हर बार सेते जाने वाले खेलों द्वारा उसका समर्थन किया जाए। जब एक बार प्रयोगात्मक खेल द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच गए तो उस निष्कर्ष का सैद्धांतिक रूप में बौद्धिकीकरण कर देना चाहिए। इस प्रकार प्रयोगात्मक खेल सैद्धांतिक मॉडल का एक दिखाई देने वाला प्रतिनिधित्व है। यह मॉडल ऐसा होता है जिसके सक्रिय भागों को उस समय अच्छी तरह समझा जाता है जबकि उनको प्रायोगिक रूप से प्रदान किया जाए।

इसी बात को अन्य रूप से भी स्पष्ट किया जा सकता है। प्रयोगात्मक खेलों का प्रयोग उन महत्वपूर्ण सम्भावनाओं को खोजने एवं प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है जो अन्य प्रकार से सामन नहीं आती। इन सम्भावनाओं का महत्व एवं उपयोगिता तार्किक रूप से प्रपचा कहीं भीर से प्राप्त प्रमाणों के आधार पर सिद्ध की जा सकती है किन्तु इन सम्भवनाओं का अस्तित्व है तथा ये सम्भावनाएँ अन्य भागों से किस प्रकार सम्बन्धित हैं, यह बात केवल प्रयोगात्मक खेल द्वारा ही खोजी जा सकती है। उदाहरण के लिये एक सम्भावना यह है कि अधिक ज्ञान भीर सूचना रखने वाले खिलाड़ी को लाभ प्राप्त न हो और अन्य खिलाड़ी को प्राप्त हो जाए जिसे इतना सूचना और ज्ञान प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि नई सूचना प्राप्त करने पर एक खिलाड़ी को लाभ होने की अपेक्षा उलटा नुकसान हो जाए यदि उसने इस तथ्य को नहीं धुपाया कि उसे वह सूचना प्राप्त है।

कुल मिलाकर यह आशा की जाती है कि इस प्रकार के प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा प्राप्त किये गये निष्कर्ष साक्ष्यिकीय विश्लेषण पर आधारित नहीं होंगे। हमारा अभिप्राय यह रहता है कि परीक्षण किये गये वातावरण को किसी सिद्धांत से सम्बन्धित करें तथा साथ ही निरीक्षण किये जाने वाले तत्वों के सम्भावित महत्व को प्रदर्शित करें। प्रयोगात्मक खेल में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि खेल की बनावट सम्बन्धी विशेषताओं को किस प्रकार रखा जाये कि उनके द्वारा कुछ विशेष परिणाम एवं वातावरण प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार प्रयोगात्मक खेल के आयोजन में हमारा उद्देश्य यह नहीं होता कि पूर्ण निर्धारित निष्कर्षों की प्रमाणीकृता को जांचे तथा उसके लिए साक्ष्यिकी प्रमाण प्रस्तुत करें। इसके स्थान पर परीक्षित परिणामों एवं प्रयोगों के आयामों रूपों के बीच निरन्तर सम्पर्क बना रहता है।

इस प्रकार के प्रयोगों का एक अन्य गीण उद्देश्य भी होता है। यह भी सिद्धांत के विकास से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार के खेल का आयो-

जन करने के लिए तथा खेल में कुछ विशेषताओं को खाने के लिए पहले व्यावहारिक मान्यताओं को परिभाषित करना जरूरी होता है। इस प्रकार का खेल सैद्धांतिक मॉडल-निर्माण पर अनुगमन कायम करता है। उसके द्वारा यह जांच की जा सकती है कि मान्यताएँ एवं प्रस्ताव अर्थपूर्ण हैं अथवा नहीं। यदि वे अर्थपूर्ण हों तो उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रयोगात्मक खेल को सैद्धांतिक संचार (Theoretical Communication) के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि हम यह चाहते हैं कि मंचों की रण नीति के बारे में किसी प्रस्ताव को सावधानी के साथ परिभाषित करें और चित्रित करें तो इसके लिए खेल के रूप में हमें एक दर्शनीय मापन प्राप्त हो जाता है।

खेल सिद्धान्त द्वारा अनुगमन

(The Research Through Game Theory)

खेल विज्ञान के आधार पर किए जाने वाले अनुगमन में हमको तीन बातों का ध्यान रखना होता है। प्रथम, यह देखना होता है कि जिन नियमों एवं प्रतिस्पर्धों के अधीन खेल खेला जायेगा तथा इस खेल की पृष्ठभूमि क्या है और खेलने वाले लोग कौन कौन हैं। दूसरे, देखने योग्य बात यह होती है कि खेल का परिणाम क्या रहा, विवादियों का व्यवहार क्या रहा, विवादियों द्वारा जो प्रतिक्रियाएँ रले गये वे क्या थे, खेल के दौरान जो विशेष परिस्थितियाँ विकसित हुईं वे कौन-कौन सी थीं आदि-आदि। तीसरे, यह देखना होता है कि वे प्रश्न या परिवर्तनाएँ कौन-कौन सी हैं जिनके आधार पर जांच को निर्देशित किया जा सकता है।

प्रथम शीर्षक के अधीन बहुत सीका निश्चित किया जाता है जिसके द्वारा खेल खेला जायेगा। इस तरीके को एक निश्चित रूप में प्रवर्णित किया जाता है। सर्वप्रथम तो अनेक खिलाड़ियों में युक्त खेल का एक मान्य रूप प्रयुक्त किया जाता है। इसके आधार पर विवादी भाग खेल के परिणामों एवं खेल के रूप के बीच पारस्परिक सम्बन्ध एवं खेलने वाले की अपनी व्याख्या के परिणामों एवं एक दूसरे के खेल के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से परिणामों के वर्गीकरण एवं विशेषण के लिये, खेल के तरीकों एवं रण नीतियों के लिये तथा खेलने वालों की व्याख्याओं के लिये सैद्धांतिक रूप रखना करनी होती है। यह सब केवल तभी किया जा सकता है जबकि मंचों में खेल खेला जाये। दूसरे, खेल की कुछ विशेषताओं में निम्नता हो सकती है। उदाहरण के लिये संचार की

व्यवस्था, सूचना की व्यवस्था आदि में मिश्रता हो सकती है। इसके प्रतिरिक्त खेल में प्रयुक्त किये जाने वाले नक्शे, परम्पराएँ, ढाल एवं इसके लक्ष्य का वर्णन करने वाली भाषा, खेल की मात्रात्मक विशेषताएँ आदि भी अलग-अलग प्रकार की हो सकती हैं। तीसरे, खेलने वालों के आधार पर अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था की जायेगी। आरम्भ-पूरित समूहों के बीच के खेल के लिए, विभिन्न समूहों के उन सदस्यों के बीच खेल के लिए जो पहले से ही अन्तर्समूह खेल का अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, अनुभवी खिलाड़ियों के बीच होने वाले खेल के लिए, अनुभवी एवं गैर अनुभवी के बीच होने वाले खेल के लिये तथा इसी प्रकार के अन्य खेलों के लिए व्यवस्था अलग-अलग प्रकार से करनी होती है। कुछ खेल मध्यस्थ के प्रभाव के अधीन खेले जाते हैं जो खेलने वालों को कुछ सुझाव दे सकता है। कुछ खेलों में तीन या तीन से अधिक खेलने वाले होते हैं; वहाँ सविद व्यवहार (Coalition behaviour) सम्भव होता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें रण नीति एक खिलाड़ी को पहले से ही स्पष्ट कर दी जाती है।

दूसरे शीर्षक के अधीन खेल के परिणामों का अभिलेख रखने की एक पर्याप्त योजना अपनायी जाती है। इस योजना में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त सभी अङ्कों को रखा जा सकता है अथवा सापेक्षिक रूप से रखा जा सकता है। खेल के विभिन्न प्रकारों के परिणामों की तुलना करने के लिये प्राप्त अङ्कों को साधारण स्तर पर रखने हेतु प्रयास करना होता है। ऐसा करना सरल नहीं होता क्योंकि इसका मार्ग सरल नहीं होता। उदाहरण के लिए यह जानना बड़ा कठिन होता है कि खेलने वाले ने खेल के दौरान क्या भाषा की थी और उसे उसके अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए या नहीं हुए। खेलने वाले की व्याख्याओं को वर्गीकृत करने के लिए भी एक योजना अपनायी जाती है। खेलने वाले खेल को जिस रूप में देखने हैं तथा खेल का जा तरीका अपनाते हैं उस पर उनकी प्रदान किये गये निर्देशों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है एवं उन प्रश्नावलियों का प्रभाव पड़ता है जो वे बनाते हैं। इसके प्रतिरिक्त वे अपनी एवं अपने मागीदार के खेल तथा रण-नीतियों पर जो बातें नोट करते हैं, वे भी प्रभाव डालती हैं। खेल के सम्बन्ध में अभिलेख रखना जरूरी है क्योंकि इसके बिना कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया जा सकता। अनुसंधान करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य जानकारी एवं गैर-जानकारी के विकास को देखना, प्रस्तावों को प्रसारित करने के लिए भाषा के प्राविण्यकार की प्रक्रिया को जानना तथा खेल के दौरान आलोचनात्मक अवसरों को ध्यान में रखना होता है। यह भी देखा जाता है कि खेलने वाले की भाषाओं का खेल में सुझाये गये विस्तारों से क्या सम्बन्ध था तथा खेलने वाले की रणनीति

कितनी सही थी। पर्याप्त भूत और सुधार के बाद ही हम यह जान पाते हैं कि रोचक एवं उपयोगी अभिलेख किस प्रकार रखा जा सकता है।

जिस समय खेल हो रहा है उस समय उसे किस प्रकार देखना चाहिए तथा उसका अभिलेख किस प्रकार रखना चाहिए इसके लिए विश्लेषणात्मक श्रेणियाँ प्रदाननी होती हैं। अभिलेख एवं निरीक्षण की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं, जैसे—सहयोगपूर्ण, बनाव असहयोगपूर्ण, भ्रात्रमणकारी बनाव बुद्धिपूर्ण आदि-आदि। ये अन्तर वास्तविक व्यवहार में उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं और नहीं भी, इसलिये ये निश्चय ही अपर्याप्त हैं। यह भी देखना होता है कि क्या तिलाठी, उसका दूसरा भागीदार एवं खेल देखने वाला खेल के तरीकों के सम्बन्ध में एक जैसी धारणा रखते हैं और क्या इसके पीछे उनका अभिप्राय एक जैसा ही है।

तीसरे, खेल का निरीक्षण करने के बाद उसके सम्बन्ध में कुछ जाँच पड़ताल की जाती है। जिस विशेष वस्तु स्थिति की जाँच होती है उसमें भाषा, नियमों एवं परम्पराओं का विकास आता है। उन तत्वों की विशेष रूप से जाँच की जाती है जो अस्थिरता के कारण बनते हैं। अस्थिरता से यहाँ हमारा अर्थ खेल की उस प्रवृत्ति से है जो विध्वसात्मक व्यवहार एवं कम अङ्कों का कारण होती है। प्रयोगों के आधार पर यह बात सामने आई है कि जब नक्शे पर राज्यों के मूल्यों को पुनः प्रभावित किया जाता है तो अधिक संघर्ष पैदा हो जाता है। यदि चाल में किये जाने वाले परिवर्तन से समझौता तोड़ने वाले किसी तिलाठी को भारी लाभ प्राप्त हो जाये तो इसमें अस्थिरता आ जाती है। इसके अतिरिक्त खेल का स्वभाव (Tempo) भी स्थायित्व पर प्रभाव डालता है। खेल की विश्लेषणात्मक रूप रखना करने के लिए पर्याप्त भूत और सुधार से काम लेना होता है। प्रयोगात्मक खेल का लक्ष्य यह नहीं होता कि स्मित परिवर्तनाओं की सत्यता को परखा जाय वरन् इसके द्वारा नवीन परिवर्तनाएँ बनायी जाती हैं।

सोदेबाजी की विचारधारा बहुत कुछ रुढ़िवादी खेल सिद्धांत का एक प्रसार है। दोनों के तरीके प्रायः एक जैसे हैं तथा दोनों की मूल मान्यताएँ एक जैसी ही हैं। जे सी हरसान्घी ने इन सिद्धांतों की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। उनके मतानुसार बौद्धिकता की दो मान्यताएँ हैं जो भौतिक हाते हुए भी कमजोर हैं इसलिये इन मान्यताओं के साथ अन्य चार को जोड़ दिया जाता है। हरसान्घी (J C Harsanyi), मज़्गनय के बयानानुसार ये छः बौद्धिक मान्यताएँ हैं—

- (१) व्यक्तिगत योग्यता का अधिकार (Individual Utility Maximization);
- (२) कार्यकुशलता (Efficiency);
- (३) उच्च क्षतिपूर्ति की स्वीकृति (Acceptance of Higher Pay off),
- (४) सममिति (Symmetry);
- (५) परिवर्तनियों का प्रतिबन्ध (Restriction of Variables) तथा
- (६) पारस्परिक रूप से आशान्वित बौद्धिकता (Mutually expected Rationality) ।

इन मान्यताओं के बीच कितना तार्किक सम्बन्ध है, यह एक विवाद का विषय है ।

खेल सिद्धांत का मूल्यांकन (Evaluation of Game Theory)

खेल सिद्धांत का व्यावहारिक दृष्टि से अत्यन्त महत्व है । यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को समझने के लिए केवल बौद्धिक चिंतन की परिधियों में सीमित रहने की स्थिति से विचारकों को बाहर निकालता है तथा उनको व्यावहारिक निरीक्षण के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान करता है । इसके मुख्य उपयोग निम्न प्रकार हैं—

(१) जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित हो गई तो इन गुटों के बीच बहुत कुछ ऐसा ही खेल खेला गया था जैसा कि खेल सिद्धांत के प्रयोगों में खेला जाता है । नाटो शक्तियाँ, साम्यवादी शक्तियाँ एवं असलान शक्तियाँ—ये इस खेल के तीन खिलाड़ी थे । यदि इस खेल का विश्लेषण किया जाये तो हमें अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होंगी जिनको बाद में हम संख्यात्मक मॉडल के रूप का आधार बना सकते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धान्त को महत्वपूर्ण मानने वालों का यह दावा है कि जितनी सूचना तथ्यपूर्ण रूप में एक खेल से प्राप्त हो सकती है वह साहित्यिक विश्लेषण द्वारा कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । साहित्यिक विश्लेषण से प्राप्त सूचना को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता ।

(२) खेल सिद्धान्त की यह विशेषता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय घटना का इसके आधार पर विश्लेषण करने के बाद दूसरी अन्य घटनाओं को समझने का मार्ग आसान बन जाता है।

(३) यह सिद्धान्त अनुभव पर आधारित (Empirical) है; इस कारण इसमें भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं, समस्या के लिए समाधान ढूँढ़े जा सकते हैं।

उक्त तर्कों का वर्णन करने हुए भी खेल सिद्धान्त के समर्थक यह स्वीकार करते हैं कि विश्व के रंगमंच पर स्थित सश्लिष्ट समस्याओं पर अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। दूसरे कुछ विचारकों द्वारा खेल सिद्धान्त को ऐसी ही दृष्टि से देखा जाता है जैसे कि वे एक खेल को देखते हैं अर्थात् विद्वानों के बीच यह सिद्धान्त कोई गम्भीर समर्थन प्राप्त नहीं कर सका। अधिकांश के विचार से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ जो गम्भीर, सश्लिष्ट तथा उसभी हुई होती हैं, इस सिद्धांत द्वारा नहीं समझी जा सकती। जैसा कि विन्सी राइट (Quincy Wright) का विचार है यदि हम भीत युद्ध का विश्लेषण इस सिद्धान्त के आधार पर करें और तब अपने देश की विदेश नीति का निर्धारण करें तो वह नीति न तो विजय प्राप्त करा सकेगी और न ही हमें निरक्षर रख सकेगी वरन् यह तो पूरी देश की हत्या का कारण बन जायेगी, ऐसी हत्या जिसे उसने स्वयं ही चुना है।

खेल सिद्धांत अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने तथा उनका समाधान करने का एक अपूर्ण माध्यम है। इसमें समय तथा शक्ति इतनी बरबाद होती है कि उनकी तुलना में इससे प्राप्त होने वाले परिणाम नगण्य रह जाते हैं। इस सिद्धान्त की अपनी कुछ समस्याएँ भी हैं जिनके कारण इसे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में लागू नहीं किया जा सकता। इसे वैज्ञानिक कहने को भी अनेक विद्वान तैयार नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त (A Realistic Theory of International Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्तों की रचना के दो तरीके हो सकते हैं जो परस्पर विरोधी हैं। पहले तरीके के अनुसार सिद्धान्त शास्त्री कुछ मान्यताओं के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की जांच करता है। अपनी निर्धारित कसौटियों के तहत अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को इस तरह बहुत कुछ निष्कर्षों पर आता है तथा इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की रचना

करता है किन्तु आलोचकों द्वारा इस तरीके को अत्यधिक घोषित करके इसकी भ्रष्टता की जाती है। इसे पूर्व कल्पित प्रमूल सिद्धांतों एवं मान्यताओं पर आधारित माना जाता है जिसका वास्तविक जगत की घटनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं होता। सिद्धान्त रचना का दूसरा तरीका पूर्ण रूप से तथ्यों एवं विश्व की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस तरीके में अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को दो शाखों में से निकलना पड़ता है—पहला है अनुभववादी (Empirical) तथा दूसरा है तार्किक (Logical)। किसी भी सिद्धान्त के तथ्यों का उनके वास्तविक स्वरूप में ही अध्ययन करना चाहिए तथा उस अध्ययन के बाद जो तर्क समुचित निष्कर्ष प्राप्त हो, उन्हीं को सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया जाय। इस प्रकार का सिद्धान्त यथार्थता के गुण से परिपूर्ण होगा। इसमें पूर्ण मान्यताओं को तथा अमूर्त आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया जायगा। इस प्रकार का सिद्धान्त यथार्थवादी सिद्धांत (Realistic Theory) कहा जाता है। ऐसा सिद्धान्त तथ्यों के साथ एकरूप (Consistent) होता है। मॉर्गेंथौ (Morgenthau) महाशय ने इस सिद्धांत को ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए उपयुक्त माना है।

मनुष्य, समाज तथा राजनीति के सम्बन्ध में यथार्थवादी सिद्धांत की अपनी स्वयं की माध्यम्यता है। इसका विश्वास है कि बौद्धिक दृष्टि से अपूर्ण यह ससार उन शक्तियों का परिणाम है जो मनुष्य की प्रकृति में पाई जाती हैं। यदि आप विश्व का सुधार करना चाहते हैं तो इन शक्तियों के साथ मिल कर आपको काम करना होगा। इस ससार में परस्पर विरोधी अनेक स्वार्थ वर्तमान हैं; इनके बीच सदैव संघर्ष होता रहता है। स्वार्थों के बीच संतुलन की स्थापना करके इस संघर्ष को कुछ अस्थायी समय के लिए दबाया जा सकता है। इस अपूर्ण ससार में नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से कभी नहीं अपनाया जा सकता। इस प्रकार अवरुध तथा संतुलन (Checks and balances) ही एक सार्वभौम सिद्धांत है जो सभी बहुलवादी समाजों पर लागू होता है। यह सिद्धांत प्रमूल मान्यताओं के स्थान पर ऐतिहासिक घटनाओं की अपनी आधार बनाता है। इसका उद्देश्य पूर्ण श्रम को प्राप्त करना नहीं है क्योंकि वह तो प्राप्त ही नहीं हो सकता, यह तो केवल कम बुराई को ही ग्रहण करना चाहता है। जैसा कि मार्गेंथौ का कहना है, यह सिद्धान्त मनुष्य की प्रकृति को उसी रूप में देखता है जैसी कि वह है, तथा ऐतिहासिक प्रतिक्रियाओं को उसी रूप में लेता है जिस रूप में कि वे प्रकट हुई थीं। इन कारणों से ही इस सिद्धान्त को 'यथार्थवादी' (Realist) की सजा प्रदान की जाती है।¹ इस सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर घीरे-

धीरे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता जा रहा है। किसी भी देश की विदेश नीति की सबसे बड़ी आलोचना यह हो सकती है कि वह नीति यथार्थवादा (Realistic) नहीं है।

यथार्थवादी सिद्धांत के तत्व

(Elements of Realist Theory)

कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो किसी देश की विदेश नीति को यथार्थवादी बनाते हैं तथा जिनका अभाव होने पर उस देश की विदेश नीति को आलोचकों के करारें प्रहार करने को मजबूर होना पड़ता है। इन तत्वों को हम यथार्थवाद का स्वरूप अथवा उसकी विशेषतायें भी कह सकते हैं। ये विशेषतायें निम्न प्रकार हैं—

(१) यथार्थवादी सिद्धान्त बौद्धिक है (Realistic theory is Rational)—यह सिद्धान्त मानवीय व्यवहारों की बौद्धिक व्याख्या करता है। यह उन वस्तुगत कानूनों (Objective laws) की खोज करता है जिनके आधार पर समस्त राजनीति संचालित होती है। इन कानूनों की जड़ें मानवीय प्रवृत्ति में होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में किसी प्रकार का सुधार करने का प्रयास करने से पूर्व इन कानूनों को समझ लेना परम आवश्यक होता है। यथार्थवाद में एक बौद्धिक सिद्धान्त की रचना की जाती है जिसके आधार पर इन वस्तुगत कानूनों का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। वैसे यह ज्ञान पूर्ण एवं समग्र नहीं हो सकता। इस विचारधारा के अनुसार 'सत्य' वस्तुगत एवं बौद्धिक होता है। यह प्रमाणों द्वारा समर्थित एवं बुद्धि द्वारा ग्राह्य होता है। मत (Opinion) को कभी भी सत्य (Truth) नहीं मानना चाहिए। यदि अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त को आप 'सत्य' बनाना चाहते हैं तो उसको बुद्धि और अनुभव—इन दो मापदण्डों पर बसना चाहिए।

हम तथ्यों का संकलन तथा परीक्षण तो करना है किन्तु केवल यही पर्याप्त नहीं है। इनकी बौद्धिक व्याख्या करके इनको भ्रम प्रदान करना भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए माना कि आप एक राजनीतिज्ञ हैं। कुछ विशय परिस्थितियों के कारण आपको सामने विदेश नीति से सम्बन्धित कुछ समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। अब आप यह देखिये कि इन्हीं परिस्थितियों में इसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर भूतकालीन राजनीतिज्ञ के सामने कौन-कौन से बुद्धिसंगत विकल्प थे तथा इन बुद्धिसंगत विकल्पों में से इन परिस्थितियों में कौन-कौन से विकल्प चुने जा चुके हैं। इस प्रकार एक तथ्य का बौद्धिक विश्लेषण करने के बाद हम उसे कुछ भ्रम

प्रदान कर सकते हैं और इस प्रकार एक सिद्धान्त की रचना को संभव बना सकते हैं।

(२) शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाओं का मुख्य प्रेरक है (Concept of interest defined in terms of Power is main signpost)—यथार्थवादी यह मानते हैं कि शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ (अर्थात् अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना ही राष्ट्रीय स्वार्थ है) एक ऐसा स्तर है जो राजनैतिक तथ्यों के बीच एक विभाजन रेखा खींचता है। जो तथ्य शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ से प्रभावित होते हैं वे राजनैतिक हैं और जो प्रभावित नहीं हैं वे राजनैतिक नहीं हैं। हम उनका नैतिक, धार्मिक या मानवीय आदि और कुछ भी कह सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त का निर्माण करने के लिए तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण करने के बाद हमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए उनकी बौद्धिक व्याख्या करनी होगी किन्तु यह बौद्धिक व्याख्या किस दृष्टि से की जाय इसका जवाब हमें शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ की मान्यता से प्राप्त होता है। यह मान्यता ही वह आधार है जिसके विरुद्ध या उदासीन होने पर एक कार्य गलत ठहराया जा सकता है तथा जिसके पक्ष में या सहायक होने पर उसे यथार्थवादी कहा जा सकता है।

इतिहास के उदाहरणों की दृष्टि पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ 'शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ' की दिशा में ही सोचता है व कार्य करता है। इस आधार पर हम यह मान सकते हैं कि राजनैतिक रगमच पर राजनीतिज्ञों द्वारा जो कुछ कदम उठाये गये, उठाये जा रहे हैं या उठाये जाएंगे वे 'स्वार्थ' (Interest) की प्राप्ति की दिशा में ही होंगे। राजनीतिज्ञ जो भी बोलता है, सोचता है अथवा लिखता है उसको समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह सब करते समय हमका उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना है। इसी दृष्टि से हम उसकी क्रियाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। 'शक्ति के रूप में परिभाषित स्वार्थ' के आधार पर ही हम अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को सिद्धान्तिक रूप प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि एक देश की विदेश नीति के मूल तत्व प्रायः एक से ही रहते हैं। यद्यपि समय-समय पर उस देश के राजनीतिज्ञों का बौद्धिक स्तर, चक्षुष्य, प्राथमिकताएँ तथा नैतिक गुण भिन्न होते हैं। इस दृष्टि से एक यथार्थवादी सिद्धान्त को अपने आपको दो भ्रमों से बचाये रखना चाहिए वे हैं—मनिस्राय (Motives) तथा वैचारिक प्राथमिकताएँ (Ideological preferences)। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति विशेष

मे एक देश क्या कदम उठायेगा यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसके अभिप्राय (Motives) क्या हैं वह किम विचारधारा (Ideology) को अधिक महत्व देता है। वह देश केवल वही कदम उठायेगा जो शक्ति के रूप में परिभाषित उसके स्वार्थ के अनुरूप होगा।

(३) यथार्थवादी सिद्धान्त अभिप्रायों की अपेक्षा परिणामों को देखता है (The Realistic Theory stresses upon results than Motives) — राजनीतिज्ञ का अभिप्राय देख कर ही यदि आप एक देश की विदेश-नीति को समझने का प्रयास करेंगे तो, आप असफल रहेंगे और धोखा-साधेंगे। अभिप्राय (Motives) एक ऐसी मनोवैज्ञानिक चीज है जिसका रूप कर्ता एव दर्शक दोनों के स्वार्थों एवं भावनाओं से प्रभावित होता रहता है। हम स्वयं अपने ही अभिप्रायों को समझने में भूल कर जाते हैं दूसरों की तो बात ही क्या है।

केवल अच्छे अभिप्रायों (Motives) के आधार पर हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि एक राजनीतिज्ञ की विदेश नीति नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय तथा, राजनैतिक दृष्टि से सफल रहेगी। विश्व शांति एवं आतुरता की भावना का उद्देश्य लेकर चलने वाला नेहरू की विदेश नीति को यथार्थवादी कह कर भालोचना का विषय बनाया जाता है। इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण वह है जो किसी कार्य का नैतिक एवं राजनैतिक स्तर उसके अभिप्रायों में नहीं बल्कि उसके परिणामों में देखता है। नेवाइल चेम्बरलेन की सतुष्टीकरण की नीति का उद्देश्य या विश्व में शान्ति बनाये रखना, किन्तु आज का विद्यार्थी जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का अध्ययन करता है तो उसमें यह नीति भी उसके अध्ययन का विषय बन जाती है। दूसरी ओर चर्चिल (Winston Churchill) की विदेश नीति मानव कल्याण की अपेक्षा सजुचित स्वार्थ का अभिप्राय (Motive) लेकर चली थी किन्तु उसके जो परिणाम हुए वे चेम्बरलेन (Nevill Chamberlain) की अपेक्षा नैतिक एवं राजनैतिक दृष्टि से ऊँचे स्तर के थे। एक राजनैतिक सिद्धांत को राजनीतिज्ञ के अभिप्रायों की अपेक्षा उसकी बुद्धि, सकल्प तथा क्रिया के राजनैतिक स्तर पर निर्णय देना चाहिए।

(४) संज्ञात्मक प्राथमिकताएँ गौण होती हैं (Ideological differences are immaterial) — अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यह देखना बिल्कुल अनावश्यक नहीं है कि एक राजनीतिज्ञ की दार्शनिक एवं राजनैतिक सद्भावनाएँ किसके साथ हैं। आजकल यह सामान्य परम्परा

तो बन गई है कि प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति को सैद्धांतिक आवरण पहना कर उसे लुभाइना बना देता है ताकि नवयुवा जनमत उसकी रूप रानि की ओर खिंचता चला जाय। उदाहरण के लिए साम्यवादी चीन की युद्धप्रिय एवं विस्तारवादी नीतियाँ विश्व के विनाश का मार्ग-प्रशस्त कर रही हैं किन्तु वह इन्हे साम्राज्यवाद विरोधी, साम्यवाद का समर्थक, पूँजीवादी शोषण का विध्वंसक और भी न जाने क्या क्या भादशों की उपलब्धि का प्रयास उद्घोषित करता है और एशिया तथा अफ्रीका के कुछ देश उसके सूपरास्ता जैसे इस भाषाविनी रूप की ओर आकर्षित हो गये हैं।

राजनैतिक मध्यमवाद राजनैतिक भादशों एवं तैत्तिक सिद्धांतों का विरोधी नहीं है। वह मानता है कि इनका भी अन्तर्राष्ट्रीय जगत में थोड़ा महत्व रहता है किन्तु हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि एक देश जो करना चाहता है तथा जो वह कर रहा है इन दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक समय हमें जो कार्य करने चाहिए (Desirable) उनमें तथा एक स्थान विशेष व समय विशेष में क्या किया जा सकता है (Possible)—इन दोनों बातों में भारी अन्तर रहता है। मध्यमवादी सिद्धान्त इस अन्तर को अलदेलना नहीं करता।

बौद्धिक विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि विदेश नीतियों का आधार हमेशा ही बौद्धिक, वस्तुगत तथा अ-भावनात्मक नहीं रहता। विदेश नीतियों पर व्यक्तित्व, विषयगत प्राथमिकताएँ (Subjective Preferences) तथा बुद्धि व सकल्प की सारी कमजोरियाँ प्रभाव डालती हैं और इस प्रकार विदेश नीतियाँ कथल बौद्धिक नहीं रह जाती। प्रजातंत्र में इन अवबोद्धिक तत्वों का प्रभाव अधिक होता है।

(५) 'स्वार्थ' तथा 'शक्ति' की मध्यमवादी परिभाषाएँ (The Realist definitions of "Interest" and "Power")—स्वार्थ' की मान्यता परिस्थितियों से प्रभावित न होते हुए भी समस्त राजनीतिक क्रियाओं का आधार रहेगी। मित्रता और वर 'स्वार्थ' की मानना से ही किये जाते हैं। यह बात राज्य के जीवन में भी उतनी ही सच है जितनी कि एक व्यक्ति के जीवन में। किन्तु राष्ट्रीय स्वार्थ क्या है? इस प्रश्न का ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो देश-काल के परिवर्तन होने पर भी सत्य बना रहे। मध्यमवाद यह मानता है कि इतिहास के एक विशेष समय में एक राष्ट्र का क्या हित है, यह उन राजनैतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों पर आधारित है जिनमें उस राष्ट्र की विदेश नीति का निर्माण किया गया है।

‘शक्ति’ (Power) के प्रयोग का दम तथा रूप भी राजनैतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है। किन्हीं परिस्थितियों में एक देश आर्थिक प्रतिबन्धों (Economic Sanctions) के द्वारा ही दूसरे देश को प्रभावित कर लेता है जबकि अन्य में उसे युद्ध की चुनौती देने को भी मजबूर होना पड़ सकता है। शक्ति उस प्रत्येक चीज को कहा जा सकता है जो एक मनुष्य का दूसरे पर नियंत्रण सम्भव बना दे। इस परिभाषा के अनुसार शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। यह शारीरिक हिंसा से लेकर मनोवैज्ञानिक पवित्र बन्धनों तक कुछ भी हो सकती है। शक्ति का उद्देश्य (नैतिक प्रथम दमनकारी) तथा रूप (हिंसात्मक या सद्भावनापूर्ण अनुबन्ध) विभिन्न प्रकारों के हो सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त यह मानता है कि बड़े पैमाने की हिंसा की जो घमकी वर्तमान विश्व के सामने है उसको दूर किया जा सकता है। आज जो राष्ट्रीय-राज्य स्थित हैं ये इतिहास की उपज हैं। ऐतिहासिक विकास के क्रम में ये भी जिन्दा नहीं रह सकते। यथार्थवादी सिद्धान्त की यह मान्यता है कि कुछ तकनीकी कारणों से तथा वर्तमान विश्व की कुछ नैतिक मांगों के कारण राष्ट्रीय राज्य विलीन हो जायेंगे। इनका स्थान एक बड़ी इकाई ग्रहण कर लेगी जिसकी प्रकृति इन राष्ट्रीय राज्यों से भिन्न होगी।

(६) नैतिक सिद्धान्तों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण (Realistic attitude towards Moral Principles)—यथार्थवादी यह मानते हैं कि नैतिक सिद्धान्तों का भी राजनीतिक प्रक्रियाओं में महत्त्व होता है किन्तु इन सिद्धान्तों के प्रभुत्व एवं सांवेमोमिक रूप को राज्य के कार्यों में व्यवहृत नहीं किया जा सकता। इसके लिए इन्हें समय तथा परिस्थिति के अनुरूप बनना होगा। एक व्यक्ति नैतिक सिद्धान्तों के ऊपर सब कुछ न्यायावर कर सकता है किन्तु ‘राज्य’ के बारे में यह सब नहीं है। एक व्यक्ति यह कह सकता है कि ‘न्याय की विजय होनी चाहिए चाहे उसका पीछे दुनिया नष्ट हो जाय’ किन्तु एक राज्य जिसमें घनेकी नागरिक रहते हैं तथा जिसके सामने राष्ट्रीय अस्तित्व (National Survival) का नैतिक कथ्य भी है, ऐसा नहीं कह सकता। राजनैतिक नतिकता किन्हीं प्रभुत्व एवं सांवेमोमिक कारकों पर आधारित नहीं है, इसका निष्पत्ति राजनैतिक परिणामों के आधार पर ही किया जा सकता है।

(७) यथार्थवादी सत्य और कल्पना के बीच अन्तर करता है (Realist distinguishes between Truth Idolatry)—यथार्थवादी

सिद्धान्त की यह मान्यता है कि एक सार्वभौम नैतिक कानून का पालन एक देश विशेष के लिए आवश्यक रूप से लाभदायक होगा, यह मंच नहीं है। हो सकता है कि वह उसके लिए मयंकर परिणाम पंदा कर दे। नैतिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिए अपने देश के हितों को बलिदान कर देने वाला व्यक्ति राजनैतिक दृष्टि से बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नतिकता को तिलाजलि देना भी इतिहासकारों की लेखनी से प्रशंसा नहीं पा सकता। ये दोनों ही भ्रमियाँ (Extremes) हैं। इनसे बचने का एक माध्यम यह है कि प्रत्येक राष्ट्र का अपने राष्ट्रीय स्वार्थ (जो कि 'शक्ति' के रूप में परिभाषित है) की दिशा में हो भ्रमसर होना चाहिए।

(८) यथार्थवादी केवल राजनैतिक पहलू पर ही अधिक ध्यान देता है (It maintains the autonomy of the political sphere)—यथार्थवादी विचारधारा अपने आपको राष्ट्रीय जीवन के अन्य पहलुओं में न उलझा कर केवल राजनैतिक समस्याओं से ही संबंधित रख कर उनका हल ढूँढना चाहती है, और इस प्रकार से यह विचारधारा बौद्धिक रूप से राजनैतिक क्षेत्र में स्वायत्तता (autonomy) को स्थापना करती है जैसे कि बानूनवेत्ता का सम्बन्ध वैधानिक बानूनों से, व्यवसायी का सम्बन्ध उपयोगिता से तथा नीतिशास्त्री का सम्बन्धी नैतिक नियमों से होता है ठीक इसी प्रकार एक यथार्थवादी विचारक शक्ति के रूप में परिभाषित स्वाध (‘Interest’ defined as power) के आधार पर ही अपने अध्ययन को भागे बढ़ाता है। वह किसी भी घटना व्यवहार नीति पर विचार करते समय यही ध्यान रखता है कि इसका उस राष्ट्र शक्ति के ऊपर कैसा प्रसर पड़न वाला है।

राजनैतिक यथार्थवादी के मरिदक में अन्य विषयों के आदर्श भी रहते हैं किन्तु उन सबको राजनैतिक आदर्शों के अधीन बना दिया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी समस्या पर निर्णय लेते समय यथार्थवादी दृष्टिकोण यह तो अवश्य देखेगा कि नैतिक दृष्टि से उस आखिर करना क्या चाहिये किन्तु वह इस प्रकार का कोई कदम न उठायेगा जो उसके राष्ट्रीय स्वार्थ के विरुद्ध जाता हो। इस प्रकार यथार्थवादी सिद्धान्त समस्याओं के प्रति वैधानिक व नैतिक दृष्टिकोण (Legalistic-Moralistic Approach) प्रदान करने का पक्षपाती है।

ऊपर वर्णित समस्त विशेषताओं को यथार्थवादी सिद्धान्त अपने आप में समाविष्ट करता है। यह मनुष्य के बहुवादी (Pluralistic) रूप को लेकर

चलता है जिनके अनुसार मनुष्य के राजनैतिक पक्ष के अलावा वैदिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्ष भी होते हैं। मनुष्य को केवल राजनीतिक मानने वाला जगली है तथा उसे केवल नैतिक बहने वाला मूल (fool) है—ज्ञान एकपक्षीय नहीं होता। मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन ही ज्ञान को पूर्ण बना सकता है।

यथार्थवादी सिद्धान्त का मूल्यांकन

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवादी सिद्धान्त एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन की वैज्ञानिकता, निश्चितता तथा भविष्यवाणी करने की सामर्थ्य आदि गुणों से विभूषित करना चाहता है। एक देश की घटनाओं का वास्तविक रूप में अध्ययन करके ही उनके आधार पर अपनी विदेश नीति निर्धारित करनी चाहिए सभी उनका प्रयास सफल हो सकता है।

‘प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थ की पूर्ति में सलग्न है तथा उसका स्वार्थ यह है कि वह अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करे’ इस बात पर जोर देकर यथार्थवादी विचारधारा दो प्रमुख सदेश प्रदान करती है, जिनको अपनी विदेश नीति निर्धारित करते समय प्रत्येक राष्ट्र को ध्यान में रखना चाहिए। पहला सदेश तो यह है कि विदेश नीति ऐसी बनाई जाय जो शक्ति बढ़ाने एवं बनाये रखने में हमारे राष्ट्र को अधिक से अधिक सहायता कर सके। दूसरा सदेश, जो इसी से सम्बन्धित है, यह है कि हम अपनी विदेशनीति का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखें कि दूसरे देश का राष्ट्रीय स्वार्थ क्या है तथा वह हमारे राष्ट्रीय स्वार्थ से (जहाँ तक सम्भव हो सके) टकराये नहीं।

इसके अतिरिक्त क्योंकि यथार्थवादी सिद्धान्त का आधार बुद्धि है अतः हमसे प्रभावित विदेश नीति भी बुद्धि तथा तर्क पर आधारित होगी। ऐसी विदेश नीति में खतरा (Risk) लेने की स्थान कम रहता है तथा अधिकांश बातें एक योजना के अनुसार ही होती चली जाती हैं। इस प्रकार की विदेश नीति राजनैतिक रूप से सफल होती है तथा नैतिक रूप से भी इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक विदेश नीति का सबसे बड़ा गुण माना जाता है कि वह यथार्थवादी (Realistic) है।

राज्य व्यवस्था (THE STATE SYSTEM)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन छैन विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंध होते हैं। ये राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइया होती हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र के सही रूप को समझने के लिए इन राज्यों की वास्तविक प्रकृति उनके धर्म, उनके आवश्यक तत्व, उनके विकास एवं वर्तमान रूप का अध्ययन करना जरूरी बन जाता है। राज्यों के भूत तत्वों का सही ज्ञान होने के अभाव में यह सम्भव नहीं होता कि उसके भावी व्यवहार के बारे में पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए। राज्य किन तत्वों से प्रभावित होते हैं, उनके आदर्श एवं आकांक्षाएं क्या होती हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में वे क्यों प्रयत्नशील होते हैं आदि बातें सभी समझ में आ सकती हैं जब कि राज्य व्यवस्था का सही चित्र हमारे सामने हो। आज के युग को अन्तर्राष्ट्रीयता का अथवा विश्व सभाज की स्थापना का युग कहा और माना जाता है। इस युग के सभी राज्यों से पारस्परिक सहयोग के साथ जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है। इसके बिना उनकी सुरक्षा एवं अच्छा जीवन दोनों ही बात खटाई में पड़ जाती हैं। विश्व के पटल पर आज १२२ से भी अधिक राज्य हैं। इनमें से कुछ तो आर्थिक पराधनता के कारण दूसरों के साथ बंधे हुए हैं तथा दूसरों के पारस्परिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने में विगत जीवन का इतिहास, भूगोल, भाषा, जाति, धर्म अथवा राजनीतिक समस्याएँ पर्याप्त प्रभाव डालती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को और भी घनिष्ठ बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सच आदि विभिन्न विश्व संगठनों द्वारा प्रयास किया जाता

है। कुल मिला कर विश्व की स्थिति ने आज जो रूप धारण कर लिया है उसे देख कर यह कहा जा सकता है विश्व समाज ने जन्म ले लिया है किन्तु यह अभी सत्रमण काल में चल रहा है। पामर तथा परकिन्स का यह कहना पूर्णतः उपयुक्त है कि इस विश्व समाज का आधार राज्य, अथवा यों कहिए कि राज्य व्यवस्था है इसलिए विश्व समाज एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का प्रारम्भ यही से करना चाहिए।¹

राज्य व्यवस्था का अर्थ (The Meaning of State System)

राज्य व्यवस्था ने तीन शताब्दियों से भी अधिक समय से अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के तरीकों को ढालने में आधार का काम किया है। 'राज्य-व्यवस्था' को पाश्चात्य राज्य व्यवस्था, राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, राष्ट्र-राज्य व्यवस्था आदि विभिन्न सजाओ से भी संबोधित किया जा सकता है। राज्य व्यवस्था को परिभाषित करते हुए पामर तथा परकिन्स लिखते हैं कि यह राजनैतिक जीवन का वह तरीका है जिसमें कि लोग सम्प्रभु राज्यों में प्रत्येक रूप से संगठित हो जाते हैं। इन राज्यों का एक साथ मिलकर रहना होता है। राज्य व्यवस्था में एक प्रमुख समस्या इन विरोधाभास पूर्ण स्थिति के कारण उत्पन्न हो जाती है कि एक ओर तो प्रत्येक राज्य सम्प्रभु है तथा कानूनी रूप से उसे पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, किन्तु दूसरी ओर उसे विश्व में दूसरे राज्यों के साथ संबंध बनाकर चलना होता है। उसे अन्य राज्यों को बर्द सैन्य में छूट देनी पड़ती है तथा समायोजन करते समय बर्द बार दबना भी पड़ता है। हर राष्ट्र का अपना राष्ट्रीय सम्मान होता है तथा उसके स्वयं के स्वार्थ होते हैं। इनकी रक्षा के लिए तथा अपनी सम्प्रभुता को बनाये रखने के लिए उसे दमनकारी शक्ति का संगठन करना होता है। वह अपनी राष्ट्रीय शक्ति (National Power) के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करता है। अपने हितों की रक्षा के लिए पहले तो यह शान्तिपूर्ण साधनों को अपनाता है किन्तु उनके निरर्थक सिद्ध हो जाने पर यह विध्वंसक शक्ति, यहाँ तक कि युद्ध को भी अपना सकता है। हितों को लेकर उठने वाले वाद-विवाद राज्यों के बीच बर्द बार युद्ध का कारण बन जाते हैं। युद्ध का मार्ग अपनाने से राज्यों को कोई रोक भी नहीं सकता क्योंकि वे सम्प्रभुता-सम्पन्न कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

राज्य व्यवस्था पात्र के अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के युग में नी एक प्रभाव-पूर्ण तत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का कोई भी विद्यार्थी राज्यों की प्रकृति, उनके अन्तर, वर्गीकरण ऐतिहासिक विकास तथा राज्य व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के अध्ययन की आवश्यकता नहीं कर सकता। 'राज्य व्यवस्था' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की यह आधारशिला है जिस पर कि समस्त विचारधारायें एवं उनके व्यापारिक प्रयोग आधारित रहते हैं। इससे पूर्व कि हम राज्य व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, यह उपयोगी रहेगा कि राज्य के अर्थ, वर्गीकरण, विभिन्नता आदि का संक्षेप में उल्लेख कर दिया जाये।

राजनैति शास्त्र के विद्वानों ने समय-समय पर राज्य की परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं को व्यक्त करने के तरीके तथा शब्दों के प्रयोग में अन्तर रह सकता है किन्तु मूलतः उन सभी की मान्यताएँ एक गहरा साम्य रखती हैं। एक परिभाषा के अनुसार राज्य जनता के उस निष्ठाव की कहा जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है तथा एक सरकार के प्राचीन राजनैतिक रूप से संगठित है। प्रायः सभी विचारक इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि राज्य के चार तत्व होते हैं—भूमि, जनता, जनसत्ता एवं सम्प्रभुता। राज्य एक वैधानिक इकाई होती है तथा मुख्य रूप से इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे राष्ट्र, राज्य एवं देश—तीन अलग-अलग पद हैं जिनके अर्थों में भी भिन्नता रहती है किन्तु फिर भी इनका एक दूसरे के लिए प्रयोग कर लिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये पद समानार्थक हैं किन्तु एक ही शब्द को बार-बार ताना भ्रष्टा प्रतीत नहीं होता अतः ऐसा कर दिया जाता है।

सभी राज्यों के पास सम्प्रभु शक्ति रहती है और इसलिए उनको एक जैसा ही माना जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून सभी राज्यों को समान स्तर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र सभ के घोषणा-पत्र की धारा दो के अनुसार यह सत्ता इसके समस्त सदस्यों की समान सम्प्रभु शक्ति के सिद्धान्त पर आधारित है। वास्तविक व्यवहार में यह समानता देखने की नहीं मिलती। अनेक छोटे, शक्तिहीन एवं साधनहीन राष्ट्र बड़े सम्पन्न एवं शक्तिशाली राष्ट्रों पर अवलम्बित रहते हैं। राज्यों के बीच जनसंख्या, आकार, संस्कृति, सैनिक शक्ति, सरकार के रूप, भाषिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोत आदि के आधार पर अनेक अनेक असमानताएँ देखी जा सकती हैं।

राज्यों का शक्ति-स्तर (Power Status of the States)

राज्य का प्रमुख मूल उद्देश्य उसकी सम्प्रभुता को माना जाता है जिसकी रक्षा के लिए वह अपनी सैनिक, आर्थिक, तथा राजनैतिक शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करता है। वैसे आधुनिक राज्यों का रूप और अन्तर्राष्ट्रीय समाज वर्तमान काल की ही उपज है। उनके इतिहास की तीन या चार शताब्दियाँ मानवीय इतिहास के उन सात हजार से अधिक वर्षों का एक छोटा सा भाग है जिनका कि ऐतिहासिक भूमिलेख प्राप्त होता है। राज्य व्यवस्था का छोटा जीवन होने के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का प्रचलन बहुत पूर्व हो चुका था। कुछ विचारकों का कहना है कि आधुनिक राज्य व्यवस्था सम्भवतः घर्म सुधार आन्दोलन के युग से प्रारम्भ होती है जब कि फ्रांस, इंग्लैण्ड, जर्मनी, आदि राज्यों के सामयिक राजाओं ने तथा यूरोप की छोटी शक्तियों ने घर्म युद्धों के कारण उत्पन्न घरायश्वता का लाभ उठाया और अपनी सीमाओं में रह कर अपनी सत्ता को स्थापित किया। वे पापिक मामलों में पोप की सत्ता के आगे झुकते थे और घर्म निषेध मामलों में रोमन साम्राज्य के बादशाह के आगे, किन्तु अपनी राजधानियों में वे शक्तिशाली सामन्तों को चुनौती देते थे। इस प्रकार सर्वोच्च सत्ता या सम्प्रभुता प्रादेशिक राज्य को प्राप्त होती थी जिसके अधिकार, स्वतन्त्रता और शक्ति, आदि सारी चीजें प्रादेशिक रूप से प्राप्त होती थीं। एक बार स्थापित हो जाने के बाद सम्प्रभुता द्वारा प्रत्येक राज्य को यह अधिकार सौंप दिया जाता था कि वह अपनी जनता और साधनों को जिस रूप में चाहे उस रूप में रखे और बिना किसी राजनैतिक उच्चाधिकारी के मात्रहृत हुए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं में कार्य करे। इसके परिणामस्वरूप एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसमें कि सम्प्रभु एवं स्वतन्त्र राज्य थे जो सभी सौदानीक रूप से समान थे किन्तु वास्तविक शक्ति की दृष्टि से उनके बीच भारी अन्तर था। उनमें से प्रत्येक अपने अस्तित्व के लिए अपने साधनों पर निर्भर करता था। इनके बाद से व्यक्तिगत सुरक्षा, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, युद्ध, व्यापार और सभ्यता एवं सभ्यता का विकास, आदि राष्ट्र राज्य की सर्वोच्च सम्प्रभु राजनैतिक द्वाँई मान कर रूप धारण करने लगे।

स्पष्टतः सभी राज्य आकार या साधनों की दृष्टि से समान नहीं हैं। शक्ति के वितरण में इस असमानता ने उस व्यवस्था की कार्यवाही को महत् रूप से प्रभावित व परिवर्तित किया जो प्रत्येक सम्प्रभु राज्य की सैदान्तिक

समानता पर आधारित है। राज्यों के बीच प्राप्त इस अन्तर की स्थिति को संयुक्तल प्राफ्टन (Samuel Grafton) ने बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है। उनके कथनानुसार यदि आप गिलहरी को एक प्रमाण-पत्र दे दें कि वह भी इतनी ही बड़ी है कि जितना बड़ा कोई हाथी होता है तो भी वह छोटी ही रहेगी तथा प्रत्येक गिलहरी एक समी हाथी इस तथ्य से परिचित रहेंगे।¹ फॉक्स महादय (T. R. Fox) ने यह सिद्ध किया है कि पश्चिमी राज्य व्यवस्था सदैव ही कुछ बड़े राज्यों द्वारा प्रभावित रही है। राज्यों के बीच प्रसमान शक्ति का वितरण होने के कारण ही उनको बड़ी शक्ति एवं छोटी शक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

बड़ी शक्ति और प्रभावशील शक्ति के बीच अन्तर होना है। बड़ी शक्ति उसे कहते हैं जो अन्य किसी भी शक्ति को अपने साथ लेने की सामर्थ्य रखती है और प्रभावशील शक्ति वह होती है जो दूसरी शक्तियों के सन्धि को अपने साथ लेकर चल सके।² शक्तियों के आधार पर राज्यों को जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें सर्वोच्च शक्ति की श्रेणी को भी ले सकते हैं। टी० फार० फॉक्स के मतानुसार सर्वोच्च शक्ति (Super Power) वह होती है जो बड़ी शक्ति होने के साथ साथ शक्ति आने के भी अनेक साधन रखती है। सन् १९४५ में देखा गया था सर्वोच्च शक्तियाँ तीन थी—संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत रूस और ग्रेट ब्रिटेन। विन्तु युद्धोत्तर घटनाओं ने ग्रेट ब्रिटेन को शक्ति हीन बना दिया। शक्तियों के आधार पर राज्य का यह वर्गीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राष्ट्रों के बीच शक्ति के वितरण की प्रवृत्तियों के द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के रूप के विकास को निर्धारित किया जाता है। यदि हम यह जान लें कि सर्वोच्च शक्तियाँ और महान शक्तियाँ कौन हैं तो यह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि बड़े स्तर की अन्तर्राष्ट्रीय हिमा की सम्भावना की आशा किससे की जा सकती है क्योंकि कोई भी छोटी शक्ति केवल छोटे मोटे सपनों एवं युद्धों का ही कारण बन सकती है। बड़े स्तर का युद्ध उस समय तक प्रारम्भ नहीं हो सकता जब तक बड़े राष्ट्र इसमें सलग्न न हों।

-
- 1 Samuel Grafton, quoted in William T.R. Fox The Super-Powers, 1944, P 3
 - 2 Martin Wight, Power Politics, Royal Institute of International Affairs, London, 1956, PP 18-27

परम्परागत रूप से राष्ट्र राज्यों पर किसी सर्वोच्च सम्प्रभु का नियन्त्रण नहीं रहता और वे अपने ही प्रयासों से उन सम्बन्धों की विनियमित करते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें। ऐसी स्थिति में शक्ति की राजनीति का विकास होता है जिनके अनुसार प्रत्येक देश अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था जैसी खतरनाक स्थिति से बचने के लिए राज्य संधियों की नीतियों में सलग्न होते हैं। इन संधियों के द्वारा राज्यों की शक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज में शक्ति-सन्तुलन बना रहे। साथ ही सम्भावित खतरों से सदस्य राज्यों को सामूहिक सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर हम विश्व के राज्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से चार श्रेणियों में कर सकते हैं—

(१) बड़ी या प्रधान शक्ति (Great or major power)—बड़ी शक्ति प्रायः उस राष्ट्र को कहा जाता है जिसके स्वार्थ बहुत अधिक फैले हुए रहते हैं, विश्व के अनेक राज्यों से वह सलग्न रहता है तथा अपने स्वार्थों एवं विदेशों में किए गए समझौतों को क्रियान्वित करने की उसके पास शक्ति रहती है। कभी कभी बड़ी शक्ति (Great power) उस देश को भी कह दिया जाता है जिसे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिला हुआ रहता है। ऐसे देश पाँच हैं—अमेरिका, राष्ट्रवादी चीन, सोवियत रूस, फ्रांस व ब्रिटेन। बड़ी शक्तियों का यह नामकरण उचित प्रतीत नहीं होता। अनेक विचारकों के मतानुसार फ्रांस व राष्ट्रवादी चीन को महान् शक्ति कहने की अपेक्षा यदि मध्यस्तर की शक्ति (Middle power) कहा जाय तो अधिक उचित रहेगा। ये विचारक भारत को भी मध्यस्तर की शक्ति मानते हैं।

(२) सघु या नोचो शक्ति (Small or lesser power)—मार्टिन वाइट (Martin Wight) महोदय के मतानुसार इस श्रेणी में हम उन देशों को ले सकते हैं जिनके स्वार्थ सीमित होते हैं तथा केवल इन सीमित स्वार्थों की पूर्ति के योग्य शक्ति ही उनके पास रहती है।^१ इस श्रेणी के देशों के नाम गिनाना सरल नहीं है अतः अल्पश्रेणियों में से बचे राष्ट्रों को हम इनके अधीन रख सकते हैं। पामर तथा परकिन्स के मत में लघु देशों के स्वार्थों का सीमित होना आवश्यक नहीं है, इसके अपवाद भी हो सकते हैं।

(३) शक्ति का अनिश्चित स्तर (Uncertain status of Power)—पामर तथा परकिन्स महोदय ने जर्मनी तथा जापान दो राष्ट्रों को इस श्रेणी

के अन्तर्गत रखा है। यह दोनों ही देश द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व महान शक्तियों में गिनी जाती थीं किन्तु युद्ध के दुष्परिणाम सबसे ज्यादा इन्हीं दो देशों को झुगटाना पड़ा। एक के तो दो टुकड़े हो गए और दूसरे की शक्ति को उसके ऊपर की गई मक्कर बमबारी ने घटा दिया। किन्तु अब भी दोनों देशों में बड़ी शक्ति बनने का लक्ष्य विद्यमान है अतः इनके स्तर को अभी से निश्चित करना उचित प्रतीत नहीं होता।

(४) विश्व शक्ति (World Power)—‘विश्व शक्ति’ (World Power) की संज्ञा प्रायः दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। एक अर्थ में तो यह उन देशों की ओर इशारा करती है जिनका सम्बन्ध तथा अधिकार विश्व भर में फैला है उदाहरण के लिए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि। दूसरे अर्थ में विश्व शक्ति (World power) उन राष्ट्रों को कहा जाता है जिनका अधिकार एवं सम्बन्ध विश्व भर में व्याप्त हो और साथ ही प्रसाधारण सैनिक शक्ति भी उसके पास हो, जैसे अमेरिका आदि। सर्वोच्च शक्ति (Supreme power) शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदित रूस, अमेरिका आदि शक्तियों के लिए किया जाता है जिनके पास प्रसाधारण शक्ति साधन हैं।

राज्य व्यवस्था का विकास (The Development of State System)

राज्य व्यवस्था का वर्तमान रूप एक लम्बे विचार का परिणाम है। इसका प्रारम्भ अस्तित्व के इस कथन से सिद्ध होता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनैतिक प्राणी है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यवस्था भी इतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं इंसान। विकास के प्रत्येक चरण पर लोगों की ऐसी आवश्यकताएँ एवं माँगें रही हैं जिनको वे स्वयं सन्तुष्ट नहीं कर सकते और इसलिए वे सामाजिक समूहों की रचना करते हैं। वे समूह परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति और क्षेत्र की दृष्टि से भिन्न प्रकार के होते हैं। इन समूहों की रचना के अनुसार इनमें अनेक संगठनात्मक समस्याएँ उठती हैं। पहली समस्या तो यह उठती है कि उद्देश्यों की दृष्टि से उनका सही आकार क्या रखा जाए। प्लेटो तथा अरस्तु ने यह सीमा नगर राज्यों के रूप में बताई किन्तु प्राधुनिक समाज शास्त्री उस आकार को आदर्श मानते हैं जिसमें सामाजिक सत्कार की विचारधाराएँ विकसित हो सकें। मानवीय संगठनों के अधिकांश अध्ययन प्राकृतिक व्यवस्था से आरम्भ होते हैं। वे इसे या दो अज्ञान से पूर्ण, या हॉब्स की तरह प्रत्येक का प्रत्येक से युद्ध अथवा

स्वयं युग के रूप में वर्णित करते हैं। राज्य की स्थापना के पूर्व की प्राकृतिक अवस्था क्या थी ? किस तरह की थी ? और इसके व्यक्ति का जीवन कैसा था ? आदि बातें प्रागैतिहासिक काल की हैं। अतः इनके सम्बन्ध में वाद विवाद करना उपयोगी प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि जिस समय मानवीय समूहों की संख्या कम थी सम्भवतः उस समय उनके बीच कोई सम्पर्क नहीं होगा किन्तु यह कल्पना की जाती है कि ज्यों ज्यों इन समूहों की संख्या बढ़ती गई और उनके बीच की जटिलताएं बढ़ती चली गई त्यों-त्यों उनका पारस्परिक सम्बन्ध विकसित हुआ। यह कल्पना की जाती है कि समूहों के सम्पर्क हिंसा पर आधारित रहे होंगे और बाद में इन्होंने अहिंसात्मक तथा सहयोग पूर्ण रूप धारण किया होगा।

ऐतिहासिक विकास के काल में इन सम्बन्धों को ऐतिहासिक बनाया गया तथा ऐसी व्यापारिक लेन-देन विकसित की गई जो सभी समूहों के लिए उपयोगी हो। एक बार जब इस प्रकार के सम्बन्ध व्यापक बन गये तो वे कार्य कुशल केन्द्रीय सरकार के संगठन की आवश्यकता को जन्म देने लगे जो उन पर नियन्त्रण रख सके। इस प्रकार राज्य की स्थापना हुई तथा सम्प्रभुशक्ति ने जन्म लिया। यह कहा जाता है कि सर्व प्रथम बड़े स्तर के राजनैतिक संगठन राज्य अथवा राज्य व्यवस्था जिनका कि हमारे पास लेख है वे ईसा से ५००० वर्ष पूर्व विकसित हुए होंगे। ये जहाँ पर विकसित हुए थे यह कोई भ्रमसर की बात नहीं थी वरन् इन क्षेत्रों की सामान्य सामाजिक आवश्यकताओं का परिणाम था। इन राजनैतिक संगठनों में ऐन शक्तिशाली केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता हुई जो सिखाई व्यवस्था का प्रवर्धन कर सके। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में सम्यता का विकास होने लगा और राजनैतिक व्यवस्था उच्च बनती चली गई। ये प्रारम्भिक राज्य व्यवस्थाएं अपनी सीमाओं की दृष्टि से बदलती रहती थीं। इन्होंने आंतरिक रूप से सांस्कृतिक एवं राजनैतिक एक रूपता का विकास किया। राज्य व्यवस्था के विकास को राजनीति शास्त्र के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कालों में विभाजित किया है। इन कालों की स्वयं की विशेषताएं थी और इन्होंने राज्य के स्वरूप को बदलने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। इस विकास पर अनेक परिस्थितियों एवं अवस्थाओं ने प्रभाव डाला है। विकास के परिणामस्वरूप जो रूप आज सामने है उस पर अतीत का पूरा प्रभाव है। सिंधु घाटी, नोल नदी तथा अन्य नदियों के मुहानों पर जो सम्यता विकसित हुई थी उसे वर्तमान राज्य व्यवस्था का रूप धारण करते कई मोड़ों से गुजरना पड़ा है। प्रारम्भिक सम्यताओं के बीच पारस्परिक लेन-देन तथा संचार की व्यवस्था

थी, साथ ही सुरक्षा एवं विजय के लिए विभिन्न सङ्घर्षों लड़ी जाती थी। पर पश्चिमी ससारा में व्यक्तिगत जीवन पंद्रहवीं शताब्दी तक ऐसा बना रहा जिसने पूर्वी दुनिया के साथ कोई सम्पर्क नहीं रखा। इतिहास के प्रारम्भ में भारत मध्य पूर्व मैक्सिको एवं दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों की सम्यता उस स्तर पर पहुँच चुकी थी जहाँ पर कि पश्चिमी यूरोप की पहुँचने में बहुत समय लगा। किंतु पश्चिमी यूरोप की संस्कृति पिछले पाँच सौ वर्षों में जितनी विकसित हुई है उतना विकास अन्य समाज अब तक नहीं कर पाए।

मध्य युग में पश्चिमी समाज का जो रूप था वह स्वतन्त्र राज्यों एवं उनके आपसी सम्बन्धों के विकास के कारण परिवर्तित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने विचारक पारवात्य सम्यता एवं समान के रूप को महत्व प्रदान करते हैं क्योंकि वे ससारा इसमें बहुत प्रभावित रहा है। पारवात्य सम्यता की जड़ें मध्य युग के माध्यम से प्राचीन यूनान और रोम तक फैली हुई हैं। यूनानी लोगों का जन्म एवं संस्कृति सामान्य होते हुए भी उनमें राजनीतिक एकता नहीं थी। वे अनेक नगर राज्यों में बँटे हुए थे, उनका आपसी सम्बन्ध बहुत कुछ ऐसा था जैसा आज के राज्यों के बीच पाया जाता है।

पश्चिमी जगत में रोमन साम्राज्य का प्रारम्भ ईसा से ३५० वर्ष पूर्व हुआ जब कि रोम के नगर राज्यों ने इटली के भागों को जीतना प्रारम्भ किया। रोमन साम्राज्य के आधीन एक नई राजनीतिक व्यवस्था का चित्र खींचा गया। प्रारम्भ में रोम वालों के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध यूनानियों जैसे थे किन्तु शीघ्र ही रोम वाले दूसरे लोगों को अपने बराबर समझने की अपेक्षा अपनी प्रजा मानने लगे। ज्यों ज्यों साम्राज्य बढ़ता गया, स्थो-स्थो सम्बद्ध क्षेत्र अधिक उपनिवेश बनते चले गए। रोम वालों की एक सबसे बड़ी सफलता एवं विरासत सामान्यतः उनके कानून की व्यवस्था को माना जाता है। कानून की एक शाखा जस जेन्टियम (Jus gentium) कहलाती है जो भौतिक रूप से परम्पराओं का एक समूह था जिसे गैर रोम वालों पर लागू किया जाता था। बाद में इसे रोम के नागरिकों पर भी लागू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रारम्भिक लेखक जो प्राकृतिक कानून की मान्यता पर जोर देते हैं, प्राकृतिक कानून को जानने के लिए जस जेन्टियम को आधार बनाया।

रोमन साम्राज्य ईसा के बाद चौथी शताब्दी में समाप्त हो गया और इसके बाद जो अर्थ जगती बातों-बातों का पता, उससे व्यवस्था पैदा हो गई।

इस स्थिति में धीरे-धीरे सामनवाद की व्यवस्था का विकास हुआ। सैद्धांतिक रूप से सामतवाद एक पद सोपान की व्यवस्था होती है जिसमें सबसे नीचे के स्तर पर भूमिहर (Serf) रहना है उसके बाद लांडे, बैसाल, राजा और शीर्ष पर बादशाह होना था, किंतु यथार्थ में यह व्यक्तिगत प्रबल की एक उलझी हुई तथा भ्रमपूर्ण व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सत्ता, भ्रम-व्यवस्था एवं जीवन को सामान्य रूप से विकेंद्रीकृत कर दिया गया। सामतवादी युग में एकता का आधार राष्ट्रीयता की भावना न होकर धार्मिक भावना थी। चर्च का लोगो के मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव था तथा इसने मुखा एकीकरण की शक्ति का काम किया। यद्यपि सामतवाद ने व्यवस्था एवं स्थायित्व की स्थापना करके एक उपयोगी कार्य को सम्पन्न किया किंतु चौदहवीं शताब्दी में यह उन नई शक्तियों से प्रभावित होने लगा जो परिवर्तन चाहती थीं। बढ़ते हुए मध्यम वर्ग ने उन शक्तिशाली-व्यक्तियों का समर्थन किया जो सामतवाद के विरोधी थे। इन विरोधी शक्तियों के मिल जाने के कारण सामतवादी लोग उद्दिन होते हुये राज्यों में अपने आपको समायोजित नहीं कर सके। दूसरी ओर पोप तथा बादशाह ने जिस रूप में इसे चुनौती दी उनका भी यह सामना नहीं कर सके।

चौदहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक यूरोप विश्व की घटनाओं का एक केन्द्रीय रंगमंच बना रहा। विश्व की प्रमुख शक्तियां इसी क्षेत्र में स्थित थी और दूसरी जगह होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में इनकी मुख्य भूमिका योगदान रहता था। सन् १५०० तक कुछ राज्य, जिनके नाम और क्षेत्र बीसवीं शताब्दी के राज्यों के नाम और क्षेत्र जैसे थे, यूरोप की सीमा में विकसित हुए। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस स्पेन और पुर्तगाल आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सन् १८१५ तक यह शक्तियां यूरोप में तथा समुद्र पार की नई दुनिया में सघर्षरत बनी रही। बड़े-बड़े साम्राज्य जीते गये, हारे गए और एक शक्ति से दूसरी शक्ति को हस्तांतरित किये गये। इसके साथ ही साथ व्यापारिक क्रांति ने स्थानीकृत सामन्यवादी अर्थ व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया, व्यापार और बन्दूक की शक्ति का अर्थ से अधिक प्रमाण होने लगा। नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने तकनीकी विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इन परिस्थितियों में यदि कोई शक्तिशाली आक्रमणकारी राज्य शक्ति के वितरण को अस्त-व्यस्त करने की धमकी देता या अन्य राज्यों को पराधीन बनाने की चेष्टा करता तो छोटे राज्य सघिबद्ध होकर उसे हराने का प्रयास करने लगते। आधुनिक काल में राज्य व्यवस्था का विकास निम्न क्रम से हुआ —

पहला काल

राज्य व्यवस्था के विकास का प्रारम्भ विचारको ने १६४८ से माना है जबकि वेस्ट फेलिया (West Phalia) की सन्धि के मधीन ब्रिटेन, फ्रांस तथा स्पेन का राष्ट्रीय राज्यों के रूप में उदय हो चुका था। राजनीति पर से धर्म का प्रभाव हटने लगा। इस समय के विचारक मॅकियावेली (Machiavelli), बोदा (Bodin), ग्रोसियस (Grotius) आदि की रचनाओं में धर्म निर्बल स्वतन्त्र राज्य का समर्थन किया गया। यद्यपि इस काल से पहले भी राज्य एवं उनका आपसी सम्बन्ध वर्तमान था किन्तु ये राज्य न तो राष्ट्रीय थे और न इनके पास सम्प्रभुता जैसी कोई चीज ही थी। वेस्ट फेलिया की सन्धि में राज्य व्यवस्था का जो रूप पैदा हुआ वह आज भी स्थित है, अर्थात् 'एक ही विषय में अनेकों सम्प्रभु राज्यों का अस्तित्व' आज भी पूर्ववत् बना हुआ है। समय के अनुसार इस राज्य व्यवस्था में अनेकों परिवर्तन व प्रभाव पड़े जिनके कारण यह विकसित होती चली गई। पामर तथा परकिन्स के मत में राज्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले मुख्य मुख्य विकास [Developments] हैं—प्रतिनिधि सरकार, औद्योगिक क्रांति, जनसंख्या का परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास, कूटनीतिक तरीकों का विकास, राष्ट्रों की आर्थिक परतिभरता, भगवों के निपटारे के शांतिपूर्ण साधनों की स्थापना, आदि आदि।

दूसरा काल

राज्य व्यवस्था के विकास का दूसरा काल वेंस्ट फेलिया व यूट्रेक्ट (Utrecht) की सन्धि के बीच का काल (१६४८-१७१३) है। लुई १४ वें (Louis XIV) ने इस काल में फ्रांस की सर्वोच्च शक्ति बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा को क्रियान्वित करने के प्रयास किये। इस समय फ्रांस, ब्रिटेन, हाब्सबर्ग तथा स्पेन के बीच औपनिवेशिक सर्वोच्चता (Colonial Supremacy) प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष हुआ। ब्रिटेन ने योरोप में शक्ति संतुलन बनाये रखने के लिए महाद्वीपीय राज्यों से सन्धियाँ कर ली तथा इस प्रकार उसने फ्रांस के पर काट दिये। फ्रांस को यूट्रेक्ट (Utrecht) की सन्धि के मधीन बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। इस सन्धि ने योरोपीय राज्यों को एक दूसरे से इतना बाध दिया कि दूसरों की प्रतिक्रिया का विचार किये बिना कोई राष्ट्र एक कदम भी नहीं चल सकता था।

तीसरा काल

यूट्रेक्ट सन्धि से लेकर विदना (Vienna) की सन्धि (१८१५) तक

का समय राज्य-व्यवस्था के विकास का तीसरा काल है। इस सन्धि के अनुसार जिन राष्ट्रों को प्रथम स्तर की शक्ति माना गया वे थे—ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रिया, रशिया, फ्रांस, प्रूसिया, स्वीडन, पुर्तगाल तथा स्पेन। इस काल में एक योरोपीय राज्य अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच से अग्रदृश्य हो गया। पोलैंड का विभाजन करके प्रूसिया, रशिया और आस्ट्रिया में उसे बांट दिया गया। काल में पश्चिमी 'गोलाद्ध' से एक नये राष्ट्र का उदय हुआ। अमेरिकन क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। ब्रिटेन, रशिया, प्रूसिया, आस्ट्रिया तथा फ्रांस प्रमुख शक्ति बने रहे जबकि स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और स्वीडन की शक्ति गिर गई, वे कम शक्ति वाले (Lesser powers) राष्ट्र बन गये। यूट्रेक्ट की सन्धि में जिस शक्ति सन्तुलन को स्थापना की गई थी, समय समय पर उसको अस्त-व्यस्त तो किया गया किन्तु पूरी तरह उसको नष्ट न किया गया। योरोप पर प्रभाव जमाने की सामर्थ्य किसी भी देश में न थी।

चौथा काल

सन् १८१५ से १९१४ तक के काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा निर्मित शक्ति-सन्तुलन बन रहा। क्रीमियन युद्ध तथा फ्रांको-प्रूसियन युद्ध द्वारा प्रमुख शक्तियों को दो बार चुनौती दी गई। किन्तु योरोप के शक्ति सन्तुलन को ये चुनौतियाँ अभ्यवस्थित न कर सकी। इस काल के कुछ प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं—

(i) बिस्मार्क की 'लोहा और खून' (Blood and Iron) की नीति के अधीन एकीकृत जर्मनी का उदय हुआ जिसे महाद्वीप पर से फ्रांस के प्रभाव को हटा कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लिया।

(ii) बल्कान्स (Balkans) में तुर्की की शक्ति घट जाने के कारण अनेक पराधीन व दास राज्यों को अपनी स्वतन्त्रता का स्वप्न पूरा करने का अवसर मिला, उनमें राष्ट्रीयता की भावना उदित होने लगी।

(iii) समुद्र पार (Overseas) के अनेक नवोदित राज्यों के समुदाय ने पश्चिमी गोलाद्ध में अमेरिका का दामन पकड़ लिया।

(iv) सूदूर पूर्व में जापान को सामन्तशाही से छुटकारा मिला। जापान को ब्रिटेन के साथ सन्धि थी, चीन तथा रूस को उसने हरा दिया था, पश्चिमी तौर-तरीकों को जापान ने अपना लिया था, इन सभी कारणों से जापान पूर्व का उगता हुआ सूर्य (The Rising Sun of the East) बन गया।

(v) विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने पर बड़ी शक्तियों के स्वार्थ एक से न रहे। प्रत्येक का स्वार्थ अलग-अलग हो गया। जिन शक्तियों के स्वार्थ विरोधी न थे तथा साथ ही विरोधी के विरोधी थे वे शक्तियाँ आपस में मिल गईं और इस प्रकार विश्व रणमंच पर एक दूसरे के खून के प्यासे दो गुट बन गये। एक था ट्रिपल एलाइंस (Triple Alliance) जिसमें आस्ट्रिया, जर्मनी और इटली शामिल थे। दूसरा ट्रिपल आला (Triple Entente) पहला था। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस व रूस मिले हुए थे। पहली १८८२ में तथा दूसरी १९०७ में बन ई गई थी। अमेरिका अभी तक विश्व राजनीति से उदासीन होकर बैठा था, ब्रिटेन को यह बात खलती थी। जापान से समझ करके तथा अन्य अनेक प्रयास करके उसने अमेरिका को रणमंच पर उतारने का सफल प्रयत्न किया।

प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व राज्य-व्यवस्था (State System) केवल योरोप महाद्वीप तक ही सीमित थी किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न सन्धि-विग्रहों ने राज्य व्यवस्था को विश्व-व्यापी (World-wide) बना दिया। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार योरोप अब भी एक दृष्टि से राज्य व्यवस्था का केन्द्र बना हुआ है किन्तु आज जो तीन सबसे शक्तिशाली राज्य हैं उनमें से एक भी पूरी तरह योरोपियन शक्ति नहीं है और इन अर्थ में यह कहा जा सकता है कि योरोपीय राज्य व्यवस्था अब भूतल की गाथा बन गई है तथा उसका स्थान अब विश्व-व्यापी राज्य व्यवस्था द्वारा ग्रहण कर लिया गया है।

भूतल की योरोपियन राज्य व्यवस्था और आज की विश्व-व्यापी राज्य व्यवस्था के बीच कुछ भिन्नताएँ वर्तमान हैं जैसे कि योरोपियन राज्य-व्यवस्था में बड़ी शक्तियों की संख्या ६ या ८ होती थी तथा इन शक्तियों के स्वार्थ महाद्वीपीय या क्षेत्रीय सीमाओं में धिरे रहते थे। किन्तु आज की विश्व-व्यापी राज्य-व्यवस्था में केवल दो या तीन ही सर्वोच्च शक्तियाँ (Super-powers) हैं। इन शक्तियों के स्वार्थ भी क्षेत्रीय न होकर विश्व व्यापी (Universal) हैं। यह भ्रम रहने पर भी अनेक विचारकों का मत है कि राज्य-सरकार का मूल ढाँचा (Basic Design) पहले जैसा ही है। उनका कहना है कि आज भी राज्यों की एक बड़ी सख्या सहप्रस्तित्व पर आधारित है, सभी राष्ट्र अपने विशेष स्वार्थों और भावनाओं से प्रभावित होकर कार्य करते हैं, सभी सम्प्रभुता के सिद्धांत को मानते व जोर देने हैं। इसके साथ ही सभी राष्ट्रों की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति का विकास

करना होता है। ये सब विशेषतायें राज्य व्यवस्था अथवा राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था में पहले भी थी और अब भी हैं।

प्रादेशिक राज्य का जन्म और अन्त (The Rise and Fall of the Territorial States)

परम्परागत रूप से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सांस्कृतिक व्यवस्था या आधुनिक राज्य व्यवस्था को अराजकतापूर्ण समझा जाता है। इसका कारण यह है कि इसका आधार असमान रूप से वितरित शक्ति थी। इसकी इकाइयाँ स्वतन्त्र और सम्प्रभु राष्ट्र राज्य थे जिनकी मजबूत शक्तियों द्वारा सर्वव्यवस्था की जाती रही है तथा ये शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के आधार पर ही अपने अस्तित्व को बनाये रख सके। मध्यकालीन व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की इकाइयाँ उच्च सत्ता एवं उच्च कानून के अधीन रहती थी। दूसरी ओर आधुनिक राज्य व्यवस्था वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अधीन रहती है। इस व्यवस्था में राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा तथा कानून के शासन का प्रमुख स्थान है। आधुनिक राष्ट्र राज्य में जो एकरूपता एवं सम्बद्धता पायी जाती है वह उसे उन राष्ट्र राज्यों से पृथक् बना देती है जो पृथक् स्वतन्त्र एवं सम्प्रभु शक्ति युक्त थे। यह देखा जाता है कि राष्ट्र राज्य की एकरूपता एवं एकरसता का कारण न तो कानून का क्षेत्र है और न ही राजनैतिक। वरन् यह एकता उस राज्यपन के कारण पैदा होती है जो इसकी भौतिक सीमाओं तथा प्रादेशिक घेरे के कारण पैदा होता है। राज्य अपनी रक्षात्मक आवश्यकताओं के कारण जो किलेबंदी करता है उसके द्वारा वह एक निश्चित प्रदेश में सीमित बन जाता है और इसके आधार पर उसे पहचानना सरल हो जाता है। इसे हम आज के राज्य की प्रादेशिकता कह सकते हैं। एक राज्य के चारों ओर सीमा रेखाएँ होती हैं जिनके कारण वह विदेशी घुमपैठ से अपने आपको सुरक्षित रख सकता है और इस प्रकार इसे वह अपनी सीमाओं में रहने वालों के लिये सुरक्षा की एक अन्तिम इकाई बना देता है।

इतिहास के दौरान जिस इकाई ने मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान की वही मूल राजनैतिक इकाई बन गई। कालान्तर में लोग केवल उस सत्ता को ही सत्ता मानते हैं जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। अणु शक्ति के विकास ने राष्ट्र राज्य की पुरानी सीमाओं को तोड़ दिया है। अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र के आविष्कार ने राज्यों की किलेबंदी और उसके आधार पर की

जाने वाली सुरक्षा की आशाओं को समाप्त कर दिया है। इस विफलता के कारण परम्परावादी शक्ति की मान्यताएँ बदली हैं। इस प्रकार प्रादेशिकता का युग निकल चुका है और इसलिये इससे सम्बन्धित स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता आदि मान्यताओं की उपयोगिता भी सदेहशील बन जाती है। कुछ विचारकों का कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति व भणुशक्ति के विकास ने राज्यों की शक्ति स्थिति में परिवर्तन अथवा किया है किन्तु इससे अन्तर्राष्ट्रीय भ्रातृत्वता, शक्ति सन्तुलन या शक्ति की राजनीति आदि की मान्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सारी बातें राज्यों की प्रादेशिक बनावट के क्षेत्र में पाती हैं और इनको राज्यों के परम्परागत रूप से भिन्न नहीं समझना चाहिये वरन् सभी के विकास की भाँति की सीढ़ियाँ माननी चाहिये। एक नये युग का सूत्रपात हम उस समय मान सकते हैं जब प्रादेशिक शक्ति का आधार और सुरक्षात्मकता समाप्त हो जाय। ऐसा इस युग में हो रहा है किन्तु इस वर्तमान को समझने के लिए हमें पुरातन व्यवस्था की प्रकृति एवं जन्म का अधिक निष्पक्ष से अध्ययन करना होगा।

वर्तमान प्रादेशिक राज्यों के जन्म से हमारा मतलब यह है कि विभिन्न देशों में सामन्तवादी भ्रातृत्वता के स्थान पर पूर्ण व्यवस्थित केंद्रीयकरण आने लगा। इसने घेरने निश्चित प्रदेश पर नौकरशाही सेना घोर कर लगाने की शक्ति को सहायता से शासन किया। विदेश सम्बन्धों की दृष्टि से इस युग में शक्ति और सत्ता के मध्यकालीन पद सोपान के स्थान पर अनुरक्षा और अव्यवस्था का प्रभाव रहा। इस अव्यवस्था और अनुरक्षा को शक्ति सन्तुलन द्वारा कुछ कम किया गया किन्तु शक्ति सन्तुलन को सदैव ही चुनौती दी जाती रही।

मध्य युग में जब सम्राट शक्ति की स्थापना में असमर्थ सिद्ध हुआ तब तक यह विचार पर्याप्त फैल चुका था कि राज्यों का प्रादेशिक सहस्रस्थित पवित्र रोमन साम्राज्य की अपेक्षा शक्ति की प्रविष्ट शारंगी दे सकता है किन्तु इस विचार के दौरान प्रादेशिकता मुश्किल से रह सकती थी क्योंकि जिस प्रकार मध्य युगीन नगर अपनी चहारदीवारी के अन्तर्गत आक्रमण से स्वतन्त्र रह सका वो उस तरह यहाँ स्वतन्त्रता नहीं थी। सैनिक तकनीकी में होने वाले नवीन विकासों की शक्ति बन्दूक के पाठडर की शक्ति ने आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक सम्बन्धों की बनावट में एक सही शक्ति का प्रादुर्भाव किया क्योंकि इसका रक्षा एवं सुरक्षा की इकाइयों पर भारी प्रभाव पड़ा। सारे यूरोप में अनुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। नये या पुराने सम्प्रभुओं को बड़े क्षेत्रों का प्रत्यक्षक मानने से पूर्व यह जानना जरूरी था कि

वे अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर पूरे प्रदेश का नियंत्रण कर सकेंगे या नहीं। पहले किलेबन्दी से पूर्ण नगरों को जो स्थान प्राप्त था वह धब धब आकार के राज्यों ने ले लिया किन्तु नयी इकाइयों को उस समय तक एकीकृत नहीं सम्मत्ता जा सकता जब तक इसके अन्दर की सभी स्वतन्त्र किलेबन्दियाँ सम्प्राप्त न हो जाय और उनके स्थान पर नई केन्द्रीय शक्ति द्वारा सीमाओं की पक्कियाँ निर्धारित न कर दी जायें। इस नवीन व्यवस्था के आधीन शांति और सुरक्षा की व्यवस्था हुई। कुछ एक विनियमित सैनिक प्रक्रिया बन गया। एक देश दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता था जब वह उनकी सीमाओं का तोड़न का प्रमाण करे। इस प्रकार प्रादेशिक राज्य के मूल ढांचे की स्थापना की गई जो वर्तमान राज्य व्यवस्था के सांस्कृतिक समय के दौरान चलता रहा। इस आधार भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक नई व्यवस्था व मान्यताएँ जन्म ले सकती थीं। मगहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रादेशिक राज्य के आधार पर नई मान्यताएँ विकसित की गई।

प्रादेशिकता के परिणामस्वरूप ऐसी मान्यताओं एवं मस्यारों ने जन्म लिया जो आधुनिक राज्य व्यवस्था के पारस्परिक सम्बन्धों को विशेषता है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून वर्तमान परिस्थितियों में विकसित हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की भाँति ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून मूलतः विरोधानाशपूर्ण सम्मत्ता जाता है क्योंकि यह कानून सम्प्रभु इकाइयों को वायने का दावा करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल तभी क्रियान्वित हो सकता है जब सम्प्रभु स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व रहे। आधुनिक युग में इसका विकास अभी सम्भव है जब यह उनकी प्रादेशिकता को अभिव्यक्त करे और उनकी सम्प्रभुता को स्थान में रखे।

परम्परागत राज्य व्यवस्था की एक अन्य विशेषता शक्ति का अनुलन है। वर्तमान काय में अनुलन के निर्पेधात्मक पहलुओं के एकपक्षीय रूप पर जोर देने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अब इसके सकारात्मक पहलु की धार जोर दिया जाता है जिसके अनुसार एक शक्ति की प्रभाववादी सामर्थ्य का दूसरी शक्ति को पूर्णतः समाप्त करने से रोका जाता है। पुरातन व्यवस्था के रुढ़िवादी रूप की अधिक मौनिक विशेषता उसका समाज के रूप में चरित्र था। उस समय के सभी देश परस्पर एक परिवार की इकाई के रूप में रहते थे। पुरानी व्यवस्था की एक अन्य विशेषता यह थी कि उसमें ऐसे उदाहरणों का अभाव था जिनमें युद्ध के कारण अथवा शक्ति राजनीति को घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई देश पूरी तरह समाप्त हो गया हो। राष्ट्रवाद का जन्म

होते ही विश्व समाज की इकाइयों का प्राग्निर्णायक एष राष्ट्रीय समूहों के रूप में व्यक्तिकरण हो गया। बई स्थानों पर राष्ट्रवाद के जन्म के कारण नये राज्यों की उत्पत्ति हुई। यह नये राज्य बहु राष्ट्रीय या उपनिवेशवादी साम्राज्यों से भिन्न हुए थे।

राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था के कारण नई समस्याएँ सामने आयी। सब सुरक्षा के लिए सन्तोषित व्यवस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी। अब यह समझा जाने लगा कि पुरानी व्यवस्था का सुरक्षात्मक कार्य केवल सापेक्षिक बरदान था। राष्ट्रवाद ने राज्यों के निरन्तर अस्तित्व का आश्वासन दिया। पुराने और नये राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई व्यवस्था की माग की जाने लगी। बैसे सामूहिक सुरक्षा की शक्ति की राजनीति का स्पष्ट विरोधी तत्व नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह प्रादेशिक राज्यों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने का एक प्रयास था।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही ऐसी प्रवृत्तियाँ सामने आयीं जो परम्परागत व्यवस्था के व्यवहार के लिए खतरनाक थी। प्रत्यक्ष रूप से भयवा अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रादेशिक राज्य की उस विशेषता पर प्रभाव रखती थी जो समान प्रकृति के अन्य राज्यों के साथ इसके स्वतन्त्र सह-अस्तित्व की सर्वाधिक गारन्टी थी। इनमें से अनेक प्रवृत्तियों का सबब युद्ध से भयवा युद्ध संचालन के तरीकों से था। सम्पूर्ण युद्ध की स्थिति के कारण राज्यों की परम्परागत सुरक्षा की दीवारें मिटने लगीं। ऐसा होने के बाद युद्ध तथा प्रादेशिक शक्ति और सम्प्रभुता के बीच का सबब बदल गया। वर्तमान काल के नये तथ्यों की प्रभावशीलता के आधार पर क्रमशः चार भागों में बाँटा जा सकता है। प्रथम, प्राथिक घेरे की सम्भावना, दूसरे, सैद्धांतिक व राजनैतिक प्रवेश, तीसरे हवाई-युद्ध और चौथे अणु-युद्ध। प्रादेशिक राज्य के पतन के बाद सारी सामग्रियाँ और कपन निरर्थक बन गये जो दीवाल खींच कर तथा खाइयाँ खोदकर जनता की रक्षा का उपदेश देते थे।

राष्ट्र राज्यों की स्थापना (The Establishment of Nation State)

अनेक स्थानों और समयों में विभिन्न जातियों ने जनता के रूप में अपने आपको विलीन कर लिया और जनता राष्ट्रों के रूप में उदित हुई। कुछ राष्ट्रों ने साम्राज्य बना लिये। बाद में साम्राज्य छोटे-छोटे भागों में बँट गये और उनकी जनसंख्या ने बढ़ी इकाइयाँ बनाने का प्रयास किया। इस

प्रकार से यह प्रतिक्रिया अधिकांग इतिहास में पायी जाती है। राष्ट्र राज्यों को परम्परागत रूप से अपने सम्बन्ध नियमित करने तथा अपनी सुरक्षा बनाये रखने के लिए स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है और उनके ऊपर कोई सर्वोच्च सम्प्रभु नहीं होता। बीसवीं सदी के प्रारम्भ में संयुक्त राज्य अमरीका और जापान ने अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में भाग लेना प्रारम्भ किया उससे पूर्व राष्ट्र-राज्य व्यवस्था केवल योरोप तक सीमित थी। उस समय राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त को जो आदर प्रदान किया जाता था उसके कारण शक्ति की राजनीति के होते हुए भी राष्ट्रीय व्यवहार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये। वैसे योरोप की सुरक्षा की भीव मौलिक स्थायित्व और प्रत्येक राष्ट्रीय प्रदेश की सुरक्षात्मकता पर आधारित थी। उस समय प्रत्येक राज्य इतना बड़ा था कि वह अपने नागरिकों को रहने की जगह प्रदान कर सके और आक्रमण का विरोध कर सके। उस समय अभीमित प्रभार के लिए न तो अवसर थे और न ही आवश्यकता। इसलिए योरोप के राज्य अपने कार्यों को सीमित युद्ध एवं शक्ति संतुलन के प्रयासों आदि के द्वारा विनियमित कर लेते थे।

कुछ विचारकों का कथन है कि १९वीं शताब्दी के योरोप में कुछ छोटे मोटे सघ को छोड़ कर मूलतः एक सुरक्षा का वातावरण व्याप्त था और इस कारण अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जनता की जिज्ञासों को सगठित करने का प्रयास नहीं किया। योरोपीय शक्तियाँ धीरे-धीरे समुद्र पार के क्षेत्रों में भी बढ़नी जा रही थीं इसमें उनकी सुरक्षा को सहारा मिल रहा था। दूसरी ओर ऐसे भी विचारक हैं जो मानते हैं कि उन्नीसवीं सदी में अनेक नवीन प्रवृत्तियाँ ऐसी थी जिन्होंने प्रादेशिक राज्य के रूप को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया। इन प्रवृत्तियों ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू करने में कठिनाई उत्पन्न की।

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद योरोपीय शक्ति व्यवस्था खण्डित हो गई। सन् १९३० के उग्र राष्ट्रवाद ने जो भ्रष्टाचर्य की स्थिति पैदा की उसका सामना राष्ट्र सघ के सामूहिक सुरक्षा मिशन द्वारा नहीं किया जा सका। नये राष्ट्रीय राज्यों एवं उनके अल्पमण्डलों के बीच मघप होने लगा और इटली तथा जर्मनी आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षियों से पूर्ण समर्थनवादी शक्तियों ने शीघ्र ही उसमें हस्तक्षेप करना प्रारम्भ किया। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना इतनी उग्र हो गयी जिसका योरोप में कहीं उदाहरण नहीं मिलता। भीषणीकरण के कारण उत्पन्न निराशा

घोर प्रचुरक्षा, धर्मों की सधि का प्रसतोप, साम्यवाद का खतरा एवं वाइमर गणराज्य की क्रियाहीनता ने जर्मनी के लोगों को एडोल्फ हिटलर के हाथों में सौंपने के लिए प्रेरित किया। हिटलर ने जातीय राष्ट्रवाद के मिष्टान्त का उपदेश दिया जिसके माधुर पर जर्मनी के लोगों को अधिक-अधिकपूर्ण सामाजिक अस्तित्व प्रदान किया जा सके। सन् १९३० के मध्य-काल तक राष्ट्रवाद पर आधारित राजनैतिक व्यवस्था का दिवालिदापन सामने आ गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद सर्वोच्च शक्तियों के बीच जो मन-मुटाव पैदा हुआ उसने घनेक राष्ट्रों के इस दावे की सीमाएँ सामने रख दी कि वे राजनैतिक सम्प्रभुता की दृष्टि से समान अधिकार रखते हैं। इस धारणा पर आधारित किसी भी विश्लेषण का भी विरोध किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में राष्ट्र राज्य अब भी अग्रिमताओं की तरह काम करते रहे किन्तु उनके बीच स्थित शक्ति की असमानता ने उस व्यवस्था का रूप बदल दिया जिसमें राज्यों को समान राजनैतिक इकाई माना जाता है।

सर्वोच्च शक्तियों तथा अन्य राज्यों के बीच स्थित शक्ति की असमानता के कारण शक्ति संतुलन की व्यवस्था दो गुटों की व्यवस्था (Bipolar System) में परिवर्तित हो गई। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान व्यवस्था में अस्थायित्व बढ़ गया है। विश्व युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप जिन दो गुटों में बँटा उनमें शान्ति के लिए किसी प्रकार के समझौते पर पहुँचने की कोई इच्छा नहीं थी तथा सहप्रतिस्पर्धा के लिए वे विस्तृत भी तैयार नहीं थे। इसी स्थिति ने एक लेखक को राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के स्थान पर गुट के कलाकार शब्द का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। इस गुटबाजी के काल में यदि सभी नहीं तो अधिकांश देश यह सोचते थे कि उनकी सुरक्षा केवल सभी बनी रह सकती है जबकि वे गुट के प्रभाव-शील या निर्देशक देश की सहमति के अनुसार कार्य करें एवं अपने व्यवहार को एकीकृत कर लें। जब एक बार कोई सदस्य किसी गुट में शामिल हो जाता है तो उस गुट में निकलना उसके लिए एक कठिन काम बन जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा करने में वह सुरक्षा का अनुभव नहीं करता। सचकार शक्ति संतुलन की व्यवस्था से निम्न दो गुट की व्यवस्था में प्रत्येक गुट अपने विरोधी को नीचा दिखाने के लिए सदैव संघर्षरत रहता है। इसमें प्रभाव के क्षेत्र तथा प्रत्येक गुट के नए सदस्यों की स्थापना सतत में पड़ जाती है। यह कहा जाता है कि जब देश ठोले-ठोले रूप से गुट के रूप में एकीकृत होते हैं तो इनके विभिन्न राष्ट्रीय मूल्य प्रायः मन-मुटाव और असहमति के स्रोत

बन जाते हैं। सन् १९५६ के स्वेज नहर-विवाद में, इस समय के वियतनाम विवाद में तथा अरब-इजरायली सघर्ष में पश्चिमी गुट के विभिन्न देशों ने जो हल अपनाया वह इस बात का प्रतीक है। यहाँ तक कि साम्यवादी गुट में भी इतने मतभेद व अंतर विभिन्नताएं आ गई हैं कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध दो विरोधियों की भाँति बटु बन गए हैं। राष्ट्रीय राज्य की भावना ने यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, अलबानिया, चीन आदि राज्यों को अलग अलग रूप से प्रभावित किया है।

दो गुटों की राजनीति के समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में राज्यों की दो अतिरिक्त श्रेणियाँ भी वर्तमान थीं। पहली श्रेणी असलमनता की ओर दूसरी निष्पक्ष राष्ट्रों की श्रेणी थी। स्विट्जरलैण्ड और स्वीडन जैसे निष्पक्ष देशों ने यह सोचा कि वे अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा अपनी प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर रह कर, कर सकेंगे और आक्रमण का विरोध कर सकेंगे। दूसरी ओर भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, अरब सघर्ष आदि असलमन शक्तियों ने शीत युद्ध की महाशक्तियों के बीच स्वार्थ पर आधारित एक संघर्ष माना और इसमें स्वयं को उलझाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। आज-कल गुटबन्दी की व्यवस्था का रूप पर्याप्त बदल चुका है। गुटों में एकता के स्थान पर अनेकता आ गई है और दो गुटों का स्थान विभिन्न क्षेत्रीय सगठनों ने ले लिया है। अणुशक्ति के विकास के कारण राष्ट्र राज्य व्यवस्था पर्याप्त प्रभावित हुई। इसके कारण महाशक्तियाँ और अधिक शक्ति-सम्पन्न बनी हैं तथा अध्रमान देश भी इसे अपनाकर प्रधानता की ओर उन्मुख हो रहे हैं। अणुशक्ति के विकास ने दो गुटों की राजनीति को विरोधी रूप से प्रभावित किया और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के विकास में एक नया मोड़ दिया।

राज्य व्यवस्था की विशेषताएं (The Features of State System)

राज्य व्यवस्था को जब व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाता है तो उसकी कई एक विशेषताएं सामने आती हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिनको राज्य व्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। इन विशेषताओं के अभाव में स्वयं राज्य व्यवस्था ही समाप्त हो जायगी। राज्य जब दूसरे राज्यों से सन्धियाँ करता है या वह उनके साथ युद्ध में उलझता है तो इसके पीछे कई एक कारण होते हैं। इन कारणों की प्रकृति एवं प्रसार सामान्य होता है। ये कारण या तब किसी भी राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय

व्यवहार की प्रेरणा प्रत्यवा आधार होने हैं। पामर तथा पर्किन्स के मतानुसार राज्य व्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के व्यवहार को संचालित, निर्देशित, नियन्त्रित और प्रेरित करती हैं।^१ प्राणकी परिस्थितियों में भी इन विशेषताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय घटना का कारण या परिणाम जानने तथा मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें इन विशेषताओं में देखा जाना आवश्यक तथा उपयोगी बन जाता है। इन तीन विशेषताओं में प्रथम राष्ट्रवाद का सिद्धान्त है + राष्ट्रवाद को मनोवैज्ञानिक, तार्किक या भावनात्मक गुण माना जा सकता है। यह एक राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है और उन बातों का समर्थन करने के लिए उस देश के लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें हम राष्ट्रीय हित कह सकते हैं। राज्य व्यवस्था की दूसरी विशेषता सम्प्रभुता की मान्यता (The Concept of Sovereignty) है। यह एक कानूनी विचारधारा होती है। सम्प्रभुता के द्वारा एक देश को उसके घरेलू मामलों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में एक प्रसीमित शक्ति प्रदान की जाती है। राज्य व्यवस्था की तीसरी विशेषता राष्ट्रीय शक्ति का सिद्धान्त (The Principle of National Power) है। राष्ट्रीय शक्ति एक देश की ताकत होती है। इसके द्वारा राज्य को वह कार्य करने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है जिन्हे वह करना चाहता है। राष्ट्रीय शक्ति अनेक तत्वों से मिल कर बनती है। ये तत्व दिखाई देने वाले और दिखाई न देने वाले दोनों ही प्रकार के होते हैं। राज्य व्यवस्था की ये तीन प्रमुख विशेषताएँ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तीन आधार शिखाएँ हैं और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सुगम एवं ग्राह्य बनाने के लिए इन विशेषताओं का भर्ष, प्रकृति, भेद एवं इतिहास जानना अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेगा।

राष्ट्रवाद का सिद्धान्त (The Doctrine of Nationalism)

राष्ट्रीय समाज अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की इकाइयाँ होते हैं। राज्य को इस राष्ट्रीय समाज का राजनैतिक संगठन माना जाता है। पैडैल्फोर्ड तथा लिंकन (Padelford and Lincoln) के कथनानुसार राष्ट्रवाद विषय की घटनाओं में राजनैतिक परिवर्तन और क्रियाओं की प्रमुख गतयात्मक शक्ति

1. Palmer and Perkins, op. cit., P 2.

होता है। राष्ट्रवाद यूरोप और अमरीका के राष्ट्रों की रूप रचना में एक प्रमुख तत्व रहा है तथा इसने अनेक युद्धों की जड़ का काम किया है। आधुनिक काल में राष्ट्रवाद ने अन्तीसवीं शताब्दी के यूरोपीय साम्राज्यवाद को समाप्त कर दिया है। राष्ट्रवाद के सहारे ही एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देश सम्प्रभु स्वतन्त्रता के अधिकार का दावा करने लगे हैं। राष्ट्रवाद के माध्यम से एक प्रदेश की जनता ने अपने आपको एकीकृत किया और स्वतन्त्रता प्राप्त की। दूसरी ओर राष्ट्रवाद ने विभाजनशील दृष्टिकोण की रचना को प्रोत्साहित किया है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, संचार एवं सहयोग में प्रतिरोधक का कार्य किया है। राष्ट्रवाद की मान्यता को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के लिए मूल तत्व माना जाता है। शार्प तथा किर्क (Sharp and Kirk) के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए राष्ट्रवाद की जानकारी उतनी ही अपरिहार्य है जितना एक घर के सारे कमरों में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए उसके मुख्य द्वार की चाबी लेना जरूरी है। वर्तमान काल में यद्यपि प्रादेशिक राज्य एक भौतिक इकाई के रूप में नहीं रह पाया है क्योंकि अणुशक्ति के विकास ने उसकी प्रादेशिक सीमाओं को महत्वहीन बना दिया है। इतने पर भी एक राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र के प्रति पूरी स्वामीभक्ति रखते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का लक्ष्य, व्यवहार, नीति एवं रूप सम्प्रभु राज्यों के व्यवहार का कार्य बन जाए। यदि हम राष्ट्र राज्य व्यवस्था के कार्यों को समझना चाहते हैं तो हमें पहले उन परिस्थितियों को समझना चाहिए जो राष्ट्र राज्य की भौतिक इकाई बना देती हैं। उसके बाद उस प्रभाव की परीक्षा करनी चाहिए जो इन इकाइयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर रखा जाता है। मैकलेलन, ओल्सन तथा सोन्डरमैन (Mc Lellan, Olsan, and Sondermann) के कथनानुसार यदि मनुष्य राष्ट्रों के रूप में संगठित नहीं होते और अपनी सरकारों की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं होते तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्तित्व नहीं होता। राष्ट्रवाद का सिद्धान्त इतना प्रचलित और सामान्य बन चुका है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित किसी गम्भीर वाद-विवाद में इसका उल्लेख न किया जाए तो इसका कारण यही समझा जाता है कि इसके महत्व को समझा जा चुका है। प्रायः प्रत्येक देश के नेता राष्ट्रीय हित को और राष्ट्र के प्रति स्वामीभक्ति को दुनिया की हर चीज से अधिक मूल्यवान समझते हैं।

कभी कभी तो राष्ट्रवाद धर्म और नैतिकता में भी ऊपर उठ जाता है। राष्ट्रवाद में रहे जाने वाले विश्वास की मात्रा के आधार पर इसे प्रायः धर्म की सजा भी दी जाती है। कुछ लेखक इसको धर्म-निर्पेक्ष धर्म (Secular Religion) कह कर पुकारते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण मनुष्य का धर्म में विश्वास उठ चुका है किन्तु इस नये धर्म अर्थात् राष्ट्रवाद के प्रति उसकी पूरी स्वाधीनता है। जिस प्रकार पहले धर्म के नाम पर जानवरों की हत्या को पवित्र माना जाता था उसी प्रकार आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत के अनेक अमानवीय कार्यों को राष्ट्रवाद के नाम पर उचित सिद्ध किया जाता है।

राष्ट्र और राष्ट्रवाद

(Nation and Nationalism)

अंग्रेजी के नेशन (Nation) शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द नेसियो (Natio) से हुई है जिसका अर्थ होता है 'जन्म या जाति'। आज राष्ट्रवाद केवल जनसंख्या को ही इंगित नहीं करता, भास की राज्यशक्ति के समय राष्ट्र शब्द को बहुत लोकप्रियता प्राप्त हो गई तथा इसका प्रयोग देशभक्ति (Patriotism) के अर्थ में किया जाने लगा, किन्तु हमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र (Nation), राष्ट्र राज्य (Nation-State), देश-प्रेम (Patriotism) आदि से भिन्नता रखता है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के अर्थों के बारे में नीचे प्रायः भ्रम पैदा हो जाना करता है। 'राष्ट्र' शब्द मुख्यतः राजनैतिक पहलू पर जोर देता है तथा एक ऐसे जन-समुदाय का चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है जो राजनैतिक दृष्टि से या तो स्वतन्त्र हो अथवा स्वतन्त्रता पाने के लिए छटपटा रहा हो। दूसरी ओर राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक घारणा है। राजनीति में इसका संबंध होना आवश्यक नहीं है। एक ही सत्त्वर्ति तथा नैतिक मान्यताओं वाले जन समुदाय में एक ही राष्ट्रियता का होना माना जायगा। इस अर्थ में एक राष्ट्र के अन्दर अनेक राष्ट्रियताओं का निवास सम्भव है। अर्थात् यह हो सकता है कि एक राष्ट्रियता विदेशी आसन के अधीन रह रही हो क्योंकि संप्रभुता एवं स्वतन्त्रता जो 'राष्ट्र' की आत्मा होती है, राष्ट्रियता के अस्तित्व के लिए उतनी आवश्यक नहीं होती। सोवियत रूस तथा ग्रेट ब्रिटेन के उदाहरणों को ध्यान में रखने पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। ब्रिटेन एक राष्ट्र है किन्तु उनमें चार राष्ट्रियताएँ निवास करती हैं—अंग्रेज, स्कॉच, उत्तरी आयरिश तथा वेल्श। इस प्रसंग में हेज (C. J. H. Hayes) महोदय का कथन युक्ति संगत है। वे लिखते हैं—“एक राष्ट्रिय राज्य (Nation State) सदा ही

राष्ट्रीयता पर अवलम्बित रहता है, किन्तु राष्ट्रीयता का अस्तित्व राष्ट्रीय राज्य के बिना भी हो सकता है। राज्य मूलतः राजनैतिक होता है जबकि राष्ट्रीयता मुख्य रूप से सांस्कृतिक होती है और संयोगवश वह राजनैतिक हो जाती है।”

राष्ट्रवाद का अर्थ एवं प्रकृति

(The Meaning and Nature of Nationalism)

राष्ट्रवाद एक भावनारमक तत्त्व है जो मानवीय व्यवहार में प्रदर्शित होता है। इस भावना से प्रभावित होकर लोग जो निर्णय लेते हैं अथवा जो कार्य करते हैं उसके आधार पर राष्ट्रवाद की प्रकृति का एक रेखाचित्र खींचा जा सकता है किन्तु यह रेखाचित्र अत्यन्त धुंधला, अनिश्चित एवं अस्थिर होता है क्योंकि मनुष्य का व्यवहार अध्ययन की दृष्टि से एक अस्थिर अंशल विषय होता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा देने वाले विचारक भी यह स्वीकार करते हैं कि इसकी किसी सतोपजनक परिभाषा पर पहुँचना बहुत कठिन है। वैसे ‘राष्ट्र’ हम व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो एकीकरण की भावना से युक्त होता है तथा जिमम दूसरों से पृथक्ता की चेतना रहती है। ‘राष्ट्र’ को या तो उसके व्यक्तिगत सदस्यों की वस्तुगत विशेषताओं के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है अथवा इन सदस्यों की विषयगत भावनाओं के माध्यम से या दोनों ही तरीकों के संयोग से। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्य इन्स्टीट्यूट ने राष्ट्रवाद पर सन् १९३६ में दी गई अपनी रिपोर्ट में इन विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सभी में नहीं तो अधिकांश राष्ट्रों में तो पाई ही जाती हैं। ये विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

१. राष्ट्र में एक सामान्य सरकार का विचार रहता है चाहे यह वर्तमान या भविष्य की वास्तविकता के रूप में हो अथवा भविष्य की आकांक्षा के रूप में।

२. समस्त व्यक्तिगत सदस्यों के बीच कुछ घनिष्टता रहनी है। जिन लोगों के बीच इस प्रकार सम्पर्क नहीं रहता वे किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते।

३. थोड़ा बहुत परिभाषित प्रदेश होता है। इजराइल की स्थापना से पूर्व यहूदियों को इस विशेषता का एक अणुवाद माना जाता था।

४. कई ऐसी विशेषताएँ भी होती हैं जो एक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से तथा गैर-राष्ट्रीय समूहों से अलग करती हैं। भाषा को इन विशेषताओं में मुख्य माना जाता है। वैसे अनेक अणुवाद ऐसे हैं जहाँ पर अनेक भाषाएँ होती

जाती है। दूसरी ओर कुछ भाषायें ऐसी हैं जिनको कई राष्ट्रों में बोला जाता है। जाति, धर्म एवं राष्ट्रीय चरित्र आदि कुछ विशेषतायें राष्ट्रीयता की सामान्य विशेषताओं के उदाहरण हैं।

१ राष्ट्र में कुछ हित (Interests) ऐसे होते हैं जो सभी व्यक्तिगत सदस्यों के लिए सामान्य होते हैं। राज्य के साधन द्वारा राष्ट्र अनेक सामाजिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने का कार्य करता है। एक राष्ट्र के होने का अर्थ है अनेक सामान्य हितों का भागीदार बनना।

२ एक राष्ट्र के व्यक्तिगत सदस्यों के मस्तिष्क में राष्ट्र के चित्र से संबंधित सामान्य भावना या इच्छा का कुछ मात्रा में अस्तित्व रहता है।

विषयगत (Subjective) परिभाषाओं के अनुसार राष्ट्रवाद मस्तिष्क की एक स्थिति है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक प्रतिनिधि सरकार (Representative Government) में यह बताया है कि एक राष्ट्र के सदस्यों के बीच सामान्य सदभावना रहती है जिसके कारण वे एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए स्वेच्छा से तैयार रहते हैं। वे एक ही सरकार के आधीन रहना चाहते हैं तथा यह इच्छा रखते हैं कि यह सरकार स्वयं उनके द्वारा या उन्हीं के किसी भाग की होनी चाहिये। रेनन (Renan) ने १८८२ में राष्ट्र को एक 'आत्मा' तथा 'आध्यात्मिक सिद्धांत' कहा था। पैडलफोर्ड तथा लिंकन (Padleford and Lincoln) के कथनानुसार एक राजनैतिक शक्ति के रूप में 'राष्ट्रवाद' राष्ट्रीयता के विचार के धारे में एक विचारधारा तथा उस विचारधारा के राजनैतिक संस्थाकरण का राष्ट्रीय राज्य में संयोग है।^१ राष्ट्रवाद की शक्ति का आधार राष्ट्रीय एकता की भावना होती है। यह भावना जाति, भाषा, सामान्य इतिहास एवं अनुभव या धर्म आदि से बनपनी है। राष्ट्रीय राज्य अपने सदस्यों के राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन को प्रतिबिम्बित करता है। यह राज्य अपने सदस्यों पर दमनकारी शक्ति रखता है तथा उनके नाम पर उस प्रदेश में सम्प्रभुता का दावा करता है जहाँ पर वे रहते हैं।

राष्ट्रवाद को परिभाषित करने की एक कठिनाई यह भी है कि इसके अनेक रूप होते हैं। मूलतः यह एक भावना है जो राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिम्बित करती है तथा एक व्यक्ति में उसके देश के प्रति स्वामी शक्ति को

1 Padleford and Lincoln, The Dynamics of International Politics, PP. 70-71

प्रेरित करती है। एक व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति बड़ी स्वाभिमन्न होता है। इसके पीछे अनेक कारण हैं। इसका मूल कारण है कि व्यक्ति अपने राष्ट्र के साथ अपने अच्छे जीवन का एकाकार कर लेता है। वह यह समझने लगता है कि उसका जीवन उस समय अधिक अर्थपूर्ण बन जायेगा जबकि वह अपने राष्ट्र के उद्देश्यों, सकलताओं और यहाँ तक कि असफलताओं में भागीदार बनेगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी चेतना है जो लोगों के समूहों के बीच एक ठोरे का काम करती है।

बार्कर महोदय ने 'राष्ट्र' को परिभाषित करते हुए राष्ट्र के जिन मूल तत्वों का वर्णन किया है वे हैं—निश्चित भूमि, निवासियों के एक से विचार, एक सा इतिहास, एक सा धर्म, एक सी भाषा, एक सा ही सकल्प और उस सकल्प को साकार करने के लिए एक पृथक राज्य का होना।¹ इस परिभाषा में से यदि राज्य (State) शब्द को अलग कर दिया जाय तो यही परिभाषा राष्ट्र की न रह कर राष्ट्रवाद की बन जाती है।

राष्ट्रियता की दूसरी परिभाषा जिमर्न (A E Zimerin) की है जिनके अनुसार 'धर्म की भाँति राष्ट्रियता भी आत्मपरक (Subjective) है मनो बंशानक है। यह मन की एक स्थिति है तथा एक आध्यात्मिक धारणा है। यह भावना, विचार और जीवन की एक प्रणाली है।'

जे एव रोज के मतानुसार "राष्ट्रियता दिलों की एकता का नाम है जो एक बार बन जाती है तो कभी टूटती नहीं।" बोइड शेफर ने अपनी पुस्तक 'राष्ट्रवाद बल्पना और सत्य' (Nationalism Myth and Reality) में यह बताया है कि राष्ट्रवाद की भाँसा में कई चीजें समाहित होती हैं। उदाहरण के लिए प्रदेश की कुछ परिभाषित इकाई सामान्य इतिहास में विश्वास, सामान्य उद्भव में विश्वास तथा यह धारणा कि राष्ट्र का भविष्य महान् होगा, इसके प्रदेश का विस्तार होगा आदि आदि। राष्ट्रवाद के द्वारा एक देश के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्य सर्वोच्च बन जाते हैं। स्वाभिमन्ति को देशमन्ति के द्वारा मापा जाता है। जो लोग प्राचीन होते हैं उनके लिए राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्र राज्य होता है। एक राजनैतिक आदर्श के रूप में राष्ट्रवाद एक देश के लोगों को अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है।

हंस कॉहन (Hans Kohn) के अनुसार राष्ट्रियता मुख्य रूप से

1 Ernest Barker National Character and the Factors in its Formation 1927, P 17

एक मन स्थिति है, यह अंतरात्मा का कार्य है। स्नाइडर (Snyder) ने भी माना है कि राष्ट्रीयता की जड़े अवचेतन दुनिया में रहती हैं जो तर्क-हीन, बुद्धिहीन तथा हवाई नित के समान स्वप्नित होती हैं। स्नाइडर महोदय द्वारा राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी गई है उसे कम प्रापत्तिजनक समझा जाता है। इनका कहना है कि राष्ट्रवाद (Nationalism) समय समय पर राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक तत्वों से प्रभावित होता है। यह ऐसे जन समुदाय के मन, भाव और सवेगों की स्थिति है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, एक सी भाषा बोलता है, जिसके पास राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने वाला साहित्य होता है, जो एक से रीतिरिवाज और परम्पराओं को मानता है, अपने नेताओं के गुणगान करता है तथा कुछ स्थितियों में एक धर्म में विश्वास करता है।

स्लाइमर (Charles P. Schleichner) महोदय ने राष्ट्रवाद को एक जनसमूह की आत्म-चेतना (*Consciousness*) नाम दिया तथा सवेगों का वर्तमान तत्व माना है जो एक व्यक्ति के भाग्य को प्राप्त या अप्राप्त राष्ट्र राज्य के भाग्य के साथ मिलाने में सदैव प्रयत्नशील रहता है।

राष्ट्रवाद की उक्त सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात् हमारे सामने यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीयता का अर्थ एवं प्रकृति क्या है। राष्ट्रीयता की भावना को कभी-कभी युद्ध एवं संधियों का कारण भी मान लिया जाता है। इसे अनेक बार विदेशी आक्रमणों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस आरोप को पूरी तरह झूठा नहीं बताया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई बार राष्ट्रवाद के नाम पर युद्ध एवं आक्रमण हो जाया करते हैं किंतु आक्रमण या युद्ध राष्ट्रवाद का उद्देश्य नहीं है यह तो इस भावना का दुर्लभयोग ही माना जायगा। सच्चा राष्ट्रवाद प्रारम्भ में एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में प्रयत्नशील रहता है और इसके प्राप्त हो जाने पर उस राष्ट्र के बहुमुखी विकास में लग जाता है।

राष्ट्रवाद की जड़

(The Roots of Nationalism)

राष्ट्रवाद एक भावनात्मक तत्व है जो अपने आपको अनेक प्रकार से सामने लाता है। एक राष्ट्रवादी व्यक्ति अतर्देशक होता है तथा वह बाहरी समूहों के लिए या तो उदासीन होता है अथवा विरोधी होता है। वह अपने देश को सत्कार का सर्वोच्च देश मानता है। हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी की रच-रंग में यह व्याप्त रहता है कि 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा।'

कभी कभी उसमें अपने राष्ट्रवासियों के प्रति सेवा के भाव उमर आते हैं। कई बार दो राष्ट्रीयताओं के बीच संघर्ष के भाव भी पैदा हो जाते हैं। फ्लोरिया जेनिकी (Florian Znanicki) के कथनानुसार राष्ट्रीयताएँ एक दूसरे से उस समय भगड़ती हैं जबकि एक राष्ट्रीयता दूसरी की कीमत पर जानबूझ कर अपना प्रसार करे अथवा दो राष्ट्रीयताएँ अपना प्रसार इस प्रकार करें कि दोनों को एक दूसरे के प्रसार में हस्तक्षेप करना पड़ जाये। यह आक्रमणकारी प्रसार, जो आगे चल कर संघर्ष का कारण बनता है, चार प्रकार का हो सकता है—भौगोलिक, आर्थिक, सैद्धान्तिक और समुत्कीकरण करने वाला। राष्ट्रवाद के अभिव्यक्तिकरण के इन विभिन्न रूपों की प्रखरता इस बात पर निर्भर करती है कि राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति में उप्रता की मात्रा कितनी है तथा उप्रता की मात्रा का निश्चय बहुत कुछ इस बात से किया जाता है कि उसकी जड़ें कितनी गहरी एवं सशक्त हैं।

राष्ट्रवाद की जड़ों से हमारा अर्थ उन अनेक तत्वों से है जहाँ राष्ट्रीयता की भावना अथवा राष्ट्रवाद को पनपाते हैं एवं उसको आश्रय प्रदान करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने इन तत्वों का विपद रूप में विवेचन किया है। श्लाइसर (Schleicher) महाशय मानव प्रकृति, भूगोल, जाति, धर्म, भाषा आदि तत्वों को राष्ट्रवाद की जड़ मानते हैं। ये वे तत्व हैं जिनमें राष्ट्रीयता की भावना जन्म लेती तथा पनपती है। वैसे इनमें से कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसके न होने पर राष्ट्रवाद न रहे किन्तु कई तत्वों के प्रभाव में यह भावना मज्द भवश्य पड़ जायेगी, ठीक इसी प्रकार जैसे कि जड़ कट जाने पर या सूख जाने पर पौधा सूख जाता है। राष्ट्रीयता की भावना के इन तत्वों में से किसी का भी अभाव होने पर असंतुलन पैदा हो जाता है, संतुलन की पुनः स्थापना करने के लिए दूसरे अथवा तत्वों की शक्तिशाली बनाना आवश्यक बन जाता है। राष्ट्रवाद को बनाये रखने वाले एवं बढ़ावा देने वाले तत्व निम्न प्रकार हैं—

(१) भौगोलिक एक्ता (A Definite territory)—भौगोलिक विशेषताएँ एक राज्य के नियासियों में एक्ता की भावना लाती हैं तथा दूसरे समुदायों से उनमें भेद स्थापित करती हैं। एक देश की प्राकृतिक सीमाएँ राष्ट्रवाद को बनाये रखने तथा विरहित करने में बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। जब इन सीमाओं का कोई दूसरा राज्य प्रतिक्रमण करना चाहता है तो दोनों देश युद्ध की भाग में कूद पड़ते हैं। चीन के विरुद्ध हिमालय की रक्षा के लिए भारतीयों ने भारी बलिदान दिये हैं तथा अब करने को तैयार हैं। रामजे म्पोर ने लिखा है कि "जिन देशों की सीमाएँ निश्चित हानी हैं उनमें

भौगोलिक एकता भा जाती है और यह तब भी भागिक रूप से बड़ा राष्ट्रपन (Nationhood) का कारण बन जाता है।^१ मातृभूमि वा होना राष्ट्रवाद की भावना के लिए एक स्थूल आधार प्रदान करता है। इसके अभाव में जिप्सी तथा कजर मारे-मारे फिरते हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना के विकास का प्रश्न ही नहीं उठता।

भौगोलिक एकता एक ऐसा तत्व है जो अन्य अनेक एकताओं को जन्म देता है। एक ही जलवायु, वातावरण एवं प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच पले व्यक्तियों की शारीरिक विशेषताएँ प्रायः समान होती हैं, उनकी अविकाश समस्याएँ एक ही होती हैं। इसी कारण उनके बीच परस्पर सहयोग एवं सहानुभूति के भाव पनपते हैं। वह पूरे प्रदेश के हित में अपना हित देखता है। प्रायः यह कहा जाता है कि "राजनीति हमें विभाजित करती है, धर्म हमारे बीच दीवार खड़ी करता है, संस्कृति हमें टुकड़ों में बांटती है, पर हमारा देश और धरती का प्यार हमें एक सूत्र में बांध सकता है।" प्रो० हेज इस विचार-प्रवाह का मछली की भाँति विरोध करते हैं। उनका स्वयं का मन यह है कि जातियों के बीच प्राकृतिक सीमाओं का विचार एक कोरी कल्पना है किंतु हम जानते हैं कि हाल के भारत पाक संघर्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वयं हेज (Hayes) महोदय का कथन ही कल्पना था। भारत के मुसलमानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए उतना ही बलिदान किया जितना कि अन्य किसी, धर्म या जाति के भारतीयों ने किया था।

(२) एक-सी जाति (Common Race)—जाति और राष्ट्रवाद के बीच एक गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रवाद की भावना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती, यदि उनमें स्थित जातियों तथा वर्गों के बीच गहरा मतभेद बतमान है। जिमर्न (A E Zimmer) तथा ब्राइस (Bryce) राष्ट्रियता की भावना के विकास में जाति का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। दूसरी ओर मैजिनो (Mazzini), रेनन (Renan), रोज (J H. Rose) तथा हेज (Hayes) आदि विचारक हैं जो राष्ट्रीयता की भावना पर एक जाति का प्रभाव मानने को तैयार नहीं हैं। इनका तर्क जैसा कि मुसोलिनी भी कहा करता था, यह है कि जीवशास्त्र की दृष्टि से आज कहीं भी कोई शुद्ध जाति नहीं है। पिल्सबरी (Pilsbury) का कहना है कि साधारणतया राष्ट्रीयता के निर्माण में जाति का भव कोई

महत्व नहीं है। किसी भी राष्ट्र में कोई भी शुद्ध जाति नहीं है। प्रत्येक मनुष्य वहाँ शकल है। झालोचको का मत आशिक रूप से सच है। वास्तविकता तो यह है कि जाति एक भावना है, वास्तविकता नहीं। भारतीय प्रशासन में पक्षपात व भ्रष्टाचार के लिए जातिवाद की बहुत कुछ उत्तरदायी ठहराया जाता है। जाति के नाम पर हिटलर ने अपनी नीतियों पर पूरे जर्मनी का समर्थन प्राप्त कर लिया था। प्रमरीका और दक्षिणी अफ्रीका में जातिभेद व रंगभेद की नीति के कारण अनेकों उपद्रव होते रहते हैं। रोडेशिया की समस्या पर विश्व की तरफ न खपाना पड़ता यदि इज्जान स्मिथ (Jan Smith) भी उन्नी जाति व रंग के होते जिसका वहाँ का बहुमत है। स्पष्ट है जातीय एकता भी राष्ट्रियता की भावना पर प्रभाव डालती है। हेज (Hayes) महोदय के मतानुसार राष्ट्रवाद प्राथमिक जाति की सीमाओं तोड़ जाता है किन्तु फिर भी जातीय एकता राष्ट्रियताओं का निर्माण करने व पक्का बनाने में सदैव प्रभावकारी शक्ति रही है।

(३) एक ही संस्कृति (Common Culture)—राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक धारणा माना जाता है। एक देश में पाये जाने वाले बला, साहित्य, सामान्य परम्पराएँ, लोकगीत, वाङ्मय आदि कृतियाँ एक बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच एकता की स्थापना करने में बल देती हैं। उदाहरण के लिए हम साहित्य को ले सकते हैं। राष्ट्रमक्तिपूर्ण श्रीजस्वा साहित्य ऐसे नागरिक बना सकते हैं जो राष्ट्रीयता के नाम पर खुशी से अपने प्राणों का बलिदान कर दें। स्वतंत्रता से पूर्व भी 'वन्देमातरम्' गीत भारतीयों के हृदय में हिलोरे उठा देता था। जोसेफ (B Joseph) महोदय का विचार है कि अंग्रेजों के व्यवहार में कुछ समानताएँ पाई जाती हैं जैसे, चाय पीना, राष्ट्रीय नीतिना पर गर्व करना तथा खेल आदि। ये समानताएँ देखने में तो साधारण सी प्रतीत होती हैं किन्तु इन्होंने राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है।

(४) एक ही भाषा (Common Language)—भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। एक भाषा भाषी दा व्यक्ति जब ऐसे प्रदेश में मिलने है जहाँ की भाषा उनसे भिन्न है तो दोनों के दिलों से परस्पर प्यार उमड़ पड़ता है। समान भाषा के प्रभाव में व्यक्ति अपने विचारों को जिस रूप में व्यक्त कर सकता था न कर सकेगा और समझने वाला जिस

प्रकार समझ सकता है न समझ सकेगा। भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारखों का जब अध्ययन किया जाता है तो अंग्रेजी भाषा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है जिनने भारत के विभिन्न भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों में एकता की स्थापना की तथा उसे मजबूत बनाया। अतः अंग्रेज महोदय ने भाषा की एकता के निर्माण का एक मुख्य तत्व माना है।

(५) समान धर्म (Common Religion)—एक ही धर्म दो व्यक्तियों के बीच एकता के निर्माण में कितना सहायक होता है इस बात को हम भारतीय धर्माती तरह जानते हैं। अतः अंग्रेजों का इतिहास साक्ष्य है कि धर्म के नाम का राजनीतिज्ञों द्वारा प्रारम्भ से ही दुरुपयोग किया गया। अपने साम्राज्यवाद के निर्माण की महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने धर्म की सजीवो वेदभूषा से सुशोभित कर दिया। जनमाधारण धर्म के नाम की चकाचौंध में पड़ा होकर एक झट्टे के नीचे आया और विधर्मियों का खून बहाने में राजनीतिज्ञों का मातहत बन गया।

धर्म और राष्ट्रवाद के बीच बहुत गहरा सम्बन्ध है। इस तथ्य को समझ लेने के बाद ही भारत में राष्ट्रीयता की ज्योति जलाने तथा उसे स्थायी बनाने के लिए ही अनेकों धर्म गुंथार धान्दोलन किये गये। अधिकांश संस्थाओं द्वारा हिन्दू धर्म के प्राचीन गौरव का गुणगान किया गया। भारत की भूमि के दो टुकड़े करने वालों के मस्तिष्क में धर्म ही राष्ट्रीयता के प्रधान आधार के रूप में था। धर्म के आधार पर ही आज पाकिस्तान भारत के अधिभ्रमण कश्मीर को हड़पना चाहता है। धर्म के नाम पर ही बहा की जनता सरकार की इन अनुचित नीतियों को सहन करती है। अतः अंग्रेज महोदय का विचार है कि धार्मिक समानता या असमानता से एक राष्ट्र की एकता बढ़ती व कम होती है। सफट काल के समय एक संगठित धर्म प्रायः राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन करता है।

राष्ट्रीयता की भावना अथवा राष्ट्रवाद को बढ़ाने, विवर्धित करने एवं बनाने रखने में उक्त तथ्यों का बड़ा महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अतिरिक्त यदि एक जनसमुदाय के धार्मिक हित समान हों, एक मुख्य शासन के वह अधीन रहे, एक ही समस्याएँ एवं कष्ट उत्पन्न लगने हों तथा एक राष्ट्र बनाने की उनकी इच्छा हो तो उस जनसमुदाय में भी अंग्रेजी राष्ट्रीयता के माथ पैदा हो जायेंगे।

(६) समय के समय राष्ट्रीय एकता (National Unity in Time of Conflict)—योरूप में जिस राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसकी रूप रचना

करने में सामन्तवादी एवं राजाशाही युद्धों ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है। इन्होंने स्वामिश्रित को मशक्त किया, नेतृत्व को विकसित किया तथा सामूहिक भावना की प्रतिष्ठा की। युद्धों ने लोगों को एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा कर सकें तथा देश की असुरक्षा में हिस्सेदार बन कर एकता की भावना विकसित कर सकें। योरोप के अनेक राष्ट्रों की रचना युद्धों के बाद तथा उन परिस्थितियों के विकसित होने पर हुई जिन्होंने कि अठारवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में राष्ट्रवाद के विकास का समर्थन किया। अमरीका में राष्ट्रवाद का उदय १८१२ के युद्ध, मैक्सीकन युद्ध तथा पश्चिमी सीमा पर सघर्ष आदि के बाद हुआ। मैक्सीकन युद्ध ने मैक्सीको में भी राष्ट्रवाद की प्राप्ति दिला दी। भारत में अनेक जातियों एवं धर्मों के अस्तित्व के कारण राष्ट्रीय एकता की समस्या रहती है और इस समस्या का सतोपजनक समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है किन्तु फिर भी यहाँ सकट के समय जो एकता दिखाई देती है वह अद्वितीय होती है। सन् १९५२ के चीन के आक्रमण के समय तथा सन् १९६५ के पाकिस्तानी आक्रमण के समय भारत की जनता अपने धार्मिक, जातीय, भाषाई, वर्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्त भेदभावों को भूल कर एक स्वर से सरकार की नीति का सहारा बन गई। पेडलफोर्ड तथा लिंकन का यह कथन पूर्णतः सत्य है कि युद्ध और आक्रमण की घमकी प्रायः प्रत्येक जगह राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने में तथा नये राष्ट्रों की रचना में महत्वपूर्ण तत्व रहते हैं।^१ इस बात के उदाहरणों की इतिहास में कमी नहीं रहती। जब पलेस्टाइन (Palestine) को विभाजित करके इजरायल राज्य बनाया गया तो मय, सदेह एवं शत्रुता के कारण यहूदियों एवं अरबियों के बीच लड़ाई प्रारम्भ हो गई। इस सघर्ष के परिणामस्वरूप अरब और यहूदी दोनों का राष्ट्रवाद पर्याप्त पनपा है।

(७) राष्ट्र का आदि भौतिक रूप (The Metaphysical Form of Nation)—जब दार्शनिकों, विचारकों एवं लेखकों ने राष्ट्र की प्रकृति को आदि भौतिक रूप में वर्णित किया तो सामान्य जनता पर इसका भारी प्रभाव हुआ। एक भावना के रूप में राष्ट्रीयता का आधार 'विश्वास' होता है। बुद्धि के स्तर पर लाने से यह भावना समाप्त या प्रभावहीन हो जाती है। इसके विपरीत विश्वास को जितना मशक्त बनाया जायेगा यह भावना भी उतनी ही विकसित होगी। यही कारण है कि जब विद्वानों ने राष्ट्र के

ईश्वरीय गुणों की कल्पनात्मक दृग् से वर्णित किया तो इस धर्म में लोगों का विश्वास दृढ बन गया। जर्मनी में फिक्टे (Fichte) तथा इटली में मेजिनी (Mazzini) आदि दार्शनिकों ने यह बताया कि राष्ट्र की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। यह शान्ति एवं सहयोग की ईश्वरीय योजना का एक भाग है। हीगेल ने इसको आध्यात्मिक अंग रचना (Spiritual Organism) माना तथा रेनन (Renan) ने इसको आत्मा, एक आध्यात्मिक सिद्धांत कहा।

(८) राष्ट्रवाद और उसके प्रतीक (Nationalism and its Symbols)—एक राष्ट्रियता के लोभ अपने आपको एक रूप तभी समझ सकते हैं जबकि सामूहिक संचार एवं संयुक्तीकरण की व्यवस्था हो। यह व्यवस्था प्रतीकों के माध्यम से तथा संचार की कला के विकास द्वारा की जा सकती है। कला, साहित्य, समूहगान एवं संगीत के द्वारा ऐतिहासिक स्मृतियों को गहन एवं अमिट बनाया जाता है और इस प्रकार उनको एक विशेष राष्ट्रीय अर्थ तथा स्वेय प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय नेताओं एवं महापुरुषों के यशोमान द्वारा राष्ट्रीय भावना का प्रसार होता है। भारत में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, अमर्गिका में वाशिंगटन, जैफर्सन तथा निकन; इटली में मेजिनी और गारीवाल्डी (Garibaldi), फ्रांस में नेपोलियन बगलैड में नेक्सन आदि नेताओं के गुणगान द्वारा राष्ट्रियता की भावना को एक समष्टि में प्रविष्ट किया जाता है। राष्ट्रीय महत्त्व के दर्शनीय स्थल, धार्मिक एवं उत्सव अनेक समाधियां आदि राष्ट्रियता के विचार का प्रसार करती हैं अनेक नारे जैसे—स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या सत्य, शिव, सुन्दरम् राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, तथा भौतिक पाशक आदि के माध्यम से एक राष्ट्र के लोगों में परस्पर अपनत्व की भावना पनपती है।

(९) राष्ट्रीय चरित्र और जीवन का तरीका (National Character and Way of Life)—यह कहना बहुत कुछ सत्य है कि राष्ट्रों का अपना एक विशेष राष्ट्रीय चरित्र होता है तथा उनके जीवनयापन का एक विशेष तरीका होता है। एक प्रदत्त वातावरण कुछ ऐतिहासिक अनुभव, सामाजिक एवं कानूनी संस्थाओं का एक निश्चित रूप आदि बातें सामूहिक एकता की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब एक समूह समान क्षेत्रीय सीमाओं में बहुत समय तक रहता है तो उसमें राष्ट्रीय चरित्र के कुछ विशेष लक्षण विकसित हो जाते हैं। यह भी हो सकता है कई राष्ट्रों के एक जैसे मूल्य तथा लक्ष्य हो। राष्ट्रीय जीवन का तरीका यह निश्चित

करता है कि एक राष्ट्र अपनी समस्याओं को हल करने के लिए क्या तरीका अपनायेगा।

राष्ट्रवाद का ऐतिहासिक विकास (The Historical Development of Nationalism)—यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयता के विचार की जड़ें इतिहास में निहित हैं किन्तु फिर भी वर्तमान राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद का जन्म पश्चिमी दुनियाँ में मध्यवी और अठारहवी शताब्दियों में हुआ था। २० वी शताब्दी की घटनाओं ने राष्ट्रवाद की मान्यता को गति प्रदान की तथा स्पष्ट हो गया कि हर जगह के लोग चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकास के किसी भी स्तर पर क्यों न हों, इसको अपना सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का जो रूप हमें प्राप्त होता है उसका विकास कई एक सोपानों में होकर गुजरा है। जिस सामाजिक प्रक्रिया ने द्वारा जागो में राष्ट्रीयता की भावना पनपती है तथा एक माथ रहने की चेतना तथा अपनत्व की भावना आती है वह बहुत पहले ही प्रारम्भ हो चुकी थी। वैसे निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि फ्रांस और इंग्लैंड कब राष्ट्र-राज्य बन गये और उन्होंने राजा या महारानी की अपेक्षा राष्ट्रीय स्वामिमक्ति का कब अपनी भावनाओं पर आश्रित किया। राष्ट्रीयता की भावना के विकास में अनेक तत्वों ने प्रभाव डाला है जैसे—सुघरी हुई संचार व्यवस्था, बढ़ते हुए सामाजिक सम्पर्क, आर्थिक लाभों की आशा तथा दमन के सामान्य तरीके का विकास आदि। राष्ट्रवाद अपने आप ही प्रकट नहीं हो गया था क्योंकि भावनाओं के बीच व्यक्तियों के दिलों में ही प्रस्फुटित होते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के दौरान जनसंख्या नये विचारों को अपनाने की दिशा में उत्सुक बन जाती है तथा नये नेताओं द्वारा जब उसे आश्वासित भूमि को प्राप्त करने की ओर संचालित किया जाता है तो राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। राष्ट्रवाद के विकास की प्रारम्भिक स्थिति में क्रियाशील अल्प-संख्यकों को तथा नए नेताओं को सजग प्रयास करना होता है। जब निष्क्रिय बहुमत का विश्वास राष्ट्रवाद से प्रभावित हो जाता है तो वह मूल्यों एवं स्वामिमक्ति की नयी व्यवस्था अर्थात् राष्ट्रवाद को सह्य अपना लेता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद की जड़ें धार्मिक तत्वों पर आधारित हैं। जब एक बार राष्ट्रीय चेतना की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है तो सांस्कृतिक सिद्धान्तों एवं सामान्य अनुभव की विरासत द्वारा एवं राष्ट्रीय एकता की विरासत के द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाता है।

राष्ट्रीयता की प्रकृति का एक धर्म के रूप में होना भी इसके विकास में एक प्रभावशील तत्व रहा है। प्रत्येक राष्ट्र में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़े

बहुमत के लिए आधुनिक धर्म बन गया है क्योंकि यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक रूप में सुरक्षा व अच्छा जीवन-प्रस्तुत करता है। राष्ट्र के प्रति स्वामित्व का कारण मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, राजनैतिक, मानवीय या कुछ भी हो सकता है किन्तु इन कारणों का विकास भी ऐतिहासिक कालक्रम की ही उपज है। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर ही लोग क्षेत्रीय अथवा विश्व संगठन के लिए अपनी स्वामित्व प्रदान कर सकते हैं किन्तु ऐसा केवल तभी होगा जबकि इससे उनकी राष्ट्रीय स्वामित्व में किसी प्रकार की कमी नहीं आती।

राष्ट्रवाद के प्रकार (Types of Nationalism)—राष्ट्रवाद के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से एक बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि राष्ट्रवाद पहले फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, स्पेन आदि पश्चिमी योरोप के देशों में फैला और उसके बाद यह शेष योरोप एवं पश्चिमी देशों में धीरे-धीरे व्याप्त हुआ। अन्य महाद्वीपों में तो इसका प्रवलन आधुनिक काल में ही हुआ है। जिस प्रकार समाजवाद या व्यापार संधवाद या अन्य कोई विचार अथवा सस्या समय-समय अपना रूप बदलती रही है, उसी प्रकार राष्ट्रवाद का अर्थ भी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है। एक समय राष्ट्रवाद का अर्थ कुछ और था तो दूसरे समय की बदली हुई परिस्थितियों में यह कुछ और हो गया। इतिहास के एक काल में राष्ट्रवादी व्यक्ति से कुछ और भाषा की जाती थी तो दूसरे काल में कुछ और। ऐसी स्थिति में जब कभी राष्ट्रवाद के बारे में सामान्यीकरण कर दिया जाता है तो पर्याप्त भ्रम पैदा हो जाता है।

राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में कोई भी सामान्यीकरण करने से पूर्व यह जरूरी है कि उसके विभिन्न रूपों तथा उनके मध्यस्थित घटकों की जानकारी प्राप्त कर ली जाये। प्रसन्न में राष्ट्रवाद का अर्थ समझने के लिए भी हमें उसकी परिभाषाओं का अध्ययन करने की अपेक्षा उसके रूपों का वर्णन करना चाहिए। राष्ट्रवाद को अनेक प्रकार का बताया जाता है। कुछ लोग राष्ट्रवाद को अच्छी चीज मानते हैं जबकि दूसरे इसे एक बुरी भावना कहते हैं, कुछ के मतानुसार राष्ट्रवाद का रूप सृजनात्मक होता है जबकि दूसरों के अनुसार इसका रूप विध्वनात्मक है। विचारकों के बीच भौतिक या आध्यात्मिक चेतन या अचेतन राष्ट्रवाद के रूपों के सम्बन्ध में भी मतभेद है। हैन्स काहन (Hans Kohn) ने राष्ट्रवाद के रूपों का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर किया है। वे पश्चिमी जगत में प्राप्त राष्ट्रवाद और पश्चिमी जगत से बाहर प्राप्त राष्ट्रवाद के बीच अन्तर करते हैं। इस अन्तर के आधार पर ही

यह देखना सम्भव होता है कि गैर योरोपीय क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया पर पड़ने वाला सांस्कृतिक प्रभाव एवं विरोध क्या थे। वैसे राष्ट्रवाद का अध्ययन प्रत्येक देश के अनुसार भी किया जा सकता है किन्तु यह प्रक्रिया जटिल तथा भ्रम पूर्ण है। राष्ट्रवाद के अध्ययन का एक मूल्यवान दृष्टिकोण कालक्रम के अनुसार इसकी जानकारी प्राप्त करना सम्भवा जाता है। काल्टन हेज (Carlton Hayes) ने राष्ट्रवाद के विकास के पांच स्तरों का वर्णन किया है। पाँचों ही स्तरों पर राष्ट्रवाद का रूप भिन्न भिन्न था और इन रूपों की विशेषतायें भिन्न भिन्न थीं। ये रूप हैं—

१. मानवतावादी राष्ट्रवाद (Humanitarian Nationalism)
२. उदार राष्ट्रवाद (Liberal Nationalism)
३. प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवाद (Jacobin Nationalism)
४. परम्परागत राष्ट्रवाद (Traditional Nationalism)
५. एकीकृत राष्ट्रवाद (Integral Nationalism)

राष्ट्रवाद के प्रथम चार प्रकार अठारहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए। मानवतावादी राष्ट्रवाद का प्रभाव १८वीं शताब्दी के दौरान रहा। फ्रांस की क्रांति के समय प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवाद के रूप का प्रभाव था। १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में परम्परागत राष्ट्रवाद और १९वीं शताब्दी के मध्यकात्त में उदार राष्ट्रवाद का प्रभाव रहा। राष्ट्रवाद के अन्तिम रूपा अर्थात् एकीकृत राष्ट्रवाद को मुख्य रूप में बीसवीं शताब्दी की उदय कहा जाता है। यह राष्ट्रवाद सम्पूर्णवादी राज्यों की नीतियों का समर्थन करता है वैसे इसके अनेक समर्थक ऐसे भी रहे जो कि मंचन होकर सम्पूर्णवादी राज्य का समर्थन नहीं करते। अनेक प्रजातान्त्रिक राज्यों में इसके लक्षण दबने को मिलते हैं।

उदार राष्ट्रवाद का जन्म काल १७वीं और अठारहवीं शताब्दी के सगम को माना जाता है। ये दोनों शताब्दियाँ जागरण के युग या बुद्धि का युग मानी जाती हैं। इस युग के दार्शनिक, जैसे—मोटेस्मो, वाल्टेयर, लॉक, रुमा एवं जेफ़रसन आदि राजा व देवीय अधिकारों को सामान्यवादी विचारों का विरोध करने थे तथा इनका विचार था कि मनुष्य को प्राकृतिक कानून द्वारा प्रामाणित होना चाहिए क्योंकि अधिकार तथा सामाजिक एवं राजनैतिक उत्तरदायित्वों का स्रोत प्राकृतिक अधिकार ही हान है। ये विचारक मविधानवाद एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देने थे तथा राष्ट्र-राज्य के अस्तित्व को व्यक्तिगत पूर्ण विकास के लिए अपरिहार्य मानते थे। इन विचारकों की रचनायें पारम्परिक उदार या मानवीय राष्ट्रवाद के स्रोत मानी जा

सकती है और इस प्रकार इनमें प्रजातन्त्रात्मक विचार के बीज उपलब्ध थे। स्वतन्त्रता के प्रमरीकी घोषणापत्र में जेफर्सन (Thomas Jefferson) भी भाषा ने इन मान्यताओं को राजनैतिक अभिव्यक्ति प्रदान की। इस घोषणापत्र में सभी व्यक्तियों की समानता पर ज़ार दिया गया तथा स्वतन्त्रता, जीवन एवं प्रसन्नता आदि को व्यक्ति के ऐसे अधिकार बताया गया जो कि उससे छीने न जा सकें। सरकार का तद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना है तथा सरकार की शक्ति का यौन प्रशासितों की स्वीकृति है। जब कभी सरकार इन लक्ष्यों के विपरीत व्यवहार करे तो जनता को यह अधिकार है कि इसे समाप्त करके नई सरकार की रचना करे। सरकार की नींव के सिद्धान्त तथा इसकी शक्तियों के संगठन का रूप इस प्रकार का होता है कि वह जनता की सुरक्षा और प्रमन्नता को प्रभावित कर सके। उदार राष्ट्रवाद उस ममत्व की अभिव्यक्ति है जो राष्ट्रवाद के मूल्यों को अन्य लोगों के लिए उपलब्ध बनाने हेतु अत्म-चेतन रूप से लग जाना है। जब यह ममत्व स्वतन्त्रता और आत्म-निर्णय के मूल्यों को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय ले लेता है तो इसका दृष्टिकोण सत्तावादी एवं प्रसारवादी बन जाता है।

१९वीं शताब्दी के साथ ही राष्ट्रवाद का यह रूप भी समाप्त हो गया। राष्ट्रवाद के इस रूप का समर्थन करने वाले विचारक उच्च बौद्धिक स्तर के तथा शान्तिवादी थे। किन्तु योरोप में इस काल में प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव था इसलिए शान्तिपूर्ण साधनों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करना सम्भव न हो सका। प्रो० हेज के कथनानुसार उदार राष्ट्रवाद असफल हो गया क्योंकि यह योरोप की राज्य व्यवस्था को अपने शान्तिवाद के आदर्श को बलिदान किये बिना राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं कर सका। इसलिए सड़ार्ड सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को राजनैतिक राष्ट्रवाद में परिवर्तित करने का एक व्यावहारिक साधन बन गई। १९वीं शताब्दी के अन्त में तथा २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में महाशक्तियों के बीच संपर्क बढ़ने लगा। यह संपर्क व्यापारिक, औद्योगिक, शैक्षिक आदि अनेक कारणों पर आधारित था। ये शक्तियाँ अपने मित्रों के लिए, अपने उपनिवेशों के लिए तथा अपनी समुद्र शक्ति की उच्चता दिखाने के लिए लड़ती रहती थीं। ऐसी स्थिति में उदार राष्ट्रवाद असामयिक बन गया और इसका स्थान सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद द्वारा ले लिया गया।

जेकोबियन (Jacobian) या प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवाद १७९२ की कन्वेंशन द्वारा प्रारम्भ किया गया तथा इसे नेपोलियन द्वारा अपनाया गया। यह राष्ट्रवाद सरकार के परम्परागत रूपों को तथा अनर्राईवीय यथा स्थिति (Status-quo) को बदलने का एक आक्रमणकारी साधन बताया जाता है। पामर

तथा परकिन्स के कथनानुसार कुछ ग्र्यों में यह क्रान्तिकारी एवं प्रजातन्त्रात्मक था। मैन्सलन तथा ग्रन्थ ने कर्नल नासिर के भरब एकता के प्रयासों को जेकोवियन राष्ट्रवाद का आधुनिक सस्करण कहा है क्योंकि कर्नल नासिर मिश्र की नई व्यवस्था के लक्ष्य को ग्रन्थ भरब राज्यों तक फैलाना चाहता है। प्रोफेसर हेज का मत है कि राष्ट्रवाद का यह रूप केवल एक सीमित एवं कार्यकारी रूप में ही प्रजातन्त्रात्मक कहा जा सकता है। विकास के क्रम में जेकोवियन राष्ट्रवाद अधिक से अधिक शीनिक होता चला गया। इसका उद्भव प्रजातन्त्रात्मक रूप में हुआ था किन्तु बाद में इसने नेपोलियन की तानाशाही का मार्ग पशस्त किया। नेपोलियन जैसे स्वयं राष्ट्रवादी नहीं था किन्तु इसने राष्ट्रवाद के भंडे को उठाया और इसी के नीचे अधिकांश योरोप पर प्राप्त की सेनाओं का नेतृत्व किया तथा दूसरे देशों की जनता की स्वतंत्रता का हरण किया। बाद में राष्ट्रवाद की शक्ति ने ही उसकी शक्ति को समाप्त किया।

नेपोलियन के आक्रमणों के कारण उसके विरोधियों में राष्ट्रवाद का जो रूप पनपा उसे प्रोफेसर हेज ने परम्परागत राष्ट्रवाद का नाम दिया है। यह जेकोवियन राष्ट्रवाद का ठीक विपरीत था। यह प्रजातन्त्रात्मक न होकर कुलीनतन्त्री था। इसकी प्रकृति विकासशील एवं रुढ़िवादी थी। इसने मयास्थिति को बदलने या नष्ट करने की अपेक्षा उसकी सुरक्षा का प्रयास किया। यद्यपि यह जेकोवियन राष्ट्रवाद के विरोधी के रूप में विकसित हुआ था किन्तु बाद में चल कर इसका स्वरूप हिंसात्मक हो गया। वाटरलू की लड़ाई में परम्परागत राष्ट्रवाद का प्रभाव देखने में आया। रूस का जार सन् १८१५ में परम्परागत राष्ट्रवाद की आशा के रूप में उदित हुआ। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांस परम्परागत राष्ट्रवाद का समर्थक रहा। इस समय के पीछे मूल कारण यह था कि वह जर्मनी के सामने अपनी राष्ट्रीय शक्ति के कम होने की भावना से पीड़ित था। संयुक्त राज्य अमरीका में जेकोवियन राष्ट्रवाद को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। सोवियत संघ बहुत पहले से ही राष्ट्रीयता के आन्दोलन का समर्थक रहा है किन्तु उसका दृष्टिकोण इसके प्रति विशेष प्रकार का था। स्टालिन के कथनानुसार राष्ट्रवाद को किसी राष्ट्र की कृपक या मजदूर जनता का आत्मनिर्णय का अधिकार समझना चाहिए। यह उस देश की पूँजीवादी जनता का अधिकार नहीं है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत समाजवाद के लिए संघर्ष के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए तथा इसे समाजवाद के सिद्धांतों के मान्य रहना चाहिए।^१

1 Quoted in Isaac Deutscher, Stalin: A Political Biography, Oxford University Press, London, 1935, P. 185

एकीकृत राष्ट्रवाद का रूप परम्परागत राष्ट्रवाद का ठीक उल्टा है। इसमें व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जो देता है तथा समाज का प्रतिस्तर एक जीवन एक प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। राष्ट्रवाद का यह रूप अधिक गत्यात्मक तथा प्रसारवादी होता है। एकीकृत राष्ट्रवाद प्रायः समाज के सम्पूर्णतावादी संगठन की व्यवस्था करता था तथा सभी नागरिकों पर राष्ट्रीय सर्वोच्चता के नाम पर प्रभुत्व रखने का कार्यक्रम बना देता है। इस राष्ट्रीयता से प्रभावित लोगों से किस प्रकार के अनर्शादीय व्यवहार की आशा की जानी चाहिए यह बात अधिक अस्पष्ट नहीं है। एकीकृत राष्ट्रवाद बीसवीं शताब्दी की विशेषता है। चार्ल्स मोरेस ने एकीकृत राष्ट्रवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया है कि यह राष्ट्रीय नीतियों की एक प्रणाली है तथा यह राष्ट्रीय शक्ति की निरन्तर वृद्धि है। एक राष्ट्र जब सैनिक शक्ति को देता है तो वह स्वयं भी समाप्त होने लगता है।¹ मोरेस ने त्रिम आन्दोलन का सूत्रपात किया वह फ्रांस में एकीकृत राष्ट्रवाद को फैलाने का आधार बन गया है। यह आन्दोलन अनेक तरीकों से मिलकर बना था, जैसे बोनापार्टवाद, शाही विचारों का प्रभाव प्रान्तवाद एवं कैथोलिकवाद आदि। इस आन्दोलन ने वर्साय की संधि को फ्रांस के लिए एक बेइज्जती माना तथा उस मुमोलिनी की प्रशंसा की जो वास्तव में फ्रांस का दुश्मन था। इसने फ्रांस को तथा स्पेन की सत्तावादी सरकार का समर्थन किया और साथ ही विदेशी सरकार का पक्ष पोषण किया। मोरेस (Maurras) प्रजातन्त्र विरोधी तथा अंग्रेज विरोधी होने के साथ-साथ जर्मनी का भी पक्का विरोधी था। अपने विनाश के दिनों में फ्रांस के हितों की रक्षा का नारा बुलन्द किया। युद्ध के बाद एक फ्रांसीसी न्यायालय ने उस पर राजद्रोह का दाय लगाया और उसे जीवन-पर्यन्त कारावास का दण्ड दिया गया। धृष्टा की राजनीति (Politics of Hate) के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है।

सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद (Totalitarian Nationalism) के विकास के लिए उदार राष्ट्रवाद द्वारा मार्ग प्रतस्त किया गया था। १९वीं शताब्दी के अन्त में मजबूत राष्ट्रीय सरकारों का उदय हुआ तथा जो ही राष्ट्रवाद ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए सामाजिक रचना में प्रवेश करना प्रारम्भ किया त्यों ही अनेक राष्ट्र कम उदार बन गये तथा अधिक राष्ट्रवादी हो गये। उदार राष्ट्रवादियों ने एक ऐसी विश्व व्यवस्था के गठन का प्रयास किया जिसमें ऐसी स्वतन्त्र सवैधानिक सरकारें हो जो व्यक्तिगत सम्पत्ति

1. Maurras, quoted in Hayes, Historical Evolution, P. 165.

और स्वतन्त्र उद्यम की रक्षा कर सकें तथा स्वतन्त्र व्यापार की अनुमति प्रदान कर सकें। इस प्रकार दो विश्व युद्धों के बीच के समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षावाद एवं आर्थिक राष्ट्रवाद का विषय बन गया। प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद के रूप निर्धारण में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। अमल में राष्ट्रवाद इस युद्ध का कारण भी था और परिणाम भी। एक कारण के रूप में राष्ट्रवाद ने राजनीतिज्ञों का मार्ग प्रशस्त किया तथा युद्ध के लिए लोगों के मस्तिष्क को बनाया। यह विश्व युद्ध न केवल राष्ट्रवाद में प्रसारित ही हुआ था वरन् इसने अधिक व्यापक राष्ट्रवाद का नेतृत्व भी किया।^१ वेडिनफोर्ड तथा लिक्न का कहना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में साम्यवाद का उदय, इटली में फासीवाद की स्थापना तथा जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद का अभ्युदय आदि ने राष्ट्रवाद की सम्पूर्ण तानादी व्यवस्था की स्थापना की। इन सभी ने राज्य की शक्ति को सर्वोच्च साधन माना तथा व्यक्तिगत अधिकारों को उसके मातहत रखा। उदाहरण राष्ट्रवादियों के मानवतावादी विचारों का स्थान तानाशाही शासन ने ले लिया। जर्मनी में सम्पूर्णतावाद ने नाज़ी शासन की पार्श्वविक्रता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इटली में भी बेनिटो मुसोलिनी तथा उनके काली वर्मीज वाले फासिस्टों ने तानाशाही शासन स्थापित किया। जर्मनी में यह राष्ट्रवाद यहाँ तक पहुँच गया कि सभी लोगों को खून की प्यास तथा आक्रमणकारी युद्धों को जीवन का वांछित लक्ष्य मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रवाद के इस रूप का नशा केवल उनी समय ढीला ही पाया जबकि सत्तार विश्व युद्ध में पुनः उलझ गया तथा मानव का वर्ण व रक्तपात हो गया। सम्पूर्णतावाद का एक अन्य उदाहरण, जो आज भी प्राण होता है, साम्यवादी देशों के राष्ट्रवाद को माना जाना है। सोवियत संघ उसके पड़ोसी देश तथा जल चीन इसी प्रकार के राष्ट्रवाद से प्रभावित हैं।

पामर तथा परकिन्स का कहना है कि साम्यवाद को सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद का एक रूप मानना शब्दों का विरोध है क्योंकि साम्यवाद कोई राष्ट्रीय घम नहीं है वरन् यह एक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है किन्तु फासीवाद ऐसा नहीं था।

साम्यवाद और राष्ट्रवाद (Communism and Nationalism)

सैद्धांतिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन होते हुए भी व्यावहारिक रूप

मे साम्यवादी शासन व्यवस्था अधिकाधिक राष्ट्रवादी हो गई है। रूस के नेताओं ने एशिया में राष्ट्रवाद के उदय की नीतियों को अपनाया जो कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। इनसे साम्यवाद को वहाँ की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के साथ एकाकार करने में सफलता प्राप्त हुई। इन महाद्वीपों के साम्यवादी नेताओं ने राष्ट्रीय भावोंसर्वों को अपने हाथ में ले लिया अथवा उसका अपने हित में उपयोग किया।

राष्ट्रवाद के प्रति सोवियत रूस का एक विशेष दृष्टिकोण रहा है। बोलशेविक क्रांति के कुछ समय बाद ही लेनिन ने सोवियत संघ की विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए आत्मनिर्णय की एक घोषणा प्रसारित की। रूसीकरण करने की आरम्भही नीतियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। रूस की लगभग १५० राष्ट्रीयताओं को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय भूमिगत की स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु राजनैतिक रूप से वे सभी सरकार और साम्यवादी दल की भाषाओं के भाषीन थीं। स्टालिन ने गणराज्यों की स्वायत्तता को समाप्त कर दिया तथा अपने विरोधियों को समाप्त किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी की सेनाओं ने रूस के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया तो रूस के लोगों से उनकी मातृभूमि की रक्षा के लिए धवील की गई। उस समय साम्यवाद या विश्व क्रांति का विचार पीछे रह गया। इस समय स्टालिन ने सोवियत रूस की सेनाओं में यह भाषा प्रकट की थी कि हमारे पूर्वजों का सहस्रपूर्ण चित्र युद्ध में उन्हें प्रेरित करे। जब साम्यवाद की सुरक्षा का नारा विरोध को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रयुक्त सिद्ध हुआ तो स्टालिन ने मातृदेश के लिए असीमित स्वामित्व की पुर्नर्दी दी। रूसी इतिहास के भूले हुए नेताओं की याद को ताजा किया गया, साम्यवादी जारों तक का गुणगान हुआ राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक प्रकार का प्रयास किया गया।

सोवियत देशभक्ति में मार्क्सवाद-लेनिनवाद की विचारधारा तथा रूस के ऐतिहासिक चरित्रों का अद्भुत समन्वय है। देश भक्ति की भावना का प्रसार प्रेस, रेडियो, साहित्य, प्रतीक एवं उन सभी माध्यमों से किया जाता है जो राज्य एवं दल की सामर्थ्य के अन्तर्गत हैं। सोवियत रूस का विश्व की साम्यवादी क्रांति का नेतृत्व करने का दावा वहाँ के प्रखर राष्ट्रवाद की ही भूमिगत माना जाता है।

मार्शल टोलो ने जब मास्को की भाषीनस्यता स्वीकार करने से मना कर दिया तो एक नया तथ्य सामने आया। यूगोस्लाविया एक ऐसे देश का जीला जागता उदाहरण बन गया जो साम्यवादी की अपेक्षा राष्ट्रवादी अधिक

था। शेष साम्यवादी संसार से अलग होने के बाद मार्शल टोटो ने मुख्य रूप से अपने देश के राष्ट्रवाद पर मरोसा किया तथा गैर-साम्यवादी देशों से सहायता प्राप्त की।

साम्यवाद का राष्ट्रवादी रूप पूर्वी यूरोप में उस समय देखने को मिला जबकि स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस-चीन विवाद गम्भीर बन गया। मार्शल टोटो के बाद अन्य साम्यवादी देश भी अपनी स्वतंत्रता पर जोर देने लगे जिसे स्टालिन कभी भी देने के लिए इच्छुक नहीं था। सन् १९५६ की बीसवीं कांग्रेस में जब ख्रुशचेव ने स्टालिन के अपराधों का भण्डाफोड किया तो पोलैण्ड तथा हंगरी आदि देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन लड़के। इमरेनेगी (Imre-Nagy) के नेतृत्व में जब गैर-साम्यवादी नेता सरकार में आ गये तथा हंगरी ने वार्मा सन्धि को मानने से मना कर दिया तो सोवियत टैंक एवं सेना ने हंगरी को रौंद डाला। फलतः इस देश के राष्ट्रवादी दवा दिये गये किन्तु विश्व वहाँ के देशभक्ती एवं स्वतन्त्रता प्रेमियों के बलिदान की स्मृतियों को कभी नहीं भुला सकता।

रुमानिया में राष्ट्रवाद की भावना के प्रभाव ने नौकरशाही के नियंत्रण को कम किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं साम्यवाद को प्रोत्साहित किया। यहाँ के राष्ट्रीय साम्यवादी अपनी सीमाओं पर स्थित सावयत सशस्त्र सेनाओं की धमकी के प्रति सजग थे तो भी उन्होंने इस नीति का अनुगमन किया। पूर्वी योरोप के साम्यवादी शीघ्र ही यह जान गये कि वे रूस पर कितने आश्रित हैं तथा विश्व राजनीति में कितनी अनिश्चिन्ता पाई जाती है।

चीन में जिस राष्ट्रवाद का विकास हुआ वह एक राष्ट्र राज्य के राजनैतिक विचारों पर आश्रित होने की अपेक्षा आचार शास्त्र के तत्वों पर निर्भर है। यहाँ के लोगों में सर्वोच्चता का एक परम्परागत दृष्टिकोण है जिसके परिणामस्वरूप यह देश अपनी मूल भूमि का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहता है। साम्यवादी चीन अपनी सीमाओं के बाहर दक्षिण एशिया में सोवियत केन्द्रीय एशिया के कुछ भागों में, सोवियत जलसेना प्रान्तों में तथा ताईवान आदि में अनेक प्रदेशों पर अपना दावा करता है। चीन का यह विश्वास है कि कोई न कोई देश सदैव ही उसका विरोधी रहता है। कन्फ्यू-सियसवाद का स्थान आज माओवाद ने ले लिया है तथा यह चीन का एक मुख्य सिद्धान्त बन गया है।

सोवियत रूस तथा साम्यवादी चीन के बीच अनेक सैद्धान्तिक बातों में तीव्र मतभेद हैं। मार्क्सवादी द्वन्द्ववाद, धार्मिक प्रगति के कार्यक्रम तथा

पश्चिमी शक्तियों ने प्रति नीतियों के विषय में इन दोनों देशों के मित्र एवं विरोधी विचार हैं। यह मतभेद अनेक कारणों से बनपा है जैसे आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण के अन्तर तथा उनकी क्रान्तियों की वयस्कता आदि। इस संघर्ष के मूल कारणों में राष्ट्रवाद भी एक है। मास्को तथा पीकिंग के बीच की वार्ता दोनों देशों के सर्वोच्चता के दावे को सामने रखती है। रूस-चीन विवाद की जड़ में राष्ट्रीय महत्वाकांक्षायें, गर्व ऐतिहासिक शत्रुता आदि घटितमान हैं।

साम्यवादी देशों का गैर-साम्यवादी देशों के साथ जो सम्बन्ध है उससे उनके सम्मान, शक्ति एवं प्रभाव की राष्ट्रवादी विशेषतायें स्पष्ट रूप से झलकती हैं। कुछ विचारकों का यहां तक कहना है कि साम्यवादी राज्यों में जो मनमुटाव है तथा रूस एवं चीन के बीच जो खुला संघर्ष है उसके देखने के बाद यह शक होने लगता है कि पहले राष्ट्रीय साम्यवादी नीतियां राष्ट्रीय लक्ष्यों को अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के हित में प्रेरित थीं भी भ्रमवा नहीं।

राष्ट्रवाद का नया रूप (The New form of Nationalism)

राष्ट्रवाद की जिस शक्ति ने योरोपीय शक्तियों को एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों में साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया था उसी शक्ति ने उनके उपनिवेशों को सम्प्राप्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमरीका में जो राष्ट्रवादी क्रान्ति फैली उसकी कुछ अपनी विशेषतायें थी जो उसको उदार एवं सम्पूर्णतावादी राष्ट्रवाद से भ्रमय करती थी। इसकी प्रथम विशेषता यह थी कि स्वतन्त्रता एवं आत्म-सम्मान पर यह बहुत जोर देता था। दूसरे, यह इस बात पर जोर देता था कि राजनैतिक एकता को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। तीसरे, घरेलू नीतियां निर्धारित करने के लिए यह स्थानीय नेताओं को स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष में था। उपनिवेशवादी शासन की पुन स्थापना को रोकने की दृष्टि से उपनिवेशवाद का विरोध अब भी नये राष्ट्रवाद की विशेषता बना रहा। ये देश उन सरकारों तथा बड़े निगमों की नीतियों को सदेह की दृष्टि से देखने लगे जो बाजार से कच्चा माल या नवीन सुविधायें प्राप्त करने का प्रयास करते थे।

उपनिवेश विरोधी आन्दोलन के सफल हो जाने के बाद यह निश्चित नहीं रहता था कि प्राप्त की गई स्वतन्त्रता का स्थायित्व बना रहेगा।

अफ्रीका के अनेक देशों को इस बात का अनुभव है कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद उन्हें किस राजनैतिक कमजारी आन्तरिक असंतोष, शोषण एवं दबावों का सामना करना पड़ा। चीन जैसे साम्यवादी देश अफ्रीका के देशों की स्थिति को आग्नि की आर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। ये देश नवोदित एवं स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के मामलों को शीघ्र ही अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं।

नये स्वतन्त्रता प्राप्त देशों के नेता एवं समूह पर्याप्त प्रभावशील होते हैं किन्तु इन देशों का राष्ट्रवाद कमजोर होता है। जिन देशों में लोगों का जीवन परिवार, जाति, गांव, वर्ग आदि के आधार पर बंटा रहता है वहाँ राष्ट्रीय चेतना जागृत करना बड़ा कठिन बन जाता है। इन देशों में उपनिवेशवाद का विरोध राजनैतिक एकाग्रता एवं समानता के अतिरिक्त कुछ ही मूल्य ऐसे होते हैं जिनमें सभी का विश्वास हो।

पश्चिमी योरोपीय एवं उत्तरी अटलांटिक क्षेत्रों में राष्ट्रवाद उस संस्कृति में मिला दिया गया जिसे औद्योगिक क्रान्ति द्वारा पहले ही बदला जा चुका था। यह राष्ट्रवाद उन सभी मूलों का स्थान देता है जिनमें सभी सामाजिक वर्गों का विश्वास है। अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जहाँ कि स्वतन्त्रता एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर जोर देने का कोई आधार ही नहीं है तथा कुछ ही अनीत के चरित्र ऐसे हैं जिनका गुणगान करके राष्ट्रीय भावना को जागृत किया जा सके। मध्यपूर्व एवं एशिया के अनेक भागों में राष्ट्रवाद का समर्थन मध्यम वर्ग एवं बौद्धिक, व्यावसायिक तथा राजनैतिक वर्ग द्वारा किया जाता है। अधिक्षित किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या राजनैतिक दृष्टि से उदासीन रहती है। नये देशों की अधिकांश राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाएँ स्वदेशी नहीं हैं वरन् पूर्व प्रशासकों से ग्रहण की गई हैं।

हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त देशों में से अधिकांश में राजनैतिक विकास के लिये उपनिवेशवादी शक्तियों ने किसी प्रकार की योजना नहीं बनाई। इसके विपरीत उन्होंने राजनैतिक गतिविधि को हतोत्साहित किया तथा स्वदेशी नेताओं को जेल में रखा। ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक है कि इन देशों की स्थानीय परिस्थितियाँ प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं के लिए उपयुक्त नहीं हों और न ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकें। जिन राजनैतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से एक प्रजातन्त्रात्मक एवं बहुलवादी समाजवाद कार्य करता है, वे एक सम्ये सामाजिक विकास का परिणाम होती हैं। यही

कारण है कि इनमें से अधिकांश देशों में सत्तावादी तानाशाही सरकारें कायम हो गईं। केवल कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय सरकार में योगदान की परम्परा लागू की गई या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन देशों में जातीय स्वामिमत्ति की बड़े काफ़ी गहरी हैं। महा विदेशियों तथा केन्द्रीय नियंत्रण को सदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इन कारणों से प्रजातन्त्रात्मक राजनैतिक संस्थाओं का विकास रुक जाता है।

नया राष्ट्रवाद यह निश्चित नहीं करता कि आर्थिक विकास किस रूप में किया जाना चाहिये। उपनिवेशवाद तथा विदेशी प्रभाव के डर से ये देश विदेशी सामान, योग्यता एवं पूँजी की डर की भावना से देखते हैं और इस प्रकार आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाते हैं।

नये राष्ट्रवाद में नेतृत्व का मुख्य स्थान है। नये राष्ट्रवाद से सम्बन्धित कुछ नेताओं ने अपने व्यक्तित्व में अनेक रहस्यमय विशेषताएँ समाहित कर ली हैं। यदि इन देशों में सार्वजनिक शिक्षा के आधार पर प्रजातन्त्र का विकास न किया गया तो यह नेतृत्व तानाशाही बन सकता है। भविष्य, गरीबी तथा उत्तरदायी सरकार में अनुभव का अभाव आदि बातें कानियों एवं बलबों का कारण बनती हैं तथा तानाशाही की नियुक्ति का आधार प्रस्तुत करती हैं। एक दलीय शासन के होने पर रहस्यमय नेतृत्व एक नये देश के लिये नामकारी भी हो सकता है और नुकसानदायक भी। इस प्रकार का नेता प्रायः अपने आपको महत्वपूर्ण मान लेता है तथा यह सोचता है कि उसके देश के लिए क्या सबसे अच्छा है यह बान वह सदैव जानता है। नेतृत्व का यह रूप उस देश के लिये स्वाभाविक होता है जो सक्रमण काल में होकर गुजर रहा है तथा जहाँ अधिकांश जनसंख्या प्रशिक्षित है। इतने पर भी इसके भविष्य में राजनैतिक एवं आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं।

एशिया और अफ्रीका के अधिकांश नेताओं ने पश्चिम में शिक्षा प्राप्त की है तथा वहाँ उदारवाद का अध्ययन किया है किन्तु फिर भी उनका विश्वास है कि यह व्यवस्था एवं स्वतन्त्र उच्चम व्यवस्था उनके देश के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ अधिक तथा सांस्कृतिक महत्व की हैं जिनको समाजवादी व्यवस्था द्वारा ही मुलभामा जा सकता है। इस व्यवस्था में सरकारी नियोजन एवं नियंत्रण आवश्यक बन जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से सोवियत संघ ने इन देशों में राष्ट्रीय आन्दोलनों

का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया है। साम्यवादी चीन ने भी इन देशों की उपनिवेशवाद विरोधी भावनाओं के साथ मिल कर चलना प्रारम्भ कर दिया है। रूस एवं चीन आदि देशों द्वारा इन देशों के विद्यार्थियों को पूरा ध्यय देकर आमंत्रित किया जाता है। उनके विचारों को साम्यवादी रंग में रंग दिया जाता है और इस प्रकार उनको उनके देश में आन्ति क लिए प्रयास करने को कहा जाता है।

राष्ट्रवाद के उक्त रूपों के क्रम एवं नामकरण के सम्बन्ध में सभी विचारक एक मत नहीं हैं। क्विन्सी राइट (Quincy Wright) ने राष्ट्रवाद के पाँच रूपों का वर्णन किया है। ये हैं—मध्यकालीन राष्ट्रवाद (Medieval Nationalism), राजतन्त्रीय राष्ट्रवाद (Monarchical Nationalism), क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद (Revolutionary Nationalism), उदार राष्ट्रवाद (Liberal Nationalism) तथा सर्वाधिकारवादी राष्ट्रवाद (Totalitarian Nationalism)। राष्ट्रवाद के इन विभिन्न रूपों में अधिक राष्ट्रवाद को कोई स्थान प्रदान नहीं किया गया है। स्नाइडर (Snyder) महोदय राष्ट्रवाद को कालक्रम के अनुसार चार भागों में विभाजित करते हैं। ये हैं—एकीकृत राष्ट्रवाद (Integrated Nationalism) १८१५-७१, विच्छिन्न राष्ट्रवाद (Disruptive Nationalism) १८७१-९०, आक्रमणकारी राष्ट्रवाद (Aggressive Nationalism) १९००-४५ तथा वर्तमान राष्ट्रवाद (Contemporary Nationalism) १९४५ से अब तक।

राष्ट्रवाद का मूल्यांकन (Evaluation of Nationalism)

राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इतना रम चुका है कि उसे अलग करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नहीं समझा जा सकता। राष्ट्रवाद के समर्थक और आलोचक दोनों ही हैं। एक ओर तो ये विचारक हैं जिनके मतानुसार राष्ट्रवाद की भावना एक जनसमुदाय के लिए बरदान के समान है। इन विचारकों को राष्ट्रवाद में केवल शुण और अच्छाईयाँ ही दृष्टिगत होती हैं। दूसरी ओर विचारकों का एक ऐसा समुदाय बनता जा रहा है जो राष्ट्रवाद की भावना को मानवता के लिए अभिशाप मानता है। ये विचारक मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक हैं। दोनों ही पक्षों द्वारा अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं।

(१), राष्ट्रवाद एक बरदान है—राष्ट्रवाद की भावना को हम, हम, हम, हम की उपमा प्रदान कर सकते हैं जो बिखरे हुए सुमनों को इकट्ठा करके

एक मान्य का रूप प्रदान करता है। मनुष्य-मनुष्य के बीच शारीरिक व मानसिक अनेको प्रकार की असमानताएँ पाई जाती हैं। इन असमानताओं के होते हुए भी सामूहिक हित के लिए वे व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलाजलि देने के लिए तैयार होते हैं, यह केवल राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने पर ही सम्भव होता है।

राष्ट्रवाद एक देश के लोगों में उनकी संस्कृति धर्म, सम्पत्ता, साहित्य, कला आदि के प्रति गर्व की भावना का उदय करता है। उनमें आत्म सम्मान के भावों को जाग्रत करता है। अतीत की गौरव-नाथाएँ मविष्य के निर्माण की प्रेरणाएँ बन जाती हैं। राष्ट्रवाद के प्रभाव में एक देश के निवासियों के दिलों में जो हीनता की भावना आ जाती है उसके होते हुए यह देश प्रगति नहीं कर सकता। वह अपनी स्वतन्त्रता भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता।

राष्ट्रीयता की भावना साम्राज्यवाद के बन्धनों को काटने में रामबाण का कार्य करती है। साम्राज्यवादी देशों का सदैव यही प्रयास रहता है कि पराधीन देश में जहाँ तक सम्भव हो, राष्ट्रीयता की भावना का विकास न होने दिया जाय क्योंकि राष्ट्रीयता प्रायः स्वतन्त्र राज्य की मांग करती है।

राष्ट्रीयता के दो रूप हैं—एक नकारात्मक (Negative) और दूसरा सकारात्मक (Positive)। अपने सकारात्मक (Positive) रूप में राष्ट्रीयता की भावना एक देश के बहुमुखी विकास में प्रयत्नशील रहने के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ सहयोग व सहानुभूति के साथ रहने का भी प्रयास करती है।

राष्ट्रवाद एक मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। व्यक्ति की अनेक मानसिक प्रवृत्तियों को राष्ट्रवाद के उपवन में आश्रय प्राप्त होता है जो अपने विकृत रूप में समाज विरोधी भी सिद्ध हो सकती है।

(२) राष्ट्रवाद के छतरे—राष्ट्रवाद का दूसरा पक्ष इतना मयकर है कि उसकी तुलना में राष्ट्रवाद की अन्धछाड़ियों वाला पलड़ा शोचनीय रूप में हल्का पड़ जाता है। आज तक वे इतिहास में जो लड़ाइयाँ लड़ी गयीं; यदि हम उनके मूल कारणों की खोज करें तो पायेंगे कि सबके मूल में मिलती-जुलती सी ही भावनाएँ थीं। वे ही राष्ट्रवाद के विभिन्न रूप थे।

राष्ट्रवान अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करना ही नहीं सिखाता बरन् यह दूसरे देशों की उपलब्धियों पर जलन करना भी सिखाता है। इस जलन के परिणामस्वरूप दूसरे देश को बर्बाद करके अपने आपको समृद्ध करने की दृष्टि से उस देश पर आक्रमण किये जाते हैं। भोपण नर सहार होता है। सदियों की सचित सभ्यता, संस्कृति एवं कला की विरासतें इन युद्धों की आग की आहुति बन कर स्वाहा हो जाती हैं। प्रो० हेज (Hayes) ने राष्ट्रीयता की आलाचना इसी आधार पर की है। यह हमको अपने राष्ट्र या जाति के बारे में अभिमान या गर्व करना सिखाता है तथा दूसरे राष्ट्रों के प्रति तुच्छता और विद्वेष के भाव भर देता है।

राष्ट्रीयता की भावना साम्राज्यवाद की प्रेरक व पालक है। यह देश को आक्रमणकारी बना देती है, उसे असहनशील बना देती है। इसी कारण इसे एक बुराई के रूप में तिरस्कृत किया जाना है। हेज के मतानुसार राष्ट्रवाद के दो रूप हैं, एक है—ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में तथा दूसरा है विश्वास के रूप में। हेज के विचारानुसार विश्वास के रूप में राष्ट्रीयता और कुछ नहीं बरन् एक अभिशाप है। मानवतावादी, अन्तर्राष्ट्रीयतावादी एवं विश्ववन्धुत्व में विश्वास रखने वाले प्रायः सभी विचारक राष्ट्रवाद को अपने मार्ग का एक रोड़ा मानते हैं जिसे हटाना परम आवश्यक है। १९वीं शताब्दी के एक रूसी दार्शनिक व्लादीमीर सोलोवी (Vladimir Solovyev) के मतानुसार राष्ट्रवाद अपने उग्र रूप में राष्ट्र को ही समाप्त कर देता है। यह मनुष्य जाति का शत्रु है। विक्टर गोलेन्ज (Victor Gollanez) ने लिखा है कि मैं सभी बुराइयों से घृणा करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि राष्ट्रवाद से मुझे सबसे अधिक घृणा है।

जॉन ड्रीवेट (John Drewett) ने लिखा है कि कट्टर राष्ट्रवाद मूर्तिपूजा के समान होता है। यह देश प्रेम के स्थान पर राज्य की पूजा कराना चाहती है। दूसरा की घृणा पर आधारित यह उनके अस्तित्व की एक चिरन्तन धमकी है। वर्तमान विश्व में समान रूप से इसी प्रकार का राष्ट्रवाद पाया जाता है। यह हमारे विश्व की समझने योग्य विशेषता है। आगे उन्होंने कहा है कि 'राष्ट्रीयतावाद अनुरक्षा और होनठपन की भावनाओं पर बनपता है और इसीलिए युद्ध तथा अशान्ति के समय इसे फैलाने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है।' ड्रीवेट (Drewett) महोदय राष्ट्रवाद को मनुष्य का एक दूसरा धर्म (Man's other religion) मानते हैं। उनके मतानुसार मनुष्य की तीन मौलिक आध्यात्मिक आवश्यकताएँ होती हैं —

- (१) एक उद्देश्य का ज्ञान (A sense of purpose)
- (२) महत्व की आवश्यकता (Need for Significance)
- (३) सुरक्षा की आवश्यकता (Need for Security)

धर्म में इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य थी किन्तु मात्र धर्म में से विश्वास उठ गया। बुद्धि का गुण भा गया है, धर्म निर्पेक्ष राज्य बहने जा रहे हैं, साम्यवादी देशों ने तो धर्म को हटा ही कर डाला है। यही कारण है कि इन तीनों मूल आवश्यकताओं को राष्ट्रवाद की मावना के माध्यम में जाना पड़ा। वहाँ इनकी पूर्ति हुई। राष्ट्रवाद व्यक्ति को तीन मुख्य कारणों से प्रभावित करता है—

(१) यह राष्ट्रीय समुदाय की सेवा करने का स्पष्ट उद्देश्य उसके सामने रख देता है।

(२) राष्ट्रवाद व्यक्ति को यह सोचने के अवसर देता है कि व्यक्ति के जीवन का भी कुछ महत्व है।

(३) राष्ट्रवाद व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके अपने हित का रक्षक व्यक्ति भकेला हो नहीं बरन् पूरा राष्ट्र है।

राष्ट्रवाद में लितने भी गुण हो किन्तु यह भन्तराष्ट्रीय शान्ति के सर पर सर्वत्र सदरी रहने वाली डेमोक्रेसी की तरवार की तरह है। यह विश्व सरकार के माय में सबसे बड़ी बाधा है। पामर तथा परकिन्स ने राष्ट्रवाद को हमारे युग की एक महान समस्या स्वीकार किया है।

राष्ट्रीय आत्म-निर्णय का सिद्धान्त (Principle of National Self-determination)

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वह स्वयं ही (आत्म) यह निर्णय ले कि क्या उसे पृथक से अपने लिए एक राज्य बना लेना चाहिये अथवा बिना राज्य में यह इस समय है उनी में उसको रहना चाहिये। कुछ विचारकों के मतानुसार प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार स्वशासित, सम्प्रभुता-सम्पन्न राज्य की स्थापना कर ले। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्रीयता के पास उसका अपना एक राज्य हो जायगा। इस सिद्धान्त के समर्थकों का यह कहना है कि यदि एक ही राज्य में कई राष्ट्रीयताओं के व्यक्तियों को रखा गया तो वह राज्य अपने नागरिकों की समान नृत्ति प्राप्त करने में बाधित

सफल नहीं हो सकेगा। आये दिन उाद्रव तथा भगडों के कारण आन्तरिक शान्ति खतरे में पड़ जायगी। इसे दूसरी तरह भी देखा जा सकता है अर्थात् यह माना गया कि यदि एक ही राष्ट्रियता के लोग एक राज्य में न रहकर अनेक राज्यों में रहें तो उनका विकास उनना तथा उतने समय में नहीं हो सकता जो उनके एक ही राज्य में निवास करने पर हो सकता था। इन बिखरी हुई राष्ट्रियताओं को प्रायः विकलाक सामाजिक संगठन (Dismembered Social Organisation) की सत्ता प्रदान की जाती है। विकलाक व्यक्ति की भाँति ऐसा समाज निष्क्रिय बन जाता है या बहुत धीमी गति से विकास के मार्ग पर कदम बढ़ाता हुआ चलता है। यही कारण है कि विभिन्न विचारकों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि राज्य तथा राष्ट्रियता की सीमाएँ एक ही होनी चाहिये। मिल (J S Mill) के मतानुसार ऐसा होना स्वतन्त्रता के हित में है।

दूसरी ओर विचारकों का एक ऐसा समुदाय भी है जो राष्ट्रीय आत्मनिभरता के सिद्धान्त का विरोध करता है। इन विचारकों ने अपने पक्ष के समर्थक में तर्क प्रस्तुत किये हैं। यह कहा जाता है कि इस सिद्धान्त को मान लेने पर विश्व में सघर्ष तथा भगड़े छिड़ जायेंगे क्योंकि वे राष्ट्रियताएँ जो इस समय एक राज्य के अधीन मुक्त एवं आनन्द से जीवन-यापन कर रही हैं अपना पलग राज्य बसाने की माग करेंगी। गृह-युद्ध बढ़ जायेंगे और इस प्रकार यह सिद्धान्त देशभक्ति की भावना को भग्नबूत बनाने की अपेक्षा उसे खण्डित कर देगा।

इन विचारकों का दूसरा तर्क, जैसा कि जोसेफ ने भी माना है, यह है कि राष्ट्रियता और राज्य दो भिन्न चीजें हैं, इनको एकाकार करने का प्रयास निरर्थक एवं अनुपयोगी है। एक राज्य में अनेक राष्ट्रियताएँ आसानी से रह सकती हैं जैसा कि ब्रिटेन और सोवियत रूस में देखा जा सकता है। इसी प्रकार एक राष्ट्रियता भी अनेक देशों में बिखरी रह सकती है। सारे मुक्तमान पाकिस्तान में ही नहीं बँठ गये हैं वे विश्व के अन्य देशों में भी बिखरे पड़े हैं, इनकी देश-भक्ति की भावना के बारे में शका नहीं की जा सकती। भारत पाक युद्ध में भारत की ओर से लड़ने वाले युगलमान सैनिक अपने देश के लिए व अपनी मातृभूमि के लिए म्रून बहा रहे थे, उनके दिलों में भारत के प्रति देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। उन्होंने यह जानने की चेष्टा न की कि दुश्मन की राष्ट्रियता क्या है। दुश्मन विदेशी है और आक्रमणकारी देश का नागरिक है, यही जानना उसके लिए काफी था। राष्ट्रियता का अर्थ, जैसा कि जोसेफ ने भी माना है, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन

में स्वाधीनता से है। भारत जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी राष्ट्रीयताओं को रहने की स्वाधीनता है। इन उदाहरणों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि अनेक राष्ट्रीयताएँ एक ही राज्य में शांति व सहयोग के साथ निवास कर सकती हैं तथा उनमें से प्रत्येक अपने राष्ट्रीय जीवन का पालन कर सकती है।

इन तर्कों के आधार पर जोसेफ (Bernard Joseph) ने माना है कि एक राष्ट्रीयता एवं एक राज्य का सिद्धान्त एक सतरनाक सिद्धान्त है जो विश्व की प्रगति में मुख्य बाधा है। लार्ड एक्टन (Lord Acton) ने इस सिद्धान्त को समाजवाद के सिद्धान्त से भी अधिक भयंहीन तथा अपराधमूलक बताया है।

इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में विचारकों का एक तीसरा समुदाय और भी है जो उक्त दोनों पक्षों के बीच का मार्ग अपनाता है। इस समुदाय के विचारकों का मत है कि अधिकार एकांगी नहीं होते, उनके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े रहते हैं। साथ ही अधिकार किसी की दोगुनी नहीं होते वे तो कुछ शर्तें पूरी करने के बाद स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। हॉकिंग ने कहा है कि किसी भी राष्ट्रीयता अथवा जाति को यह जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह एक राज्य बन ही जाय। रामजेम्स ने इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा है कि मोटे तौर पर ही यह बात सही है कि प्रत्येक राष्ट्र या जाति की स्वाधीनता और एकता का अधिकार होता है। व्यक्तियों की भांति राष्ट्रों या जातियों को भी अपने अधिकारों का अर्जन करना होता है।

डा० आशीर्वादम के मतानुसार कोई भी राष्ट्र स्वतन्त्र या सम्प्रभु बने इससे पहले उसे निम्न शर्तें पूरी करनी चाहिए—

(१) उसमें अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था करने की और अपने प्राकृतिक साधनों तथा पूँजी का विकास करने की क्षमता होनी चाहिये।

(२) उसे अच्छे कानूनों का निर्माण तथा न्याय की उचित व्यवस्था करनी चाहिये। देश से बाहर के न्यायालयों में जाने की आवश्यकता न रहे।

(३) वह एक उपयुक्त ढंग की सरकार बनाये।

(४) उसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये।

(५) यात्रा, व्यापार आदि करने की स्वतन्त्रता देनी चाहिये।

(६) वह विदेशी आक्रमणों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो।

उक्त पूर्व शर्तों को पूरा करने पर ही एक राष्ट्रीयता को स्वतन्त्र व

सम्प्रभु राष्ट्र बनाने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। इसके अभाव में दिये गये अधिकार का दुरुपयोग भी हो सकता है।

सम्प्रभुता की मान्यता (The Concept of Sovereignty)

राष्ट्रवाद की भाँति सम्प्रभुता भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आवश्यक तत्व है। सम्प्रभुता राज्य के उन तत्वों में प्रधान है जिसके अभाव में राज्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। मैकल्वेन (Mc Ilwain) के शब्दों में यह वह केन्द्रीय सूत्र है जिसके अधीन हम हमारे राजनैतिक जीवन के उन सभी तत्वों को बौद्धिक बनाने का प्रयास करते हैं।^१ सम्प्रभुता के रूप, प्रकृति एवं अर्थ के बारे में विचारकों में मतभेद नहीं है। इसके संबंध में सबसे अधिक विवाद तथा भ्रमों की स्थिति है।

सम्प्रभुता का अर्थ

अंग्रेजी भाषा के शब्द Sovereignty (सम्प्रभुता) की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द 'Superanus' से हुई है जिसका अर्थ है सर्वोच्च (Supreme)। सम्प्रभुता के सिद्धान्त की प्रारम्भिक व्याख्या करने वालों में बोदा, हॉब्स, लॉक व रूसो का नाम उल्लेखनीय है। प्राधुनिक काल में जेलोनेक (Jellineck), दुग्वा (Duguit), केलसन (Kelsen) और लास्की ने सम्प्रभुता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। सम्प्रभुता के ये विभिन्न विचारक अलग-अलग कर्मों की भाँति ये जिनमें डल कर सम्प्रभुता की समय-समय पर नये रूप मिलते रहे। कभी इसने स्वेच्छाचारी राजा का समर्थन किया तो कभी जनतान्त्रिक सरकार का, कभी इसका रूप अन्तर्राष्ट्रीय बन गया तो कभी यह उग्र राष्ट्रवाद की उत्तेजक बनी। बहुलवादी विचारकों ने तो इसका अस्तित्व ही मिटा देने का बीड़ा उठाया था। कोकर (Coker) महोदय के मतानुसार राजनीति शास्त्र में कोई भी शब्द इस प्रकार से विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त नहीं किया गया है।

सम्प्रभुता की वर्तमान विचारधारा का जन्मदाता १६वीं सदी का राजनैतिक विचारक बोदा (Jean Bodin) था, बोदा के अनुसार सम्प्रभुता नागरिकों पर और प्रजा पर एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जिस पर कानून का

निष्पन्न नहीं होता। सम्प्रभुता के रूप की व्याख्या करते समय बोदा के भक्तिपूर्ण पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव था। उस समय उसने जैसा आवश्यक समझा उसी रूप में सम्प्रभुता को परिभाषित किया। सम्प्रभुता को इस परिभाषा के दो महत्वपूर्ण प्रभाव हुए—(१) इसने ऐसे राज्य की स्थापना की जो पूर्ण तथा असीम था तथा जिसकी सत्ता को कोई भी माननीय शक्ति चुनौती नहीं दे सकती। (२) इसने पोप के सार्वभौमिक अधिकार पर प्रहार करके साम्राज्यशाही तथा एकता को विच्छिन्न करने वाली सामन्तवादी प्रवृत्तियों का विरोध किया। बोदा नहीं चाहता था कि उसकी सम्प्रभुता की परिभाषा एक स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश राजा का सृजन करे और इसी कारण उसने राजा की सर्वोच्च शक्ति पर नैतिक तथा परम्परागत अधिकारों के प्रतिबन्ध लगाये।

एक दूसरे विचारक प्रोमियस ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय (International Community) का समर्थन करते हुए सम्प्रभुता को इसके कानूनों से सीमित माना। उसके अनुसार सम्प्रभुता एक सर्वोच्च राजनैतिक शक्ति थी—इसे वह ऐसे व्यक्ति से निहित करता है जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन न हों तथा जिसकी इच्छा का कोई उत्तरदायक या अतिक्रमण न कर सके। उसने माना था कि वह किसी राज्य पर शासन करने की एक नैतिक शक्ति होती है। प्रोमियस ने राष्ट्रीय सम्प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्रभुता से एकाकार किया। इसका समग्र सन्भवतः यह था कि राज्य की सत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त हो जाय।

एक फ्रांसीसी विचारक दुगुय (Duguit) का विचार है कि सम्प्रभुता राज्य की वह शक्ति है जिसके अनुसार वह अपने राज्य व प्रदेश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को बिना किसी शर्त के आदेश दे सके। सम्प्रभुता राष्ट्र की इच्छा है जो एक राज्य में सङ्गठित होती है।

राजनीति के वर्तमान विचारकों की दृष्टि में सम्प्रभुता का रूप लगभग एक समान है। ओपेनहिम (Oppenheim), विल्लोबी (Willoughby) तथा केल्सन (Kelsen) आदि विचारक सम्प्रभुता को एकमत होकर सर्वोच्च शक्ति मानते हैं जो किसी प्रकार की भर्थादाओं को नहीं जानती। अमरीकन लेखक बर्गस (Burgess) ने माना है कि सब व्यक्तियों और व्यक्तियों के सभी पर मौलिक स्वेच्छाचारी और भ्रम्यदित शक्ति का नाम सम्प्रभुता है। नास्की, जो सम्प्रभुता के सिद्धांत पर आक्रमण करने वालों के प्रमुखा माने जाते हैं, यह मानते हैं कि बंध रूप से राज्यसत्ता प्रत्येक व्यक्ति और

समुदाय से उच्चतर है, इसके नाम पर राजा विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पोलक महोदय ने सम्प्रभुता के रूप को सरल शब्दों में प्रकट किया है। वे मानते हैं कि सम्प्रभुता एक स्थायी शक्ति है, वह किसी दूसरे द्वारा नहीं दी जाती तथा वह किसी ऐसे नियम के अधीन नहीं है जिसे बदलने की शक्ति उसमें न हो।

सम्प्रभुता के सिद्धांत के जन्मदाता बोदो ने उसके ऊपर नीति और परम्पराओं की जो सीमाएँ लगाई थी, हाब्स ने उन सबको तोड़ दिया। हाब्स का सम्प्रभु पूर्ण रूप से निरकुण्ड है। सम्प्रभु के ऊपर केवल ईश्वर तथा ईश्वरीय नियमों का प्रतिबन्ध रहता है। किन्तु व्यवहार में यह प्रतिबन्ध न के बराबर है। सम्प्रभु स्वयं ही इन नियमों में सशोधन एवं परिवर्धन करता रहता है। हाब्स की परिभाषा के अनुसार राज्य की सत्ता की तुलना में अन्य सभी सत्ताएँ शक्तिहीन हैं। राजा कानून का निर्माता है। इस प्रकार हाब्स तथा बोदो दोनों ही विचारक सम्प्रभुता का निवास राजा में मानते हैं। रूसो के काल में जबकि राजतन्त्र का स्थान लोकतन्त्र लेता जा रहा था सम्प्रभुता का आश्रय एक व्यक्ति या राजा न रह कर जनता या बहुमत बन गया। आदमवादी विचारकों ने पुनः एक बार सम्प्रभुता राजा के हाथों में सौंप दी क्योंकि उनकी दृष्टि में सर्वोच्च समाज तथा समाज का रक्षक और मनुष्य के नैतिक एवं सुसंस्कृत जीवन का मूल था। बाद में बेन्थम जैसे उपयोगितावादी विचारकों ने सम्प्रभुता को संसद को सौंप दिया जो इतनी शक्तिशाली बन गई कि पुरुष को नारी और नारी को पुरुष में परिवर्तित कर सके।

बोदो के बाद सम्प्रभुता के सिद्धांत की विपद व्याख्या करने वाला तथा उसका वैधानिक विश्लेषण-कर्त्ता जॉन आस्टिन (John Austine) था। उसने बताया कि यदि किसी समाज का अधिकतर भाग सामान्यतः एक निश्चित प्रमुख व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और उस निश्चित व्यक्ति को किसी दूसरे प्रधान की आज्ञा मानने का अभ्यास न हो, तो वह निश्चित व्यक्ति उस समाज में सम्प्रभु है तथा वह समाज (उस प्रधान सहित) एक स्वाधीन राज्य है। आस्टिन की इस परिभाषा की हेनरी मेन, साहकी एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीयतावादी व बहुलवादी विचारकों ने कड़ी भलोचनाएँ की हैं। ये विचारक सम्प्रभुता जैसी किसी चीज का अस्तित्व न तो आवश्यक ही मानते हैं और न उपयोगी ही।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सम्प्रभुता

(The Concept of Sovereignty in International Politics)

सम्प्रभुता के अध्ययन से यहाँ हमारा तात्पर्य यह जानना है कि

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इस मान्यता का कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है तथा उस प्रभाव को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? सम्प्रभुता के व्याख्याकारों ने इसका अविभाज्य, स्वाधीन, असौमित्र, सर्वोच्च एवं विधि के स्रोत का जो रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे देखकर यह प्राशङ्क करता निराधार न होगा कि सम्प्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक घातक मान्यता है। अब प्रश्न यह है कि क्या सम्प्रभुता को समाप्त कर दिया जाय ? बहुलवादी विचारक ऐसा करने को शीघ्र ही तैयार हो जायगा। बहुलवाद के विचारकों ने सम्प्रभुता के प्रभाव में रहने वाली राज्य व समाज व्यवस्था का चित्र भी हमारे सामने रखा है। कहा जाता है कि राज्य सम्प्रभुता के बिना रह ही नहीं सकता क्योंकि सम्प्रभुता राज्य की आत्म शक्ति है। बहुलवादी इससे चिन्तित नहीं होता। उसकी दृष्टि से यह उपयुक्त है कि आतंकीय, शोषणकर्ता एवं हिंसामय इतिहास से रजित राज्य नाम की संस्था को यथाशीघ्र भली-भाँति की गयी बना दिया जाय। यह सुझाव व्यावहारिक जगत में मान्यता प्राप्त न कर पाया क्योंकि यह असम्भव था।

सम्प्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून

(Sovereignty and International law)

सम्प्रभुता का निरंकुश, अविभाजनीय तथा असौमित्र रूप अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल आधार को ही नष्ट कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का लक्ष्य विश्व के राज्यों के बीच के सम्बन्धों को उच्छेदित, भाकमणकारी तथा विध्वंसक होने से रोक कर विश्व-कल्याण की दृष्टि से उनका नियमन करना है। यह एक राज्य को मनमाने करने में रोकता है, उस पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना चाहता है। किन्तु इन प्रतिबन्धों व कानूनों, को वह सम्प्रभु जो किसी की आज्ञा मानने का अस्वस्त नहीं होता, कभी स्वीकार न करेगा। जैसस माटिन का कथन है कि सम्प्रभुता के समर्थकों के अनुसार प्रत्येक सम्प्रभु राष्ट्र 'राष्ट्रों के समुदाय' (Community of Nations) से ऊपर है और पूरी तरह से वह स्वतन्त्र है और इस प्रकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो राज्यों को प्रतिबंधित करता है, पालन नहीं किया जा सकता।

सम्प्रभुता और विश्व-शांति तथा सहयोग

(Sovereignty and World-peace and Co-operation)

सम्प्रभुता का विरोध विश्व-शांति के लिए सतत है। सम्प्रभुता की भावना राष्ट्रियता की भावना के साथ मिलकर साम्राज्यवाद और मुडों को

बढ़ावा देती है। आज की परिस्थितियों में बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का उचित संचालन करने के लिए राज्य की सम्प्रभुता को सीमित करना आवश्यक हो गया है। लास्की का मत था कि 'दूसरे राष्ट्रों के साथ एक राष्ट्र को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है' यह एक ऐसा विषय है जिसका लिए यह भ्रमेला ही नहीं हो सकता। यदि एक राष्ट्र अपनी मनमानी करना चाहेगा तथा अपनी सम्प्रभुता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कानून या अन्य देशों के प्रभाव को मानने से इन्कार कर देगा तो यह स्वभाविक है कि विश्व के राज्यों के बीच सघर्ष और तनाव उत्पन्न होगा। यही तनाव बढ़कर एक दिन विश्व युद्ध का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतन्त्रता समाज की परम्पराओं को तथा राज्य के कानूनों को मानने में है उसी प्रकार राज्य को भी विश्व समाज के कानूनों का पालन करना चाहिए। स्वतन्त्रता कभी निर्बाध नहीं होती। यही बात आज राष्ट्रीय सम्प्रभुता के बारे में भी कही जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रीय सम्प्रभुता नाम की कोई चीज नहीं है और नहीं रह सकती है। सर्वोच्च सम्प्रभु तो केवल एक ही रह सकता है, अनेक नहीं। ससार में सहयोग एवं शांति बनाय रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सम्प्रभुता की पुरानी परिभाषा को बदला जाय, जैसा कि पामर तथा परकिन्स का विचार है, या तो नई परिभाषा विकसित की जाय या पूरी मान्यता को ही ठुकरा दिया जाय। जहाँ तक सम्प्रभुता पर कानून की सीमाएँ लगाकर उनको व्यवहार में नहीं लाया जाता तब तक शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समाज की आशाएँ कम ही दिखाई देती हैं।

सम्प्रभुता के कुछ रूप

(Some Aspects of Sovereignty)

आजकल के अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता व सहयोग के बिना नहीं रह सकता। इसके लिए राज्यों को समझौते व सन्धियाँ भी करनी पड़ती हैं। फलतः प्रत्येक राज्य दूसरे राज्यों के प्रभावों सन्धियों, वायदों तथा आश्वासनों से घ घ जाता है। ऐसी स्थिति में उसे बौद्धा भयवा आइन्स्टीन का सम्प्रभु समझना पड़ेगा। सच तो यह है कि आज सम्प्रभुता के दो रूप बन गये हैं—राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्प्रभुता का रूप सर्वोच्च, स्थाई एवं अविभाज्य रह सकता है किन्तु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस पर अनेक सीमाएँ एवं प्रतिबंध लग जाते हैं। क्विन्सी राइट (Quincy Wright) के मतानुसार स्पूनिस्पल कानून की दृष्टि से सम्प्रभुता एक ऐसी इकाई है जिसे सीमित अथवा विभाजित नहीं किया जा

सकता किन्तु अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से इसे विस्तरेपित, विनाशित तथा सीमित किया जा सकता है।

क्लाइड ईगलटन (Clyde Eagleton) के मतानुसार सम्प्रभुता अपने पूर्ण रूप में कभी नहीं रह सकती। टक्का बटना है कि सम्प्रभुता को पूर्ण (Absolute) तथा निर्बाध (Unrestrained) मानना अथवा यह कतना कि सम्प्रभुता को छोड़ दिया जाय या मिला दिया जाय, यह दोनों ही वचन मूर्खतापूर्ण हैं। इस समय समस्या सम्प्रभुता को फैकने की नहीं है। यह आवश्यकता नहीं है कि सम्प्रभुता को मान्यता को ही नष्ट कर दिया जाय वरन् आवश्यकता यह है कि कुछ विषय जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं उन पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित किया जाय तथा अन्य पर राष्ट्र स्वयं ही नियंत्रण रखें। इस प्रकार दूसरे शब्दों में ईगलटन महोदय सम्प्रभुता का विनाश करने के पक्षपाती हैं।

दूसरी ओर मार्गेन्थो (Morgenthau) आदि विचारकों के मत में सम्प्रभुता अविभाज्य है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दृष्टि से पूरी सम्प्रभुता अथवा उसके किसी रूप को त्याग देना सैद्धान्तिक दृष्टि से असिपर तथा व्यावहारिक रूप से अतन्त्र है।

क्विन्सी राइट (Quincy Wright) महोदय ने सम्प्रभुता को आंशिक व पूर्ण (Partial and Full) तथा राजनैतिक व वैधानिक (Political and legal) आदि रूपों में विभक्त किया है। उनके मतानुसार सम्प्रभुता के तीन क्षेत्रों में सीमायें लगाना अति आवश्यक है —

(१) अंतर्राष्ट्रीय विवादों में स्वयं निर्णय देने की शक्ति (The power of self judgement in international controversies)

(२) अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सशस्त्र सैनिक शक्ति का निर्माण एवं प्रयोग की शक्ति (The power to prepare and use armed Forces in international relations)

(३) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर मनमाने प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति (The power to impose arbitrary barriers to international trade)

प्रत्येक राष्ट्र की इन तीनों ही शक्तियों का प्रतिबन्धित एवं सीमित करना आवश्यक बन गया है। कोहेन (E.H. Cohen) के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व सम्प्रभुता को हमारे सामने तीन रूपों में रखता है—

(१) सम्मिलित सम्प्रभुता की मान्यता (Concept of Joint Sovereignty) इसका प्रयोग सभी राष्ट्र मिलकर समान रूप से कर सकते हैं। (२) विभाजित सम्प्रभुता (Divided Sovereignty), इसके अनुसार सम्प्रभुता आन्तरिक व बाह्य दो रूपों में बंट जाती है। (३) अन्तर्राष्ट्रीय निगमों की सम्प्रभुता (Sovereignty of International Corporation)। इन तीनों ही शक्तियों का उपयोग करते समय यदि राष्ट्र अपनी स्वतंत्र एवं निर्बाध इच्छा का प्रयोग करेंगे तो स्वानाधिक है कि यह उनके राष्ट्रीय हित के लिए अधिक उपयोगी होगा। किन्तु जहाँ तक सम्पूर्ण विश्व की शान्ति एवं सहयोगपूर्ण जीवन का सम्बन्ध है यह व्यवहार इसके लिए घातक रहेगा। समार से मघपों एवं युद्धों की सम्भावना को दूर करने के लिए इन तीनों शक्तियों के प्रयोग में प्रत्येक राष्ट्र पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है। इन प्रतिबन्धों को लगाते समय भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इनका उद्देश्य विश्व-हित हों न कि किसी गुट विशेष या देश विशेष के स्वार्थों की पूर्ति।

सम्प्रभुता पर चारों ओर से आघात किये गये। विचारों के क्षेत्र में इस विषय ने एक हलचल सी मचा दी। बहुलवादियों के तर्कों के प्रकाशन के बाद ऐसा लगने लगा कि शायद सम्प्रभुता की मान्यता मरने के लिए राजनीति शास्त्र के कोप से निकाल दी जावेगी। किन्तु ऐसा न हुआ। बहुलवादी एवं अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों की आवाजनाओं एवं प्रहारों ने राज्य की शक्ति की निरंकुशता को कम किया। अन्य समस्याओं का मनुष्य के जीवन में महत्व समझा जाने लगा। किन्तु राज्य का स्थान ग्रहण करने वाला कोई व्यावहारिक विकल्प सम्मुख न होने के कारण सम्प्रभुता पुनर्वन् बनी रही। काहन (H. E. Cohen) महोदय के मतानुसार सम्प्रभुता की विचारनाला (Theory of Sovereignty) बनी समाप्त नहीं हो सकती। यह शक्ति या शक्ति के स्तर को परिभाषित करने वाले पद (Term) के रूप में या वैधानिक व्यवस्था या उस व्यवस्था के किसी भाग के स्तर को या उस व्यवस्था की सर्वाधिकारता को परिभाषित करने वाले पद के रूप में मरिद्व बनी ही रहेगी। यह हा सकता है कि यदि आलोचकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप शब्द 'सम्प्रभुता' को मिटा दिया जाये, किन्तु सम्प्रभुता की जो मूल विशेषताएँ हैं वे मरने बनी ही रहेंगी। समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिए जब तक मनुष्यों में सामक ओर शामिल तथा नता ओर समर्थकों का भेद रहेगा तब तक सम्प्रभुता की मान्यता भी बनी रहेगी। शक्ति की आवश्यकता ओर उपयोगिता जब तक रहेगी तब तक सम्प्रभुता भी विनीन नहीं हो सकती। महात्मा गांधी ने भी अपने रामराज्यके सिद्धांत में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था। वे मानते थे

कि राज्य हिंसा तथा विध्वंसकारी शक्तियों पर आधारित है, यह मनुष्यों को मनुष्य के रूप में देखने में अग्रमर्थ है किन्तु फिर भी स्थितियाँ अभी ऐसी नहीं कि राज्य को नष्ट किया जा सके या उसकी सम्प्रभुता का गुचला जा सके। पामर तथा परकिन्स ने माना है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय समाज में प्रभावशाली रूप राष्ट्र राज्य व्यवस्था ही रहेगी तब तक सम्प्रभुता बनी रहेगी।

राष्ट्रीयतावाद और सम्प्रभुता की मान्यता दो ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में खलबली मी मचा दी है। इन दोनों का उपयोग विध्वंसक तथा रचनात्मक दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। अब समस्या यह है कि यदि ये दोनों विध्वंसक रूप धारण कर लें तो फिर क्या होना तथा उस समय की स्थिति को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके प्रतिरोधात्मक एवं प्रतिशोषात्मक दोनों ही प्रकार के कदम उठाना आवश्यक है। विश्व संस्था (U.N.O.) अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सदन्यवहार एवं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि साधनों द्वारा इन दोनों तत्वों के चारों ओर ऐसी बाड़ लगा दी जाय कि इनको उच्छूलित बनने का अवसर ही प्राप्त न हो सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इन दो प्रभावकारी तत्वों के बारे में यह कहना उचित एवं उपयुक्त न होगा कि इनकी प्रवृत्ति सुनिश्चित है तथा उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। इतिहास साक्षी है कि समय की परिस्थितियों के अनुसार इन दोनों की प्रवृत्ति में भी समय-समय महत्वपूर्ण मोड़ आते रहे हैं। विचारकों ने इसी कारण इनको लचीले सिद्धांत (Flexible doctrines) की संज्ञा प्रदान की है।

राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता दोनों ही सिद्धांत अपने आप में न अच्छे हैं न बुरे, न नैतिक हैं और न अनैतिक। ये तो एक घुरी के समान नैतिक दृष्टि से उदासीन हैं। यह आपकी इच्छा एवं मानसिक ततर पर निर्भर करता है कि आप उनका प्रयोग अपने पक्ष काटने में करते हैं अथवा किसी का रक्षा। सम्भावनायें दोनों ही मौजूद हैं। अमल में राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता दोनों ही दोष रहित हैं। यदि उनका इतिहास रक्त-रजित और काळा रहा है तो इनका उत्तरदायित्व इन भावनाओं पर डालना अधिक सगत नहीं कहा जा सकता। यह कुछ ठुने हुए राजनीतिज्ञों के कारणोंमें हैं जिनकी महत्वाकांक्षायें बड़ बड़ मानव सम्यता के विकास के मार्ग की बाधायें बनो हैं। बुरे इरादे तथा सीमित स्वार्थ का दृष्टिकोण होने पर बरदान भी अनिश्चाय में बदल जाया करते हैं। शिव और नरसामुर की पौराणिक कथा इसी भाव को अमिष्यक्त करती है। अब मैं हम पामर तथा परकिन्स महोदय के शब्दों की दुहराते हुए यह कह सकते हैं कि ये दोनों अनियंत्रित रही या इनका उपयोग किया गया तो ये

आततायी शासन का या युद्ध का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और यदि इन्हें रचनात्मक लक्ष्यों की ओर मोड़ा गया तो वे शुभ लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक अनेक कल्याणकारी मानवीय भावों को उत्प्रेरित कर देंगे।

सम्प्रभुता सम्बन्धी रूसी विचार (Russian Views on Sovereignty)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय स्वार्थ (National interest) की दृष्टि से ही कोई कार्य करता है अथवा किसी दृष्टिकोण को अपनाता है। सम्प्रभुता के सम्बन्ध उसके राष्ट्रीय स्वार्थ से प्रभावित सांविध्यत रुख की धारणायें विश्व के अन्य देशों से इतनी भिन्न हैं कि उनका उत्प्रेषण करना अप्राप्तगिक न होगा।

सांविध्यत रुख राष्ट्रीयता की भावना का पक्का समर्थक है। इनका पक्षपात करते हुए वह यह चाहता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता को बनाये रखे। सम्प्रभुता को सीमित करने अथवा उसका समर्पण करने का रुख सर्वदा ही विरोध करता रहा है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर इतना जोर देने के कारण ही रुस ने सुरक्षा परिषद में बड़ी शक्तियों के एक मत होने की आवश्यकता का पूरा-पूरा समर्थन किया। जब भी किसी निषेधाधिकार (Veto power) को सीमित करने का प्रश्न आया, सोवियत रुस ने उस पर विचार करता भी उचित नहीं समझा क्योंकि यह उसकी सम्प्रभुता और सर्वोच्चता के विपरीत जाता था।

साम्यवादी रुस के चारों ओर पश्चिमी गुट ने सैनिक गठबन्धनों के आवार पर एक घेरा सा बना लिया था ताकि साम्यवाद का आगे प्रसार रुक जाय तथा उस घेरे के भीतर उसका दम घुट जाय। सम्प्रभुता के समर्पण की रूसी राजनीतिज्ञा द्वारा जो व्याख्या की जाती है उसका अनुसार यह पश्चिमी देशों की एक चाल है तथा उनके साम्राज्यवादी भावनाश्रा की इसमें अभिव्यक्ति होती है। यदि एक देश जो आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं अन्य दृष्टियों से अविकसित है अपनी सम्प्रभुता का समर्पित कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? रूसी विचारकों के मतानुसार वह देश पूरी तरह से शक्तिशाली राष्ट्रों के हाथ में चला जायगा, एक बिना डोरी की बछलुतली बन जायगा।

राष्ट्रवाद की भांति सम्प्रभुता भी एक ऐसी धारणा है जो प्राचीन राष्ट्रों की साम्राज्यवादी देशों के अंगुल से छुड़ाती है तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति-कोदित राष्ट्रों को उनके प्रभाव से दूर रख सकती है। यदि ऐसे देशों से शिखा

नौ प्रकार का प्रलोभन देकर या आदेशों के महल दिखाकर छोन लिया गया तो शोषण के विरुद्ध प्रारम्भ की गई क्रांति की गति बहुत धीमी पड़ जायगी। कोरोविन (E A Korovin) जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सोवियत दृष्टिकोण के माहिर हैं, के मतानुसार एक राज्य जहाँ वास्तविक प्रजातन्त्र स्थित है, अपनी सम्प्रभुता को सीमित करने के लिए कभी राजी न होगा। अपनी इच्छा से की गई सन्धिया, समझौते आदि सम्प्रभुता को सीमित नहीं करते, इसकी सीमाएँ तो एक पक्षीय रूप में ऊपर से थोपी जाती हैं।

सम्प्रभुता को सीमित करने वाली हरेक चेष्टा के प्रति रूस का रुख सशक्त हो जाता है। उसे लगता है कि यह उसकी पूर्ण सम्प्रभुता को एक चुनौती दी गई है। रूस द्वारा सीमित सम्प्रभुता का विरोध करने के मुख्य कारण दो हैं—

(i) पूँजीवादी राष्ट्रों से घिरा हुआ रूस सम्प्रभुता के समर्पण के नाम पर अपने आदेशों के विरोधी राजनैतिक व आर्थिक तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहता क्योंकि ऐसा करने से समाजवादी क्रांति में विलंब हो जायगा तथा रूस के सम्भावित मित्रों की सहायता घट जायगी।

(ii) सम्प्रभुता का अर्थ, रूस की निगाहों में, यह नहीं कि एक राज्य मनमाने ढंग से निरक्षुण्ण शक्ति का प्रयोग करे। रूस सम्प्रभुता को धरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में आत्मनिर्णय (Self determination) का सिद्धान्त मानता है। सम्प्रभुता एक प्रकार की वैधानिक दीवार है जो साम्राज्यवादियों के सैनिक तथा आर्थिक आक्रमणों से राष्ट्रों की रक्षा करती है। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार असीमित सम्प्रभुता (Unlimited Sovereignty) रूसी अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ऐसी विशेषता है जो उससे अलग नहीं हो सकती।

PART—II

International Politics as a struggle for power : Concept of National Power; Essence and elements of National Power: Geography, natural resources, population, technology, ideologies, morale, leadership : Evolution of national Power.

अध्याय ३—राज्य-शक्ति का सामान्य विचार
[The concept of National Power]

अध्याय ४—राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : भूगोल और प्राकृतिक तत्व
[The Elements of National Power :
Geography and Natural Resources]

अध्याय ५—राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : जनसंख्या और तकनीकी
[The Elements of National Power :
Population and Technology]

अध्याय ६—राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : विचारधारा, मोरेल और नेतृत्व
[The Elements of National Power :
Ideology, Morale and Leadership]

"राजनीतिक संदर्भ में शक्ति का अर्थ है—मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो।"

—मोरगेन्थो

"भौतिक भूगोल विश्व राजनीति को अधिक निरन्तर रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है। यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों, नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है जिनको राज्य अपने हितों की दृष्टि से मानते हैं।"

—वेडलफोर्ड तथा लिंकन

"यहाँ से जनसंख्या के आधार तथा एक देश की शक्ति के बीच कोई आवश्यक एवं एकरूप सम्बन्ध नहीं है किन्तु फिर भी इतना तो सच है कि छोटी सी जनसंख्या वाला कोई देश बड़ी शक्ति नहीं बन सकता।"

—जोसेफ कंकल

"अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के एक अनुशासन के रूप में तर्कनीकी एक ऐसा विज्ञान है जो आविष्कार और मौलिक सृष्टि की प्रगति को विश्व राजनीति से सम्बन्धित करता है। यह यांत्रिक प्रयासों के विकास की वधा है जो युद्ध, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और संचार में इसका प्रयोग करती हैं।"

—विक्सी राइट

"विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निवास है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कार्यों की योजना तैयार करती है।"

—वेडलफोर्ड तथा लिंकन

"राष्ट्रीय मनोबल (Morale) निश्चय का वह अनुपात है जिसके अनुसार एक राष्ट्र आग्नि एवं युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। मनोबल में राष्ट्र की सारी क्रियाएँ—भौद्योगिक व कृषि उत्पादन तथा सैनिक तैयारियाँ और कूटनीतिक सेवाएँ, समाहित होती हैं।"

—मार्गेन्थो

राष्ट्रीय शक्ति का सामान्य विचार (THE CONCEPT OF NATIONAL POWER)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सबसे बड़ी एवं कठिन समस्या यह स्पष्ट करना मानी जाती है कि एक राष्ट्र ने जिस रूप में व्यवहार किया है, उसने उसी रूप में क्यों किया, अन्य रूप में क्यों नहीं किया। विचारको द्वारा इस स्पष्टीकरण के लिए अनेक कारण प्रस्तुत किये जाते हैं। कोई 'शक्ति' की प्रमुखता देता है तो कोई 'राष्ट्रीय हित' को, जबकि कुछ लोग दोनों को एक साथ मिला कर प्रस्तुत करते हैं। कुछ एक विचारकों का मन है कि विचार-धारा राष्ट्रीय व्यवहार की सबसे बड़ी प्रेरक होती है। अन्य लोग राष्ट्रीय व्यवहार का बीझीकरण उस राष्ट्र के उपलब्ध साधनों, महत्वाकांक्षामो, राष्ट्रीय चरित्र, भाषिक स्थिति एवं भौगोलिक स्थिति आदि के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। किन्तु वर्तमान काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अधिकांश विद्वान् यह मानने लगे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्पन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, प्राप्त शक्ति को बढ़ाने, शक्ति का प्रदर्शन करने आदि से सम्बन्ध रखता है। ये विचारक इस तर्क को गुनना पसन्द नहीं करते कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ के लोग लड़ाकू होते हैं अथवा जर्मनी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। वे इसका वास्तविक कारण जानना चाहते हैं जो शक्ति को राजनीति का ही एक पहलू है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक रूपता एवं मानवीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर ही परिभाषित किया जा सकता है।

‘शक्ति’ का अर्थ प्रायः उस तत्व से लिया जाता है जिसके आधार पर एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के मन, कर्म तथा विचार पर प्रभाव एवं नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त होता है। शक्ति का यह रूप सभ्यता के प्रारम्भ से ही मानव-समाज में अपना अस्तित्व बनाये हुए है। मानव सभ्यता के आदि-काल में शक्ति का स्वरूप एवं प्रकृति तो यही थी किन्तु उसका क्षेत्र आज की भाँति विस्तृत न होकर सकुचित था। आज ‘शक्ति’ का क्षेत्र केवल व्यक्तिगत न रह कर राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके अन्तर्राष्ट्रीय बन गया है तथा इसकी इकाईया केवल व्यक्ति न रह कर राष्ट्र बन गये हैं। राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र की आभाओं और महत्वाकांक्षाओं को परिपूर्ण करने का उसके हाथों में एक ऐसा अस्त्र है जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उसका स्तर, महत्व एवं स्थान आका जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय शक्ति एक मापदण्ड का कार्य करती है जिसके आधार पर हम किसी भी राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का मूलांकन कर सकते हैं और इस प्रकार अन्य देशों को भी अपनी विदेश नीति में तदनुकूल समायोजन (adjustment) करने का अवसर प्राप्त हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्रीय शक्ति (National Power) को एक राष्ट्र का सबसे बड़ा केन्द्र बिन्दु माना है जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। सभी विद्वान् एकमत होकर यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक राज्य अपने स्वार्थ कि दृष्टि से ही क्रियाओं का संचालन करता है। एक राज्य का सबसे बड़ा स्वार्थ यह है कि वह अधिक से अधिक राष्ट्रीय शक्ति का अर्जन करे, जिन माध्यमों एवं तत्वों के द्वारा राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है उनकी ओर वह पर्याप्त ध्यान दे तथा उनके विकास एवं अनिवर्धन में अपना सारा ध्यान केन्द्रित करे। यदि कोई भी राष्ट्र इस सिद्धांत के विपरीत आचरण करके अपनी राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर बनाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि वह स्वयं ही अपने विनाश के बीज बो रहा है। ये बीज धीरे धीरे अकुरित एवं प्रसृष्टित होकर उस देश की स्वतन्त्रता के लिए एक गम्भीर समस्या बन जायेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी सिद्धान्त (Realist theory) इस बात पर अधिक जोर देता है कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के रूप में परिमाणित स्वार्थ की दृष्टि से ही मौजूद है।

एक राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों की एक इकाई के रूप में जो शक्ति होती है वह उस राज्य का राष्ट्रीय शक्ति के समकक्ष नहीं होती क्योंकि ‘राष्ट्र’ जैसा कि कि मार्गेन्यो महोदय का कथन है, एक निगूढ़ (Abstract) तत्व है

जो समान विशेषतायें रखने वाले उस देश के सभी निवासियों से पृथक् होता है ।¹ कारण यह है कि उस देश के निवासी कुछ समान राष्ट्रीय विशेषताओं का पालन करने के अतिरिक्त अन्य अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि समस्याओं के भी सदस्य होते हैं तथा तन्नुकूल व्यवहार करते हैं । राष्ट्र की विदेश नीति का संचालन एवं राष्ट्र की शक्ति का प्रयोग प्रत्येक निवासी की सामर्थ्य एवं योग्यता के बाहर का विषय है । यह उस राष्ट्र के चुने हुए नेताओं के हाथ में रहती है और इसीलिए एक राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि का तात्पर्य यह नहीं होता कि अब उसका प्रत्येक व्यक्ति शक्तिशाली हो गया है किन्तु केवल वे लोग जो अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर होने वाले घर्षणों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वे ही एक राष्ट्र की बढ़ती हुई शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं । यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतवर्ष का स्थान ऊँचा है तो निश्चय ही उसके राजनीतिज्ञों का स्थान भी सम्माननीय एवं उत्कृष्ट समझा जायगा । यहाँ यह प्रश्न ही सकता है कि जब एक व्यक्ति पर उसके राष्ट्र की शक्ति एवं विदेश नीति का सीधा प्रभाव नहीं होता तो वह किस आधार पर अपने आपको उनके समरूप मान लेता है । इस प्रश्न का उत्तर एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा दिया जा सकता है जिसके अनुसार अविज्ञान व्यक्तियों को उनके राष्ट्रीय जीवन में कोई सम्मान और इज्जत प्राप्त नहीं हो पाती जिसके लिये वह सदैव प्रयत्न करता रहता है । अपने इस प्रभाव की पूर्ति वह दूसरे रूप में कर लेता है अर्थात् उसके देश के प्रतिनिधियों को अन्तर्राष्ट्रीय वगैरह में जो सम्मान प्राप्त होता है उसको वह स्वयं का सम्मान मान लेता है । जिस शक्ति को व्यक्तिगत जीवन में एक बुराई माना जाता है तथा जिसे प्रजातन्त्र, समानता व स्वतन्त्रता के विरुद्ध माना जाता है उसी शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तथा शक्ति प्राप्त करने के सभी प्रयासों को न्यायोचित ठहराया जाता है । राष्ट्रीय शक्ति के साथ अपनी शक्ति को समरूप बनाने वाले लोग प्रायः मध्यमवर्गीय परिवारों के होते हैं जिनके पास शक्ति की मात्रा प्रायः अपर्याप्त रहती है तथा जो अपने आपको असुरक्षित अनुभव करने हैं ।

राष्ट्रीय शक्ति का रूप एवं स्तर का निर्धारण हमेशा तुलनात्मक रूप से ही किया जाता है । एक राष्ट्र कमजोर है यह कहने समय हमारे मस्तिष्क में एक दूसरे राष्ट्र का चित्र भी रहता है जो इससे अपेक्षाकृत शक्तिशाली होता है । इसी प्रकार एक राष्ट्र को शक्तिशाली कहते समय हमारे

ध्यान में कमजोर राष्ट्र की मूर्ति रहती है। इस प्रकार की तुलना करते समय यह ध्यान रहना चाहिये कि हम एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व की तुलना दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति के उसी तत्व के साथ ही कर सकते हैं।

इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति की पहली विशेषता उसका 'तुलनात्मक रूप' होता है। इसकी दूसरी विशेषता के अनुसार राष्ट्र शक्ति का चरित्र स्थायी नहीं होता। उसके विभिन्न तत्वों का रूप एवं स्तर समय-समय पर बदलता रहता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसके सभी तत्वों का महत्व समान होता है। राष्ट्रीय शक्ति के किसी एक तत्व को अधिक महत्व देकर उसके आधार पर ही यदि एक देश अपनी विदेश नीति का निर्माण कर लेगा तो उसे निश्चय ही असफलता प्राप्त होगी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रायः भूगोल की राजनीति (Geopolitics), राष्ट्रवाद (Nationalism) और सैनिकवाद (Militarism) पर अधिक जोर दिया जाता है जो राष्ट्रीय शक्ति के प्रतिनिधि न होकर उसके केवल एक तत्व के परिचायक मात्र हैं।

कुछ विद्वानों के मतानुसार एक देश के व्यवहार रहन-सहन, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर दूसरे देश का जो प्रभाव पड़ता है वह भी शक्ति का एक रूप माना जायेगा क्योंकि शक्ति आवश्यक रूप से अपने आपकी हिंसात्मक रूप में ही प्रकट करती हो, यह बात नहीं है। वह शान्तिपूर्ण तरीके से 'प्रभाव' के रूप में हो सकती है। आज के युग में विश्व जनमत (World public opinion) का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भारी प्रभाव होता जा रहा है। अनेक देशों को अपनी विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय केवल इसी कारण बदलने पड़े हैं क्योंकि विश्व जनमत ऐसा होने के पक्ष में था। विश्व जनमत को बनाने के लिये प्रत्येक देश प्रचार के साधनों का समुचित विकास करता है ताकि विश्व के अन्य देश भी उनकी नीतियों का समर्थन कर सकें। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आज विश्व जनमत को भी शक्ति के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना कि सैनिक शक्ति को। मर्यादा में शक्ति एक अविभाजित इकाई है जिसे व्यावहारिक रूप से बड़ी विभाजित नहीं किया जा सकता।

शक्ति-राजनीति इस तथ्य को मान कर चलती है कि आज राष्ट्रों के आपसी सम्बन्ध प्रराजकतापूर्ण हैं। इसके मुख्य रूप से तीन कारण हैं—प्रथम, राष्ट्रों की तथाकथित सम्प्रभु स्वतन्त्रता, दूसरे, उच्च सत्ता का प्रभाव और तीसरे, बाहरी प्रचुरता से स्वतन्त्रता।¹ इस प्रराजकता की स्थिति में

G. Nicholas Spykman, America's Strategy in World Politics,

एक देश अपने शत्रु के बराबर शक्ति प्राप्त करने मात्र से ही सुरक्षित नहीं बन जाता, वह केवल तभी सुरक्षित रह सकता है जबकि वह उसमें कुछ अधिक शक्तिशाली होगा। निरन्तर शक्ति प्राप्त का प्रयास ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वास्तविकता है। राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता की शक्ति भी एक ऐसा तत्व है जिसे राज्य-व्यवस्था से छिपा नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत अध्याय में हम राष्ट्रीय शक्ति के सामान्य रूप इसकी आवश्यकता, इसके आधार तथा इससे सम्बन्धित संसारवादी एवं आदर्शवादी विचारधारा को प्रबलोकन करेंगे।

राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप

(The Nature of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति का विश्व राजनीति के क्षेत्र में जितना महत्व एवं प्रभाव है उसे देखते हुये इस विषय पर किया जाने वाला बौद्धिक विचार विमर्श का परिणाम बहुत कम है। 'शक्ति' को राजनीति का एक मूल तत्त्व माना जाता है। शक्ति प्राप्त करने के निम्ने सघर्ष किया जाता है और सघर्ष करने के लिये शक्ति प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक स्थान पर चलती रही है। यह एक ऐसा स्रष्टव है जो मनुष्य पर आधारित है और जिसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ लेखक तो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि शक्ति के बिना कोई राजनीति रह ही नहीं सकती। जिस प्रकार डार्विन मनुष्य ने जीव के विकास में अस्तित्व के लिये सघर्ष (Struggle for existence) एवं योग्यतम की विजय (Survival of the Fittest) के नियमों का प्रतिपादन किया है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक विश्व राजनीति के विकास में भी इन नियमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। डार्विन के विकास की प्रक्रिया की इकाई जीव था जबकि इन विचारकों के अध्ययन में विकास की इकाई राज्य है। यह कहा जाता है कि राज्य शक्ति के लिए सघर्ष में केवल इसलिए उलझते हैं क्योंकि वे अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अनेक देशों द्वारा क्षेत्रीय प्रसार एवं युद्ध की जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनके पीछे भी सुरक्षा की भावना प्रेरक के रूप में कार्य करती है। वैसे राइनहोल्ड नीबुर् (Reinhold Niebuhr) की तो यह मान्यता है कि जीने की इच्छा और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा के बीच अंतर नहीं किया जा सकता।¹ एक देश

किमी व्यवहार विशेष के समय अपने अस्तित्व की आकांक्षा से प्रेरित हुण हैं अथवा शक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा से, यह निर्णय करना कई बार असम्भव बन जाता है। प्रत्येक राज्य का यह अधिकार होता है कि वह शक्ति प्राप्त करे क्योंकि इसके बिना वह अपने नागरिकों की रक्षा एवं विकास के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सकता। शक्ति का दुरुपयोग भी किया जा सकता है और किया जाता है किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं होता कि एक राज्य को शक्ति प्राप्ति का प्रयास ही नहीं करना चाहिए। दूसरे राज्य द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावनाओं एक राज्य के शक्ति प्राप्त करने के अधिकार को और भी अधिक आवश्यक बना देती है।

राष्ट्रीय शक्ति का आधार सम्प्रभुता की मान्यता को माना जाता है। जब राज्य अपने नागरिकों के विकास का उत्तरदायित्व सम्भाल लेता है तो वह इस दायित्व की पूर्ति के लिए अपनाई गई नीतियों पर किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं चाहता। सम्प्रभुता की मान्यता राज्य को अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती है, साथ ही यह चुनौती देती है कि यदि उसने शक्ति प्राप्ति के प्रयासों में ढील की तो उसका स्वयं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। शक्ति को सम्प्रभुता की एक आवश्यक विशेषता माना जाता है और कोई भी राज्य सम्प्रभुता के बिना नहीं रह सकता, इसलिए यह स्वाभाविक है कि कोई भी राज्य शक्ति के बिना नहीं रह सकता। राष्ट्रीय शक्ति को सम्प्रभुता की मान्यता द्वारा एक बाधनी घोषित प्रदान किया जाता है दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की शर्तों में भी इसे अपरिहार्य तत्व बना देती है।

राष्ट्रीय शक्ति की तुलना किसी भी अन्य सत्ता या व्यक्ति की शक्ति से नहीं की जा सकती। इसका कारण यह है कि राज्य की शक्ति से ऊपर कोई भी सैद्धांतिक सीमा नहीं होती। राज्य के प्रतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक आदि संस्थाएँ भी अपने पीछे कुछ शक्ति एवं दबाव रखती हैं, किन्तु इनमें से प्रत्येक संस्था की शक्तियों पर सीमाएँ तथा प्रतिबंध हैं जबकि राज्य की दमनकारी शक्ति कोई मर्यादा नहीं जानती। इस अर्थ में राज्य अपने प्रकार की एक अलग ही संस्था है तथा राष्ट्रीय शक्ति इसकी प्राणवायु है। राज्य द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के परिणामस्वरूप उसकी शक्तियों पर अन्य किसी राज्य की शक्ति की मर्यादाएँ भी प्रभावी नहीं हो सकतीं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि जब एक राज्य के पास

सैनिक शक्ति की मात्रा कम होती है तो उसकी शक्तियों पर अधिक सैनिक शक्ति वाले राज्य द्वारा सीमा लगाई जा सकती है।

इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के कानून एवं नैतिक दो आधार बन जाते हैं। कानूनी आधार सम्प्रभुता की मान्यता द्वारा प्रतिपादित किया गया है और नैतिक आधार राज्य के उस उत्तरदायित्व से प्रकट होता है जिसके अनुसार वह अपने नागरिकों के अच्छे जीवन की प्राप्ति में सहायता करता है। राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने एवं उसे अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये किये जाने वाले राज्य के प्रयासों का पहला कारण यह है कि वर्तमान राष्ट्र-राज्य व्यवस्था में शक्ति ही सुरक्षा का एक मात्र साधन है। इसका दूसरा कारण शक्ति का भाव्यक रूप है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शांतिवादी बर्ट्रान्ड रसल (Bertrand Russel) का कहना है कि यदि सम्भव हो तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि वह ईश्वर बन जाये। कुछ लोग तो इस बात को असम्भवता को स्वीकार करने में भी कठिनाई अनुभव करते हैं। अर्थात् वे सचमुच ही ईश्वर बनने का प्रयास करते हैं तथा उनका यह विश्वास रहता है कि वे इस प्रयास में सफल हो जायेंगे। शक्ति राजनीति का यह एक रोचक पहलू है कि जब भी किसी देश से यह पूछा जाता है कि वह अपनी शक्ति को क्यों बढ़ा रहा है तो इस प्रश्न का जवाब वह हमेशा यही देता है कि विदेश आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए वह ऐसा कर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में यह बात भारत, पाकिस्तान और साम्यवादी चीन के उदाहरणों में देखी जा सकती है। चीन व पाकिस्तान की सैनिक तैयारियाँ देख कर भारत को अपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई देती है अतः वह भी सैनिक तैयारी करता है। भारत की सैनिक तैयारी में पाकिस्तान व चीन को असुरक्षा की अनुभूति होती है और इसलिए वे अपने प्रयासों की गति को और भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार शस्त्रों की होड़ लग जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रायः ऐसा होता रहता है। शस्त्रों की होड़ के प्रतिरिक्त मानसिक, नैतिक एवं क्षेत्रीय आधार पर मतभेद, तनाव और खिचाव बढ़ता है। इसकी वृद्धि निरन्तर रूप में होती है और एक दिन युद्ध के रूप में सामने आती है। यह शक्ति राजनीति का एक स्पष्ट तथ्य है।

राष्ट्रीय शक्ति के अनेक रूप होने हैं। ई. एच. कार ने इसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। ये हैं—सैनिक शक्ति, प्राथमिक शक्ति तथा मत (Opinion) पर शक्ति। शक्ति प्रदर्शन के इन रूपों के प्रतिरिक्त हत्या एवं आतंक आदि राजनैतिक युद्ध के कुछ रूपों का भी उल्लेख किया जा सकता है। सैनिक शक्ति का महत्व इसलिए है क्योंकि यह एक अन्तिम साधन है।

जब एक राज्य शक्ति के अन्य रूपों का प्रयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता तो वह युद्ध की अपनाता है। यह एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है जिसका प्रयोग बहुत कम तथा मजबूरी की अवस्था में ही किया जाता है। मि. कार का कहना है कि शक्ति के क्षेत्र में राज्य का प्रत्येक कार्य युद्ध की दिशा में संचालित होता है किन्तु यह युद्ध को एक बाह्यनीय हथियार नहीं मानता किन्तु एव ऐसा हथियार मानता है जिसका प्रयोग यह अन्य कोई उपाय शेष न रहने पर करे।

‘राष्ट्रीय शक्ति’ मूल रूप से सैनिक शक्ति ही है किन्तु इस शक्ति की रचना में अनक तरह कार्य करते हैं और इसलिए वे भी शक्ति के प्रतीक कहे जा सकते हैं। कई बार ये प्रतीक ही राज्य के लक्ष्य की पूर्ति में सफल हो पाते हैं और युद्ध का मार्ग ही नहीं अपनाना होता। उदाहरण के लिए हम एक देश की आर्थिक शक्ति को ले सकते हैं। सैनिक शक्ति के प्रसार के लिए इसका होना परम आवश्यक है। यह कहा जाता है कि युद्धों के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए आर्थिक शक्ति ही सैनिक शक्ति है। यह कथन चाहे अतिशयोक्ति के दोष से पूर्ण हो किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि करोड़ों रुपये प्रतिदिन का मार डालने वाले युद्ध में कोई भी देश उस समय तक प्रवृत्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके आर्थिक आधार मजबूत न हो। लोक मत पर प्रभाव की शक्ति प्रचार के माध्यम से सम्भव होती है। प्रचार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मोरेल की स्थापना का प्रयास किया जाता है और विदेशों में इसे मनोवैज्ञानिक युद्ध के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रचार को भी राष्ट्रीय शक्ति के अन्य रूपों से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देश में उत्पादन बढ़ाने तथा बलिदान करने की सतपरता पर जोर देता है तथा विदेशों में मंत्री बढ़ाने तथा दुश्मनों को कम करने का प्रयास करता है।

भूटनीति को भी राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप माना जाता है। अधिवाश लेखकों के गणनानुसार यह राष्ट्रीय शक्ति का द्योतक एव रूप दोनों ही हैं।

शक्ति के लिए संघर्ष के आधार (The Bases of Struggle for Power)

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति का संघर्ष प्रकारण ही नहीं होता, उसके कुछ आधार होते हैं। इस संघर्ष के प्रथम आधार की प्रकृति मानवीय है। इसके अनुसार किसी भी देश की सुरुवात और अन्तः प्रकृति जीवित की एक शक्ति होती है। यदि उस देश की स्वतन्त्रता के लिए कोई धमकी दी जाती है

तो इसका अर्थ यह होगा कि उसके जीने के तरीके को तथा उसके मूल्यों को समझी दी जा रही है । अतः राज्य का यह एक मुख्य कर्त्तव्य माना जाता है कि वह अपने नागरिकों को शांति का वातावरण एवं सम्पन्नता के अवसर प्रदान करे । राष्ट्र राज्य व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संघर्ष का एक प्रमुख कारण है किन्तु यह एक मात्र कारण नहीं है । समुन्नत राज्य समरीका और सोवियत रूस के बीच अनेक प्रश्नों पर जो मतभेद है उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक एवं राजनैतिक संगठनों तथा विवादाओं के बीच स्थित भिन्नताएँ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष के मुख्य कारण हैं । कुछ विचारकों का कहना है कि विचारधारा (Ideology) कभी-कभी तो राष्ट्रीयता की भावना से भी ऊपर उठ जाती है । एक देश के लोग दूसरे देश का समर्थन केवल इसी बात के आधार पर करने लगते हैं कि वहाँ के लोगों के विचार तथा विश्वास उन्हीं के जैसे हैं । विचारधारा के आधार पर ही विभिन्न राज्यों के अलग-अलग संघर्ष या गृह युद्ध प्रारम्भ होते हैं वे बढ़कर अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं । इस दृष्टि से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारम्भ होने वाला शीत युद्ध दो नैतिक दर्शनों के मध्य छिड़ने वाला एक भगड़ा था । मार्क्सवादी महाकाव्य इस मत के समर्थक नहीं है । उनका कहना है कि राज्य जो भी कार्य करता है या जो भी निरर्थक लेता है उसका मुख्य उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है । यह विचारधारामों के आधार पर तो अपने व्यवहार एवं निर्णयों का औचित्य मान निरूपित करता है । अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का एक तीसरा आधार मूल्यों को माना जाता है । क्लाइड क्लक्होर्न (Clyde Kluckhohn) आदि जाति शास्त्र के विद्वानों का मत है कि संघर्षपूर्ण नैतिक मूल्य मनमुटाव के प्रधान स्रोत होते हैं । मूल्यों के द्वारा व्यवहार का प्रभावित किया जाता है और कभी कभी तो उसे निर्णित भी किया जाता है ।

विचारधारा एवं विश्वास के आधार पर मनुष्य की बौद्धिक एवं मना-बैज्ञानिक आवश्यकताओं को सहारा दिया जाता है । उससे यह ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है तथा वह जो कुछ कर रहा है वह ठीक है या नहीं । मूल्य व्यवस्था को चुनौती देने का अर्थ होता है एक ऐसी चीज को चुनौती देना जो मानव जाति के लिए गहरा अर्थ रखती है । इस प्रकार का व्यवहार नैतिक सुरक्षा एवं निश्चितता को खतरे में डाल देता है । एक देश की विदेश नीति पर वहाँ के लोगों के सामाजिक मूल्यों का पर्याप्त प्रभाव रहता है । कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि नैतिक एवं वैज्ञानिक विश्वासों के अतिरिक्त लोगों का या राज्य का कोई हित ही नहीं होता । अपने स्वीकृत नैतिक विचारों के दृष्टिकोण से ही वे यह तय करते हैं कि उनके

हित क्या है।^१ विदेश नीति के सम्बन्ध में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। जब एक देश यह मान लेता है कि पूँजीवादी व्यवस्था की अपरिहार्य गति के कारण सघर्ष का होना अनिवार्य है अतः वह यह नीति अपनाता है कि गैर साम्यवादी देशों की यथा शक्ति सहायता करे ताकि वे यथा स्थिति को बनाये रखें तथा आति का विरोध करें। सैद्धांतिक मूल्यों को विदेश नीति का अन्तिम निर्णायक माना जावे अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अधिकांश विचारकों के बीच मतभेद है। वैसे अधिक लेखक एवं विचारक यह मानते हैं कि कोई भी राजनीतिज्ञ उन मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता जो उसके अनेक देशवासियों द्वारा स्वीकृत हैं। दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कोई भी ऐसी विचाराधारा यथार्थवादी नहीं कही जा सकती जो विरोधी मूल्यों पर गम्भीर रूप से विचार करने में असमर्थक रही हो।

कोई भी देश जब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उतरता है तो उसके व्यवहार को प्रभावित करने में उक्त तत्वों के अतिरिक्त समाज के दबाव समूह भी पर्याप्त महत्त्व रखते हैं। एक देश में रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूह एवं बुद्धि वर्ग अलग-अलग आर्थिक एवं राजनैतिक स्वार्थ रखते हैं और उसी के अनुरूप वे देश की विदेश नीति को प्रभावित करना चाहते हैं। प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक लोग होते हैं जिनकी स्वामीमति उनके देश की अपेक्षा उनके धार्मिक, व्यावसायिक अथवा ऐसे ही अन्य सगठनों के प्रति अधिक रहती है। जब ये लोग अपने देश की विदेश नीति के लक्ष्यों का मूल्यांकन करने लगते हैं तो दृष्टिकोण भिन्न प्रकार का होता है।

लेनिन ने राज्यों के व्यवहार एवं शक्ति सघर्ष के लिए एक अन्य आधार को उत्तरदायी ठहराया है। उनका कहना है कि 'साम्राज्यवाद' पूँजीवाद का दूसरा सोपान है। पूँजीवादी देश अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए एक सुरक्षित बाजार चाहता है। अपने देश में उसे यह प्राप्त नहीं हो पाता। लेनिन की व्याख्या चाहे वैज्ञानिक थी अथवा नहीं थी यह बात भलग है किंतु इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक औद्योगिक एवं बैंक की समस्याओं को देश की राष्ट्रीय नीतियों का अतिक्रमण करना होता है। लेनिन ने इस तथ्य का उद्घाटन किया कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे लोग या वर्ग होते हैं जो दूसरे लोगों की जमीन, जीवन एवं भूमि पर अपनी राष्ट्रीय सत्ता का प्रसार करना चाहते हैं।

शक्ति की राजनीति पर यथार्थवादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण (Realist and Idealist Views about Power Politics)

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सञ्चालन जिस रूप में होता है उसका वर्णन करने के लिए कई एक विचारधाराएँ विकसित की गई हैं। इन विचारधाराओं में यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विचारधाराएँ प्रमुख हैं जो शक्ति के लिए स्वार्थ के व्यवहार की सकारण व्याख्या करती हैं। यथार्थवादी विचारधारा मुख्य रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस छोटे से कथन में ही यथार्थवादी विचारधारा का मूल निहित है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पर 'राज्य' मुख्य अभिनेता का कार्य करते हैं। ये सभी सम्प्रभु इकाई होते हैं और इस प्रकार वह राज्य व्यवस्था की स्थापना करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना शतरंज के खेल से की जाती है जिसमें प्रत्येक इकाई यदि सर्वाधिक शक्ति की प्राप्ति का नहीं तो कम से कम आगे बढ़ने रहने का प्रयास तो करती ही है। इस प्रकार सभी राज्य प्रायः एक-जैसी इच्छा एवं उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनका व्यवहार एक प्रकार से उन राजाओं की भांति होता है जिनका वर्णन मैकिणवेली ने किया है। राजाओं की तरह ये राज्य भी एक-दूसरे में पूरी तरह स्वतन्त्र होते हैं। समाज का उनके ऊपर ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं होता जो शक्ति की प्राप्ति में रत उनके व्यवहारपूर्ण प्रयासों पर रोक लगा सके। आर्नोल्ड वाफर्स (Arnold Wolfers) का कथन है कि राज्य-शक्ति के लिए प्रतिद्वन्द्वी होते हैं तथा अपने अस्तित्व के लिए निरन्तर रूप से अपरिहार्य संघर्ष में रत रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये राज्य एक-दूसरे के सम्भावित शत्रु बन जाते हैं। उनके बीच हम किसी प्रकार की मैत्री की सम्भावना नहीं देख सकते जब तक कि उनको किसी सामान्य शत्रु के विरुद्ध सन्धि बद्ध होने के लिए मजबूर न हाता पड़े। ऐसी स्थिति में हिंसात्मक व्यवहार की सम्भावनाएँ सदैव ही उपस्थित रहती हैं। यदि इस तथ्य को भुला दिया जाये अथवा कोई राज्य शक्ति प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना ही छोड़ दे तो इसका परिणाम उसके लिए पर्याप्त घातक हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य को निरन्तर रूप में संघर्ष में लगे रहना चाहिए क्योंकि यह उस समय तक संभव नहीं हो सकता जब तक दूसरे पक्ष के पास में विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्ति है। यद्यपि कोई भी राज्य शक्ति को संतुलित करने में रुचि नहीं लेता किन्तु फिर भी यह हो सकता है कि अपनी शक्ति को बढ़ाने के राज्यों के प्रयास के परिणामस्वरूप शक्ति संतुलन स्थापित हो जाए।

जब राज्यों की शक्ति बीच मनुबन रहता है तो प्रायः शान्ति की अवस्था रहती है। यदि विश्व में शान्ति स्थापित करनी है तो इसका एकमात्र उपाय यह बताया जाता है कि राज्यों के बीच शक्ति मनुबन स्थापित कर दिया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रियों के बार में अस्तित्व के लिए निरन्तर संघर्ष या शान्ति की स्थापना के लिए शक्ति मनुबन की स्थापना के बारे में जा विचार प्रकट किए गए थे वे आन की बदली हुई परिस्थितियों में उपयोगी प्रतीत नहीं होते। कुछ विचारकों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रियों को कुछ रूप से शक्ति के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता किन्तु फिर भी यह प्रयास राज्यों के व्यवहार के सम्बन्ध में एक यथार्थवादी प्रयास सिद्धता है। दूसरी ओर विचारकों का मत है कि शक्ति मनुबन के प्रतिरिक्त भी शान्ति की नीतियां हानी हैं और इनकी सफलता के अवसर भी पर्याप्त होते हैं।

यथार्थवादी विचारकों द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य एक निश्चित तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें किसके द्वारा वाध्य किया जाता है। यथार्थवादियों के मतानुसार इसके दो कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से एक एक राष्ट्रीय रूप में इस प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार कि जंगली जानवर प्रयास उनमें मर्दव ही शक्ति प्राप्ति की इच्छा प्रदान करते हैं। जब शक्ति की इच्छा की व्यक्तिगत स्तर से राज्य के स्तर पर लाया जाता है तो उसका स्तर व्यापक बन जाता है और इस व्यापक स्तर के अनुसार राज्यों के द्वारा अपने अस्तित्व के लिए निरन्तर संघर्ष किया जाता है। इसका दूसरा कारण यह बताया जाता है कि राज्य शक्ति की मात्रा में इसलिए नहीं लग रहते कि उनमें शक्ति की कामना होती है बल्कि इसलिए लग रहते हैं क्योंकि वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं। वर्तमान राज्य व्यवस्था में प्रत्येक राज्य अपने आरक्षा समुचित समझता है क्योंकि कोई एक कन्द्रीय सत्ता नहीं है और अतः सम्पूर्ण राज्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में वर्तमान है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य यह चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक शक्ति हो ताकि दूसरे राज्य उस पर आक्रमण न कर सकें। यद्यपि एक राज्य के अधिकारी शक्ति प्राप्त करने के प्रयास में कई बार उसके मूल उद्देश्य के विपरीत भी चल जाते हैं। जब सभी राज्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शक्ति की बढ़ा रहे हैं, तो इससे और भी समुदाय उत्पन्न हो जाती है। यथार्थवादी विचारक राज्यों के व्यवहार में एक स्पष्टता देखते हैं क्योंकि वे सभी राज्य शक्ति की साधना में रत हैं। इस पर भी आगे चलकर वे यह मानते

लगे कि शक्ति के प्रति राज्यों का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होना और इसके आधार पर राज्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मार्गेंथो (Morgenthau) के मतानुसार पहली श्रेणी उन राज्यों की है जो यथा स्थिति चाहते हैं। इन राज्यों की नीतियाँ शक्ति के वितरण को बदलने की दिशा में नहीं चलनी वरन् शक्ति के स्तर को यथावत बनाए रखना का प्रयास करती हैं। दूसरी श्रेणी के राज्य साम्राज्यवादी कहे जा सकते हैं। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने का होता है। फ्रेड्रिक शुमा (Frederick Schuman) ने भी प्राग्म्य में इस बात पर जोर दिया था कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति अपने आपमें एक लक्ष्य होती है किन्तु बाद में शुमा महोदय ने भी शक्ति के आधार पर राज्यों को दो भागों में वितरित किया। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों को स्थापित वस्तु स्थिति से लाभ होता है वे उसे बनाये रखना चाहते हैं और दूसरी ओर जो लोग यथास्थिति से असन्तुष्ट हैं वे उसे बदलना चाहते हैं।

यथार्थवादी विचारधारा के अतिरिक्त राष्ट्रीय शक्ति के महत्व एवं कार्यों के संबंध में एक अन्य विचार आदर्शवादी विचारको द्वारा रखा गया है। आदर्शवादी विचारको का मुख्य ध्यान शक्ति की नीतियों की ओर तथा एक अच्छी दुनिया बनाने की ओर है। ये विचारक जिन नीतियों को लागू करना चाहते हैं उनका ध्यान करने से पूर्व इन्हें वर्तमान वस्तुस्थिति का अध्ययन करना होता है। आदर्शवादियों ने अन्तर्राष्ट्रीय-राजनीति का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह यथार्थवादी दृष्टिकोण से भिन्न ही नहीं वरन् विपरीत है। आदर्शवादी विचारक राज्यों को अपने अध्ययन का विषय नहीं बनाते वरन् व्यक्तियों को, जनता को अथवा मानव जाति को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं। आदर्शवादी यह मानकर नहीं चलते कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत राज्य व्यवस्था है जिनमें प्रलग-अलग राष्ट्रीयताएं पाई जाती हैं; किन्तु ये तो विश्व समाज को अपने अध्ययन का आधार बनाने हैं और उन लोगों से संबंध रखते हैं जो विश्व समाज के सदस्य हैं। इस प्रकार आदर्शवादी विचारक यथार्थवादियों की भांति इस बात पर जोर नहीं देते कि प्रत्येक राष्ट्र शक्ति के लिए सघर्ष करता रहता है अथवा राज्यों के बीच सदैव ही सघर्ष रहता है। इन विचारकों द्वारा मानव जाति के सामान्य उद्देश्य अथवा व्यक्तिगत रूप में मनुष्य के सामान्य मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इनका कहना है कि अपिकाश लोग प्रायः एक जैसी चीजों को मूल्यवान मानते हैं, उदाहरण के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, स्वप्रशासन का अधिकार, अपनी मातृभूमि की रक्षा और इन सबके अतिरिक्त हिंसा के

अभाव आदि । इस प्रकार के मूल्यों के होते हुए यह कहना गलत होगा कि राष्ट्रों के बीच निरन्तर सघर्ष बना रहता है । यदि राष्ट्रों के बीच गलत फहमियाँ न हो तथा एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करे तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शांति एवं सहयोग रहेगा और राष्ट्रीय शक्ति का पूर्ण अभाव रहेगा । एक बार राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था कि कोई भी जनता किसी दूसरे देश की जनता के विरुद्ध कभी भी युद्धरत नहीं हुई किन्तु फिर भी सरकारें एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करती हैं । राष्ट्रपति विल्सन का यह कथन आदर्शवादी विचारधारा के आधार को ही नष्ट कर देता है क्योंकि आदर्शवादी विचारक अपने अध्ययन का आधार उस जनता को बनाते हैं जो कभी युद्ध नहीं करती और उन सरकारों को अध्ययन के क्षेत्र से बाहर रखते हैं जिनके कारण युद्ध होता है ।

आदर्शवादी विचारधारा को हम एक स्पष्ट दृष्टा नहीं मान सकते क्योंकि यह इस बात को पूरी तरह नहीं भुला देती कि विश्व में स्वतन्त्र राष्ट्र हैं जिनके बीच सघर्ष रहता है और जो शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं । आदर्शवादी लोग शक्ति की राजनीति की धुनोनी से सदैव सजग रहते हैं । यद्यपि वे संघर्ष का अध्ययन करते हैं किन्तु फिर भी उनका मुख्य ध्यान इस बात पर रहता है कि क्या होना चाहिए और क्या होगा । आदर्शवादी विचारक उन घातक शक्तियों का भी ज्ञान रखते हैं जो समाज के कानूनों और विश्व की शांति को तोड़ते हैं । इन शक्तियों की प्रकृति के बारे में उनको किसी प्रकार का संदेह नहीं है । ये शक्तियाँ उस युग के भ्राजकतावादी अवशेष हैं जो प्रबल समाप्त हो रहा है । यह युग उन्नत स्वेच्छाचारी शासकों का युग था जो राष्ट्रों के भाग्य को स्वयं नियन्त्रित करते थे किन्तु अब नियन्त्रण की यह शक्ति जनता के हाथों में आती जा रही है । स्वेच्छाचारी शासकों के युग में जनता के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और शासकवर्ग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए शक्ति की राजनीति में उतर्भा कर शक्ति के सेन खेलता था । जहाँ वहाँ और जब कभी इस प्रकार की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ प्रभाव में आती हैं वही शांतिप्रिय राष्ट्रों का समाज । इनकी भ्रात्रमणकारी शक्ति एवं हिंसा का मोक्षार बन जाता है । इस प्रकार विश्व राजनीति के रूप में शांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं । प्रजातन्त्रात्मक राज्यों की स्थापना के बाद से राष्ट्रीय शक्ति का रूप और उद्देश्य दोनों में भारी परिवर्तन आ गया है । आज यदि विश्व में सघर्ष है या लड़ाईयाँ होती हैं तो उनका कारण कुछ राज्यों के प्रशासकों की स्वेच्छाचारी प्रकृतियों एवं व्यक्तिगत स्वामिमान आदि हैं । वैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति शांतिप्रिय राज्यों

से पूर्ण हैं। आज यदि सघर्ष भी होना है तो उनका रूप पहले से भिन्न है। पहले तो प्रत्येक राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की स्थिति थी किन्तु आज केवल कुछ आक्रमणकारी एवं तानाशाही देश ही विश्व शांति को भंग करते हैं और उनका विरोध करने के लिए शांतिप्रिय राष्ट्रों को सामूहिक शक्ति कार्य करनी है।

आदर्शवादी विचारधारा के मानोवकों का कहना है कि इसके द्वारा वर्तमान विश्व की जी व्यावस्था की गई है उसमें से अधिकतर की प्रकृति कल्पनात्मक है। यह पहले से ही कुछ मान्यताएँ लेकर चलती है और मान-बोध प्रकृति तथा हितों के सामन्वय के बारे में इसकी ये मान्यताएँ अत्यधिक आभावादी हैं। आदर्शवादी लोगों ने आक्रमण की भी सही-सही रूप में परिभाषित किया है।

शक्ति की राजनीति के बारे में यथार्थवादी एवं आदर्शवादी विचारकों ने जो मत प्रस्तुत किए हैं वे अनेक दृष्टियों से एक दूसरे के विपरीत हैं तथा पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। इतने पर भी दोनों विचारधाराएँ कई क्षेत्रों में गहरा सम्बन्ध रखती हैं। आर्नोल्ड वाफर्स (Arnold Wolfers) के कथनानुसार दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समान स्तर पर देखती हैं, जिसे शक्ति का स्तर कहा जा सकता है यद्यपि वे इसको विरोधी सिद्धांत से देखती हैं। यदि हम इन दोनों विचारधाराओं के अन्तर्गत का सरलीकरण करना चाहें तो कह सकते हैं कि यथार्थवादी विचारक मुख्य रूप से शक्ति की सौज में रुचि लेते हैं और हितान्तरक रूप में इसकी अभिव्यक्ति को राष्ट्रों के मध्य स्थित राजनीति का मूल तत्व मानते हैं। दूसरी ओर आदर्शवादी इसको समाप्त करने में रुचि लेते हैं। इस स्तर पर दोनों के बीच कोई मेल नहीं हो सकता। आदर्शवादियों का यह विचार पर्याप्त सार्थक प्रतीत होता है कि शक्ति दूसरे लोगों के लिए साधन होती है। यह अपने आप में कोई सत्य नहीं है। यदि दुश्मनों के बिना ही शक्ति पर विचार किया जाए तो यह उसका एक निषेधार्थक पहलू होगा। आदर्शवादी विचारधारा को इस अर्थ में भी सही माना जा सकता है कि मनुष्य सामान्य रूप से शांति को मूल्य प्रदान करते हैं और उनके इस मूल्यांकन का नीति निर्माताओं के निर्णयों पर प्रभाव हो सकता है। जब शांति प्रिय व्यक्तियों की अधिकतम संख्या प्रभाव डालती है तो राजनीतिज्ञों को कुछ परिस्थितियों में बाध्य होकर अपनी राष्ट्रीय भावों को शक्ति के साधन द्वारा पूरा कराने का मार्ग छोड़ना पड़ता है अथवा मार्ग कम करनी पड़ती है। दूसरी ओर यथार्थवादी विचारधारा का भी

अपना महत्व है क्योंकि इसने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व का वर्णन किया है; यद्यपि इसने उन नीति सम्बन्धी लक्ष्यों पर कम ध्यान दिया जो शक्ति की खोज की प्रेरणा बनते हैं। इसने यह माना कि बहुराज्य व्यवस्था शक्ति के लिए संघर्ष की ओर लगी हुई है। अमल में आदर्शवादी और यथार्थवादी विचारधाराएँ शक्ति की राजनीति के सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत करती हैं वे दो ध्रुवों की भाँति विपरीत हैं। एक विचारधारा शक्ति के लिए संघर्ष में उलझने के लिए कहती है तो दूसरी विचारधारा शक्ति की ओर से पूर्णतः उदासीन होने का उपदेश देती है। बैसे दोनों का उद्देश्य समान है और वह है शान्ति की स्थापना। एक उसे शक्ति को सन्तुलित करके पाना चाहता है जबकि दूसरा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा।

शक्ति संघर्ष के रूप (The Forms of Struggle for Power)



मार्गेन्थो (Morgenthau) महोदय ने शक्ति संघर्ष के तीन मुख्य-मुखर रूपों का वर्णन किया है। ये रूप शक्ति के प्रति रहने वाले विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित रहते हैं। शक्ति के ये तीन मूल रूप निम्न प्रकार हैं—

(१) शक्ति को बनाये रखना (To keep power)—शक्ति का यह वह रूप (Pattern) है जिसमें एक देश शक्ति स्थिति को ज्यों की त्यों रखना चाहता है। शक्ति के इस रूप से प्रभावित विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य यह होता है कि विश्व के देशों की शक्ति स्थिति इस समय जैसी है वह वैसी ही बनी रहे; उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न आये। यह नीति यथास्थिति (Status quo) की नीति कही जाती है।

(२) शक्ति में अभिवृद्धि करना (To increase power)—कुछ देशों की विदेश नीति का लक्ष्य वर्तमान शक्ति स्थिति को पलटना होता है। ऐसे देशों के पास जितनी शक्ति होती है वे उसे और भी अधिक बढ़ाना चाहते हैं। शक्ति स्थिति में वे देश ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो उनके पक्ष में हो। ऐसे देश साम्राज्यवाद की नीति को अपनाते हैं।

(३) शक्ति का प्रदर्शन करना (To demonstrate power)—बहुत से देश ऐसी नीति अपनाने हैं जिसमें अनुसार उनको शक्ति का प्रदर्शन करने का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। यह प्रदर्शन शक्ति को ज्यों की

राष्ट्रीय शक्ति का सामान्य विचार

रूपों बनाये रखना तथा उसे बढ़ाने, इन  लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस नीति को सम्मान की  कहते हैं।

उक्त तीनों ही रूपों में शक्ति के विभिन्न स्तर समय-समय पर खेले जाते हैं तथा ये ही अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियमित भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में पाया जाने वाला शक्ति का सघर्ष हमें दार्विन के अस्तित्व के लिए सघर्ष (Struggle for existence) तथा योग्यतम की विजय आदि सिद्धान्तों का स्मरण कराता है जिसका उल्लेख जीव विकास के प्रसंग में किया गया था किन्तु यह राज्य व्यवस्था के विकास पर पूरी तरह से लागू होता है। विश्व के राज्यों के हित आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं सैनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में जब परस्पर टकराते हैं तो एक सघर्ष की सी स्थिति पैदा हो जाती है। इस सघर्ष में जो राष्ट्र विजयी होता है वह भागे बढ़ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको सम्माननीय पद प्राप्त हो जाता है। इस पद की प्राप्ति के लिए प्रायः सभी राष्ट्र समान रूप से बलाघात रहते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : भूगोल और प्राकृतिक स्रोत

[THE ELEMENTS OF NATIONAL POWER:
GEOGRAPHY AND NATURAL RESOURCES]

एक राष्ट्र की शक्ति उसकी वह सामर्थ्य होती है जिसके आधार पर वह अन्य राष्ट्रा पर अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। शक्ति प्रत्येक राज्य का मूल आधार है। शक्ति के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विभिन्न राज्यों के पास रहने वाली शक्ति के अनुपात में पर्याप्त असमानता रहती है। साथ ही उनकी शक्ति के रूप भी भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में जब भी हम राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन करें तो यह मान कर चलना चाहिये कि हम एक अत्यन्त जटिल विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय की परिधिया इतनी अस्पष्ट हैं कि प्रत्यक्ष रूप से देखने पर ज्ञात नहीं हो पाती। जब एक राष्ट्र अपनी भौतिक शक्ति का प्रयोग करता है तो वे आमानी से दिखाई दे जाती हैं किन्तु जब वह अन्य भौतिक साधनों के द्वारा शक्ति का प्रदर्शन करता है तो देखने वाला तुरन्त ही पहचान नहीं पाता। इस प्रकार राष्ट्रीय शक्ति के दर्शनीय एवं अदर्शनीय दो प्रकार के तत्व हैं। इसके अदर्शनीय तत्वों में भूगोल, तकनीक एवं मोरेल का नाम लिया जा सकता है। ये तत्व प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव डालने वाले नहीं लगते किन्तु असल में इनका पर्याप्त प्रभाव रहता है। राष्ट्रीय शक्ति के समस्त तत्व एक दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं।

यदि एक राष्ट्र एक तत्व की दृष्टि से सम्पन्न है तो वह अन्य तत्व की दृष्टि से भी कुछ विविध समस्या में होगा। जिस प्रकार बिना तेल के इंजन बेकार हो जाता है—उसी प्रकार बिना प्राकृतिक साधनों के तकनीकी विकास पर्याप्त उपयोगी नहीं रह जाता। शक्ति के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक सम्बन्ध को देखकर कई बार यह कहा जाता है कि शक्ति एक अविभाज्य चीज है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में शक्ति की समस्या मूल रूप से एक सापेक्षिक तत्व है। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति उस देश की जनसंख्या, कच्चा माल एवं अन्य मात्रात्मक तत्वों से मिश्र होती है। एक राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने वाले कुछ गुणात्मक तत्व भी होते हैं। उदाहरण के लिये उस राष्ट्र के सम्भावित मित्रों की सहायता उसकी सत्त्वामों की खचीली प्रकृति, उस देश के लोगों का तकनीकी ज्ञान आदि। किसी भी देश की राष्ट्रीय शक्ति को मापना एक अत्यन्त ही जटिल कार्य है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करना ही इस दृष्टि से उपयोगी रहेगा। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रायः सभी विचारक इन तत्वों के अस्तित्व के बारे में एकमत हैं किन्तु उनके वर्णन करने का तरीका भिन्न भिन्न है। राष्ट्रीय शक्ति के इन तत्वों का विकास जिस देश में जितना अधिक होता है उसे राष्ट्रीय शक्ति से उतना ही सम्पन्न माना जाता है। प्रत्येक देश की विदेश नीति इस प्रकार निश्चित की जाती है ताकि वह इन तत्वों के अधिक विकास को ध्यान में रख कर चल सके।

राष्ट्रीय शक्ति के इन तत्वों को मार्गेन्थो महाशय ने दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रथम वर्ग को वे स्थायी तत्व (Relatively Stable Elements) कहते हैं और दूसरे वर्ग को अस्थायी तत्व (Elements Subject to Constant Change) कहते हैं। इन दोनों ही वर्गों में आने वाले राष्ट्रीय शक्ति के तत्व मार्गेन्थो के मतानुसार नीचे होते हैं जो ये हैं—

१. भूगोल (Geography)
२. प्राकृतिक साधन (Natural Resources)
३. औद्योगिक क्षमता (Industrial Capacity)
४. सैनिक तैयारी (Military Preparedness)
५. जनसंख्या (Population)
- ✓ ६. राष्ट्रीय चरित्र (National Character)
- ✓ ७. राष्ट्रीय मोरेल (National Morale)
- ✓ ८. कूटनीति का गुण (Quality of Diplomacy), तथा
- ✓ ९. सरकार का गुण (The quality of Government)

पामर तथा पारकिन्स ने राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को गैर-मानवीय एवं मानवीय वर्गों में विभाजित किया है। गैर-मानवीय तत्वों में वे भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों का वर्णन करते हैं और मानवीय तत्वों में वे पांच का उल्लेख करते हैं। ये हैं—

- १ जनसंख्या (Population)
- २ तकनीकी ज्ञान (Technology)
- ३ विचारधाराएँ (Ideologies)
- ४ मोरेल (Morale), तथा
- ५ नेतृत्व (Leadership)

राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्णन अन्य अनेक लेखकों द्वारा भी किया गया है। इनके बीच थोड़ा बहुत अन्तर ही वर्तमान है। उदाहरण के लिये ब्राइसर महाशय ने अन्य तत्वों के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (Productive Capacity) एवं आर्थिक तथा राजनैतिक संस्थाएँ (Economic and Political Institutions) का भी नामोल्लेख किया है।

मार्गेन्थो (Morgenthau) की भाँति ब्राइसर (Schleicher) महोदय भी यह स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों के बीच स्थायित्व (Stability) की दृष्टि से अन्तर रहता है। कुछ तत्व दूसरों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं तथा उनको मापना भी सरल होता है। उदाहरण के लिए भूगोल तथा प्राकृतिक साधनों में स्थायित्व तथा मापे जाने की सम्भावनाएँ जनसंख्या की संस्थाएँ एवं गुणों की तुलना में अधिक होती हैं। ये सभी तत्व मिलकर एक देश को तीन प्रकार की सामर्थ्य प्रदान करते हैं—

- (१) आर्थिक सामर्थ्य (Economic Capacity)
- (२) मनोवैज्ञानिक सामर्थ्य (Psychology Capacity) तथा
- (३) भौतिक सामर्थ्य (Physical Capacity)

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों का महत्व सदा एकसा नहीं रहता है, यह समय की परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए आज स दो सौ वर्ष पूर्व जनसंख्या का राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से जो महत्व था वह आज नहीं है। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन की भौगोलिक स्थितियाँ पहले उसकी शक्ति को बढ़ाने में जो योगदान करती थीं वह आज के वैज्ञानिक युग में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं। राष्ट्रीय शक्तियों के विभिन्न तत्वों के परिचय तथा महत्व के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के

एक छात्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गणित के सवाल करने से पूर्व गिनती का ज्ञान होना आवश्यक होता है।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का विश्लेषण करना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचार्यों के लिए परम आवश्यक होते हुए भी इनके सम्बन्ध में यह बात सदैव ही ध्यान में रखनी होती है कि इन तत्वों का योगमात्र ही एक राज्य की शक्ति की मात्रा को व्यक्त नहीं कर पाता। राज्य की शक्ति को असल में उनके व्यवहार के माध्यम में ही परखा जा सकता है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन करने के बाद हम इस योग्य हो जाते हैं कि किसी कार्य को करने की एक राज्य की सामर्थ्य का अनुमान लगा सकें। जब भी किसी राज्य की शक्ति के किसी तत्व का विश्लेषण किया जाये तो उसके सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस सम्बन्ध में पहली बात यह है कि शक्ति के सभी तत्व सापेक्षिक महत्त्व रखते हैं। उनका मूल्यांकन करते समय अन्य राज्यों, विशेषतः पड़ोसियों एवं सम्भावित विरोधियों के ऐसे ही तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यदि हम यह कहे कि ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या ५३ मिलियन है तो यह कथन उम्र समय तक उसके शक्ति सम्बन्धों की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता जब तक कि उसके आस-पास के देशों की जनसंख्या को न देखा जाये तथा महा शक्तियों की जनसंख्या को न देखा जाये।

२. दूसरे, राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों की मात्रा का उल्लेख मात्र कर देना भी अर्थहीन होगा। हमें यह भी देखना होगा कि ५३ मिलियन जनसंख्या में कितने लोग ब्यस्क हैं, कितने बूढ़ हैं, कितने बालक हैं, कितने रोगी, अपाहिण तथा असमर्थ हैं? कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या क्या है तथा पुरुषों की संख्या क्या है? इनमें भी शिक्षित लोग कितने हैं और अशिक्षित कितने? आदि आदि। इन सारी बातों का स्पष्टीकरण करने के बाद ही जनसंख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि एक विशेष देश की राष्ट्रीय शक्ति कितनी है।

३. तीसरे, राष्ट्रीय शक्ति के तत्व अपने आप में कोई महत्त्व नहीं रखते। उनकी उपयोगिता एवं सापेक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके लिए शक्ति के अन्य तत्वों का कितना सहारा प्राप्त है। जब भी कभी हम एक तत्व का मूल्यांकन करने लगे तो इसके लिए दूसरे तत्वों की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त करनी होगी। यदि शक्ति के अन्य तत्वों का एक राज्य में अभाव है तो किसी भी एक तत्व की पर्याप्त मात्रा को वहां सापेक्ष नहीं माना जा सकता और इसलिए वह भी महत्त्वहीन बन जायेगा। उदाहरण के लिए

यदि एक देश सैनिक तैयारियों की दृष्टि से पर्याप्त प्राप्ति है किन्तु उसके पास पर्याप्त जनसङ्ख्या एवं औद्योगिक स्रोत नहीं है तो वह अपने उस शत्रु के सामने भी नहीं टिक सकेगा जिसकी सैनिक तैयारियाँ उतनी अधिक नहीं थी। इसका कारण यह है कि जब उस विशेष देश को युद्ध में क्षति होगी तो वह उसकी पूर्ति करने में अपने आपको असमर्थ पायेगा। जब एक देश के पास अतिरिक्त साधन होते हैं तो उनका महत्व अविष्य की रणनीति की दृष्टि से होता है किन्तु तत्काल में उनको राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि का एक आवश्यक साधन नहीं माना जा सकता। भारतवर्ष एवं साम्यवादी चीन की जनसङ्ख्या एक दृष्टि से देखने पर उनकी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाते हैं किन्तु दूसरी दृष्टि से वे उनकी कमजोरी के कारण हैं क्योंकि इन देशों के पास इतने साधन स्रोत नहीं हैं कि वे अपनी जनसङ्ख्या का स्वमेव ही भरण-पोषण कर सकें। सब तो यह है कि जिसे एक स्थिति में शक्ति का तत्व माना जाता है वही दूसरी स्थिति में एक भार बन सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक देश अन्य तत्वों की दृष्टि से मरीब है किन्तु उसके प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त सम्पन्न हैं तो वह देश बड़ी शक्तियों की ललचाई नजरो का शिकार बन जायेगा और अपनी स्वतन्त्रता को खोकर साम्राज्यवादी शक्तियों का उपनिवेश मान रह जायगा।

चौथे, शक्ति के तत्वों का प्रयोग कम कुशलता के साथ भी किया जा सकता है और अधिक कुशलता के साथ भी। एक विशेष देश में किसी विशेष समय पर शक्ति का एक तत्व अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है जबकि दूसरे समय में उसका महत्व इतना नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए, हम दो देशों की ले सकते हैं जिनमें एक का स्टील का उत्पादन दूसरे से कम है; किन्तु इस आधार पर हम एक देश को कम शक्तिशाली नहीं कह सकते क्योंकि यह हो सकता है कि उस देश के उद्योगों की माँग ही कम हो; जबकि अधिक स्टील उत्पादन वाले देश में यदि उद्योगों की 'माँग' पूर्ति से भी अधिक है तो वह अधिक मात्रा भी देश की कमजोरी का कारण हो सकती जायेगी। इसी प्रकार एक हथियार का शक्ति मूल्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि वह रणनीति में किस स्थान पर कार्य कर रहा है। मई १९४० में जब फ्रांस पर हिटलर का आक्रमण हुआ तो उस समय एक टैंक का मूल्य जर्मनी के हाथों में रहने पर अधिक या अपेक्षाकृत जैसे ही उस टैंक के जो फ्रांस के हाथों

में था।

पासवें, हम जिस युग में रह रहे हैं वह तकनीकी विज्ञान का युग है। हम बाल्य में परिवर्तन यही सीख गति से हो रहे हैं। शक्ति के विभिन्न तत्व जो कभी पर्याप्त महत्वपूर्ण थे आज उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं तथा अन्य

नये महत्वपूर्ण तत्वों का विकास होता जा रहा है। पहले कोयले को ईंधन का मुख्य स्रोत माना जाता था किंतु बाद में इसका स्थान तेल ने ले लिया। तेल का स्थान यूरेनियम लेता जा रहा है। यह भी सम्भव है कि विज्ञान के विकास, यूरेनियम को भी महत्वहीन बना दें। ठीक इसी प्रकार हथियार भी सामायिक बन जाते हैं। विज्ञान एवं तकनीक का विकास नये आविष्कार करता है और पुरानों को महत्वहीन बना देता है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के साथ-साथ शक्ति के कम इष्ट तत्वों में भी परिवर्तन होता रहता है। जब कभी सरकार की कुशलता एवं जनता के मोरेल में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं तो इसके कारण शक्ति-सम्बन्धों में भी गम्भीर परिवर्तन आ जाते हैं।

छठे, तैयारी के पहलू को भी नहीं भुलाया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अतीत काल में भी रणनीति या तय करते समय सिपाहियों के बीच इस आधार पर भेद किया जाता था कि वे हथियारों से तैयार तथा युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। जो सैनिक सशस्त्र खड़े हैं वे उनसे अधिक मूल्यवान हैं जिनको कि तैयार होने में समय लगेगा। आज का जमाना बटन को दबा कर युद्ध करने का जमाना है। ऐसी स्थिति में बमबारी करने वाला वह जहाज जिसे उड़ने के लिए कुछ घण्टे चाहिए, उस जहाज से मित्र है जो बमबारी के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि अचानक ही आक्रमण कर दिया जाये तो वह बम-वर्षक जहाज निरर्थक रहेगा जिसे तैयार होने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। यही बात शक्ति के अन्य तत्वों पर भी इसी प्रकार लागू होती है। यदि वे क्रियान्वित होने के लिए तैयार हैं तब तो ठीक है वरना उनका महत्व एवं प्रभाव उतना नहीं रहेगा।

इस प्रकार जब भी कभी किसी राष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन किया जाये तो उसके विश्लेषण को केवल प्राप्त प्राक्‌दोष तक ही सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी मावी प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में देखना चाहिए। यहाँ एक समस्या यह उठती है कि विश्वसनीय सांख्यिकीय एवं अनुमानों तथा उनके समय के बीच किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जाये। राष्ट्रीय शक्ति की प्रकृति सापेक्षिक होने के कारण एक अन्य समस्या यह उठती है कि दूसरे देश की शक्ति को किस प्रकार जाना जाये। केवल अनुमानों एवं सम्भावनाओं के आधार पर किया गया भूल्याकन कई बार गलत साबित होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल का योगदान (The Role of Geography in International Politics)

किसी देश का भूगोल उसकी शक्ति के विभिन्न तत्वों में सर्वाधिक

स्थापी होता है। नेपोलियन ने एक बार कहा था—एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित की जाती है। भासोवको के मतानुसार नेपोलियन का यह कथन प्रतिशयोक्तिपूर्ण है क्योंकि वस्तुस्थिति के अनुसार भूगोल के अनिश्चित अन्य तत्व भी होते हैं जो प्रभाव डालते हैं। इतने पर भी यह निर्विवाद सत्य है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यूनानी सम्पत्ता के काल से ही मनुष्य ने प्रकृति एवं उसके प्रभावों का मानवीय सस्यामों के साथ सम्बन्ध का अध्ययन किया है। अस्तु ने बताया कि वातावरण एवं मानवीय चरित्र के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करके राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को जानने के लिए जिज्ञासु को ऐतिहासिक के साथ साथ भौगोलिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सक्रिय कार्यकर्त्ताओं एवं पर्यवेक्षकों को एक ऐसे मानचित्र की आवश्यकता होती है जो जनसंख्या, कच्चा माल, संचार के रास्ते आदि बातों का दिग्दर्शन करा सके। भूगोल के प्रति राष्ट्रीय चेतना का स्रोत प्रायः उम्र दश का इतिहास होता है, पश्चिमियों के साथ उसके सम्बन्ध होते हैं तथा धार्मिक क्रियाएँ होती हैं। इन सभी स्रोतों के द्वारा ससार का जो रूप प्रदर्शित किया जाता है वह गलत भी हो सकता है। समुक्त राज्य अमरीका शताब्दियों तक अपने आपको भौगोलिक दृष्टि से योरोप से अलग समझता रहा। यही कारण है कि उसने पारंपरिक की नीति को अपनाया जो भाज के अनेक निष्पक्ष देशों द्वारा अपनायी जा रही है। भूगोल प्रादेशिक राज्यों के व्यवहार पर प्रभाव डालने वाला इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि अनेक विचारक केवल भौगोलिक प्रभावों के आधार पर ही एक देश की विदेश नीति का स्पष्टीकरण करते का प्रयास करते हैं। पैडelford तथा लिंकन (Padelford & Lincoln) के कथनानुसार भौतिक भूगोल विश्व राजनीति को अधिक निरन्तर रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है। यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों, नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है जिनका राज्य अपने हितों की दृष्टि से अपनाते हैं। अनेक विचारक यह मानते हैं कि एक देश के प्रदेश के आधार तथा उसकी शक्ति के बीच संबंध अवश्य रहता है। विश्व का राजनैतिक नक्शा बदलता रहता है उसमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। दिक्कत के वक़्त में व्यक्ति जब तो अन्तरिक्ष एवं समय यहाँ का भी स्वाभिमूर्ति करने की योजनाएँ बना रहा है। इतने पर भी जलवायु, वातावरण एवं भौतिक विशेषताएँ अपने आपको बहुत कम बदलती हैं। भूगोल की कुछ मान्यताओं एवं तथ्यों का अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सागू करने की दृष्टि से उनका आलेखन किया जाना अत्यंत

अनिवार्य है। भूगोल के अर्थ एवं प्रभाव को अन्य तत्वों के सम्बन्ध में देखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, दृष्टिकोण, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएँ, आर्थिक तत्व, तकनीकी एवं जनसंख्या आदि। ये सभी तत्व परिवर्तित प्रकृति वाले होते हैं इसलिए भूगोल का प्रभाव भी गत्यात्मक बन जाता है। एक ही ही जलवायु अलग-अलग समय एवं परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार का प्रभाव डालती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भौगोलिक दृष्टिकोण

(The Geographical Approach towards International Affairs)

बीसवीं शताब्दी से पूर्व विचारकों ने भूगोल और राज्य के कार्यों के बीच सम्बन्धों की एक व्यवस्थित मान्यता को विकसित करना प्रारम्भ कर दिया। भौगोलिक-राजनीति (Geo-Politics) का सन् १९४५ से पूर्व पर्याप्त प्रभाव था किन्तु पिछले कुछ दिनों से यह प्रभाव कम हो गया है। भूगोल में ढ़चि कम होने के कारण अनेक गैर भौगोलिक तत्वों का विकास हुआ, जैसे कि विचारधारा तकनीकी राष्ट्रवाद एवं नेतृत्व आदि। आज यह भी माना जाने लगा है कि अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी एक तत्व प्रभावपूर्ण नहीं होता। भूगोलशास्त्रों इस बात को स्वीकार नहीं करते कि प्रकृति मानव-व्यक्ति या राष्ट्रों को निर्धारित करती है। किन्तु वे यह अवश्य मानते हैं कि वातावरण और राजनीति के बीच एक अन्तर सम्बन्ध है और इससे व्यक्ति एवं राज्यों के कार्यों, मूल्यों तथा प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ता है। यह कहा जाता है कि जब तक शक्ति अथवा शक्ति की घमकी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नियमित करने वाला अन्तिम तत्व है तब तक कोई भी राज्य शक्ति के इस तत्व की अवहेलना नहीं कर सकता।

राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने वाली विचारधाराओं में भूगोल के बराबर महत्वपूर्ण कार्य बहुत कम के द्वारा किया गया है। आज से लगभग पचास वर्ष पूर्व भौगोलिक स्थिति का राष्ट्रीय शक्ति से सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे अधिक स्थायी तत्व माना जाता था। यूरोप में विशेष रूप से, वातावरण, जनसंख्या और साधनों का ऐसा उपयुक्त संयोग था कि उसकी आर्थिक, तकनीकी एवं सामाजिक व्यवस्था ससार में सर्वोच्च बन गई। ससार के प्रायः सभी देश भूगोल और जलवायु के प्रभाव से सीमित रहते हैं। रुडॉल्फ़ ज़ेल्लिन (Rudolf Kjellen) ने सबसे पहले सन् १९१६ में भौगोलिक राजनीति (Geo-Politics) शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक

'राज्य-जीवन का एक रूप' (The State as a Form of Life) में मीगो-निक राजनीति को परिभाषित करने हुए बताया है कि यह राज्य की एक विचारधारा है जो उसे एक भौगोलिक माध्यमकी मानती है।

भौगोलिक-राजनीति के कुछ विचारकों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भूगोल की मुख्य मुख्य चीजों से सम्बद्ध रहते हैं। पेंडिलफाई तथा लिन्न के कथनानुसार भौगोलिक राजनीति भूमि विज्ञान और राजनीति विज्ञान के मध्य स्थित क्षेत्र को जोड़ने का एक प्रयास है। यह भौगोलिक सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रनीति के रूप में मूल्यांकित करने का प्रयास करती है। कुल मिला कर भौगोलिक-राजनीति (Geo-Politics) एक ऐसा शब्द है जो राज्यों की शक्ति और नीतियों के अध्ययन तथा विक्षेपण के प्रति एक दृष्टिकोण का द्योतक है।

(१) मैकाइन्डर के विचार (The Ideas of Mackinder)

भौगोलिक राजनीति के आधुनिक विचारों के विकास के लिए सर हाल्फर्ड मैकाइन्डर (Sir Halford Mackinder) को उत्तरदायी बनाया जाता है जो इंग्लैंड के भूगोलशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने दुनिया की भूमियों की कुछ भौगोलिक विशेषताओं का विद्वत्पूर्ण विश्लेषण किया और समुद्रों से उनका सम्बन्ध दिखाते हुए बताया कि कुछ भौगोलिक वास्तविकताएँ भावी विश्व की घटनाओं के विकास को मोड़ने में महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। मैकाइन्डर ने अपने विचार सर्वप्रथम सन् १९०४ में 'रसे और इनको सन् १९१९ में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्रजातन्त्रात्मक आदर्श और सत्य' (Democratic Ideals and Realities) में परिवर्तित किया और सन् १९४३ में उनको पुनः समायोजित किया।

मैकाइन्डर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका को दुनिया के द्वीप के रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने इस प्रदेश की केन्द्रीय भूमि (Heart land) यूरेशिया के आन्तरिक क्षेत्र को बनाया जो पश्चिम जर्मनी से घनकर साबियन यूरोप में जाता हुआ, केन्द्रीय आइबेरिया तक पहुँचा है। उन्होंने विश्व के अन्य भागों को भी आन्तरिक क्रीसेंट (Inner Crescent), रिमलैंड (Rim Land), बाहरी क्रीसेंट (Outer Crescent), आदि शीपकों में वर्गीकृत किया तथा उनकी प्रलय-ध्वज विशेषताओं एवं प्रभावों का वर्णन किया। मैकाइन्डर का विश्वास था कि प्रभावशाली समुद्र शक्ति का युग समाप्त होने को है। उनका कहना था कि फेंक कर मारे जाने वाले

शस्त्रों के आविष्कार से पूर्वी यूरेशियन मुख्य भूमि आक्रमणों से अपेक्षाकृत स्वतन्त्र रहेगी और क्योंकि इस भूमि में प्राकृतिक साधन और मनुष्य शक्ति बहुतायत से प्राप्त होती है इसलिए यह महान शक्ति को उत्पन्न करने में सक्षम है। मैकाइन्डर का तर्क था कि यदि ग्रन्थ चीजें ममान हैं तो मुख्य भूमि (Heart Land) दुनिया का मुख्य क्षेत्र है। उनका यह कहना था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वही मुख्य भूमि (Heart Land) पर अधिकार रखता है और जो मुख्य भूमि पर शासन करता है वह विश्व-द्वीप पर अधिकार रखता है और जो विश्व-द्वीप पर शासन करता है वह ससार पर अधिकार रखता है।

वार्शिय के शांति सम्मेलन के दौरान मैकाइन्डर ने यह चेतावनी दी कि जर्मनी पुनः खड़ा होकर यूरोपीय रुस पर अधिकार कर सकता है और इस प्रकार मुख्य भूमि पर नियन्त्रण कर लेगा। सन् १९४३ में उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि रुस जर्मनी पर अधिकार कर लेता है तो वह आंतरिक क्रीसेट को जीत सकता है और उसके बाद विश्व-माझाज्य बनाने की ओर अग्रसर हो सकता है। यह ठर उस समय और अधिक बढ़ गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आल-सेनाओं ने केन्द्रीय यूरोप और पूर्वी जर्मनी पर अधिकार कर लिया। जब चेंकोव्स्कोवाक्रिया में फरवरी सन् १९४८ में साम्यवादी क्रांति हो गई तो पश्चिमी यूरोप के देश कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका आदि ने नाटो संधि की। ट्रूमैन प्रशासन की संधियों की नीति, ट्रूमैन सिद्धांत, नाटो, सिएटो, और सैंटो आदि संधियाँ मैकाइन्डर के विश्लेषण के आधार पर ही चल रही थीं ताकि रिंगलैंड को मुख्य भूमि की शक्ति के द्वारा प्रशासित होने से रोका जा सके।

विश्व की घटनाओं को देखने तथा उनका अनुमान लगाने की दृष्टि से मैकाइन्डर के विचार पर्याप्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। इसके आधार पर किसी भी देश की सम्भावित सामर्थ्य को देखा जा सकता है। मैकाइन्डर के विश्लेषण के आधार पर ही महाशक्तियाँ यूरोप से एशिया की ओर बढ़ रही हैं। यदि सोवियत सभ और चीन एक साथ मिल कर कार्य कर रहे होते तो शायद मैकाइन्डर की भविष्यवाणी पूरी हो गई होती। मैकाइन्डर का विचार मुख्यतः यूरोप से प्रभावित था और उन्होंने अमरीका को एक बड़ी शक्ति के रूप में नहीं देखा। बाद में उन्होंने उत्तरी अटलांटिक मुख्य भूमि के विकास को पहचाना और उसके बाद सैनिक शक्ति पर जोर देना प्रारम्भ किया किन्तु फिर भी इतिहास उसके विश्लेषण को केवल अमिश्रित भाग नहीं बना सकता।

(२) समुद्र शक्ति पर माहून के विचार (The Ideas of Mahan on Sea Power)

माहून ने भी एक विद्वत्पूर्ण नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत किया है और समुद्र की शक्ति के महत्व पर जोर डाला है। माहून का दृष्टिकोण मकाइन्डर के उस विचार से भिन्न है कि समुद्र शक्ति का महत्व घट रहा है। वैसे इन दोनों ही विचारकों ने यह कल्पना नहीं की थी कि भूमि, समुद्र, वायु और प्रक्षेपणास्त्रों की शक्ति को एक ही सैनिक शक्ति में एकीकृत किया जा सकता है। माहून के विचार इस मान्यता पर आधारित थे कि यूरोप या एशिया की कोई भी महाद्वीपीय शक्ति ब्रिटेन या अमरीका के नौ-सैनिक नेतृत्व को मजबूततापूर्वक चुनौती नहीं दे सकती। माहून का विश्वास था कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पड़ोसी फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे शक्तिशाली देश हों और फिर भी वह समुद्रों का नियन्त्रण कर सके। ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी भूमि की सीमाएँ नहीं हैं जिनकी रक्षा करें। इसलिए वे बड़ी नौ-सेना की स्थापना पर अपनी मुरझा क्रियाओं को केन्द्रित कर सकते हैं। माहून का विश्वास था कि समुद्र पर ही बड़े शक्ति युद्धों का निर्णय होता है। उसकी मान्यता थी कि ब्रिटेन अपनी नौ-सैनिक सर्वोच्चता को स्थाई रूप में बनाये नहीं रख सकता। इसलिए संयुक्त राज्य अमरीका को चाहिए कि बड़ी नौ-सेना का समर्थन करे ताकि घर से बाहर भी किसी युद्ध में भाग ले सके। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट माहून के विचारों में रुचि लेते थे किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका की नीति इन विचारों पर आधारित नहीं थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजय प्राप्त हुई वह संयुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन की कुशल नौ-सेना पर आधारित थी जो अपने देश से दूर रह कर लड़ने में सक्षम थी। इस प्रकार माहून के विचारों में गहरा प्रकट हुआ। आधुनिक काल में होने वाले विकासों ने माहून के विचारों का कई दृष्टियों से सीमित कर दिया है। हवाई बहाक, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्र, आधुनिक औद्योगिककरण आदि के कारण माहून की कई मान्यताएँ महत्वहीन बन गई हैं। माहून के विचारानुसार महाशक्ति बनने के लिए एक देश को ऐसी सैनिक शक्ति की रचना करनी चाहिए जो अपने देश में बाहर रह कर महार्द्ध लड़ सके। यदि माहून न वायु सेना और भूमि सेना को भी अपने विचारों में ध्यान दे दिया होता तो उनका महत्व बढ़ जाता। माहून के विचारों का आज की दुनिया में प्रभाव ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका की नीतियों के द्वारा ही प्रकट नहीं होता बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की शक्तिशाली नौ सेना और

वायुसेना और सन् १९४७ के बाद से मोवियन मच की जन सेना एव वायु-सेना का विकास उसके विचारों की उद्युक्तता सिद्ध करता है। यदि माशन ने आज की परिस्थितियों में लिखा होता तो वह मल सेना पर अधिक जोर देता।

(३) स्पाईकमैन के विचार

(The Ideas of Spykman)

प्रोफेसर स्पाईकमैन (सन् १८६३-१९४३) का मुख्य सम्बन्ध यह देखने से था कि दुनियाँ के भौगोलिक एव राजनैतिक तत्वों का समुक्त राज्य अमरीका की रणनीति की स्थिति एवं विदेश नीति से क्या सम्बन्ध है। उनके विचारों में वायु एव प्रलेनलाइवों के रणनीति सम्बन्धी महत्व को ध्यान में रखा गया है। स्पाईकमैन के मतानुसार भूगोल विदेश नीति की रचना में सर्वाधिक मौलिक रूप से प्रभाव डालने वाला तत्व है। उन्होंने यह बताया कि एक देश की सापेक्षिक शक्ति केवल उसकी सैनिक सामर्थ्य पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि यह अन्य अनेक तत्वों पर आश्रित रहता है जस प्रदेश का आकार, सीमाओं की प्रकृति, जनसंख्या, कच्चा माल, आर्थिक और तकनीकी विकास, वित्तीय शक्ति, प्रभावशील सामाजिक एकता, राजनैतिक स्थायित्व एव राष्ट्रीय भावना आदि आदि। जिस समय समुक्त राज्य अमरीका पार्थिव्य की नीति को अपना रहा था उस समय स्पाईकमैन महाशय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि समुक्त राज्य अमरीका विश्व की शक्ति में सतुलन की स्थापना के लिए ग्रेट ब्रिटेन के साथ सहयोग करके अपनी क्षमता को प्रयुक्त नहीं करेगा तो पुरानी विश्व शक्तिवा नए विश्व को घेरने के लिए समर्थित हो सकती है। स्पाईकमैन के विचारानुसार अमरीका की नीति प्रभावशील शक्तियों को यूरोप के महाद्वीपीय रिमलैंड में स्थापित होने से रोकना था। यदि यूरोप, मध्यपूर्व अफ्रीका, दक्षिण एशिया और सुदूरपूर्व रिमलैंड में से किसी भी क्षेत्र में कोई विरोधी महाशक्ति विकसित हो गई तो वह समुक्त राज्य अमरीका के हितों के लिए एक चुनौती बन जायगी। समुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन के पास पर्याप्त नौसेना है। यदि वे दोनों मित्र बन गए तो उस प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित कर सकते हैं जिसे मैकाइन्डर ने आन्तरिक शीशेन्ट कहा था और स्पाईकमैन उसे रिमलैंड कहते हैं। स्पाईकमैन का विचार है कि जो रिमलैंड पर नियन्त्रण करता है वह यूरेशिया पर शासन करता है और जो यूरेशिया पर शासन करता है वह विश्व के माध्य पर नियन्त्रण करता है। स्पाईकमैन के अध्ययन का उद्देश्य यह नहीं था कि समुक्त राज्य अमरीका दुनिया पर शासन करे। वह विश्व में शांति चाहते

थे और इसके लिए यूरेशिया के अन्तर्गत शक्ति सन्तुलन को आवश्यक समझते थे। स्पाईकमैन के समय में ही यह स्पष्ट हो गया है कि कोई भी स्थानीय शक्ति सन्तुलन विश्व शक्ति सन्तुलन के अधीनस्थ होता है और समुक्त राज्य अमरीका की शक्ति किसी भी शक्ति सन्तुलन के लिए परमावश्यक है।

(४) हाशोफर के विचार

(The Ideas of Haushofer)

जर्मनी के भूगोलशास्त्री कार्ल हाशोफर (१८६६-१९४६) ने भौगोलिक राजनीति पर बहुत कुछ लिखा है कि नाजी विचारों पर उनका बहुत प्रभाव था। हाशोफर तथा उसके अनुयायियों के मतानुसार भौगोलिक-राजनीति एक गुप्त वस्तु थी जो जेलेन (Kjollen) के इस विचार पर आधारित थी कि राज्य अपने आप में महत्वपूर्ण है तथा शक्ति राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। इस आधार पर हाशोफर ने यह बताया कि जर्मनी के लोगों की उच्च जाति के रहने के लिए अलग से क्षेत्र की आवश्यकता है। इसे भौतिक शक्तों की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए तथा योरोपीय मुख्य भूमि का नियन्त्रण करना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग में ग्रेट ब्रिटेन की भी शक्ति एक सोवियत संघ की चल-सेना आती थी, अतः जर्मनी के सामने युद्ध करने के प्रलाप और कोई रास्ता नहीं था। नाजी पार्टियों की हार के साथ ही हाशोफर के विचारों का प्रभाव भी समाप्त हो गया। संक्षेप में उसने नाजी आक्रमण का समर्थन करने के लिए भूमि प्रसार की विचारधारा का पक्ष लिया तथा भौगोलिक राजनीति के विश्लेषण की प्रवहेलना की।

(५) भूगोल पर साम्यवादी विचार

(Communist Ideas on Geography)

साम्यवादी तरीके पूर्ण शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं किन्तु साम्यवादी लेखकों द्वारा कहीं भी भौगोलिक राजनीति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके विपरीत उनका विश्वास इतिहास के विकास की दृष्टात्मक प्रक्रिया में है तथा वे वर्ग युद्ध जीतने की मजदूरों की योग्यता में विश्वास करते हैं। साम्यवादी नेतृत्व भूगोल को रणनीति के दृष्टिकोण से समझता है। द्वितीय विश्वयुद्ध के द्वारा प्रदान किये गये अवसरों का साम्यवादी रूस ने प्रयोग किया और पूर्वी योरोप में प्रभावित राज्यों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त टर्की के दर्रे में, उत्तरी ईरान में, बोरनम द्वीप में तथा अल्बानिया में भी अपने अपने दायरे जमाने का प्रयास किया किन्तु सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। इसी प्रकार साम्यवादी चीन भी दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व

एशिया में बढ़ता जा रहा है तथा इन क्षेत्रों से साम्राज्यवादी शक्तियों के हटने की निरन्तर मांग करना रहता है। वह भारत के कुछ भाग पर तथा आन्तरिक एशिया में कुछ प्रदेश पर सोवियत सप से दावा कर रहा है। यह कहा जाता है कि साम्यवाद को पेरिस पट्टवने के लिए जो रास्ता अपनाता होगा वह है यूरेशियन रिमलैंड (Eurasian Rimland) का। यदि इस मार्ग में अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका ने टांग फमाई तो साम्यवाद की विजय सम्भी पड़ सकती है। सन् १९४५ में जापान के आत्म-समर्पण की शर्तों के अन्तर्गत पर साम्यवादी चीन के उप-प्रधानमंत्री लिन पियाओ (Lin Piao) ने साम्यवादी विजय विजय की राजनीति की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। इस रूपरेखा में भौगोलिक रणनीति के कुछ तत्वों को स्थान दिया गया। यह बताया जाता है कि चीन में माओत्सेतुंग की साम्यवादी विजय की राजनीति कबल इसलिए सफल हो पाई थी क्योंकि उसने देहाती क्षेत्रों को आन्ति का आधार बनाया और बाद में शहरों की भी घेराबन्दी की गई। इसी नीति को विश्व में साम्यवादी आति लाते समय काम में लाया जा सकता है। चीनी नेताओं के मतानुसार यदि हम सम्पूर्ण ग्लोब पर विचार करें तो उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप को 'दुनिया के नगर' माना जा सकता है तथा एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका को दुनिया के देहाती क्षेत्र कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के पूँजीवादी देशों में मजदूरों का आन्तिकारी आन्दोलन कई कारणों से मन्द पड़ गया है जबकि एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में जनता का आन्दोलन व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार साम्यवादी विचारकों के मतानुसार विश्व का वर्तमान रूप बहु विज प्रस्तुत करता है जिसमें शहरों के चारों ओर देहाती क्षेत्रों का घेरा डला हुआ है। देहाती क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक है और वे ही विश्व में आन्ति ला सकते हैं। इस प्रकार चीन के नेता भौगोलिक राजनीति को एक विशेष रूप में लेकर चलते हैं। उनकी दुनिया की तस्वीर अलग है और जब तक उसको नहीं समझा जाता तब तक साम्यवादी देशों के अन्तराष्ट्रीय व्यवहार को सही रूप में समझना कठिन होगा।

अन्तराष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव (The Influence of Geography upon International Politics)

वर्तमान काल में अधिकांश भूगोल शास्त्री भूगोल की सापेक्षता के सम्बन्ध में पर्याप्त सजग हैं तथा यह मानते हैं कि भूगोल कोई निर्णायक तत्व

नहीं है, वरन् यह राज्य के व्यवहार को रूप देने वाले कई तत्वों में से एक है। भूगोल का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव है यह जानने के लिए मि० जेम्स (P E James) का यह कथन पर्याप्त उपयोगी प्रतीत होता है कि धरती का भौतिक चरित्र अलग अलग लोगों के लिए अलग-अलग अर्थ रखता है। अर्थात् भौतिक वातावरण का व्यक्ति के लिए क्या महत्व है यह तय करना उसके स्वयं के दृष्टिकोण, तकनीकी योग्यता एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। मानवीय संस्कृति के इन तत्वों में से किसी में भी परिवर्तन होने पर धरती द्वारा प्रदत्त आधार का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस प्रकार शक्ति के तत्व के रूप में भूगोल का महत्व सापेक्षिक है, किन्तु इस तथ्य से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल का प्रभाव कम नहीं हो जाता क्योंकि शक्ति के प्रायः सभी तत्वों का महत्व सापेक्षिक है। वह सच है कि भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या, वातावरण एवं उद्योग आदि के आकड़ों का उल्लेख मात्र ही कोई महत्व नहीं रखता जब तक कि इस उद्देश्य के प्रसंग में इनको न देखा जाये जिसके लिए कि मनुष्य इनका प्रयोग करना चाहते हैं। मनुष्य अपने वातावरण को अलग अलग रूप से देखने और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में भूगोल का सम्बन्ध भी बदलता रहता है। अर्थात् स्पष्ट रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि भूगोल का क्या रूप एक देश के लिए उपयुक्त रहेगा तथा उसकी शक्ति को बढ़ाने का साधन होगा तथा किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति उसकी शक्तियों को कम कर दगी।

भौगोलिक तत्व पर विचार करते समय उसकी सापेक्षिकता को नो ध्यान में रखना ही चाहिए किन्तु साथ ही यह तथ्य भी जान लेना चाहिए कि भूगोल राष्ट्रीय शक्ति एवं रणनीति से अनेक विशेष रूपों में सम्बन्ध रखती है। एक के बाद एक होने वाले तकनीकी विकासों के कारण विश्व में अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं किन्तु इसमें स्थिति, जलवायु आकार एवं मानचित्र का महत्व कम नहीं हुआ है। स्टीफेन जॉन्स (Stephen B Jones) ने सुझाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भूगोल के प्रभाव को दो दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। प्रथम है गत्यात्मक चीजों की विस्तृत सूची (Inventory) और दूसरा है 'रणनीति' (Strategy)। जॉन्स महाशय के मतानुसार द्वैष्टी शब्द एक देश की उस सम्भावित शक्ति को इंगित करता है जो उसके आकार जनसंख्या, साधन स्रोत एवं भौगोलिक आधार के कारण उसे प्राप्त होती है। इसमें आकार एवं विकास का अधिकतम सम्मिश्रण होता है। यह शक्ति उत्पादित वस्तुओं के प्रकार के

भाषार पर अनेक रूपों वाली हो सकती है। इसके प्रतिरिक्त उत्पन्नित वस्तुओं का विवरण इस प्रकार किया जाये कि ध्वज की अधिक से अधिक भाषा सैनिक सामान में खड़े। स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक साधन भादि पर्याप्त हैं, उनको समुक्त करने के साधनों की भी कमी नहीं है किन्तु फिर भी वहाँ ये सब चीजें लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में ही महामाग कर सकती हैं। दूसरी ओर समुक्त राज्य ममरीका ओर सोवियत सघ के पास पर्याप्त प्रायिक भाषार हैं जिस पर शक्ति अन्तिम रूप से भाशित रहती है। 'रएनीति' उन चलभलों की ओर इशारा करती है जो भौगोलिक स्थिति की तकनीकी से निवा देने पर अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रभुत्व स्थापित करने से उत्पन्न होती है।

अदि हम विद्यनी शताब्दी के ऐतिहासिक परिचयों पर दृष्टिगत करें तो इन्वेन्ट्री तथा रएनीति के मध्य स्थित अन्तर का विवेचनार्थक मूल्य स्पष्ट हो जायेगा। १९वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में जर्मनी के एकीकरण एवं इतुतगति से होने वाले भौगोलिक विकास ने उसके प्रायिक, जनसंख्या सम्बन्धी एवं भौगोलिक इन्वेन्ट्री को व्यापक रूप से बढ़ा दिया। इसके फल-स्वरूप जर्मनी इस भाषा और विषय के साथ दो बार विश्वयुद्ध में उलझा कि इसके कारण उसे योरोप में प्रभुत्व प्राप्त हो जायेगा। रएनीति की दृष्टि से जर्मनी के एकीकरण एवं भौगोलीकरण ने उसे भौगोलिक विविधता की स्थिति के दुष्परिणामों से हेन्डीकृत शक्ति के लाभों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान की। एक देश के अस्तित्व पर स्थिति (Location) के रएनीति सम्बन्धी परिणाम क्या हो सकते हैं इस- लिए अन्य सदाहरण स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम भादि देशों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। बेल्जियम एक ऐसी जगह रहा हुआ है जो तीन बड़ी शक्तियों—फ्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स एवं जर्मनी के लिए रएनीति की दृष्टि से पर्याप्त महत्वपूर्ण है। अतः वह चाहते हुए भी निष्पक्ष (Neutral) नहीं रह सकता। दूसरी ओर स्विट्जरलैंड की स्थिति ऐसी है कि इस-तः पश्चिमी योरोप की इन बड़ी शक्तियों के लिए रएनीति की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। यही कारण है कि यह देश अपने भाष की दो विश्व युद्धों से दूर बचाये रह सका।

कनाडा एवं लेटिन अमेरिका के गणराज्यों में कुछ समय पूर्व तक न तो पर्याप्त जनसंख्या थी और न ही भौगोलिक भाषार, कि इनको बड़ी शक्ति कहा जा सके। ये देश भौगोलिक रूप में शक्ति के मुख्य केन्द्रों से दूर थे और इसलिए वे भाषमण से सुरक्षित बने रहे। समुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत सघ को सर्वोच्च शक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि वे राष्ट्रीय शक्ति की

उपयुक्त इन्वेन्ट्री एवं एक रणनीति युक्त स्थिति—दोनों ही भौगोलिक सामों का उपयोग करते हैं। इन सामों के संयोग के परिणामस्वरूप ही एक शताब्दी पूर्व डी टांकविल ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन रूस और अमेरीका प्राचीन दुनिया के भाग्य को अपने हाथों में कर लेंगे। मैकाइन्कर ने यद्यपि विश्व के प्राधुनिक विकासो को न देखा था और न ही इनकी कल्पना की थी किन्तु भौगोलिक आधार पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वे आज भी सही ठहरते हैं और उमने समार के जिन क्षेत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था उनमें से कई एक अब भी संघर्ष के केन्द्र हैं।

मध्यपूर्व एवं एशिया के जलवायु पर राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि के कभी विचार नहीं किया गया जैसा कि योरोप में किया गया है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में जनसंख्या की समस्या भी अधिक है इसलिए अरब एवं एशिया के राष्ट्र अपने स्रोतों का विकास नहीं कर पाते। परिणामस्वरूप ये क्षेत्र शक्ति के केन्द्र रहने की अपेक्षा शक्ति से शून्य रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भूगोल के महत्व के सम्बन्ध में मेकलेनन एवं अन्य का यह कथन उचित ही है कि भूगोल वह नींव स्थापित करती है जिस पर कि सामर्थ्य पारस्परिक माधुर्यता एवं संघर्ष निर्भर रहते हैं। इसके महत्व को कम नहीं आया जाना चाहिए।

भौगोलिक तत्व एवं विश्व राजनीति (Geographical Elements and World Affairs)

भौगोलिक तत्वों का विश्व की घटनाओं पर किस प्रकार और कितना प्रभाव पड़ता है उसके सम्बन्ध में लेखकों ने समय-समय पर अपने विचार प्रकट किये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान प्रायः इस बात पर एक मत हैं कि एक देश का मानचित्र, उसका आकार, उसकी सीमायें, जलवायु, स्थिति बाह्य अन्तरिक्ष आदि का किसी न किसी रूप में उस देश की विदेश नीति पर उल्लेखनीय प्रभाव रहता है। इन तत्वों का कोन सा रूप किस देश के लिए सामंदायक रहेगा और कितना लाभदायक रहेगा अथवा हानिकारक रहेगा यह बात उस देश में अन्य शक्ति के तत्वों की स्थिति पर निर्भर करती है। ये तत्व निम्न प्रकार वर्णित किये जा सकते हैं।

(१) मानचित्र (Maps)—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए सामान्य रूप से मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। कई बार एक

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व

राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध की गई आक्रामक कार्यवाहियों को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए नक्शों का प्रयोग करता है। आक्रान्ता देश भी विश्व जनमत को अपने पक्ष में लाने व उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। भारतीय सीमा सचपं के समय संकमोहन रखा का प्रयोग तथा भारत-पाक युद्ध के दौरान समय-समय पर अखबारी में अपने वाले सीमाओं के मानचित्रों की याद करके हम यह प्रमाण सकते हैं कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति में नक्शों का कितना महत्वपूर्ण भाग है।

मानचित्र को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए मर्केटर विधि (Mercator Projection), समान क्षेत्रीय मानचित्र (Equal area maps), उपरी दिशावे का प्रस्तुतीकरण (Orthographic projection) आदि। मानचित्र को प्रस्तुत करने का कोई भी एक तरीका पूर्णरूप से सतोपजनक नहीं माना जा सकता। प्रत्येक तरीके का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की दृष्टि से हम उसे सही मान सकते हैं।

(ii) आकार (Size)—किसी भी देश का बड़ा आकार उसके लिए हितकारी एवं ग्रहितकारी दोनों ही प्रकार का हो सकता है। श्लाइटर (Schleicher) महोदय के मतानुसार यदि अन्य बातें समान हैं तो एक देश जितना बड़ा होगा, सुरक्षात्मक शक्ति उसमें उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए सन् १९१७ में तथा १९४५ में दो बार ऐसे अवसर आये कि जापान चीन को कुचल सकता था किन्तु चीन का आकार बड़ा था और इसी कारण दोनों बार उसकी सेनायें विशाल पश्चिमी क्षेत्र में पीछे हट गईं। अपने बड़े आकार के कारण ही रुस १९१२ में 'नेपोलियन' के विरुद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिटलर के विरुद्ध अपनी रक्षा सफलतापूर्वक कर सका था। यदि एक देश का आकार बड़ा है तो आक्रमणकारी को सतार एवं पातापात में कठिनाई होती है, तथा आवश्यकता की चीजें समय पर प्राप्त नहीं हो पातीं। यदि देश के किसी भाग पर उसने अधिकार भी कर लिया तो वह प्रभावकारी तथा स्थायी नहीं रह सकता।

आकार में बड़ा होना यह सिद्ध नहीं करता कि वह देश शक्तिशाली होगा। असल में स्थिति यह है कि जब देश की भूमि जनसंख्या के केन्द्रों को बाट देती है तो उस देश का आकार एक रोड़ा बन जाता है जब तक कि एक सम्बन्धित संचार व्यवस्था काम में ली जाये। इस बन्धन के उदाहरणस्वरूप अस्ट्रेलिया का नाम लिया जा सकता है। देश की शक्ति पर आकार के अतिरिक्त स्थिति, उपद्राकमन, वर्षा की मात्रा, लोगों का

स्वभाव, नेतृत्व का स्तर, तकनीकी ज्ञान का स्तर आदि तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि १९०४-०५ के रूसी-जापानी युद्ध के समय छोटे देश जापान ने बड़े देश रूस को चारों खाने चित कर दिया। रूस आकार की दृष्टि से बड़ा होने के कारण दूरस्थ साइबेरिया में सेना एवं समान को एकत्रित करने में असमर्थ रहा। एक देश का आकार बड़ा होने पर यातायात एवं संचार के साधनों का प्रयोग बड़ा महंगा तथा कठिन पड़ जाता है। जनसंख्या ऐसे देशों में फैली रहती है और इस कारण उसमें एकता का प्रभाव रहता है। फलतः उस देश की शक्ति घटती है, सांस्कृतिक एकता एवं प्रभावकारी प्रशासन का प्रभाव रहता है।

देश का आकार रक्षामयक एवं आक्रमणकारी दोनों ही प्रकार के युद्धों पर प्रभाव डालता है, किन्तु यह प्रभाव कैसा व कितना पड़ेगा यह अन्य अनेक बातों पर निर्भर करता है जैसे उस देश के कूटनीतिज्ञ कितने दूरदर्शी हैं, उस देश का मौसम कैसा है, आवासमन के साधन कितने प्रभावकारी हैं, तथा सेना के नेताओं का मस्तिष्क कैसा है आदि।

(iii) जलवायु (Climate)—एक देश के निवासियों का स्वास्थ्य तथा मानसिक एवं बौद्धिक स्तर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश का जलवायु किस प्रकार का है। जलवायु से भूमि के उत्पादन तथा लोगों के चरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठण्डे देशों के लोग अधिक सक्रिय एवं परिश्रमी होते हैं, गर्म देशों के निवासी अपेक्षाकृत आलसी होते हैं। एक देश की जलवायु के आधार ही वहाँ की सांस्कृतिक साधन (Natural resources) तथा कुछ सीमा तक राजनैतिक संगठन एवं सरकार के रूप का निर्धारण किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर जलवायु का अप्रत्यक्ष प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए यदि भारत में अनावृष्टि या अतिवृष्टि होती है तो यहाँ की साख स्थिति शोचनीय बन जायेगी हमें विदेशों से सहायता लेनी पड़ेगी और यह सहायता भारत के विदेशों से सम्बन्धों को महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित करेगी। इस प्रकार जलवायु का देश के लोगों की शक्ति पर सीधा तथा राष्ट्रीय शक्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक सर्दी तथा बहुत अधिक गर्मी एक देश की राष्ट्रीय शक्ति, उत्पादन क्षमता, एवं शक्ति के लिए बहुत हानिकारक होती है।

(iv) राष्ट्रीय सीमाएँ (National boundaries)—प्रत्येक देश एक निश्चित क्षेत्र में बसा हुआ होता है। इस क्षेत्र की, सीमाएँ कभी-कभी प्रकृति द्वारा बना दी जाती हैं। प्राकृतिक चीजें जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि के

द्वारा दो देशों के बीच में सीमा रेखा खींच दी जाती है, उदाहरण के लिए फ्रांस और ब्रिटेन को विभाजित करने वाली प्राकृतिक शक्तियाँ ही हैं। जिन राष्ट्रों के बीच प्रकृति द्वारा सीमाएँ निर्धारित नहीं की जाती वहाँ पर प्रायः सीमा संघर्ष होते देखे जाते हैं। बहुत समय से हिमालय को भारत का उत्तरी प्रहरी माना जाता है। यह भारत की रक्षा के लिए निर्मित प्राकृतिक दीवार के समान है। यह सच है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के इस युग में इन प्राकृतिक सीमाओं का पूर्ववत् महत्व नहीं रहा है किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि आज ये महत्वहीन हैं। आल्प्स की पहाड़ियों द्वारा इटली की जो रक्षा रेखा खींची गई है उसने इतिहास में कई बार इटली की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की है। इन पहाड़ियों का सैनिक एवं राजनैतिक महत्व आज भी बनाया नहीं जा सकता। राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर आज विश्व में अनेक संघर्ष वर्तमान हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय शानि के लिए गम्भीर खतरा बने हुए हैं, उदाहरण के लिए भारत-चीन संघर्ष, भारत-पाक संघर्ष, उत्तरी एवं दक्षिणी विपतनाम को लेकर अमेरिका व चीन का संघर्ष, रूस तथा चीन का संघर्ष आदि-आदि।

प्रत्येक राज्य के पास भूमि का जो क्षेत्र होता है वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से एक मूल चीज मानी जाती है। प्रत्येक राज्य की सीमाएँ उन क्षेत्रों से मिली रहती हैं जो अन्य सम्प्रभु राज्यों के नियन्त्रण में हैं अथवा वे अन्तर्राष्ट्रीय जल को छूती हैं। प्रत्येक राज्य को अपने प्रदेश के ऊपर के मुक्त प्राकाश पर अधिकार होता है। ये राष्ट्रीय सीमाएँ हम देश की राष्ट्रीय शक्ति और स्वतन्त्रता के प्रतीक होते हैं तथा अपनी सुरक्षा करने की राज्य की योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। एक राष्ट्र की सीमाओं को साधना अनेक गम्भीर अन्तर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न कर देना है और परम्परागत रूप से राष्ट्रीय सीमाएँ झगड़े का कारण रही हैं। राष्ट्रीय सीमाओं को नई प्रकार से राष्ट्रीय सम्प्रभुता का प्रादोक्त सीमा कह सकते हैं। प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं पर रक्षा दल नियुक्त करता है जो हमारे देशों के अनाधिकार आक्रमणों को रोक सके। ये सीमा के रक्षक प्रवेश करने वाले विदेशियों के उनके पासपोर्ट आदि को देखते हैं। कभी-कभी राष्ट्रीय सीमाओं की क्लिबन्दी कर दी जाती है अथवा दीवार खींच देते हैं या तार लगा देते हैं ताकि अनाधिकार रूप से कोई प्रवेश न करे। वर्तमान समय में क्षेत्रीयकरण की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसके कारण यूरोप तथा एशिया महाद्वीपों में इन राष्ट्रीय रक्षादलों का महत्व कम हो गया है ताकि व्यापार का संचालन एवं लोगों का आवागमन सुविधापूर्वक किया जा सके। रेडियों संचार के

माध्यम से राष्ट्रीय सीमाओं को बांधा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अच्छी सड़को तथा आवागमन के साधनों के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय संर को काफी प्रोत्साहन मिला है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सीमा सम्बन्धी अनेक गम्भीर झगड़े हैं। राष्ट्रों के बीच जो लड़ाइयाँ छिड़ती हैं उनका एक मूल कारण क्षेत्रीय सीमा विवाद होता है। रूस और चीन, चीन और भारत, मिस्र और इजरायल, भारत और पाकिस्तान आदि देशों के बीच सीमा सम्बन्धी गम्भीर विवाद हैं जो समय-समय पर मशरूम सघर्ष का रूप धारण कर लेते हैं। एशिया और अफ्रीका में नए राज्यों की रचना के समय उनके साथ ऐसी भूमि जोड़ दी गई जिस पर विश्व के दूसरे देश महमत नहीं हैं। इन अपरिभाषित नई सीमाओं के परिणामस्वरूप काश्मीर समस्या अरब-इजरायली सघर्ष, सोमालीलैण्ड—इथोपिया—केन्या का सघर्ष आदि सामने आए। राष्ट्रीय सीमाएँ प्रायः इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि सम्बन्धित राष्ट्र प्रदेश की प्राकृतिक विशेषताओं का पूरा पूरा लाभ उठा सके। राष्ट्रीय सीमाओं के लिए राजनैतिक या ऐतिहासिक स्पष्टीकरण ही मान्य ममके जाते हैं। कभी शैतिक शक्ति के आधार पर भी एक देश की सीमाएँ बदली जा सकती हैं। जर्मनी का विभाजन उत्तरी और दक्षिणी कोरिया की सीमाएँ, इटली एवं यूगोस्लाविया की सीमाएँ इनके कुछ उदाहरण हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करने में जनता की आत्म निर्णय की मान्यता का पर्याप्त प्रभाव था। भारत और पाकिस्तान की सीमाएँ, जो खींची गई उनका आधार मुख्य रूप से धार्मिक और साम्प्रदायिक था। वैसे जाति धर्म, सम्प्रदाय, आदि को कठोर रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के निर्धारण का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये चीजें राष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखे बिना ही परस्पर संयुक्त रहती हैं। बदलती हुई परिस्थितियों के प्रसंग में यह जरूरी बन जाता है कि राष्ट्रीय सीमाओं में परिवर्तन किया जाए। किन्तु यह परिवर्तन बड़ा कठिन होता है और प्रायः शक्ति के माध्यम से ही किया जाता है। सन् १९५५ में सार के क्षेत्र में जनमत संग्रह की सीमा परिवर्तन का आधार बनाया गया। कुछ राज्यों ने सीमा विवादों पर विचार करने के तरीकों को परिभाषित करने के मार्ग अपना लिए हैं। वैसे सीमा विवाद आज भी अनेक क्षेत्रों में विश्व शांति के लिए गम्भीर खतरा बना हुआ है और अनेक जटिलताओं का कारण है।

(१) स्थिति (Location)—राष्ट्रीय शक्ति पर प्रभाव डालने वाला एक दूसरा भौगोलिक तत्व है स्थिति (Location)। स्थिति का अर्थ है

कि एक देश किस स्थान पर स्थित है। यद्यपि स्थिति को परिवर्तित करना किसी भी देश की शक्ति के बाहर है किन्तु स्थिति के कारण उत्पन्न सम्स्याओं का सामना करने के लिए वो उस देश की प्रयास करना ही पड़ेगा। स्थिति ही यह तय करती है कि उस देश में क्या पैदा हो सकता है, वहाँ कौन-कौन से खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकने, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, उद्योग-धन्यो के विवास के लिए वहाँ कितनी परिस्थितियाँ मौजूद हैं इत्यादि।

पामर तथा परकिंस (Palmer and Perkins) के मतानुसार दूसरे प्रदेशों एवं राज्यों के साथ की सेनीय स्थिति एक देश की मज्जति एवं अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी धार्मिक एवं सैनिक शक्ति पर भी असर डालती है। अर्थव्यवस्था पर स्थिति का प्रभाव पड़ने का कारण यह है कि यातायात के मार्गों का निर्धारण स्थिति के द्वारा किया जाता है। एक देश की स्थिति ही उस देश के कूटनीतिक एवं युद्ध-कौशल के स्तर का निश्चय करती है। हो सकता है कि वह देश युद्धस्थल बन जाय और यह भी सम्भव है कि वह देश एक निरोधक राज्य (Buffer State) बने। इस प्रकार स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर एवं एक देश की शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्थिति के कारण ही अनेक देशों को न चाहते हुए भी युद्ध में शामिल हो जाना पड़ता है।

उक्त सभी भौगोलिक तत्वों का एक देश की शक्ति के ऊपर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। ये तत्व एक देश की कमजोरी का कारण भी बन सकते हैं तथा उसी प्रकार उसकी शक्तिशीलता के भी। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास यह स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है कि अतीत काल में भूगोल ने एक देश की शक्ति को किस प्रकार से प्रभावित किया था। राष्ट्रीय शक्ति के भौगोलिक तत्व का महत्व अन्य तत्वों की स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए भावागमन एवं संचार के द्रुतगामी साधनों के द्वारा भाज दूरी का महत्व बहुत कुछ दूर कर दिया गया है। फिर भी दूरी एवं आकार का सुरक्षात्मक दृष्टि से भारी महत्व है। वायु-मार्गों यानों के आविष्कारों ने इस महत्व को और भी बढ़ा दिया है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का राष्ट्रीय शक्तियों के विकास के लिए उतना ही महत्व है जितना कि एक पोषे के विकास के लिए उपजाऊ भूमि एवं अनुकूल जलवायु का होता है।

(vi) बाह्य अन्तरिक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (Outer space and International Politics)—भाज की स्थिति में दुनिया की समस्याएँ

इतनी गम्भीर हैं कि उनको सुलझाने के लिए बंटा जाए तो पर्याप्त समय, शक्ति और धन लगेगा, किन्तु उसके बाद भी आवश्यक नहीं कि प्रयास सफल हो जाए। ऐसी हालत में बाह्य अन्तरिक्ष की समस्याओं पर ध्यान देना कई विचारकों के मतानुसार उपयुक्त नहीं है, किन्तु फिर भी विज्ञान और तकनीकी के विकास ने मनुष्य को जो क्षमता प्रदान की है उसने उनकी महत्वाकांक्षाओं का बढ़ा दिया है। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ अन्तरिक्ष की दौड़ में बेहताशा लगे हुए हैं। चन्द्रमा, मंगल और शुक्र ग्रहों पर कृत्रिम उपग्रह भेजे जा रहे हैं और इस प्रकार मानवीय सभ्यता के विकास में नए अध्याय जोड़े जा रहे हैं। अन्तरिक्ष में किए जाने वाले विकासों का एक दूसरा रूप भी है जो राष्ट्रीय गोपनीयता को हटा कर आक्रमण को सम्भव बनाता है। पर्याप्त मानवीय और प्राथिक साधन इस प्रकार की तकनीकी पर खर्च किए जा रहे हैं। अन्तरिक्ष में रहने वाले धरु शस्त्रों ने एक गम्भीर समस्या उत्पन्न कर दी है क्योंकि उनकी उपस्थिति को आमानी से परखा नहीं जा सकता। अन्तरिक्ष की तकनीकी के विकास में दोनों ही सम्भावनाएँ हैं। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग सैनिक उद्देश्य से करते हैं अथवा शान्तिपूर्ण उद्देश्य के लिए। बाह्य अन्तरिक्ष में किए जाने वाले विकासों ने विश्व राजनीति के रूप को एकदम बदल दिया है। फलतः व्यवहार के नए नए साधन विकसित होते जा रहे हैं। विश्व किस दिशा में मोड़ लेगा यह इन साधनों के प्रयोग पर निर्भर है।

प्राकृतिक स्रोत (Natural resources)

राष्ट्रीय शक्ति में अभिवृद्धि करने वाले दूसरे प्रमुख तत्व प्राकृतिक स्रोतों को मूल्यवान तभी समझा जा सकता है जबकि उनसे उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का व्यक्ति उपयोग करने लग जाय। प्राकृतिक स्रोतों से चीज बनेंगी तब काम में लायी जायेंगी यह बात उस देश की तकनीकी प्रगति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है। मॉर्गेन्थौ (Morgenthau) महोदय ने इस तत्व को भी स्थाई प्रकृति का (Stable) होना स्वीकार किया है। पामर तथा परकिन्स ने प्राकृतिक स्रोतों को प्रकृति के उपहारों (Gifts of nature) के रूप में परिभाषित किया है। इन उपहारों की एक निश्चित उपयोगिता होती है। अधिकतर खनिजों की, जलप्रपातों की तथा भूमि के उपजाऊपन की इस प्रकार के उपहारों में ही गिना जा सकता है।

प्राकृतिक स्रोतों (Natural resources) तथा कच्चे माल (Raw material) के बीच प्रायः भ्रन्तर दिखाया जाता है। जलप्रपात एवं उपजाऊ भूमि को प्राकृतिक स्रोत माना जा सकता है किन्तु उनको कच्चा माल नहीं कहा जा सकता।

प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग एवं महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। किसी भी वस्तु को तब तक प्राकृतिक स्रोत एवं राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं माना जा सकता जब तक कि लोग उसका उपयोग करना प्रारम्भ न कर दें। भ्रन्जानी साने की खान का इस दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। कहा जाता है कि समुद्र में से मनेको खनिज पदार्थ प्राप्त किये जा सकते हैं। इस भौर वैज्ञानिक खोजें की जा रही हैं। ये खोजें जब तक सफल न हो जायेंगी तब तक समुद्र को प्राकृतिक स्रोत नहीं माना जायेगा।

सम्भावित (Potential) भौर वास्तविक (Actual) प्राकृतिक स्रोत के बीच भेद करना भी आवश्यक है। वास्तविक स्रोत ही भ्रन्ल में एक देश को शक्ति प्रदान करते हैं किन्तु इसका यह भ्र्प कदापि नहीं होता कि सम्भावित स्रोत निरर्थक एवं महत्वहीन होने हैं। कभी-कभी तो सम्भावित स्रोतों का भी उनना ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है जितना कि वास्तविक स्रोत राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए करते हैं।

प्राकृतिक स्रोतों को मार्गेन्थो ने दो प्रकारों में विभाजित किया है—

- (१) खाद्य (Food), भौर
- (२) कच्चा माल (Raw Material)।

पायर तथा परकिन्स ने प्राकृतिक स्रोतों का वर्णन करते समय इसके निम्न रूपों का उल्लेख किया है—

- (१) कच्चा माल (Raw material)
- (२) खनिज पदार्थ (Minerals)
- (३) भौरोगिक शक्ति के साधन
(Sources of Industrial Strength)
- (४) खाद्य पदार्थ एवं कृषि उत्पादन
(Food stuffs and Agricultural products)

थनाइसर ने इन स्रोतों को तीन प्रकार (Types) का बताया है—

- (१) खाद्य (Food)
- (२) रचनात्मक पदार्थ (Construction materials)
- (३) शक्ति उत्पादक (Energy producers)

प्रकृति द्वारा दिये गये उपहारों का उपयोग करके एक देश अपने आपको अधिकाधिक शक्तिशाली बना सकता है। जब तक एक देश द्वारा इनका प्रयोग नहीं किया जाता तब तक इन तत्वों का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता। ये प्रकृति प्रदत्त उपहार अथवा प्राकृतिक स्रोत किस प्रकार के होते हैं तथा इनका राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर कितना और कैसा प्रभाव पड़ता है, यह जान-कारी करना उपयोगी रहेगा—

(१) खाद्यान्न (Food)—अन्तर्राष्ट्रीय जगत में यह एक कहावत है कि 'सेनायें उनके उदरों पर यात्रा करती हैं' (Armies travel on their stomachs)। इसे दूसरे ढंग से इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि सैनिक भूखे पेट रह कर नहीं लड़ सकते। खाद्य पदार्थों का अभाव एक राष्ट्र को घराशाही करने में सफल हो सकता है। भारत का इतिहास इस कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए अनेकों उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। यहां अनेक बार दुश्मन द्वारा किले को घेर लिया जाता था, रसद पहुँचाने के सारे रास्ते बन्द कर दिए जाते थे और फलतः आक्रमणकारी विजयी होता था। आक्रमणकारी के भय से जिन गांवों को खाली किया जाता था वहां किसी प्रकार की खाद्य वस्तुयें नहीं छोड़ी जाती थीं जिनका दुश्मन द्वारा उपयोग किया जा सके। स्थानीय स्तर की ये चालें (Tactics) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चलती हैं। पी० एल० ४८० के अर्धशताब्दी के अन्तराल में भारत-पाक संघर्ष के दौरान भारत पर अपना अनुचित प्रभाव डालना चाहता था।

खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर भूमि और जनवायु का भारी प्रभाव पड़ता है। विश्व के केवल कुछ देश ही खाद्य पदार्थों की दृष्टि से आत्मनिर्भर कहे जा सकते हैं। अनाज का निर्यात करने वाले देशों में अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनाज की अत्यधिक मात्रा होने के कारण कहा जाता है कि वहां भूख के कारण मौतें नहीं होतीं वरन् अधिक खा जाने के कारण होती हैं।

अनाज की कमी एक देश की शक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, यह राष्ट्र के ध्यान को अपनी ओर खींच लेती है तथा अन्य विकास के कार्यों की ओर जाने से रोकती है। भूखा आदमी सतुलित बुद्धि से कोई भी कार्य करने में असमर्थ रहता है। मिलर (Miller) महोदय का मत है कि भूख आज के विश्व की सबसे प्रमुख समस्या है। २० वीं शताब्दी की वास्तविक चुनौती मनुष्य तथा भूख के बीच होने वाली दौड़ है। इस दौड़ में परिणाम पर ही

मानव सम्यता का अस्तित्व निर्भर करता है। वर्तमान में तो प्राकृतिक एवं मनुष्य निर्मित अनेक कारण ऐसे हैं जो इस दौर में मनुष्य की विजय को असम्भव बना रहे हैं जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, अज्ञान और अंधविश्वास, अष्ट एवं अस्मर्य नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संदेह और अविश्वास, प्रकृति के प्रकोप आदि।

भारत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लाख पदार्थों के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने का प्रयास कर रहा है किन्तु चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों ने इन प्रयासों की गति को मन्द कर दिया। भारत को आज़ भी विदेशों से अनाज का आयात करना पड़ता है। यदि भारतवासी स्वाभिमानों न होते और एक समय का खाना छोड़ कर या भूखे मर कर भी अपनी सम्प्रभुता व स्वतन्त्रता की रक्षा का संकल्प न करते तो निश्चय ही भोजन के नाम पर भारत की ऐसी बातें पाने की भजबूर किया जा सकता था जो उसके हित के विरुद्ध थीं।

मार्गेन्थौ (Morgenthau) महोदय ने माना है कि अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर एक राष्ट्र उस राष्ट्र की तुलना में अनेक दृष्टियों से श्रेष्ठ है जो अनाज का आयात करते हैं, स्वयं नहीं उगा पाते या भूखे मरते हैं। जब तक एक देश अनाज की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता तब तक उस देश की महान शक्ति की उपाधि प्रदान नहीं की जाती और यदि वह अनाज की दृष्टि से लगातार अभावग्रस्त बना रहा तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी वह लगातार कमजोर ही बना रहेगा। किसी भी देश में—अनाज की अभावग्रस्त अवस्था के मुख्य-मुख्य पहलू होते हैं—उस देश की निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या के मुकाबले में उत्पादन की हीन मात्रा विदेशों से आयात के अवसरों की कमी अथवा निर्यात की जाने वाली उन वस्तुओं का अभाव जिनके बदले में अनाज आयात किया जा सके आदि। एक देश को अनाज की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए आवश्यक है कि इन सभी पहलुओं पर दृष्टि ध्यान दिया जाय।

राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में खाद्यान्न एक स्थाई तत्व है तो भी विज्ञान की सहायता लेकर इस तत्व में भारी परिवर्तन किये जाने की सम्भावनाएँ हैं।

(२) कच्चा माल (Raw material)—कच्चा माल एक देश की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव डालता है और इस प्रकार अत्यन्त रूप से वह राष्ट्रीय शक्ति को भी प्रभावित करता है। 'कच्चा माल' एक ऐसा शब्द है

जिसमें हम अनेक चीजों को समाहित कर सकते हैं उदाहरण के लिए खनिज पदार्थों से वनस्पतिक उत्पादन (Vegetable Products) तथा जानवरों से उत्पादित कच्चा माल (Animal Products) आदि। वनस्पतिक उत्पादनों में अनेक खाद्यान्न, रई रबड़, कुछ तेल हर प्रकार की लकड़ियाँ, बांस, बीज, नारियल, तारकोन आदि चीजें आती हैं। पशुओं से उत्पादित चीजों के उदाहरणस्वरूप गाय दूध, अण्डे, ऊँ, रेशम, कुछ तल, पखे आदि का नाम लिया जा सकता है। कच्चा मान औद्योगिक उत्पादन के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। युद्ध सम्बंधी अनक तैयारियाँ भी इसके बिना नहीं की जा सकती।

पुराने युग में, जबकि युद्ध आमने-सामने खड़े होकर लड़े जाते थे, योद्धाओं का महत्व अधिक था अपेक्षाकृत उनके हथियारों के, किंतु आज समय बदल गया है। आज १९ वीं शताब्दी की भाँति एक देश की शक्ति को केवल उसके योद्धाओं व सिपाहियों की मात्रा एवं सामर्थ्य के आधार पर ही नहीं आँका जा सकता। आज तो चाहे शांति काल हो या युद्ध काल, एक राष्ट्र की शक्ति उसके द्वारा प्राप्त कच्चे मान की मात्रा एवं विस्म के आधार पर आँकी जायगी। सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व की महान शक्ति मानने के पीछे यही रहस्य है। ये दोनों ही देश उस कच्चे माल की ओर से आत्मनिर्भर हैं जो औद्योगिक उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। इस लक्ष्य से भारतीय विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू भली भाँति परिचित थे, जबकि उन्होंने असलगतता की नीति को भारतीय विदेश नीति का आधार बनाया और रक्षात्मक तैयारियाँ तथा सैनिक तैयारियों की अपेक्षा अधिक अवस्था एवं औद्योगिक उत्पादन को सम्मालन की ओर अधिक ध्यान दिया था। आलोचकों के तर्क नेहरू की विदेश नीति को नगा कर सकते हैं किंतु उसके पीछे जो उद्देश्य था वह वास्तविक नीति से प्रभावित था।

उद्योग एवं युद्ध की दृष्टि से रेल का महत्व भी भुलाया नहीं जा सकता। रेल उद्योगों की तो आत्मा होती ही है किंतु युद्ध का भी उसके बिना नहीं लड़ा जा सकता। विश्व में मध्य एशिया का महत्व बहुत कुछ केवल इसी कारण है कि वहाँ पर रेल का सञ्जाल है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्लेमेंसो (Clemenceau) ने यह कहा था कि 'रेल की एक बूढ़ हमारे सैनिकों के खून की एक बूढ़ से भी अधिक मूल्यवान है।' रूस और अमेरिका रेल की दृष्टि से बहुत कुछ आत्मनिर्भर हैं। जिन क्षेत्रों में रेल की बहुतायत पाई जाती है उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाय रखने के लिए एक विश्व के

रगमच पर अनेक अभिनेताओं द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। इन प्रयासों को 'तेल कूटनीति (Oil diplomacy)' की मज्जा दी जाती है।

आज के अणुयुग में यूरेनियम (Uranium) का कच्चे माल के रूप में भारी महत्व हो गया है। यूरेनियम में जो शक्ति छिपी है उसने विभिन्न देशों के शक्ति स्तर को बदल कर रख दिया। पिछड़े देश अग्रगण्य बन गये तथा बड़ी शक्तियाँ दूसरी श्रेणी की शक्तियाँ बन गईं। श्लाइमर (Schleicher) महोदय के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कोयला, पेट्रोल, गैस, जलशक्ति तथा सम्भावित यूरेनियम शक्ति के अदम्य भण्डार हैं। ये पर्याप्त खाद्यान्न के उत्पादन के लिए पातायात के लिए तथा उद्योगों के पहियों को घुमाने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

केवल कच्चा माल अधिक होने से कोई भी देश सम्पन्न नहीं बन जाना यह सच है, किन्तु यह भी सच है कि कोई देश बिना कच्चे माल की अपेष्ट मात्रा के एक बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। यदि एक देश की भौगोलिक स्थिति उपयुक्त है और साथ ही उसके पास प्राकृतिक स्रोत भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं तो स्वभावतः ही दूसरे देशों का उसकी महायत्ना व सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक केन्द्रीय स्थान प्राप्त कर लेगा वरना उसे ही दूसरे राज्यों पर अवलम्बित रहना पड़ेगा। कच्चे माल की अपेष्ट मात्रा आर्थिक एवं सैनिक शक्ति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

कच्चे माल की मुख्य रूप से तीन जातों में विभाजित किया गया है। ये हैं—खनिज पदार्थ, वनस्पतिक उत्पादन और पशु उत्पादन। खनिज पदार्थों की भी प्रायेः कई विभागों में विभाजित किया जा सकता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से यह विभाजन अधिक उपयोगिता नहीं रखता। कुछ खनिज पदार्थों की उपयोगिता सामान्य एवं सुविदित होती है। उसके बारे में सभी जान जाते हैं जबकि अन्य खनिजों का उपयोग केवल विद्वानों के ही अध्ययन का विषय है। कच्चे माल के दूसरे समूहों में वनस्पतिक उत्पादन आते हैं। इस शीर्षको में हम अधिकांश मोजन सामग्री, रई, रबड़, कुछ तेल, चीर, दवाइयाँ, रंग एवं वार्निश उत्पादन आदि को ले सकते हैं। पशु उत्पादनों के शीर्षको में मांस, दूध, अण्डे, रेशम, कुछ तेल, पखे, हाथी दात, दवाइयाँ जैसे कुछ उत्पादन आते हैं।

दुनिया के देश कच्चे माल की दृष्टि से समान नहीं हैं और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो सभी आवश्यक कच्चे माल की दृष्टि से आत्म निर्भर हो। तीन प्रधान भौगोलिक खनिज अर्थात् कोयला, लोहा और पेट्रोलियम

पर्याप्त असमान रूप से वितरित है। जिन देशों के पास इनका अभाव होता है वे इसकी पूर्ति किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रबन्ध द्वारा करते हैं अथवा उसके विकल्प का विकास करते हैं। ऐसा करने के लिए व्यापक साधनों एवं साध की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त आधुनिक औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को सहारा देने के लिए भी पर्याप्त कच्चे माल की आवश्यकता है। अनेक खनिज पदार्थ हाल ही में विकसित हुए हैं। यह कहा जाता है कि मशीनीकृत युद्ध का विकास होने के बाद केवल वे ही देश बड़ी शक्ति बन सकते हैं जिनमें कि गुणात्मक एवं सख्यात्मक दृष्टि से पर्याप्त कल-कारखाने हैं क्योंकि खनिज पदार्थ कारखाने की क्षमता को तय करते हैं, इसलिए अत्यन्त रूप में वे प्रभावशाली सैनिक शक्ति की आवश्यक शर्तें होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के वर्तमान कालीन अध्ययन राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में खनिज पदार्थ पर पर्याप्त ध्यान देते हैं।

कच्चा माल और राष्ट्रीय नीतियाँ :—प्रत्येक देश को अपने आयात की मात्रा को अपने देशों में उत्पादित कच्चे माल से मन्तुलित करना होता है और इस प्रकार घरेलू राजनीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालती है। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोल, लोहा, चीनी, ताम्बा, मैंगनीज, आदि बड़ी मात्रा में आयात करता है यद्यपि यह स्वयं भी उनका उत्पादन करता है। जब भी कभी इन सामानों की खरीद की कीमतों में थोड़ा बहुत अन्तर कर दिया जाता है तो इससे सामान भेजने वाले देश पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक देशों द्वारा कच्चे माल के सम्बन्ध में जो नीतियाँ अपनाई जाती हैं वे दूसरे रूप में उनकी विदेशी नीतियाँ हैं। विदेशों से प्राप्त होने वाले सामान की उपलब्धता एवं मूल्य समय और दूरी पर निर्भर करता है। किसी भी सामान को भेजने की प्रक्रिया आर्थिक या राजनैतिक कारणों से अथवा मतभेदों या अन्य दवावों से रुक सकती है। उदाहरण के लिए भारत के लिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका से गेहूँ आ रहा था वह परद-इजरायली संघर्ष के कारण इसलिए देर से आया क्योंकि मिस्र द्वारा स्वेज नहर को बन्द कर दिया गया था। इसी संघर्ष के दौरान कई एक अरब राष्ट्रो ने पश्चिमी देशों को तेल भेजना बन्द कर दिया था। सभी दूरी को पार करने के लिए जल मार्ग अत्यन्त आवश्यक होता है क्योंकि इसके बिना अनेक महत्वपूर्ण कच्चे मालों को नहीं भेजा जा सकता है। कच्चे माल के आयात में रोक धाने की सम्भावना से ही देश उसका स्टॉक रखते हैं।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : जनसंख्या और तकनीकी

[ELEMENTS OF NATIONAL POWER: POPULATION
AND TECHNOLOGY]

जनसंख्या (Population)

जनसंख्या एक राष्ट्र की शक्ति पर प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। इस तत्व के द्वारा समय-समय पर राज्यों को एक विशेष प्रकार का निर्णय लेने तथा एक विशेष नीति अपनाने की प्रेरणा दी जाती रही है। सभार के इतिहास में ऐसे अनैक उदाहरण हैं जबकि एक राज्य ने अपनी अधिक जनसंख्या को धमाले की समस्या मुलभूतने के लिये अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया, उसके कुछ प्रदेशों को छीन लिया अथवा युद्ध को भड़का कर भीषण नरसंहार करके अपनी असहनीय खास समस्या से राहत पायी। जनसंख्या अपने मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही पहलुओं से विश्व राजनीति को प्रभावित करती है।

जनसंख्या कम होने पर लोगों में एकता की भावना जल्दी पैदा की जा सकती है और देर तक बनाय रखी जा सकती है। कम जनसंख्या वाले राज्य की सरकार भी प्रायः कार्यकुशल होती है और यद्वा राष्ट्रीयता की भावना अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होती है। दूसरी ओर अधिक जनसंख्या वाले

राज्य में मतभेद रहते हैं, राष्ट्रीय एकता की समस्या रहती है, कार्यों में एक रूपता नहीं रहती, प्रशासनिक प्रकायंकुशलता एवं वस्तुओं का उपयोग होता है और इस प्रकार यह देश सक्क का मुकाबला करने में हड़ता के साथ कार्य नहीं कर सकता। कम जनसंख्या एक देश की कमजोरी का भी प्रतीक बन जाती है क्योंकि वहाँ शक्ति एवं सैनिक सामर्थ्य की मात्रा कम होती है। अधिक जनसंख्या वाला देश इस दृष्टि से लाभ में रहता है कि उसके पास मानव शक्ति पर्याप्त उपलब्ध रहती है। शक्ति तत्त्व के रूप में पहचान जिन दो तत्वों (भूगोल और प्राकृतिक स्रोत) का वर्णन किया गया है वे एक प्रकार से स्थायी तत्व होते हैं क्योंकि वे एक देश के लिये प्रदत्त चीजें हैं उनमें परिवर्तन बहुत कम ही किया जा सकता है। दूसरी ओर जनसंख्या राष्ट्रीय शक्ति का ऐसा तत्व है जिसमें कि परिवर्तन होता रहता है तथा आवश्यकता के अनुसार किया भी जा सकता है।

वैसे जनसंख्या के प्रकार तथा एक देश की शक्ति के बीच कोई प्राथम्यक एवं एकरूप सम्बन्ध नहीं है किन्तु फिर भी इतना तो सच है कि छोटी सी जनसंख्या वाला कोई देश बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। पेडितफोर्ड तथा लिक्नर का कहना है कि यद्यपि बड़ी जनसंख्या का मध्य यह नहीं होता है कि वह देश अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रभाव डालेगा किन्तु फिर भी कम जनसंख्या वाले देश अधिक जनसंख्या वाले देशों की तुलना में नुकसान में रहता है। विश्व के कम विकसित देश यदि अपने आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लें तो वे निश्चय ही शक्तिशाली देश बन जायेंगे क्योंकि इन देशों की जनसंख्या अधिक है।

एक समय ऐसा था जबकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विद्यार्थी जनसंख्या की नवीन प्रवृत्तियों का अध्ययन राष्ट्रीय शक्ति के परिशिष्ट के रूप में अलग से किया करते थे। प्रत्येक उम्र के स्त्री और पुरुषों की संख्या की विस्तृत जानकारी करने के बाद यह ज्ञात करना सम्भव बन जाता था कि सैनिक सेवा के लिये कितने लोग प्राप्त हो सकते हैं तथा औद्योगिक कार्यों के लिये कितने मजदूर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि घाने वाले बीम या पचबीम वर्षों में क्या अनुपात रहेगा। यह कहा जाता है जब १९वीं शताब्दी में जर्मनी की ज़रूरतें अधिक हो गईं तो प्राप्त का एक बड़ी शक्ति के रूप में अभिवृद्धि घटने लगा। वर्तमान समय में साम्यवादी चीन अपनी आक्रामक नीतियों के द्वारा जिस प्रकार विश्व में स्थान बनाता जा रहा है उसके पीछे उसकी एक बड़ी जनसंख्या का तत्व भी

काम कर रहा है। कम जनसंख्या की हानियों को अन्य प्रकार से कम किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को अपने घने युवकों एवं श्रद्धों से हाथ धोना पड़ा था, किन्तु उसने अपनी जनसंख्या की एक श्रेणी की कमी को दूसरी श्रेणी से पूरा किया। वहाँ की श्रमरतियों में काम करने की क्षमता अधिक है और इस क्षमता के आधार पर ही हम अपनी इस क्षति को पूरित कर सका।

जनसंख्या उन अनेक तत्वों में से ही एक है जो एक देश की शक्ति और सम्पत्ति की वृद्धि में भाग लेते हैं। यदि जनसंख्या का प्रकार स्थित उत्पादन के स्रोतों से अधिक होता है अथवा इन स्रोतों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता तो जनसंख्या की अधिकता, साम होने के स्थान पर हानि बन जाती है। समाज के छोटे एवं जनसंख्या के प्रकार के बीच एक संतुलन प्रस्थापित रहनी चाहिये ताकि वह देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सके और इस प्रकार महावृद्धि बनने की दिशा में प्रगति हो सके। जब कभी भी हम जनसंख्या का राष्ट्रीय शक्ति के सम्बन्ध में मूल्यांकन करें तो उससे पूर्व हमें यह देखना चाहिये कि पूँजीगत व्यय तथा शिक्षा एवं विज्ञान के लिए पर्याप्त अनुपात में उपलब्ध है, कितनी जनसंख्या शिक्षित है तथा तकनीकी परिवर्तनों के साथ समावांजित होने की उसमें कितनी क्षमता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए जनसंख्या का महत्व शक्ति की दृष्टि से तो है ही, इसके अतिरिक्त भी है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनसंख्या और साधन स्रोतों के बीच गम्भीर असंतुलन बढ़ता जा रहा है। पूर्व-विकासित देशों में जनसंख्या की प्रकृति को देन माना जाता है तथा उसे रण कौशल की दृष्टि से महत्वहीन बताया जाता है, किन्तु विकसित देशों में जनसंख्या के नियन्त्रण की प्रक्रिया को सफलता के करीब ला दिया गया है। अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करके ही ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ महा शक्ति बन गये हैं।

जनसंख्या का संख्यात्मक पहलू

(The Numerical Aspect of Population)

प्रत्येक विचारक इस बात को स्वीकार करता है कि अतीत-कालीन युद्धों में सेना की संख्या सदैव ही एक निर्णायक भूमिका रही है, किन्तु उस समय भी कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ होते थे, उनको मर्यादा व अधिक मोर्चा प्राप्त हो जाता था तथा उनके पास अधिक बंदे

हथियार रहते थे। इन सब के आधार पर लोगों के बीच बहुत कम ही अन्तर रहता था और इसलिए सख्या का महत्वपूर्ण स्थान था। भाज का युग पूरी तरह से बदल गया है। भाज युद्ध कौशल का रूप, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास पर पर्याप्त आधारित हो गया है। युद्ध में एक देश अपने सभी साधन स्रोतों को लगा देता है। ऐसी स्थिति में किसी देश की शक्ति का अनुमान उसके निवासियों के सर गिन कर या कार्यकर्त्ताओं के हाथ गिन कर नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए यह भी देखना होगा कि सर के भीतर कुछ है या नहीं और हाथों की शक्ति को काम में लाने के अवसर भी देश में उपलब्ध हैं या नहीं। देश के भूगोल, प्राकृतिक साधन जनसख्या, तकनीकी विकास का स्तर, विचारधाराओं का प्रभाव, मोरेल, नेतृत्व का गुण आदि बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं। इन सबके आधार पर किसी देश की शक्ति के सम्बन्ध में किये गये अनुमान भी युद्ध भूमि में कभी कभी गलत सिद्ध होते हैं क्योंकि शक्ति के अदृश्य तत्वों का प्रभाव भी कम नहीं होता।

अधिक जनसख्या वाले कुछ देशों के शक्ति के स्तर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जनसख्या का राष्ट्रीय शक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता। भारत और चीन की आबादी विश्व में सभी राज्यों से अधिक है किन्तु फिर भी सैनिक शक्ति की दृष्टि से वे सर्वोपरि नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ की शक्ति के भागे वे अत्यन्त निम्न श्रेणी के हैं। दूसरी ओर यह भी देखने को मिलता है कि एक कम जनसख्या वाला देश आवश्यक रूप से तीसरी श्रेणी की शक्ति नहीं बन जाता। वस्तुस्थिति का रूप यह होते हुए भी विचारकों का कहना है कि एक अधिक जनसख्या वाला देश अपनी अधिकांश जनसख्या का उपयोग कर भी सकता है और नहीं भी; किन्तु केवल एक अधिक जनसख्या वाला देश ही प्रथम श्रेणी के सैनिक स्थापन के लिए मानविय शक्ति एवं साधन प्रदान कर सकता है।

यदि कम जनसख्या वाला छोटा देश भी आधुनिक हथियारों, फंक्ट्रियों एवं अच्छे नेतृत्व के गुणों से सम्पन्न है तो वह अधिक जनसख्या वाले उस देश को आसानी से हरा सकता है जिसके पास ये सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। इतिहास में इस सम्भावना के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। वह मुख्य बात जिससे हम बार-बार दोहराना भी अनावश्यक नहीं मानते वह यह है कि जनसख्या तो राष्ट्रीय शक्ति के अनेक तत्वों में से एक है, केवल एकमात्र तत्व नहीं है। यदि दो दश अन्य सभी बातों में बराबर हैं और उनके बीच जनसख्या की मात्रा का अन्तर है तो निश्चय ही अधिक जनसख्या वाला देश कम जनसख्या वाले देश को परास्त कर देगा। फिर भी जो लोग जनसख्या के आधिपत्य

को बहुत अधिक महत्व देते हैं वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि प्राधुनिक तकनीकी के विकास ने जनसंख्या की शक्ति को महत्वहीन सा बना दिया है।

कुछ विचारकों के मतानुसार जिस देश की जनसंख्या बड़ी होती है वह शक्तिशाली होता है। वाल्टेयर कहा करता था कि ईश्वर सर्वे सबसे बड़ी बटालियन के पक्ष में रहता है (शायद उसने महाभारत को नहीं पढ़ा था जिसमें कृष्ण ने कौरव सेना का साथ देने की प्रेरणा अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था)। स्लाइसर (Schleicher) महोदय ने भी इस मत की सत्यता में विश्वास प्रकट करते हुए लिखा है कि उत्पादन तथा युद्ध के लिए मनुष्यों की आवश्यकता रहती है। यदि और तत्व समान रहे तो, जिस राज्य में इन दो कार्यों को करने के लिए बड़ी संख्या में लोग होंगे वह राज्य शक्तिशाली बन जायेगा। यह कथन कुछ पक्षों में सत्य है क्योंकि जब तक एक देश के पास लोग न होंगे जो औद्योगिक साधनों को संचालित कर सकें तब तक वह देश प्रगति कैसे कर पायेगा। युद्ध के समय भी अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए जल, पत्त एवं वयु चेतो में युद्ध लड़ने के लिए तथा योद्धाओं को उनकी जख्मों की चोटों पहुँचाने के लिए यथेष्ट जनसंख्या न होगी तब तक कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। यही कारण है कि साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीति को अपनाते वाले देश जनसंख्या के प्रसार को रोकने की प्रेरणा बढ़ावा देते हैं। जर्मनी के हिटलर तथा इटली के मुसोलिनी ने यह किया था। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में अधिक से अधिक सतान उत्पन्न करना महिलाओं की अधिक राष्ट्र सेवा का प्रतीक माना जाता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर विटमन चर्चिल ने २२ मार्च, सन् १९४२ के रेडियो भाषण में कहा था कि यदि यह देश विश्व के नेतृत्व में अपना उच्च स्थान बनाये रखना चाहता है तथा एक ऐसी बड़ी शक्ति के रूप में जन्मा रहना चाहता है जो बाहरी दबावों के होते हुए भी स्वतंत्र में रह सके तो प्रत्येक साधन द्वारा हमारी जनता को बड़े परिवार रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चर्चिल का यह कथन शक्ति-तत्व के रूप में जनसंख्या के महत्व को सामने लाता है। अधिक जनसंख्या के राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से निम्नलिखित लाभ हैं :—

(i) बड़ी जनसंख्या लड़ने के लिए अधिक सिपाही तथा उत्पादन कार्य के लिए अधिकाधिक मजदूर प्रदान कर सकती है।

(ii) अधिक जनसंख्या होने पर अच्छे से अच्छे मैनिक छांटने की सुविधा रहती है।

(iii) अधिक जनसंख्या का ज्ञान लोगों के आचरण या चरित्र (Morale) को ऊँचा उठाने में सहायक होता है।

(iv) जिस राज्य में जनसंख्या अधिक होती है वहाँ असहयोग आन्दोलन एवं छुपी हुई प्रक्रियाओं जैसे साधनों को अपना कर स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है।

(v) अधिक जनसंख्या एक राज्य को सैनिक एवं आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है ताकि उस अधिक जनसंख्या को बसाने के लिए दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा किया जा सके। हो सकता है कि साम्यवादी चीन की विस्तारवादी नीति के पीछे यही कारण छिपा हो।

जनसंख्या की अधिक मात्रा केवल तभी लाभदायक रह सकती है जबकि और तत्त्व समान हों। किन्तु प्रायः अन्य तत्वों के बीच संतुलन नहीं पाया जाता और यही कारण है कि व्यावहारिक जगत में जनसंख्या की अधिक मात्रा राष्ट्रीय शक्ति पर उल्टा प्रभाव डालती है। इसी अर्थ में मॉर्गन्थौ (Morgenthau) महोदय ने कहा था कि यह कहना सही न होगा कि एक देश की जनसंख्या ज्यादा है अतः उस देश की शक्ति भी अधिक होगी। अगर हम एक क्षण के लिए इस बात को सही भी मान लें तो इसका स्वभाविक परिणाम होगा कि साम्यवादी चीन विश्व की सबसे बड़ी शक्ति माना जायेगा, जो सभ्यता के विरुद्ध होगा। जनसंख्या की अधिक मात्रा कभी-कभी राष्ट्रीय शक्ति के विपरीत भी चली जाती है। भारत, चीन एवं अन्य देशों के अध्ययन करने के बाद हम पायेंगे कि वहाँ साधन तो कम हैं तथा उपयोग करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इन देशों में खाने वाले मुँह अधिक हैं तथा भोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश उच्च शक्ति नहीं बन सकता। ये देश अति जनसंख्या (Over population) के रोग से पीड़ित हैं। यहाँ सैनिक एवं औद्योगिक दृष्टि से इतने लोगों की आवश्यकता नहीं रहनी जिसके कारण बेरोजगारी फैलती है, समाज में भ्रष्टाचार आदि बुराईयाँ फैलती हैं। अभाव की राजनीति (Politics of Scarcity) के दोषों के बीच रहना हमें कोई भी देश विश्व राजनीति में अपना स्थान शक्तिपूर्ण नहीं बना सकता। अधिक जनसंख्या होने पर देश में एकता कायम करना और उसे बनाए रखना बड़ा कठिन पड़ जायेगा।

आज की बदलती हुई परिस्थिति एवं विज्ञान के युग में यह सम्भव नहीं रहा है कि सैनिक शक्ति के संचालन की अधिक लोगों के हाथों में छोड़ा जाय, यह आवश्यक भी नहीं है। कुछ मोड़ों से ही लोग विध्वंसकारी प्रशस्त्रों

का प्रयोग करके अतद्योगियों के परिश्रम के परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक तकनीकी ज्ञान के प्रसार से अधिक जनसंख्या का होना निरर्थक बन गया है। राष्ट्रीय शक्ति के लिए इसका अधिक महत्व नहीं है।

जनसंख्या का गुणात्मक पहलू

(The qualitative aspect of Population)

निवासियों की केवल अधिक संख्या का होना ही एक देश को शक्तिशाली नहीं बना देता, उन निवासियों की उम्र, लिंग, जन्म-दर की गति, जीवन का स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन क्षमता, चातुर्यता, रीत-रिवाज, विश्वास, नैतिकता, धार्मिक विश्वास आदि बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। श्लाइमर (Schleicher) महोदय के मतानुसार युद्ध और शान्ति दोनों ही समय यद्यपि जनसंख्या की अधिक संख्या आवश्यक है किन्तु जनसंख्या के गुण इससे भी अधिक अपेक्षित हैं। उद्योग धर्मों में अशिक्षित एवं अनुसृत कुलियों से काम नहीं चलना वहाँ कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। उम्र के हिसाब से जिस देश की निवासियों में १८ से ४५ तक के लोगों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर मनुष्य शक्ति को अधिक कामों में लगाया जा सकता है। एक परिपक्व औद्योगिक समाज में बूढ़ों की संख्या उम्र समाज की तुलना में अधिक होती है जहाँ औद्योगीकरण अभी आरम्भ हो रहा है।

लोगों की शक्ति, सामर्थ्य तथा उत्पादन-क्षमता निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर तथा आर्थिक पहलू करने की शक्ति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त जलवायु, लोगों का चरित्र तथा लोगों के सामाजिक तथा धार्मिक मूल्य एवं दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हैं।

जातों की जाति (Race) का भी राष्ट्रीय शक्ति पर भारी प्रभाव पड़ता है। एक जाति के लोगों के बीच विचारों की समानता, परम्पराओं की निकटता एवं आपसी मेलजोल का मान पाया जाता है। उनकी यह एकता राष्ट्र को शक्ति प्रदान करती है। यदि एक देश की जाति एवं प्रजाति सबधी समुदायों का अध्ययन कर लिया जाये तो उस देश के चरित्र एवं व्यवहार को समझना आसान हो जाता है। विभिन्न जाति, एवं प्रजातियों के रहने पर अत्यावश्यकता के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होता है। अल्पमत तथा बहुमत के बीच भगडे उस देश की शक्ति में दीमक का काम करते हैं और एक दिन उस देश का पतन हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका के भगडों की जाति की मिश्रता हो गई है। इसी प्रकार जातिगत (Racial) भेद ने

ही रोडेजिया में ऐसी समस्या निमित्त बर दी है जिसके प्रति आज विश्व का ध्यान बंटा हुआ है। अल्पसंख्यक गोरी सरकार ने वही जो एकतरफा स्वतन्त्रता की घोषणा करके इथान-स्मिथ के अधीन शासन की बागडोर समाली वह बहुसंख्यक लोगों को पसन्द नहीं है। दोनों के बीच आज दिन प्रकार का संघर्ष चल रहा है उसके होने पर कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता।

जनसंख्या का वितरण

(The Distribution of Population)

यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का मानचित्र देखें तो पायेंगे कि कुछ क्षेत्रों में तो जनसंख्या बड़े घने रूप से बसी हुई है और अनेक बड़े क्षेत्रों में केवल कुछ ही लोग रहते हैं। अनुमानतः दुनिया की आधी जनसंख्या एशिया के दक्षिण पूर्वी कोने में रहती है जो दुनिया की कुल भूमि का लगभग दसवा भाग है। कुल जनसंख्या का पाँचवाँ हिस्सा योरोप में रहता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग छः प्रतिशत भाग ब्रिटेन और अमेरिका में रहता है। जनसंख्या के इस असमान वितरण के पीछे अनेक कारण रहते हैं। अधिकांश लोग प्रायः उन क्षेत्रों में रहना चाहते हैं जहाँ की भूमि उपजाऊ है तथा जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। लोग वहाँ रहना पसन्द नहीं करते जहाँ कि कृषि या उद्योगों के आधार पर जीवन यापन करना कठिन हो अथवा असम्भव हो। उदाहरण के लिए सहारा अथवा अफगानिस्तान आदि स्थान। लोग प्रायः ऐसे स्थानों में बसना पसन्द करते हैं जहाँ आवागमन के साधन पर्याप्त अच्छे हैं, तथा घरेलू भण्डे कम होते हैं तथा युद्ध नहीं होते रहते। जो क्षेत्र कच्चे माल की दृष्टि से सम्पन्न होते हैं वहाँ भी लोग अधिक रहना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ औद्योगिक विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। वातावरण का भी लोगों की बसावट पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष वातावरण में लोग बसेंगे या नहीं बसेंगे यह बात उन दृष्टिकोणों लक्ष्यों एवं तकनीकी योग्यताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में अधिक लोग क्यों रहने हैं तथा दूसरे क्षेत्र में कम लोग क्यों रहते हैं इसके लिए कोई एक निश्चित स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। विश्व में जनसंख्या के वितरण की प्रवृत्तियाँ अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक तत्वों से प्रभावित होती हैं तथा इनमें से कोई भी एक तत्व बसने या स्थानांतरण करने का कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं बन सकता।

जनसंख्या का प्रकार एवं विकास (Size and Growth of Population)

यह अनुमान लगाया जाता है कि सन् १७५० में ससार की जनसंख्या १०० मिलियन थी। एक सौ पचास वर्ष बाद यह संख्या दो गुनी हो गई और उसके पैंसठ साल बाद पुन दो गुनी हो गई। समुक्त राष्ट्र सभ के जनसंख्या सर्वेक्षी अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि की वर्तमान दर को देखते हुए विश्व की ३.३ बिलियन जनसंख्या आने वाले पैंतीस वर्षों में दो गुनी हो जाएगी। यदि वर्तमान प्रवृत्तियां जारी रही तो सन् १९८० के बाद विश्व की जनसंख्या में प्रति वर्ष सौ मिलियन से भी अधिक की वृद्धि होगी तथा सन् २००० के बाद यह वृद्धि २०० मिलियन प्रति वर्ष के हिसाब से होने लगेगी। इस विषय के विशेषज्ञ इस तथ्य के प्रति सजग हैं कि जनसंख्या के दो गुना होने का समय निरन्तर घटता ही जा रहा है और भावी जनसंख्या के लिए भोजन, मकान, शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। गणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि यदि विकास का झुकाव आज की तरह ही रहा तो सन् २००० तक विश्व की जनसंख्या १ बिलियन हो जाएगी।

जनसंख्या में जो भी वृद्धि होती है उसका लगभग ८५ प्रतिशत भाग लेटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कम आय वाले देशों से सम्बन्ध रखता है। सन् २००० तक दुनिया की आबादी का लगभग ४/५ भाग इन क्षेत्रों में रहने लगेगा। ऐसा होने पर उत्तरी अमेरिका, योरोप, सोवियत सभ, जापान आदि उच्च आय वाले औद्योगीकृत देशों तथा इन विकसित देशों के मध्य स्थित अन्तर की लाई बढ जायेगी। विकसित देशों में नियन्त्रित जन्मदर एवं निम्न मृत्युदर के बीच लगभग सन्तुलन रखा गया है। विकासशील देशों में सुपरी हुई मंडीकल सुविधाओं एवं जन-स्वास्थ्य के प्रयासों के कारण प्रौढ मृत्युदर कम हो गई है जबकि जन्मदर अब भी उच्च बनी हुई है। विकासशील देशों में भावी जनसंख्या अत्यधिक होने लगेगी; यदि जन्मदर इसी तरह ऊँची बनी रही और मृत्युदर धीरे-धीरे घटती चली गई। जनसंख्या की मात्रा में वृद्धि ही इस बात का तथ्य करेगी कि ससार आने वाली जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र और मकान का प्रबन्ध कर सकेगा या नहीं।

यद्यपि जनसंख्या विश्व भर में बढ़ती जा रही है फिर भी जनसंख्या के विशेषज्ञों का कहना है कि यह वृद्धि प्रच-विकसित देशों में तीव्र गति से हो रही है। ऐसी स्थिति में २५ वर्ष या इससे भी कम समय में उनकी जन-

सख्या दो गुनी हो जाती है। अफ्रीका के विभिन्न देशों में जनसख्या की वृद्धि की दर अलग-अलग है, किंतु वहाँ भी आने वाले ३० से ३५ वर्षों में जनसख्या दो गुनी हो जाती है। विज्ञान के विकास ने अनेक लाइलाज बीमारियों का सफल उपचार खोज दिया है। इसके अतिरिक्त टीका कीटाणुनाशक दवा, आदि के आविष्कार ने बीमारियों को कम कर दिया है और इन सबके परिणामस्वरूप मृत्यु दर घट गई है। भोजन में सुधार होने से भी मृत्यु दर के घटने में सहायता मिली है। वस्तुस्थिति इस प्रकार की होती हुई भी यदि एक देश चाहता है कि वह अपने नागरिकों को सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्रदान करे, सम्पत्ति की रक्षित करे तथा आधुनिक समाज एवं अर्थ व्यवस्था और जीवनस्तर को ऊँचा करने के लिये अन्य तत्वों की व्यवस्था करे तो उसे जनसख्या की वृद्धि को कम करना होगा।

जनसख्या की वृद्धि में लिंग और उम्र का महत्व होता है। एक पत्नी विवाह वाले समाजों में सन्तानोत्पत्ति में सक्षम स्त्री और पुरुषों के बीच का समतुलन यह तय करेगा कि दूसरी पीढ़ी की जनसख्या क्या होगी। युद्धों के कारण जो भीतें होती हैं और जिस प्रकार जन्म दर घट जाती है उससे जनसख्या के झुकाव में परिवर्तन आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई के परिणामस्वरूप सोवियत रूस में यही हुआ। स्त्रियाँ अधिक होती हुई भी युवक पुरुषों की सख्या कम होने के कारण वहाँ जन्म दर घट गई। एक देश में किस उम्र की जनसख्या अधिक है, यह बात भी जनसख्या के विकास पर प्रभाव डालती है। जिस देश में सन्तानोत्पत्ति में सक्षम उम्र वाले की सख्या अधिक होती है और कम उम्र वाले समूह अधिक होते हैं वहाँ आने वाले तीस वर्षों में जनसख्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसे देशों में सन्तानोत्पत्ति अधिक होती है तथा मृत्यु दर घट जाने के कारण जनसख्या शीघ्र ही अधिक हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा भोजन, रोजगार आदि से सम्बन्धित गम्भीर समस्याएँ पैदा होती हैं। विकासशील देशों में एक बड़ी सख्या में लोग इस उम्र तक पहुँच रहे हैं जहाँ कि वे सैनिक सेवा मनदान एवं औद्योगिक मजदूर के रूप में काम कर सकें। चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया, लेटिन अमेरिका के कुछ देश, अफ्रीका के कुछ भागों में ऐसा ही हो रहा है। जनसख्या के इन समूहों द्वारा यहाँ शिक्षा एवं लाभदायक रोजगार की विशेष समस्याएँ पैदा की जा रही हैं। अर्थात् जनसख्या होने के कारण इन देशों में राजनैतिक अस्थिरता तथा राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियाँ जोरों पर हैं। दूसरी ओर समुन्नत राज्य अमरीका और संवियत संघ में ४६ वर्ष से अधिक के लोगों का प्रतिशत पर्याप्त ऊँचा है।

जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रवाद की भावनायें भी एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के कुछ भागों में बढ़ती जा रही हैं। जनता को यह कहा गया था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उनका जीवन स्तर बढ़ जायेगा। यदि जनसंख्या तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो राष्ट्रीय उत्पादन भी उसी दर से बढ़ना चाहिये तभी हम वर्तमान निम्न जीवन स्तर को बनाये रक्त सकेंगे। उसे ऊँचा उठाने की बात तो सत्य है। वास्तविक प्रगति प्राप्त करने के लिये उत्पादन की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात से दो गुनी होनी चाहिये।

जनसंख्या की वृद्धि के परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जिस औद्योगीकरण के कारण औषध प्रगति होती है वह औषधी जनसंख्या को शहरी बेन्दो की ओर मोड़ने में सहायता करता है। इसके परिणामस्वरूप परम्परागत बन्धन ढीले हो जाते हैं और युवकों में एक स्थिरता छा जाती है। टर्बो, भारत और चीन आदि देशों में सत्रमण बाल की ये बठिनाइयाँ देखने को प्राप्त होती हैं। वस्तुस्थिति यह है कि विकासशील देशों की विवर्तित देशों द्वारा जो आर्थिक और तकनीकी सहायोग दिया जाता है, ये देश गेहनस करके जिन राष्ट्रीय योजनाओं को बनाते हैं उन सब का परिणाम प्राप्त होने से पहले से ही आर्थिक एवं अन्य सामाजिक विकास को जनसंख्या की वृद्धि द्वारा चुनौती दे दी जाती है। प्रधान मन्त्री नेहरू ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले कहा था कि यदि जनसंख्या अभी न पकड़ी जाने वाली गति से बढ़ती रही तो हमारी पञ्चवर्षीय योजनाओं का कोई फल नहीं होगा।

इस समस्या का आर्थिक विश्लेषण करने पर कुछ विशेष बारे सामने आती हैं। जन्म दर अधिक होने का अर्थ है कि जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात १५ साल के नीचे का है, वह उपभोक्ता है और आर्थिक दृष्टि से शेष जनसंख्या पर आश्रित है। एशिया और सुदूर पूर्य के देशों की ४० प्रतिशत जनसंख्या १५ वर्ष से कम उम्र वाली है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और जापान में इस उम्र वाली जनसंख्या की मात्रा तीस प्रतिशत है। यदि ये देश चाहते कि वहाँ आघात पूजा बढ़े, अन्तर्देशीय बचत अधिक हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो तो इन्हे उत्पादन को जनसंख्या की मात्रा से दृग्ना करना पड़ेगा। गरीब देश जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति के कारण और गरीब होते जा रहे हैं। ये देश बचत करने में पर्याप्त बठिनाई का अनुभव करते हैं। इन देशों की अपनी सतिरिक्त जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करने में भी बठिनाई का अनुभव हो रहा है। यह कहा जाता है कि यदि विदेशी सहा-

यता का कुछ भाग जनसंख्या नियन्त्रण में लगाया जाए तो इससे इन देशों के विकास में गंभीरता होगी।

जनसंख्या में विकास की गति आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। दूसरी ओर वह स्वयं भी आर्थिक विकास के स्तर से प्रभावित होती है। कृषि प्रधान देशों में जन्म-दर और मृत्यु दर प्रायः समान रूप से ऊँची होती है। औद्योगीकरण के बाद जन्म दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर कम हो जाती है। जब औद्योगीकरण अपनी परिपक्वता की स्थिति में आ जाता है तो जन्म-दर और मृत्यु-दर दोनों ही कम हो जाती है। ऐसे देशों में वृद्धों की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और जनसंख्या के विकास की गति धीमी हो जाती है। जब जन्म दर बढ़ती है तो उस देश के लोगों का मारेल ऊँचा हो जाता है और घटने पर कम। बढ़ती हुई जनसंख्या वाले देशों में सरसाह एवं शक्ति पर्याप्त मात्रा में देखी जाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या वाले देशों में युवकों की मात्रा अधिक होती है और इन देशों के आर्थिक एवं सैनिक विकास की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

जनसंख्या सम्बन्धी सक्रमण

(The Demographic Transition)

प्रत्येक देश का औद्योगिक विकास जिस प्रक्रिया एवं तरीके से हो रहा है वह जनसंख्या सम्बन्धी सक्रमण की है। इस सक्रमण में पहला काल उच्च जीवन दर एवं उच्च मृत्यु दर का था और दूसरा काल निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर का है। इस परिवर्तन के दौरान जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक ऊँची हो जाती है और यह उस समय तक ऐसी बनी रहती है जब तक कि दूसरे काल में न पहुँच जाए। इस परिवर्तन के द्वारा पर्याप्त कार्यकुशलता बढ़ती है। जब यह परिवर्तन पूरा हो जाता है तो युवक प्रौढ़ों की प्रत्येक नई पीढ़ी कम से कम मनुष्योत्पत्ति करती है और कम बच्चे मरते हैं तथा शिक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। इस विकास की गति के बाद बच्चे मसानों में प्रजनन क्रिया कम हो जाने के कारण आर्थिक व्यक्तियों की उम्र बच्चे लोग बढ़ जाते हैं। ये सब कारण जनसंख्या सम्बन्धी सक्रमण औद्योगीकरण को साने पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं।

विकास की यह गति साम्यविद्ध होने की अपेक्षा प्रभुत्व अधिक है। सन् १९३० की आर्थिक मशी के दौरान इन औद्योगिक देशों में पर्याप्त कठिनाइयाँ आयीं और उसके बाद से इन सभी देशों की जन्म दर बढ़ गई ताकि जनसंख्या के विकास में नई सहर आ सके। कुछ भी हो किन्तु औद्योगिक

राष्ट्रों के जन्म दर की वृद्धि उन्नीसवीं सदी के स्तर पर नहीं पहुँच सकती। अधिकांश औद्योगिक देशों में तो जन्मदर गिर गई है। जापान में प्रजनन शक्ति घटने में यह सिद्ध हो गया कि पूर्वी देशों में भी औद्योगीकरण का वही प्रभाव होता है जो पश्चिमी देशों पर हुआ। संवेप में जनमरुपा सम्बन्धी सक्रमण का माडल अत्यन्त उपयोगी है। यह वास्तविकता की पूरी तरह व्याख्या करता है तथा यह हमें तर्प्यों के देखने के साथ-साथ कुछ मूल अनुमान पर आधारित प्रश्न उठाने में भी सहायता करता है।

जनसंख्या के विकास की वर्तमान प्रवृत्तियाँ

(The Present Trends of Population Growth)

जनसंख्या के विकास के बारे में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आज के अर्धविकसित देश उस जनमरुपा सम्बन्धी सक्रमण की दुहरा रहे हैं जिसमें होकर वर्तमान औद्योगिक देश निकले हैं। यदि ऐसा ही हो रहा है तो हम उस समय का अनुमान लगा सकते हैं जो इन देशों को अपने विकास में व्यतीत करना होगा, किन्तु सच तो यह है कि इन देशों को विकास की उनी प्रक्रिया में होकर गुजरना नहीं पड रहा है। एक स.से महत्वपूर्ण अंतर तो यह है कि आज के अर्धविकसित देशों में प्राकृतिक वृद्धि इतनी नहीं हो रही है जितनी कि कमी आज के औद्योगिक देशों में हुई थी। असल में ये देश अधिक प्राकृतिक वृद्धि का दिग्दर्शन करा रहे हैं। इस वृद्धि की गति का उदाहरण मानव इतिहास में प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि आज इन देशों में जन्म दर बहुत ऊंची है और मृत्यु दर घट गई है। इन देशों की मृत्यु दर ऐसे समय में कम हो गई है जब कि ये आर्थिक विकास के प्रारम्भिक सोपानों की ही पार कर रहे हैं, आज के औद्योगिक देशों में यह कमी उन समय आई थी जबकि पर्याप्त सम्पन्नता के स्तर पर पहुँच गये। अर्धविकसित देशों में मृत्युदर इतनी शीघ्र कम हो जाने का कारण यह है कि इनको अंतराष्ट्रीय वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध है। स्वास्थ्य की प्रक्रियाओं ने सामूहिक स्तर पर अपना महत्व सिद्ध कर दिया है। आज के औद्योगिक देशों के विकास की गति धीमी रही, क्योंकि उनको प्रत्येक चीज का प्रयोग करना पडा, उसका आविष्कार करना पडा। जब कि आज मृत्यु से लड़ने के सभी तरीके ईजाद हो चुके हैं, वर्तमान कृषि प्रधान देश अपनी वैज्ञानिक प्रगतियाँ समझ के बिना ही इन आविष्कारों एवं प्रयोगों द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आयातित स्वास्थ्य प्रयासों के लिए सामाजिक संगठन में परिवर्तन करने

की आवश्यकता बहुत कम रहती है। इन देशों में जन्म निरोध या प्रजनन शक्ति को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते, अतः जन्म दर पूर्ववत् उच्च ही बनी रहती है। इसके परिणामस्वरूप इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि यहां के आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं होती जैसा कि आज क. प्रौद्योगिक देशों में हुई था। किन्तु इसके विपरीत यह तो आर्थिक विकास की एक बाधा का काम करती है। इसके अतिरिक्त इन देशों में जनसंख्या वृद्धि की यह प्रक्रिया ऐसे समय में हो रही है जबकि ससार में इतने अधिक क्षेत्र नहीं बच गये हैं जहां पर कि अतिरिक्त जनसंख्या को बसाया जा सके तथा स्थानान्तरण द्वारा इस समस्या की गम्भीरता को कम किया जा सके। आज जो भी देश अपने आपको प्रौद्योगिकृत बनाना चाहता है उसके सामने अनवरत बाधाएँ आती हैं, प्रौद्योगिकृत देशों के साथ प्रतियोगिता पंदा होती है तथा राजनैतिक रूप से इन देशों को हताश किया जाता है।

आज का ससार जिस अकल्पनीय एवं अपूर्व जनसंख्या वृद्धि की प्रक्रिया का अनुभव कर रहा है तथा इसके अधिकांश अनुपात का भार गरीब एवं अर्धविकसित राष्ट्रों पर पड़ रहा है इससे दो परिणाम उत्पन्न होते हैं प्रथम यह है कि अर्धविकसित देशों में जहां कि पहले से ही जनता घने रूप में बसी हुई है वहां जनसंख्या की वृद्धि अन्य परिहार्य बाधाओं के साथ मिल कर इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक विकास की गति को धीमा कर रही है। दूसरा और अनेक कारणोंवश इन देशों की महत्वाकांक्षायें बड़ी तीव्र गति से घायल बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय सैन्यों एवं राष्ट्रीय भावनाओं के बीच महान् असमानता हान के कारण इन देशों में राजनैतिक अस्थिरता है। दूसरे, इन देशों की राजनैतिक अस्थिरता एवं उनके आर्थिक विकास की धीमी गति मिल कर इनको विकसित देशों की तुलना में अधिकतम कमजोर बनाती जा रही है। इस स्थिति में एक ऐसी रित्त स्थान की रचना हो रही है जिसने कभी उपनिवेशवाद को जन्म दिया था।

अर्धविकसित देशों में मृत्यु दर कम हान के कारण वहां युवक जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई। इससे आर्थिक बालकों की संख्या बढ़ी जिसने आर्थिक समस्याओं को और भी अधिक जटिल बना दिया। जब युवकों का समुदाय रोजगार की तलाश करता है तो उनमें से सभी को इस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती और अगर मिलती भी है तो सतोषप्रद रूप से नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में उनकी शक्तिशाली आन्दोलन, क्रान्ति एवं युद्ध की ओर मुड़ जाती है। भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति को इसका एक जीता-जागता उदाहरण माना जा सकता है।

कृषि प्रधान देशों में जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण उससे ठीक विपरीत रूप में हो रहा है जैसा कि भौगोलिक प्रगति के लिए होना चाहिए था। आर्थिक विकास के दौरान लोगों के रहने की स्थिति में भारी परिवर्तन आता है, वे शहरों की ओर दौड़ने लगते हैं। जो कोई भी तब इस गति को रोकता है वह एक प्रकार से आर्थिक विकास रोक रहा है। इस विकास मार्ग की एक बाधा तो यह तथ्य है कि अधिक प्रजनन शक्ति देहाती क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रों पर जनसंख्या अधिकाधिक घना रूप लेती जाती है तथा कृषि के आधुनिकीकरण की कठिन बना देती है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के परिणाम देहाती क्षेत्रों के कम रोजगार की तुलना में इतने अधिक गम्भीर होते हैं कि सरकार प्रायः इस प्रकार की नाति मननाती है जिससे कि अनेक प्रकार से शहरीकरण को हतोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए उद्योगों की विकेंद्रित कर दिया जाता है, हस्त-कला को प्रोत्साहन दिया जाता है, कृषि सुधार के प्रयासों पर व्यय किया जाता है, आदि-आदि। ये प्रयास जिस सीमा तक सफल होते हैं वे उतना ही देश के आर्थिक विकास पर रोक लगाते हैं तथा राष्ट्र की कमजोरी का प्रतीक बन जाते हैं।

अनेक विकसित देशों में जो शहरीकरण हो रहा है, उसके पीछे दो कारण हैं। प्रथम तो यह आर्थिक विकास का परिणाम है और दूसरा यह देहाती क्षेत्रों में बढ़ा हुई जनसंख्या का परिणाम है। इनका राजनैतिक महत्व तो इस बात में निहित है कि इनमें द्रुत संचार व्यवस्था के लिए सम्भावनाएँ बढ जाती हैं। साथ ही सामूहिक क्रम उठना भी सम्भव बन जाता है। बढ़ती हुई आबादी वाले नगरों में अफवाहें बिखरने की तरह फँडती हैं। विभिन्न वर्गों के बीच पतित सम्पर्क के कारण धार्मिक एवं सजातीय ईर्ष्या का भावना का उदय होता है। इन सब परिस्थितियों में अवहेतना, भयनायक या अत्याचार की प्रतिक्रिया बड़ी शीघ्र, व्यापक एवं हिंसात्मक होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में जनमत का स्थान

(The Role of Public Opinion in International Relations)

एक देश की विदेश नीति में जनमत द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह इस बात का संकेतक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जनता का स्थान महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। पहले नीतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रतीक सदा से ही इतिहास के निर्णायक तत्व रहे हैं; किन्तु फिर भी

इनका योगदान इतना महान कभी भी नहीं रहा जितना कि यह प्राधुनिक युग में पाया जाता है। आज का युग मजदूरों की शान्ति का युग कहनाता है जिसमें सत्तार के अधिकांश भागों को समाजवाद के रंग में रंगना एक उद्देश्य है। इस युग में जासूसों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है तथा कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेते समय जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता।

मजदूर वर्ग हमारे समय के सामाजिक विकास की एक मुख्य प्रेरक शक्ति है। मानव इतिहास में आज तक जिन वर्गों ने समाज की अध्यक्षता की है उनमें यह वर्ग सख्या में सभी से अधिक है तथा यह प्रायः सभी दलित वर्गों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। लेनिन ने विश्व में होने वाले विकासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताया था कि साम्यवाद की विजय का कारण यह है कि सैकड़ों और हजारों लोग धीरे-धीरे इसके समर्थक बन गये हैं। यह बहुमत अब जागृत हो चुका है तथा कुछ कर गुजरने के लिए आतुर है। इसी मजबूत से मजबूत और शक्तिशाली से शक्तिशाली सत्ताओं द्वारा भी रोका नहीं जा सकता।

माक्स और लेनिन के प्रयासों से मजदूर वर्ग में यह पहचानने की शक्ति आ गई है कि उनका हित क्या है तथा इसकी साधना के किस प्रकार कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति में मजदूर वर्ग के योगदान के साथ साथ अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में इसका प्रभाव से एक नया विक्रम यह हुआ है कि विदेश नीतियों का भावनात्मकीकरण हो गया है। आज युद्ध और शान्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों में जनता की रुचि बढ़ती जा रही है। वह विदेश नीति के विभिन्न पहलुओं में पर्याप्त रुचि लेती है। इस सबके परिणामस्वरूप विदेश नीति की जनता की दृष्टियों से प्रभावित होना पड़ता है।

आरबेटोव (Y Arbatov) जैसे साम्यवादी लेखकों का कहना है कि शोषित मजदूर वर्ग चुनावों में भाग लेता है इसके प्रतिरिक्त भी उनके पास कुछ साधन हैं जिनके माध्यम से वह विदेश नीति को प्रभावित कर सके। मजदूर वर्ग का सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं आक्रामकता का विकास करना होता है। माक्स द्वारा दुनिया के मजदूरों को एक होने का जो नारा दिया गया उसके साम्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि जाहिर होती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के बाद ही साम्यवादी शान्ति के सपनों का पूरा किया जा सकता है। मजदूर वर्ग के पास

हड़ताल आदि के रूप में कई एक शक्तिशाली हथियार हैं जो यदि प्रयुक्त किये जायें तो पर्याप्त प्रभावशाली साबित हो सकते हैं ।

आजकल के युद्ध केवल भ्यावसायिक सेनाओं के माध्यम से ही नहीं लड़े जाते । लेनिन के कथनानुसार आज के युद्ध राष्ट्रो द्वारा लड़े जाते हैं । इन युद्धों के संचालन के लिए आवश्यक व्यापक संख्या में जो सेना नियुक्त की जाती है वह मूल रूप से काम करने वाली जनता के कंधों पर बन्दूक रख कर ही चलती है । जनसंख्या का कार्य गृह स्तर पर भी बढ़ जाता है क्योंकि प्रत्येक सेना का माध्य उसके श्रम एवं भोग्य पर निर्भर करता है । यही कारण है कि युद्ध, शान्ति एवं विदेश नीति के बारे में बड़ी जनसंख्या के विचार एक महत्वपूर्ण तत्व बनते जा रहे हैं । ये एक देश की सैनिक सामर्थ्य का निश्चय करते हैं तथा सेना के भोग्य, अपने डिवीजन के गुण एवं गृह स्तर पर स्थायित्व आदि का निर्धारण करते हैं । यह ज्ञात जाता है कि पिछले दो विश्व युद्धों के अनुभव के बाद यह बात सामने आई कि युद्धों एवं विदेश नीति के प्रति जनता का दृष्टिकोण केवल नैतिक तत्व तक ही मर्यादित नहीं है । यह उस वर्ग के शासन को भी समाप्त कर सकता है जो युद्ध में रत है । यह शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नवीन शक्ति के रूप में उदित हो रही है । इसके फलस्वरूप प्रजातन्त्रमय विदेश नीतियां बनने लगी हैं । इस दृष्टि से उपनिवेशों एवं आश्रित देशों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता मोर्चे हैं उनका भी अपने धारों पर्याप्त महत्व है ।

यह माना जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जनसाधारण का जो महत्त्व बढ़ा है वह कोई भ्रमसर की ही बात नहीं है और न ही यह राजनीतिज्ञों एवं कूटनीतिज्ञों के विषयगत गलत भाकलन का ही परिणाम है । यह तो विषयगत ऐतिहासिक विकास का एक प्राकृतिक परिणाम है । यह एक सामाजिक वातावरण है जो मानवता की प्रगतिशील एवं शान्तिवादी शक्तियों का पक्ष लेता है । विदेश नीति पर जनसाधारण का बढ़ता हुआ प्रभाव प्रतिक्रियावादी एवं भाकमणकारी नीतियों तथा रूपों को संभव नहीं होने देता । यह आज की दुनिया की एक अद्वितीय प्राप्ति है । कोई भी देश इस प्राप्ति से छोड़ना नहीं चाहेगा ।

बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करने के मार्ग
(The ways of dealing with Population Increase)

जनसंख्या की वृद्धि का एक देश के ऊपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो प्रभाव पड़ता है वह बहुधा हानिकारक होता है । ऐसी स्थिति में जन

तरीकों की जानकारी उपयोगी रहेगी जो जनसंख्या के बढ़ने पर उसके बु परिणामों को कम करने के लिए काम में लाये जा सकते हैं। विचारकों कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को रोकने के लिए तीन मा अपनाये जा सकते हैं। पहला, विस्थापन (Migration) दूसरा, उत्पादन वृद्धि (विशेषकर कृषि उत्पादन में) और तीसरा, जनसंख्या नियन्त्रण (Population Control)। इन तीनों मार्गों का कुछ विस्तार के लिए अध्ययन किया जाना भी उपयोगी रहेगा।

(I) विस्थापन (Migration) का तरीका—जब से विचारधारकों ने यह निश्चित किया है कि जनसंख्या के दबाव प्रसारवादी नीतियों को प्रोत्साहित करते हैं तब से यह विश्वास किया जाने लगा है कि अधिक जनसंख्या वाला देश पर्याप्त भूमि और साधन स्रोत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उन्नीसवीं शताब्दी की उपनिवेशवादी एवं साम्राज्यवादी नीतियों को इन्हीं विचारों का प्रतीक माना जा सकता है, यद्यपि उस समय समुद्र पार के प्रदेशों में बहुत कम लोग जाकर बसे। सोवियत संघ और साम्यवादी चीन अपनी जनसंख्या की समस्या को सुलझाने के लिए अपनी सीमाओं के क्षेत्रों में लोगों को बसा रहे हैं। मास्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे देश अब भी यूरोप के कुशल कार्यकर्ताओं को अपने देश में धुसने के लिए आकर्षित करते हैं किंतु वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार भाजकल अधिकांश देश विस्थापितों को स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाते हैं; इसका कारण चाहे बेरोजगारी हो अथवा आंतरिक राजनैतिक तत्व। इसका एक कारण यह हुआ कि विस्थापन के द्वारा जनसंख्या की समस्या को सुलझाने के आसार कम हो गए।

(II) खाद्य सामग्री का अधिक उत्पादन—बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए तथा उसकी समुचित व्यवस्था करने के लिए खाद्य सामग्री के उत्पादन को बढ़ाना परमावश्यक है। यह कहा जाता है कि दुनिया की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कम भोजन से गुजर करती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में भोजन के उत्पादन में वृद्धि कम से कम २.२५ प्रतिशत प्रति वर्ष होनी चाहिए। अनुमान के अनुसार सन् १९५० में यह वृद्धि ०.६ प्रतिशत हुई थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि का अभिलेख संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया जहाँ २.२५ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई, किंतु इस देश को अतिरिक्त कृषि उत्पादन की इतनी आवश्यकता नहीं रहती। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि उद्योग की विशेषता यह है कि उसका मशीनीकरण हो गया है, धम बचाने वाले अनेक तरीके अपनाये जा रहे हैं, मारी

पूँजीगत व्यय किये जा रहे हैं, अनेक प्रकार की खाद्य का प्रयोग होता है। यदि ये बातें अन्तर्विशिष्ट देशों से लागू की जायें तो इनके लिए पहले सामाजिक और प्राथमिक व्यवस्था में भारी परिवर्तन करने होंगे और अनेक देश इन परिवर्तनों को आने वाली दशाब्दियों तक नहीं कर सकते चाहे उनको विदेशी सहायता दी जाए अथवा न दी जाए। चीन से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों से साफ जाहिर है कि वहाँ मनुष्य शक्ति का व्यापक प्रयोग किए जाने के बाद भी भोजन की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सका है और इस कमी को पूरा करने के लिए उसे आस्ट्रेलिया तथा कनाडा से भारी खाद्य सामग्री मागनी होती है। खाद्यान्न की बड़ी हुई मात्रा उसी समय प्राप्त की जा सकेगी जब प्रत्येक एकड़ जमीन पर अधिक अन्न उपजने लगेगा क्योंकि जिसनी भी खाकी जमीन है वह इस समय खेती के काम में ली जा रही है और ऐसी कोई जमीन शेष नहीं बची जो नए पियरे से खेती के काम ली जा सके।

खाद्य सामग्री का निर्यात धीरे-धीरे विश्व राजनीति में नीति का एक महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। समुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया एवं कुछ अन्य देश यह शक्ति रखते हैं कि निर्यात किये जाने योग्य प्रतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें। समुक्त राज्य अमरीका ने मार्च-जनिक कानून ४८० (Public Law 480) के माध्यम से सरकारी स्वामित्व के अधीन पर्याप्त प्रतिरिक्त खाद्यान्न का सग्रह किया है। सन् १९५५ से लेकर सन् १९६५ तक पर्याप्त दस वर्षों के काल में समुक्त राज्य अमरीका ने केवल भारत को ही लगभग ३ बिलियन डालर के मूल्य का खाद्यान्न भेज दिया। एक अन्य कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रपति जॉनसन ने प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से सोन बिलियन टन प्रतिरिक्त खाद्यान्न देने का वायदा किया ताकि भारत की भूख को मिटाया जा सके। यह कहा जाता है कि जब तक वर्ष भर में प्रत्येक दिन पच्चीस हजार टन अनाज भारतीय बन्दरगाह पर न उतारा जाएगा तब तक भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। दूसरी ओर आस्ट्रेलिया और कनाडा अपने गेहूँ के उत्पादन की अधिकांश मात्रा को विश्व बाजार में बेचते या साल के आधार पर निचाल देते हैं। उनकी विप्री की अधिकांश मात्रा रूस और साम्यवादी चीन को जाती है। खाद्य समस्या की गम्भीरता को पहचान कर विदेश सहायता कार्यक्रम कृषि उत्पादन को अधिक महत्व दे रहे हैं। समुक्त राष्ट्र संघ के साथ और कृषि संगठन के महा संचालक डा० बी० थार० सेन ने इस सन्दर्भ को स्पष्ट करते हुए बताया है कि कुछ अधिक जनसंख्या वाले देशों से गम्भीर अनाज की नहीं रोका जा सकता और यह एक सरल गणितीय निष्कर्ष है कि यदि खाद्य

उत्पादन को प्रत्येक जगह इसी मात्रा में रखा गया जिसमें कि वह भव है, तो इस शताब्दी के अन्त तक भूखे या अर्ध भूखे लोगों की संख्या घाज की तुलना में दो गुनी हो जाएगी। पेडलफोर्ड तथा लिंकन के कथनानुसार विश्व-व्यवस्था को प्राप्त करने तथा बनाए रखने के मार्ग में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अनेक अर्द्ध विकसित देश विकसित देशों के साधनों के जहाजों पर आश्रित हैं। जिन देशों के पास खाद्य सामग्रियों की अतिरिक्त मात्रा है वे अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के बाद भी अकालप्रस्त एवं भ्रमावप्रस्त देशों की आवश्यकताओं को केवल आंशिक रूप से ही पूरा कर पा रहे हैं। इस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए समस्या पर कई दिशाओं से विचार किया जाना चाहिए। आवश्यकतामन्द देशों में उत्पादन को बढ़ाया जाय। अल्पसंख्यक देशों को अधिक सामग्री भेजने का प्रबन्ध किया जाए। इसके अतिरिक्त समुद्र के पानी को सिंचाई के लिए और मानवीय प्रयोग के लिए अधिक रक्षित किया जाए। सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई का उचित प्रबन्ध किया जाए और ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए कि भूमि का अधिक प्रयोग किया जा सके, खेतों पर आश्रित लोगों की संख्या कम हो और साधनों का मि-व्ययता के साथ प्रयोग किया जा सके। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि खाद्य संकट को दूर करने के लिए स्वयं उस देश को ही प्रयास करना होगा। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरण और विशेषीकृत क्षेत्रीय निकाय भी इस दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कम आमदनी वाले देशों में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के मार्ग में अनेक बाधाएँ होती हैं उदाहरण के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक बाधाएँ जो कृषि उत्पादन को परम्परागत बना देती हैं। यही समस्या यह नहीं है कि तकनीकी का अभाव रहता है बल्कि यह है कि उसका पर्याप्त उपयोग नहीं होता। गरीब और अशिक्षित लोग धीमी गति से काम करते हैं और अकार्यकुशल होते हैं। इन देशों में बचत की मात्रा कम होती है और अनेक किसानों को भारी कर्ज भार के नीचे रह कर जीवन व्यतीत करना होता है। इस सबके परिणामस्वरूप व कृषि के क्षेत्र में प्रयोग नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त अच्छा खाद और अच्छे बीज भी नहीं खरीद पाते। इन सभी कमियों को विदेशी सहायता, तकनीकी सहयोग और योग्य नवृत्त के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है।

(iii) जनसंख्या का नियन्त्रण—जनसंख्या का नियन्त्रण इस समस्या पर विचार करने का एक तीसरा तरीका है। अर्द्ध विकसित देशों में सरकारी समर्थन के आधार पर इन कार्यक्रमों को सफल बनाया जाना चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष मि० लॉर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक

समिति के सम्मुख कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकना गरीब देशों में जीवन स्तर को सुधारने के लिए किये गये प्रयासों में से एक है। जब तक जनसंख्या की वृद्धि को नहीं रोका जाता, उस समय तक हम मीड में युक्त एशिया और मध्यपूर्व के देशों में प्राथिक उन्नति की भांति इम शताब्दी में नहीं कर सकते। यह ऐसा सच नहीं है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समीकरण कृत्रिम कर सकें।

जनसंख्या के नियन्त्रण के प्रति दृष्टिकोण धीरे धीरे कम भावुक होते जा रहे हैं और अधिकतर लोग यह समझने लगे हैं कि दुनिया की जनसंख्या की वृद्धि का एक मात्र इलाज साक्ष्य एवं विकास की स्थिति को सुधारने का प्रयास है। एक दर्जन से भी अधिक देशों की सरकारें जन्म दर को कम करने के कार्यक्रमों को अपना रही हैं। इस प्रकार के कुशल राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रभाव जापान में देखा जा सकता है जहाँ पर कि क्रमशः जन्म दर गिरती चली गई। भारत एवं सोवियत संघ की सरकारें जनसंख्या पर नियन्त्रण के प्रयास कर रही हैं, किन्तु भारत में यह कार्यक्रम बड़ी घीमी गति से चल रहा है। इसके लिए उत्तरदायी प्रत्येक कारण है, जैसे डाक्टरों की कमी एवं शिक्षा आदि। शिक्षा के कारण जनसंख्या नियन्त्रण के कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है क्योंकि परम्परागत मूल्य एवं रीति रिवाज अधिक से अधिक बड़े परिवार का समर्थन करते हैं। जिन देशों में शिक्षा व्यापक मात्रा में पाई जाती है वहाँ जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है क्योंकि इन क्षेत्रों में किसी बात को सनातित करना अत्यन्त कठिन होता है और नये विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसीलिए छोटे परिवार की बात यहाँ अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। यह कहा जाता है कि साम्यवादी चीन में जनसंख्या नियन्त्रण की ऐसी नीति को अपनाया गया है जिसमें तीन बच्चों से अधिक बाले परिवार को हतोत्साहित किया जाता है। यह कहा जाता है कि एक तानाशाही सरकार शिक्षा के रहते हुए भी प्रभावशाली जनसंख्या कार्यक्रम को लागू कर सकती है। समुक्त राज्य अमेरिका की सरकार एक अन्य व्यक्तिगत समीकरण विदेशी सरकारों की सहायता कर रहे हैं ताकि उन्हें जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त हो सके। फिर भी इतना अवश्य है कि जन्म दर को कम करने जैसी समस्या को सुलझाने में विदेशी सहायता कम उपयोगी सिद्ध होगी। जनसंख्या नियन्त्रण की समस्या को अत्यन्त गम्भीर एवं महत्वपूर्ण मान कर चलना चाहिए। यह कहा जाता है कि प्राथमिक विकास और जनसंख्या नियन्त्रण की दोहरी समस्या इतने बड़े स्तर का

नियोजन एवं व्यापक दृष्टिकोण चाहती है जितना कि अणुबम के विकास की समस्या ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय चाहा था।

राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तकनीकी (Technology as an Element of National Power)

आज की दुनिया तकनीकी दुनिया है और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रायोगिक विज्ञानों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। तकनीकी के कारण जनसंख्या में परिवर्तन आता है, सुरक्षा के मांग बनते हैं और आर्थिक प्रगति का रास्ता खुलता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से पूर्व किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन को होने के लिए जितने समय की आवश्यकता थी वह एक व्यक्ति के जीवन से अधिक लम्बा होता था। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति को निश्चित परिस्थितियों में समायोजित होने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। किन्तु आज यह समय मानव जीवन की अपेक्षा छोटा हो गया है इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम व्यक्तियों को नए परिवर्तनों में ढलने का अभ्यास करावें। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रति दस या पन्द्रह वर्षों के बाद विज्ञान की प्रगति दुगुनी हो जाती है। आज दुनिया के अधिकांश लोग तकनीकी का प्रयोग करने लगे हैं। इसलिए विश्व की घटनाओं पर भी तकनीकी के प्रभाव का अनुभव किया जाता है।

तकनीकी को कभी-कभी प्रायोगिक विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें भौतिक विज्ञान एवं जीवशास्त्र को इन्जीनियरिंग, उद्योग एवं अन्य मानवीय क्रियाओं में लागू किया जाता है। विज्ञान अपने शुद्ध रूप में समाज एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव नहीं रखता किन्तु जब वह तकनीकी के रूप में परिणत हो जाता है, तो समाज प्रभावित होने लगता है। एक शुद्ध अनुसंधान विशेषज्ञ या विज्ञान का प्रोफेसर ज्ञान को ऐसे रूप में परिणत नहीं कर सकता जिसे कि शक्ति के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। यह कार्य इन्जीनियर या तकनीकी अभ्यासकर्ता द्वारा किया जाता है।

तकनीकी समाज और दुनिया में परिवर्तन लाती है। प्रोफेसर रेमण्ड सोन्टेग (Raymond Sontag) के कथनानुसार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच की घटनाएँ तीन मुख्य विचारों से प्रभावित थी—राष्ट्रवाद, सन् १९१४ से १९१९ के बीच के गम्भीर परिवर्तन जिन्होंने इतिहास की प्रगति की धारा को रोक दिया एवं तकनीकी परिवर्तन। ये तीनों ही विचार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रुक गए और इनके स्थान पर अन्य विचार जुड़ गए,

जैसे साम्यवाद का उदय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का विकास। तबनीवा, राष्ट्रवाद, साम्यवाद एवं अन्य शक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

तकनीकी ने मानव जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डाला है। इसके परिणामस्वरूप वे मूल्य जो कभी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डाला करते थे वे अब उतने ही महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। आज की दुनिया में भौतिक सन्तोष की इच्छा धार्मिक एवं सैद्धांतिक सत्त्वों से भी अधिक बढ़ गई है और राजनीति में इनका प्रभाव घटिक हो गया है। आज जिस आधार पर सैनिक सुरक्षा को व्यवस्था की जाती है उसमें तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यूरोप और अमरीका विश्व की राजनीति में इसलिए प्रभावशाली हो गए हैं क्योंकि इनका तकनीकी विकास बहुत बढ़ गया है। आजकल तकनीकी विकास गैर पश्चिमी देशों में भी घपनाया जा रहा है। इसे वहां राष्ट्रवाद के साथ मिला दिया गया है। इस प्रकार यह विश्व राजनीति में एक अनिश्चित शक्ति का स्रोत बन गया है। तकनीकी के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सांघिक विकासों की प्रक्रिया पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। सोवियत रूस और अमरीका में लाखों लोग हम क्षेत्र में अनुसंधान में लगे हुए हैं। यह सम्भायना की जाती है कि इससे मानव शक्ति एवं व्यय में पांच प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। समुक्त राज्य अमरीका के ६० प्रतिशत से अधिक प्रयास सैनिक एवं अन्तरिक्ष क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव हो रहा है। समुक्त राज्य अमरीका की सरकार कुल अनुसंधान एवं विकास का ६५ प्रतिशत प्रदान करती है। किन्तु व्यक्तित्व उपयोग कुल कार्य के ७० प्रतिशत से अधिक के लिए मुक्तान करने हैं। अन्य १३ प्रतिशत योगदान विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है और शेष की पूर्ति सरकारी संस्थाएँ करती हैं। तकनीकी क्रांति ने विश्वविद्यालयों के अनुसंधानों को सरकारी कोष पर आश्रित बना दिया है। तकनीकी विषयों पर सांस्कृतिक एवं भाषागत रुकावटों का प्रभाव बहुत कम होता है। तकनीकी में यह समझता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवाहित हो सके। इसके लिए केवल शिक्षा और पर्याप्त सम्पत्ति की आवश्यकता है।

कुछ समय पूर्व यह विश्वास किया जाना था कि पश्चात्य देशों की जनता के प्रतिरिक्त लोग साधुनिक तकनीकों की काम में नहीं ला सकते। इसी आधार पर दो विश्व युद्धों के बीच यह मान्यता रही कि आपाप साधुनिक जगो बहाजों एवं वायुयानों का निर्माण नहीं कर सकता। किन्तु आज जगो जहाज बनाने के कार्य में आपाप दुनिया का समुदा है और इस बात में कोई

सदेह नहीं है कि वह आधुनिक तकनीकी को प्रयोग में लाने की योग्यता रखता है। यदि अर्द्ध-विकसित देशों में शिक्षा, समूह-एव पर्याप्त पूँजी हो ती-वे अपने और उन्नत पश्चिमी राज्यों के बीच स्थित तकनीकी अंतर को कम कर सकते हैं। तकनीकी प्रगति के प्रभाव स्पष्ट होते हैं। आज दुनिया के देश अधिक पराश्रित बन गए हैं क्योंकि औद्योगिक तकनीकी का विकास विदेशी बाजार और विदेशी कच्चे माल की भाग करता है। पहले यह माना जाता था कि राज्यों को कच्चा माल प्रदान करना चाहिए जबकि औद्योगिकृत पश्चिमी राज्यों को बनी हुई चीजें भेजनी चाहिये। आज औद्योगिकृत राज्यों एवं गैर-सरकारी नियमों के बीच पिछड़े हुए राज्यों में तकनीकी का विकास करने के लिए होड़ सी लगी हुई है क्योंकि इससे सुदूर भविष्य में राजनैतिक प्रभाव बढ़ेगा और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। राज्यों के बीच परस्पर अन्तर एवं राजनैतिक झगड़े रहते हुए भी व्यक्तियों एवं निगमों के बीच तकनीकी सहयोग रह सकता है। वर्तमान युग में तकनीकी एवं आर्थिक सम्बन्धों की लहर बढ़ती जा रही है इसके प्रभाव और रूप को परिभाषित नहीं किया जा सकता, किन्तु पिछली शताब्दियों में अन्तर्देशीय विवादों का अन्तराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता था उनसे इसकी तुलना की जा सकती है। राज्यों के द्वारा जान बूझ कर यह प्रयास किया जाता है कि उनका तकनीकी ज्ञान दूसरे देशों में न जाए। वे सैनिक तकनीकी को गोपनीय रखने का प्रयास करते हैं। आधुनिक तकनीकी का सम्बन्ध अणु शस्त्रों से है। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने मित्रों को इस बात के लिए प्रभावित करता है कि वे साम्यवादी देशों को लड़ाई के काम की चीजें न भेजें। दो सताब्दी पूर्व ग्रेट ब्रिटेन ने ऊनी कपड़ा बनाने की मशीन और तकनीकी के निर्यात पर रोक लगा दी। ऐसी कुछ नीतियाँ अल्पकालीन दृष्टि से उपयोगी होती हैं, किन्तु धीरे धीरे तकनीकी राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ कर फैलने लगती है। जब एक बार संज्ञानकों का यह मालुम पड़ जाता है कि काम हो चुका है तो वे बड़ी शीघ्रता ही उसे पूरा कर लेते हैं।

आज के युग में बढ़ती हुई आकांक्षामों की क्रांति है। आज सरकारें यह आशा करती हैं कि उनका राज्य आधुनिक तकनीकी प्राप्त कर लेगा। उनकी यह आशा सैनिक हथियारों से आगे बढ़ कर औद्योगिक एवं संचार तकनीकी तक फैल जाती है। अर्द्ध-विकसित देश अपनी पराश्रयता का कम करने का प्रयास करते हैं और बड़ा उद्योग के विकास पर जोर दिया जाता है।

जनसंख्या की विशेषताएँ, भूगोल के कुछ तत्व और अनेक आर्थिक तत्वों को नक्शों, मापकों और चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु तकनीकी स्थिति इस प्रकार उपस्थित नहीं की जा सकती, किंतु इसका कुछ प्रतीकों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। इसका एक प्रतीक यह है कि उस देश की जनसंख्या का जितना अनुपात कृषि में लगा हुआ है। यदि कृषि कार्य में लगे हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो यह माना जाएगा कि कृषि तकनीकी बहुत पीछे है और औद्योगिक तकनीकी ने भी अपनी पिछड़ी स्थिति होने के कारण अधिक मजदूरों की मांग नहीं की। दूसरा सूचक यह है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन कितना होता है। तीसरा सूचक यह है प्रति व्यक्ति शक्ति का व्यय या खपत कितनी है। यह कहा जाता है कि समुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति की प्रति व्यक्ति खपत पश्चिमी यूरोप और सोवियत संघ से तीन गुनी अधिक है। यह भारत से पचास गुनी अधिक है और जापान से छः गुनी अधिक है। किसी राज्य के स्तर को मापने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इन सभी सूचकों का बख़्त किया जाए क्योंकि एक राज्य अपनी प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी के किसी भी एक पहलू पर जोर दे सकता है और इस प्रकार उस क्षेत्र में प्रगति करके एक स्तर प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए साम्यवादी चीन ने हार्डड्रोजन बम का विस्फोट कर लिया। तकनीकी का अर्थ

(The Meaning of Technology)

तकनीकी शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है जिसमें लोहा, फीलाद एवं मशीनरी को तो लिया ही जाता है, किन्तु भारत में प्रत्येक संगठित ज्ञान (Organized Knowledge) चाहे वह कृषि, उसायन शास्त्र या अन्य किसी भी विषय में हो, उसे हम तकनीकी के क्षेत्र में ले सकते हैं। किन्सी राइट (Quincy Wright) के कथनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के एक अनुशासन के रूप में तकनीकी एक ऐसा विज्ञान है जो आविष्कार और भौतिक संस्कृति की प्रगति को विश्व राजनीति से सम्बन्धित करती है। यह यान्त्रिक प्रपातों के विकास की कला है जो युद्ध, कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, यात्रा और संचार में इसका प्रयोग करती है। प्रायः प्रत्येक देश की सरकार इस कला के विकास के लिए अधिक से अधिक आयोग, संस्थाएँ एवं अन्य अन्विकरण स्थापित करती है। सामान्य रूप से तकनीकी हम उस कला को कहते हैं जो प.ा.ओं, शक्तियों, प्रक्रियाओं एवं सम्बन्धों को मानवीय उद्देश्यों की सहायता के लिए मिलाती है और प्रयोग में लाती है। दूसरी ओर विज्ञान इन कला के व्यवहार के परिणामस्वरूप होने वाले आविष्कारों और तरीकों

ने मानवीय एवं सामाजिक प्रभावों को नियन्त्रित करती है और उनके बारे में भविष्यवाणी करती है। विज्ञान के अतर्गत आविष्कारों की रचना, विकास एवं प्रयोग के इतिहास के अध्ययन किया जाता है और दार्शनिक अध्ययन जो संस्कृति, सम्यता आदि के विकास के लिए तकनीकी के महत्व का मूल्यांकन करते हैं वे भी विज्ञान के अन्तर्गत आते हैं। तकनीकी शब्द सामाजिक और नैतिक आविष्कारों को अपने क्षेत्र से निकाल देता है। इन क्षेत्रों में भी अनेक नए आविष्कार होते रहते हैं किंतु तकनीकी इनसे सम्बंध नहीं रखती। ऐसे भौतिक चीजों के विकास और नैतिक मान्यताओं के बीच हम विमाजक रेखा नहीं खींच सकते हैं क्योंकि प्रायः उन्हीं चीजों का आविष्कार किया जाता है जिनको हम मूल्यवान मानते हैं और चीजें हम प्रायः मूल्यवान इसलिए मानते हैं क्योंकि वे व्यवहार में अभिव्यक्त हो चुकी हैं।

तकनीकी और राष्ट्रीय शक्ति

(Technology and National Power)

तकनीकी (Technology) मानव सम्यता एवं मनुष्य जाति के लिए एक बरदान है या अभिशाप है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है जिस पर विद्वान प्रायः कभी एकमत नहीं हो सकते क्योंकि दोनों पक्षों के तर्कों में आंशिक सत्यता वर्तमान है। किंतु यह तो मानना ही पड़गा कि तकनीकी का राष्ट्रीय शक्ति से गहरा संबंध है। जिस देश के जनजीवन में तकनीकी देनी की बहुतायत रहती है वहां का जनजीवन स्तर ऊंचा रहता है तथा जिन राष्ट्रों के सैनिक उत्कृष्ट तकनीकी शस्त्रों से सुसज्जित रहते हैं वे उन राष्ट्रों की अपेक्षा शक्तिशाली होते हैं जिन राष्ट्रों के पास वे नहीं होते। तकनीकी हथियारों को अपनाने में पहल करने वाले राष्ट्र उन राष्ट्रों की अपेक्षा लाभ में रहते हैं जो इन शस्त्रों का प्रयोग भयंकर इनसे बचाव के उपायों को काम में लाना बाद में जाकर सीखते हैं। उदाहरण के लिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन के विरुद्ध (Submarines) का प्रयोग करने में पहल करके शत्रु को नीचा दिखाया। इसी प्रकार युद्ध के अन्तिम काल में ब्रिटेन द्वारा प्रयुक्त टैंकों ने मित्र राष्ट्रों की विजय को सम्भव बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ में जर्मनी तथा जापान ने युद्ध की जिम् जाल को अपनाया उसके अनुसार उन्होंने अपनी वायु सेना को घस एवं जल सेना का सहकारी बना दिया। इस प्रक्रिया द्वारा इन देशों को सर्वोच्चता प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की अन्तिम पृष्ठ पर अणुबम की मार से जब जापान को दबा दिया गया तो अमरीका को एक सैनिक शक्ति के रूप में सर्वोच्चता प्राप्त हो गई क्योंकि अणु शक्ति पर उसका एकाधिकार था।

वर्तमान भारत-पाक संघर्ष के समय तकनीकी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह माना जाता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से प्राप्त टीका-के ऊपर बड़ा भरोसा था और इसी भरोसे के आधार पर उसने दिल्ली के साल किले पर पाकिस्तानी भंडा कहराने का शेलबिस्ली खेला दिवा-स्वप्न देखा था। किन्तु भारतीय सेना में इन टैंकों की शक्ति से परिचित थी और इनके प्रतिहार स्वरूप सारे प्रबन्ध कर लिये गये थे। फलतः पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में पीछे धिखानी पड़ी। भारतीय वायु सेना ने भी पल सेना के साथ जिस सहयोग से कार्य किया, उसने भी सन्तु-के पीर उखाड़ दिये।

तकनीकी का विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि एक देश की शक्ति को निर्धारित करने में इसका बड़ा हाथ रहता है। शक्ति एक देश को सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। एक देश के निवासियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि उस देश की सेना को तकनीकी तरीकों से सुसज्जित किया जाये।

तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम आविष्कार, विकास एवं प्रयोग के स्तरों में विभाजित कर सकते हैं। कोई भी आविष्कार एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर होता है। वह आविष्कार स्वतन्त्र रूप से उसी समय अन्य स्थानों पर हो यह जरूरी नहीं है। आविष्कार एक सन्तु प्रक्रिया का परिणाम है। इस प्रक्रिया में पूर्ण ज्ञान को ऐसी भौतिक स्थितियाँ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो समाज के द्वारा आवश्यक समझी गई हैं। इस प्रकार आविष्कार तकनीकी सम्भावना और सामाजिक आवश्यकता का योग है। उदाहरण के लिए हवाई जहाज का आविष्कार उस समय तक नहीं हो सकता था जब तक शक्ति के पर्याप्त रूप के स्रोत का और मानव शक्ति के कम्युटेशन इजिन का आविष्कार न हो जाता और रेल, मोटर आदि यातायात के साधनों की प्राप्ति इस चीज को बढ़ावा न देती कि अधिक द्रुतगति का यातायात जरूरी है। जब कभी आविष्कार सामाजिक मांग से पहले हो कर लिये जाते हैं तो वे बर्बाद हो जाते हैं। वर्तमान तकनीकी में जिन चीजों के प्रति उत्साह है वे भी आविष्कार का विरोध करते हैं। यह कहा जाता है कि चाहे सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो किन्तु आविष्कार अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आविष्कारकर्ता सब तक के बिचारे हुए लोगों को नए संयोग में मिला देता है। जब एक बार आविष्कार हो जाता है, और उसका प्रयोग आरम्भ हो जाता है तो सङ्कलित और समाज के अन्य तत्वों को उसके अनुरूप बनाने की समस्या उठ खड़ी होती है। आवि-

प्राज्ञों के सामाजिक कारण होते हैं। उसी तरह सामाजिक परिणाम भी होते हैं।

तकनीकी की प्रकृति और प्रभाव

(The Nature and Influence of Technology)

तकनीकी को संस्कृति का एक ही तत्त्व माना जाता है। एक समूह की नैतिक और भौतिक संस्कृति उसके तकनीकी प्रयोग करने तथा आविष्कार करने की क्षमता को प्रभावित करती है। दूसरी ओर तकनीकी आविष्कारों के परिचय से सम्पूर्ण संस्कृति में परिवर्तन आ जाते हैं। संस्कृति के भौतिक एवं नैतिक पहलू अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तकनीकी के द्वारा समाज की मूल्य व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है। मानव सम्पत्ता पाषाण युग, चारामाह युग, टुपि युग, ताम्बा युग, लोहा युग, आदि में भिन्न-भिन्न सामाजिक मूल्यों को अपनाती रही है। लिखने के तरीके और सामूहिक संचार के तरीकों को सामाजिक प्रगति का स्तरीकरण करने में प्रमुख माना जाता है। यानामान के चोग में बीगाडी, घोड़ा, पालकी, रेल, मोटर, हवाई जहाज आदि साधन संस्कृति को प्रभावित करते रहे हैं। इसी प्रकार मानव शक्ति के अनिश्चित शक्ति के अन्य रूपों के आविष्कार ने सम्यता की भौतिक रूप से प्रभावित किया है।

कार्ल मार्क्स का कहना था कि तकनीकी अपने व्यवस्था के रूप को ढालने में अत्यन्त प्रभावशाली है। अपने व्यवस्था के द्वारा धार्मिक, राजनैतिक, नैतिक, सोशलिस्ट आदि क्षेत्रों में समाज के जीवन को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने भौतिक प्रगति के प्रभाव का महत्वपूर्ण बताते हुए सुझाया कि व्यक्ति को जैसा मानावरण दिया जायेगा वैसा ही बन जाएगा। इतिहासकारों ने युद्ध, तकनीकी एवं नैतिकता के पारस्परिक प्रभावों का वर्णन किया है। युद्ध के द्वारा तकनीकी के विकास को प्रोत्साहन दिया जाता है। किन्तु यह मूल विज्ञान की प्रगति को रोक देता है जिससे नई तकनीकी जन्म लेती है। तकनीकी प्रगति के द्वारा प्रतिरिक्त उत्पादन करके युद्ध को प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है और यह शांति व नैतिक प्रगति के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ भी तैयार कर सकती है। एक देश की नैतिक स्थिति यह युद्ध और आविष्कार दोनों की स्थिति को प्रभावित करती है।

तकनीकी का सभी संस्कृतियों पर एक सा प्रभाव नहीं होता। कुछ संस्कृतियाँ नए आविष्कारों को अपना कर धीमे-धीमे चलती हैं। इसलिए

वे उनको प्रयत्न से कतरावेंगे। दूसरी ओर आधुनिक मन्त्रतान्त्रिक आन्दोलन से नई तकनीकी की प्रेरणा मिलेगी है। यद्यपि सत्कृति के सभी पहलुओं पर हमका प्रभाव प्रायः जगत् भर में गहरा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि तकनीकी हल-पुल्ल प्रदात नहीं है जिनसे कि सभी सत्कृति का आना-निबट हो सके और जो वहीं भी जन्म ले सके तथा आन्दोलन से और तुरन्त बढ़ाई जा सके। इसके विपरीत तकनीकी मन्त्रतान्त्रिक रूप से सम्बन्ध रखती है और इसका जन्म प्रसार एवं प्रभाव उस सत्कृति के सम्बन्ध में ही सम्पन्न होता है जहाँ जन्मी है और जहाँ इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह सच है कि एक आविष्कार को सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है और उनको मिटाने के लिए भी, किन्तु फिर भी कुछ आविष्कार सत्कृति से ही सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहित देने वाले होते हैं और अन्य आविष्कार उन मूल्यों को मिटाने के काम करते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि अणु शक्ति एवं अणु प्रयुक्तों का आविष्कार एक नैतिक अर्थ है। उनको यह दूर है कि यदि ऐसे हथियार रहे तो इनका प्रयोग भी किया जाएगा और इस प्रयोग के द्वारा सम्पूर्ण मानव सभ्यता समाप्त हो सकती है। जब हम तकनीकी और नैतिकता के पारस्परिक सम्बन्धों को मान कर चलते हैं तो हम स्पष्ट रूप से तकनीकी की नैतिक निष्पक्षता को अस्वीकार करते हैं। यह सच है कि तकनीकी नैतिक रूप से तटस्थ नहीं होती। एक अनुशासन के रूप में तकनीकी नैतिक मापदण्डों और मूल्यों पर अपने प्रभाव को नहीं डाल सकती। उसे सम्पत्ति पर अपने तात्कालिक एवं अन्तिम परिणामों का ध्यान रखना चाहिए।

तकनीकी के सम्बन्ध में एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि इसका प्रयोग इसके उद्देश्य से बाहर भी किया जा सकता है। आज के युग में मनार के साधनों का इतना विकास हो चुका है कि पर्याप्त गोपनीयता रखते हुए भी तकनीकी आविष्कार एक देश से गीघ्र ही दूसरे देशों में फैल जाते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका ने अणुबम बनाया और पर्याप्त प्रयास किया कि वह उसे गुप्त रखे, किन्तु सोवियत संघ गीघ्र ही इस तकनीक को अपना लेने में सफल हो गया। वर्तमान समय इस तथ्य को ध्यान में रख कर अविद्या देश यह चाहते हैं कि मनार ने स्थित तकनीकी अन्तर को बम दिया जाए। समुक्त राज्य अमेरिका और समुक्त राष्ट्रमंडल तकनीकी सहायता कार्यक्रमों द्वारा राज्यों के बीच स्थित तकनीकी अन्तरों को समाप्त करने में गीघ्र दूर चलना चाहते हैं।

विज्ञान और तकनीकी का इतिहास एक रचना और निरन्तरता के साथ आगे बढ़ता रहा है। एक बार जो आविष्कार कर दिए जाते हैं उनको बाद में

भुलाया नहीं जाता। वे मनुष्य जीवन के अग वन जाते हैं। यह सम्झना बड़ा मुश्किल है कि मनुष्य अणुबम या हवाई जहाज से कैसे छुटकारा पा सकता है। अनेक लोग वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासों की आलोचना करते हैं, किंतु फिर भी इनका प्रयोग करने से अपने को तथा अपनी सन्तान को रोक नहीं सकते। यदि हम तकनीकी दृष्टिकोण से मानव इतिहास को लियें तो यह इतिहास उतार-चढ़ाव का इतिहास नहीं होगा बल्कि यह निरन्तर प्रगति का इतिहास है। राजनैतिक, आर्थिक, भौतिक और कलात्मक इतिहास के उतार-चढ़ाव कभी कभी तकनीकी के इतिहास की गति को रोक देते हैं किंतु वे उसे पीछे नहीं ढकेल सकते। ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति ने जो आविष्कार किए हैं वह उनको भूल जाए। आधुनिक युद्ध की विध्वंसकारी एवं सार्वभौमिक प्रकृति के कारण यह सम्भावना होने लगी है कि युद्ध अब तक की तकनीकी प्रगति को नष्ट करके मनुष्य को सम्पत्ता के प्रथम सोपान पर लौटा देगा। यह निराशपूर्ण दृष्टिकोण अणुबम के तकनीकी आलोचकों द्वारा प्रकट किया गया।

तकनीकी और वैज्ञानिक विकास का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मन-मुटाव बढ़ते जायेंगे और वे इतने उच्च स्तर पर पहुँच जाएंगे कि वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय नियमन जरूरी तथा व्यावहारिक बन जायगा। वैसे बढ़ते हुए मन-मुटाव एवं बढ़ते हुए नियन्त्रण की प्रगति की सामान्य विशेषता सम्झा जाता है। मनुष्य जानि रीति-रिवाजों से पूर्ण प्रारम्भिक समाजों से निकल कर मत्तों से निर्देशित सम्य समाजों में इसी विशेषता के कारण आ पाई। उच्च लिचाव को प्रायः ऐसी स्थिति सम्झा जाता है जिसे कि मिटाया जा सके, किन्तु जब यह लिचाव प्रतिशय की स्थिति में पहुँच जाता है तो वह युद्धों को जन्म देता है और यह युद्ध आज की स्थिति में सम्पत्ता को नष्ट कर देंगे। दूसरी ओर अत्यन्त कम लिचाव व्यक्ति में आसत्य और निष्क्रियता ला देता है जो सम्पत्ता के विकास का एक रोज़ा है। उदाहरण के लिए एक बाइलर के उच्च दबाव को यदि नियन्त्रित एवं निर्देशित कर दिया जाये तो यह मनुष्य के लिए मन्थवान साबित हो सकता है। उसी प्रकार यदि उच्च लिचाव (High tension) को सामाजिक रूप से नियन्त्रित एवं निर्देशित कर दिया जाये तो यह प्रगति का जनक बन सकता है। इस प्रकार उच्च लिचाव युद्ध एवं प्रगति दोनों का कारण बन सकता है। परिणाम दो में से क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि नियन्त्रण

की दिशाएँ एवं प्रभाव क्या है। सामाजिक नियंत्रण एवं निर्देशन संस्थाओं, कानूनों एवं संगठनों के माध्यम से किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विचार्य राष्ट्रों के बीच की सीमाओं पर जन्म होता है तथा दोनों पक्षों की बढ़ती हुई शक्ति के अनुपात में बढ़ता जाता है। प्रि. ओगबर्न (Ogburn) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विचार्य राजनैतिक एवं प्रशासनिक सीमाओं की कठोरता से विकसित होता है तथा परिवर्तित परिस्थितियों के प्रति समायोजन न हो सकने के कारण यह बट जाता है। परिवर्तित परिस्थिति का प्रत्यक्ष दबाव से है जो प्रत्येक राज्य द्वारा सामान्य सीमाओं पर डाला जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय विचार्य से राहत पाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण की स्थापना करना जरूरी है ताकि सभी राष्ट्रों की शक्ति को सामान्य तथ्य के लिए प्रयुक्त किया जा सके। सघर्षपूर्ण साम्राज्यवादी दावों के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की जाये तथा राजनैतिक सीमाओं के पार भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन दिया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय तथ्यों पर पढ़ने वाले तकनीकी के प्रभाव को जानने के लिए यह जरूरी है कि राज्य, राज्य व्यवस्था, विश्व की प्रत्यक्ष व्यवस्था एवं विश्व राजनीति पर तकनीकी विकास के परिणाम को जाना जाये।

विश्व राजनीति और तकनीकी प्रगति

(World Affairs and the Progress of Technology)

तकनीकी विकास विश्व राजनीति को चार प्रकार से प्रभावित करता है। यह राज्य के रूप को बदल देता है, राज्य व्यवस्था में परिवर्तन लाता है, विश्व की प्रत्यक्ष व्यवस्था को परिवर्तित करता है तथा विश्व सरकार की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को प्रभावित करता है।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों का कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि तकनीकी विकास एक राज्य के क्षेत्र एवं जनसंख्या को प्रभावित करता है। जिन समय संचार साधन पर्याप्त नहीं थे तथा आवागमन के साधनों का भी विकास नहीं हो पाया था उस समय शक्ति कुछ ही वर्ग भौल के प्रदेश में भौतिक रूप से रहते थे। इनकी संख्या भी अधिक नहीं होती थी। आवागमन के साधनों के विकास ने लोगों का अधिक से अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण करने की ओर प्रेरित किया। तकनीक आधिपत्यों को राज्य के बड़े मानदार एवं जनसंख्या में मिलाप का प्रयास किया गया। आवागमन व संचार के साधनों के विकास ने साम्राज्यों का आकार बढ़ा दिया।

तकनीकी विकास ने राज्यों के केन्द्रीयकरण एवं ठोसपन को बढ़ा दिया है। द्रुतगामी संचार के माध्यम से कूटनीतिज्ञ अपने विदेश कार्यालय से सीधा सम्पर्क बनाए रख सकते हैं और इस प्रकार विदेश नीति निर्माण का कार्य सरकार में केन्द्रित हो सकता है। दुनिया के प्रत्येक भाग में सरकार की नीति को दूसरे भागों से सम्बन्धित किया जा सकता है। एक उपयुक्त नीति को अपनाने के लिए भाज विश्व भर के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को मिला कर देखा जा सकता है तथा अपनाई गई नीति को साकार करने के लिए सैनिक, आर्थिक, प्रचार एवं कूटनीतिक साधनों का सहारा लिया जा सकता है। संचार के साधनों के क्षेत्र में तकनीकी प्रसार ने तथा सैनिक प्रसाधनों के जन्म ने घरेलू शक्ति की सम्भावनाओं को कम कर दिया है। साथ ही घरेलू प्रचार की प्रभावशीलता को बढ़ा दिया है तथा जनता अपनी सरकार पर अधिक से अधिक आश्रित होती जा रही है। इस प्रकार विदेश नीति एवं घरेलू नीति के व्यवहार में अधिक राष्ट्रीय एकता एवं ठोसपन सम्भव हो पाता है। तकनीकी विकास ने शक्ति के नये स्रोतों का आविष्कार किया है, उत्पादन के नये साधन दिये हैं तथा जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को प्रभावशील बनाया है, इन सबके कारण सामाजिक शक्ति में वृद्धि हुई है तथा रहन-सहन का स्तर ऊँचा हुआ है।

अधिक आकार वाले, शक्ति वाले एवं केन्द्रीयकरण वाले राज्य अधिक आशावादी होते हैं, अधिक विश्वासपूर्ण होते हैं तथा अधिक सम्प्रभु होते हैं। ऐसे राज्य अपने आपकी अधिक शक्तिशाली एवं आत्मनिर्भर अनुभव करते हैं और इस प्रकार वे आक्रमणकारी बन जाते हैं। तकनीकी उन्नति राज्यों का शक्तिशाली एवं सतर्क बना देती है।

(ii) तकनीकी विकास राज्यों की शक्ति स्थिति में परिवर्तन ला देता है। जब वायुयानों का विकास हो गया तो श्रेष्ठ छिपेन की शक्ति पर इसका भारी प्रभाव पड़ा क्योंकि यह समुद्री संचार व्यवस्था पर आश्रित या तथा एक शक्तिशाली नौसेना का स्वामी होने के कारण उसे किसी के आक्रमण का भय नहीं था किन्तु वायुयानों के विकास ने उसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी की शक्ति न रहन दिया। यदि विश्व इतिहास का ऊपरी तौर पर अध्ययन किया जाये तो ज्ञान होगा कि प्रारम्भ में शक्ति उन देशों के हाथों में थी जो घोड़ों की पर्याप्त संख्या रखते थे एवं शृंगि कार्य में सक्षम थे। मध्य युग में शक्ति का केन्द्र उत्तरी योरोप, पश्चिमी एशिया, भारत एवं चीन के कृषि क्षेत्र बन गये। पुनर्जागृति के बाद शक्ति उन देशों

के हाथ में आ गई जो विशाल लड़ाई देने के स्वामी थे । बाद में बन्दूक के पाठशाला एवं छात्रावास के आदिष्कारण तरंगारो की शक्ति को सामन्ती की शक्ति से अधिक बढ़ा दिया । लोहा और कोयले पर प्रेट ब्रिटेन का नियन्त्रण होने के कारण वह आधिपत्य शक्ति की पकड़ करने लगा और अपने योरोप में शक्ति प्रचुरता स्थापित किया गया । १९वीं शताब्दी में गैर योरोपीय देशों पर प्रभुत्व रखा । वायुयान के विकास के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संपुक्त राज्य अमेरीका और सोवियत संघ प्रभावशाली शक्ति बन गये ।

तकनीकी आविष्कारों ने राज्यों की शक्ति स्थिति में जो परिवर्तन किया उनके प्रतिरिक्त हमने छोटे व बड़े राज्यों के बीच स्थित शक्ति के अंतरों को भी अधिक बढ़ा दिया और इस प्रकार नयी राज्यों की सुरक्षा की शक्ति को घटा दिया । केवल वे राज्य ही आधुनिक युद्ध के उपकरण तैयार कर पाते हैं जिनकी जनसंख्या अधिक है तथा उद्योग धंधे उच्च स्तर पर हैं । एक राज्य का क्षेत्र जितना छोटा होता है वह अपनी जनसंख्या एवं साधनों का केन्द्रीकरण करना भी कम कर पाता है और इस प्रकार वह वायु साधनों का शिकार बड़ी जल्दी ही बन सकता है ।

तकनीकी विकास सामान्य रूप से एक देश की सुरक्षात्मक स्थिति को अपेक्षा प्राप्तकारों शक्ति को घटा देता है । इस प्रकार नयी राज्यों की आत्मरक्षण करने की शक्ति तथा नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता बढ जाती है । संविदा क्षेत्र में नियंत्रण आविष्कारों ने हथियारों को गणितीय बना दिया है और इस प्रकार आत्मरक्षणारी का काम पहुँचाया है । धर्मों की विनाशकारी शक्ति बड़ी तीव्र गति में बढ गई है । तलवार और धनुष-बाण के युद्ध में एक व्यक्ति एक ही व्यक्ति को मार पाता था । राष्ट्रों के आविष्कार के बाद शत्रु को विघेता की अपेक्षा प्रतिरक्षा ही होने लगी । अणु बम का प्रयोग होने पर तो सहार का क्षेत्र और भी अधिक व्यापक हो गया । युद्ध के अजिगी-परण में लोगों के सहार की सम्भावनाओं का बहुत दबा दिया है ।

आय को टैंक, जेट विमान, हाइड्रोजन बम आदि देखने में आते हैं उनका ज्वाहरण युद्ध के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता । आज आत्मरक्षा यह नहीं देखना कि शत्रु को जितनेभी कम है अथवा उनके सुरक्षात्मक हथियार कितने प्रभावशील हैं बल्कि यह देखना है कि शत्रु के विरोध की क्षमता कितनी है अर्थात् वह विघात के उत्तर में कितना प्रतिक्रिया करने की क्षमता रखता है । कुछ आत्मरक्षा तकनीकी विशेषज्ञ इस बात पर जोर

देते हैं कि हवाई अणु आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के लिए राडार सचेतक व्यवस्था एवं राज्य के चारों ओर रक्षायानों की व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु दूसरी ओर राजनीतिज्ञों का यह विचार है कि इस व्यवस्था में खर्च अधिक होता है और सीमाओं की तम्बाई और जेट विमानों की गति व ऊँचाई को देखते हुए यह व्यवस्था अधिक प्रभावशाली नहीं दिखती।

तकनीकी विकास ने युद्ध के रूप एवं राज्यों के शक्ति स्तर को जिस हासत में ला दिया है वही शक्ति सतुलन में स्वायत्त नहीं बचा है। इस प्रकार यहाँ एक विरोधाभास सा नजर आता है कि एक ओर तो राज्य अपने आपको अधिक शक्तिशाली, स्वतन्त्र एवं सम्प्रभु अनुभव करते हैं। दूसरी ओर शक्ति का सतुलन बड़ी शीघ्रता से बदलता जाता है। सभी राज्य आक्रमण करने में मक्षम हो गये हैं। युद्ध के परिणाम सम्पत्ता के लिये भयानक हो गये हैं तथा अन्तिम परिणाम तो और भी अधिक समस्याजनक है। राज्य यद्यपि अपने आपको सम्प्रभु मानते हैं किन्तु वे असल में बहुत कम सम्प्रभुता सम्पन्न हैं।

(iii) जन साधारण की दृष्टि से तकनीकी विकास जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की आशाओं को बड़ा देता है। कृषि एवं उद्योगों में होने वाले आविष्कार प्रकृति पर व्यक्ति के नियंत्रण को बड़ा देते हैं तथा जन्म नियन्त्रण, दवाई एवं सफाई के क्षेत्र में होने वाले आविष्कार उसे जनसंख्या के नियंत्रण की क्षमता देते हैं। इस प्रकार जनसंख्या एवं भोजन के अनुपात को विनियमित किया जा सकता है तथा सभी लोग अधिक सम्पन्न हो सकते हैं। जो देश इन आविष्कारों का प्रयोग करता है उसकी शक्ति एवं आशाएँ बढ़ जाती हैं। किन्तु ये सभी लाभ स्थायी शक्ति सतुलन के प्रभाव में रहने वाली अमरुद्धा द्वारा महत्वहीन बना दिये जाते हैं क्योंकि सैनिक तैयारी में भारी व्यय करना होता है। तकनीकी विकास न विश्वव्यापी आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग की भावनाएँ बढ़ा देता है।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तीव्र शक्ति में बदलती हुई शक्ति स्थिति से उत्पन्न राजनैतिक अमरुद्धा की भावना, आक्रमण करने की सामान्य शक्ति तथा युद्ध में आक्रमणकारी होने के लाभ आदि बातों ने मिल कर शक्ति को विश्व की मुख्य आवश्यकता बना दिया है। इसके अतिरिक्त तकनीकी विभाग के माध्यम से विश्वव्यापी आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग की भावना भी परिपक्व होती है तथा शक्ति की स्थापना के लिए एक मार्बनोमिज संगठन की जरूरत को महसूस किया जाता है। इन दिशाओं में चिये जाने वाले आन्दोलनों को राष्ट्रीय राज्यों के अपनी सम्प्रभुता में आत्मविश्वास एवं उनकी

जनता की राष्ट्रीय भावनाओं द्वारा मजबूत बना दिया जाता है। ग्राम विकास ने प्रत्येक राज्य के सामने वास्तविक चुनौतियाँ रख दी हैं। यह चाहे तो अपनी शक्ति स्थिति को संरक्षित बनाने के लिए प्रयास करे ताकि आक्रमण को रोक सकें और यदि युद्ध छिड़ जाये तो वह जीत सके। इस मार्ग को अपनाते के कारण संचार बढ़ेगा और शक्ति की तुल्यमूल्यता और भी अधिक अस्थायी बन जायेगी। राज्य के सामने एक अन्य विकल्प यह है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अपना विषयम जाहिर करे तथा सामूहिक सुरक्षा के विकास का प्रयास करे। इस मार्ग को अपनाने में आशंका यह है कि दूसरे राज्य सहयोग करने से मना करके सामूहिक सुरक्षा के विकास में रोक लगा देंगे। तकनीकी विकास ने यह जरूरी बना दिया है कि या तो दुनिया एक हो जाये अथवा वह नहीं रहेगी। जब तक दुनिया के सभी देश अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को सकल बनाने के लिए दिल से प्रयास नहीं करते तब तक 'एक विश्व' भी बहुत कम सुरक्षा प्रदान करेगा, किन्तु कुछ विद्वानों के मतानुसार यह कम सुरक्षा भी वर्तमान स्थिति से तो अच्छी ही होगी; क्योंकि अब प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा का प्रयास स्वयं ही करता है किन्तु असल में कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है।

इस प्रकार तकनीकी का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। पेडिनफोर्ड तथा रिक्कन ने एक राष्ट्र के जेप विश्व के साथ सम्बन्धों पर पड़ने वाले मुख्य तकनीकी प्रभावों के वर्णन को पाँच श्रेणियों में विभाजित किया है। ये निम्न प्रकार हैं—

प्रथम, तकनीकी के कारण एक देश अपनी मान्यताओं एवं लक्ष्यों को बदल लेता है। वैसे तकनीकी प्रगति के महत्त्व की तत्काल ही नहीं समझा जाता। समुक्त राज्य अमेरिका ने जिस समय अपनी पारंपरिकवादी नीति को छोड़ा उस समय नई तकनीकी के कारण देश की आक्रमण की क्षमता पर्याप्त बढ़ चुकी थी। तकनीकी ने सम्पूर्ण युद्ध को नष्ट कर बना दिया है इसलिए आज युद्ध को रोकना एवं प्रमुख लक्ष्य बन गया है। आज तकनीकी ने दुनिया को एक बना दिया है। यह 'एक विश्व' उन आदर्शवादी स्वप्न द्रष्टाओं की कल्पना से भिन्न है जो विश्व शांति के लिए विश्व सरकार की स्थापना करना चाहते थे। आज की दुनिया इस अर्थ में एक है कि सभ्यता के साधन विकसित हो चुके हैं, देशों की पराधीनता बढ़ चुकी है और इसलिए सभ्यता के किसी भी भाग में होन वाला छोटा-मोटा संघर्ष भी सभ्यता के सभी देशों की शक्ति का विषय बन जाता है। इस स्थिति में विश्व के राज्य अपना हित व्यापक बना लेते हैं और कभी कभी तो यह व्यापकता सम्पूर्ण धरती पर फैल जाती है।

तकनीकी के प्रभाव में ज्ञान यह बन गई है कि कोई भी देश अपनी इच्छाओं को केवल शक्ति के माध्यम से अधिपत्य नहीं कर सकता और न ही वह यह सोच सकता है कि पर्याप्त दूरी पर की समस्याओं का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरे, तकनीकी द्वारा अन्य विषयगत तत्वों जैसे आर्थिक तत्व, भौगोलिक तत्व एवं जनसंख्या आदि को भी प्रभावित किया जाता है। उदाहरण के लिए तेल का उत्पादन करने वाले देशों को परम्परागत रूप से रणनीतिक की दृष्टि से महत्व का समझा जाता था किन्तु अणु शक्ति का प्रसार हो जाने के बाद इन देशों को दी जाने वाली प्राथमिकता घट सकती है। दूरी का भौगोलिक तत्व अपने परम्परागत अर्थ का बहुत कुछ भाग खो चुका है। आज मंचर, समाचार एवं फोटो आदि की बड़ी भोद्यता के साथ प्रसारित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में दुनिया के किसी कोने में पहुँच सकता है। जिन समुद्रों के द्वारा पहले दो देशों के बीच स्थापना के मार्ग में एक बाधा का काम किया जाता था वे ही समुद्र आज हम सम्पर्क को बढ़ाने व घटाने की अतिरिक्त कड़ा करने के प्रतीक बन गये हैं। आज 'टाइमो' चीन की अपेक्षा समुक्त राज्य अमेरिका के अधिक नजदीक है।

यदि हम जनसंख्या एवं तकनीकी के मध्य स्थित सम्बन्धों पर विचार करें तो ज्ञान होगा कि जनसंख्या का अर्थ एवं महत्त्व ही उस समय होता है जबकि वह तकनीकी पर अधिकार रखती है। इस परिवर्तन की प्रति व्यक्ति के ज्ञान से राष्ट्रीय उत्पादन का देश बन मापा जा सकता है। केवल मात्र जनसंख्या अपनी सीमाओं में बाहर बाई प्रभाव नहीं रखती। इसीलिए जिन देशों को महानक्ति बनना होता है वे तकनीकी की दौड़ में आगे चलते हैं।

तीसरे, तकनीकी विज्ञान नीति की विषयवस्तु को प्रभावित करती है तथा इसके द्वारा सम्पूर्ण कार्यक्रमों पर भी प्रभाव डालती है। तकनीकी विषयों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध किया जाता है, तकनीकी महायुद्ध कार्यक्रम चलते रहते हैं। शस्त्रों के नियंत्रण पर अधिक जोर दिया जाता है, तकनीकी ज्ञान का प्रसार करना होता है, बाह्य अन्तरिक्ष एवं मंचर स्थलों को नियमित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास किया जाता है, तकनीकी आदान-प्रदान के द्वारा विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, इन प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले वे विभिन्न कार्य तकनीकी में अग्रसर या अग्रगण्य रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं।

चौथे तकनीकी राष्ट्रीय निर्माण में एक प्रमुख भाग है। यह ओझामीटा बना का वह गमक्य देता है जिससे आधार पर कि वे सम्पत्ति

की रचना कर सकें तथा उसका निर्माण कर सकें। यह अव्यवस्थित देशों की पूंजी सौजन्य की सामर्थ्य प्रदान करता है। विश्व के देश राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार मानवीय एवं साम के उद्देश्यों को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय तकनीकी नियमों सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तरों पर विकसित होने लगती हैं। जो देश विकास की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं वे राजनैतिक एवं सामाजिक प्रगति के अतिरिक्त तकनीकी के क्षेत्र में बेतहामा दौड़ रहे हैं।

पाचवें, तकनीकी का विदेश नीति के संचालन के तरीकों पर आन्तरिकी रूप से प्रभाव पड़ा है। पहले जो कूटनीतिक तरीके काम में लाये जाते थे वे आज असाधारण बन गये हैं। रेडियो तथा टेलीविजन पर किया गया प्रचार, तकनीकी सहायता एवं वैज्ञानिक आदान-प्रदान, अन्तरिक्ष एवं अन्य प्रकार के कार्यक्रम आदि तरीकों ने विदेश नीति के आचरण का रूप ले लिया है। गचार साधनों की गति में जो वृद्धि हुई है वह सचमुच एक आन्तरिकी परिवर्तन है।

यद्यपि तकनीकी का पर्याप्त नीतिगत प्रभाव होता है और वह एक प्रकार से स्पष्ट भी है किन्तु फिर भी विश्व राजनीति की घटनाओं के विप्लव के पीछे कोई स्वीकृत बौद्धिक श्रद्धित्व नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि तकनीकी एक मापन योग्य है तथा साध्य नहीं होती। इसका स्वयं का कोई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ नहीं होता किन्तु इसका मूल्यवान तो अर्थशास्त्र, सुरक्षा एवं अन्य तत्वों के सर्वन में करना होता है। योंसे यह मूल्यवान अंतिम रूप में एक राजनैतिक निर्णय होता है। यह हो सकता है कि राजनीतिज्ञ अपने निर्णयों को लेने की दृष्टि से तकनीकी की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लें किन्तु किसी व्यक्ति के एक अच्छी तकनीकी विशेषज्ञ होने का यह अर्थ नहीं होता कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी होगा।

प्रायोगिक विज्ञान का ज्ञान आज राज्यों का एक वास्तवीय साधन बन गया है। मार्गन योजना, संयुक्त राज्य सहायता कार्यक्रम, समुक्त राष्ट्र तकनीकी परामर्श कार्यक्रम, विदेशों में मोविपत तकनीकी विशेषज्ञ, अर्थ विकसित देशों के विद्यार्थियों को शिक्षा आदि सभी कार्यक्रम ऐसे काले हैं जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की भावना करना होता है। बुद्ध तकनीकी ज्ञान तुलनात्मक रूप से सरल एवं कम खर्चीला होता है, किन्तु अनेक तकनीकी ज्ञान अत्यन्त पटिल होते हैं तथा उनको केवल बड़ी औद्योगीक शक्तियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। अनी-अनी तकनीकी में ज्ञान लेने के लिए तथा पूंजीगत व्यय के

लिए दीर्घकालीन कार्यक्रम की आवश्यकता होती है किन्तु घरेलू राजनीति के प्रभाव के कारण देश केवल अल्पकालीन कार्यक्रम ही अपना पाता है।

यदि हम मनुष्य शक्ति एवं साधन स्रोतों की दृष्टि से विचार करें तो पायेंगे कि आधुनिक तकनीकी पर्याप्त जटिल तथा खर्चीली है। जो देश इस खर्च को वहन करने के लिए तैयार रहता है कवल वही तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तकनीकी आविष्कारों के उपयोग में लाने समय उनको वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी कुशलता, व्यापक शोध कार्य, सुरक्षित पूंजीगत कोष आदि से मिलाना होता है। ये सारी बातें बड़े तथा विकसित देशों में स्थित बड़े निगमों द्वारा ही उपलब्ध की जा सकती हैं।

आजकल अनेक प्रकार की तकनीकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। इनका अलग अलग विस्तार व साथ अध्ययन करने की अपेक्षा यहां केवल यही कहना पर्याप्त रहेगा कि तकनीकी एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा इसका महत्व धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है।

तकनीकी के मुख्य प्रकार व उनका महत्व (Main Types of Technology and Their importance)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले तकनीकी के रूपों में उल्लेखनीय हैं, संचार, औद्योगिक तकनीकी एवं मैनिक तकनीकी। इनके अतिरिक्त भी तकनीकी के अन्य रूप विश्व राजनीति पर अपना असर रखते हैं। स्वास्थ्य विज्ञानों का जनसंख्या के विस्तार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार यह जनसंख्या नियंत्रण एवं भोजन की समस्याओं को अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज की मुख्य समस्याएं बना देती है। तकनीकी के जिन दो प्रकारों को मनुष्य की विश्व घटनाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है वे हैं—कृषि एवं जनसंख्या नियंत्रण। वर्तमान काल में सामाजिक एवं व्यावहारिक विज्ञानों को भी चाहिए कि वे बदलते हुए समय की आवश्यकताओं को देख कर उनके अनुरूप बनने का प्रयास करें।

(1) संचार के साधन (The Means of Communication)—आज के युग में वायु मार्ग के वातावात एवं विद्युत मार्गों संचार व प्रसारण आदि के क्षेत्र में भारी प्रगति हो गयी है। संचार साधनों के द्वारा शक्ति, कूटनीति एवं प्रचार के सामयिक प्रयोग पर विशेष प्रभाव डाला जाता है। वातावात के क्षेत्र में होने वाले नये विकासों ने नीति निर्माताओं को आश्चर्य में डाल दिया है। एक स्थान पर घटने वाली घटनाओं की सूचना शीघ्र ही

राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व ; जनसाख्या और तकनीकी

दूरस्थ देश तक पहुँच जाती है और उस देश को अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवह में उस सूचना के आधार पर कुछ निर्णय लेने होते हैं।

संचार एवं यातायात के साधनों के विकास के कारण हा सयुक्त राज्य अमरीका जैसे देश के लिए यह सम्भव हो जाता है कि वह पर्याप्त दूरी पर स्थित देशों की समस्याओं में सक्रिय रूप से उभास सके, जैसे—कोरिया, उत्तरी अफ्रीका, दियतनाम आदि। संचार साधनों एवं यातायात के साधनों के द्रुतगामी हो जाने के कारण एक देश तक शीघ्र ही सेना भेजी जा सकती है, शीघ्र ही आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं, शीघ्र ही यातायात-निर्यात की व्यवस्था परिवर्तित की जा सकती है और इस प्रकार किसी स्थानीय संघर्ष में हार-जीत का फैसला कुछ ही दिनों में किया जा सकता है। वायु यातायात के माध्यम से भी विश्व भर में सामान एवं श्रम का अद्वितीय आदान-प्रदान होना है।

इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं वायु यातायात के विकास के परिणाम-स्वरूप राजदूतों की कार्य करने की कूटनीतिक स्वतन्त्रता बढ गई है तथा उनको कुछ नये उत्तरदायित्व भी सौंप दिये गये हैं। पहले कूटनीतिज्ञों की व्यक्तिगत बातचीत पर जनता का जितना ध्यान जाता था उतना ही ध्यान अब प्रेस साक्षात्कार एवं रेडियो तथा टेलीविजन पर कही गई बातों पर जाता है। आज एक कुशल कूटनीतिज्ञ को तकनीकी का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए। अनेक कूटनीतिज्ञ मिशनो में तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं क्योंकि आज भी कूटनीति शस्त्र-निपट्टन एवं आर्थिक विकास जैसे तकनीकी विषयों से सम्बन्ध रखती है।

आजकल यह आम बान हो गई है कि एक राज्य के नेता दूसरे राज्य के नेता की अनुमति के बिना ही रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से वहाँ की जनता से प्रत्यक्ष रूप से अपील करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के लिए सयुक्त राज्य अमरीका का राज्य सचिव उत्तरी अटलांटिक में किसी के भी द्वारा टेलीविजन पर देखा जा सकता है कि वह लन्दन में रिपोर्टर्स के सम्मुख विषयनाम से सम्बन्धित प्रश्नों का जवाब दे रहा है। यद्यपि विश्व के अनेक भागों के अधिकांश लोग अनिश्चित होते हैं किन्तु वे भी ट्राजिस्टर रेडियो के माध्यम से खबर सुनते हैं। आजकल अन्तर-महाद्वीपीय टेलीविजन का भी प्रचार होता जा रहा है। भारत के प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू की श्रव यात्रा की तीसरी में सयुक्त राज्य अमरीका में देखा। तकनीकी के विकास के कारण राज्यों की सीमापारता नुमायन हो गई है। तीव्र गति से बाम करने वाले साधनों के कारण यह सम्भव हो गया है कि बहुत सारी पुस्तकें,

परि-पत्र, समाचार आदि प्रचार के लिए और सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिए वितरित किए जा सकें।

(ii) औद्योगिक तकनीकी (The Industrial Technology) — तकनीकी के विकास ने औद्योगिक शक्ति को विश्व-यापी बना दिया है। इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रश्न किए जा सकते हैं कि तकनीकी को अर्धविकसित देशों में किस प्रकार भेजा जाए और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर इसका क्या प्रभाव होगा? अतीतकाल में तकनीकी को अर्धविकसित भागों में व्यक्तिगत उद्यम एवं पहल द्वारा प्रसारित किया जाता था। यद्यपि औद्योगिक शक्ति धीरे-धीरे फैली किन्तु इसमें उत्पादन और रहन-सहन के स्तर को बढ़ावा। यह कहा जाता है कि दुनिया के कम विकसित क्षेत्रों को जितने कि हाथ ही में उपनिवेशवाद से छुटकारा पा कर स्वतन्त्रता प्राप्त की है, स्वयं की सहायता से ही विकास करना चाहिए, किन्तु यह सुझाव दो कारणों से उपयोगी नहीं रहता। प्रथम यह कि आज की तकनीकी अधिक जटिल बन गई है और प्रगति के लिए सामाजिक तथा आर्थिक दबाव पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बन गए हैं।

औद्योगिकरण तकनीकी और तगई जाने वाली पूँजी के सहयोगपूर्ण स्रोतों का परिणाम है। यद्यपि पूँजी सगाना और तकनीकी दोनों ही नीति को निर्धारित करने वाले साधन हैं, किन्तु मविष्य के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इनका प्रभाव अभी तक अनिश्चित है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तकनीकी का महत्व शक्ति की दृष्टि से पर्याप्त है। शक्ति को आर्थिक और सामाजिक प्रगति में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। यह उत्पादन को सामर्थ्य प्रदान करता है तथा समाज के छोटे व बड़े काम में सहायता देता है। यह शक्ति, कोयला, प्राकृतिक गैस, पानी और तेल से प्राप्त की जाती है। अब धीरे-धीरे अणुशक्ति भी शक्ति के स्रोत के रूप में प्रभावशाली बनती जा रही है, किन्तु जब तक इमरता और अधिक विकास होगा तब तक पेट्रोल एवं उसके उत्पादन के क्षेत्र ही अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्वपूर्ण बने रहेंगे।

तकनीकी शक्ति को उत्पन्न करने वाला प्रमुख तत्व होता है और जब शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो वह अधिक तकनीकी मांग करती है ताकि उसे उत्पादन के उद्देश्यों में प्रयुक्त किया जा सके। दुनिया के अविश्वसनीय भागों में आर्थिक नवीनीकरण की समस्या मुख्य रूप से शक्ति उत्पन्न करने और प्रयुक्त करने की समस्या है। एक राज्य की शक्ति भी बहुत कुछ इस तक उसकी शक्ति बनाने और प्रयुक्त करने की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। जब औद्योगिक तकनीकी बढ़ जाती है तो ऐसे देशों की सध्या भी बढ़ जाती

है जो बच्चे माल का आयात करता चाहते हैं। इन प्रकार बच्चे माल की कुछ मात्रा बच जाती है। दूसरी ओर विज्ञान और तकनीकी बच्चे माल का विस्तार लोग रहे हैं। तकनीकी के प्रसार का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसे कम बतन वाले क्षेत्र में तुरन्त अपनाया जा सकता है। कुछ मिला कर भौद्योगिक तकनीकी अन्तराष्ट्रीय घटनाओं में महत्वपूर्ण गत्यात्मक तत्त्व है।

(iii) सैनिक तकनीकी (Military Technology)—वर्तमान तकनीकी का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके द्वारा एक देश की सैनिक शक्ति पर व्यापक प्रभाव डाला जा सकता है। बीसवीं शताब्दी तक सैनिक तकनीकी में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। पहले सामान्य रूप का मुख्य सामान घोड़ा का था जिनमें तीन हजार वर्ष तक यह कार्य करता रहा। उस समय आक्रमणकारी एक रक्षात्मक स्थिति में और तरीकों के बीच संतुलन बना रहा। सैनिक शक्ति उस समय सीमित और स्थानीय थी। मुख्य नगर से घटनास्थल की भौगोलिक दूरी जितनी बड़ जाती थी उतनी ही इस सैनिक शक्ति का प्रभाव कम हो जाता था। भौद्योगिक प्रगति के बाद से सैनिक शक्ति के क्षेत्र के रूप में तकनीकी पर अधिक निर्भरता बिना जाने लगा। यूरोप की सैनिक तकनीकी ने उत्तीसवीं शताब्दी में उस बड़े उपनिवेशवादी साम्राज्य बनाने की स्वतन्त्रता प्रदान की। उन दिनों तकनीकी और सैनिक परिवर्तन विकास के मार्ग पर थे किन्तु आधुनिक युद्ध में तकनीकी के प्रसार ने सैनिक शक्ति के क्षेत्र और प्रगति को बिस्तृत बदल दिया है। आधुनिक तकनीकी ने अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों को जिस रूप में प्रभावित किया उसे हम चार क्षेत्रों में विभाजित करके देा सकते हैं—

(1) हथियारों की सामर्थ्य में परिवर्तन होने जा रहे हैं। किसी भी राष्ट्रों की रणनीतिक सम्बन्धों पृष्ठभूमि बनाने के लिए जिन सैनिक विध्वंसकों प्रयुक्त की जाती है, उसका रूप भी बदल गया है। आज हथियारों की शक्ति बढ गई है तथा उन्हें कम समय में दूर ले जाना भी सम्भव हो गया है। इन हथियारों के प्रभाव के क्षेत्र में अर्थ व्यवस्था एवं नागरिक समाज भी आ जाता है। यदि इन हथियारों का प्रयोग नहीं भी किया जाता है तो भी इनकी सुरक्षा के लिए जो सामाजिक एवं आर्थिक प्रयत्न किये जाते हैं वे महत्वपूर्ण मूल्यों को समाप्त करने में सक्षम हैं।

आज के तकनीकी के विकास ने पूरा सैनिक शक्ति के महत्व का मूल्यांकन करने में भूगोल को कम महत्वपूर्ण बना दिया है। आज विध्वंस-

पारी शक्ति को कुछ ही मिनटों में हजारों मील दूर भेजा जा सकता है। सुरक्षा सचिव मैकनामारा के अनुमान से यदि सन् १९७० में संयुक्त राज्य अमरीका पर न्यूक्लीयर आक्रमण किया गया तो इससे उनकी बीम से लेकर गत्तर प्रतिशत तक जनसंख्या समाप्त हो सकती है। आज के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य विशेषता यह है कि यद्यपि राज्यों के पास आक्रमणकारी शक्ति बढ गई है, किन्तु वे मुश्कालमय प्रयासों की दिशा में इतने नहीं बढ़े हैं।

आज की सैनिक शक्ति यदि युद्ध में सलग्न है तो वह अत्यन्त मर्यादित है, क्योंकि सैनिक तकनीकी ने उसे कम समय में भारी विध्वंस करने की सामर्थ्य दे दी है। इस सम्बन्ध में डा० जेम्स शाटवेल (Dr. James Shatwell) का कहना पर्याप्त उचित है कि समाज की बदलती हुई प्रकृति ने युद्ध को नीति का न अपनाया जाने वाला माध्यम बना दिया है। अब युद्ध ध्वन प्रसार और दिशा में अनिश्चित है। यह राजनीतिज्ञता का सुरक्षित हथियार नहीं है। आज युद्ध का रूप एक छूट के रोग जैसा बन गया है जिसके फैलने पर उसे रोकना उस राज्य के धन की बान नहीं रह जाती जिसने कि इसे प्रारम्भ किया है। इस प्रकार इन अनियन्त्रित साधनों को अपनाता सतरे से खाली नहीं है।

(ii) आज तकनीकी के विकास ने सीमित युद्ध की सामर्थ्य में भी भारी परिवर्तन कर दिया है। आज परम्परागत गोलाबारी के तरीकों एवं सैनिक सत्ता के शीघ्र कार्य करने के साधनों में विराग हो गया है। यद्यपि तकनीकी ने महान् विध्वंसकारी शस्त्र दिए हैं फिर भी इसने व्यक्तियों एवं परम्परागत सैनिक इकाइयों की गति लोचशीलता, गोलाबारी की शक्ति एवं व्यावसायिकता पर भी पर्याप्त जोर दिया है। सैनिक एर संचार तकनीकी के कारण आज सैनिक शक्ति स्थानीय नहीं रह गई है। दि इकनामिस्ट (The Economist) ने संयुक्त राज्य अमरीका के नये सैनिक वायु मातायात के साधन Sec 5 A के सम्बन्ध में बताया कि ऐसे तीन विमान सन् १९४६ में सम्पूर्ण बलिन की वायु सेना को उड़ा सकते थे और ऐसे ब्यालीस विमान आधे दिन में एक द्वीपजन को यूरोप पहुँचा सकते हैं। इस कार्य में सन् १९६० से पूर्व ढाई दिन लगना था और २३४ वायुयानों की आवश्यकता थी। कुछ आधुनिक इतिहासकारों का यह कहना है कि सीमित उद्देश्यों के लिए शक्ति का सीमित प्रयोग सम्भव है क्योंकि अधिकांश देशों के पास अणु युद्ध के साधन नहीं हैं इसलिए उनके युद्ध अणु-युद्ध का कारण नहीं बनेंगे जब तक कि अणु शक्तियाँ विवाद में न उलझें। आज तकनीकी विराग ने स्थिति यह

बना रही है कि बड़ी शक्तियाँ किसी सङ्घर्ष में उसभले से पहले पर्याप्त सोचती और विचारती है किन्तु छोटे देश बड़ी जल्द ही सैनिक कार्यवाही में उतार आते हैं ।

(iii) वैज्ञानिक ज्ञान ने अपने विकास की गति से अनेक अनिश्चित-ताओं को जन्म दिया है । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से सैनिक नीति के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे इतनी जल्दी-जल्दी हो रहे हैं कि जब तक उनको समझा जाता है तब तक कोई नया विकास सामने आ जाता है । ऐसी स्थिति के दो परिणाम होने हैं । पहला यह कि शस्त्रों के निर्माण की जीवन लैबी हो जाती है और दूसरे परम्परागत हथियार प्रामाणिक बन जाते हैं । प्रामाणिक होने हुए भी कुछ क्षेत्रों में इन हथियारों का पूरा सम्मान होता है और बहुत इनको सैनिक दृष्टि से प्रभावशाली माना जाता है । बड़ी शक्तियाँ इन हथियारों को छोटे देशों में वितरण करती हैं जिन देशों में भौतिक शक्त समझ इतनी नहीं है कि वे स्वयं इन हथियारों का उपयोग कर सकें । थॉमस फिन्लेटर (Thomas Finletter) ने बताया है कि सैनिक तकनीकी इतनी तीव्र गति से बढ़त रही है कि सैनिक व्यक्तियों का अधिष्ठान को घोटाना बनाने का काम असम्भव बन गया है । सैनिक नियोजन सचिवालय के इन शब्दों को विश्लेषित करने के लिए अचिर नहीं रुक सकता । कोई सैनिक संस्थान किसी विशेष हथियार के प्रभाव एवं विशेषताओं को समझ पाता है उस समय तक नये प्रयोग व्यवहार में आ जाते हैं । द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद स्थिति यह हो गई है कि एक देश किसी शस्त्र के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय करता है तो कुछ समय बाद ही विरोधी पक्ष ऐसे हथियारों का आविष्कार कर लेता है कि वह सुरक्षात्मक कार्यवाही पर्याप्त महत्वहीन बन जाती है । एक देश की सुरक्षा हथियार व्यवस्था की आधुनिकता पर निर्भर करती है । जब एक राष्ट्र शस्त्रों की दौड़ में पिछड़ जाता है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए दो ही रास्ते अपनाते होते हैं या तो वह किसी तीसरे देश से आधुनिक शस्त्रों की खरीद करे अथवा अपने विरोधी की प्रतिद्वन्द्विता करने के लिए प्रागे अनुसंधान, विकास एवं शस्त्रों का उत्पादन करे ।

(iv) तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप सैनिक क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि सुरक्षा के लिए राज्यों की पराभयता बढ़ जाती है । भौतिक एवं भौतिकीय तकनीकी तथा उत्पादन के मूल्य के कारण आधुनिक हथियार केवल कुछ शक्तियों के एकाधिकार बन जाते हैं । किन्तु यदि उन्हें प्रसार कर दिया जाय तो अन्य देश इनका प्रयोग कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में सामूहिक सुरक्षा और अन्य पारस्परिक प्रबन्धों पर जोर दिया

जाता है। महाशक्तियाँ अपनी सैनिक शक्तियों का प्रयोग किसी तीसरे दल को शक्तिशाली बना कर करती है। क्योंकि यदि महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष सङ्घर्ष छिड़ गया तो यह अत्यन्त खतरनाक रहेगा। इससे अनिश्चित मित्रों के साथ सहयोग आज की आवश्यकता बन गया है। छोटे देश सैनिक कार्यक्रमों के न तो अनुसंधान एवं विकास में ही प्रतियोगिता कर सकते हैं और न ही उसके सैनिक पहलू में। यहाँ तक कि कई औद्योगिक देश भी सैनिक तकनीकी के क्षेत्र में पर्याप्त आगे नहीं बढ़ पाते। विज्ञान, भूगोल, उद्योग, प्रशिक्षण, आदि की वास्तविकताएँ, पर-निर्भरता एवं सहयोग को प्रोत्साहन देती हैं। कोई भी राज्य शस्त्र प्राप्त करने की आवश्यकता को सन्तुष्ट करने के लिए आर्थिक एवं राजनैतिक जोखिम उठाता है। उदाहरण के लिए भारत ने सोवियत संघ और पश्चिम दोनों से हथियार लिये इसी प्रकार पाकिस्तान ने चीन और अमरीका, आदि देशों से सहायता ली।

छोटे देशों की भाँति संयुक्त राज्य अमरीका जैसे बड़े राज्यों को भी सुरक्षा के लक्ष्यों की पूर्ति करनी होती है। तकनीकी ने सैनिक शक्ति को शीघ्रता के साथ चलने एवं प्रयुक्त होने की शक्ति प्रदान की है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न किया जाता है कि छोटे राज्यों को किस सीमा तक मित्र बनाया जाना चाहिए। क्या बड़ी शक्तियाँ अपनी सुरक्षा की दृष्टि से राजनैतिक तटस्थता का दृष्टिकोण नहीं अपना सकती? भारत इस प्रश्न का एक जीता जागता उदाहरण है। उसने असमत्तता की नीति को अपनाया और जब उसकी उत्तरी सीमाओं पर साम्यवादी चीन का आक्रमण हुआ तो संयुक्त राज्य अमरीका ने शीघ्र ही उसकी सहायता की। तथ्य यह है कि जब एक राज्य को मित्र बनाने में तथा तटस्थ होने में अधिक अन्तर नहीं दिखाई देना तो वह तटस्थ रहना चाहता है ताकि उसकी राजनैतिक स्वतन्त्रता सुलभ्यता को सन्तुलित कर सके।

जो छोटे राज्य अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बड़े राज्यों के साथ मित्रता के दम्भन में औपचारिक रूप से बंध गए थे उनके ऊपर अब दबाव और चुनौतियाँ डाली जा रही हैं। आज की स्थिति में अणु युद्धों का रूप पूर्ण युद्ध का हो चुका है। ऐसी स्थिति में छोटे राज्यों को यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि एक मित्र देश आक्रमण के समय छोटे राज्य की मदद करने में कितना जोखिम उठाएगा। यह प्रश्न नाटो की शक्तियों की समस्या का एक भाग बन गया है। एक फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ पीयरे गैलाइस (Pierre Gallois) ने बताया है कि अणु शस्त्रों ने मित्रों को और सन्धियों को निरर्थक

ना दिया है क्योंकि कोई भी राज्य दूसरे की खातिर अपने अस्तित्व को मजबूत न दालेगा ।

पर निरंतरता के कारण छोटी शक्तियों की अपेक्षा बड़ी शक्तियों के समाने अधिक उपकरणों का जाता है । ये अपने मित्रों के बीच भाड़ा होने पर शेरारा पक्ष का जाते हैं । तकनीकी विकास की सीध शक्ति ने सामूहिक सुरक्षा का मार्ग को कुछ सरल बनाया है और कुछ जटिलताएँ भी ला दी हैं । उदाहरण के लिए समुक्त राज्य अमेरिका यह अनुभव करने लगा है कि कुछ नाटो देशों का सीमित दृष्टि से उससे लिए बार्ड महत्व नहीं है ।

जब एक बड़ी शक्ति अनीयोरिफ देशों को अलग-अलग भेजती है तो उसके यह उन देश की सहाय्य सेवा को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाती है । इस प्रकार वह उन देश के सामाजिक एवं राजनैतिक साठनों पर भी प्रभाव डाल पाती है ।

विज्ञान, तकनीकी एवं विदेश नीति (Science, Technology and Foreign Policy)

विज्ञान और तकनीकी के विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक प्रक्रिया के किसी भी प्रमुख तत्व को भंग नहीं छोड़ा है । राज्य एवं राज्य व्यवस्था की बनावट, राज्य की नीति के लक्ष्य एवं प्राकाराद्यों तथा इनको प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन साधन आदि सभी की तकनीकी के विकास द्वारा प्रभावित किया गया है । विदेश नीति से विज्ञान का सम्बन्ध अत्यन्त रूप में रहता है । इसका कारण यह है कि समाज द्वारा नये वैज्ञानिक ज्ञान का अनुभव प्रायः तकनीकी के रूप में किया जाता है ।

यह कहा जाता है कि तकनीकी विकास ने विदेश नीति के क्षेत्र में संचार साधनों का विकास करके जो कुछ भी एक हाथ से दिया है उसे दूसरे हाथ से ले लिया है, क्योंकि इसने विरोध करने के लिए समय नहीं छोड़ा है । तकनीकी विकास ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों जैसे — अखिलता, तत्त्व, आकाशवाणी, साधन का क्षेत्र, आदि को जिस रूप में प्रभावित किया है वह पर्याप्त महत्वपूर्ण है । इस प्रभाव की कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर तकनीकी का पड़ने वाला प्रभाव स्वयं की कुछ एवं विशेषताएँ रखता है, वे निम्न प्रकार हैं :—

(1) जो तकनीकी विकास राजनैतिक परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यक्ष नहीं होते किन्तु उनकी प्रवृत्ति बहुत होती है । किसी देश की विदेश नीति के

सम्बन्ध में निर्णय लेते समय केवल एक ही तकनीकी आविष्कार से प्रभावित नहीं किया जाता बल्कि अनेक आविष्कार एक साथ मिल कर उसे प्रभावित करते हैं ।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रवृत्ति में जो प्रमुख परिवर्तन आये वे तकनीकी तत्वों के साथ-साथ अनेक गैर-तकनीकी तत्वों के परिणाम हैं । उदाहरण के लिए यदि हम १८वीं शताब्दी के सीमित युद्ध की समाप्ति के कारणों का अध्ययन करें तो हमारे सामने कुछ तकनीकी कारण आयेगे जैसे—अच्छे मार्ग, धातु के उत्पादन की वृद्धि, अग्नि आयुधों की बड़ी हुई कार्य-कुशलता आदि । इसके अतिरिक्त अनेक गैर तकनीकी कारण भी बताये जा सकते हैं जैसे—राजनैतिक लक्ष्यों में आलोचनात्मक परिवर्तन, सैनिक मिथ्यान्त में परिवर्तन, तथा सामान्य सभ्यता के बाढावरण में परिवर्तन आदि ।

(iii) तकनीकी परिवर्तन के राजनैतिक लानों को स्थायी एवं अस्थायी रूप में राज्यों के बीच अनुमान रूप में वितरित किया गया । एशिया तथा अफ्रीका के देशों में आज आर्थिक विकास जटिल बन गया है, क्योंकि महा औद्योगीकरण को मृत्यु दर में वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं का सामना करना होगा । योराप को ऐसा नहीं करना पड़ा था । आज समय और स्थान के क्षेत्र में होने वाले विकासों ने औद्योगिक सर्वोच्चता के महत्त्व को कम कर दिया है ।

(iv) औद्योगिक प्रगति के प्रारम्भिक वर्षों में तकनीकी का विकास उसके वैज्ञानिक ज्ञान से स्वतन्त्र रह कर हुआ । भाप के इंजिन का आविष्कार पहले ही हो गया और उनको प्रगाथित करने वाले वैज्ञानिक नियम बाद में विकसित किये गये, किन्तु बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही तकनीकी का विकास भौतिक विश्व के मूल ज्ञान के विस्तार पर निर्भर रहने लगा है । अणु बम का आविष्कार न्यूक्लीयर भौतिक शास्त्र के अनुसंधानों पर निर्भर था । इस नये ज्ञान के अनेक व्युत्पन्न स्वयं भौतिक शास्त्रियों के द्वारा सम्पन्न किये गये ।

(v) तकनीकी आविष्कार एवं वैज्ञानिक ज्ञान प्रायः एक ही गति से आगे बढ़ते हैं । वैज्ञानिक ज्ञान प्रत्येक दस से पंद्रह साल के बाद दो गुना हो जाता है ।

(vi) नये वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति एवं नये उत्पादन का खर्च पर्याप्त बढ़ जाता है । आज विकसित देशों के विश्व विद्यालयों का अनुसंधान बजट सधीय कोष पर आधारित हो गया है, क्योंकि इस कीमत को चुकाने

बाला और कोई भी खात नहीं है। ग्लूबलीयर भौतिकी के क्षेत्र में इस व्यय की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए एक वैज्ञानिक ने बताया कि एक प्रयत्न पूरने तक की कीमत एक मिलियन डालर हो जाती है। इन प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप यह स्थिति भी गई है कि महान् तकनीकी केवल महान् शक्तियों के साम हो रह सकती है तथा भविष्य में केवल महान् शक्तियाँ ही महान् विज्ञान सम्पन्न बन सकेंगी।

(vii) द्वितीय विश्व युद्ध में विज्ञान विदेश नीति के समर्थन में प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से उत्तरा। अपने युद्ध रूप में विज्ञान १९वीं शताब्दी से विकसित होता हुआ मूलतः एक स्वायत्त सामाजिक सम्पदा बन गया। उस समय वैज्ञानिक समाज के अपने कार्य की अवस्थाओं के सम्बन्ध में स्वयं के कुछ नियम थे। उसका एक अन्तराष्ट्रीय या अर्थात् प्रकृति के तथ्य उन सभी के लिए खुले हुए थे जो विज्ञान के तरीकों से उनकी खोजना चाहे। विज्ञान का विकास अनुसंधान की स्वतन्त्रता पर आधारित था। वैज्ञानिक को अपने अनुसंधान के लिए कोई भी समस्या छानने की तथा अपने अनुसंधान के परिणामों को संचारित करने की स्वतन्त्रता थी; किन्तु इस सबके पीछे सामान्य मान्यता यह भी कि नया ज्ञान अन्तिम रूप से मानव जाति के लिए लाभदायक होगा तथा वैज्ञानिक समाज का इन आविष्कारों के परिणामों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

१९वीं शताब्दी के प्रारम्भ में होने वाले विचारधारागत युद्धों के दौरान वैज्ञानिकों एवं उनके विचारों की स्वतन्त्रता पूर्वक राजनीतिक सीमाओं पार करने की अनुमति दी गई। वे शक्ति एवं युद्ध दोनों बातों में इस स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकते थे, किन्तु ज्यों ज्यों वैज्ञानिक ज्ञान की जटिलता बढ़ती गई तथा तकनीकी आविष्कार गतिमान व विध्वंसक होते गये, त्यों त्यों इस क्षेत्र में प्रतिबन्ध बढ़ते चले गये।

अणु और राष्ट्रीय शक्ति (The Atom and National Power)

अणुशक्ति का प्रयोग वर्तमान युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो पुराणों में बर्णित अग्निबाण और अन्य इसी प्रकार की वस्तुनामों को सत्य के घरातल पर ला देती है। अणुशक्ति के धोखेलेख ने विश्व के सामने अनेक प्रश्न और समस्याएँ लाकर रख दी हैं। उनमें से एक यह भी है कि हमने विश्व राजनीति को हिला दिया है तथा देशों की शक्ति स्थिति को बदल दिया है।

अणुशक्ति के विकास ने आक्रमण करने की सामर्थ्य को बढ़ा कर सर्वोच्च शक्तियों की शक्ति को और भी भारी बना दिया है। प्रारम्भ में अणुशक्ति के मालिक केवल दो ही देश थे—सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमरीका किन्तु आज ब्रिटेन, फ्रांस, साम्यवादी चीन, कनाडा आदि देशों ने भी इसी ओर कदम बढ़ा दिये हैं। इण्डोनेशिया जैसे छोटे देश भी आज अणुबम बनाने की सोचने लगे हैं। अणु शक्ति की इस लाकप्रियता के कारण छोटे छोटे देश भी इतने साधन जुटाने में समर्थ हो जायेंगे कि एक बड़ी शक्ति को उन पर आक्रमण करने में भारी खर्च वहन करना पड़ेगा।

अणुबम ने सभी देशों को समान बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। 'अणु शक्ति' कितनी विध्वंसक होगी यह बात किसी देश के प्रकार पर अथवा उस देश की जनसंख्या की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। एक बम चाहे वह एक छोटे से देश द्वारा बनाया गया हो या एक बड़े देश द्वारा जब काम में लाया जायगा तो समान रूप से विनाश करेगा और इस दृष्टि से देखने पर हम यह कह सकते हैं कि अणु शक्ति ने राष्ट्रों के बीच समानता की स्थापना कर दी है। सजबेरगर (Sulzberger) महोदय ने सन् १९५४ में अणु शक्ति के इस पहलू को स्पष्ट करते हुए कहा था कि "एक दिन न केवल सर्वोच्च शक्तियां या बड़ी शक्तियां ही बरन् छोटे राष्ट्र भी अणु आयुधों से युक्त बन जायेंगे तथा वे इन आयुधों को परम्परागत मानने लगेंगे। अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुलन तो आज बदल ही चुका है क्योंकि कमजोर राष्ट्रों को भी एक नया महत्व प्राप्त हो गया है। यह सन्तुलन उस समय तो बिस्तुल ही बदल जायगा जबकि छोटे छोटे भूमि खण्डों के पास ऐसे हथियार आ जायेंगे जो दुनिया को उड़ाने की शक्ति रखते हैं। इन समय 'अणुबम' राष्ट्रों को समान बनाने का कार्य (Equalizer) करेगा।

तकनीकी विकास का आधार (The basis of Technological Progress)

राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व होने के कारण 'तकनीकी विकास' (Technical Progress) की ओर सभी राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित होने लगा है। प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयास करता है कि वह अपने देश के उद्योग व वे, अर्थ व्यवस्था, सैनिक तैयारियां आदि में तकनीकी ज्ञान का अधिकारिण प्रयोग करके उच्चता के अंतर पर पहुँचने के मार्ग को सुगम बना दे, किन्तु व सभी राज्य अपना वे अनुरूप परिणाम प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते। इस असम्यक्ता का मुख्य कारण उस देश में स्थित

समाज की परम्परायें, सोचने के तरीके, रहने का ढंग तथा विकास के प्रति उसका दृष्टिकोण है। यदि हम विश्व के राष्ट्रो पर इसी दृष्टि से एक सरमरी निगाह डालें तो पायेंगे कि एक ओर सोवियत रूस और जापान जैसे राष्ट्र हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही तकनीकी क्षेत्र में इतना विकास कर लिया जिसे देख कर विश्व आश्चर्यान्वित रह जाता है। जापान ने अपने दृष्टिकोण एवं मस्यामो में बिना कोई भारी परिवर्तन किये ही औद्योगिक उत्पादन एवं सैनिक समूहों की पश्चिमी तकनीकी को अपना लिया है। किन्तु दूसरी ओर साम्यवादी चीन की स्थिति को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ तकनीकी शान का प्रसार इसी तेजी के साथ हुआ है या निकट भविष्य में हो सकता है।

रूस, जापान और साम्यवादी चीन के उदाहरणों को देखने के पश्चात् हम कुछ निष्कर्षों पर पहुँचते हैं जैसे कि—

(१) एक देश में होने वाले तकनीकी विकास पर उस देश की सरकार के रूप का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तकनीकी विकास, दूसरे शब्दों में, पश्चिमी राष्ट्रो या प्रजातन्त्रात्मक देशों का एकाधिकार नहीं है, साम्यवादी देशों में भी यह हो सकता है।

(२) 'तकनीकी विकास साम्यवादी व्यवस्था में अधिक शीघ्रता से हो जाता है' यह मान्यता तथ्यों के विपरीत है। क्योंकि चीन में साम्यवादी शासन होते हुए भी तकनीकी की गति बड़ी धीमी है।

(३) तकनीकी विकास पर सरकार के रूपों का नहीं बल्कि सामाजिक पद्धतियों का प्रभाव पड़ता है। यदि समाज एक परिवर्तनशील एवं विकसनीय दृष्टिकोण (Radical attitude) वाला है तो तकनीकी विकास का मार्ग सुगम हो जायगा किन्तु परम्परावादी, रुढ़िवादी तथा पुराने विचारों से मुक्त समाज में इसे अनेक बाधाएँ एवं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।

निस समाज का ढाँचा वैज्ञानिक आधार से मेल नहीं खाता वह समाज पिछड़ा जाता है। भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू इस तथ्य से बनी भाँति परिचित थे। उन्होंने जीवन भर देश की जो मूल शक्त पड़ाया, वह था 'विज्ञान तथा तकनीकी का महत्व'। उनके प्रसिद्ध जन-सभावाचन (Public lecture) में अनेकों पर यह प्रभाव डाला जाता था कि हमारा धर्म, संस्कृति एवं परम्परायें ऊँचे हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनको यदि हम छोड़ देंगे तो 'हम', हम न रहेंगे। किन्तु केवल इनमें धिपके रहना भी समझोचिद नहीं है। इस युग की विशेषता विज्ञान तथा तकनीकी है इसे

यदि न अपनाया गया तो हम पिछड़ जायेंगे, सम्यता की दौड़ में पीछे रह जायेंगे। प० नेहरू ने विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में जो कुछ किया, माने वाली पीढ़िया उसे कभी नहीं भुला सकती। नेहरू के कृत्यों का महत्व प्राकृते समय यह नहीं देखना है कि भारत के पास कितनी वैज्ञानिक उपलब्धिया हैं, वरन् देखना यह है कि क्या भारतीय समाज विज्ञान के महत्व को समझने लगा है ?

साम्यवादी चीन में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के मार्ग की बाधाओं का वर्णन करते हुए केयरबैक महोदय ने यह माना है कि ये बाधाएँ ७ हैं—तर्क की व्यवस्था (System of logic), चरित्र-चित्रण (Character writing), सांस्कृतिक शिक्षा (Classical Education), हाथ से किये गये श्रम का विरोध (Aversion of manual labour), भ्रम व्यवस्था पर राज्य का अधिकार (State monopoly of the economy), तिरस्कृत मनुष्य शक्ति (Abundant man power) और शक्तिशाली एवं रूढ़िवादी नौकरशाही (The powerful and conservative bureaucracy)।

अन्तिम पंक्तियाँ

(The Final Lines)

तकनीकी परिवर्तन इतिहास में निश्चय ही एक मुख्य तत्व रहा है। आविष्कारों ने मानव के इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से संचार, यातायात, युद्ध, दवाई, भोजन की तैयारी एवं रक्षा आदि के क्षेत्र में किये गये आविष्कारों का अपना महत्व है। उनको सहारा देने के लिए शक्ति के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, धातुओं के क्षेत्र में तथा रचना के क्षेत्र में किये जाने वाले आविष्कारों ने भी महत्वपूर्ण कार्य किया। यदि सम्पूर्ण मानव जाति की दृष्टि से विचार किया जाये तो ज्ञात होगा कि तकनीकी उन्नति के लिए एक व्यापक आन्दोलन चल रहा है। जो तकनीकें एक बार आविष्कृत हो जाती हैं बाद में उनको समाप्त नहीं किया जाता वरन् वे मानव जीवन का आवश्यक भग बन जाती हैं।

राष्ट्र और सम्यताएँ गिरती और उठती रहती हैं तथा शक्ति और सम्यता के केन्द्र एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलते रहते हैं किन्तु यह मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि प्रवृत्ति की शक्तियों पर नियंत्रण करे। इसके कारण लोग एक दूसरे के घनिष्ठ एवं निकट सम्पर्क में आये हैं, सारा ससार एक पट्टीसी जैसा बन गया है। दूसरी ओर प्रत्येक देश सैनिक, आर्थिक एवं प्रचार की दृष्टि से आक्रमण करने में अधिक सक्षम बन गया है। प्रत्येक

देश दूरस्थ देश के साथ व्यापार, संस्कृति एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित हो गया है । देशों में बड़े एवं छोटे समूह बनते जा रहे हैं । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी, मस्यागत एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता जा रहा है । देशों का व्यवहार सह-प्रवृत्ति, परम्परा एवं आत्म चेतना से कम और मत से अधिक प्रभावित होने लगा है । तकनीकी का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक पहलू पर व्यापक तथा गहरा प्रभाव पड़ा है । इसने देशों की शक्ति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया है ।

इसी प्रकार जनसंख्या भी शक्ति तत्व के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है । जनसंख्या की मात्रा एवं जनसंख्या का गुण दोनों ही इस दृष्टि से अपना महत्व रखते हैं । गुण के बिना केवल मात्रा का होना एक राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक होने की अपेक्षा उसका कमजोरी का आधार भी बन सकता है । इसी प्रकार मात्रा के बिना जनसंख्या का केवल गुण तत्व अधिक उपयोगी नहीं हो पाता क्योंकि युद्ध काल में सैनिक तथा आतंकाल में प्रौद्योगिक श्रम सभी पर्याप्त उपलब्ध हो सकेगा जबकि देश में जनसंख्या की निश्चित मात्रा प्राप्त हो ।

आज तकनीकी, भूगोल एवं जनसंख्या को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मुख्य विज्ञान माना जाता है । यह कहा जाता है कि इन विज्ञानों का अध्ययन करने के बाद जनसंख्या एवं तकनीकी का इस प्रकार नियमन हो सकेगा कि भौतिक संसाधनों एवं स्रोतों का पर्याप्त उपयोग किया जा सके । इस प्रकार सार्वभौमिक समाज की वह भौतिक नींव रखी जा सकेगी जिससे संस्कृति के आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं अन्य तत्व विरसित होंगे ।

राष्ट्रीय शक्ति के तत्व : विचारधारा, मोरेल और नेतृत्व [ELEMENTS OF NATIONAL POWER : IDEOLOGY, MORALE AND LEADERSHIP]

पिछले अध्यायों में राष्ट्रीय शक्ति के जिन मूल तत्वों का हमने अध्ययन किया है उनकी प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि उनके अस्तित्व को देखा जा सकता है, मापा जा सकता है तथा उनके प्रभाव का भी स्पष्टतः पर्यवेक्षण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनका नियमन एवं नियन्त्रण भी आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। इन तत्वों के अतिरिक्त राष्ट्रीय शक्ति के ऐसे तत्व भी होते हैं जो दिताई नहीं देते और उनका अस्तित्व केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इन तत्वों को पृथक् करके देखना तथा परिभाषित करना निश्चय ही एक कठिन काम है किन्तु इसके कारण इन तत्वों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। ये तत्व असल में मौलिक तत्व न होकर मानवीय तत्व हैं जिनका प्रभाव मौलिक तत्वों का प्रयोग करने में एक निर्णायक का काम करता है। ये मानवीय तत्व विचारधारा (Ideology), मोरेल (Morale) तथा नेतृत्व (Leadership) हैं। इनका अध्ययन करना अस्तुतः अध्याय का सध्य है।

ये मानवीय तत्व मूल रूप से व्यक्ति के दृष्टिकोणों, विश्वासों एवं उसके सामाजिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में इनका

स्व-उन्नता और पतनता है। ये राज्यों के व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव रखते हैं। एक देश के लोग अपने भौतिक एवं राजनैतिक वातावरण के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करेंगे यह बात इन्हीं तत्वों के द्वारा निर्धारित की जाती है। सामाजिक वातावरण के रीति-रिवाज एवं परम्परायें दृष्टिकोणों को जन्म देती हैं जो कि धीमे चल कर विश्वास बन जाते हैं। व्यक्ति के दृष्टिकोण और विश्वास मिल कर उन मूल्यों को परिभाषित करते हैं जिनको व्यक्ति रखता है और उन मूल्यों को स्पष्ट करते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहता है।

मूल्यों को हम ऐसे मापदण्ड कह सकते हैं जिनको व्यक्तियों द्वारा सहो एवं वाछनीय समझा जाता है। इस प्रकार कोई भी राजनैतिक कार्य उनके द्वारा तथा उनके लिए संचालित हो सकता है। व्यक्ति स्वभावतः अपने वाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है। वह विशेष वातावरण की स्थितियों में अपने मूल्यों को समायोजित करता है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक क्रिया का संचालन करता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जो भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवहार को समझना चाहे उसे इस माध्यता को स्वीकार करके धीमे चलना चाहिए कि मानवीय समूहों में निम्न निम्न दृष्टिकोण, विश्वास एवं मूल्य होने हैं। मूल्य-मूल्य देशों के लोगों का सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण भी बहुत प्रकार का होता है। वाह्य वातावरण के ये विभिन्न तत्व इस बात का निश्चय करते हैं कि उस देश की मिश्रता किसके साथ होगी तथा गठुता किसके साथ होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते समय यह जानना पर्याप्त महत्वपूर्ण समझा जाता है कि व्यक्ति कुछ मूल्यों को क्यों अपनाता है तथा अन्य सृष्टि तथा शक्तियों के प्रभाव से ये मूल्य कैसे तथा क्यों बदल जाते हैं। एक देश के विभिन्न सामाजिक समूह सामान्य दृष्टिकोण, मूल्य एवं लक्ष्यों में जितनी अधिक मात्रा में नाय लेते हैं वही चेतना उतनी ही अधिक पायी जाती है तथा इससे बड़ा ही राजनैतिक समस्याओं को स्पष्टिपूर्वक प्रभाव होता है। जिन देशों के दृष्टिकोणों एवं मूल्यों में समानता रहती है उनके सम्बन्ध शक्तिपूर्ण, महयोगपूर्ण एवं मंत्रीपूर्ण रहेंगे। जिस देश में लोगों के दृष्टिकोण एवं मूल्यों के बीच एकरूपता नहीं रहती वही प्रायः अस्थिरता एवं सङ्घर्ष रहता है। यही बात दो देशों के पारस्परिक सम्बन्धों पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व विचारधारा, मोरेल एवं नेतृत्व, जिनका वर्णन हम इस

अध्याप्य में करने जा रहे हैं, एक देश के लोगों के दृष्टिकोणों, विश्वासों एवं मूल्यों से पर्याप्त प्रभावित होने हैं।

विश्व राजनीति में विचारधारा (Ideology in World Politics)

विचारधारा के द्वारा एक देश की जनता अपने मूल्य तथा दृष्टिकोणों को अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त करती है। पैडेलफोर्ड तथा लिंकन (Padelford & Lincoln) के कथनानुसार विचारधारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक मूल्यों तथा लक्ष्यों से सम्बन्धित विचारों का निकाय है जो कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। विचारधारा व्यक्ति एवं समाज की प्रकृति के बारे में कुछ मान्यताओं पर आधारित रहती है। विचारधारा के द्वारा समाज की कठिन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं के लिए भी समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं। विचारधारा व्यक्तियों एवं समूहों को एक ऐसे समाज में बांध देती है जिसका सामान्य उद्देश्य होता है तथा उसे प्राप्त करने के लिए वे समान तरीकों में विश्वास करते हैं।

विचारधारायें एक देश की शक्ति पर अपना पर्याप्त प्रभाव रखती हैं। यह प्रभाव सीधा न होकर अप्रत्यक्ष होता है। जिस विचारधारा को एक देश मानता है उसी विचारधारा को मानने वाले दूसरे देशों की मदद करना एवं मोत्री उनके प्रति रहना स्वभाविक है। व्यक्तिगत जीवन में मित्रता दो समान विचार वाले व्यक्तियों के बीच ही निम्न पाती है, उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दो राष्ट्र प्रायः तभी साथी बनते हैं जबकि उनके राजनैतिक सिद्धांत, आर्थिक नीतियां, विदेश नीतियां आदि बातें समान हो या कम से कम उनके बीच विरोध न हो। सोवियत रूस साम्यवाद का समर्थक है, 'साम्यवाद' समुक्त राज्य अमेरिका के आदर्शों एवं विचारों के विपरीत जाकर पड़ता है। यही कारण है कि दोनों देश न केवल मित्र हैं वरन् दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, एक के अहित में दूसरा अपना हित पाता है।

आजकल अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में 'विचारधारा' (Ideology) शब्द पर्याप्त लोकप्रियता पा चुका है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रा के बीच जो भेद पाया जाता है उसका मुख्य कारण विचारधाराओं की भिन्नता होती है। परस्पर विरोधी विचारधारायें अनेक बार युद्ध का कारण बन जाती हैं।

स्ताइडर तथा विलसन (Snyder & Wilson) महोदय ने विचारधारा की परिभाषा देते हुए कहा था कि "एक 'विचारधारा' जीवन, समाज, और सरकार से सम्बन्धित विचारों का वह समूह है जो प्रायः सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक नारों या युद्ध के नारों से उत्पन्न होती है तथा जिसका लगातार प्रयोग उसकी एक विशेष समुदाय, दल या राष्ट्रीयता का प्रमुख विश्वास या सिद्धांत बना देता है।"^१ विचारधारा की एक दूसरी परिभाषा स्ताइडर महोदय ने दी है। उनके मतानुसार विचारधारा व्यक्ति के अमूर्त विचारों की व्यवस्था है। ये विचार वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं, मूल्यात्मक लक्ष्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तथा इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को प्राप्त करने अथवा बनाये रखने का प्रयास करते हैं जिसमें उनके विश्वास के अनुसार लक्ष्यों को सर्वश्रेष्ठ रूप में साकार किया जा सकता है।

अनेक पश्चिमी देशों में लोगों के विश्वास और राजनैतिक जीवन के लक्ष्यों के प्रति समान दृष्टिकोण हैं। जब कभी हमारे देश द्वारा पुर्णतः दी जानी है तो एकता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्नताओं के बीच समझौता किया जा सकता है। जब पूरे राष्ट्र की एक राय रहती है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। बड़ी शक्तियाँ केवल तभी जन्म लेती हैं जबकि अनेक राष्ट्र समान विचारों एवं समान लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं।

कुछ विचारकों का यह कहना है कि सत्तावादी समाजों में दल अथवा सरकार के पीछे जनता का सच्चा मत नहीं रहता। केन्द्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व, व्यापक प्रचार, कठे राजनैतिक यन्त्र एवं स्वामिभक्त अनुयायियों के कारण केन्द्रीय शासन के पीछे शक्ति की लेकर चल सकता है। सोवियत रूस, साम्यवादी चीन और युद्ध पूर्व के इटली तथा जर्मनी में यही बात देखने को मिलती है। सैद्धान्तिक विचारधारायें प्रायः वास्तविकता की कुछ मान्यताओं पर या पूर्ण बलताओं पर आधारित रहती हैं जिन्हें उनके अनुयायी सत्यता देने का प्रयास करते हैं। यदि ये पूर्ण मान्यतायें बड़ा और व्यापक समर्थन रखती हैं तो सिद्धांत की प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

साम्यवाद की सैद्धान्तिक शक्ति को इतिहास के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के आधार पर बढ़ाया जाता है। इस विचारधारा के द्वारा पूंजीवाद एवं

साम्राज्यवाद पर मजदूर वर्ग की विजय का वायदा किया जाता है। साम्यवाद के ये वायदे अविश्वसित समाजों में पर्याप्त योगदान रखते हैं। इन समाजों में जनसंख्या की गलत सूचनाएँ दी जाती हैं और इन सूचनाओं को वे बिना किसी घात विवाद के स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी दशा को सुधारने की आशा है। गीने मच्चा साम्यवादी राज्य तो शायद साम्यवादी रूस और चीन के नेताओं के जीवन काल में भी प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु फिर भी वे इसको अपना उद्देश्य मान कर चलते हैं। सिद्धांत की प्रतीति को व्यापक संचार के साधनों द्वारा कई गुना बना दिया जाता है। अनेक विभिन्न देशों में उन नए विचारों एवं लोकप्रिय आन्दोलनों के लिए पर्याप्त उपजाऊ परिस्थितियाँ होती हैं जो कि सुधार एवं तुरन्त परिवर्तन का वायदा करते हैं। तुरन्त परिवर्तन के लिये सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करने के हेतु साम्यवादी विचारधारा एक उपयुक्त सिद्धांत प्रतीत होती है। सरकार के नए रूप की स्थापना के लिए, उपनिवेशवादी शासन को समाप्त करने के लिये तथा आर्थिक पक्षों को पूरा करने के लिये यह विचारधारा अनेक वायदे करती है। व्यापक महत्वाकांक्षायें एवं शीघ्र प्राप्त किए जाने वाले परिणाम, आज्ञाकारिता एवं अनुशासन की मांग करते हैं और यह साम्यवादी विचारधारा में सम्मिलित हो जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रणेता शक्ति के लिये सधर्म की महत्त्वपूर्ण मानते हैं और उनसे मतानुसार सिद्धान्त इसी की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। विश्व राजनीति में जो वास्तविकता है और जो दिग्राई देता है उन दोनों के बीच पर्याप्त अन्तर है। राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियाँ निर्धारित करते हैं, किन्तु ये नीतियाँ उनके द्वारा नीतिक, कानूनी या जीव शास्त्रीय अर्थ में अभिव्यक्त की जाती हैं। कहने का अर्थ यह है कि नीति के सहो रूप को सौदागिक व्यापकता एवं बोद्धिमानता के द्वारा छिपा लिया जाता है। मारक्सेयों के मतानुसार जो लोग शक्ति सधर्म में जितने उभरे रहते हैं वे इस बात को उतना ही कम देता पाते हैं कि यह शक्ति सधर्म किस लिए हो रहा है। राजनीतिक रणमंच के अभिनता, राजनैतिक विचारधारा के पीछे जो राजनैतिक क्रियाओं की सच्ची प्रकृति होती है उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति शक्ति के सधर्म से जितना अभिन्न दूर होता है वह उसकी गहरी प्रकृति को समझने में उतना ही अधिस्त समर्थ होता है। इस आधार पर यह स्पष्ट स्पष्ट हो जाता है कि एक देश विशेष की राजनीति को, उनके मूल, क्रियाश्रितियों की विशेषता, विदेशी अभिन्न शक्तियों से सम्बन्ध पाता है। साथ ही विज्ञान अभ्ययनकर्ता

राजनीतिज्ञों की प्रेरणा अधिक जानकारी हासिल कर लेता है। राजनीतिज्ञों की यह सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उसे दिखाना चाहते हैं और इसलिए अपने कार्यों की शक्ति की शब्दावली में सम्पूर्ण न बरके नीतिक और कानूनी सिद्धान्तों या जैविक आवश्यकताओं के सम्पर्क में करते हैं। मारकेन्यो ने शब्दों में जबकि समस्त राजनीति धान्यक रूप से शक्ति की राज है विचारधारामें इन शक्ति संपर्क को ऐसा रूप देती हैं जो अभिनताओं और उनके आनाओं के लिए मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक रूप से स्वीकार्य हैं।

कानूनी एवं नैतिक सिद्धांत तथा जीवशास्त्रीय आवश्यकताएं अन्तराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में दोहरा कार्य करती हैं; या तो राजनैतिक क्रिया का अन्तिम लक्ष्य है अथवा वे एक झूठे पर्दे का काम करती हैं जिसके पीछे कि शक्ति संपर्क की यह स्थिति छिपी हुई है जो कि समस्त राजनीति की मुख्य विशेषता है। ये सिद्धान्त और आवश्यकताएं पहले अथवा दूसरे कार्य को अथवा दोनों कार्यों को एक साथ सम्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए न्याय का कानूनी और नैतिक सिद्धांत या पर्याप्त जीवन स्तर की जीवशास्त्रीय आवश्यकता विदेश नीति का लक्ष्य हो सकती है या एक विचारधारा हो सकती है अथवा एक ही समय में दोनों चीज हो सकती हैं। इस प्रकार नैतिक और कानूनी सिद्धांत तथा जीवशास्त्रीय आवश्यकताएं विचारधारामें के कार्य सम्पन्न करती हैं। कहा जाता है कि यह राजनीति की प्रकृति में निहित है कि वह राजनैतिक समूह के अभिनेता को अपने कार्यों के सफलतापूर्ण लक्ष्य को दिखाने के लिए विचारधारा का प्रयोग करने के लिए बाध्य करती है। प्रत्येक राजनैतिक कार्य का तात्त्विक उद्देश्य शक्ति है और राजनैतिक शक्ति व्यक्ति के कार्य एवं मस्तिष्क पर शक्ति होती है। शक्ति की राजनीति में जो व्यक्ति दूसरों की शक्ति का विषय है वह दूसरों पर स्वयं भी शक्ति प्राप्त करना चाहता है। एक ही माय में दोनों कार्य होने हैं कि व्यक्ति दूसरों पर अपनी शक्ति जमाना चाहता है और दूसरे उस पर अपनी शक्ति जमाना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वनामधेय अपनी शक्ति प्राप्ति की इच्छा को कानूनी और न्यायमूर्त मानता है तथा दूसरों की ऐसी इच्छाओं को जो कि उनके ऊपर शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह अनुचित और अनाप-पूर्ण मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सोवियत संघ ने जो नीति अपनाई उसे यह अपनी मूर्खता की दृष्टि से ग्राह्योचित ठहराना है, किन्तु दूसरों की शक्ति के प्रसार को वह विश्व विजय की तैयारी या साम्राज्यवादी प्रयास कह कर आलोचना का विषय बनाता है। दूसरों और संयुक्त राज्य

अमरीका भी रुस की महत्वाकांक्षाओं को यही उपाधि प्रदान करता है और अपने अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं बताता है। मारगेन्वी द्वारा उद्धरित जान एडम्स के ये शब्द उल्लेखनीय हैं कि शक्ति हमेशा यह सोचती है कि इसकी आत्मा महान है और इसके दृष्टिकोण व्यापक हैं तथा जिस समय ईश्वर के सारे कानूनों को तोड़ रही है उस समय यह ईश्वर की सेवा कर रही है।¹

अब एक देश अपने रूप से यह स्वीकार कर लेता है कि वह शक्ति चाहता है और इसलिए दूसरे राष्ट्रों की ऐसी महत्वाकांक्षाओं का विरोध कर रहा है तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा और उसे शक्ति सघर्ष में नुकसान होगा। स्पष्ट मान्यता के द्वारा एक और तो दूसरे देशों को इसके विरुद्ध एक बना देगी जो कि मिल कर उसके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करेंगे तथा उसे विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा न करने देंगे। दूसरी ओर स्पष्ट कथन के कारण वह सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय समाज के नैतिक मापदण्डों को अस्वीकृत कर देगा और इस प्रकार वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहाँ स्वयं की विदेश नीति को वह भावे दिल से या बुरी आत्म चेतना से सम्पन्न करेगा। यह कहा जाता है कि अगर कोई सरकार जनता को विदेश नीति के पीछे खाना चाहती है या समस्त राष्ट्रीय शक्तियों को तथा साधनों को उसके पीछे लगा देना चाहती है तो उसे चाहिए कि जीवशास्त्रीय आवश्यकताओं पर जोर डाले, जैसे राष्ट्र का अस्तित्व आदि। नैतिक मित्रांशों जैसे न्याय पर जोर डालना भी उपयोगी हो सकता है किन्तु उसे शक्ति की शब्दावली में नहीं बोलना चाहिए। केवल इसी मार्ग को अपना कर एक राष्ट्र शक्तिदान के लिए उत्साह एवं स्वेच्छा प्राप्त कर सकता है जिसके बिना उसकी विदेश नीति शक्ति के अन्तिम मापदण्ड से बाहर नहीं निकल सकती।

अनेक मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ होती हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों की विचारधाराओं को अपरिहार्य रूप से प्रभावित करती हैं तथा उन्हें शक्ति के सघर्ष में अस्त्र बना देती हैं। यदि हम उदाहरण के लिए दो सरकारों को लें जिनमें से एक सरकार अपनी विदेश नीति को बौद्धिक भाग्यताओं एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर अपनी जनता के प्रसारित करती है और दूसरी सरकार ऐसा नहीं कर पाती तो निश्चय ही हम पहली सरकार को दूसरी की अपेक्षा अधिक लाभ में पावेंगे। मारगेन्वी ने सही लिखा है कि

1. John Adams, Quoted by Morgenthau, op cit, P 88

विचारधारामें समस्त विचारों की भाँति ऐसे हथियार होते हैं जो कि राष्ट्रीय मारेल को उठा सकने हैं और इसके साथ ही एक राष्ट्र की शक्ति का बड़ा तत्व हैं। ऐसा करके वे अपने विरोधी के मारेल को नीचा कर सकने हैं। वहाँ जाता है कि बड़े विद्वान के चौदह मूल्यवान् प्रयोग विश्व युद्ध में 'मैं' राष्ट्रों की भाँति में बहुत सहायक दिखा क्योंकि इनसे उनका मारेल बड़ा गया था और विरोधियों का मारेल नीचा हो गया था।

विचारधारा के प्रकार (The Types of Ideology)

विचारधारा शब्द का जन्म हुए सौ वर्ष के आसपास हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग डेस्टुट डि ट्रैसी (Destutt de Tracy, 1754-1836) द्वारा किया गया जबकि अन्य लोगों के अनुसार जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham) या नेपोलियन ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। पारमर तथा पॉकिंस का यह कहना उचित प्रतीत होता है कि यद्यपि विचारधारागत तत्त्व इतिहास की शताब्दियों तक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के निरन्तर तत्व रहे हैं किन्तु बीसवीं शताब्दी से पूर्ण उनका कदाचित् ही निष्पत्तिक महत्त्व था। आज हम जिनको विचारधारा कहते हैं वे अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में नई जान फूँकने का काम कर रहे हैं। इस प्रसंग में जोसेफ रोजेक (Joseph Roveck) का यह कथन भी समान रूप से महत्त्व रखता है कि हमारा युग ही वह पहला युग नहीं है जिसने कि विचारों की नवीन व्यवस्था को उत्पन्न किया है या जो कि विचारधारागत सपनों से युक्त है। किन्तु फिर भी सोलहवीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों को छोड़ कर ऐसा कोई युग नहीं रहा जबकि इनके प्रकार के विचार ही।

विचारधारा को जिस रूप में परिभाषित किया गया है वह प्रत्येक भाषा में पर्याप्त महत्वपूर्ण है। विश्व राजनीति में विचारधारामें का महत्त्व इसलिए बड़ा गया है क्योंकि वे राष्ट्रीय शक्तियों से सम्बन्ध रखती हैं। जिस प्रकार शक्ति महत्त्वकांक्षी राष्ट्रवाद का जन्म बनी उसी प्रकार से यह विचारधारामें का साधन बन गई है। वेने सपांसोरी विचारकों को मान्यता इससे विपरीत है क्योंकि वे शक्ति को तत्त्व एवं विचारधारामें की साधक कहते हैं, किन्तु दूसरे विचारकों के मतानुसार अब तक किसी प्रकार की शक्ति विचारधारा के साथ नहीं है उन समय तक यह विचारधारा निर्विकल्पक एवं सम्बन्धित विचारों का हानि रहित योग्य मात्र रहेगा। इस मत को मानने वालों का यह दावा है कि साम्यवाद को ऊपर उठाने वाला मार्क्स

या लेनिन का उपदेश नहीं है वरन् सोवियत शक्ति है जो इनके पीछे कार्य कर रही है। शक्ति के बिना साम्यवाद एक निष्क्रिय मनोविशेषण मात्र बन जाएगा।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधाराओं के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करने में पूर्व यह उपयोगी रहेगा कि उससे बढ़ते हुए महत्व के कारणों का अध्ययन किया जाय। विचारकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विचारधारा के बढ़ते हुए महत्व के लिए दो उत्तरदायी कारण बताए गए हैं। प्रथम कारण यह है कि विचारधाराओं में प्रमुख समस्याओं—याने—अनेक शक्तिशाली ऐसे राज्यों का विकास—हो-गया—है—जो कि—उत्साहवादी-राजावादी के पश्चिमी विश्व की परम्पराओं पर निर्भर, उदार एवं प्रजातन्त्रवादी समाजों का स्पष्ट विरोध करते हैं। सन् १९१७ में रूसी साम्यवादी क्रांति और उसके बाद इटली की फासिस्टवादी और जर्मनी की नाजीवादी विश्व इतिहास की मुख्य घटनाएँ थीं। इन विचारधाराओं का सम्बन्धित देशों की विदेश नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इस प्रकार दूसरे देशों के साथ उनके सम्बन्धों में भी अनेक मोड़ आए। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव राष्ट्रवादी शक्ति सन्तुलन से विचारधारागत शक्ति सन्तुलन की ओर मुड़ गई है।

विचारधारा के महत्व का एक दूसरा कारण यह है कि आजकल नीति निर्माण पर जन साधारण का प्रभाव बढ़ गया है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में सामान्य जन सक्रिय रूप से रुचि लेने लगे हैं। ई. एच. कार (E. H. Carr) के कथनानुसार सन् १९१४ के पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का व्यवहार केवल उन लोगों की रुचि का विषय था जो व्यावसायिक रूप से सलग्न हैं। प्रजातन्त्रवादी देशों में विदेश नीति को परम्परागत रूप में दलीय राजनीति के क्षेत्र से बाहर समझा जाता था तथा प्रतिनिधि सभाओं विदेशी कार्यालयों के रहस्यपूर्ण व्यवहार पर बड़ा निम्न-ग्रह रतने में अपने आपको योग्य नहीं मानती थी।^१

बैसे विदेश नीति के अनेक विषय ऐसे होते हैं जो विशेषज्ञों को सोच जान चाहिए। इनमें से कुछ विषयों पर तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि वे उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। ये विषय संगठित समूहों के

1. Edward Hallett Carr, The Twenty Years Crisis, 1919-1939, 2nd ed., 1946, P. 1

विशेष हितों को प्रभावित नहीं करते तथा उन लोगों की सामान्य स्वीकृति पर आधारित रहने हैं जो कि राजनैतिक रूप से जागरूक हैं।

भारत के युग में वैदेशिक मामलों में नागरिकों के जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करने हैं। इसने पर भी जनता विदेश नीति के निर्मादकों पर निर्भर रूप से अपना प्रभाव नहीं रख पायी। वह उपलब्ध विवेका के चयन में भी विशेष योगदान नहीं रखती। इसने पर भी नीति निर्माता मंदिर ही जनमत को ध्यान में रखते हैं। जनता के दृष्टिकोणों, विश्वासों, मूल्यों एवं लक्ष्यों की अवहेलना करके वे अधिक समय तक काम नहीं चला सकते। प्राचीन काल के तानाशाहों की भाँति जनता की धर्मस्थितियों का विचार किए बिना ही भारत में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते। प्रजातन्त्रात्मक देशों में तो प्रजा का सहयोग अनिवार्य सम्मान ही जाता है, सम्पूर्णतावादी राज्यों में भी यह विशेषता महत्व रखती है। सम्पूर्णतावादी राज्य अपनी जनता के मतों की अवहेलना करने की अपेक्षा जनमत को अपनी नीतियों के अनुकूल ही रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने के लिए उनके द्वारा दो मार्ग अपनाए जाते हैं। प्रथम यह कि जनता को यह सूचना प्रदान नहीं की जाती जो नेताओं द्वारा उनके हित के विपरीत मानी जाती है। दूसरे, वे इस सूचना को ऐसा सैद्धांतिक रूप प्रदान कर देते हैं जो शासन के दृष्टि में होता है। यद्यपि प्रजातन्त्रात्मक सरकारें भी जनहित की दृष्टि से विचारों पर नियन्त्रण रखती है किन्तु उनके द्वारा रखे जाने वाले नियन्त्रण की भाषा सम्पूर्णतावादी राज्यों की तुलना में कम होती है। यह कहा जाता है कि जनता की विचारधारा यद्यपि अत्यन्त अस्पष्ट और उलझी हुई होती है किन्तु यह विदेश नीति के निर्णयों के लिए कुछ व्यापक बाहरी सीमाएँ निर्धारित कर देती है। साथ ही यह एक ऐसे साधन का काम करती है जो सरकार द्वारा स्वीकृत नीतियों एवं लिए गए निर्णयों पर जनता का समर्थन प्राप्त कर सके। जिस समय विचारधारा की जाँच का समर्थन प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है उस समय इसका बोद्धिकीकरण (Rationalisation) किया जा सकता है; प्रयत्न नीति के वास्तविक कारणों को चेतन प्रयत्न अभेदन रूप में दिया गया जाता है और उसका आधार विचारधारा की दृष्टि दिया जाता है। यह भी हो सकता है कि नीति यथार्थ में विचारधारा के कुछ पहलुओं से प्रेरित एवं निर्दिष्ट हो।

विचारधारा के महत्व का एक अन्य आधार यह है कि राजनीतियों का कई चीजें विदेशों की जनता से भी दिया कर रखनी होती है क्योंकि

उन देशों की विदेश नीति का प्रभाव उनके स्वयं के निर्णयों पर पड़ सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो 'सूचना' कार्यक्रम का नया विकास हुआ है वह विकास कूटनीति के इस नए प्रकार का प्रमाण है। आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देशों ने कुछ पक्षों को चुन लिया है जिनका प्रयोग करके वे अपने देश के आदर्श तथा एवं मानवीय दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं तथा अपने विरोधियों की प्रालोचना करते हैं। विरोधी नीतियों को साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी, विस्तारवादी, विध्वंसक आदि कह कर प्रालोचित किया जाता है और दूसरी ओर अपनी नीतियों को साम्राज्यवाद विरोधी, मानवीय, उपनिवेशवाद विरोधी बना कर उसके लिए सम्मान प्राप्त किया जाता है।

प्रचार कार्य की प्रभावशीलता के परिणामस्वरूप एक देश अपनी राष्ट्रीय शक्ति को पर्याप्त बढ़ा लेता है। विचारधारा उसके इस प्रकार कार्य को सशक्त बना देती है। अधिक जनसंख्या वाले नये विकासशील देशों में लोगों के मस्तिष्कों को प्रभावित करने की सम्भावनाएँ अधिक रहती हैं। अतः यहाँ के लोग विचारधारा को अत्यधिक महत्व देते हैं। इन देशों की परम्परागत सामाजिक एवं बौद्धिक नींव कमजोर पड़ जाती है तथा ये मजबूत की अवस्था में रहते हैं। यहाँ पर राष्ट्रवाद एक बौद्धिक शक्ति के रूप में कार्य करता है। महात्मा गांधी ने इन प्रदेशों में लोगों को एकीकृत करने में पर्याप्त योगदान किया है तथा इन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता दी है किन्तु फिर भी ग्लाइसर महाशय का विचार है कि यह राष्ट्रवाद तीन दृष्टियों में अपर्याप्त है। प्रथम, यह वास्तविकता का कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता, दूसरे, यह मूल्यों के सतोषजनक दर्शन के रूप में अपर्याप्त है, तीसरे, यह उन आवश्यक आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थाओं के बारे में कुछ नहीं कहता जो कि जनता की बदलती हुई एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं को अनुकूल कर सकें। इस प्रकार इन देशों में एक प्रकार का रिक्त स्थान है जिम्मेरी पूर्ति के लिए विभिन्न विचारधाराएँ प्रयास करती हैं। एक विचारधारा सभी प्रभावशील हो सकती है जबकि यह स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप हो। एक बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि इस विचारधारा को राष्ट्रवाद की भावनाओं को विरोध नहीं करना चाहिए। मार्क्स तथा लेनिन की विचारधारा को इन प्रदेशों के अनुकूल समझा जाता है क्योंकि इनमें पर्याप्त लोकशीलता रहती है जो इसे परिस्थिति के अनुकूल परिणामित होने की क्षमता प्रदान करती है। साम्यवादी विचारक साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद

का विरोध करने इन देशों के लोगों की भावनाओं को अपने साथ मिला लेते हैं। साथ ही वे इन देशों में फैली हुई गरीबी को मिटाने के लिए उपाय भी सुझाते हैं। साम्यवादी कम और चीन ने छोटे से समय में जा प्राथमिक विज्ञान किया है उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने साम्यवाद इन देशों के भावपूर्ण का केन्द्र बन गया है। जो देश साम्यवाद के सर्वाधिकारवादी रूप में विश्वास नहीं करते वे भी यह तो स्वीकार करते हैं कि पश्चिमी प्रजातन्त्र की परम्पराओं उनके वातावरण के अनुकूल नहीं हैं।

विचारधारा के रूपों के सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि 'बाद' बहे जाने वाले समस्त विचारों को हम विचारधारा कह सकते हैं क्योंकि विचार जब 'बाद' का रूप धारण कर लेता है तो वह एक संगठित बिकार बन जाता है। इन दृष्टि से सर्वाधिकारवाद (Totalitarianism), साम्यवाद (Communism), फासिस्टवादी (Fascism), नाज़ीवादी (Nazism), समाजवाद (Socialism), उदारवाद (Liberalism), समष्टिवाद (Collectivism) आदि सभी को हम विचारधारा के विभिन्न रूप मान सकते हैं। पारस्परिक परस्परिक न तो प्रजातन्त्र, ईसाई धर्म एवं इस्लाम धर्म को भी विचारधारा कहा है।

मार्क्सवादी महाम्य ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न विचारधाराओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार कुछ विचारधाराओं ऐसी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव (Status-quo) बनाए रखना चाहती हैं। दूसरे प्रकार की विचारधाराओं विस्थापनवादी नीति अपनाती हैं और इसलिए उन्हें 'साम्राज्यवादी' कहा है। तीसरे प्रकार की विचारधाराओं अनेकार्थक एवं अस्पष्ट होती हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि साम्राज्यवादी नीतियों पर हमला ही विचारधारा का पदो धोना जाता है। किन्तु यदि देश बदलाव का समर्थन कर रहा है तो वह अपनी नीतियों को अपने मथारों रूप में प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचारधाराओं के कुछ प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों के कुछ प्रकारों के साथ समन्वित रहते हैं।

बदलाव की विचारधाराएँ

जो देश बदलाव की नीति में विश्वास करता है वह अपने व्यवहार को विचारधाराओं के आधारों से दिशाना नहीं चाहता। इसका

कारण यह है कि वस्तुस्थिति का अस्तित्व होता है और इस आधार पर उसे कुछ नैतिक न्यायोचितता प्राप्त हो जाती है क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व है उसमें कुछ न कुछ अच्छाईया तो अवश्य ही होगी वरना उसका अस्तित्व ही न रहता। जो देश यथास्थिति की नीति को अपनाता है वह उस शक्ति की रक्षा का प्रयास करता है जो कि उसने प्राप्त की हुई है। इसके लिए सम्भव है कि वह किसी को भी अपना शत्रु या मित्र न बनाए। ऐसा वह केवल तभी कर सकता है जबकि उसके क्षेत्रीय स्वामित्व को कोई कानूनी या नैतिक चुनौती नहीं दी जाती। स्विटजरलैण्ड, डेनमार्क, नार्वे, स्वीडन आदि देश अपनी विदेश नीति को यथास्थिति बनाए रखने वाली नीति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि उनकी यथास्थिति को न्यायोचित मान लिया गया है। अन्य देशों ने जैसे कि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया एवं रूमानिया आदि ने दो विश्व युद्धों के बीच में यथास्थिति की नीति को अपनाया। किन्तु ये देश यह घोषणा नहीं कर सकते थे कि उनकी विदेश नीति का लक्ष्य उनकी प्राप्तियों की रक्षा करना है। इसका कारण यह था कि सन् १९१९ की वस्तुस्थिति को इन देशों में आन्तरिक रूप से एवं बाह्य रूप से चुनौती दी जाती थी। अतः इन देशों को इस चुनौती का सामना करने के लिए आदर्श सिद्धान्तों की रचना करनी पड़ी। अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं शान्ति के आदर्शों द्वारा उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति की।

जो देश यथास्थिति की नीति को अपनाता है वह आवश्यक रूप से शांति एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून का समर्थक बन जाता है। दूसरी ओर साम्राज्यवादी नीतियाँ यथास्थिति में रहोउदन करने के लिए प्रायः युद्ध का मार्ग भी अपना लेती हैं और इस प्रकार वह युद्ध की सम्भावना को सदैव ध्यान में रखती हैं। जो विदेश नीति शान्तिवाद का समर्थन करती है, वह साम्राज्यवाद का विरोध करती है तथा यथास्थिति को बनाये रखने का पक्ष लेता है। जब एक राजनीतिज्ञ अपनी यथास्थिति की नीति के लक्ष्यों को शान्तिवादी रूप में अभिव्यक्त कर देता है तथा अपने साम्राज्यवादी विरोधियों पर युद्ध प्रेमी होने का आरोप लगाता है तो वह अपनी तथा अपने देशवासियों की नैतिक चेतना को उभार देता है और ऐसी स्थिति में वह उन सभी देशों का समर्थन प्राप्त करने की आशा कर सकता है जो कि यथास्थिति में विश्वास करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आदर्श भी यथास्थिति की नीति के लिए समान मेटा-नैतिक कार्य करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्य की सामाजिक

शक्ति होता है। यह कुछ शक्तों में शक्ति के विवरण को परिभाषित करता है तथा कुछ ऐसे मापदण्ड प्रदान करता है जिनके द्वारा इसे प्रयुक्त किया जा सकता है।

यथास्थिति की नीति का समर्थन करने के लिए कभी-कभी राष्ट्र सच जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सपटन को भी प्रयोग में लाया जाता है। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद से ही इस नीति का समर्थन प्रायः कानूनी विचारधाराओं के आधार पर ही किया जाता है। यथास्थिति का बनाम राजन का अन्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की रक्षा से लगाया जाता है। दोनों के बीच पारस्परिक शत्रुता सम्बन्ध बना कर ही इस नीति के मानने वाले अपने समर्थकों की सहायता बढ़ाते हैं। यह नीति सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की ओर भी प्रेरित हो सकती है क्योंकि यथास्थिति को बनाये रखने के समर्थक देश इसे बदलने वाले देशों के विरुद्ध सगठित हो सकते हैं। यथास्थिति की नीति की एक अन्य विचारधारा यह है कि छोटे राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा की जाए। यह विचारधारा इसलिए आवश्यक बन जाती है क्योंकि यथास्थिति में किये जाने वाले परिवर्तन प्रायः छोटे राष्ट्रों की कीमत पर ही किये जाते हैं।

साम्राज्यवाद की विचारधारायें

जब कोई देश साम्राज्यवाद की नीति को अपनाता है तो उसे अवश्य ही एक विचारधारा की आवश्यकता पड़ती है। ये देश जिस विचारधारा को भी अपनाते हैं उसका औचित्य सिद्ध करना इन देशों का उत्तरदायित्व बन जाता है। इन देशों ने यह सिद्ध करना होता है कि वे जिन यथास्थिति को बदलने जा रहे हैं उसे बदला जाना जरूरी एवं उचित है। इनके दावों में शक्ति का नये सिरे से वितरण किया जाएगा वह नैतिक होगा तथा न्यायपूर्ण होगा। कोई भी युद्ध करने वाला देश अपने युद्ध का लक्ष्य सुरक्षा, सम्मान, सुविधा, उत्साह आदि किसी भी तत्त्व को बना सकता है।

साम्राज्यवाद की कुछ विचारधारायें कानूनी मान्यताओं का भी प्रयोग करती हैं, किन्तु ऐसा करते समय वे स्थित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हवाला नहीं देती। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रकृति कठोर एवं अपरिवर्तनीय होती है अतः उनको यथास्थिति का ही साथी मान लिया जाता है। दूसरी ओर साम्राज्यवाद की नीति गतिशील होती है। अतः गतिशील विचारधारा की ही आवश्यकता रहती है। कहा जाता है कि प्राकृतिक कानून का सिद्धांत साम्राज्यवाद को सैद्धांतिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है।

साम्राज्यवादी राष्ट्र स्थित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विरोध करने हैं क्योंकि वह यथास्थिति चाहता है; अतः उसे अन्यायपूर्ण बनाने हैं। उनके विरुद्ध उससे भी ऊँचा कानून बना देने हैं जो न्याय की मांगों को पूरा करता हो। नाज़ी जर्मनी ने वास्तविक सन्धि वाली संधिस्थिति को जब बदलने की मांग की तो उसका आधार समानता को बताया और कहा कि वास्तविक सन्धि में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था।

नाज़ी जर्मनी का उदाहरण तो ऐसा उदाहरण है जहाँ कि एक साम्राज्यवादी देश ने युद्ध में हारे हुए अपने भागों को वापिस लेने की मांग की थी, किन्तु यदि ऐसी स्थिति न हो तो भी साम्राज्यवादी देश कमजोर देशों की सत्ता को स्वीकार समान सकता है; और यह सब करते समय वह नैतिकता एवं मानवीयता के नाम की दुहाई देता है। वह इसे गौरे सोपों का दासित्व या ईसाइयों का वर्तमान या राष्ट्रीय मिशन आदि कुछ कह कर अन्यायपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास करता है। उपनिवेशी साम्राज्यवाद को ऊँचे ऊँचे सौदानीय तारों के नीचे ढबाने का प्रयास किया जाता है। अरब विस्तार के काल में अरब साम्राज्यवाद को यह कह कर जासोबिन ठहराया जाता है कि यह धार्मिक वर्तमानों को पूरा करने के लिए उल्लेखनीय था। इसी प्रकार नरेशियन का साम्राज्यवाद, स्वतन्त्रता, समानता एवं बहुपक्ष के नाम पर योरोप भर में फैल गया। इसी प्रकार रूसी साम्राज्यवाद विश्व शांति एवं पूँजीवादी धर्म के विरुद्ध सुरक्षा के नाम पर फैल रहा है। अमरीकी साम्राज्यवाद भी साम्यवाद से सुरक्षा एवं स्वतन्त्र दुनिया के हिस्से की रक्षा के नाम पर बढ़ रहा है।

आधुनिक समय में डार्विन तथा स्पेन्सर के सामाजिक दर्शनों के प्रभाव में साम्राज्यवादी विचारधाराओं ने जीव शस्त्रीय तरीकों को प्राथमिकता प्रदान की। योग्यता की विजय एवं अस्तित्व के लिए मरण के सिद्धांतों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में ला दिया गया है। इससे परिणामस्वरूप सैनिक शक्ति की दृष्टि से उच्च देशों को कमजोर देशों की अपेक्षा अधिक सम्मान दिया जाता है। इस दर्शन के अनुसार यदि शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों पर प्रभाव नहीं रखता अथवा कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के बराबर होने का प्रयास करता है तो यह बात प्रकट कि विरुद्ध मानी जायेगी क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार तो शक्तिशाली एवं योग्यता की विजय होनी ही चाहिए। शक्तिशाली राष्ट्र का स्थान सर्वोच्च है तथा वह पृथ्वी पर रत्न की भाँति है। एक अतिरिक्त अर्थन सम्राज्यवादी का बहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जर्मन हारों की शिष्टेय के दुःखानाशों के ऊपर

जीत हाना अवश्यम्भावी था । जो जलिया कमजोर व घटिया दर्जे की हैं उनको अपने में उच्च जातियों की सेवा करना ही चाहिए । यह प्रकृति का कानून है और केवल दुष्ट व्यक्ति तथा मूर्ख ही इसका विरोध करेंगे ।

ये जीवनास्त्रीय तर्क फासीवाद, नाजीवाद एवं जापान के साम्राज्यवाद द्वारा दिये गये । इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रकृति ने इन राष्ट्रों को परती का स्वाभित्व करने के लिए भेजा है और जो इस कार्य में बाधा डाल रहा है वह प्रकृति के नियम का विरोध कर रहा है । इन तीनों राष्ट्रों ने बताया कि यद्यपि प्रकृति ने हमें विश्व का स्वाभित्व करने के लिए भेजा है किन्तु कमजोर राष्ट्रीय की चालाकी और हिमा के कारण वे अपने निश्चित पद पर नहीं हैं । इन राष्ट्रों की उन पूँजीवादी राष्ट्रों से लड़ना चाहिए ताकि अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें तथा जर्मनी, जापान और इटली अत्यधिक जनसंख्या के कारण अपनी विचारधारा को प्रभावशील रूप में प्रस्तुत कर सकें । उनका कहना था कि जर्मनी के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है । यदि वे अतिरिक्त भूमि प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो समाप्त हो जायेंगे । यदि उनको पच्चे माल के और स्रोत नहीं मिलें तो वे भूखे मर जायेंगे । कुछ थोड़े बहुत अन्तर के साथ यही विचारधारा इटली और जापान द्वारा अपनी प्रसारवादी नीतियों को उचित ठहराने के लिए और साम्राज्यवादी लक्ष्यों को छिपाने के लिए प्रयुक्त की गई ।

साम्राज्यवादी व्यवहार को न्यायोचित बतान तथा छिपान के लिए देश साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा को अज्ञात है । इस विचारधारा के अनुसार एक देश यह सिद्ध करता है कि दूसरे देश शक्ति प्राप्ति की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर अपनी नीतियों को संचालित कर रहे हैं तथा उसकी स्वयं की नीतिमा शुद्ध रूप से भावार्थ उद्देश्यों की ओर प्रेरित है । इस विचारधारा को इसलिए अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह साम्राज्यवाद की विचारधाराओं में सर्वाधिक प्रभावशील है । हुएलंग (Hucylong) के कथनानुसार समुक्त राज्य अमेरिका में 'फासीवाद' फामीवाद विरोधी के रूप में आया । इसी प्रकार अनेक देशों में 'साम्राज्यवाद' साम्राज्यवाद विरोधी पदों में छिप कर आता है । पिछले दोनो महायुद्धों में नाग लेने वाले दोनो पक्षों का दावा था कि वे दूसरे पक्ष के साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी रक्षा कर रहे हैं । जर्मनी ने जब सन् १९४१ में सोवियत रूस पर आक्रमण किया तो यह कहा था कि वह सोवियत संघ के साम्राज्यवादी दुरादों को तोड़ने के लिए ऐसा कर रहा है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से

साम्प्रदायी एवं गैर-साम्प्रदायी दोनों गुटों के राष्ट्रों की विदेश नीतियाँ साम्राज्यवाद के विरुद्ध संचालित हो रही हैं। इस प्रकार के तर्कों के आधार पर एक देश अपनी जनता में सद्बुद्धि एवं विश्वास जागृत करके उनके कार्यों को न्यायोचित ठहराता है और उसके बाद वह जनता देश की विदेश नीति का सच्चे दिल से समर्थन करती है तथा इसके लिए सफलतापूर्वक लड़ती है।

अनेकार्थक एवं अस्पष्ट विचारधाराएँ

साम्राज्यवाद विरोधी विचारधारा की प्रभावशीलता उसकी अस्पष्टता एवं अनेकार्थकता से आती है। इस विचारधारा में देखने वाला निश्चिन्त रूप से यह नहीं जान पाता कि वह साम्राज्यवादी विचारधारा पर विचार कर रहा है अथवा यथास्थिति की नीति की सच्ची अभिव्यक्ति पर विचार कर रहा है। ऐसा प्रायः तब होता है जबकि एक विचारधारा किसी विशेष नीति को समर्थित करने के लिए नहीं अपनाई जाती और उसे यथास्थिति के समर्थकों एवं साम्राज्यवाद के समर्थकों दोनों ही द्वारा अपना लिया जाता है। उदाहरण के लिए शक्ति सन्तुलन (The Balance of Power) को लिया जा सकता है। अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताब्दी में इसे यथास्थिति के समर्थकों एवं साम्राज्यवाद के समर्थकों-दोनों द्वारा एक सैद्धान्तिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया। वर्तमान काल में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त और संयुक्त राष्ट्र सभ इस कार्य को निभा रहे हैं।

राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के आधार पर केन्द्रीय एवं पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रीयताओं की विदेशी प्रभावों से स्वतन्त्रता को उचित ठहराया गया। सैद्धान्तिक रूप से इसका विरोध किया गया था, किन्तु राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के आधार पर पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था को मिटाना उचित बताया गया। पोलैण्ड, रूमानिया, यूगोस्लाविया आदि देशों में पुरानी साम्राज्यवादी व्यवस्था हट गई तथा एक रिक्त स्थान बन गया। इस स्थान पर नवीन स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने लगे। जो ही उन्होंने शक्ति प्राप्त की तो वे अपनी नई यथास्थिति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का समर्थन करने लगे।

हिटलर ने अपने प्रचार कार्य की प्रभावशीलता के कारण राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर बरारी चाट की ताकि वह अपनी प्रादेशिक प्रसार की नीतियों को दिया मके एवं उचित ठहरा सके। चैंकोवोवाकिया और पोलैण्ड में रहने वाले जर्मन अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के भंडे के नीचे इन देशों के राष्ट्रीय अस्तित्व को मिटाने के लिए वही कार्य करने लगे

जा कि चैंक्सलोवाक और पोलिस राष्ट्रीयताओं ने इसी सैद्धान्तिक नज़रे के नीचे आस्ट्रिया हंगरी के साम्राज्य को मिटाने के लिए किया था । इस प्रकार साम्य की सन्धि की दशास्थिति से लाभान्वित होने वाले देशों का सैद्धान्तिक हथियार उन्हीं के विरुद्ध चला गया । अब उनके पास दशास्थिति की रक्षा करने के लिए कोई विचारधारा नहीं रही और अब वे कानून और व्यवस्था की दुहाई देने लगे । चैंक्सलोवाकिया के संवत्स में आधुनिक समझौता हुआ उनमें भी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धान्त उलझा हुआ था । इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विचारधाराओं का जो महत्व एवं प्रभाव रहा उसका उदाहरण मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलता । इस काल में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की दृष्टांत एवं अनेकार्थक विचारधारा का अधिकतम प्रयोग किया गया ।

संयुक्त राष्ट्र संधि की जब स्थापना की गई तो उसे चीन, फ्रांस, ब्रिटन, सोवियत संध तथा संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दशास्थिति को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किया गया जो कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इन जो की विषय के कारण बनती थी । द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने के कुछ ही दिन बाद विभिन्न राष्ट्रों के विरोधी दावों एवं व्याख्याओं के कारण यह सिद्ध हो गया कि दशास्थिति बेवक्त सामयिक है । ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संधि की विचारधारा को इन देशों के द्वारा अपने लक्ष्यों को व्यापारित सिद्ध करने के लिए तथा अपने विरोधी दावों को दियाने के लिए प्रयुक्त किया गया । अब सभी राष्ट्र अपने आपको संयुक्त राष्ट्र संधि का एक ही समर्थक कहने लगे और अपनी विदेश नीतियों के समर्थन में उनके चार्टर का उद्धरण देने लगे । इन देशों की नीतियाँ परस्पर विरोधी होती हैं किन्तु फिर भी संयुक्त राष्ट्र संधि और उसके चार्टर का सन्दर्भ एक विचारधारागत प्रदात बन गया जिसके द्वारा एक देश की नीतिशासनात्मक रूप से समर्थित सिद्धांतों के प्रकाश में सही सिद्ध की जा सकें और उनकी सही प्रकृति को दियाना जा सके । संयुक्त राष्ट्र संधि के अनेकार्थक स्वरूप में एक ऐसा हथियार प्रदान किया जिसके द्वारा शत्रुओं का विरोध और मित्रों का समर्थन किया जा सके ।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शान्ति की विचारधारा भी इन बार्न की सम्पन्न करने में योग दे रही है । आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण युद्ध का स्वरूप पराजित विध्वंसकारी बन गया है और कोई भी देश अपनी विदेश नीति पर अपनी जनता एवं दूसरे देशों का समर्थन उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उनके

अभिप्राय शांतिपूर्ण हैं। अपने विरोधियों को बदनाम करने के लिए आज उन्हें 'शांति विरोधी' 'शानि धानी' एवं 'शांति विघ्नसक' आदि कहने का रिवाज हो गया है। आज शांति को दुहाई देना और अपने उद्देश्यों को शांतिपूर्ण बताना बिल्कुल अर्थहीन बन गया है क्योंकि कोई भी देश शांतिवादी विदेश नीति को आज इसलिये नहीं अपनाता क्योंकि उसे शांति से प्यार है वरन् इसलिए अपनाता है, क्योंकि वह युद्ध छेड़ कर जातिम नहीं लेना चाहता। वर्तमान युद्ध का अकल्पनीय विध्वंसिता के कारण प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को शांतिपूर्ण साधनों से प्राप्त करने का ही प्रयास करेगा। किन्तु फिर भी शांति का नाम लेकर एक देश दो महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य करता है। प्रथम, वह अपनी वास्तविक नीति के उद्देश्यों को छिपाना चाहता है और दूसरे, वह अपनी नीतियों के लिए सर्वत्र सद्भावना प्राप्त करना चाहता है।

प्रजातन्त्रात्मक एवं साम्यवादी विचारधाराएँ

(The Democratic and Communist Ideology)

यद्यपि प्रत्येक विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का प्रभावित कर सकती है किन्तु फिर भी जो विचारधारा एक संगठित आन्दोलन द्वारा समर्थित होती है अथवा जो राजनीतिक संस्थाओं का रूप ले लेती है उसका प्रभाव अधिक होता है। कुछ विचारधाराएँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों से दूर का रिश्ता रखती हैं अतः उनका प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम होता है। किन्तु जो विचारधाराएँ ऐसे मूल्यों को अभिव्यक्त करती हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ता उनका प्रभाव अधिक होगा। इस दृष्टि से राष्ट्रवाद का नाम लिया जा सकता है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मूल्यों को अभिव्यक्त करता है तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के निर्देशक का भी काम करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रवाद एक सार्वभौमिक विचारधारा है। यह अधिकांश साम्यवादियों, प्रजातन्त्रवादियों, फासीवादियों, आदि की विचारधाराओं का एक भाग है। राष्ट्रवाद के अतिरिक्त साम्यवाद भी अपने मित्रों, दुश्मनों एवं निष्पक्षों के मतानुसार एक सर्वाधिक प्रभावशील विचारधारा है। लगभग एक-तिहाई मानव जाति साम्यवाद के क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त प्रायः सभी राष्ट्रीय समाजों में साम्यवादियों का प्रभाव है। आज लगभग एक तिहाई सत्तार साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है। यह मत सभी विचारकों को मान्य नहीं है। कुछ का कहना है कि यह सत्य न होकर केवल भ्रम है और इसका कारण यह है कि साम्यवादी नेता अपने देश में जनमत पर नियन्त्रण रखते हैं, उसकी अवहलना करते हैं। एक

अन्य विचारधारा फासीवाद एवं नाज़ीवाद द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व इटली और जर्मनी में पनपी। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध में घुरी राष्ट्रों की हार के बाद एक सगठित शक्ति के रूप में यह समाप्त हो गई। बाद में कुछ देशों में इसे दूसरे नामों से तथा भिन्न माना न अपनाया गया। फासीवाद और साम्यवाद इनके प्रयोगों में एक जैसे घम हैं और दोनों के सिद्धांत पर्याप्त मेल पाते हैं किन्तु उदारवादी और प्रजातन्त्रात्मक विचारधाराएँ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रखती।

१९वीं शताब्दी के उदारवाद ने अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था कि समाजवाद के ठीक विपरीत है। किन्तु आज इस नीति को हर जगह अस्वीकार कर दिया गया है और इसलिए समाजवादी भी यह दावा करने लगे हैं कि वे अधिक उदार हैं। आज के स्वतन्त्र समाज की विचारधाराओं को अभिव्यक्त करने के लिए पूँजीवाद, उदारवाद, कल्याणकारी पूँजीवाद, प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिन देशों में प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था नहीं है वहाँ भी प्रजातन्त्र को अच्छी निगाह से देखा जाता है। साम्यवादी देश अपनी व्यवस्था के अतिरिक्त व्यवस्थाओं का प्रजातन्त्रात्मक मानने से इनकार करते हैं। उनका यह दावा है कि केवल साम्यवादी देश में ही अच्छा प्रजातन्त्र रह सकता है—अन्य देश तो नाम के लिए ही प्रजातन्त्रात्मक हैं। वास्तविकता यह है कि वे प्रजातन्त्र के नाम से अपने पूँजीवादी रूप पर पर्दा डालना चाहते हैं जिसमें कि शोषण है, अन्याय है, घनमानता है तथा अमानवीयता है। इस प्रकार वर्तमान विश्व मुख्य रूप से दो विचारधाराओं के प्रभाव में है—प्रजातन्त्र और साम्यवाद। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं तथा दोनों विरोधी लक्ष्यों की पूर्ति का साधन बन रही हैं। इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है—

(१) प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा (The Democratic Ideology) — यहाँ प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा से हमारा अर्थ सौधानिक प्रजातन्त्र से है; यद्यपि गैरे तो साम्यवादी भी अपने आपको प्रजातन्त्रवादी कहते हैं तथा उनका दावा है कि उनके यहाँ प्रजातन्त्र का व्यवहार होता है, वह केवल कागज पर लिखे गये कुछ अधिकारों का सकलनमात्र नहीं है। सौधानिक प्रजातन्त्र देश के संविधान को प्रजातन्त्रात्मक रूप देने पर अधिक जोर देता है और इसका विश्वास है कि ऐसा करने से प्रजातन्त्र धीरे धीरे किन्तु निश्चित रूप में स्वतः हो आ जायेगा।

प्रजातन्त्र को एक विचारधारा के रूप में तथा व्यवहार के एक तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसे मूल्यों की व्यवस्था तथा

निर्यय लेने का एक तरीका माना जाता है। इस प्रकार 'प्रजातन्त्र' समाज की सामान्य प्रवृत्ति का प्रदर्शन करना है। प्रजातन्त्र का केन्द्र बिन्दु प्रत्येक व्यक्ति की समानता एवं सम्मान को समझना जाता है। उदार सर्वमानिक प्रजातन्त्र की वर्तमान विचारधारा का जन्म मानवतावादों एवं ईसाई धर्म की सामान्य परिवर्तनी परम्पराओं में हुआ है। इसके विकास पर उन विचारों का प्रभाव पड़ा है जो कि १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ग्रट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, आदि देश में पनपे तथा प्रचारित हुए। प्रजातन्त्र कोई एक सक्षिप्त धर्माचरण नहीं है जो कि किसी एक पुस्तक के कुछ पृष्ठों में पाया जाना हो जहाँ से पढ़ कर उसे समझा जा सके। इसके विपरीत प्रजातन्त्र तो उन अनेक सिद्धांतों एवं मान्यताओं का सङ्कलन है जो कि वाणिगटन, अर्थमंडल, विज्ञान, एवं क्लजबल्ट से लेकर आज तक के राजनैतिक विचारकों के लेखों में पाये जाते हैं। प्रजातन्त्र के ये सिद्धांत अनेक महत्वपूर्ण अभिनेत्रों में पाये जाते हैं जैसे मैगनाकार्टा, स्वतन्त्रता का अमरीकी घोषणापत्र, सघीय संविधान एवं अधिकार विधेयक, नागरिक कानून अधिनियम आदि।

प्रजातन्त्र की मूल रूप-रचना में कुछ केन्द्रीय विरवाम होते हैं। इन विश्वानों की साधना में सलग्न व्यवस्था को ही प्रजातन्त्रात्मक माना जा सकता है और जो व्यवस्था इनकी अव्यक्ति के मार्ग में बाधा बनती है वह अप्रजातन्त्रात्मक बही जाती है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था की ये मूल मान्यतायें निम्न प्रकार हैं—

१. प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से महत्व है। उसकी स्वतन्त्रता, सम्मान एवं कल्याण की रक्षा एवं अभिवृद्धि प्रत्येक राज्य का दायित्व है।

२. सरकार अपनी शक्तियाँ प्रणामितों की स्वीकृति में प्राप्त करती है। ऐसी स्थिति में जनता अपना प्रहामन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं ही करती है। उसे अपनी सरकार का रूप व सम्बन्ध में चयन की पूरी स्वतन्त्रता है।

३. सर्वमानिक व्यवस्था का यह उत्तरदायित्व है कि न्याय की अभिवृद्धि कर, कानून व शासन की स्थापना कर तथा व्यक्ति के न छीने जाने वाले अधिकारों की स्वच्छाचारों आचरण का विच्छेद रक्षा करे।

४. प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह शानदार आर्थिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करे। राज्य द्वारा उसे ऐसा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

५. व्यक्तियों तथा समूहों को अपने मिते मन एवं दृष्टिकोण प्रकट करने की म्यन-प्रवा रहनी चाहिए और राज्य का यह कर्तव्य है कि यह इन प्रकार की स्वतन्त्रता की रक्षा करे।

६. यह व्यवस्था अपने विधान के मार्ग पर है। यह नवीन परिस्थितियों में अपने मूल्यों को बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोजती है।

७. प्रजातन्त्रात्मक मूल्य उन अधिकारों पर जोर देते हैं जिनको सार्वभौमिक माना गया है।

प्रजातन्त्र के ये विश्वास राजनैतिक जीवन का रूप ढालने हैं। इनके आधार पर कुछ मौलिक मूल्यों, लक्ष्यों तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों के समायोजन के साधनों को सामान्य स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन विश्वासों की प्रकृति ही ऐसी है जो कि परिवर्तन के लिए अवसर प्रदान करती है। इनमें राजनैतिक प्रक्रिया के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। सधियों के समायोजन को आतिथ्य साधनों द्वारा सन्तुष्ट रूप प्रदान कर दिया जाता है।

प्रजातन्त्र की यह विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव रखती है। समानता का प्रजातन्त्रात्मक भावने केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक ही परिमित नहीं रह जाता, क्योंकि प्रजातन्त्र किसी एक देश विशेष के लोगों की समानता में ही विश्वास नहीं करता बल्कि वह तो मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास करता है। ऐसी स्थिति में इन भावनों को राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर भी लागू किया जा सकता है तथा किया जाना चाहिए। प्रजातन्त्रात्मक भावनों को जब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है तो अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं जो कि इसलिए उत्पन्न होती हैं कि राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर सामाजिक एकता एवं ठोसपन नहीं रहता; दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक समझौतों की तकनीकें प्रभावशील नहीं हैं, और तीसरे, राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया प्रत्येक देश में चलती रहती है। यथाशक्ति महाशय का यह कथन पर्याप्त अर्थपूर्ण है कि चाहे कारण कुछ भी हो किन्तु समानता विरोधी प्रजातन्त्रात्मक भावनों को प्रजातन्त्रात्मक सरकारों एवं लोगों को भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने में रुझाई होती है।

प्रजातन्त्रात्मक भावनों की राष्ट्रवाद के साथ भी कुछ समझौते बसाई जाते हैं। यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र व्यक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य मानता है तथा राज्य को मानवीय कल्याण का एक साधन मात्र कहता है। दूसरी

और राष्ट्रवाद राज्य को सर्वोच्च मूल्य प्रदान करता है। प्रजातन्त्र 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रता' को भी उच्च मूल्य प्रदान करता है। प्रजातन्त्रात्मक देश का नागरिक अपने अधिकारों का पूरा ध्यान रखने हुए दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों को भी पूरा सम्मान देता है। वैसे पूर्ण स्वतन्त्रता तो एक अवावहारिक आदर्श है और आंशिक स्वतन्त्रता का अर्थ हमेशा कुछ लोगों की अधीनस्थता तथा कुछ लोगों का प्रभुत्व होता है। इन विरोधाभासों को कातून के अतर्गत स्वतन्त्रता की मान्यता द्वारा कम करने का प्रयास किया जाता है। स्वतन्त्रता केवल तभी रह सकती है जबकि एक मान्य व्यवस्था कायम की जाये।

प्रजातन्त्र का सम्बन्ध प्रत्येक जगह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अधिक से अधिक बनाने से रहता है। अतः यह स्वतन्त्रता को प्रत्येक बाधा का विरोध करता है। दूसरी ओर 'राष्ट्रवाद' व्यक्ति को राज्य का अधीनस्थ बना देता है। राष्ट्रवादी द्वारा राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर जोर दिया जाता है और इसलिये वह प्रत्येक बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है, चाहे वह प्रजातन्त्र के अनुकूल हो अथवा न हो। इस प्रकार राष्ट्रवाद और प्रजातन्त्र दोनों अपने शुद्ध रूप में साथ साथ नहीं चल सकते। इसके लिये एक सुझाव यह दिया जाता है कि मानवीय अधिकारों के विषय को राज्यों के क्षेत्राधिकार से निकाल लिया जाये तथा उनको अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दिया जाये।

प्रजातन्त्र की विचारधारा साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था में प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति को निर्णय लेने में हाथ बटाने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह स्वायत्त सरकार का एक मूल लक्ष्य तथा आदर्श है। किन्तु साम्राज्यवादी व्यवस्था में वेदम कुछ लोग अन्य सभी पर शासन करते हैं जिनको निर्णय लेने की प्रशिया में भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता। साम्राज्यवादी व्यवस्था को प्रजातन्त्रात्मक केवल तभी बनाया जा सकता है जबकि निर्णय की प्रशिया में भाग लेने से वंचित किये गये पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया जाये।

यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रजातन्त्रात्मक व्यवहार के प्रभाव का अध्ययन करें तो पायेंगे कि यह अनेक प्रकार से इसके व्यवहार का रूप निर्धारण करती है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रजातन्त्रात्मक व्यवहार यह होता है जहाँ जहाँ, धार्मिक, सामाजिक, एक राष्ट्रीय स्तर की, और ध्यान दिये बिना ही सभी व्यक्तियों के कल्याण का प्रयास करता है। इसके

प्रजातन्त्रात्मक रूप का अर्थ विशेष रूप से यह है कि किसी भी देश का कल्याण दूसरे देश के विरुद्ध नहीं किया जायेगा । एक को दबा कर अन्य को उठाना प्रजातन्त्रात्मक प्रक्रिया नहीं है । मादलों में यह है कि विश्व न्याय का सामाजिक तथा आर्थिक एकीकरण कर दिया जाये ।

दूसरे, एक राजन का मूल्यांकन इन आधार पर किया जायेगा कि उसने व्यक्तिगत सम्मान और गौरव की प्रमिष्टुष्टि में कितना योगदान किया है । ऐसा करने समय केवल उस देश के नागरिकों की दृष्टि में ही विचार नहीं किया जायेगा बल्कि सामान्य मानव जाति की दृष्टि से ही विचार किया जायेगा । राज्य अपने आपमें कोई सत्य नहीं होता है और इसलिए यदि राज्य किसी व्यक्ति या समुदाय की स्वतन्त्रताओं पर प्रतिबन्ध लगाता है तो उसे ऐसा करते समय व्यक्ति की अधिक स्वतन्त्रता एवं मूल्यों की रक्षा को ध्यान में रखना चाहिए ।

तीसरे, सम्प्रभुता मानवीय अधिकारों एवं अन्य मूल्यों की रक्षा के मार्ग में नहीं आनी चाहिए । उसे प्रजातन्त्रात्मक विचारों तथा विश्वासों के मार्ग की बाधा नहीं बनना चाहिए ।

चौथे, प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा उन तत्त्वों की स्थापना में सहयोग देगी जो व्यक्ति की शान्तिपूर्ण साधनों से उन महत्त्वपूर्ण निर्यातों के लेने में योगदान का अवसर प्रदान कर सकें जो कि उनके हितों एवं मूल्यों का प्रभावित करते हैं । समान व्यक्तियों द्वारा अनमान शक्तियों के उपयोग के प्रत्येक प्रयास को रोक जायेगा । प्रत्येक समूह को प्रतिनिधि नेजने तथा मतदान करने का अधिकार उनी अनुपात में सौंपा जायेगा जिनकी कि उनके सदस्यों की संख्या है । प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था अन्य व्यक्तियों पर कुछ व्यक्तियों के शासन का विरोध करती है अतः यह अतिव्यवस्था के प्रत्येक रूप का विरोध करेगी ।

पाचवें, प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा लोगों के शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए उपयुक्त एवं अनुकूल वातावरण संपाद करती है । साथ ही यह बहुमत की इच्छानुसार शान्तिपूर्ण परिवर्तन में विवनात करती है । दूसरी ओर इनके द्वारा कुछ प्रतिनात्मक सुरक्षाओं भी लगाई जायेंगी जिनके आधार पर अधिक से अधिक लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण की व्यवस्था की जा सके ।

ये कुछ प्रजातन्त्र की विशेषताएँ हैं जो कि अपने प्रभावशील रूप द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं । कुछ विचारकों का यह कहना है कि प्रजातन्त्रात्मक मूल्यों को प्रभावशील बनाने का प्रयास करना

उपयोगी रहेगा या नहीं रहेगा—इसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मानवीय इतिहास में ऐसे अनेक अत्याचारों के उदाहरण प्राप्त होते हैं जो कि अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गये थे। प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति विभिन्न दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों के प्रति सहनशील होता है। वह सभी सत्यों की ओर सदेहशील नजर से देखता है यहा तक कि स्वयं के सत्य पर भी उसे पूरा विश्वास नहीं होता।

(२) साम्यवादी विचारधारा (The Communist Ideology)—साम्यवाद की विचारधारा का रूप एक तत्त्व दोनों ही प्रजातन्त्र की विचारधारा से भिन्न होते हैं। साम्यवाद की प्रकृति मूल रूप से सत्तावादी होती है और इसलिए यह प्रजातन्त्र की अपेक्षा कम अस्पष्ट हो सकती है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था का कोई ऐसा प्रणेत नहीं है जैसा कि हमको साम्यवाद में देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्रजातन्त्र की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसे 'दास कॉपीटल' या 'साम्यवाद घोषणा-पत्र' की भांति गीता समझा जा सके। प्रजातन्त्र को लेनिन, स्टालिन, ख्रूशचेव या माप्रोत्सेतुज्ज जैसे नेताओं द्वारा सत्तापूर्ण व्याख्याएँ पदान नहीं की गई हैं। परिणामस्वरूप साम्यवाद के अनुयायी के लिए एक विशेष समय में पूर्ण सत्य का स्पष्ट ज्ञान हो सकता है। किन्तु एक क्षण का उसका पूर्ण सत्य दूसरे ही क्षण का पूर्ण असत्य भी बन सकता है।

कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माप्रोत्सेतुज्ज आदि के लेखों द्वारा साम्यवाद की जो विचारधारा सामने आई है उसकी अनेक मूल मान्यताएँ हैं। इन मान्यताओं में प्रथम यह है कि इतिहास एक निरन्तर सघर्ष की कहानी है जिसमें साम्यवाद की प्रगतिशील शक्तियों का पूँजीवाद की प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा विरोध किया गया है किन्तु वर्ग सघर्ष में पूँजीवादी शक्तियाँ समाप्त कर दी जायेंगी।—

७ दूसरे, साम्यवाद और उदार सवैधानिक प्रजातन्त्र के बीच मूलभूत सघर्ष है और इस केवल साम्यवाद की अन्तिम विजय द्वारा ही मिटाया जा सकता है। साम्यवादी दल तथा राज्य को अपने मारे साधन इस सघर्ष में प्रयुक्त करने चाहिए। ऐसा करते समय लेनिन का यह कथन ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ विजय अनिश्चित हो वहाँ निर्णयात्मक रूप में न उलझा जाये और जहाँ संवियत सघर्ष के माध्य के लिए जोखिम है वहाँ पूर्णतः निर्णयात्मक रूप से उलझना माना जायेगा।

तीसरे, साम्यवादी विचारधारा एक वर्गहीन समाज की रचना का समर्थन करती है तथा यह अन्तिम रूप से राज्य की समाप्ति के लिए प्रयत्न-

शील है। साम्यवाद के माध्यम से पूँजीगत श्रम का गरीब मजदूर वर्ग में पुनः वितरण किया जायेगा, आर्थिक विकास किया जायेगा तथा जनसाधारण का शोषण समाप्त किया जायेगा।

चौथे, साम्यवादी दल मजदूर वर्ग की तातागाही का प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी देशों में साम्यवाद की प्राप्ति का साधन है। साम्यवादी दल पूर्ण शुभ है। यह पूर्ण आजागरिता की न्यायोचित उहराता है।

पाचवें, साम्यवाद के लक्ष्य एवं तरीकों की दृष्टि से शक्ति एवं शक्ति समर्थन मूल साम्यवादी हैं। लेनिन, स्टालिन तथा माप्रोत्तेतुङ्ग आदि ने मुख्य रूप से शक्ति प्राप्त करने एवं एकीकृत करने की रणनीति तथा तकनीकों का वर्णन किया है।

छठे, विचारधारागत एवं दलीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपायों की सोचशीलता की अनुमति प्रदान की गई है। अनुयायियों को साम्यवाद के लक्ष्यों की साधना के लिए कोई भी साधन अपनाने की स्वतन्त्रता है। गैर-साम्यवादी व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, विरोधियों के विरोधों का नाम उठाने के लिए तथा कान्तिकारी दृष्टियों की रचना को प्रोत्साहन देने के लिए साम्यवादी अन्दोलन के कर्ता कोई भी साधन अपना सकते हैं।

साम्यवादी रुत एवं अन्य साम्यवादी देशों में साम्यवादी दल की शक्ति के एकाधिकार को विचारधारा के आधार पर न्यायोचित उहराया जाता है। इसके द्वारा राजनीति एवं क्रियाओं की वैधानिकता तथा वैधिकता को सिद्ध किया जाता है। साम्यवादी छोटे देशों में राज्य की विचारधारा सेवियत प्रभाव एवं निर्देशन के साधन के रूप में कार्य करती है। गैर-साम्यवादी देशों में यह दल के पक्के समर्थक छाटने का कार्य करती है। इस तथा अन्य साम्यवादी देशों में होने वाली सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति ने साम्यवादी सिद्धांत की व्याख्या करने में पर्याप्त सोचशीलता ला दी है। किन्तु चीन के साम्यवादी नेता मानते हैं कि लेनिन के कथनों के अनुसार चलना चाहते हैं और इन कथनों का जरा भी उल्लंघन करना उनकी दृष्टि से साम्यवाद के विरुद्ध है। सेवियत प्रवक्ताओं के द्वारा जो उदार व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं उनको चीनी नेता 'संशोधनवाद' कहते हैं तथा साम्यवाद के लक्ष्य से पीछे हट जाना मानते हैं। पहले साम्यवादी रुत तथा पश्चिमी शक्तिधर्मों के बीच एक स्पष्ट किन्तु कठो विभाजक रेखा थी तथा उनके बीच किसी प्रकार के समर्थ, सन्धि या विचार-विमर्श की भाशा ही नहीं की जाती थी, किन्तु आज रुत

का दृष्टिकोण कुछ उदार हो गया है। यद्यपि अब भी सोवियत सघ कुछ सीमाओं में रह कर ही पश्चिमी शक्तियों से बात करता है। साम्यवादी चीन की अपेक्षा इस में अधिक सहनशीलता है।

प्रजातन्त्र एवं साम्यवाद का इन दोनों विचारधाराओं के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान चाहे या अनचाहे रूप में अवश्य हो रहा है। फ्रांस, इटली आदि अनेक देशों में साम्यवादी दल कानूनी दल है तथा जनता के समर्थन को आकर्षित कर रहा है। यह सार्वजनिक मततोष का साम उठा कर तथा अपने दल के पक्ष में प्रचार करके चुनावों के समय पर्याप्त मत प्राप्त कर लेता है। इतने पर भी यह आशा नहीं की जा सकती कि किसी पश्चिमी प्रजातन्त्र में सामान्य स्थिति के अन्तर्गत साम्यवादी शासन स्थापित हो जायेगा।

[विश्व राजनीति के व्यापक पटल पर आज सोवियत सघ शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पक्षपाती बन गया है तथा पश्चिमी शक्तियों के साथ निःशस्त्रीकरण, आर्थिक सहयोग, विश्व शान्ति आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मिल कर चलने का प्रयास करता है। कुछ विचारकों का यह मत है कि सोवियत सघ की नीति में आये हुए इस परिवर्तन का कारण यह है कि वह पश्चिमी शक्तियों द्वारा उस पर रखी जाने वाली कड़ी नज़र एवं सावधानी को ढीला करना चाहता है। दूसरे, वह नव स्वतन्त्रता प्राप्त राष्ट्रों को यह दिखाना चाहता है कि अपने स्टालिन की आक्रमणकारी नीतियों को त्याग दिया है। ऐसा करके वह यथास्थिति को बनाये रखना चाहता है। इसका अर्थ यह नहीं होना कि साम्यवाद ने पश्चिम के साथ अपने सघर्ष को समाप्त कर दिया है।]

पश्चिम के साथ सोवियत सघ का सघर्ष आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। प्रत्यक्ष रूप से यह आर्थिक, राजनैतिक एवं प्रचार के शस्त्रों द्वारा सघर्ष में रत है तथा अप्रत्यक्ष रूप से इसने विश्वमण्डल देशों में मनमुटाव पैदा किया है। इन सघर्षों का परिणाम बहुत कुछ इन बातों पर निर्भर है कि विकासशील देशों में क्या होता है। सहायता कार्यक्रम, सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं राजनैतिक समर्थन आदि सभी कार्यों के पीछे एक ही लक्ष्य है और वह यह है कि इन देशों की मित्रता प्राप्त की जाये तथा भविष्य के लिए उनका प्रयासों को निर्देशित किया जाये।

साम्यवादी विचारधारा अब स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गई है। मास्को तथा पीकिंग के नेतृत्व के बीच जो सघर्ष की छाई बढ़ती जा

रही है उसकी कल्पना सन् १९१६ में नहीं की जा सकती थी। इस सघर्ष की स्थापना एवं प्रभाव पर्याप्त हैं। चीन के नेता यह मानने से मस्वीकार करने हैं कि सोवियत रुम विश्व साम्यवाद का नेता तथा संचालक है। इस प्रकार इन दोनों देशों के बीच विरोध पैदा हो गया है—यह विरोध नेतृत्व के लिए विरोध है। हमने उस आधार को नष्ट कर दिया है जिस पर कि सोवियत सघर्ष व साम्यवादी चीन के बीच सर्वप्रथम नाईचारे के सबन्ध स्थापित हुए थे। इन दो महा शक्तियों के मजबूती का प्रभाव केवल इनके पारस्परिक सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं रहता। यह विश्व साम्यवादी आन्दोलन में सघर्षों की रचना करता है। छोटे राज्यों का दलीय नेतृत्व भी एक कठिन स्थिति में आ जाता है क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि जिसके निर्देशनों को मानकर भागे बड़े। इससे एशिया और अफ्रीका के देशों में दोनों देशों की प्रतिद्वन्द्विता बढ़ जाती है। भारत पर चीनी आक्रमण के समय यह बात मिट्टी हो गई कि सावित्र सघर्ष एवं साम्यवादी चीन दोनों एक ही विचारधारा को मानने वाले देश होने हुए भी एक दूसरे के मध्य में कितने गहरा बन्धन बने है। भारत पर पाकिस्तानी आक्रमण के समय भी रुम द्वारा धमकाया जाने वाला खैसा साम्यवादी चीन द्वारा अनायास जाने वाले खैसा से भिन्न था।

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर विचारधारा का प्रभाव उतना नहीं है जितना कि यह जिस समय था। विश्व राजनीति में राज्यों के व्यवहार की प्रकृति महानविषय गुणान्त के इन कथन से स्पष्ट हो जाती है कि देश धान की स्थिति में कुछ नावनायों प्रदर्शित करते हैं, कुछ बड़ी प्रातिक्रियाएँ, कुछ कठोरताएँ और यहाँ तक कि कुछ अकड़पन भी।

साम्यवादी विचारधारा जिस रूप में साम्यवादी राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करती है उसे निर्धारित करना बड़ा कठिन है। विभिन्न समयों एवं स्थानों पर इसके अर्थ अलग-अलग रह हैं किन्तु फिर भी कुछ एक ऐसे तत्व हैं जो कि इन दृष्टि से महत्वपूर्ण मान जा सकते हैं। साम्यवादी देशों विरोध की पट्टामो को देखने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह विचारधारा यह मान कर चलती है कि इतिहास कुछ ऐतिहासिक बानूनों को मान कर चलता है जिन्हें नीतिज्ञ देशों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सत्ताएँ तथा सत्कृति और कुछ भी नहीं है वरन् सामाजिक विकास के एक विशेष स्तर पर पाई जान वाली नीतिक शक्तों की ही अभिव्यक्ति मात्र है। यद्यपि व्यक्ति ऐतिहासिक परिवर्तन के मूल रूप को नहीं बदल सकता किन्तु फिर भी वह आतिहास्य को सीझ ता सकता है।

यदि साम्यवादी देशों के निर्णायक अपनी विचारधारा को गम्भीरता के साथ मान कर चलें तो उनका विश्व के प्रति दृष्टिकोण अनेक प्रकार से प्रभावित होगा। प्रथम, साम्यवादी एवं पूँजीवादी राज्यों के बीच सघर्ष को अपरिहार्य माना जायेगा। दूसरे, यह समझा जायेगा कि समय साम्यवाद के पक्ष में है तथा पूँजीवादी राज्यों के विरुद्ध है। तीसरे, चीन और सोवियत संघ प्रगतिशील शक्तियों के नेताओं के रूप में अपने राष्ट्र-राज्यों की ओर में ही नहीं लड़ रहे हैं बल्कि प्रत्येक जगह रहने वाले सर्वहारा के लिए लड़ रहे हैं। वैसे लेनिन द्वारा विकसित साम्यवादी विचारधारा केवल यह कहती है कि पूँजीवाद में एकाधिकार के परिणामस्वरूप साम्राज्यवाद आता है और साम्राज्यवाद के परिणामस्वरूप पूँजीवादी राज्यों के बीच अपरिहार्य रूप से युद्ध होते हैं। साम्यवादी विचारधारा कही भी यह नहीं कहती कि साम्यवादी राज्यों को अपने हितों की साधना के लिए युद्ध का मार्ग अपनाना चाहिए। इतने पर भी साम्यवादी लोग यह कहते हैं कि प्रगतिशील शक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए न्यायपूर्ण युद्ध लड़ा जा सकता है। वैसे साम्यवादी लोग सघर्ष को अपरिहार्य मानते हैं किन्तु युद्ध को नहीं। इस प्रश्न पर लुश्चेव तथा माओ त्से तुङ्ग के बीच पर्याप्त मतभेद था। माओ के मतानुसार पूँजीवाद के साथ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का लुश्चेव का विचार लेनिन के सिद्धान्तों से भ्रष्ट होना है। जब हम सघर्ष को अपरिहार्य मान रहे हैं और समय हमारे पक्ष में है तो युद्ध क्यों न किया जाए। दूसरे सोवियत रूस के विचारक यह कहते हैं कि विजय के लिए कोई कार्यक्रम का समय निश्चिन नहीं है—कब हमें आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, यह घटनाओं के द्वारा तय किया जाएगा। यदि पूँजीवादी प्रजातन्त्र अपरिहार्य को रोक सकें तो वे अपने अन्त को भी अनिश्चित काल के लिए रोक देंगे। साम्यवाद की विचारधारा के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संहारा वर्गों की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए साम्यवादियों को प्रत्येक जाह नैतिक, प्राकृतिक एवं प्रगतिशील वर्गों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद को मुख्य स्थान देना चाहिए तथा सोवियत संघ और अन्य साम्यवादी राज्यों के हितों की साधना करनी चाहिए न कि अपने पूँजीवादी स्वामियों की। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार ऐसा करके वे साम्यवाद के उच्च उद्देश्य की पूर्ति करते हैं जिसकी साधना के लिए वर्तमान साम्यवादी राज्य प्रयास कर रहे हैं। स्टाइनर मन्दाप में कथनानुसार सत्ते में साम्यवादी विचारधारा सच्चे रूप में अन्तर्राष्ट्रीय है, जिसका आधार वर्गवाद है। राष्ट्रवाद के लिए वह जानी छुट्टी देती है वह अस्थायी है तथा इसकी रणनीति है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल्य और दृष्टिकोण (Values and attitudes in International Relations)

[अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवहार को समझने में हमें लेने वाले को यह मान कर चलना चाहिए कि मानवीय समूहों में अनेक दृष्टिकोण, विश्वास एवं मूल्य पाए जाते हैं।] मनुष्य भिन्न भिन्न सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और भौतिक वातावरण में रहते हैं। वातावरण की इन विशेषताओं द्वारा ही यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति का मित्र कौन होगा और उसका शत्रु कौन होगा। व्यक्ति अपने उपलब्ध साधनों की सीमितता को भी जान लेता है जिनके साथ रहने के लिए समायोजन करना जरूरी है। राजनैतिक एवं सामाजिक मूल्य तथा सहयोग की परम्पराएँ इसी पृष्ठभूमि में विकसित होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में यह विचार किया जाता है कि व्यक्ति कुछ मूल्यों को बरी अपनाता है और अन्य मरुति तथा शक्तियों के प्रभाव से वह उन्हें बर्मे बदल लेता है। एक राष्ट्र के लोगों के दृष्टिकोणों, मूल्यों एवं उद्देश्यों की समानता यह निर्धारित करती है कि उनके बीच विभिन्न प्रश्नों पर कितना मतभेद रहेगा। इसमें राजनैतिक सम्स्याओं का स्वाभाविक प्राप्ति होता है। जिन देशों के मूल्य और दृष्टिकोण मिल जाते हैं; उनके बीच सहयोग, शांति एवं विचार विमर्श की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर दृष्टिकोण और मूल्यों में भारी असमानता रहती है वहाँ सम्स्याओं की अभिरक्षा एवं संघर्ष पाया जाता है।

विभिन्न राज्यों की जनता और नेता अनेक विषयों पर अपना मत निर्धारित करते हैं और यह मत उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को प्रभावित करता है। शांति, युद्ध, साम्राज्यवाद, जातिवाद, पूँजीवाद, अणु शस्त्र एवं विदेशी सहायता आदि विषयों पर एक राज्य के लोगों तथा नेताओं का जो दृष्टिकोण होता है वही उसकी विदेश नीति को तय करता है। यह दृष्टिकोण उनके मूल्यों द्वारा लिया रत किया जाता है और मूल्य व्यवस्था ही यह तय करती है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह राज्य क्या साधन अपनाए। अनीत के अनुभव से इन दृष्टिकोणों एवं प्रतिनिधियों के निर्धारण में पर्याप्त महामत्वा मिलती है।

दृष्टिकोण वास्तविकता को स्पष्ट कर सकते हैं अथवा उसे ओभस्त्र बना सकते हैं। व्यक्ति की प्रश्रिया उसके वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। यदि व्यक्ति का एटलस यह कहता है कि पृथ्वी चपटी है तो वह उस जगह पर अपनी नान नही चलावेगा जहाँ कि उसके मतानुसार चिनारा है।

इस प्रकार वास्टर लिप्मैन ने यह सही करमाया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह उसके प्रत्यक्ष या निश्चित ज्ञान पर आधारित नहीं बरन् उन चिन्तों पर आधारित है जो कि उस ने स्वयं बनाए हैं, ~~अतः~~ उसे दिखे गए हैं।¹

संसार को वस्तुगत रूप से देखने में दो चीजें हमारी योग्यता को सीमित करती हैं। पहली बात तो यह है कि तथ्यों को जानने की व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। उसका ज्ञान अपूर्ण होता है और तथ्यों के समझने की उसकी योग्यता, समय, अनुभव, सम्पर्क एवं कुशलता के अभाव के कारण सीमित रहती है। लिप्मैन के ही कथनानुसार हमारे मन को एक व्यापक क्षेत्र से सम्पर्क रखना होता है, बहुत शीघ्र ही वस्तुस्थिति का पता लगाना होता है तथा इतनी सारी चीजें देखने को होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देखने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में हमें बहुत कुछ इन बातों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि दूसरों के द्वारा कही गई हैं और हम जिनको कल्पना कर सकते हैं। यह समस्या उस समय और भी कठिन बन जाती है जबकि समान तथ्यों वाले दो व्यक्ति निर्धारित कार्य के सम्बन्ध में विरोधी निष्कर्षों पर पहुँचते हैं।

तीसरा निर्धारित करने वाली दूसरी बात अत्यन्त भ्रष्ट एवं उलझी हुई है। यह अपने मनोवैज्ञानिक तत्वों का संयोग है। वास्तविकता को पहचानने की हमारी योग्यता, हमारे ज्ञान और दुराग्रह, हमारे पहले के प्रतीकों एवं हमारे तरीकों द्वारा सीमित होती है। व्यक्ति ने दुनिया के बारे में जो स्वयं की मान्यताएँ बना रखी हैं वह अपने सीमित ज्ञान को उमी में बँटाने की सोचता है। व्यक्ति की पूर्ण मान्यताएँ एक प्रकार से सुरक्षा यंत्र का काम करती हैं जो कि दुनिया की तस्वीर को इस रूप में रखने में मदद करती हैं जिसके साथ वह समायोजित हो चुका है। व्यक्ति के मस्तिष्क में यह शक्ति है कि वह अपने ही विचारों और कार्यों के उद्देश्यों को दिया सके। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए मनोविश्लेषण का महत्व बढ़ जाता है। राजनैतिक त्रियांगों को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण वे होते हैं जिनको अपरिवर्तनशील प्रतिमाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये वे निरूप्य होते हैं जिनको एक व्यक्ति स्वयं निरूप्य होने में समर्थ होने से पहले ही दूसरों से प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति जब विचार करता है तो उसके सामने ऐसे अपने

अपरिवर्तनीय 'स्टेरियो टाइप्स' होने हैं जैसे 'मासीसी', 'सैनिक मस्तिष्क' 'विदेशी', 'बालशेविक', 'गुप्त प्रेमी', आदि । इन शब्दों का अरुतु एक विशेष अर्थ होता है । इन अपरिवर्तनीयों को तर्कपूर्ण मतों के स्थान पर रखा जाता है । व्यक्ति उन चीजों को तुरन्त ग्रहण कर लेता है जो कि उसकी सत्कृति में पहले से ही परिभाषित की हुई हैं । ये प्रतिभाषे व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी अरुतु होती हैं ।

विदेशियों तथा उनके लक्ष्यों के प्रति अविद्वान रहना सोणी की परम्परागत विज्ञेपना है । इसमें व लोग अधिक विश्वास करते हैं जो कि विदेशी शासन या शोषण के विचार रहे हैं अथवा रह रहे हैं । एशिया और अफ्रीका के देशों में जो तटस्थता की नीति अपनाई जा रही है उसका कारण केवल यह नहीं है कि ये देश युद्ध को दूर रक्षता चाहते हैं अथवा महा शक्तियों के युद्ध में तटस्थ रहना चाहते हैं । इस नीति की जड़ों में उन पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध स्वतन्त्रता जाहिर करने की कामना है जिन्होंने कि अतीत काल में एशिया और अफ्रीका पर शासन किया तथा शोषण किया था । अब ये देश पश्चिमी प्रभाव का विरोध करने के लिए राजनैतिक शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं । फ्राँज सैटिन अमेरीका का समुक्त राज्य अमेरीका के प्रति जो विषय का दृष्टिकोण है वह डर और ईर्ष्या से पूर्ण है । इसका आधार अतीत काल में समुक्त राज्य अमेरीका के हस्तक्षेप तथा उनके कुत्त व्यावसायिक व्यवहार हैं । व मनभेद और विरोध केवल ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर ही नहीं बनवने वरन् विभिन्न सरकृतियों एवं सामाजिक रूपों पर आधारित निम्न मूल्यों के कारण भी बढते हैं ।

दुराग्रह और प्राथमिकताएँ (Prejudices and Preferences) भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अथना महत्वपूर्ण योगदान रखने हैं । पश्चिमी राज्यों ने अपने बीच घनिष्ठ राजनैतिक एकता विकसित कर ली है । उनकी सामान्य, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परम्पराएँ हैं । उनके मूल्यों तथा राजनैतिक व्यवस्थाओं में भी पर्याप्त एकरूपता देखने को मिलती है । दूसरी ओर साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित देश समाज की प्रकृति के सम्बन्ध में विरोधी मान्यताएँ लेकर चलते हैं, वे आपस में भी मतभेद रख सकते हैं जैसा कि सोवियत संघ और चीन के बीच में पाया जाता है । जिन राज्यों के बीच इन विषयों पर भूल अन्तर रहते हैं उनकी मैत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की कल्पना नहीं की जा सकती । उनका कोई समझौता अधिक दिनों तक नहीं चलेगा ।

यह कहा जाता है कि सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का मूल आधार 'वे' बनाम 'हम' की भावना है जो कि सामूहिक जीवन के द्वारा प्रभावित की जाती है। राष्ट्रवाद का विचार, आधुनिक संचार साधन, इतिहास, परम्पराएँ तथा अन्य वैज्ञानिक तत्व भी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। प्रजातन्त्रीय समाजों में ये तत्व सरकार को पर्याप्त प्रभावित करके विदेश नीति के सम्बन्ध में उनकी स्वतन्त्रता को सीमित कर सकते हैं।

जो राज्य अपने पड़ोसियों की ओर से सुरक्षित अनुभव करते हैं वे प्रायः अपने अन्तरो को शांतिपूर्ण साधनों से गुलाम लेते हैं। किन्तु जब एक राज्य के हितों को चुनौती दी जाती है और चुनौती देने वाले राज्य के साथ उसके सहयोग का कोई इतिहास या परम्परा नहीं होती तो उनके अन्तरो को मिटाना बड़ा कठिन बन जाता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मौखिक सम्बन्धों की एक लम्बी परम्परा है और इसलिए उनको पारस्परिक प्रबन्ध करने में पर्याप्त सुविधा रहती है। दूसरी ओर रूस और टर्की के बीच औपचारिक सम्बन्ध हैं किन्तु फिर भी टर्की के दर्रे पर नियंत्रण के लिए प्रतिभागिता के इतिहास ने टर्की को रूसी उद्देश्यों के प्रति सन्देह-शील बना दिया है और इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक है तथा नाटो की मददयता स्वीकार करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सहयोग की सम्भावनाएँ काश्मीर के ऊपर चलने वाले लम्बे भण्डे के कारण असम्भव बन गई हैं।

नैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (Morality and International Politics)

नैतिक एवं कानूनी नियम मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामूहिक व्यवहार को नियमित करते हैं। इन्हें व्यवस्था के आधार कहा जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर दूसरों के अधिकारों का आदर करने का कर्तव्य उत्पन्न कर सभी की स्वतन्त्रता को बढ़ाते हैं। यदि नैतिक मापदण्ड पूरी तरह से प्रभाव-हीन रहे तो कानून अनावश्यक बन जायेंगे। नैतिक आधार महिना सदैव ही कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करती है। केवल तानाशाह ही अपने कानून द्वारा प्रशसन कर सकता है। हम समझ उसी को कहते हैं कि अण्ड और बुरे के सम्बन्ध में एमम हाता है तथा दूसरे के अधिकारों का आदर करता है। जो समाज सामान्य मापदण्ड नहीं रखता उसमें नैतिक दृष्टिकोणों पर थोड़ा ही गमभीरता रहता है। एक सच्चा समाज वह होता

है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य प्रायः समान होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का स्वामी या सबक नहीं होता। आज हम जब 'अन्तर्राष्ट्रीय समाज' शब्द का प्रयोग करते हैं तो सप्रता है कि यह वास्तविकता का उद्घाटन होने की अपेक्षा केवल एक वाङ्मयीय आशा मात्र है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इकाइयों की समानता का तत्व नहीं पाया जाता। अन्तर्राष्ट्रीय समाज (International Community) जैसी कोई चीज न होने की वजह से ही यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई नैतिक आचरण संहिता भी नहीं होती। कुछ लेखकों का विचार है कि एक राज्य के अधिकारी जब दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार करते हैं तो उनकी नैतिक निर्णयों के अनुसार चलना चाहिए।

नैतिकता की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। नैतिकता की न तो कोई सर्वमान्य परिभाषा है और न ही इसका कोई सर्वमान्य व्यवहार है। व्यवहार के नैतिक मापदण्ड प्रत्येक संस्कृति एवं सभ्यता में अलग-अलग होते हैं। एक देश की सभ्यता तथा संस्कृति में जो मापदण्ड तथा मूल्य प्रचलित हैं उनको दूसरे देश पर लागू नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस चीज को आदर्श माना जाता है, वह जरूरी नहीं है कि अफ्रीका और एशिया के देशों में भी उसे आदर्श माना जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नैतिकता का वही अर्थ नहीं होता जो कि व्यक्तिगत सम्बन्धों में हुआ करता है। एक देश के नेता जब विदेश नीति के सम्बन्ध में निर्णय लेते हैं तो वे अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्डों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को नैतिक तथा मानवीय सिद्ध करने का प्रयास करता है। नैतिकता प्रायः सही आचरण को कहा जाता है किन्तु सही आचरण वास्तव में क्या है, यह जानना बड़ा कठिन है। एक स्थिति में एक आचरण एक व्यक्ति विशेष की दृष्टि से सही है किन्तु हो सकता है कि वह आचरण अन्य स्थिति में उनके लिए अनैतिक हो प्रमत्त। उगी स्थिति में अन्य व्यक्ति के लिए अनैतिक हो। नैतिकता के सम्बन्ध में अनेक विचार हैं। इनमें से मुख्य दो निम्न प्रकार हैं—

१. कुछ लेखक यह मानते हैं कि एक सार्वभौमिक नैतिक मापदण्ड होता है और वही कार्य नैतिक कहा जा सकता है जो कि उसके अनुरूप हो। नैतिकता का मापदण्ड केवल एक ही होता है, अनेक नहीं होते। व्यक्ति यह जान सकता है कि नैतिक मापदण्ड उससे किस प्रकार के व्यवहार की आशा करता है। यह नैतिक मापदण्ड सभी व्यक्तियों पर समान रूप से

लागू होता है चाहे वे कुछ भी कार्य करते हों। इसके विरुद्ध दिया गया आचरण अनीतिक है। इन पर समय तथा स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हत्या करना पाप है तो वह प्रत्येक परिस्थिति में पाप ही होगा।

२. नीतिवत्ता के इस अर्थ की पर्याप्त आलोचना की जाती है। इसे आदर्शवादी तथा अभ्यावहारिक बताया जाता है। दूसरे लेखकों का कहना है कि नीतिवत्ता का केवल एक ही मापदण्ड नहीं होना। इतिहास एवं अनुभव के आधार पर इसमें परिवर्तन आते रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए शत्रु को मार कर खा जाना एक अनीतिक कार्य है कि तु वह यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके मृत्यु जगती व्यक्ति के मृत्यु से किस प्रकार उच्चतर है जो कि शत्रु तो क्या मित्र को भी मार कर खा जाता है। इन विचारकों की मान्यता है कि कार्य एवं स्थिति के अनुसार व्यक्ति के नीतिक आचरण का रूप भी बदल जाता है। यदि एक लखपति व्यक्ति चोरी नहीं करता तो हम उसको एक महान नीतिक व्यक्ति नहीं मान सकते। अमल में उसका नीतिक स्तर उस व्यक्ति से भी नीचा है जो कि अपने घच्चों की भूल को मिटान के लिए चोरी कर लेता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता जैसी कोई चीज है अथवा नहीं है, इस सम्बन्ध में विचारकों के बीच मतभेद है। प्रत्येक देश अपने इतिहास, अनुभव एवं परम्पराओं के आधार पर स्वयं का नैतिक मापदण्ड बना लेता है और उसी के अनुसार आचरण करता है। इस प्रकार आचरण का कोई अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्ड होने की अपेक्षा प्रत्येक देश की विशेष आचरण संहिता है।

ले अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक आचरण संहिता के अस्तित्व से सम्बन्धित समस्या का समाधान अपने-अपने हथों में लिया जाता है। कुछ लोग का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई नैतिक आचरण की संहिता नहीं होती। दूसरे लोग कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए भी नैतिक मापदण्ड है। किन्तु यह मापदण्ड क्या है उसके सम्बन्ध में वे एकमत नहीं हैं। कुछ का कहना है कि यह आचरण संहिता ठीक ऐसी ही होनी है जैसी कि व्यक्तिगत सम्बन्धों पर लागू होती है। अन्य का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के नैतिक मापदण्ड तो विशेष प्रकार के होने हैं।

नैतिक मापदण्ड के अस्तित्व की भांति इस प्रश्न पर भी विचारकों के विचार भिन्न-भिन्न हैं—**प्रश्न**—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार अनीतिक होता है? **जा** लोग अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक मापदण्ड के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं

वरने उनके मतानुसार यह प्रश्न अप्रासंगिक है। अन्य के लिए यह प्रश्न जितना महत्वपूर्ण है उतना ही कठिन भी है। इस सम्बन्ध में एक सामाजिक धारणा यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता और कानून का जिनका पालन किया जाना है उससे अधिक उसका उल्लंघन किया जाता है।

कुछ विचारक यह मानते हैं कि अधिकांश व्यक्ति प्रायः अपराधी प्रकृति के होते हैं। केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो उन नैतिक मापदण्डों का पालन करने हैं जिनका कि वे उपदेश देते हैं। कुछ नैतिक धारणाएँ ऐसे होने हैं जिनको व्यक्ति समाज परिस्थितियों में अपना लेता है किन्तु अपराधपूर्ण परिस्थितियों में वह उनका पालन नहीं कर सकता और इस उल्लंघन को बुद्धिपूर्ण एवं न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत के अनुसार आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। कुछ परिस्थितियों में राजनीतिज्ञ केवल आवश्यकता से प्रभावित होकर ही व्यवहार करते हैं तथा ऐसे गिराए लेते हैं जिनको वे दित से नहीं लेना चाहते किन्तु उनके सामने कोई विकल्प नहीं है अतः से रहे हैं।

नैतिकता के इस दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए अन्य विचारक यह मत प्रकट करते हैं कि नैतिक धारणा और सुगमता का प्रायः साथ नहीं रहता। आवश्यकता और मजबूरी यदि हमको नैतिकता के विरुद्ध कर देती है तो यह हमारी स्वयं की कमजोरी का प्रतीक है। आर्नोल्ड वॉल्फर्स (Arnold Wolfers) के मतानुसार यदि एक राजनीतिज्ञ यह निर्णय लेता है कि उनकी देश की सुरक्षा के लिए सत्तरा इतना महान है कि उसे युद्ध में डलभना आवश्यक बन गया है तो यहाँ वह राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यधिक मूल्य प्रदान कर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि कई बार मूर्खों के बीच सपने उत्पन्न हो जाता है और उस समय प्राथमिकता के आधार पर यह चुनना होता है कि किस मूल्य को महत्व दिया जाये। कुछ मूल्यों की साधना में रत रहने पर युद्ध आवश्यक हो सकता है किन्तु तब निश्चयिक को यह तय करना होगा कि क्या ये मूल्य इतने उच्च हैं कि उनके लिए अन्य मूल्यों की बलिदान किया जा सकता है। इस प्रकार आवश्यकता एवं मजबूरी का नाम लेना तो केवल बहाना मात्र है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी कार्य पूर्ण शुभ या अशुभ नहीं होगा बल्कि प्रत्येक कार्य में अच्छाई व बुराई दोनों के तत्त्व पाये जाते हैं। यह तय करना पड़ता है कि कम बुराई क्या है उसी को अपनाया जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता का प्रश्न अत्यन्त जटिल है। अधिकांश व्यक्ति आत्मरक्षा की खातिर दूसरों की हत्या कर देना ठीक मानते हैं। उनके मतानुसार न्यायपूर्ण युद्धों में जो हत्याएँ होती हैं वे ठीक हैं तथा

नैतिक हैं। एक देश जिस समय युद्ध कर रहा होता है उस समय उसका कोई भी नागरिक यह मानने को तैयार नहीं होता कि उसका देश अन्यायपूर्ण युद्ध में सलग्न है। प्रायः सभी व्यक्ति इस बात में विश्वास करते हैं कि अपराधी को उसके दुष्कर्मों के लिए दण्ड दिया जाना चाहिए और गम्भीर अपराध के लिए शक्ति की जान भी ले ली जाये तो बुरा नहीं है। यह कार्य भी न्यायपूर्ण एवं नैतिक ही माना जायेगा, किन्तु यह व्यवहार उन व्यक्तियों के विरुद्ध जाता है कि 'तुम्हारे शत्रु को प्यार करो', 'बुराई का बदला बुराई से न दो' आदि। नैतिकता के समर्थकों का कहना तो यह है कि "भला करने वाले भलाई किये जा, बुराई के बदले दुष्कार दिये जा।" नैतिकता का यह रूप आदर्श है किन्तु केवल व्यक्तिगत जीवन में ही इसे व्यवहृत किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता को राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यहाँ विदेश नीति के निर्णायकों के हाथ में असंख्य लोगों का जन-जीवन होता है और उनके स्वयं व मूल्यों की खातिर वे इसकी बाजी लगाने का कोई अधिकार नहीं रखते। कभी-कभी अन्याय का विरोध करने के लिए हिंसात्मक साधनों को अपनाना जरूरी बन जाता है। जो लोग यथास्थिति से सतुष्ट हैं वे यह कहते हैं कि यथास्थिति को बदलना और इसके लिए शक्ति का प्रयोग करना अन्याय है, किन्तु ये ही लोग उस यथास्थिति को कायम रखने के लिए शक्ति के प्रयोग को न्यायोचित ठहराते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के पीछे दबाव रहता है जिसके कारण विभिन्न देश उसे मानने के लिए बाध्य होते हैं। विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने वालों को आन्तरिक या बाह्य दबाव के कारण अन्तर्राष्ट्रीय नैतिक आचरण को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आन्तरिक दबावों में हम निर्णायकों की स्वयं की अन्तरात्मा एवं देशी लोकमत का नाम ले सकते हैं। वैसे लोगों की प्रायः यह प्रवृत्ति रहती है कि वे अपनी सरकार की अपेक्षा दूसरे देशों की सरकार को भला बुरा कहते हैं, किन्तु उनके स्वयं के देश की सरकार भी उनकी आलोचना से बच नहीं पाती। समुक्त राज्य अमरीका में वियतनाम युद्ध एवं बमबारी के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहे हैं तथा जलूस निकाले जा रहे हैं वे इसी बात के प्रमाण हैं। यह कहा जाना है कि सन् १९६१ में बमबारी के विरुद्ध अमरीकी शक्ति के प्रयोग करने पर देश में भारी विरोध होने की आशंका थी और इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त नहीं की गई।

जनमत की आलोचना एवं विरोध का असर होने के कारण ही भारत के देश केवल गृहात्मक एवं न्यायपूर्ण युद्ध ही लड़ना चाहते हैं। इसके

अतिरिक्त अनेक कारणों से आज विश्व के अधिकांश देश एक स्वामी विश्व व्यवस्था चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रख कर कुछ छोटी-मोटी इच्छाओं की अभिव्यक्ति की अवहेलना कर सकते हैं।

विदेश नीति के निर्माणकों पर विश्व जनमन का प्रभाव भी उत्प्रेक्षणीय रूप से पड़ता है। यही कारण है कि प्रत्येक देश सरकार के सामने अनेकों सर्वश्रेष्ठ प्रतिभूति रखना चाहता है। साथ ही वह अपने प्रत्येक कार्य को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रसार साधनों का साधन लेता है। जिन लोगों का यह विश्वास है कि केवल शक्ति ही सब कुछ होती है वे भी इन लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं। प्रत्येक राज्य की सामर्थ्य उनकी शक्ति एवं स्वीकृति (Consent) पर निर्भर करती है। उसे जितनी अधिक स्वीकृति प्राप्त है उसे शक्ति की उतनी ही कम जरूरत होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा के कार्य (Functions of ideology in International Politics)

विचारधारा के पीछे राष्ट्रीय शक्ति होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विचारधाराओं के प्रभाव से घटती नहीं रहती। ये प्रभाव अनेक तथ्या बुरे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। 'विचारधारा' विश्व में चलन-प्रचलन भाषों में बसे लोगों के बीच एकता, ईम और भाईचारे के भाव को जागृत कर सकती है, यह राष्ट्रीय भी एकता का कारण बनती है, लोगों में सामान्य उद्देश्यों की भावना जागृत करती है किन्तु दूसरी ओर विचारधारा समर्थन, झगड़ों व विश्व युद्धों का कारण भी बन सकती है।

विचारधाराएँ प्रायः अवबोद्धिक (Irrational) होती हैं; उनका आधार बुद्धि न हाकर भावनाएँ होती हैं। विचारधाराओं की भाँड में परिस्थिति के तथ्यों को तथा महत्वाकांक्षी नेताओं के वास्तविक लक्ष्यों को धिक्काने का प्रयत्न किया जा सकता है। विचारधारा का प्रयोग यदि पूरी वृद्धता से किया जाये तो इसके अनेक नयनपर परिणाम निकल सकते हैं जैसे—

(१) दो विरोधियों के बीच बौद्धिक समझौता तथा विचार-विमर्श कठिन और पहा तक कि असम्भव बन जायगा;

(२) समझौते के क्षेत्र दृढ़ होने के लिए वां प्रयास किये जायेंगे उनको निराशा मिलेगी,

(३) राष्ट्रीय सम्मान तथा इज्जत का अनुचित रूप से बलिदान किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करना कठिन बन जायेगा;

(४) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रयोग कूटनीतिक लाभ प्राप्त के अवसर के रूप में न किया जाकर अपनी विचारधारा के प्रचार के लिए किया जायेगा ।

पामर तथा परकिन्स ने भी यही विचार व्यक्त किये हैं । उनका कहना है कि यदि दो देशों के बीच, जो अपनी-अपनी विचारधारा का कट्टरता के साथ प्रयोग कर रहे हैं, मतभेद पैदा हो गया तो वह एक अन्तर्राष्ट्रीय संकट बन कर रहेगा जिसे मुचभाना अपभ्रम है ।

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्थित विचारधाराओं में प्रमुख हैं साम्यवादी विचारधारा तथा पश्चिमी राष्ट्रों की प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा । इन दोनों ही गुटों के बीच असलम्नता की नीति अपनाने वाले राष्ट्रों की भी एक अलग विचारधारा सी बन गई है । उदाहरण के लिए भारत और अरब के सम्बन्धों का आधार बनाते समय अरब लीग के प्रो० मकसूद ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता, साम्राज्यवाद का विरोध, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता व समानता पर बल और असलम्नता की विदेशनीति आदि कुछ तत्व हैं जिनके कारण भारत-अरब सम्बन्ध बड़े गहरे व स्याई हैं । इस प्रकार असलम्नता की नीति (Policy of Non-alignment) भी देशों को निकट लाने में विचारधारा जैसा ही काम करती है । आजकल विश्व सरकार या विश्वसंघ के समर्थन में एक नवीन विचारधारा और जोर पकड़ती जा रही है । वैसे तो साम्यवादी भी सार्वभौमिकता के विचारों से युक्त हैं तथा भारे तसार को लाल झण्डे के नीचे लाने के पक्ष में हैं । अनेक राष्ट्र न रहे एक ही विश्व रहे, विश्व-वन्धुत्व और वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी भावनाएँ इस विचारधारा की जड़ में हैं ।

मोरल

(The Morale)

अंग्रेजी शब्द 'Morale' का हिन्दी रूपान्तर मानविक या नैतिक अवस्था के रूप में किया जाता है । व्यवहार में इसका सकेत 'मनोबल' शब्द से भी कर देते हैं जो अन्य शब्दों से अधिक उपयुक्त लगता है ।

मनोबल का अर्थ

(Meaning of the term morale)

मनोबल की परिभाषा देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विचारक मार्गेंसो ने बताया था कि राष्ट्रीय मनोबल निश्चय (determination) का वह अनुपात (Degree) है जिसके अनुसार एक राष्ट्र शान्ति एवं

युद्ध के समय अपनी सरकार की विदेश नीति का समर्थन करता है। मनोबल में राष्ट्र की सारी क्रियाएँ—औद्योगिक व कृषि उत्पादन तथा सैनिक तैयारियाँ और कूटनीतिक सेवाएँ, समाहित होती हैं। लोकमत के रूप में बदल कर राष्ट्रीय मनोबल सरकार की विदेश नीति को इतना प्रभावित करता है कि कभी कभी तो यदि दोनों के बीच मतभेद पैदा हो जाय तो या तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है अथवा सरकार को वह नीति लोकमत के अनुकूल परिवर्तित करनी पड़ती है। प्रजातन्त्रात्मक राज्यों में मनोबल या लोकमत का प्रभाव स्पष्ट एवं वास्तविक रूप से उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करता है जबकि दूसरे तानाशाही या राजतन्त्रात्मक राज्यों में ऐसा सम्भव नहीं हो पाया। किन्तु फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन राज्यों में मनोबल या लोकमत का कोई महत्व नहीं होता। हिटलर की विदेश नीति को जर्मनी की जनता का ६० प्रतिशत से भी अधिक समर्थन प्राप्त था।

यह कहा जाता है कि युद्ध केवल सेनाओं को रणक्षेत्र में भेजने से नहीं जीते जा सकते। जब तक कि जनता का पूरा सहयोग एवं हार्दिक सहभावन्यता अपने वीर सिपाहियों के उत्साह का वर्धन न करेंगी, तब तक वे अपनी पूरी शक्ति से नहीं लड़ सकते। वे अपनी कुर्बानी की मातृभूमि की सेवा में बलिदान न भान कर आत्म हत्या समझने लगेंगे। इस प्रकार जनता का मनोबल किसी भी युद्ध की सफलता, जोश एवं सफलता के लिए एक आवश्यक तत्व होता है।

मनोबल कभी कभी युद्ध के प्रतिरोधक (Deterent) के रूप में भी काम करता है अर्थात् जिस देश के लोगों में एकता होती है तथा वहाँ की सरकार की नीतियों के पीछे जनता का जोर रहता है—उस देश पर कोई भी दुश्मन देश आक्रमण करने का हौसला नहीं कर पाता, यदि करता भी है तो बहुत सोच समझ कर। इस प्रसंग में भारत पर किये गये पाक आक्रमण के कारकों पर, यदि गौर किया जाये तो हम पायेंगे कि पाकिस्तान ने जो दुःसाहम किया उसके प्रमुख कारणों में से एक यह भी था कि उसने भारत में अनेक समस्याएँ एवं भेदभावों के होने से उत्तम अनुमान लगा लिया कि वहाँ का मनोबल ऊँचा नहीं है तथा सरकार की नीतियों को जनता का एकमत से समर्थन प्राप्त होना असम्भव है और ऐसी स्थिति में अव्यवस्थित भारत शीघ्र ही उसके कदमों में जा गिरेगा किन्तु भारतवासियों ने सकट के समय जो प्रद्वितीय एकता दिखाई वह अपारचर्यजनक थी। सरकार की नीतियों को सभी विरोधी दलों ने अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। सभी भेदभावों को सकट

का मुकाबला करने के लिए भुला दिया गया। समय-समय पर सरकारी प्रवक्तव्यों एवं विदेशी पत्रों ने यह स्वीकार कर लिया कि भारत का मनोबल बड़ा ऊँचा है। इस दृष्टि से गृहमन्त्री नन्दा तो पाकिस्तानी आक्रमण को एक परीक्षा की घड़ी कह कर यह मानने लगे थे कि इस संकट में से निक्ला हुआ भारत बँसा ही होगा जँसा कि भाग से निकला हुआ खनिज सोना, उसमें कुन्दन जँसी ही चमक आ जायगी।

पामर तथा परकिम्स ने मोरेल (Morale) को परिभाषित करते हुए इसे आत्मा की एक चीज माना है जो स्वामिमक्ति, साहस तथा विश्वास से मिल कर बनती है, यह व्यक्तित्व एवं सम्मान की रक्षा की लालसा है, जात के प्रति 'भावना' है तथा अज्ञात के प्रति भय एवं भ्रष्टि। यह आत्म-स्वार्थ है। आत्म-स्वार्थ यह इस अर्थ में है कि एक देश का मोरेल (Healthy frame of mind) उस देश के निवासियों में 'समात्मभाव' की स्थापना करता है। इसके अस्तित्व में वह समाज प्रेम, सेवा, बलिदान, बन्धुत्व, दाम्पत्य, सख्य, शास्त्रसत्य, भक्ति आदि के माबो से परिपूर्ण हो जाता है। स्थूल जगत में इन भावों के अनेक परिणाम परिलक्षित होते हैं। जब लोग सबके सुख में अपना सुख और सबके दुख में अपना दुख देखने लगते हैं तो स्वामाविक रूप से ही उस देश की विकास योजनाओं की गति तीव्र हो जाती है। सभी लोग मिल कर सच्चे दिल से परिश्रम करते हैं, राष्ट्रीय हित के प्रागे वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बलिदान कर देते हैं। इस सबका परिणाम यह होता है कि वह देश आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन, शैक्षिक तैयारी अथवा और जिस किसी भी क्षेत्र में कदम बढ़ाता है, वहीं सफलता उसके कदम धूमती है।

मनोबल के निर्माण के साधन (Means for maintaining Morale)

किसी भी देश में मनोबल के निर्माण के समय कौन-कौन से तत्व प्रभाव डाल सकते हैं इस सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न मत हैं। कुछ विचारकों के मतानुसार तो मनोबल विकसित होता है, इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। ये विचारक मानते हैं कि कोई सरकार या व्यक्ति विशेष यदि किसी भी कारण से देश में मनोबल का निर्माण करना चाहे तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इसका कारण, जँसा कि पामर तथा परकिम्स महोदय ने बताया है, यह है कि राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) कुछ निश्चित तथा अनेक अनिश्चित तत्वों का उल्लेखपूर्ण समवाय है।

दूसरी ओर विचारकों का एक समुदाय है जो उक्त मत के ऊपर दो आपत्तियाँ उठाता है। प्रथम, उसका कहना है कि यदि यह मान लिया जाये कि मनोबल निर्माण का नहीं बल्कि विकास का परिणाम है तो भी क्या यह उपयुक्त न रहेगा कि इस विकास पर प्रभाव डालने वाले तत्वों की खोज की जाये। दूसरे, प्रायः यह देखा जाता है कि युद्ध के समय, सकट का मुकाबला करने की दृष्टि से राष्ट्रीय मनोबल एकाएक उठ खड़ा होता है, ऐसी अवस्था में उसे हम विकास का परिणाम न मान कर एक विशेष परिस्थिति की उपज कहेंगे। चीनी तथा पाकिस्तानी भाष्यमण्डलों के विरुद्ध भारत में जिस मनोबल का निर्माण हुआ था वह इतना तत्काल हुआ कि उसे विकसित मानना अमंगल प्रतीत होता है।

उक्त बौद्धिक मतभेदों में अधिक उलझने की अपेक्षा यहाँ हमारे लिए यह उपयुक्त होगा कि राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) के विकास या निर्माण पर सम्भावित या वास्तविक रूप से प्रभाव डालने वाले तत्वों की संक्षिप्त जानकारी की जाय। ये तत्व निम्न प्रकार हैं—

(१) राष्ट्रीय चरित्र (National character)—राष्ट्रीय चरित्र का अर्थ उन मूल्यों तथा आदर्शों से है जिन्हें एक देश प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरे देश उसे नहीं देते। एक देश के लोगों का चरित्र अर्थात् उनका रहन-सहन, विचार, भाषा, आदर्श, धर्म, संस्कृति आदि उस देश के मनोबल पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। एक धर्म-प्रधान राष्ट्र के लोगों में युद्ध के विरुद्ध मनोबल तैयार करना एक दुर्बल कार्य है। इसी प्रकार व्यक्तिवादी विचार-धारा से प्रभावित देश के लोग अन्तर्राष्ट्रीय समाज के पक्ष में मनोबल का निर्माण नहीं होने देंगे।

पामर तथा परकिन्स के मत में राष्ट्रीय चरित्र एक देश के मनोबल (Morale) के निर्माण में बहुत कम प्रसर डालता है। वे इतिहास के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि समय-समय एक ही देश में दो विरोधी प्रकृति के मनोबल उभरते देखे गए हैं जो इस बात का प्रमाण हैं कि उस देश के चरित्र की दोनों में से किसी एक मनोबल के साथ एकरूपता नहीं होगी।

(२) संस्कृति (Culture)—संस्कृति एक देश के निवासियों के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक स्तर को प्रभावित करती है। बदलती हुई संस्कृति के लोगों का सोचने एवं अनुभव करने की शरीर की भी बदल जाता है। बहुत से विचार एवं व्यवहार जिन्हें प्राचीन-संस्कृति धारक मानती है, नवीन संस्कृति

उन्हे मानता कहती है तथा नवीन सस्कृति में जो आचार-विचार उपयुक्त माने जाते हैं प्राचीन सस्कृति उनको अमानवीय या मर्यादाहीन घोषित करती है।

कुछ विचारक यह सोचते हैं कि पुरानी सस्कृति में प्रभावित एक देश के मनोबल की प्रकृति तथा परिणाम उस देश के मनोबल की प्रकृति एवं परिणामों से विभिन्न प्रकार के होंगे जिनमें कि नवीन सस्कृति का प्रभाव है। किन्तु पामर तथा परकिन्स इस मन को भी नहीं मानते और इतिहास के आधार पर ही दोनों प्रकार के मनावना में समानता दर्शाते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि सांस्कृतिक अन्तर एक देश के मनोबल को निश्चित करने के लक्ष्य नहीं होते।

(३) नेतृत्व (Leadership) — एक राष्ट्र का मनोबल उस देश के महान् पुरुषों के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होता है। भारत पार संघर्ष के दौरान आकाशवाणी छोड़े-थोड़े समय के अन्तर पर उन वाक्यों को दोहराती थी जो नेहरू न कभी समझ में कहे थे। यह प्रपक्ष लाभकारी था क्योंकि जब एक भारत बानी को यह याद दिलाया जाना कि उसके एक स्वर्गीय नेता ने आजादी की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने की कहा था, तो उसकी नसों का रक्त प्रवाह उत्तेजित हो जाता है। यह मानुषीयता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने में गौरव का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार देश में एक उच्च मनोबल की सृष्टि होती है। पामर तथा परकिन्स न इसी विचार का समर्थन करते हुए कहा है कि यदि एक नेता जनता में लोकप्रिय हो चुका है तो उसका विचारों का प्रभाव उस देश के मनोबल पर पड़े बिना नहीं रह सकता।

ऊपर वर्णित राष्ट्रीय मनोबल पर प्रभाव डालने वाले तीनों ही तत्वों का स्वल्प 'सम्भावित' है अर्थात् वे तब प्रभाव डाल भी सकते हैं और नहीं भी। ऊरोक्त के अभाव में कुछ ऐसा भी नत्व है जो आवश्यक रूप से मनोबल पर प्रभाव डालते हैं। इनमें प्रमुख रूप से उत्प्रेरणीय दो हैं— सरकार का सश्रिय रूप और प्रवचन।

(४) अच्छी सरकार (A good Govt) — एक राष्ट्र में स्वल्प एक सुगठित मनोबल का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि वहां की सरकार सश्रिय हो, गुणवान हो, तथा प्रजा की इच्छा एवं लोकमत का प्रभाव से संचालित हो। जिस देश की सरकार जनताप्रिय तरीके से चलाई जाती है वहां जनता की महत्वाकांक्षाओं में तथा सरकार की नीतियों में

एकदमता पाई जाती है । एक देश का मनोबल वहां की राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि का साधन बन जाय यह बात वहां की सरकार के गुप्तो पर निर्भर करती है । जिन देशों की सरकार मुशानिन होती है वहां का मनोबल उन देशों की तुलना में ऊंचा होता है जहां कि सरकार कमजोर है ।

सरकार मुशानिन न होकर यदि कमजोर होगी तो इसका प्रभाव राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों जैसे प्राकृतिक स्रोत, भौतिक सामर्थ्य, सैनिक तैयारिया आदि पर भी बुरा प्रभाव डालेगी और इस प्रकार उस देश को कमजोर बना देगी । मार्गेन्थो (Morgenthau) सहोदय के मतानुसार राष्ट्रीय मनोबल को सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि सरकार के रूप को सुधार दिया जाय ।

(६) परिस्थिति (Circumstances)—राष्ट्रीय मनोबल का निर्माण करने वाले विभिन्न तत्वों में यह भी एक प्रमुख तत्व है जो प्रभावपूर्ण रूप में कार्य करता है । अनेक बार ऐसी परिस्थितियां तथा अवसर घट जाते हैं जो राष्ट्रीय मनोबल की मूर्ष्टि का कारण बन जाते हैं । युद्ध में पड़ने वाली अनेक घटनायें राष्ट्र के मनोबल को उत्तेजित करती हैं । सितम्बर १९६१ में जब भारतीय सैनिकों लगातार बुद्ध विराम रेखा के उन पार बड़ी जा रही थी, भारतीय जनता में जोश की एक लहर आई हुई थी । प्रत्येक रेडियो के चारों ओर एक मेगा-वा लग जाता था तथा प्रत्येक खबर के साथ जनता की करुणा ध्वनि के नीचे रेडियो की आवाज भी दब जाती थी । लोगों में एक प्रचुर उत्साह था । दुश्मन के उबड़ने हुए पक्षों के मित्रों के देखने में वे इतने खी गए कि उन्हें यह भी ध्यान न रहा कि उनकी स्वयं की किन्ती ध्वनि हो रही है । राष्ट्र का मनोबल युद्ध की इन विजयों के कारण इतना बढ़ गया था कि नई, ओर में पूरे ताहौर पर अधिकार करने की या पाकिस्तान की दुनिया के नक्के में हटाने की बातों की जाती थी । मनोबल परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होता है । मार्गेन्थो ने इसी अर्थ में कहा था कि यह सब मनमरी पर ही निर्भर करता है ।

अवसर राष्ट्रीय मनोबल को गिरा भी सकते हैं । उदाहरण के लिए यदि लड़ाई में हार हो जाये, कोई बड़ा नेता मर जाये, जहाज डूब जाये, कोई मित्र फूट जाये, शत्रु की शक्ति बढ़ जाये अथवा देश में ही फसल नारी जाये, हवताल हो जाये, बाढ़ आ जाये, रेल दुर्घटनायें हो जायें, बीमारी फैल

जाये तो देश का मनोबल गिर सकता है। कभी कभी जीत की खबर भी लोगों के उत्साह एवं प्रयासों को ढीला कर देनी है।

राष्ट्रीय मनोबल (National Morale) को एक देश की रीढ़ कहा जा सकता है जिसके टूटते ही राष्ट्र का सारा ढांचा घरासाहों हो जायेगा। एक देश का गिरा हुआ मनोबल उठाना उतना ही कठिन तथा समय लेने वाला है जितना कि टूटी रीढ़ को पुनः कार्य योग्य बनाने का प्रयास। मार्गेंथो ने राष्ट्रीय मनोबल को राष्ट्र की शक्ति का एक प्रमुख भाग माना है जिसके बिना राष्ट्र की शक्ति एक निर्जीव शक्ति बन कर रह जायेगी। यह केवल सम्भावित बन कर रह जायेगी जिसे कभी भी वास्तविक नहीं बनाया जा सकता।

नेतृत्व

(The Leadership)

राष्ट्रीय शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व नेतृत्व है। राज्य चाहे वह प्रजातन्त्रात्मक हो या राजतन्त्रात्मक, केवल कुछ लोगों द्वारा ही संचालित किया जाता है। स्विट्जरलैंड को भ्रष्टाचार के रूप में निकाल देने के बाद विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं रह जाता है जहाँ की सरकार के कार्य अथवा विदेश नीति के मामलों पर जनता का सीधा हस्तक्षेप हो। देश की बागडोर कुछ नेताओं के हाथों में होती है। इन नेताओं के गुण एवं महानता पर ही उस देश का भविष्य निर्भर रहता है। जितने कुशल नेता होंगे तथा उनका जितना प्रभावकारी नेतृत्व होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली वह देश बन जायेगा।

नेतृत्व के मुख्य रूप से दो कार्य हैं जिन्हें करके वह एक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रथम, नेतृत्व राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों के बीच समन्वय की स्थापना करता है, दूसरे राष्ट्र अधिक शक्ति प्राप्त कर सके इसके लिए भी नेतृत्व का अस्तित्व आवश्यक होता है। मार्गेंथो (Morgenthau) महोदय के शब्दों में हीनव नेतृत्व के गुण का राष्ट्रीय शक्ति पर बड़ा महत्त्व भर रहा है। उदाहरण के लिए १८वीं शताब्दी में प्रशा (Prussia) फ्रेडरिक महान के नेतृत्व के अधीन था। उस समय उसकी शक्ति भी बढ़ी चढ़ी थी किन्तु उसकी मृत्यु होने ही प्रशा की शक्ति गिर गई और १८०६ में नेपोलियन द्वारा उसकी सेना को हरा दिया गया। इसी प्रकार हम जर्मनी के उदाहरण को देख सकते हैं जहाँ बिस्मार्क और हिटलर के नेतृत्व में इसकी राष्ट्रीय शक्ति संचित हो गई थी।

कि जिसने सत्ता को चकित कर दिया। सही तथा प्रभावशाली नेतृत्व के होने पर एक देश के भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, जनसंख्या आदि का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि ये सभी तत्व उस राष्ट्र को विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र बना दें। इस प्रकार नेतृत्व का राष्ट्रीय शक्ति के अन्य तत्वों से बड़ा गहरा सम्बन्ध रहता है। नेतृत्व के अभाव में एक देश की सरकार कोई काम नहीं कर सकती, एक विकसित एवं संपन्न तकनीक नहीं रह सकती, मनोबल भी इसके अभाव में महत्वहीन होता है। नेतृत्व ही वह तत्व है जो कि शक्ति के सम्भावित कारणों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। नेतृत्व दूसरे लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है किन्तु दूसरे लोगों के व्यवहार से वह स्वयं अधिक प्रभावित नहीं होता। मेकाइवर और पेन ने नेतृत्व को एक व्यक्ति की ऐसी योग्यता माना था जो उसके पद से सम्बन्धित न होकर उसकी स्वयं की व्यक्तिगत होती है। इस योग्यता के आधार पर ही वह लोगों को प्रोत्साहित व निर्देशित करता है। गिव महोदय ने नेतृत्व को केवल व्यक्तिगत गुण न मान कर यह स्वीकार किया है कि उस पर सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है।

नेतृत्व के समय तथा स्थान के अनुसार मिश्र मिश्र रूप बदलते रहते हैं। युद्ध के समय किसी दूसरे प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता रहती है जबकि शान्ति काल में किसी दूसरे ही प्रकार के नेतृत्व की।

नेतृत्व की विशेषताएँ

(Characteristics of Leadership) ✓

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व के स्वरूप, महत्व एवं उत्तरदायित्वों के उक्त संक्षिप्त परिचय के बाद यह उचित रहेगा कि उसकी कुछ सामान्य विशेषताओं को भी समझ लिया जाय जिनके कारण एक नेतृत्व को अधिक से अधिक सक्रिय, सफल एवं प्रभावशाली होने के अवसर प्राप्त होते हैं। ये विशेषताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार हैं—

✓(१) नेतृत्व एक आन्तरिक एवं व्यक्तिगत गुण होता है; यह दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने तथा उनको प्रभावित करने में कार्य करता है।

✓(२) नेतृत्व एक बहुमुखी व्यक्तित्व की मांग करता है। राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पहलू पर निर्देशन एवं मार्ग दर्शन की आवश्यकता रहती है। यह मार्गदर्शन किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यक्ति अपूर्ण है तथा उसकी योग्यता एवं ज्ञान की कुछ सीमाएँ भी होती हैं।

(३) उक्त कमी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिखर पर राजनीतिज्ञों की सहायता के लिए विशेषज्ञ हो और इस प्रकार नेतृत्व किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार न होकर विशेषज्ञ मण्डली के सामान्य निर्देशन के अधीन किया जाय।

इसी भाव को व्यक्त करते हुए पामर तथा परकिन्स ने यह कहा था कि नेतृत्व एक लचीला पद है इसका प्रयोग अनेक भयों में किया जा सकता है किन्तु जिस भय में यह राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है, इसे अनेक ऐसे व्यक्तियों को समाहित करना चाहिए जिनके नेतृत्व के गुणों पर सैनिक सम्भावनाओं का विकास निर्भर करता है।

शान्तिकाल में नेतृत्व

(Leadership in peace time)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व का एक सर्वव्यापी महत्व है। दो राज्यों के बीच के सम्बन्धों को निर्धारित करने वाली इकाइयाँ उन देशों के नेता होने हैं। सामान्य जनता समस्या एवं परिस्थिति को न तो मती प्रकार समझ पाती है और न ही वह इतना समय एवं योग्यता रखती है कि सरकार के निर्णयों को बदल सके। सरकार की कोई भी नीति यदि प्रजा के हितों पर सीधा आघात करती हो तो वात दूसरी है वरना देश के नेताओं ने जो नीतियाँ प्रपना ली हैं, प्रजा उनका समर्थन कर देती है।

नेतृत्व का यह उत्तरदायित्व है कि वह दूसरे देशों के साथ आदिक, सैनिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं अन्य ऐसे सम्बन्ध स्थापित करे जिनके द्वारा उसके देश की राष्ट्रीय शक्ति घटे नहीं तथा बढ़ती चली जाये तथा राष्ट्रीय शक्ति के जो विभिन्न तत्व हैं वे परस्पर सहयोग के माध्यम पर बँध कर शक्ति के उच्चतम शिखर की ओर प्रमाण करें। यह सब करने के लिए नेतृत्व जिस नीति को प्रपनाता है वह कूटनीति कहलाती है।

जिस प्रकार राष्ट्रीय मनावन एक देश की आत्मा हाता है उसी प्रकार कूटनीति उस देश का मस्तिष्क होती है। इसके अन्तर्गत म राष्ट्र के पास पाहे कितने ही अन्य साधन क्यों न हो, वह स्थायी रूप से एक शक्तिशाली देश कभी नहीं बन पायेगा। कूटनीति (Diplomacy) का मुख्य कार्य जोता कि मार्गों-मोहोदय भी मानते हैं, यह है कि यह विदेश नीति के माध्यम और साधनों को प्राप्त राष्ट्रीय शक्ति के स्रोतों के साथ एकरूप करती है। कूटनीति के माध्यम से उन सभी रास्तों को खोजा जाता है जिनसे द्वारा उस राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाया जा सके। कूटनीति का व्यवहार करने के लिए एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है।

शांति काल में नेतृत्व का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह कूटनीति के माध्यम से दूसरी राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को बढ़ावे, अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करे तथा राष्ट्रीय स्वार्थों की पूर्ति का भरमक प्रयास करे।

युद्ध काल में नेतृत्व

(Leadership in war time)

शान्तिकाल में राष्ट्र की शक्ति कूटनीति में रहती है जिसका संचालन नेतृत्व द्वारा किया जाता है। कूटनीति जहां अनकल हो जाती है वहीं पर युद्ध आरम्भ हो जाते हैं। युद्ध कूटनीति की असफलता का परिणाम है और इस प्रकार यह नेतृत्व की नीतियों की कुछ अंशों में कमजोरी माना जायगा। युद्ध काल में नेतृत्व को जो उत्तरदायित्व सम्भालने पड़ते हैं वे गुण एवं अनुपात दोनों ही दृष्टियों से शान्तिकालीन उत्तरदायित्वों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं।

पुराने समय में युद्धकालीन नेतृत्व की प्रकृति आज से भिन्न थी क्योंकि युद्ध का स्वरूप भी उस समय आज जैसा न था। उदाहरण के लिए हम महाभारत से लेकर १८५७ के स्वतन्त्रता संग्राम तक के भारतीय युद्धों की ले सकते हैं। इनमें सेनापति सामने-सामने लड़ते थे, युद्ध की हार-जीत का निर्णय बहुत कुछ योद्धाओं की वीरता, शौर्य, कौशल एवं सेना-नायक के नेतृत्व की योग्यता पर निर्भर करता था। सेनापति के गुण और शक्ति को उसकी सेना का गुण एवं शक्ति माना जाता था। कुशल सेनानित्य, मोर्चेबन्दी, घेरा डालना आदि योग्यताओं के साथ सेना का नेता विजय थी को हासिल कर लेता था। उस समय के युद्ध भीमिन थे, केवल सेनापति ही लड़ कर निर्णय कर लेती थीं कि कौन घासन करने का अधिकार रखता है।

आज के युद्ध इतने सीमित नहीं बरकराए गए प्रकृति के हैं। इसी कारण इनको सम्पूर्ण युद्ध (Total war) की संज्ञा प्रदान की जाती है। युद्ध के समय सारा राष्ट्र ही सक्रिय बन जाता है। राज्य के प्रत्येक स्रोत को सरक्षित, विकसित करने एवं काम में लाने की आवश्यकता पड़ जाती है। देश के नेता का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह राष्ट्र की समस्त सामर्थ्य को तथा उसकी शक्ति के प्रत्येक पहलू को संगठित एवं नियोजित करे। इस प्रकार आज के युद्धों की प्रकृति को देखते हुए नेतृत्व का कार्य केवल यहाँ नहीं रह गया है कि वह राष्ट्रपति या सरकार सेना का संचालन करे यद्यपि आज उसे राष्ट्रभूमि से अलग सामान्य नागरिक जीवन में समस्त देश की शक्तियों को सुसंगठित करना होगा।

राज्य चाहे वह प्रजातन्त्रात्मक हो या सर्वाधिकारवादी अथवा राजतन्त्र, राज्य के नेतृत्व की शक्ति कुछ चुने हुए लोगों के हाथों में ही केन्द्रित रहती है । ये चुने हुए लोग ही यह देखते हैं कि क्या देश के सारे साधन युद्ध में देश के पक्ष की शक्तिशाली बनाने में रत हैं अथवा नहीं । पामर तथा परकिन्स के मतानुसार आज के युद्धों को सम्पूर्ण युद्ध (Total war) इसी कारण कहा जाता है क्योंकि इसमें सम्पूर्ण स्रोतों की, सम्पूर्ण संगठन की तथा सम्पूर्ण प्रयत्नों की तथा कमी कमी सरकार की सारी शक्ति की आवश्यकता पड़ जाती है । राज्य के राजनीतिक नेताओं का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे राज्य की सारी शक्तियों का Coordination करें ।

इस प्रकार चाहे शांति हो अथवा युद्ध, चाहे विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना हो अथवा युद्ध की सामग्री का निर्माण, प्रत्येक देश को 'नेतृत्व' की आवश्यकता पड़ती है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रत्येक देश को नेतृत्व के रूप में एक 'श्वणकुमार' की आवश्यकता होती है । 'नेतृत्व' राष्ट्रीय शक्ति के अन्य स्रोतों के सहारे देश का लेकर आगे बढ़ता है । कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि किसी दशरथ द्वारा जाने या अनजाने एक देश के नेतृत्व की हत्या कर दी जाय तो वह देश शक्तिहीन हो जायेगा, उसके शक्ति के सारे स्रोत विसर्जित हो जायेंगे तथा अन्धदम्पति की भांति वह रो-रोकर अपने आप को विनष्ट कर देगा ।

राष्ट्रीय शक्ति का मूल्यांकन (Evaluation of National Power)

राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्व भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, जनसङ्ख्या, तकनीकी, मनोबल, नेतृत्व आदि की विस्तृत जानकारी करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यदि एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनना है तो उसे इन सभी की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा । इन सभी तत्वों का एक सन्तुलित रूप में समन्वय उपयुक्त ही नहीं आवश्यक भी है । राष्ट्रीय शक्ति के परिचय के अध्ययन को समाप्त करने से पूर्व इस अध्ययन की कुछ मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर देना अधिक उपयुक्त रहेगा क्योंकि इन विशेषताओं पर ध्यान दिये बिना आगे बढ़ने पर हम गलत निष्कर्षों की ओर अग्रसर हो सकते हैं । शक्ति की दृष्टि से यदि हम एक राष्ट्र का स्तर मापने जा रहे हों तो, हम जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं—

(१) समन्वयात्मकता—किसी भी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन करते समय हमको सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रीय शक्ति के ऊपर वर्णित सभी तत्व परस्पर सम्बन्धित होते हैं; इन सबके बीच अन्तर्गत और लगाव का सा सम्बाध है। दूसरे शब्दों में अगर ये तत्व आपस में मिल कर एक समन्वित (Coordinated) रूप में कार्य करते हैं तो अवश्य ही एक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर पायेंगे। किन्तु अलग-अलग रहने पर न केवल राष्ट्र को कमजोर करेंगे वरन् ये स्वयं का महत्व भी खो देंगे। पामर तथा परकिन्स महोदय ने राष्ट्रीय शक्ति के समस्त तत्वों को एक-एक करके लिया है तथा यह बताने की कोशिश की है कि यदि वे परस्पर सम्बन्धित न रहे तो नष्ट हो जायेंगे, प्रभावहीन रहेंगे। उनके मतानुसार यह कहना भी गलत होगा कि शक्ति केवल वही रहती है जहां कि वे सभी वर्तमान हो क्योंकि लोग बिना हथियार, नेतृत्व, मनोबल एवं क्षेत्र के भी लड़ सकते हैं। तो भी यह तो सच है कि बिना तत्वों के कोई भी राष्ट्र उल्लेखनीय राष्ट्रीय शक्ति नहीं पा सकता।

(२) सापेक्षिकता—‘शक्ति’ अपने आप में पूर्ण नहीं होती या यों कहिये कि ‘शक्ति’ की कोई सीमा नहीं होती। आप किस देश की शक्तिशाली कहेंगे यह बात राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्वों की एक निश्चित मात्रा के स्वामित्व पर निर्भर नहीं करती। आवश्यक नहीं कि एक हाइड्रोजन बम रखने वाले राष्ट्र को हम शक्तिशाली कहें क्योंकि यदि सभी देशों के पास हाइड्रोजन बम हो तो एक राष्ट्र ऐसी स्थिति में शक्तिशाली न कहला कर सामान्य शक्ति वाला कहा जायेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ‘शक्ति’ एक सापेक्षिक विशेषण है जो उसी को शोभित कर सक्ता है जो कि तुलनात्मक दृष्टि से शत्रु की अपेक्षा शक्ति के तत्वों की अधिक मात्रा का स्वामी है। पामर तथा परकिन्स ने इस बात को बड़े रोचक ढंग से व्यक्त करते हुए बताया है कि एक ४० वर्ष का व्यक्ति १० वर्ष के बालक के सामने तो बड़ा समझा जायगा किन्तु ८० वर्ष के वृद्ध की तुलना में हम उसको युवक ही कहेंगे। इस प्रकार ‘यह देश शक्तिशाली है’ यह कथन भ्रमहीन है जब तक कि यह उल्लेख न किया जाय कि कौन-कौन से देश इससे कमजोर हैं। इस प्रकार कमजोर राष्ट्र को जानने के लिए भी उसे दूसरे राष्ट्रों की शक्ति की कसौटी पर कसना पड़ेगा।

(३) परिवर्तनशीलता—शक्ति के विभिन्न तत्वों की स्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है। एक देश कल यदि सर्वोच्च शक्ति या तो आवश्यक नहीं कि आज भविष्य में होने वाले समय में भी वह शक्तिशाली बना

PART III

Instruments for the promotion of national interest, Diplomacy, Propaganda and Political Warfare : Economic Instruments for National Policy, Imperialism and Colonialism, War as an instrument of National policy.

अध्याय ७—राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन : कूटनीति, प्रचार और राजनैतिक युद्ध
(Instruments for the Promotion of National Interest : Diplomacy, Propaganda and Political Warfare)

अध्याय ८—राष्ट्रीय नीति की अभिवृद्धि के साधन : आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद-अपनिवेशवाद एवं युद्ध
(Instruments for the promotion of National Interest : Economic Instruments, Imperialism, Colonialism and War)

“अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के सभी साधन एवं तकनीकें मैत्रीपूर्ण तथा भगडेपूर्ण, सम्बन्धों में, शान्ति एवं युद्ध दोनों ही कालों में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यद्यपि इतना अवश्य है कि इनमें से कुछ की प्रकृति अधिक समझाने बुझाने की है जबकि अन्य दवावकारी हैं।”

—फ्रैंकेल

“कूटनीति अथवा राज्य स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करने को कहते हैं जो कभी-कभी उनके अधिनस्थ राज्यों से उनके सम्बन्धों के लिए भी लागू होता है।”

—सर अरनेस्ट सेटा

“जब कभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वे दूसरे देशों का अहित करती हों अथवा नहीं, वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन हैं।”

—यामर तथा परकिन्स

“साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित रहना है किन्तु दूसरे देशों को जीतने की नीति को ही हम साम्राज्यवाद नहीं कह सकते।”

—बुसरिन

“उपनिवेशवाद अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में राष्ट्रीयता का स्वामायिक अति-प्रवाह (over-flow) है। इसकी परीक्षा उपनिवेशियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे अपनी सम्यता को अपने नवीन सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाल सकें।”

—हाथसन

“अगर तूम शान्ति चाहते हो तो पहले युद्ध को समझो।”

—सिडेल हाट्ट

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन : कूटनीति, प्रचार और राजनैतिक युद्ध

[INSTRUMENTS FOR THE PROMOTION OF NATIONAL
INTEREST DIPLOMACY, PROPAGANDA AND
POLITICAL WARFARE]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के दो रूप हैं । पहला रूप सहयोग (Co-operation) है । यह बड़ा पाया जाता है जहाँ पर कि भगड़ा या सघर्ष नहीं होता । दूसरा रूप लड़ाई है । यह तब उत्पन्न होती है जब कि सघर्ष में समझौते की गुञ्जाइश न रह जावे तथा विरोधी को नष्ट करना ही एकमात्र लक्ष्य रह जाये । जैसे अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार इन दोनों ही अतिस्थितियों के बीच में रहता है । इस स्थिति को हम प्रतिযোগिता कह सकते हैं । राज्यों के बीच सदैव किसी न किसी विषय पर सघर्ष की स्थिति रहती है किन्तु यह सघर्ष अधिक नहीं बढ़ पाता और प्रायः समझौते में इसका अन्त होता है । राज्यों के मध्य स्थित व्यवहारों को राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज दोनों की ही प्रवृत्ति के द्वारा प्रशासित किया जाता है । राज्यों की एक मुख्य विशेषता यह होनी है कि वे मानवाय समूहों का सर्वोच्च रूप होते हैं, वे अपने ऊपर किसी भी सर्वोच्च को नहीं देखना चाहते और भाव आत्म-हित की दृष्टि से ही कार्य करते हैं । यह आत्म-हित ही उनका राष्ट्रीय हित है । अन्तर्राष्ट्रीय समाज राज्यों के ऊपर अधिकारपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं करता, वह उनके व्यवहार के लिए केवल कुछ नियम मात्र प्रस्तावित कर सकता है ।

इन नियमों का पालन ये राज्य अपने राष्ट्रीय हित (National Interest) की दृष्टि से करते हैं। आज का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार प्रत्येक स्तर पर सघर्ष का प्रदर्शन करता है। युद्ध एवं हिंसा की घमकियाँ लगातार दो जानी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत कुछ ऐसी स्थिति में आ गया है जिस स्थिति में कि हास के कथनानुसार व्यक्ति राज्य की स्थापना से पूर्व रहता था। इस अराजकता एवं अव्यवस्था की स्थिति से कैसे बाहर आया जाये ? यह एक भिन्न प्रश्न है। यहाँ हम इस प्रश्न की गम्भीरता या इसके समाधानों पर विचार नहीं कर रहे हैं बरन इस अध्याय में तथा अगले अध्याय में हम उन विभिन्न साधनों का अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा एक राज्य अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना आज प्रत्येक राज्य का सब प्रमुख राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा कर वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रहे निरन्तर सघर्ष में विजय पाने की चेष्टा करता है तथा अपने अस्तित्व एवं विकास के लक्ष्यों की साधना करता है।

अपने राष्ट्रीय हित (शक्ति की अभिवृद्धि) की प्राप्ति के लिए एक राज्य अनेक साधन अपनाता है। स्वयं की सामर्थ्य एवं योग्यता तथा अवसर की अनुकूलता के आधार पर वह यह तय करता है कि उसे किस साधन को किस राज्य के साथ और कब अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए विश्व के राज्य जिन साधनों को अपनाते हैं तथा अपना सकते हैं वे मुख्य रूप से ये हैं—

- (i) कूटनीति (Diplomacy)
- (ii) प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध
(Propaganda and Political Warfare)
- (iii) आर्थिक साधन (Economic Instruments)
- (iv) साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद
(Imperialism and Colonialism)
- (v) युद्ध (The war)

प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इन साधनों में से कुछ को अथवा सभी को अपनाता है। कूटनीतिक सम्बंध तो सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की विशेषताएँ हैं जो कि प्रायः सर्व ही राज्यों के पारस्परिक सम्बंधों का आधार बनते हैं। प्रचार का और राजनैतिक युद्ध का द्वारा राज्य अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मलगन कूटनीति की सहायता करता

है। प्रायिक साधन भी उसे कुछ ऐसा ही करने का अवसर प्रदान करते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाने की सातिर एक देश प्रसारवादी नीतियाँ अपनाता है और साम्राज्य तथा उपनिवेश कायम करता है। जब कूटनीति एक राज्य के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में असफल हो जाती है तो वह राज्य युद्ध का मार्ग अपनाता है और जो कामें वह बार्ता द्वारा नहीं कर सका उसे शक्ति द्वारा करने का प्रयत्न करता है। युद्ध के समय भी अन्य साधन सक्रिय रह नकने हैं और प्रायः रहते हैं किन्तु अन्य साधनों की सक्रियता के साथ युद्ध का रहना जरूरी नहीं है। यदा-कदा उसकी घमकी अवश्य प्रभावशाली सिद्ध हो सकती है। प्रस्तुत अध्याय में हम राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के प्रथम दो साधनों अर्थात् कूटनीति तथा प्रचार और राजनैतिक युद्ध का अध्ययन करेंगे, जो के सम्बन्ध में अनेक अध्याय विचार करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का बदलता रूप (The Changing Pattern of Inter-State Behaviour)

राज्यों का पारस्परिक व्यवहार एक बात में सभी स्थानों पर और सभी कालों में एक स्थान पर कभी भी एक जैसा नहीं रहा है। स्थान तथा काल का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है और इसलिए इसका रूप भी तदनुसार बदलता रहा है। ऐसी स्थिति में हम चाहें तो दो राज्यों के एक निश्चित काल के पारस्परिक व्यवहार को आसानी से जान सकते हैं। किन्तु इन सम्बन्धों में दूसरे बहुत से राज्य भी जोड़ दिये जायें तथा इतने एक समूह समय तक के लिए व्याप्य बना दिया जाये तो मुश्किल हो जायेगी। विभिन्न क्षेत्रों एवं कालों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का रूप बहुत कुछ बदल जाता है। कई देश आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उतर आए जबकि तिब्बत और नेपाल जैसे हिमालय की तराई के देश वर्तमान सत्ताधीन तक घृणक बने हुए थे। हम किसी भी देश की विदेश नीति का मूलांकन उस समय तक नहीं कर सकते जब तक कि पहले नौदल से निवृत्त दूसरे राज्यों के सम्बन्धों में बिना उनका हुमा है। विदेश नीति के प्रायः सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक देश के उत्तमत्वे पर निर्भर करते हैं। कुछ देश शक्ति राजनीति के क्षेत्र में परम महिम्ना के साथ उत्तक्रे हुए हैं, जबकि दूसरे देश शक्ति राजनीति से अलग रह कर एक सदस्य या असदस्य दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं।

परम्परागत रूप से प्रत्येक राज्य विदेशी सम्बन्धों में अत्यधिक उपनिवेशी का ओत्तिम नहीं उठाना चाहता और इसलिए वह घृणक या तटस्थ रहना

चाहता है। आज की परिस्थितियों में पार्यव्ययता की नीति प्रायः समाप्त हो गई है और तटस्थता की नीति ने भी अपना अर्थ पूरी तरह से बदल दिया है। पार्यव्ययवाद का अर्थ यह होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से एक देश अपना हाथ पूरी तरह खींच ले। मौगोलिन पार्यव्यय के आधार पर यह नीति पहले सम्भव थी और इसीलिए यूरोपीय प्रभाव से पूर्व चीन तथा जापान इसे अपना सके, किन्तु आज की परिस्थितियाँ इसे असम्भव बना देती हैं।

आज से पचास वर्ष पूर्व तटस्थता को एक कानूनी मान्यता समझा जाता था जिसका अर्थ था युद्ध में भाग न लेना। यह नीति तटस्थ राज्य की कुछ अधिकार सौंपती थी और कुछ वर्तक्य डालती थी। आज की स्थिति में इसका अर्थ यह है कि दो प्रमुख गुटों के बीच असलमन रहा जाए तथा सन्धियों की व्यवस्था में भाग न लिया जाए। आज के तटस्थ देश सोवियत रूस या समुक्त राज्य अमरीका के गुट की किसी भी सैनिक शक्ति में सम्मिलित नहीं होते, वे किसी भी प्रश्न पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। हमारे अनिरिक्त वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक रूप से भाग ले सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते समय यह जरूरी है कि एक राज्य की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में दृष्टिकोण को जाना जाए और दूसरे किसी एक राज्य से सम्बन्धित उसके दृष्टिकोण को जाना जाए। इस दृष्टि में हम राज्यों को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। कुछ राज्य यथास्थिति के समर्थन होते हैं। ये राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि उनसे मनुष्यानुसार इससे उनसे हितों की रक्षा होती है। दूसरे राज्य यह अनुभव करते हैं कि विश्व व्यवस्था उनके राष्ट्र हित के विरुद्ध है और इसे बदलने पर उन्हें प्राप्ति होगी। ये देश सशोधन वाले देश कहाते हैं। ये सकारात्मक एवं निपेधात्मक दृष्टिकोण व्यापकता एवं निश्चय की दृष्टि में पर्याप्त मिश्रता रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यथास्थिति के सभी समर्थन शिथिल व्यवस्था की रक्षा के लिए समान रूप से तैयार नहीं हैं और इसी प्रकार सशोधनवादी राज्य भी वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समान रूप से उत्कण्ठ नहीं हैं। दुनिया के राज्य अपने मित्रों के प्रति, अपने सम्भावित शत्रुओं के प्रति एवं तटस्थ देशों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाते हैं उनके बीच पर्याप्त मिश्रता होती है। एक विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही वे यह तय करते हैं कि दूसरे राज्य से सम्बन्ध रखने के लिए कौन से साधन और तकनीक अपनायें।

कोई भी राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हित साधनों का प्रयोग करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि शक्ति के विभिन्न तत्व वहां किस माना में उपलब्ध होते हैं। जो देश संनिव दृष्टि से कमजोर हैं वे स्वतः ही अपने विदेश सम्बन्धों को गैर-सैनिक साधनों एवं तकनीकों के आधारे पर विकसित करेंगे। जो राज्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं वह विदेश नीति के तत्वों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक साधनों को नहीं अपना सकते। इस प्रकार यह राज्य की इच्छा मात्र का ही प्रश्न नहीं है क्योंकि यह उनके अन्य राज्य के प्रति बौद्धिक दृष्टिकोण तथा उसके साधनों की क्षमता पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में कुछ अपरिहार्य तत्व भी पैदा हो जाते हैं। समय के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में अवसर एवं चुनौतियां बदलती रहती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय तौर तरीके तथा अन्तर्राष्ट्रीय आदान प्रदान के खेल को प्रभावित करने वाले नियम स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं होते। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की अमरीकी विदेश नीति की यह कह कर आलोचना की जाती है कि यह अणु हथियारों पर अत्यधिक आश्रित थी क्योंकि अमरीका इन हथियारों की दृष्टि से शक्तिशाली था किन्तु तथ्य यह है कि अनेक प्रश्नों पर ये हथियार बेकार थे तथा मुख्य सोविपत चुनौतियां धीरे धीरे संज्ञात्मक एवं आर्थिक क्षेत्रों में आती जा रही थी। ग्रेट-ब्रिटेन तथा फ्रांस ने सन् १९१६ में स्वेज नहर विवाद के समय यह ज्ञान लिया कि बीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में कोई भी सैनिक हस्तक्षेप केवल तभी किया जाना चाहिए जबकि कम से कम एक बड़ी शक्ति या समुक्त राष्ट्रमण्डल का समर्थन प्राप्त हो।

प्रथम विश्व युद्ध तक अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध केवल दूपरी सरकारों के साथ ही संचालित किये जाते थे किन्तु उसके बाद से अन्य राज्य के लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का महत्त्व बढ़ गया है। फलतः अन्त-सरकारी सम्बन्धों के साधनों एवं तकनीकों को अग्र बढ़ता जा रहा है तथा उनके स्थान पर ऐसी तकनीकों का लाया जा रहा है जो कि जनता में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उपयुक्त हैं। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इन दोनों हलों के बीच विरोध भी स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए समुक्त राज्य अमरीका पूर्वी योरोप को गैर-पाराना सरकारों के सम्बन्धों को निश्चित करने के लिए कभी-कभी उनकी आर्थिक बठिनाइयों में इस आशा से मदद कर देता है कि उनकी सद्भावना प्राप्त कर सके तथा सोविपत सच के प्रति उनकी स्वाभिमानिता का कम कर सके। यह नीति अलगाव (D-detachment) की नीति कहलाती है। इसका प्रिक्ल्प यह है कि इन देशों की जनता से प्रयोग की जाये कि वे अपनी सरकारों का सक्ता पलट दें तथा उनके स्थान पर ऐसी

सरकारें स्थापित करें जो कि समुक्त राज्य अमरीका के प्रति अधिक मंत्री-पूर्ण हो। यह नीति सहार (Subversion) की नीति कहलाती है। स्पष्ट है कि ये दानो प्रकार की नीतियां परस्पर विरोधी हैं।

एक राज्य की विदेश नीति दूसरे देश की सरकारों के प्रति केवल निर्देशित ही नहीं होनी बरन् उनको अपने साधन के रूप में भी प्रयुक्त कर लेती है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से यह प्रवृत्ति पर्याप्त बढ गई है कि महाशक्तियां स्वयं प्रत्यक्ष रूप से किसी सधर्प में नहीं उलझती तथा किसी देश को अपने हितों की सिद्धि का सहारा बना कर उसे उलझा देती हैं तथा स्वयं पीछे से सहायता करती रहती हैं। यह बात साम्यवादी गुट में अधिक देखने का मिलती है क्योंकि साम्यवादी विचारधारा अन्तर्राष्ट्रीय भाति में विश्वास करती है अतः कोई भी साम्यवादी देश सोवियत सत्र के हितों की साधना का माध्यम बनने में प्रायः एतराज नहीं करता। चीन, यूगोस्लाविया आदि कुछ देशों को विदेश नीति का साधन नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वहां राष्ट्रवाद की भावनाएँ उभर चुकी हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रभाव भी धीरे-धीरे बढता जा रहा है। समुक्त राष्ट्रसंघ के चाटर् में यह लिखा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति का प्रयोग या शक्ति की धमकी से काम न लिया जाय। इस प्रावधान का यद्यपि सदैव ही पालन नहीं किया जाता किन्तु फिर भी राज्यों के व्यवहार पर इसका पर्याप्त प्रभाव होता है। सामान्य रूप से यदि अतः बात समान रह तो राज्य उन साधनों एवं तकनीकों को अपनाता चाहेंगे जो कि चाटर् के अनुरूप हो तथा महासभा में अभिभूत अंतर्राष्ट्रीय लोकमत की स्वीकृति प्राप्त कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में मित्रों एवं शत्रुओं के बीच तथा समझाने-बुझाने एवं दबाव डालने के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं होता। अनेक मामलों में सबंध कई प्रकार का होता है। अधिकतर मंत्रीपूर्ण संधियों में भी दण्ड की धमकी प्रायः दी जा सकती है तथा विचारधारागत रूप से विरोधी देश भी व्यापार के मामलों में प्रायः समझौता कर लेते हैं। शक्तिकाल का अर्थ यह नहीं होता कि सधर्प का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार युद्ध का अर्थ भी यह नहीं होता कि अब दबावहीन साधन बकाय ही हो गये हैं। फौज महानयन का यह कथन इस दृष्टि से पर्याप्त उपयोगी एवं तथ्य संगत प्रतीत होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के सभी साधन एवं तकनीकें, मंत्रीपूर्ण तथा भगड़ेपूर्ण सम्बन्धों में, शांति एवं युद्ध दोनों ही कालों में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यद्यपि इतना

अवश्य है कि इनमें से कुछ की प्रकृति अधिक समझाने बुझाने की है जबकि अन्य दबावकारी हैं। वर्तमान काल में राष्ट्रीय नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीति के बीच का अन्तर एवं दूरी भी कम होती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंध उन नीतियों से पर्याप्त प्रभावित होते हैं जिनको कि हम शुद्ध रूप से घरेलू नीति कहते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े देश की प्राथमिक नीति उसका स्वयं का घरेलू मामला है किन्तु यह उन छोटे देशों के व्यापार एवं मुद्रा पर भारी प्रभाव डाल सकता है जो कि उस पर आश्रित हैं। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव रखने वाले किसी भी राष्ट्रीय हित को अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का समझा जा सकता है। भारत में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। यह विषय शुद्ध रूप से उसकी घरेलू नीति या विषय था तथा विश्व के अन्य देशों को इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। इतने पर भी हम यह नहीं कह सकते कि भारत की इस नीति में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई प्रभाव न डालना शक्य था यह उसमें पूर्ण रूप से असम्बद्ध थी। भारत द्वारा निर्यात एवं आयात किए जाने वाले सामान के मूल्यों पर इसका भारी प्रभाव पड़ा। दूसरे देशों की भी इसके प्रभावों द्वारा उनकी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ा।

राष्ट्रीय हित का अर्थ (The Meaning of National Interest)

मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की भांति राष्ट्रीय जीवन में भी व्यवहार के दो पक्ष होते हैं—पहला स्वायत्त पक्ष और दूसरा परमार्थ पक्ष। पहले पक्ष के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक कार्य का प्रमुख लक्ष्य उसके स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करना होता है। इस दृष्टि से एक राष्ट्र का न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, केवल स्थायी स्वार्थ होते हैं। अन्य देश यदि उस राष्ट्र के इस स्वार्थ की पूर्ति में एक सहायक का कार्य करेंगे तो अवश्य ही गहरे मित्र बन जायेंगे किन्तु यह मित्रता केवल तभी तक स्थिर रहेगी जब तक कि इसका आधार 'स्वार्थ पूर्ति' कायम करना रहता है। इस आधार के समाप्त होते ही मित्रता का महत्व भी घराशायी हो जायगा और यह भी सम्भव है कि वे देश परस्पर उतने ही शत्रु बन जायें जितने कि पहले वे मित्र थे। विश्व का इतिहास एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्रम इस कथन की पुष्टि के लिए इतने प्रमाण दे सकता है कि यह कथन आजकल स्वयं सिद्ध सत्य सा बनता जा रहा है।

राष्ट्रीय क्रियाओं के परार्थमूलक पक्ष में उन सभी कार्यों को समाविष्ट किया जा सकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्व शांति एवं विश्व समाज में समानता, स्वतन्त्रता तथा भाईचारे (Liberty, Equality and Fraternity) के सिद्धांतों को सफल बनाने की दिशा में किये जाते हैं। समुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से अनेक राष्ट्र पिछड़े देशों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। वे उनके शैक्षणिक, आर्थिक, तकनीकी, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करके वहां के जीवन स्तर को अपने समकक्ष बनाने में प्रयत्नशील हैं। समुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक अभिकरण इन परार्थमूलक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन (ILO), खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO), अन्तर्राष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण (IAEA), विशेष अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास की राशि (SUNFED), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (IDA) तथा बाल विकास की राशि (UNICEF) आदि महत्वपूर्ण हैं।

राष्ट्रीय क्रियाओं के स्वार्थमूलक तथा परार्थमूलक पक्षों का तुलनात्मक महत्व आकस्मिक समय प्रायः स्वार्थमूलक क्रियाओं को ही प्रभावशील ठहराया जाता है। अनेक विचारकों की यह मान्यता बहुत कुछ सत्य है कि परार्थमूलक क्रियाएँ अपने आप में साध्य नहीं हैं, वे साधन हैं तथा उनका परम लक्ष्य है उस राष्ट्र के स्वार्थों की पूर्ति। उदाहरण के लिए हम भारत की विदेश नीति के समर्थकों के तर्कों को ले सकते हैं। यह कहा जाता है कि भारत की शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित असलम्यता की विदेश नीति को केवल आदर्शवादी मानना भ्रमपूर्ण है क्योंकि देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए विश्व में शान्ति बनाये रखना परम आवश्यक है। भारतीय विदेश नीति विश्व शांति एवं विश्व सहयोग की अभिवृद्धि का प्रयास करती है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय हित (National Interest) को उपेक्षणीय या गौण नहीं बनाती बल्कि सच्चे अर्थों में उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को सहयोग एवं सहायता इसलिए देता है कि वह उसके स्वयं के दूरगामी हित में है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एक व्यापार के समान है जिसमें कोई भी सर्वां उससे दुगुनी आमदनी की आशा में किया जाता है। मूल रूप में क्रूर स्वार्थ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का प्रेरक है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि राष्ट्रों के बीच युद्ध हुए, भगबे हुए, शान्ति हुई, सन्धियां हुई,

इन सबके पीछे एक ही मूल कारण था जो कि सारे घटनाचक्र को घुमाने के लिये उत्तरदायी रहा और वह था प्रभावशील राष्ट्रों का अपना-अपना स्वार्थ ।

यदि यह मान लिया जाय कि राष्ट्रीय हित ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सब कुछ है तो अब समस्या यह आती है कि आखिर इस 'हित' की प्रकृति एवं स्वरूप क्या है । किन-किन बातों को इस शब्द की परिधि में समाहित किया जाय और किस आधार पर । दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने की समस्या उठ खड़ी होती है । राष्ट्रीय हित कोई स्थिर या शाश्वत वस्तु नहीं है, वह तो एक परिवर्तनशील तत्त्व है जिसे गत्यात्मक (Dynamic element) कहा गया है । लम्बे इतिहास में एक समय ब्रिटेन का स्वार्थ भारतवर्ष में अपना साम्राज्य बनाये रखना हो सकता है तो दूसरे पक्ष में उसका यह कार्य हित साधक की अपेक्षा हित का विरोधी भी हो सकता है । राष्ट्रीय हित स्थान एवं काल (Time and Place) के परिवर्तन के साथ अपने स्वरूप को बदलता रहता है । एक राष्ट्र के एक ही समय में अनेक हित हो सकते हैं । इन हितों के बीच परस्पर विरोधभास भी रह सकता है । ऐसी अवस्था में जो हित महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से उच्च स्तर का होता है उसको वह राष्ट्र प्राथमिकता प्रदान करता है । निम्न-स्तर वाले राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के कारण अनेक बार राष्ट्रों की राजनीति की असफल होशें देखा गया है ।

राष्ट्रीय हित (या हितों) के स्वरूप में भिन्नता, अस्थिरता, विरोधभास, स्तरों की असमानता आदि अनेक विशेषताएँ देखने को मिलती हैं । मॉर्गेन्थो (Morgenthau) महोदय के मतानुसार राष्ट्रीय हित में प्रायः दो तत्व निहित होते हैं—एक तो यह कि यह तार्किक रूप से वाछनीय है और इस प्रकार आवश्यक भी । दूसरे, यह अस्थिर तथा परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है । राष्ट्रीय स्वार्थ को आवश्यक मानने से उनका भयं यह है कि प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता (Identity) की रक्षा करना आवश्यक बन जाता है । इसके अभाव में उनका स्वयं का अस्तित्व भी मिट सकता है । एक देश का राष्ट्रीय हित दूसरे देश के राष्ट्रीय हित के अनुकूल भी हो सकता है और विरोधी भी, किन्तु भाग के सम्पूर्ण युद्ध (Total War) के युग में एक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए तथा राजनैतिक नैतिकता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्र अपने स्वार्थों को निर्धारित करते समय दूसरे राष्ट्रों के हितों को भी ध्यान में रखे तथा दोनों के बीच अनुकूलता की स्था-

पना का प्रयास करे। राष्ट्रीय हितों की मान्यता यह मान कर नहीं चलती कि विश्व में सहयोग रहेगा तथा ससार में शान्ति बनी रहेगी और न ही यह मान कर चलती है कि ससार में अशान्ति एवं युद्ध छिड़ जायगा वरन् इसका यह विश्वास है कि ससार में हमेशा सघर्ष तथा झगड़े बने ही रहेंगे तथा ये झगड़े युद्ध का रूप धारण न कर लें इसके लिए कूटनीति (Diplomacy) के माध्यम से इन सघर्षों के बीच सतुलन की स्थापना कर ली जायगी।

राष्ट्रीय स्वार्थ अथवा राष्ट्रीय हित के उपरोक्त रूप को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय हित के माधनों को जानना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित
(National Interest defined in terms of National Power)

राष्ट्रीय हित की प्रकृति एवं स्वरूप के सम्बन्ध में जो विचार ऊपर व्यक्त किये गए हैं यदि उनको मान कर अपने अध्ययन को हम आगे बढ़ायें तो भाव में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय हित का प्राप्त करने का मुख्य साधन 'शक्ति' है। राष्ट्र के हित का चाट काढ़ भी रूप एवं लक्ष्य क्यों न हो एक देश उसे तभी प्राप्त कर सकता है जबकि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। शक्ति अनेक प्रकार की हो सकती है जैसे आर्थिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, भौगोलिक शक्ति, सैनिक शक्ति आदि। शक्ति के इन विभिन्न रूपों का वर्णन राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन करते समय किया जा चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के गणमान्य विद्वानों के मन में राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के बीच इतना गहरा एवं अमिश्र सम्बन्ध है कि दोनों को पृथक् करने से दोनों का ही अस्तित्व सतरे में पड़ जाता है। इन विचारों के मतानुसार यदि राष्ट्रीय शक्ति को ही राष्ट्रीय हित मान लिया जाय तो अनिश्चयिता नहीं होगी। यह मन सही भी है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र शक्तिशाली बनने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है और शक्ति का सघर्ष ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास का मूल तत्व है। 'शक्ति' यद्यपि एक साधन है जिसका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना, उन्हें सम्भव बनाना तथा राष्ट्र को विश्व समाज में उच्च स्थान प्रदान कराना है किन्तु फिर भी ये समस्त बातें आज इतनी प्रचलित हो चुकी हैं कि आज शक्ति एक साधन मात्र न रह कर साध्य बन गयी है। यही कारण है कि अनेक राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने की धुन में अपने अस्तित्व तक की दाव पर लगा देते हैं। हिटलर के जर्मनों और मुसोलिनी के इटली को देखने पर यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है।

इन प्रकार हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति एक राष्ट्र का सबसे प्रमुख 'राष्ट्रीय हित' (National Interest) है जिसे प्राप्त करने के बाद ही अन्य हितों की प्राप्ति करना भी सम्भव होता है। राष्ट्रीय शक्ति के विभिन्न तत्व यदि एक देश में संतुलित एवं सुविकसित रूप में प्राप्त होते हैं तो स्पष्ट है कि वह देश उन देशों की अपेक्षा शक्तिशाली माना जायेगा जिनके पास इन तत्वों के ऐसे स्तर का अभाव है। एक राष्ट्र का यह सबसे बड़ा हित होगा कि राष्ट्रीय शक्ति के इन तत्वों का संतुलित विकास किया जाय और उन सभी बाधाओं को दूर किया जाय जो कि राष्ट्रीय शक्ति को उच्च शिखर तक पहुँचने में रोक लगाने हैं। उदाहरण के लिए यदि एक देश की आर्थिक शक्ति को हम बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ा औद्योगीकरण करना पड़ेगा। निम्न देश में औद्योगीकरण (Industrialization) किया जाना है वे देश अविश्वसनीय होने के कारण मुख्यतः द्वितीय विश्वयुद्ध के होने के तत्पश्चात् वे उन सभी दृष्टिकोणों, सामाजिक नीतियों एवं तकनीकों को विरोध करने हैं जिनसे एक औद्योगिक समाज की विस्तृता माना जाता है। ऐसी स्थिति में तीव्र गति से औद्योगीकरण नहीं किया जा सकेगा जो कि उस देश का प्रभाव राष्ट्रीय हित होगा है। इस हित को प्राप्त करने के लिए जनता में शिक्षा का प्रसार किया जायेगा, वहाँ के जीवन स्तर को ऊँचा बढ़ाया जायेगा तथा साथ ही विकसित राष्ट्रों से उनका सम्पर्क स्थापित किया जायेगा। किन्तु यह सब करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है। बिना पूँजी के एक अर्धविकसित (Semideveloped) देश के नागरिकों को ऐसा बनाना असम्भव है कि वे परिवर्तन के लिए पहल कर सकें। साथ ही पूँजी का औद्योगीकरण की प्रक्रिया में भी महत्व है। यहाँ आकर पूँजी प्राप्त करना उस देश का राष्ट्रीय हित बन जाता है। पूँजी प्राप्त करने के मुख्य रूप से तीन तरीके हो सकते हैं—

प्रथम, पूँजी हमारे देशों से सहायता एवं ऋण के रूप में प्राप्त की जाय।

द्वितीय, पूँजी अपने देश में ही उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर प्राप्त की जाय; और

तृतीय, पूँजी बढ़ाने का तीसरा अर्थान्वय विधेयात्मक है अर्थात् देश की खपत (Consumption) को कम कर दिया जाय—जैसा कि लाख स्थिति में स्वावलम्बन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समय का खाना छोड़ने एवं इसी प्रकार के अन्य प्रतिबंध लगा कर किया जा रहा है।

जहाँ तक पूँजी की विदेशों से प्राप्त करने का प्रश्न है वह किया जाना चाहिए और उसके बिना भागे बड़ा भी नहीं जा सकता किन्तु साथ ही केवल

विदेशी सहायता पर निर्भर रह कर ही एक देश अपना समुचित विकास (आत्मसम्मान के साथ) नहीं कर सकता। इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि देश की पैदावार को बढाया जाय। साम्यवादी चीन में मनुष्य शक्ति का जो अमानवीय रूप से प्रयोग किया गया वह इसी तथ्य को लेकर किया गया है। इस प्रकार औद्योगीकरण की प्रक्रिया में एक देश का जीवन स्तर प्रारम्भ में तो बढन की अपेक्षा घटता है और यह जीवन स्तर की कसौटी अप्रत्यक्ष रूप से उस देश का राष्ट्रीय हित (National interest) है।

असल में राष्ट्रीय हित गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है क्योंकि परिस्थितियाँ एवं समय की आवश्यकताएँ उसे जैसा चाहती हैं मोड़ देती हैं किन्तु फिर भी यह एक सार्वकालिक सत्य (Universal truth) है कि राष्ट्रीय हित को बिना शक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिक शक्ति प्राप्त करना एक राष्ट्र का ऐसा हित है जो कि सभी कालों में एवं सभी स्थानों में स्थिर रहता है। परिस्थितियों में उतार-चढ़ाव आते हैं और चले जाते हैं किन्तु एक राष्ट्र की 'राष्ट्रीय शक्ति' में वृद्धि की अभिलाषा अप्रमादित बनी रहती है। अब तक के अनुभवों में ऐसा प्रतीत होता है कि 'राष्ट्रीय शक्ति' के रूप में परिभाषित 'राष्ट्रीय हित' (National interest defined in terms of national power) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सार्वकालिक अपरिवर्तनशील सत्य है और शायद इसी कारण मार्गेनथो (Morgenthau) महोदय ने यथार्थवाद के समर्थकों को अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय दूसरे देश के 'शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित' को ध्यान में रखने का परामर्श दिया है। राष्ट्रीय हित के रूपों को ध्यान में रख कर यदि अध्ययन किया जाय तो हम एक देश के व्यवहार तथा एक विशेष प्रश्न पर उसके दृष्टिकोण के बारे में भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं।

राजनय या कूटनीति (Diplomacy)

एक देश के दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों का संचालन एवं प्रतिपत्ति वर्ग द्वारा किया जाता है जिसे कूटनीतिज्ञ कहा जाता है। इस वर्ग के कार्यों की प्रणाली एवं उनके परिणामों पर उस देश का विचार एवं भाव्य निर्भर करता है। दो देशों के बीच छोड़ा मतभेद रहने पर भी मामूलीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का काम इन कूटनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार टैलर (Taylor) के मतानुसार यदि कूटनीतिज्ञ डॉनहान के कानों को देखा जाय तो हमें कूटनीति का महत्त्व ज्ञान हो जायगा। यह कहना पर्याप्त

होगा कि जब-जब भी व्यक्ति ने ऐसा चाहा है, कूटनीतिक मनुष्यों ने शांति में रहने में सहायता की है। इस प्रकार कूटनीति का अन्तराष्ट्रीय राजनीति में महत्त्व है क्योंकि यह शान्ति बनाये रखने में सहायता करता है, देशों की हित पूर्ति की साधन बनता है और शक्ति संघर्ष के बीच सामंजस्य पैदा करती है।

कूटनीति का अर्थ और परिभाषाएँ

(Meaning and Definitions of Diplomacy)

कूटनीति को परिभाषित करते समय विभिन्न-विद्वानों ने इसके अलग अलग अर्थ बताये हैं। कूटनीति (Diplomacy) के प्रसिद्ध विचारक हैराल्ड निकल्सन (Harold Nicolson) के मतानुसार कूटनीति शब्द का प्रयोग पाँच भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग विदेश नीति (Foreign policy), समझौता (Negotiation), समझौते की प्रक्रिया (The process and machinery by which such negotiation is carried out), विदेश सेवा की एक शाखा (A branch of Foreign Service) आदि अर्थों में किया जाता है। निक्ल्सन महोदय के मतानुसार कूटनीति का पाचवें अर्थ में प्रयोग बड़ा दुर्भाग्यशाली है। इन अर्थों में सबसे अच्छा रूप वह है जबकि यह शब्द समझौते (Negotiations) करने की बुद्धि के लिए प्रयुक्त किया जाय तथा इसका सबसे बुरा रूप वह है जबकि इसे एक कण्ठपूर्वक तथ्य (Glibful aspect of fact) के लिए प्रयोग में लाया जाये।

मोर्गेन्सकी (Organski) महोदय ने निक्ल्सन द्वारा बताये गये कूटनीति (Diplomacy) के उक्त अर्थों में से कुछ को अस्वीकार किया है। उनके कथनानुसार कुशलता, चतुराई और कपट एक अच्छी कूटनीति के लक्षण अने ही हो सकते हैं किन्तु इनकी कूटनीति को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं कहा जा सकता। कूटनीति को विदेश नीति के समनदा भी नहीं माना जा सकता। 'कूटनीति' विदेश नीति का एक ऐसा अंग है जिसके द्वारा स्वयं विदेश नीति का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। मोर्गेन्सकी ने कूटनीति को परिभाषित करते हुए उसे "दो या दो से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाले समझौतों की प्रक्रिया माना है।"

मैकलेलन, मोलसन तथा सोल्डरभेन के कथनानुसार "कूटनीति की एक सर्वाधिक मूल परिभाषा यह है कि यह प्रत्येक राज्य के द्वारा प्रतिनिधित्व पर आधारित राष्ट्रों के मध्य स्थित सम्पर्क का एक रूप है।"

विक्सो राइट के कथनानुसार "लोकप्रिय रूप में कूटनीति का अर्थ है किसी सौदे में या लेन-देन में चातुरी, धोनेवाजी तथा कुशलता का प्रयोग। अपने विशेष अर्थ में जिसमें कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयुक्त की जाती है यह मोदेवाजी की वह कला है जो राजनीति की उस व्यवस्था में कम मूल्य में अधिक से अधिक सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है जिसमें कि युद्ध एक सम्भावना है।"

कूटनीति (Diplomacy) एक अनेकार्थक शब्द है जिसकी कोई सामान्य और सन्तोषजनक, सर्वसम्मत परिभाषा सम्भव नहीं हो सकती। आक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार 'कूटनीति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का समझौता (Negotiations) द्वारा प्रगट है।' एक दूसरे विचारक सर एर्नेस्ट सैटो (Sir Ernest Satow) के शब्दों में "कूटनीति" स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि (Intelligence) और चतुर्य (tact) का प्रयोग करने को कहा जाता है। कूटनीति की प्रकृति समझाने हुए पनिकर (K M Panikkar) महोदय ने महामारत के एक वृत्तान्त का उद्धृत किया है जिसमें युद्ध से पूर्व समझौते के लिए बोरबो के दरबार में जान वाले श्रीकृष्ण से द्रोपदी ने उनके जाने के महत्त्व पर सदेह प्रकट किया था। उस समय श्रीकृष्ण ने उत्तर दिया कि— मैं बोरबो को तुम्हारा पक्ष सही रूप में समझाने जा रहा हूँ, मैं प्रयत्न करूँगा कि वे तुम्हारी मांगों को स्वीकार कर लें। किन्तु यदि ऐसा न हुआ और युद्ध करना पड़ा तो दुनिया यह समझ जायेगी कि गलत बोन था और इस प्रकार वह हमारे बारे में गलत निर्णय नहीं देगी।" कूटनीति का पूरा रहस्य पनिकर के मतानुसार कृष्ण के इस कथन में निहित है। श्री पनिकर के कथनानुसार "अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त 'कूटनीति' अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की एक कला है।"

पामर तथा परकिंस (Palmer & Perkins) ने सर एर्नेस्ट सैटो द्वारा की गई परिभाषा में सदेह प्रकट करते हुए यह प्रश्न किया है कि यदि राज्यों के सम्बन्धों के बीच बुद्धि और चतुर्य न रहे तो क्या ऐसी व्यवस्था में कूटनीति असम्भव बन जायेगी? उन्होंने कूटनीति की कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार हैं—

(१) कूटनीति अपने भाव में एक मशीन की तरह न नैतिक होती है, न नैतिक। इसका मूल्य तो हमें प्रयोग करने करने के नैतिकप्रश्नों व योग्यताओं पर निर्भर करता है।

(२) 'कूटनीति' विदेशी आगियों, दूतावासों, दूतकर्मों (Legations), राजपुखों (Consulates) तथा विश्वव्यापी विशेष मिशनो के माध्यम से कार्य करती है।

(३) कूटनीति प्रधान रूप से द्विपक्षीय (Bilateral) है, अर्थात् यह दो राष्ट्रों के बीच सम्बन्धों का ही कार्य करती है।

(४) आज अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय प्रयोगों और सामूहिक सुरक्षा प्रयत्नों का महत्व बढ़ जाने के कारण कूटनीति के बहुपक्षीय (Multilateral) रूप का महत्व बढ़ गया है।

(५) कूटनीति राष्ट्रों के बीच माध्यमों मामले से लेकर शान्ति और युद्ध जैसे-बड़े सभी मामलों पर विचार करती है। जब यह दृष्ट जातो है तो युद्ध या कम से कम एक बड़े संकट का खतरा पैदा हो जाता है।

पेरिजकोड नया निम्न के शब्दों में— कूटनीति को प्रतिनिधित्व एवं मोड़वलों की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा राज्य परस्परसम्बन्ध रूप से शांतिपूर्ण में परस्पर सम्बन्ध रखते हैं।

तकनीकी अर्थ में कूटनीति की व्याख्या राजदूत जार्ज के शब्दों में की जा सकती है कि यह सरकारी के बीच संचार का व्यापार है।

कूटनीति के विकास का इतिहास (Development of Diplomacy)

'कूटनीति' अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का सार है और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए स्वाभाविक एवं दृढ़ता आवश्यक है कि इसके बिना राज्यों के बीच परस्पर सम्बन्धों की स्थापना होना सम्भव ही नहीं है। श्री पनिकर (K. M. Panikkar) का कहना है कि "जहाँ से संगठित राज्य का अस्तित्व है वहीं से कूटनीति एवं कूटनीतिज्ञों का अस्तित्व रहा होगा क्योंकि राज्य एक दूसरे से सम्बन्ध रखें बिना नहीं रह सकते।" किन्तु फिर भी कूटनीति के संगठित रूप का प्रारम्भ प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के समय से ही माना जाता है। थ्यूसीडायड (Thucydides) ने यूनानियों में प्रचलित कूटनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उसने ईसा के जन्म से पूर्व स्पार्टा में होने वाले एक सम्मेलन का उल्लेख किया है जिसने स्पार्टा के निवासियों

एव उनके मित्रों ने एग्रेन्स बानो के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों के बारे में विचार-विमर्श किया था।

रोम वालों ने समझौते द्वारा कूटनीति (Diplomacy by negotiation) की दिशा में बहुत कम उन्नति की किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International law) के क्षेत्र में उनकी देन बड़ी महत्वपूर्ण है। रोमन युग में पूर्व के सम्राटों के प्रतिनिधि दूसरे देशों में भेजे जाते थे जिनका कार्य अच्छा से अच्छा प्रतिवेदन (Report) देने के साथ-साथ अच्छा प्रतिनिधित्व करना भी होता था।

मध्य युग में उत्तराधिकारी राजाओं और पोप के प्रभुत्व के प्रयोन पहली बार अनुभव एव परम्पराओं पर आधारित कूटनीति का व्यवहार एक विज्ञान के रूप में सामने आया।¹

कूटनीति के आधुनिक रूपा का सूत्रपात इटली में उत्तर-मध्यकाल में किया गया। इस युग के प्रथम राजनीतिक विचारक एन 'दी प्रिंस' (The Prince) के अमर रचयिता निकोलो मैकियावेली (Machiavelli) को कूटनीति का पिता माना जाता है। इस विचारक ने तत्कालीन इटली में स्थित नगर-राज्यों के बीच सघर्ष तथा उनसे छुटकारा पाने के विभिन्न उपायों का वर्णन बड़े कुशलतापूर्वक ढंग से किया है। इन्हीं दिनों स्याई कूटनीतिक प्रतिनिधि रखने की प्रथा का भी प्रचलन हो गया था जिसे कि आज की कूटनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है।

आगे आने वाले तीन सौ वर्षों तक कूटनीति न तो पर्याप्त थी और न ही स्वरुद्ध। यह केवल दरबारों तक ही सीमित थी। इस समय सम्प्रभु द्वारा विदेशी राज दरबारों में जिस प्रतिनिधि को भेजा जाता था वह सही या गलत, नैतिक या अनैतिक सभी तरीकों से अपने सम्प्रभु के हितों की रक्षा करने का प्रयास करता था। १७वीं शताब्दी में वेस्टफेलिया (Westphalia) की सन्धि के साथ राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय राज्य-व्यवस्था का विकास हुआ और इसके साथ ही कूटनीतिक मिशनों का स्याई रूप अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अभिन्न अङ्ग बन गया।

अठारहवीं शताब्दी में कूटनीतिक व्यवहार को नियमबद्ध कर दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अमरीकन व फ्रांसीसी औद्योगिकीकरण ने कूटनीति के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। राजाओं और

सम्राटों के हाथ से निकल कर शासन सत्ता के प्रजा के हाथों में जाने का सूत्रपात हो गया। अब कूटनीतिज्ञ न केवल अपने सम्प्रभु का बरत पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने लगा तथा अब उसका कार्य केवल शासक की इच्छा देखना न होकर लोकमत की दिशा को देखना बना। इस प्रकार उसके कार्यों का क्षेत्र जटिल तथा दुसूह बनता चला गया।

समय के परिवर्तन के साथ-साथ कूटनीति के रूप एवं व्यवहार में भी परिवर्तन आए। इससे सम्बन्धित ऐसे नियमों का निर्माण किया गया जो प्रायः सर्वमान्य बन गए। वियना की कांग्रेस (Congress of Vienna) की इस क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण देन रही है। इस कांग्रेस ने व्यवहार के कुछ नियम बनाए जिनको आज भी माना जाता है।

कूटनीति का उद्देश्य

(Objectives of Diplomacy)

कूटनीति का सबसे बड़ा उद्देश्य एक राष्ट्र के हितों की रक्षा करना तथा उनको बढ़ाना है। सामान्य रूप से एक देश के हितों की पूर्ति एवं विकास शांति काल में ही हो पाना है। इसलिए कूटनीति शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ही राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास करती है। यदि कूटनीति का अन्त युद्ध में जाकर होता है तो मार्गेन्या महोदय इसे उनकी अमकलता का चोटक मानेंगे।¹ कूटनीति के भारतीय पण्डित आचार्य चाणक्य के मतानुसार कूटनीति का उद्देश्य अन्धे परिग्राम प्रदान करना है। उनके विचार में कूटनीति का आदर्शों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सम्बन्ध तो राज्य के लिए व्यावहारिक परिग्राम प्राप्त करने से है। पनिक्कर (K. M. Panikkar) के मतानुसार 'कूटनीति का कार्य राज्य की भौगोलिक, राजनैतिक और आर्थिक अखण्डता को बनाए रखना है।' कूटनीतिक व्यवहार का मुख्य रूप समझौता (Negotiation) होता है। इसके माध्यम से एक देश दूसरे देशों को अपना मित्र एवं साथी बनाने का कार्य करता है। पनिक्कर ने राज्यों के कूटनीतिक व्यवहार के मुख्य-मुख्य लक्ष्यों का विवरण किया है। इन लक्ष्यों का हम संक्षेप में निम्न प्रकार कह सकते हैं—

(१) मित्र राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों को मजबूत बनाना तथा बिन देशों के साथ मतभेद हो उनसे तटस्थ रहना।

(२) अपने राष्ट्रीय हित की विरोधी शक्तियों का तटस्थ बनाये रखना ।

(३) अपने विरुद्ध दूसरे राष्ट्रा का एक मुटु बनने से रोकना ।

(४) यदि दूसरे राष्ट्रा के विरुद्ध ध्यान हिनो की रक्षा करते समय सामंजस्य और भेद के तीनों ही नीतियाँ अमल होती चली जायें तो युद्ध का सहारा निरा जाए। किंतु कूटनीति का काय है कि युद्ध ऐसी परिस्थिति में तथा एक ही में अपनाया जाय कि दूसरे देश यह समझ जायें कि तुम्हारा पक्ष मायबूझ है तथा तुम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उठ रहे हो और आक्रमणकारी तुम नहीं बल्कि दूसरा पक्ष है ।

(५) चाणक्य का मत था कि यदि युद्ध और शांति दोनों से समान परिणाम प्राप्त होता हो तो शांति को अपनाओ, तथा युद्ध और निष्पक्षता का समान नाम मिल रहा हो तो निष्पक्षता को । युद्ध को तो केवल तभी अपनाना चाहिए जबकि अन्य सभी साधन अमफल हो जायें ।

(६) युद्ध कूटनीति की अमलगाथा का ध्यानक है कि तुम्हारा अर्थ यह नहीं लगाटना चाहिए कि युद्ध के समय कूटनीति ही समाप्त हो जाती है बल्कि सच तो यह है कि बिना कूटनीति के न तो युद्ध किये जा सकते हैं और न ही जीत जा सकते हैं । युद्ध से पूर्व चलत कूटनीतिक तयारियाँ तथा युद्ध के समय की प्रभावहीन कूटनीति हार को स्वामादिक बना कर शक्तिशाली राष्ट्रों का भी विध्वंस कर देती है ।

माग था (Morgenthau) मॉर्गन्थौ ने कूटनीति के चार काय दिये हैं । उनके अनुसार पंच काय तो यह है कि कूटनीति अपने लिए कुछ वस्तु (Objects) निर्धारित करे । ये वस्तु वास्तविक (Actual) और सम्भावित (Potential) शक्ति का ध्यान में रख कर ही निर्धारित किये जायें ताकि उनका प्राप्त किया जा सक ।

दूसरे कूटनीति को दूसरे देशों के लक्ष्यों को आक्राना चाहिए तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए उनका पक्ष सम्भावित एवं वास्तविक शक्ति कितनी है यह भा देना चाहिए ।

तीसरे कूटनीति को यह देखना चाहिए कि यह उद्देश्य किस सीमा तक एक दूसरे के अनुरूप हैं ।

चौथे कूटनीति को अपने उद्देश्यों (Objectives) को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त साधन प्रयुक्त करने चाहिए । मार्गों को के बचनानुसार इन चारों

बापों में मे एक की भी सम्फलता एक राष्ट्र की विदेश नीति की सफलता का तथा विश्व की शान्ति को खतरों में डाल देगी।¹

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कूटनीति निम्न तीन साधनों को काम में ला सकती है—

- (1) समझाना (Persuasion);
- (ii) समझौता करना (Compromise);
- (iii) शक्ति प्रयोग की धमकी देना (Threat of Force)।

एक सफल कूटनीति को चाहिए कि जहाँ तक समभव हो सके वह प्रयत्न दो साधनों के माध्यम से हो अर्थात् उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास करे क्योंकि कोई भी कूटनीति जो केवल शक्ति को धमकी देकर ही काम निकालना चाहती है, न तो शान्तिप्रिय कही जायगी और न ही बुद्धिपूर्ण। किन्तु कभी-कभी ऐसे भी अवसर आ सकते हैं जबकि शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाये। कूटनीति की कला इसी बात में है कि वह समय व परिस्थिति के अनुसार ही तीनों में से किसी का प्रयोग करे।²

आधुनिक कूटनीति के अभिनेता (The Actors of Modern Diplomacy)

राष्ट्र की कूटनीति के अभिनेताओं में हम जिनको सम्मिलित कर सकते हैं उनमें सरकार के अध्यक्ष, विदेश सचिव तथा उनके विदेश अधिकारी, स्टाफ, दूसरे देशों में स्थित कूटनीतिज्ञ कर्मचारी वर्ग एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने वाले सैनिक तथा अन्य विशेषज्ञ सेवी वर्ग आदि प्रमुख हैं। इनके अनिश्चित अन्य राजनृप भी होते हैं जैसे भ्रमणशील राजदूत, व्यक्तिगत प्रतिनिधि एवं मौलानी लोग।

राष्ट्र के नाम मात्र के अध्यक्ष जैसे ग्रेट ब्रिटेन के राजा या रानी, भारत का राष्ट्रपति आदि विदेशों मामलों में सूचना प्रसारित योगदान करने हैं। वे जब विदेश घूमन जाते हैं तो इसका उद्देश्य मुख्यतः सद्भावना की अभिवृद्धि होता है। दूसरी ओर सरकारों के अध्यक्ष अपने देश की कूटनीति में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ट्रूमेन, रूजवेल्ट, आईजनहोवर, कनेडी तथा जानसन आदि सभी अपने देश की

1. Morgenthau, op. cit., P. 506.

2. Morgenthau, op. cit., P. 507.

सरकार के अध्यक्ष होने के साथ-साथ देश तथा विदेश में सन्धि समझौतों के कार्यों में सलग्न रहे हैं। यही बात भारत के प्रधानमंत्री नेहरू फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल, ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन आदि के बारे में भी कही जा सकती है।

कूटनीति के क्षेत्र में तानाशाही द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कुछ भिन्न प्रकार का होता है। तानाशाह किसी अन्य के माध्यम से अपने लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करते हैं। जैसे स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों के साथ तेहरान, याल्टा, पोर्टस्मथ आदि सम्मेलनों में भाग लिया था किन्तु वह साधारणतः पृष्ठभूमि में रहता था और अपने विदेश मंत्री मोलोटोव (Molotov) के माध्यम से विदेशी मामलों पर नियन्त्रण रखता था। दूसरी ओर प्रधानमंत्री खुशेव विश्व राजनीति के क्षेत्र में स्वयं सक्रिय रचि लेते थे। इसी प्रकार संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने मिस्री कूटनीति का उत्तरदायित्व सम्भाला और एक अरब नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने की कोशिश की ताकि वह एक तटस्थ गुट संगठित कर सके जो महाशक्तियों के साथ सौदेबाजी करने में सक्षम हो।

जैसे को तैसा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ सिद्धान्त है जो सरकार के अध्यक्षों को एक की पहल पर कूटनीति में रीज ताना है। इस सिद्धान्त के क्रियान्वित रहते हुए यह सम्भावना की जाती है कि सरकार के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी नेता कूटनीति में आज की भांति ही सक्रिय रहेंगे। इस नीति का एक उदाहरण हम प्रधानमंत्री कोसीगन के आमन्त्रण को मान सकते हैं जो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री श्री शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खां को उनके आपसी मतभेद मिटाने के लिए ताणकन्द में आने के लिए भेजा था। इस आमन्त्रण को दोनों ही देश के नेता नहीं ठुकरा सके।

कूटनीति के क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय अभिनेता विदेशी मामलों के राज्य सचिव होते हैं। विदेश सम्बन्ध उनका मुख्य कार्य है। वे अपने पूरे जीवन भर कूटनीतिज्ञ वार्तालाप करते रहते हैं, अन्य देशों के बारे में सोचते रहते हैं, सम्मेलनों में उपस्थित होते हैं तथा महत्वपूर्ण सौदेबाजियों की तैयारी करते हैं। वे अपने राज्याध्यक्षों को परामर्श देने के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा विदेशी मामलों के सम्बन्ध में उनको सूचित करते हैं। अपने विदेश कार्यालय एवं विदेश सेवा की बहुत बड़ी नौकरशाही को प्रशासित करना भी उनका उत्तरदायित्व है। वे मन्त्रिमण्डल तथा अन्य नीति सम्बन्धी बैठकों में उपस्थित होते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश सचिवों ने सन् १९४५

के बाद से अपना अधिकांश समय अपने कार्यालय से दूर रह कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को उपस्थित करने में व्यतीत किया। अनुमानतः यह कहा जाता है कि जान फास्टर डुलस (John Foster Dulles) न अपने पाच वर्ष के कार्य काल में प्रति वर्ष एक लाख हवाई मीलो से भी अधिक की यात्रा की। इतनी लम्बी यात्रा करके वह चांद तक जाकर वापस आ सकते थे। यह सारी यात्रा उन्होंने दुनिया के अन्य नेताओं के साथ बातचीत के लिए की। विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वयं अधिक यात्रा करने की अपेक्षा यह उक्ति समझा कि दूसरे लोग ही वाशिंगटन आ जायें।

आज कूटनीति में सन्नत अनेक लोग ऐसे हैं जिनको हम व्यावसायिक विशेषज्ञ कह सकते हैं। इनमें हम उन नागरिक सेवकों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित करेंगे जो विदेशों में दूतावासों एवं राजगुरुष कार्यालय तथा देश में विदेश कार्यालय में कार्य करते हैं। ये अधिकारी विदेश सम्बन्धों के प्रचलित पहलुओं को सम्पादित करते हैं। ये अध्ययन, प्रतिवेदन एवं निर्देशन तैयार करते हैं। वे दूसरे देशों के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ विचार करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने वाले प्रतिनिधि मण्डल के स्टाफ का काम करते हैं। उनके कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। प्रथम यह कि अपने मालिकों के काम को सम्पन्न करें और दूसरा यह कि दूसरों के कार्यों की सज्ज करे। व्यावसायिक विशेषज्ञों का यह दल एक दिन में सगठित नहीं हो जाता। आज के युग की परिस्थितियों में एक योग्य विदेश सेवा के विकास के लिए पर्याप्त समय एवं अनुभव की आवश्यकता है।

सरकारें समय-समय पर विशेष गुप्त सन्देशवाहक (Emmissary) नियुक्त कर सकती हैं जो महत्वपूर्ण अवसरों पर विशेष सगमभीते करे तथा सरकार को प्रतिनिधित्व करे। अमरीका के राष्ट्रपति फ्रेडरिड डी रूजवेल्ट ने हेरी हॉपकिंस (Harry Hopkins) को अपना विश्वास प्रदान किया और राज्य सचिव तथा सम्बन्धित राजधानियों के राजदूतों की भवहेलना करके कई बार बर्लिन और स्टालिन के पास गुप्त वार्ता के लिए भेजा। इसी प्रकार राष्ट्रपति आइजनहोवर ने अपने माई मिहटन आइजनहोवर को अनेक विशेष अवसरों पर प्रयुक्त किया। राजदूत एवरल हरीमैन (Averell Harriman) को राष्ट्रपति ट्रूमैन, कनेडी और जानसन द्वारा अनेक विशेष अवसरों पर प्रयुक्त किया गया। राज्य सचिव बनने से तीन वर्ष पूर्व जान फास्टर डुलस को जापान की शान्ति सन्धि में वास्तुमार्ग का काम सौंपा गया। ये सारी नियुक्तियां राज्य के अध्यक्ष के विशेषाधिकार हैं। यह ही सचता है कि कुछ देशों की प्रभावित करने वाले क्षेत्र की किसी विशेष समस्या में गुप्त सन्देश-

वाहन राजदूत की अपेक्षा अधिक कुशल हो। किन्तु फिर भी सम्भावना यह रहती है कि वह उस देश के राजदूत की प्रभावशीलता एवं सम्मान को कम कर देगा और ऐसी स्थिति में हम तकनीकी का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

आज के जटिल वातावरण में राज्यों के आपसी सम्बन्ध राजनैतिक, आर्थिक, सुरक्षा एवं वैज्ञानिक अनेक विषयों से युक्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि सरकारों के विभिन्न विभागों के सेबीवर्ग को कूटनीतिक सम्बन्धों में तथा नीति-निर्माण में भाग लेने का अवसर दिया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सर्वाधिक सक्रिय रूप से भाग लेने वालों में सशस्त्र सेनाओं एवं सुरक्षा स्थापनों के सदस्य होते हैं। नाटो देशों के सुरक्षा सचिव तथा उनके अग्रोन्मुख अधिकारियों जब नाटो की बैठकों में गए सुरक्षा प्रबन्धों पर विचार करते हैं तो एक प्रकार से कूटनीति में उलझ जाते हैं। इसी प्रकार जब जन स्वास्थ्य अधिकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (W H O) की बैठक में भाग लेते हैं या राजकाय के प्रतिनिधि विश्व बैंक की बैठक में भाग लेते हैं तो वे भी कूटनीति में उलझते हैं। इसी प्रकार से पारस्परिक सुरक्षा, सांस्कृतिक सम्बन्ध, आर्थिक एवं तकनीकी सहायता कार्य आदि में किसी न किसी प्रकार से कूटनीति से सम्बन्ध रहते हैं। पीयरसन के कथनानुसार अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमरीका का भूमि वैज्ञानिक संयुक्त राज्य अमरीका की नीति के बारे में अफगानिस्तान के मत को मजबूत या बुरे के लिए अधिक प्रभावित कर सकता है अपेक्षाकृत अमरीकी राजदूत के।

कूटनीतिक विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ (Diplomatic Privileges and Immunities)

कूटनीतियों को कुछ विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ सौंपी जाती हैं जो अन्य व्यक्तियों को प्रदान नहीं की जाती। पामर तथा पॉन्स के मतानुसार इन विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताओं को प्रदान करने के पीछे दो महत्वपूर्ण कारण हैं। प्रथम यह कि कूटनीतिज्ञ अपने राज्य के अध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रतिनिधि होते हैं। साथ ही वे अपनी सरकार और अपने देश की जनता के भी प्रतिनिधि होते हैं। दूसरे वे अपने कर्तव्यों को मन्तापत्रनरूप में तभी सम्पन्न कर सकते हैं जबकि स्थानीय वातावरण द्वारा लगाई गई कुछ बाधाओं से उन्हें मुक्त किया जाए। साधारण रूप से सम्बन्धित कर एवं करों आदि से मुक्त रहने के। वे जिस देश में रह रहे हैं उनके दीवानी एवं पौज-

दारी क्षेत्राधिकार में मुक्त रहते हैं। घमेल में वे विदेशी राज्य के कानूनों से अप्रभावित रहते हैं। उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर और उनके स्टाफ के सदस्यों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई श्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूतावासा, उनकी सम्पत्ति सामग्रियों एवं संप्रदायों को उन देशों की राष्ट्रीय सम्पत्ति समझा जाता है जिनका कूटनीतिज्ञ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए उन पर राज्य के अधिकारियों द्वारा तथा स्थानीय सत्ताओं द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता। यही अधिकार और विशेषाधिकार राष्ट्र सघ के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का दिए जाते थे और अब समुक्त राष्ट्र सघ के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को दिए जाते हैं।

राजपुरुषों (Consuls) को सामान्यतः इतने अधिकार एवं विशेषाधिकार नहीं सौंपे जाते जिनसे कूटनीतिज्ञों का सौंपे जाते हैं। इन राजपुरुषों का स्तर दो देशों की सरकारों समझौते द्वारा तय करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सुस्थापित नियमों द्वारा तय नहीं किए जाते। कुछ उदाहरणों में इन राजपुरुषों को वे सब विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ दे दी जाती हैं जो कूटनीतिज्ञों को प्रदान की जाती हैं। ऐसा उस समय होता है जबकि राजपुरुष कूटनीतिज्ञों का भी काम कर रहे हों। अन्य राजपुरुषों को बहुत कम स्वतन्त्रताएँ प्रदान की जाती हैं। राजपुरुषों का कार्यालय एवं संप्रदाय को उनके देश की राष्ट्रीय सम्पत्ति माना जाता है और इस प्रकार वह राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इनको प्रायः स्थानीय करो एवं कस्टम से मुक्त रखा जाता है किन्तु वे उस राज्य के कानूनों के अधीन होते हैं जिसमें कि वे रह रहे हैं।

कूटनीतिज्ञ तथा राजपुरुष अधिकारियों के सामान्यतः मान्य स्तर में अनेक भिन्नताएँ तथा अन्तर हैं। सन् १९२८ की हवाना कन्वेंशन में यह प्रस्ताव किया गया था कि इन अधिकारियों के स्तर के सम्बन्ध में सामान्य रूप से स्वीकृत नियम बना दिए जायें। किन्तु ये कन्वेंशन भी सामान्य स्वीकृति नहीं प्राप्त कर सके। ऐसे अनेक मामलों सामने आते हैं जहाँ कि कूटनीतिज्ञों या राजपुरुषों ने अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किया अथवा राज्य ने इन प्रतिनिधियों या उनके साथ वालों के विशेषाधिकारों को तोड़ा। समुक्त राज्य अमेरिका ने समुक्त राष्ट्र सघ के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को पूरे कूटनीतिज्ञ विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ सौंपे हुए हैं, यद्यपि देश के कुछ लोग तथा कांग्रेस के कुछ सदस्य इसका विरोध करते हैं। दूसरी ओर सोवियत दूतावास में अन्धविश्वास विभिन्न कार्यालय पदव्यवहारी कार्यवाहियों के केन्द्र प्रतीत होना है इसलिए उनके ऊपर कड़ी देखभाल रखी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राजनयिक अधिकारियों को किसी पदयत्र में सम्मिलित होने से मना किया गया है ।

कूटनीतिक कार्यों का स्वरूप (The nature of diplomatic functions)

एक देश की कूटनीति के संचालन का उत्तरदायित्व एक पृथक् आफिस को ही सौंपा जाता है जो विदेशों में स्थायी रूप से निवास करता है । इस आफिस के कार्यकर्त्ता विभिन्न स्तरों के होते हैं, पदथेणी के अनुसार इस आफिस का गठन किया जाता है । इस आफिस के प्रत्येक कर्मचारी के कुछ निर्धारित विशेषाधिकार एवं स्वतन्त्रताएँ होती हैं, साथ ही इनके कार्य सञ्चालन के कुछ निश्चित नियम और तरीके भी होते हैं ।^१

कूटनीतिज्ञ को अनेक बार एक देश का दूसरे देश में स्थित भाँख और कान भी कहा जाता है । इसका अर्थ यह है कि कूटनीतिज्ञ के माध्यम से एक देश दूसरे देश की घटनाओं को देख कर तथा सुन कर बहुत शीघ्र ही जानकारी प्राप्त कर सकता है । एक सफल एवं भ्रष्ट कूटनीतिज्ञ का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में चाणक्य और मैकियावेली से लेकर आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है । चाणक्य ने अपनी पुस्तक 'अर्थशास्त्र' में दूत के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया है—

- (१) अपनी सरकार के दृष्टिकोणों का आदान प्रदान करना,
- (२) संधियाँ करना;
- (३) अपने राज्य के दावों (Claims) को मनवाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाना । इसके लिए यदि आवश्यकता हो तो ताकत की धमकी भी दी जा सकती है । इसके प्रतिरिक्त उसे अपने मित्र बढ़ाने चाहिए उस देश में बसह के बीज बाने चाहिए, गुप्त सागठनों का निर्माण करना चाहिए, सिपाहियों के आंदोलन की सूचना एवम्पत्र बननी चाहिए उन सन्धियों की अवहेलना करनी चाहिए जो उसके देश के हितों के विपरीत हो, उस देश के सरकारी अधिकारियों को अपनी ओर मिला लेना चाहिए । ये सभी एक दूत के कार्य हैं ।

(४) दूत को मुख्यतः उन सरकारी अधिकारियों से मित्रता बढ़ानी चाहिए जिनके अधिकार में जगलात, सीमावर्ती क्षेत्र आदि विषय होते हैं ।

(५) दूत को यह जानकारी रहनी चाहिए कि उस देश के किलो का क्षेत्र व भावार क्या है तथा मूल्यवान चीजों के खजाने विधर स्थित हैं।

चाणक्य द्वारा ईसा से ४ शताब्दी पूर्व बताये गये दूत के उक्त कार्य आज भी उसी प्रकार से सत्य एवं उपयोगी हैं। चातुर्ष्य, कुशलता एवं कपट आदि को एक सफल कूटनीतिज्ञ के गुण माना जाता है। जोसेफ स्टालिन ने कूटनीति को एक प्रकार की कला माना है। उसके अनुसार एक कूटनीतिज्ञ के शब्दों का उसके कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये वरना यह कूटनीति ही क्या? हमने एक चीज है और करनी दूसरी। अच्छे शब्द बुरे कार्यों को छुपाने में ढान का काम करते हैं। एक निष्कपट कूटनीति (Sincere diplomacy) उसी तरह सम्भव है जितना कि 'सूखा पानी' या 'नरम लोहा'।^१ इस प्रकार स्टालिन ने कूटनीति का जो रूप प्रस्तुत किया है उसके अनुसार कूटनीति एक देश के वास्तविक उद्देश्यों को छुपाने का साधन है। यह उसके कार्यों के सही रूप पर पर्दा डाल देती है। कूटनीतिज्ञ के चरित्र से सम्बन्धित एक दूसरी बहावत के अनुसार यदि कूटनीतिज्ञ किसी विषय पर सहमति प्रकट करे तो समझिये कि सम्भवतः वह विषय से सहमत है। यदि वह सहमत होने की सम्भावना प्रकट करे तो समझिये कि वह विषय से असहमत है और यदि वह असहमति प्रकट करता है तो वह सच्चे अर्थों में एक कूटनीतिज्ञ नहीं माना जा सकता। कूटनीतिज्ञ की स्थिति एक स्त्री से पूर्णतः विपरीत होती है। किसी भी सम्भव बात के लिए वह 'नहीं' कहती है तथा अपनी स्वीकृति को सम्भव शब्द से जाहिर करती है। यदि वह 'हाँ' कह दे तो सच्चे अर्थों में वह एक स्त्री नहीं है।^२ मैकियावेली (Machiavelli) ने अपने ग्रन्थ 'दी प्रिंस' (The Prince) में भी राजा के लिये तथा उसके प्रतिनिधियों के लिये व्यवहार से सम्बन्धित अनेक उपयोगी परामर्श दिये हैं।

दूसरी पार ऐसे विचारक भी हैं जिनके अनुसार चाणक्य, मैकियावेली, स्टालिन आदि नेता एवं विचारकों द्वारा कूटनीति पर व्यक्त किये गये सुझावों एवं व्यावहारिक से दिखने वाले विचार उचित नहीं हैं। पत्रिकार महोदय के मतानुसार चातुर्ष्यपूर्ण कूटनीति एक देश की उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कम सहायता कर पाती है।^३ कारण यह है कि कूटनीति का एक लक्ष्य यह

1. Joseph Stalin, Quoted in David Dallin, the Real Soviet Russia 1944, P. 71

2. Quincy Wright, op cit., P. 165

3. K M Pamkhar, Ibid, P. 39

है कि यह जग देव के प्रति दूसरे देशों की शुभ इच्छा सशुद्धीत करे। यह चार प्रकार से हो सकता है—दूसरे देश उस देश की नीतियों को ठीक प्रकार से समझे एवं उसके प्रति सम्मान के भाव रखें, वह देश दूसरे देशों की जनता के न्यायोचित हितों को जानें, सबसे ऊपर, वह ईमानदारी से व्यवहार करें। ये सारी चीजें निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार द्वारा ही प्राप्त की जा सकती हैं। यह सच है कि आप बहुत से लोगों को बहुत समय तक धोखे में नहीं रख सकते और इस दृष्टि से चातुर्य, कुशलता और कपट से पूर्ण कूटनीति के पदों में जब छिद्र हो जायेंगे और उस देश की नीति का सही रूप सामने आयेगा तो विश्व समाज में उस देश का क्या स्तर रह जायगा। व्यक्तिगत जीवन की भांति, ये विचारक यह मानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है।

हिन्दू नीति-शास्त्रों में कूटनीति के साधन और उपाय चार प्रकार के बताये गये हैं—साम दाम, दड और भेद। 'साम' के अनुसार एक देश मित्रता-पूर्ण व्यवहार, सुभाव एवं बौद्धिक तर्कों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास करता है। 'दाम' के अनुसार एक देश अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये धन व्यय करता है। ऐसे समझौते करता है जिसमें स्वयं की आर्थिक हानि हो और दूसरे पक्ष का लाभ हो। कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये कुछ देना, कुछ व्यय करना भी आवश्यक बन जाता है। यह समझौते का एक तरीका है। जहाँ साम और दाम से काम बनता न दीखना हो वहाँ 'भेद' का सहारा लेना होता है अर्थात् शत्रु के शत्रु से मैल कर लेना और शत्रु के मित्रों में आपस में फूट डाल देना आवश्यक बन जाता है। कूटनीति का सबसे अन्तिम हथियार 'शक्ति' है। जब सभी अन्य साधन असफल हो जायें तो कूटनीति को युद्ध अपनाना पड़ता है। पामर तथा परकिन्स के कथनानुसार विदेश-नीति की भांति कूटनीति का यह लक्ष्य है कि वह जहाँ तक सम्भव हो शांतिपूर्ण साधनों से देश की रक्षा करे किन्तु यदि युद्ध अपरिहार्य बन जाये तो सैनिक तैयारी द्वारा ऐसा करे। यदि कृष्ण के अनुनय विनय के बाद भी कौरवों का यही उत्तर रहे कि वे बिना लड़े एह सुई के बराबर भूमि भी देन को तैयार नहीं हैं तो मजबूर होकर महामारा का युद्ध करना ही पड़ेगा। युद्ध के समय 'शांतिमालीन कूटनीति' का स्वरूप प्रदर्शन कर युद्ध की अवस्थाओं के अनुकूल बन जाता है। विजयी राइट का कहना है कि कूटनीति युद्ध से भिन्न इसलिए है क्योंकि यह भीतर की स्थिति का स्थान पर दूसरों का प्रयोग करती है। शक्ति का प्रदर्शन एवं युद्ध की घमकी कूटनीति का

ही मायन हैं। किन्तु यदि युद्ध टिङ्ग जाता है तो आनमणवारियों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाता है।

चाटलैम महादय ने कूटनीतिज्ञ के कार्यों को मुख्यतः चार भागों में बाटा है, य निम्न प्रकार हैं—

- १ प्रतिनिधित्व करना (Representation)
- २ संमन्धन करना (Negotiations)
- ३ प्रतिबन्धन प्रस्तुत करना (Reporting)

४ विदेशी भूमि में अपने देश के नागरिकों तथा देश के हितों की रक्षा करना (The protection of the interests of the nation and of its citizens in foreign lands)

कूटनीतिज्ञ को उक्त चारों ही कार्य करने होते हैं। ये कार्य एक प्रकार से कूटनीति की सीढ़ियाँ हैं। इनका अन्तिम लक्ष्य तो एक देश के प्राधिक, राजनैतिक, भौगोलिक, सैनिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना होता है। कूटनीतिक व्यवहार के मार्ग में कुछ बुराईयाँ आ जाती हैं। एक कूटनीतिज्ञ की चाहिए कि वह अपने अनुभव के द्वारा इन बुराईयों से मुक्ति पान या बचन का प्रयत्न करे। प्रयत्न यदि एक कूटनीतिज्ञ ने बहुत ईर्ष्या के दृष्टिकोण को प्रयत्न कर काम किया तो उसका मार्ग अवरोध हो जायेगा। कूटनीतिज्ञ को यह ध्यान में रखना होगा कि कूटनीति के प्रत्येक कार्य में शक्ति का अभाव किसी न किसी रूप में अवरोध प्रभाव डालता है। यदि आप शक्तिशाली हैं तो दूसरे देशों का व्यवहार आपके साथ मित्र प्रकार का होगा और यदि आप शक्तिहीन या कमजोर हैं तो उसे व्यवहार का रूप भी बदल जायगा।

कूटनीतिज्ञ जिस स्थान पर रहता है वहाँ के वातावरण का, व्यवहार का एवं सम्प्रदायों का प्रभाव उसके व्यवहार पर भी पड़ता है। राजदूतों की कालोनी में रहने वाले अन्य लोगों के साथ उनके सम्बन्धों में घृणा, प्रेम, सम्पर्क, भेद, ईर्ष्या, भगड़े आदि सभी तत्वों की स्थान प्राप्त होता है। ये सभी उनके व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। यह देखते हुए एक कूटनीतिज्ञ को स्वतन्त्र विचारों वाला होना चाहिये जो स्थिति को अग्रिम स अग्रिम विषयगत (Objective) रूप में देख सके।

एक दूसरी बाधा ध्यान आपको हमेशा धीरे मानने की है। इसके अनुसार कूटनीतिज्ञ का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिये कि या चीज उसकी शक्ति व बुद्धि के अनुकूल है उसे उचित माने और जो विरुद्ध है उसे अनुचित माने। दूसरे शब्दों में उसे सहनशील होना चाहिये। सहनशीलता कूटनीति

के व्यवहार का विशेष गुण है। यदि आप एक देश की कूटनीति की सफलता जानना चाहते हैं तो यह ज्ञात कीजिए कि क्या इसने देश के हितों को प्राप्त किया, क्या इनने मित दशों की सुमकामनायें या अमित्र देशों से आदर प्राप्त किया ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक है तो कूटनीति अमफल माना जायेगी वरना वह सफल है।

पेंडिलफोर्ड तथा लिबन ने कूटनीति के मुख्य रूप से चार कार्य बनाए हैं, ये हैं—सुरक्षा, प्रतिनिधित्व, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन और वार्तावाप करना। इसके अतिरिक्त आज कूटनीतिज्ञ पदों पर रहने वाले प्रतिनिधि अनेक अर्थ कूटनीतिज्ञ कार्य भी करते हैं क्योंकि उनके राष्ट्र क्षेत्रीय या पारस्परिक सुरक्षा प्रबन्धों में, विदेश सहायता कार्यक्रमों में या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के भाग लेते हैं। इन विचारकों द्वारा वर्णित कूटनीतिज्ञों के प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार दिया जा सकता है—

सुरक्षा (Protection)—एक कूटनीतिज्ञ का यह प्रमुख कार्य माना जाता है कि वह अपने देश के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करे और प्रोत्साहन दे तथा विदेशों में रहने वाले अपनी राष्ट्रीयता वालों के अधिकारों की रक्षा करें। उसे हमेशा दी जाने वाली घमकियों अथवा दी जाने वाली असमानताओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि उनके देश के सम्मान के प्रति कोई मौदेबाजी न की जाए। यह उत्तरदायित्व प्रतिनिधित्व, सम्झौता, सन्धि एवं कार्यपालिका की सहमतियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। कूटनीतिक मिशन के अधिकारियों को उन लोगों से बान्धन करनी होती है जो सहायता की मांग करते हैं तथा जहां कहीं इनके अधिकारों को छीना गया है, सम्मति को ले लिया गया है या उनके व्यक्ति हताहत हुए हैं अथवा उन्हें कानून की पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है तो ये कूटनीतिक उनके कष्टों को दूर करने में पूरा सहयोग देते हैं। जब राजनैतिक परिस्थितियाँ अस्त-व्यस्त होती हैं तो यह गुणवत्तात्मक कार्य एक भारी उत्तरदायित्व बन जाता है। एनी स्थिति में दूतावास को शरणावियों का स्थान बनाना होता है। जिस समय गृह युद्ध या अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध की सम्भावना हो अथवा छिड़ रहा हो उस समय कूटनीतिक मिशनो से उनकी शक्ति भर वह सब करने की आज्ञा की जाती है जिससे उनके राष्ट्रीयता के लोग अपने घर लौट जाए अथवा सुरक्षा के स्थानों को पहुँच जाए। जब युद्धरत दशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध टूट जाते हैं तो परम्परागत रूप से तटस्थ देशों के राजनयिकों से यह कहा जाता है कि वे प्रत्यक्ष पक्ष की राष्ट्रीयता वाले लोगों के हितों की दूमरे क्षेत्र के देशों में

रक्षा करें। प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के समय स्वीट्जरलैण्ड तथा स्वीडन ने यह मुरझातमक एवं मध्यस्थता का कार्य किया।

प्रतिनिधित्व (Representation)—प्रत्येक कूटनीतिक वा यह उत्तरदायित्व है कि उसे चाहे दूसरे राज्यों में भेजा जाए अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में, वह अपने देश का प्रतिनिधित्व करेगा और अपनी सरकार तथा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करेगा। एक प्रतिनिधि के रूप में कूटनीतिज्ञ अपने राज्य और सरकार का प्रतीक होता है और उनके विचारों को स्पष्ट करता है। यदि दूसरे देश के अधिकारी या गैर सरकारी व्यक्ति एवं समूह एक देश के दृष्टिकोण तथा अभिप्रायों को जानना चाहें तो उन्हें कूटनीतिज्ञ से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। कूटनीतिज्ञ अपने देश के दृष्टिकोण एवं अभिप्रायों को बड़ी चतुरता, स्पष्टता एवं सक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करता है। उसके व्यक्तिगत विचार चाहे कुछ भी हों किन्तु दूसरे देशवासियों को वह उन्हीं विचारों को बतलाएगा जो उनके देश की सरकार के हैं। अपनी सरकार के प्रतीक और प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हुए राजदूत विदेश में अपने देश के लिए मित्रता को बढ़ाता है और इनके लिए वह सरकार के नेमाग्री एवं व्यापार, समाज, शिक्षा और राजनैतिक जीवन के नेताओं के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क विकसित करता है। एक कूटनीतिज्ञ के उत्तरदायित्व का वर्णन करते हुए जोसेफ सी० सी० क्रू (Joseph C Crew) ने कहा है कि "उसे सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से एक व्याख्याता (Interpreter) होना चाहिए। वह व्याख्याता का कार्य दोनों तरीकों से कर सकता है। प्रथम, वह जिस देश में कार्य कर रहा हो उस देश को समझेगा, उसकी परिस्थितियों, उसकी मनाइशा, उसके कार्य, और उसके मूल अभिप्रायों को जानने के बाद वह इन चीजों को अपनी सरकार के लिए स्पष्ट करेगा। दूसरी ओर वह जिस देश में रह रहा है उसकी सरकार और जनता को अपने मूल देश के उद्देश्य, भाषा एवं इच्छाओं से अवगत कराएगा। वह उन विचारों और शक्तियों के बीच पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने वाला एक अभिकरण है जिनके आधार पर राष्ट्र कार्य करते हैं। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि कूटनीति गिज्ञान के सदस्य अपने स्वयं के देश के बारे में अच्छी प्रकार से सूचित हो और जहाँ आवश्यकता हो वे निरन्तर और तुरन्त सूचना प्रदान कर सकें। जब कभी वह सार्वजनिक समारोहों में बोलने का अवसर प्राप्त करें तभी उसे व्यापार एवं गृह नीति निर्माण के सम्बन्ध में अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए और सरकारी तथा गैर सरकारी अभिप्रायों में

अपनी प्रगति का वर्णन करना चाहिए तथा अपने देश की कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना चाहिए।

वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ एवं कूटनीतिक मिशन के अध्यक्ष महन्वपूर्ण अक्सर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे यात्रा के माध्यम से पूरे देश की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वे अन्य राजदूतों के सम्मान में स्वयं भाग देते हैं और दूसरों द्वारा दिए जाने वाले नोटों में सम्मिलित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह आवश्यकता होती है कि जिन्होंने अभी निमन्त्रित किया था उन्हें जरूर निमन्त्रित किया जाए और सरकार के तथा वाणिज्य के महन्वपूर्ण सदस्यों को निमन्त्रित किया जाए। हेरल्ड सीमर (Harold Seymour) ने कहा है कि एक अच्छा भोज कूटनीति की दृष्टि से बहुत महन्वपूर्ण हो सकता है।

अधिकार देग अपने कूटनीतिज्ञों को खर्च करने के लिए पर्याप्त धन देते हैं ताकि वे अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत इस बात पर बहुत जोर दिया जाता था और इसलिए कूटनीतिक पद उन व्यक्ति को मिले जाते थे जो अधिक दृष्टि से सम्पन्न हों। किन्तु अब फिर तब तक सम्पत्तिको के साथ अन्य अधिकारी भी इन पदों को सम्मान सकते हैं। परम्परागत रूप से अपने देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि अधिकारी हान के नाम राजदूत प्रायः मुख्य प्रणामनीय एवं प्रणामात्मक उत्तरदायित्वों को पूरा करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत को अक्सर अमेरिकी अभियन्तों की क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना होता है तथा संस्था अधिकारियों का प्रणामनीय उत्तरदायित्व सम्भालना होता है। इन कार्यों के परिणामस्वरूप उनके समय पर पर्याप्त भार पड़ जाता है।

अवलोकन एवं प्रतिवेदन (Observation and Reporting)—
कूटनीतिज्ञ का विदेश में स्थित एक देश के आन्तरिक और बाह्य राज जानना है व अपने सरकार को विदेशी मामलों का बुद्धिपूर्वक मन्वचन करने की क्षमता देना है तथा उन्हें इस बात की भी जानकारी देना है कि क्या उनसे भय है और क्या उनके विरोधी हैं। विदेश में काम करने वाली प्रत्येक मिशन का यह प्रयोग कर्त्तव्य होता है कि वह अपने देश का निरन्तर प्रतिवेदन भेजता रहे। ये प्रतिवेदन अक्सर विषयों पर भेजे जाते हैं, जैसे, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सैनिक परिस्थितियाँ विचाराधीन व्यक्तित्व, स्थान, उद्देश्य एवं उद्देश्य, जननीय प्रशिक्षण तथा शिक्षा में आने वाले परिवर्तन आदि।

वाते हैं किन्तु फिर भी यह समभव है कि एक देश की कूटनीति में उक्त में से कुछ रूप एक साथ प्राप्त हो सकें। उदाहरण के लिए एक कूटनीति प्रजातन्त्रात्मक होने के साथ-साथ प्रचार द्वारा, खुली, सम्मेलनों द्वारा एवं दूतानुसार जैसी भी हो सकती है। इस दृष्टि से यदि कूटनीति के उपर्युक्त विभिन्न भेदों को 'भेद' की सत्ता न देकर केवल कूटनीति की विशेषतायें कह कर पुकारें तो भी अनुचित न होगा। इन विशेषताओं प्रमदा भेदों का सजिष्ठ वर्णन प्रागे प्रस्तुत किया जा रहा है।

(१) प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति (Democratic diplomacy)

बीसवीं शताब्दी की 'प्रजातन्त्र' के जन्म एवं विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय शासन सत्ता राजा और सम्राटों के हाथ से निकल कर सामान्य जनता के हाथों में आ गई। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्णायक एक देश का शासन मात्र न रह कर पूरी जनता बन गई। प्रजातन्त्रात्मक प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ने कूटनीतिक व्यवहार पर प्रभाव डालना प्रारम्भ कर दिया। कूटनीतिज्ञ अग्रतम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी बन गये, किन्तु जैसा कि पामर तथा परकिन्स का विचार है, कूटनीतिक कार्यों पर आज भी उन्हें लोगों का अधिकार है जिनके हाथ में शक्ति, प्रभाव और धन है। प्राचीन भारत के अनेक राजा, महाराजा और जागीरदार स्वतन्त्र भारत के राजदूतों का पद सम्माने हुए हैं।

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति की कुछ विशेषतायें हैं जैने—

१. कूटनीतियों को केवल अपने देश के शासनो की रुचि का ध्यान रखना ही पर्याप्त नहीं है किन्तु उन्हें लोक-रुचि और लोक-हित का ध्यान रखना होता है।

२. कूटनीतिक स्तर पर किये गये सभी मन्त्रि एवं सम्मेलनों से सामान्य जनता को परिचित रखना आवश्यक है ताकि जनता उन पर अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर सके।

३. जनता के अनेक समुदाय एवं वर्गों भाषण, प्रचार, आन्दोलन एवं जुलूसों द्वारा विदेशों से किये गये मन्त्रि या सम्मेलनों का विरोध या समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्द्ध पर किये गये भारत-पाक सम्मेलनों पर जनमध आदि दोनों के रुख को लिया जा सकता है।

४. प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति एक देश की स्वतन्त्र प्रेम, भाषण की स्वतन्त्रता, सरकारी प्रचारपरिया पर जनमत का प्रभाव, विभिन्न सत्ताधी

एव सगठनों के विशेष हितों आदि के साक्षों में डलने के बाद रूप ग्रहण करती है तथा कूटनीति के इस रूप का लक्ष्य होता है सम्पूर्ण देश का सामान्य हित ।

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के भव तक के अनुभव अधिक अच्छे नहीं रहे हैं । निकल्सन (Harold Nicolson) महोदय ने अपनी पुस्तक 'कूटनीति' (Diplomacy) के पाचवें अध्याय में प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के अनेक दोषों का वर्णन किया है । प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति का प्रथम दोष यह है कि इसमें 'सम्प्रभु जनता' अनुत्तरदायी होती है । कूटनीतिक कार्यों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालना जनता का अधिकार समझा जाता है किन्तु उन कार्यों से होने वाले दुष्परिणामों के लिए वह जिम्मेदार नहीं बनना चाहती ।

इसका दूसरा दोष यह है कि सामान्य नागरिक विदेश नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने में असमर्थ रहता है । यदि उसके सामने सभी तथ्य यथाविधि प्राप्त कर दिये जायें तो भी वह विश्व राजनीति का एक सतोषजनक चित्र अपने मस्तिष्क पर नहीं उतार सकता और न ही वह उसके प्राणियों परिवर्तनों का अनुमान लगा सकता है ।

तीसरा दोष यह है कि प्राणिक रूप से सूचित लोग विदेश नीति के उलझे हुए प्रश्नों पर शीघ्रतापूर्वक विषादी (Positive) निर्णय ले लेते हैं । यह उन लोगों के लिए एक दुःखद स्थिति पैदा कर देता है जो तथ्यों के आधार पर कुछ बौद्धिक निर्णय लेना चाहते हैं ।

चौथा दोष यह है कि प्रजातन्त्र में लोकमत द्वारा एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिसके आधार पर एक देश की विदेश नीति को चलना चाहिए । इस सीमा के अनेक लाभ हैं किन्तु सबसे बड़ा दोष यह है कि देश के नेता भवमय क अनुकूल कोई निर्णय तत्काल नहीं ले पाते । पामर तथा परकिन्स के कथनानुसार प्रजातन्त्रीय देशों की 'बहुत कम और बहुत देर की नीति' (too little and too late) अपनाने के लिए आलाचित किया जाता है । समय पर कोई कदम न उठाने से बाद में अनेक दिक्कतें लड़ी हो जाती हैं ।

पाचवां दोष यह है कि कयनी और करनी के बीच भारी अन्तर रहने लगा है । बार्तोलोप, मायरा एव कार्यों द्वारा यही प्रयत्न किया जाता है कि नीति का वास्तविक स्वरूप लोगों की आँखों से छिपाया न रहे । एक कूटनीतिज्ञ जब किसी मामले में बोलता है तो वह कम से कम बोलता है और जो भी बोलता है उसे बड़े लुभावने ढंग से । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति के कार्यों में निश्चितता एवं पारदर्शिता की अपेक्षा अनिश्चितता (Vagueness) अधिक है।

(२) सर्वाधिकारवादी कूटनीति (Totalitarian diplomacy)

बीसवीं शताब्दी का ही एक दूसरा विकास सर्वाधिकारवाद है जो प्रजातन्त्र के विपरीत तानाशाही प्रवृत्तियों को प्रवर्धित करता है। इस व्यवस्था में देशों की कूटनीति के संचालक उच्च स्तर के कुछ परमाण्विक नेता होते हैं। प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से ये देश में अपनी महत्वाकांक्षियों एवं सही लक्ष्यों को एक पद के पीछे डाल देते हैं। सर्वाधिकारी राज्यों के आदर्श, विश्वास, लक्ष्य एवं कार्य भिन्न होने के कारण उनकी कूटनीति का रूप भी प्रजातन्त्रात्मक देशों से भिन्न रहता है। इस कूटनीति की विशेषताओं निम्न प्रकार हैं—

१. यह कूटनीति विचारधारा (Ideology) को आधार बना कर घाते बढ़ती है तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए जातीय बड़प्पन, भक्तिवाद, भक्तिवाद आदि का सहारा लेती है।

२. सर्वाधिकारी कूटनीतिज्ञों का उद्देश्य मान्यपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का निर्माण करना नहीं है बल्कि उनका मूल उद्देश्य अपनी विचारधारा का प्रसार करना है। इसके लिए दूसरे देशों में वे विशेष दलों का निर्माण, पोषण एवं समर्थन करते हैं।

३. सर्वाधिकारी कूटनीतिज्ञ कूटनीति के सामान्य नियमों का पालन तभी तब करते हैं जब तक वह उनके स्वार्थों की योजनाओं से मेल खाता हो।

४. ये मुले रूप से यह घोषणा करते हैं कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि एवं संधि को इच्छा के अनुसार तोड़ा या अस्वीकृत किया जा सकता है।

५. ये कूटनीतिज्ञ यह प्रचार करते हैं कि साम्यवादी एवं पूँजीवादी राज्यों के बीच का संघर्ष एवं मतभेद सदा रहने वाला तथा कभी न मिटने वाला है।

६. दूसरे देशों के मित्रतापूर्ण व्यवहार को ये उस देश की कमजोरी, पाषण्डतापूर्ण नीति एवं बुरे इरादों का प्रतीक मानते हैं तथा विश्व सन्धि को अपने प्रचार का केन्द्र बना लेते हैं।

७. सर्वाधिकारी राज्यों के साथ दूसरे राज्यों के सम्बन्ध इतने भेदपूर्ण एवं सघर्षपूर्ण हैं कि कूटनीति का व्यवहार असम्भव सा बन गया है क्योंकि कूटनीति तब ही पर कार्यन्वित हो सकती है जहां कि दो राज्यों के बीच कुछ बातों पर तो मेल या एक जैसी राय हो। शीतयुद्ध की स्थिति में कूटनीतिक व्यवहार नहीं चल सकता। अब ज्यों-ज्यों शीतयुद्ध समाप्त होता जा रहा है त्यों-त्यों दोनों दलों के बीच समझौतों की मात्रा बढ़नी जा रही है और समझौते कूटनीति की आत्मा होते जा रहे हैं।

(३) सम्मेलनों द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Conference)

कूटनीति के रूप में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस समय में लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना की गई और इससे विश्व के राष्ट्रों को मिल कर तथा सम्मेलनों के रूप में विचार करके अपनी समस्याओं को सुलझाने का विचार सूझा। समय के अनुसार यह विचार व्यवहार में लोकप्रिय बनना चला गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सम्मेलनों के माध्यम से कूटनीतिक व्यवहारों को संचालित करना एक साधारण बान बन गई। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार आजकल प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के ६ हजार से १० हजार तक सेशन होते हैं।

सम्मेलन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वे सम्मेलन जो महत्वपूर्ण तथा तबनीकी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं। ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थोड़ी ही होती है। केवल विशेषज्ञ ही भाग लेते हैं। दूसरे प्रकार के वे सामान्य सम्मेलन होते हैं जिनमें सौ सौ व्यक्ति भाग लेते हैं। ऐसे सम्मेलन प्रायः संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में आयोजित किये जाते हैं तथा उच्च स्तर के कूटनीतिज्ञ भी इनमें भाग लेते हैं।

लॉर्ड जॉर्ज के युद्ध मन्त्रिमण्डल के एक सदस्य मॉरिस हेन्के (Lord Maurice Hankey) ने 'सम्मेलन द्वारा कूटनीति' को युद्ध रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय माना है। उनके अनुसार ऐसी कूटनीति के अनेक लाभ हैं जैसे—इसकी प्रक्रिया लचीली होती है, अनौपचारिकता रहती है, सदस्य एक दूसरे से परिचित रहते हैं, सिद्धान्तों के बीच मैत्री रहती है, गुप्त प्रक्रियाओं एवं प्रकाशित परिणामों के बीच एक सामंजस्य रहता है, सचिव एवं व्याख्याता विश्वासजनक होते हैं।^१

1 Lord Maurice Hankey, 'Diplomacy by Conference' (1946)

अनेक क्षेत्रीय तथा ग्रन्थ प्रकार के समूह जैसे नाटो (NATO), अमरीकी राज्यों का संगठन (OAS) तथा योरोपीय एकता आन्दोलन आदि को भी सम्मेलन की कूटनीति के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इन सोमिन समूहों के बीच समझौते की बातचीत कभी-कभी पर्याप्त कठिन हो जाती है क्योंकि इन देशों के बीच का सम्बन्ध पर्याप्त निकट का है। पेडितफोर्ड तथा बिकन का यह कथन पर्याप्त तथ्य-मग्न है कि राजनैतिक विषयों एवं विरोधियों की अपेक्षा कई बड़े मित्रों के साथ लेन देन की बात करना अधिक कठिन बन जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जब से जनता रुचि लेने लगी है तब से सम्मेलन की कूटनीति अधिक लोकप्रिय हो गई है। अब महाशक्तियाँ छोटे राज्यों की आवाज को महत्व देने लगी हैं तथा उनको बराबर का मत प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में वे इन राज्यों के समर्थन की आवश्यकता को जानने लगी हैं। इस प्रकार के प्रबन्ध में एक समस्या यह उठ खड़ी हुई है कि जब बड़े राज्य किसी प्रभावशील निर्णय को लेना चाहते हैं तो छोटी शक्तियाँ यह माग कर सकती हैं कि किसी राज्य की आलोचना करने या बुरा मला कहने से पूर्व इसके लिए मतदान करा लिया जाये। इस प्रकार बड़ी शक्तियाँ बड़ी अटपटी स्थिति में पड़ जाती हैं जहाँ कि वे छोटे राज्यों पर आक्रमण करने की अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाती। इसीलिए वे कभी-कभी इस प्रकार के मतदान की उद्युक्तता के बारे में सन्देह प्रकट करती हैं। सम्मेलन की कूटनीति, समुक्त नियोजन एवं क्रिया का प्रयोग करके विशेष क्षेत्रों में सहयोग का बढावा है। उदाहरण के लिए नाटो को एक महत्वपूर्ण प्राप्ति यह है कि इसने शक्तिशालीन रीतिक सहयोग का विकास किया है। यद्यपि अनेक न सुलझाई जाने वाली समस्याएँ हैं किन्तु फिर भी नाटो संगठन सम्मिलित विचार, समुक्त क्रियाएँ एवं कार्यों की हिस्सेदारी को विकसित करने में पर्याप्त सफल हुआ है और इसलिये उत्तरी एटलांटिक समाज के लिए परमावश्यक है।

सम्मेलन की कूटनीति का एक दूसरा विकास समाज की मान्यता का विकास है। यह योरोपीय आर्थिक समाज तथा इससे सम्बद्ध निकायों की रचना करके प्रोत्साहित किया गया है। सम्मेलन की कूटनीति ने सशस्त्रीय कूटनीति को जन्म दिया जो आज के कूटनीतिक दृश्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है।

सम्मेलन की कूटनीति हमेशा एक खुली कूटनीति होती है। जिन प्रकार खुले समझौते खुले में किए जा सकते हैं उसी प्रकार खुले मतभेद भी

खुले में ही प्रदर्शित किए जायेंगे। इससे यह सम्भावना है कि सम्बन्धित दोनों पक्षों के हितों का नुकसान हो और उस सम्मेलन या संगठन का नुकसान हो जिसमें कि ये किए गए हैं। कभी कभी वाद विवाद और असहमति का जनता की आँखों से ओझट रखना अच्छा समझा जाता है क्योंकि इससे समस्या स्पष्ट होती है और विवादपूर्ण समस्याओं पर विचार-विमर्श अच्छी प्रकार किया जा सकता है। आज से सौ साल पूर्व ऐसा कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं था जो कि निरन्तर रूप से मिलता हो। आज संयुक्त राज्य अमरीका प्रति वर्ष लगभग ४०० सम्मेलनों में भाग लेता है। इनमें से अनेक तकनीकी विचार विमर्श होते हैं और जिनमें सरकारी विभागों के विभिन्न अधिकारी भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रयासों से राष्ट्रों की कूटनीतिक सेवाओं पर पर्याप्त भार बढ गया है। यदि सम्मेलनों के लिए पर्याप्त तैयारी न की जाए तो उनका परिणाम असफलतापूर्ण होगा। सम्मेलन की कूटनीति को कभी कभी प्रचार के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह प्रवृत्ति अत्यन्त खतरनाक है क्योंकि इससे कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने और अन्य की शक्ति को कम करने का प्रयास करता है।

सम्मेलन की कूटनीति की अनेक सीमाएँ हैं। कूटनीति को इस प्रकार का समर्थन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह ऐसी ही प्रक्रिया दिखाई देती है जैसी कि किसी राज्य की व्यवस्थापिका की बैठक में रहती है किन्तु असल में किसी व्यवस्थापिका की बैठक तथा सम्प्रभु राज्यों के सम्मेलनों के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। पहला अन्तर तो यही है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति और महत्व के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों के प्रतिनिधि स्वतन्त्र एजेंट नहीं होते। किन्तु अपनी सरकारों के निर्देशनों से बंधे रहते हैं और उनका काम होता है अपने राज्य के हितों की रक्षा एवं अभिवृद्धि करना।

साम्यवादी राज्यों एवं पश्चिमी शक्तियों के बीच सम्मेलन की कूटनीति के लिए कुछ बातों पर मित्र राष्ट्रों के बीच समझौता होना जरूरी है कि किस विषय पर समझौता बार्ता की जाए? कब की जाए? क्या समझौते तथा मुक्तियाँ की जा सकती हैं? और कब बड़ा दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है? जा भी महत्वपूर्ण समझौते किए जायें वे सम्बन्धित सरकार द्वारा स्वीकृत हाने चाहिए। कुछ स्थितियों में महत्वपूर्ण समझौते व्यवस्थापकों के सम्मुख स्पष्ट करने होते हैं क्योंकि उनकी स्वीकृति परमावश्यक है। जेम्स रेस्टन (James Reston) का कहना है कि इन समझौतों को करते समय प्रेस पर भी आँख रखनी होती है क्योंकि प्रजासत्तव में प्रेस पर्याप्त साधन

सम्पन्न होती है और वह यह मान कर कार्य करती है कि सनी कूटनीतिक प्रयास समाचार होते हैं।

सर्वाधिकारी राज्यों के अधिकारियों को राजनीति स्थिति एवं प्रेस के इन दबावों के प्रयोग कार्य नहीं करना होता। ये देन दिए गए सम्झौतों को किसी भी समय बिना किसी परेशानी के बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त महा की प्रेम भी उपयुक्त सत्ता की स्वीकृति प्राप्त किए बिना सम्मेलन के वातावरण को प्रकाशित नहीं करती। इसके अतिरिक्त प्रेस द्वारा नियंत्रित लेने वालों के मध्य स्थित विवादों को भी प्रकाशित नहीं करती और न ही यह प्रकाशित करती है कि निष्पक्षिकों द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए किस प्रकार प्रयास किया गया, क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसा करने से विरोधियों को बल मिलेगा। सन् १९६१ के बर्लिन संकट के दौरान जब पश्चिमी विदेश मंत्री साबियत विदेश मंत्री से बात करने से पूर्व मिल रहे थे तो जेम्स रेस्टन ने न्यूयार्क टाइम्स में इस पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि सोवियत विदेश मंत्री जब बात के लिए आयेंगे तो उनके हाथ के कांठ छिपे हुए रहेंगे। वह जब राज्य सचिव रस्क से मिलेंगे तो उन सम्झौतों के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद मिलेंगे जो किए जा चुके होंगे तथा उनके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। यह व्यवस्था स्पष्टतः एक असमान व्यवस्था है और उस समाज के पक्ष में है जो पराजित गोपनीयता रखता है और सब तक ऐसा रहेगा जब तक पश्चिमी देश अपने हित की दृष्टि से कूटनीति के संचालन की कोई नई प्रक्रिया नहीं खोज लेते।

(४) व्यक्तिगत कूटनीति (Personal Diplomacy)

कूटनीति के इस रूप के अनुसार दो देशों के कूटनीति विषयों का संचालन स्वयं उन देशों के विदेश मंत्रियों, प्रधानों एवं प्रमुखों के द्वारा किया जाता है न कि उनके कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा। कूटनीति के इस रूप का प्रयोग संघर्ष पहले भी होता था किन्तु वर्तमान युग में तो यह एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर इन उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। जेनवा सम्मेलन वाप्टुग सम्मेलन अल्जीरस सम्मेलन एवं अन्य अनेक विदेश सम्मेलनों को इस प्रकार की कूटनीति के उदाहरणस्वरूप लिया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भी बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श करने की मिले थे। शीत युद्ध के काल में नाटो (NATO) शक्तियों

के विदेश मन्त्री अपने सामान्य हित के मामलों पर विचार करने के लिए कई बार मिला चुके हैं।

व्यक्तिगत कूटनीति को प्रियान्वित करने के लिए कई बार एक देश के प्रधानमन्त्री एवं विदेश मन्त्रियों द्वारा प्रतिनिधियों का सहारा लिया जाता है। स्वयं के कार्य को हल्का करने एवं कार्य की सम्पन्नता में समय की बचत करने के लिये ऐसा किया जाता है। भारत-पाक संघर्ष के दौरान भारत ने अनेक मन्त्रियों एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कार्यकारिणी के एजेण्ट अथवा प्रधानमन्त्री के व्यक्तिगत प्रतिनिधि के रूप में विदेशों में भेजा था, क्योंकि इस संघर्ष में भारत के पक्ष को स्पष्ट करना तथा दूसरे देशों की सहानुभूति एवं सहयोग प्राप्त करना शीघ्र ही आवश्यक था। ताशकंद में ४ जनवरी, ६५ को निश्चित शास्त्री-अयूब का मिलन भी व्यक्तिगत कूटनीति का ही एक रूप कहा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अग्निनेता चर्चिल और रुजवेल्ट प्रायः अनीपचारिक एवं व्यक्तिगत रूप से ही मिला करते थे।

व्यक्तिगत कूटनीति, कुछ विचारकों के मतानुसार, नुस्सानदायक है। इन विचारकों का कहना है कि प्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री आदि उच्च स्तर के पुरुषों का काम नीति का निर्माण करना है न कि समझौते करना, यह काम तो कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञों को सौंप देना चाहिये। कारण यह है कि उच्च स्तर के अधिकारी समझौते करने के लिये योग्य नहीं होते। माथ ही डर रहता है कि वे विषय को विषयी (Subjective) दृष्टि से देखेंगे जो राष्ट्रीय हित के विपरीत भी जा सकता है। लार्ड वंसिस्टार्ट (Lord Vansittart) के मत में ऐसी कूटनीति का व्यवहार कभी कभी ही सफल हो पाता है क्योंकि 'परामर्श' की प्रत्येक को आवश्यकता रहती है। हेरल्ड निकल्सन (Harold Nicolson) तथा सिसली हाडल्स्टन (Sisley Huddleston) आदि का विचार भी व्यक्तिगत कूटनीति के विरुद्ध जाता है।

दूसरी ओर लार्ड हेन्की (Lord Hankey) आदि के विचार से व्यक्तिगत कूटनीति का अपना महत्व है क्योंकि कई समस्याओं का समाधान इतना बटिन हो सकता है कि कूटनीतिज्ञों के पास जो साधन हैं वे उसके लिये अपर्याप्त रह जायें। इन विचारकों के मत में ससदात्मक प्रजातन्त्र के युग में मध्यस्थों पर निर्भर रहना उचित नहीं है।

(५) दूकानदार जैसी कूटनीति बनाम युद्धप्रिय कूटनीति
(Shopkeeper diplomacy Vs Warrior diplomacy)

यदि हम विभिन्न देशों की कूटनीति पर एक विह्वल दृष्टिपात करें

तो पायेंगे कि उन सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। निक्लसन (Nicolson) महोदय ने ब्रेट ब्रिटेन की कूटनीति में वे सभी गुरा पाये हैं जो कि एक व्यापार में पाये जाते हैं।^१ जो कूटनीति बुद्धिपूर्ण समझने करने को तैयार रहती है, दूसरे राष्ट्रों के साथ प्रेम बढ़ाती है तथा विभिन्न मन्त्रियों के द्वारा शान्ति निर्माण में प्रयत्नशील रहती है, वही कूटनीति व्यवहार में आकांक्षित परिणामों को प्राप्त कर पाती है। एक दूकानदार जैसी यह कूटनीति महत्वपूर्ण एवं लाभदायक है क्योंकि यह मन्त्रियों की अपेक्षा अधिक नैतिक है तथा उन रूपों की तुलना में अधिक सफलता प्राप्त करने में समर्थ रहती है। एक देश की सफलता एवं अन्तराष्ट्रीय समाज में उसका स्थान मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करता है—यह देश किस प्रकार की कूटनीति अपना रहा है, उस देश की राष्ट्रीय नीति कैसी है, तथा समझौता वक्तव्यों का अस्तित्व कैसा है।

कूटनीति का एक दूसरा रूप जो उपर्युक्त से पूर्णतः भिन्न प्रकृति का है, युद्धप्रिय रूप है। यह समझौतों में विश्वास नहीं करता तथा युद्ध के वातावरण को अधिकाधिक उत्तेजित करने के लिए सर्वप्रयत्नशील रहता है। कुछ विचारक यह मानते हैं तथा इतिहास का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस प्रकार की कूटनीति को मानने वाला देश अन्त में स्वयं ही नष्ट हो गया तथा कोई सन्तोषजनक सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

दूकानदार जैसी एवं युद्धप्रिय कूटनीतियों के बीच अनेक भिन्नताएँ हैं। दोनों ही विशेषताएँ परस्पर विरोधी हैं। यदि हम इनके व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास के पृष्ठ उलटें तो पायेंगे कि आ देन स्थिर व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाये रखने के पक्ष में हैं वे पहली की तथा जो देश स्थिर व्यवस्था को पुनर्निर्माण देने हैं तथा बदलन की टोह म रहते हैं वे दूसरी की अपेक्षाते हैं। इस दृष्टि से यदि हम पश्चिमी प्रजातन्त्रों की कूटनीति को देखें तो हमें ज्ञान हो जायेगा कि उसमें वे सभी विशेषताएँ वर्तमान हैं जो एक दूकानदार जैसी कूटनीति की वस्तु की गई है। दूसरी ओर साम्यवादी देशों की कूटनीति में हमें युद्धप्रियता का आभास मिलता है विशेषतः साम्यवादी चीन की कूटनीति में।

दोनों ही प्रकार की कूटनीतियों का आधार परिस्थितियाँ, राज्य का स्वरूप एवं विचारधारा है अतः दोनों का ही अपना मूल्य है। दूकानदार जैसी कूटनीति की क्रिया-विवरण करते समय ब्रिटेन ने चानुरं, दुर्गलता एवं तपट

से भी कई बार काम लिया है। इसमें उसे सफलता और असफलता दोनों ही प्राप्त हुई है। एक देश कूटनीति के किस रूप को अपनाता है तथा उस रूप को अपनाने में उसे सफलता कितनी प्राप्त होती है, इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय पदस्थेणी में वह देश कौन सा स्थान रखता है तथा उस देश की शक्ति कितनी है। प्रारम्भ से ही ब्रिटेन की कूटनीति सफल होती चली आई इसका कारण उसकी शक्ति थी। मित्र के मामले पर उसे पीछे हटना पड़ा; इसका कारण यह है कि अब वह दूसरी श्रेणी की शक्ति बन गया है।

युद्धप्रिय तथा दूकानदार जैसी कूटनीतियों के बीच का मुख्य अन्तर इस प्रकार है —

(१) युद्धप्रिय कूटनीति जब समझौते करने बैठती है तो असबोद्धिक (Unreasonable) बन जाती है क्योंकि बोद्धिक रूप से सोचने पर स्थित व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। इसके विपरीत दूकानदार जैसी कूटनीति बुद्धिपूर्ण समझौते करती है।

(२) प्रभावशील (Dominant) देशों की माग बड़ी होती है, तथा बुद्धिपूर्ण होती है। वे स्थित व्यवस्था से सन्तुष्ट रहते हैं और इसलिए शक्ति के प्रयोग के प्रत्येक रूप को बुरा मानते हैं। वे समझौतों को आवश्यक मानते हैं। इसके विपरीत चीन जैसे देश युद्ध को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का आवश्यक साधन मानते हैं।

(३) प्रभावशील देशों की (जो स्थित व्यवस्था के हिमायती हैं) कूटनीति अस्पष्ट रहती है। उनके कूटनीतिक समझौतों का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं रहता।

(४) प्रभावशील देश ऐसी किसी चीज की माग नहीं करने जो उनके पास नहीं है। साथ ही वे यह भी चाहते हैं कि दूसरे देश भी उन चीजों की माग बन्द कर दें जो कि उनके पास नहीं हैं। ये देश स्थित विश्व व्यवस्था से सन्तुष्ट रहते हैं अतः स्पष्टतः नहीं जान पाते कि उनकी आवश्यकतायें क्या हैं।

(५) युद्धप्रिय कूटनीति को अपनाने वाले देशों के कुछ निश्चित लक्ष्य होते हैं। वे वर्तमान को बदल कर अपने अनुकूल विश्व बनाना चाहते हैं जहाँ उनके हितों को सन्तुष्ट किया जा सके। इस नये विश्व का मानचित्र उनके मस्तिष्क में रहता है। जैसे साम्यवादी चीन सारे ससार को लाल भूके नीचे लाने के स्वप्न में मस्त है।

(६) मुद्रप्रिय कूटनीति अपनाते वाले देश प्रायः गरीब, कम शक्ति वाले तथा असन्तुष्ट होते हैं, शक्ति के अनुपात में उनको कूटनीतिक सफलताएँ कम मिल पाती हैं, विश्व समाज में भी उनका स्तर अधिक ऊँचा नहीं रहता। यही कारण है कि वे वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए युद्ध और संघर्ष का सहारा लेते हैं, बर्बोदिक समझौतों से घाये बटने हैं। दुकानदार जैसी कूटनीति अपनाने वालों का स्वभाव व सज्ज इसके विपरीत होता है।

(६) खुली कूटनीति बनाम गुप्त कूटनीति

(Open Diplomacy Vs Secret Diplomacy)

प्रजातन्त्रात्मक कूटनीति का परीक्षण करते समय प्रथमता यह बताया गया था कि आज के प्रजातन्त्रात्मक युग में जनसाधारण यह अपना अधिकार मानते तथा है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सन्धि, समझौते समवा कूटनीतिक व्यवहार किये जायें उन सबकी जानकारी उनको दी जानी चाहिए। खुली कूटनीति का समर्थन नैतिक एवं आदर्शात्मक दृष्टिकोणों से भी किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार की कूटनीति की मांग बढ़ती गई। युद्धो विलसन के १४ सिद्धान्तों में से पहला सिद्धान्त था कि सभी शान्तिपूर्ण समझौते खुले रूप में किये जाने चाहिए। कूटनीति हमेशा जनता के दृष्टिकोण से एवं स्पष्ट रूप में संचालित की जाये न कि व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के आधार पर।^१ खुली कूटनीति के समर्थक घनने पक्ष के प्रतिपादन में निम्नलिखित तर्क प्रदान करते हैं—

✓ (१) एक राष्ट्र के लोगों को यह अधिकार है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये समझौतों की जाने बर्बोदिक आवश्यकता पड़ने पर इन और जीवन का बलिदान वे ही करते हैं।

(२) प्रजातन्त्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है यह उत्तरदायित्व तब तक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता को दूरों से परिचित न रखा जाये।

(४) कूटनीतियों द्वारा जिन विषयकारी मुद्दों का बानावरण होमार किया जाता है तथा जिसमें लोगों की सबभूर करके झोंक दिया जाता है, वह सब न हो यदि जनता का कूटनीतिक कार्यों पर सरक्षण रहे।

(४) खुली कूटनीति का अर्थ जैसा कि स्वयं विलसन ने सीनेट को लिखा था, यह बताना नहीं है कि महत्त्वपूर्ण मामलों पर व्यक्तिगत रूप से

विचार-विमर्श ही न किया जाय। इसका अर्थ तो यह है कि कोई समझौता गुप्त न रखा जाय, तय करने के बाद सभी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्पष्ट कर देने चाहिए, प्रकाशित कर देने चाहिए।

उक्त तर्कों का विरोध करती हुए गुप्त कूटनीति के समर्थक अपने पक्ष के प्रतिपादन में जो तर्क प्रस्तुत करती हैं उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—

(१) एक सफल कूटनीति के लिए गुप्त रहने की आवश्यकता है।

(२) गुप्त रूप से जो समझौते किए जाते हैं उनमें स्पष्टता (Frankness) रहनी है तथा कूटनीतिज्ञ उन सुविधाओं को देने के लिए भी राजी हो जाते हैं जिनको वे सब नहीं दे सकते जबकि जनता उनसे परिचित हो।

(३) प्रकाशन की परम्परा से 'कूटनीतिज्ञ' प्रचारक (Propagandist) बन जायेंगे तथा वे जनता के क्षणिक दुराग्रहों से भी प्रभावित किये जायेंगे।

दोनों ही पक्षों के तर्कों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से प्रत्येक समर्थक नहीं है। मुली कूटनीति के समर्थकों का सबसे बड़ा तर्क यह है कि उनके द्वारा समर्थित कूटनीति प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुकूल है। ये विचारक मानते हैं कि कूटनीति अपने आप में एक लक्ष्य होती है। कूटनीति को प्रजातन्त्रात्मक बनाने का लक्ष्य इन विचारकों के मत में यह है कि इससे युद्ध का खतरा टल जायगा तथा शान्ति की जड़ें गहरी होगी। किन्तु यह मत देखने में जितना मानने योग्य लगता है, व्यवहार में हवाई जिले से अधिक सत्य नहीं है।

गुप्त कूटनीति के समर्थकों का मुख्य विश्वास यह है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को प्रकाशित कर दिया गया तो इससे समझौता करने वालों में लचीलापन नहीं रह पायेगा। वर्तमान समय के अधिकांश सम्मेलनों में समझौता करने वालों में लचीलापन नहीं रहता। इसका कारण यही माना जाता है कि उनको प्रकाशित कर दिया जाता है। किन्तु इस विश्वास के पीछे कोई प्रभाव नहीं है, अतः यह भ्रामक है। गुप्त कूटनीति के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आज सुखी होने के कारण कूटनीति असफल हो गई है। पहले कूटनीति सफल थी क्योंकि वह गुप्त होती थी। यह तर्क भी सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि कूटनीति की असफलता के अन्य दूसरे कारण बहुत हैं।

कूटनीति की प्रभावशाली होने के लिये चुना होता न आवश्यक है और न उपयोगी ही। पामर तथा परकिंस के विचार से जनता का मत इसमें है कि समझौते के परिणामों एवं उद्देश्यों के लिये मताओं को उत्तर-दायी ठहराया जाये न कि इसमें कि समझौते ही देसीविजन के पर्दे पर बिछे जायें।^१

(७) प्रचार द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Propaganda)

कूटनीतिक निशानों की अपने हितों के अनुकूल बनाने में प्रचार का महत्वपूर्ण कार्य है। रेडियो, प्रेस तथा प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जनता को एक विशिष्ट नीति के सम्बन्ध में प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। जार्ज वी० एलेन (George V Allen) के मतानुसार प्रचार कूटनीति का एक सचेतन (Conscious) हथियार बन गया है। बिस्मार्क द्वारा इस हथियार का प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया जाता था। ब्रेस्ट लिट्स्क (Brest Litvsk) में ट्राट्स्की ने भी समझौते के तरीके के रूप में प्रचार का प्रयोग किया था। बाद में यह व्यवस्था साधारण बन गई तथा अनेक देश इसे अपनाने लगे। कूटनीति में प्रचार दो प्रकार से सहायक बनता है—

(१) प्रचार द्वारा समझौते पर विचार करने योग्य वातावरण तैयार किया जाता है।

(२) जब समझौता हो रहा हो तो उसे प्रभावित करके अपने हित व अनुकूल बनाया जाता है।

जहां तक पहले कार्य का सम्बन्ध है, प्रचार उपयोगी है और इसलिए प्रत्येक देश प्रशासन एवं प्रचार पर बहुत धन खर्च करता है। किन्तु हमारे कार्य का जहां तक सम्बन्ध है प्रचार बहुत कम ही सफल हो पाता है। प्रचार कार्य मुख्य रूप से विदेश मन्त्री या अन्य राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है न कि कूटनीतिज्ञों द्वारा। यद्यपि प्रचार के द्वारा जनता में अनेक मिथ्या विश्वास एवं भ्रम पैदा होते हैं किन्तु आज की परिस्थितियों में यह अपरिहार्य बन गया है। पनिकर (K M Panikkar) महोदय ने समझौते (Negotiation) को एक गुप्त तरीका माना है। उनके मतानुसार जिस समय समझौते चल रहे हों उस समय प्रचार बड़ा खतरनाक होता है।^२

१ Palmer and Perkins, op cit, P. 115

२ K M Panikkar, op cit, P 93

दिया है कि भाज कूटनीति का श्रियान्वित होना रठिन बन गया है। कूटनीति के महत्व को गिराने में तथा उनके सफल संचालन के मार्ग में प्रभाव डालने वाले कुछ नवीन विकास भी हैं।

कूटनीति पर प्रभाव डालने वाले कुछ नए विकास (New developments responsible for changing role of diplomacy)

भाज कूटनीति द्वारा विश्व राजनीति में उस कार्य का सम्पादन नहीं किया जा रहा है जो वह विश्व युद्धों के पूर्व करता था। मार्गेन्थो (Morgenthau) महोदय के मतानुसार "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कूटनीति अपना महत्व खो चुकी है। इसके कार्य अब जितने कम रह गए हैं इतने राज्य व्यवस्था के इतिहास में कभी नहीं रहे थे।" कूटनीति का महत्व घटाने लिए उन्होंने ५ कारणों को उत्तरदायी ठहराया है। ये विभिन्न प्रकार हैं—

१ संचार के साधनों का विकास (Development of Communications)

२ कूटनीति का अवमूल्यन (Depreciation of diplomacy)

३. मसदात्मक प्रक्रिया द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Parliamentary Procedure)

४ सर्वोच्च शक्तियाँ—कूटनीति में नवागत (The superpowers Newcomers in Diplomacy)

५. वर्तमान विश्व राजनीति का स्वरूप (The nature of contemporary world politics)

उन कारणों से कूटनीति का व्यवहार कठिन बन गया है। विचार-धारा के आधार पर समार के दो गुटों में बंट जाने से सबसे बड़ा जतरा कूटनीति को ही हुआ है। जैसा कि पहले भी एक बार कहा जा चुका है कूटनीतिक व्यवहार केवल वही समभव होता है जहाँ कि इसकी आवश्यकता के बीच कुछ समझौते—मे तो समानता हो। समझौते का प्रश्न ही वही उठता है जहाँ कि कुछ बातों में दोनों पक्ष सहमत हों तथा कुछ बातों पर उनमें मतभेद हो। समझौता इस मतभेद को मिटाने का प्रयास करता है किन्तु जिन देशों के बीच प्रत्येक बात में अंतर एवं विरोध हो वहाँ समझौता सम्भव ही नहीं हो सकता। पत्रिचर महोदय के मतानुसार "विश्व के दो प्रधान गुटों के

बीच इतनी गहरी खाई है कि उनके बीच कूटनीतिक सम्बन्ध रह ही नहीं सकते ।”

एक ओर तो विभिन्न कारणों के फलस्वरूप कूटनीति का व्यवहार आज के युग में दुम्ह बन गया है और दूसरी ओर उसकी आवश्यकता जितनी आज के समुदाय में है उतनी ज़ायद ही किमी युग में रही होगी । विश्व में शक्ति के लिए मर्द सपस होजा रहजा है, इस सपस को सीमित एवं सतुतिन बना कर कूटनीति विश्व में शान्ति-स्थापना का एक प्रमुख साधन बनता है । कूटनीति के प्रभाव का धर्म होगा युद्ध और युद्ध का धर्म होगा प्रलय तथा मानव सम्पत्ता और सङ्कृति का विनाश । इस सतरे को टालने के लिए उन तरकों को खोज करना आवश्यक है जो कि वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में भी कूटनीति को सम्भव बना सके । कूटनीति को पुन स्थापित करने के लिए पहले तो उन सभी तरकों को मिटाना होगा या कम करना होगा जो कि पुरानी कूटनीति के पतन का कारण मान जाते हैं । हेरल्ड निकल्सन (Harold Nicolson) के मतानुसार तीन ऐसे विकास हैं जिन्होंने कूटनीति के सिद्धांत एवं व्यवहार को प्रभावित किया है, वे हैं—

१. राष्ट्रीय समुदाय के प्रति बढ़ती हुई चेतना (Growing Sense of the community of nations)
२. सोचमत्त का बढ़ता हुआ महत्व (Increasing appreciation of the importance of public opinion)
३. संचार के साधनों का विकास (Rapid increase in Communications)

मार्गेन्थो महोदय के मतानुसार आज की परिस्थितियों में एक देश की कूटनीति को सफल रूप से कार्य करने के लिए नौ नियमों का पालन करना चाहिए । इनमें चार मौलिक नियम निम्न प्रकार हैं—

१. कूटनीति को मान्योक्तन करने वाली विचारधारा से प्रेरित रखा जाय । इस नियम का उल्लंघन करने पर युद्ध का सुतरा बढ जाता है ।
२. विदेश नीति को राष्ट्रीय हित के प्रकाश में परिनामित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय शक्ति द्वारा उसे समर्थित किया जाना चाहिये ।
३. कूटनीति को चाहिए कि यह राजनैतिक दृश्य को दूसरे देशों के दृष्टिकोण से देखे ।

४ एक राष्ट्र को उन सभी विषयों पर समझौता करने को तैयार रहना चाहिए जो उसके लिए अधिक महत्व नहीं रखने हैं ।

समझौते के सफल होने के लिए पांच अथवा नियमों का पालन करना चाहिए । ये इस प्रकार हैं—

१ राजीनामा करते समय राष्ट्र की तरफ ध्यान न देकर जता के हित ही ध्यान दिया जाना चाहिए ।

२ ऐसी स्थिति में बर्ती मत रहो जहाँ से पीछे हटने के लिए तुम्हें अपमानित होना पड़े तथा आगे बढ़ने के लिए सम्भीर आपत्ति का सामना करने पड़े ।

३ कमजोर गिन राष्ट्र को अपने लिए निर्णय बनाने का असमर्थ न हो ।

४ गणस्य सेना विदेश नीति का साधन होनी है, उसका स्वामी नहीं । एक विदेश नीति, जो गणितों द्वारा सैनिक बल के नियमों के अनुसार चलाई जानी है, हमारा युद्ध का ही कारण बनती है, क्योंकि जमा बीज बोया जाता है वैसे ही पत्र भी चढ़ने को मिलते हैं ।

५ सरकार जनमत का नेतृत्व करती है न कि गुनामी का । लोकमत के पीछे भागने वाली कूटनीति सफल नहीं हो पाती क्योंकि लोकमत बौद्धिक की अपेक्षा भावात्मक अधिक होता है ।

कूटनीति के विषय पर अपना निष्कर्ष देने हुए मार्सेनो महादय ने बताया है कि अब तक के इतिहास में कूटनीति सफल हो रही है । प्राचीन समय में राजाओं द्वारा युद्ध रोकने नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था अब वह अपने लक्ष्य में सफल रही, यद्यपि शान्ति की दृष्टि में वह असफलता थी । बिम्बु कूटनीति तो एक साधन मात्र है जिसे एक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा व प्रभिवृद्धि के लिए अपनाता है । कूटनीति का एक ही परिणाम इसे प्रयोग करने वाली की योग्यता एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है ।

संसदीय कूटनीति

(Parliamentary Diplomacy)

संसदीय कूटनीति शब्द के प्रचलन का श्रेय डैन रस्क को दिया जाता है । इनके मतानुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकें राष्ट्रीय संसद से मिलती-

जुनही है क्योंकि उनमें भी प्रक्रिया के नियमों के अनुसार कार्य किया जाता है। प्रारोपित प्रस्तावों पर समुक्त राष्ट्र सच में जो वाद-विवाद एवं कार्य होता है अधिकारियों के चुनाव होते हैं, वोट का निर्धारण होता है और न अन्धविश्वास का बाधित प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया जाता है वह राष्ट्रीय व्यवस्था-तिका की प्रक्रियाओं से भेज लानी हैं।

समुक्त राष्ट्र सच की प्रक्रिया की तथा उन प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित करने को ऐसीय तथा राजनैतिक मुद्दे ऐसे ही प्रमाण करते हैं जैसे कि राष्ट्रीय व्यवस्था में राजनैतिक दलों, ऐसीय मुद्दों एवं विभिन्न हित समूहों द्वारा सत्तादीय व्यवस्था में किया जाता है। समुक्त राष्ट्र सच के बाहरी बलों में प्रतिनिधि मतों का आशय प्रदान करते हैं, अपनी स्थिति के सम्बन्ध में तर्क देते हैं और अपने पक्ष में मत प्राप्त करने का प्रयास करने हैं। समुक्त राष्ट्र सच की बैठक के दौरान भी सोजन बलों में तथा प्रतिनिधियों के विश्वास ब्यक्तों में विचार-विमर्श होते हैं। महा सभा के सत्र के दौरान तथा अन्तराष्ट्रीय सन्ध के समय न्यूयार्क नगर में विरत की किसी राजधानी की प्रवेश अधिक नूतनीति विचारों होती है।

समक्षीय नूतनीति की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। यह इन बात पर जोर देती है कि एक मामले का सबके सामने खाने से तथा उस पर वाद-विवाद करने एवं प्रस्ताव-मांग-करने-मान-ले-गुन-काम-का-संकेत। किन्तु यह एक भ्रम मान है। व्यावहारिक रूप में इस प्रकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप मनमुटाव और राष्ट्रीय मानवायें उत्पन्न होती हैं। यह भी सम्भव है कि एक राज्य बिना प्रस्त को समझे हुए तथा उसके परिणामों पर विचार के ही प्रस्तावित प्रारूप पर मत प्रदान कर दे। जब पूर्ण मतदान होता है तो उसमें अनुसन्धित रहने वाली की सत्ता का भी महत्व हो जाता है। समुक्त राष्ट्र सच में मुद्दे की राजनीति सक्ति राजनीति का रूप धारण कर सकती है जो कि अपने उत्तरदायित्वों से घमण्ड रहे।

समक्षीय नूतनीति उपजोशी भी हो सकती है क्योंकि यह विरत जनमत का रोग देने से पूर्णतः अनजानी मिला हो सकती है। यह अनेक देशों के सहयोग को सुविधाजनक पतानी है तथा सामूहिक कार्य के लिए नींव रोजार करती है। इस प्रकार की नूतनीति को अन्य प्रकार की नूतनीति का विरुद्ध नहीं माना जा सकता।

सोवियत कूटनीति के कुछ रूप (Some Styles of Soviet Diplomacy)

सोवियत मध्य द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जिस कूटनीति का प्रयोग किया गया है वह अनेक दृष्टियों से पश्चिमी राष्ट्रों से भिन्नता रखती है। बोलशेविक क्रांति के बाद से ही सोवियत मध्य विश्व की सरकारों को अन्दरूनी करने में उस समय आया पीछा नहीं देता जबकि ऐसा करने से उनके हितों की साधना होती हो। सन् १९४५ में पोमैंट, सन् १९४८ में चेकोस्लोवाकिया और सन् १९५६ में हंगरी में किए गए उसके प्रयास इस बात के उदाहरण हैं। सोवियत मध्य ने पश्चिमी शक्तियों के प्रति एक अस्पष्ट रहण नीति को अपनाया है ताकि इन राष्ट्रों की प्रतिक्रिया अनुकूल न हो सके। सोवियत मध्य द्वारा अपनाई गई सरकारों को उखाड़ने की नीति (Policy of Subversion) का समुक्त राज्य अमेरिका ने कई प्रयासों से जवाब दिया है। माण्डल योजना एवं नाटो का संगठन आदि प्रयास उसकी प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। बर्लिन के प्रति भी सोवियत मध्य की कूटनीति पर्याप्त अस्पष्ट थी। उसने कई बार बर्लिन के घेरे की तथा दीवार की रचना की घमकी दी और जब भी कभी शक्ति प्रदर्शन का अवसर आया वह पीछे हट गया।

सोवियत कूटनीति की एक अन्य विशेषता यह है कि वह मजिदवा एव समझौते करत समय शब्दों के परम्परागत अर्थों पर विवाद करता है और इस प्रकार संघर्ष को लम्बा बना देता है। यान्टा समझौते पर जो मतभेद रहा, उसका मूल कारण बहुत कुछ यह था कि सोवियत मध्य फासिस्ट एव डेमोक्रेटिक (Fascist and Democratic) शब्दों के प्रयोग पर मतभेद रखता था। सोवियत मध्य ने अपनी विचारधारा को एक रूप रखते हुए गैर-साम्यवादी सरकारों का फामीवादी कहा और उनकी हटाकर साम्यवादी सरकार की स्थापना के कार्य को न्यायाचित्त ठहराया। सोवियत मध्य के मतानुसार साम्यवादी सरकारें ही प्रजातन्त्रवादी थीं। यान्टा समझौता इन पक्षों का निश्चित अर्थ नहीं बता पाया इसलिए माजिदवा मध्य के तर्कों पर विचार किया जाना मुश्किल हो गया।

सोवियत कूटनीति के इस की एक अन्य विशेषता यह है कि वह अपने विरोधी को बदनाम करने की खातिर तर्कों को बहुत दूर तक ले जाती है। सोवियत मध्य की धारा से समझौता बाधा करने वाले लोग अपनी स्थिति में उस समय तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक कि पॉलिट ब्यूरो को ऐसी

स्थिति का ज्ञान न करा दें घबड़ा नए निर्देशन न प्राप्त कर लें। विदेश मन्त्री मात्तोलैंग सोवियत कूटनीति की मोलहीनता का एक प्रतीक माना जाता है। कुछ समय से सोवियत कूटनीति न अपने बठोर दृष्टिकोण को बम बर दिया है।

निन्दा करना एवं भूटे आरोप लगाना सोवियत कूटनीति का एक दूसरा तरीका है। इस प्रक्रिया से एक बार अमरीकी राज्य सचिव जार्ज सी० मार्शल (George C. Marshall) इतने नाराज हो गए कि वह रूसियों से युक्त एक सम्मेलन से उठ कर भा गए और फिर कभी वापस नहीं गए। समुक्त राष्ट्र सभ में भी सोवियत कूटनीतिज्ञों ने अनेक बार परम्परागत कूटनीति सदाचार की अवहेलना की है, जैसे एक बार सुखेच ने अपने जूते द्वारा मेज को बजाया।

सन् १९६० के मध्य तक सोवियत कूटनीति ने जो दृष्टिकोण अपनाया वह अन्तर-राज्य स्वरथा के प्रति सामान्यतः विरोधपूर्ण एवं विदेशियों के प्रति सन्देहपूर्ण था। फिर भी सन् १९६६ के प्रारम्भ में सोवियत प्रधान मन्त्री कोसीगिन ने कुशलता एवं धैर्य के साथ अपने पद का सदुपयोग करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। उस समय सोवियत सभ एक महा शक्ति के रूप में कार्य करते हुए शान्ति स्थापना के अपने उत्तरदायित्व को समझ रहा था।

सोवियत सभ पहले जिन परम्परागत कूटनीतिक तरीकों को पुँजीवादी कह कर ठुकराता था आज वह उनको स्वीकार करने लगा है तथा आदर देने लगा है। यह ज्ञान सन् १९६६ के एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। इस वर्ष साम्यवादी चीन में पीपिंग स्थित सोवियत दूतावास के सामने सद्गति रूप से प्रदर्शन किया गया। सर्वहारा वर्ग की सांस्कृतिक शान्ति के अधीन चीन के वयस्कों ने सोवियत तरीकों के प्रति विरोध प्रकट किया। मारका न इसके प्रति चीन की सरकार ने विरुद्ध बड़ा विरोध प्रकट किया और कहा कि सोवियत दूतावास के सामने की जाने वाली नारेबाजी और दंगे अनुचित थे। इसके प्रतिरुक्त सोवियत भूटे से युक्त एक बार को रोका जाना भी गलत था क्योंकि उसमें सरकारी कार्यबल चार्ज डी प्रेक्पर्स यात्रा कर रहा था। इस समय पवित्रता कूटनीति की भाषा को धरना देने हुए सोवियत सभ ने चीन को परामर्श दिया कि इस प्रकार के कार्य अन्तर्राष्ट्रीय नियम के सामान्य रूप से स्वीकृत मापदण्ड के प्रथम उल्लंघन हैं। राज्यों को कूटनीतिक दूतावास के अधिकारियों के प्रति उपयुक्त सम्मान प्रदर्शित करना होगा है तथा उनकी

व्यक्तिगत स्थानम्भता एवं सम्मान के विरुद्ध किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को रोकना होता है।

मित्रतापूर्ण समझौता-वार्ता करके के लिए तथा समझौता-वार्ता से न सुनने वाले विषयों को निराकरने के लिए यह यह तरीका भी अपनाया जा सकता है कि समझौता-वार्ता करने वाले को समाप्त कर दिया जाए अथवा सरकार को समाप्त कर दिया जाए अथवा उनसे प्रभावशाली तत्वों को मिटा दिया जाए। हत्या और सत्कार को बदलना कूटनीति के परम्परागत तरीके नहीं हैं किन्तु फिर भी इनका प्रयोग किया जाता है। हत्या द्वारा कूटनीति (Diplomacy by Assassination) का प्रचलन पुर्तगाली काल में इटली के राज्यों के बीच था और आज भी इसका प्रयोग समाप्त नहीं है। जैसे विदेशी प्रभाव द्वारा की गई हत्या का स्पष्टतः तम ही सिद्ध किया जा सकता है। फिर भी ऐसे दोषारोपणों के उदाहरण अनेक प्राप्त हो जाते हैं। कई बार अरब राज्यों द्वारा मिस्र पर ये आरोप लगाए गए कि उसने हत्या की कार्यवाहियों का समर्थन किया है। सन् १९५० में कुछ लैटिन अमरीकी राज्यों के अध्यक्षों ने ऐसा ही दोष ट्रुजिलो (Trujillo) पर निरुद्ध भी लगाया जो डोमोनिकन गणराज्य का तानाशाह था और जिनकी हत्या के बाद ही हत्या कर दी गई। हत्या के साधन तो विभिन्नानों द्वारा बहुत प्रयुक्त किया गया है किन्तु उन्होंने इसे सरकार के उच्च स्तर पर प्रयुक्त करने की अवस्था प्राप्ति अथवा विचारियों के स्तर पर ही प्रयुक्त किया है। इन्डोनेशिया में सन् १९६५ में साम्यवादी पटपट्य इग्निए गफन नहीं हो पाया क्योंकि जिन मंत्रि मंत्रियों की हत्या की योजना बनाई गई थी वह न की जा सकी।

सरकार को बदल देना साम्यवादी नीति का एक आम साधन रहा है। साम्यवादी देश यह दावा करते हैं कि गैर साम्यवादी सरकारों को शक्तिहीन बना देना अथवा समाप्त कर देना उनके स्वयं के हित में है और न्यायोचित भी है। ऐसा करके वे अपने एजेण्डों को सरकार की शक्ति सौंप देते हैं और अपने तरीके से समाज का रूप बना लेते हैं। साम्यवादी देश आन्तरिक उपद्रव कराने में, गृह युद्ध छेड़ने में तथा राजनैतिक पटपट्य रचने में नहीं हिचकिचाते।

साम्यवादी देश समझौता-वार्ता की गृष्टभूमि में शक्ति की घमनी को रखते हैं। उनकी कूटनीति के पीछे सीमित शक्ति हमेशा उपस्थित रहती है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तथा नीतिगत तत्वों को प्राप्त करके लिए जब भी कभी जरूरत समझी जाए, उसे चुना लिया जाता है। साम्यवादी राज्य जिस प्रकार की सुरक्षा या संरक्षण चाहते हैं यदि वह प्रदान न किया

जाए तो वे सशस्त्र सेना का प्रयोग करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में चीन और जापान की व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए उनकी भूमि खोलने की बाध्य करी के हेतु जति प्रयत्न का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे बाद चीन में गो-ताई कूटनीति का तरीका विदेशियों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने का एक लोकप्रिय टग बन गया। बीसवीं शताब्दी में भी इसका पर्याप्त प्रयोग किया जाता है। मई १९१६ में ताल सेना का हंगरी भेजा गया था ताकि सावित्रत संधि के सम्बन्धों को चुनौती देने वाले का जवाब दिया जा सके। वर्तमान अरब इजरायल संधि के समय सोवियत संधि के का मुद्राओं पाई गई के बखतर तथा बहुत बड़ी बात के प्रतीक हैं कि अरब राष्ट्रा की शक्ति का साथ व भी शामिल हैं तथा का तो सोवियत संधि के मुद्दों को मान्यता दी जाय नहीं तो य मुद्राओं किसी भी समय विप्लव के विरुद्ध सक्षम हो सकते हैं।

सफल कूटनीति के प्रतीक

(The Symbols of Successful Diplomacy)

वर्तमान समय में कूटनीति अति से अधिक जटिल हो गई है। वर्षों में प्रायः प्रसार का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सुलभता में गहराई बनाने का प्रयास है। कूटनीति की सफलता के लिए यह जरूरी है कि उपयुक्त नीति अपनायी जाय तथा उसे प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली वादक प्रयत्न किया जाय। एक कूटनीतिक कार्य के लिए यह ही बात मान्य है कि राजपातियों तथा सुदूर राष्ट्र संधि में काम किया जाता जारी है। प्रभावशाली कूटनीति में सदैव एकता रहती है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि एक कार्य द्वारा दूसरे कार्य का समापन न कर दिया जाये तथा दो कार्यों का बीच बिना पड़ा न हो जाय। उचित स्थान पर उचित नदम उठाने के लिए पढ़ने से ही समय निश्चित कर लेना उचित रहेगा। कार्य की सम्पन्नता के लिए विशेष कुशलता जरूरी है और कभी-कभी का सामूहिक सशस्त्र सेना का प्रयोग भी जरूरी बन जाता है। आयुनिष्ठ कूटनीति के कार्यों की मुश्किल समस्याओं में ध्यान-धीन भी हो सकती है। कूटनीति का यह एक प्रमुख कार्य होता है कि यह संश्लेषण तथा पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना करे और इस कार्य की सफलता कोई भी कूटनीति नहीं कर सकता।

कूटनीति द्वारा जो भी समस्याएँ हल की जायें उनके अनुसार उचित कार्यवाही की जानी चाहिए तथा प्रभावशाली हो पायेगा। समस्याओं के निराकरण में हम सन्धि की सहमति, समझौते की आवश्यकता, तथा

कार्यक्रम की श्रियान्विति को ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कूटनीति की सफलता के लिए जहाँ भी जरूरी हो वहाँ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। जहाँ कहीं उपयोगी समझा जाये वहाँ प्रचार यन्त्र को सक्रिय करना चाहिए तथा नीति के कूटनीतिक साधन के समर्थन के लिए सैनिक शक्ति रखनी चाहिए। इस सभी दृष्टियों से कार्यक्रम कूटनीतिज्ञ के शब्दों को जान देता है। प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था में जनमत को भी सरकारी नीति का समर्थक बनाना चाहिए।

तकनीकी तथा कार्यक्रमों को बदली हुई परिस्थितियों के साथ समायोजित करने की योग्यता को भी सफल कूटनीति का एक चिह्न माना जाता है। विश्व के एक भाग में यदि विदेश सहायता का कार्यक्रम सक्रिय है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि विश्व के अन्य भागों में इससे यह नीति अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी। युद्धोत्तर योरोप के लिए मार्शल योजना उपयुक्त थी किन्तु एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीका के देशों को अन्य प्रकार का सहयोग चाहिए। योरोप में नाटो के अधीन एक संगठित सेना का होना ठीक था किन्तु सीएटो में यह प्रक्रिया सम्भव नहीं थी। प्रभावशाली राजनीतिज्ञता वह होती है जो स्थिति व स्थान के अनुसार तकनीकों के चयन में पर्याप्त सावधानी बरतती है।

इन सब बातों के अतिरिक्त एक सफल कूटनीति के लिए राजनीतिज्ञों को भी कुछ गुण विकसित करने होते हैं। जब वह दूसरों से बातें करे तो इस रूप में करे कि जैसे बड़ी प्रतिभा शब्द कह रहा है। उसे अपने हित की साधना धीरज, प्रेम, एवं ज्ञान्ति के साथ करनी चाहिए तथा उसमें अपनी सफलता के प्रति विश्वास होना चाहिए। उसमें यह जानने की क्षमता हो कि वह सौदेबाजी की सीमा को जान सके तथा अपनी कमजोरी को शक्ति में बदल सके। वह अनिश्चय एवं संघर्ष की दुनिया में रहता हुआ भी धीरजयुक्त होना चाहिए। उसे यह मान बर चलना चाहिए कि ये तो विश्व राजनीति की सर्वव्यापी विशेषतायें हैं। उसे यह भी जानना चाहिए कि कब अन्य राज्यों को अपनी सन्धियों तथा नीति के समर्थन में खड़ा करे।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया की धारा होते हैं जिसमें समस्याएँ उठती हैं, समायोजित होती हैं, सुलभनी हैं और उसके बाद नवीन उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ ही समस्याएँ ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से सुलभ हो जायें। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संचालन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि कूटनीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र बिन्दु है

किन्तु फिर भी इसकी सफलता अन्य अनेक तत्वों पर निर्भर करती है जैसे प्राथिक, राजनैतिक एवं सैनिक शक्ति तथा इन शक्तियों का उचित रूप में उपयोग करने की राजनीतिज्ञों की योग्यता एवं क्षमता आदि। लेस्टर पीअर्सन (Lester Pearson) ने उचित ही कहा है कि शक्ति कुशल कूटनीतिक विद्या के बिना प्राप्त की सीधे परस्पर की दीवाल से टकरा सकती है। किन्तु यदि कूटनीति के पीछे शक्ति नहीं है तो यह एक उद्देश्यहीन कसरत मात्र बन जायेगी।

प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध (Propaganda and Political War-fare,

राष्ट्रीय हित के साधन के रूप में प्रचार एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है। इसका दो रूपों में महत्त्व है। प्रथम तो यह कि प्रचार द्वारा राष्ट्रीय हित के अन्य साधन जैसे कूटनीति, प्राथिक साधन, साम्राज्यवाद, युद्ध आदि की अधिक सफलतापूर्वक तथा अधिक प्रभावपूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरे, प्रचार स्वयं में भी इतना शक्तिशाली तथा मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाला है कि बिना इसके शक्तिशाली रूप के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, वह विश्व समाज में एक उच्च स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। भोज के प्रजातन्त्र के युग में भी प्रचार के महत्त्व को बर्दा गुना कर दिया है क्योंकि वर्तमान युग में अपनी नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सक्रिय, सद्भावना प्राप्त करने के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि आप उस देश के शासन के कुछ व्यक्तियों को प्रमत्त करके अपनी घोर कर लें वरन् आज तो प्रचार के समस्त साधनों द्वारा उस देश की जनता को प्रभावित किया जाता है। अपने देश की नीतियों के पक्ष में वहाँ जनमत तैयार किया जाता है तब वही जाकर उस देश की सरकार को अपने पक्ष में लिया जा सकता है। साम्यवादी देशों द्वारा प्रचार के साधन का उपयोग पूरी शक्ति द्वारा किया जाता है। यह स्वभाविक भी है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था को परिध्वस्त करके एक नयी व्यवस्था स्थापित करने वाले देशों को प्रचार के हथियार की अधिक आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि उनका कार्य वस्तुस्थिति को बनाये रखने वालों की अपेक्षा दूना है। एक घोर तो उन्हें यह सिद्ध करना पड़ता है कि वर्तमान स्थिति की क्या बुराइयाँ हैं तथा इसे किस प्रकार बदला जा सकता है घोर दूसरी घोर उन्हें अपनी आदर्श योजना का चित्र भी खींचना होता है। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साम्यवादी देश प्रचार के प्रभावशाली पद्धतियों का प्रयोग करते हैं।

प्रचार के प्रभावशाली यन्त्र कोई मुनिषिचउ नहीं होते वरन् समय की आवश्यकता एवं नवीन आविष्कारों के प्रवाह में उनका प्रभाव एवं महत्व घटता-बढ़ता रहता है। आज के युग में उपाखाना, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, मस्य पत्रिकाएँ, अखबार, चरचिन आदि साधनों को प्रचार के काम में लाया जाता है। साम्यवादी देशों को अपने प्रचार में बड़ी सुविधा रहती है जो एक आन्तर्गुप्तकारी का रहती है। व प्रचार द्वारा स्थित व्यवस्था की कड़ो से कड़ो आत्माचना कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रचार का प्रभाव विश्व के छोटे देशों पर अधिक होता है जो शक्तिहीन तथा कमजोर हैं तथा साम्यवाद का तानत्रिक दानिक उनको बड़ा सुमानना प्रतीत होता है। दूसरी ओर पश्चिमी प्रजातन्त्रों के पास ऐसा कोई प्रभावोन्मादक दानिक नहीं है और उनका साम्राज्यवादी इतिहास भी विश्व के देशों से छिपा नहीं है। इस प्रकार पश्चिमी प्रजातन्त्रों के प्रचार का प्रभाव इतना अधिक नहीं होता। दूसरी ओर साम्यवादी देशों की अपेक्षा इन देशों को प्रचार की इनकी आवश्यकता भी नहीं रहती इनके प्रचार का कवन एक ही लक्ष्य होता है और वह है साम्यवाद के प्रचार का रोकना। अपने प्रचार के यन्त्रों का प्रयोग व कवन साम्यवादी देशों में ही कर सकते हैं क्योंकि साम्यवादी प्रस्था में वह का पर्दा किसी भी साम्यवाद विरोधी विचार एवं प्रक्रिया को आन में लाता है। ऐसी समस्या साम्यवादी देशों के प्रचार मार्ग में नहीं आती।

आज की परिस्थितियों में विश्व का कोई भी देश प्रचार की अवहलना नहीं कर सकता। एक देश चाहे अथवा न चाहे प्रचार का मार्ग उनको अपनाता पड़ेगा, नहीं तो जितने के समय में वह देश विद्रुत जायगा, हो सकता है कि उगना प्रभित्व ही अन्तर में पड़ जाय।

प्रचार का अर्थ एवं परिभाषा

(The meaning and definition of Propaganda)

प्रचार की आवश्यकता देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए तथा विद्वजों में अपनी नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए आज दुनवी बढ़ चुकी है तथा व्यक्तिगत, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में प्रचार इतना आवश्यक हो चुका है कि हमारा अर्थ एवं परिभाषा इन का कोई महत्व नहीं रह जाता। "२०वीं शताब्दी में राष्ट्रीय नीतियों का यह प्रमुख अन्तर्गत बन गया है।" इसके रूप में सम्पूर्ण विभिन्न विचारों व कथनों को दानने में यह स्पष्ट हो जायगा कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार (Propaganda) से

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव डालने वाला प्रचार केवल एक देश की सरकार द्वारा ही किया जाता हो ऐसी बात नहीं है। गैर सरकारी स्रोतों से भी प्रचार के इस रूप का पोषण हो सकता है। अनेक व्यक्ति, व्यापारिक हित, विशेष उद्देश्यों को लेकर बनाये गये असंख्य सगठन इस प्रचार के कार्य में सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। विभिन्न राजनैतिक दल दूसरे देशों में प्रचार द्वारा अपने राष्ट्र के हित के लिए समर्थन प्राप्त करते हैं। समय के अनुसार प्रचार के नये-नये साधनों का विकास होता रहता है।

प्रचार के उद्देश्यों पर यदि हम विचार करें तो पायेंगे कि मूल रूप में सभी प्रचार सम्बन्धी कृत्य राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर ही क्रियान्वित किये जाते हैं। ऐसा अनेक रूपों में हो सकता है। उदाहरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते जिस समय होते हैं उनको अपने हित में मोड़ने के लिए एक देश प्रचार का सहारा ले सकता है। दूसरे, किसी समस्या या विशेष प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई सम्मेलन बुलाने के उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए भी प्रचार का सहारा ले सकता है। तीसरे, प्रचार के द्वारा विचार-धारा का प्रसार भी किया जाता है। एक देश के राजनीतिज्ञ सदैव इस बात में प्रयत्नशील रहते हैं कि जिस विचारधारा पर उनका देश आरुढ़ है उसी को दूसरे देश भी मानें, क्योंकि मंत्री एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का दृढ़ आधार विचारों की एकता होती है। चौथे, प्रचार का सहारा अपनी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नीतियों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। प्रचार का महत्व युद्ध से पूर्व एवं युद्ध के दौरान बहुत बढ़ जाता है। शांतिकाल की भांति सकटकाल एवं युद्धकाल में भी प्रचार द्वारा विभिन्न तरीके अपना कर राष्ट्रीय हित की साधना की जाती है। कूटनीति और युद्ध के बीच में जो सम्पूर्ण स्थिति रहती है उसमें दो देशों के बीच बड़े बदलावपूर्ण सम्भव रहते हैं। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर विषममत बिना जाता है। दूसरे को गलत ठहरा कर अपनी नीति का औचित्य प्रस्तुत किया जाता है। इस स्थिति को राजनैतिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक राज्य के सामने ऐसे अवसर आते हैं जबकि वह दूसरे राज्यों पर प्रभाव डाल सके। यह प्रभाव धन्य भी हो सकता है और बुरा भी। इन अवसरों पर प्रचार का सहारा लिया जाता है। प्रचार द्वारा व भी हमें राजनैतिक युद्ध (Political warfare) की भी स्थिति पेश कर दी जाती है किन्तु, जैसा कि पामर तथा परकिन्स का कहना है, इन दोनों के बीच अमिन्नता का सम्बन्ध नहीं है। प्रचार का प्रयोग करने पर आवश्यक नहीं कि राजनैतिक युद्ध (Political warfare) की ही स्थिति पैदा हो जाय तथा राजनैतिक युद्ध भी

प्रचार का रूप ले घीर नहीं भी लें, दोनों ही बातें सम्भव हैं। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का इतिहास हमें बतलाता है कि प्रचार के माध्यम से युद्ध के परिणामों को भी बदला जा सकता है।

प्रचार के तरीके (Techniques and methods of propaganda)

अन्तराष्ट्रीय राजनीति में भी प्रचार के वे ही तरीके हैं जो व्यापार में विज्ञापन करते समय अपनाये जाने हैं। विज्ञापनबाजी में लोगों की रुचि का तथा भाग का भारी खयाल रखना पड़ता है। लोगों के मनोविज्ञान का काफी ध्यान रखा जाता है। प्रचार की विधि अपनाते समय यह सदैव भ्रमिष्ठ में रहता है कि लोगों की इच्छायें, भय तथा कमजोरियाँ क्या होती हैं। इन सब के अनुकूल ही फिर नीति तैयार की जाती है। प्रचार करने की विधियाँ भयदा तरीके अनेक होती हैं। हार्टर तथा सुलिवान (Harter and Sullivan) महोदय ने प्रचार के तरीकों की सरया बारह बताई है। इन सभी तरीकों को पामर तथा परकिन्स न चार शीर्षकों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार प्रचार की विधियाँ निम्न प्रकार हैं—

१. प्रस्तुत करने की विधि (Method of Presentation)
२. ध्यान ग्रहण करने की युक्ति (Techniques for gaining attention)
३. उत्तर प्राप्त करने की युक्ति (Devices for gaining response)
४. स्वीकृति पाने के साधन (Methods of gaining acceptance)

उक्त चारों विधियों को अपना कर एक दश द्वारा प्रचार की मशीन का उपयोग किया जाता है।

प्रस्तुत करने की विधि

पहली विधि के अनुसार प्रचारकर्ता देव एक समस्या को प्रस्तुत करते समय उठाया पूरा विवरण नहीं देता, वह केवल उसी पक्ष का दिग्दर्शन करता है जो उसके हित में होता है। उदाहरण के लिये भारत पाँच सप्ते के समय किये जाने वाले पाकिस्तानी प्रचार को लिया जा सकता है। काश्मीर समस्या के बारे में पाकिस्तानी अखबार तथा अन्य अफिकारी साठों से बराबर यही प्रचार किया जाता रहा कि काश्मीर पाकिस्तान का अङ्ग है क्योंकि वहाँ

की जनता मुसलमान है और वहाँ के जनमत की मांग है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, काश्मीर समस्या पर युद्ध छेड़ने का उत्तरदायित्व भारत का है न कि पाकिस्तान का घ-दि-आदि। इन बयानों के प्रमाणस्वरूप बहुत सी ऐसी घटनाएँ व निष्कर्षों का हथका दिया जाता है जो यदि सही रूप में रखी जायें तो पाकिस्तान के दावे के विपरीत जायें किन्तु उनका तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक उस धरती की तरह से जो अपने पक्ष के समर्थन के लिये किसी तथ्य के पूर्ण रूप को देखने की अपेक्षा कमकम मात्रा का ही देखना है। कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन जिन दिनों बकान्त करते थे एक व्याघ्राघात ने उनके तर्कों पर एतराज किया और कहा 'मि० लिंकन इस समय आप जो बातें दे रहे हैं वे आपके द्वारा ही एक दूसरे के समक्ष रख दिये हुए तर्कों के विपरीत हैं।' इस पर लिंकन का उत्तर था 'माई ताई, हो सकता है कि मैं न बल को तर्क दिये वे वो गान हो किन्तु मेरे ये तर्क पूर्णतः सत्य हैं।' प्रत्येक प्रकार का अब्राहम लिंकन के इस उत्तर को ध्यान में रख कर ही अपना कार्य करता है। वह उन सभी तथ्यों को टिप्पणी लेता है जो उनके मामले के विपरीत जायें हो। काश्मीर का पाकिस्तान जिन कारणों से हथियाना चाहता है उनका न बल कर वह केवल धर्म का ही आश्रय लेता है।

आश्विन सत्र से पूर्ण प्रकार द्वारा जमनी में विस्मार्क तथा हिटलर ने कई बार अपने उद्देश्यों को बड़ी सकलतापूर्वक प्राप्ति कर लिया था। इन प्रकार प्रकार के भी कई रूप हो सकते हैं, उदाहरण के लिए—

✓ १. भूतकाल के किसी तथ्य को, जो अथवा किसी भी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, आप इस तरह से तोड़-मरोड़ सकते हैं कि वह मान्य समझ में आये कि जिसके अनुसार परिणाम उसमें प्राप्ति प्राप्त हो गये।

✓ २. प्रकार से ऐसी घटनाओं एवं प्रमाणों का अपने पक्ष में समर्थन के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसका उद्देश्य बुरा और ही होता है किन्तु आप उससे अपना उल्लू मीठा कर लेता है। उदाहरण के लिए हिटलर यहूदियों के विरुद्ध जर्मनी में रोष मड़काना चाहता था। उसने अपनी कहानियाँ तथा पुस्तकें प्रस्तुत कीं और उनके आधार पर यह मित्र करने की चेष्टा की कि यहूदी लोग पूरे विश्व पर राज्य करने की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार का तत्काल परिणाम हुआ। यहूदियों के प्रति जर्मनी में रोष की अग्नि मड़क उठी।

३. प्रचार करते समय झूठ और धाँसे का भाग दियाना बिल्कुल साना-गोही या अर्थाविहारवादी दायरा का दायित्वकारी है, वह दूर प्रभाव कहें जायें जल-राष्ट्रा द्वारा भी प्रयोग में आना जा सकता है। किन्तु दानों व्यवस्था द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रचार एक जो मोट्टी का गी नही जा सकता उन दानों के बावजूद उद्देश्य का अन्तर रहता है। प्रजातन्त्रात्मक देशों का प्रचार सानागोही दायरा की तुलना में अधिक उद्देश्य के नियंत्रित जायगा, जो प्रचार की जाना है। वेस व्यवस्था को प्रत्येक माध्यम से नियंत्रित हो जाते हैं। प्रचार में का दान पर एक प्रकार की अर्थव्यवस्था का पूरा भी नहीं कहा जा सकता। मर्यादायुक्त के समय प्रचार का भाग के भाग के अन्तर्गत समाचार का भाग व्यवस्था में अन्तर्गत प्रचार दिया गया था जिसको उद्देश्य की दृष्टि से नहीं कहा जा सकता और नागरिक का समर्थन प्राप्त हुआ।

४. घटनाओं के समय हम को भी प्रचार का विषय बनना जाना है और यह भी सम्भव है कि ऐसा प्रचार वास्तविक प्रभावकारी सिद्ध हो। जर्मनी के सन्धि के समय में प्रचारवादी विचारवादी एवं अन्य नेताओं द्वारा आन्तरीय को चीन और पाकिस्तान के सिद्ध साधन रहने की चेष्टा की जाती है। प्रचारवादी ने यह वातावरण दुर्लभ किया है कि सन्धि अभी टूटा नहीं है, मित्राचारों के कारण हमारा यह युद्ध एक लम्बे समय तक चल सकता है। यह प्रचार सत्य है और नागरिकों के रुकने की भी कोशिश में नाराज होता है। व. उ. जर्मनी ने भी प्रचारवादी का सहन करने के लिए तैयार है जो इस सन्धि को उलट है।

५. शायद झूठी और मर्यादायुक्त घटनाओं को युद्ध का कारण बना दिया जाता है। जर्मन पाक युद्ध के दौरान साम्यवाद चीन के भारत पर नई युग के गैर-महत्वपूर्ण और मई आगे के तथ्य और युद्ध आचार्य बनाने का प्रयत्न किया कि वह जब चाहे नव भारत पर हमला कर सके। हमला करने का विचार तो उभरा पड़ना बनाया और बाद में इन कटाक्षों घटनाओं को सारा दायित्व को नियंत्रित करने के लिए प्रचार का विषय बना दिया।

ध्यान रखने की सुविधा

दूसरी विधि—यह विचार की प्रक्रिया की प्रतीति सीढ़ी है। जब प्रचार के मन्त्रिण में एक निश्चित सत्य निर्धारित हो जाता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वह विभिन्न साधन अपनाया प्रारम्भ करता है ताकि हमारे दायरा का ध्यान भी उसका और प्रभावित किया जा सके। अपने प्रचार-

रिजि हिंसा पर दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक देश द्वारा जो साधन अपनाये जाते हैं वे मुख्यतः निम्न प्रकार हैं—

(१) सरकारी प्रयत्न (Official devices)—दूसरे देश की सरकार के लिए समय-समय पर नोट्स (Notes) भेजे जाते हैं, विरोध प्रकट किया जाता है व राजनीतिज्ञों एवं नेताओं द्वारा दिये गये भाषण भेजे जाते हैं। भारत-चीन संघर्ष एवं भारत-पाक युद्ध के दौरान विरोध-पत्रों का प्रादान-प्रदान एक सामान्य बात बन गई थी।

(२) शक्ति का प्रदर्शन (Power demonstration)—पानी मांगो तथा हिंसा की ओर दूसरे देशों का ध्यान आकर्षित करने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि एक देश अपनी शक्ति बढ़ा के तथा उसका प्रदर्शन करता फिरे, जल, धूल, तम सेना की पूरी तैयारी करने पर एक देश की ओर विश्व सशक्त दृष्टि से देखने लगेगा। प्रचार के इसी तरीके को अपना कर साम्यवादी चीन ने अक्टूबर १९६८ में प्रणुबम का विस्फोट किया ताकि सम्पूर्ण एशिया और अफ्रीका का नेतृत्व कर वह विश्व की महाशक्ति में स्थान पा सके।

(३) सांस्कृतिक कार्यक्रम (Cultural programme)—सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा एक देश की जनता को अपने पक्ष में किया जा सकता है। विभिन्न देशों के दूतावातों के द्वारा यह प्रवन्ध किया जाता है कि विभिन्न तरीकों द्वारा उनके देश की संस्कृति, रहन सहन, साहित्य, परम्पराएँ आदि से विदेशों को परिचित कराया जाये।

(४) राजनैतिक दौरे (Political visits)—विदेशों से मित्रता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन, जो अब पर्याप्त लोकप्रिय बनता जा रहा है, सरकार के अध्यक्षों के दौरे हैं। एक देश का नेता जब दूसरे देश में सद्भावना यात्रा के लिए जाता है तो उस देश की जनता और नेता दोनों के ऊपर बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भारत को पाकिस्तानी आक्रमण के समय मित्रों की आवश्यकता पड़ी। जिनसे उसे आशायी भी वे पूर्ण न हो सकी। विदेश नीति पर पुनर्विचार के लिए दबाव डाला जाने लगा। इस सच का परिणाम यह हुआ कि नेताओं एवं राजनीतिज्ञों की विदेश यात्राओं की संख्या बड़ी गुनी हो गई। २१ दिन तक नेपाल के महाराज सपरिवार भारत में रहेगे, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि भारत-नेपाल भीरी हठ हो जायगी। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री स्वर्ण-सिंह, प्रधानमंत्री श्री शस्त्री, राष्ट्रपति राधाकृष्णन् आदि नेताओं की विदेश

(२) प्रतीकों का प्रचलन (Symbolic devices)—नारों की भाँति प्रतीक भी मनुष्य की भावनाओं को प्रभावित करने में बहुत सफल रहते हैं। प्रत्येक देश द्वारा चित्र, जानवर, संकेत, राष्ट्रगीत, झंडा एवं अनेक प्रकार के प्रतीकों का उपयोग देशवासियों में भावनात्मक एकता लाने एवं राष्ट्रीय नीतियों का समर्थन कराने के लिए किया जाता है। वर्तमान काल में प्रतीकों के रूप में स्वस्तिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जर्मनी में हिटलर ने इसे नाज़ी पार्टी का चिन्ह बना दिया। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार स्वस्तिक का स्वाभाविक अर्थ (Intrinsic meaning) न तो नाज़ी पार्टी के लिए ही कुछ था और न उन दूसरे देशों के लिए ही जिन्होंने इसे बाद में अपनाया। इसे अपनाने का कारण केवल इसकी सरलता थी। साधारण एवं सरल होन के कारण इसे वही भी चित्रित किया जा सकता था। इस कथन में आशिर्य सत्य है। पहला बात तो यह है कि इससे भी सरल 'क्रास' जब मौजूद था तो 'स्वस्तिक' को क्यों अपनाया गया जो अपेक्षाकृत टेढ़ा है। दूसरे स्वस्तिक का कोई आन्तरिक मूल्य (Intrinsic value) नहीं है। यह कथन भारतीय संस्कृति की अनभिज्ञता का द्योतक है। भारत में स्वस्तिक को एक अर्थ के साथ अपनाया गया था।

(३) विचारों का वैयक्तिकरण (Personification of Ideas)—विचारों के साथ व्यक्ति को एकाकार कर दिया जाता है। एक व्यक्ति जब यह कहता है कि वह महात्मा गांधी का अनुयायी है तो तुरन्त ही हमारा मतिष्क यह स्वीकार कर लेता है कि उस व्यक्ति में साति, अहिंसा और सत्य आदि गुणों के प्रति श्रद्धा है। असहमता की विदेश नीति (Nonaligned foreign policy) का प्रसंग छिड़ते ही हमारे मानस-पटल पर स्वर्गीय प० नेहरू का चित्र उभर आता है। व्यक्ति को प्रायः उस देश के साथ भी एकाकार कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने के पीछे यही भावना है।—

(४) परिस्थिति और दृष्टिकोणों का उपयोग (Utilization of situations and attitudes)—जिस प्रकार एक कुशल रूपक बनी होना है जो वातावरण, जलवायु और भूमि के अनुकूल ही बीज आरोपित करता है उसी प्रकार एक सफल प्रचारक वह माना जायेगा जो स्थित परिस्थितियों और दृष्टिकोणों का लाभ उठा कर उन्हें अपने हित में मोड़ ले और प्रचारित करे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में सुरक्षा और आर्थिक संकट की जो स्थिति पैदा हुई उसके कारण वहाँ के लोग हिटलर की तानाशाही को स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। साम्यवादी चीन ने भारत विरोधी

प्रचार करके पाकिस्तान की नीती प्राप्त कर ली। चीन-पाकिस्तान के इस गठजुटन की जड़ें काश्मीर समस्या पर टिकी हुई हैं। इस प्रकार पामर तथा पाकिस्तान के मन में "प्रत्येक प्रचारक स्थित दृष्टिकोणों से लाभ उठा कर उम्ह ऐसी दिशा में भाँड़ने का प्रयास करता है जिससे कि उसका हित साधन हो सके।"

स्वीकृति पाने के साधन

प्रचार प्रक्रिया की चौथी एवं अन्तिम सीढ़ी अपने प्रचारित तथ्यों पर स्वीकृति प्राप्त करने की है। प्रचारक द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जिनके द्वारा दूसरे देश उनकी नीतियों की स्वीकृति प्रदान करें। अपनी योजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यह मानसपर है कि प्रचार के विषय एवं धम्मे के बीच का भेद मिटा दिया जाये। आपका प्रचार तब तक महत्वहीन रहेगा जब तक कि उन लोगों के साथ घाय एककार न हो जाओ जिनमें प्रचार करना चाहते हैं। इस तथ्य की महत्ता गांधी ने बड़ी अग्रणी प्रकार समझाया। उन्होंने देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच उनकी ही बड़ी खाई है जिसकी नि एक भारतीय और अंग्रेज के बीच थी। फलतः उन्होंने अपने रहन-सहन के उन में भारती बरती, खान-पान बदला, सारे ऊपरी आडम्बर जो आदमी-आदमी के बीच भेदभाव बसा देते हैं, गांधीजी ने धाँड़ दिये। यही कारण है कि वे जनता के एक मजबूत सहयोगी नेता बनने में सफल हो सके। भारतीयानी उनकी बात पर जान देने को तैयार हो जाते थे।

प्रचार पर स्वीकृति प्राप्त करने का दूसरा तरीका है धर्म और जाति को प्रभावित करना। मनोवैज्ञानिक रूप से यह सच है कि यदि व्यक्ति धर्म में और धर्म शास्त्र में समानता देखने ला जाये तो आपसे लिए सब कुछ करने का तैयार हो जायेगा। यह समानता धर्म और जाति के नाम पर भी स्थापित की जा सकती है। भारत पाकिस्तान मुक्त के दौरान पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों में सहायता प्राप्त करने की कोशिशें की थी। वहीं भारत देश उनसे प्रचार के प्रभाव में भारत विद्रोह का समर्थन करने की आगे आये नी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धर्म जाति के बहाने का पाठ पड़ा कर हिटलर ने जर्मनी की अपने प्रचार से बलीभूत कर लिया था।

प्रचार की प्रभावकारी बनाने के लिए एक तीसरा तरीका धरनाते समय धर्म की दुहाई दी जानी है। ईश्वर के नाम पर आज तक धर्म के मुक्त सब गये हैं। भारत पर हानि वाले प्राचीन मुस्लिम शासकों के पीछे धर्म

प्रचार की भावनाये थीं। मुस्लिम धर्म का प्रचार करते समय मोहम्मद साहब की भावाज पर प्रारम्भ में किसी ने ध्यान न दिया किन्तु जब उन्होंने यह कहना शुरू किया कि वे ईश्वर के पैगम्बर हैं और जो कुछ भी वे कह रहे हैं वह ईश्वर का आदेश है तो लोगो ने उनका अनुगमन किया। ईश्वर की भाति न्याय और इतिहास का सहारा लेकर भी प्रचार को प्रभावशाली बनाया जाता है। इन तरीको से प्रचार सर्वमान्य बन जाता है।

ऊपर जो प्रचार की प्रक्रिया के विभिन्न स्तर वर्णित किये गये हैं उनके सम्बन्ध में विधायी कदम लेने से प्रचार को सफल बनाया जा सकता है। किन्तु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक प्रचार को उसके विरोधी प्रचार का भी सामना करना पड़ता है। विरोधी प्रचार भी एक प्रति-द्वन्दी के रूप में दूसरे का ध्यान आकर्षित करने, उत्तर प्राप्त करने एवं उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का हर सम्भव प्रयास करेगा। प्रचार पर सरकार का नियन्त्रण रहता है, ऐसा किये बिना कोई भी शासन सफल रूप से कार्य नहीं कर सकता, किन्तु इस नियन्त्रण के रहते हुए भी एक देश की जनता बाकी विश्व के प्रचार के प्रभावों से पूर्णतः भ्रष्ट नहीं रह सकती।

प्रचार के क्षेत्र में प्रतिद्वन्दिता बहुत रहती है। इसलिए प्रचार-प्रक्रिया में एक तरफ यह भी मिलाना पड़ता है—कि विरोधी प्रचार का खण्डन किया जाय। विरोधी का खण्डन करते समय उसके विपरीत तरह-तरह के नारों का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिये उन सभी कथनों को ले सकते हैं जो पश्चिमी प्रजातन्त्र साम्यवादी देशों के लिए तथा साम्यवादी देश पश्चिमी प्रजातन्त्रों के लिए प्रयुक्त करते हैं। पामर तथा परकिन्स के कथनानुसार "यह एक आवश्यक तथ्य है कि प्रायः प्रत्येक प्रचार की प्रभावशीलता को रोकने के लिए उसका प्रतियोगी रहता है।"

विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ प्रचार के नये नये साधनों का प्रचलन होता जाता है। प्रचार की प्रक्रियाएँ एवं विधियाँ भी समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती हैं। यह तथ्य प्रचार के इतिहास पर एक विहङ्गम दृष्टि डालने से स्पष्ट हो सकता है। यहाँ हम वर्तमान विश्व की दो महान शक्तियों के प्रचार की पद्धतियों को इतिहास के सदम में देखने का प्रयास करेंगे।

प्रभावशाली प्रचार की आवश्यकताएँ (The Requisites for Effective Propaganda)

प्रभावशील प्रचार के लिए कई बातें जरूरी होती हैं जैसे उसकी सरलता, रुचि उपयुक्तता, धादि। प्रचारक को धरना विशेष उद्देश्य प्रभाव-

शील रूप से प्रचारित करने के लिए समाज शास्त्र, मनोविज्ञान एवं सामूहिक विनयण, आदि का महारा लेना होता है। यह प्रभावशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विभिन्न माध्यमों द्वारा एक बात को कई बार सुदराया जाय ताकि श्रोतागण उसे भली प्रकार सुन सकें। श्रोताओं पर प्रभाव डालने के लिए प्रचारित विषय को देखने, सुनने और पढ़ने योग्य बनाया जाय। यह सब बातें एक प्रचार कार्य को प्रभावशील बना देती हैं।

प्रचार कार्य की वस्तुगतता (The Objectivity of Propaganda).—प्रचार करने का एक सरल तरीका यह है कि सबसे तथा सूचनाओं को यथासम्भव वस्तुगत तथा तथ्यगत रूप से प्रस्तुत किया जाय और श्रोता घबरा पाऊँगे की स्वयं ही अपने निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। सीधे और बिना मिलावट की सूचना राजनैतिक दृष्टि से प्रभावशील होती है। इसका प्रभाव उस समय और भी अधिक होता है जबकि यह उन सर्वाधिकारी राज्यों पर प्रभाव डालती है जो सूचना को नियन्त्रित करते हैं। वस्तुगत एवं तथ्यगत सूचना का साम यह है कि श्रोता उसे यह जानने के लिए सुनना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी सब्रें प्राप्त की हैं उनमें सत्यता का कितना भग है। वैसे पूर्ण वस्तुगतता तो प्रायः प्राप्त नहीं हो पाती। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी बी. सी. की वस्तुगतता के लिए पर्याप्त सौकरिमता प्राप्त हो गई थी।

बड़ा झूठ और उसका दोहराव (Big Lie and its Repetition).—प्रचार कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए एक अन्य तकनीक यह है कि कोई बड़ा झूठ बाला जाय और उस झूठ को बार-बार दोहराया जाय। इस तकनीकी को ऐडाल्फ हिटलर द्वारा पर्याप्त प्रयुक्त किया जाता था। हिटलर का विश्वास था कि यदि एक बहुत बड़ी झूठ को बार-बार दोहराया जाता है तो वह जनता का विश्वास प्राप्त कर लेती है। अधिकांश जनता में यह समझने की कल्पना नहीं होती कि बार-बार दोहराए जाने वाले कथन पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। इस तकनीकी को प्रभावशील बनाने के लिए विभिन्न सोलों पर नियन्त्रण रखना जरूरी है ताकि परस्पर विरोधी बातें सामन न आयें। छोटे स्तर की झूठ कम सामंदायक होती है और इससे खतरा देने वाले की विश्वसनीयता जानी रहती है।

सरलता (Simplicity).—जनता के मस्तिष्क पर सीधे गाँढ़े नारों का सर्वाधिक प्रभाव होता है। वह विभिन्न राजनैतिक एवं आर्थिक विचार-पाराओं के सुलनामक गुराओं के सम्बन्ध में तब किनके सुनने की प्रवेष्टा सरल

नारे सुनना अधिक पसन्द करती है। जैसे—‘सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण’ ‘बम पर रोक लगाओ’ तथा पूँजीवादी साम्राज्यवादी आदि। हंगरी के ‘स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों की प्रशंसा की गई।’ इसी प्रकार आज के अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में स्वतन्त्र विश्व (Free world) और शीत युद्ध (Cold war) पर्याप्त सामान्य शब्द बन गए हैं।

रुचि, एव, आकर्षण (Interest and Attraction)—प्रचार उस समय तक प्रभावहीन रहता है जब तक कि वह सुनने वालों को रुचिकर न लगे। एशिया और अफ्रीका के जिन देशों का सम्बन्ध आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय निर्माण से है और जब संयुक्त राज्य अमरीका वहाँ साम्यवाद को रोकने पर जोर देता है तो इन देशों का ध्यान नहीं जाता। यह एक मनो-वैज्ञानिक तथ्य है कि लोग उस विषय में रुचि लेते हैं जो उनसे सम्बन्ध रखता है। किसी विषय पर लोगों की रुचि उनकी ही कम हो जाती है जितना कि वह उनसे दूर है। संयुक्त राज्य अमरीका के सूचना अभियंत्रण ने एक प्रकाशन द्वारा अफ्रीका के सम्बन्ध में अमरीकी इन्स्टीट्यूट को प्रस्तुत किया है। इसमें जो लेख हैं वे अफ्रीका से सम्बन्ध रखते हैं और अफ्रीकी पाठकों को यह अनुभूति देते हैं कि अमरीका उनके मामलों में रुचि लेता है। प्रचार कार्य को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शारीरिक प्रदर्शन एवं दृश्य प्रभाव भी महत्वपूर्ण रूप से असर डालते हैं।

स्पष्टता एवं प्रामाणिकता (Clarity and Factuality)—एक वार्ता का प्रभाव कबल तभी हो पाता है जबकि वह सरलतापूर्वक सुनने वालों की समझ में आ जाय। यदि प्रचार का विषय बनावटी है या मृष्टी प्रकृति का है तो उससे वांछित लक्ष्य नहीं मिल सकता। प्रचार को दीर्घकालीन रूप में नीति के साथ संयुक्त होना चाहिए। किसी भी प्रचार पर तब विश्वास किया जाना है जबकि उसका अनुसार कार्य भी किया जाय। जब सोवियत रुस द्वारा अन्तरिक्ष में उपग्रह छोड़ा गया तो यह प्रभावशाली प्रचार का साधन बना; क्योंकि एक तो यह एक विशेष प्राप्ति थी और दूसरे दुनिया के असह्य लोग इस उपग्रह को अपनी आँखों में देख सकते थे। प्रथम शान्ति के कारण सोवियत सच का पर्याप्त मान हुआ। कुछ दिन पूर्व मुक्त ब्रह्म पर उठरने वाले सोवियत यान ने उसे भारी प्रतिष्ठा प्रदान की है।

संयुक्त राज्य अमरीका ने जब यह प्रचार किया कि वह यूरोप में रुचि रखता है, इसके सहित अमरीकी सैनिक शक्ति पश्चिमी यूरोप में रखी गई। सोवियत सच द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका के सहायता कार्यों की आलोचना

की जाती है किन्तु वह स्वयं ऐसे रूप में सहायता प्रदान करता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके और इस प्रकार इसे वह प्रचार का एक साधन बना देता है।

स्थानीय अनुभवों एवं दृष्टिकोणों से समरूपता (Identification with Local Experiences and outlook)—प्रचार कार्य लोगों का अपनी ओर ध्यान ही आकर्षित नहीं करना चाहता बल्कि उनकी प्रतिक्रिया भी चाहता है। प्रचारक जिनकी प्रभावित करना चाहता है उनकी स्थानीय रुचियों, अनुभवों एवं दृष्टिकोणों का ध्यान रख कर अपने और उनके बीच की दूरी को मिटाता है। एक प्रभावशाली प्रचारक यह होता है कि जो सामान्य विशेषताओं और सामान्य रुचियों पर जोर देता है। नात्रो जर्मनी द्वारा प्रायः जाति का नाम लेकर और साम्प्रदायी रुम द्वारा विकासशील देशों को एमता का नाम लेकर इसी तकनीकी को अपनाया जाता है। जहाँ इस प्रकार की एक-रूपता प्रभावशाली रूप से स्थापित नहीं की जाती वहाँ प्रचार कार्य समफल हो जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जो साम्प्रदाय विरोधी भावनाएँ फैलाई जाती हैं उनका प्रभाव कम होता है क्योंकि दूसरे लोग उनमें विश्वास नहीं करते। पहले संयुक्त राज्य अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन यह सोचा करते थे कि साम्प्रदायी प्रचार इन देशों को साम्प्रदायी और एकाधिकार पूर्ण पूँजीवादी यह कर एक मरे घोड़े की पीटता है, किन्तु ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार का अपना साम है क्योंकि जिन विकासशील देशों में पश्चिमी प्रभावों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं, वहाँ इस प्रकार की व्याख्याएँ प्रभावशाली सिद्ध होती हैं। इस प्रकार के प्रचार की अनेक बातें बड़ी सरल और सीधे समझने योग्य हैं जैसे कम मजदूरी तथा बड़ी विदेशी पूँजी आदि। किसी भी प्रभावशाली प्रचार का मापदण्ड यह नहीं है कि उसमें सभी विश्वास करते हैं या नहीं करते, बल्कि यह है कि उनके लिए विश्ववर्गीय हैं प्रयत्न नहीं करने लिए कि यह वांछित परिणाम प्राप्त करने के हेतु किया जा रहा है।

स्थिरता (Consistency)—बैसे प्रचार कार्य की हमें एक जैसा रहन की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु फिर भी जब विशेष योजनाओं पर किसी विशेष समस्या के सम्बन्ध में प्रचार किया जा रहा है तो एकमतता न रहने पर अनेक समस्याएँ उत्पन्न होंगी। जोसेफ फ्रांकेल (Joseph Frankel) का यह कहना उपयुक्त है कि 'प्रचार की प्रभावशीलता उसकी निरन्तरता एवं स्थिरता के कारण बहुत बड़ जाती है। माप ही सूचना के प्रति-योगी साधनों को समाप्त कर देना भी उपयोगी रहता है।' आर्थर ओर

(Arthur Krock) ने बताया है कि, एक प्रजातन्त्रात्मक सरकार को अपना प्रचार प्रभावशील बनाने के लिए, वास्तविक कार्यों से, अपने कथनों की सत्यता सिद्ध करनी चाहिए। प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनी असफलताओं को नहीं छिपा सकती। दूसरी ओर स्वेच्छाचारी सरकार अपनी असफलताओं तथा असंगतियों को छिपा सकती है और छिपाती है। इस प्रकार की सरकारों का प्रचार उनके कार्यों से असंगत होता है और रातों-रात उल्टा बन सकता है।

सूचना और प्रचार के रूप (The Types of Information and Propaganda)

प्रचार कार्यक्रम के सत्य भयेवा उद्देश्य अनेक होते हैं और ये कर्तों के उद्देश्य के आधार पर समय-समय पर बदलते रहते हैं। प्रचार भयेवा सूचना के उद्देश्य को देख कर ही उसका रूप भी निश्चित किया जाता है। प्रचार के विभिन्न रूपों एवं प्रकारों में से कुछ को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है।

(१) खबर एवं सूचना (News and Information)—इस प्रकार का अधिकांश प्रचार खबर देने के अलावा और कुछ नहीं करता तथा सुनने वाले की स्वयं ही निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए आमन्त्रित करता है। यह दृष्टिकोण राजनैतिक संचार में आगल अमरीकी प्रयासों की विशेषता है। द्वितीय विश्व के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका ने जो प्रचार की नीति अपनाई उसे सत्य की रणनीति (Strategy of truth) कहा जाता है। आज का संयुक्त राज्य अमरीका का सूचना अभिकरण दूसरों देशों की जनता को प्रभावित करने के लिए और विदेशों में संयुक्त राज्य का स्थाका खींचने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में तथ्यों एवं स्पष्टीकरणों का प्रयोग करता है। जब मि० कार्ल रोवन (Carl Rowan) का यू० एस० आई० ए० का सचालक बनाया गया तो राष्ट्रपति जानसन ने उनसे कहा कि “सच कहिए” इस पर मि० रावन ने उत्तर दिया कि “मि० राष्ट्रपति केवल यही तो बंध चीज है जिसे मैं जानता हूँ।” इसी प्रकार संयुक्त राज्य के देशों में किये जाने वाले अपने प्रसारणों में धी० बी० सी० भी इन सिद्धांतों को अपनाता है। सत्य प्रतिवेदन भयेवा समाचार के आधार पर एक प्रचार यंत्र श्रोताओं का विश्वास प्राप्त कर लेता है और यह एक बड़ी उपलब्धि है।

(२) घनन द्वारा तथ्यों की मोड़ना (To distort the Facts through Election)—जब एक देश विदेशी जनमत को एक विशेष रूप

देना चाहता है तो वह तथ्यों को, छोड़, सरोह, कर उसके सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की संचार व्यवस्था में ईमानदारी जैसी चीज नहीं रहती और एक कोशिश की दृष्टि में कभी भी झूठ को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार प्रचार के दो मार्ग दिखाई देते हैं। एक मार्ग यह है कि झूठे तथ्यों को सामने लाया जाए और दूसरा मार्ग यह है कि झूठे तथ्यों को प्रचारित किया जाए। इन दोनों के बीच का भी एक मार्ग होता है और वह यह है कि झूठ ता न बोली जाए लेकिन कुछ तथ्यों को छिपा लिया जाए ताकि लोग सत्य को समझ न सकें। इस मार्ग को अपना कर प्रचारक उन तथ्यों पर पर्याप्त जोर देता है जो सत्य तो हैं किन्तु उसके पक्ष में हैं। दूसरी ओर वह उन तथ्यों की ओर से श्रोताओं का ध्यान हटा देता है जो सत्य होते हुए भी उसके पक्ष में नहीं हैं। इस प्रचारक द्वारा भावनात्मक व्याख्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रचार में प्रचारक यह सिद्ध करता है कि वह स्वयं निरपराध है और जो भी गलती की गई है वह सब विरोधी द्वारा की गई है। दोनों पक्ष अपने प्रति प्रेम की दुहाई देते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि उन्होंने इस प्रेम के निर्वाह में क्या बलिदान किया और दूसरे पक्ष ने उन पर क्या प्रशंसा की। इस प्रकार के प्रचार में तथ्यों की जानकारी का कार्य सुनने वाले के मस्तिष्क पर छोड़ दिया जाता है। एक पक्ष द्वारा जो दूसरे पक्ष की तस्वीर खींची गई है यदि वह उस तस्वीर को मिटा कर दूसरी नहीं बना सकता तो निश्चय ही वह भाग्यशाली या साम्राज्यवादी समझा जायेगा। इस प्रकार का प्रचार विदेशों में दृष्टिकोणों को ढालने के लिए तथा दूसरों पर दबाव डालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रचार के इस रूप में तथ्यों को प्रयत्न तथ्यों से मिलती जुलती चीजों की बन्ध बिन्दु बनाया जाता है और अपने स्वार्थ की दृष्टि से उसकी व्याख्या की जाती है।

(३) आध्यात्मिक प्रचार (Covert Propaganda)—कभी-कभी प्रचार कार्य में ऐसे साधन प्रयुक्त होते हैं जो अदृश्य एवं दृष्टि से अज्ञेय होते हैं। अनेक देश ऐसा करते हैं कि वे अन्य राज्यों के समाचार पत्रों एवं प्रकाशनों को खरीद लेते हैं तथा उनसे पक्षपात पूर्ण तथा झूठमूठ की बहानियाँ प्रकाशित कराते हैं जो स्वयं उनसे स्वयं के ही हित में होती हैं। जनता की भावनाओं एवं प्रतिभूतियों को बदलने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में विशेष रूप से संचार की गई फिल्में बाँटी जाती हैं। इन फिल्मों के मूल निर्माता एवं प्रसारक का नाम बाहिर नहीं किया जाता।

ऐसी विदेशनीति अपनाने के लिए दबाव डालती थी जो सोवियत रूस के अनुकूल हो। १९३५ के ब्राड योरोपीय देशों के साम्यवादी दलों ने मास्को के निर्देशन पर ही नाजी जर्मनी के विरुद्ध उदारवादी समुदायों से सहयोग करना पसन्द किया था।

द्वितीय विश्व युद्ध की उत्तरकाल—द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत रूस के प्रचार के लक्ष्य एवं प्रक्रिया में पर्याप्त अन्तर आ गया। इसका क्षेत्र केवल राष्ट्रीय न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय अधिक बन गया। इसका प्रयोग शीत युद्ध की बनाये रखने के लिए किया गया। पामर तथा परकिम्स के मतानुसार १९४५ से ४७ तक सोवियत प्रचार के दो लक्ष्य थे—(१) जन प्रजातन्त्र के विकास को प्रोत्साहन, और (२) अमेरिका के प्रभाव को कम करना।

“इस काल में किये गये सोवियत प्रचार की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार थी—

(१) साम्यवादी प्रचार का क्षेत्र मुख्य रूप से अर्धविकसित या अविकसित देशों को बनाया गया।

(२) साम्यवादी जीवन के तरीके की प्रशंसा की गई और पूँजीवादी राष्ट्रो के अत्याचारों और शोषणों का रक्तरेजित काला चित्र खींचा गया।

(३) पूर्व में चीन तथा पश्चिम में योरोप में साम्यवाद फैलाने के लिए प्रबल व प्रभावकारी प्रचार किया गया।

(४) अमरीका द्वारा विभिन्न देशों को दी जाने वाली आर्थिक व सैनिक सहायता को उसके साम्राज्यवाद का ही दूसरा रूप माना गया। पत्रों और लेखों द्वारा यह जोरदार प्रचार किया गया कि अमरीका दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है।

(५) सोवियत रूस ने शान्ति का अभियान शुरू किया। प्रचार द्वारा सोवियत जनता एवं विश्व वालों को यह बताने का भरसक प्रयास किया गया कि रूस अपनी पूरी शक्ति से शान्ति की स्थापना के लिए तत्पर है तथा अणु अस्त्रों को मिटा कर वह निःशस्त्रीकरण करना चाहता है।

(६) कोरिया के मामले पर सोवियत प्रचार बहुत प्रभावशाली रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही रूस ने यह प्रचार प्रारम्भ कर दिया कि कोरिया की जनता अमरीकी नीति व व्यवहार के प्रति असन्तुष्ट व दुःख है और रूस की प्रशंसा करती है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की तुलना करके यह प्रचारित

इस काल का मित्रराष्ट्रो का प्रचार तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए किये गये उनके प्रयास पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। उन्होंने जो मार्ग अपनाये, शत्रु उन्हें पहले से ही अपना रहा था। मित्रराष्ट्रो के प्रचार की असफलता के कई कारण थे—

(१) प्रारम्भ में मनोवैज्ञानिक युद्ध की जो उच्चस्तरीय योजनाएँ बनाई गईं उनको शत्रु के विरुद्ध क्रियान्वित न किया गया। जापान में यदि प्रचार द्वारा चरित्र (Morale) को गिरा दिया जाता तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध द्वारा उसे कमजोर कर दिया जाता तो वहाँ बम गिराने की वरुस द्वारा उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

(२) एक दूसरी बड़ी गल्ती यह की गई कि मित्रराष्ट्रों ने अपने प्रचार द्वारा जर्मनी के सामान्य नागरिकों और शासन के बीच कोई भेद न किया। उनके प्रचार के फलस्वरूप वहाँ के नागरिक इस निष्कर्ष पर आये कि मित्र राष्ट्र उनके भी दुश्मन हैं न केवल नाजी सरकार के। अतः उन्होंने नाजी शासन का पूरा पूरा समर्थन किया। नाजी प्रचार यन्त्र के सचालक गोएबल्स (Goebbels) ने कहा था कि “अगर मैं शत्रु पक्ष में हाता तो नाजीवाद के विरुद्ध लड़ने का नारा लगाता न कि जर्मन जनता के विरुद्ध।”

(३) युद्ध के बाद अमरीकी प्रचार—शीतयुद्ध के प्रवाह के साथ-साथ अमरीकी जनता और सरकार द्वारा प्रचार के महत्त्व को समझा जाने लगा। १९४८ में स्मिथ मंड एक्ट (Smith Mundt Act) पास किया गया। इसका उद्देश्य था अमरीकन जनता और विश्व की जनता के बीच सद्भावना की स्थापना की जाय। प्रचार से सम्बन्धित नवीन योजना को क्रियान्वित करने के लिए एक संगठनात्मक ढाँचे की स्थापना की गई। १९५१ में राज्य विभाग (State Department) के अन्दर एक पृथक् अभिकरण अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रशासन (IIA) स्थापित किया गया। १ अगस्त, १९५३ को राष्ट्रपति द्वारा समुक्त राज्य सूचना अभिकरण (USIA) की एक स्वतन्त्र एकात्मिक रूप में स्थापना की गई। इसको समुद्र पार के सूचना कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व सौंपा गया।

USIA ने लगभग ७६ देशों में लगभग २१० सूचना चौकियाँ स्थापित की हैं। यह असाम्यवादी देशों के हजारों भ्रमधारा के लिए करोड़ों की सख्या में परचे, पोस्टर, भ्रमवार एवं पत्रिकाओं के लिए विशेष सामग्री, व्ययवित्र

तथा सूचना सम्बन्धी मसाला आदि भेजती है। 'वाइस ऑफ अमेरिका' (Voice of America) भी USA का एक महत्वपूर्ण एव प्रसिद्ध भाग है। यह लगभग ३८ भाषाओं में प्रतिदिन चौबीसो घण्टे प्रसारण करता है। इसके अधिकांश प्रसारणों का निशाना साम्यवादी देशों की ओर होता है।

अमेरिकी प्रचार में से अधिकांश तो प्रचार की प्रतिक्रिया (Counter propaganda) है। इसके अतिरिक्त विदेश नीति के मुख्य भागों को भी प्रचारित किया जाता है। मार्शल योजना का प्रचार एक प्रभावकारी रूप में किया गया था।

प्रचार में सरकार के अतिरिक्त व्यक्तिगत सस्यार्वों भी अपना सहयोग प्रदान करती हैं। अनेकों अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और नुमाइशों में अमेरिका के व्यक्तिगत संगठनों एवं व्यापारिक सस्यार्वों ने सक्रिय रूप से उत्साहपूर्वक भाग लिया है।

अमेरिकी प्रचार साम्यवादी देशों की तुलना में कम प्रभावशील है; इनके पामर तथा परनिन्दा में दो कारण बताये हैं—

(१) सोवियत यूनियन का प्रचार के क्षेत्र में अनुभव अधिक है पर्याप्त साम्यवादी जाति से पूर्व ही वे इसके अभ्यस्त हैं। इसने बाद अनेकों ऐसे अवसर आये जबकि उनको एक प्रभावकारी अष्टन के रूप में अपनाता पडा था।

(२) अमेरिकी प्रचार भाषण की स्वतन्त्रता पर आधारित है, सरकारी नियन्त्रण पर नहीं।

सांस्कृतिक सम्बन्ध और विदेश नीति (Cultural Relations and Foreign Policy)

नूषना कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक देश सांस्कृतिक माध्यम से भी अपना प्रचार कार्य संचालित करते हैं। यह कहा जाता है कि ज्ञान के आदान-प्रदान का सर्वाधिक प्रभावशील तरीका यह है कि व्यक्ति को अपने साथ वाघ लिया जाये। पश्चिमी शक्तियां परस्पर शैक्षणिक सम्बन्धों के माध्यम से एक दूसरे के पर्याप्त निकट आ गई हैं। उन देशों के हजारों छात्र एक दूसरे के देश में अध्ययन करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अपने उपनिवेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध थे, इसीलिए वह अधिकांश को शांतिपूर्वक प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान कर सका किन्तु राष्ट्रमण्डल के आधार पर उसने इस सांस्कृतिक सम्बन्ध को बनाये रखने की व्यवस्था कर ली। इन देशों के

नेताओं को 'ग्रेट' ब्रिटेन में 'प्रशिक्षण' प्राप्त हुआ था उसके कारण यहाँ के मूल्यों तथा मूल राजनैतिक एवं कानूनी समस्याओं को सराहना करते हैं।

फ्रांस जड़-पहला बड़ा देश है जिसने सांस्कृतिक सम्बन्धों को सरकारी कर्तव्य बना दिया था। फ्रांस के उदाहरण को देख कर १९ वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में इंग्लैण्ड तथा जर्मनी ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिये। ब्रिटेन की दूरदर्शिता के परिणामस्वरूप तथा अमरीकी मिशनरियों एवं अमरीकी सरकार के प्रयास से आज अधिकांश देशों के लगभग दस मिलियन से भी अधिक लोग अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं तथा इनके माध्यम से ये सरकारें इन क्षेत्रों में भासनों से संचार व्यवस्था चला सकती हैं।

समुक्त राज्य अमरीका का सांस्कृतिक कार्यक्रम—अमरीका में सन् १९३८ में राज्य विभाग के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों का एक समान जोड़ दिया गया। इसने सबसे पहले सेंटिन अमरीका पर अपना ध्यान आकषिप्त किया क्योंकि नाजीवाद तथा फासीवाद का प्रभाव वहाँ बढ़ता जा रहा था। सरकारी एवं गैर सरकारी सहयोग के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या को विकसित किया गया ताकि विद्यार्थियों का आदान-प्रदान एवं विदेशी अध्ययन संभव बन सके।

समुक्त राज्य अमरीका द्वारा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की दृष्टि से विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। साथ ही पासपोर्ट तथा बीसा के सम्बन्ध में उदार नीति अपना कर पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। विकासशील देशों में प्रशिक्षित मानव शक्ति का पर्याप्त महत्व होता है इसलिए वहाँ पर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया जा सकता है। जो विद्यार्थी अमरीका में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे राजनीति को पर्याप्त प्रभावित करेंगे और हो सकता है कि वे ही नेता बनें। इसी प्रकार अमरीका के जो विद्यार्थी एवं शिक्षक विदेशों में अध्ययन कार्य में रत हैं वे भी उन लोगों पर प्रभाव डालने का पर्याप्त अवसर पाते हैं जो अपने देश में सम्मान एवं उत्तरदायित्व के पद पर हैं अथवा पहुँच जायेंगे। सन् १९४६ के फुल ब्राइट कानून ने विदेशी छात्रों को वजीफे देने का प्रावधान रखा तथा सन् १९४८ के स्मिथ-मण्ड अधिनियम ने नेतृत्व के आदान-प्रदान का प्रबन्ध किया। इन अधिनियमों ने संघीय सरकार को सांस्कृतिक सम्बन्धों की रचना में रुचि लेने की ओर प्रवृत्त किया। अस्तित्व में आये 'अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के आदान-प्रदान के क्षेत्र में पर्याप्त कार्य करते हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका के करीब दस-पन्द्रह हजार लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं। इससे अमरीका को अन्य देशों की जनता से संपर्क बनाये रखने का अवसर प्राप्त होता है। इन अमरीकी लोगों में से अधिकांश का सम्बन्ध सशस्त्र सेनाओं से है तथा पाँच लाख से भी अधिक लोग व्यक्तिगत उद्यमों में सलग्न हैं। प्रति वर्ष दस लाख के लगभग अमरीकी पर्यटक के रूप में अमरीका से जाते हैं। इन सम्पर्कों एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से विदेश के लोगों के साथ निकटता बढ़ती है। किन्तु यहाँ एक यह भी खतरा है कि जाने वाले लोगों ने अमरीकी जीवन के अच्छे पक्ष का प्रतिनिधित्व न किया तो यहाँ की संस्कृति के प्रति सम्मान पैदा नहीं किया जा सकता तथा उल्टा प्रभाव पड़ने का भी खतरा है।

संयुक्त राज्य अमरीका के सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि विदेशों को यहाँ से पुस्तकें भेजी जाती हैं। प्रति वर्ष लाखों कम कीमत की पुस्तकें विदेशों को भेजी जाती हैं।

स्टालिन की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्धों का विकास हो गया है। सन् १९५८ से रुस जाने वाले अमरीकियों की संख्या दो गुनी हो गई है। इसी प्रकार अमरीका आने वाले रुसियों की संख्या भी बढ़ी है।

सोवियत सांस्कृतिक कार्यक्रम—यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सोवियत सरकार द्वारा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना के लिए कितना खर्च किया जाता है। सन् १९५३ में सोवियत सरकार इस कार्य पर दो बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च करती थी। अब यह खर्च बढ़ा हो है। कुछ लेखकों का अनुमान है कि सोवियत संघ इस कार्य पर जितना धन व्यय करता है उतना इस कार्य पर शायद सभी देशों द्वारा मिल कर भी नहीं किया जाता होगा।

विकासशील देशों में अपना प्रभाव लाने के लिए तथा अपनी संस्कृति का निर्यात करने के लिए सोवियत संघ, शोध कार्य, भाषा एवं अन्य विशेषीकृत प्रशिक्षणों पर खर्च—करना है—तथा प्रकाशित सामग्री वितरित करता है। सोवियत प्रचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्य, संचार अनुसंधान आदि के द्वारा विदेशों में जो सोवियत तस्वीर खींची जाती है वह एक शान्तिप्रिय किन्तु शक्ति सम्पन्न देश की है जिसने बहुत कम समय में ही अपनी

आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के कारण महान् प्राप्तिया की हैं। सोवियत सघ में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको सरकारी कर्मचारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है तथा जहां वे चाहे वही उनको ले जाया जाता है।

सोवियत सघ में एक राष्ट्रों का मंत्री विश्वविद्यालय (Friendship of Nations University) स्थापित किया गया है जो मास्को विश्वविद्यालय से अलग है। महा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देशों के युवकों को रूसी भाषा, विज्ञान, कला एवं साम्यवाद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। इन सम्पर्कों के माध्यम से यह आशा की जाती है कि जब ये युवक अपने देश को वापस लौटेंगे तो साम्यवाद के हित में कार्य करेंगे। अनेक अमरीकी शिक्षा शास्त्रियों ने जब व्यक्तिगत रूप से उच्च सोवियत शिक्षा-शास्त्रियों से बातें की तो उनको यह विश्वास हो गया कि सोवियत सघ विकासशील देशों से अमेरिका को पूरी तरह निकालना चाहता है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो गया कि उदार प्रजातन्त्र अपने सांस्कृतिक सम्बन्धों का प्रसार करे तथा विदेशों से आने वाले छात्रों को अधिक नम्रता एवं शिष्टता का व्यवहार प्रदान करे। यह एक चुनौती है जिसका सामना करना जरूरी हो गया है।

राजनैतिक युद्ध (Political Warfare)

मानव सम्पत्ता के प्रभाव से ही 'युद्ध' समाज की एक अग्रिम विशेषता बना रहा है। प्रारम्भ से ही इस खतरनाक विध्वंसक व्यवस्था को नियंत्रित करने की प्रयास किये गये किन्तु असफल रहे और युद्ध मानव विकास के साथ प्रलयकर बनता चला गया। आज विश्व में युद्ध का लगातार भय बना हुआ है। विभिन्न देश या तो युद्ध कर रहे हैं, या करने की तैयारी में हैं। पामर तथा परकिन्स के शब्दों में "शान्ति तो एक अल्पनालीन सपने के समान है जिसमें विचारधारा का प्रत्येक समय अपने लिए उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने के हेतु दूसरे को धोखा देने की तैयारी है।" युद्ध केवल सेना द्वारा हथियारों से युद्ध के मैदान में ही नहीं लड़े जाते। युद्ध के कई रूप होते हैं उदाहरण के लिए—

- १ मनोबैज्ञानिक युद्ध (Psychological Warfare)
- २ राजनैतिक युद्ध (Political Warfare)
- ३ सैनिक युद्ध (Military Warfare) आदि।

युद्ध के विभिन्न रूपों को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि युद्ध निरन्तर चलते रहते हैं और शान्ति केवल प्रेरण्य होने पर ही आ सकती है।

राजनैतिक युद्ध का अर्थ कूटनीति तथा प्रचार द्वारा एक देश द्वारा दूसरे देश को विजय दिलाने के लिए युद्ध करना (Meaning of Political Warfare)

राजनैतिक युद्ध क्या होता है यह कुछ थोड़े से शब्दों में बताना अथवा इसे परिभाषित करना सम्भव नहीं है। इतिहास के उदाहरणों को पुनः पुनः कर यह बताया जा सकता है कि इस प्रकार की नीति या कार्यक्रम अपनाने पर एक देश राजनैतिक युद्ध का कर्त्ता माना जा सकता है। इसमें एक राष्ट्र सैनिक शक्ति का प्रयोग नहीं करता बल्कि शक्ति का प्रयोग अवश्य करता है। युद्ध का अर्थ होता है विपक्षी को किसी बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। यदि आप ऐसा सैनिक शक्ति अपना कर करते हैं तो वह सैनिक युद्ध माना जाएगा बल्कि एक देश को विजय बनाने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग अपरिहार्य नहीं है। कूटनीति और प्रचार का सहारा लेकर भी ऐसा किया जा सकता है। प्रचार तथा कूटनीति का प्रयोग इस रूप में किया जाय कि दूसरा देश एक देश की नीतियों को मानने के लिए विवश हो जाय तो यह प्रक्रिया राजनैतिक युद्ध कहलायेगी। अगर वह देश उस विवशता को स्वीकार कर लेता है तो यह दूसरे देश को विजय मानी जायगी और यदि विवशता को स्वीकार नहीं करता तो उसके सामने सैनिक युद्ध के अनिरिक्त कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। कूटनीति एवं प्रचार का प्रयोग जब मुद्दाव के रूप में किया जाय तथा निर्णय लेने में दूसरे देश को स्वतन्त्र इच्छा का प्रयोग करने दिया जाय तो यह स्थिति राजनैतिक युद्ध की स्थिति नहीं कही जायगी।

इस प्रकार राजनैतिक युद्ध को कूटनीति तथा युद्ध के बीच स्थिति (Twilight zone between Diplomacy and War) माना जाता है। प्रचार के साथ राजनैतिक युद्ध का सम्बन्ध बताते हुए सामर तथा परकिन्स ने बताया है कि "दोनों के बीच का सम्बन्ध इतना घट्ट नहीं है क्योंकि बिना प्रचार के राजनैतिक युद्ध हो सकता है तथा प्रचार भी बिना राजनैतिक युद्ध प्रकट किए रह सकता है।"

इस प्रकार कूटनीति, प्रचार एवं आर्थिक उपाय आदि को राजनैतिक युद्ध केवल उसी अवस्था में माना जा सकता है जबकि उनका परिणाम विवशकारिता हो।

राजनैतिक युद्ध के साधन (Devices of Political Warfare)

राजनैतिक युद्ध का मुख्य उद्देश्य यहा होता है कि दूसरे देश को कमजोर बना दिया जाय और इस प्रकार अपने स्वार्थ की साधना की जाय। दूसरे राष्ट्रों को कमजोर बनाने के लिए एक देश द्वारा अपने को तरीके अपनाये जा सकते हैं। इनमे कुछ निम्न प्रकार हैं—

(१) भ्रम में डालने व फूट डालने के लिए प्रचार (Propaganda to confuse and divide)

संगठन में शक्ति होती है। इसके विरुद्ध जहा फूट होती है वहां अपने को कठिनाइया उपस्थित हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध पक्तियां— 'जहा सुमान तहा सम्पत्ति नाना,' जहा कुमति वहां विपत्ति नाना' इसी भाव को प्रदर्शित करती हैं। दो विल्लियों की फूट का फायदा कोई बन्दर ही उठाना है। भन्तराष्ट्रीय जगत में भी फूट डालने की प्रक्रिया को शत्रु के विरुद्ध काम में लाया जाता है ताकि वह कमजोर पड़ जाय और एक देश इस स्थिति का इच्छित लाभ उठा सके। भारत के इतिहास में यह युक्ति प्रारम्भ से ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है। जयचन्द और पृथ्वीराज की फूट ने मोहम्मद गोरी के तिर पर भारत का ताज रखा। फूट डाला और राज करो की नीति अपना कर अंग्रेज सदियों भारत का शोषण करते रहे और जाने-जाने भी उसके दो भाग कर गए जो अब भी कलह का कारण बना हुआ है। सार यह है कि जिस देश के विरुद्ध मान राजनैतिक युद्ध छेड़ना चाहते हैं उसमें ऐसा-प्रचार करिए कि वहां के लोग सत्य को न समझ पायें उनमें परस्पर समर्थन की स्थिति पैदा हो जाय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों ने टटली को Tripple Alliance से पृथक् करने के लिए गुप्त सन्धियों का जाल सा बिछा दिया।

(२) अल्पसंख्यकों को समर्थन देना (To Support the minority groups)

शत्रु के देश में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों के समुदायों, मुख्यतः वे जिन्हें हित दावी लोगों से भिन्न है, को सहायता व समर्थन करके भी एक देश को कमजोर किया जा सकता है। पाकिस्तान ने इसी नीति को अपना कर फीजो को प्राथम्य प्रदान किया है। पाकिस्तान सरकार द्वारा नागाओं को मददया जाता है। यही कारण है कि भारत में नागालैंड की

समस्या अभी तक बनी हुई है; नहीं तो अब तक तो इसका समाधान हो भी चुका होता।

कितो देश के अल्पसंख्यक समुदायों का पक्ष लेकर सरकार के सुचारु संचालन में बाधा डाली जा सकती है। किन्तु ऐसी सम्भावना प्रजातन्त्रात्मक प्रणालियों में ही प्राप्त हो सकती है, साम्यवादी देश सर्वाधिकारवादी होते हैं। वहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं दी जाती इसलिए वहाँ का कोई अल्पसंख्यक समुदाय सरकार के कार्यों में बाधा नहीं डाल सकता। यदि उसने ऐसा करने का साहस भी किया तो देशद्रोही होने के अपराध में उसे अपना अस्तित्व खोना पड़ेगा।

(३) क्रान्ति को प्रोत्साहन देकर

(By encouraging the revolt to overthrow the existing Government)

राजनैतिक युद्ध का यह बड़ा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रूप है। यह दूसरे रूपों की एक भगली कड़ी भी माना जा सकता है। प्रारम्भ में तो एक देश में फूट के बीज बोये जाते हैं, तात्पर्यवान् अल्पसंख्यकों के हितों का पक्षपात लेकर उस फूट की खाई को और चौड़ा किया जाता है और जब दो किनारे बहुत दूर हो जाते हैं तथा कुछ-कुछ समान शक्ति पा लेते हैं तो विरोधी पक्ष को उकसा कर स्थित सरकार के विरुद्ध क्रान्ति करा दी जाती है।

पाकिस्तान ने प्रास्त, १९६५ में एक दिवा-स्वप्न देखा था। वैसे तो अपने जन्म दिन से पूर्व ही उसने भारत को शक्तिहीन बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था किन्तु जब चीन जैसे सलाहकार मित्र उसे प्राप्त हो गए तो वह अपने स्वप्नों को साकार करने की सोचने लगा। अफ़्रीरिया के उदाहरणों को देखकर उसने याचना बढ़ तरीके से भारत-प्रधिकृत काश्मीर में क्रान्ति कराने की चाल चली। हजारों सशस्त्र पुनर्पठिये चोरी दिये भारतीय सीमा में भेज दिए गए। भासा था कि काश्मीर के मुसलमान घम क नाम पर पुनर्पठियों की सहायता करेंगे तथा निहत्थे हिन्दू जनता को दबा दिया जायेगा। पाकिस्तान रेडियो ने प्रसारित भी कर दिया कि काश्मीर में क्रान्ति हो गई किन्तु सत्य इसके विपरीत था। काश्मीर वालों की देशभक्ति और भारतीय रक्षा सेना की जागरूकता के कारण पुनर्पठिये पकड़ लिये गये। पाकिस्तान का स्वप्न दुन्टा होकर उसकी शक्तिहीनता पर नजर आन गया।

क्रान्ति का यही तरीका एक दूसरे एशियाई देश चीन द्वारा अपनाया गया। साम्यवादी चीन ने इण्डोनेशिया के साम्यवादियों को उकसाया और दा. मुक्तों की सरकार को उलट देने का प्रयत्न किया। किन्तु यह क्रान्ति भी सफल न हो सकी। विद्रोही साम्यवादियों ने मध्य जावा आदि क्षेत्रों में भारी उपद्रव किए किन्तु बाद में बन्दी बना लिये गये।

(४) उद्योगों एवं यातायात को क्षति पहुँचाना

(The use of sabotage to wreck industry and transport)

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने उस उद्योग को अपनाया और अमेरिका में जहाँ मित्र राष्ट्रों के लिए हथियार बनने थे उसने अपने गुप्तचरों और भेदियों को छोड़ दिया। इन गुप्तचरों का मुख्य कार्य उस उत्पादन को नष्ट भ्रष्ट करना था जो मित्र राष्ट्रों के लिए बन रहा था। इन दिनों अमेरिका में कई स्थानों पर आगें लगीं जिनके कारण शांत न हो सके। अनुमान लगाया जाता है कि यह आग जर्मनों के द्वारा लगाई गई थी। यातायात के मार्गों एवं यानों को नष्ट करने से, रेलगाड़ियों को उड़ा देने से कारखानों में मशीनों को लुढ़का देने व तैयार माल को नष्ट करा देने से एक देश के जनजीवन तथा अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उसकी कमर सी टूट जाती है।

(५) नेताओं की हत्या करना एवं जनता को अनीतिक बनाना

(The resort to assassination to remove key

leaders and demoralize the population)

भारत-पाक संघर्ष के समय अरब राष्ट्रों ने पाकिस्तान का समर्थन न किया। पाकिस्तान को आशा थी कि उसके जिहाद में सभी मुस्लिम राष्ट्र एक होकर मर मिटेंगे। किन्तु कर्नेल नासिर का व्यवहार उनकी आशाओं पर तुल्यभाषा के समान था। इसके परिणामस्वरूप नासिर की हत्या का पड्यन्त्र रचा गया। कहा जाता है कि पाकिस्तान सरकार का इस पड्यन्त्र में पूरा सहयोग था। इसी प्रकार अरब अनीक नेताओं के साथ भी हो चुका है। मानव अधिकारों के पीछे राष्ट्रपति कैनेडी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे प्रतापसिंह कैरो की हत्या की जा सकती है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के प्रधान की हत्या करके अपने स्वार्थ की साधना की जा सकती है। किसी देश की जनता के मनोबल को गिराकर उस अनीतिक, दुराचारी और भ्रष्टाचारी बना दिया जाय तो वह देश अधिक दिन तक नहीं टिक सकता।

इस प्रकार विभिन्न तरीकों को अपना कर राजनीति युद्ध का समाप्त किया जाता है। राजनीतिक युद्ध सैनिक युद्ध की अपेक्षा कम नरसंहार करके ही आशमणकारी के लक्ष्यों को पूरा कर देता है। इसमें आशमणकारी को भी अधिक नुस्खान नहीं उठाना पड़ता। किसी किसी परिस्थिति में तो यह आहंसात्मक रूप से भी किया जा सकता है। सैनिक युद्ध प्रारम्भ हो पर राजनीतिक युद्ध समाप्त हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। पारस्परिक परस्पर के मतानुसार युद्ध के समय इसकी भारी आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय नीति की अभिवृद्धि के साधन :
 आर्थिक साधन ; साम्राज्यवाद-
 उपनिवेशवाद एवं युद्ध

(INSTRUMENTS FOR THE PROMOTION OF
 NATIONAL POWER - ECONOMIC INSTRUMENTS,
 IMPERIALISM-COLONIALISM AND WAR)

राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के जिन साधनों का अध्ययन हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं वे ही एवमान साधन नहीं हैं यद्यपि उनका भी अपना महत्व होता है। कूटनीति, प्रचार एवं राजनैतिक युद्ध के द्वारा निरन्तर एक देश अपने हितों की साधना में सलग्न रहता है। ये उसके प्रति-दिन के जीवन की विशेषतायें हैं किन्तु एक देश कुछ ऐसे साधन भी अपनाता है जो कि उनके प्रति दिन के जीवन व्यवहार का घन तो नहीं होते क्योंकि इनका प्रयोग प्रायः दीर्घकालीन नीति के रूप में किया जाता है किन्तु फिर भी ये अपने आपमें कोई लक्ष्य नहीं होने तथा साधन के रूप में ही इनका महत्व होता है। इनमें हम आर्थिक साधन, साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद एवं युद्ध आदि का नाम ले सकते हैं। इन साधनों को अपना कर के एक देश अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहता है। इस दायें में उसे किन्ती संपत्ति प्राप्त होगी है तथा उसकी शक्ति बढ़ती है भयंश नहीं, यह हम बात पर निर्भर करता है कि उसने इन साधनों का प्रयोग करने में किन्ती कुशलता एवं व्यावहारिक बुद्धि से काम लिया है। प्रस्तुत अध्याय में इन साधनों के

स्वरूप को निर्धारित करने वाला तीसरा तत्व है ^(३) उन दो राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों का रूप। यदि वे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं तो एक देश अपने आन्तरिक विकास एवं कल्याण के लिए ऐसी नीतियाँ अपनायेगा जो दूसरे देश के हितों के लिए घातक न हो। किन्तु यदि उन दो देशों के बीच के सम्बन्ध मित्रतापूर्ण न हो कर परस्पर शत्रुतापूर्ण हो तो वह देश ऐसी आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर सकता है जिनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से दूसरे देश को हानि पहुँचाना हो। एक देश द्वारा जो आर्थिक नीति अपनायी जायगी उसका निर्धारण करने वालों में चौथा तत्व है, ^(४) दूसरे देशों का प्रभाव। उदाहरण के लिये रोडेशिया पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबन्धों पर ब्रिटेन के हस्त को चिया जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन के हस्त को देख कर लगता था कि वह इन प्रतिबन्धों का हृदय से समर्थन नहीं करता है, किन्तु विश्व जनमत के प्रभाव से उसने रोडेशिया को तैत न भेजने की नीति को अपना लिया। दूसरे देश के प्रभावों को मानने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह कि आज विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी सीमा तक दूसरे देश पर आश्रित रहता है और दूसरे यह कि प्रत्येक देश को कुछ चीजों का आयात और कुछ चीजों का निर्यात करने की आवश्यकता रहती है।

आर्थिक साधनों का महत्व

(The importance of economic instruments)

आर्थिक साधनों का प्रयोग शांतिकाल और युद्धकाल दोनों में ही किया जा सकता है; किन्तु उनका उद्देश्य दोनों कालों में एकता नहीं रहेगा। शांतिकाल में इनका प्रयोग जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है वे मुख्य रूप से उस देश के कल्याण और आन्तरिक विकास से सम्बन्धित रहते हैं, उदाहरण के लिए देश की बेरोजगारी को दूर करना, तकनीकी का विकास करना, लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों को सुरक्षित रखना आदि। युद्ध के समय आर्थिक साधनों का प्रयोग मुख्य रूप से दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है—प्रथम तो अपने देश में युद्ध की तैयारियों को पूरे वेग से करने के लिए और दूसरे शत्रु देश की युद्ध तैयारियों का प्रतिरोध करने के लिए। इस प्रकार युद्धकाल में आर्थिक साधनों के प्रयोग का मूल लक्ष्य दूसरे देश का अधिक से अधिक घात करना होता है। यदि ऐसा करने में स्वयं का भी मोड़ सा सहित होता हो तो कोई बात नहीं है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक साधनों का प्रयोग अच्छे तथा बुरे दोनों ही साधनों के लिए किया जा सकता है। इन्हें एक देश अपने

जन जीवन के कल्याण के लिए प्रयुक्त कर सकता है तथा वह इन्हें अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का साधन भी बना सकता है। एक देश के द्वारा आर्थिक साधनों का प्रयोग चाहे किसी तत्त्व से प्रभावित हो कर किया जाये और चाहे उसका कुछ भी उद्देश्य हो किन्तु आज की परिस्थितियों में यह स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव विश्व के दूसरे देशों पर भी पड़ेगा, यह प्रभाव उन देशों के पक्ष में भी हो सकता है और विपक्ष में भी। आर्थिक साधनों के रूप का वर्णन करते हुए पामर तथा परकिन्स ने लिखा है कि 'जब कभी राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाई जाती हैं, चाहे वे दूसरे देशों का अहित करती हों अथवा नहीं वे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन हैं।'^१

आर्थिक साधनों का अर्थ

(The Meaning and Scope of Economic Instrument)

आर्थिक साधन शक्ति के प्रयोग के प्रमुख साधन हैं। इन रूप में उन्हें हम विदेश नीति के अस्त्र कह सकते हैं। आजकल राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्थाओं की पराश्रयता के कारण आर्थिक साधन राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों में अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। वेडिलकोर्ड तथा लिबन ने आर्थिक साधन को किसी भी आर्थिक क्षमता सत्या या तकनीक के रूप में परिभाषित किया है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से विदेश नीति के लक्ष्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है। जिन लक्ष्यों की ओर ये संचालित किये जाते हैं उनकी प्रकृति आर्थिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, सैनिक हो सकती है अथवा मनोवैज्ञानिक हो सकती है। इन साधन के द्वारा देश आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं; निर्यात किये जाने वाले व्यापार को बढ़ाते हैं, कम विकसित राज्यों में व्यवस्थित विकास को प्रोत्साहन देने हैं, दूसरे राष्ट्रों की नीति के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं या समर्थन करते हैं।

आर्थिक लक्ष्यों का उनके साधनों के साथ और साधनों का उनके लक्ष्यों के साथ समायोजन अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का एक सर्वाधिक जटिल पहलू है। ये जटिलताएँ एक तो इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि स्वतन्त्र दुनिया के देशों में गैर-सरकारी पहलू आर्थिक क्रिया का संचालनकारी तंत्र है। व्यक्तिगत पहलू हमारा मूल्यों एवं लाभ से प्रभावित होती है और इसलिए यह सुरक्षा, कल्याण एवं विश्वास के राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा नीतियों का अनुरूप हो भी

सकती है और नहीं भी। राष्ट्रवाद की शक्तिशाली मत्तायें जिनके द्वारा देशों के बीच अनेक संधयें रीढ़ी किये जा रहे हैं वे परम्परागत सांघिक लक्ष्यों के भार पार हो जाते हैं।

सांघिक सम्बन्धों की दुनिया अनेक विरोधों से पूर्ण है। प्रत्येक राज्य एक अन्तर्राष्ट्रीय सांघिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करता है जो उसके स्वयं के हितों के अनुरूप हो। हमरी ओर उसे अन्य राज्यों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है जो उसके सर्वश्रेष्ठ ग्राहक भी होते हैं और शक्तिशाली प्रतिपक्षी भी। इसके अतिरिक्त सांघिक दृष्टि से कमजोर राज्य अन्तर्राष्ट्रीय संधि-व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देता है क्योंकि उनको परिवर्तन की दिशा में चुननी होती है। राज्यों के पारस्परिक सांघिक सम्बन्ध इतने अधिक तथा व्यापक होते हैं कि वे अन्य सभी प्रकार के अन्तर्राज्य सम्बन्धों की कुल संख्या से अधिक होते हैं। कभी-कभी इन सांघिक सम्बन्धों की राष्ट्रवाद एवं सुरक्षा की भावनाओं से प्रभावित होना पड़ता है।

सांघिक शक्ति विश्व की घटनाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव रखती है। एक कमजोर संधि-व्यवस्था राजनैतिक स्थिरता का कारण बनती है और साम्यवाद के लिए अनुकूल भूमि तैयार करती है। किसी भी देश के सांघिक मामलों की अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण समझा जाता है। सांघिक दृष्टि से जो महात् प्रतिद्वन्द्वी हैं वे भी सांघिक एवं राजनैतिक दृष्टि से एक दूसरे की संधि व्यवस्था के स्वास्थ्य पर निगरान रहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के अनेक निगम ये चाहेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन के समुद्र पार के व्यापार को वे स्वयं समाल लें। किन्तु संयुक्त राज्य अमरीका यह भी सहन नहीं कर सकता कि उसका मित्र ग्रेट ब्रिटेन सांघिक दृष्टि से कमजोर हो।

संयुक्त राज्य अमरीका की सांघिक शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही उसकी शक्ति का प्रदान खोल रही है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका इसलिए महा शक्ति बन पाया क्योंकि उसके पास अणु शक्ति थी। किन्तु अणु शक्ति भी अमरीका को केवल इसलिए प्राप्त हो गरी थी क्योंकि वह सांघिक शक्ति सम्पन्न था। संयुक्त राज्य अमरीका अधिकांश देशों का सबसे बड़ा ग्राहक है और सबसे बड़ा व्यापारी है। अमरीका की सांघिक शक्ति ने ही उसे अन्तर्राष्ट्रीय सांघिक मामलों का नेतृत्व प्रदान किया। इसकी सांघिक शक्ति साम्यवाद के विरुद्ध स्वतन्त्र दुनिया के देशों को सैनिक सहायता देने का साधारण रही है। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा जिन विदेश नीति के साधनों को अपनाया जाता है उन सभी का समर्थन मुख्य रूप से सांघिक व्यवस्था करती है। यही कारण है कि सरकारी अधिकारी कई बार यह तर्क

करते हैं कि आर्थिक मन्दी देश की सुरक्षा के लिए उतनी ही सतरनाक है जितनी कि साम्यवाद की प्रत्यक्ष चुनौती ।

एक देश विशेष की राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था विश्व की घटनाओं को प्रभावित करती है । बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति विदेश नीति के लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए अधिक धन प्रदान करती है । योजनाओं में जब सफलता प्राप्त होती चली जाती है तो एक देश उन साधनों का प्रचार कर सकता है जिनको उसने प्रयुक्त किया था । आर्थिक सम्बन्धों के आधार पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है । यह कहा जाता है कि यदि साम्यवादी चीन के बड़े उद्योगों का उत्पादन सन् १९७० तक भारत और जापान को मिला कर अधिक हो जाए और चीन का दृष्टिकोण इतना ही कठोर बना रहे तो यह सम्भावना है कि चीन के नक्शे के अनुसार यहाँ राजनीतिक और आर्थिक गड़बड़ी हो जाए ।

आर्थिक शक्ति को राष्ट्रीय सैनिक शक्ति एवं कुल राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण का मूलभूत आधार-स्तम्भ कहा जाता है । आज के युग में मानव शक्ति, सैनिक शक्ति का उतना महत्त्व माग नहीं है जितना कि पहले कभी होती थी । आज के सैनिक शक्ति अधिकतर तकनीकी उद्योग एवं सरकारी वित्त पर आधारित है । यह एक सर्वविदित तत्व है कि घरेलू आर्थिक संस्थाएँ एवं साधन स्रोत विदेशी मामलों में एक राज्य की नीतियों एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करने हैं । अनेक राज्य उस समय तक पर्याप्त सैनिक शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते जब तक कि दूसरे राज्यों के उद्योगों का समर्थन प्राप्त न कर लें । वे ऐसे समर्थन के बिना बड़े सधनों को नहीं चला सकते । यह कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान और भारत का सन् १९६५ का संघर्ष राजनीतिक प्रयासों में राफ न दिया गया होता तो वेग भी इन देशों को अपने सैनिक प्रसाधनों एवं अन्य साधनों की क्षति के कारण इसे रोकना पड़ता ।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन की प्रकृति (The Nature of International Economic Life)

राष्ट्रों के आर्थिक सम्बन्धों का इतिहास १९वीं शताब्दी के साथ प्रारम्भ होता है । इस समय अनेक कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला तथा पर्याप्त मात्रा में एक देश द्वारा आयात व निर्यात किया जाना प्रारम्भ हो गया । इन कारणों में उल्लेखनीय हैं जैसे—शक्ति तकनीकी के कारण होने वाला औद्योगिक विफल, अमेरिकन जाति, जनसंख्या में वृद्धि

तथा औद्योगिक शक्ति और उसके कारण लोगों द्वारा देशांतरीकरण (Migration) आदि ।

१९वीं शताब्दी में उदारवाद की विचारधारा का बोलबाला था । अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जीवन पर इस विचारधारा का प्रभाव पड़ा और यह सोचा जाने लगा कि आयात तथा निर्यात पर यदि राज्य का नियन्त्रण कम में कम रखा जायेगा तो इससे दोनों ही पक्ष (निर्यात एवं आयात) लाभान्वित होंगे, किन्तु व्यवहार में यह विचारधारा अधिक कारगर सिद्ध न हो सकी और राज्य का थोड़ा बहुत नियन्त्रण बना ही रहा ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में जब वस्तुओं के आयात और निर्यात की परम्परा का शीघ्रगण ह्रस्व तब प्रत्येक देश यह प्रयत्न करने लगा कि वह अपने देश के आयात और निर्यात के बीच सन्तुलन बनाये रखे ताकि उसे विदेशों में घन न भेजना पड़े । लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशों में घन लगाया जाने लगा । विदेशों में घन लगाने के दो तरीके थे एक तरीके के अनुसार तो पूँजी मिल, कारखाने आदि लाने में लगाई जाती थी जहाँ उत्पादन करके लाभ प्राप्त किया जा सके दूसरा तरीका यह था कि वहाँ की सरकार भयवा उसके किसी भाग को बर्जा दे दिया जाय ।

प्रथम विश्व युद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया । युद्ध के परिणामस्वरूप जो परिस्थितियाँ पैदा हुयी उनके अधीन प्रारम्भ में तो यह प्रयत्न किया गया कि उसी अर्थव्यवस्था को कायम रखा जाय जो युद्ध से पहले स्थित थी, किन्तु यह व्यवस्था बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल न थी । फलतः राष्ट्री की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी (Economic Depression) का सामना करना पड़ा । पहले राज्यों द्वारा आर्थिक जीवन में जा निषेधात्मक रख अपनाया जाता था उसे अब छोड़ दिया गया । इसके स्थान पर आर्थिक मामलों में राज्य के प्रतिवन्ध बढ़ गये और राज्य ही समस्त आर्थिक सम्बन्धों का नियमन करने लगा । इस प्रकार आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का जन्म हुआ जो आगे चल कर द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की शुरुआत में तिरोहित हो गया । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक मंदी के कारण व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था का स्थान समाजवादी अर्थव्यवस्था ने ले लिया । पारस्परिक तथा परस्पर ने ठीक ही लिखा है कि "एक राष्ट्र जब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रण लगाता है तो उसे, चाहे या अनचाहे रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी प्रतिवन्ध लगाने पड़ते हैं ।

जब व्यापार पर प्रतिबन्ध लग जाते हैं तो व्यापार का क्षेत्र एवं व्यापार सीमित रह जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ। दो विश्व-युद्धों के बीच के समय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र निरन्तर कम होता चला गया। १९३३ के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन आया किन्तु इस परिवर्तन का कारण यह था कि अधिकांश देशों द्वारा पुनः शस्त्रीकरण किया जा रहा था और सभी बड़ी शक्तियों का सैनिक बजट बहुत बढ़ गया था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित हो गई। एक ओर साम्यवादी देश हैं और आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) का प्राधान्य है और दूसरी ओर पूँजीवादी प्रजातन्त्र है जो अपेक्षाकृत स्वतन्त्र-विश्व व्यापार के पक्षपाती हैं। वर्तमान विश्व की अर्थव्यवस्था का इतिहास इन दो प्रमुख समुदायों के बीच के मौलिक विरोध एवं संघर्ष की कहानी है। एक राष्ट्र के पास उसके राष्ट्रीय हित के मोर्चने के रूप में जो आर्थिक हथियार रहते हैं उनका अध्ययन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है।

आर्थिक साधनों के प्रकार (Kinds of Economic Instruments)

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक साधन अपनाये जाते हैं वे अनेक प्रकार के हैं। इन सब साधनों के समुक्त रूप को पामर लक्स-मस्किन्स ने आर्थिक शस्त्रागार (Economic Arsenal) का नाम दिया है। इस शस्त्रागार के आयातों का प्रयोग केवल सरकार ही नहीं करती बल्कि व्यक्ति भी, बिना सरकार के भाग लिए, कर सकते हैं। इन विभिन्न प्रकार के आर्थिक दवावों का उपयोग किसी आर्थिक लक्ष्य की अपेक्षा राजनैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये सभी साधन परस्पर इतने सम्बन्धित हैं कि एक को अपनाने पर दूसरे को अपनाना आवश्यक बन जाता है। इन सभी साधनों का महत्व परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। शांतिवादी स्थिति में जो साधन उपयोगी रहते हैं, युद्धकाल में उनका महत्व नहीं रह जाता और युद्धकालीन उपयोगी साधन शांतिमान में अपनी उपयोगिता खो देते हैं।

वर्तमान काल में एक देश द्वारा अपनी राष्ट्रीय नीति के लिए जिन विभिन्न प्रकार के आर्थिक साधनों का उपयोग किया जाता है, वे मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं—

(i) शुल्क लगाना (The Tariff)

राष्ट्र की प्राय बढ़ाने के लिए एक देश अपने आयात पर कर लगा सकता है। इस शुल्क के लगाने पर विदेशी माल महंगा पड़ेगा और इसलिए स्वदेशी माल की प्रतियोगिता में लाभ रहेगा। आयात की मात्रा नियंत्रित पर भी बर लगाया जा सकता है किन्तु ऐसा बहुत कम होता है और अमरिका आदि राष्ट्रों में तो इसके विरुद्ध कानून भी बन गया है।

आयात या निर्यात पर शुल्क लगाने के कई लक्ष्य हो सकते हैं—

✓ (१) यह उम्र देश की आय को बढ़ाने के लिए लगाया जा सकता है।

✓ (२) यह शुल्क विदेशी उद्योगों से स्वदेशी उद्योगों को बचाने के लिए लगाया जा सकता है, इसी कारण इसे संरक्षण शुल्क (Protective tariff) भी कहा जाता है।

(३) इस शुल्क का अप्रत्यक्ष उद्देश्य मजदूरों की जीवन वृद्धि, स्थानीय कारखानों के लाभ को बढ़ाना, दूसरे राज्यों की तुलना में अपने राज्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना आदि हो सकते हैं, किन्तु यदि शुल्क का आधार ऐसे संरक्षणभक्त लक्ष्य है तो उसका सम्बन्ध केवल एक विशेष उद्योग या कारखाने से होना चाहिए।

(४) शुल्क के द्वारा एक देश आरामदेह चीजों के आयात को कम करके तथा आवश्यक नागरिक वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकता है।

(५) शुल्क लगाने से जो आयात की मात्रा कम होगी उतनी विदेशी मुद्रा का सुरक्षित रखा जा सकता और आयात के भुगतान में कमी नहीं रहेगी।

✓ (६) एक देश द्वारा शुल्क बढ़ाने की भावना से भी लगाय जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारे देश द्वारा इसके किसी माल पर ऐसा शुल्क लगा दिया गया है तो यह भी उस देश से आयात या निर्यात पर ऐसा ही शुल्क लगा देगा। ऊँचे शुल्क का परिणाम सर्वत्र ही ऊँचा शुल्क होगा है इसलिए जब एक देश द्वारा शुल्क की दीवार को तोड़ दिया जाता है तो उसका प्रभाव अनेक देशों पर पड़ता है।

एक देश शुल्क घटाने अन्य प्रतिस्पर्धित नीतियों द्वारा जब अपने घावों को हमारे देशों के मूल्य पर सम्पन्न बनाना चाहता है तो ये नीति 'bigger my-neighbour' नीति कहलाती है।

इस प्रकार शुल्क के रूप में प्रत्येक देश के पास एक ऐसा हथियार रहता है जिसके कारण वह दूसरे देश को नुकसान पहुँचा सके। युद्ध के बाद शांति की जो शर्तें लगाई जाती हैं उनमें परिवर्तित शुल्क नीतियों को भी प्रायः समाविष्ट कर दिया जाता है।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल्स का प्रयोग (The use of International Cartels)

कर्टेल को स्वतन्त्र उद्योगों की एक संस्था कह सकते हैं जो उन कार्यों से समानता रखती है जिनको प्रतियोगिता पर नियन्त्रण रखने के लिए व्यवहृत किया जाता है। यदि इस संस्था के सदस्य अलग-अलग देशों के रहने वाले हैं अथवा विदेशों में व्यापार करते हैं तो यह कर्टेल अन्तर्राष्ट्रीय कही जायगी। 'कर्टेल' शब्द की व्युत्पत्ति 'चार्टा' (Charta) शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होना है ठेका (Contract)। कर्टेल का उद्देश्य बाजार को नियमित (To regulate the market) करना होता है अर्थात् वह बाजार में किसी का एकाधिकार नहीं रहने देनी और इस प्रकार इसका कार्य केवल विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना होता है न कि खरीददारों के हितों की रक्षा। एक संस्था होने के कारण यह स्वाभाविक है कि कर्टेल सभी कार्य कर सकती है जबकि इसके सभी साझेदार सहमत हो। यह निश्चित समझौतों पर एक शक्तिशाली संस्था भी हो सकती है और केवल ऊपरी वादचाल पर निर्भर एक कमजोर सप भी। बाजार को प्रभावित करने के लिए कर्टेलों द्वारा जिन साधनों को अपनाया जाता है उनके आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है—

- (१) मूल्य निर्धारित करने वाले कर्टेल,
- (२) उत्पादन को सीमित करने वाले कर्टेल, तथा
- (३) विश्व के प्रदेशों को विभाजित करने वाले कर्टेल।

उक्त तीनों ही प्रकार के कर्टेलों का आधारभूत तत्त्व मूल्यों को निर्धारित करना होता है। कर्टेल प्रथा के उपयोग का प्रारम्भ कुछ अस्पष्ट रूप से मध्य युग में ही हो गया था तथा अठारहवीं सदी के ग्रेट ब्रिटेन में और उन्नीसवीं शताब्दी के जर्मनी और फ्रांस में ऐसी अनेक संस्थाएँ वर्तमान थी, किन्तु इन संस्थाओं के लिए कर्टेल (Cartel) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग १८७० में जर्मनी में किया गया। जर्मन का 'कर्टेल की पुरातन भूमि' (The classic land of the cartel) कहा जाना है। बाद में आस्ट्रिया, स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों ने कर्टेल के विरुद्ध कानून बना दिये किन्तु जर्मनी, इटली

एक हस्त आदि सर्वाधिकारवादी देशों में इस तथ्या की प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

कर्टेल का प्रयोग उन्ही उद्योगों में अच्छी प्रकार किया जा सकता है जिनमें काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सके तथा जहाँ गुणवत्तात्मक धनरों का महत्व नहीं हो । अरविन हैक्सनर (Ervin Hexner) महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेलन की मुद्रणत घाट क्षेत्रियों में विभाजित किया है । समुक्त राज्य अमरीका का लोचनन कर्टेलन का विरोध करना है । वहाँ रसायनिक एवं विद्युत उद्योगों में कर्टेलन है, यही कारण है कि इन उद्योगों की भारी आलोचना की जाती है । अमेरिका के अर्थशास्त्रियों का एक समुदाय ऐसा है जिसके मतानुसार कर्टेलन का प्रभाव अन्तिम रूप से एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होता है । एक अमेरिकन विद्वान व्हिटलेसी (Whittlesey) के अनुसार कर्टेलन के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

१. कर्टेल व्यवस्था स्वामित्व का विभाजन करके तथा लान प्राप्ति के स्वार्थ की देशमक्ति की भावना के ऊपर रख कर मुद्रों की प्रोत्साहन देती है ।

२. कर्टेल व्यवस्था के अघोन उत्पादन तथा वितरण पर जो प्रतिद्वन्द्व लगाने जाते हैं उनके कारण एक देश किसी बड़े मुद्र के लिए उपयुक्त भाव-स्वक सामग्री से वंचित रह जाएगा ।

३. कर्टेल एक गुप्तचर का काम करता है क्योंकि यह एक गुप्त अन्वेषण (Undercover agency) है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को एक देश में ले जाकर दूसरे ऐसे देश में भी पहुँचा सकता है जो उस देश का सम्भावित शत्रु हो ।

४. कर्टेल द्वारा विदेश में पूँजी लगाने की व्याज दर निश्चय कर दी जाती है और इन प्रकार तीसरा कोई देश वहाँ अपनी पूँजी नहीं लगा सकता ।

५. कर्टेल मुद्रण रूप से सर्वाधिकारवादी राज्यों के विदेशी औजार (Special Tool) है और इसलिए इनको बहिष्कृत किया जाना चाहिए ।

व्हिटलेसी (Whittlesey) महोदय कर्टेल के विरुद्ध किए जाने वाले तर्कों की मत्तना स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि कर्टेलन के द्वारा जहाँ राष्ट्रवाद का पृष्ठभूमि होता है वहाँ इससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है । जर्मन-कर्टेल के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क असल

इस प्रकार शुल्क के रूप में प्रत्येक देश के पास एक ऐसा हथियार रहता है जिसके कारण वह दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सके। युद्ध के बाद शांति की जो शर्तें लगाई जाती हैं उनमें परिवर्तित शुल्क नीतियों को भी प्रायः समाविष्ट कर दिया जाता है।

(II) अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल्स का प्रयोग (The use of International Cartels)

कर्टेल को स्वतन्त्र उद्योगों की एक संस्था कह सकते हैं जो उन कार्यों से समानता रखती है जिनको प्रतियोगिता पर नियन्त्रण रखने के लिए व्यवहृत किया जाता है। यदि इस संस्था के सदस्य अलग-अलग देशों के रहने वाले हैं अथवा विदेशों में व्यापार करते हैं तो यह कर्टेल अन्तर्राष्ट्रीय कही जायगी। 'कर्टेल' शब्द की व्युत्पत्ति 'चार्टा' (Charta) शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है ठेका (Contract)। कर्टेल का उद्देश्य बाजार को नियमित (To regulate the market) करना होता है अर्थात् वह बाजार में किसी का एकाधिकार नहीं रहने देनी और इस प्रकार इसका कार्य केवल विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना होता है न कि खरीददारों के हितों की रक्षा। एक संस्था होने के कारण यह स्वाभाविक है कि कर्टेल सभी कार्य कर सकती है जबकि इसके सभी साझेदार सहमत हो। यह निश्चित समझौते पर एक गतिशील संस्था भी हो सकती है और केवल ऊपरी वातचीत पर निर्भर एक कमजोर संघ भी। बाजार को प्रभावित करने के लिए कर्टेलों द्वारा जिन साधनों को अपनाया जाता है उनके आधार पर इन्हें तीन भागों में बाटा जा सकता है—

- (१) मूल्य निर्धारित करने वाले कर्टेल,
- (२) उत्पादन को सीमित करने वाले कर्टेल, तथा
- (३) विपणन के प्रदेशों को विभाजित करने वाले कर्टेल।

उक्त तीनों ही प्रकार के कर्टेलों का आधारभूत लक्ष्य मूल्यों को नियंत्रित करना होता है। कर्टेल प्रथा के उपयोग का प्रारम्भ कुछ असंगत रूप से मध्य युग में ही हो गया था तथा अठारहवीं सदी के ग्रेट ब्रिटेन में और उन्नीसवीं सताब्दी के जर्मनी और फ्रांस में ऐसी अनेक संस्थाएँ बतमान थी, किन्तु इन संस्थाओं के लिए कर्टेल (Cartel) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग १८७० में जर्मनी में किया गया। जर्मनी का कर्टेल की पुरातन भूमि (The classic land of the cartel) कहा जाता है। बाद में आस्ट्रिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों ने कर्टेल के विह्वल पानून बना दिये किन्तु जर्मनी, इटली

एव रूस आदि सर्वाधिकारवादी देशों में इस सस्या को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ ।

कर्टेल का प्रयोग उन्ही उद्योगों में अच्छी प्रकार किया जा सकता है जिनमें काफी मात्रा में उत्पादन किया जा सके तथा जहाँ गुणात्मक अन्तरों का महत्व नहीं हो । अरविन हैक्सनर (Ervin Hexner) महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय कर्टेल को मुख्यतः आठ श्रेणियों में विभाजित किया है । समुक्त राज्य अमरीका का लोचमत् कर्टेल्स का विरोध करता है । वहाँ रसायनिक एवं विद्युत उद्योगों में कर्टेल्स है, यही कारण है कि इन उद्योगों की भारी आलोचना की जाती है । अमेरिका के अर्थशास्त्रियों का एक समुदाय ऐसा है जिसके मतानुसार कर्टेल का प्रभाव अन्तिम रूप से एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक मिद्ध होता है । एक अमेरिकन विद्वान व्हिटलेसी (Whittlesey) का अनुसार कर्टेल्स के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

१. कर्टेल व्यवस्था स्वामित्व का विभाजित करके तथा लाभ प्राप्ति के स्वार्थ को देशभक्ति की भावना के ऊपर रख कर युद्धों को प्रोत्साहन देती है ।

२. कर्टेल व्यवस्था के अधीन उत्पादन तथा वितरण पर जो प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं उनके कारण एक देश किसी बड़े युद्ध के लिए उपयुक्त आवश्यक सामग्री से वंचित रह जायगा ।

३. कर्टेल एक गुप्तचर का काम करता है क्योंकि यह एक गुप्त अन्वेषण (Undercover agency) है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को एक देश में ले जाकर दूसरे ऐसे देश में भी पहुँचा सकता है जो उस देश का सम्भावित शत्रु हो ।

४. कर्टेल द्वारा विदेश में पूँजी लगाने की व्याज दर निश्चय कर दी जाती है और इस प्रकार तीसरा कोई देश वहाँ अपनी पूँजी नहीं लगा सकता ।

५. कर्टेल मुख्य रूप से सर्वाधिकारवादी राज्यों के विशेष औजार (Special Tool) है और इसलिए इनको वहिष्कृत किया जाना चाहिए ।

व्हिटलेसी (Whittlesey) महोदय कर्टेल के विरुद्ध लिए जाने वाले तर्कों की सत्यता स्वीकार नहीं करते । उनका मत है कि कर्टेल्स के द्वारा जहाँ राष्ट्रवाद का पृष्ठपोषण होता है वहाँ इससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है । जर्मन-कर्टेल के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क असल

मे वटेल-प्रवस्था के दोष नहीं हैं वरन् वे तो नाज़ी दल के शासन से उत्पन्न हो गयीं थुराईया हैं। वटेल व्यवस्था भेदिया अथवा गुप्तचर इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके द्वारा दी जाने वाली सूचना एकपक्षीय नहीं होती, यह दोनों ही देशों को परस्पर परिचित कराता है। व्हिटलेसी (Whittlesey) का विचार है कि वटेल अपने आप में एक बुराई नहीं होता वह तो एक साधन (Instrument) है जिसका प्रयोग अच्छे तथा बुरे दोनों ही लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है। यह मानना अनुचित रहेगा कि वटेल के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर बनाया जाता है।¹

(iii) अंतरसरकारी वस्तु समझौता

(Intergovernmental Commodity Agreement)

अन्तरसरकारी वस्तु समझौता एक देश विशेष को विश्व बाजार में एक निश्चित भाग (Definite Share) के लिए आश्वस्त (assure) करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य हमेशा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना होता है। ऐसे समझौते उपभोक्ताओं के हितों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। ये समझौते तभी किए जाते हैं जब किसी विशेष वस्तु का सामान्य रूप में अति-उत्पादन (Over Production) हुआ हो तथा उसे विनाशकारी प्रतिद्वन्द्विता से बचाना हो। ऐसे समझौते के अनेक रूप होते हैं। यदि ये समझौते सरकार द्वारा न किए जाकर व्यक्तियों द्वारा किए जायें तो इन्हें कार्टेल कहा जाएगा।

जब एक वस्तु अनेक देशों में पैदा की जाती है तो केवल एक देश अपनी कीमतों को स्थिर रखने में समर्थ नहीं हो सकता। मान लीजिए एक देश किसी वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दे अथवा उसके उत्पादन को सीमित कर दे तो दूसरे राज्यों द्वारा उत्पादित वही वस्तु बाजार में आयेगी और तब यह आवश्यक बने जाएगा कि वस्तु समझौता (Commodity agreement) किए जाए। अन्तरसरकारी वस्तु समझौता प्रायः कृषि एवं खनिज उत्पादनों पर ही किया जाता है। औद्योगिक उत्पादनों पर प्रायः यह लागू नहीं होता। इसका कारण यह है कि औद्योगिक उत्पादन कुछ थोड़े से व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से समझौते कर सकते हैं किन्तु कृषि एवं खनिज उत्पादन कार्य अनेक व्यक्तियों द्वारा किया

1 Whittlesey, Charles R., National Interest and International Cartels, 1946, P 36

(४) एक देश द्वारा निर्यात किए जाने वाले सामान की कीमत घटा दी गई है तो जो देश उस सामान का आयात कर रहा है उस देश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा तथा यह सम्भव है कि विरोध के रूप में वह दूसरा देश भी अपने निर्यात किए जाने वाले सामान की कीमत घटा दे।

(५) विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भी एक देश द्वारा डम्पिंग (Dumping) की व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी तथा जापान ने ऐसा ही किया था। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य के कारण हो सकते हैं जैसे कि-सैनिक तैयारियों के लिए, फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कुशल मजदूर रखने के लिए, तकनीकी शोध कार्य के लिए आदि।

डम्पिंग यदि दीर्घकाल के लिए किया जा रहा हो तो यह उचित रहेगा कि विदेशी माल के आयात पर शुल्क (Tariff) लगा दिया जाय। इसी प्रकार निर्यात-पारितोषिक (Export-bounties) का भी मारी महत्व है। विनर (Viner) के मतानुसार “आज की प्रतियोगितापूर्ण परिस्थितियों में बिना निर्यात-पारितोषिकों के एक दीर्घकालीन व्यवस्थित डम्पिंग के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।”¹ डम्पिंग व्यवस्था के अन्तर्गत जो देश माल का आयात कर रहा है उस देश के स्वामीय उद्योग एवं कारखाने प्रतियोगिता में निष्ठ हो जायेंगे। यद्यपि उस देश के करोड़ों लोग इस लाभान्वित अवश्य होंगे किन्तु स्वामीय कारखानों पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक बन जायेगा।

(४) पहले से ही माल खरीद लेना
(Pre-emptive Buying)

इस प्रक्रिया के अधीन उद्योग देश के सामान को इसलिए खरीद लिया जाता है ताकि वह शत्रु के हाथों न पड़ने पायें। ऐसा सामान खरीदते समय उसके व्यापारिक पक्षधरों का भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार की खरीद प्रायः युद्ध और सन्धि के दौरान ही की जाती है तथा इसका मूल उद्देश्य शत्रु को आवश्यक सामान से वंचित करना होता है। पॉल एन्जिग (Paul Einzig) ने लिखा है कि “ज्यों ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ

1 Viner, Jacob, Dumping : A problem in International Trade, 1923, P. 93

मे भारतीय निवास करते हैं। इन विदेशी राष्ट्रीयता वाले लोगों की जो सम्पत्ति होती है वह उनकी स्वयं की व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है। जिस राष्ट्र में वे रह रहे हैं उसका अधिकार है कि वह इस सम्पत्ति को छीन ले। राज्य का यह व्यवहार दूसरे राष्ट्रों की सम्पत्ति पर नियन्त्रण कर लेना माना जायगा क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से यह सम्पत्ति उस राष्ट्र की थी जिस राष्ट्रीयता का वह व्यक्ति था। यह सम्पत्ति माल, ऋण, कोयला घन, बीमा पॉलिसी आदि अनेक रूपों में हो सकती है।

सम्पत्ति के अपहरण की यह परम्परा तेरहवीं शताब्दी तक सामान्य मानी जाती थी किन्तु बाद में दूसरी राष्ट्रीयता वालों को कुछ स्वतन्त्रताएँ (immunity) प्रदान की गयीं जिनमें उनको सम्पत्ति रखने का अधिकार था। सन् १६१७ ई० से पूर्व अमरीका द्वारा किसी भी युद्ध में सम्पत्ति के अपहरण को मान्यता नहीं दी गई किन्तु प्रथम विश्व युद्ध के बाद वासाय की सन्धि (Treaty of Versailles) के अधीन यह व्यवस्था की गई थी कि भिन्न राष्ट्र अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में बसने वाले सभी जर्मन राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों की सम्पत्ति का अपहरण कर सकते हैं तथा जर्मनी का यह उत्तरदायित्व माना गया कि ऐसे लोगों की वह क्षति पूरि करे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय डेनमार्क और नार्वे पर जर्मनी का हमला होने पर अमेरिका ने वहाँ के लोगों की सम्पत्ति को अपने में मिला लिया। कहा जाता है कि यह इसलिये किया गया था ताकि निरपराध तन्त्र्य लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। इसका कारण हिटलर को सम्भावित प्राप्ति (Potential gains) से वंचित रखना न था।

(viii) कर्जें तथा उपहार (Loans and Grants)

प्राचीनकाल से ही उपहार तथा कर्जें राज्यों के परस्पर सम्बन्धों की विशेषता बने हुए हैं। दो देशों की मंत्री को बढ़ाने में उपहारों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान युग में उपहार तथा कर्जें प्रतिदिन के व्यवहार की बात बनी गयी हैं। प्रत्येक देश एक देश से कर्जा और उपहार प्राप्त करता है और दूसरे देश को वह प्रदान भी कर देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कर्जें तथा उपहारों की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं—

१. ऐसे कर्जें या उपहार देने वाले राष्ट्र के तथा लेने वाले राष्ट्र के अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य कोई विशेष हो सकता है अथवा सामान्य। लेनदार और देनदार की बातें सीधी हो सकती हैं और किसी तीसरे राष्ट्र द्वारा भी उनके बीच सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।

२. जो कर्जा दिया जाता है उसकी वापसी प्रायः घन प्रथवा सामानों में न की जाकर सामान के रूप में की जाती है।

३. कर्ज देने वाला भी अपने देश के कारखानों के विकास की दृष्टि से कर्जा देता है। उसका दूसरा लक्ष्य अन्य देशों के साथ संबंधों बढ़ाना भी हो सकता है।

४. कर्जा जब दिया जाता है तो उस पर ब्याज बतना कम लिया जाता है कि इसे भी एक प्रकार का उपहार समझा जा सकता है। कर्जा विदेशी मुद्रा, मशीन, सामान, कच्चा माल आदि रूपों में दिया जा सकता है और इसका लक्ष्य दूसरे देश का औद्योगिक उद्योग एवं विकास योजनाओं को सफल बनाना होता है।

५. कभी-कभी कर्जा लेने वाले देश को कर्जों के प्रभाव में अपनी नीतियाँ बदलने के लिये मजबूर भी होना पड़ जाता है। कर्जा देने वाले देश तथा कर्जा लेने वाले देश के बीच यद्यपि मित्रता की भावनाएँ रहती हैं किन्तु यह मैत्री समान भावनाओं पर आधारित नहीं रहती बरन् ऊँच नीच के भावों का अस्तित्व रहता है।

६. कर्जा देने एवं उपहार प्रस्तुत करने के नाम पर कभी कभी एक देश दूसरे देश पर अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए भारत पाक संघर्ष के समय अमेरिका और ब्रिटेन के रुख को लिया जा सकता है। ब्रिटेन ने भारत को हथियार भेजना बन्द कर दिया क्योंकि भारत सरकार पाकिस्तान के सम्बन्ध में ब्रिटेन के बताये गये रुख को अपनाने के लिए तैयार न थी। अमेरिका ने भारत को गेहूँ भेजने के ऊपर शर्तें लगानी चाही तथा अन्न सञ्चय को दूर करने में सहायता देने के नाम पर भारत पर अपने कुछ निर्णय थोपने चाहे। किन्तु जब सम्बन्ध भारतीय जनता की प्रतिक्रिया को देखा तो उसे अपना रुख बदलना पड़ा।

अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए इस साधन का बहुत अधिक प्रयोग किया है। इसी कारण रुस ने इसी नीति को साम्राज्यवाद का ही एक बुरा रूप कहा है। विदेशों की सहायता करने के लिए अमेरिका द्वारा मार्शेल योजना, ट्रुमेन सहायता सिद्धांत, परस्परिक सहायता योजना आदि अपनाये गये हैं। अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर ही एक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अधिकारशी (Economic agencies) का समर्थन करता है। कुछ पारितोषिकों में एक देश कर्जा चुकाने से मना भी कर सकता है, उदाहरण के लिए सोवियत रुस ने उन सभी कर्जों का भुगतान करने से मना कर दिया जो कि 'जार' द्वारा लिए गये थे।

(ix) विनिमय नियन्त्रण
(Exchange Control)

प्रत्येक देश के पास उतनी विदेशी मुद्रा नहीं रहती जितनी कि उसके उपयोग के लिए आवश्यक होती है। इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि वह विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण रखे ताकि आयात व निर्यात के बीच सन्तुलन की स्थापना की जा सके। इसके लिए एक देश कुछ आयातों एवं निर्यातों का प्रोत्साहन देगा और दूसरों को हतोत्साहित (Discourage) करेगा। विनिमय नियन्त्रण के द्वारा एक देश अपनी पूँजी को विदेश जाने से रोक सकता है, वह अपनी मुद्रा की अधिक कीमत स्थिर कर सकता है और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को पृथक करके घरेलू योजनाओं (Domestic programmes) की सुरक्षा कर सकता है। क्रोसे (Krause) महोदय के विचारानुसार "पृथक करने की व्यवस्था के कारण विनिमय नियन्त्रण उन देशों के आर्थिक शस्त्रागार का प्रमुख हथियार रहा है जो योजनाबद्ध रूप से विकास करना चाहते हैं।"¹ विनिमय नियन्त्रण का सबसे अधिक प्रयोग स्टर्लिंग क्षेत्रों (वे देश जहाँ की मुद्रा ब्रिटिश पाउंड से जुड़ी हुई है) में किया गया है।

(x) आर्थिक सहायता
(Subsidies)

आर्थिक सहायता, जैसा कि पामर तथा परकिन्स का मत है, वह भुगतान है जिसका उद्देश्य देश में उत्पादन को तथा विदेश में उनकी विक्री को प्रोत्साहित करना होता है। इस सहायता का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत कुछ वसा ही प्रभाव होता है जैसा कि शुल्क (Tariff) का हुआ करता है। फिर भी दोनों का अपना अपना महत्व है। सरकार द्वारा देश के किसी कारखाने को आर्थिक सहायता प्रदान करके जब देश में और विदेशों में भागे बढ़ा दिया जायगा तो वह निश्चय ही दूसरे देशों के कारखानों के समक्ष एक प्रतियोगी के रूप में खड़ा हो जायगा तथा दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इनका घुरा असर पड़ेगा। डॉटी बन्धुओं के मतानुसार शुल्क (Tariff) और आर्थिक सहायता (Subsidy) के बीच का अन्तर यह है कि—"आर्थिक युद्ध (Economic warfare) में शुल्क का प्रयोग केवल आत्म-रक्षा के लिये किया जा सकता है किन्तु आर्थिक सहायता का उपयोग आक्रमण करने के लिए भी किया जा सकता है।" एक आक्रमणकारी हथियार होने के कारण

अधिक सहायता डम्पिंग (Dumping) के लिए वातावरण तैयार करती है किन्तु शुल्क (Tariff) द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता ।

(x) कोटा और लाइसेंस

[Quotas and Licenses]

जब एक सरकार आयात पर सीमा नियन्त्रण रखना चाहती है तो वह कोटा व्यवस्था को अपना लेती है । इस व्यवस्था के अधीन एक देश से आयात सभी देशों से आने वाले माल की एक सीमा निश्चित कर दी जाती है । कोटा व्यवस्था को इसलिए अपनाया जाता है ताकि देश के उत्पादकों की रक्षा की जा सके और यह व्यवस्था की जा सके कि देश का 'आयात' निर्यात की अपेक्षा अधिक न हो जाये, निर्यात व्यापार पर कोटा का प्रयोग प्रायः केवल युद्ध काल में ही किया जाता है । क्योंकि युद्ध काल में यह आदेश रहता है कि जिस देश को माल निर्यात किया जा रहा है वह उसी माल को शत्रु देश के लिए निर्यात न कर दे । आयात पर और भी अधिक नियन्त्रण लगाने के लिए लाइसेंस व्यवस्था को अपनाया जाता है । इस व्यवस्था के अधीन कोई भी दूसरा देश जब-जब निर्यात करना चाहेगा तब-तब उसे इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा । यह लाइसेंस देते समय एक देश उस समय की अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा । कोटा तथा लाइसेंस प्रणाली द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह को रोक दिया जाता है तथा इन व्यवस्थाओं की प्रतिश्रिया एवं विरोध बहुत जल्दी होता है । फिर भी दो महायुद्धों के बीच के समय में इन दोनों प्रणालियों का उपयोग काफी किया गया, मुख्य रूप से फ्रांस ने इनको खूब अपनाया है ।

(xi) वर्ग सूची

[Black lists]

इस साधन के अधीन एक देश द्वारा ऐसी सूची प्रसारित की जाती है जिसमें उन राष्ट्रों/राज्यों के नाम होते हैं जिनके साथ व्यापार को बहिष्कार करना हो । सूची में दिये गये नामों के साथ देश का कोई व्यक्ति या संस्था व्यापारिक सम्बन्ध नहीं रख सकता । उन सूचीबद्ध लोगों की संपत्ति का भी उस देश के द्वारा अन्वहरण कर लिया जाता है । इस सम्बन्ध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि वर्ग सूची किसी राज्य के सम्बन्ध में नहीं बनाई जाती किन्तु केवल व्यक्तिगत उद्योगों और व्यक्तियों पर ही लागू होती है ।

(xii) मूल्य निर्धारित करना
[Valorization]

सरकार जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाती है तो Valorization कहा जाता है। किन्तु, यहाँ इसका अर्थ केवल उसी वस्तु की कीमत बढ़ाने में सम्बन्धित है जिसकी कीमत बहुत अधिक गिर गई हो। ऐसा करने के लिए सरकार उस वस्तु को खरीद कर अपने पास रख लेती है अथवा उसके उत्पादन को कम कर देती है। अन्तर्संस्कारी वस्तु-समझौतों के प्रचलन के कारण अब इस साधन का प्रचलन अब महत्व बहुत कम हो गया है।

ऊपर जिन विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है उनको समय की आवश्यकता एवं परिस्थितियों की प्रकृति के अनुसार एक देश द्वारा अपनाया जाता है ताकि उसके स्वार्थों की पूर्ति हो सके। वैसे राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन केवल यही नहीं हैं जिनको कि वर्णित किया गया है वरन् इनके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं तथा समय-समय पर सरकारी द्वारा नये भी आविष्कृत कर लिये जाते हैं। दूसरे देशों को हानि पहुँचाने वाले आर्थिक साधनों को यद्यपि घुरा-मला कहा जाता है किन्तु फिर भी अनेक देशों द्वारा इनको अपनाया जाता है। यह तथ्य वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की एक प्रधान समस्या है। आजकल विश्व के अनेक राज्यों में मुख्य रूप से सर्वाधिकारवादो राज्यों में आर्थिक राष्ट्रवाद (Economic Nationalism) की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीयतावाद (Economic Internationalism) की तरफ भी कुछ प्रयास किये जा रहे हैं। दोनों प्रवृत्तियों में से विश्व किसका वरण करेगा इसका निर्णय भविष्य ही करेगा।

आज का विश्व एक परिवार के समान हो गया है। आवागमन एवं संचार के द्रुतगामी साधनों ने देशों की दूरी को बहुत कम कर दिया है। इस उत्तरोत्तर बढ़ते हुए निकटस्थ सम्बन्धों के कारण राष्ट्रीय नीति के साधनों के रूप में आर्थिक साधनों का महत्व जितना इस युग में है उतना शायद पहले कभी नहीं था। आर्थिक साधनों के महत्व का एक दूसरा कारण यह भी है कि अणुशक्ति ने युद्धों के रूप को परिवर्तित कर दिया है तथा आज के विध्वंसकारी शस्त्रों के रूप में कोई भी राष्ट्र सैनिक क्षय पेंच दिया कर अपने को शक्तिशाली सिद्ध करने का साहस सम्भवतः न करेगा। इसके लिए वह आर्थिक साधनों का आश्रय ले सकता है।

वैदेशिक आर्थिक सहायता [Foreign Economic Assistance]

आज के युग में विदेशी व्यापार, विदेशी सहायता एवं विदेशी व्यय की सीमाएं मिट गई हैं। ये सभी कार्य संचालन की दृष्टि से परस्पर गुंथ गए हैं। आर्थिक सहयोग से हमारा तात्पर्य एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को आर्थिक साधन प्रदान करने के प्रावधान से है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि होता है। यदि गैर सरकारी लोग लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विदेशों में पूंजी लगाते हैं तो यह उचित समझा जाएगा। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान ग्रेट ब्रिटेन का समुद्र पार का व्यापार ऐसा ही था। इन व्यापार के परिणामस्वरूप जो पूंजी ग्रेट ब्रिटेन को मिली तथा उसके हित जितने अधिक उत्तमोत्तम उनका ही उसे लाभ रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से विदेशी सहायता के तीन रूप रहे हैं। जो युद्ध से पीड़ित देश हैं उनको राहत एवं आर्थिक पुनर्निर्माण की जरूरत होती है। जो राष्ट्र उदित हो रहे हैं उनको अपने सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक आधुनिकीकरण के लिए सहायता की जरूरत रहनी है। तीसरे प्रकार के देश ऐसे होते हैं जिनको कि साम्यवादी दबावों का विरोध करने के लिए सहायता की जरूरत होती है या आन्तरिक उपद्रवों को दबाने के लिए सहायता आवश्यक होती है अथवा खराब फसल होने के कारण या कोई ऐसी घटना घटने के कारण जो उस राज्य के अधिकार के बाहर की चीज थी, सहायता आवश्यक होती है। सहायता के अन्तिम दो लक्ष्यों के बीच कभी कभी अन्तिम हो जाता है।

कुछ लोगों का यह तर्क है कि सहायता के आधार पर निरन्तर भिन्नता एवं समर्थन वायम नहीं किया जा सकता और न ही निश्चित रूप से देश का विकास सम्भव होता है। यह तर्क अधिक महत्व नहीं रखता क्योंकि शक्ति सम्बन्धों को आत्म हित के मापदण्ड से निर्देशित किया जाता है न कि परोपकार की भावना से सहायता कार्यक्रम द्वारा ऐसी घटनाओं को विकसित होने के लिए भी आमन्त्रित किया जाता है जो कि वैसे घटित नहीं होती।

संयुक्त राज्य अमरीका ने उपर्युक्त तीन उद्देश्यों से विदेशी सहायता प्रदान की है। सन् १९४५ से लेकर सन् १९५० तक संयुक्त राज्य अमरीका ने २० बिलियन डॉलर में अधिक धन पश्चिमी यूरोप की रचना में व्यय कर दिया। इसमें से अधिकांश राशि मार्शल योजना के अन्तर्गत राशि की गई। इस कार्यक्रम की सफलता के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार में बड़ी प्रतिक्रिया-

गिता हो गई है और पश्चिमी यूरोप अब इतना समर्थ हो गया है कि उदीयमान देशों के विकास में सहयोग दे सके। मार्शल योजना के अन्तर्गत जो सहयोग प्रदान किया गया उसमें अधिकतर छालर एवं पूंजीगत माल के आदान-प्रदान में ही था। तकनीकी सहायता की मात्रा बहुत कम थी क्योंकि पश्चिमी यूरोप के राज्यों में यह पहले से ही स्थित थी।

सन् १९५० के बाद से दी जाने वाली अधिकांश सहायता का रूप बदल गया है और अब यह अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों, विशेषकर विश्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती है। यह सहायता मुख्यतः विकासशील देशों को दी जाती है। इस सहायता में अनुदान की अपेक्षा ऋणों पर अधिक जोर दिया जाता है तथा इन देशों को दिए जाने वाले तकनीकी सहयोगों में अमरीकी सरकार, उसके कई गैर सरकारी अभिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण योगदान करते हैं। एक विकासशील देश में विभिन्न सहायता कार्यों का समन्वय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण किन्तु नई समस्या है।

सहायता प्रदान करने के तरीके विभिन्न प्रकार के होने हैं। कुछ उदाहरणों में एक सहायता देने वाला देश किसी बहु उद्देश्यीय अभिकरण को योगदान दे सकता है, जैसे, अन्तर-अमरीकी विकास बैंक को, जो कि बाद में अन्य देशों को कर्जा देती है। कोई देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के अभिकरण को भी सहायता प्रदान कर सकता है जो बाद में अन्य देशों को तकनीकी सहयोग दे। सहायता करने वाला देश प्रत्यक्ष रूप से भी अन्य देशों की सहायता कर सकता है अथवा वह सहायता देने वाले कुछ देशों के साथ मिलकर ऐसा कर सकता है। दक्षिण एशिया के लिए बोमबो योजना कुछ इसी प्रकार की सहायता का उदाहरण है। सहायता करने वाले देश अब अनुदान एवं ऋण के व्यवस्थापन को सामान्यतः अपने उत्पादन के साथ जोड़ देते हैं। किन्तु जो घन अनेक देशों द्वारा मिल कर दिया जाता है उसे इस प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता। सहायता प्राप्त करने वाला देश उस घन को किसी भी काम के लिए प्रयुक्त कर सकता है जैसे कि तैयार माल का आयात करने के लिए, स्कूलों और अस्पतालों के लिए, संचार व्यवस्था की रचना के लिए, नए उद्योगों की रचना के लिए, शिक्षा एवं मानवीय कुशलता के विकास के लिए, प्रादि प्रादि। घन की दृष्टि से नापने पर यह कहा जा सकता है कि विदेशी सहायता एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बन गया है। इससे राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों पर पर्याप्त प्रभाव डाला जाता है।

सहायता के कर्ता एवं रूप

सन् १९६३ में उदीयमान स्वतन्त्र दुनिया के राज्यों ने ऋण तथा अनुदान के रूप में ८१ बिलियन डालर की आर्थिक सहायता प्राप्त की। इसमें से ६० प्रतिशत सहयोग समुदाय राज्य अमरीका द्वारा किया गया, चार बिलियन पौण्ड द्विपक्षीय आधार पर दिया गया और १४ बिलियन डालर का अनुपात अन्तराष्ट्रीय समिकरणों द्वारा प्रदान किया गया। अन्य विकसित देशों ने २.७ बिलियन डालर सहायता के रूप में प्रदान किए। इनमें से अधिकांश ने विकास परामर्शदाता समिति के साथ मिल कर कार्य किया। समुक्त राज्य अमरीका ने लगभग एक बिलियन डालर सैनिक सहायता के रूप में खर्च किए। केवल साट्विकीय के आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक देश से स्थायित्व की रक्षा के लिए कुछ अल्पकालीन ऋण भी होते हैं। जो देश सहायता प्राप्त करते हैं उन पर विदेशी वजों का पर्याप्त भार बढ़ जाता है और भुगतान की समस्या खड़ी होती है। व्याज तथा भुगतान के रूप में इन देशों को अपनी विदेशी मुद्रा की आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग देना होता है।

विदेशी सहायता केवल धन के ही रूप में नहीं दी जाती बरिक्त जिन विद्याथियों, प्रशासकों एवं तकनीकी परामर्शदाताओं को प्रशिक्षित किया जाता है वे जब स्वदेश लौट कर जाते हैं तो आर्थिक सहायता से किमी भी प्रकार कम नहीं होते। विकसित देश अपने तकनीकी विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों को दूसरे देशों के विकास में सहायता देने के लिए भेजते रहते हैं। सन् १९६४ में लगभग १४५०० तकनीकी विशेषज्ञ करीब ३० देशों में कार्य कर रहे थे तथा हजारों विदेशी छात्र वजीफे के आधार पर साम्यवादी देशों में अध्ययन कर रहे थे। साम्यवादी चीन ने अफ्रीका तथा दुनिया के अन्य भागों में अपने सहायता कार्यक्रम को पर्याप्त व्यापक बना दिया है परन्तु उसने सहायता कार्यक्रमों को जिस प्रकार राजनैतिक लक्ष्यों के लिए प्रयुक्त किया है बड़े घटिया दर्जे के थे और इसीलिए यह कार्यक्रम वांछित रूप में फलदायक न बन सका। समुक्त राष्ट्र सभ के समिकरण भी विकासशील देशों में अपने हजारों प्रतिनिधि भेजते हैं। समुक्त राष्ट्र सभ के १८००० कार्यकर्ताओं में से करीब १६००० कार्यकर्ता सामाजिक एवं आर्थिक क्रियाओं में सलग्न हैं। सन् १९५५ में समुक्त राज्य अमरीका ७० देशों को सहायता प्रणय कर रहा था। उसका अधिकांश व्यय एक दर्जन देशों में केन्द्रित था और शेष ५८ देशों में आर्थिक मिशन कार्य कर रहे थे। समुक्त राज्य अमरीका के कितने लोग सहायता कार्यक्रमों में

विदेशों में कार्य कर रहे हैं इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। किन्तु यह तो निश्चित है कि यह सबका साम्यवादी देशों की तुलना में अधिक है।

सहायता का उद्देश्य

व्यक्तिगत जीवन की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी परस्परकार, सहायता और सहज्यता का स्थान होना है। जिस रूप में विदेशी सहायता हो जाती है उससे ऐसा लगता है कि सहायता देने वाला देश मुक्त-मानवीयता को ध्यान में रख कर ऐसा कर रहा है। सहायता का कार्य विकसित देश की अनिच्छित उत्पत्ति की समस्या को सुलझाना है। इनके अनिच्छित जब एक विकसित देश दूसरे देश के विकास के लिए कुछ धन प्रदान कर देता है तो इससे उसके सामान की सप्लाई के लिए दीर्घकाल तक बाजार भिन्न जाते हैं। यह कारण एक तत्पक्ष होते हुए भी सहायता देने का मुख्य कारण नहीं समझा जाता। कहते हैं कि सहायता का मुख्य कारण राजनैतिक है। उदीयमान राज्य शीघ्रता के साथ आधुनिकीकरण चाहते हैं। इनमें से अविश्वसनीय की स्थिति आन्तरिकारी है, अन्तर्भावित है और खतरनाक हो सकती है। समुक्त राज्य अमेरिका एवं कुछ विकसित देश यह मानते हैं कि विदेशी सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से आवश्यक है। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उदीयमान देशों के सम्बन्ध में साम्यवादी तथा पश्चिमी शक्तियों के बीच जो प्रतिद्वन्द्विता है तथा साम्यवादी गुट में जो सघर्ष है उसने विदेश नीति के इस साधन की अवहेलना करना महाशक्तियों के लिए अवाञ्छनीय बना दिया है। राष्ट्रपति कनेडी ने २५ मई, १९६१ को कांग्रेस को दिए गए अपने संबोधन में यह कहा था कि आज स्वतन्त्रता के प्रचार एवं सुरक्षा के लिए बड़ी युद्धभूमि दुनिया का सम्पूर्ण दक्षिणी भाग अर्थात् एशिया, सेंटिनल अमेरिका, अफ्रीका और मध्यपूर्व हैं जो उठने हुए लोगों की भूमि हैं। उनकी भाँति मानव इतिहास में महान है।^१

इस प्रकार विश्व में सघर्ष का रूप बदल गया है। आज के दिनों में अफ्रीका के साधनों में हम हथियार, दवा करने वाले, सहायता, विद्येपत्र, प्रचार, सरकार को बदलना, आग्नि के लिए सघर्षन, आदि मावनों को ले सकते हैं। इन सभी हथियारों से युक्त साम्यवादी देश अपने प्रदेशों की एकीकृत करने की योजना बनाते हैं ताकि नए राष्ट्रीय का शोषण कर सकें उन

1. President John F. Kennedy, in a message to Congress on May 25, 1961.

पर नियन्त्रण रख सकें और अन्त में उनकी आशाओं को समाप्त कर सकें। साम्यवादियों का कार्यक्रम है कि शीघ्र ही अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करें। इन सघर्ष से कोई भी बड़ी शक्ति अपने आपको अलग नहीं रख सकती।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा संचालित विदेशी सहायता कार्यक्रम पर अमरीकी जनमत का पर्याप्त प्रभाव है। वहाँ का जनमत इस कार्यक्रम के अधिक पक्ष में नहीं है। भालोचनाओं एवं विरोधों के कारण यह अलोकप्रिय एवं अकार की दृष्टि से सीमित है। जनता दग बात पर विचार नहीं करती कि सहायता कार्यक्रम मुख्य रूप से कज होता है और इनसे उन वस्तुओं की माग भी पूरी हो जाती है जो कि वैसे खरीदनी पड़ती। जो लोग सहायता कार्यक्रम के सही रूप को समझते हैं वे इसे विदेश नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। एक बार राज्य सचिव डीन रस्क ने सदन की विदेशी मामलों की समिति को यह कहा था कि आर्थिक सहायता संयुक्त राज्य अमरीका की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित के लिए मूल तत्व है। इसके बिना अधिकांश देश निश्चय ही पिछनी दो दशाब्दियों में साम्यवादी बन गये होते और इस प्रकार सारतन्त्रता की सीमायें बहुत सकरी बन जानी तथा अमरीकी लोग कम स्थिर एवं अत्यधिक चुनौतीपूर्ण दुनिया में निवास करते।¹

विदेशी सहायता कार्यक्रम के माध्यम से कोई देश सहायता प्राप्त करने वाले देश की स्याई गिनता की आशा नहीं कर सकता। पश्चिमी शक्तियों एवं साम्यवादी देशों का इस सम्बन्ध में एक जैसा अनुभव है। इण्डोनेशिया को चीन तथा सोवियन संघ की पूरी सहायता मिल रही थी किन्तु फिर भी वहाँ सन् १९६५ में साम्यवादी दल को दवा दिया गया और इण्डोनेशिया ने ३१ अक्टूबर, १९६७ को अपना अन्तिम राजनयिक कर्मचारी भी चीन से वापस बुला लिया। वर्मा के सम्बन्ध में भी चीन को ऐसे ही अनुभव प्राप्त हुए और इनके कारण उसे अपने तकनीकी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों को वापस स्वदेश बुलाने का निर्णय लेना पड़ा। साम्यवादी चीन के अनेक अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं को कई अफ्रीकी देशों ने अपने देश से निकाल दिया यद्यपि ये देश चीनी सहायता प्राप्त कर रहे थे।

जब सहायता कार्यक्रम का रूप निर्धारित किया जाता है तथा उनका संचालन किया जाता है तो अनेक विकल्प सामने आते हैं जिनके सम्बन्ध में

कोई निश्चित सूत्र नहीं है। किसी देश को सहायता दी जाए या नहीं दी जाए?, सहायता का अनुपात कम हो या अधिक हो?, कम समय के कर्ज पर अधिक जोर दिया जाए या अधिक समय के कर्ज पर?, व्यक्तिगत लागत एवं व्यक्तिगत उद्यम को प्राप्ताह्न देने के लिए विशेष प्रयास किए जायें अथवा न किए जायें?, क्या सहायता कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दूसरों से प्रतियोगिता करनी चाहिए?, ये अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर निश्चिन्त रूप से देना बड़ा कठिन है। एक समस्या यह भी उठती है कि सहायता कार्यक्रम के प्रभाव को कैसे नापा जाए तथा प्राथमिकतायें कैसे तय की जायें। कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ राजनैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों द्वारा तय की जा सकती है जिसे नापा नहीं जा सकता।

आर्थिक युद्ध (Economic Warfare)

एक देश अपने आर्थिक साधनों का प्रयोग जब दूसरे विरोधी राज्य की सम्भावित एवं वास्तविक शक्ति को कम करने का प्रयास करता है तो उसे हम प्रायः आर्थिक युद्ध का नाम देते हैं। इस प्रकार से सघर्ष परम्परागत रूप से होने रहे हैं इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। इस सम्बन्ध में वनामविज का यह कहना अत्यन्त तथ्य मगत प्रतीत होता है कि शान्तिकाल में अपने शत्रु को कूटनीति और व्यापार द्वारा निःशस्त्र बना दो तब उसे तुम युद्ध के मैदान में आसानी से जीत सोगे। प्रत्येक राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सम्मान बुझान से लेकर हिंसात्मक साधनों तक प्रत्येक कदम को अपना सकता है। आर्थिक तकनीकों तथा प्रसाधन इन तरीकों के बीच में ही स्थान रखते हैं। आर्थिक साधन जैसे किसी देश की सहायता के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं वैसे किसी के विरुद्ध भी काम में लाये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि अन्तर्राष्ट्रीय मानदरी फण्ड (International Monetary Fund) एक देश में विनिमय की मात्रा को आर्थिक मुद्दों से जोड़ सकता है किन्तु यदि एक देश से इस प्रकार की साख को रोक दिया जाए तो यह उस देश के विरुद्ध आर्थिक दबाव कहलाएगा और स्पष्ट रूप से आर्थिक युद्ध की परिभाषा में आएगा। आर्थिक दबाव एक देश की आर्थिक स्थिति एवं सामर्थ्य को कमजोर बना देते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व दुनिया के देश आर्थिक दबावों की प्रभाव-शीलता को बहुत महत्व देते थे। सन् १९३५ में राष्ट्रमण्ड ने इटली के विरुद्ध आर्थिक दबाव लगाये क्योंकि उसने इथोपिया के विरुद्ध आक्रमण कर दिया

था। किन्तु ये दबाव प्रभावहीन रहे। ऐसे ही दबाव समुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा द्वारा सन् १९५१ में साम्यवादी चीन के विरुद्ध लगाए गए जब कि उसने कोरिया पर आक्रमण किया। ये दोनों ही दबाव प्रभावहीन रहे। ग्रेट ब्रिटेन ने सन् १९६५ में रोडेशिया पर आर्थिक दबाव लगाए और समुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य कुछ देशों ने उसका सहयोग दिया। केवल कागजी रूप से बेराबन्दी उस समय तक प्रभावहीन रहती है जब तक कि इसका समर्थन करने वाले एक या अधिक राज्य उस देश के महत्वपूर्ण आर्थिक प्रान्तों के स्वामी न हों, जैसे—तेल, हथियार, खाद्य सामग्री आदि।

आर्थिक दबाव किसी देश के विरुद्ध केवल सीमित प्रभाव ही डाल पाते हैं। ये केवल थोड़े समय तक ही प्रभावशाली रहते हैं और बाद में मित्र राष्ट्रों के समूह के बीच अनक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। सम्बन्धित देश यह सोचते हैं कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। व्यापारिक लेन-देन के सन्तुलन की प्राथमिकता दी जाती है और इन दबावों की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में सन्देहशील दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में धीरे-धीरे इन दबावों की प्रभावशीलता कम हो जाती है। पैडिन्फोर्ड तथा लिस्नका यह कथन उपयुक्त है कि शान्तिकालीन आर्थिक युद्ध की प्रकृति सम्बद्ध रहनी चाहिए, इसमें पर्याप्त कूटनीति एवं समायोजन की आवश्यकता है तथा यह देखना जरूरी है कि बढ़ते हुए मनमुटावों का लाभ हो रहा है या नहीं।

साम्राज्यवाद-उपनिवेशवाद (Imperialism-Colonialism)

समाजवाद की भांति साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की तुलना एक ऐसे टोप से की जा सकती है जिसे हर कोई पहन लेता है और इस कारण उसका रूप एवं आकार निश्चिन् नही रह गया है। इन पदों का अर्थ तथा रूप समय और स्थान (Time and Space) के साथ-साथ परिवर्तित होना रहा है। किसी समय साम्राज्यवादी और उपनिवेशवाद को प्रशंसित दृष्टि से देखा जाता था, साम्राज्यवादी देश को विश्व के कल्याण का प्रतीक माना जाता था किन्तु आज इसे हेय-समझा-जाता है। आज के प्रजातन्त्रवादी युग के प्राण 'स्वतन्त्रता और समानता' (Liberty and Equality) में हैं इसलिए एक देश की नीतियों को साम्राज्यवादी अथवा विस्तारवादी कहना उनकी सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है। पहले तो

दूसरे देशों की भूमि को अधिकृत कर लेना ही साम्राज्यवाद कहा जाता था किन्तु आजकल एक देश का दूसरे देश पर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रभाव भी साम्राज्यवाद की परिधि में समाविष्ट किया जाता है। यद्यपि साम्राज्यवाद के स्वरूप, उद्देश्य, साधन एवं परिणामों के बारे में विचारकों के बीच भारी मतभेद है किन्तु इस बात को प्रायः वे सभी स्वीकार करते हैं कि यह राष्ट्रीय हित की प्राप्ति का एक प्रभावशाली साधन रहा है और आज भी है। साम्राज्यवाद का गुलुगुलान करने वाले विचारक एक देश की सड़क, स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य शानन, व्यापार आदि उपलब्धियों का चित्रण करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि एक देश ये सभी चीजें सभी प्राप्त कर सका जबकि वह एक बड़े साम्राज्य का एक भाग बना। दूसरी ओर साम्राज्यवाद के प्रालोचक इसे युद्ध, शोषण, श्रमरता, दुःख, अमानवीयता, घृणा आदि के विशेषण प्रदान करते हैं। साम्राज्यवाद के रूप को समझने के लिए यह उपयोगी रहेगा कि भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा इसकी जो परिभाषायें दी गई हैं उनका प्रयत्नकन किया जाय।

साम्राज्यवाद की परिभाषायें (Definitions of Imperialism)

साम्राज्यवाद के लक्ष्य का वर्णन करते हुए बोन (Bonn) महानगर ने बताया है कि साम्राज्यवाद वह नीति है जिसका उद्देश्य साम्राज्य स्थापित करना संगठित करना और बनाये रखना होता है। साम्राज्य एक बड़े आकार का राज्य होता है जिसमें अनेक राष्ट्रीयताओं वाले लोग निवास करते हैं तथा जिस पर एक केन्द्रीय इच्छा (Central will) शासन करती है। सी० डी० बर्न्स (C D Burns) ने साम्राज्यवाद को विश्व सरकार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना है। उनके कथनानुसार साम्राज्यवाद उस सामान्य पद्धति को कहा जाता है जिसके अनुसार अनेक देशों में कानून बनाये जाते हैं और शासन किया जाता है। वह क्षेत्रीय राष्ट्रीयता (Regional nationality) के दोषों को दूर करना है, उनसे ऊपर उठना है। प्रसल में 'साम्राज्यवाद' क्षेत्रीय राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता (Internationalism) के बीच की स्थिति है। शूमान (Schuman) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों का विचार इससे भिन्न है। उनके मतानुसार हम चाहें कितने ही महान् बनायें और नीतिकता का चाहें जितना ही ठोस पीटें किन्तु सत्य तो यह है कि अघोषित देशों पर शक्ति और हिमा के बल

पर विदेशी राज्य स्थापित रखना साम्राज्यवाद है। एक देश साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाने समय किसी परोपकारी वृत्ति या मानवतावादी भावना से प्रभावित नहीं होता बल्कि उसका राष्ट्रीय स्वार्थ ही सदैव उसके ध्यान में रहता है। बीयर्ड (Beard) का मत है कि साम्राज्यवाद यह होता है जब कि एक देश की सरकार एवं कूटनीति की मखौन दूसरी जाति के लोगों के प्रदेशों (Territories), रक्षित राज्यों (Protectorates) तथा प्रभाव के क्षेत्रों (Spheres of influence) को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाती है और औद्योगिक, व्यापारिक एवं धन लगाने के अवसरों को बढ़ाने का कार्य करती है। एक अन्य विचारक मून (Parker T. Moon) के द्वारा दी गई परिभाषा में साम्राज्यवाद के जाति पक्ष की ओर अधिक जोर दिया गया है।

उक्त परिभाषाओं में साम्राज्यवाद की जिन विशेषताओं को प्रमुख माना गया है वे हैं—व्यापिक लक्ष्यों की प्राप्ति, बड़ा प्रदेश प्राप्त करना, दूसरी जातियों पर शासन करना आदि। मॉर्गेन्थौ (Morgenthau) महोदय ने इन सभी विशेषताओं को ओख माना है। उनका विचार है कि एक देश द्वारा अपने राज्य की सीमाओं से बाहर शक्ति का विस्तार ही साम्राज्यवाद है। एक अन्य विचारक बुखारिन (Bukharin) का कहना है कि साम्राज्यवाद में दूसरे देशों को जीतने का प्रयास निहित रहता है किन्तु दूसरे देशों को जीतने की नीति को ही हम साम्राज्यवाद नहीं कह सकते।¹

शुम्पेटर (Schumpeter) महोदय का विचार है कि साम्राज्यवाद का कोई सचेतन लक्ष्य नहीं होता तथा इसके उद्देश्यों की परिभाषा भी नहीं की जा सकती। किन्तु इसके विपरीत विन्सलो (Winslow) ने साम्राज्यवाद के संगठन तथा उसके विशेष उद्देश्यों का वर्णन किया है। उसकी परिभाषा के अनुसार साम्राज्यवाद एक बुराई है। बूएल (Buell) महोदय भी साम्राज्यवाद को अच्छी निगाह से नहीं देखते। उनका कहना है कि एक सरकार से दूसरी सरकार द्वारा दी गई प्रत्येक अन्यायपूर्ण मांग तथा प्रत्येक आक्रमणकारी युद्ध को साम्राज्यवादी कहा जाता है। 'साम्राज्यवाद' एक ऐसा शब्द है जिसमें अनेकों पाप समाहित हैं।²

1. N I. Bukharin, Imperialism and world economy. 1929, P. 114.
2. Raymond L Buell, International Relations, P. 305.

साम्राज्यवाद के अर्थ की समस्या

(The problem of the meaning of imperialism)

साम्राज्यवाद से सम्बन्धित अनेक परिभाषाओं के अवलोकन के बाद यह कहा जा सकता है कि इस शब्द का प्रयोग विचारकों द्वारा अपने-तकों अथवा अपने राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से विभिन्न अर्थों में किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि साम्राज्यवाद शब्द अनेक सही अर्थ खो बैठा। आज किसी भी देश को आप साम्राज्यवादी कह सकते हैं, यदि उसकी विदेश नीति आपके देश की विदेश नीति के विपरीत पड़ती हो। मून (Parker Thomas Moon) ने 'साम्राज्यवाद' शब्द को उपनिवेशी विस्तार का समानार्थक माना है। किन्तु यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि आखिर उपनिवेशी विस्तार (Colonial expansion) शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, क्योंकि विस्तार के सैनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि रूप होते हैं।

मार्गेन्थो (Morgenthau) महाशय का कहना है कि साम्राज्यवाद का सही अर्थ जानने से पूर्व यह आवश्यक है कि उससे सम्बन्धित भ्रान्तियों का निवारण कर लिया जाय। उनके मतानुसार प्रत्येक विदेश नीति जिसका उद्देश्य एक राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना है, आवश्यक रूप से साम्राज्यवाद का प्रदर्शन नहीं करती। केवल उसी नीति को साम्राज्यवादी कहा जा सकता है जो वस्तुस्थिति (Statusquo) को नष्ट भ्रष्ट करने का लक्ष्य रखती है। इस प्रकार वे लोग भ्रम में हैं जो यह मानते हैं कि अपनी शक्ति को बढ़ाने वाला देश साम्राज्यवादी है। दूसरे वे लोग भी भ्रम में हैं जो कि पहले से ही स्थित साम्राज्य की रक्षा करने वाली विदेश नीति को साम्राज्यवादी कहते हैं। मार्गेन्थो (Morgenthau) का विचार है कि साम्राज्यवाद की प्रकृति गत्यात्मक (Dynamic) होती है किन्तु पूर्व स्थित साम्राज्य की रक्षा करने वाली नीति में इस प्रकृति का आभास नहीं होता। अतः इस नीति को हम रुढ़िवादी कह सकते हैं न कि 'साम्राज्यवादी'। साम्राज्य (Empire) की रक्षा और एकीकरण (Consolidation) तो एक चीज है तथा साम्राज्यवाद दूसरी। दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। सन् १९४२ में चर्चिल ने जब ब्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने को मना कर दिया तो वह उसकी साम्राज्यवादी नीति का नहीं किन्तु रुढ़िवादी नीति का परिचायक था।

साम्राज्यवाद के स्वरूप से सम्बन्धित तीन मुख्य विचारधाराएँ हैं। प्रथम मार्क्सवाद विचारधारा है जो पूँजीवाद को मुख्य बुराई मानती है।

तथा साम्राज्यवाद को उन्ही का आवश्यक या सम्भावित परिणाम। दूसरी ओर होम्स जैसे उदार विचारक हैं जो यह मानते हैं कि 'साम्राज्यवाद' पूँजीवाद का आवश्यक परिणाम नहीं है क्योंकि पूँजीवाद के सम्मुख अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। तीसरी विचारधारा शंनान विचारधारा (Devil theory) है जिसके अनुसार युद्ध के कारण जिन समुदायों या व्यक्तियों को लाभ होता है वे सदैव युद्ध को प्रोत्साहन देने रहते हैं ताकि वे स्वयं सम्पन्न बन सकें। इन युद्धों का परिणाम ही साम्राज्यवाद है। ये तीनों ही विचारधारयों एकपक्षीयता (One sidedness) के दोष से दूषित हैं। 'साम्राज्यवाद' असल में एक राजनैतिक तत्त्व है और जैसा कि कुछ विचारकों का कहना है, इसको आर्थिक रूप देने का असफल प्रयास इन विचारधारायों द्वारा किया गया है।

साम्राज्यवाद सम्बन्धी कुछ निष्कर्ष

(Some conclusions about Imperialism)

'साम्राज्यवाद क्या है' शीपेंक के नीचे अमरीकी विद्वान पामर तथा परकिन्स का प्रथम वाक्य यह है कि हम साम्राज्यवाद पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, इसका विरोध कर सकते हैं, इसका समर्थन कर सकते हैं और इसके पीछे प्राण भी दे सकते हैं किन्तु इसकी ऐसी कोई परिभाषा नहीं दे सकते जो सर्वमान्य हो। कोई सर्वमान्य परिभाषा देना आज इस कारण भी असम्भव बन गया है क्योंकि साम्राज्यवाद का वर्तमान रूप पहले रूप से भिन्न है। साम्राज्यवाद के इन विभिन्न रूपों को एक परिभाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता किन्तु विभिन्न परिभाषायों तथा साम्राज्यवाद के वास्तविक व्यवहार को देख कर इसकी कुछ विशेषतायें बताई जा सकती हैं; जो निम्न प्रकार हैं—

(१) 'साम्राज्यवाद' शब्द विषयगत (Subjective) है और इसीलिए विचारक अपनी इच्छानुसार जैसी चाहते हैं इसकी परिभाषा दे देते हैं।

(२) 'साम्राज्यवाद' शब्द अपने विरोधी देशों की नीतियों की भालोचना करने का एक साधन बन गया है।

(३) साम्राज्यवाद की कुछ अवसरगत विशेषतायें जैसे आर्थिक लाभ का लक्ष्य, क्षेत्र का विस्तार, दूसरी जातियों पर शासन, एक मुनियोजित कार्यक्रम आदि। ये विशेषतायें प्रायः साम्राज्यवाद के साथ रहती हैं किन्तु साम्राज्यवाद इनके बिना भी रह सकता है।

(४) साम्राज्यवाद नैतिक दृष्टि से शून्य होता है। यह राष्ट्रीय नीतियों का एक ऐसा साधन है जिसका उद्देश्य बुरा भी हो सकता है और

अच्छा भी। हो सकता है कि साम्राज्यवाद के अधीनस्थ देश अधिक, राजनैतिक सामाजिक, सामूहिक आदि क्षेत्रों में पर्याप्त विनाश करें और यह भी सम्भव है कि साम्राज्यवादी देश द्वारा अधीनस्थ लोगों का शोषण किया जाय उनका दमन किया जाय तथा उनकी सम्पत्ता और सभ्यता के विकास को रोक दिया जाय। पामर तथा परकिंस के मतानुसार साम्राज्यवाद तो शक्ति सम्बन्धों का उच्च और अधीनस्थ के बीच के सम्बन्धों का नाम है नतिजता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(५) साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने वाले तत्त्व मार्गों को के मतानुसार तीन हैं। पहला तत्त्व वे अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियाँ हैं जो युद्ध के बाद शांति स्थापना के की जाती हैं तथा जिनके द्वारा युद्ध से पूर्व की स्थिति को पुनर्निर्धारित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए वार्सा की सन्धि का नाम लिया जा सकता है। दूसरा तत्त्व वह प्रयास है जो कुछ राष्ट्रों को स्थायी रूप से अधीन (Subordinate) बनाये रखने के लिए किया जाता है। ऐसे प्रयासों की प्रतिक्रिया यह होती है कि हारा हुआ राष्ट्र अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने की कोशिशें करता है। फलतः उसकी नीति साम्राज्यवादी हो जाती है। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देने वाला तीसरा तत्त्व कमजोर एवं राजनैतिक शक्ति से हीन राज्यों का अस्तित्व है। ऐसे राज्य शक्तिशाली राज्यों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं ठीक उसी प्रकार जैसा कि 'शव' द्वारा गिद्धों को आकर्षित किया जाता है। ये तीनों ही तत्त्व ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं जिनमें साम्राज्यवाद की नीतियाँ बनती क्रियान्वित होती तथा सकल हाती हैं।

साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद (Imperialism, Colonialism and Nationalism)

साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के बीच का अन्तर इतना कम है कि प्रायः एक के लिए दूसरे का प्रयोग कर दिया जाता है। हॉब्सन (Hobson) महोदय ने साम्राज्यवाद विषयक अपनी पुस्तक में साम्राज्यवाद की जो परिभाषा दी है वह असल में उपनिवेशवाद पर अधिक लागू होनी है। उनके मतानुसार 'उपनिवेशवाद अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में राष्ट्रियता का स्वाभाविक अतिप्रवाह (Overflow) है। इसकी परीक्षा उपनिवेशियों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे अपनी सम्पत्ता का अपने नवीन सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाल सकें।' साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का ही एक

रूप समझा जाता है किन्तु यह उपनिवेशवाद की तुलना में अधिक सगठित होता है, अधिक सैनिक होता है, निर्यत रूप से अधिक भाष्यकारी होता है तथा विभिन्न उद्देश्यों में पूर्ण होता है। इतने मन्त्रों के रहते हुए भी व्यावहारिक जगत में इन दोनों के बीच एक विनाशक रेखा सीधना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। इन दोनों ही पक्षों का प्रयोग उच्च तथा होन का सम्बन्ध (Superior-inferior Relationship) बनाने के लिए किया जाता है।

सिद्धान्त रूप में यदि देखा जाये तो राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद के बीच विरोध रहता है, क्योंकि साम्राज्यवाद दूसरे देशों को पराधीनता के पाश से जकड़ता है जबकि राष्ट्रीयता प्रत्येक देश को स्वतन्त्र रहने की प्रोत्साहित करती है। किन्तु "प्रश्न" में पराधीन देश स्वतन्त्र होने के बाद जब शक्तिशाली बन जाता है तो प्रायः साम्राज्य निर्माण के स्वप्न देखना प्रारम्भ कर देता है। पराधीन राष्ट्रों में साम्राज्यवाद के प्रभाव से राष्ट्रीयता की भावना उत्तेजित होती है और स्वतन्त्र राष्ट्रों में राष्ट्रीयता साम्राज्यवादी भावनाओं को उकसाती है। बुकल (Buell) का कहना है कि "दुर्लभ राष्ट्रवाद सरकारों को साम्राज्यवाद का रास्ता अपनाते के लिए मजबूर कर देती है।"¹

उपनिवेशवाद की नीति और साम्राज्यवादी नीति के बीच बहुत थोड़ा अन्तर होता है। साम्राज्यवाद का अस्तित्व वहाँ समझा जाता है जहाँ कि स्थानीय विरोध को दूर करने के लिए उपनिवेश को बनाए रखने के लिए या अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक होता है। जहाँ यह शक्ति प्रयुक्त नहीं की जाती है तथा जहाँ विदेशी शासन के प्रति कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया जाता है वह कार्य उपनिवेशवाद कहलाता है। सपुत राज्य अमेरिका ने क्लिफाइन को स्पेन से छुड़ाने के बाद उस पर उपनिवेशवादी शासन लागू किया। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बीच का अन्तर विषयगत है और यह अन्तः सम्बन्धित लोगों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। सैंडिलफोर्ड तथा लिंकन के अनुसार दो प्रकार के प्रशासनों को सामान्य रूप से साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी शासन नहीं समझा जाता। प्रथम उन संरक्षणीय देशों का प्रशासन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मन्धित के अधीन हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनेक छोटे-छोटे पराधीन देशों को संरक्षण परिपक्व के अधीन रख दिया गया था कि अलग-अलग मंडे

1. Buell, Raymond L., *International Relations*, 1929, P.315.

देशों को इनमें आत्म प्रशासन की क्षमता का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंप देती है। दूसरे, किसी अन्य राज्य के प्रदेश में अस्थायी हस्तक्षेप को भी उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी नहीं कहा जा सकता जो अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया हो, जैसे वहाँ रहने वाले अपनी राष्ट्रीयता के लोगों की सम्पत्ति एवं जीवन की रक्षा के लिए अथवा शान्ति बनाये रखने के लिए। यहाँ हस्तक्षेप का उद्देश्य शासन स्थापित करना नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन् १९६४ में कांगो में हस्तक्षेप किया ताकि वहाँ स्थित मिशनरियों की सहायता की जा सके। सन् १९६५ में अमरीका ने अमरीकी राज्यों के संगठन के सहयोग से डोमिनिकन गणराज्यों की सेनायें भेजी ताकि गृहयुद्ध की स्थिति पर रोक लगाई जा सके। जब अकेला राष्ट्र किसी देश के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उसे साम्राज्यवादी कहा जा सकता है। जब ग्रेट ब्रिटेन की सेनाओं को सन् १९६५ में जम्बिया में रोडेसिया की सरकार द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से देश की रक्षा के लिए आमन्त्रित किया गया तो ग्रेट ब्रिटेन को साम्राज्यवादी कहा गया। इन दोषारोपणों से बचने के लिए राज्य को अपने ऐसे कार्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। कांगो, साइप्रस और अन्य स्थानों पर संयुक्त राष्ट्र सभ की अस्थायी शान्ति सेनायें रखी गई हैं उनको साम्राज्यवाद का प्रतीक नहीं माना जाता क्योंकि उनकी प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय है और वे जहाँ स्थित हैं वहाँ की स्थानीय सरकार का उनको समर्थन प्राप्त है। यह माना जाता है कि इन शान्ति सेनाओं का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय समाज की ओर से शान्ति बनाए रखना है। इसलिए साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग यहाँ अपने ऐतिहासिक अर्थ में नहीं किया जा सकता।

साम्राज्यवाद की नींव के पत्थर (Foundation Stones of Imperialism)

साम्राज्यवाद का विशाल भवन क्यों निर्मित किया जाता है तथा उसके स्थिर रहने का क्या आधार है यह जानना साम्राज्यवाद के समर्थक एवं आलोचक दोनों के लिए उपयोगी एवं आवश्यक है। आधार का पोषण करके साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को उकसाया जा सकता है उसी प्रकार आधार को कमजोर करके साम्राज्यवाद के महल को भी गिराया जा सकता है। साम्राज्यवाद के अधीनस्थ क्षेत्र जिनको प्रायः प्राप्ति (Possessions), उपनिवेश (Colonies), रक्षित राज्य (Protectorates) अर्धरक्षित राज्य (Semiprotectorates) और आश्रित राज्य (Dependent States) आदि नामों से पुकारा जाता है, साधारणतया अपनी स्थिति से कभी सतुष्ट नहीं

रहते । साम्राज्यवादी और प्रभावित राज्यों के प्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि हित परस्पर टकराते हैं और यही कारण है कि उनके बीच सघर्ष और कलह के भाव बने रहते हैं । कारण यह है कि साम्राज्यवादी शक्ति द्वारा प्रभावितों का प्रायः शोषण किया जाता है, उनको कुचला जाता है तथा उनका इतना दमन किया जाता है कि वे स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए तिलमिला उठते हैं । प्रभावितों के सतत् और कड़े विरोध के बाद भी साम्राज्यवादी शक्तियाँ प्रपन्ना पाव जमाये रखती हैं । ऐसा नया होता है यह जानने के लिए यह ज्ञात करना उपयुक्त रहेगा कि साम्राज्यवाद के उद्देश्य प्रथवा कारण क्या हैं । नीचे कुछ ऐसे ही कारणों या उद्देश्यों (Causes or Motives) का वर्णन किया जा रहा है—

(१) डार्विन का सिद्धान्त (Darwin's Theory)—डार्विन ने जीव विज्ञान में दो सिद्धान्तों की रचना की, पहला या जीवन के लिए सघर्ष (Struggle for existence) और दूसरा या योग्यतम की विजय (Survival of the fittest) । डार्विन ने बताया कि ये सिद्धान्त सामाजिक औपचारिक रचना (Social Organism) पर लागू नहीं होते । किन्तु फिर भी यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का एक महत्वपूर्ण भाग बन गये । लंगर (Langer) के मतानुसार इन्होंने विस्तार के लिए एक दिवीय अनुमोदन (Divine Sanction) प्रदान किया ।^१

साम्राज्यवाद मूल रूप से मनुष्य की लुटेरी प्रवृत्तियों का परिणाम है । जिस प्रकार छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती है उसी प्रकार छोटे राष्ट्रों को बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा शक्ति तथा हिंसा के सहारे शोषित किया जाता है । राज्यों के बीच में शक्ति के लिए सघर्ष—(Struggle for Power) बहुत पहले से ही पाया जाता है । प्रो० शुमन (Schuman) के विचार से आधुनिक साम्राज्यवादी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा तथा विजय प्राप्त करने की लालसा की एक नई अभिव्यक्ति है । प्रायः सभी तानाशाह और सर्वाधिकारवादी राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद का समर्थन और अनुशीलन करते हैं । इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है । जिस प्रकार साम्यवादी चीन विश्व को लाल झंडे के नीचे लाना चाहता है वैसे ही हिटलर भी सारे विश्व को जर्मनी के अधीन लाना चाहता था । मुसोलिनी

1 "It.....supplied a divine sanction for expansion"

—William L. Langer, "A critique of Imperialism,"
Foreign Affairs, XIV (Oct 1935), P. 109.

ने शक्ति एवं साम्राज्य प्राप्ति की दृष्टि का फामिस्ट राज्य बताया था। उनके मतानुसार साम्राज्यवाद का अर्थ प्रादुर्गिक, सैनिक और व्यापारिक विस्तार के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक प्रसार भी था। साम्राज्यवादी विस्तार की एक दश के द्वारा सम्मान की दृष्टि से दबा जाता है। यही कारण है कि सवाधिकारवादी राज्यों की जनता अपने तानाशाहों की नीतियों को पूरा-पूरा समर्थन प्रदान करती हैं। हंस कोह (Hans Kohn) के मतानुसार साम्राज्यवाद में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का बड़ा महत्व है। साम्राज्यवादी देश की जनता अपने आपसे राज्य से अधिक उच्च मानती है तथा साम्राज्य को अपने सम्मान, गौरव एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक।

(२) बढ़ती हुई आबादी (Growing Population)—साम्राज्यवादी विस्तार नीति को व्यापकित ठहराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि देश का आबादी निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा प्रदेश उतना ही धीरे सीमित है अतः बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए नए साम्राज्य बनाना और नए उपनिवेश प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। इटली, जापान आदि देशों ने समय समय पर अपनी नीतियों के समर्थन में इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत किए हैं। किन्तु यथार्थ में यह तर्क दिल्ली की घमंतीयता की दुहाइया में अधिक अर्थ नहीं रखता है। ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित किया जा सकता है कि साम्राज्यवादी देशों की बहुत बड़ी जनता उपनिवेशों में जाकर बसती है। जितने लोग उपनिवेशों में जाकर बसने हैं तब तब देश में उठने-निराज्य ले लते हैं।

(३) आर्थिक उपलब्धियाँ (Economic achievements)—यद्यपि ब्रिटन और अमेरिका के अनेक विचारक यह मानने लगे थे कि उपनिवेशों से कोई आमदनी नहीं होती (Colonies do not pay) किन्तु फिर भी आर्थिक कारण प्रारम्भ में ही साम्राज्यवाद के सबसे अधिक मौलिक कारणों में से एक रहा है। साम्राज्यवादी देशों में प्रायः कच्चे मान की कमी पाई जाती है। इस कमी का वे अपने उपनिवेशों से पूरा करते हैं। डॉ॰ शबैट (Dr Shacht) के अनुसार विश्व की राजनीति में शान वाले अधिकांश संघर्षों का आधार कच्चे मान की प्राप्ति होता है। साम्राज्यवादी राज्य प्रायः औद्योगिक (Industrialized) होते हैं जहाँ इतना उत्पादन किया जाता है जितनी कि मांग नहीं होती। उत्पादित मान का उपभोग के लिए उपनिवेशों में बाजार खोजे जाते हैं। इसी अर्थ में चेम्बरलेन कहा करता था कि साम्राज्यवाद का अर्थ है 'वाणिज्य'। दूसरी ओर कुछ विचारक ऐसा हैं जिनके मत में साम्राज्यवाद द्वारा वाणिज्य को अधिक लाभ नहीं मिल पाता।

बूथल (Buell) के अनुमान से विश्व के व्यापार का पाचवा भाग उन देशों के साथ होता है जो साम्राज्यवाद के अधीन है जबकि स्वतन्त्र देशों के साथ होने वाले व्यापार की मात्रा १५ भाग है। साम्राज्यवाद एक देश को ऐसे अवसर प्रदान करता है कि वह विदेशों में पूँजी लगा सक। अमेरिका ने विभिन्न देशों में पूँजी लगा रखी है, यही कारण है कि वह उन देशों की आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को प्रभावित करता रहता है। यह डालर कूटनीति (Dollar Diplomacy) कहलाती है। कुछ विचारकों के अनुसार तो यह जितनी ही उपयोगी तथा प्रभावशाली होती है जितनी कि एक सशस्त्र सेना। प्रो० पानर तथा परकिन्स ने साम्राज्यवाद से होने वाली इन समस्त आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन किया है।

साम्राज्यवाद का आर्थिक कारण पर्याप्त लोचप्रिय माना जाता है। साम्यवादी विचारकों ने, मुख्य रूप से लेनिन ने, तो साम्राज्यवाद को पूँजीवाद के अन्तर-विरोधों का ही परिणाम माना है। लेनिन की व्याख्या के अनुसार पूँजीवाद में एकाधिकार की प्रवृत्ति का विकास होता है और अतिरिक्त उत्पादन की व्यवस्था के कारण वह खपत के लिए बाजारों की माँग करता है। पूँजीवादी व्यवस्था की इस माँग के कारण ही साम्राज्यवाद के सहारे अतिरिक्त भूमि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। साम्राज्यवाद और आर्थिक तत्त्व के बीच इतना गहरा सम्बन्ध है कि साम्राज्यवाद के एक रूप को ही आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है। बारबारा वार्ड (Barbara Ward) के मतानुसार आर्थिक साम्राज्यवाद यह होता है जिसमें कि एक बाहरी शक्ति स्वाधीन साधन श्रोतों को अपने हाथ में कर लेती है और उन्हें मुख्य रूप से या पूरा तरह से अपने लाभ के लिए प्रयुक्त करती है। आजकल यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक मानी जाती है क्योंकि आज की आर्थिक स्थिति में विभिन्न देश आर्थिक रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में अनेक नए राजनीतिक एवं नीतिक विरोधाभास उत्पन्न होते हैं।

विदेशी आर्थिक प्रभाव व्यक्तिगत पूँजी की लागत के माध्यम से हो सकता है और सरकारी आर्थिक कार्यों के माध्यम से भी। किन्तु इस नियन्त्रण की मात्रा और तरीके अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। कुछ बड़े औद्योगिक देश अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पूँजी बाजार और विभिन्न व्यवस्था को मुख्यतः व्यक्तिगत उद्यमों के माध्यम से नियन्त्रित करते हैं। मध्यपूर्व से जो तेल का व्यापार किया जाता है वह बहुत कुछ विदेशी व्यक्तिगत निगमों के माध्यम से किया जाता है। यद्यपि इन क्रियाओं से स्थानीय राजनैतिक इकाइयाँ भी सामान्वित होती हैं। जिस तरीके से आर्थिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं उसके

आधार पर ही यह निश्चिन किया जाता है कि इसे हम सहयोगी विश्वास के रूप में वर्गीकृत करें प्रथवा साम्राज्यवादी शोषण के रूप में। आधुनिक बाल में सरकार द्वारा जो विदेशी सहायता कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं उनको भी साम्राज्यवाद का प्रतीक माना जाता है।

(४) **व्यक्तिगत उपलब्धियाँ (Personal gains)**—साम्राज्यवादी अभिव्यक्तियों में बहुत से लोगों का पोषण होना है। इससे साम्राज्यवादी देश के व्यापारियों को लाभ होता है क्योंकि उनको उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा और स्रोत दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। उनको पर्याप्त रूप से कच्चा माल मिल जाता है तथा निमित्त माल की खपत के लिए बाजार भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार साम्राज्यवाद के साथ देश के व्यापारियों के हित जुड़ जाते हैं और यही कारण है कि वे इन नीतियों को पूरा-पूरा समर्थन प्रदान करते हैं। इन व्यापारियों के अतिरिक्त अन्य और भी लोगों का भरण-पोषण होता है। साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ विदेशी उप-वाणिज्य दूतों (Pro-consuls), कूटनीतिज्ञों (Diplomats) तथा विदेशी असेनिक प्रशासन-सेवकों (Civil-Servants) के अनेक स्थान रिक्त होते हैं। फलतः साम्राज्यवादी देश के अनेक नागरिकों को इसमें रोजगार प्राप्त होता है। इन सबके अतिरिक्त साम्राज्यवादी देश की सेना का एक बहुत बड़ा भाग विदेशी खर्च पर चलता है। कहा जाता है कि सन् १९४७ से पूर्व प्रत्येक चार अंग्रेजों में से एक की जीविका का भार भारत के ऊपर आता था। साम्राज्य के कारण जिन लोगों का स्वार्थ पूरा होता है वे अधिकृत देश के स्वशासित होने के प्रत्येक उपाय का हठना से विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद में निहित स्वार्थ रखने वालों का एक वर्ग बन जाता है जिसका सदैव यही प्रयास रहता है कि साम्राज्य बड़े और रक्षित रहे।

(५) **राष्ट्रीय सुरक्षा (Defence of the Nation)**—सुरक्षा की दृष्टि से प्रायः शान्तिप्रिय देश भी साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाने लग जाते हैं। विश्वास किया जाता है कि शान्ति का मार्ग कमजोरी नहीं है, शक्ति है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक बड़ा विरोधाभास है कि यदि कोई देश शान्ति का समर्थक एवं इच्छुक है तो उसे बड़े से बड़े युद्ध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिये, क्योंकि राज्यलक्ष्मी सीता उसी का वरण करती है जो शिव के धनुष को तोड़ने की शक्ति रखता है। कमजोर देश शक्तिशाली देशों के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार बन जाते हैं। इस सबका निष्कर्ष यही है कि यदि आप किसी अन्य राष्ट्र का साम्राज्य बनने से बचना चाहते हैं और अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं तो साम्राज्य-

वाद के पथ पर आगे बढ़िये । अपने देश की सीमाओं को शत्रु से रक्षित बनाने के लिये सीमा के निकटवर्ती इलाकों को रक्षित-राज्य, अर्धरक्षित राज्य, प्रभावकारी क्षेत्र अथवा बाधक राज्य (Buffer State) बना देना उपयोगी रहता है । उन्नीसवीं शताब्दी में रूस से भारत की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन ने अफगानिस्तान, पर्सिया और तिब्बत आदि राज्यों से बाधक राज्य (Buffer State) का काम लिया था । अधिकृत राज्यों के कच्चे मान और मनुष्य-शक्ति (Man-power) का प्रयोग करके साम्राज्यवादी देश अपनी अर्थ-व्यवस्था को भी मजबूत बना सकता है । कहते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया थी किन्तु साम्राज्यवादियों के हाथों उसे कागज के मोटी से ताद दिया गया ।

(६) साम्राज्यवाद का धार्मिक आधार (Religion as the basis of Imperialism) - धर्म के प्रचारकों और साम्राज्यवादियों के हित प्रायः एक स्थल पर जाकर मिल जाते हैं । जहाँ धर्म प्रचारक यह चाहता है कि उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य की शक्ति उसका समर्थन करे और साम्राज्यवादी यह सोचता है कि उसकी नीतियों की बर्बरता को ढकने के लिए, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए और नीतियों को एक आदर्शवादी रूप प्रदान करने के लिए धर्म-प्रचारकों का सहयोग मिल जाय । फलतः दोनों का स्वार्थपूर्ण गठबन्धन हो जाता है और सेनाएँ 'जिहाद' का 'धर्म युद्ध' का नाम लेकर साम्राज्यवादियों की महत्वाकांक्षाओं से पूर्ण तृप्ति को तृप्त करने के लिए आगे बढ़ती चली जाती हैं । इतिहास में ऐसे गठबन्धनों द्वारा साम्राज्य निर्माण के उदाहरणों की कमी नहीं है । सत्रहवीं शताब्दी में 'श्याम' पर फ्रांस का अधिकार जेसुइट (Jesuit) धर्म-प्रचारकों द्वारा किया गया था । अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार में लन्दन की धर्म-प्रचार-समिति (Missionary Society) ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया था । अमरीकन राष्ट्रपति काल्विन कुलिज (Calvin Coolidge) का कहना था कि अमरीका द्वारा जो सेनाएँ विदेशों में भेजी जाती हैं उनके साथ तलवार नहीं होती बल्कि 'शाम' (X) होता है ।

धर्म-प्रचार का प्रभाव साम्राज्यवाद के निर्माण में तो अनुकूल रहता है किन्तु जब उसकी रक्षा का प्रश्न आता है तो धर्म-प्रचार अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद के बन्धनों को ढीला करता है । भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारणों में धर्म-सुधार आन्दोलनों का बड़ा महत्व है । ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीयों को सुशिक्षित, जागरूक, स्वतन्त्रता-प्रेमी एवं मानवतावादी

बना कर भनजाने ही साम्राज्यवादियों का विरोध करने के योग्य बना दिया गया था ।

(७) मानवतावादी दृष्टिकोण (Humanistic outlook)—साम्राज्यवादी नीतियों के समर्थक मानवतावादी तर्कों के आधार पर अपने पक्ष का पोषण करते हैं । यह कहा जाता है कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ मिछड़े हुए देशों में व्याप्त अज्ञान, अविकसित शासन, न्याय सम्बन्धी आदिम विचार आदि बुराइयों को दूर करके वहाँ ज्ञान, विकसित शासन तथा आधुनिक विचारों की स्थापना करती हैं । प्रमुख देशों में जहाँ दासता, मनुष्य मक्षण, कर्जदारी, मूढबोरी आदि की प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, साम्राज्यवादी देशों द्वारा सम्पत्ता का दीप जलाया जाता है । साम्राज्यवाद के समर्थक सीनेटर बेवरिज (Beveridge) का कहना था कि ईश्वर ने हमें (अमेरिकनो को) प्रशासकीय दक्षता प्रदान की है और हमारा यह कर्तव्य है कि जगलियों तथा प्रान्तों के ऊपर शासन करें । सन् १८६३-६० में डिजरेनी (Disraeli) ने घोषणा की थी कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अफ्रीका को सम्म बनाने के कार्य में हाथ बटायें । साम्राज्यवादी देशों के अधिकांश विचारक साम्राज्यवाद की मानवता की कसौटी पर वाछनीय ठहराते हैं ; किन्तु अधिकृत राज्यों अथवा साम्राज्यवादी शक्तियों से शामिल राज्यों के कोई विचारक इस दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं हैं । प्रवादस्वरूप कुछ विचारकों को छोड़ कर अधिकांश तो साम्राज्यवाद के काले कारनामों का ही विवरण करते हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि मानवतावादी तर्कों द्वारा साम्राज्यवाद की न्यायोचित ठहराना तथा इसे बाले लोगों को सम्पत्ता सिलाने के गोरे लोगों के उत्तरदायित्व (The white man's burden) की पूर्ति बताना एकपक्षीय और इस प्रकार भ्रामक एवं असत्य तर्कों पर आधारित है ।

साम्राज्यवाद के रूप [Forms of Imperialism]

साम्राज्यवाद को चाहे पामर तथा परकिन्स द्वारा परिभाषित धर्म में लिया जाये अथवा मार्गेंथो द्वारा परिभाषित धर्म में, हम देखते हैं कि मात्रा और गुण के अनुसार इसके कई रूप हो सकते हैं । यदि 'साम्राज्यवाद' सर्वोच्च तथा अधीनस्थ (Superior and inferior) के बीच शक्ति सम्बन्धों (Power relations) का नाम है तो हमें यह भी देखना होगा कि उच्चता (Superiority) किन-किन विषयों पर है, किन विषयों पर नहीं है—

पूर्वोच्चता का प्रयोग कित प्रकार किया जाता है । इस दृष्टि से साम्राज्यवाद के निम्न रूप हो सकते हैं—

१. संरक्षित तथा अर्धसंरक्षित राज्य (Protectorate and semi-protectorate)
२. प्रभाव के क्षेत्र (Spheres of influence)
३. बाह्य प्रादेशिकता (Extra territoriality)
४. अनौपचारिक नियंत्रण (Informal control)
५. शुल्क का नियंत्रण (Tariff control)
६. संयुक्त विदेशी प्रशासन (Condominium)
७. आर्थिक नियंत्रण (Financial control)
८. पट्टा (Lease hold)

साम्राज्य-निर्माण में जो साधन अपनाये जाते हैं उनके अनुसार मार्सेल्लो ने साम्राज्यवाद के तीन रूपों का वर्णन किया है । उनके मतानुसार साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तीन साधनों को अपनाया जा सकता है । ये साम्राज्यवाद के साधन हैं साध्य नहीं । साध्य भी तीन प्रकार के हो सकते हैं—

१. राजनैतिक रूप से सङ्गठित सारी पृथ्वी पर शासन करना,
२. कवल महाद्वीपीय प्रदेशों पर राज्य करना ।
३. स्थानीय प्रदेशों पर राज्य करना ।

इन साधनों को प्राप्त करने के लिये जो सैनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक साधन अपनाये जाते हैं उनको प्रायः साध्य समझने की भूल कर दी जाती है । साधनों के अनुसार साम्राज्यवाद का रूप भी बदल जाता है । सैनिक साम्राज्यवाद में सैनिक विजय (Military conquest) की जाती है, आर्थिक साम्राज्यवाद में दूसरे देशों का आर्थिक शोषण किया जाता है; सांस्कृतिक साम्राज्यवाद में एक संस्कृति के स्थान पर दूसरी संस्कृति की प्रतिष्ठापना की जाती है । इन तीनों ही रूपों के आधीन जो भी नीतियाँ अपनाई जाती हैं उनका लक्ष्य साम्राज्यवादी, अर्थात् वस्तु-स्थिति (Status-quo) को बदलना होता है ।

साम्राज्यवाद का सबसे स्पष्ट और अत्यन्त प्राचीन रूप सैनिक विजय है । आज तक जितने भी विजेता हुए हैं वे प्रायः सभी बड़े-बड़े साम्राज्यवादी थे । सैनिक साधनों से जब साम्राज्य निर्माण का कार्य किया जाता है तो

इसकी प्रतिक्रिया हारे हुए राज्यों पर बड़ी शीघ्रतापूर्वक होती है और वे भी उन्हीं साधनों एवं नीतियों को अपनाते हैं जो साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा अपनायी गयी थी। इस प्रकार 'साम्राज्यवाद' साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देता है। साम्राज्यवाद का दूसरा रूप 'डालर साम्राज्यवाद' कहलाता है। यह आधुनिक युग की उपज है तथा ऐनिक साम्राज्यवाद की तुलना में कम विध्वसात्मक तथा कम प्रभावशाली है। इन दोनों से मिश्र सांस्कृतिक साम्राज्यवाद एक सूक्ष्म साधन है। यदि कोई देश इसका सफल प्रयोग कर सके तो यह माना जायगा कि उसकी साम्राज्यवादी कुशलता तीक्ष्ण है। मार्सेन्यो कहते हैं कि साम्राज्यवाद के इस रूप का उद्देश्य न तो प्रदेश जीतना है और न उसके आर्थिक जीवन पर नियंत्रण करना, इसका लक्ष्य तो व्यक्तियों के मस्तिष्कों को जीतना व उस पर नियंत्रण करना है ताकि दो देशों के बीच के शक्ति सम्बन्धों को बदला जा सके। आजकल सांस्कृतिक साधन को साम्राज्यवाद के अन्य साधनों के सहायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके द्वारा शत्रु को नम्र बना कर सैनिक आक्रमण के लिए भयवा आर्थिक शोषण के लिए भूमि तैयार की जाती है।

साम्राज्यवाद का मूल्याङ्कन (Imperialism : An evaluation)

अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बारे में प्रायः यह कहा जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य विश्व-व्यापी न्याय और उदारता का चिरन्तन स्रोत (Perennial spring) है जिस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता। कोन्ह (Kohn) का विचार है कि एशिया और अफ्रीका में जातीय एवं आर्थिक शोषण, गरीबी और युद्धों की रचना करने वाला साम्राज्यवाद नहीं था क्योंकि ये सारी बातें वहाँ पहले से ही वर्तमान थी। एशिया के लोग एशिया के दूसरे निवासियों को दास बनाते थे तथा अफ्रीकी जातियाँ दूसरी अफ्रीकी जातियों को अपना दास बना लेती थी। कान्हु महाशय के अनुसार पश्चिमी साम्राज्यवाद के अन्य शोष हो सकते हैं किन्तु यह तो सच है कि इन प्रदेशों में उन्होंने जागृति फैलाई और सम्यता का पाठ पढ़ाया। पामर और परकिन्स के मतानुसार साम्राज्यवाद के समर्थकों द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें बहुत कुछ सत्य (Much truth) है।

साम्राज्यवाद के साम और हानियों का लेखा-जोखा करने के बाद अधिकांश विचारक इस निष्कर्ष पर आते हैं कि यह एक बुराई है। इससे प्राप्त होने वाले जिन लाभों की प्राप्ति की जाती है वे कार्पनिक अधिक हैं। यदि वे

प्राप्त भी होते हैं तो इस रूप में प्राप्त होते हैं कि उनका महत्व ही समाप्त हो जाता है। साम्राज्यवाद का इतिहास हिंसा, युद्ध, दमन, शोषण, असमानता और वर्बरतापूर्ण कारनामों से भरा हुआ है। कहा जाता है कि साम्राज्यवाद से होने वाले तथानुचित लाभ उनकी हानियों की तीव्रता की थोड़ा कम कर देते हैं किन्तु इनके आधार पर इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। साम्राज्यवाद विश्व-शान्ति के लिए राह के प्रमाण है। डैनोय विश्व युद्ध से पूर्व बार्नेस (Barnes) ने लिखा था कि ब्रिटेन इतने बड़े साम्राज्य का भरोसा ही स्वामी है यह बात विश्व शान्ति से मेल नहीं खाती, क्योंकि सत्तार के अन्य पूँजीवादी देशों की यह शिकायत रहती थी कि इसके कारण उनको सत्तार के व्यापार और भू-प्रदेशों में उचित भाग नहीं मिल पाता। ऐसे अननुष्ठानावरण में विश्व शान्ति 'बच्चे घातों पर भूँचड़ी है।'

साम्राज्यवाद अमानवीय है। साम्राज्यवाद के समर्थन में यह तर्क दिये जाते हैं कि 'यह मनुष्यों को इसलिए पराधीन-गुलाम बनाना है ताकि वे स्वतंत्रता का महत्त्व सीख सकें, वह उनका इसलिए दमन करता है ताकि उनमें स्वासन के लिए प्रेम उत्पन्न हो सके, उनका इसलिए आर्थिक शोषण किया जाता है ताकि वे गरीब और हीन बनने के बाद उद्योगों में मजदूर होकर पहल करना सीखें तथा साम्राज्यवाद में अधिकृत प्रदेशों की जातिश्री की इसलिए हीन और तुच्छ समझा जाता है, जिनसे कि उनमें आत्म सम्मान तथा परस्पर एकता की भावनाएँ आ सकें।' य मसी तर्क बड़े हान्यारोप हैं तथा उद्देश्य और परिणाम में भ्रम पैदा करने के लिए प्रायः प्रस्तुत किये जाते हैं। यह ही सचता है कि साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में ये सब परिणाम उत्पन्न हो किन्तु साम्राज्यवाद इन परिणामों को अपना लक्ष्य बना कर कभी नहीं चलता। व्यवहार में हम देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय आन्दोलनों को साम्राज्यवादी सरकार द्वारा किस प्रकार दबाया गया था, भारतीयों की राजनैतिक अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ कितने त्याग, बलिदान के बाद कठुनी के साथ दी गई थी। अब यह कह कर विश्व को भुनाया नहीं दिया जा सकता कि इन सब नीतियों के पीछे 'छूट डालो और राज्य करो' के व्यवहार के पीछे भारतवासियों को राजनैतिक रूप से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। कोई यह स्वीकार नहीं कर सकता कि जनरल डायर ने भारतीयों को मर्गोन गनों से इसलिए भूना जिससे कि उनका दूसरा जन्म दिनी स्वतंत्र और समृद्ध देश में हो। पार्कर मून (Parker Thompson Moon) के मतानुसार अंग्रेज पहले-पहल भारत में धागे और धाकर बस गये। इसका कारण यह नहीं है कि वे भारत की भलाई चाहते थे बल्कि यह कि वे ब्रिटेन को मचाई चाहते

थे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत में अंग्रेजी कानून के शासन (Rule of law) का लक्ष्य जनता का शोषण था। चाहे जितनी बातें बनाई जायें, झूठे आँकड़े दिखा कर चित्र को उजवा बिपा जाय किन्तु अनेक गाँवों में उस समय जो हड्डियों के चलने-फिरते ढाँचे दिखते थे उनके कारण सत्यता पर धूल नहीं डाली जा सकती।

साम्राज्यवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोधी है। राजनीतिक दासता को साम्राज्यवाद का अभिन्न अंग माना जाता है। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा स्थापित निरन्तर पराधीनता में रहने वाले लोग स्वतंत्रता को अपना सम्पत्ति अधिकार बहुत दिनों बाद समझ पाते हैं। हमने ने ठीक ही कहा था कि यदि ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रकृति से ही दास हैं तो इसका कारण यह है कि पहले प्रकृति के विरुद्ध उनको दास बनाया गया होगा।

साम्राज्यवाद के पक्षपातियों द्वारा स्वतंत्रता की जागृति लाने के लिए लोगों को दास बनाने का जो तर्क दिया जाता है उसकी असत्यता को प्रो० हॉकिंग (Hocking) ने बड़े सीधे और सरल शब्दों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि एक अच्छा गुलाम सदैव यह चाहता है कि उसका शिष्य योग्य एवं स्वावलम्बी बने और इसीलिए वह शिष्य की सारी समस्याओं को हल करके नहीं देता। अपने शिष्य की आन्तरिक शक्तियों के विकास को वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसी प्रकार मिथ्याचारियों की समस्या का हल यह नहीं है कि हम उनको भीत बाट दें किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आजीविका कमाने की शिक्षा तथा प्रेरणा दी जाय।

साम्राज्यवाद अधिभूत देशों की जनता के चहुँमुखी विकास के विरुद्ध तो है ही किन्तु यह स्वयं साम्राज्यवादी देशों की जनता के हित में भी नहीं है। लोग पालतू कुत्तों को प्रायः इसलिए मास नहीं देते कि कहीं किसी दिन भूल से वह अपने स्वामी की ही न काट ले। यह अन्देश साम्राज्यवादी शक्तियों पर चरितार्थ हो गया है। जो सरकार अपनी उपनिवेशी जनता पर निरन्तर शत्याचार डालती हैं, उनका शोषण और दमन करती हैं वरना वह अपने देश की जनता को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर सकेगी यह आशा नहीं की जा सकती। कुछ विचारकों के अनुसार स्वाधीनता के प्रति स्वाधीनता-प्रेमी गणेशों का मोलित उसाह अब कुण्ठित हो चुका है। इसका कारण उन सैनिक शत्याचारों तथा बड़े प्रतिवन्धों को बताया जाता है जो उनके देशवासियों द्वारा विदेशी जनता पर दिये गये थे।

साम्राज्यवाद के उपर्युक्त दोषों को देखने के बाद अनेक विचारकों के मस्तिष्कों की तरियों में एक अकार हुई। वह विचार किया जाने लगा कि

साम्राज्यवाद का विरोध किस प्रकार किया जाय । कुछ विचारकों ने साम्राज्यवाद को समाप्त करने की बजाय उसे सशोषित करने के उपाय प्रस्तुत किये हैं । पार्कर मून (Parker Moon) का कहना है कि साम्राज्यवाद मध्य-विक्टोरियन युग का बना चुना अण्ड है जो एक नितान्त गैर-विक्टोरियन युग में कायम है । यदि सन्तुलन काल में साम्राज्यवाद अपना औचित्य सिद्ध करना चाहता है तो उसे शोषण-मूलक न होकर उत्तरदायित्व मूलक होना चाहिए । कुछ विचारकों के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की भावना का प्रचार करके लोगों की मनोवृत्ति को बदलना साम्राज्यवाद को बदलने, सशोषित करने या अन्त करने की पूर्व आवश्यकता है । दूसरे लोग साम्राज्यवाद को सशोषित करने के लिए निम्न सुझाव देते हैं—

- १ गोरी जाति को उच्चता प्रदान नहीं की जानी चाहिए;
- २ साम्राज्यवादी देश मजदूरों का शोषण न करें,
- ३ पिछड़े देशों में व्यक्तिगत पूँजी के प्रयोग की निर्मिन्न रचना चाहिए,
- ४ पिछड़े देशों को स्वाशासन के योग्य बनाया जाय;

५ बार्नेम् (Barnes) के मतानुसार साम्राज्यवाद की जड़ें हिलाने के लिए उसके मुख्य आधार पूँजीवाद पर चोट की जाय । यह मन्त्रा रहेगा कि मातृ देश में पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना की जाय ।

पूँजीवाद का विरोध करने के लिए मार्गे-यो ने उन नीतियों का वर्णन किया है जो विभिन्न देशों द्वारा समय समय पर अपनायी जाती रही हैं । ये नीतियाँ मुख्य रूप से तीन हैं—

- १ तुष्टीकरण की नीति (Policy of appeasement)
- २ घेराबन्दी की नीति (Policy of containment)
- ३ भय की नीति (Policy of fear)

मार्गे-यो का कहना है कि साम्राज्यवाद की प्रतिक्रिया के रूप में जब कोई राष्ट्र तुष्टीकरण की या भय की नीति अपनाता है तो उसके कार्यों का परिणाम प्रायः साम्राज्यवाद को सज्जित व अधिक शक्तिशाली बनाने में पलित होता है । साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने के मार्ग में कई कठिनाइयाँ हैं । प्रथम कठिनाई तो यह है कि विजय (Conquest) की नीति को सभी साम्राज्यवादी माना जा सकता है जबकि यह वस्तु-स्थिति (Statusquo) को बदलने का प्रयास करे किन्तु यह अन्तर बदलना बड़ा कठिन कार्य है कि कौन सी नीति वास्तव में साम्राज्यवाद की परिधि में आती है और कौनसी

नहीं। दूसरी कठिनाई यह है कि जब एक देश वस्तुस्थिति को बनाये रखने की नीति अपनाता है तो यह निश्चित नहीं रहता कि वह कब अपनी इस नीति को छोड़कर साम्राज्यवादी बन जायेगा। तीसरी कठिनाई यह है कि जब तक एक देश स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाता है तो उसकी अन्य नीतियों के उद्देश्यों को भी 'भूमि' (Territory) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि यह देश प्रमुख प्रदेश पर अपना प्राधिपत्य जमाना चाहता है किन्तु परेशानी तो एक देश द्वारा अपनाई गई सांस्कृतिक तथा धार्मिक नीतियों का उद्देश्य बनाते समय होती है। यह जानना बहुत मुश्किल है कि एक देश द्वारा अपनायी जाने वाली सांस्कृतिक एवं धार्मिक नीति का उद्देश्य साम्राज्यवादी है अथवा नहीं। स्विटजरलैंड द्वारा विश्व क्षेत्र में सक्रिय धार्मिक नीतियों अपनाई जाती हैं किन्तु उनको साम्राज्यवादी नीति नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार स्पेन का होटिन अमेरिका की संस्कृति में प्रवेश साम्राज्यवाद की दृष्टि से कोई मदद नहीं रखता क्योंकि अमेरिका की तुलना में स्पेन की शैक्षिक शक्ति इतनी नहीं कि स्पेन द्वारा शक्ति सम्बन्धों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने का कोई प्रयास किया जा सके। इन समस्या परेशानियों के बावजूद भी यदि यह प्रमाणित हो जाय कि एक देश की नीति साम्राज्यवादी है तो एक दूसरी कठिनाई आ उपस्थित होती है वह यह कि इस बात का निश्चय कैसे किया जायेगा कि इस साम्राज्यवाद का लक्ष्य क्या है। अर्थात् यह देश केवल क्षेत्रीय प्राधिपत्य चाहता है या महाद्वीपीय अथवा सम्पूर्ण पृथ्वी पर ही शासन करना चाहता है। सफलताओं और बदली हुई परिस्थितियों के साथ-साथ प्रायः साम्राज्यवाद का लक्ष्य भी बदलता रहता है। पृथ्वी पर शासन करने का लक्ष्य लेकर चलने वाला देश जब प्रारम्भिक प्रयासों में ही सफल नहीं हो पाता तो उसे अपना लक्ष्य बदलना पड़ता है। उसी प्रकार एक राज्य जो केवल स्थानीय प्रदेशों पर ही अधिकार करने का लक्ष्य लेकर चले और इस लक्ष्य में सफल हो जाय तो वह महाद्वीप की जीतने का और बाद में सारी पृथ्वी पर शासन करने का उद्देश्य भी बन सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद में एक गतिशील ताकत (Dynamic Force) है। इस प्रकार साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ तथा उनकी प्रतिक्रियावादी नीतियाँ कभी निश्चिन नहीं होती। ये दोनों ही बदलती रहती हैं तथा इनका मूल्यांकन भी समय-समय पर होता रहता है।

साम्राज्यवाद का प्रतिरोध करने की पाचवी तथा अन्तिम कठिनाई यह है कि यह अपने आपको इस रूप में प्रदर्शित करना है कि इसके सही रूप

को नहीं समझा जा सकता। एक देश की विदेश नीति प्रथम साम्राज्यवादी नीति जैसी लगती है और जैसी वह वास्तव में होती है—इन दोनों के बीच भारी अन्तर रहता है। आज सम्पूर्ण-युद्ध के युग में यह आवश्यक हो गया है कि साम्राज्यवाद के प्रसार को रोका जाय, उसका रूप परिवर्तित किया जाय और हों सके तो उसे समाप्त किया जाय। समुक्त राष्ट्रमण्डल तथा अन्य शक्ति के द्रुत साम्राज्यवाद के रूप की विध्वंसकर्त्ताओं को घटाने व इसके प्रसार को रोक करने में प्रयत्नशील हैं किन्तु उनको कितनी सफलता प्राप्त हो सकेगी इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा।

पश्चात्य उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद (Western Colonialism and Imperialism)

पश्चिमी देशों में साम्राज्यवाद का विकास किसी एक राजनैतिक या आर्थिक उद्देश्य से नहीं किया गया। ईसाई मिशनरी के लक्ष्य तथा गोरे लोगों का उत्तरदायित्व के विचार ने अधिकांश प्रचीनस्थ लोगों को सुधारने के नाम पर साम्राज्यवादी व्यवहार को अधिष्ठान प्रदान किया। ईसाई मिशनरियों के प्रयासों के बाद व्यापारिक एवं राजनैतिक नियन्त्रण प्रारम्भ हो जाता था। साम्राज्यवाद के अनेक लक्ष्य शक्ति और आर्थिक उद्देश्यों के साथ मिल कर कार्य करते हैं। अनेक पश्चिमी देशों ने समुद्र पार के देशों में जो साम्राज्य स्थापित किए थे कुछ तो उनके सांठसिक कार्यों के परिणाम थे; कुछ प्रभावित लोगों के आलम्ब, अज्ञान एवं भ्रूट के परिणाम थे। उन्नीसवीं शताब्दी में एक देश के पास जितने उपनिवेश होते थे और जिनके प्रभाव का क्षेत्र जितना अधिक होता था उसे उतना ही अधिक शक्तिशाली समझा जाता था और सम्मान दिया जाता था। फ्रांस को अपने कुछ उपनिवेशों से तो वस्तुओं के रूप में लाभ होता था और अन्य में केवल सम्मान और स्थिति ही प्राप्त होती थी। पश्चिमी शक्तियों ने न केवल सम्मान और शक्ति की प्राप्ति के लिए ही बरन् अपने मुख्य हितों की रक्षा के लिए भी विदेशों में प्रदेशों की खोज की। समुक्त राज्य अमरीका पनामा नहर की रक्षा करना चाहता था। इसलिए उसे ग्वान्टानामो और ब्रिजित आदि द्वीपों पर अधिकार करना पड़ा। इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन भारत, सिंगापुर, हांगकांग और आस्ट्रेलिया के लिए सुरक्षित मार्ग चाहता था इसलिए उसे भूमध्य सागर और हिन्द महासागर पर अधिकार करना पड़ा। उपनिवेशवाद के समर्थक यह तर्क देते हैं कि उपनिवेशों के द्वारा अनिश्चित जनसंख्या के लिए निवास स्थान प्रदान किया जाता है। किन्तु इस तर्क को अनेक उदाहरणों की साक्ष्यकीय के द्वारा गलत सिद्ध किया जा

मक्ता है। सन् १९१४ में जर्मनी ने अफ्रीका में नौ लाख इक्कीस हजार वर्ग मील भूमि पर अपने उपनिवेश बनाए। इनकी जनसंख्या बारह मिलियन थी। किन्तु इनमें से केवल बीस हजार लोग ही जर्मन के निवासी थे। अमल में जर्मनी वालों की इससे अधिक जनसंख्या परिम में रहती थी। इस प्रकार जनसंख्या का तर्क तथ्यमय नहीं है यह साम्राज्यवाद को न्यायोचित सिद्ध करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

साम्राज्यवाद कभी-कभी अतिरिक्त साम्राज्यवाद को परित करता है। एक साम्राज्यवादी देश जब दूसरे देश के प्रदेशों पर अधिकार कर लेता है तो वह प्रभावित देश अपनी क्षति पूर्ति के लिए किसी अन्य देश के प्रदेशों पर अधिकार कर लेता है। हिटलर, मुसोलिनी तथा तोमो, प्रादि ने यह दावा किया था कि शोपित शक्तियों के रूप में यह देश समुद्र पार के प्रदेशों पर नियन्त्रण रखन का अधिकार रखते हैं। इस प्रकार सन् १९३६ में पूर्व के उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के लिए विभिन्न प्रकार के राजनैतिक और रण कोशन सम्बन्धी औचित्य प्रदान किए गए। प्रत्येक जगह पर केवल एक ही मूल का लागू नहीं किया गया। प्रत्येक तर्क एक समय न्यायपूर्ण प्रतीत होता था, किन्तु बाद में इनके निरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों को न्यायपूर्ण बन जाने थे।

पश्चिमी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का धीरे-धीरे पतन हुआ। इस दृष्टि में ब्रिटिश नवोपनिवेश विरोधी नीति अपनाई वह सबसे अधिक प्रभावशाली मानी जाती है क्योंकि उसने ५३० मिलियन में भी अधिक लोगों को स्वतन्त्रता प्रदान की। सन् १९६६ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद में केवल ३० छोटे टाटे अवस्थित प्रदेश थे जिनकी जनसंख्या ६ मिलियन से भी कम थी। ग्रेट ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यवाद को एक नियोजित तरीके से सीमित किया और यह प्रयास किया कि नव स्वतन्त्रता प्राप्त राज्यों में स्थायी सरकार बनें, प्रभावशाली प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हो और एक शक्तिशाली वर्ग जन्म ले। इससे अतिरिक्त इन राज्यों को राष्ट्र मण्डल में मिलाए रखा गया ताकि सामान्य हितों एवं वियाधों की निरन्तरता बनी रहे। ये सब परिवर्तन बिना अधिक संघर्ष और हिंसा के ही हो गए। यद्यपि कुछ देशों में स्वतन्त्रता आन्दोलन बहुत लम्बा और गम्भीर रूप में चला तथा स्वदेशी सैनिकों की दक्षता और जेल में रहने की नीति अपनाई गई। रोडेसिया ही एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जिसे ब्रिटेन के समर्थन के ही स्वतन्त्रता की एकपक्षीय घोषणा कर दी। राष्ट्र मण्डल के सदस्यों का पारम्परिक सम्बन्ध उस समय उत्तरे में पड़ गया जब इसकी सदस्यता बढ़ गई और दक्षिण अफ्रीका

की ज़ानि भेदभाव की नीतियों ने अफ्रीका और एशिया के देशों के बीच मत-मुटाव पैदा कर दिया। जाते अफ्रीकी राज्यों के दबाव में आकर सन् १९६४ में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र मण्डल में अलग हो गया।

फ्रान्स के साम्राज्य की समाप्ति इससे कुछ कम मरत रूप में हुई। हिन्द-चीन (Indo China) में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी अधिकार ने फ्रान्स की शक्ति को कमजोर कर दिया। विमतनाम के साम्यवादियों की सैनिक प्राणियों के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र सन् १९५४ में चार भागों में बांट दिया गया। ये थे—उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया। फ्रान्स को कम्बोडिया के सम्बन्ध में कुछ छेड़ता पड़ा किन्तु सन् १९५८ में जनरल डिगाल ने उपनिवेशवादी नीति को विपरीत बना कर कम्बोडिया को स्वतन्त्रता प्रदान की। डिगाल के नेतृत्व में एक प्रगामी सरकार की रचना की गई। यह प्रगति राष्ट्र मण्डल के विचार पर आधारित था। फ्रान्स के सभी प्रकीर्ण देशों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और गिनी को छोड़ कर इन सभी ने इस सरकार में रहना स्वीकार किया। किन्तु यहाँ घटने हुए राष्ट्रवाद के प्रभाव ने शीघ्र ही नाबन्ध को सीता कर दिया।

समुक्त राज्य अमरीका ने अपने प्रमुख उपनिवेशों को द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। फिलीपीन्स स्वतन्त्र हो गया, प्योर्टो रिका (Puerto Rico) को राष्ट्र मण्डल का स्तर प्रदान किया गया और एलासका तथा हवाई को संघ के राज्य बना दिया गया। समुक्त राज्य अमरीका ने बर्जिन द्वीप, अमरीकी सामोआ, ग्वाम तथा प्रगल्भ महानगर के कुछ द्वीपों पर अधिकार बनाए रखा।

अफ्रीकी राष्ट्रवाद के दबाव के कारण बेनिन को सन् १९६० में कागो स्वतन्त्र करना पड़ा, यद्यपि इस समय कागो के लोग स्थायित्व सरकार के लिए तैयार नहीं थे। फलन राजनैतिक अस्थिरता पंजी और समुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं द्वारा सरकार को स्थायित्व प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। कागो में साम्यवादी शासन की स्थापना की पूरी सम्भावनायें थी, किन्तु एशियमो कूटनीति की सजाता एवं समुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसा न हुआ।

पुर्तगाल और स्पेन के साम्राज्य अब भी बाकी हैं। पुर्तगाल का यह दावा है कि अज़ोरा और मोज़ामबीक उसके देश के ही प्रांत हैं। यह सर्व उपनिवेशवाद के अफ्रीकी आलोचकों को गम्भीरजनक प्रतीत नहीं होता। इन क्षेत्रों के लोगों की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए तैयार करने की दिशा में प्रयत्न

और उत्तरी विदलनाम पर नाम मात्र के लिए स्वतन्त्र राज्यों पर राजनीति, सैनिक एवं आर्थिक नियन्त्रण स्थापित कर लिया है। इसके अतिरिक्त यह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका की राष्ट्रवादी क्रान्तियों का शोषण करके उन्हें धनिम रूप से साम्यवादी शासनो की स्थापना की ओर मोड़ देता है। इस और चीन प्रमुख साम्यवादी देश होने के नाते साम्यवादी साम्राज्यवाद के मुहर नता है।

सोवियत साम्राज्यवाद (Soviet Imperialism)

पूर्वो यूरोप के देशों में सोवियत साम्राज्यवाद ने एक सामान्य रूप धारण किया है। सन् १९४५ से सन् १९४७ तक साम्यवादी अपनी शक्ति को स्थापित एवं एकीकृत कर रहे थे। उस समय विचारधारा पर अधिक जोर नहीं दिया गया और जनता के प्रजातन्त्रों को समाजवाद के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करने की अनुमति दी गई जो वे साल सेना के अधीन रह कर ही अपना सकते थे। स्टालिन के शासन के अन्तिम वर्षों के दौरान इन देशों पर नियन्त्रण की मात्रा बढ़ा दी गई। किन्तु इस तानाशाह की मृत्यु के बाद पोलैंड और हंगरी में जागृतियाँ हुईं। उसके बाद सोवियत संघ और चीन के बीच सघन घेरा हुआ। उसके बाद ज्यों ही चीन की प्रगुशक्ति बढ़ी त्योंही यहाँ की राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतन्त्र रूप से आर्थिक विकास की नीति बनाना और संचालित करना प्रारम्भ किया। प्रत्येक राज्य में बुद्धिवादियों का एक निरिच्छित वर्ग केन्द्रीय रूप से नियन्त्रणकर्ता बना दिया गया। अल्पसंख्यक जन नियन्त्रण का स्तर बढ़ा दिया गया है किन्तु फिर भी यहाँ अब भी सोवियत नियन्त्रण है। सोवियत संघ के साथ इन देशों के सहायक आर्थिक बन्धन उतने ही मजबूत हैं जितने कि सैनिक एवं राजनैतिक प्रभाव।

सोवियत गुट के बाहर साम्यवादी रणनीति ने राष्ट्रवाद के साथ सन्धि कर ली है। साम्यवादी नेता यह माता करते हैं कि पहले साम्यवादी आंदोलन को भड़काया जाए और उसके बाद राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को पूँजीवादी सत्ता से लेकर शक्ति सौंप दी जाए। सर्वप्रथम साम्यवादी व्यापार, आर्थिक सहायता आदि के सहारे प्रभाव डालते हैं। सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति का उदाहरण दिया जाता है और प्रभावशाली समूहों तथा दुसपैठियों के द्वारा साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाया जाता है। साम्यवादी देशों का विकासशील देशों के साथ व्यापार बढ़ रहा है। इन देशों को जो सोवियत सहायता दी जाती है वह इतनी स्पष्ट एवं मूर्त रूप में होती है कि उसके सहारे सोवियत संघ का सम्मान एवं राजनैतिक प्रभाव अधिक से

अधिक डाल दिया जाता है। उदाहरण के लिए मिस्र में आस्वन बांध बनाया गया और भारत में स्टील के कारखानों में सहायता दी। प्रचार के सभी साधनों को प्रयुक्त करके यह सिद्ध किया जाता है कि सोवियत सघ बीसवीं शताब्दी में तीव्र गति के विकास का एक नमूना है। सोवियत सघ की नीति यह मान कर चलती है कि हमारे स्तर पर विकासशील देश साम्यवाद को अपना लेंगे। बदलती हुई वस्तुस्थिति एवं बढ़ते हुए आंतरिक गतिरोध साम्यवादियों को शक्ति में आने का अवसर प्रदान करेंगे। ज्यो ज्यों स्वतंत्रता का आंदोलन आगे बढ़ता है त्यों त्यों यह माना बढ़ती है कि विश्व का शक्ति सन्तुलन बदल जाएगा और पश्चिमी देश साम्यवाद के प्रभाव और प्रसार को रोक नहीं पाएंगे। सोवियत नीति नेनिन की इस गतिविध्यवाणी को मान कर चलती है कि सघ का परिणाम दुनियां की जनसंख्या के बहुमत द्वारा निर्धारित किया जायगा जो कि रूस चीन और भारत में रहती है।

चीनी साम्राज्यवाद

(The Chinese Imperialism)

साम्यवादी चीन को दगने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चीन में अपना प्रभाव एवं शासन प्रसारित करना चाहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसके द्वारा तीन साधन अपनाए जाते हैं। प्रथम, परम्परागत सीमाओं के बाहर सैनिक प्रभाव को बढ़ाया जाता है। दूसरे, तीन स्वतंत्रता प्राप्त राज्यों को नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तीसरे विश्व साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किया जाए। इन तीनों साधनों को अपनाते समय चीन को पग पग पर सोवियत रूस का प्रतिद्वंद्वी बनना होता है। चीनी साम्राज्यवाद के इन तीनों साधनों या रूपों के सम्बंध में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करना अनुपपुक्त न रहेगा।

परम्परागत रूप से चीन एक प्रसारवादी देश है क्योंकि यह अपने प्रदेश को एक मध्य राजधानी (Middle Kingdom) मानता है जो कि दुनिया का केन्द्र है। जब माओ साम्राज्य के साथ चीन की शक्ति केन्द्रीय एशिया साइबेरिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से हट कर वापस आ गई तो उसका प्रभाव कम हो गया किन्तु बाद में जब यहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई तो चीन ने अपने शासन को विस्तृत तब बढ़ा लिया। इसका प्रभाव उत्तरी कोरिया में स्थापित हो गया। दमकी सैनिक शक्ति भारत की सीमाओं का पार प्रवाह करने लगी। चीन के द्वारा दम प्रदेश पर अधिकार जताया जाने लगा जिस पर कि बहुत समय पहले से भारत का अधिकार है।

राष्ट्रवादी चीन के क्वीमोय और मात्सू (Quemoy and Matsu) द्वीपों पर साम्यवादी चीन ने आक्रमण किया तथा यह दावा किया कि फारमोसा द्वारा नियन्त्रित भूमि पर उसका स्वयं का अधिकार है। धीरे-धीरे पीकिंग का प्रभाव उत्तरी वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस पर फैलने लगा। चीन की पोपुलरफो द्वारा यह दावा किया गया कि क्वीमोय एरिना 4 जो भूमि सीमित रूप के अधीन है वह कभी चीन के अधीन थी और अब उसे चीन को ही लौटा देना चाहिए। पीकिंग ने होचीमिन्ह को प्रभावित करके इस बात का प्रत्येक प्रयास किया कि अमरीकियों को वियतनाम से बाहर निराल दिया जाए। अनेक प्रकाशित पत्रों के आधार पर यह कहा जाता है कि साम्यवादी चीन ने इण्डोनेशिया के साम्यवादियों को उभार कर उन्हें उच्च सैनिक अधिकारियों की हत्या के लिए प्रेरित किया ताकि शक्ति साम्यवादियों के हाथ आ सके। नवम्बर १९६५ का यह देवद्राही कार्य स्थानीय दलीय नेतृत्व के विरुद्ध सेना के प्रभावशील कदमों ने सफल न होने दिया। चीन द्वारा बर्मा और थाईलैण्ड की सीमाओं पर भी दबाव डाला जाता है तथा यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है कि किसी भी मध्य धारामार्ग को प्रोत्साहित करने सैनिक कार्यवाही कर दी जाये। कहा जाता है कि भारत में एशियमी अग्रात की जो हिंसात्मक घटनाएँ हुई थी उनमें साम्यवादी चीन का प्रत्यक्ष रूप से हाथ था। पीकिंग के साम्यवादी दल की देशीय समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाता है उसको क्रियाविध करने के लिए अनेक देशों में उसके कार्यकर्ता उन्मुख रहते हैं।

राजनैतिक क्षेत्र में चीन के नेताओं ने नव स्वतन्त्रता प्राप्त राष्ट्रों को शांति के प्रतीक माना है। सन् १९५५ में एशिया और अफ्रीका के देशों के वाण्युग सम्मेलन में चीन ने इन देशों का नेतृत्व सम्भालने की दिशा में कई कदम उठाए। इसके बाद सन् १९६५ में अल्जीरस में होने वाले अफ्रीकी-एशियाई देशों के सम्मेलन में भी चीन ने इन देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। किन्तु यह सम्मेलन नहीं हो सका क्योंकि यहाँ कान्ति होने के कारण अहमद बेनबेला की अग्रस्थता पर दिया गया सोवियत सप ने एक एशियाई शक्ति के रूप में इस सम्मेलन में उपस्थित होने का दावा किया था। अल्जीरिया सम्मेलन की समाप्ति चीनी भाषाओं पर एक तुपारापान था। सन् १९६५ में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन लाई ने अफ्रीका और एशिया के कुछ देशों का दौरा किया और चीटने पर अपने नेताओं को बताया कि अफ्रीका कान्ति के लिए एक चुका है। यह बात उन स्थानीय नेताओं को अधिक नहीं अच्छी जिन्होंने विभिन्न प्रकार की कान्तियों द्वारा

अपना पद प्राप्त किया था। उन्होंने उस परिवर्तन की सम्भावनाओं का स्वागत नहीं किया जो कि नेता द्वारा वर्णित किए गए थे। यह सूचित उन्होंने आग तुक नेता को भी दे दी। कुछ अफ्रीकी देशों में साम्यवादी चीन के कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों को देश निकाला दे दिया गया। जब एक के बाद एक अफ्रीकी राज्य ने चीनी मिशन के लिए दरवाजा बन्द कर दिया तो इससे साम्यवादी महत्वाकांक्षाओं को ठेग लगी। यह बात घाना के उदाहरण को देखकर स्पष्ट हो जाती है। इस दश ने एम्बूमा के अपदस्थ होने के बाद चीनी मिशन को बाहर निकाल दिया और सोवियत संघ के अधिकारियों का आमन्त्रित किया। इस स्थिति के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि चीन अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देगा। वह पुनः इस दिशा में प्रयास कर सकता है। चीन का दर्शन यह है कि उनकी क्रान्ति सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व के अधीन एक समाजवादी क्रान्ति को लाने में सफल पाठ प्रस्तुत करती है जिसे अपनाकर कोई भी देश आगे बढ़ सकता है।

चीनी साम्यवाद अपने सामने दीर्घकालीन लक्ष्यों को रख कर चलता है। इनमें प्रमुख यह है कि चीन द्वारा साम्यवादी दुनिया का नेतृत्व किया जाए। पीकिंग और मास्को के बीच का संझान्तिक संधि साम्यवादी गुट में शक्ति संधि का एक उदाहरण है। चीन अणु शक्ति संपन्न देश बनना चाहता है क्योंकि सोवियत संघ ने उसे यह शक्ति प्रदान करने से मना कर दिया था। वह आधुनिक औद्योगीकरण के माहारे विश्व साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहा है उसमें उसकी हानि अधिक होती है और लाभ कम। यह अपने आपका मार्क्सवाद-लेनिनवाद का सच्चा समर्थक मानता है और एक आक्रमणकारी शक्ति के रूप में सोवियत नेतृत्व से ऊपर आता है। चीनी प्रचार की सैनिक प्रवृत्ति एवं आक्रमणकारी विचारों के कारण विकासशील देशों में सोवियत संघ को अपनी रक्षा की रिक लगी है। चीन के तरीके माओ के इस विचार पर आधारित हैं कि जनता के युद्ध एवं राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों का आक्रमणकारी रूप से समर्थन करके साम्यवादी विजय को शीघ्र लाया जा सकता है।

चीनी साम्यवादियों का यह मत है कि एशिया और अफ्रीका के देशों में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए उसके उद्देश्य में सबसे बड़ी बाधा संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिका भी यह अनुभव करने लगा है कि सोवियत प्रसार को यूरोप में रोकने की समस्या जितनी जटिल थी उससे बड़ी प्रविष्ट आज़ साम्यवादी चीन के साम्राज्यवाद को घेरने की समस्या बन गई है। क्योंकि यह समस्या उन क्षेत्रों की है जहाँ वे लोग पश्चिम से मित्र मूल्य

रखते हैं। ये पश्चिमी शक्तियों की भी अपने देश में आने से उतना ही रोकना चाहें जितना कि चीन की चुनौती को। साम्यवादी चीन के साम्राज्यवाद को एशिया और अफ्रीका में तटस्थता एवं असह्यता की व्यापक नीतियों द्वारा रोकना जा सकता है। इस साम्राज्यवाद को रोकने के प्रयास में जो भयपूर्ण घटनाएँ होगी तथा इस प्रयास के असफल होने पर जो स्थिति सामने आएगी वह अंतराष्ट्रीय जीवन के रूप को निर्धारित करेगी।

वर्तमान स्थिति अत्यन्त गम्भीर है। अनेक नए राज्यों के दृष्टिकोण अमन्युक्त हैं। वे पश्चिम के विकास और स्तर की प्रशंसा करते हैं तथा उसे प्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु हमारी ओर उपनिवेशी शासन के ऊच-नीच के सम्बन्ध द्वारा एक विरामत छोड़ी गई है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम विरोधी दृष्टिकोण सामने आता है और ये देश पश्चिम के साथ राजनैतिक सहयोग की नीति को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। पश्चिमी शक्तियों के प्रति ये भावनाएँ साम्यवादी देशों के लिए लाभप्रद बन जाती हैं। साम्यवाद के द्वारा पश्चिमी सम्प्रदाय के आदर्श मूल्यों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यह विभिन्नताओं के शांतिपूर्ण समायोजनों पर और नहीं देता। यह बहुजनवाद की सहनशीलता को महत्व नहीं देता। यह व्यक्तिगत महत्व एवं भावाकांक्षों को आदर नहीं देता। उपनिवेशवाद के विरुद्ध अफ्रीका में जो आन्दोलन चला वह कोई नई बात नहीं है। समुक्त राज्य अमरीका की पूर्वज तरह उपनिवेशों ने इंग्लैण्ड के विरुद्ध आन्तिकारी लड़ाई लड़ी थी। किन्तु उस समय साम्यवाद अभी कोई शक्ति नहीं थी जो विरोधों को बढ़ा कर लाभ उठाना चाहें।

वर्द्धार समुक्त राज्य अमरीका के सामने यह सन्देह उत्पन्न हो जाता है कि वह अपने यूरोपीय मित्रों एवं नए देशों के बीच में से किसको चुने। कहा जाता है कि अमरीकी जनता अपने ऐतिहासिक अनुभव और राजनैतिक मूल्यों के आधार पर उपनिवेशों की जनता की स्वतन्त्रता प्राप्ति की महत्वाकांक्षा का आदर करती है। समुक्त राज्य अमरीका ने इन नए राज्यों का जो आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया है वह अद्वितीय है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उन देशों में जागृति आ गई जो एक लम्बे समय से सुलाम थे। यहां के लोगों की यह इच्छा है कि वह अपने आपको विश्व राजनीति में सम्मान के रूप में अभिव्यक्त करें। यह पश्चिमी शक्तियों और समुक्त राज्य अमरीका के हित में है कि वे इन राज्यों के विकास में सहयोग दें। वर्तमान समय में इन नए राज्यों के सम्बन्ध में पश्चिमी शक्तियों तथा साम्यवादी देशों के बीच स्पर्ध इतनी जात पर है कि वे दोनों ही

इन राज्यों के मूल्यों को रूप देना चाहते हैं ताकि ये राज्य अपने भावी विकास की दिशा चुन सकें। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का नया रूप क्या मोड़ लेगा इस सम्बन्ध में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती केवल भविष्य ही इसका निर्धारण करेगा।

युद्ध (The war)

Imp.

युद्ध मनुष्य की सधर्ममयी प्रवृत्ति के परिणाम है। इनका प्रारम्भ तभी से माना जाता है जब स मनुष्य ने इस घराघाम पर प्रथम बार पदार्पण किया। विश्व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद की अनेक स्तुतियाँ और श्लोक देवता तथा राक्षसों में युद्ध का उल्लेख करते हैं। वैदिक काल के बाद पौराणिक काल, महाभारत एवं रामायण काल में भी युद्धों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। समस्त भारतीय दर्शन और धर्म के ग्रन्थों में युद्ध के उत्तरोत्तर विकसित रूप की ओर सचेत किया गया है। मनुष्य की राक्षसी और दैवीय प्रवृत्तियाँ एक साथ नहीं रह सकती, दोनों के बीच संघर्ष का होना अवश्यम्भायी है। जो प्रवृत्ति प्रबल होती है युद्ध में वह विजयी होती है तथा दूसरी का पराधीन बना लेती है। न केवल भारत, किन्तु सम्पूर्ण विश्व के समस्त मानव समाज का इतिहास इसी प्रकार बीभत्स, प्रलयकारी, हिंसात्मक एवं विध्वसात्मक युद्धों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यह एक बड़ी विरोधाभासपूर्ण स्थिति है कि मनुष्य सम्पन्न के पथ पर ल्यो-ज्यों आगे बढ़ता चला गया ल्यो-ज्यों युद्ध का रूप अधिक विध्वंसकारी बनता चला गया। युद्ध के द्वारा मनुष्य जाति को अनेकों द्वार राष्ट्रीय नीति के हिंसात्मक साधनों का बहुधा फल चखाया गया है। इसने असंख्य हत्यायों की, सोने की लूट को खार में मिलाया, बड़े बड़े शक्तिशाली और सम्पन्न राष्ट्रों को पददलित किया, लोगों के जीवन को अस्त-वस्त कर दिया और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतन्त्रता के आगे प्रत्येक चिह्न ला सड़ा किया।

आज के अणुयुग में युद्ध का क्षेत्र और स्वभाव इतना बदल चुका है कि इसने मनुष्य जाति के अस्तित्व तक को चुनौती दे डाली है। आज मनुष्य जाति के सामने युद्ध की समस्या इतनी प्रबल तथा प्रभावकारी है कि इस पर नये जाने वाले विचार को आगे के लिए नहीं टाँका जा सकता। मनुष्य के सामने केवल दो ही विकल्प हैं, युद्ध या शांति। एक मृत्यु है दूसरा जीवन, एक विनाश है दूसरा विकास। आज, जहाँ हिंस्र, रक्त, रक्त, रक्त, रक्त, पहुँचा है जहाँ प्रत्येक राष्ट्र को-चाहे वह छोटा हो प्रथम बड़ा, शक्तिशाली

हो या कमजोर-यह समझ लेना पड़ेगा कि 'युद्ध' के द्वारा राष्ट्रीय हितों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध आज के युग की अन्यायहारिकता बन गया है तथा राष्ट्रों के बीच के समस्त झगड़ों और मतभेदों को शांतिपूर्ण वार्ताओं एवं समझौतों से मूलभूताना वेवल आदर्शमात्र न रह कर एकमात्र सफल, सम्भव, न्यायोचित और सुरक्षित साधन बन गया है।

'युद्ध' के वर्तमान स्वरूप एवं विषय में उसके स्थान को देखने हुए यह जानना अप्राप्तनिक तथा विश्व शांति के ग्रहित में होगा कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं, इनमें क्या कौशल अपनाये जाते हैं, व्यूह रचना किस प्रकार की जाती है आदि। युद्धों को रोकने की दृष्टि से उपयोगी रहेगा कि युद्ध के स्वरूप, कारण तथा प्रतिरोध के उपायों की व्याख्या की जाय।

युद्ध का अर्थ

(Meaning of war)

कैप्टन लिडेल हार्ट (Captain Liddell Hart) का कहना है कि अगर तुम शांति चाहते हो तो पहले युद्ध को समझो। युद्ध के ममानक परिणामों के चित्रण मात्र से इसकी पुनरावृत्तियों को नहीं रोका जा सकता। युद्ध के मयों के सम्बन्ध में अनेक विचारकों ने अपने मन प्रकट किये हैं। प्रो० मेलिनास्की (Professor Malinowski) के मतानुसार युद्ध दो स्वतन्त्र राजनैतिक इकाइयों के बीच का सशस्त्र संघर्ष है, यह संघर्ष राष्ट्रीय अथवा जातीय नीतियों को प्राप्त करने के लिए संगठित भौतिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। मेलिनास्की द्वारा दी गई परिभाषा के तीन भाग किये जा सकते हैं—

- (१) युद्ध करने वाली इकाइया राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र होती हैं।
- (२) युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष है जो संगठित भौतिक शक्तियों द्वारा किया जाता है।
- (३) युद्ध जातीय (Tribal) अथवा राष्ट्रीय नीतियों की साधना के लिए किया जाता है।

युद्ध की इस परिभाषा में युद्ध की जो विशेषताएँ बताई गई हैं वे प्रायः एक साथ समुक्त रूप में प्रत्येक युद्ध में प्राप्त नहीं होती। उदाहरण के लिए यह युद्ध होते हैं तो उनके कर्त्ता दो स्वतन्त्र राजनैतिक इकाइया नहीं होती। इसी प्रकार वर्तमान काल के आधुनिक युद्ध, शीत युद्ध, राजनैतिक युद्ध आदि में संगठित सशस्त्र सेनाओं का सहारा नहीं लिया जाता। हान का भारत-पाक

सघर्ष संगठित, सशस्त्र सेनाओं द्वारा राष्ट्रीय नीति की साधनों के लिए किया गया दो स्वतन्त्र राजनैतिक इकाइयों के बीच का सघर्ष था किन्तु ऐसा होते हुए भी उसको तकनीकी धर्मों में युद्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनैतिक सम्बन्ध बने हुए थे तथा किसी भी पक्ष द्वारा मरहारी तौर पर युद्ध की घोषणा नहीं की गई थी।

नवीन अंग्रेजी शब्द कोप द्वारा दी गई परिभाषा युद्ध युद्ध को भी अपने में समाहित कर लेती है। उसके अनुसार युद्ध सशस्त्र शक्ति द्वारा शत्रुतापूर्ण व्यवहार है जो कि राष्ट्रो, राज्यो या शासकों के बीच में होता है या एक ही देश के दो देशों के बीच में होता है, यह विदेशी शक्ति के विरुद्ध या उसी राज्य के विराधी दल के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग है। युद्ध के सामान्य स्वरूप को चित्रित करने वाली एक दूसरी परिभाषा सरल शब्दों में हाफमैन निकर्सन (Hoffman Nickerson) द्वारा की गई है। वे कहते हैं कि युद्ध दो ऐसे मानव समूहों के बीच किया जाने वाला व्यवस्थित बल का प्रयोग है जो कि विरोधी नीतियों का अनुसरण करते हैं तथा जिनमें से प्रत्येक अपनी नीति को दूसरे पर लागू करने का प्रयत्न करता है। युद्ध के एक जर्मन विचारक कार्ल क्लाजविच (Karl Clausewitz) का कहना है कि 'युद्ध' राजनैतिक व्यवहार का आवश्यक अङ्ग है और इसलिए अपने ध्येय में कोई अन्तर्गत चीज नहीं है। युद्ध और कुछ नहीं केवल कुछ अन्य साधनों के माध्यम से राजनैतिक व्यवहार (Political intercourse) है। पामर तथा परकिन्स के कथनानुसार क्लाजविच के शब्दों को 'युद्ध' की परिभाषा मानना उपयुक्त नहीं है, फिर भी यह सच है कि इनके द्वारा युद्ध के स्वरूप की एक भूलक का आभास मिलता है। आज 'न शान्ति-न युद्ध' की जो स्थिति वर्तमान है उसका इन शब्दों द्वारा दिग्दर्शन कराया गया है।

युद्ध की जितनी भी परिभाषायें दी जाती हैं या ता मधुरी होनी हैं अथवा एकपक्षीय इतनी सामान्य होती हैं कि जिने किसी विशेष युद्ध पर लागू न किया जा सके अथवा इतनी विशिष्ट हानी हैं कि उनका आधार पर युद्ध के अन्य रूपों का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। इस सबका कारण परिभाषा वर्तमानों के अध्ययन का दोष अथवा उनकी प्रक्षमता नहीं है बल्कि युद्ध की प्रकृति की विभिन्नता है। इसके साधनों, कारणों, परिणामों एवं अन्तों में इतनी विभिन्नताएँ (diversities) वर्तमान हैं कि कोई सर्वमान्य, सर्व-यापी तथा पूर्ण रूप से सतोषजनक परिभाषा दी ही नहीं जा सकती। युद्ध के कारणों को जानने के बाद सम्भवतः इसके स्वरूप का अवगमन मुगम बन जायेगा।

युद्ध के कारण (The causes of war)

कार्य के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कार्य का कारण होता है और यदि उस कारण को हटा दिया जाए तो कार्य स्वतः ही विनष्ट हो जायेगा। युद्ध के मयांक परिणामों और मानव जाति के लिए इसके खतरों को देख कर प्लानि-प्रेमी तथा बुद्धिशील वर्ग द्वारा उन कारणों को खोजने का प्रयत्न किया गया है जो एक राष्ट्र को युद्ध का रास्ता भ्रमने के लिए उत्तेजित या मजबूर करते हैं। मिने मिने विचारकों ने युद्ध के अनेक मूल एवं गौण और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कारणों का वर्णन किया है। युद्ध के कारणों को प्रायः दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम भाग में वे सभी कारण हैं जिनके कारण युद्ध की प्राण नष्टक उठती है, इनको युद्ध के तत्सम्बन्धित कारण कहा जा सकता है। दूसरी श्रेणी में वे सभी कारण आते हैं जो उस युद्ध के लिए एक लम्बे समय से ही अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे थे।

प्रथम विश्वयुद्ध के कारणों का अध्ययन करते हुए प्रोफेसर सिडनी फे (Professor Sidney B. Fay) ने बताया कि युद्ध का सबसे मूल कारण गुप्त संधियों की व्यवस्था (System of secret alliances) थी जो फ्रांको-प्रुमियन युद्ध के बाद प्रारम्भ हुई थी। दूसरे अल्प सहायक कारण चार थे—सैनिकवाद, राष्ट्रवाद, धार्मिक साम्राज्यवाद और सम्राट् पत्र-व्यवहार। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति के एक दूसरे विद्वान् क्विन्सी राइट (Quincy Right) ने युद्ध के विभिन्न कारणों का वर्णन किया है—इन कारणों में कुछ तो मूल हैं तथा कुछ तात्कालिक हैं। कभी-कभी कुछ घटनाएँ युद्ध का कारण बन जाती हैं, कभी लोगों की मनोभावनाएँ एवं महत्वाकांक्षाएँ युद्ध को प्रारम्भ करा देती हैं। इनके अतिरिक्त शस्त्रों की दौड़, कूटनीतिक व्यवहारों की अनुसृतता, पालिग्य सम्बन्धी नीतियाँ, सम्प्रभुता की मान्यता, उपनिवेशों के मतभेद, देश के विस्तार की प्रवृत्ति, आदि अन्य बातें भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को भड़काने में सहायक होती हैं। विषमता राइट के मतानुसार युद्ध के कारणों को बड़े दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है। इसके राजनैतिक, तकनीकी, सैद्धान्तिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक तथा धार्मिक कारण हैं। टर्नर (Tall A. Turner) ने अपनी पुस्तक 'युद्ध के कारण और नवीन शक्ति' (The causes of war and the new revolution) में युद्ध के ४१ कारणों का उल्लेख किया है। वे इन कारणों

को चार भागों में विभाजित करते हैं—धार्मिक, राजवश सम्बन्धी, धार्मिक और भावात्मक । अन्य अनेक विचारकों द्वारा भी युद्ध के कारणों की व्याख्या की गई है । मुख्य रूप से जिन कारणों को प्रायः सभी विद्वान किसी न किसी रूप में मानते हैं, वे निम्न हैं—

(१) युद्ध का सामाजिक कारण (Social cause of war)

युद्ध का आधारभूत कारण विरोध होता है । जब दो देशों के सामाजिक जीवन की भिन्नता इतनी बढ़ जाती है कि उनके बीच सामन्तस्य का कोई तत्त्व बाकी नहीं बचता और एक दूसरे के हित परस्पर टकरा जाते हैं तो उन देशों के बीच युद्ध अवश्यम्भावी बन जाता है । इतिहास में युद्ध के उदाहरणों पर ध्यान देने में यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म, जाति, संस्कृति और दुःसाहस एवम् इतने प्रभावित होकर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं । मध्ययुगीन यारोव में धार्मिक आचार पर अनेक युद्ध हुए हैं । यारोव के विभिन्न देशों ने एशिया और अफ्रीका में अपना साम्राज्य बढाने के लिए किए गए युद्धों में उनका का समर्थन जानीय आधार पर प्राप्त किया—काने-गोरे का और धार्मिक तथा अनार्य के भेद की दृष्टि दी गई । विभिन्न जाति एवं धर्म वाले लोगों के बीच सांस्कृतिक सर्वोच्चता का प्रचार करके अनेक देशों को सांस्कृतिक दृष्टि से हीन देश पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया । कुछ देशों का ममान दुःसाहसपूर्ण प्रवृत्तियाँ का होता है जबकि दूसरे कुछ देश सर्वत्र अनादनीय रूप से भयभीत रहते हैं—इन दोनों ही स्थितियों में वे देश युद्ध के पथ के राहें बन जाते हैं ।

(२) युद्ध का राजनैतिक कारण (Political cause of war)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में संपर्क का मुख्य कारण राजनैतिक विभिन्नता एवं विरोधों की भी माना जा सकता है । एक देश की धरेख राजनीति उस देश को दूसरे देशों के साथ युद्ध छेड़ने के लिए प्रारम्भित कर देती है । द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व इटली ने एवीमीनिया पर जा आक्रमण किया था उसका कारण यह बताया जाता है कि इसे प्रकार के युद्धों से बचा के तानाशाही शासक जनता का ध्यान अनेक प्रशासनिक समस्याओं से हटाना चाहते थे । दूसरे अन्य देशों में जहाँ राजसत्तात्मक शासन होता है, एक राजा की महत्वाकांक्षाएँ एवं प्रसारवादी नीतियाँ प्रायः युद्ध का कारण बन जाती हैं । एक देश जब साम्राज्यवादी नीतियों को अपना लेता है तो

उसे युद्ध छेड़ने की प्रमुख आवश्यकता पड़ जाती है। साम्राज्यवाद जैसा कि मार्गेन्थो का मत है, वर्तमान स्थिति (Status-quo) को बदलने का प्रयास है। यह परिवर्तन करते समय उन शक्तियों से युद्ध करना आवश्यक बन जाता है जो स्थिति को बनाये रखने के पक्ष में हैं तथा परिवर्तन के द्वारा उनके हितों को भ्रष्ट पट्टवती है। युद्ध के राजनैतिक कारणों में ही एक दूसरा कारण है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रवाद के निर्पेक्षात्मक और विधेयात्मक दो रूप हैं। जब राष्ट्रीयता की भावना एक देश के निवासियों को विदेशी शासकों के बगुल से छूटने को वलिदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है और स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के बाद जब उनको राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों की प्रेरणा देती है तो इसे इसका उज्ज्वल पक्ष माना जाता है। किन्तु राष्ट्रीयता की भावना का कार्य केवल यही समाप्त नहीं हो जाता। एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रीयता की भावना से प्रभावित लोग दूसरे देश पर अपना शासन स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। युद्ध इस प्रयत्न की आवश्यक एवं स्वाभाविक परिणति है। इन सबके प्रतिरिक्त कूटनीतिक सम्बन्धों में एक देश के स्वार्थों की अत्यधिक अभिव्यक्ति भी प्रायः युद्ध का कारण बन जाती है।

(३) युद्ध के युद्ध-कौशल सम्बन्धी कारण (Strategic causes of war)

जिस प्रकार साम्राज्यवाद का कारण साम्राज्यवाद होता है उसी प्रकार युद्ध का कारण कभी-कभी युद्ध या युद्ध सम्बन्धी अन्य बातें बन जाती हैं। उदाहरण के लिए हम एक ऐसे भूतण्ड का ले सकते हैं जिसका सामरिक दृष्टि से भारी महत्व है और जिस पर अधिकार करके एक देश दूसरे की अपेक्षा अधिक शक्ति-सम्पन्न बन सकता है। ऐसे भूतण्डों के पीछे इतिहास में अनेक बार युद्ध छेड़े गये हैं। इसी प्रकार शस्त्रों की समस्या भी कई बार युद्ध का कारण बन जाती है। कुछ देशों का राष्ट्रीय हित इस बात में निहित रहता है कि अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगा दी जाए। दूसरे दूसरे देश जो शस्त्रों का निर्माण करते हैं उस देश के राष्ट्रीय हित के विरोधी बन जायेंगे क्योंकि ऐसा होने पर उस देश को जो निःशस्त्रीकरण की नीति अपनाता असम्भव बन जाता है।

पाकिस्तान तथा चीन की नीतियों से मजबूर होकर भारत को शस्त्रीकरण का मार्ग अपनाना पड़ा, उसे अपने बजट का अधिकांश भाग रक्षा-व्यवस्था को मजबूत करने एवं सैनिक तैयारियाँ करने पर व्यय करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों से उस पर अणुबम के निर्माण का भी दबाव डाला जा

रहा है क्योंकि साम्यवादी चीन ने १९६४ में ही अणुबम का परीक्षण कर लिया है। युद्ध के कारणों में विश्व की स्थिति का भी भारी प्रभाव पड़ता है। विश्व में कितने गुट हैं, किम गुट की कितनी शक्ति है तथा एक विशेष देश पर इनका प्रभाव कैसा तथा कितना पड़ता है यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की स्थिति के अनुसार एक देश के हितों में भी भेद भाग रहता है और उस स्थिति के अनुसार यदि युद्ध आवश्यक बन जाए तो देश उसे अपनाते का तयार हो जायेगा।

(४) युद्ध के आर्थिक कारण

(Economic Causes of war)

युद्ध के आर्थिक कारणों का उल्लेख ऐसे तो अनेक विचारकों द्वारा किया गया है किन्तु कार्ल मार्क्स तथा साम्यवाद के अन्य समर्थकों ने तो इसे युद्ध का एकमात्र महत्वपूर्ण कारण माना है। स्टालिन तथा लेनिन आदि साम्यवादी नेताओं ने यह माना था कि पूँजीवादी देशों में जो आर्थिक विकास होने है तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसका यह आवश्यक परिणाम है कि साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया जाय। माँग से अधिक उत्पादन होने से विदेशों में उस माल की खरीद के लिए बाजारों की खोज की जाती है, आवश्यक किया जाते हैं और दूसरे देशों को पराधीन बनाया जाता है। साम्राज्यवाद के जितने भी कारण होने हैं उन सबको युद्ध का कारण बताया जा सकता है। एक देश की बाणिज्य नीति, विदेश में उसकी पूँजी का व्यय, तथा अन्य आर्थिक तत्व एक देश को युद्ध के लिए मजबूर करते हैं।

युद्ध के उक्त कारणों के प्रतिरिक्त भी विभिन्न गौण कारण हैं जो या तो इन कारणों के प्रत्यक्ष हैं अथवा स्वतन्त्र रूप से ही युद्ध के अनुकूल वातावरण तैयार करने का काम करते हैं। इन समस्त कारणों का महत्व परिस्थिति और अवस्था के साथ साथ बदलता रहता है। यह हो सकता है कि एक युद्ध में राजनैतिक कारण प्रभावकारी रहे हों और यह भी हो सकता है कि वह युद्ध केवल राजनैतिक कारणों से ही संचालित किया जा रहा हो। युद्ध के कारणों के आधार पर युद्धों को अलग-अलग नाम दिया जा सकता है जैसा कि साम्यवादी आलोचकों द्वारा किया जाता है। वे लौंग साम्राज्यवादी युद्ध, क्रान्तिकारी युद्ध, स्वतन्त्रता के लिए युद्ध आदि के बीच भेद दिखाते हैं।

विक्रम स्टीड (Wickham Steed) ने युद्ध के कारणों में 'मय' को प्रधान माना है। वे कहते हैं कि सभ्रस्य की भावना निश्चय ही भाव के

विश्व में युद्ध का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरे विचारक 'सम्प्रभु' राज्यों के अस्तित्व को युद्ध का प्रमुख कारण मानते हैं। आर्नोल्ड ब्रेच्ट (Arnold Brecht) ने लिखा है कि सम्प्रभु राज्यों के बीच युद्ध होते हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि विश्व में सम्प्रभु राज्य हैं। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए क्विन्सी राइट महोदय ने बताया कि युद्ध का कारण सम्प्रभु राज्यों का अस्तित्व है; यह कहने की अपेक्षा यदि यह कहा जाय कि युद्ध इस कारण होता है कि विभिन्न देश सम्प्रभु बनना चाहते हैं तो अधिक उपयुक्त रहेगा। युद्ध प्रायः इस कारण होते हैं क्योंकि देशों की शक्ति के प्रयोग को नियमित करने के लिए कानून अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसी कोई सशक्त व्यवस्था नहीं है। कुछ विचारक युद्ध को मनुष्य की प्रकृति में निहित मानते हैं। उनका तर्क यह है कि मानव सम्यता के प्रारम्भ से ही युद्धों का अस्तित्व है। आज तक किसी युग में विश्व का कोई स्थान ऐसा न रहा जिसे युद्ध की विपत्ती गैर से छूटता या अप्रभावित माना जा सके। किन्तु दूसरी ओर पामर तथा परकिन्स जैसे विचारक हैं जो इस तर्क की सत्यता में सन्देह करते हैं। उनका कथन है कि इतिहास से युद्धों के उदाहरणों का सचप करके यह कहेना उचित नहीं है कि मनुष्य युद्धप्रिय होता है बल्कि यह कहा जा सकता है कि मनुष्य अब तक कोई ऐसी शैक्षिक, सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था करने में असमर्थ रहा जिसमें कि युद्ध का कोई स्थान ही न हो।

सच तो यह है कि युद्ध का कोई एक विशेष कारण नहीं बताया जा सकता बल्कि युद्ध तो एक दूसरे से सम्बन्धित अनेक कारणों का समन्वित परिणाम है। इसी भाव का व्यक्त करते हुए क्विन्सी राइट (Quincy Right) ने बताया है कि युद्ध वास्तव में एक ऐसी परिस्थिति का परिणाम है जो उन सारी चीजों से पैदा होती है जो युद्ध प्रारम्भ होने तक मनुष्य जाति में हुई हैं। युद्ध के कारण ही प्रायः एक देश की राष्ट्रीय नीति के आधार बन जाते हैं। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सम्प्रभुता एवं अन्य युद्ध के उपयुक्त कारण जब एक देश की राष्ट्रीय नीति का आधार बन जाते हैं; उसके बाद ही युद्ध प्रारम्भ होता है। पामर तथा परकिन्स के मत में जब 'कुछ बीज' युद्ध का कारण बनती हैं तो इसका कारण यही है कि वह 'कुछ बीज' उस देश की राष्ट्रीय नीति का आधार बन चुकी होती हैं।

युद्ध के कार्य

(The Functions of War)

युद्धों के द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है और यही कारण है कि विभिन्न देशों द्वारा इसका सहारा लिया जाता है। यदि युद्ध की सैबत हानिपा

ही होती अथवा यह केवल निरर्थक ही होता तो यह व्यक्ति की पूछ की भाँति कमी को मिट गया होता। युद्ध तब तक विश्व में रहेगा जब तक मानव जाति के शासक इसका कोई विकल्प नहीं खोज निकालते। युद्ध से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है उनको दूसरे किसी साधन द्वारा प्राप्त किया जाना असम्भव है और यही कारण है कि युद्ध खर्चोला, विध्वंसक तथा हिंसात्मक होने पर भी अपनाया जाता है। क्लाइड ईगल्टन (Clyde Eagleton) का कहना है कि युद्ध से कुछ साध्यों की प्राप्ति होती है। युद्ध से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है वे एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित रहते हैं कि उनमें से कौन सा प्रधान है तथा कौन सा गौण, यह निश्चित करना बड़ा कठिन हो जाता है। युद्ध के विभिन्न कारणों का निम्न प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है।

(१) न्याय की स्थापना—युद्ध चाहे बितना भी बुरा क्यों न हो, इसके द्वारा समाज में फैले हुए अनेक अन्यायों को दूर किया जाता है। किसी दूसरे साधन के द्वारा इस दुर्गति को दूर करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि मनुष्य की अन्याय की भावनाएँ उसके स्वार्थ में गहरी जमी रहती हैं तथा मुझारवादी नीतियाँ उसकी जडा को कुदेने में असमर्थ रहती हैं। किन्तु युद्ध द्वारा जो नीतियाँ अपनायी जाती हैं वे शपथवादी होती हैं तथा उनकी सफलता में थोड़ी निश्चितता का पुट रहता है। यही कारण है कि शताब्दियों से युद्ध को अन्याय को दूर करने वाले साधन के रूप में अपनाया जा रहा है। प्रो० शॉटवेल (Professor Shotwell) के मतानुसार युद्ध का प्रयोग जैसे आक्रमणों के लिए किया गया है उसी प्रकार उसे अन्यायपूर्ण आक्रमणों के एक विरोधी साधन के रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। इतिहास में युद्ध के द्वारा जैसे एक अपराधी का अभिनय किया गया है उसी प्रकार इसने अनेक लाभदायक कार्य भी किये हैं।

(२) शोषण का विरोध—जब किसी देश, वर्ग, जाति या धर्म के लोगो द्वारा दूसरे भिन्न देश, वर्ग, जाति या धर्म के लोगो का शोषण इस आधार पर किया जाय कि वे दूसरे की अपेक्षा शक्तिशाली हैं तो प्रायः शोषित वर्ग की मुक्ति के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि वह युद्ध जैसे हिंसात्मक साधन को अपनाये। इतिहास साक्षी है कि व्यक्ति एवं समुदायों द्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए तथा शोषण से मुक्ति के लिए अनेक बार युद्ध लड़े गये हैं। दमन को सहने की व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसके अगे बढ़ने पर दमन का विरोध करने के लिए युद्ध का सहारा लेना आवश्यक बन जाता है। अमरीका की आन्ति, फ्रान्स की आन्ति, लेटिन अमरीकियों का स्वतन्त्रता

के लिए युद्ध, भयभीतता का गृहयुद्ध तथा स्पेन-भयभीतता युद्ध आदि उदाहरणों तथा उनके परिणामों को देख कर यह कहा जा सकता है कि युद्ध के भले ही अनेकों दुष्परिणाम हों किन्तु इसको स्थगन्यता, अधिकार, न्याय आदि की प्राप्ति के साधन के रूप में अपनाया जा सकता है।

(३) युद्ध एक आवश्यक बुराई है—हिंसात्मक साधनों का प्रयोग शुभ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कभी-कभी आवश्यक बन जाता है। हिन्दु पुराणों एवं धर्मशास्त्रों में जिव प्रयात् कल्याण या शुभ को पार्श्वी अर्थात् शक्ति का पति माना गया है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप द्वारा शुभ और शक्ति के अभिन्न स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। देवताओं ने राक्षसों के विरुद्ध अनेक बार युद्ध किये क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। आज के साम्यवादी भी यह मान कर जाते हैं कि वे अपने अंतिम लक्ष्यों को बिना युद्ध के प्राप्त नहीं कर सकते। उनका विचार है कि साम्यवादी और पूँजीवादी राष्ट्रों के बीच सघर्ष और युद्ध होना स्वामाविक है। ये विचारक ऐसे युद्धों को न्यायपूर्ण मानते हैं।

(४) युद्ध का सन्तोषजनक विकल्प नहीं है—मनोविज्ञान यह बताता है कि कमजोर व्यक्ति प्रायः अधिक गुस्सा वाता व भगबालू होता है। इसी प्रकार जो देश अथवा देश के भी जो बर्ग गरीबी से पीड़ित, अज्ञानी और बहिष्कृत व्यक्तियों से पूर्ण होते हैं, वे युद्ध को, अपनी असहनीय दशा से छुटकारा पाने के लिए अपना स्विकार कर लेते हैं। जिस प्रकार दीपक बुझने से पूर्व एक तीव्र चमक देता है उसी प्रकार ये देश भी अपने साम्य के पासे को पनटने की धुन में युद्ध को अपनाते हैं क्योंकि जीवन उनकी दृष्टि से बड़ा सस्ता होता है और युद्ध में जीने के लिए उनके पास बहुत कम या कुछ भी नहीं रहता।

(५) युद्ध सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति का साधन है—अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक राष्ट्र सम्प्रभु है और इस नाम से युद्ध छेड़ना वह अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। यदि सच्चे अर्थों में प्राप्त युद्ध को नष्ट करना चाहते हैं तो इसका प्रथम होगा राज्यों की सम्प्रभुता को मिटाना और इसे पाई भी राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। जिब प्राप्ति की स्वायत्तता के लिए एक राज्य सध कुछ स्वीकार कर लेता किन्तु वह 'स्वतन्त्रता' (Self defence) के अधिकार को नहीं छोड़ेगा क्योंकि यह उसकी सम्प्रभुता का परिचायक है। एक राज्य के ऊपर अनेक उत्तरदायित्वों का भार रहता है, इन उत्तरदायित्वों की निभाने के लिए उसे सम्प्रभुता की आवश्यकता रहती है और जब तक सम्प्रभुता रहेगी तब तक युद्ध भी रहेगा। पापक तथा परहिंस का मत है कि

राज्यों का तब तक युद्ध छेड़ने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता जब तक कि उनके पास परा कर देने के लिए अनेकों उत्तरदायित्व है। विश्व में जब तब दुर्ग और बुराईया मौजूद हैं तथा इनको दूर करने का कोई सफल विवरण नहीं है तब तब युद्ध घना रहेगा। सत्तार से दमन, अन्याय एवं बुराईयो का दूर किये बिना युद्ध को मिटाने का प्रयास अधिक लाभदायक नहीं लगता है।

(६) युद्ध आधुनिक विश्व का निर्माता है—कहा जाता है कि सोने को प्राण में तपाने पर ही वह कुन्दन बनता है और जैसे प्रापतियों के बीच एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निलरता है तथा उसका जीवन प्राण बढ़ता है उसी प्रकार युद्ध द्वारा एक राष्ट्र के व्यक्तित्व का सही अर्थों में निर्माण होता है। युद्धों के द्वारा ही एक राष्ट्र की सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं। जैसा कि प्रोफेसर शाटवेल ने लिखा है कि आज के विश्व का नक्शा अधिकांश युद्ध के मैदानों में ही निश्चित किया गया है। यह कथन बहुत कुछ सही भी है क्योंकि वर्तमान विश्व के अधिकांश राज्यों की सीमाओं का अन्तिम रूप युद्ध द्वारा ही निश्चित किया गया है। किन्सी राइट (Quincy Right) के मतानुसार युद्ध को विश्व के महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तनों को करने के लिए, राष्ट्र राज्यों के निर्माण के लिये, आधुनिक सभ्यता का विश्व भर में प्रसार करने के लिए तथा उस सभ्यता के प्रभावकारी हितों को परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया गया है। वातून, विदेश नीति, सैनिक, तकनीकी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की कुछ परिस्थितियों में युद्ध नीति का एक मूल्यवान् साधन बन जाता है। फामर तथा परदिन्ता के शब्दों में 'संक्षेप में युद्ध आधुनिक विश्व का—उसके राज्यों, कारखानों, इसकी नैतिकता और इसके सांस्कृतिक रूप का प्रमुख निर्माता रहा है।'

(७) युद्ध व्यक्ति को ऊँचा उठाता है—युद्ध में जीवन घन, जमीन, जायदाद आदि का जो विनाश होता है वह व्यक्ति के मन में इन सब वस्तुओं की नश्वरता के भाव जाग्रत कर देता है। इसके परिणामस्वरूप वह स्वार्थ, परिग्रह, लोभ, मोह आदि दुर्गुणों के स्थान पर उदार मन, निर्भय, तथा अपरिग्रही बनता है, उसमें बलिदान करने की शक्ति आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि युद्ध के कारण व्यक्ति की नैतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताएँ प्रखर होकर सामने आती हैं। भारत-पाक संघर्ष के समय भारत के मनोबल तथा सैनिकों को भारतीयों द्वारा दी गई तन, मन और धन की सहानुभूति को देख कर लगता है कि इस युद्ध द्वारा भारत में एक नितार आ गया। गृह-मन्त्री नन्दा ने युद्ध के दौरान राष्ट्र के नाम अपने एक संदेश

मे यह स्वीकार किया था कि यह युद्ध एक प्रकार की अग्नि परीक्षा थी और भारत इसमें से निक्कन कर एक नया ही रूप धारण कर लेगा। प्रायः दवाईयां कड़वी होती हैं किन्तु रोग को दूर करने व स्वास्थ्य में निखार लाने के लिए वे आवश्यक होती हैं। वही प्रकार युद्ध भी कुछ दुरे परिणाम लाता है किन्तु देश के व्यक्तित्व के निर्माण में यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है। कहा जाता है कि सम्मानहीन एव भ्रष्ट शक्ति की अपेक्षा सम्मानपूर्ण युद्ध अच्छा है जो आत्म-वसतिदान, समानता, ईश्वर प्रेम, परार्थ राष्ट्रीय एकता आदि के भारों का विकास करता है।

(८) युद्ध विकास को सहो दिशा देता है—डाबिन ने जीव विज्ञान के सम्बन्ध में दो सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था जहाँ के आधार पर यह कहा जाता है कि युद्ध का होना राष्ट्रों के सही विकास के लिए आवश्यक है। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कमजोर राष्ट्रों को मिला देती है तथा शक्तिशाली लोगों के उन्नति व विकास के लिए मार्ग साफ कर देती है। बर्नार्डो (Bernhardt) महोदय के मतानुसार युद्ध प्रथम मूल की प्राणी-शास्त्रीय आवश्यकता है। बिना युद्ध के कमजोर जातिना स्वल्प दरवा के विकास को रोक देंगे तथा सामान्य रूप से पतन प्रारम्भ हो जायगा।^१

युद्ध के उपर्युक्त कारणों अथवा लाभों की अतिशयोक्ति बना कर इनकी आलोचना की जा सकती है किन्तु इनको पूरी तरह से अस्तित्व नहीं माना जा सकता। विलर्ड वालर (Willard Waller) के मतानुसार युद्ध से कोई लाभ नहीं है तथा किसी भी समस्या को इसके द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता। किन्तु पामर तथा परकिन्स का कहना है कि प्रमाणों के आधार पर यह हिट किया जा सकता है कि युद्ध के द्वारा कभी-कभी अनेक लाभ प्राप्त हो जाया करते हैं। इसलिए उनका कहना है कि युद्ध का विरोध करते समय यह ठक देना अनुचित रहेगा कि इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता या इनका कोई उपयोग नहीं है वरन् कहना यह चाहिए कि यह एक अमानवीय तथा जगती साधन है और इनके द्वारा अच्छे उद्देश्य भी प्राप्त नहीं करने चाहिए।

युद्ध का विगत एवं वर्तमान स्वरूप (The Past and Present Form of War)

जब से राज्य व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ उसी समय से राष्ट्रीय सुरक्षा

1. Friedrich Von Bernhardt, Germany and the next war, P. p. 18,20

के नाम पर राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए तथा सधर्मों को सुलभाने के लिए सशस्त्र शक्ति का प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की केन्द्रीय विशेषता रही है। सशस्त्र सेना से हमारा तात्पर्य किन्सी राइट (Quincy Wright) महाशय की मानि अनुशासित या सोद्देश्य नियन्त्रित हिंसा से है, चाहे उसके साधन हथियों के टुकड़े, परपर, घनुष बाण, बन्दूकें, तोपें, धनुषम या प्रक्षेपास्त्र कोई भी चीज हो और इस तरीके को प्रयुक्त करने वाले समूह में चाहे दर्जनों व्यक्ति हो अथवा लाखों व्यक्ति। यह सशस्त्र शक्ति अथवा सैनिक शक्ति विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाला अन्तिम तत्व होता है और गैर सैनिक साधनों की प्रभावशीलता बहुत कुछ इसी पर आधारित रहती है। राजनीति की भाँति युद्ध में एक समूह द्वारा अन्य समूहों के विरुद्ध क्रिया की जाती है। युद्ध का व्यापक रूप असा कि आज हमें दिखाई देता है केवल सशस्त्र सधर्म ही नहीं होता बरन् कूटनीति, आर्थिक साधन एवं प्रचार आदि अनेक साधनों को प्रयुक्त किया जाता है। युद्ध का यह व्यापक रूप अपने प्रारम्भिक काल में इतना जटिल नहीं था। सैनिक शक्ति का अस्तित्व पहले भी एक रक्षात्मक रूप में था और इसे दबावकारी साधन के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता था। यह अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की एक मापने योग्य वास्तविकता एवं प्रमुख मनोवैज्ञानिक तत्व था। सैनिक शक्ति का अस्तित्व केवल युद्ध में ही नहीं चलकता बरन् यह निष्क्रिय रूप में भी रह सकता है और समय-ममय पर अपनी उपस्थिति का भान भी करा सकता है। आज के राजनैतिक तरीकों में जो गैर सैनिक तकनीकें अपनाई जाती हैं वे भी सैनिक साधनों के सहारे प्रभावशील बनाई जाती हैं।

युद्ध एवं हिंसा का अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में इतना महत्व है कि वाल्टेयर जैसे विचारकों को यह कहना होता है कि इतिहास मुख्य रूप से हिंसा विध्वंस, मानवीय काट एवं मृत्यु का अभिलेख है। पैडिलकोर्ड तथा रिमन इस कथन पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कोई इस दर्शन को माने या न माने किन्तु तथ्य यह है कि मानव जानि ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज में रहती है जिसमें कि भगड़े और सधर्म हैं। सन् १८२० से लेकर सन् १९२९ तक करीब ८२ युद्ध लड़े गए तथा इनमें से प्रत्येक में दस हजार से भी अधिक लोग मारे गये। सन् १९४५ से लेकर सन् १९६५ तक के छोटे से बाल में चालीस युद्ध लड़े गए। युद्धों की गति कम होने की अपेक्षा बढ़ती ही जा रही है।

अतीत काल में युद्धों का स्वरूप सीमित था और सामान्य व्यक्ति इसमें बहुत कम सम्बन्ध रखता था। यदि युद्ध में उसका स्थानीय समाज ही उलझ जाए तो उसे ज्ञात होता था। प्रसारहवी शताब्दी तक युद्धों का स्वरूप सीमित

होता था और वर्तमान राज्य व्यवस्था के प्रारम्भ तक वे सीमित रहे। इससे पूर्व युद्धों का सम्बन्ध राजाओं और प्रजापतियों में रहता था तथा इन भगवों और सधवों का परिणाम भी शाही परिवारों पर होता था। पन्द्रहवीं शताब्दी से लेकर फासीवीं क्रि.पू तक यूरोप की सेनाएँ छोटे व्यावसायिक निकाय होती थी। इनमें अधिकांश कार्यकर्ता भाड़े पर रखे जाते थे। युद्ध के क्षेत्र में भी सिपाही के विरुद्ध सिपाही को लड़ाने में अधिक धृष्टता और विरोध का प्रचार नहीं करना होता था। इन भाड़े के सैनिकों का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना होता था। वे यह नहीं चाहते थे कि युद्ध भूमि पर अपने प्राण दे दें और न ही उनकी यह कामना होती थी कि वे अपने अधिकतम विरोधियों के प्राण ले लें। इसके अतिरिक्त विरोधी सेनाओं के नेता भी यह नहीं चाहते थे कि उनके सिपाही बलिदान हो जाए क्योंकि वे उनकी कार्य करने वाली पूँजी थे। वे जब अपनी सेनाओं पर खर्च करते थे तो यह कामना करते थे कि सेनाएँ बनी रहे। विरोधी वर्ग दूसरे पक्ष के सैनिकों को इसलिए नहीं मारना चाहता था कि उन्हें जिन्दा रखने पर या बन्दी बना कर बेचा जा सकता था भ्रष्टा स्वयं की सेना में रखा जाता था। शत्रु को समाप्त करना किसी भी पक्ष का उद्देश्य नहीं होना था क्योंकि यदि शत्रु न रहेगा तो वे बेरोजगार हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में इस काल में लड़े जाने वाले इटली के अधिकांश युद्ध क्रूरता एवं कृतनीति की मांग करते थे जिसके आधार पर बिना पुनः तरावा किये ही उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मैकियावेली (Machiavelli) ने पन्द्रहवीं शताब्दी के ऐसे अनेक युद्धों का वर्णन किया है जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थे किन्तु जिनमें एक भी व्यक्ति नहीं मरा और मरा भी तो एक या दो। उनकी मृत्यु का कारण भी शत्रु का आघात नहीं होता था बल्कि घोंडे से गिर कर मर जाता था। मैकियावेली का यह कथन चाहे अतिशयोक्ति मान लिया जाए किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय के युद्ध पर्याप्त सीमित होते थे। नेपोलियन के युद्धों को तथा धार्मिक युद्धों को छोड़ कर वे शांति की युद्धों में कोई समानता नहीं रखते थे। फ्रांस की क्रांति ने और बाद में नेपोलियन ने बड़ी सेनाएँ बनाने और उनका समयन करने की तकनीकों का विकास किया। राष्ट्रवाद के उदय के कारण इन बड़ी सेनाओं की अन्धा समझा जाने लगा। जनसत्ता की वृद्धि के परिणामस्वरूप और औद्योगिक क्रांति के कारण युद्ध के आचरण का रूप एवं स्तर परिवर्तित हो गया। राष्ट्रवाद की भावना ने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय हितों को एक बना दिया। इसने लोकप्रिय सेनाओं को व्यापकित ठहराया। मि० ई० एच. कारे के मतानुसार राष्ट्र का समाजीकरण धार्मिक नीति का राष्ट्रीयकरण तथा राष्ट्रवाद

का भौगोलिक प्रसार आदि तत्व मिल कर हमारे समय के सर्वाधिकारवाद के कारण बने हैं और इसकी अभिव्यक्ति सम्पूर्ण युद्ध में हुई। युद्ध के पुरातन एवं नवीन रूप का तुलनात्मक रूप से उल्लेख करते हुए सन् १९१७ में मार्शल फोक (Marshall Fock) ने फ्रांसीसी युद्ध महाविद्यालय के सम्मुख कहा था कि सचमुच एक नया युग प्रारम्भ हो चुका है। यह युग राष्ट्रीय युद्धों का है जिनमें कि राष्ट्र के सारे साधन खोत लग जाते हैं। इसका उद्देश्य शाही खानदान का हित नहीं होता और न ही एक प्रांत को जीतना या अधिकार में करना होता है बल्कि प्रथम तो दार्शनिक विचारों की सुरक्षा एवं प्रसार है और उसके बाद स्वतन्त्रता के सिद्धान्त, एकता तथा विभिन्न प्रकार के भौतिक लाभ आते हैं। ये युद्ध प्रत्येक सैनिक की रुचि और योग्यता को जागृत करते हैं तथा उसके भावों एवं सम्बन्धों का लाभ उठाना चाहते हैं। इन्हें पहले कभी भी शक्ति के तत्व नहीं समझा जाता था। एक ओर तो प्रबल भावनाओं से युक्त मानव शक्ति का व्यापक प्रयोग है जिसमें कि समाज की प्रत्येक क्रिया आ जाती है। इस व्यवस्था में किलेबन्दी, भूमिगत साधनों का प्रयोग, हथियार, गोला बारूद आदि चीजें उपयोगी मानी जाती हैं। दूसरी ओर छठारहवीं शताब्दी के साधन खोतों का प्रयोग अब सैनिक भावना और उचित परम्पराओं के साथ किया जाने लगा है।

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आते आते युद्धों का स्वरूप पूरी तरह बदल गया और अब सम्पूर्ण समाज को युद्ध में अपना योगदान देना होता है जहाँ कि बहुत बड़ी फौज लड़ाई के क्षेत्र में भेज दी जाती है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, अमरीका आदि महाशक्तियों ने प्रत्येक नवम्बर ८० लाख सशस्त्र सैनिक युद्ध के मैदान में भेजे। कुछ राष्ट्रों में तो महिलायें भी सशस्त्र सेनाओं में भाग लेती हैं। सोवियत स्त्रियाँ लड़ाई के मैदान में हथियार धारण करती हैं। युद्ध की दृष्टि से आधुनिक समय ने एक सैनिक और नागरिक के बीच का अन्तर दूर कर दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी तक नागरिकों को जो मुक्ति प्राप्त थी वह अब समाप्त हो गई है और अब आवश्यकता के समय उसे कभी भी युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सकता है। आधुनिक युद्ध की मारों की केवल तभी पूरा किया जा सकता है जबकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र युद्ध की ओर चलते हों तथा समाज की सारी शक्तियाँ इकट्ठी होकर इस एक ही उद्देश्य की ओर लग जायें। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध की परम्पराओं से हमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके आधार पर तृतीय विश्वयुद्ध की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में अधिक अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि तृतीय विश्वयुद्ध में अणुशक्ति के प्रसार का

एक नया तत्व जुड़ गया है। आज की स्थिति में यह सम्भव है कि यदि तृतीय विश्वयुद्ध हुआ तो सशस्त्र सेनाओं को शायद इतना नुकसान न हो और नागरिक जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाए। युद्ध के अर्थ एवं महत्व के प्रति अब जन धारणायें बदल चुकी हैं। साम्यवादी चीन आदि कुछ देशों को छोड़ कर अधिकांश देश यह मानने लगे हैं कि तृतीय विश्वयुद्ध मानव का अन्तिम युद्ध होगा। इतिहासकारों का कहना है कि प्रथम विश्वयुद्ध ही वह आखिरी युद्ध था जिसमें कि राष्ट्रीय ने युद्ध के बाजे बजा कर भाग लिया और नागरिकों न प्रशंसा करके उनके उत्साह को बढ़ाया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद में कुछ नये प्रकार के युद्ध भी सामने आए हैं जैसे राजद्रोह और स्वतन्त्रता के लिए युद्ध, आदि। साम्यवादी देशों द्वारा इन युद्धों को आंतरिक विप्लव द्वारा समर्थित किया जाता है। इस प्रकार के संघर्षों ने सशस्त्र सेनाओं को संयुक्त रूप से राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक कार्य सौंप दिए हैं। इन युद्धों में गैर सैनिक साधनों की भी आवश्यकता होती है क्योंकि केवल सेनाओं द्वारा छारामार युद्ध एवं राजद्रोह नहीं किया जाता। आज अणुशक्ति तृतीय विश्वयुद्ध के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक शक्ति बन गई है। ऐसी स्थिति में छोटे राज्यों की सुरक्षा उस समय तक खारे में है जब तक कि कोई अणुशक्ति सम्पन्न बड़ी शक्ति उसकी रक्षा को अपना हित न समझे।

सम्पूर्ण युद्ध (The Total War)

आधुनिक युद्ध की प्रकृति को देख कर हमें सम्पूर्ण युद्ध की संज्ञा प्रदान की जाती है। मार्गण्डो महाकाव्य में माना है कि आधुनिक युद्धों को चार अर्थों में सम्पूर्ण युद्ध कहा जा सकता है। प्रथम इसलिए कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भावनाओं तथा प्रेरणाओं की दृष्टि से पूर्णतः एक रूप होकर अपने राष्ट्र के युद्ध में लग जाता है। दूसरे, युद्ध में योगदान करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ी होती है। तीसरे, युद्ध से प्रभावित लोग बड़ी संख्या में होते हैं और चौथे, युद्ध के द्वारा जिन उद्देश्यों की साधना के लिए जो प्रयास किये जाते हैं वे अत्यन्त व्यापक होते हैं। पहले इन सभी दृष्टियों से युद्ध सीमित हुआ करता था क्योंकि उनका कोई ही लोगों का भावनात्मक एवं धारणात्मक सहयोग प्राप्त होता था; युद्ध में सक्रिय रूप से बहुत थोड़े लोग लड़ते थे, युद्ध से प्रभावित होने वाली जनसंख्या अधिक नहीं होती थी और युद्ध के उद्देश्य भी सीमित थे; किन्तु आज की स्थिति पूर्णतः विपरीत हो चुकी है।

वर्तमान युग में जब कभी कोई लड़ाई होती है तो समस्त व्यक्तिगत नागरिक अपने देश के द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध के साथ अपने आपको एक रूप कर लेते हैं। यह एकरूपता नैतिक एवं अनुमतात्मक तत्वों के आधार पर स्थापित की जाती है। नैतिक तत्व न्यायपूर्ण युद्ध के सिद्धांत की बीसवीं शताब्दी में पुनरावृत्ति है। इसके अनुसार युद्ध में सलग्न दो राज्यों के बीच भेद करता हुए यह निश्चित किया जाता है कि कौन ऐसा है जिसका कार्य कानून और नैतिकता की दृष्टि से न्यायोचित है तथा जिसकी कानूनी तथा नैतिक दृष्टि से हानिहार न उठाने का अधिकार है। यह सिद्धांत मध्ययुग में अत्यन्त प्रभावशाली था किन्तु आधुनिक राज्य व्यवस्था के जन्म ने इस पर पानी फेर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक नया सिद्धांत विकसित हुआ जो प्रत्येक प्रकार के युद्ध को न्यायोचित ठहराता है। सीमित युद्ध के दौरान न्यायोचित और अन्यायपूर्ण युद्ध के बीच का अन्तर अस्पष्ट रूप से बना रहा किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब युद्ध को एक तथ्य मात्र समझा जाता है जिसका आचरण कुछ नैतिक एवं कानूनी नियमों का विषय है किन्तु इन नियमों की रचना राज्य अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। इस प्रकार युद्ध राष्ट्रीय एवं शासकों के व्यक्तिगत हित का साधन बन गया जिस कूटनीति के साथ संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जाता है।

इस प्रकार के युद्ध में जनता अपने आपको एकाकार करने में कठिनता का अनुभव करती है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जबकि युद्ध के उद्देश्य को नैतिक सिद्ध किया जाए। दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि शत्रु के विरुद्ध तथा अपने समर्थन में नैतिक उत्साह जागृत करने के लिए यह जरूरी है कि अपने पक्ष को न्यायोचित बनाया जाए और दूसरे पक्ष को अन्याय पर आधारित। हो सकता है कि जो व्यावहारिक रूप से या भाववश सैनिक हैं वे बिना इस सबके भी युद्ध में अपनी जान दे दें। किन्तु शस्त्र धारण करने वाले सामान्य नागरिक बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते। उन्नीसवीं शताब्दी के नेपोलियन के युद्धों में तथा इटली और जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के युद्धों में राष्ट्रवाद की भावना ने न्याय के सिद्धांत का कार्य किया।

जिस समय युद्धों के पीछे कोई नैतिक या कानूनी सिद्धांत कार्य नहीं करता या उस समय कोई भी सेना कभी भी लड़ना बन्द कर सकती थी क्योंकि लड़ने वालों की प्रेरणा का स्रोत केवल धन था। युद्ध से पूर्व सेना उस पक्ष का समर्थन छोड़ कर दूसरे गुट में मिल जाती थी जिससे उसने वेतन

प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए सन् १६२५ में पाविया की लड़ाई (The Battle of Pavia) से कुछ दिन पूर्व ६ हजार स्विज और २ हजार इटली के सैनिक फ्रांसीसी सेना को छोड़ गए और इस प्रकार फ्रांसीसी शक्ति एक तिहाई रह गई। सौलहवी एव सत्रहवीं शताब्दियों के घामिक युद्धों में पूरी की पूरी सेना कई बार पक्ष बदल लेती थी। युद्ध क्षेत्र में पर्याप्त व्यक्ति रखने के लिए फ्रेड्रिक महार ने उन लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा की जो कि ६ महीने के अन्दर उनकी इच्छाओं में लौट आयें।

पहले सैनिक सेवा को अपराधों के लिए सजा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। जिन लोगों को मौत की सजा सुनवाई जाती थी उनके सम्मुख एक विकल्प यह होता था कि वे चाह तो सेना में आ जायें। इस प्रकार से संगठित सेना में मारेले जैसी किसी चीज के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लोग न तो अपने देश के प्रति स्वामिमत्ति रखते थे और न ही अपने राजा के प्रति स्वामिमत्त थे। इन लोगों को केवल कड़े अनुशासन और इनाम के आधार पर एक साथ रखा जाता था। उस समय के युद्धों की प्रकृति सैनिकों का सामाजिक सम्मान तथा सामाजिक पृष्ठभूमि आदि बातों के सन्दर्भ में ऐसा होना स्वाभाविक ही था।

सीमित युद्धों के समय जब युद्ध विहासन प्राप्ति के लिए या किसी नगर की प्राप्ति के लिए या राजा के सम्मान के लिए लड़े जाते थे वहां सैनिक सेवा को राजा का वंश परम्परागत विशेषाधिकार समझा जाता था, किन्तु सन् १७६३ के फ्रांसीसी कानून ने जब १८ और २५ के प्रत्येक स्वस्थ पुरुष के लिए सैनिक सेवा आवश्यक बना दी तो युद्ध की नई प्रकृति को पहली बार व्यवस्थापिका की मान्यता प्राप्त हुई। फ्रांस की भाति प्रुसिया (Prussia) ने भी सन् १८०७ में कानून पास किया जिसके अनुसार भाड़े के सैनिकों को रखना बन्द कर दिया, सेना में विदेशियों को लेना बन्द कर दिया तथा सन् १८१४ के कानून के अनुसार अपने देश की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य घोषित कर दिया। इस प्रकार युद्ध का स्वरूप ऐसा हो गया जिसमें कि सारी जनता भाग लेती है।

(७) सम्पूर्ण युद्ध की दूसरी विशेषता यह है कि यह युद्ध केवल सम्पूर्ण जनता का ही नहीं होता बरन् सम्पूर्ण जनता द्वारा लड़ा जाता है। जब बीसवीं शताब्दी में युद्ध की प्रकृति परिवर्तित हो गई और इसका उद्देश्य केवल राष्ट्रीय मुक्ति न होकर राष्ट्रवादी विश्व व्यापकता हो गया तो युद्ध में जनता का योगदान भी अपेक्षाकृत बढ़ गया। अब न केवल स्वस्थ शरीर वाले पुरुषों

को ही युद्ध में लिया जाता है वरन् सर्वाधिकारवादी देशों में तो स्त्रियों और बच्चों को भी युद्ध में भाग लेना पड़ता है। गैर-सर्वाधिकारवादी देशों में भी स्त्रियों की सहायक सेवाएँ उनकी स्वेच्छा के आधार पर माँगी जाती हैं। हर देश में राष्ट्र की सभी शक्तियाँ युद्ध में लगा दी जाती हैं। मोमिन युद्ध के समय अधिकांश जनता का युद्ध में कुछ लेना देना नहीं होता था। सामान्य जनता पर तो केवल यह प्रभाव पड़ता था कि उनसे अधिक कर लिए जाने थे किन्तु आज का युद्ध प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है और उसे इसमें अपना सक्रिय योगदान देना होता है।

इस विकास के लिए उत्तरदायी दो कारण माने जाते हैं। प्रथम यह कि सेनाओं के आकार में वृद्धि हो गई है और दूसरा यह कि युद्ध का यांत्रिकीकरण हो गया है। सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में सेनाओं का आकार बढ़ कर अधिक से अधिक दम हजार हो जाता था। नैपोलियन के युद्धों में कुछ सेनाओं की संख्या कुछ लाख व्यक्तियों तक हो गई। प्रथम विश्वयुद्ध में पहली बार सेनाएँ दम लाख से ऊपर निकल गयीं और द्वितीय विश्वयुद्ध में इनकी संख्या एक करोड़ में भी ऊपर निकल गई। युद्धों में हथियारों, आवश्यक सामग्रियों, यानायाँन एवं संचार आदि का यन्त्रीकरण तथा सेना का बड़ा आकार आज यह माँग करता है कि कार्य करने वाली सारी जनसंख्या अपना पूरा योगदान दे। ऐसा होने पर ही सैनिक सम्पत्ति को युद्ध के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि युद्धभूमि में एक व्यक्ति को सक्रिय रखने के लिए कम से कम एक दर्जन व्यक्तियों के उत्पादनशील प्रयासों की आवश्यकता रहती है। युद्ध-भूमि में लड़ रहे सैनिकों को खाना पट्टुचाने, कपड़ा पट्टुचाने, हथियार भेजने, यातायात और संचार की व्यवस्था करने आदि कार्यों में जितने लोगों को सक्रिय होना पड़ता है उसके आधार पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्तमान युद्ध सम्पूर्ण जनसंख्या द्वारा युद्ध बन गए हैं।

③ युद्धों को सम्पूर्ण कहने का एक तीसरा आधार यह है कि ये सम्पूर्ण जनसंख्या के विरुद्ध लड़े जाते हैं। केवल यही नहीं कि प्रत्येक को युद्ध में भाग लेना पड़ता है वरन् प्रत्येक को युद्ध का परिणाम भी भुगनना पड़ता है। किसी भी युद्ध में होने वाली क्षति के आँकड़े यद्यपि वे विश्वसनीय कम होते हैं किन्तु वे इस कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। पहले युद्ध में जनसंख्या का जो प्रतिशत अपनी जान खो देना या वह आज़ की अपेक्षा बहुत कम है। बीसवीं शताब्दी में युद्ध का स्वयं विध्वंसकारी स्वरूप स्पष्ट हो गया है, इसलिए सैनिक कार्यवाही से हाने वाले हताहतों की संख्या भी

अपेक्षाकृत बढ गई है। धार्मिक युद्धों की समाप्ति के काल से ही गैर-सैनिक जनसंख्या को भी युद्धों के दुष्परिणाम भुगतने होने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं किया जाता कि द्वितीय विश्वयुद्ध की सैनिक कार्यवाही से सामान्य नागरिकों की जितनी जानें गयी वे सैनिकों की तुलना में अधिक थीं। द्वितीय विश्वयुद्ध में सोवियत संघ के हताहतों की संख्या उनकी कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत थी। इस प्रकार आधुनिक युद्ध में गैर सैनिक लोगों के विध्वंस की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। सन् १९६५ के भारत-पाक सैनिक संघर्ष के समय पाकिस्तानी बमबारी ने न केवल भारतीय सैनिकों को हताहत किया बरन् जोधपुर, अमृतसर आदि नगरों के भरीजो, बन्दियों एवं अन्य सामान्य नागरिकों को भी निर्मम हत्या की।

(५) आज के युद्धों को लक्ष्य की दृष्टि से भी सम्पूर्ण युद्ध कहा जाता है। आज विश्व की महान् शक्तिषः केवल इसलिए युद्ध नहीं लड़ती कि वे युद्ध क्षेत्र में शत्रु की सेनाओं को हरा दें या अपनी क्षतिपूर्ति कर लें अथवा अपनी सीमाओं को बढा लें। आज के युद्धों का उद्देश्य शत्रु देश की जनता को पूरी तरह से नष्ट करना हो सकता है, उसके कल कारखानों एवं युद्ध क्षमता को समाप्त करना हो सकता है उनकी सरकार का पुनर्गठन हो सकता है तथा उस देश की विचारधारागत भाव्यताओं को बदलना हो सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाले लोगों के राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन तक को परिवर्तित कर दिया गया। ऐसा परिवर्तन जापान में मिन राट्टो द्वारा और कन्द्रीय यूरोप में सोवियत संघ द्वारा किया गया।

युद्ध की प्रवृत्ति में सामाजिक परिवर्तन के रूप में लक्ष्यों को जोड़ना प्रमुख आधुनिक विकास माना जाता है। मुक्ति के लिए युद्ध (Wars of Liberation) असुरक्षा की भावना को बढाते हैं और ये न केवल विजित राट्टो पर ही लागू होते हैं बरन् इनको तटस्थ एवं विजयी राट्टो में भी छेड़ा जा सकता है। युद्ध के द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था लाई जाती है, वह बिना सैनिक पराजय के भी अन्तिकारी परिवर्तन ला देती है। आधुनिक सम्पूर्ण युद्ध में सम्पूर्ण हार का जोखिम रहता है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में असीमित राजनैतिक उद्देश्यों के लिए असीमित सैनिक साधनों का प्रयोग किया गया। इस दृष्टि से यह सुझाया जाता है कि यदि हम युद्ध में अपनाये जाने वाले साधनों के प्रयोग को सीमित करना चाहते हैं तो हमें लक्ष्यों को भी सीमित करना होगा।

आज के युद्ध विश्व विजय को अपना उद्देश्य बना कर भी लड़े जा सकते हैं। अनेक यान्त्रिक विकासों के परिणामस्वरूप मातृशाला, संचार और

राष्ट्रों के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसने यह सम्भव बना दिया है कि विश्व को जीता जा सके और विजयी राष्ट्र द्वारा उसका प्रबन्ध किया जा सके। यह सच है कि इससे पहले भी बड़े-बड़े साम्राज्य थे किन्तु ये साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं चले सके, क्योंकि उस समय ऐसे यान्त्रिक साधनों का अभाव था जिनसे व्यापक जनता पर नियन्त्रण रखा जा सके।

एक विश्वव्यापी साम्राज्य को स्थायी रूप देने के लिए तीन चीजें मूल रूप से आवश्यक हैं। प्रथम, साम्राज्य के सभी लोगों के मस्तिष्क पर केन्द्रीकृत नियन्त्रण द्वारा सामाजिक एकीकरण लागू करना, दूसरे, साम्राज्य में जहाँ भी कहीं एकता के विरोध की सम्भावना हो वहाँ सर्वोच्च सगठित सेना रखना, और तीसरा, नियन्त्रण एवं प्रभाव के इन साधनों में स्थायित्व होना चाहिए तथा सम्पूर्ण साम्राज्य में फैले रहने चाहिए। इन तीनों सैनिक एवं राजनैतिक पक्ष आवश्यकताओं में से अतीतकाल में एक को भी प्राप्त नहीं किया जा सका किन्तु आज ये तीनों ही सम्भव हैं।

पहले संचार के साधन गैर-यान्त्रिक थे और जहाँ कहीं यान्त्रिक थे वहाँ वे कठोर रूप से बंधकीकृत थे और इस प्रकार विकेन्द्रीकृत थे। कोई भी समाचार या विचार या तो मुह के शब्दों द्वारा प्रसारित किया जाना या अथवा पत्रों, प्रेस आदि के द्वारा जिनको कि केवल एक ही व्यक्ति अपने घर में संचालित कर सकता था। ऐसी स्थिति में भावी विजेता को असंभव विरोधियों से लड़ना होता था। विश्व विजय की कामना रखने वाला यदि अपने विरोधियों को पकड़ ले और पहिचान ले तो उन्हें जेल में डाल सकता था, उनकी हत्या करा सकता था, किन्तु वह यह नहीं कर सकता था कि उनकी जवान को नरम बना दे या समाचार, रेडियो एवं चलचित्रों पर एकाधिकार कर ले।

पहले हिंसा के साधन भी बहुत कुछ गैर-यान्त्रिक विकेन्द्रीकृत और व्यवित्तकृत थे। ऐसी स्थिति में विश्वव्यापी साम्राज्य बनाने का स्वप्न देखने वाला पग पग पर ऐसे सगठनों का खड़ा पाएगा जो कि उसमें सगमन बराबरी का स्तर चाहते हैं। दोनों के पाम समान हथियार थे। ऐसी स्थिति में कोई भी विजेता साम्राज्य की स्थापना के लिए सभी सम्भावित विरोधियों के विरुद्ध हर जगह एक सर्वोच्च सगठित सेना कायम नहीं कर सकता था। पहले के साम्राज्य का कोई भी भङ्ग कहीं पर विद्रोह कर दे तो उसे दबाना असंभव बन जाता था क्योंकि केन्द्रीय सत्ता को इसकी सूचना बहुत दिनों में पहुँचती थी और सूचना मिलने के बाद भी विद्रोह का दबाने के लिए जो प्रबन्ध किया जाता था उसमें भी पर्याप्त समय लग जाता था; किन्तु आज की स्थिति में

कोई भी विश्व साम्राज्य की सरकार रेडियो के माध्यम से सीधे ही वस्तु-स्थिति से सूचित हो जाएगी और कुछ ही घण्टों में सैकड़ों समवर्षक भेज देगी तथा पैराशूट, मोर्टार, टैंक, तथा हथियारों से भरे हुए बीतियों या न मिजवा देगी जिनका कि वह एकाधिकार रखती है और इस प्रकार राजद्रोह प्रस्त नगर की स्थिति पर काबू पाया जा सकता है।

भाज यातायात के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों ने ऐसी स्थिति ला दी है कि विश्व साम्राज्य की स्थापना करने वाले को अनुकूल जलवायु और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता जिसके कारण नैपोलियन के प्रयास निरर्थक बन गए और विश्व विजय का विचार रखने वाले दूसरे नेमाघों ने अपनी हिम्मत हार दी। पहले हिमपात के समय, शरद ऋतु में तथा बसन्त प्रारम्भ होने के समय युद्ध को रोकना पड़ता था, क्योंकि ऐसे मौसम में सेना की रक्षा करना और लड़ने के लिए आवश्यक सामग्री भेजना असम्भव था। अब शत्रु को यह भवसर मिल जाता था कि वह दुबारा युद्ध प्रारम्भ होने तक अपनी शक्ति पूर्ण कर ले और पुन सशक्त बन जाए। यह भी हो सकता था कि शत्रु की शक्ति इतनी बढ जाए कि विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखने वाले को अपनी जान के साते पड जायें। इन परिस्थितियों में विश्व विजय की कामना करना निरी भ्रूखता थी, क्योंकि एक मौसम में लड़ाई के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया वह दूसरा मौसम आने तक बराबर हो जाता था और उसे प्राप्त करने के लिए पुन उत्ता ही प्रयास करना होता था। इस प्रकार जितनी दूर आगे बढ़ने और उतनी ही दूर पीछे फिसलने की चाल से विश्व विजय की कल्पना करना रोसचिल्ली के स्वप्नों से अधिक सार्थक नहीं था।

भाज की स्थितियों में सम्भावित विरव विजेता के पास तकनीकी साधन हैं जिनके द्वारा वह एक बार की गई प्राप्ति को स्थायी बना सकता है। जीते हुए प्रदेश में उसकी सगठित सेना की सर्वोच्चता हर समय और हर जगह मानी जाएगी, चाहे मौसम कुछ भी हो और दूरी कितनी भी हो। प्रचार के सशक्त साधनों के माध्यम से विजेता अपने सम्भावित शत्रुओं पर सर्वोच्चता कायम कर सकता है। इस प्रकार से यदि एक बार किसी में विश्व साम्राज्य स्थापित कर लिया तो वह उसको बनाए रख सकता है और सफल रूप में उसका सवालन कर सकता है इस सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को एक बार जीत लिया गया वे हमेशा के लिए विजित बनाए जा सकते हैं। भाज यदि एक देश प्रभाव के तकनीकी साधनों में सर्वोच्चता रखने में सक्षम है तो वह विश्वव्यापी साम्राज्य भी

स्थापित कर सकता है। यदि एक राष्ट्र अणुशस्त्रों पर और संचार तथा यातायात के प्रमुख साधनों पर एकाधिकार रख सके तो वह दुनियाँ को जीत सकता है और इस जीत को स्थायी बना सकता है। किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि वह इस एकाधिकार और नियंत्रण को बनाये रखने में समर्थ हो। आधुनिक तकनीकी ने यह सम्भव बना दिया है कि दुनिया के प्रत्येक कोने के लोगों के दिमाग और कार्यों पर प्रत्येक मौनम में नियंत्रण रखा जा सके।

सैनिक शक्ति की सम्भावनाएँ (The Possibilities of Military Power)

सैनिक शक्ति एक देश की रचना का आवश्यक भाग होती है जिसके बिना वह एक बंदम नौ भोगे नहीं बड़ सकता। राज्य के जो चार आवश्यक तत्व माने गये हैं उनमें महत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सम्प्रभुता का स्वान सर्वोपरि माना जाता है और इसी भी राज्य की सम्प्रभुता उसकी सैनिक सामर्थ्य एवं सम्भावनाओं द्वारा तय की जाती है। सैनिक शक्ति की सम्भावनाओं को चार शीर्षकों के अधीन वर्णित किया जा सकता है। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि एक देश की सैनिक शक्ति उसकी राष्ट्रीय नीतियों को कितना समर्थित करती है तो चार मुख्य तौरों के अंतर्गत अध्ययन करना उपयोग रहेगा। ये निम्न प्रकार हैं—

(१) आक्रमणकारी क्षमता (The Offensive Capability)

बहुत समय पूर्व से ही राज्य अपने पड़ोसियों व विशुद्ध प्रायः आक्रमणकारी युद्ध लड़ते रहे हैं। राज्यों के द्वारा अनेक राजनीतिक आर्थिक एवं अन्य गुप्त उद्देश्यों के लिए युद्ध किये जाते हैं। सैनिक शक्ति के प्रयोग के ये उद्देश्य प्रायः अप्रत्यक्ष एवं छिपे रहते हैं। प्रारम्भ में इन युद्धों का स्वरूप एवं प्रभाव सीमित था।

यह सच है कि अनेक आक्रमणकारी युद्धों ने आक्रमणकारियों को अनेक लाभ प्रदान किए। राज्यों ने सैनिक शक्ति के प्रयोग के सहारे अपनी स्वतंत्रता को बनाये रखा। अनेक राज्यों ने अपने प्रदेशों को बढ़ाया और अपनी घन-सम्पदा को भी सैनिक शक्ति के सहारे व्यापक बना दिया। अतीतकाल में सैनिक शक्ति के सहारे राज्यों ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का सकल प्रयास किया। वर्तमान समय के सशस्त्र संपर्कों द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय सैनिक शक्ति के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की सिद्धि

का मार्ग छोड़ा नहीं है। कई बार आक्रमणकारी को भारी असफलताएँ भी मिलती हैं। इन असफलताओं के अनेक कारण हैं। स्पष्ट आक्रमणकारी के विरुद्ध देश अपनी सुरक्षा के लिए सज्जित भी हो जाते हैं। आक्रमण की नीति को अपनाने पर एक देश अपने पूर्व मित्रों एवं तटस्थ देशों के सहयोग तथा समर्थन को छोड़ देता है। कुछ आक्रमणकारी प्रयासों की सफलता से यह सिद्ध नहीं हो पाता कि नविष्य में भी आक्रमणकारी प्रयास इतने ही सतुरनाक होंगे। आक्रमणकारी को एक सबसे बड़ा लाभ यह रहता है कि यह आक्रमण के स्वान्त, समय एवं प्रकार को निश्चित करने का अवसर प्राप्त कर लेता है। पर्यवेक्षकों का मत है कि आधुनिक शस्त्रों के आविष्कार ने आक्रमणकारी की शक्ति को पर्याप्त लाभदायक स्थिति में रख दिया है।

प्रत्येक आक्रमणकारी को अपने आक्रमण के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लेने होते हैं। वही यह तय करता है कि क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाएँ, कौन से हथियार या शक्तियाँ अगताई जाएँ, किन भौगोलिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाये और किन को तिनारा जाय, युद्ध में रणकोशल से काम लिया जाए अथवा चातुरी से काम लिया जाए, आदि आदि। तकनीकी युद्ध का अर्थ उम युद्ध से है जिसमें रण की सशस्त्र सेना पर आक्रमण किया जाता है और रणकोशल युक्त युद्ध वह होता है जो शत्रु की अर्थ व्यवस्था एवं गृह व्यवस्था को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। युद्ध के उद्देश्य एवं तरीके का निश्चय करने के बाद यह निर्णय किया जाता है कि कौन से हथियारों का प्रयोग किया जाए।

आक्रमणकारी को यह स्वतन्त्रता रहनी है कि वह असीमित युद्ध छेड़ दे, शत्रु में बिना कर्ष आत्मसमर्पण की धान करे, घातक शस्त्रों का प्रयोग करे तथा भौगोलिक सीमाओं को न रखे। वह चाहे तो अपने कार्यों को मर्यादित भी रख सकता है, सीमित युद्ध अपना सकता है, कम हथियारों का प्रयोग कर सकता है, वह शत्रु की अर्थ व्यवस्था में कुछ भी किए बिना केवल सेना पर आक्रमण कर सकता है, आदि-आदि। इन प्रकार आक्रमणकारी द्वारा किए जाने वाले आक्रमण कई श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं; जैसे, सर्व विनाश के लिए आक्रमण, परम्परागत आक्रमण, सीमित युद्ध एवं गृह युद्ध। बाद वाली श्रेणियों के बीच अन्तर करना असम्भव है क्योंकि किसी भी गृह युद्ध में किसी भी महानक्ति का ध्यान आकर्षित हो जाता है।

(२) सुरक्षात्मक क्षमता
(Defensive Capability)

शत्रु के आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की रीतिक क्षमता का एक मुख्य

को मन्द बनाने के लिए उसकी स्वयं की रक्षा को चुनौती देना जरूरी हो जाता है। सुरक्षा के लिए नियोजन एक बड़ा ही जटिल विषय है जिसके सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं।

❶) प्रतिरोध की क्षमता

(Deterrent Capability)

विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग प्रतिरोधात्मक रूप में भी किया जा सकता है। शक्ति के प्रयोग का यह प्रतिरोधात्मक रूप रक्षात्मक योजना से अधिक मिश्र नहीं है। सैनिक शक्ति के इस प्रयोग का पर्याप्त महत्व है किन्तु इसे प्राप्त कैसे किया जाए? यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है। यह कहा जाता है कि सुरक्षा का चाहे कितना भी महत्व हो किन्तु केवल सैनिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक सकल रक्षात्मक योजना में प्रतिरोधात्मक शक्ति का होना परमावश्यक है। यह कहा जाता है कि जब आक्रमणकारी के विरुद्ध रक्षात्मक तैयारी में सैनिक शक्ति का विस्तार किया जाता है तो इसकी प्रतिक्रियास्वरूप आक्रमणकारी भी अपनी शक्ति को बढ़ाता है और इस दौड़ में सीमा रेखा कहा भाएगी यह निश्चित नहीं रहता। वैसे एक बड़े आकार की सेना में सदैव ही एक प्रतिरोधात्मक शक्ति रहनी है। किन्तु फिर भी आज प्रतिरोधात्मक शक्ति का महत्व अधिक हो गया है। एक सफल प्रतिरोधात्मक शक्ति की कुछ आवश्यक विशेषतायें होती हैं। प्रथम आवश्यकता यह है कि रक्षक के पास इतनी पर्याप्त सेना हो कि वह सम्भावित शत्रु के किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना कर सके। दूसरे, प्रोत्साहित किए जाने पर रक्षक को उस शक्ति का प्रयोग करने की तैयार रहना चाहिए।

❷ तीसरे, सम्भावित आक्राता को रक्षक की सामर्थ्य का थोड़ा-बहुत अनुमान रहना चाहिए। उसे रक्षक के समिप्रायो का भी गान रहना चाहिए। यह बात उस परम्परागत सिद्धान्त के विरुद्ध है जिसके अनुसार सेना सम्बन्धी प्रत्येक बात को शत्रु के हाथों में जाने से रोका जाना था। चौथे, रक्षक को आक्राता के मूखों का ध्यान रखना चाहिए। अन्तर्ग, सम्भावित आक्राता बुद्धिशील होना चाहिए।

इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त एक बात यह महत्व रखती है कि उस आक्रमण का प्रकार क्या है जिसका कि प्रतिरोध किया जाना है और क्या सेना द्वारा उसका प्रतिरोध किया जा सकेगा। आक्रमण व्यापक निम्नतः, परम्परागत, सीतमुद्ध एवं गृह युद्ध-किसी भी रूप में हो सकता है और प्रत्येक रूप में आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए एक ही प्रकार की

शक्ति अर्पणार्थ रहती है। आजकल विध्वंसकारी शस्त्रों के प्रतिरोध की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। यह सच है कि यूरोप में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद व्यापक संहार के अथवा परम्परागत शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया है। किन्तु फिर भी आजकल व्यापक संहार के शस्त्रों के विकास को एक मूल सैनिक आवश्यकता समझा जाता है।

केवल व्यापक संहार के शस्त्र ही पर्याप्त नहीं कहे जा सकते। इन हथियारों के द्वारा आक्राता को व्यापक संहार का युद्ध करने से अथवा परम्परागत युद्ध छेड़ने से रोका जा सकता है किन्तु ये निश्चय ही शीतयुद्ध एवं गृहयुद्ध जैसे आक्रमणों में प्रतिरोध का काम नहीं कर सकते। इन आक्रमणों का विरोध करने के लिए अन्य साधनों एवं तरीकों से युक्त परम्परागत हथियारों की आवश्यकता है।

प्रतिरोधारमक सामर्थ्य की एक बड़ी निहित कठिनाई यह है कि इसके लिये किये गये प्रयासों की सफलता को उस समय तक प्रमाणित नहीं किया जा सकता जब तक कि आक्रमण न हो जाये। प्रतिरोधात्मक शक्ति की एक सफलता तो यह हो सकती है कि आक्रमणकारी अपनी सेना को घटा ले। इस प्रकार सैनिक शक्ति शत्रु के विरुद्ध प्रयुक्त किये बिना भी लाभदायक बन सकती है।

(४) छापामार क्षमता

(Guerrilla Capability)

छापामार तकनीक को सैनिक शक्ति की किसी भी मात्रा के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को छापामार विरोधी तकनीकों का बहुत कम ज्ञान था। इसका कारण यह था कि रूस, चीन आदि साम्यवादी देशों के छापामार मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहे थे। कोरिया के मघर्ष के समय समुक्त राष्ट्र मघ की फौजों ने छापामार युद्ध का विरोध करने की कुछ तकनीकों का विरोध करना सीखा। जब कोरिया में साम्यवादी देशों द्वारा पश्चिम का विरोध किया गया तो उन्हें छापामार युद्ध के प्रतिरोध का अनुभव करना पड़ा। साम्यवादियों को युद्ध के इस तरीके का महत्व ज्ञात है तथा वे इसका हर जगह प्रयोग करते हैं। माओसे तुङ्ग को छापामार युद्ध का प्रमुख विशेषज्ञ माना जाता है। उसकी पुस्तिका छापामार युद्ध (Guerrilla warfare) सन् १९६७ में चीन में प्रकाशित हुई इसमें उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया जो कि चीनी व रूसी छापामारों द्वारा अपनाये गये थे।

युद्ध को रोकने का प्रयास (Preventive and detective measures)

अमरीका के राज्य-सचिव (Secretary of States) जॉन फास्टर डलेस (John Foster Dulles) द्वारा युद्ध को रोकने के लिए समय-समय पर दिये गये सुझावों की निम्नलिखित सूची पेश की गई है—

१. युद्ध के भयावह परिणामों की शिक्षा देना
(Education as to the horrors of war)
२. 'युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा' इस बात की शिक्षा देना
(Education to the fact that "war does not pay")
३. एकान्त और आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीयवाद
(Isolation and Economic Internationalism)
४. कैलिंग-ब्रियाँ सन्धि या पेरिस की सन्धि
(The Pact of Paris Vs Kellogg-Briand Pact)
५. राष्ट्र सघ (League of Nations)
६. आक्रमण से प्राप्त होने वाले लाभों को मान्यता प्रदान न करना
(Non-recognition of the fruits of aggression)
७. शस्त्रीकरण (Armament)
८. निःशस्त्रीकरण (Disarmament)
९. अनुमति या दबाव (Sanctions)

युद्ध को रोकने तथा शान्ति की स्थापना करने के उक्त सभी प्रयासों को डलेस (Dulles) ने असत्य तथा अपर्याप्त सुझाव (False and inadequate solutions) कहा है। उन्होंने इन सभी सुझावों का प्रमथः परीक्षण किया है तथा पाया है कि इनके द्वारा विश्व शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, ये बूझा हैं। पामर तथा परकिन्स के मतानुसार डलेस ने इन सुझावों पर जो विचार-विमर्श किया है वह मुख्य रूप से सैद्धान्तिक या विद्वत्तापूर्ण (Theoretical or Academic) है। उनके विचार से डलेस (Dulles) द्वारा दी गई सूची में अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा विश्व सरकार का उल्लेख नहीं है। जैसे कई विचारकों ने इन दोनों ही साधनों द्वारा विश्व शान्ति की स्थापना की सम्भावना पर जोर दिया है। किन्तु पामर तथा परकिन्स ने इन दोनों सुझावों पर विचार करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि युद्ध के विकल्प (Alternative) के रूप में ये दोनों ही सुझाव अपूर्ण तथा असन्तोषजनक हैं। आज के प्रत्यक्ष युग में युद्धों को रोकने का प्रयास करना परम आवश्यक बन गया है। राष्ट्रपति फ्रूब से वार्ता के लिए ताशकन्द जाने से एक दिन पूर्व (२ जनवरी, १९६६) प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने कहा था कि यदि हरेक समस्या का हल करने के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया गया तो विश्व में शान्ति नहीं रह सकती। सभी देशों को अपने आपसी

विवाद शान्तिपूर्ण वार्ताओं द्वारा तय करने चाहिये। युद्ध का विकल्प दुटना घाज के युग की प्रमुख आवश्यकता बन गया है किन्तु युद्ध के केवल वही विकल्प कारगर हो सकते हैं जो युद्ध द्वारा किये जाने वाले सुरक्षा के कार्य को सम्भाल सके तथा जो बुद्धिशील व्यक्तियों द्वारा शान्ति स्थापित रखने के लिए प्रयुक्त किया जाये।

युद्ध का परिवर्तित क्षेत्र एवं प्रभाव (The changed area and influence of war)

विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों एवं यातायात व संचार के साधनों के विकास के कारण सारा विश्व उद्यों ही एक परिवार के रूप में आया, युद्ध का क्षेत्र भी क्षेत्रीयता एवं प्रादेशिकता की परिधियों को लाँच कर विश्वव्यापी बन गया। इससे पूर्व युद्धों का क्षेत्र सीमित था और इस कारण इसमें विजय एवं हार का उत्तरदायित्व उसके सेना सँता तायकों तथा प्रशासकों पर ही जाता था तथा युद्ध के परिणाम भी मुख्यतः इन्हीं वर्गों को भुगतने पड़ते थे। सामान्य जनता के लिए तो प्रशासकों के परिवर्तन से अधिक बाधा या सुविधा प्राप्त होने की सम्भावना न थी, किन्तु आज वस्तुस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। घाज के युद्धों में लड़ाइयाँ केवल सैनिकों और बन्दूकों से नहीं, जनता के मनोबल और लोकमत के सहारे ही लड़ी एवं जीती जाती हैं। यही कारण है कि घाज के युग को कभी-कभी पूर्ण युद्ध का युग (Age of total war) कह दिया जाता है। मार्गोथो के मतानुसार आधुनिक युद्ध को पूर्ण (Total) कहने के चार कारण हैं—

१ क्योंकि जनता के एक भाग के भाव और विचार उसके देश के युद्धों के साथ पूरी तरह एकरूप हो जाने हैं,

२ क्योंकि जनता का एक भाग युद्ध में भाग लेता है,

३ क्योंकि जनता का एक भाग युद्ध से प्रभावित होता है,

४ क्योंकि युद्ध के द्वारा अभीसिप्त लक्ष्यों की प्रकृति ही ऐसी होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युद्ध पूर्ण (Total) इस कारण है क्योंकि ये पूरी जनता द्वारा लड़े जाते हैं, ये पूरी जनता के होते हैं, ये पूरी जनता के विरुद्ध लड़े जाते हैं, और इन युद्धों में जिन तरीकों तथा यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वे भी इनकी प्रकृति को सम्पूर्ण बना देते हैं, उदाहरण के लिए आधुनिक शस्त्रों का प्रयोग (Mechanization of weapons) तथा यातायात व संचार साधनों का प्रयोग (Mechanization of transportation and communication) आदि।

PART—IV

Limitations of National Power : Balance of Power :
Collective Security and Pacific Settlement of Inter-
national disputes, International Law, World Govern-
ment; Disarmament; International Morality and
World Public Opinion.

अध्याय—६

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ ।
(Limitations of National Power)

अध्याय—१०

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ—(क्रमशः)
(Limitations of National Power—Contd)

“शक्ति सन्तुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्षिक शक्ति की ओर इंगित करता है।”

—शताइसर

“यदि केन्द्रीकरण की दृष्टि से देखा जाय तो हम पायेंगे कि सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है। इसमें शक्ति सन्तुलन से अधिक केन्द्रीकृत प्रबन्ध होता है किन्तु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम रहता है।”

—बलाड

“अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन प्रचलित एवं परम्परावादी नियमों का नाम है जिनको सभ्य राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी व्यवहार में वैधानिक रूप से बाध्य माना जाता है।”

—ओवेनहिम

“नि शस्त्रीकरण का लक्ष्य आवश्यक रूप से नि शस्त्र कर देना नहीं है। इसका लक्ष्य तो यह है कि जो भी हथियार इस समय उपस्थित हैं उनके प्रयोग को घटा दिया जाय।”

—हंटमेन

“अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता उसी दिन समाप्त हो गई जबकि राष्ट्रीय उद्देश्यों को वाकी सत्तार द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए शुद्ध लक्ष्य माना गया।”

—थोम्पसन

“विश्व जनमत स्पष्ट रूप से लोकमत है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है तथा काम से कम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मौलिक प्रश्नों पर विभिन्न देशों के सदस्यों को एकमत में संगठित करता है।”

—मार्गेन्थो

राष्ट्रीय शक्ति की सीमार्ये II (LIMITATIONS OF NATIONAL POWER)

प्रत्येक राजा अपने सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास करता है क्योंकि इसके बिना घोर अस्त-व्यस्तता व्याप्त हो जायगी और केवल प्राकृतिक शक्ति का ही बोलबाला हो जायगा। इसी दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न देशों द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे नियन्त्रित एवं मर्यादित करना बहुत आवश्यक है। इसका कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के दुरुपयोग के परिणाम बड़े भयानक होते हैं। आज की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या यह है कि राष्ट्रों की शक्ति को नियमबद्ध करने के लिए अभी तक कोई सन्तोषजनक साधन आविष्कृत नहीं हो सका है। अनेक विचारकों ने इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं जिनमें से कुछ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग भी किया गया है। राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने वाले विभिन्न साधनों में व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन मुख्य रूप से निम्न हैं—

- (१) शक्ति सन्तुलन (Balance of Power)
- (२) सामूहिक सुरक्षा (Collective Security)
- (३) अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law)
- (४) विश्व सरकार (World Govt)
- (५) निःशस्त्रीकरण (Disarmament)
- (६) अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता (International Morality)
- (७) विश्व जनमत (World Public Opinion)

प्रारम्भ में शक्ति-सन्तुलन का सहारा लेकर विश्व के देशों को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने का प्रयत्न किया गया किन्तु बाद में अनेक कारणों से शक्ति सन्तुलन अव्यावहारिक बन गया और विश्वशांति की स्थापना के लिए सामूहिक सुरक्षा का मार्ग अपनाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहारे देशों को सही व्यवहार अपनाने के लिए प्रभावित किया गया। अनेक विचारकों ने विश्व से युद्धों का सदा के लिए विदा करने तथा स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए राष्ट्र-राज्यों के म्यान पर विश्व सरकार की रचना करने का विचार रखा। कुछ लोगों के मतानुसार यदि देशों के पाम शस्त्रों का अस्तित्व न रहे तो स्वामाविक रूप से वे किसी देश के विरुद्ध आक्रमणात्मक नीति न अपनायेंगे। इन सभी साधनों के अर्थ, रूप, प्रयोग एवं अपूर्णताओं पर विचार करना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के भूत, वर्तमान एवं भविष्य को समझने में सहायता कर सकेगा।

‘शक्ति’ और ‘समप्रभुता’ जब तक राज्यों की विशेषताएँ हैं तब तक यह समावना बनी रहेगी कि दो राज्यों के बीच सघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाय। इस सम्भावना को मिटाने की दृष्टि से ही यथार्थवादी विचारकों का मत है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने प्रदेश और सम्मान का वित्तिार करने का प्रयत्न करता है और दूसरे राज्य में स्थित सैनिक शक्ति द्वारा उनके इन प्रयत्न पर अंकुश लगाया जाता है। यही दूसरे शब्दों में ‘शक्ति सन्तुलन’ (Balance of Power) है। इसी प्रकार अर्थशास्त्री ‘आर्थिक पर निर्भरता’ को, कानून विशेषज्ञ अधिकार और कर्तव्यों की मान्यता को तथा एक आदर्शवादी विचारक धर्म, मानव की अच्छाई तथा विश्व जनमन को एक कारण मानते हैं जिसके आधार पर राज्यों के बीच सद्भावना और परस्पर सहयोग के भाव वर्तमान रहते हैं। एक राष्ट्र की आक्रमणकारी प्रवृत्ति को रोकने के अन्य साधन जब असफल हो जाते हैं तो दूसरे देश की राष्ट्रीय शक्ति ही उस पर अंकुश लगानी है और इस दृष्टि से राष्ट्रीय शक्ति (National power) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर नियन्त्रण रखने वाला सबसे अधिक प्रभावकारी साधन है। इसका प्रयोग रक्षात्मक (Protective) तथा आक्रमणात्मक (Aggressive) दोनों ही उद्देश्यों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति पर सीमा लगाने वाले उक्त साधनों के अनिर्दिष्ट नैतिक विश्वास मानवतावाद, शांतिवाद, सहिष्णुता, सजग स्वार्थ आदि विचारों की अनेक दिशाएँ हैं जो विश्व के देशों को अराजकता व सघर्ष के वातावरण की अपेक्षा शांति से रहने की प्रोत्साहित करती हैं।

शक्ति-सन्तुलन (The Balance of Power)

जैसे व्यक्तिगत जीवन में मित्रता का आधार व्यवहार का सन्तुलन और स्थिति व स्तर की समानता होता है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में विश्वगानि तथा राष्ट्रों की परस्पर शक्ति का आधार उनके बीच स्थित शक्ति का सन्तुलन (Balance of Power) है। असन्तुलित शक्ति कभी भी विश्ववृद्ध प्रयत्न सफल का कारण बन सकती है क्योंकि यह शक्तिशाली राष्ट्रों को कमजोर राष्ट्रों पर अपना साम्राज्य फैलाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

शक्ति सन्तुलन की परिभाषाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन द्वारा लगभग १५०० वर्षों से राज्यों के परस्पर सम्बन्धों को समायोजित करने का कार्य किया जा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने मित्र-मित्र परिभाषाएँ देकर शक्ति सन्तुलन के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। सुप्रसिद्ध विचारक मार्गेनथो (Morgenthau) के मतानुसार "प्रत्येक राष्ट्र वस्तु-स्थिति (Status-quo) को बनाये रखने या परिवर्तित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों से अधिक शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखता है। इसके परिणामस्वरूप जिन ढांचे (Configuration) की आवश्यकता होती है वह शक्ति सन्तुलन कहलाता है और जिन नीतियों की आवश्यकता होती है उनका लक्ष्य शक्ति सन्तुलन को बनाये रखना होता है। श्लाइमर (She'icher) के मत में "शक्ति सन्तुलन स्थितियों तथा समुदायों की सापेक्षिक शक्ति की ओर इशारा करता है। क्लॉड (I L Claude) महोदय ने शक्ति सन्तुलन की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति-सम्बन्धों की समस्या से सम्बन्धित माना है। उनका कहना है कि "शक्ति सन्तुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतन्त्र राष्ट्र अपने आपकी शक्ति मापदण्डों के बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वायत्ततापूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था (Decentralized System) है जिसमें शक्ति व नीति निर्मायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है।" प्रो० फे (Prof. Fay) के शब्दों में "शक्ति सन्तुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति में न्यायपूर्ण सुन्ध्यमात्रता (Jus Equilibrium) जो किसी राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लागू करने में रोक सके।" बिकिसन के मत में सन्तुलन (Balance) शब्द का प्रयोग समानता और असमानता दोनों ही अर्थों में किया जाता है।

जब लेखा (Account) सन्तुलन हो तो इसका अर्थ है समानता किन्तु जब सन्तुलन किसी एक के हित में हो तो इसका अर्थ असमानता है। उनका कहना है कि शक्ति सन्तुलन का सिद्धांत प्रथम अर्थ का दावा करता है किन्तु दूसरे के लिए प्रयत्नशील रहता है। मार्गो-यो भी शक्ति सन्तुलन शब्द का अर्थ राष्ट्रों के मध्य स्थित शक्ति की समानता से ही लगाते हैं किन्तु यह तभी सम्भव है जब कि शक्ति शब्द के साथ कोई विशेषण न प्रयुक्त किया गया हो। इसके विपरीत स्पाइकमन (Spykman) के कथनानुसार 'नत्यू तो यह है कि प्रत्येक देश केवल उसी शक्ति सन्तुलन में रुचि लेता है जो उनके हित में होता है।' इस प्रकार जो राष्ट्र शक्ति सन्तुलन की स्थापना करना चाहता है वह 'सन्तुलन' नहीं बल्कि अपने हित में असन्तुलन (Inbalance) की स्थापना का प्रयत्न करेगा।

पामर तथा परकिन्स ने शक्ति सन्तुलन की भाग्यता की निम्न सात विशेषताओं का उल्लेख किया है :—

✓ १. विश्व के राष्ट्रों के बीच शक्ति का सन्तुलन सदैव बना नहीं रह सकता,

✓ २. शक्ति सन्तुलन की स्थापना स्वयं ही नहीं हो जाती, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है,

✓ ३. शक्ति सन्तुलन का मापदण्ड युद्ध है क्योंकि युद्ध प्रायः तभी प्रारम्भ होते हैं जबकि सन्तुलन बिच्छिन हो जाता है,

✓ ४. शक्ति सन्तुलन की नीति गतिशील (Dynamic) एवं परिवर्तनशील (Changing) है,

✓ ५. दृष्टिानुसार शक्ति सन्तुलन को वस्तुगत (Objective) दृष्टि से देखता है किन्तु राजनीतिज्ञ उसे द्विपक्षगत (Subjective) दृष्टि से देखता है,

✓ ६. शक्ति सन्तुलन न तो प्रजातन्त्रात्मक देशों के लिए ही उपयुक्त है और न ही तानाशाही देशों के लिए ही,

✓ ७. शक्ति सन्तुलन के खेल में केवल बड़े राष्ट्र ही खिलाड़ी होते हैं, छोटे राष्ट्र केवल प्रभावित (Victim) या दर्शक के रूप में रहते हैं। किन्तु यदि वे आपस में मिल जायें तो इस खेल में सक्रिय हिस्सेदार भी बन सकते हैं।

मान्यता का इतिहास

(The History of Concept)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन की मान्यता का इतिहास पर्याप्त पुरातन है। राज्यों के बीच सम्बन्धों में बहुत पहले से ही संधर्ष, मतभेद, विरोध एवं सदाशया रही हैं। इनका निपटारा करने के लिए कोई स्थाई व्यवस्था बनाने की अपेक्षा प्रारम्भ में एक या एक से अधिक राज्य अनेक राज्यों पर प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा करते थे और फिर विश्व की अपनी मान्यता के अनुसार स्व प्रदान करने का प्रयास करते थे। दूसरे राज्यों द्वारा स्थिति को बनाये रखने की चेष्टा की जाती थी और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अपने विभिन्न सोपानों में गुजरती हुई आगे बढ़ती चली गयी। जब विरोधी राज्य कुछ राज्यों के सामान्य हितों को चुनौती देते थे तो वे भिन्न कर अपने हितों की रक्षा के लिए सन्धि बद्ध हो जाते थे। शक्ति सन्तुलन की प्रक्रिया एक प्रकार से दूसरे राज्यों के शक्ति प्रयोग को सीमित करने का प्रयास है।

शक्ति सन्तुलन का तुल्यमात्रिता का विचार मूल रूप से प्रकृति के विरोधी शक्तियों के बीच स्वामाविन तुल्यमात्रिता से लिया गया। मनुष्य ने बहुत पहले से ही इस बात की अनुभूति की कि सारे सौर मण्डल में अनेक सितारे और ग्रह निम्न प्रकार सन्तुलन बनाये रखते हैं। राजनीति के क्षेत्र में अस्तु ने यह विचार प्रकट किया कि समाज गरीब, निर्धन और मध्यवर्ग के लोगों के बीच न्याय प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप सन्तुलन बनाये रखते हैं। एक अन्य राजनैतिक विचारक जेम्स मैडीसन (James Madison) का विश्वास था कि सरकार को जनता के बीच सन्तुलन बनाये रखना चाहिए जो परिवर्तन चाहते हैं और यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। राजनैतिक विचारकों ने बहुत पहले से ही शक्ति सन्तुलन के ऊपर अपने विचार अभिव्यक्त किए। ये विचार सही थे, भ्रमवा नहीं थे यह अलग बात है किन्तु इनके समय में ये पर्याप्त प्रभावशाली रहे।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन को पूर्ण शक्ति एवं तानाशाही को दबाए रखने के साधन के रूप में देखा गया है। डेविड ह्यूम (David Hume) ने अपने निबन्ध 'शक्ति सन्तुलन पर' (On the Balance of Power) में पोलिबियस (Polybious) को उद्धरित किया है जिसका कहना था कि किसी भी राज्य या शासक को इतना महान न बनने दो कि वह अपने पड़ोसी को, उसके अधिकारों की रक्षा में असमर्थ बना दे। मैक्यावेली ने अपनी

‘द प्रिन्स’ (The Prince) में यह परामर्श दिया है कि जो कोई भी दूसरे की शक्ति को बढ़ाने में योगदान देता है वह अपनी शक्ति को नष्ट करता है। रिचार्ड कोब्डन (Richard Cobden) ने शक्ति सन्तुलन को एक असम्भव कल्पना के रूप में विशेषीकृत किया है। यह और कुछ नहीं केवल शब्द मात्र है। उनके मतानुसार शक्ति सन्तुलन केवल मस्तिष्क की छूटा है, विचारों की नहीं। हमारे पूर्वजों ने शब्दों के सम्बन्ध में अपने आपको परेशान करने की जो नीति अपनाई थी वह उसी का एक उदाहरण है। फ़ांसीसी दार्शनिक फ़ेनलोन (Fenelon) इस मान्यता को पर्याप्त महत्व देने हैं। उनके कथनानुसार अपने पड़ासी को बहुत अधिक शक्तिशाली बनने से रोकना अपने आपको तथा अन्य पड़ोसियों को गुनाह बनने से रोकने का प्रयास है। यह स्वतन्त्रता, समानता एवं सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि एक देश की अनिश्चित शक्ति एक सीमा से बाहर निकलने के बाद सम्बद्ध राज्यों की सामान्य व्यवस्था को परिवर्तित कर देती है। लिओपोल्ड वान राके (Leopold von Ranke) का मन है कि यूरोपीय राजनीति में एक और तो दबाव डाले जाते थे और दूसरी ओर उनका विरोध किया जाता था। हम व्यवस्था के कारण ही यूरोप अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सका तथा अपने प्रत्येक राज्य का स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रख सका। कुछ-कुछ यही मत एडवार्ड गिबबन (Edward Gibbon) ने प्रकट किया है। उनका कहना है कि अनेक स्वतन्त्र राज्यों में यूरोप का विभाजन होना अनेक सामंजस्यपूर्ण परिणामों का जनक रहा है। इसमें मानव जाति की स्वतन्त्रता बनी रही। जिस तानाशाह को अपनी जनता के विरोध का सामना नहीं करना पड़ता उसे अपने समकक्ष राजाओं की शक्ति का प्रभाव शीघ्र ही ज्ञात हो जाता था, उसे अपने मित्रों की सलाह और शत्रुओं की चुनौतियों से पर्याप्तित होना पड़ता है।

सन् १८१५ में जैफ़रसन (Jeffarson) ने अपने एक मित्र को लिखा कि इस बात में हमारा हित नहीं है कि समस्त यू।ए. एक राजतन्त्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। मैं उसने माना था कि राष्ट्रीय के बीच एक उपयुक्त शक्ति सन्तुलन स्थापित किया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने आपको यूरोपीय व्यवस्था से अलग बनाय रखा किन्तु जब सन् १८१७ और सन् १८४१ में उसे सन्तुलन की स्थापना के लिए बुलाया गया तो वह मना नहीं कर सका। राष्ट्रपति फ्रैंक्लिन डी रूजवेल्ट ने बात करने के बाद सन् १८४८ में फॉरेस्ट डेविस (Forrest Devis) ने बताया कि इंग्लैंड की भांति हमारा ऐतिहासिक स्तर भी यह मांग करता है कि यूरोप में शक्ति

संतुलन बना रहे और कोई भी एक राष्ट्र इस महाद्वीप के साधन, श्रोतों तथा मानव शक्ति को हमारी सम्भावित हानि के लिए प्रयुक्त न करे। इस मूल मान में प्रभावित होकर ही हम सन् १९१७ में लड़े और इसीलिए अब खड़े रह हैं ताकि किसी एक आक्रमणकारी शक्ति को यूरोप पर स्वामित्व रखने से रोका जा सके। पर्ल हार्बर (Pearl Harbour) से लेकर अब तक संयुक्त राज्य अमरीका यूरोपीय तथा विश्व रणमय को इसी दृष्टि से देख रहा है।

शक्ति संतुलन या तुल्यकारिता की मान्यता घनेक सन्धियों का आधार मानी जाती है। सन् १६४८ से लेकर सन् १९१४ तक का काल स्वेटन शक्ति संतुलन का काल कहलाता है। कहा जाता है कि सन् १६४८ को वेस्ट फ़ैलिया की संधि (The Treaty of West Phalia), सन् १८१५ का विपना समझौता (Vienna Settlement), सन् १९१९ की वासाय की संधि (The Treaty of Versailles) तथा सन् १९४५ में संयुक्त राष्ट्र संधि की स्थापना के पीछे शक्ति संतुलन की मान्यता कार्य कर रही थी। ये विभिन्न सन्धियाँ एवं समझौते इसलिए हुये क्योंकि समय-समय पर नैपालियन, कैसर विल्हेम (Kaiser Wilhelm), ट्रिडलर और साम्यवादी नेताओं ने विश्व पर स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास किया। शक्ति संतुलन की मान्यता में एक विरोधाभास है और वह यह है कि जो देश इसका व्यवहार करते हैं वे भी यह घोषणा नहीं करना चाहते कि वे इसका व्यवहार कर रहे हैं। यही कारण है कि कोई भी देश शक्ति संतुलन को अपनी नीति मानने का दावा नहीं करता। राजनीति की इस प्रकार की व्यवस्था में सम्मिलित होने से मना करते हैं यद्यपि उनकी नीतियाँ दूसरे राज्यों की शक्तियों को क्षाने, विरोध करने, कम करने तथा उनसे धागे धटने की ओर संचालित रहती हैं। अपने पक्ष में शक्ति संतुलन की स्थापना की राष्ट्रीय तत्त्व के रूप में घोषणा दूसरे देशों को विरोधी नीति विकसित करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है। आक्रमणकारी देश ऐसी स्थिति में अपने आपको मजबूत तथा मशक्त बनाने के प्रयासों को न्यायात्मिक उद्देश्य मन्दना है तथा उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक मान सकता है।

शक्ति संतुलन की तीन स्वयंसिद्ध बातें

(Three Postulates of Balance of Power)

शक्ति संतुलन के सिद्धान्त की कुछ स्वयंसिद्ध बातें होती हैं उनमें से तीन यहाँ उल्लेखनीय हैं। प्रथम बात यह है कि एक राज्य को परिस्थितियों के बदलने पर तथा नई समस्याओं के ज्ञान पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहना चाहिये। विचारधारानुसार दुराग्रह एवं

वचनबद्धता शक्ति सन्तुलन में कठोरता एवं अपरिवर्तनशीलता का तत्व ला देते हैं। इसलिये शक्ति सन्तुलन की राजनीति इनको ठुकरा देती है। किन्तु यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि साम्यवादियों ने दूसरे राज्यों पर अपनी विचारधारा को थोप दिया है। इसीलिये विचारधारागत सघर्ष वर्तमान विश्व राजनीति की एक प्रमुख वास्तविकता बन गया है। शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के समयको द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को कम से कम कर दिया जाता है, क्योंकि ये राजनीतिज्ञों को राष्ट्रीय हितों की साधना के लिए शक्ति की दृष्टि से सोचने से रोक देते हैं। एक देश किसी भी मधि के अनुसार वचनबद्ध हो सकता है किन्तु परिस्थितियाँ बदलने पर वह वचनबद्धता टूट सकती है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान के साथ सधि में वचनबद्ध था किन्तु जब उसने संयुक्त राज्य अमरीका के साथ अपना सहयोग बढ़ा लिया तो यह जरूरी बन गया कि वह सधि को तोड़ दे। इस प्रकार राज्यों को अपने हितों तथा सम्बन्धों का पुननिरीक्षण करने के लिये तैयार रहना चाहिये। फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल डिगाल ने नाटो संधि के सम्बन्ध में ऐसा ही किया है। इस दृष्टि से यह भी सम्भावना है कि यदि आवश्यकता हुई और इन देशों के राष्ट्रीय हितों ने जरूरी बनाया तो संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ साम्यवादी चीन का विरोध करने में ऐसे ही मिल जायेंगे जैसे कि वे जर्मनी का विरोध करने में मिले थे। इतिहास में प्रचानक ही बड़े-बड़े परिवर्तन हो जाते हैं जिनकी हम पहले से कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिस जर्मनी और जापान के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी सारी शक्ति लगा दी वह अब इनका परम मित्र है।

⑨ दूसरी स्वयंसिद्ध बात यह है कि जब राज्यों को यह ज्ञात हो कि दूसरे राज्य शक्ति सन्तुलन को उसके मुख्य हितों के विरुद्ध परिवर्तित कर रहे हैं तो उसे सघर्ष के लिये और यहाँ तक कि आवश्यकता हो तो युद्ध के लिए भी तैयार रहना चाहिए। क्यूबा के प्रश्न पर संयुक्त राज्य अमरीका का दृष्टिकोण इस बात का द्योतक है। जब सोवियत संघ क्यूबा में बड़े स्तर पर प्रचोदनात्मक काम करने जा रहा था तो राष्ट्रपति कॅनेडी ने २२ अक्टूबर, १९६२ को अमरीकी जनता और प्रधानमन्त्री लुइस ए. ब्रैक को कहा कि "सोवियत भूमि के बाहर रणनीति के हथियारों को स्थापित करने का यह आकस्मिक प्रथम निर्णय यद्यपि स्थिति में जानबूझ कर किया गया आक्रमणकारी एवं अत्यापपूर्ण परिवर्तन है जिसको कि इस देश द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता वरना इस देश के शत्रु और मित्र इसके साहस और वचनों

मे कभी दुबारा विश्वास नहीं करेंगे।" इनके पर भी जब चुनौती सामने आई तो राष्ट्रपति ने कहा कि 'हम अनावश्यक रूप से घबड़ा बिना सोचे समझे विश्व-शान्ति समुदाय के परिणामी की जोखिम नहीं लेंगे जिसमें विजय के फलस्वरूप हमारे पक्ष में केवल राख बचेगी। किन्तु यदि हम उस जोखिम से बचने में अनमर्त्य रहे तो किसी भी समय उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।"

⑤ एक तीसरा सन्धानित उन्मुख दोनों थे ही सम्बद्ध है तथा उन्हीं से निकलता है। इनके अनुसार यदि युद्ध या अन्य झड़प उत्पन्न होता है तो उसमें किसी भी देश को इतना पूरी तरह में नष्ट नहीं किया जाना चाहिये कि सम्बद्ध शक्तिना प्रचली पड़ जाय और विजेता के लिए अनुपयुक्त शक्ति सन्तुलन की स्थिति बनावे। ऐसा सन् १९४५ में जर्मनी के साथ किया गया, उसका पूरी तरह में विनाश कर दिया गया और इस प्रकार इटली और जापान की शक्ति मद्धिम पड़ गई। इनके बाद पांच वर्षों के भीतर-भीतर पश्चिमी शक्तियों को यूरोप और एशिया में साम्यवादी चुनौती के विरुद्ध शक्ति सन्तुलन को बनाए रखने के लिए इन तीनों पूर्व शक्तियों की सहायता करना जरूरी बन गया।

शक्ति सन्तुलन का मूल तत्व लॉर्ड पैलमर्स्टन (Lord Palmerston) ने अभिव्यक्त किया है। उनके कथनानुसार "क्षेत्रों का कोई अन्तरण स्थित नहीं है और न ही कोई अन्तरण शक्त है बल्कि उनके तो अन्तरण हित हैं।" प्रोफेसर निहोमन नाइरमैन ने भी कुछ इसी प्रकार के भावों को अन्य शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उनका कहना है कि "तो राज्य शक्ति सन्तुलन का खेल खेलता है उनका कोई स्थायी मित्र नहीं होता तथा। उसकी स्वाभि-मक्ति किसी एक राज्य के प्रति नहीं हो सकती बल्कि केवल सन्तुलित शक्ति में प्रति होगी। आज के मित्र प्रायः बाने बल के शत्रु हो सकते हैं।" स्प्राइकमैन ने प्रायः बताया है कि शक्ति राजनीति का एक मुख्य आधारभूत यह है कि यह एक राज्य के मित्रों को विनाश होने का भयानक नहीं देती। यदि हम सन् १९३० के दौरान तथा उसके बाद में होने वाली संघर्षों तथा सह-योगों पर दृष्टि डालें तो ज्ञात होगा कि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था हमें इस बात का आश्वासन देती है कि कोई भी विरोधी हमें का के लिए विरोधी नहीं बनाता क्योंकि यह अक्सर और परिस्थितियों के बदलते ही पुनः-निर्माण का हाथ बड़ा देता है।

शक्ति सतुलन के अनेक अर्थ

(Balance of Power as an ambiguous concept)

शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग इतने अविश्व अर्थों में किया जाता है कि यह शब्द आज अर्थहीन सा बन गया है तथा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कहेन चाहा बिचर को सहेन करना चाहता है। पोलार्ड (Pollard) के मतानुसार शक्ति सतुलन (Balance of power) शब्द के शब्दकोष के अर्थ को अनेक मतलबों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। उनका निष्कर्ष यह है कि 'शक्ति सतुलन का अर्थ कुछ भी हो सकता है और इसका प्रयोग केवल मित्र-मित्र लोगों द्वारा मित्र मित्र अर्थों में अथवा एक ही व्यक्ति द्वारा मित्र-मित्र समय अलग अलग अर्थों में प्रयोग नहीं किया जाता किन्तु एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही समय में मित्र-मित्र अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है।' क्लाउड (Claude) के मत में शक्ति सतुलन एक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञ के लिए उसी प्रकार है जैसे कि एक रसोइया के लिए नमक की चिकुटी होती है और जैसे एक मार्क्सवादी विचारक के लिए द्वा-द्वात्मक भौतिकवाद होता है। अर्थात् रसोइया उस नमक की चिकुटी का किसी भी सब्जी या पकवान में प्रयोग कर सकता है उसी प्रकार शक्तिसतुलन का प्रयोग भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों द्वारा हर किसी अर्थ में कर लिया जाता है। हैम (Ernst B Hass) के अध्ययन के आधार पर इससे आठ मित्र मित्र अर्थ हो सकते हैं तथा चार मुख्य मुख्य आचरण हो सकते हैं। एक देश के लिए एक विशेष स्थिति शक्ति सतुलन हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरे देश के लिए वैसी ही होगी। मार्टिन वाइट (Martin Wight) के अनुसार "इतिहासकार शक्ति सतुलन तब मानेगा जब विरोधी समुदाय भी शक्ति उसके बराबर होंगे किन्तु राजनीतिज्ञ के मन में शक्ति सतुलन तब होगा जब कि उसका पक्ष दूसरे की अपेक्षा शक्तिशाली होगा और वह तभी सतुलन मानेगा जबकि उसके देश को राष्ट्रीय हित के अनुसार चाहे जिस पक्ष में मिलने की स्वतन्त्रता होगी।"

क्लाउड (J. L. Claude) ने बताया है कि शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग मनुष्य, तिम्रु हथों में लिया जा सकता है—

(१) एक अवस्था के रूप में (As a Situation)—यद्यपि उदाहरण तथा विचारकों की परिभाषाएँ देने के बाद उन्होंने यह बताया है कि शक्ति सतुलन का प्रयोग कभी तो तुल्यमात्रता (Equilibrium) के लिए

‘दिया जाता है और कभी इसे तुल्यभारिता के विरोध अर्थ ‘Dis-equilibrium’ में किया जाता है। इस दृष्टि में शक्ति सन्तुलन ‘शक्ति के विन्मूल’ का समानार्थक बन जाता है जिस प्रकार कि ‘तापम’ जलवायु की स्थिति के दत्ताना है चाहे वह गर्म हो या ठण्डा इसी प्रकार शक्ति सन्तुलन भी शक्ति स्थिति’ का दत्ताना है चाहे वह सन्तुलित हो अथवा असन्तुलित।

(२) नीति के रूप में (As a Policy)—शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी नीति के रूप में भी दिया जा सकता है जो तुल्यभारिता का निर्माण करने अथवा उसकी रक्षा करने का कार्य कर सके। यह नीति इस माय्यता पर आधारित रहती है कि असन्तुलित शक्ति खतरनाक होती है। जय चर्चिल (Winston Churchill) ने यह लिखा है कि शक्ति सन्तुलन ब्रिटिश नीति की आन्वयजनक अवधारणा परम्परा (Unconscious tradition) रहा है तब उनका अर्थ सन्तुलन की स्थिति से नहीं था बल्कि सन्तुलन करने वाली नीति से था। मोवरर (Mowrer) ने शक्ति सन्तुलन का जो रूप बताया है उससे भी शक्ति सन्तुलन का अर्थ एक ऐसी नीति से लगाया जा सकता है जो बाधों के बीच तुल्यभारिता (Equilibrium) लाने में प्रयत्नशील हो। इस प्रकार शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग प्रायः शक्ति स्थिति से सन्नित सम्बन्ध रहता है। मार्क्सो और एंगल्स ने भी शक्ति सन्तुलन का प्रयोग नीति के रूप में ही किया है क्योंकि वे मानते हैं कि ‘शक्ति सन्तुलन’ एक देश के उन प्रश्नों को कहते हैं जिन्हें वह दूसरे देश के विरुद्ध अपनी ताकत की इतनी बढ़ाने के लिए करता है कि जिससे उनकी ताकत उसके देश से यदि अधिक नहीं हो वन् से कम बराबर हो हो जाय।

(३) व्यवस्था के रूप में (As a System)—प्रायः शक्ति सन्तुलन का प्रयोग अनेक राज्यों से पूर्ण इस दिश में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की विशाल-न्दिन करने के किसी प्रकार के प्रवन्ध के रूप में भी कर दिया जाता है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित पुस्तकों में शक्ति सन्तुलन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। टेलर (Taylor) ने शक्ति सन्तुलन का प्रयोग राज्यों के परस्पर सम्बन्धों के नाम के रूप में किया है।

(४) प्रतीक के रूप में (As a Symbol)—अनेक विचारकों ने शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग किसी परिभाषा योग्य अर्थ में न करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति की समता के अन्तर्द्वन्द्वी तथा दूरदर्शी प्रतीक (Symbol) के रूप में किया है। इन विचारकों के मतानुसार शक्ति सन्तुलन नीति के अभाव का अर्थ है सैनिक दमजोरी, मित्रों का अभाव तथा आक्रमण-

कारी की शक्ति को सन्तुलित करने के प्रयत्नों का अभाव ।¹ बुडरो विनसन की नीति की आलोचना प्रायः इसी आधार पर की जाती है कि उसने शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तथ्य के रूप में देखने से मना कर दिया तथा एक आशावादी के मस्तिष्क से बाम लेने हुए अन्तर्राष्ट्रीयवाद पर ही विचार करता रहा । इस सब का अर्थ यही होता है कि शक्ति सन्तुलन को यथार्थवाद का प्रतीक माना जाने लगा है और इसलिए राजनीतिज्ञों एवं विचारकों से आशा की जाती है कि वे इसका आदर करेंगे ।

मि० ई० हेस (Mr Ernst Hass) ने उन लोगों के अर्थ एवं अभिप्राय का वर्णन किया है जिन्होंने शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग किया है । मि० हेस के कथनानुसार कुछ लोग शक्ति, सन्तुलन को व्याख्या के रूप में (As description) प्रयुक्त करते हैं । ये विचारक किसी भी सैद्धान्तिक या विश्लेषणात्मक उद्देश्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने से पूर्व शक्ति सन्तुलन को समझना आवश्यक मानते हैं । वर्तमान समय में पत्र सम्पादकों एवं रेडियो के आलोचकों द्वारा इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है । जब श्रोतागण इस शब्द को सुनते हैं तो वे इसका अर्थ केवल शक्ति का वितरण ही लगाते हैं न कि सन्तुलन । दूसरे भवसरो पर शक्ति सन्तुलन का अर्थ शक्ति के वितरण से कुछ अधिक होता है । यहाँ इसका अर्थ तुल्यमारिता या प्रभुत्व या महत्त्व से हो सकता है । यहाँ एक बात यह उल्लेखनीय है कि इस शब्द का प्रयोग करने वाले के अभिप्राय भी शब्द के अर्थ पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं । प्रत्येक लेखक अपने उद्देश्य के अनुसार ही एक कार्य को शक्ति सन्तुलन का स्थापक मानता है जबकि दूसरा अपने उद्देश्य की दृष्टि से उसके विपरीत कार्य को ऐसा मान सकता है । पिछली शताब्दी में फ्रांसीसी लेखकों ने तुल्यमारिता (Equilibrium) शब्द का प्रयोग आस्ट्रिया पर युद्ध की माँग का समर्थन करने के लिए किया । सान वर्ष तक यह युद्ध चला किन्तु इस काल में ब्रिटिश अधिकारी शक्ति सन्तुलन की नीति के आधार पर प्रुसिया (Prussia) के समर्थन को व्यापोजित ठहराने लगे । क्योंकि उनके मतानुसार फ्रीडरिक द्वितीय (Frederick II) ने ही आस्ट्रिया पर आक्रमण करके शक्ति सन्तुलन को बिगाड़ा था । आज भी शक्ति सन्तुलन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है

1 The alternative to balance of power policy 'is to remain poorly armed, without allies and with no attempt to balance the power of the aggressor state "

—Mill & Mc Laughlin, World Politics in Transition, P.109

वह सदैव ही एक अर्थ में नहीं होता। वह शक्ति के वितरण, तुल्यभारिता एवं प्रभावशीलता में से किसी भी अर्थ में प्रयुक्त किया जा सकता है।

२ शक्ति सतुलन के प्रयोग का दूसरा रूप प्रचार एवं विचारधारा (Propaganda and Ideology) का है। जब सतुलन का अर्थ शक्ति अथवा युद्ध के साथ एक रूप कर दिया जाता है तो उसे सम्भन्ध सहज बन जाता है। जब हम सतुलन शब्द का प्रयोग शक्ति की स्थापना एवं सतुरे के लिए तथा युद्ध को छेड़ने एवं रोकने के लिए कर सकते हैं तो यह स्पष्ट है कि सतुलन जैसी कोई चीज 'सतुलन' (अर्थात् शक्ति एवं युद्ध) के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ सतुलन शब्द का प्रयोग बिना किसी निश्चित अर्थ के ही केवल प्रचार के लिए किया जाता है। शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग करके एक राज्य अपनी नीतियों को यथारिथि रूप में हो न्यायोचित सिद्ध करता चाहता है। कुछ उदाहरणों में इस शब्द का प्रयोग विचारधारागत मतभेदों के सहारे के रूप में किया गया तथा कुछ उदाहरणों में हारे हुए राज्य की शक्ति एवं आधार को न्यायोचित बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस प्रकार इस शब्द के प्रयोग का अर्थ यह नहीं है कि प्रयोगकर्ता किसी निश्चित सिद्धांत में विश्वास करता है वरन् यह है कि वह इसे अपने हितों की प्राप्ति में उपयोगी मानता है।

प्रचार की दृष्टि से जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो तथ्यों का प्रयोग बेईमानी के साथ किया जाता है तथा बौद्धिक रूप से स्थापित मान्यताओं को तोड़-मरोड़ कर रखा जाता है। प्रचार तो सचेत-रूप से जान बूझ कर किया गया झूठ बात का स्थापन होता है। शक्ति सतुलन के द्वारा विचारधारागत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। मानहैम (Mannheim) के कथनानुसार विचारधारा कुछ प्रतीकों में विश्वास करती है चाहे वे प्रतीक वस्तुगत रूप से झूठे ही क्यों न हों। शक्ति सतुलन का सहारा लेकर एक देश नीतियों को प्राकृतिक वातून के रूप में अनिवार्य कर सकता है, नीतिक रूप से उचित सिद्ध कर सकता है अथवा इनको एक ऐतिहासिक आवश्यकता बता सकता है। इस अर्थ में जब शक्ति सतुलन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हम इसे केवल प्रचार मात्र ही नहीं कह सकते क्योंकि इस प्रकार इसे प्रयोग करने वाला अपने आपको भी धोखा देता है।

१८वीं शताब्दी में शक्ति सतुलन की मान्यता की आलोचना की गई। मि० जस्टी (Justi) ने अपने एक लेख में बताया कि शक्ति सतुलन का सिद्धांत और कुछ भी नहीं है केवल विचारधारागत तर्क है जो अपने

की अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का मूल तत्त्व मानने हैं। इस अर्थ में सन्तुलन इतिहास का कानून बन जाना है। प्रोफेसर मार्गोव्सो तथा शुमा ने शक्ति सन्तुलन को स्थापक अर्थ प्रदान किया है। वे इसे केवल तुल्यभारिता एवं प्रभुत्वशीलता मान ही नहीं मानते। इन लेखकों का मत है कि 'शक्ति सन्तुलन' सम्प्रभुता पर आधारित वैराज्य व्यवस्था में निहित रहता है। ये राज्य किसी भी लक्ष्य के लिए पारस्परिक विरोधी नीतियों में सलग्न रहते हैं। इस प्रक्रिया में यह स्वभाविक है कि राज्य सतुलित शक्ति की किराक में रहें तथा किसी को भी प्रभुतापूर्ण बनने से रोकने के लिए गुट तथा विरोधी गुट बनायें। परिवर्तन लाने में रुचि रखने वाले राज्य सदैव ही उन राज्यों के विरुद्ध गुट बना लेते हैं जो पयास्थिति को बनाय रखना चाहते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सामान्य है कि यह एक ऐतिहासिक कानून का रूप धारण कर लेती है। यह कानून राज्यों के व्यवहार का विशेषण प्रदान करता है। जब शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग विशेषण के एक औजार के रूप में किया जाता है तो इसकी एक मुख्य विशेषता यह बन जाती है कि इसे सरकारों के लक्ष्यों से पृथक् कर दिया जाता है।

③ 'शक्ति सन्तुलन' शब्द का चौथा प्रयोग एक उपचार के रूप में (As prescription) किया जा सकता है। विशेषण के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इन बातों पर जोर नहीं दिया जाता कि सरकारें सजगता से माय सन्तुलनकारी नियमों को अपनाती हैं। किन्तु ऐसे घनेक विचारक थे तथा हैं जो यह मानते हैं कि शक्ति सन्तुलन सरकारों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का निर्देशन सिद्धान्त है अथवा होना चाहिए। ये विचारक हॉम की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने के बाद यह कहते हैं कि इस अवस्था में ही शक्ति सन्तुलन के समर्थक राज्यों को उन राज्यों के विरुद्ध मभिबद्ध होने के लिए मजबूर किया जो विश्व में अथवा किसी क्षेत्र में प्रभुत्व की स्थापना करना चाहते थे अथवा विश्वव्यापी राजतन्त्र की रचना करना चाहते थे। इनमें से कुछ का कहना है कि दुनिया के राज्य एक दूसरे पर निर्भर रहने के कारण परस्पर बंधे हुए हैं। इनकी सामान्य समस्याएँ हैं, सामान्य कानून की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में यदि कोई भी एक राज्य प्रभुत्वपूर्ण बनना चाहेगा तो इसे सम्पूर्ण साव्यधी इकाई के विरुद्ध एक मात्र-मण समझा जायेगा। यह राज्य व्यवस्था स्वतन्त्र राज्यों से पूर्ण है तथा प्रभुत्व प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राज्य या विरोध प्रत्येक अपनी इच्छा से ही करेगा। इस व्यवस्था में शक्ति सन्तुलन का होना जरूरी था। इसने राज्यों की नीतियों को निर्देशन प्रदान किया।

शक्ति सन्तुलन को विदेश नीति की रचना का व्यावहारिक एवं सिद्धान्तिक रूप में निर्देशक माना जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। मैटर्निक (Matternich) जैसे परम्परावादियों एवं उदारवादियों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय सस्या के रूप में यह सिद्धांत पर्याप्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सम्पूर्ण सस्यागत यथास्थिति की रक्षा का प्रयास करता है। मैटर्निक के शब्दों में आधुनिक इतिहास इस बात का प्रदर्शक है कि एकता एवं शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्तों का प्रयोग एक ऐसा नाटक हमारे सामने लाता है जिसमें कुछ राज्य मिल कर एक राज्य को प्रभुत्व प्राप्त करने से रोकने हैं तथा उसके प्रभाव को सीमित करते हैं और इस प्रकार उस राज्य को सामान्य कानून की ओर लौटने के लिए बाध्य करते हैं।

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त के आधार पर राज्य अपनी रक्षा का प्रयास करता है अथवा इसे राज्य व्यवस्था की रक्षा के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्ति सन्तुलन का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह संगठन-आक्रमणकारी के इरादों को मोड़ने तथा उस पर प्रति-बन्ध लगाने का प्रयास करता है।

इस प्रकार शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है जो भिन्न होने के साथ साथ कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी भी बन जाते हैं। यदि आप शक्ति सन्तुलन की मायता को समझना या मूल्यांकित करना चाहे तो बड़ी परेशानी होगी क्योंकि अनेक लेखकों की यह प्रवृत्ति है कि इसके एक अर्थ का वर्णन करते-करते इसके दूसरे अर्थ का वर्णन करने लग जाते हैं और कुछ देर बाद पुनः उसी पहले वाले अर्थ पर आ जाते हैं कि तु वही भी इस बात का उल्लेख तक नहीं करते कि उनके द्वारा शक्ति सन्तुलन का प्रयोग भिन्न अर्थों में किया गया है। डाइके के अनुसार 'हम सन्तुलन (balance) शब्द का प्रयोग इस प्रकार करते रहे हैं कि मानो सभी इस बात को जानते हों कि इसका अर्थ क्या है किंतु वास्तव में सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है।'¹

शक्ति सन्तुलन की स्थापना के तरीके

(Methods for maintaining the Balance of Power)

विश्व में शांति की स्थापना के लिए, युद्धों को रोकने के लिये, शक्ति के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए तथा प्रत्येक राष्ट्र की सम्प्रभुता एवं

निरुपेक्ष लेने की स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर विवाद के राष्ट्रों के बीच शक्ति सन्तुलन की स्थापना का प्रयास किया गया है। शक्ति सन्तुलन में एक देश के रुचि लेने का प्रधान कारण यह है कि उसमें उसका राष्ट्रीय हित (National interest) निहित रहता है। शक्ति सन्तुलन की स्थापना करते समय एक राष्ट्र हर प्रकार के साधन अपना लेता है। बड़ी-बड़ी राजनैतिक व कूटनीतिक चालों के द्वारा यह इसे अपने हित में मोड़ लेता है। भावकल शक्ति सन्तुलन एक खेल सा बन गया है जिसमें उसके अपने नियमों, तकनीकों व तरीकों से खेला जा सकता है। मार्गोन्मत्त के कथनानुसार सन्तुलन की स्थापना या तो मारी पत्तों के बजन की वजह से की जा सकती है अथवा हल्के पत्तों में बजन डाल कर की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति सन्तुलन की स्थापना के लिए निम्न तरीके अपनाये जाते या जा सकते हैं—

(१) मुआवजा या प्रतिफल (Compensation)

एक देश द्वारा जब किसी प्रदेश पर अधिकार करने सन्तुलन को खतरा पहुँचाया जाये तो उसे रोकने के लिए उस देश की भूमि पर अधिकार करके पुनः शक्ति के सन्तुलन की स्थापना कर दी जाती है, यह प्रथा मध्य-युगी तथा उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित लोकप्रिय थी। १७१३ की युद्ध के सन्धि द्वारा प्रथम बार स्पेन द्वारा अधिकृत भूमि को वांट कर इस साधन द्वारा शक्ति सन्तुलन स्थापित करने की कोशिश की गई थी। इतिहास में पोलैण्ड का तीन बार विनाशित किया गया है और तीनों बार उसका बंट-बारा इस प्रकार किया गया कि सन्तुलन बना रहे। इस समय इस साधन की लोकप्रियता का कारण यह था कि भूमि के उपजाऊपन तथा लोगों की संख्या और गुण को इस समय राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। प्रदेशों के मुआवजे प्रायः युद्ध के बाद में बड़ी और विजयी शक्तियों द्वारा पराजित व कमजोर देशों के विपरीत किये जाते थे। १८७० से १९१४ तक इस साधन का रूप केवल भूमि पर बेम्हिस न रहा और प्रभाव क्षेत्रों (Spheres of influences) को भी विभाजित किया जाने लगा। इस युग में कोई भी राजा दूसरे राज्यों को राजनैतिक लाभ देने की सोच नहीं होता, जब तक कि उसे यह ज्ञात न हो जाय कि बदले में उसे कितना लाभ मिल रहा है या मिल सकता है। मार्गोन्मत्त के शब्दों में राजनैतिक मामलों में इस प्रकार के कूटनीतिक समझौतों की सोदेबाजी अपने

सामान्य रूप में मुसामवे का ही सिद्धान्त है तथा यह मूल का में शक्ति सन्तुलन से सम्बन्धित है ।^१

(२) हस्तक्षेप एवं युद्ध

(Intervention and War)

शक्ति सन्तुलन का दूसरा साधन युद्ध है। इतिहास में उदाहरणों को देख कर ऐसा लगता है कि शक्ति सम्बन्धों में परिवर्तन लाने के लिए कई बार युद्ध किये गये हैं। हस्तक्षेप (intervention) का अर्थ एक देश की विदेश नीति के उन पहलुओं व कार्यों से लगाया जाता है जिन्हें दूसरा देश भी अपने कार्य मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटन ने यूनान व जोर्डन में हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने क्यूबा, लेबनान व लाओस में किया, रूस ने उत्तरी कोरिया, हंगरी व पूर्वी योरोप में किया। इन सभी हस्तक्षेपों में शक्ति सन्तुलन की स्थापना उद्देश्य था या नहीं यह नहीं कहा जा सकता किन्तु यह परिणाम अवश्य था। कुछ विचारक शक्ति सन्तुलन की स्थापना के लिए हस्तक्षेप न करने की नीति को भी इतना ही महत्व प्रदान करते हैं। इस नीति का प्रयोग या तो उन कमजोर राष्ट्रों द्वारा किया जाता है जो लड़ाई में भाग लेने की शक्ति नहीं रखते या उन शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा जो कि स्थिर राजनैतिक व्यवस्था में संतुष्ट हैं और शान्तिपूर्ण साधनों से ही शक्ति सन्तुलन को बनाये रख सकते हैं। हस्तक्षेप की नीति का अन्तिम स्वर ही युद्ध है।

(३) सन्धिया

(Alliances)

यह साधन शक्ति सन्तुलन की स्थापना के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाता है। जब एक राष्ट्र की बढ़ी हुई शक्ति द्वारा विश्व के शक्ति सन्तुलन का चुनौती दी जाती है तो दूसरे राष्ट्र उसके विरुद्ध सन्धियाँ करके इस चुनौती का उत्तर देते हैं। सन्धियाँ दूसरे देशों पर आक्रमण करने की दृष्टि से भी की जा सकती हैं तथा आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने के लिए भी। पहले प्रकार की सन्धियाँ आक्रमणात्मक (Offensive) हैं तथा दूसरे प्रकार की रक्षात्मक (defensive)। वर्तमान में का सम्बन्ध शक्ति सन्तुलन से रहता है। आक्रमणात्मक सन्धियाँ शक्ति सन्तुलन को अपने हित में बदलना चाहती हैं जबकि रक्षात्मक सन्धियाँ शक्ति सन्तुलन को बनाये रखने का प्रयास

(४) फूट डालो व शासन करो (Divide and Rule)

इसके अनुसार एक देश ऐसी नीति अपनाता है ताकि उसके शत्रु आपस में मिल न सकें, उनके बीच फूट पड़ी रहे और वे कमजोर बने रहे। फ्रांस ने जर्मनी के सम्बन्ध में और सोवियत यूनियन ने शेष योरोप के सम्बन्ध में इस नीति को अपनाने का प्रयास किया। इस साधन के द्वारा एक शक्तिशाली देश की शक्ति को घटा कर कम और सन्तुलन के निकट किया जाता है। बहुत समय से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इस साधन का महत्त्व रहा है। ग्रेट ब्रिटेन को इस नीति का सबसे बड़ा पण्डित माना जाता है। इसी नीति के आधार पर वह अपने इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करता रहा था। इस काल में सोवियत यूनियन द्वारा उन सभी योजनाओं और प्रस्तावों का विरोध किया जाता है जो पश्चिमी योरोप में राजनैतिक व आर्थिक एकीकरण ला सकते हैं। इसका लक्ष्य मूलतः साम्यवादी व गैर-साम्यवादी गुट के बीच सन्तुलन को बनाय रखना है।

(५) बाधक राज्य (Buffer State)

विश्व जब दो गुटों में बँट गया तो उनके बीच सन्तुलन की स्थापना करने के साधन के रूप में बाधक राज्य के अस्तित्व का महत्त्व बढ़ गया। यदि विरोधी शक्तियाँ आमने-सामने रही तथा उनके बीच कोई बाधक प्रदेश या निष्पक्ष क्षेत्र न रहा तो सन्तुलन की स्थापना करना बड़ा कठिन हो जायेगा। मार्टिन वाइट के मतानुसार दुनिया का सबसे बाधक क्षेत्र 'था' (Tha) है जो रूस को ब्रिटिश साम्राज्य से अलग करता था। यह क्षेत्र कमजोर व दूरस्थ राज्यों का था जिनके बीच भौगोलिक गड़बड़े हुये थे, जिनमें राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। इस दृष्टि से उन देशों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो असलगतता की विदेश नीति अपना रहे हैं। भारत के नेतृत्व में ऐसे देशों का महत्त्व विश्व में शक्ति सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से बहुत कुछ बढ़ गया है।

(६) शस्त्रीकरण तथा निःशस्त्रीकरण (Armaments and disarmament)

मार्गेण्यो के मतानुसार शक्ति सन्तुलन का एक तरीका यह है कि शक्तिशाली राष्ट्रों की शक्ति को कमजोर कर दिया जाय। उन्हीं के

कथनानुसार ऐसा शस्त्रों की दौड़ द्वारा तथा निःशस्त्रीकरण द्वारा किया जा सकता है। शस्त्रों के नये नये रूपों का आविष्कार करके आक्रमणकारी के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्थाओं को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। सैनिक तैयारी तथा आधुनिकतम शस्त्रों का प्रयोग करके विश्व में स्थित असंतुलन का रोक जा सकता है। विद्वान्तरूप में एक स्थायी सन्तुलन की स्थापना अभी की जा सकती है जबकि शस्त्रों की दौड़ को समाप्त करके विरोधी शक्तियों के शस्त्रों के ऊपर सीमा लगा दी जाय। आज तक निःशस्त्रीकरण के अनेक प्रयास किये गये हैं किन्तु उनका परिणाम अविनाशितोपजनक न रहा। स्पेन के एक विद्वान् सेलवाडर माडरियागा (Salvador Madariaga) के मतानुसार निःशस्त्रीकरण की समस्या, निःशस्त्रीकरण की समस्या नहीं है यह वास्तव में विश्व समुदाय के संगठन की समस्या है। पानर तथा परकिन्स के मतानुसार मूल रूप में यह शक्ति सन्तुलन की स्थापना की समस्या है।^१

शक्ति सन्तुलन तथा राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले अन्य तत्व

(Balance of Power and other limiting factors)

कई कारणों से जब राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करने वाले तत्व के रूप में शक्ति सन्तुलन का महत्त्व कम हो गया तो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शक्ति सन्तुलन के विकल्पों की खोज की जाने लगी जो व्यावहारिक हों। अमेरिकन राष्ट्रपति वूडरो विलसन ने शक्ति सन्तुलन की आलोचनायें करके विश्व शान्ति की स्थापना के लिए सामूहिक सुरक्षा (Collective Security) पर जोर दिया। सामूहिक सुरक्षा के अधीन सभी देश परस्पर सम्बद्ध रहेंगे। अतः यह कहा जाता है कि किसी प्रकार की सन्धियों की, घस्र शस्त्रों की दौड़ की, राजनैतिक मतभेदों की तथा परस्पर स्रष्टवों की कोई आवश्यकता न रहेगी। ये सभी बातें शक्ति सन्तुलन में पाई जाती हैं। किन्सी राइट (Quincy Wright) का मत है कि शक्ति सन्तुलन का सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्ध एक ही साथ पूरक (Complementary) तथा एक विरोधी (Antagonistic) का है। सामूहिक सुरक्षा का आधार शक्ति सन्तुलन है जो ऐसे स्थायित्व का निर्माण करता है जिसमें नीति की क्रियाओं को स्थायित्व देना सम्भव होता है। सामूहिक सुरक्षा के उदाहरण हैं योरोप का मेल (Concert of Europe), राष्ट्रसंघ (League of Nations) और

1. Salvador de Madariaga, Disarmament, 1929, P. 56.

संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations)—शक्ति सन्तुलन का सम्बन्ध इन तीनों ही रूपों से रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के साथ भी शक्ति सन्तुलन का वही सम्बन्ध है जो विन्सो राइट द्वारा शक्ति सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा के बीच बताया गया है। ओपेनहिम (L. F. Oppenheim) के मतानुसार शक्ति सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रों का कानून (A law of nations) केवल तभी रह सकता है जबकि विश्व में शक्ति का सन्तुलन या तुल्यमारिता रहेगी। राष्ट्रों के ऊपर कोई सम्प्रभु व शक्तिशाली व्यवस्था न होने के कारण केवल शक्ति सन्तुलन द्वारा ही ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है कि एक राष्ट्र दूसरे पर विवशकारी शक्ति का प्रयोग न कर सके। कुछ विचारकों के मत में अन्तर्राष्ट्रीय कानून शक्ति सन्तुलन को धीरे-धीरे सामूहिक सुरक्षा में परिणत कर देगा। विन्सो राइट का मत है कि यदि वर्तमान परिस्थितियों में शान्तिपूर्ण साधनों से कानून द्वारा प्रशासित विश्व का निर्माण करना हो तो राजनीतिज्ञों को अधिक सश्लिष्ट सन्तुलन (Complicated balance) का प्रयत्न करना होगा।

शक्ति सन्तुलन पर मार्गेन्थो के विचार (Morgenthau on Balance of Power)

शक्ति सन्तुलन से सम्बन्धित कोई भी अध्ययन तब तक अधूरा माना जायगा जब तक कि इस विषय के प्रमुख विचारक मार्गेन्थो के विचारों का वर्णन न किया जाय।

(१) मार्गेन्थो के मतानुसार शब्द 'शक्ति सन्तुलन' का प्रयोग चार भिन्न-भिन्न अर्थों में किया जा सकता है—(i) एक नीति के रूप में जो कुछ निश्चित कार्य करना चाहती है, (ii) वास्तविक कार्यों के रूप में, (iii) शक्ति के लगभग समान वितरण के रूप में तथा (iv) शक्ति के किसी भी वितरण के रूप में। उनका कहना है कि जब शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग बिना किसी विशेषण (Qualification) के किया जाता है तो यह कार्यों के वास्तविक स्तर को बताता है जिसमें कुछ राष्ट्रों के बीच शक्ति का लगभग समान वितरण कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में मार्गेन्थो के अनुसार शक्ति सन्तुलन का अर्थ तुल्यमारिता है। किन्तु जैसा कि क्लॉड (I. L. Claude) का मत है, मार्गेन्थो द्वारा शक्ति सन्तुलन शब्द का प्रयोग

नई ग्रंथों में किया गया है तथा इस परिवर्तन की सूचना भी पाठक को नहीं दी गई है।^१ उन्होंने इस शब्द का प्रयोग शक्ति के वितरण के रूप में भी किया है। मार्गेन्थो की पुस्तक पढ़ते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस बार इस शब्द का प्रयोग किताब में किया गया है। सच तो यह है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पाँच ग्रंथों में किया है।

(२) मार्गेन्थो ने शक्ति सतुलन के सिद्धान्त को अपरिहार्य (inevitable) बताया है। उनका मत है कि शक्ति सतुलन तथा इसे बनाये रखने वाली नीतियाँ न केवल अपरिहार्य हैं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्रों के समाज में स्थायित्व लाने वाले मूल तत्व हैं।

(३) मार्गेन्थो के अनुसार शक्ति सतुलन विदेश नीति का एक सामान्य साधन (universal instrument) है। इसका प्रयोग अपनी स्वतन्त्रता चाहने वाले प्रत्येक राष्ट्र द्वारा प्रत्येक समय में किया गया है। यह शक्ति के संघर्ष का स्वाभाविक एवं अपरिहार्य परिणाम है।

(४) मार्गेन्थो के शक्ति सतुलन सम्बन्धी विचारों में कुछ अतृप्तियाँ हैं। जब वे शक्ति सतुलन को अपरिहार्य तथा स्वाभाविक मानते हैं तो वे यह नहीं बताते कि शक्ति सतुलन के कौन से रूप के बारे में वे ऐसा कह रहे हैं। एक ओर वे इसे मनुष्य कृत मानते हैं। इसी प्रकार शक्ति सतुलन का सामान्य रूप भी आजकल प्राप्त नहीं होता है।

(५) तुल्यभारिता को अपरिहार्य मान कर अमेरिकन विदेश नीति के गुण को सुधारने के लिए मार्गेन्थो ने प्रत्येक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। शक्ति सतुलन को अपरिहार्य मानने का उनका अर्थ क्या हो सकता है यह जानना बड़ा कठिन है। पुस्तक को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति सतुलन की अपरिहार्यता से उनका अर्थ न तो यह है कि तुल्यभारिता (equilibrium) की स्थिति सदैव रहती है और न यह कि राज्यों की नीतियाँ सदैव ऐसी स्थिति बनाने या उसकी रक्षा करने का लक्ष्य रखती हैं। मार्गेन्थो ने यह माना है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के लिए शक्ति सतुलन के अतिरिक्त इतिहास में अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन आदि साधनों का भी विकास किया गया है। इस मान्यता

का स्पष्ट अर्थ यह है कि शक्ति समुत्तम को अपरिहार्य नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका कार्य समालने के लिए दूसरे विकल्प मौजूद रहते हैं। मार्गेन्यो ने बताया कि राष्ट्रों के सामने दूसरा रास्ता ही नहीं होता। बुद्धि के आधार पर निर्मित एक विदेश नीति सदैव शक्ति के संतुलन का सिद्धांत अपनाती है, किन्तु जो देश इसका बहिष्कार करता है, या तो उसे विश्व को विजय करना पड़ेगा अथवा वह नष्ट हो जायेगा।

शक्ति संतुलन के सिद्धांत का मूल्यांकन

(An Evaluation of the Balance of Power Principle)

शक्ति संतुलन का सिद्धान्त एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे विचारकों ने प्रशंसा करके अपरिहार्य बना दिया और साथ ही जिसे आलोचना वालों का इतना सामना करना पड़ा कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। रिचार्ड कोबडन (Richard Cobden) का कहना है कि "शक्ति संतुलन का सिद्धान्त केवल एक असम्भव कल्पना मात्र है—राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क की एक उपज है—एक छाया मात्र है जिसका कोई निश्चित रूप ही नहीं है, एक स्वास में बोले जाने वाले शब्दों का योग है, इसके प्रक्षर हैं जो कुछ आवाज करते हैं किन्तु उनका कोई अर्थ नहीं होता।"¹

कुछ विचारक शक्ति संतुलन को एक पाप मानते हैं जिसे शरी ही दूर किया जाना चाहिए जबकि दूसरे एक ऐसा मार्गदर्शक मानते हैं जिसका अनुसरण किया जाना आवश्यक है। परम्परागत अमेरिकी विचार के अनुसार शक्ति संतुलन का मूल्य लोगों के जीवन तथा प्रसन्नता से जुड़ाया जाता है। विलसन (Wilson), हल (Hull) तथा रूजवेल्ट (Roosevelt) आदि ने शक्ति संतुलन को भगवद्गीता तथा मूर्खों का कारण माना है तथा इसके स्थान पर सानूहिक सुरक्षा प्रवर्धनों की स्थापना का पक्ष लिया है। इसके विपरीत मार्गेन्यो का विचार है कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माता के रूप में शक्ति संतुलन इतिहास के विभिन्न स्तरों पर सफल रहा है, इसने किसी भी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया है जो अन्य दूसरों की स्वतन्त्रता को समाप्त कर सके।"² प्रसिद्ध इतिहासकार फेररो (Ferrero) के मतानुसार

1. Richard Cobden, Political Writings.

2. Morgenthau & Thompson, Principles and problems of international Politics P. 103.

“उन्नीसवीं शताब्दी का यूरोप युद्धों के लिए प्रसिद्ध है किन्तु इस समय के युद्धों को स्थानीय एवं सीमित बनाने का श्रेय शक्ति सन्तुलन को दिया जा सकता है।” क्लाड (I L. Claude) ने माना है कि “शक्ति सन्तुलन व्यवस्था इस रूप में कार्य कर सकती है कि तुल्यभारिता (equilibrium) की रचना व सँभाल कर सके किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह ऐसा करे और यह इन परिणामों को उत्पन्न करने वाली उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं है।”^१

दूसरी ओर अनेक विचारक ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था ने कई बार युद्धों को रोका है। फ्रेडरिक गेन्ज (Friedrich Genz) का कहना है कि “युद्ध प्रायः तभी उत्पन्न होता है जब एक देश बहुत अधिक शक्ति (The excessive overweight) प्राप्त कर लेता है। अन्य कुछ विचारकों के मतानुसार भी शक्ति की निश्चित जड़ें शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त में निहित रहती हैं। क्लेमेंटो (Clemenceau) का कहना था कि प्रथम विश्वयुद्ध सन्तुलन के टूटने का परिणाम था। यदि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था जाती रहती तो निश्चय ही निम्न युद्ध न दिखता। क्लाड (I L. Claude) का विचार है कि “शक्ति सन्तुलन को युद्ध रोकने का साधन मानने वाले तथा उसे ऐसा न मानने वाले विचारकों के बीच कोई इतनी नहीं है कि जिसे पाटा नहीं जा सके।” सत्य तो यह है कि दोनों ही पक्ष इसे तुल्यभारिता को बनाने व रक्षित रखने का एक साधन मानते हैं। एक पक्ष का विचार है कि युद्ध इस तथ्य को प्राप्त करने का आवश्यक साधन हो सकता है जबकि दूसरा पक्ष यह सोचता है कि तुल्यभारिता आक्रमणात्मक कार्यों पर रोक लगा कर शक्ति की स्थापना करता है। क्विन्सी राइट के शब्दों में ‘शक्ति सन्तुलन एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रत्येक राज्य में निरन्तर यह विश्वास पैदा करती है कि यदि उसने आक्रमण करने का प्रयत्न किया तो दूसरे राष्ट्रों के संगठित प्रयत्न द्वारा उसका विरोध किया जायेगा।’^२

1. The Reconstruction of Europe, P. 338.
2. Power and International Relations, Pp. 66.
3. Quincy Wright, A study of war, I, 254.

शक्ति सन्तुलन को युद्ध का कारण मानने वाले यह भूल जाते हैं कि यह व्यवस्था किसी शान्तिवादी दर्शन से सम्बन्धित नहीं है: इसका अर्थ तो केवल यह है कि राज्यों को धक्के ही या संगठित रूप से शक्ति का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि ऐसी शक्ति को भी कुचल देना चाहिए जो भविष्य में उनकी स्वयं की सुरक्षा को चुनौती दे सकती है। इस प्रकार 'युद्ध' तुल्यभारिता (Equilibrium) की स्थापना के लिए आवश्यक हो सकता है या तुल्यभारिता के द्वारा युद्ध को रोका जा सकता है, दोनों ही बातें सच हैं।

(m)n

शक्ति सन्तुलन की मान्यता के अनेक लाभ हैं—यह आक्रमणों का हतोत्साहित (Discourage) करके राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा करता है, यह विजय की योजनाओं को हतोत्साहित करके विश्व साम्राज्य को बनने से रोकता है, यह गड़बड़ को रोक कर वस्तुस्थिति (Statusquo) को स्थाई बनाता है। यह हो सकता है कि प्रतिरोध का यह साधन असफल हो जाए और युद्ध को न रोक पाए किन्तु यह गलत नहीं है कि शान्ति स्थापना में इसकी भारी देन है। ऑर्गन्स्की (Organski) यह नहीं मानते कि तुल्यभारिता शान्ति की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। उनका विश्वास है कि शान्ति और शक्ति सन्तुलन के बीच जो सम्बन्ध माना जाता है वास्तव में यह उससे विचरित है। सन्तुलन का काल चाहे वह वास्तविक या या काल्पनिक—युद्ध का समय है जबकि शान्ति अधिक शक्ति का समय, शान्ति का समय या।^१ मार्गेन्थो ने बताया है कि शक्ति सन्तुलन न केवल पोलैंड की रक्षा करने में ही असफल हो गया किन्तु भूमि के मुद्रावजे के रूप में वितरण करने के नाम पर पोलैंड का ही विनाश कर दिया गया। शक्ति सन्तुलन ने किसी राज्य विशेष या पूरी राज्य व्यवस्था के किसी भी कार्य को युद्ध के साधन के अलावा अन्य किसी साधन से पूरा नहीं किया। मार्गेन्थो के मतानुसार इसका कारण शक्ति सन्तुलन की तीन कमजोरियाँ हैं—यह अनिश्चित है, यह अवास्तविक है, यह अपर्याप्त है।^२

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की मान्यता का मूल्यांकन करते हुए पेंडिल फोर्ड तथा लिक्न ने बताया है कि इस सिद्धान्त के द्वारा यह दावा किया जाता

1. Organski, World Politics, P 292.

2. Morgenthau, Politics among Nations, P 185.

है कि इसने युद्धों को रोका है तथा हतोत्साहित किया है। दूसरे राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा की है और तीसरे, एक राज्य प्रथवा राज्यों के समूहों द्वारा अनुचित प्रभुत्व स्थापित करने पर रोक लगाई है और इस प्रकार बहुराज्य व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता की है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि शक्ति सन्तुलन की राजनीति ने कुछ युद्धों को रोका, कुछ में देरी की और कुछ को हतोत्साहित किया। किन्तु युद्ध की दृष्टि से हम इसे एक प्रचूक प्रोपधि नहीं मान सकते क्योंकि यह अतीतकाल में अनेक युद्धों की रोकने में असफल रहा और भविष्य में भी यह युद्ध का एक सफल प्रवरोधक नहीं है। शक्ति सन्तुलन की नीति को व्यवहारवादिता के आधार पर समर्थन प्रदान किया जाता है और यह कहा जाता है कि आक्रमणकारी शक्ति को मर्यादित करने का यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है।

शक्ति सन्तुलन की राजनीति ने अनेक यूरोपीय राज्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा में सहयोग दिया है। किन्तु बीसवीं शताब्दी में इसने इटली को इथियोपिया पर आक्रमण करने से नहीं रोका और जापान को चीन का एक बड़ा भाग लेने से नहीं रोका। यूरोप में सन् १९३० में जो बड़ी शक्तियों के बीच सन्धि समझौते किये गये उनमें से अनेक ऐसे थे जो छोटे राज्यों के मूल्य पर हुए। हिटलर की माँग पर चेकोस्लोवाकिया को समाप्त कर दिया गया और पोलैण्ड को रुम तथा जर्मनी के बीच बांट दिया गया। मैम्बरलेन तथा डालाडोर ने यह सोचा था कि हिटलर के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाकर युद्ध को रोका जा सकता है किन्तु इतिहास साक्ष्य है कि जब स्थित सन्तुलन को बिगाड़ने वाले राज्य की माँगों को स्वीकार किया जाता है तो वह और अधिक प्रोत्साहित होता है।

महत्त्व

शक्ति सन्तुलन के सिद्धांत के महत्त्व के सम्बन्ध में लिखते हुए जोराफ फ्रैंक ने बताया है कि शक्ति सन्तुलन की मानव जाति के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण नवीन कृति मानने के अनेक कारण हैं। उनके मतानुसार रोमन साम्राज्य के विध्वंस के बाद यूरोप ने पहली बार कुछ थोड़ा बहुत स्थायित्व प्राप्त किया। यह स्थायित्व ऐसा नहीं था जिसे कि किसी एक प्रभुत्वशाली

द्वारा विजय और सत्ता के आधार पर स्थापित किया गया हो और दूसरे लोग जिसे मग से स्वीकार न करते हो। आधुनिक विचारों एवं राष्ट्रवादी शक्तियों के अनुरूप राज्य की नवीन व्यवस्था बहुलवादी बनी। शक्ति सन्तुलन की धारणा ने कुछ बड़ी शक्तियों को प्रभावित किया और धीरे-धीरे यह यूरोप की सीमाओं से भी बाहर निकल गया। इतिहास के आधुनिक काल में पहली बार विश्व के विभिन्न देशों ने यह स्वीकार किया कि शक्ति सन्तुलन का विचार उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नाम पर राज्यों ने अपनी स्वार्थ भावनाओं को छोड़ दिया था। वरन् इसके विपरीत राज्य अब भी पहले की भाँति प्रतियोगी एवं सन्देशशील बने रहे। इनमें से प्रत्येक अपने व्यवहार का सर्वोच्च निर्णायक था। राज्य इस व्यवस्था के नियमों को तोड़ने के लिये स्वतन्त्र थे। अन्य पूर्व व्यवस्थाओं की भाँति शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था में भी एक राज्य अपने स्वार्थ की भावना से प्रभावित होकर दूसरों पर विजय पाने के लिये तथा शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था को तोड़ने के लिए प्रयास कर सकता था।

इतने पर भी शक्ति सन्तुलन की धारणा अपनी पूर्व व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक विचारपूर्ण एवं व्यावहारिक थी। यदि व्यवस्था के सदस्य राज्य इसके नियमों का पालन करने के लिए तैयार न हों तो उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता था। प्रत्येक राज्य अपने सामान्य हित को ध्यान में रख कर उन नियमों की रक्षा के प्रति सजग रहना है जिसे कि दूसरों के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जाता है। जब एक राज्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है तो दूसरे राज्य आत्मरक्षा की दृष्टि से मिल जाते हैं। शक्ति सन्तुलन की धारणा ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में स्वायत्तत्व की रचना की। प्रथम वेस्ट फेलिया की सन्धि द्वारा प्रदेश का पुनर्वितरण करके सन्तुलन स्थापित किया गया और इस प्रकार स्वायत्तत्व की रचना की। इस सन्धि के बाद कुछ प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ जो अपने बीच में तुल्यभाविता रखने में समर्थ थी। नेपालियन के बाद के बाद वाले समझौते का आधार कानूनी औचित्य का बताया गया और इकाइयों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान आटोमन साम्राज्य श्रमश, क्षिप्र-भिन्न होने लगा किन्तु यह साम्राज्य शक्ति सन्तुलन व्यवस्था के लिए आवश्यक

नहीं था। जब इटली और जर्मनी के एकीकरण के बाद नई शक्तिशाली इकाइयों का उदय हुआ तो यह व्यवस्था गम्भीररूप से अस्त व्यस्त हो गई।

शक्ति सन्तुलन का व्यवस्था को सुरक्षा की प्राप्ति के लिए अपनाया जाता है। यह विद्वान् ज़्याड़े के स्थान पर समझौता करने के लिए अवसर प्रदान करता है। दूसरों की शक्तियों के साथ तुल्यभारिता रखने के लिए भारपाई शक्तियाँ की जाती हैं। उन शक्ति सन्तुलन को चुनौती दी जाती है और उसे शान्तिपूर्ण साधनों से नहीं दबाया जा सकता वो युद्ध छिड़ जाता है। किन्तु यह युद्ध विरोधियों को समाप्त करने के लिए नहीं लड़ा जाता वरन् हारे हुए राज्य को सम्भावित भावी मित्र के रूप में बनाने के लिए लड़ा जाता है।

— (1910-1911) —

— शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त की आलोचना भी कम नहीं हुई है। कई बार यह दोषारोपण किया जाता है कि यह सिद्धान्त शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए एक प्रभावशाली सूत्र होने की अपेक्षा युद्धों को प्रोत्साहन देने वाला तथा असुरक्षा को बढ़ाने वाला रहा है। बुद्धो विन्सन शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की स्पष्ट रूप से आलोचना करते थे। जनवरी, १९१७ में उन्होंने घोषणा की कि अब मानव जाति जीवन की स्वतन्त्रता की तलाश में है न कि शक्ति के सन्तुलन की तलाश में। उनके मतानुसार अब शक्ति सन्तुलन की जरूरत नहीं है वरन् एक शक्तिपूर्ण समाज की जरूरत है, अब समन्वित विरोधियों की जरूरत नहीं है वरन् एक समन्वित सामान्य शक्ति की जरूरत है। विन्सन का मत था कि प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेने वाले लोगों का यह उद्देश्य था कि शक्ति सन्तुलन को अब और हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। अब राष्ट्रों का कोई एक शक्तिशाली समूह नहीं होना चाहिये जो कि दूसरे शक्तिशाली समूह के विरुद्ध खड़ा हो किन्तु राष्ट्रों का एक ही शक्तिशाली समूह होना चाहिए जो कि विश्व की शान्ति का संरक्षक बन जाए।

शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की अनेक आलोचनाओं के बाद भी प्रोफेसर डी विट सो पूल (De Witt C. Poole) जैसे लोगों की यह मान्यता है कि स्वतन्त्रता केवल उस दुनिया में ही रह सकती है जिसमें कि शक्ति को व्यापक रूप से वितरित एवं संतुलित किया गया है। कुछ सन्देहशीलों का इस सम्बन्ध में मतभेद है कि शक्ति सन्तुलन की मान्यता ने वास्तविक स्थिति का कभी अभिव्यक्त किया है अथवा नहीं। यह कहा जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक तथा तकनीकी परिवर्तन राष्ट्रों की शक्ति स्थिति में निरन्तर परिवर्तन लाते रहे हैं और ऐसी स्थिति में राज्यों के बीच शक्ति सन्तुलन कैसे स्थापित हो सकता है। प्रत्येक राज्य की नीतियों एवं कार्यों की देखने से यह

प्रकट होता है कि हर राज्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है
जितनी कि अन्य राज्यों के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य
सन्तुलन की स्थिति को बनाए रखने की खातिर ऐसे कार्यक्रमों को स्वीकार
नहीं करेगा जो उसकी शक्ति के स्वाभाविक विकास को रोक दें।

कुछ लेखकों का मत है कि शक्ति सन्तुलन का नैतिक रूप में विश्लेषण नहीं करना चाहिए। विल्सन तथा अन्य लोगों ने शक्ति सन्तुलन को एक अनैतिक कार्य माना है। किन्तु उनका यह दृष्टिकोण उचित नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय शक्ति का अस्तित्व एक तथ्य है और वह एक तथ्य बना रहगा। चाहे सन्तुलन को नैतिक माना जाए अथवा अनैतिक माना जाए, किन्तु वह तो हर युग में रहेगा। शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था में आने वाले सम्प्रभु राज्यों के निष्पत्तियों को उनके सहयोगियों द्वारा नियन्त्रित नहीं किया जा सकता। राजनैतिक नेताओं पर अनेक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। वे अपने राष्ट्रीय राजनैतिक अन्तरो एव दबाव समूहों द्वारा प्रभावित होते हैं। शक्ति सन्तुलन की स्थिति में सहयोग करते हुए भी व्यक्तिगत राज्य द्वारा एक विषय की किस तरह से व्याख्या की जाएगी यह बात किसी समस्या विशेष की प्रकृति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए युद्ध-राज्य अमेरिका के मित्र राष्ट्र उसकी विद्यमान नीति से सहमत नहीं हैं। शक्ति सन्तुलन के व्यवहार को प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति के राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सैनिक रूपों द्वारा भी जटिल बना दिया जाता है। एक देश अपने मित्र देश से सैनिक सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा आर्थिक सहायता प्राप्त करने में अधिक रुचि ले सकता है। इसी प्रकार कई बार केवल राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक सहयोग ही पर्याप्त होता है। एक राज्य जब अपने मित्र राज्य की सहायता करने का निर्णय लेता है तो उसे अनेक बातों से प्रभावित होना पड़ता है जिनको कि पहले से नहीं देखा जा सकता।

आजकल दुनिया में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं जो कि मनु-
लन व्यवस्था को पर्याप्त प्रभावित कर रहे हैं। विश्व राजनीति में इस दृष्टि
से पहला प्रमुख परिवर्तन राज्यों की शक्ति स्थिति में परिवर्तन है। वेने आज भी पश्चिमी यूरोप महा शक्तियों का केन्द्र है किन्तु उससे व्यक्तिगत राज्यों के पास आज सर्वाधिक शक्ति नहीं है। समुद्रराज्य अमेरिका और सोवियत संघ के पास सर्वाधिक निर्णायक शक्ति है। शक्ति के अतिरिक्त केन्द्रों के रूप में चीन, जापान और भारत का उदय हो रहा है। हमारे अतिरिक्त अफ्रीका के एक दो राज्य तथा पाकिस्तान, इथियोपिया आदि को भी कुछ महत्व की शक्ति माना जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से अनेक छोटे छोटे कमजोर राष्ट्र,

उदाहरण के लिए अफ्रीका राज्य भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण सृष्टियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार शक्ति किसी देश विशेष या महाद्वीप विशेष में नहीं रही है, बरन् यह पूरी दुनिया में फैल गई है। शक्ति-शाली केन्द्रों की बढ़ोतरी ने शक्ति सन्तुलन व्यवस्था की स्थापना एवं प्रयोग को अत्यन्त जटिल बना दिया है। आज यदि कहीं सन्तुलन है तो इसका अस्तित्व बहुत कुछ एक सन्तुलनकर्त्ता या नियन्त्रक के हस्तक्षेप पर निर्भर करता है जो कि सलग क्षेत्र से बाहर वाला ही कोई होता है।

और शक्ति सन्तुलन की स्थिति पर प्रभाव डालने वाला एक अन्य तत्व आर्थिक विकास है। औद्योगीकरण का प्रसार करने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक पर-निर्भरता बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में शक्ति सन्तुलन पर आर्थिक तत्व का प्रभाव भी बढ़ गया है। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण एक तीसरा विकास राष्ट्रवाद की भावना है जो कि विचारधारा के प्रभाव के साथ मिल कर उल्लेखनीय बन जाता है। आज संचार के व्यापक माध्यमों के द्वारा जनता को सामूहिक रूप से विचारधारा और राष्ट्रवाद के नाम पर प्रभावित किया जा सकता है और इस प्रकार सन्तुलनकारी व्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है। आजकल संचार एवं प्रचार की जो तकनीकें अपनाई जाती हैं, उनके द्वारा विश्व के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कम समय में ही बात को पहुँचाया जा सकता है और इसलिए कोई भी राज्य जो थोड़े समय पहले मित्र था, अब शत्रु बन सकता है। क्यूबा के उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए यह कहा जाता है कि यह बहुत शीघ्र ही सयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत रूस तथा पश्चिमी शक्तियाँ मित्र बन गए किन्तु सामान्य मूल्यों एवं लक्ष्यों के अभाव में यह मित्रता केवल कुछ समय तक ही चली। इसी प्रकार सयुक्त राज्य अमरीका और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में परम शत्रु थे, किन्तु सन् १९५० के बाद वे परम मित्र बन गए। शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के लिए आत्म-समांगीजन का तत्व बहुत जरूरी होता है और आजकल की परिस्थितियों में यह अत्यन्त जटिल बन गया है तथा इसकी पहले से कल्पना नहीं की जा सकती। आज सोवियत राश और चीन के बीच पर्याप्त संघर्ष है। दूसरी ओर फ्रांस की नीतियों ने पश्चिमी शक्तियों की एकता तथा ठोसपन को कमजोर कर दिया है। इन प्रकार दोनों पक्षों के बीच सन्तुलन की स्थापना हो गई है। आजकल असलग्न देशों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इन देशों के विकास ने सन्तुलन की व्यवस्था में अनिश्चय का एक अन्य तत्व जोड़ दिया है जो कि उनीनियों गतांशों में नहीं था। आजकल सम्प्रभु राज्यों के उदय, विचारधारागत विभिन्नतायें,

क्षेत्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति, आदि ने शक्ति सन्तुलन की प्रकृति, प्रसार व अस्तित्व को विवादास्पद बना दिया है।

शक्ति सन्तुलन का वर्तमान रूप

(The Modern Picture of Balance of Power)

आज की बढ़ती हुई परिस्थितियों में शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था मुश्किल पड़ गई है। विलसन ने तो इसे सिद्धान्त रूप में ही आलोचित किया था किन्तु दूसरे विचारक इसे समय के परिवर्तन के कारण अव्यावहारिक बताते हैं। विलसन का विचार था कि शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था प्रजातन्त्र के लिए घातक थी, मानवतावाद के लिए अभिशाप थी, तथा आत्मनिर्णय के सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता आदि के विपरीत थी। आज शक्ति सन्तुलन के सिद्धान्त की क्या स्थिति है इसका अध्ययन करते हुए पामर तथा परकिन्स ने बताया है कि "वर्तमान विश्व की परिस्थितियाँ शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था के लिए विशेषतः अनुकूल नहीं हैं, किन्तु फिर भी यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक प्रभावकारी रूप है और अभी तक इसका कोई प्रभावशाली विकल्प (Effective substitute) नहीं बन पाया है।"

शक्ति सन्तुलन ने सबसे अच्छा कार्य तभी किया था जबकि अनेक राज्य लगभग समान शक्ति वाले थे। फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद जब शक्ति सन्तुलन योरोप की सीमाओं से निकल कर विश्वव्यापी बन गया तो राष्ट्रों के बीच सन्तुलन स्थापित करने वाली परिस्थितियाँ उतनी उपयुक्त न रह गयीं। वर्तमान युग में अनेक विकास ऐसे हुए जिनके कारण शक्ति सन्तुलन एक ही साथ अत्यधिक सहज तथा कठिन नीति बन गया है। इनमें से उल्लेखनीय इस प्रकार हैं—राष्ट्रवाद, औद्योगीकरण, प्रजातन्त्र, शिक्षा का प्रसार, युद्ध के नये तरीके व तकनीक, लोचमत्ता का बढ़ता हुआ महत्व, अन्तर्राष्ट्रीय कानून व संगठन में विकास, राष्ट्रों की बढ़ती हुई आर्थिक परनिभरता, उन्नतिवादी का अन्त आदि। क्विन्सी राइट (Quincy Wright) ने बीसवीं शताब्दी के उन परिवर्तनों का अध्ययन किया है जो शक्ति सन्तुलन के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। ये मुख्यतः ऐसी चार परिस्थितियों का वर्णन करते हैं—

१ विश्व स्पष्टतः दो गुटों में बंट गया है तथा अब व्यवस्था का कोई सन्तुलनकर्त्ता (balancer) नहीं है।

२ आज युद्ध का रूप भयावह हो गया है तथा इसने सम्पूर्ण युद्ध (Total war) का रूप धारण कर लिया है जिसके विध्वंसक परिणामों को देख कर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति या राष्ट्र सन्तुलन स्थापित करने की खातिर युद्ध का सहारा नहीं ले सकता।

३ विचारधाराओं (ideologies) तथा शक्ति के दूसरे कम व्यवहार्य (less tangible) तत्वों का महत्व बढ़ता जा रहा है।

४ राज्यों की शक्ति के बीच भारी अन्तर पड़ता जा रहा है। उच्च शक्ति अधिक शक्तिशाली तथा कमजोर राष्ट्र सापेक्ष रूप में अधिक कमजोर बनते जा रहे हैं।¹ राइट के कथनानुसार स्थिरता के उभे तरीके पर (शक्ति सन्तुलन पर) निर्भर करता एक अविश्वासी मनुष्य पर निर्भर रहने के समान है।²

Imp

सामूहिक सुरक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का शान्तिपूर्ण निपटारा (Collective Security and Peaceful Settlement of International Disputes)

अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित करने का एक दूसरा साधन सामूहिक सुरक्षा है जिसमें विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिल कर सम्भावित आक्रमणकारी का विरोध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शक्ति सन्तुलन की व्यवस्था में जो सन्धिवादी की जाती हैं उनका लक्ष्य एक देश या कुछ देशों के गुट का विरोध करना, उन पर आक्रमण करना या उनके आक्रमण से अपनी रक्षा करना होता है किन्तु सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था में विरोधी अस्पष्ट एवं सम्भावित होता है। इस प्रकार की संधि में यह व्यवस्था होती है कि किसी भी एक इकाई पर आने वाला संकट या आक्रमण सन्धिबद्ध सभी इकाइयों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाता है और सामूहिक रूप से ही उसका विरोध किया जाता है। इस व्यवस्था को शान्तिपूर्ण एवं शान्ति का अतिवर्धक माना जाता है। क्लॉड (Claude) के मतानुसार यदि केन्द्रीकरण की दृष्टि से देखा जाय तो हम पायेंगे कि सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है। इसमें शक्ति सन्तुलन से अधिक केन्द्रीकृत प्रबन्ध होता है किन्तु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम रहता है।³

सामूहिक सुरक्षा का अर्थ

(The Meaning of Collective Security)

सामूहिक सुरक्षा जैसा कि शब्दों से ही प्रकट होता है, देशों द्वारा सुरक्षा

1. Quincy Wright A study of war, II, P P 760, 766, 809, 860

2. Quincy Wright, cited by I L Claude in Power and International Relations, P 86

3. I L Claude, Power and International Relations, P 94

के लिए बिदे गये सामूहिक प्रयत्नों से सम्बन्धित है। इसे परिभाषित करते हुए जान स्वर्ज़ेन बर्गर (John Schwarzen Berger) ने इसे एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रमण को रोकने या प्रतिजिया करने के लिए किए गये सम्मिलित कार्यों की मशीनरी कहा है। समय-समय पर साम्राज्यवादी महात्वाकांक्षी एवं युद्धप्रिय देशों द्वारा विश्व-शान्ति को चुनौतियाँ दी जाती रहो हैं। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यह प्रयत्न करती है कि इस प्रकार की चुनौतियों का रोकने व सामना करने के लिए सभी देश सामूहिक रूप से कार्य करें। आज की बदली हुई परिस्थितियों में यह व्यवस्था अपरिहार्य बन गई है। कुछ विचारकों के मतानुसार सुरक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कहा जाता है कि सामूहिक सुरक्षा का विरोधी है असुरक्षा। राष्ट्रों द्वारा मिल कर किया गया प्रत्येक कार्य सामूहिक सुरक्षा नहीं माना जा सकता।

सामूहिक सुरक्षा की किसी भी व्यवस्था को प्रभावपूर्ण तथा लाभदायक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास पर्याप्त शक्ति हो ताकि वह आक्रमणकारी राज्य का मुकाबला कर सके। एकता में शक्ति होती है किन्तु राष्ट्रों की एकता सच्चे अर्थों में सभी मानी जायगी जबकि सभी राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रयोग सामूहिक लाभ के करने को तैयार रहे। शक्ति के अभाव में एकता केवल कागजी रह जायगी तथा सामूहिक सुरक्षा का कोई प्रभाव ही न रहेगा। आवश्यकतानुसार एकता का विरोध करने से पूर्व एक आक्रमणकारी राज्य भली प्रकार सोच विचार लेगा। स्टैनले बाल्डविन (Stanley Baldwin) के मतानुसार सामूहिक सुरक्षा तब तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि इसमें भाग लेने वाले सभी राष्ट्र आवश्यकतानुसार आक्रमणकारी को प्रतिबन्धों की धमकी देने तथा लड़ने के लिए एक साथ तैयार न हो जायें। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में प्रत्येक देश को अपनी सम्पत्ति को सीमित करना पड़ता है।

2. व्यक्तिगत राष्ट्रीय सकल्प (National will) का सामूहिक निर्णय के लिए समर्पण (Submission) कर दिया जाता है। इसका सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में सैनिक शक्तियों तथा प्रमुख हथियारों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण रखना आवश्यक बन जाता है। सकट के समय सभी इकाइयाँ एकमत से सहयोगी बन कर कार्य कर तथा सभी या अधिक से अधिक बड़ी शक्तियाँ इसके सदस्य बन जायें। सामूहिक सुरक्षा केवल सन्धि मान नहीं है इसका लक्ष्य सिर्फ एक सामान्य-राष्ट्र या आक्रमणकारी की चुनौती का सामना करना ही नहीं करन इसके भी धागे यह इकाइयों के विकास को विधायी पक्ष द्वारा भी प्रभावित करती है।

सामूहिक सुरक्षा के विचार का विकास

(Development of the Collective Security Idea)

सामूहिक सुरक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में लाने व लोकप्रिय बनाने का ध्येय बहुत कुछ अमरीकन राष्ट्रपति वडरो विलसन (Woodrow Wilson) को दिया जाता है। किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता (Concept) का न तो वह आविष्कारक था और न सारी व्याख्याएँ व स्पष्टीकरण ही उसकी ओर से दिये गये थे। इस विचार का प्रारम्भ सत्रहवें शताब्दी की ओसनाब्रिक (Osnabrick) की सन्धि में पाया जाता है जिसके सत्रहवें अनुच्छेद में सम्भावित शत्रु के विरुद्ध सामूहिक कदम उठाने की बात कही गई है। विलियम पेन (William Penn) तथा विलियम पिट (William Pitt) ने भी इस पर अपने विचार रखे। १८१० में थियोडोर रूजवेल्ट (Theodore Roosevelt) ने बताया कि शान्तिप्रिय बड़ी शक्तियाँ एक शान्ति संधि (League of Peace) बना लें जिससे न केवल उनके बीच ही शान्ति रहे किन्तु किसी दूसरे राष्ट्र द्वारा उभे तोड़े जाने की भी यदि आवश्यकता हो तो शक्ति द्वारा भी रोका जा सके। अमेरिका में शान्ति स्थापना करने वाले संधि में अनेक बुद्धिशील तथा प्रमुख राजनीतिज्ञ शामिल थे। इसने विश्व सगठन का समर्थन दिया और कहा कि इस सगठन में अमेरिका की शक्तिपूर्ण साधनों से भी शान्ति स्थापित करने की सम्मिलित होना चाहिए। पेरिस में राष्ट्रसंघ के निर्माण के लिए जो समझौते किये गये उनमें सामूहिक सुरक्षा की मान्यता को नई व्यवस्था का आधार बना दिया गया। राष्ट्रसंघ आयोग की पाचवी बैठक में संधि के नियमों के सोलहवें अनुच्छेद को बिना अधिक वाद-विवाद के स्वीकार कर लिया गया। मिलर (Miller) ने लिखा है कि प्रतिबन्धों (Sanctions) के प्रमुख सिद्धान्तों को सर्वसम्मति से मान लिया गया, मूल प्रश्नों के बारे में भी कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। इन प्रकार सामूहिक सुरक्षा के विचार को व्यवहार में आने से पूर्व विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ा।

सामूहिक सुरक्षा और शक्ति सन्तुलन

(Collective Security and Balance of Power)

सामूहिक सुरक्षा को प्रायः शक्ति सन्तुलन का विकल्प माना जाता है।

सामूहिक सुरक्षा के व्यावहारिक रूप के जनक विलसन ने अपने विचारों का प्रतिपादन शक्ति सन्तुलन के विरोध में किया था। वे मानते थे कि शक्ति सन्तुलन में राष्ट्र प्रतियोगितापूर्ण सन्धियों में बद्ध हो जाता है तथा विवशकारी शक्ति (Coercion) का प्रयोग राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को तथा स्वायत्तपूर्ण

लक्ष्यों को पूरा करने के लिये किया जाता है जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में देशों के सहयोग का अर्थ होता है सभी की न्याय एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा जिसमें विवशकारी शक्ति का प्रयोग सामान्य शान्ति की स्थापना के लिए किया जाता है। क्लाड (I. L. Claude) ने लिखा है कि "विलसन से लेकर आज तक सामूहिक सुरक्षा के सभी समर्थक इसे शक्ति सन्तुलन से भिन्नता दिखाते हुए परिभाषित करते रहे हैं।"¹

विभिन्नताएँ

(The Differences)

शक्ति सन्तुलन एवं सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के बीच कुछ अन्तर है जो मुख्यतः निम्न प्रकार हैं :—

१. सामूहिक सुरक्षा एक सामान्य सन्धि (Universal alliance) है जो प्रतिযোগी संधियाँ (Competitive alliances) से भिन्न है, जिनको शक्ति सन्तुलन की विशेषता माना जाता है। कॉर्डेल हल (Cordell Hull) ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के बारे में लिखा है कि यह कुछ संगठित राष्ट्रों के विरुद्ध संधि नहीं है बरन् प्रत्येक आक्रमणकारी के विरुद्ध है। यह संधि युद्ध के लिए नहीं बरन् शक्ति के लिए है।² यह कथन दोनों मान्यताओं के मूल अन्तर को स्पष्ट करता है।

२. शक्ति सन्तुलन की मान्यता दो या दो से अधिक विरोधी गुटों की वृत्तना करके चलती है जो परस्पर सघर्षशील प्रकृति के हैं किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता 'एक विश्व' (One World) है जो सहयोग के आधार पर व्यवस्था का निर्माण करने के लिए संगठित होता है।

३. यद्यपि दोनों मान्यताएँ सघर्ष व सहयोग को अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के मूलतत्त्व मानती हैं तथा सघर्ष का मुकाबला करने के लिए सहयोग की सिफारिश करती हैं, किन्तु शक्ति सन्तुलन व्यवस्था के निर्माण के लिए सघर्षपूर्ण सहयोग चाहता है जबकि सामूहिक सुरक्षा सघर्ष को प्रतिवधित रखने के लिए सामान्य सहयोग पर बल देती है।

४. शक्ति सन्तुलन कुछ सीमित गुटबन्दी करके ही आक्रमणकारी का विरोध करता है तथा यह मानता है कि सघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सर्वकालीन विशेषता है किन्तु सामूहिक सुरक्षा सामान्य सहयोग के आधार पर आक्रमणकारी का मुकाबला करने को तैयार रहती है तथा यह मानती है कि आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का केवल अपवाद है, नियम नहीं।

1. I. L. Claude, Power and International 'Relations P 111.

2. The Memoirs of Cordell Hull, II, 1948

✓ ५. सामूहिक सुरक्षा यह मान कर चलती है कि किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी भी राष्ट्र पर कभी भी किया गया आक्रमण विद्व-शांति के लिये खतरा है और इसका विरोध करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को कटिबद्ध हो जाना चाहिये किन्तु शक्ति सतुलन की मान्यता इससे भिन्न है। इसमें एक राष्ट्र पर आक्रमण होने के समय दूसरी सहयोगी इकाइया उसका मुकाबला करने में तभी साथ देगी जबकि वह उनके हितों से मेल रखता हो। यदि एक राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उस आक्रमण से प्रभावित नहीं होता तो वह युद्ध में भाग लेने से विमुख हो सकता है।

६ इस प्रकार सतुलन व्यवस्था व्यवहारवादी (Pragmatic) है तथा एक राष्ट्र को आक्रमण का विरोध करने की केवल तभी सलाह देती है जब कि आक्रमण उसकी स्वयं की सुरक्षा के लिए घातक हो। किन्तु सामूहिक सुरक्षा की मान्यता में कुछ सैद्धांतिक पृष्ठ अधिक प्रभावशाली है क्योंकि यह राज्य को सदैव आक्रमण का विरोध करने को कहता है, कारण यह है कि उसका हित आक्रमण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

७. शक्ति सतुलन व्यवस्था बहुत अस्त-व्यस्त होती है। यह स्वायत्त, एवं स्वनिर्देशित अनेक राज्यों से मिलकर बनती है जिसमें थोड़े ही बड़े राज्य होते हैं किन्तु सामूहिक सुरक्षा में एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाता है तथा अन्तर्गोष्ट्रीय सम्बन्धों को एक सगठनात्मक रूप देने की कोशिश की जाती है।

विन्स्टी राइट के मतानुसार सामूहिक सुरक्षा व शक्ति सतुलन के बीच वही अन्तर है जो कि कला (Art) और प्रकृति (Nature) के बीच होता है।

समानताएँ

(The Similarities)

शक्ति सतुलन व सामूहिक सुरक्षा की मान्यताओं के बीच स्थित उक्त अन्तरो के अतिरिक्त कुछ समानताएँ भी हैं जो निम्न प्रकार से हैं—

१. कहा जाता है कि शक्ति सतुलन की योजना का आधार दूसरे पक्ष की आक्रमणकारी सामर्थ्य (Aggressive capacity) है जबकि सामूहिक सुरक्षा आक्रमणकारी नीति पर अधिक ध्यान देती है। यह आशङ्क सत्य है क्योंकि शक्ति सतुलन में दूसरे पक्ष की केवल आक्रमणकारी सामर्थ्य पर ही ध्यान नहीं दिया जाता बरन आक्रमणकारी नीति को भी देखा जाता है।

✓ २. दोनों मान्यताएँ प्रतिरोध (deterrence) के सिद्धांत की भूमि पर आधारित हैं। शक्ति संतुलन में अपने का इतना शक्तिशाली बनाया जाता है कि विरोधी मुंह न उठा सके, सामूहिक सुरक्षा में भी शक्ति का एकीकरण वर आश्रमणकारी की महत्ववशाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है।

३. शक्ति संतुलन का आधार तुल्यभारिता तथा सामूहिक सुरक्षा का आधार प्रबलता (Preponderance) माना जाता है किन्तु असल में तुल्यभारिता का रूप भी निश्चित नहीं है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था में भी कोई पक्ष किसी देश से यह नहीं कहता कि दूसरा पक्ष कमजोर है अतः संतुलन की स्थापना वह उसी के साथ मिल जाय। इस प्रकार दोनों मान्यताओं के बीच वास्तविक अन्तर बहुत कम है।

४. दोनों ही व्यवस्थाएँ 'शांति के लिए युद्ध' (War for Peace) में विश्वास रखते हैं तथा कहते हैं कि शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि लड़ने की इच्छा पैदा करने की सामर्थ्य का विकास किया जाय।

५. दोनों ही राज्यों के सामंजस्य सहयोग में विश्वास करते हैं यद्यपि आश्रमणकारी या शांति को चुनौती देने वाला राष्ट्र नहीं है।

६. दोनों मान्यताओं की समानता उन आधारभूत परिस्थितियों के आधार पर भी बताई जा सकती है जो कि दोनों ही व्यवस्थाओं के सफल व्यवहार के लिए आवश्यक मानी जाती है। उदाहरण के लिए दोनों में शक्ति का फैलाव (diffusion) इतना किया जाता है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र या पक्ष अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा न पहुँचा सके, दुनिया का दो गुटों में बंट जाना (bipolarity) दोनों ही मान्यताओं व सफल संचालन के लिए आवश्यक है, दोनों में लचीली नीति (Flexible policy) अपनाई जाती है ताकि आवश्यकतानुसार पुराने शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु की तरह देखा जा सके। प्रजातन्त्र के इस युग में दोनों ही मान्यताएँ लोकमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। दोनों की स्थापना प्रायः एक ही दुनिया में किया जाता है। विश्व के जिन परिवर्तनों ने शक्तिशाली संतुलन के मार्ग में बाधा डाली है वे सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सफल संचालन में भी बाधक हैं। एडवार्ड वी. गुलिक (Edward V. Gulick) के मतानुसार शक्ति संतुलन का विकास हुआ है। सश्रि (alliance), सम्मिलन (Coalition), तथा सामूहिक सुरक्षा (Collective security), इसके विकास प्रम के सोपान हैं। क्लॉड (I. L. Claude) का कहना है कि निष्कर्ष रूप में अनेक विचारकों ने यह माना है कि सामूहिक सुरक्षा को शक्ति

संतुलन का एक पन्विषित भस्करण मानना चाहिए न कि पूरी तरह से भिन्न और शक्ति संतुलन का विकल्प।¹ शक्ति संतुलन के सिद्धान्त की मान्यतायें सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त की पूरक हैं।

सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्रसंघ

(Collective Security and League of Nations)

सामूहिक सुरक्षा की मान्यता ने राष्ट्रसंघ के रूप में प्रथम बार सगठनात्मक रूप धारण किया। यही कारण है कि राष्ट्रसंघ को कभी कभी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त का सत्कारमक अभिव्यक्तिकरण भी कह दिया जाता है। राष्ट्रसंघ के निर्माताओं का यह विश्वास था कि वे दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध कुछ राष्ट्रों का एक संगठन बनाने नहीं जा रहे हैं, किन्तु सामान्य हित के लिए जितने सम्भव हो सके राष्ट्रों का, एक संघ बनाने जा रहे हैं। आर्थर लिंक (Arthur S Link) के मतानुसार² सभी उदारवादी यह चाहते थे कि संधियों का जाल, शक्ति संतुलन और मुक्त बूटीनीति की व्यवस्थाएँ, जिनके कारण युद्ध अपरिहार्य बन जाता है, समाप्त कर दी जानी चाहिए। पुराने तरीके के स्थान पर उन्होंने शक्ति के लिए शक्ति के मेल (Concert of power) का प्रस्ताव किया। अनेक सगठनात्मक एवं व्यावहारिक कारणों से राष्ट्रसंघ के अधीन सामूहिक सुरक्षा का सिद्धान्त सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाया। कई बड़ी शक्तियाँ इसका सदस्य न बनीं और जो इसके सदस्य थे वे सामूहिक सुरक्षा के कोई खास प्रतिपादन नहीं थे जिसे किसी राज्य के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के लिए चिन्तित थे कि सामूहिक सुरक्षा के लिए। मध्यक नियम के अनुच्छेद १६ के अधीन सदस्य राज्य सामूहिक सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने को संधि बद्ध थे किन्तु यह अनुच्छेद कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। पामर तथा परकिंस के शब्दों में संघ के सदस्यों द्वारा इसके अर्थों की एकपक्षीय व्याख्या की गयी तथा सिवाय बातें बनाने के और कुछ नहीं किया गया। फलतः अनुच्छेद की आत्मा उसमें पृथक् हो गई। अपने जन्म के प्रारम्भिक वर्षों में संघ द्वारा कुछ समस्याओं को सुलझाया गया। किन्तु बड़ी व महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करते समय बड़ी शक्तियों द्वारा इसके नियमों (Covenant) पर आघात किए गए। १९३१-३२ में मन्चूरिया के सक्च से लेकर हिटलर के आक्रमणों की शृंखला तक अर्थात् द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ तक प्रभावशाली सामूहिक सुरक्षा के अभाव में एक के बाद एक अन्तर्राष्ट्रीय हर्षता से पूर्ण काय होते रहे। संघ की असमर्थता एवं शक्तिहीनता

1. Claude, I L Power and International Relations, P. 132

2. Wilson the Diplomatist, P 92

१९३५-३६ के स्टाली के इयोपिया के आक्रमण के समय पूरी तरह जात हो गई थी। यह सामंजस्य उसकी परीक्षा का प्रतीक था जिसमें वह असफल हो गई।

राष्ट्रसंघ की असफलता का प्रमुख कारण इसके सदस्यों का असमंजसता पूर्ण दृष्टिकोण था। मार्च १९३६ में स्टालिन (Stalin) के कहा था कि आक्रमणकारी राज्य मुख्यतः इङ्ग्लैन्ड, फ्रांस तथा अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा की नीति को अनाक्रमणकारी का सामूहिक विरोध करने की नीति को त्याग दिया और असंलग्नता की तथा निरपेक्षता की नीति अपना ली। इस नीति का अर्थ था आक्रमणकारी को प्रोत्साहन देना, उसे स्वतन्त्रता देना और इस प्रकार युद्ध को विश्व-युद्ध बना देना। क्लाड (I. L. Claude), का विचार है कि जाने या अनजाने दुनियाँ के राज्यों ने सामूहिक सुरक्षा को मशौन राष्ट्र संघ के दोषों को कम करने की अपेक्षा और अधिक बढ़ाया। अन्तर्राष्ट्रीय सामुदाय की सामूहिक सुरक्षा के वे फल प्राप्त न हो सके जिनकी कल्पना की गई थी। सामूहिक सुरक्षा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की प्रकृति के कारण नहीं वरन् राष्ट्रीय नीतियों के कारण असफल हो गई।

सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ (Collective Security and U. N. O.)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ (League of Nations) के चोले को छोड़ कर सामूहिक सुरक्षा ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में पुनर्जन्म धारण किया। इस बाद सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की ओर विश्व के अधिकांश देश जागरूक थे। अत्युत्तम जैसे अनेक विकासों ने तृतीय विश्व युद्ध के परिणामों को स्पष्ट कर दिया था और कोई भी राष्ट्र मानव सभ्यता को मिटाने की अपेक्षा विश्व शान्ति की स्थापना में अधिक रुचि ले रहा था। विश्व की जनता भी अब जागरूक हो चुकी थी। जोसेफ बेच (Joseph Bech) के मतानुसार जनता अपने शामकी को माफ नहीं करती, यदि वे पुन पुरानी शक्ति सतुलन की नीति का अपना लेते। क्योंकि इस नीति द्वारा सदस्यों की दोड़ गुरु होती है जो कि दूसरे युद्ध पर जाकर ही रुकेगी। अनेक विचारकों का मत था कि सान फ्रांसिस्को में वे सामूहिक सुरक्षा की स्थापना के लिए खड़े हुए हैं। इसका अर्थ है विश्व संगठन ताकत द्वारा भी शान्ति की स्थापना कर सनता है और करेगा। चाटेंर के वारे में बोलते हुए जनरल स्मट्स (Jan C Smuts) ने कहा था कि आक्रमणकारी के विरुद्ध शान्ति-प्रिय देश के संगठित मंच के लिए, बड़ी तथा छोटी शक्तियों के संगठित मंच के लिए यह दानों के साथ शान्ति प्रदान करती है। तथा यह शान्ति

की संगठित सेनाओं के लिए केन्द्रीय संगठन और निर्देशन प्रदान करती है। इस कथन का अर्थ यही है कि संयुक्त राष्ट्र संधि के रूप में जब सामूहिक सुरक्षा का अवतरण हुआ तो उसकी कई विशेषताएँ थीं। वह शान्तिप्रिय देशों का संगठन है, उसमें बड़ी ब छोटी दोनों ही शक्तियाँ हिस्सेदार हैं, यह शान्ति सेनाओं का एक केन्द्रीय संगठन है तथा यह ताकत (Teeth) से भी शान्ति स्थापित कर सकता है। महासचिव ट्रिग्वे लो (Trygve Lie) के शब्दों में संयुक्त राष्ट्रों की शान्ति की सड़क सशस्त्र आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा की मांग करती है। वह हमें प्राप्त करनी चाहिए और मेरा विश्वास है कि हम प्राप्त करके रहेंगे। शान्ति के लिए एकीकरण की योजना (Uniting for peace plan) पर बोलते हुए कनाडा के प्रतिनिधि ने कहा था कि हम सामूहिक सुरक्षा को संगठित करने की दिशा में एक नया कदम उठा रहे हैं जो कि हमारा लक्ष्य (Goal) है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के जन्म के बाद उसकी परीक्षा की घड़ी प्रथम बार १९५० में आई जबकि सारे विश्व की आँखें कोरिया के युद्ध पर जमी हुई थीं। यह एक अवसर था जबकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया जा सकता था। दक्षिण कोरिया पर साम्यवादी आक्रमण के समय संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कृत एवं प्रभावित सामूहिक सैनिक कदम उठाया गया, औपचारिक रूप से यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रेरित था और संगठन के धर्मतः द्वारा या निष्क्रिय रूप से समर्थित भी था। संयुक्त राष्ट्रसंघ के झंडे के नीचे किया गया संगठित कार्य-व्यवहार में सामूहिक सुरक्षा के प्रयास का पूर्ण चित्रण है। कई विचारकों के मन से यह कदम उस सकल्प का क्रियान्वित रूप था जो कि सान फ्रांसिस्को में लिया गया था। दूसरी ओर कुछ विचारकों का मत यह भी है कि कोरिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्य था उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया था। इन अनुभवों के आधार पर पामर तथा पर्किन्स (Palmer and Perkins) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि "संयुक्त राष्ट्रसंघ अपनी प्रकृति के कारण वास्तविक सामूहिक सुरक्षा का प्रभावशाली साधन न तो कभी था, न है और न भविष्य में ही कभी हो सकता है।" वॉल्फर्स (Wolffers) का भी कुछ ऐसा ही मत है। वे यह मानते हैं कि कोरिया में सामूहिक सुरक्षा का सही रूप नहीं निखर पाया था। यहाँ सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार होना तो यह चाहिए था कि आक्रमणकारी को सजा देने या प्रतिरोध करने के लिए किसी भी आक्रमणकारी के विरुद्ध बली भी लड़ा जाता, किन्तु इसके स्थान पर सामूहिक सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल

अमरीका के प्रबल शत्रु के विरुद्ध किया गया था। इन दोनों विचारकों के बीच का विचार अमरीका के तत्कालीन राज्य सचिव (Secretary of State) एचेसन (Acheson) का था जो यह मानते थे कि कोरिया की समस्या को हमें सामूहिक सुरक्षा का अन्तिम धर्म युद्ध (Final Crusade) नहीं मान लेना चाहिए। वैसे कोरिया (Korea) के युद्ध ने भी संयुक्त राष्ट्रसंघ का कुछ अनुभव प्रदान किए तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। यह इसी अनुभव का परिणाम था कि महासभा द्वारा शान्ति के लिए एकीकरण का प्रस्ताव (Uniting for peace) पास किया गया था। संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उठाये गये इस प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अधिक शक्तिशाली बनाया गया। उरुग्वे (Uruguay) के प्रतिनिधि का मत था कि कोरिया के अनुभव से हम काफी लाभान्वित हुए हैं तथा इसके व्यवहार को एक व्यावहारिक, यथार्थवादी और विश्वव्यापी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का निर्माण करने के लिए काम में लाया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संगठन सुरक्षा परिषद (Security Council) में निषेधाधिकार (Veto) की व्यवस्था को सामूहिक सुरक्षा के विरुद्ध तथा उसका एक करक माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब तक यह व्यवस्था है तब तक संयुक्त राष्ट्रसंघ किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध कोई कदम उठाने में असमर्थ बन जायगा। यह केवल छोटी शक्तियों के विरुद्ध ही कार्यवाही कर पायेगा। किन्तु सत्य तो यह है कि शक्तिशाली राष्ट्र ही शायद आक्रमणकारी होता है और ऐसे आक्रमण के विरुद्ध कदम उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ अनुमति न देगा। कहा गया है कि निषेधाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ एक ऐसी व्यवस्था बन गया है जिसमें चूने को कुचला जा सकता है किन्तु धोरे को नहीं रोका जा सकता। निषेधाधिकार न सामान्य सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था का छिन्न-भिन्न कर दिया है। दूसरी ओर फॉक्स (T. R. Fox) जैमे भी विद्वान हैं जो यह मानते हैं कि इसमें छोटे राष्ट्रों को यह आश्वासन प्राप्त हो जाता है कि इसके कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ बड़ी शक्तियों के गुट के किसी दूसरी बड़ी शक्ति के विरुद्ध युद्ध का समर्थन न करेगी। भारत का भी इस सम्बन्ध में कुछ ऐसा ही विचार है।

सामूहिक सुरक्षा और क्षेत्रीय संधियाँ

(Collective Security and Regional Alliances)

विश्व का दो गुटों में बंट जाना सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के भाग्य-चक्र राह का समान सिद्ध हुआ। शीत युद्ध के दाँव पचाँ तथा घरे बंदी के

परिणामस्वरूप साम्प्रदायी और पूँजीवादी गुटों द्वारा सन्धि-संगठनों का निर्माण किया जाने लगा। विचारकों के एक पक्ष की यह मान्यता रही और आज भी है कि इन क्षेत्रीय संगठनों के आधार पर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुलभ तथा लोकप्रिय बनाया जा सकता है तो दूसरे पक्ष वालों का मत है इन सन्धियों का आधार गुट-बन्दी होता है और इन्हें कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये शान्ति और सुरक्षा को नहीं बरन् युद्ध की प्रेरित को प्रोत्साहित करते हैं। इनके विचार में क्षेत्रीय सन्धियों अथवा प्रादेशिक संगठनों और समझौतों से आम खाने की कल्पना करना आकाश कुसुम की भांति निराधार और मृग-मरोचिका की भांति भ्रामक है।

क्षेत्रीय सन्धियों को चाहे अनेक राजनीतिज्ञों और शान्तिवादियों ने अनुचित बताया, लेकिन इनका विकास होता ही गया। द्वितीय महायुद्ध के मध्य-वर्ती काल में क्षेत्रीय संगठनों और समझौतों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया। बहुत कुछ इन्हीं के कारण राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में असफल हुआ और वह उन राज्यों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका जिन्होंने आक्रान्ता रूप धारण किया।

जब द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तो उसके चार्टर में भी प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय संगठनों और समझौतों सम्बन्धी उपबन्ध रखे गये। वस्तुतः अधिकांश अमेरिकन और पश्चिमी राजनीतिज्ञों तथा संन्य-विचारकों के लिए यह चिन्ता का विषय था कि 'रूसी दानव' यूरोप में लोह आवरण' (Iron curtain) के पूर्व में उद्दण्डतापूर्वक विचर रहा था और उसका प्रभाव सारे यूरोप पर पड़ रहा था। पामर और परकिन्स ने लिखा है—“यह तो अटकल लगाने की बात थी कि रूसी सेनायें कुछ ही दिनों, सप्ताहों अथवा महिनों में इंगलिश चैनल तथा अटलान्टिक सागर तक पहुँच सकती हैं अथवा नहीं, परन्तु यह निश्चित था कि 'पूर्व' (अर्थात् रूस) की ओर से हवाई आक्रमण के मार्ग में कोई भौगोलिक अथवा मैतिक बाधाएँ नहीं थी।”

चूँकि राजनीतिज्ञों का बहुमत और अधिकांश राजन यह नहीं चाहते थे कि आक्रमण के समय संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के ५ स्थायी सदस्यों के हाथ में ही कार्यवाही करने का अधिकार रहे, अतः उन्होंने अपनी भावी सुरक्षा के लिए प्रादेशिक-अथवा-क्षेत्रीय-संगठनों को बनाने के सिद्धान्त का समर्थन किया और इसी बात को सामने रखते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर में संयुक्त व्यवस्था की।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर की व्यवसायश्री में यही घोषणा की गई कि क्षेत्रीय संगठन और समझौते विश्व संगठन के उद्देश्यों का परित्याग न कर रहे हूँ संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होंगे, परन्तु विश्व की महा शक्तियों ने इस आइ.एम.ओ. अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों का खेल खोला। परिणामतः विगत १५-२० वर्षों में क्षेत्रीय सन्धियों और संगठनों की बाढ़ सी आ चुकी है जिनसे विश्व शान्ति और सामूहिक सुरक्षा की समस्या सुलझाने के स्थान पर उलझ रही है। इन संगठनों और समझौतों ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को उत्पन्न किया है, तनाव को बढ़ाया है और संयुक्त राष्ट्रसंघ के महत्व को घटाया है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक संगठन और समझौते (Regional Alliances) ये हैं—ब्रूसेल्स सन्धि संगठन, नाटो, वारसा पैक्ट, केन्द्रीय सन्धि संगठन (सेंटो), दक्षिण-पूर्वी-एशिया-सन्धि संगठन (सीटो) आदि। यथायन्त क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक सन्धियों और संगठनों का क्रम सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की अपेक्षा शक्ति-संतुलन की मान्यता के अधिक निकट है।

एक मूल्यांकन
(An evaluation)

आलोचना

सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की, एकता में ही शक्ति है, सारे विश्व का हित एक है, विश्व युद्ध मनुष्य सभ्यता की अतीत की गाथा बना देगा आदि। कुछ मान्यताओं को आधार बनाकर आगे बढ़ाया जाना है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वह किसी भी रूप तथा आकार में हो, तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक कि उसे नियन्त्रित करने के लिए पर्याप्त शक्ति उपलब्ध न की जा सके। शक्ति के बिना किसी भी दमनकारी आक्रमण को कुचला नहीं जा सकता। सामूहिक सुरक्षा की विश्वासवारी शक्ति के रूप के सैद्धांतिक दृष्टि से तीन विकल्प हो सकते हैं—

✓ (१) सदस्य राज्यों द्वारा सहयोग का वचन दिया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सैनिक शक्तियों को प्रयुक्त करने का वायदा भी लिया जा सकता है।

(२) राज्य अपनी सेना के कुछ भाग अन्तर्राष्ट्रीय सन्स्था के पास छोड़ देंगे ताकि वह सामूहिक सुरक्षा के लिए उनकी आवश्यकता पड़ने पर काम में ला सकें।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय सन्घ अपनी स्वयं की सेना का अलग से निर्माण करे तथा यह सेना सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का संचालन करे।

राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम विकल्प को अपनाया गया था, राष्ट्रसंघ में किस विकल्प को अनायास जाय इस सम्बन्ध में बहुत समय तक भारी वाद-

विवाद रहा। अन्त में कुछ देशों की पूरी सहमति न रहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध की जड़ें लगाई गईं। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की आज की परिस्थितियों में अव्यावहारिक, असम्भव तथा निष्फल माना जाता है। इस विचार की मान्यता वाले लोग अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रदान करते हैं—

(१) आक्रमणकारी जब आक्रमण करता है तो पूरी तैयारी और सोच विचार का प्रयत्न करता है और जिस देश पर आक्रमण किया जाता है उसकी प्रतिक्रिया भी तत्काल ही होती है—यह तो पूरी सैनिक तैयारी की प्राप्ति, सशस्त्र-कायान्वित बजट प्राप्त किया जायगा तथा परिस्थिति के अनुकूल जो भी आवश्यक होगा किया जायगा किन्तु सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की इनाइमों की पूरी तरह यह पता नहीं रहता कि कहा, किसके विरुद्ध, कब, किसके साथ मिलकर सैनिक कार्रवाही करनी चाहिए और इसी कारण तत्कालीन सम्मिलित युद्ध बंठित हो जाता है। फलतः सामूहिक सुरक्षा समुदाय की सैनिक शक्ति उसके निचो भाग से सर्वत्र कम होगी।

(२) सन् १९४५ ई० के बाद सैनिक तकनीकी में भारी परिवर्तन आ गया है। वैज्ञानिक विकास के कारण आज के युद्ध ऐसे बन चुके हैं कि आक्रमणकारी के विरुद्ध बंदम संहार के लिए विचार करने की सामूहिक सुरक्षा प्रवृत्ति करे तब तक आक्रमणकारी के द्वारा देश को नष्ट भी किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रत्येक राष्ट्र यह जानता है कि वह अपने जीवन और मरण का प्रश्न सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं छोड़ सकता इनका उसे स्वयं ही प्रबंध करना होगा।

(३) विश्व का दो छुट्टों में बंट जाना (Bipolarity) भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के विपरीत प्रवृत्ति है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यह मानती है कि उसके प्रतिद्वन्द्वी का प्रभाव प्रत्येक देश पर पड़ेगा और कोई भी देश आक्रमण करने का साहस न कर सकेगा। किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद इस व अमरीका की नई शक्ति का उदय ऐसा हुआ जिस पर सामूहिक सुरक्षा के प्रतिद्वन्द्वी का कोई प्रभाव होने जाने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त दो छुट्टों की व्यवस्था में यह भी एक बारा होती है कि आक्रमणकारी राज्य किसी भी एक छुट्टी का सदस्य या नेता होते हैं और इस कारण उन छुट्टी के दूसरे राज्य सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं होने देते।

(४) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि आक्रमणकारी तथा जिन पर आक्रमण किया गया है उस देश को सन्तुष्ट करने से प्रोत्साहित कर दिया जाये क्योंकि बिना इसके कोई बंदम नहीं उभरता या

सकता है। भारत-पाक संघर्ष के समय भारत द्वारा बराबर यह भाग बी जाती रही कि वह पाकिस्तान को आश्रय घोषित करे किन्तु ऐसा न किया गया क्योंकि यह घोषणा जितनी सरल दिखती है उतनी नहीं है, इसमें अनेक राष्ट्रों के हित टकराने हैं। इसी कारण वे किसी भी राष्ट्र को आश्रमणकारी घोषित करने से कतराते हैं। आश्रमण की परिभाषा एवं अर्थ भी अनेक लगाये जाते हैं। इस कारण यह बड़ा कठिन है कि पहले तो यह पता लगाया जाये कि गोया यह कार्य आश्रमण है या नहीं, यदि है भी तो आश्रमणकारी कौन है ?

(५) सामूहिक सुरक्षा की सफलता की विषयगत परिस्थितियाँ बढ़ने की अपेक्षा धीरे-धीरे घटती ही जा रही हैं। जिस समय इस सिद्धांत को अपनाया जा सकता था उस समय राजनीतिज्ञों का ध्यान इसकी तरफ न था अब वे इसे त्रियान्वित करना चाहते हैं किन्तु बाह्य परिस्थितियाँ ऐसा नहीं होने देती। विषयगत आवश्यकताओं (Subject requirements) को देखकर ऐसा लगता है कि यह सिद्धांत अरिपक्व है क्योंकि न तो राजनीतिज्ञ और न ही जनता इसकी पूर्ण आवश्यकताओं से परिचित है। आज के युग में ऐसे समुदाय का विकास हो गया है जो अपने अपने राष्ट्रीय हित के प्रति पूरी तरह जागरूक है और इसी कारण उसमें भिन्नता है। इस समय सामूहिक सुरक्षा की सफल त्रियान्विति यह मांग करती है कि ऐसे राजनीतिज्ञ हों जो नेतृत्व कर सकें और ऐसी जनता हो जो उसका अनुगमन कर सके। इस विचार का विकास किया जाय कि जो विश्व के लिये शुभ है वही राज्य के लिए भी शुभ है। राष्ट्रीय हित का विश्व शांति तथा व्यवस्था के साथ एक-त्प कर दिया जाय। क्लाड (Claude) महोदय का मत है कि "कार्यशील सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण आवश्यकताएँ प्राप्त होने से अभी बहुत दूर है और यह भी सदिग्ध है कि इस दिशा में कुछ अर्थपूर्ण विकास हो सकेगा।"

(६) जिस व्यक्ति के हाथों में विदेश नीति के संचालन का भार रहता है वह सदैव व्यवहार प्रधान नीति को अपनायेगा तथा प्रत्येक मामले को गौर से देखने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। वह केवल सिद्धांतों के पीछे न दौड़ेगा, कोई भी राजनीतिज्ञ यह पसंद न करेगा कि वह सामूहिक सुरक्षा जैसे किसी भी सिद्धांत की जंजीरो में अपने हाथों को जकड़ कर कुछ करने के लिए अपने आपको बाध्य बना ले। एक सफल राजनीतिज्ञ वही है जिसके सामने अनेक विकल्पों के द्वार खुले रहते हैं और परिस्थिति के अनुसार एक मार्ग को अपनाने में उनके सामने कोई बाधा नहीं आती। दूसरे शब्दों में आज

की दुनिया के लोग यह विश्वास नहीं करते कि सामूहिक सुरक्षा के साधन को अपनाकर विश्व व्यवस्था (World order) या राष्ट्रीय हित को प्राप्त किया जा सकता है।

(७) सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आलोचना मार्गेन्यो आदि विचारकों द्वारा की गई है। ये विचारक यह मानते हैं कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत युद्ध का क्षेत्र सीमित या स्थानीय न रहकर विश्व-व्यापी बन जाता है। जिस युद्ध के परिणामों को एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित किया जा सकता था वे विश्व को विध्वंस की आय से झुलस देते हैं। एक देश यदि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अधीन भी आत्मरक्षणकारी के विरुद्ध प्रभावित देश का साथ दे रहा है तो भी यह समझा जायगा कि ऐसा वह अपने स्वार्थ को साधने के लिए कर रहा है। ससार में ऐसा सन्ध्यासी राष्ट्र देखने को नहीं मिलता जो बदनामी और आलोचनाएँ सहकर भी परोपकार तथा न्याय की स्थापना में रत रहे। दूसरी ओर कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि विश्व में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए बजाय सैद्धांतिक के व्यावहारिक नीति की आवश्यकता होती है। क्लॉड (Claude) महाशय का निष्कर्ष है कि सामूहिक सुरक्षा शक्ति की ओर से अप्रयार्थ नहीं है वरन् यह नीति की ओर से अप्रयार्थ है।

शान्तिपूर्ण समझौते

(Peaceful Settlements of International Disputes)

ताशकन्द बार्ता के लिए मास्को खाना होने से कुछ दिन पहले प्रधान मन्त्री शास्त्री ने एक आम सभा में कहा था कि "कोई भी देश हमेशा युद्ध करता हुआ नहीं रह सकता। युद्ध को एक न एक दिन बन्द होना ही पड़ता है। युद्ध ने द्वारा किसी भी समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता, हाँ इसके नई समस्याओं का निर्माण जरूर किया जा सकता है।" युद्ध को अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने का एक साधन बनाना कितना विघ्नसक तथा खतरनाक है इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी कई राष्ट्र युद्ध के मार्ग पर चलते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। युद्ध का मार्ग एक राष्ट्र केवल तभी अपनाता है जबकि शान्तिपूर्ण साधनों से समस्या का हल उसके पक्ष में होता हुआ नहीं दीखता है। दूसरे, यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपनी अत्याधिक माँगों को स्वीकार कराना चाहता है तो उसे आवश्यक रूप से युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। तीसरे युद्ध एक राष्ट्र की आन्तरिक कमजोरी का द्योतक है। कोई भी देश जो आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य दृष्टियों से सम्पन्न है वह नहीं चाहेगा कि युद्ध का रास्ता अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा व सम्पन्नता पर दाग

लगाया जाय। उनके पास शान्तिपूर्ण बूनीनिन साधन इतने प्रबल होते हैं कि युद्ध के बिना भी वह समस्या का समाधान कर सकता है।

सानुहित सुरक्षा व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय झगडों के शान्तिपूर्ण निपटारे के बीच काफी सम्बन्ध है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में समस्या को सुनज्ञान के माधन के रूप में युद्ध या शान का सहारा तभी दिया जाता है जबकि दूसरे अन्य साधन अमकर हो जाय। प्रारम्भ में तो यह प्रयास किया जाता है कि आक्रमण से प्रभावित राष्ट्र तथा आश्रयण करने वाले राष्ट्र के बीच समझौते, शान्ति वार्ता एवं अन्य मित्रतापूर्ण साधनों से मेज करा दिया जाए किन्तु ऐसा सम्भव न हो सके तब अन्त में मजबूर होकर शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। शान्तिपूर्ण समझौते की सम्भावना तथा उनकी सफलता की सम्भावना केवल तभी रहती है जब दोनों पक्षों के बीच तुल्यभारता (Equilibrium) या शक्ति समुत्तन की स्थिति वर्तमान हो। जैसे सन्धियों जैसे शान्तिपूर्ण साधनों से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का प्रयास बहुत समय से ही प्रचलित है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि शान्तिपूर्ण साधनों का प्रयोग केवल छोटे-मोटे झगडों के निपटारे के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है जो दो देशों के बीच स्थित मनमुटाव की भावना के परिणाम स्वरूप पेश होते हैं किन्तु इसके द्वारा मनमुटाव को निर्मूल नहीं किया जा सकता। इलाइसर (Schleicher) महोदय के दावा में अन्तर्राष्ट्रीय समाज में शान्तिपूर्ण समझौते का अर्थ राज्यों के बीच भेदों को मिटाने के दक्षिण के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य सभी साधन आ जाते हैं।¹ शक्ति का महत्व शान्तिपूर्ण समझौतों की सफलता के लिए भी आवश्यक है क्योंकि जेने कीर्ष भौ न्यायालय का निर्णय तब तक प्रभावशील नहीं हो सकता जब तक कि पुलिस शक्ति उस निर्णय को न्यायान्वित कराने में सक्षम सहयोग न दे। उन्ही प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन देशों के शब्दों का प्रभाव अधिक होता है जो नि शक्तिशाली हैं तथा निर्णय का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र का, जिनसे कुछ सतरा हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय झगडों के शान्तिपूर्ण निपटारे की दिशा में अब तक पर्याप्त विकास हो चुके हैं, उदाहरण के लिए सन् १८६६ की हेग कन्वेंशन, राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थाई न्यायालय सन् १९२४ का जेनवा सन्धि लेख तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर आदि का नाम लिया जा सकता है।

शान्तिपूर्ण समझौते की दो श्रेणियाँ

(The Categories of Pacific Settlement)

शान्तिपूर्ण समझौतों को मुख्य रूप से दो भागों में बाटा जा सकता है—निर्णायक (Decisional) तथा गैर-निर्णायक (Non decisional)। गैर-निर्णायक शान्ति समझौता उनको माना जाता है जो ऐसा कोई सुझाव नहीं देता जिस अन्तिम रूप में दोनों ही पक्ष मानने को मजबूर हों। ऐसे समझौतों में बातचीत (Negotiation), अनुरजन (Conciliation) आदि साधनों द्वारा बिना निष्कर्षों अथवा निर्णयों पर पहुँचा जाता है उनको मानने या न मानने के लिए दोनों ही पक्ष स्वतन्त्र रहते हैं। निर्णायक (Decisional) समझौते वे होते हैं जिनके निर्णयों का पालन करने के लिए दोनों ही पक्ष बाध्य रहते हैं। पचायत (Arbitration) तथा न्यायीकरण (Adjudication) आदि साधनों द्वारा इस प्रकार के समझौतों तक पहुँचा जाता है। यह व्यवस्था है कि दोनों ही पक्षों को यह स्वतन्त्रता रहती है कि वे अपने झगड़ों को इन व्यवस्थाओं के सुपुर्द करें या न करें किन्तु सुपुर्द करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि वे उस पचायत अथवा न्यायीकरण के निर्णयों को मानें। कुछ विचारकों के मत में उत्तमसवी तथा बीसवी सताब्दी में यह भाग बढो है कि राजनैतिक तथा कानूनी मामलों को निर्णायक प्रक्रियाओं के सुपुर्द किया जाये। किन्तु समस्या यह है कि राजनैतिक या वैधानिक झगड़े क्या होते हैं तथा इनको सुझाने के लिए अपनाये गये तरीकों, न्यायीकरण या पचायत व्यवस्था का रूप कैसा होना चाहिए।

शान्तिपूर्ण समझौतों के साधन

(Methods of Peaceful Settlements)

मदकत राष्ट्र संधि के चार्टर में शान्तिपूर्ण समझौतों के विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है, जैसे—बातचीत (Negotiation), पूछताछ (Enquiry), मध्यस्थता (Mediation), अनुरजन (Conciliation), तथा क्षेत्रीय अभिकरण आदि (अनुच्छेद-३३)

पामर तथा परकिन्स ने उक्त सभी साधनों को दो मुख्य श्रेणियों में बाटा है। पहली श्रेणी में वे भी राष्ट्र आते हैं जो कि बिना शक्ति का सहारा लिए ही प्रोत्साहन पर आधारित रहते हैं। इसमें बातचीत, अन्धे पद, पूछताछ, मध्यस्थता तथा अनुरजन आदि आते हैं। दूसरी श्रेणी में वे सभी साधन आते हैं जिन्हें मानने के लिए दोनों ही पक्ष मजबूर रहते हैं। इस प्रसङ्ग में इन साधनों की थोड़ी जानकारी करना उपयोगी रहेगा।

(१) यातचीत (Negotiation)—छोटे-मोटे मनुमटावों से उत्पन्न होने वाले झगड़ों को प्रायः बातचीत द्वारा सुलझाने की परम्परा है। इसके अन्तर्गत जिन देशों के बीच झगड़े होते हैं उनके कूटनीतिज्ञ आरस में बातचीत करके झगड़े के रूप, कारण, समाधान आदि पर भी भलीप्रकार से विचार-विमर्श कर लेते हैं। इस प्रकार की बातचीत उन देशों के प्रमुखों अथवा विदेश मन्त्रियों के बीच की जा सकती है। बातचीत करने का अवसर सयुक्त राष्ट्रसंघ में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में तथा प्रादेशिक व्यवस्थाओं आदि में प्रदान किया जाता है।

(२) अच्छे पद तथा मध्यस्थता (Good Officer and Mediation)—अनेक बड़े राज्य कभी-कभी दो राज्यों के बीच के झगड़े को दूर करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ४ जनवरी १९६६ से ताशकन्द में प्रारम्भ, शास्त्री-अयूब शांति-वार्ता को लिया जा सकता है। सोवियत रूस जैसे एक शक्तिशाली देश ने एशिया महाद्वीप में शांति की स्थापना में भारत एवं पाकिस्तान में सुलह कराने का जो प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है तथा यह उसके अच्छे पद का सदुपयोग है। कभी-कभी प्रतिष्ठित राष्ट्र को मध्यस्थता करने का काम भी सौंपा जा सकता है। मध्यस्थता करते समय यह आवश्यक है कि दोनों ही पक्षों का उसमें विश्वास हो तथा किसी भी ओर से उसके पक्षपाती होने की आशंका न की जाय। अच्छे पद का झगड़े के निपटारे में प्रयोग करते समय एक राष्ट्र मित्र की हैसियत से कार्य करता है तथा सुझाव देता है किन्तु मध्यस्थता करने समय यह एक न्यायाधीश बन जाता है तथा उसके निर्णयों को दोनों ही पक्षों द्वारा मानने की आशा की जाती है। १९०५ में राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने जापान और रूस के बीच युद्ध को रोकने के लिए अपने अच्छे पद का प्रयोग किया तथा एक मध्यस्थ के रूप में भी कार्य किया।

(३) पूछताछ और अनुरंजन (Enquiry and Conciliation)—प्रथम हेग सम्मेलन में पूछताछ के आयोग के ऊपर अधिक बल दिया गया था। द्वितीय सम्मेलन में भी इसकी आवश्यकता व महत्व पर विचार विमर्श किया गया था। इस कमीशन को यह काम सौंपा गया कि वह उन-तस्वों की जाँच करे जो कि सधर्मे के आधार हैं। कमीशन की सिफारिशों को मानने के लिए दोनों ही पक्ष मजबूर नहीं किये जा सकते। राष्ट्रसंघ (League of Nations) ने १९३१ से लिटन आयोग (Lytton Commission) का निर्माण किया था। अनुरंजन (Conciliation) में तीसरे देश द्वारा समझौता कराने का भरसक प्रयास किया जाता है। इसके लिए यह पूछताछ (Enquiry) का साधन भी अपनाता है। मध्यस्थता प्रायः व्यक्ति द्वारा की जाती है जबकि

अनुरजन करने वाले कमेटी, कमीशन या कौन्सिल हुआ करते हैं। पेल्लेस्टाइन की समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्रमण्डल द्वारा कमीशन की नियुक्ति की गई थी।

(४) पच फंसले और न्याय व्यवस्था (Arbitration and Judicial Settlement)—पचायत और अनुरजन में भेद दिखते हुए प्रायः यह कहा जाता है कि पचायत व्यवस्था एक कानून से पूर्ण न्याय है, यह फंसला करती है तथा इसका फैसला मानने के लिए दोनों ही पक्ष बाध्य होते हैं किन्तु दूसरी ओर अनुरजन में समझौते की सिफारिशें होती हैं तथा उनका प्रभाव एक मित्र की राय से अधिक नहीं होता जिसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। पच फंसलों का प्रचलन उन्नीसवीं शताब्दी में काफी था। इस काल में किया गया बलबामा का समझौता जिसमें ग्रेट ब्रिटेन को पच बनाया गया था, उल्लेखनीय है। १८६६ के हेग सम्मेलन में संधियों को कानून द्वारा तय करने के लिए पचायत के स्थायी न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। १९२२ में अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय की प्रतिष्ठापना की गई।

क्षेत्रीय व्यवस्था और शान्तिपूर्ण निपटारे

(Regional Arrangements and Pacific Settlements)

प्रादेशिक व्यवस्थाओं द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को दूर करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्रमण्डल द्वारा समर्थित है। उसके चार्टर में यह कहा गया है कि झगड़ों को किसी भी शान्तिपूर्ण तरीके से तय किया जाना चाहिए। यह कहा गया है कि जो देश ऐसे समझौते में सम्मिलित हो रहे हैं उनको सुरक्षा परिषद् के सम्मुख लाने से पूर्व प्रत्येक झगड़ा इन्हीं के द्वारा तय करने का प्रयत्न करना चाहिए। अमेरिकन राज्य के संगठन (Organisation of American States) को इस प्रकार की प्रादेशिक व्यवस्थाओं का उदाहरण माना जा सकता है।

संयुक्तराष्ट्र मण्डल में सुरक्षा परिषद् तथा महासभा के द्वारा शान्तिपूर्ण समझौतों की ओर अनेक सफल कदम उठाये गये हैं। सामूहिक सुरक्षा तथा झगड़ों के शान्तिपूर्ण निपटारे परस्पर सम्बन्धित हैं। पहले की विनाश-कर्म की जगहों सीढ़ी माना जाता है, जबकि दूसरा प्रयत्न सीढ़ी कहा जायगा। कुछ विचारक इन दोनों के सम्बन्ध के बारे में पूर्णतः भिन्न विचार रखते हैं। उनके मतानुसार न केवल ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी व पूरक नहीं हैं बल्कि विरुद्ध भी हैं। किन्तु यह तो एक तथ्य है कि दोनों का प्रयोग युद्ध को रोकने के लिए किया जाता है तथा दोनों साधनों के समर्थक एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ शान्ति का साम्राज्य हो, युद्ध और झगड़े न हों।

तथा परस्पर सहयोग और मेल के आधार पर अपने देश का विकास करने के लिए प्रत्येक राजनीतिज्ञ प्रयत्नशील हो। शान्तिपूर्ण समझौतों का अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार माना जाता है। इस समय विश्व में अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो वस्तु स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, वे अधिकारी एवं कर्त्तव्यों का रूप बदलना चाहते हैं। इसके लिए उनको शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ता है क्योंकि उनका काम का विरोध उन देशों द्वारा किया जाता है जो उस व्यवस्था को बनाये रखने के पक्ष में हैं। दोनों गुटों के बीच मनमुटाव से अनेक झगड़े तथा वाद विवाद पैदा होते हैं। इन झगड़ों को सामूहिक सुरक्षा तथा शान्तिपूर्ण समझौतों की व्यवस्था द्वारा दूर किया जा सकता है किन्तु मन-मुटाव तो तभी दूर हो सकेगा जबकि वर्तमान विश्व-व्यवस्था में परिवर्तन का कोई शान्तिपूर्ण साधन हाथ लग जाय। परिवर्तन तो अपरिहार्य है, वह होकर रहेगा। हमारे सामने दो विकल्प हैं कि इसके लिए हम शान्तिपूर्ण साधन अपनाये या शक्तिपूर्ण तरीके। शक्ति को अपनाया नहीं जा सकता क्योंकि इसके परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। किन्तु शान्तिपूर्ण साधन जो भी हैं वे अपर्याप्त हैं अतः आवश्यकता है कि अधिक उपयुक्त साधनों की खोज की जाय। कुछ विचारकों के मन में ऐसा उपयुक्त साधन व्यवस्थापन का है किन्तु यह राष्ट्रीय सम्प्रभुता के प्रतिकूल पड़ता है। इस प्रकार विश्व के सामने दो रास्ते हैं—पहला तो सम्प्रभुतापूर्ण राष्ट्रीय राज्यों की ओर जाता है जहाँ की दिनचर्या में युद्धों का वाद्व्यवहार होगा और दूसरा रास्ता जाता है विश्व सरकार (World Govt) की ओर जहाँ पर शान्ति का प्रभुत्व रहेगा। इस प्रकार आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के लिए राष्ट्रों की शक्ति को दूषित होने से रोकना है, उससे दुर्दमय पर सीमाएँ लगानी हैं। किन्तु हमने देखा कि शक्ति सन्तुलन तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था यद्यपि इस क्षेत्र में प्रभावपूर्ण रही किन्तु वह पर्याप्त नहीं बनी जा सकती। उनके अपन दोष तथा अपूर्णताएँ हैं, इनको कम करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानून, विश्व सरकार एवं निःशस्त्रीकरण आदि दूसरे साधनों द्वारा इसकी सहायता करना उपयोगी रहेगा। इन सभी साधनों को मिल कर एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना करनी है जिसमें युद्ध को घेरे में डाल दिया जाय। विश्व के देशों को यदि युद्ध की आवश्यकता न रहे तो शान्ति का अखण्ड दीप जल सकता है।

राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ-II

(LIMITATIONS OF NATIONAL-POWER)

विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की भारी आवश्यकता रहती है जो शक्ति के प्रयोग को दूषित होने से बचा सके तथा राष्ट्रीय हित को अन्तर्राष्ट्रीय हित के साथ एकाकार कर सके। यथार्थवादी सिद्धान्त के समर्थकों का विचार है और यह बहुत कुछ सही भी है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रधान विशेषता शक्ति के लिए संघर्ष करना है। प्रत्येक राष्ट्र यह प्रयास करता रहता है कि यह विश्व की एक बड़ी शक्ति बन जाये। उसकी नीतियाँ भी इस प्रकार संचालित की जाती हैं कि यह यदि आवश्यकता हो तो दूसरे देश के मूल्य पर भी अपने हित की साजना कर ले। इस प्रकार की नीतियाँ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था एवं सहयोग तथा मित्रतापूर्ण व्यवहार के लिए एक अभिशाप होती हैं। इनके विरुद्ध ऐसी नवीन व्यवस्थाओं की रचना करनी होगी जो ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें सभी राष्ट्र अपनी शक्ति को इतना मर्यादित रख सकें कि दूसरे राष्ट्रों को उनसे किसी प्रकार का खतरा न रहे। दूसरे, यदि उक्त प्रकार की नीतियाँ अनेक रोक लगने पर भी उकसने से न सकें तो इनका प्रतिकार करना पड़ेगा।

शक्ति सन्तुलन तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था द्वारा गुटों को रोकने, उनको सोमित करने तथा राष्ट्रों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगपूर्ण सम्बन्धों का निर्माण करने का भूतकाल से ही प्रयास किया जा रहा है। अनेक विचारकों के मतानुसार शक्ति सन्तुलन और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ऐसे साधन हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को समय-समय पर बहुत

प्रभावित किया है किन्तु वर्तमानकाल के विभिन्न विकासों के कारण इन व्यवस्थाओं का व्यवहार धीरे धीरे कठिन तथा असम्भव होता जा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य-समाज अन्तर्राष्ट्रीय कानून, विश्व सरकार, और निःशस्त्रीकरण जैसे विभिन्न उपायों को राष्ट्रीय शक्ति पर सीमाय लगाने के लिए प्रयुक्त करता है। ये तीनों ही साधन कुछ आदर्शात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि इनकी पूरी तरह से प्राप्त न तो किया गया है और न किया जा सकता है। किन्तु इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना तथा इनकी ओर धोखा भी अग्रसर होना विश्व शान्ति के हित में है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून

(International Law)

कानून का शासन (Rule of Law) अस्तु के काल से ही मनुष्य को शासन से अछूट माना जाता रहा है। अवैयक्तिक एवं निःस्वायं होने के कारण कानून के आधार पर संचालित व्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्ति नहीं होती और आशा की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध नहीं होंगे। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का संचालन कानून द्वारा न किया जाय, उसका केवल एक ही विकल्प है और वह यह कि शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्धारण का प्रमुख तत्व बन जाएगी। जंगल का नियम, जिसके अनुसार बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, का बोल-बाला हो जामना जिसके परिणामस्वरूप जन-साधारण का जीवन तथा समूची मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। अनेक विद्वानों के विचारानुसार अगु-आयुधों के इस वर्तमान युग में कानून के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का निर्धारण करना परम आवश्यक बन गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ

(The Meaning of the International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्वरूप एवं प्रकृति के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपनी-अपनी सम्मतिया प्रकट की हैं। इन विषय के प्रधान विचारक ओपनहैम (Oppenheim) के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय कानून उन प्रचलित एवं परम्परावादी नियमों का नाम है जिनको सम्य राष्ट्रों द्वारा अपने आपसी व्यवहार में वैधानिक (legally) रूप से मान्य माना जाता है।" अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध विश्व के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता बरन् अप्रत्यक्ष रूप से होता है अर्थात् इनका सम्बन्ध केवल राज्यों से होता है। अन्तर्राष्ट्रीय

कानून कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो कि राज्यों के ऊपर हो और राज्यों को कुछ भी मानने के लिए बाध्य कर सके। किन्तु इसमें भिन्न इसका स्थान राज्यों के बीच में रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को हम राज्यों की आचार-संहिता (Code of conduct) भी कह सकते हैं जिसके आधार पर उनके परस्पर-सम्बन्धों का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि दूसरे राज्यों के अधिकार तथा स्वतंत्रताओं पर बाध आये बिना ही एक देश अपने हितों की पूर्ति कर सके। कुछ विद्वानों का मत इससे भिन्नता रखता है। उनका विचार है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय केवल राज्य ही नहीं है बल्कि व्यक्ति (Individuals) और वे समुदाय भी हैं जिनके पास राज्य की सभी विशेषतायें नहीं होती।¹ स्टोवेल (Ellery C Stowell) के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे नियम होते हैं जिनका सम्बन्ध समस्त विश्व के मानव सम्बन्धों से होता है तथा जो सामान्य रूप से समस्त मानव जाति द्वारा व्यवहृत किये जाते हैं तथा जो उन स्वतन्त्र समुदायों की सरकार के माध्यम से लागू किये जाते हैं जिनमें कि मानवता बटी हुई है।²

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सम्बन्ध व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। इसका अर्थ यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यक्ति की हैसियत से एक व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं रखता किन्तु जब वह व्यक्ति किसी पद विशेष को धोमिल कर रहा होता है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उससे सम्बन्ध रहता है—एक राज्य के सरकारी प्रतिनिधि के रूप में जब व्यक्ति द्वारा फूटनीतिक कार्यों में भाग लिया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुव्यवस्था नैतिकता एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि वह कुछ नियमों का पालन करे, कुछ कानूनों का आचरण करे। इस प्रकार के आचरण के लिये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हो भी सके है और नहीं भी। परम्परागत रूप से तो यदि किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माताओं ने कोई अवैध (Illegal) कार्य किया है तो उसके लिये पूरे देश को ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।

एक अमेरिकन न्यायाधीश फिलिप जेसप (Philip Jessup) जो १९६० में न्याय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of

1 See Hans Kelsen in Principles of International Law 1952.
Pp 96-188

2. Ellery C. Stowell, International Law, P. 10. fn.

कुछ राज्य उसे चाहे किसी भी कारण से मान्यता देते हैं तब यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था का अस्तित्व है। इन विचारकों के तर्क के अनुसार कानून का अधिकतर पालन इसलिए नहीं होता कि इसके पीछे शक्ति है बल्कि इसलिए होता है कि वह कानून है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति कानून का आदर और पालन करेगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे बाध्यकारी शक्ति अच्छे और बुरे का ज्ञान है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान कबूट तभी हो सकता है जबकि बड़ी शक्तियाँ कानून द्वारा स्थापित सीमाओं को स्वीकार करे तथा हर जगह के लोग इस प्रकार की व्यवस्था को मानने के लिए तैयार हों।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के महत्व के सम्बन्ध में ई. एन. वान क्लेफेन्स (E N Van Kleeffens) ने बताया है कि यह सभी राष्ट्रों के लिए लाभदायक है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक मात्र वस्तुगत एवं निष्पक्ष मापदण्ड माना जा सकता है। यह किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक ठोस आधार है। इसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाया जा सकता है तथा राजनीति चतुरता एवं अवसरवादिता का एक प्रभावशील आधार है। अन्तर्राष्ट्रीय आशावाद, विश्वास एवं सज्जनता प्रत्यक्ष रूप से एक देश की शक्ति एवं प्रगति में प्रभाव रखते हैं, इसलिए इनके निर्माता अन्तर्राष्ट्रीय कानून को महत्वपूर्ण बना देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बासदेवन्त (Basdevant) के कथनानुसार "एक राज्य जब विधायी अन्तर्राष्ट्रीय कानून के नियम का पालन करने की स्थिति में होता है तो वह अपने को विशेष रूप से शक्ति सम्पन्न अनुभव करता है।"

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून का महत्व एवं प्रभाव बढ़ रहा है। विचारकों का मत है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर इस बात की अवहेलना करता है कि लागे चल कर विश्व व्यवस्था व्यक्तियों पर नहीं बल्कि कानून पर आधारित रहेगी जिनमें कि न्याय और नैतिकता के सिद्धान्त अन्तर्निहित रहते हैं। यह तथ्य संयुक्त राष्ट्रसंघ की अपर्याप्तता का एक आधार है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को मानने के बाद एक देश की शक्ति इसलिए अधिक हो जाती है कि प्रत्येक देश ऐसा करने में नैतिक दायित्व का अनुभव करता है जैसे व्यक्तिगत जीवन का यह एक कानून है कि किसी व्यक्ति पर आक्रमण न किया जाए और उसकी सति अथवा बेइज्जती न की जाए, इस कानून का सभी के द्वारा आदर किया जाएगा और जो इसका उल्लंघन करेंगे उनको गलत समझा जाएगा। कोई भी कानून एक सम्य एवं

विचारशील व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि एक राज्य ने गलती की है या वह गलती करने वाला है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से समझा और स्वीकार किया जा सकता है। केवल शक्ति या नैतिकता के आधार पर किसी चीज को गलत या सही सिद्ध करने की अपेक्षा यह उपयोगी रहता है कि उसे कानून पर आधारित किया जाए।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की उपयोगिता एवं प्रभाव कई बातों पर निर्भर करता है। कुछ राज्यों में सचिवान के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावशील बना दिया गया है। अन्य कुछ राज्यों में न्यायपालिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को आवश्यक घोषित कर दिया गया है। अनेक राज्य ऐसे भी हैं जहाँ कि सचिवान, कानून अथवा न्यायपालिका द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, किन्तु ऐसा नहीं है कि ये राज्य उसकी अवहेलना करते हों। इनसे पित्त होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता केवल राष्ट्रीय सचिवान, कानून या न्यायिक परम्पराओं पर आधारित नहीं है—इसके लिए उत्तरदायी कुछ अन्य कारण हैं।

अनेक विचारक यह मानते हैं कि कानून का पालन केवल इसलिए नहीं किया जाता कि उसके उल्लंघन करने पर हमें पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर रहता है। यद्यपि यह सच है कि प्रायः कानूनों के पीछे अत्याचारों को रोकने वाली एक शक्ति रहती है, किन्तु इसके बिना भी कानून है।

कानून की मान्यता का आधार जनता की इच्छा की भी नहीं माना जा सकता। यह कहना अपर्याप्त होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस कारण बाध्यकारी है क्योंकि लोग इसे ऐसा ही समझते हैं। इससे एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है कि लोग उसे बाध्यकारी क्यों मानते हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय कानून को क्यों माना जाता है ? उसके पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे बाध्यकारी बना देती है ? इस सम्बन्ध में सताब्दियों से बहुत कुछ लिखा जाता रहा है। सिसरो (Cicero) ने बताया कि दूसरों के मूल्य पर स्वयं का लाभ करने की प्रवृत्ति प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि यदि हर कोई ऐसा करने लगे तो मानव समाज नष्ट हो जाएगा। ग्रीशियस (Grotius) ने बताया कि जो कुछ भी प्रकृति के विरुद्ध है सत्ता बुद्धिशील लोगों के समाज के विरुद्ध है वह अन्यायपूर्ण है। इन दोनों विचारकों ने कानून के प्रति सम्मान का आधार समाजशास्त्र और नैतिकता के क्षेत्र में ढूँढा, कानून के प्रदेश में नहीं जब सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से कानून की बाध्यकारिता को देखा जाता है तो लगता है कि स्वयं व्यक्ति के भले-बुरे की भावना ही उसे कानून का पालन

करने के लिए प्रभावित करती है। किन्तु यह बात सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को कानूनों नियमों का पालन करना ही होता है, चाहे वह उनको न्यायपूर्ण समझे अथवा अन्यायपूर्ण। जब शच्छाई और बुराई को मौलिक कानूनी नियमों का रूप दे दिया जाता है तो वैयक्तिक इच्छा का महत्व बरत नहीं रहता।

अठारहवीं शताब्दी के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानूनी आधार प्रदान करने का प्रयास किया गया। एक जर्मन ककील (सन १६७६-१७५४) ने प्रथम बार एक विचारधारा सामने रखी जिसके अनुसार यह माना गया कि राज्यों के कुछ मौलिक अधिकार होने हैं जो कि राज्य की भाँति स्थायी, पूर्ण तथा अपरिहार्य हैं। इनसे राज्यों को यदि वंचित किया गया तो राज्य, राज्य नहीं रहेगा। इन मौलिक अधिकारों की सूची अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग प्रकट की। किन्तु इनमें सामान्य स्वीकृति मुख्यतः पाँच को मिल सकी; ये थे सुरक्षा का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आदर पाने का अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य का अधिकार। राज्यों की तुलना व्यक्तियों से करना अधिक गलत नहीं है, जिस प्रकार व्यक्तियों को समान और स्वायत्त समझा जाता है, उसी प्रकार राज्यों को भी समझा जाता है। स्वायत्त होते हुए भी राज्य व्यक्तियों की भाँति अपने साधियों के अधिकारों की इज्जत करते हैं। विशेष रूप से उनके बीच समानता रखी जाती है क्योंकि यदि उनमें से एक के भी पास अधिकार न हुए तो अन्य के अधिकार भी सुरक्षित नहीं रह पायेंगे। वर्तमान शताब्दी में इस विचारधारा का बहुत विरोध होता है। विरोध करते समय अन्य बातों के साथ एक बात यह भी कही जाती है कि यह वास्तविकता के साथ अनुरूपता नहीं रखती। यह कहा जाता है कि अगर स्वतन्त्रता राज्य से न छीना जाने वाला अधिकार है तो ऐसा क्यों होना है कि कुछ राज्यों को पूरी तरह से स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती। किन्तु इतने पर भी वे राज्य बने रहते हैं। वर्तमान विश्व राजनीति का तथ्य यह है कि राज्य निरन्तर अधिक से अधिक एक दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं। इसलिए इस सिद्धान्त को अस्वीकार किया जाना जरूरी है।

कानून का जो वास्तविक स्वरूप है उनका पर्याप्त प्रभाव है। कानून की मान्यता के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद अन्त में इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आदर का अन्तिम आधार यह है कि हम अपने दिल से तथा अपनी चेतना से यह मानने हैं कि कानून का पालन किया जाना उपयोगी है। यद्वा ऐसा नहीं है कि कोई मौलिक कानून का शासन हमें यह आदेश दे रहा हो कि हमें इसको ठीक मानना ही पड़ेगा, चाहे हम इसे स्वीकार करें अथवा न करें। कानून के पालन न करने

का विकल्प अराजकता है और अराजकता से व्यक्ति अपने स्वभावस्य दूर रहना चाहता है। अन्तराष्ट्रीय कानून एक मुख्य सुरक्षामक हथियार के रूप में काम लाया जा सकता है। अब तक विश्व के देश इसी पर्याप्त अवहेलना करते रहे हैं। नरशा का यह साधन बिना प्रयोग किए ही पड़ा रहा। अब देशों को चाहिए कि वे इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें।

यथा अन्तराष्ट्रीय कानून एक सत्य है ?

(Is International Law a Reality)

अनेक विचारक अन्तराष्ट्रीय कानून के कानून होने में ही संदेह प्रकट करते हैं। मार्गो के शब्दों में लेसकों का एक बुद्धिशील समुदाय बनना मन प्रकट करता है कि अन्तराष्ट्रीय कानून जैसी कोई चीज ही नहीं होती। जो विचारक यह मानते हैं कि अन्तराष्ट्रीय कानून द्वारा राष्ट्रीय शक्ति को मर्यादित किया जा सकता है और इस प्रकार उसके दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सकती है, उनकी संख्या दिनों-दिन घटती ही जा रही है। विचारकों के इन दोनों पक्षों की स्थिति का दृष्टा अचछा वर्गन ब्रिअरली (Brierly) नोटिस द्वारा किया गया है। उनका कहना है कि अनेक विचारक अन्तराष्ट्रीय कानून के चरित्र एवं इतिहास पर विचार किये बिना ही यह कह देते हैं कि अन्तराष्ट्रीय कानून हमेशा एक धोना (Sham) रहा है तथा अब भी है। दूसरी ओर कुछ विचारक ऐसे हैं जो कि यह मानते हैं कि यदि दोनों द्वारा अन्तराष्ट्रीय कानून को पजीबड कर दिया जाय तो हम शान्ति से रह सकते हैं तथा विश्व में भी सब कुछ ठीक ही होगा। ब्रिअरली (Brierly) का निवार है कि इन दोनों मतों में से किसी को भी सही नहीं कहा जा सकता क्योंकि दोनों ही समान मर्यादों के मिश्रण हैं यद्यपि दोनों ही यह मानते हैं कि अन्तराष्ट्रीय कानून एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी निता सम्बन्धित तथ्यों का अवलोकन किये बानी जन्तराणा के आधार पर कोई भी मत बना सकता है। उदाहरण के लिए श्लेचर (Schleicher) दो धिया ला सकता है जिनके मत में कुछ निरम (Norms) ऐसे होते हैं जिनको कि ज्ञानवेत्तना (Conscience), समुदायिक भावना (Community Sentiment) एवं सरकार के जर्गों द्वारा लागू किया जा सकता है। नन्दा जी परम्परा एवं आदर्शों के प्रतिकूल होने पर राष्ट्रीय कानूनों का जैने विरोध किया जाता है उसी प्रकार प्रचलित व्यवस्था से अधिक भिन्नता रखने वाला अन्तराष्ट्रीय कानून भी आलोचनाओं एवं विरोधों का शिकार बन जाता है। इन प्रकार के तर्कों द्वारा कुछ विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अन्तराष्ट्रीय कानून सच्चे अर्थों में एक कानून है यद्यपि राष्ट्रीय कानून में उसकी प्रकृति अनेक

बातों में भिन्नता रखती है तो भी कुछ बातों में दोनों के बीच समान लक्षण भी देखने को मिलते हैं।

दूसरी ओर विचारकों का वह वर्ग है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून जैसी किसी चीज के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं करता और राष्ट्रीय सम्प्रभुता के आधार पर इसे एक असत्य कल्पना भिन्न करने का प्रयास करता है। सम्प्रभुता के विचारक ऑस्टिन (Austin) आदि के मतानुसार जिसे हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं वह 'कानून' नहीं है वरन् वह तो अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की एक शाखा है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून न मानने वाले विचारक अपने पक्ष के समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र बड़ा सीमित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक बड़ा भाग इसके कार्य-क्षेत्र में नहीं आता। एक कानून के रूप में इसे राज्य में समस्त आपसी सम्बन्धों पर लागू होना चाहिये किन्तु इसके विपरीत व्यवहार में यह केवल उन्हीं विषयों पर लागू होता है जिनको कि राज्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को मानने के लिए कोई भी राज्य बाध्य नहीं है। यह कहा जाता है कि राज्य की सम्प्रभुता और अन्तर्राष्ट्रीय कानून जिसे मानना राज्य के लिए आवश्यक हो, चाहे वह उसकी इच्छा के विपरीत हो या अनुकूल, के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता।

(३) यह कहा जाता है कि जब एक राज्य द्वारा किसी कानून को स्वीकृति दे दी जाती है तो वह उसका पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। स्वीकृति की विचारधारा (Theory of Consent) के समर्थक यह नहीं बता पाते कि जिन कानूनों पर राज्य अपनी सहमति प्रकट न करे उनको हम कैसे कानून कह सकते हैं तथा राज्यों को उन्हें मानने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। यदि मजबूर किया जा सके तो उस राज्य की सम्प्रभुता का क्या होगा।

(४) ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार कानून सम्प्रभु का आदेश होता है तथा यह उन पर लागू किया जाता है जो कि उमें सम्प्रभु के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। इस परिभाषा के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून सच्चा कानून नहीं कहा जा सकता क्योंकि सयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा नहीं है जो व्यक्तियों अथवा राज्यों के ऊपर सम्प्रभुता रखता हो।

(५) राष्ट्रीय स्तर की भांति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीकृत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका नहीं होती और इस आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून को एक सच्चा कानून नहीं कहा जा सकता।

उक्त अनेक तर्कों द्वारा समय समय पर यह प्रमाण दिया जाता रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून का स्तर प्रदान न होने दिया जाय, किन्तु आलोचकों ने इन तर्कों के मुख्य आधार 'राष्ट्रीय सम्प्रभुता' की मान्यता पर आधारित किया है। उदाहरण के लिए इस विषय के ब्रिटिश विचारक बिजली को लिया जा सकता है जो यह मानते हैं कि पूर्ण एवं अविभाज्य सम्प्रभुता के समर्थक जीन बोदा (Jean Bodin) और थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) को गलत समझा गया है। उन्होंने कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता का समर्थन नहीं किया जैसा कि उनके अनुयायियों की मान्यता है। पामर तथा परकिन्स (Palmer and Perkins) के शब्दों में व्यवहार में व्यक्तिगत राज्य भी अपनी इच्छा के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून से बाध्य हो सकते हैं, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि वह कानून राष्ट्रों के समुदाय की सामान्य स्वीकृति प्राप्त कर ले।¹ वास्तविकता इन दोनों ही विचारों के बीच में स्थित है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आलोचकों एवं समर्थकों द्वारा दिये गये तर्क केवल आंशिक रूप से ही सत्य हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व है किन्तु जैसा कि मार्गेन्यो का विचार है यह कानून राष्ट्रीय कानून की भाँति प्रभावशाली वैधानिक व्यवस्था (Effective legal System) नहीं है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्ध पर यह राष्ट्रीय शक्ति की सीमाएँ एवं नियंत्रित करने में प्रभावशाली अवश्य है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून पूर्ण रूप से एक विकेंद्रित कानून होता है और इस अर्थ में इसको पुरातन तरीके का कानून (Primitive type of law) कह सकते हैं।² कुछ विचारकों के मतानुसार, 'राज्य एवं व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना अच्छा मानते हैं तथा करना एक कर्तव्य स्वीकार करते हैं, उनके कानून होने के लिए यही पर्याप्त है। यदि उसका पूरी तरह से अनुशीलन नहीं किया जाता तो उसकी कानूनी प्रकृति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता।'

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकेंद्रित स्वरूप

(Decentralized nature of International Law)

राष्ट्रीय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के बीच अंतर दिखाने समय प्रायः यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय कानूनों का पालन कराने के लिए व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका आदि विनियम अभिकरण होते हैं। यही कारण है कि इसे एक केंद्रित व्यवस्था (Centralized System) कहा जाता है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन वैधानिक समुदाय के सदस्यों

1. Palmer and Perkins, International Relations P. 308

2. Morgenthau, Politics among Nations—P. 251

द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और इसलिए यह विकेन्द्रित व्यवस्था कहलाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के निर्माण के तरीके, उनकी व्याख्या के रूप एवं उनके व्यवहार की प्रणालियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक पूर्णरूपेण विकेन्द्रित व्यवस्था है। ऐसे कानूनों का प्रचलन प्रायः प्राचीन समुदायों में पाया जाता था। अन्तर्राष्ट्रीय कानून की तुलना कभी-कभी मध्ययुगीन ब्रिटिश कॉमन लॉ (British Common Law) से की जाती है। वर्तमान युग की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं से पुनः भी कानून है। इनका विकास रीति रिवाजों द्वारा होता था और धर्मियों एवं समुदायों के द्वारा इनको लागू किया जाता था ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को आज राज्य द्वारा लागू किया जाता है। मार्गों में के शब्दों में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विकेन्द्रित प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय समाज के विकेन्द्रित ढाँचे का आवश्यक परिणाम है। जिस प्रकार एक राष्ट्र के कानूनों का निर्माण एवं संचालन कुछ मुख्यवस्थित एवं सुविकसित अंगों द्वारा किया जाता है वैसे कोई व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रचलित नहीं है और न हो सकती है। जब तक कि अपने-अपने क्षेत्रों में सम्प्रभु राज्यों द्वारा विश्व समुदाय की इकाइयों का अभिनय किया जाता है तब तक कानून का निर्माण करने वाले तथा उसे लागू करने वाली कोई केन्द्रीय व्यवस्था जन्म नहीं ले सकती। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अस्तित्व एवं व्यवहार दो तत्वों के कारण है—

(1) राज्यों के समान अथवा एक दूसरे के पूरक हित,

(2) राज्यों के बीच समुल्लेख की स्थापना। यह कहा जाता है कि जहाँ हितों का युक्त समुदाय नहीं होता तथा उनके बीच शक्ति का समुल्लेख नहीं पाया जाता वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून नहीं रह सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास एवं पालन सम्बन्धित सामाजिक शक्तियों (Objective Social Forces) का परिणाम होता है। प्रोफेसर ओपेनहिम ने शक्ति समुल्लेख को अन्तर्राष्ट्रीय कानून की अभिन्न शक्ति माना है। उनका मत है कि यदि शक्तियाँ एक दूसरे को प्रतिस्पर्ध में नहीं रख सकती तो कानून के नियम का कोई प्रभाव नहीं रह सकता क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र स्वमानस मनमानी करना चाहता तथा वह कानून का उल्लंघन करता, क्योंकि सम्प्रभु राज्यों के ऊपर कोई केन्द्रीय राजनैतिक शक्ति नहीं रह सकती इसलिए यह आवश्यक है कि शक्ति समुल्लेख से राष्ट्रों के परिवार के किमा भी मदद को स्वेच्छाचारी हान से रोका जाय। एक रूप एवं परस्पर सहायक हित (Identical and Complementary interests) भी विकेन्द्रीकरण के अभिचरण के रूप में सदैव क्रियाशील रहते हैं व किसी भी वैधानिक व्यवस्था के व्यवस्थापक,

न्यायिक एवं कार्यपालिक तीनों ही कार्यों पर प्रभाव डालते हैं। मार्गेंथो (Morgenthau) ने इनकी जीवन रक्त (lifeblood) की सत्ता प्रदान की है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास

Development of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रारम्भ किस समय हुआ तथा वह अपने प्रारम्भिक रूप में किस तरह का था इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आदिम युग के मानव समुदायों के आपसी सम्बन्धों का निश्चय दोनों पक्षों की इच्छा के आधार पर ही किया जाता था। कहते हैं कि इन लोगों के बीच अपने-अपने शिकार, गुफा, घर, नदी का किनारा आदि के ऊपर एक प्रकार का सहज ज्ञान था और दूसरे व्यक्ति को इसी चीजों को लेने में एक व्यक्ति का अन्तःकरण ही बाधक बन जाता था। मानव सभ्यता अपने आदिम काल की परिस्थितियों को पार कर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने लगी त्यों-त्यों समुदायों, गुटों, प्रदेशों, राज्यों एवं राष्ट्रों के आपसी सम्बन्धों में सुनिश्चितता आने लगी। आज के अन्तर्राष्ट्रीयता के युग में आवर राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों को कानून द्वारा नियन्त्रित करने का सचेतन एवं प्रभावपूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है। हिन्दू धर्म-शास्त्रों में राज्यों के बीच स्थित शांति एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का वर्णन आया है। यैसे तो शान्ति एवं सहयोगपूर्ण विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून जैसी संस्था का किसी न किसी रूप में प्रारम्भिक काल से ही महत्त्व रहा है किन्तु कई कारणों से वर्तमान समय में यह महत्त्व द्विगुणित हो गया है। राज्यों के बीच का बढ़ता हुआ व्यापार, आर्थिक दृष्टि से राज्यों की परस्पर निर्भरता, युद्ध में अणु आगुंधी के उपयोग का भयानक परिणाम आदि तत्वों ने मिलकर विश्व-शान्ति एवं व्यवस्था को न केवल महत्त्वपूर्ण बन अपरिहार्य बना दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का इतिहास

(The History of International Law)

वातावरण और परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के रूप पर समय-समय जो विचार प्रस्तुत किये गये हैं उन पर एक विह्वल दृष्टि डालना अप्रासंगिक न होगा।

(१) प्रारम्भिक काल

(The Early Period)

यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आधुनिक व्यवस्था उस महान् राजनैतिक परिवर्तन का परिणाम है जिसने मध्य युग की आधुनिक युग

में परिवर्तित कर दिया। वैसे इसका प्रयोग प्राचीन यूनान के नगर राज्यों के आपसी सम्बन्धों के निर्धारण में किया जाता था। नगर राज्यों के सम्बन्धों के रूप ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को बहुत कुछ दिया है। इस काल में अन्तर्नगर राज्यों के सम्बन्धों को कुछ नियमों के अनुसार संचालित करने का जो प्रयत्न किया गया उसके परस्परव्युत्पन्न युद्ध के नियम, पचायत (Arbitration) का प्रयोग आदि का विकास हुआ। रोमन काल में जब नगर राज्यों के स्थान पर बड़े साम्राज्य निर्माण का प्रयत्न किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता कम हो गई। रोमन काल में विश्व सरकार का जो विचार पनपा तथा दो प्रकार के कानूनों की जो स्थापना की गई उससे अन्तर्राष्ट्रीय कानून बहुत अधिक प्रभावित हुआ व सामान्य नागरिकता और सभी लोगों को 'निष्पक्ष न्याय' का विचार पनपा। मध्य युग में आकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने आधुनिक रूप लेना प्रारम्भ कर दिया तथा यह विचार धीरे-धीरे प्रभावशील होता गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का नियन्त्रण कुछ निश्चित वैधानिक सिद्धान्तों (Legal principles) द्वारा किया जाना चाहिये।

रोमन साम्राज्य के पतन और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के विकास के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून के चरित्र एवं महत्त्व में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आया। अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रवेश विभिन्न पहलुओं में हो गया जैसे— युद्ध का आचरण, निष्पक्षता की रक्षा, समुद्रों का शान्ति एवं युद्ध के समय प्रयोग, उपनिवेशों की सीमाएँ निर्धारित करना आदि। इस युग में लेगुनो (Leguano), विक्टोरिया (Victoria), सोरेज (Suarez), जेन्टिलिस (Gentilis) आदि अनेक विचारक हुए जिन्होंने कुछ न कुछ नया जोड़ कर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को गतिमान रखा। ह्यूगो ग्रीसियस को अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पिता माना जाता है।

(२) ग्रीसियस काल

(Period of Hugo Grotius 1583-1645)

ह्यूगो ग्रीसियस ने पौलैण्ड में जन्म लेकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सबंध में जो कार्य किये उनसे ही उसे राजनीति शास्त्र में एक अमर पद प्राप्त हो गया है। ग्रीसियस ने इस विषय पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। उनमें 'युद्ध और शान्ति के कानून के ऊपर' (On the Law of War and Peace) को पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई है। ओपेनहिम के मतानुसार इस पुस्तक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक विज्ञान का सूत्रपात किया गया था क्योंकि इस पुस्तक में प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून के विज्ञान की एक स्वतन्त्र शाखा बना दिया गया। वॉलिन हॉवन (Vollen Hoven) के विचारानुसार इस पुस्तक की चार मुख्य विशेषताएँ हैं। प्रथम, ग्रीसियस ने

राज्यों को उन्हीं कानूनों के अधीन रखा है जो व्यक्ति पर लागू होते हैं। इन कानूनों के उत्खनन को वह अपराध घोषित करता है जिसका प्रतिकूल मजा होना चाहिये। दूसरे, धर्म शास्त्र, प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक ग्रन्थों के आधार पर ग्रोसियस ने अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है। उसने शानि के कानूनों (Law of peace) का वर्णन किया है जो कि वर्तमान कानून की जड़ बन गये हैं। तीसरे, उसने बताया कि 'राज्य' कानून का उत्खनन करने वाले हमारे राष्ट्र को सजा दे सकते हैं। चौथे, उसने प्राकृतिक कानून या शुद्ध बुद्धि (Natural Law or right reason) को राज्यों के उचित व्यवहार के निर्णायक नियम माना था। पामर तथा परकिंस (Palmer and Perkins) के शब्दों में "आज ग्रोसियस की सबसे अधिक प्रशंसा इस कारण की जाती है क्योंकि उसने राष्ट्र को मानवता के सिद्धान्त स्वीकार करने को प्रेरित किया था। प्राकृतिक कानून को परिभाषित करते समय स्वयं ग्रोसियस ने कहा था कि यह शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है जो कि एक कार्य विशेष का परीक्षण करने के बाद यदि पाता है कि यह मनुष्य के बौद्धिक स्वभाव के प्रतिकूल है जो उसे नैतिक रूप से गलत बता देता है और यदि यह अनुकूल है तो उसे नैतिक रूप से आवश्यक कह देता है। ग्रोसियस की मान्यता थी कि ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता है और नैतिक रूप से आवश्यक कार्यों की आज्ञा उसी के द्वारा दी जाती है, अन्य कार्य उसकी इच्छा के विपरीत होते हैं। इस प्रकार ग्रोसियस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की कोई सूची नहीं दी गई वरन् यह बताया गया कि कानून क्या होना चाहिये। उसके द्वारा समर्थित प्राकृतिक कानून की मान्यता लगभग दो शताब्दियों तक विचारकों के मस्तिष्क को प्रभावित करती रही।"

(३) निश्चित कानूनों का युग

(Period of Positive Laws)

ग्रोसियस द्वारा दिये गये प्राकृतिक कानून के विचार व उनकी व्याख्या से मित्र जोचे (Zouche) आदि कानूनी विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। कई विचारकों के मतानुसार जोचे के कानून सम्बन्धी विचार ग्रोसियस की तुलना में पूर्णतः विरोधी हैं। उसने प्राकृतिक कानून को गौण बता कर प्रचलित कानून (Customary Law) को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। एक नयीन शाखा के प्रतिपादक के रूप में कभी-कभी उसे अन्तर्राष्ट्रीय कानून का दूसरा पिता कह दिया जाता है। विश्वास किया जाना है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून (International Law) शब्द का प्रयोग प्रथम बार बेन्थम के द्वारा किया गया था किन्तु जेरेमी बेन्थम (Jeremy Bentham)

को इस शब्द के प्रयोग की प्रेरणा जोचे के द्वारा प्रयुक्त शब्द 'राष्ट्र के बीच का कानून' (Law between nations) से मिली होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून से सम्बन्धित विचारधाराओं को मुख्यतः तीन भागों के बाटा जा सकता है। प्रथम, वे प्रचलित कानून (Customary Law) को गौण और प्राकृतिक कानून (Natural Law) को प्रधान मानते हैं। दूसरे वे जो कि प्रचलित कानूनों को प्राकृतिक कानूनों की तुलना में प्रमुल्ला दत्त है। तीसरे, विचारकों का दम है जो कानून के दोनों ही रूपों को समान महत्त्व प्रदान करता है। जनेसमी सताब्दी में आकर अन्तर्राष्ट्रीय कानून विचारों, वादविवादों एवं अन्वाडेवाजियों से उत्तर कर व्यवहार के क्षेत्र में आ गया और अब इस पर दार्शनिकों एवं नीतिशास्त्रियों की अपेक्षा राज-नीतिज्ञों और राजनीतिशास्त्रियों द्वारा विचार किया जाने लगा। दूसरे शब्दों में अब अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्वरूप वस्तुगत (Objective) हो गया तथा अपनी विषयगत प्रकृति (Subjective nature) को इसने छोड़ दिया। अन्तर्राष्ट्रीय परिवर्तनों एवं परिस्थितियों का इस पर प्रभाव पड़ने लगा। विचारकों ने अपना आदर्शवादी दृष्टिकोण त्याग कर यथार्थवादी रूप में विचार करना प्रारम्भ किया।

(४) वर्तमान काल

(The Modern Period)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक विचारकों में क्रोबे (Krabbe), दुग्नी (Duguit) और केलसन (Kelsen) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विचारकों ने मुख्य रूप से इस प्रश्न पर विचार किया है कि सम्प्रदायों को अन्तर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए किम प्रकार बाध्य किया जा सकता है। इन सभी विचारकों द्वारा एक मत से यह माना जाता है कि सभी कानूनों का एक सामान्य स्रोत (Common Source) है। क्रोबे का मत है कि उचित व प्रति चेतना का ज्ञान मनुष्य का एक मनोवैज्ञानिक निहित गुण है, जैसे—नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान आदि होता है। दुग्नी सामाजिक ठोसता (Social Solidarity) को कानून का आधार बताते हुए यह मानते हैं कि कानून का पालन इस कारण किया जाता है क्योंकि ऐसा करना समुदाय व अस्तित्व के लिए आवश्यक है। केलसन (Kelsen) के विचार से कानूनों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वे प्रचलित रीति रिवाजों की उपज हट्टे हैं। रीति रिवाजों के विरुद्ध एक तो कानून बनता ही नहीं है, और यदि बन भी जाये तो उसका पालन नहीं किया जाता, उदाहरण के लिए भारत के बाल-विवाह विरोधी कानून को लिया जा सकता है जो कि अनेक बगों में छोटे छोटे बच्चों की शादी की प्रथा को रोकने में असमर्थ रहा है। किसी भी कानून की

सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके अनुकूल प्रथाओं और रीति-रिवाजों को मोटा जाए। कानून का केवल एक स्रोत मानने वाले विचारकों को, इस धर्म को एकलवादी (Monist) कहा जाता है। इन एकलवादी विचारकों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून या किसी राज्य विशेष का कानून भिन्न भिन्न नहीं है—दोनों के बीच उच्चता एवं अधीनस्थता का सम्बन्ध है। यदि एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका के कानून के बीच विरोध हो जाए तो उसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इन विचारकों के मत में स्वीकृति (Consent) अन्तर्राष्ट्रीय कानून का आधार न तो है और न हा सकता है। समस्त कानूनों का स्रोत अवैधानिक (Nonlegal) तत्वों में पाया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण (Creation of International Laws)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण नहीं होता इनका तो प्रायः विकास किया जाता है। सम्प्रभु राष्ट्रों के ऊपर ऐसी कोई सत्ता नहीं है जिसे सर्वोच्च कहा जा सके और जो ऐसे कानूनों का निर्माण कर सके जिनको कि राष्ट्रों द्वारा बाध्य होकर माना जाए। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास दो रूपों में होता है अथवा यों कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून दो प्रकार से बनते हैं। प्रथम प्रकार से तो इन कानूनों का व्यवहार एवं चलन (Practice and Process) की क्रमिक प्रक्रिया द्वारा विकास होता है। दूसरे प्रकार के अनुसार ये 'सन्धियों की रचना एवं स्वीकृति' के माध्यम में जन्म लेते हैं। प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास मुख्यतः प्रचलन एवं व्यवहार द्वारा किया गया है किन्तु इन कानूनों की व्याख्या करने वाला कोई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय न होने के कारण इनका व्यवस्थित रूप से विकास नहीं हो पाता। यह निश्चय करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन सी प्रथा या प्रचलन कानून बन जायेगा। अनेक बार ऐसा होता है कि रीति रिवाज प्रचलित होने पर भी सामान्य (Universal) नहीं बन पाते। प्रचलित कानूनों (Customary laws) की वही कमी यह भी है कि इनके द्वारा विश्व की घटनाओं के परिवर्तित एवं गत्यात्मक (Dynamic) रूप के साथ समाधान नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि दा या दो से अधिक राज्यों द्वारा सन्धि अथवा सम्मेलनों में नवीन नियमों का निर्माण किया जाता है, सन्धियाँ प्रायः प्रचलित कानून के आधार पर की जाती हैं, सन्धि की इकाइयाँ राज्य होते हैं। सन्धियों की बाध्यकारी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है तथा इसके उपबन्धों का प्रभाव केवल उन देशों पर ही होता है जो इसमें भाग लेते हैं। संधि एवं समझौतों द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है वे मुख्यतः

राज्यों की सामान्य समस्याओं का मुकाबला करने के सद्योगपूर्ण प्रयास का प्रतीक होते हैं। कुछ का सम्बन्ध सामाजिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक मामलों से होता है जबकि दूसरे शान्ति और युद्ध जैसी समस्याओं से सम्बन्धित रहते हैं। राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के परित्रों द्वारा संधियों के मार्ग को आसान बना दिया गया था, ताकि कूटनीति को दूर किया जा सके। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक सन्धि को पहले पंजीबद्ध (Registered) कराया जायेगा तथा बाद में सचिवालय उसे प्रकाशित कर देगा। राष्ट्रसंघ की सन्धि ग्रन्थमाला में २०५ सस्करण (Volumes) हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के ४८३४ समझौते हैं। इसी प्रकार १९६१ तक संयुक्त राष्ट्रसंघ के सन्धि ग्रन्थमाला में भी ३६४ सस्करण बन गये जिनमें ५,२१२ सन्धियों का उल्लेख है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून एवं राष्ट्रीय कानून

(International Law and the National Law)

प्रायः प्रत्येक संस्था एवं संगठन के अपने कुछ नियम तथा परम्पराएँ होती हैं जिनके आधार पर वह अपना शासन संचालित करता है। अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर कानून विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं, उदाहरण के लिए पंचायत कानून, नगरपालिका कानून, राज्य कानून, राष्ट्रीय कानून एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून। इनमें से प्रत्येक कानून का क्षेत्र विशेष होता है और उसी के आधार पर इसका महत्त्व निर्धारित किया जाता है। कुछ विचारकों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अतिरिक्त कानून के अन्य समस्त प्रकार एक श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध एक राष्ट्र की जनता से होता है। किन्तु दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय कानून में वे नियम समाहित रहते हैं जो कि सम्यं राज्यों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार में आवश्यक मान लिए जाते हैं। राष्ट्रीय कानून द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित किया जाता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के व्यवहार को विनियमित करता है। इन दोनों प्रकारों के कानूनों के बीच एक अन्य अन्तर यह भी है कि एक का सम्बन्ध घरलू राजनीति से है किन्तु दूसरे का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से है। राष्ट्रीय कानून तो सम्प्रभु की आज्ञा होती है और इसलिए वह उस देश के नागरिकों पर लागू किया जाता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के ऊपर नहीं होता बल्कि राज्यों के बीच रहता है, इसलिए उसकी शक्ति एवं प्रभाव कम है। राष्ट्रीय कानून का यदि किसी के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दण्ड दिया जा सकता है और कानून का पालन करने के लिए

उसे बाध्य किया जा सकता है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सम्बन्ध में ऐसी कोई प्रभावशील व्यवस्था नहीं है।

राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मध्य स्थित असमानता को कई प्रकार से वर्णित किया जाता है और इस सम्बन्ध में अनेक विचार-धारायें विकसित हुईं। एक द्वैतवादी सिद्धान्त (Dualist theory) के अनुसार राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून दोनों परस्पर भिन्न एवं व्यात्म-भूत हैं और एक, दूसरे के क्षेत्र में महत्त्व नहीं रखता। दोनों प्रकार के कानून दो पृथक् वैधानिक आदर्श हैं जो कि भिन्न स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, अलग-अलग विषयों से सम्बन्ध रखते हैं और उनके लक्ष्य भी अलग-अलग होते हैं।

दोनों प्रकार के कानूनों के सम्बन्ध को वर्णित करने वाली एक अन्य विचारधारा अद्वैतवादी विचारधारा (Monistic theory) है जिसके मतानुसार राष्ट्रीय कानून और अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय मूल रूप से एक जैसा है। यह सच है कि एक का सम्बन्ध व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित करने से है और दूसरे का सम्बन्ध राज्यों के व्यवहार को विनियमित करने से। इस दृष्टिकोण के अनुसार कानून मूल रूप को एक ऐसा आदेश होता है जो कि अपने विषयों पर उनकी इच्छा से स्वतन्त्र रह कर लागू होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून एक ही चीज के दो पहलू हैं।

साहित्यिक एवं आलंकारिक रूप में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अभिन्न मानने वाले विचारक सैद्धान्तिक दृष्टि से चाहे कितने ही सही क्यों न हो किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उनकी असत्यता स्पष्ट जाहिर हो जाती है। समस्या उस समय उत्पन्न होती है जबकि हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि कानून के इन दो प्रकारों में से किसे प्राथमिकता दी जाए। विषयवस्तु भिन्न होने के कारण कई अवसरों पर राज्य के कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बीच विरोध उत्पन्न हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए प्रभावशील कार्यपालिका एवं न्यायपालिका नहीं होती। अतः उसे राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था एवं न्यायपालिका वा हो स्तरांतर लेना होता है। किन्तु यदि कानून के इन दोनों रूपों के बीच किसी धाराओं में संपर्क उत्पन्न हो गया तो महत्त्व एवं प्रधानता किसे प्रदान की जाएगी, इसका कोई निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है। इस उत्तर की तलाश में सैद्धान्तिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर चार प्रकार से दिया जाता है इसका अध्ययन हम निम्न प्रकार से करेंगे—

(१) सिद्धान्तिक विश्लेषण

(The Theoretical Analysis)

सिद्धान्तिक दृष्टि से विचार करते हुए विद्वानों ने जो चार मत प्रस्तुत किए हैं उनमें प्रथम को द्वैतवादी विचारधारा कहा जाता है जो कि इन दोनों कानूनों को अलग अलग मानती है। इस विचारधारा के गमयंत्रों में ट्रिपेल (Triepel) एवं एन्जिलोटी (Angilotti) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने विषयवस्तु, मूल स्रोत एवं बाध्यकारिता के आधार पर दोनों प्रकार के कानूनों के बीच भेद दिखाया है। दोनों की भिन्नता के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्र कानून को प्रभावित नहीं कर सकता और इसी प्रकार राज्य का कानून अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सृजन अथवा परिवर्तन करने में असमर्थ है।

इस सिद्धान्त के विरोध में यह कहा जाता है कि असल में कानून व्यवस्था एक निःकाय है और ये दोनों प्रकार के कानून उसकी शाखाएँ मात्र हैं जो अलग अलग क्षेत्रों पर लागू होती हैं। जो विचारक अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विषय व्यक्ति को नहीं वरन् केवल राज्य को मानते हैं वे सही नहीं हैं क्योंकि जब कभी युद्ध अपराधों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये जाते हैं तो वे व्यक्ति पर भी चलाए जाते हैं। दूसरे जो स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत सामान्य इच्छा को मानते हैं वे एक ऐसा जटिल स्रोत हमारे सामने रखते हैं जो कि अस्पष्ट है।

दूसरा मत अद्वैतवाद कहलाता है जिसका प्रचार नीत्सा (Kelsen), क्रेब (Krabbe), कुन्ज (Kunz), दुरखीम (Durkheim) एवं राईट (Wright) आदि ने किया। इन विचारकों के मतानुसार कानून को दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को राष्ट्रीय कानून से पूर्णतः अलग मानते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को कानून ही नहीं मान रहे हैं। ये विचारक दोनों कानूनों का प्रादुर्भाव एक ही उच्चतर कानून से मानते हैं जो कि अच्छे तथा बुरे (Right and Wrong) के सिद्धांत पर आधारित है। कानून के ये दोनों प्रकार अभ्योन्मोहित और एक जैसे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून द्वारा राज्यों की सीमाओं को निर्धारित किया जाता है और उनका क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादों को ठीक किया जाता है। दूसरी ओर राज्य कानून द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकृति प्रदान करने में पर्याप्त सहायता प्रदान की जाती है। यह कहा जाता है कि बाध्यता के आधार पर भी दोनों कानूनों को हम भिन्न नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों ही ऐसी आज्ञाएँ हैं जिनका पालन इच्छा के विरुद्ध भी करना होता है।

इस सिद्धान्त को भी विचारकों की आलोचनाओं का विषय बनना पड़ा। इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि यह बात तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती कि दो पूर्णतः स्वतन्त्र कानूनी पद्धतियाँ एक साथ कार्य करेंगी। इतने पर भी अद्वैतवादी सिद्धान्त द्वैतवादी सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना गया। विचारकों का कहना है कि विषयस्तु के आधार पर कानून के इन दोनों रूपों के बीच अधिक भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय विषय को अन्तर्राष्ट्रीय संधि द्वारा वैदेशिक विषय में परिणत किया जा सकता है। यदि राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून के बीच सघर्ष होता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों अलग-अलग कानून हैं, क्योंकि कई बार राज्य के दो कानूनों के बीच भी सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। जिन प्रकार कानून के विरुद्ध होने हुए भी एक अभिसमय उन समय तक चलती रहती है जब तक कि उसे रद्द न कर दिया जाये। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होते हुए भी राज्य का कानून लागू रह सकता है।

तोसरा मत प्रोफ़ेसर स्टार्क (Stark) का है। यह मत रूपान्तरवादी (Transformation) एवं विशिष्ट ग्रहण (Specific adoption) की विचारधारा कहलाता है। इन विचारधारा के मतानुसार अन्तर्राष्ट्रीय कानून को न्यायवित्त होने के लिए राष्ट्रीय कानून में परिणत होना पड़ता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो समझौते किये जाते हैं उनके नियमों को एक देश अपनी जनता पर तभी लागू कर सकता है जबकि वह उनके मध्य में कानून बना दे। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय कानून को प्रभावशील बनाना चाहते हैं तो राज्य के कानून का रूप प्रदान कर देना चाहिए। इस सिद्धान्त की कई प्रकार से आलोचना की जाती है। यह कहा जाता है कि इसके द्वारा राज्य के कानून तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अलग-अलग मानना उचित नहीं है। दूसरे यह कहना भी सही नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को केवल राज्य के कानूनों के माध्यम से ही मायता प्राप्त होता है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रत्यक्ष रूप में भी मान्य हात हैं।

चौथा मत प्रत्यायोजनवादी कहलाता है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य को इस बात के निश्चय करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जाता है कि संधि एवं अभिसमय राज्य पर कब और किस प्रकार लागू किए जायेंगे। अर्थात् यह सिद्धान्त भी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून को स्पष्ट नहीं कर पाता।

(ii) व्यावहारिक विवेचन

(The Practical Analysis)

सिद्धान्तिक आधार पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करने के बाद यह उपयोगी रहेगा कि राष्ट्रों के व्यवहारों को देख कर कानून के इन दोनों रूपों के मध्य स्थित सम्बन्धों का निश्चय किया जाये। ग्रेट ब्रिटेन में जब अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उस समय न्यायालयों के व्यवहार की तीन प्रमुख विशेषतायें रहती हैं। पहली बात तो यह है कि जिन अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को विश्वव्यापी मान्यता अथवा इंग्लैंड की सम्मति प्राप्त हो चुकी है, वे अपने आप राष्ट्रीय कानून का भाग मान लिये जाते हैं। दूसरे जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ व्यक्तिगत अधिकारों को प्रभावित करती हैं अथवा जिनके द्वारा कॉमन लॉ में परिवर्तन आ सकता है उनको लागू करने से पूर्व संसद द्वारा कानून बनाना जरूरी है। तीसरे, यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून या राज्य के कानून में कभी संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो राज्य के कानून को महत्त्व दिया जाएगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवहार को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सम्मिश्रण सिद्धान्त (Incorporation theory) को अपनाया जाता है जिसके अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून देश की परम्पराओं के अनुकूल है तो वह राज्य कानून बन आता है। दूसरे, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवहार को एक नवीनता यह है कि अगर राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि कर ली जाए तो वह मान्य समझी जाती है। तीसरे, यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का प्रथम नियम ही राज्य कानून के विरुद्ध है तो राज्य का कानून मान्य समझा जायेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद ५१ का राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान रखने को कहता है। यद्यपि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन नीति निर्देशक सिद्धान्तों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता किन्तु फिर भी यह आशा की जाती है कि इससे विधि निर्माण की प्रक्रिया पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा।

जर्मनी में और कुछ परिवर्तनों के साथ सोवियत रूस में वही व्यवहार मिलता है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रकार

(The Kinds of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण कई प्रकार से होता है और इसके स्रोत भी विभिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए यह स्वभाविक ही है कि इन कानूनों की प्रकृति, रूप एवं लक्ष्य में विभिन्नता आ जाय। कई आधारों

पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विभाजन किया जाता है, इनमें प्रमुख विभाजन निम्नलिखित हैं—

१. व्यक्तिगत एवं सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Private and Public International Law)
२. प्रक्रिया सम्बन्धी एवं वास्तविक कानून (Procedural and Substantial Law)
३. शांति, युद्ध एवं निष्पक्षता के नियम (Laws of Peace, War and Neutrality)
४. विशेष और सामान्य या सार्वभौमिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Particular and general or universal law)
५. शक्ति, सहयोग और परस्पर सम्बन्धों के कानून (Law of power, co-ordination and reciprocity)

प्रो० डिकिन्सन (Professor Edwin D. Dickinson) ने बताया है कि व्यक्तिगत अधिकारों एवं कर्तव्यों से सम्बन्धित विषयों पर न्यायीकरण एवं नियमन (Adjudication and regulation) की समस्या उठ खड़ी होती है क्योंकि चीजों एवं व्यक्तियों का एक देश से दूसरे देश में आवागमन लगा ही रहता है तथा राष्ट्रीय सीमाओं के परे सम्पत्ति, परिवार, समझौते, आदि भी संपते (Consumated) ही रहते हैं। पापर तथा परकिन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के दो अन्य रूपों का भी वर्णन किया है। एक तो समुद्रीय व्यापार का कानून है जिसे वे एडमिरैल्टी कानून (Admiralty law) कहते हैं और इसके दूसरे प्रकार को अन्तर्राष्ट्रीय सञ्जनता (International Comity) का नाम देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में युद्ध के कानून और शांति के कानून का नाम भी उल्लेखनीय है।

युद्ध के कानूनों की आवश्यकता इस कारण हुई कि जहाँ न्याय की स्थापना एवं शोषण तथा अन्याय का विरोध करने में शान्तिपूर्ण साधन सफल नहीं हो पाते वहाँ पर युद्ध अपरिहार्य बन जाता है। यह एक देश की आत्म-रक्षा का अन्तिम तरीका है। कई स्थितियों में युद्ध न्यायपूर्ण एवं धर्मयुद्ध बन जाते हैं किन्तु धर्मयुद्धों में भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक बन जाता है। अनेक अभिसमयों एवं अभिलेखों द्वारा भूमि और समुद्र पर युद्ध के विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया है। ऐसे कानून युद्ध के पायलों की देखभाल, युद्ध के बन्दिनों के साथ बर्ताव, मेडीकल कर्मचारियों को सुविधायें देना, अवरुद्ध हथियार एवं अभिकरणों, जीती हुई शत्रु की भूमि में सैनिक कमाण्डर की शक्ति, निष्पक्ष राष्ट्रों के कर्तव्य एवं अधिकार, जह-शीली गैसों का प्रयोग आदि बातों से सम्बन्धित रहते हैं। युद्ध के कानूनों ने,

यह माना जाता है कि युद्ध को मानवीय बनाने में भारी सहायता की है। प्रायः सभी देशों द्वारा इनका अनुशीलन किया जाता है। किन्तु अभी तक वायु के युद्ध के सम्बन्ध में किसी प्रकार के ऐंगे कानूनों का निर्माण नहीं किया गया है जो कि प्रभावशाली हों। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्व युद्ध के कानून प्रायः निष्पक्षता के कानून थे। इन कानूनों का पालन युद्ध के समय न किया जा सका। जहाँ इन कानूनों का व्यवहार सम्भव था वहाँ भी इनकी अवहेलना की गई। आज जब कि पूर्ण युद्धों (Total wars) का प्रचलन है, निष्पक्षता का प्रयोग बड़ा ही असम्भव बन गया है। फिलिप जेसा (Philip C Jessup) के विचार से यदि समाज के वर्तमान या भविष्य की एकता को देखा जाय तो हम पायेंगे कि निष्पक्षता (Neutrality) आज एक समाज विरोधी स्थिति (Antisocial Status) बन गई है।

शान्ति के कानून में युद्ध के कानूनों की भाँति विश्व व्यवस्था को बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील रहने हैं किन्तु शान्ति के कानूनों का विषय-क्षेत्र युद्ध के कानूनों से पर्याप्त भिन्न रहता है। शान्ति के कानूनों के विषय क्षेत्र को डिकिनसन (Professor Dickinson) द्वारा मुख्यतः ६ भागों में बाँटा गया है जो निम्न प्रकार हैं—

- १ राष्ट्र राज्यों के जन्म, स्वीकृति, जीवन और मृत्यु में सम्बन्धित,
- २ राष्ट्रीयता एवं उसके तत्वों में सम्बन्धित,
- ३ राष्ट्रीय प्रशासन से सम्बन्धित;
- ४, ५ समशीतो, सम्पर्कों और अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित,
- ६ जगहों के नियंत्रण से सम्बन्धित कानून।

पामर तथा परकिनस (Palmer and Perkins) ने बताया है कि उक्त में से प्रत्येक पहलू पर बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है तथा इन पहलुओं का मान्यता से ही अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को विभाजित करने का प्रत्येक आधार दुश्चारा, अधूरापन एवं परस्पर विरोध जैसे अक्षुण्णों में दूषित है। इन दोषों का होना स्वाभाविक है तथा ये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रकृति की उत्पत्ति हैं। मार्शेल्स ने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण करने में क्या-क्या व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य करने पड़ते हैं तथा उनकी व्याख्या के लिए कौन से न्यायिक (Judicial) और उन्हें लागू करने के लिए कौन-कौन से कार्यशालिका में सम्बन्धित कार्यों की माँग की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों का सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है किन्तु इसके न्यायिक तथा कार्यकारिणी सम्बन्धी कार्यों का सुधार करने के लिए अनेक मफल प्रयास किये गये हैं। इन सब प्रयासों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून की विवेकित

प्रकृति (Decentralized Nature) ने अपने आपको सबल बनाया है और इस प्रसार विकेंद्रित प्रकृति अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूलतत्त्व (Essence) बन गई है। जो सिद्धांत विकेंद्रीकरण को अपरिहार्य बना देते हैं वे सम्प्रभुता के सिद्धान्त में प्राप्त होते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को नियमबद्ध करना

(Codification of International Law)

प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अर्थ एवं स्वभाव के बारे में पर्याप्त भ्रम रहता है तथा इसके अनेक अर्थ लगाये जा सकते हैं। इस व्यवहार को रोक्ने की दृष्टि से उनको नियमबद्ध करने का प्रायः सुझाव दिया जाता है ताकि उनकी व्याख्या का एक-सा तरीका अपनाया जा सके। किन्तु नियमबद्ध (Codified) करने से जितनी समस्याएँ दूर होती हैं लगभग उतनी ही कठिनाइयाँ इसके कारण उत्पन्न भी हो जाती हैं। यह एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें कानूनों को ज्यों का त्यों पत्रीबद्ध कर लिया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। किन्तु विभिन्न विचारकों द्वारा यह सुझाया जाता है कि यदि कानून में सुधार करना हो तो उन्हें लिखते समय निश्चितता एवं स्पष्टता लाकर उसके अभावों एवं असहमतियों को प्रकट किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कानूनों का परिवर्तन करने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकती है। कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को नियमबद्ध (Codified) करने से अनिश्चय की भावना का प्रसार भी हो जाता है।

विधान के अनेक विचारार्थी इस बात के पक्ष में हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून को सकलित एवं व्यवस्थित कर दिया जाय तथा राज्यों के परस्पर सम्बन्धों के विषय में जो विचार हों उनको स्पष्ट किया जाय। नियमबद्ध करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्थापन दो अलग-अलग बातें हैं। पामर तथा परकिनस के शब्दों में नियम संग्रह (Code) का निर्माण कानून को एक निश्चित क्षेत्र में व्यवस्थित बनाना है। इस प्रक्रिया द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का नियम संग्रह बनाने का कार्य सर्वप्रथम १८६१ में आस्ट्रिया के एक न्यायशास्त्री (Jurist) द्वारा किया गया था। उसके बाद फ्रांसिस लीबर (Francis Lieber), ब्लन्टश्ली (Bluntschli), डेविड डडले फील्ड (David Dudley Field) आदि न्याय शास्त्र के विचारकों द्वारा भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाये गये। वर्तमान काल में विभिन्न विचारकों द्वारा ऐसे नियम संग्रह प्रस्तुत किये गये हैं। अनेक संस्थाओं ने इस कार्य में योगदान किया। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय कानून संस्था (International law association), अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अमेरिकन समाज (The American Society of International Law) आदि

महत्त्वपूर्ण है। १८६४ के जेनवा सम्मेलन के बाद में अधिकारी रूप में नी ऐसे नियमों का संग्रह प्रकाशित किया जाने लगा। इसके बाद राष्ट्रसंघ (League of Nations) तथा मधुवत राष्ट्रसंघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून का संग्रह तैयार करने का कार्य समाल लिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नियमबद्ध करने की प्रक्रिया कुछ बिज्ञानों के मतानुसार उसनी ही आवश्यक एवं आधारभूत है जितनी कि उसकी विकसित प्रकृति होती है। अधिकतर नियमबद्धता उन अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों पर की गई जिनका सम्बन्ध संचार साधनों के क्षेत्र तथा मानवीय उद्देश्यों में होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पीछे दबाव

(Sanctions behind International Law)

प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन क्यों किया जाता है। यह सब है कि विश्व शांति में एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से यह आवश्यक एवं अपरिहार्य बन जाता है कि सभी देश अपने व्यवहार को कानून द्वारा समर्थित रखें तथा उचित व्यवहार के प्रत्येक लोभ का स्वरण करते रहें। किन्तु यह एक व्यावहारिक तथ्य है कि आवश्यक एवं अपरिहार्य चीजें बड़ी कठिनाइयों के बाद ही व्यवहृत की जा सकती हैं। जीवन का यह एक विरोधाभास है कि प्रेय बहुधा श्रेय नहीं होता और श्रेय प्रायः प्रेय नहीं बनता। इस विरोधाभास को मिटाना ही मानव सम्यता और सस्कृति के उत्थान का बीज है। अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की सबसे बड़ी आलोचना यह की जाती है कि इन कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता। इनका पालन स्वयन्त एवं सम्प्रभु राष्ट्रों की इच्छा पर निर्भर है जो जैसा कि यथार्थवादी विचारक मानते हैं, सदैव स्वार्थ में लिप्त तथा शक्ति वृद्धि के लिए आकर्षित रहती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय स्वार्थ एवं राष्ट्रीय शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से सहानुभूति हो सकता है किन्तु प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप में तो वह एक प्रभावशाली वाचक का ही कार्य करता है। राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून की जानबूझ कर, पोषणाय करके अवहेलना की जाती है किन्तु फिर भी ऐसा कोई साधन नहीं कि उनमें इस घृष्ट कर्म के लिए उनकी सजा दी जा सके। तथ्यों के आधार पर कुछ विचारकों ने यह मत प्रकट किया है कि ज्यों-ज्यों अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सुधार होता है, अर्थात् इसका स्तर ऊँचा उठता है त्यों-त्यों इसके मानने वालों की, इस पर अमल करने वालों की संख्या भी कम होती चली जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कुछ निश्चित परिस्थितियों का परिणाम होता है। एक राष्ट्र विशेष के उद्देश्य एवं दृष्टिकोण भी उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

को लागू कराने में अनेक परिस्थितियों, मनो-भावों, घटनाओं आदि पक्षों अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हाथ रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए एक राष्ट्र को प्रेरित करने वाले विभिन्न तत्वों में मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं—

१. आदत २ सुविधा ३ आत्मचेतना ४ अनौपचारिक दबाव ५. आत्महित (Self-Interest) आदि। प्रत्येक राष्ट्र एक समय में अनेक प्रकार के हथ अंपनाने के लिए स्वतन्त्र रहना है, उदाहरण के लिए वह दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक या आर्थिक प्रभाव का उपयोग कर सकता है। ये प्रभाव प्रायः सभी वैधानिक व्यवस्थाओं में प्रयुक्त किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त एक राज्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू कराने के कुछ अन्य औपचारिक साधन भी अपनाये जा सकते हैं। इन साधनों को प्रायः प्रतिबन्ध (Sanctions) कहा जाता है। श्लाइसर (Schleicher) के शब्दों में प्रतिबन्ध एक ऐसी क्रिया है जो कि साधारणतः अवैध होती है किन्तु कानून तोड़ने वाले के विरुद्ध वैध समुदाय (Legal Community) द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।¹ कानून का पालन करने वाले के विरुद्ध ये प्रयुक्त नहीं की जाती। राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ के व्यवस्थापनों में इस प्रकार के प्रतिबन्धों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के कदम उठाना सामूहिक सुरक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में ही राष्ट्रसंघ एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि यदि सामूहिक सुरक्षा के शांतिपूर्ण साधन असफल हो जायें तो शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके विरुद्ध यह कहा जाता है कि एवं आदर्श कानून को लागू कराने के साधन भी वैधानिक ही होने चाहिये; शक्ति द्वारा उनको लागू कराने का अर्थ होगा कानून की आत्मा का हनन कर देना। इसी आधार पर श्लाइसर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि “संयुक्त राष्ट्रसंघ मर्यादा में अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नष्ट करता है, यह इनको लागू करने का स्वयं उत्तरदायित्व नहीं लेता।”

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन (An evaluation of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में जो महत्त्व रहा उस पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेक बार इसने अन्तर्राष्ट्रीय मनमुटावों को पैदा होने एवं बढ़ने से रोका है किन्तु फिर भी जैसा कि

1. Schleicher, International Relations, P. 385

2. Schleicher, Ibid, P. 385

अनिकाश विचारकों का मत है अन्तर्राष्ट्रीय कानून के परिणाम आशाजनक एवं अधिक प्रभावशाली न हो सके। पामर तथा परकिन्स महोदय ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून की पाँच सीमाओं का वर्णन किया है जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कानून मफल्तापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा एक अपर्याप्त साधन मात्र रह जाता है। ये पाँच सीमाय निम्न है—

- १ व्यवस्थान कार्य की अपूर्णता,
- २ न्यायिक कार्यों में विभिन्न गम्भीर सीमायें,
- ३ प्रभावशील प्रयोग की (न्यायान्विति की) कमी,
- ४ अन्तर्राष्ट्रीय कानून के कार्यों एवं क्षेत्रों पर सीमायें,
- ५ कानून के सद्देश्य एवं प्रकृति के सम्बन्ध में गलतफहमिया (Misunderstandings) ।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की ये समस्त सीमायें अन्तर्राष्ट्रीय समाज के वर्तमान चरित्र में निहित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समाज सामान्यतः बंध व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता तथा उसका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जा सकता। जेसप (Philip Jessup) का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून की मूल कमजोरी यह है कि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून केवल राज्यों के बीच का कानून है। यह व्यक्तियों के बीच का या व्यक्ति और राज्यों के बीच का कानून नहीं है।^१ जेसप का विचार है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधुनिक रूप का विकास करना है तो व्यक्तियों सहित अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विस्तार करना होगा। उन्होंने बताया है कि अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था की दो मूल बुज्जिया हैं। पहली यह है कि राष्ट्रीय कानून की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय कानून भी सीधे व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। वह परम्परावादी कानून की भाँति व्यक्ति से दूर नहीं रहना चाहिये। दूसरे उस हिन का स्वीकृति होना चाहिये जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पालन करने से पूरा होने वाला है। कानूनों का उल्लंघन भी केवल राज्यों का ही मसला नहीं माना जाना चाहिए। हेग्स केलसन (Hans Kelsen) के मतानुसार युद्ध को रोकने का एक प्रभावपूर्ण साधन यह है कि युद्ध क्षेत्र पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से सरकार के सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से ढाला जाना चाहिये। बिन्सी राइट ने इस मत के समर्थकों के विचारों की व्याख्या करते हुए बताया है कि ये सिद्धांत रूप से विश्व समाज को सम्प्रभु राष्ट्रों से विश्व सङ्गठन में परिवर्तन करना चाहते हैं जिसमें कि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मानव अधिकारों

1. Philip Jessup, A Modern Law of Nations

की रक्षा को जायगी, अन्तर्राष्ट्रीय अनराधों को सजा दी जायगी तथा व्यक्ति एवं राज्य दोनों पर अपने कानूनों को लागू करेगा ।

विश्वशांति की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय कानून की बहुत प्रशंसा की जाती है । किन्तु कुछ विचारकों के मतानुसार यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक पहलू मात्र है और किसी भी अर्थ में यह एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है । कहा जाता है कि युद्ध और शान्ति पर प्रभाव डालने वाले बड़े-बड़े मसले अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिधि के बाहर रहते हैं । जिन विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हस्तक्षेप है उनमें भी आवश्यक नहीं कि प्रभावित राष्ट्र उसका आदर करें । राष्ट्रीय सम्मान तथा आदर के प्रश्न इसके सफल संचालन के मार्ग की बाधायें हैं । इन सबके बावजूद पामर तथा परकिन्स जैसे विचारकों का मत है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था का निर्माण करने में विधेयात्मक प्रयास करता है जिसके अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति व स्थिरता खतरे में पड़ सकती है ।¹

अन्तर्राष्ट्रीय कानून एक प्रकार से उन सभी प्रयासों के परिणामों को पजीबड कर देता है जो कि शांति की खोज में किए जाने हैं । डिकिन्सन (Dickinson) के शब्दों में शांति का प्रत्येक दिवस कानून के विस्तार का एक समय है । सीनेटर टाण्ट ने कहा था कि विश्व शांति तब तक असम्भव है जब तक कि राष्ट्र उनके परस्पर के सम्बन्धों की प्रशंसित करने वाले किसी निश्चित कानून पर सहमत नहीं हो जाते । राष्ट्रों को सहमत होकर यह मानना चाहिए कि वे अपने झगड़ों को बिना निषेधाधिकार का प्रयोग नये न्यायाधिकरण (Abjudication) के लिए प्रस्तुत करेंगे तथा निम्न न्यायालय का जा निर्णय होगा उसे बाध्य होकर मानेंगे । इसके लिए ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता पर जोर देते हैं । उनका कहना है कि जब तक विश्व सरकार की स्थापना द्वारा सम्पन्न राष्ट्र की व्यक्तिगत इच्छा को सामूहिक इच्छा के अधीन नहीं बना दिया जाता तब तक कानून के अन्तिम लक्ष्य, अर्थात् मानव-सध्यों के सुलझाने में शक्ति प्रयोग को निटाना, को प्राप्त नहीं किया जा सकता ।² अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को सफ़ल रूप से संचालित करने के लिए विश्व के अधिकांश देशों में सहयोग की भावना का होना अनिवार्य है । यह भावना न केवल कानून निर्माण के बाद बल्कि कानून निर्माण के पहले भी होनी चाहिए । विश्व सरकार की स्थापना तथा निःसस्त्रीकरण के प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं ।

1. Palmer and Perkins, op cit., p 327

2. Jessup, A Modern Law of Nations, P. 2.

विश्व सरकार

(THE WORLD GOVERNMENT)

विश्व के स्वरूप पर संझाना रूप से विचार करते समय अधिकतर विद्वानों द्वारा आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता अन्तर्राष्ट्रीयतावाद को माना जाता है। यातायात एवं संचार साधनों के विकास तथा अन्य वैज्ञानिक प्रगतियों के सहारे विश्व के रूप में जो परिवर्तन आया है उसे देखते हुए यह विशेषता अतिशयोक्ति की परिधि में नहीं आती। यह निःसन्देह स्वीकार किया जाता है कि मानव ने बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ज्योंही प्रवेश किया त्योंही एक विश्वव्यापी समाज या विश्वसभ्यता विश्व के तबसे पर उभरने लगी। विश्व के देश आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक आदि दृष्टियों से परस्पर इतने सम्बन्धित तथा आश्रित हो गए हैं कि एक देश में इन क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव विश्व के अन्य देशों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता। -

अणु शक्ति के आविष्कार से सम्पूर्ण युद्ध (Total War) का जो उदय हुआ है उससे सभी देशों में एक साथ विनाश की प्रवृत्ति का विरोध करने के भाव विकसित हुए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आशा की जाती है कि अधिक से अधिक लोग यह सोचने लगेंगे कि मानव जाति ने आज तक जो प्राप्त किया है तथा विश्व का समस्त कला, विज्ञान, धर्म, संगीत आदि उनका अपना ही है वह उसे विनाश से बचाना चाहिये। किन्तु केवल इस भावना का विकास ही विश्व शांति के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सधर्ममय रूप का समन न किया जाए। इस समस्या पर उचनात्मक रूप से विचार करते हुए विभिन्न विचारकों ने विश्व सरकार की स्थापना का सुझाव दिया है जिनके अनुसार वर्तमान स्वतन्त्र सम्प्रभु राष्ट्र विश्व संगठन की उनी रूप में इकट्ठी बन जायेंगे जिस रूप में एक संघीय व्यवस्था में इनाइया हुआ करती हैं।

विश्व सरकार की मान्यता का आधार

(Basis of the Concept of World Government)

सारे तत्कार में एक ही शासन व्यवस्था का संचालन बहुत पुराने समय से ही मनुष्य जाति का आदर्श रहा है। इस आदर्श के उद्देश्यों के रूप में समय समय परिवर्तन आता रहा है। भारत में चक्रवर्ती सम्राट् बनने की महत्वाकांक्षा के पीछे प्रजासत्ताकों की अहंकार भावनाएँ ही व्यक्त होती थीं किन्तु आज की विश्वव्यापी सरकार की मान्यता का आधार इससे भिन्न है। आज के लोग विश्व से युद्धों को दूर करने तथा शांति का विरस्थापी बनाने

के लक्ष्य से विश्व सरकार की मान्यता का समर्थन करने हैं जबकि प्राचीन साम्राज्यवादी भावनाओं और विश्वव्यापी सरकार के स्वप्नों को साकार करने के लिए युद्ध का सहारा लिया जाता था। आज विश्व सरकार की मान्यता का समर्थन मुख्यतः विचारकों एवं सामान्य जनो द्वारा किया जाता है जबकि पहले इसके समर्थन का स्रोत केवल प्रशासक वर्ग था जिसके शांति विरोधी एवं जन विरोधी हित इसके साथ जुड़े हुए थे।

वर्तमान काल में विश्व सरकार के विचार का जो समर्थन दिया जाता है वह अनेक आधार स्तम्भों पर स्थित है। मानवीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि के आधार पर इसे न्यायोचित आवश्यकता ठहराया जाता है। यह कहा जाता है कि मनुष्य मनुष्य के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के कारण भेदभाव रखना अनुचित है। मनुष्य होने के नाते अश्वरीका का नागरिक भी उत्तुहा ही मुख्यवान् एवं महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य छोटे देश का होता है। राष्ट्रीय सरकार एवं सीमाओं में परिमित रहने के कारण उन दोनों के बीच प्रायः अन्तर दिखाया जाता है जो अमानवीय है और इसका एकमात्र इलाज है 'विश्व सरकार'। अनेक विचारकों के अनुसार विभिन्नता एवं क्रियात्मक शक्ति को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति की संस्कृति का आधार-स्तम्भ माना जाता है। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर एक जनसमुदाय अपनी संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति पर लादने का प्रयास कर सकता है और इस प्रकार विश्व के विभिन्न मानव समुदायों को अपने स्थान विशेष एवं स्वी विशेष के अनुसार स्वयं की संस्कृति का विकास करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। विश्व सरकार की स्थापना करके सांस्कृतिक विकास की इस प्रमान बाधा को दूर किया जा सकता है। आज समस्त विश्व को एक परिवार मानने की धारणा सर्व-सर्वें जोर पकड़ती जा रही है। 'बमुर्धन कुटुम्बक' तथा 'सारा जहा हमारा' के नारों के पीछे विश्व सरकार की स्थापना का विचार निहित है।

विश्व सरकार की मान्यता की कुछ विशेषताएँ

(Some characteristics of the concept of World Government)

विश्व सरकार वर्तमान समय की एक अनिवार्य आवश्यकता समझी जाती है। यह महत्व एवं उपयोगिता की दृष्टि से जितनी आवश्यक है, यथार्थता एवं विधानविधि की दृष्टि से उतनी ही अप्रवाहार्किक भी है। विश्व सरकार के स्वरूप का वर्णन करने समय निम्नलिखित विचारकों ने जो मत प्रकट किए हैं उनका निरीक्षण करने के बाद इस मान्यता की निम्नलिखित मुख्य-मुख्य विशेषताएँ सामने आती हैं—

(१) विश्व सरकार शांति और व्यवस्था की निर्मापक है—
(World-Government is maintainer of peace and order)

यह कहा जाता है कि जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए एक शक्ति सम्पन्न सरकार की आवश्यकता होती है जिसके पास पुलिस व सैनिक शक्ति रहे तथा जिसकी आज्ञाओं के उल्लंघनकर्ता को दण्ड दिया जा सके, उसी प्रकार यदि विश्व में शांति और व्यवस्था की स्थापना करनी है तो विश्व सरकार की रचना करना जरूरी होगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति रखी जाएगी—ताकि विश्व के देश सदैव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते न रह सकें और सदैव सर्वोच्च शक्ति के अधीन अनुशासन बनाए रख सकें। क्लाड (Claude) महोदय के शब्दों में 'सामान्य रूप से विश्व सरकार के सिद्धांत का अर्थ ऐसी सत्ताधारी, शक्तिशाली केन्द्रीय संस्थाओं का निर्माण करना है जो राज्यों के बीच में सम्बन्धों का, मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को रोकने के लक्ष्य से, प्रबंध कर सकें।¹ मार्सेन्यो के मतानुसार विश्व सरकार के समर्थकों के तर्क अकाट्य हैं। संसार में तब तक कोई स्थायी शान्ति नहीं हो सकती जब तक कि राजनैतिक विश्व की सीमाओं से ऊपर एक राज्य का अस्तित्व न हो जायेगा। विश्व शांति के लिए अब तक किए गए प्रयासों में मनुष्य जाति को कई बार निराशा का अनुभव करना पड़ा है। इसका कारण यह बताया जाता है कि संघर्ष तथा युद्ध के मूल कारण आघात न करके उसके परिणामों की ही रोकथाम की गई थी। शक्ति मतुलन, सामूहिक सुरक्षा, नि:शस्त्रीकरण आदि साधनों के द्वारा राष्ट्रीय सम्प्रभुता पर केवल सीमाएं लगाने का प्रयास किया गया, उसे समाप्त न किया गया तथा इस सबका फल यह हुआ कि विश्व-शांति को स्थायी रूप से प्राप्त न किया जा सका।

(२) राष्ट्रीय सम्प्रभुता का विरोधी—
(Opposite to the National Sovereignty)

वर्तमान विश्व अनेक ऐसे राष्ट्रों से मिल कर बना है जो अपने क्षेत्रों में सम्प्रभु हैं तथा जिनका आन्तरिक एवं बाह्य व्यवहार स्वेच्छा से संचालित होता है न कि किसी दूसरी शक्ति के दबाव के कारण। व्यवहार में स्वेच्छा और स्वतन्त्रता का प्रयोग एक सीमा तक ही उपयुक्त रहता है। उससे आगे बढ़ने पर एक देश का व्यवहार दूसरे देश के व्यवहार की स्वेच्छा और स्वतन्त्रता को नष्ट कर देता है तथा विश्व समाज में शक्तिशाली की विजय का जगली कानून प्रभावशील बन जाता है। इन सम्भावनाओं से बचने के

1 Claude I. L., Power and International Relations P. 206,

लिए विश्व सरकार का समर्थन दिया जाता है। यह कहा जाता है कि यदि विश्व को आत्म-विश्वास से बचना है तो राष्ट्रीय सम्प्रभुता को अन्तर्राष्ट्रीय दारों और समस्याओं से प्रतिबन्धित करना ही पर्याप्त न होगा। इसके लिए व्यक्तिगत राज्यों की सम्प्रभुता का एक विश्व शक्ति को हस्तांतरण करना होगा। यह विश्व सत्ता इन व्यक्तिगत राज्यों के ऊपर उतनी ही सम्प्रभु रहेगी जितने सम्प्रभु वे राष्ट्र अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं। मार्गेन्यो के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय समाज में जो सुधार के प्रयास किए गए वे अमफल रहे क्योंकि वे तो असफल होने ही थे। आवश्यकता यह है कि सम्प्रभु राष्ट्रों के इस विश्व समाज को व्यक्तियों के राष्ट्रों से उच्च समुदाय (Supranational Community) में परिवर्तित कर दिया जाये।"¹

(३) विश्व सरकार शक्ति प्रबन्धक के रूप में (*World Government as a manager of Power*)

राज्यों के शक्ति सम्बन्धों का प्रबन्ध करने के लिए प्रारम्भ से ही अनेक विचार सुझाए गये हैं। किन्तु कोई आशाजनक सफलता अभी तक प्राप्त नहीं की जा सकी है। यह कहा जाता है कि विश्व सरकार की स्थापना का दृष्टिकोण हम काम को करने के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि इस विषय पर भारी साहित्य उपलब्ध है। विश्व सरकार की मान्यता का प्रधान महत्व इस बात में निर्भर है कि इसे सर्वसम्मति से शक्ति के प्रबन्ध की समस्या का एक उचित सैद्धान्तिक सुधार माना जाता है। यह स्वीकार किया जाता है कि इस समय स्सार में एक प्रकार की अराजकता वर्तमान है, इसके कारण युद्ध अनिवार्य सा बन जाता है। युद्ध को रोकना एक भारी आवश्यकता बन गया है। इस लक्ष्य को विश्व सरकार की स्थापना के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। 'नीलिक रूप से नवीन' इस व्यवस्था की स्थापना विश्व-व्यवस्था (World-order) का आवश्यक और सम्भवतः पर्याप्त साधन कहा जाता है। अल्बर्ट आइन्स्टीन ने कहा था कि "राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों में अभी तक पूर्ण रूप से अराजकता व्याप्त है। मेरा विश्वास नहीं है कि हमने पिछले कुछ हजार वर्षों से इस क्षेत्र में कोई वास्तविक प्रगति की हो।"²

1. Morgenthau, Politics among Nations P. 470.

2. Otto Nathan and Heinz Norden. eds, Einstein on Peace, P. 494.

(४) सामूहिक सुरक्षा का अगला कदम

(World Government is next to 'collective security')

विश्व सरकार की मान्यता को शक्ति सन्तुलन तथा सामूहिक सुरक्षा की मान्यता से नवीन माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के गम्भीर विचारविमर्श में इसका प्रभाव अभी बढ़ने लगा है। शक्ति सन्तुलन को आधुनिक विश्व व्यवस्था की परम्परावादी मान्यता (Traditional concept) कहा जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा की मान्यता ने प्रथम विश्व युद्ध के समय सैद्धान्तिक चित्र ग्रहण किया और विश्व सरकार की संभावना तथा संगठित समर्थन द्वितीय विश्व युद्ध के साथ प्रारम्भ हुआ जबकि शीत युद्ध ने जोर पकड़ा था। विश्व सरकार का मान्यता दो दृष्टियों से शक्ति सन्तुलन एवं सामूहिक सुरक्षा से आगे का कदम माना जा सकता है। प्रथम, यह साहित्यिक इतिहासक्रम में एक वाद की मान्यता है। द्वितीय, यह शक्ति के केन्द्रीकरण का प्रतीक है। शक्ति सन्तुलन ने शक्ति के केन्द्रीकरण को मिटा दिया था, सामूहिक सुरक्षा ने इसको पुन स्थापित किया तथा विश्व सरकार की मान्यता में शक्ति का एकाधिकार (Monopoly of Power) स्थापित हो गया है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना करते समय प्रायः यह कहा जाता है कि इसने शक्ति सन्तुलन द्वारा स्थापित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था का सही विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। विश्व सरकार की मान्यता इस आलोचना से बच जाती है तथा सामूहिक सुरक्षा की अपूर्णताओं को दूर करने का प्रयास करती है।

(५) विश्व सरकार एक संघात्मक व्यवस्था है—

(World Government is a Federal System)

विश्व सरकार का रूप एकात्मक न होकर संघात्मक है जिसमें विभिन्न राज्य इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। संघवाद होने के कारण विश्व सरकार की मान्यता में विधेयात्मक एवं नियेयात्मक दोनों ही तत्वों को समाविष्ट किया जाता है। इसके अनुसार विश्व समुदाय की निर्मापक इकाइयों के ऊपर एक सर्वोच्च अभिकरण की स्थापना की जाती है तथा दूसरी ओर इसके अन्दर सम्प्रभु राष्ट्रों की शक्ति को कम करते हैं। विश्व संघ व्यवस्था के असांख्यभौतिक सदस्य का स्तर प्रदान किया जाता है। संघवाद में कार्यरूप में 'संमित केन्द्रीकरण' होता है। किन्तु प्रभावित क्षेत्र के अनंगत बहूत कुछ केन्द्रीकरण होता है। इस दृष्टि से विधि का शासन (Rule of Law) तथा निस्स्त्रीकरण (Disarmament) को विश्व सरकार की पूरक बुनियाद माना जाता है।

विधि के शासन द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता की स्थापना का प्रयास किया जाता है तथा निश्चयीकरण द्वारा इकाइयों की शक्ति को इतना कम कर दिया जाता है कि वह उस स्थापित सत्ता को चुनौती न दे सके। विश्व सरकार की मान्यता के विधेयात्मक एवं निषेधात्मक दोनों ही पक्षों का लक्ष्य विश्व में शान्ति और व्यवस्था कायम करना तथा युद्धों को दूर करना है। निषेधात्मक रूप से विश्व सरकार की योजना द्वारा राज्यों की विधायी सामर्थ्य को तथा सैनिक सामर्थ्य को इतना कम कर दिया जाता है कि वे प्रभावशाली युद्ध की योजना बनाने में असमर्थ रह जाते हैं। नार्मन कौसिन्स का कहना है कि "एक ऐसी सत्ता का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि राष्ट्रो से पूरी तरह न केवल उस यन्त्र को ले ले जो कि युद्ध थालू कर सकता है वरन् निर्णय लेने के उस यन्त्र को भी हस्तगत कर ले जिससे कि युद्ध को प्रारम्भ भी किया जा सकता है।"¹

(६) एक अनिश्चित मान्यता,
(An Indefinite Concept)

विश्व सरकार की मान्यता का चित्रण करते समय इसके समर्थकों ने इसके रूप तथा व्यवस्था का विस्तार में साथ वर्णन किया है किन्तु विश्व सरकार का यह नवजा व्यवहार जगत में यथार्थ सिद्ध होगा अथवा नहीं इस सम्बन्ध में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ लोग इसकी तुलना हवाई किले से करते हैं जो कि देखने में जिनना-सुभावना एवं उपयोगी है, व्यवहार में उतना ही अप्रयोज्य एवं अवास्तविक है, किन्तु दूसरी ओर विचारकों का यह वर्ण है जो कि विश्व सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अनिवार्य एवं एकमात्र आगामी विकास मानता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं राजनैतिक विचारक बर्ट्रैंड रसल का मत है कि आज के युद्ध इतने भयानक एवं बीभत्स हो गये हैं कि इसमें हारा हुआ तो नष्ट हो ही जाता है किन्तु जो जीतता है वह भी समाप्त हो जाता है। उनका निष्कर्ष है कि मानव जाति के सामने इस समय केवल दो ही विकल्प हैं—या तो विश्व सरकार की स्थापना करके शान्ति की व्यवस्था की जाय अथवा एक साथ विनाश के लिए तैयार रहा जाय। क्लॉड (Claude) के मतानुसार विश्व सरकार के केवल कुछ समर्थकों को ही निश्चित भविष्य में अपना आदर्श प्राप्त होने की आशा है। क्लार्क तथा शेन (Clark and Shen) ने एक आशाजनक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने बौद्धिक विचार विमर्श के बाद यह भविष्यवाणी की है कि सन् १९७५

तब विश्व सरकार की व्यवस्था क्रियान्वित हो जायेगी।¹ राबर्ट हट्चिन्स (Robert Hutchins) के शब्दों में “आज हमारे विश्वास का नारा यह होना चाहिए कि विश्व सरकार आवश्यक है इसलिए सम्भव है।” यह कहा जाता है कि विश्व सरकार के बारे में किया जाने वाला विश्व-व्यापी विचार-विमर्श दुनिया को छिन्न भिन्न करने की अनेकाएक होने के अवसर प्रदान करता है। गरहर्ट नीमेयर (Gerhart Niemeyer) के मतानुसार “अबकि आगामी अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के विरुद्ध निश्चित गारण्टी केवल विश्व सरकार की व्यवस्था द्वारा दी जा सकती है, वहा वर्तमान समय में विश्व की एकता भी सुलभ नहीं है।”² इस प्रकार विश्व सरकार की स्थापना की सम्भावनाओं पर दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। इसके सम्बन्ध में निरवधपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

विश्व सरकार की उपयोगिता

(The Utility of World Government)

विश्व सरकार का समर्थन जिन आधारों पर किया जाता है तथा उसकी जो प्रमुख विशेषताएँ वर्णित की जाती हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व सरकार की स्थापना के पश्चात् मानव-जाति इतने किस प्रकार लाभान्वित हो सकती है। आज की सबसे बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या विश्व में शान्ति स्थापित करने की है जिसकी तुलना में अन्य सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याएँ गौण बन जाती हैं। शान्ति स्थापित करने के लिए क्या स्थापित शान्ति को स्थायी बनाने के लिये द्वि-द्वयी कार्यक्रम अपनाया चाहिये। प्रथम, यह प्रयास किया जाये कि विश्व-समाज का कोई भी देश शान्ति भंग करने की इच्छा ही न करे। इनके लिए यह आवश्यक है कि युद्ध के आवर्षणों की शान्ति की उपलब्धियों की तुलना में इतना गौण बना दिया जाये कि कोई भी राष्ट्र स्वच्छता से ही इस मार्ग को अपनाना पसन्द न करे। साथ ही एक ऐसी सर्वोच्च संस्था का गठन किया जाये जो कि युद्धप्रेमी एवं शान्ति की भंग करने वाले राष्ट्रों की विद्याओं पर प्रतिबन्ध लगा सके।

दूसरे, राष्ट्रों के पास केवल इतनी शक्ति रखनी चाहिये कि वे युद्ध छेड़ने का साहस भी न कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर हम यह देखते हैं कि

1. Clark and Shon, World Peace through World Law

Pp Xlib-Lit.

2. Gerhart Niemeyer, World Order and the Great Powers

समानक व्यवस्था में इकाइयाँ आपस में अथवा केंद्र के साथ शानः हितानक युद्ध पर नहीं उतर आती। उनके बीच मतभेद रहते हैं, उनमें हित कभी २ परस्पर टकरा भी जाते हैं किन्तु उनके शक्तियों का निरन्तर बाधकीज द्वारा एवं वाद-विवाद द्वारा तय कर लिया जाता है। इनका कारण यह है कि राज्यों अथवा मध्य तो इकाइयों के पास केवल पुराने शक्ति होती है जो कि राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने का कार्य करती है, किन्तु केंद्र ने पाठ राज्यों से भिन्न दूसरी सैनिक शक्ति हावी है कि उसके डर से कोई भी राज्य शक्ति के आसार पर अवनति की रक्षा का प्रयास नहीं करता। ठीक इसी प्रक्रिया का अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञात जाने तो विश्व शांति हमारी बन सकती है। दूसरे माध्यम में यह कहा जा सकता है कि विश्व सरकार की मान्यता को व्यावहारिक रूप प्रदान करके शांति की जड़ों को अन्तराष्ट्रीय मूल में इसकी गहरी पहुँचाया जा सकता है कि जिस पर बड़े से बड़े तूफान का भी प्रभाव नहीं हो सके। जिस समय विश्व सरकार से प्राप्त होने वाले लाभों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन किया जा रहा हो उस समय हमारी कल्पना के मानन राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त होने वाली समस्त उपलब्धियाँ रहनी चाहिए।

विश्व सरकार द्वारा विश्व के नागरिक को वे सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो कि एक राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक राष्ट्र के नागरिक को प्राप्त होते हैं। दोनों के बीच अन्तर यह है कि विश्व सरकार के अधीन कोई भी नागरिक किसी अन्य नागरिक की हानि पर लाभ प्राप्त न करेगा जैसे कि कभी-कभी एक राष्ट्र के नागरिक को दूसरे राष्ट्र के नागरिक के विरुद्ध सुविधाएँ एवं विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि सरकार चाहे वह राष्ट्रीय हो अथवा अन्तराष्ट्रीय, सर्वत्र अपने प्रभाव क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम रखने का कार्य करती है। स्ट्यूवार्ट बोल (Stewart Bohl) के शब्दों में "सरकार का 'क्षेत्र' शान्ति का 'क्षेत्र' है। शहर, राज्य एवं राष्ट्र में जिस प्रकार शांति स्थापित की जाती है उससे तो सभी परिचित ही हैं। यदि इन्ने बड़े क्षेत्र पर किसी तरह सरकार की स्थापना की जा सके तो विश्व सरकार निश्चय ही शांति के लिए मार्ग है।" विश्व सरकार की अनेक उपलब्धियों में से कुछ प्रमुख का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—

(१) विश्व सरकार विश्वव्यापी अराजकता को दूर करती है

अराजकता, स्वाधीनता, नागरिक एवं हिंसक मनुष्य शक्ति एवं सम्पदा की प्राप्ति के लिए सर्वत्र दूसरों से झगडा करता रहता है। शक्ति द्वारा शक्ति

रहे हैं। नावें तथा स्वीडन के धारे में कार्ल डेस (Karl W Deutsch) ने बताया है कि उनके शान्ति सम्बन्ध अब अच्छे रहें हैं जबकि वे स्वतन्त्र सम्प्रदाय हैं। ऐसे सम्बन्ध उनके बीच तब न थे जबकि वे एक ही सरकार के अधीन थे। सरकार के बिना भी शान्ति रहती है। इस शान में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सैद्धान्तिक मान्यता गलत है कि बिना सरकार के मानवीय सम्बन्धों को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता।

(३) विश्व शान्ति का एक मात्र साधन है

यह माना जाता है कि स्थायी एवं सुरक्षित रूप से विश्व शान्ति को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी व्यवस्था के लिए विश्व सरकार के रूप में कोई सर्वोच्च सत्ता न हो जो कि शान्ति भंग करने वाले के लिए दण्ड व्यवस्था का विधान कर सके। क्लाड (Claude) के शब्दों में 'विश्व सरकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यवस्था उत्पन्न करने वाली सभी विकल्पित योजनाएँ अर्याप्त सिद्ध हुई हैं तथा यह उचित है क्योंकि यह इस कार्य के लिए एक सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है'। आइन्स्टीन (Einstein) ने बताया है कि जब सारा विश्व एक हो जाएगा, एक सरकार के अधीन हो जाएगा तो युद्धों का रूप आज के जैसा न रहेगा वह बदल जायेगा और एकीकृत विश्व-व्यवस्था में गृह युद्ध होंगे। ये गृह युद्ध परिणामों की दृष्टि से इतने भयानक होंगे कि कोई भी इनको करने का साहस ही न करेगा। यह विश्वास किया जाता है कि सध की विभिन्न इकाइया एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं छेड़ सकती। अतिराष्ट्रीय (Supranational) व्यवस्था द्वारा राष्ट्रीय युद्धों को न केवल अनावश्यक बना दिया जायेगा बल्कि उन्हें असम्भव ठहरा दिया जायेगा। जॉफ्री सेवर (Geoffrey Sawyer) का कहना है कि "किसी भी बड़े भयानक युद्ध की सम्भावना को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि सम्प्रभु आत्म-निर्णायक राज्यों की व्यवस्था को विश्व सरकार की स्थापना द्वारा स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता"। आइन्स्टीन का विचार था कि विश्व में वास्तविक सुरक्षा का प्रदत्त अन्तर्राष्ट्रीय सस्था के निर्माण द्वारा किया जा सकता है। यह सस्था इतनी शक्तिशाली होगी कि जो शान्ति को सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो।

विश्व सरकार द्वारा शान्ति की स्थापना के लिये किये गये प्रयासों की सफलता में कुछ विचारकों की सदेह रहता है। उनका मत है कि जब तक युद्ध एवं मन-मुटाद के कारण दो देशों के बीच में वर्तमान रहेंगे तब तक विश्व सरकार द्वारा कितनी भी कोशिशें कर ली जायें वे शान्ति को स्थायी बनाने में नाकामयाब रहेंगी। युद्ध को मानव की प्रकृति में निहित मानने वाले लोगों

का विश्वास है कि विश्व सरकार यदि युद्धों को सबमुक्त रोक देगी या समाप्त कर देगी तो वह कभी बन ही नहीं सकती है और यदि वह वास्तविक जगत में क्रियान्वित की गई तो कोई आशा नहीं है कि वह युद्धों को समाप्त कर देगी। काँजिंग (Cousins) का मत है कि विश्व सरकार शान्ति की गारंटी नहीं दे सकती और विश्व कानून युद्ध का दूर करने की एक आशा ही नहीं बन एकमात्र आशा है, एकमात्र अवसर है।

कोर्ड मेयर (Cord Meyer) का विचार है कि "राष्ट्रों में और राष्ट्रों के बीच तब तक कोई शान्ति नहीं रह सकती जब तक कि कोई स्थापित कानून न हो तथा यह ज्ञान न हो कि इन कानूनों का तुरन्त एवं निश्चित रूप से पालन भी कराया जा सकता है।" रेक्स (Reves) कहते हैं—'शान्ति कानून है, यह व्यवस्था है, यह सरकार है'। विश्व सरकार को एक सरकार के नाते शान्ति एवं व्यवस्था का कर्ता मान लिया जाता है। क्लॉड (Claude) महोदय कहते हैं कि यदि सरकार को शान्ति स्थापित करने वाले पत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है तो विश्व सरकार निश्चय ही युद्ध रोकने का एक प्रबल साधन है। विश्व सरकार द्वारा शान्ति स्थापित करने की आवश्यकता उतनी न रहेगी जितनी कि वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के होने पर रहती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों एवं समुदायों के बीच व्यक्तिगत सम्पत्ति के बारे में कितने झगड़े और संघर्ष होते रहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति या भूमि को हट्ट कर लेता है तो दूसरा पहले की सम्पत्ति या भूमि पर अपना अधिकार सिद्ध करता है किन्तु सार्वजनिक सम्पत्ति पर इस प्रकार का कोई विवाद नहीं होता। सड़क, बगीचा, बाजार एवं अन्य सार्वजनिक महत्व की उपयोगी वस्तुओं से सभी व्यक्ति बराबर लाभ प्राप्त करते हैं, किसी को कोई बाधा नहीं होती। इसी प्रकार जब सभी राष्ट्रों की व्यक्तिगत उपलब्धियों को सार्वजनिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया जायेगा तो मदमाव एवं मन मृदाव के कारण ही नष्ट हो जायेंगे।

अनेक बार एक देश युद्ध इसलिए छेड़ता है क्योंकि वह दूसरे राष्ट्र के खनिज पदार्थों या तेल के कूरा या महत्वपूर्ण बन्दरगाहों पर अपना अधिकार करना चाहता है किन्तु विश्व सरकार व्यवस्था के अभाव में सभी चीजें स्वतः ही उस राष्ट्र के स्वामि बन आ जायेंगी, वह इनका उपयोग करने में अधिकार न रहेगा। युद्ध कभी-कभी एक प्रदेश विशेष को जीतने की नीति के लिए भी किया जाता है। भारत-चीन मोरा विवाद तथा भारत-पाक काश्मीर विवाद के समान इस प्रकार के अनेक उदाहरण देये जा सकते हैं। छोटे-छोटे भूमि के भागों के लिए लाखों निरपराध, निरपराध और अनजान लोगों का मृत्यु

बहाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। यह सब किसलिए होता है ? एक देश के मैनिक दूसरे देश के अनजान मैनिकों पर गोलियों और बमों की बौटारें क्यों प्रारम्भ कर देते हैं ? इस सबका कारण खोजने के लिए हमे आल्ट्रग्रस हथमले आदि लेखकों की रचनाओं पर ध्यान देना होगा। ये लेखक राष्ट्रीयता की भावना, मिथ्या राष्ट्र अभिमान को युद्ध और सघर्ष के प्रमुख कारण मानते हैं। विश्व सरकार के अधीन युद्ध का यह मूल तोन मूख जायेगा और दुनिया में शान्ति, समृद्धि एवं प्रसन्नता का साम्राज्य हो जायेगा। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व सरकार द्वारा युद्धों को समाप्त करके विकास के स्वाभाविक मार्ग को रोक दिया जायगा जिससे कि सविनशाली की विजय होती है और योग्यतम ही जीवन रहता है। इसी आधार पर विश्व सरकार की आलोचना करने वालों में युद्धप्रिय एवं फासीवादी प्रवृत्तियों के समर्थकों का नाम उल्लेखनीय है। ये लोग मानते हैं कि विश्व का शांतिकरण (Pacification) कर दिया गया तो इसने एक प्रकार की निर्जीव एकरूपता (Dull uniformity) जन्म लेगी और पतयेगी जिसमें स्वतन्त्र शक्तियों का विकास असम्भव बन जायेगा। किन्तु विश्वयुद्धों एवं क्षत्रीय युद्धों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग यह जानते हैं कि ये तब तक कितने भ्रामक तथा मिथ्या हैं जोर 'शान्ति' विश्व के लिए कितनी लाभदायक एवं मूल आवश्यकता है।

(४) विश्व की प्रगति का प्रतीक

युद्धों द्वारा न केवल प्राप्तियों (Achievements) का ही विध्वंस किया जाता है किन्तु उन तत्वों एवं परिस्थितियों को भी मिटा दिया जाता है जिनके फलस्वरूप विश्व की सम्पत्ता एवं सभ्यता आगे बढ़ती है। दूसरे शब्दों में युद्ध द्वारा एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रगति का वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। विश्व सरकार की स्थापना करके इस चक्रव्यूह को असम्भव बनाने का प्रयास किया जाता है। एक ओर से तो युद्ध का समाप्त करके विश्व सरकार द्वारा उन सभी घातक जीवों एवं जहरीलों चीजों को दूर कर दिया जाता है जो कि शान्ति के पौधे को विकसित एवं प्रस्फुटित होने में घातक बनते हैं। दूसरी ओर साद देकर एवं अनुकूल वातावरण तैयार करके उस पौधे को पुष्पित एवं फलवित होने की सामर्थ्य प्रदान की जाती है। इस प्रकार निषेधात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही रूपों में विश्व सरकार द्वारा प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा।

निषेधात्मक रूप से विश्व सरकार द्वारा उस भारी विनाश एवं विध्वंस से मानव जाति को बचा लिया जाता है जो कि युद्ध के कारण पैदा होती

है। विगत दो विश्व-युद्धों के अनुभवों द्वारा मानव जाति यह भली-भाँति समझ गई है कि इनमें सदियों में अजित की गई सम्पत्ति को किस प्रकार से नष्ट कर दिया जाता है। जॉन स्ट्रेची (John Strachey) के शब्दों में “दो युद्धों से योरोपीय सभ्यता को होने वाले नुकसान की यातना को हम सभी न अनुभव किया है और अब पुनः हम इस प्रकार के युद्धों में सम्मिलित होना नहीं चाहते।”¹ युद्ध के कारण होने वाले विनाश का गुण एव परिणाम वर्तमान काल में कई गुना बढ़ गया है। जिस प्रकार प्लेग आदि महामारियों से चटापट मौत होने लगती है उसी प्रकार युद्ध में भी व्यवन के जीवन का मूल्य बहुत घट जाता है। कहा जाता है कि १३४८ तथा १३४९ में ब्रिटेन में जब प्लेग, महामारी का प्रकोप हुआ था तो वहाँ की एक तिहाई या तीन चौथाई जनता मौत के घाट उतर गई थी। इसी प्रकार आज के अमेरिका के लगभग १८ करोड़ मूल निवासियों में से ६ करोड़ से लेकर १२ करोड़ तक को ग्लूकस्टर युद्ध के कारण मौत के घाट उतरना पड़ सकता है। अणु शक्ति के प्रयोग से पूर्व युद्ध द्वारा जो क्षति होती थी उसे धीरे-धीरे पूरा कर लिया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा जापान, सोवियत रूस और अमेरिका को जो क्षति भुगतनी पड़ी थी वह काफी थी। इन देशों की अधिकांश जनता को युद्ध में घायल या मृत होना पड़ा। अनुमान किया जाता है कि हम जो इस युद्ध में एक करोड़ बीस लाख से लेकर दो करोड़ चौबीस लाख देशवासियों की जान से हाथ धोना पड़ा था। इसके साथ-साथ उसके लगभग ४० प्रतिशत उत्पादन के साधनों को नष्ट कर दिया गया। जर्मनी के करीब चालीस लाख व्यक्ति युद्ध में काम आये या घायल हो गये। इसी प्रकार जापान के शहरों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी। हिरोशिमा और नागासाकी के क्षेत्रों में मनुष्य और उसकी सम्पत्ति को जो राख बनी वह हृदय द्रावक थी। किन्तु फिर भी इनकी सारी मौतों के बाद तथा उद्योग-धन्यों के अस्त-व्यस्त हो जाने के बाद भी बहुत थोड़े से ही समय में इन देशों ने वह प्रगति कर दिखाई जो अद्वितीय थी। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध द्वारा आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक एवं सैनिक आदि सभी दृष्टियों से कुचले गये जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में इतनी प्रगति की कि वह विश्व-विजय के अपने स्वप्न को साकार करने का दुस्साहस करने लगा। इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि ‘यदि एक देश उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचना चाहता है तो उसको युद्ध का साधन अपनाना चाहिए और युद्ध में वह चाहे हारे या जीते, उसकी प्रगति का मार्ग खुल जायगा, उसकी प्रगति की गति तीव्र हो जायेगी?’

बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक, हो सकता है कि इन निष्कर्ष में थोड़ी बहुत भी सत्यता रही हो, किन्तु बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में जो विभिन्न वैज्ञानिक विकास हुए तथा युद्ध का जो रूप सामन आया उसे देखकर युद्ध के परिणामों के बारे में किसी प्रकार का भी संदेह वांछनीय नहीं रह जाता। आधुनिक तकनीकी व संहार लड़ा जान वाला तृतीय विश्व युद्ध विश्व की रसातल में पहुँचा कर पृथ्वी की उसी स्थिति में ला देगा जिसमें कि वह अपने जन्मदाता सूर्य से अलग हाते समय थी। यह कथन सत्यता से परे नहीं है कि 'यदि चतुर्थ विश्व युद्ध लड़ा गया तो वह जगल के वृक्षों से तोड़ी गई छड़ियों से लटा जायगा।' अर्थात् तृतीय विश्व युद्ध, यदि वह कभी हुआ, तो मनुष्य की समस्त सन्ध्या एवं सभ्यता का नाश कर देगा और सदियों बाद पुनः पृथ्वी पर जीवन की सृष्टि होगी। इस तथ्यपूर्ण आशंका को प्रभावहीन बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संसार में विश्व सरकार की स्थापना की जाये।

निर्देशात्मक रूप से विश्व सरकार का दूसरा उपयोग यह है कि इसके द्वारा विश्व की अर्बव्यवस्था को अन्त-व्यस्त होने से बचाया जा सकता है। युद्ध में करोड़ों रुपये प्रति दिन का व्यय किया जाता है। यह व्यय ऐसा होता है कि जिसका प्रतिकूल कभी प्राप्त नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आने वाली विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा उसने उत्पन्न होने वाली यातनाओं से हम सभी अलोकप्रकार परिचित हैं। भारत का संघर्ष के कारण हाल ही में दोनों राष्ट्रों की जितनी क्षति उठानी पड़ी है उसको आने वाले अनेक वर्षों में पूरा किया जा सकेगा। इन तथ्यों के समय भारत को चतुर्पक्षीय व्यवस्था पर कई बार विचार किया गया और प्रत्येक पुनर्विचार के समय विकास कार्यों पर कटौतियाँ करके रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की ओर योजनाओं को मोड़ दिया गया। देश रक्षा का एक बहुत बड़ा भाग मनुष्य संघर्षों एवं रक्षा व्यवस्था में व्यय करना पड़ा। यह ठीक है कि ऐसा करने के लिए भारत मजबूर हो गया था किन्तु यह मजबूर होना ही विश्व सरकार का उत्तरदायित्व है। गोमा विवाद एवं प्रयोग के विवेक से स्वीकार्य हथियारों तक तक नहीं बढ़कर जाना कि गोमा सरकार एक दृष्टि के नीचे नहीं आ जाता और एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिक का भा संघर्ष और व्यावहारिक अर्थों में अपने समान नहीं मानते पाते।

कुछ विचारकों का मत है कि विश्व सरकार ही साक्षात् है निम्न भविष्य में मनुष्य का प्राण न कर सके अथवा यह कभी भी व्यवस्था को परिधि में लाकर न हो सके किन्तु विश्व की इसी वृद्धि एवं विस्तार में दिने गये तर्कों को दखना उनका मूल प्रश्न में परीक्षण करता है कि विश्व

है क्योंकि इसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर लोक दृष्टिकोणों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। विश्व सरकार के विचार का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण (एक साथ ही इसकी कमजोरी भी) तत्त्व इसका विस्तृत रूप है।

यदि विश्व सरकार स्थापित कर दी जाये तो यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की सभी समस्याओं को तय कर देगा। अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें तो दूर की चीज हैं यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की ही मिटा देगा। इसमें कोई सम्प्रभु राज्य ही न रहेगा इसलिए राज्यों के बीच झगड़े उठने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विश्व की सारी शक्ति केवल एक ही इकाई में केन्द्रित कर दी जायेगी। यह एक शान्तिकारी बरदान है। विश्व के इतिहास में आज तक यथास्थिति (Status quo) का इतने शान्तिकारी रूप में परिवर्तन कभी नहीं हुआ था। बैसे परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ एकाएक हो जाते हैं, कुछ धीरे-धीरे किन्तु कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होता जो कि विश्व को ऐसा बना दे जैसा कि वह बल या कुछ वर्ष पूर्व या कुछ दशकों पूर्व नहीं था। विश्व सरकार के इस व्यावहारिक रूप को देख कर ही कुछ विचारक अर्ध विश्व सरकार (Quasi-World Government) के विचार का प्रतिपादन करते हैं किन्तु यह विचार भ्रामक है क्योंकि सच्चे अर्थों में जिसे विश्व सरकार कहा जाता है वह तो रहेगी या नहीं रहेगी—इन दोनों अवस्थाओं के बीच का विकल्प नहीं हो सकता कि कुछ अर्थों में विश्व सरकार रहे और दूसरे अर्थों में वह न रहे, अथवा कुछ स्थानों पर रहे और बाकी स्थानों पर न रहे। विश्व सरकार का अस्तित्वनात्मक रूप स्वयं में अविरोधी है।

(५) विश्व सरकार और राष्ट्रीय सरकारें

विश्व सरकार के समझने के मतानुसार जो महत्व एक उपयोगिता राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों के अस्तित्व की है वही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सरकार की ही रहेगी अर्थात् राष्ट्रीय समाज का सदस्य होने पर व्यक्ति में अपने राष्ट्रवासियों के प्रति एकता की भावना आती है क्योंकि उसके रीति-रिवाज, भाषा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक एवं राजनैतिक दर्शन तथा राष्ट्रीय प्रतीक उनसे मिलते हैं और वह एक से अलग पटना है, समान रेशमो मुनता है, समान छुट्टियाँ मनाता है और समान व्यक्तित्वों की पूजा करता है। यद्यपि एक राष्ट्र में अनेक समाज वाले लोग रहते हैं और उनके आपस में हित परस्पर टकराते हैं किन्तु फिर भी उनके बीच सामंजस्य बना रहता है। राजनैतिक दल धार्मिक प्रभाव, जातीय समुदाय, क्षेत्र और प्रदेशों के आधार पर यद्यपि उनके बीच भारी असमानतायें एवं परस्पर विरोधी तत्व स्थित रहते हैं किन्तु फिर भी उनके ये मतभेद एवं भिन्नतायें प्रायः हिसाबनक

रूप धारण नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच अनेको भिन्नताएँ, विरोधी स्वार्थ एवं असमान स्थितियाँ रहती हैं जो कि आजकल प्रायः हिंसात्मक रूप में अभिव्यक्त होती हैं किन्तु विश्व सरकार की स्थापना के बाद यह हिंसात्मक रूप परिवर्तित होकर सामंजस्यपूर्ण बन जायेगा और तब विश्व के प्रति राजभक्ति को विश्व के नागरिक का सबसे प्रधान कर्त्तव्य माना जायगा। विश्व की एकता को चुनौती देने वाले किसी कार्य को सहन नहीं किया जायेगा तथा केवल उन्हीं हितों, विचारों और राजभक्तियों को चलने दिया जायेगा जो विश्व की एकता को खतरा पैदा न करें। इस प्रकार विश्व सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राजभक्ति (Supranational Loyalties) का समर्थन किया जाता है।

राष्ट्रीय सरकारों की भाँति विश्व सरकार द्वारा न्याय की स्थापना के लिए प्रयास किये जायेंगे। एक राष्ट्र में अल्पमत एवं पिछड़े वर्गों की भी सरकार से यह आशा रहती है कि उनको न्याय प्रदान किया जायेगा तथा उनके हितों और दावों की अवहेलना करने की बजाय उन पर यथोचित ध्यान दिया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें सार्वजनिक न्याय की व्यवस्था के लिए कानूनों का निर्माण करती हैं तथा उनका पालन कराती हैं और किसी वर्ग विशेष की माँगों पर भी ध्यान देती हैं उसी प्रकार विश्व सरकार द्वारा भी सामान्य हित के विषयों पर समस्त विश्व को समान न्याय प्रदान किया जायेगा। और यदि कोई एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्र मिल कर अथवा राष्ट्रों से भिन्न किन्तु सामंजस्यपूर्ण कोई विशेष न्याय की माँग करते हैं तथा वह माँग यदि उचित एवं सगत है तो विश्व सरकार उस माँग पर भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान देगी, करना शांति के लिए खतरा हो सकता है।

राष्ट्रीय सरकार के पास भारी शक्ति होती है जिसके आधार पर वह शांति की स्थापना करती है और शान्ति भंग करने वाले किसी भी प्रयास को कुचल देती है। इसी प्रकार विश्व सरकार के पास भी शक्ति रहेगी और इस शक्ति के आधार पर वह अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था को बाधा पहुँचाने वाले तत्वों का दमन कर देगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व सरकार की शक्ति के दो रूप होंगे। प्रथम, उसके पास सैनिक शक्ति केन्द्रित हो जायेगी और दूसरे विश्व लोकमत भी उसके हाथ में रहेगा जिसकी अवहेलना करने का कोई भी राष्ट्र साहस नहीं कर सकेगा। एक राष्ट्र जो लोकमत के विरोध का शिकार नहीं बनना चाहता है, आवश्यक रूप से विश्व सरकार द्वारा स्थापित व्यवस्था का अनुशीलन करना रहेगा और इस प्रकार विश्व के सभी राष्ट्र शांति और कानून के अनुशासन में रह सकेंगे।

राष्ट्रीय दानि वी सीधार्थ और व्यवस्था की स्थापना के लिए जिन प्रकार काय एव आनन्दक साधन है उनी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय दानि एव व्यवस्था भी विश्व राज्य एव विश्व सरकार की स्थापना के बाद ही हो सकती है। एक राष्ट्र की दानि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज की लोड-फोड के धनेक ताव दत्तमान रहते हैं जिनका समन करने के लिए एक दानिशाही विश्व सरकार परम आवश्यक है। वर्ण, जाति, धर्म, क्षेत्र एव अन्य राजनैतिक प्रगडो से विश्व समाज को छिन्न-भिन्न करने वाले अनेक तत्वों की सृष्टि होती है जो कि जाति, संघर्ष और युद्धों के रूप में प्रतिफलित होते हैं। विश्व सरकार द्वारा इन सभी तत्वों पर अकुश रखा जायेगा।

विश्व सरकार के रास्ते और साधन

(The Ways and Means of World Government)

विश्व सरकार उपयोगी है तथा विश्व दानि और व्यवस्था की स्थापना के लिए यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विभिन्न विचारक इस बात से सहमत होते हुए भी विश्व सरकार के विचार को अधिक महत्त्व देना उचित नहीं समझते क्योंकि उनके मतानुसार इस विचार को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता तथा वास्तविक जगत में नहीं उतारा जा सकता। केवल कहना लोक में ही इसे रण-विरणे स्थलों द्वारा संचालित जा सकता है किन्तु जब समय की घरती पर इसे साया जायेगा तब न वो वे रंग ही रहेंगे और न इसका जीवन सुखम सौंदर्य ही। व्यावहारिक समय के शोर्कों के आगे चलना लोक की यह बालू की दीवाल तुरन्त ही ढह जायगी।

किन्तु इन विचार के समर्थकों से भिन्न विचारकों का एक दूसरा वर्ण भी है जिनका यह निररात है कि विश्व सरकार आज नहीं तो कल अवश्य आकर रहेगी क्योंकि विश्व उसके बिना पायग नहीं रह सकता। राष्ट्रीयता, सहन की लोड, सैदान्तिक मनभेद, विज्ञान के आविष्कार आदि से युक्त विश्व आज जिस पौराटे पर आकर लडा हुआ है वहा से चूतानी आत्मनिर्भर भगर राज्यों की धोर लोड पाने का कोई मार्ग नहीं है, केवल दो ही पथ सीधे दिखाई दे रहे हैं-एक ससार को विनाश की ओर ले जायेगा, जहा मनुष्य की अब तक अजित सम्पना एन सहृते एक अनीत की गापा बन जायेगी जिसे न कोई बहने वाला ही मीगेगा और न ही गुनने वाला। दूसरा मार्ग है विश्व सरकार का दानि और व्यवस्था का, प्रगति और उद्धान का। अब निर्णय की घडी आ चुकी है। पहला मार्ग तो गहज है, उत्तक लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है वह तो विश्व की स्वाभाविक गति का प्रतीक है। मनुष्य जाति को इन मार्ग की स्वाभाविकता में आगहक रह कर विश्व सरकार

की स्थापना का प्रयास करना चाहिये ताकि ससार में चैन और अमन रह सके तथा आगामी पीढ़ियाँ वर्तमान के निर्णायकों की बुद्धि एवं कुशलता के प्रति आभार प्रदर्शित कर सकें।

अब प्रश्न यह उठता है कि माना हमने दूसरा मार्ग अपना भी लिया तो विश्व सरकार की स्थापित केंस किया जायगा? विश्व सरकार युग की आवश्यकता है, उपयोगी है एवं अपरिहार्य है आदि बातों से विश्व सरकार स्थापित तो नहीं हो जाती। बहुत सी चीजें आवश्यक एवं अपरिहार्य होते हुए भी अप्राप्य या दुर्लभ होती हैं, विश्व सरकार की भी एक ऐसी ही चीज कहा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक तथा मानवशास्त्री दार्शनिकों ने विश्व सरकार के रूप एवं इसे प्राप्त करने के उपायों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। विश्व सरकार की स्थापना से सम्बन्धित इन विभिन्न विचारों के सागर का मग्न्यन करने के बाद निष्कर्ष रूप में जो सावन हमारे सामने आते हैं उनकी मूल रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है —

- (1) रचनात्मक,
- (11) विकासत्मक और
- (111) मध्यस्थिति वाले।

विश्व सरकार की रचना से सम्बन्धित ये तीनों ही प्रकार के साधन सरकार की प्रकृति से सम्बन्धित हैं। जो विचारक यह मानते हैं कि सरकार एक व्यावहारिक बला है तथा मनुष्य की उपयोगिता के अनुसार उसे किसी भी रूप में मोड़ा जा सकता है वे यह स्वीकार करते हैं कि सरकार 'आविष्कार' का परिणाम है। मनुष्य द्वारा इनका निर्माण किया जाना है तथा यह उसी की इच्छा पर अवलम्बित है कि वह सरकार बन या न बनाये तथा किस ढंग पर और कैसे तरीके से उसे बनाये। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि यदि आप एक श्रेष्ठ सरकार की रचना करना चाहते हैं तो पहले लोगों को समझाइये कि यह श्रेष्ठ सरकार है, इसके बाद उन्हें उस सरकार को अपनाने पर राजी करियें, इस प्रकार आप एक सरकार की रचना करने में सफल हो जायेंगे। विश्व सरकार भी इसी ढंग से बनाई जा सकती है। विश्व सरकार की स्थापना का यह रचनात्मक विचार है।

उपयुक्त से मिला विचारकों का दूसरा वर्ग सरकार की विकास का परिणाम और इस प्रकार सरकार के विज्ञान को प्राकृतिक इतिहास का एक भाग मानता है। इस वर्ग के विचारकों का विश्वास है कि सरकार किसी की इच्छा का विषय नहीं है। वे जैसी भी मिल जायें हमको अपना लेनी चाहिए। पूर्वनिर्धारित रूपों के अनुसार सरकारों का निर्माण नहीं किया जा सकता।

वे बनाई नहीं जाती, बरन् उन्हें ही होती हैं। मूल राजनैतिक समस्याओं का जन्म सामयिक विचार का परिणाम होता है। यह लोगों की प्रकृति और उनके जीवन, उनकी आदतों, मूलप्रवृत्तियों, अचैनन आवश्यकताओं एवं इच्छाओं तथा उनके लक्ष्य आदि से प्रभावित होती है। यदि एक सरकार लोगों की भावना, प्रवृत्ति एवं लक्ष्यों के विमूढ़ निमित्त कर दी गई तो राज्यों में नानि हो जायेगी तथा हिनात्मक रूप से उसका विरोध किया जायगा।

विचारकों का एक तीसरा वर्ग भी है जो कि उक्त दोनों वर्गों के बीच की स्थिति का अग्रगण्य है। इस वर्ग के लोगों की यह मान्यता है कि उक्त दोनों ही मन आधिक रूप से सत्य हैं। राजनैतिक समस्याएँ मनुष्य द्वारा निमित्त होती हैं तथा उसी की इच्छा पर अवलम्बित रहती हैं किन्तु ये राजनैतिक समस्याएँ स्वतः ही कार्य नहीं करती, इनके सफल संचालन के लिए कुछ अनुकूल स्थितियाँ का होना आवश्यक है। कोई भी सरकार तनी टिक सकती है जबकि वह कुछ शक्तों को पूरा कर सके, यदि ऐसा न किया गया तो सरकार असफल हो जायेगी।

इस प्रकार सरकार की प्रकृति के सम्बन्ध में मत वैभिन्न्य है और इसी आधार पर उसकी रचना के बारे में भी अलग-अलग विचार हैं। "विश्व सरकार का मनुष्यों द्वारा निर्माण किया जायगा, विश्व सरकार की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वह स्वतः ही विकसित होगी, विश्व सरकार का निर्माण कर दिया जाये और उनकी शक्तों का विचार किया जाय ताकि वह सफल हो सके।" इन तीन विचारों के मानने वाले विचारकों ने विश्व सरकार की प्राप्ति के प्रयासों का अपने-अपने ढंग में वर्णन किया है। विश्व सरकार के जन्म से सम्बन्धित विचारकों को हर्ट्सेन (Frederich H. Hartmann) महोदय ने दो भागों में विभाजित किया है—

१. विकसमील विश्व सरकार के समर्थक (Evolutionary world Govt. advocates)
२. प्रान्तिकारी विश्व सरकार के समर्थक (Revolutionary world Govt. advocates)

प्रथम श्रेणी में आने वाले विचारक विश्व में संधवाद की स्थापना के लिए मनुष्य राष्ट्र-त्व को बहाल देना उचित मानते हैं तथा इसमें वे विश्व सरकार के प्रारम्भिक रूप की शलक पाते हैं। इनका विचार है कि विश्व सरकार की ओर तो हमारा विचार दिया जाता है अर्थात् एक संध के रूप में दुनिया का एकदम परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रथम

परिवर्तन के लिए समुक्त राष्ट्र सत्र को एक केन्द्रबिन्दु के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ये विचारक विश्व सरकार के समान रूप का समर्थन करते हैं।

हमारी श्रेणी में आने वाले विचारक विश्व को एकदम परिवर्तित करके विश्व राज्य का रूप देना चाहते हैं और विश्व सरकार की रचना करना चाहते हैं। एमरी रेव्स (Emery Reves) ने अपनी पुस्तक एनेटोमी ऑफ पीस (Anatomy of Peace) में यह सुझाव दिया कि रूस और अमेरिका को अन्य देशों के साथ एक सत्र में सम्मिलित हो जाना चाहिए। दूसरे कुछ विचारकों का मत है कि रूस के नेतृत्व में और अमेरिका के नेतृत्व में अलग-अलग दो विश्व सरकारें यदि बना दी जायें तो इस प्रयास का अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि तृतीय विश्व-युद्ध छिड़ जायगा। इस प्रकार विश्व सरकार की प्रतीक्षा करने वाले विकासवादी विचारक विश्व विनाश की एक जोखिम (Risk) को लेकर आगे बढ़ते हैं। युद्ध के समाप्त होने से कुछ पूर्व तक विश्व सरकार से सम्बन्धित यह कान्तिकारी विचार अपने चरम उत्कर्ष पर था।

उक्त दोनों ही विचारों की अपनी-अपनी विशेषताएँ एवं अभाव हैं। विकासवादी पक्ष के समर्थकों की यह भावना सत्य है कि वर्तमान विश्व के समस्त मध्यों को मिटा कर उनके स्थान पर एक रान में ही सामरस्यपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना नहीं की जा सकती। ये विचारक मानते हैं कि राष्ट्रसंघ (League of Nations) तथा संयुक्त राष्ट्र मण्डल (United Nations Organisations) दोनों ही सत्यायें कान्तिकारी नहीं थीं। दूसरी ओर कान्तिकारी व्यवस्था के समर्थकों का यह विचार सही है कि प्रजातन्त्रों की आशिक विश्व सरकार या एटलांटिक सत्र योजना या चनिष्ठ तथा दो गुटों की अर्ध स्थायी सन्धि व्यवस्था आदि से विश्व शांति की दिशा में अधिक प्रगति न होगी किन्तु यह हो सकता है कि वे सदस्य राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था कर दें। किन्तु इस प्रकार के पन्नाम विश्व को राष्ट्र रान में दो विरोधी गुटों में विभाजित कर देंगे तथा शक्ति सन्तुलन की बीच लोचशीलता न रहेगी।

उपर्युक्त विचारों से प्रभावित होकर अनेक विचारक विश्व सरकार के प्राप्ति करने की नव उपायों का समर्थन करते हैं उनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं—

(१) विश्व विजय द्वारा

(Through World Conquest)

विश्व सरकार में दो बाँटों का होना परम आवश्यक है। पहली तो यह कि एक स्थान पर शक्ति का केन्द्रीकरण हो अर्थात् सभार में एक सत्ता

ऐसी हो जिनके हाथों में शक्ति का एकाधिकार (Monopoly of Power) हो जाये। इनसे यह कि सत्तार के सभी राष्ट्रों के पास से सम्प्रभुता को छीन दिया जान क्योंकि यह एक विवेका दात होता है जिसके रहने पर एक राष्ट्र सभों की भाँति मरझुर बन जाता है किन्तु दात के टूट जाने पर सभ के साथ बापक को भी खेनन दिया जाय तो कोई हानि न होगी। विश्व सरकार की स्थापना के इन दातों परन्तुओं की उपस्थिति के लिए विश्व-विषय की कलना को साकार कर देने में साध्यता बताई जाती है। यह कहा जाता है कि कोई भी एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों का समूह, जो कि विश्व सरकार के निर्माण की सबसे हृदय से इच्छा करता हो, सैनिक शक्ति का सहारा ले सकता है। शक्ति के जोर से वह उस राष्ट्र या राष्ट्रों के समूह को प्रभावित कर सकता है जो विश्व सरकार की स्थापना करना नहीं चाहते। इस प्रक्रिया में विश्व सरकार के दोनों ही पहलुओं की पूर्ति हो जाती है। जो देश शक्ति का सहारा लेकर सत्तार को जीतने का अभियान प्रारम्भ करेगा उसकी सत्तारगर्भे निरन्तर उसे शक्तिशाली बनाती जाएंगी, उसमें धीरे-धीरे विश्व की शक्ति का केन्द्रीकरण होता चला जाएगा। दूसरी ओर जिन राष्ट्रों को विविध बनाया गया है वे शक्तिशाली राष्ट्र के अधीनस्थ बन जाएंगे, उनका सम्प्रभुता रूपी विवेका दन्त टूट जाएगा और शक्ति के लिए जो सत्तार या बहु दल जाएगा।

सत्तार के सावर्गिक इतिहास में विश्व विषय के स्वर्णों तथा उनकी सत्तार करने के प्रयासों वाले पहलु पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो हम पायेंगे कि ऐसे प्रयासों द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सके थे। सिन्दर से लेकर एडॉल्फ हिटलर तक अनेक व्यक्तियों एवं राज्यों ने विश्व साम्राज्य के स्वप्न देखे हैं। उन्होंने सैनिक शक्ति के आधार पर सभी विश्व को विजय करने का अभियान गुरु किया किन्तु इनने से अधिकांश के ये अभियान उनके जीवनकाल में ही अलक्ष हो गये। पाश्चात्य सभ्यता को रोमन साम्राज्य की दीर्घकालीनता पर गर्व है। रोमन साम्राज्य के समय विश्व सभ्य इतने दिनों तक चला रहा, इसका कारण दो परिवर्तनों को बताया जाता है। रोमनों ने जिन देशों को जीता, वहाँ के लोगों को, यदि वे सम्य थे तो अपने देश बना लिया और यदि इतने सम्य न थे तो उनको दास बना लिया। विजय के दौरान रोमन विदेशियों ने अपने आप को भी विदेशों के आचार-विचार से प्रभावित होने दिया। इस प्रकार दोहरी प्रक्रिया द्वारा सभ्यता स्थापित करते रोमन साम्राज्य को इतने दिनों तक स्थायी रखा जा सका था। वहाँ एक निजी-जुनी नई सभ्यता का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त विश्व विजय के प्रायः अन्य सभी प्रयास सफल होने

के छोड़े समय बाद ही टिज़ मिश्र हो गये। इसका कारण यह था कि विजयी देशों के नैतिक मूल्य तथा राजनैतिक त्रिज विजित देश में भिन्न होने थे और इस कारण विजित राष्ट्र मईव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता था कि किसी प्रकार विजिता की शक्ति का जगह नो बाट दिया जाये। जब विजयी देश की सैनिक शक्ति साम्राज्य का विस्तार करता रोर देती है या ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है तो विजित राष्ट्रों में शक्ति का उद्वेग प्रारम्भ होता है वे दूसरे अविजित राष्ट्रों के साथ मिल कर विजिता राष्ट्र की सफलताओं को धूल धूमरित कर देते हैं।

छोटे स्तर पर की गई विजय जा कि विजयी एवं विजित का सांस्कृतिक समन्वय करके नवीन समुदाय (Community) का निर्माण नहीं कर पाती उसमें गृह-युद्धों और भेद-भावों की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। यदि विजयी राष्ट्र के लोगों की शक्ति एवं सामर्थ्य विजितों की तुलना में कम है तो शीघ्र ही उस राज्य में क्रांति हो जायेगी। सोमित विजय के इन सभी परिणामों के साथ एक नवीन समुदाय का विकास नहीं किया जा सकता। मार्गेन्थो (Morgenthau, Hans J) के कथनानुसार "ये विश्व राज्य विश्व समुदाय (World Community) के स्वाभाविक विकास नहीं थे किन्तु ऐसी शक्ति का निर्माण वे जो विभिन्नताओं से पूर्ण राष्ट्रीय सभाओं पर उसकी इच्छा के विपरीत थोपी गई थी।"

इस प्रकार विश्व साम्राज्य या विश्व विजय के द्वारा विश्व राज्य एवं विश्व सरकार की स्थापना सम्भवे अर्थों में नहीं की जा सकती। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न कमियाँ पाई जाती हैं—

१ यह विश्व में शान्ति निमाग करने एवं ठो कश्मि रमने में सफल नहीं हो पाती। हर समय क्रांति, गृह युद्ध एवं फूट द्वारा उत्पन्न भगवों का मय बना रहता है, कमा कमो तो यह मय मयार्थ भी बन जाता है।

२ इस प्रकार से स्थापित विश्व राज्य का आधार शक्ति होता है, इच्छा नहीं। शक्ति के आधार पर स्थापित इस राज्य में गमानता और स्वतन्त्रता जैसे मूल सिद्धान्तों का कोई महत्त्व नहीं रहेगा। विजित राष्ट्र पराधीन, शोषित तथा पतनोन्मुख बन जायेंगे जबकि विजया राष्ट्र उच्छृङ्खल, मनमानी करने वाला, दमनकारी एवं अधिकाधिक शक्तिशाली बन जायेंगे। शक्ति व्यक्ति को अष्ट बना देती है और मागे विश्व की शक्ति का कुछ व्यक्तियों में ही केन्द्रीकरण अगुत्रम की भांति भयावह होता है।

३ महात्मा गांधी ने बताया था कि हम बुने मापनों द्वारा कभी भी अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इस आधार पर यह आपत्ति की जा

सकती है कि हिंसा और युद्ध के द्वारा विश्व-शांति और सुरक्षा की खोज करना कहा तक उचित है। यह एवं विरोधाभास है कि हम एक व्यक्ति की हत्या इमलिये कर देते हैं ताकि वह प्रमर हो जाए अथवा एक व्यक्ति को इमलिये दाम बनाते हैं ताकि वह स्वतन्त्र बन सके। मच तो यह है कि यह विरोधाभास विजयी राष्ट्रो द्वारा दूसरों को भ्रमिज करने का एक साधन है तथा उनका अश्वित इरादों पर पर्दा डालने वाला एक प्रयास है।

४ विश्व विजय द्वारा स्थापित विश्व राज्य में न केवल अनेक भिन्नतायें बरन् अनेक विरोध रहने हैं। इस प्रकार के समाज में एकरूपता नहीं रहती। इस राज्य के लोगो में अभी तक देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के भाव भरे रहने हैं, वे आज आपको विश्व का नागरिक नहीं मान पाते। दूसरे शब्दों में विश्व राज्य का साध-माध विश्व समुदाय का निर्माण नहीं किया जाता और न यह किया जा सकता है उसका न तो केवल विकास ही किया जा सकता है।

(२) एक संघ के निर्माण द्वारा

(Through a creation of World Federation)

कुछ विचारक विश्व सरकार की स्थापना के लिये स्विटजरलैंड के सदाहरण को प्रस्तुत करते हुए उसी आधार पर विश्व का एक संघ बना देने की सलाह देते हैं। स्विटजरलैंड में अलग-अलग भाषा, संस्कृति, इतिहास, राजभक्ति एवं नीतियों से पूर्ण बार्डर सम्प्रभु राज्यों को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर दिया गया है। उसी प्रकार वर्तमान विश्व के समस्त राज्यों को मिलाकर यदि एक संघ में एकीकृत कर दिया जाय तो बहुत अच्छा रहे। सभी राज्यों पर स्विटजरलैंड के ते सविधान को लागू किया जाय तथा सभी राष्ट्र एक दूसरे से उसी प्रकार के सम्बन्ध रखें जिस प्रकार वे सम्बन्ध स्विटजरलैंड के विविध कंटनों के मध्य स्थित हैं। इस प्रकार विश्व सरकार की समस्या का समाधान हो जायगा।

विश्व सरकार की स्थापना के लिये स्विटजरलैंड का आदर्श प्रस्तुत करने वाले विचारकों ने तर्कों में कुछ आकर्षण है किन्तु इसे चिन्तान्वित करने के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ एवं असमानतायें हैं—

(१) स्विटजरलैंड संघ की इकाइयाँ कंटन हैं। इनका इतिहास देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके संघ में एकवद्ध होने का कारण यह था कि प्रायः सभी की एक समान धनु से अपनी रक्षा करनी थी। इस प्रकार उनके राष्ट्रीय हित समान बन गये थे किन्तु विश्व के राज्यों के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। विश्व के राज्यों के सम्मुख कोई ऐसा समान खतरा नहीं

है जिसके विरुद्ध वे अपनी सुरक्षा के लिये एक संधि का निर्माण कर लें। एक असम्भव बलना के अनुसार यदि चन्द्रलोक या मंगलग्रह के मानव पृथ्वीलोक के निवासियों पर आक्रमण करें तो विश्व के सभी राष्ट्र मिलकर स्विटजरलैंड की भाँति का संधि बना सकते हैं।

(१) जनक प्रमुख एवं गौण परिस्थितियों के संयोग के कारण यद्यपि स्विटजरलैंड में सामाजिक शासन की व्यवस्था हो गई तथा इस व्यवस्था के अधीन वह अपनी सुरक्षा करने में और बड़ी शक्तियों के बीच अग्रमावित रहने में सफल भी हो गया किन्तु उसमें आन्तरिक शांति की स्थापना नहीं की जा सकी। ३०० वर्षों की अवधि में स्विस् राजन्य में पांच बड़े धर्म युद्ध लड़े गये जिनमें प्रायः सभी ईसाईयों ने सक्रिय भाग लिया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे युद्ध भी लड़े गये जिनमें कुछ राष्ट्रों ने भाग लिया। युद्ध बलह के परिणामस्वरूप अनेक प्रांति एवं शासन परिवर्तनों ने स्थान ग्रहण किया।

(२) स्विटजरलैंड के संधि का अनुभव यह बनाना है कि विश्व सरकार की स्थापना नहीं की जा सकती क्योंकि संधि की रचना के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है और ये परिस्थितियाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पैदा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त विश्व संधि का त्रियान्वित रूप यह स्पष्ट करता है कि संधि का निर्माण करना न बलवत् आवश्यक है बल्कि हानिकारक भी है। युद्ध युद्धों के कारण विश्व में जो स्थिति विश्व संधि के निर्माण के बाद उत्पन्न होगी वह वर्तमान में भी भयंकर होगी। रेपार्ड (William E. Rappard) का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज की सुरक्षा क्योंकि पूर्णतः सम्प्रभु राज्यों के स्वतन्त्र सन्तुलन पर निर्भर करती है इसलिये यह आवश्यक रूप से नीचे टूटने वाला होना चाहिये।

(३) संवैधानिक परिपत्र द्वारा

(Through Constitutional Convention)

कभी-कभी संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देकर यह कहा जाता है कि संवैधानिक परिपत्र द्वारा विश्व संधि की रचना कर ली जाय। किन्तु यह सुझाव भी अधिक सार्थक नहीं है क्योंकि विश्व राज्य की स्थापना एक स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थितिवादी भाँति सम्भव नहीं है। इस सुझाव के विरुद्ध निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

(१) संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म से पूर्व ही एक नैतिक एवं राजनैतिक समुदाय का निर्माण हो चुका था जिसने अमेरिका की स्थापना की बिना विरोध किये ही सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिये विश्व राज्य की

स्थापना भी केवल स वैधानिक परिषद द्वारा नहीं की जा सकती जब तक कि उसके पहले विश्व समुदाय (World Community) की रचना न कर दी जाये।

(२) समुक्त राज्य अमेरिका की इकाइया सभ में बचने से पूर्व स्वतन्त्र एवं सम्प्रभु न थी वे सब साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन थी। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद ये इकाइया अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने के बारे में निश्चित एवं विशद नहीं थी। अनेक आशंकाओं ने उनको एक समुक्त राज्य बनाने के लिये प्रेरित किया। किन्तु राष्ट्रों के पास स्वतन्त्रता है, वे सम्प्रभु हैं तथा इनका व एक ठोके समय में उपयोग भी करने आ रहे हैं। विश्व सरकार की रचना उनको सम्प्रभुता एवं स्वतन्त्रता के लिये सहारा या रक्षक नहीं बनगी किन्तु वह तो उल्टे दन पर सीमाएं लगादगी।

(३) विश्व सरकार का निर्माण विश्व के पृथक्-पृथक् अनेक छोटे-बड़े राष्ट्रों को मिटाकर किया जाना है, ये राज्य अपने आप में स्वतन्त्र होने के साथ साथ अपना स्वयं का व्यक्तित्व भी रखते हैं। विश्व राज्य इन सभी इकाइयों के लिए एक नया ही अनुभव होगा। किन्तु यह बात अमेरिका की इकाइयों पर लागू नहीं होती। यहाँ पर किसी नये राज्य का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि असल में हस्तान्तरण किया गया था। इकाइयों के संविधान, सम्प्रभुता एवं राज्य पहले साम्राज्यवादियों के हाथों में थे अब समुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दिया गये।

(४) विश्व समुदाय के निर्माण द्वारा (Through creation of Community)

जो विचारक विश्व सरकार का निर्माण एक कृत्रिम विकास की प्रक्रिया द्वारा करना चाहते हैं उनका यह मत है कि पहले विश्व समुदाय का निर्माण किया जाय। संसार के सभी देशों के निवासियों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि सम्बन्धों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास करके उनको एक दूसरे के निकट लाया जा सकता है। इन प्रयत्नों द्वारा लोगों में यह भावना पैदा कर दी जाय कि संसार के किसी भी देश का निवासी उसका अपना भाई है, वह उसका समुज्ज्वल है तथा उसको ओर से किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिये। इस प्रकार राष्ट्रीयता की दीवार को तोड़कर अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रचार किया जाय। राष्ट्रीय अभिमान, गर्व एवं अहंकार को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान में परिवर्तित कर दिया जाय। ऐसा हो जाने के बाद विश्व सरकार की स्थापना सहज हो जायेगी तथा स्थापित होने के बाद विश्व सरकार का सफल संचालन भी

सम्भव हो सकेगा। विश्व जनमन को राष्ट्रोपना को संकुचित प्राचीरो से निकाल कर विश्व के खुले प्राण में ला सड़ा किया जाये तो विश्व सरकार स्वयं ही स्थापित हो जायेगी। इस प्रकार निम्न विश्व सरकार लोगों पर लायी नहीं जायेगी, उसमें शक्ति एवं हिंसा का प्रयोग नहीं किया जायगा वरन् प्रेम, सहयोग, सद्भाव, नैतिकता आदि गुणों पर उसे आश्रित रखा जायगा।

विश्व समुदाय का निर्माण करने में संयुक्त राष्ट्रसंघ का शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) तथा अन्य विशेष संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यूनेस्को (UNESCO) का दशन इस मान्यता पर आधारित है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्माण के लिए तथा शांति को बनाये रखने के लिये शिक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा विभिन्न राष्ट्रों के सदस्यों के बीच परस्पर सम्बन्ध बढ़ाने वाली सभी क्रियाओं का बड़ा महत्व है जो कि एक दूसरे को समझने में सहायता करती हैं। इस मान्यता में यह कल्पना निहित है कि राष्ट्र इस कारण राष्ट्रीय होते हैं तथा युद्ध में भाग लेते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जानते और क्योंकि वे शिक्षा और सस्कृति के विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं। कुछ विचारकों के मतानुसार ये दोनों ही मान्यताएँ गूढ़पूर्ण एवं असंभव हैं। शिक्षा और सस्कृति की मात्रा एवं गुण विश्व-समुदाय के प्रश्न में कोई सम्बन्ध नहीं रखता है। मार्गोन्गो के शब्दों में विश्व समुदाय नैतिक निर्णयों एवं राजनैतिक कार्यों का समुदाय होता है न कि बौद्धिक अनुदान एवं सौन्दर्यात्मक प्रशंसाओं का। इस प्रकार यूनेस्को द्वारा किए गए कार्यों का विश्व समुदाय की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के अथर्व विश्व अभिकरण जो विश्व के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिये प्रयास करते हैं, भी विश्व समुदाय के निर्माण में कुछ सहायक बन सकते हैं। ये अभिकरण राष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता को भावना को विकसित करते हैं। प्राफेसर मित्रानी (Professor Mitrany) का मत है कि विश्व समुदाय केवल तभी निश्चित हो सकता है जबकि संसार के विभिन्न देशों के सदस्यों की सामान्य आवश्यकताएँ मनुष्य हो जायेंगी।

विश्व सरकार की मान्यता की आलोचना (Criticism of World Government's Concept)

विश्व सरकार की मान्यता की कई दृष्टियों से आलोचना की जाती है। यह अन्वयावहारिक है तथा इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता आदि बातें कहकर इसे अयथा एवं बेबुद्ध विचारविमर्श का विषय ही बताया

जाता है। यह दर्शनियों की आदिमौलिक कल्पना की भाँति सुमन एवं आशाजनक है किन्तु वास्तविक जगत में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि इसके मार्ग में दुर्जन, बाधाएँ जन्मी हैं कि इसे अमम्भव मानना पड़ता है। राष्ट्रवाद, मध्यमता, प्रतियोगी दृष्टिकोण, आर्थिक प्रतिद्वन्द्व आदि कुछ प्रमुख एवं गौण तत्वों व कारण जो मध्य, सुख और विज्ञान की स्थिति पैदा हो जाता है उसका कारण ही विश्व सरकार की आवश्यकता एवं उपयोगिता है किन्तु ये तत्त्व दिन भर सरकार के मार्ग की बाधाएँ भी हैं। यदि इन बाधाओं को दूर कर दिया जाय तो विश्व सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती और यदि उन्हें रद्द रद्द दिया जाय तो विश्व सरकार बन नहीं सकती और यदि इन की सहायता यह संभवतापूर्वक नाम नहीं कर सकती। इस प्रकार विश्व सरकार की सम्भ्यता का व्यावहारिक दृष्टि में आलोचनाओं की जाती है।

संसारिक दृष्टि में विश्व सरकार की सम्भ्यता की आलोचना करने हुए भवक विचारक यह स्पष्ट करते हैं कि विश्व सरकार अनात्मक है। यह निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जायेगी वे, हमसे प्राप्त नहीं किये जा सकते। यह विश्व की शांति, सुरक्षा एवं सद्भावनापूर्ण वातावरण प्रदान नहीं कर सकती। दूसरे और यदि विश्व सरकार की स्थापना किसी प्रकार कर दी गई तो यह विश्व की विनाश की उस स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी अतः से उसके बचाव के साधन ढूँढ करना भी अमम्भव बन जायेगा।

व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक दोनों आधारों पर विश्व सरकार की जो आलोचना की जाती है उनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) धर्मिक विरोध द्वारा विश्व सरकार की रचना में विरोध करने वाले विचारक समुक्त राष्ट्रवाद की विश्व सरकार का प्रारम्भिक रूप कह देते हैं किन्तु यह कहना गलत है। समुक्त राष्ट्रवाद राज्या का एक साधन (Instrument) मात्र है, हमने अति यह कुछ कहा है। इस बयान को स्पष्ट करने के लिए सुरक्षा परिषद् के प्रतिरोधों (Deadlocks) एवं महासभा (General Assembly) के एक महत्वपूर्ण विरोध के रूप में उदाहरण को दिया जा सकता है। महासभा केवल विचारिकी कर सकती है, उसकी वास्तविक रूप में परिणत करता राज्या की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसी प्रकार सुरक्षा परिषद् में विरोध अधिकार (Veto power) के प्रयोग न भी यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रवाद का प्रयोग सभी राष्ट्रों द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की साधना के लिए किया जाता है।

(२) विश्व-व्यापी साहचर्य एवं गहनतरि मित्रताओं को देखते हुए सभा सचों को कम करने की दृष्टि से विश्व सरकार के समर्थक हों

एकात्मक के स्थान पर सघात्मक स्वरूप देना अधिक पसन्द करते हैं। किन्तु ऐसा करते समय वे उन सब कठिनाइयों को भुला देते हैं जो कि एक सघात्मक ढाँचे के निर्माण एवं स्थायित्व के मार्ग में स्वाभाविक रूप से आ सकती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्विट्जरलैण्ड और संयुक्त राज्य अमरीका आदि स्थानों पर सघ के निर्माण से सम्बन्धित उदाहरणों को देखने के बाद, यह कहा जाता है कि एक सघ के निर्माण से पूर्व समान हितों वाले समुदाय की आवश्यकता होती है जिसके अनीत को जड़ें दीर्घकालीन इतिहास में निहित हों। सघ निर्माण प्रक्रिया पर बाहरी दबाव भी पड़ते हैं। सघ बन जाने पर 'इकाइया प्रघात होगी अथवा केन्द्र'—इस प्रश्न को लेकर हिमात्मक साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है।

(३) अनेक विचारकों द्वारा यह माना जाता है कि विश्व सरकार युद्धों के रूप को बदल सकती है, वह उनको राष्ट्रीय युद्धों के स्थान पर गृह युद्ध बना सकती है, किन्तु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकती। इसी प्रकार दो राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करके यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे को समझने तथा उनमें धातुत्व एवं मैत्री के भाव पैदा होंगे। सिद्धान्त रूप में हम कुछ भी सोचने को स्वतन्त्र हैं किन्तु, व्यवहार में अशास्य प्रतीत नहीं होती। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में पाश्चात्य राँक एण्ड रॉन नृत्य एवं अन्य सभ्यता के प्रतीकों को भोटे प्रदर्शन एवं वासनायुक्त उत्तेजक क्रियाएँ समझा जाता है। वहाँ के रहन-सहन, वेष भूषा, आचार-विवार को देख कर पहले तो कुनूठल होता है किन्तु बाद में घृणा के भाव उभर आते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक अन्तर्विरोध के कारण राष्ट्रों के बीच अविश्वास एवं घृणा पैदा हो जाती है जो कि विश्व सरकार के तलने को पलटने में सहयक बन जायेगी।

(४) विश्व सरकार के लिए अनेक संवैधानिक सुझाव प्रस्तुत किये जाते हैं। इन सबका अपना महत्व है तथा ये निस्संदेह विश्व सरकार को रचना में सहयोग प्रदान कर सकते हैं किन्तु ऐसे राज्यों में खतरा संविधान से पैदा नहीं होगा वरन् उन लोगों से पैदा होगा जो आजादी से या शक्ति द्वारा इसे एक तरफ रख कर सारी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं।

(५) विश्व सरकार को सबसे अधिक आलोचना यह की जाती है कि उसमें गृह युद्धों को बड़ावा मिलेगा। आज की राष्ट्रीय व्यवस्था में अधिकांश राष्ट्र शान्तिप्रिय होते हैं। आक्रमणकारी राष्ट्र तुलनात्मक रूप से बहुत कम हैं। आक्रमणकारी राज्य के पास सम्प्रभु शक्ति रहने के कारण उसे निर्णय लेने में सुविधा रहती है। किन्तु कोई भी राज्य तब तक युद्ध नहीं छड़ सकता जब तक कि सामान्य जनता का सहयग उसके साथ न

हों। इस सहयोग का अर्थ है जनता की सम्ममृता। विश्व राज्य स्थापित हो जाने के बाद भी कोई जन-समूह बिना किसी सम्ममृ शक्ति के चाहे तो, कुछ घेड़ सकता है।

(६) गृहयुद्ध के खतरे को ढालने के लिए समस्त सैनिक शक्ति का विश्व सेना के रूप में केन्द्रीकरण करना होगा। एक विश्व सैन्य जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय सेनाएँ उसी की स्वीकृती रहें, एक स्वविरोधी बात होगी। यदि मन्त्रों के पास हथियार रहें तो सभी उनका प्रयोग कर सकते हैं, यदि किसी के पास हथियार न रहें तो भी वे केवल हाथों से लड़ सकते हैं। यही कारण है कि विभिन्न विचारकों द्वारा विश्व सेना का सुझाव दिया जाता है जिसमें सारी सैनिक शक्ति का एकाधिकार होगा किन्तु यह सुझाव भी खतरे से खाली नहीं है।

(७) विश्व सरकार का विश्व तानाशाही में परिवर्तित होने का खतरा सदैव बना रहता है। शक्ति की सातवण रखने वाले अथवा दुनिया के मनमुटावों को दूर करने का प्रयास करने वाले आदर्शवादी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति दुनिया को नियन्त्रित करना चाहेंगे। चाहे उद्देश्य अच्छा हो अथवा बुरा, विश्व को नियन्त्रित करने के लिए सेना पर नियन्त्रण करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए घोषा, चालबाजी या शक्ति के प्रयोग का सहारा लिया जायेगा। चाहे चालबाजी से या स्वतन्त्र-जित गृह-युद्ध में यदि एक समुदाय द्वारा दूसरे पर अधिकार कर लिया गया तो विश्व भर की तानाशाही का जन्म हो जायेगा। यदि उन तानाशाहों द्वारा समस्त बिनाशकारी हथियारों पर अधिकार कर लिया गया तो उसके विरुद्ध शक्ति का भविष्य भी धुधला पड़ जायेगा। इस प्रकार विश्व सरकार जिस लक्ष्य को सामने रख कर बनाई गई, वह तो गूरा हो ही न सका उन्हे शक्ति और स्वतन्त्रता भी दोषकाल के लिए विश्व का दामन छोड़ कर खली जायेगी।

उन आलोचनाओं के मध्यमन के बाद ऐसा लगता है कि विश्व सरकार पर विचार करना समय की एक व्यर्थ तथा प्रभावहीन कार्य में मग्न करना है इनसे अधिक कुछ नहीं। किन्तु यह आनास भी एकाग्री है। यह सब है कि यदि विश्व सरकार बना दी गई तो उसके परिणाम बड़े भयंकर होंगे किन्तु यह भी सब है कि एकाग्रीय की नीति (Unilateralism) भी खतरे से खाली नहीं। यही कारण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ही इन दोनों अतिवृत्तियों (Extremes) के बीच का मार्ग खोजने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अब तक विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जैसे 'एक संघीय राज्य के रूप में प्रजातन्त्रों का संघ' जो कि एक विचार या सम्भावना बन कर ही

रह गया। दूसरा मुझाव था नाटो (NATO) का जिसे त्रियान्वित कर लिया गया है। इस प्रकार के मुझावो को क्षेत्रीय सन्धि (Regional alliances) भी कहा जा सकता है। इस प्रकार की सन्धियों में बड़े राष्ट्र अपने झगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण साधनों द्वारा कर लेते हैं इस प्रकार ये सन्धियाँ क्षेत्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतीक मानी जा सकती हैं।

वर्तमान काल में कुछ अन्य मुझाव भी दिये जाते हैं जिनको न तो क्षेत्रीय संगठन कहा जा सकता है और न ही क्षेत्रीय सन्धियाँ ही। इनकी इन दोनों ही श्रेणियों से अलग माना जायगा। इस प्रकार के मुझाव मुख्यतः निम्न हैं—

- (१) योरोप का कोयला एवं स्टील समुदाय या शुमन योजना
(European Coal and Steel Community or Schuman Plan)
- (२) योरोप का सामान्य बाजार
(European Common Market)
- (३) योरोप का अणु अधिकार
(European Atomic Authority)
- (४) योरोप का सुरक्षा समुदाय
(European Defence Community)
- (५) योरोप का राजनैतिक समुदाय
(European Political Community), आदि।

उक्त मुझावों में न अस्त्रियोग को न त्रियान्वित भी कर दिया गया है। इन मुझावों की स्वीकार करने के मार्ग में भी प्रायः वही बाधा है जो कि राष्ट्रवाद से प्रभावित द्वय युग में विश्व सन्धार के समर्थकों का मार्ग अवरोध करती है। जहाँ सन्धि एवं राजनैतिक एकीकरण का प्रयत्न होता है वहाँ ये बाधाएँ अपना प्रभाव दिखाने लग जाती हैं।

निःशस्त्रीकरण (Disarmament)

विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शस्त्रों की होड़ पर रोक लगाना एक बहुत महत्वपूर्ण काम बन गया है जिसमें देरी नहीं की जा सकती। अणु शक्ति से पूर्ण सैनिक तैयारियों का बीच मनुष्य यदि मानव सभ्यता के विकास को रोकना चाहता है तो उसे कुछ करना पड़ेगा। शस्त्रों को जहाँ मनुष्य की हिंसा बल की अभिव्यक्ति माना जाता है वहाँ उनको युद्ध का उत्तमज भी कहा जा सकता है। ये हिंसा का प्रतीक हैं और किसी भी

व्यक्ति या समाज की हिंसा ने पूर्ण प्रवृत्तियों को पैदा नहीं भी उभरना लगते हैं। यदि बार अनुभव किया गया है कि जब व्यक्ति के हाथ में कोई छद्म रहती है, तो वह लगातार ही पर प्रयोग करने की लातना रहने लगता है। अन्तराष्ट्रीय समाज में जब एक देश द्वारा सम्प्रोकरण की नीति पर जमल दिया जाता है तो 'उभेता प्रभाव' उभरे पड़ोसी अथवा दूरस्थ राष्ट्रों पर भी पड़े बिना नहीं रह पाता क्योंकि यह नीति अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा एवं विकास के लिए एक मजद का कारण बन जाती है। परिणामस्वरूप इन देशों की नीति में परिवर्तन आता है और वे भी राष्ट्रों की शीट में उतर आते हैं ताकि वे दूसरों से पीछे न रह जायें। इस शीट की प्रतिक्रिया होती है और राष्ट्रों के निर्माण को उस सीमा पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ एक देश की समस्त विकास योजनाएँ एक नागिकी नीतियाँ अमल में आती हैं। इस प्रकार सम्प्रोकरण की नीति का विरुद्ध पर पड़ने वाला प्रभाव बड़ा हो भयानक है। इस नीति के कारण विश्व के राष्ट्रों के बीच भय, संदेह और प्रतिस्पर्धा की भावनाएँ बढ़ती हैं। एक देश की अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है क्योंकि उसे अपने बजट का अधिशेष भाग सैनिक लेवारियों पर खर्च करना पड़ता है। देश का जीवन स्तर गिर जाता है। सम्पत्ति और सशक्ति के विकास का मार्ग बन्द हो जाता है।

राष्ट्रों की शीट में भाग लेने वाले सरकार की अपनी लोकप्रियता को जाने का भय पैदा हो जाता है और 'मागामी' जासूसों को दूर रखने एवं अपनी नीतियों का अधिकतम निरूपण करने के लिए वह बेन-बैन-प्रतारण किसी भी राष्ट्र के विरुद्ध व्यक्ति या अनुचित विधि भी कारण पर करने देश को मुक्त की भाव में लौट देती है ताकि जनता को वह दिखा सके कि यदि उसने देश का पैट वाट कर इन विध्वंसकारी राष्ट्रों का निर्माण न किया होता तो देश का स्वतंत्रता और सुरक्षा पर कितने बुरा प्रभाव पड़ता, और इस प्रकार राष्ट्रों पर जोर देने वाली सरकार अपनी सूझ-बूझ एवं दूरदर्शिता का प्रभाव जमाने का अवसर प्राप्त कर लेगी। इन सभी विधाएँ प्रतिक्रियाओं पर विचार करने के बाद शक्ति, मानवता एवं सहयोगपूर्ण नीति के समर्थक अन्तराष्ट्रीय राजनीति के विचारक निम्नोक्त पर जोर देते हुए इसे वर्तमान युग की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हैं।

निम्नोक्त नीति का व्यापारिक, नैतिक, बौद्धिक एवं राजनीतिक आदि अनेक दृष्टिकोणों से समर्थन किया जाता है। बौद्धिक आधार पर इस नीति का समर्थन करने में व्यापारी वर्ग का योग महत्वपूर्ण है। वे युद्ध को अन्तराष्ट्रीय व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के हिा के विपरीत मानते हैं। उनको मनुष्यव्यवहार करने वाले विभिन्न देशों के बीच युद्ध होने में सभी

को नुकसान रहता है। यह व्यापारियों के भाग्य चक्र के लिए राष्ट्र के समान है तथा उनके व्यवहारों को यह हीन बना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं राजनैतिक विचारक कांत (Kant) के मतानुसार युद्ध के मनव व्यापारिक उत्पाद माने नहीं रह सकते। इन अनेक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की निम्नलिखित एक अराजकतावादी प्रवृत्तियों पर सीमा लगाने का समयन किया जाता है। इस प्रकार की सीमाएं लगा कर शांति प्राप्त करने के माध्यमों में सबसे स्थायी प्रभावपूर्ण एवं निश्चित साधन निर्वाहोत्तरण का माया जाता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वर्तमान विद्वत् अनेक समस्याओं एवं संघर्षों से पूर्ण है जो कि अनेक कारणों एवं शक्तों से पैदा होता है।

विश्व राजनीति की समस्याएं और उनके स्रोत

(The Problems of World Politics and their Sources)

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच व्यापार, वाणिज्य, सम्मान और प्रभाव एवं विचारधारा की साक्षि अनेक संघर्ष होते रहते हैं। युद्ध के मद्दान में स्थिति सम्मान एवं शक्ति की प्राप्ति के लिए जानबूझ कर किए जाने वाले प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में बहुत मिल जाते हैं। प्रति दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में स्थायी एवं शांति का रहना कोई स्वाभाविक विषयवा नहीं है। राष्ट्रों के बीच स्थित प्रतिस्पर्धा द्वारा एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है जिसके आगे शांति नहीं हो जाएगा। सैद्धांतिक दृष्टि से शांति की सभी पूर्व आवश्यकताएं यद्यपि हान के बाद भी शांति का रहना जल्द नहीं है। राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा उनके स्वतंत्र एवं सम्पूर्ण स्वल्प के कारण आवश्यक बना रहती है।

शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों का अध्ययन इस प्रतिस्पर्धा को दूर नहीं करता। इसके द्वारा संघर्ष का युद्ध के द्वारा मुकसान के प्रयासों पर राक लगा दी जाती है और यह प्रयास किया जाता है कि युद्ध को राष्ट्र शांति का एक साधन न रहने दिया जाये। इस अध्ययन के द्वारा संघर्ष का समाप्त करने का प्रयास किया जाता है उसकी दृष्टि का नहीं क्योंकि असंयुक्त संघटन बाद में विवाद के कारण बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थित संघर्ष को युद्ध का रूप न देकर प्रत्येक राष्ट्र का सम्भावित संभाव्य प्रयत्न करके शांतिवशा विचारधारा युद्ध का अनादम्बक बनाने का प्रयास करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा के रूप समय के विधान एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार संघर्ष को दूर करने के लिए एक युग में जो प्रयास किए जाते हैं वे भी अगले युग में उपयोग नहीं रहते। विश्व युग में भौगोलिक क्षेत्र की जा रही थी तथा नये वातावरणों के

लिए प्रतियोगिता हो रही थी उस समय शांतिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की स्थापना के लिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता थी किन्तु तीव्र गति से होने वाले औद्योगिक विकास के युग में अन्य प्रकार की व्यवस्था जल्द ही है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का रूप एवं बनावट उन प्रतियोगिता की प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए जिसे कि विनियमित किया जाना है। एक युग में जिस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सधर्प को दबाया जाता था वह दूसरे युग में सधर्प को बढ़ाने का कारण बन सकता है। कहा यह जाता है कि एक समय शक्ति संतुलन स्थायित्व की रचना के प्रभावशील साधन के रूप में अत्यन्त महत्वपूर्ण था किन्तु आज की विचारपारायण प्रतियोगिता तथा अणुयुग के सतरे में यह महत्वहीन बन गया है।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का संगठन एवं नियंत्रण समय के राजनैतिक विचारों एवं सामाजिक मूल्यों से मिलता हुआ होना चाहिए। पहले जब युद्धों में जान-माल की हानि अधिक नहीं होती थी तब अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों को सामान्य रूप से स्वामाविक सस्या माना जाता था। किन्तु जब से युद्ध की प्रकृति बदली है तब से नए मूल्यों का विकास हुआ है और युद्ध को सर्वमान्य रूप से धुरा बताया जाता है। अणु शस्त्रों ने युद्ध को राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में न केवल अवाञ्छनीय बना दिया है बल्कि अस्वाभाविक भी बना दिया है। यद्यपि प्रतियोगिता और सधर्प अब भी अन्तर्राष्ट्रीय जीवन की एक विशेषता है किन्तु युद्ध सधर्पों को सुनसाने के लिए अस्वाभाविक बन गया है। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नई प्रक्रिया एवं नया रूप जरूरी है। अतीत काल से जो विरासत के रूप में लिखा गया है वह बीसवीं शताब्दी की राष्ट्रीय नीतियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय रचना के लिए अनुपयुक्त है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सधर्प देखने को मिलता है उसके पीछे अनेक कारण कार्य करते हैं। इसका पहला कारण यह है कि परिवर्तन और अस्थायित्व के बीच घोर सधर्प रहता है। राज्यों ने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन के लिए माग की जाती है। किन्तु पधारिणति चाहने वाले इस माग का विरोध करते हैं।

सधर्प का दूसरा रूप सीमाओं के ऊपर शगड़े हैं। सधर्प का यह रूप अत्यन्त प्राचीन है और बीसवीं शताब्दी तक इसका बहुत प्रभाव रहा। नई सोवियत रूस पर दावा करना, उपनिवेश की भूमियों की प्राप्ति करने के ऊपर सधर्प करना, आदि सधर्प के सामान्य कारण थे। रुढ़िवादी शक्ति के अनुसार न्याय वही है जो कि कानून है और कानून का अर्थ वह है जो कि

सामान्यतः स्वीकृत है। किन्तु दूसरी ओर शक्तिशाली शक्ति के मतानुसार वर्तमान स्थिति अन्यायपूर्ण है और आवश्यकता पड़े तो उसे शक्ति के साथ बदला जाना चाहिए। इन दोनों स्थितियों के बीच समझौता होना बड़ा मुश्किल है। इस आधार पर विश्व में अनेक झगड़े होते रहते हैं। सन् १९५६ में जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया तो ब्रिटेन तथा फ्रांस ने कानूनी दृष्टिकोण अपनाए तथा वस्तुस्थिति को बनाये रखने की बात कही। किन्तु मिस्र ने अन्य कानूनी दृष्टिकोण अपनाया जो कि उसके सम्प्रभुता के अधिकार पर आधारित था। सीमा सम्बन्धी झगड़े सघर्ष का पुरातन रूप हैं। सीमा सम्बन्धी झगड़े जब तक सम्बन्धित सरकारों की सम्प्रभुता के अनुसार मान्य एवं स्थापित नहीं हो जाते तब तक वे सघर्ष के स्रोत बने रहते हैं। बीसवीं शताब्दी में स्वतंत्र राष्ट्रों की हर जगह निरन्तर स्थापना होती जा रही है तथा उनकी सम्प्रभुता को मान्यता दी जाती है। पहले विदेशियों को शोषण का अधिकार था किन्तु अब स्वदेशियों को सम्प्रभुता का अधिकार है और ऐसी स्थिति में यह आशा की जाती है कि सघर्ष का यह रूप अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का कम से कम महत्वपूर्ण स्रोत बनता जाएगा।

आर्थिक रुकावट को अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का तीसरा कारण माना जाता है। आर्थिक रुकावट उन लोगों के ऊपर डाली जाती है जो कि एक महत्वपूर्ण रणनीति की स्थिति में युक्त होते हैं। वैसे आर्थिक प्रतिरोध प्रायः अचानक जनता पर किया जाता है किन्तु अनेक ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र भी होते हैं जो कि दूसरे राष्ट्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्धों को मानने की प्रवृत्ति रखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने इस कथन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इस काल के लेखों में जो राजनैतिक तथ्यों से सम्बन्ध रखते हैं, आर्थिक प्रतिबन्धों, उनके कारणों तथा राजनैतिक प्रमाणों पर बहुत जोर दिया गया है। सन् १९३० के पूर्व अनेक व्यापारिक राष्ट्रों ने जापान के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगा दिये, क्योंकि एक तो उनका महा आर्थिक मन्दी की स्थिति थी और दूसरे वे बढ़ती हुई जापानी प्रतियोगिता का मुकाबला करना चाहते थे। जब जापान को उपयुक्त माल और वाजार नहीं मिले तो उसने शक्ति के साधन को अपनाया। यदि जापान अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहता था तो उसे उन प्रदेशों को अपने कब्जे में करना चाहिए जहाँ उस बच्चा माल मिलता है या मात्र की सपत्त होती है।

अनेक देशों की गरीबी और उस गरीबी के विषम लड़ाई अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष का चौथा कारण है। एर दस की गरीबी और निम्नतर विकास का कारण उसका इतिहास एवं प्राकृतिक साधन है। इन स्थितियों को आज भी

कोई देश पुनर्जाप सहज नहीं करता क्योंकि वह दूसरों की उच्च आमदनी से परिवर्तित हो जाना है और उन साधनों को जान लेता है जिससे कि वह स्वयं की आय को बढ़ा लेता। ऐसी स्थिति में साम्राज्यवादी शक्ति के विरुद्ध शक्ति की जाती है और उन सामन्तवादी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जो कि यहाँ निम्न जीवन स्तर के कारण बने। निम्न जीवन स्तर के उत्थार के लिए स्वयंसेवा की माग जोर पकड़ती है। जब स्वयंसेवा प्राप्त करने के बाद अधिक फायदा नहीं होता तो उस राजनैतिक एवं अधिक व्यवस्था को चुनौती दी जाती है जो कि साम्राज्यवादी शक्ति से विरासत में प्राप्त हुई है।

समर्थ का पाँचवाँ कारण तब उत्पन्न होता है जब कि बाजार की दशाओं को परिवर्तित किया जाता है। अनेक देश यद्यपि उच्च जीवन स्तर से सम्पन्न होते हैं किन्तु फिर भी वे एक या कुछ चीजों के उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं और ऐसी स्थिति में यदि उस वस्तु के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया तो वह देश विरुद्ध हो जाएगा। कुछ देश मुख्यतः रबर के उत्पादन पर निर्भर होते हैं, अन्य देश कपास के उत्पादन पर निर्भर होते हैं। यदि इन चीजों का विकल्प ढूँढ कर रख दिया जाए तो इन देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय समर्थ का छठा स्तंभ विचारधारागत—समर्थ—है। इसके अनुसार एक देश कुछ विचारों एवं समस्याओं को अपने देश में संगठित करने का प्रयास करता है और उसके बाद उन्हें अन्य देशों में भी फैलाना चाहता है। बीसवीं शताब्दी के पूर्व भी विचारधारा का अस्तित्व था किन्तु उस समय वह समर्थ का कारण नहीं था। पुनर्जाति के युग में तथा प्रारम्भिक शक्ति और वैज्ञानिक के युग में धार्मिक तथा विचारधारागत अन्तर महत्वपूर्ण थे, किन्तु वे निर्गोपक नहीं थे। इस सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री श्री नेहरू का यह कथन महत्वपूर्ण है कि इतिहास के प्रमाण इस बात का समर्थन नहीं करते कि विरोधी विचारधाराओं के बीच का समर्थ अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष का मुख्य स्रोत रहा है। मान भी विचारधारागत पहलू हमारे विभाजित विश्व का कारण होने की अपेक्षा साधन अधिक है। इस मत में चाहे कितनी भी सरलता हो किन्तु इतना अवश्य है कि जब साम्यवाद की औद्योगिक एवं नैतिक शक्तें बढ़ गईं तो उसने विचारधारागत अन्तरों को हल्का कर दिया जो कि पहले समर्थ के मूल स्रोत प्रतीत होते थे। मन् १९५६ में एच. एल. राबर्ट्स (H. L. Roberts) ने कहा था कि प्रायः यह कहा जाता है कि यदि सोवियत संघ को समाप्त होगा है तबदा विश्व साम्राज्य के प्रति दिल को परिवर्तित करना है तो हमें अभी भी अनेक उन समस्याओं को मुँहझाना है

जिनको कि सोवियत घमकी का पहलू माना जाता है। हम यह नहीं कह सकते कि साम्यवाद के अभाव में अमरीका के लिए सोवियत रुस की चुनौती की प्रकृति क्या होगी किन्तु यह सोचना अबुद्धिपूर्ण नहीं है कि यह चुनौती हम के नए औद्योगिक स्तर पर आधारित होगी।

विचारधारा का महत्व सम्भवतः कम नहीं होगा क्योंकि जो भी आज तक प्रगति हुई है उसके बीच वे आर्थिक और सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं जिनका आधार उन अध्यापकों एवं समन्वयकर्त्ताओं की क्रियाएँ हैं जो कि सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था, प्राथमिकता एवं अभिनायों में बिखरे हुए हैं। यह सब कुछ विचारधारा की धृष्टभूमि में हुआ जिसके बिना औद्योगिक प्रगति हो ही नहीं सकती थी। इसके अतिरिक्त साम्यवाद की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याएँ दुनिया के पिछड़े हुए लोगों से सम्बन्ध रखती हैं। ऐसी स्थिति में यह निश्चय करना कठिन है कि क्रान्तिकारी शक्तियों का अन्य देशों पर जितना असर होगा। सोवियत संघ के नेता बड़े विकसित देशों में तीव्र गति से विकास लाने की बात कहते हैं। वे विचारधारा को अपनी प्राप्तियों से सम्बन्धित कर देते हैं और अपनी प्राप्तियों के आधार पर विचारधारा को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। मास्को की एक प्रसिद्ध पत्रिका (International Affairs) में कहा गया था कि अमरीकी तथा अन्य एकाधिकारीवादी व्यवस्थाएँ पूर्वी देशों द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले क्रान्तिकारी तरीके से बहकाते हैं। वे बड़े विकसित देशों को एक शताब्दी तक प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं जबकि पश्चिम की सहायता से ये देश आर्थिक प्रगति के फल प्राप्त सकेंगे। किन्तु इन देशों के लोग प्रतिक्षा नहीं करना चाहते। वैसे तो पश्चिम भी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं है और कई बार सयन राज्य अमरीका की कार्रवाई में यह माना गया है कि कम विकसित देश प्रतीक्षा नहीं करेंगे वे अपनी आर्थिक शक्ति अभी चाहते हैं तथा उसके फल को दो शताब्दियों की अपेक्षा दो दशान्दियों में ही प्राप्त करना चाहते हैं।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध का अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क मुख्य रूप से बड़े विकसित देशों से सम्बन्धित है। इन क्षेत्रों में अधिकांश देश पहले पश्चिमी प्रभाव में थे किन्तु अब अपनी आर्थिक समस्याओं को जल्दी सुलझाने की फिगत में साम्यवाद की ओर आकर्षित हो गये हैं। इन क्षेत्रों में महाशक्तियों के बीच स्थित सम्बन्ध उस विशेष क्षेत्र की अपेक्षित सैनिक एवं राजनैतिक शक्ति पर निर्भर करते हैं। कहीं-कहीं पर विरोधी शक्तियों के सैनिक अड्डे स्थापित हो गये हैं और कहीं क्षेत्रीय सैनिक संधियाँ कर ली गई हैं ताकि विरोधी शक्ति द्वारा आक्रमण किये जाने पर उसका मुकाबला

निरा जा सके। अन्वेषण एवं सुस्था के लिए अपनाए जाने वाले हथियार हैं—मैनिक तथा आर्थिक सहायता, प्रचार और राजद्रोह, तथा सरकार उलटने व अशांति फैलाने की अन्य तकनीकें। यह कहा जाता है कि इन सम्बन्धों में महाशक्तियों के बीच जो प्रतिपोगिता हो रही है वह सबसे अधिक खतरनाक है।

महाशक्तियों के इस सघर्ष से सम्बन्धित विकासशील देश प्रायः असहमता की नीति अपनाते हैं। यह मूलतः इसलिए होता है क्योंकि वे अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की मूल समस्याओं में ही लगे रहते हैं। साथ ही नई शक्तियों के रूप में वे अपने आपको महाशक्तियों के इस सघर्ष से दूर ही रखना चाहते हैं। कुछ विकासशील देशों ने अपने आपको सैनिक सन्धियों का सदस्य बना लिया है क्योंकि उनके ऐतिहासिक बन्धन ये और धर भी वे इन महाशक्ति के साथ इन ऐतिहासिक बन्धनों को बनाये रखना चाहते हैं अथवा अपने कटु ऐतिहासिक अनुभवों के कारण एक शक्ति का विरोध करके दूसरे पक्ष में मिलना चाहते हैं। जहाँ तक साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरोध तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रश्न है, वहाँ तक इन देशों की भावनाएँ एक जैसी हैं किन्तु इसके अतिरिक्त इनकी स्वामिभक्ति विभाजित हो जाती है। प्रारम्भ में असहमता की नीति के प्रति दोनों शक्ति गुटों का एक अनुकूल नहीं था क्योंकि पश्चिमी शक्तियाँ इसको अनैतिक मानती थी तथा साम्यवादी देश इसको छिपा हुआ पूँजीवादी कहते थे। किन्तु १९५६ के एशियाई-अफ्रीकी देशों के बाण्डुंग सम्मेलन के बाद से स्थिति में सुधार आ गया। अब दोनों ही गुट इसी नीति का आदर करते हैं।

सन् १९६० में सनेक नये अफ्रीकी राज्यों का जन्म हुआ और इन समय के बाद महाशक्तियों के सघर्ष में भारी परिवर्तन आ गया। अब असहमता राष्ट्रों को एक तीसरा गुट माना जाने लगा। किन्तु असल में इस नीति को मानने वाले देशों के बीच पर्याप्त एकता एवं सहयोग नहीं था। स्वतन्त्रता एवं साम्राज्यवाद के बारे में कुछ एक जैसे विचार होने के अतिरिक्त उनके बीच मंत्रों की अन्य कोई कड़ी नहीं थी। उनका अस्तित्व तथा महत्व इसलिए था क्योंकि वही शक्तियाँ इनके अस्तित्व को उपयोगी मानती थीं। अणु शस्त्रों का विकास होने के बाद यह आवश्यक समझा जाने लगा कि महाशक्तियों के बीच जिन प्रश्नों पर भारी मतभेद है उनको बातों द्वारा सुझाना लिया जाये। सन् १९६१ के प्रारम्भ में लाओस की आन्तरिक समस्या को सुझाने के लिए वहाँ तदर्थ सरकार की स्थापना की गई और इसे दोनों ही महाशक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया। इस प्रकार

दोनों गुटों ने अपने दृष्टिकोण को नरम किया तथा बीच के मार्ग को अपनाने का प्रयास किया।

विचारधारागत संघर्ष के परिणामस्वरूप उत्पन्न समस्याओं को पश्चिमी देश पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक लेते हैं। उनके विचार से यह संघर्ष एक आक्रमण से अधिक घातक है तथा केवल व्यापारिक एवं अन्य परम्परागत हितों पर ही आघात करता हो ऐसी बात नहीं है। यहाँ समस्या केवल यथास्थिति को बनाये रखना ही नहीं है। आज जो यथास्थिति में परिवर्तन किया गया है वह ऐसा नहीं है जैसा कि परम्परागत अर्थ में माना जाता है। सीमाओं, सेनाओं एवं शक्ति के बीच सतुलन की स्थापना शक्ति की घमकी द्वारा अथवा शान्ति सन्धियों द्वारा की जा सकती थी और इस प्रकार यथास्थिति बनाये रखी जा सकती थी यदि सधन करना भी जरूरी बन जाना था तो मामले को युद्ध के द्वारा सुलझा लिया जाता था। किन्तु आज की स्थितियाँ भिन्न प्रकार की हैं। आज यथास्थिति को जो चुनौती मिली है वह सैनिक शक्ति के आधार पर नहीं मिली है बल्कि साम्यवादो गुट की आधिक प्रगति एवं जनसंख्या वृद्धि द्वारा मिली है। जब इस प्रकार की स्थिति पर लागू किया जाता है तो शक्ति यथास्थिति को मान्यता देकर ही जाती है।

साम्यवादी विचारधारा के बढ़ने से पश्चिमी शक्तियों को जो चुनौती मिली है उसका परिणाम सोवियत संघ को भी है। यही कारण है कि जिस समय वह आणु आक्रमण के विरुद्ध रक्षा की व्यवस्था पर्याप्त नहीं कर पाया था उस समय प्रतिनिधित्ववाद के भय को अभिव्यक्त करता रहता था। इस समय साम्यवादियों की ओर से कहा गया कि वे यथास्थिति को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं तथा पश्चिमी शक्तियों की ओर से यह खतरा है कि वे इसे बदलने का प्रयास करेंगे। सिद्धान्त रूप में पश्चिम भी यथास्थिति को स्वीकार कर चुका था और उसके द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयास शायद इसी दिशा में किए जाने वाले प्रयास थे। आश्रित जनता की सुरक्षा की गारंटी दी गई तथा क्षत्रिय सन्धियाँ तो गयीं। सोवियत रूस उस समय तक भयभीत रहा जब तक कि उसका पर्याप्त औद्योगिक एवं वैज्ञानिक विकास नहीं हो गया तथा पश्चिम की नीतियों का मुकाबला करने योग्य नहीं बन गया।

नई परिस्थितियों के सदम में पश्चिमी शक्तियों ने भी अपनी नीतियाँ बदलीं। अब सीमित गुटों एवं शक्तों के नियन्त्रण को उठाने अपनी नीति का आधार बना लिया। इस नीति को अपना कर पश्चिम ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह साम्यवाद को एक व्यापक चीज मानता है तथा मानव संहार के साधनों का प्रयोग करके वह प्रतिनिधित्ववाद ज्ञाति नहीं मानता चाहता।

इस प्रकार साम्यवाद एवं पूँजीवाद के बीच का विचारधारागत सघर्ष कम हो गया तथा सीमित बन गया। इन दोनों विरोधी व्यवस्थाओं की उन्नयनता, गमन एवं स्थान के अनुसार तब हानी है और इसी के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि कौन सा व्यवस्था कितने क्षेत्रों तथा लोगों पर उन्नयन रहेगी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का कोई अधिक प्रभाव नहीं होगा, उदाहरण के लिए पश्चिम की विकसित उर्ध्व-व्यवस्थाओं का नाम लिया जा सकता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ कि आर्थिक षट्टी की मिट्टान के सादन न रूप में साम्यवाद का नियोजन एवं तकनीक अधिक प्रभावशाली मिट्ट होती है। इसके अतिरिक्त दोनों विचारधाराओं के मध्य स्थित सघर्ष को छोटे राज्य में विन राष्पवाद एवं स्वतन्त्रता की भावनाओं न पर्याप्त सीमित कर दिया है। नवादिन राष्प अपने आर्थिक विकास की अपक्षा अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तटस्थता की नीति न दोनों ही पक्षों को ऐसी सन्धिया करने से रोक दिया जो कि एक सफल सैनिक सघर्ष के लिए आवश्यक समझी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष का एक अन्य कारण अनुत्तरदायी लोगों के द्वारा अथवा उनका विरुद्ध किए जाने वाले कार्य हैं। इन अनुत्तरदायी व्यक्तियों में हम ऐसे पुरखों, निगमों एवं शक्तिशाली हितों को ल सकते हैं जो कि सवैधानिक रूप से कोई नीति सम्मन्धी उत्तरदायित्व नहीं रखते। गैर मरकाती ध्याहारित संगठनों के कार्य उत्तरदायी सत्ताओं को ऐसी नीतियों को मानने के लिए बाध्य कर देने हैं जो कि ध्याहारित में भागमणों को प्रोत्साहन देती हैं।

राष्ट्रों के द्वारा भी अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष को प्रोत्साहन दिया जाता है। मि० एम० टेट (M. Tate) के कथानुसार "यूरोप में राष्ट्रों का ध्यापक प्रसार तथा उनसे उत्पन्न होने वाली अनुरक्षा एवं डर की भावना ने युद्ध को अपरिहार्य बना दिया।" उनका मत है कि इतिहास का सच्चा अध्ययन यह है जिसमें कि हम भावी शान्ति के हित में वर्तमान के लिए जतीत से पाठ रते हैं। युद्ध को राष्ट्रों द्वारा इसीलिए अपनाया जाता है ताकि वे शान्ति स्थापित कर सकें। युद्ध की तैयारियों में सतोषजनक स्थिति रहने पर अन्य देश के भागमण को विता कम हो जाती है। प्रभावशाली सुरक्षा के लिए यह जरूरी होता है कि राष्ट्रीय राष्ट्रों को सतोषजनक रूप से पूरा कर लिया जाये। किन्तु क्या यह शान्ति का सही रास्ता है? अधिकांश विचारक एवं राजनीतिज्ञ इस मत के समर्थक हैं कि युद्ध की तैयारियाँ युद्ध को रोकती नहीं, वे उसके छिड़ने में देरी कर सकती हैं किन्तु रथाई शान्ति वे बनी नहीं ला

सकती। जिस प्रकार 'प्रेम' हमेशा प्रेम को उत्पन्न करता है और शोध हमेशा शोध-को, उसी प्रकार हिंसा भी हमेशा हिंसा को ही उभारती है। सेनायों शान्ति की रक्षा नहीं करती वरन् वे युद्ध को उभारती हैं। कान्ट (Kant) ने शान्ति की स्थापना के लिए यह बताया था कि सेनाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये हमेशा लड़ने के लिए तैयार रह कर राज्यों को सदा युद्ध की चुनौती देती रहती हैं।

शस्त्रों की दौड़ युद्ध को रोक नहीं सकती वह उनको प्रोत्साहन ही देती है, इस बात का उदाहरण बीसवीं शताब्दी में ही दो बार प्राप्त हो चुका है और मानव जाति तीसरे युद्ध की सम्भावना से भी ग्रस्त है। युद्ध आज भी राष्ट्रीय नीति का एक स्वीकृत एवं व्यावहारिक अन्तिम साधन बना हुआ है। जैसे यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शस्त्रों की कितनी मात्रा युद्ध को प्रोत्साहन देती है किन्तु इतना अवश्य सच है कि संघर्ष के अन्य कारणों में ये प्रभावशाली है तथा भय एवं सन्देह को अन्तिम रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं महत्व

(The Necessity and Importance of Disarmament)

जब युद्धों के भीषण भन्दन से मानवता कराह उठी तो यह सोचा गया कि किसी भी प्रकार इनसे छुटकारा पाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के घुरगुर दिग्गजों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और वे युद्ध के उन कारणों की खोज में व्यस्त हो गये जिनको शान्ति की स्थापना के हेतु दूर में करना आवश्यक था। अपने विचार के दौरान उन्होंने यह पाया कि निःशस्त्रीकरण के बिना शान्ति स्थापना के लिए किये गये अन्य प्रयासों की सफलता सिद्धि बन जायगी। निःशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करने के कुछ आधार ये जो निम्न प्रकार हैं—

(१) अणु युद्धों का भय

कोई भी सतरा जितना भयानक होना है उससे बचने की मानव की उत्कृष्टता भी उतनी ही तीव्र हो जाती है। इस कथन की सत्यता इस तथ्य से सिद्ध की जा सकती है कि युद्ध ज्यों-ज्यों विध्वंसकारी अधिक होता जा रहा है, विचारकों एवं राजनीतिज्ञों का ध्यान उससे बचने के उपायों की खोज में उतना ही अधिक केन्द्रित होने लगा है। नागासाकी और हिरोशिमा पर डाले गये अणुबमों का परिणाम देख कर मानवता आश्चर्यचकित रूप से ग्रस्त हो गई। इससे पूर्व कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक शस्त्र द्वारा इतने कम समय में इतनी अधिक मात्रा में विनाश किया जा सकता है।

आज विज्ञान के आविष्कारों ने बहुत प्रगति कर ली है तथा आज के वयो मे १९४५ की तुलना मे कई गुना अधिक विध्वंस करने की शक्ति बढ गई है। केवल कुछ ही वयों के विस्फोट से विश्व का विनाश किया जा सकता है, धरती को पाताल में पहुँचाया जा सकता है। इन शस्त्रों के बीच में आज विश्व अनिश्चिन्त भविष्य के साथ रह रहा है, किसी को पता नहीं रहता कि अगला क्षण किस प्रकार बीतेगा। शक्ति का भूँसा कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र भावनाओं के आवेश में अंधा होकर इन शस्त्रों का प्रयोग करके मानव द्वारा अर्जित अब तक की सृष्टि एवं सम्पत्ता को धूल में मिला सकता है। इन आतकाओं से भयभीत होकर यह कहा जाता है कि इस प्रकार के शस्त्रों का निर्माण न किया जाय, इन पर रोक लगाई जाय। शान्ति के पक्षपाती लोग नि शस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। उनके मतानुसार युद्ध एवं विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग यही है। नि शस्त्रीकरण की नीति का विरोध करने वाले को युद्ध का समर्थक (War monger) कहा जाता है। अधिकांश देश यद्यपि स्वयं शस्त्रों को सीमित नहीं रखते हैं फिर भी अपने आपकी एक शान्ति प्रेमी राष्ट्र बनाने की दृष्टि से वे नि शस्त्रीकरण का जोरदार प्रचार करते हैं।

शान्ति एवं शस्त्रों के बीच के सम्बन्ध के बारे में विचारक एक मत नहीं है। कुछ का मत है कि युद्धों के कारण शस्त्रों का उत्पादन किया जाता है जबकि दूसरे लोग यह मानते हैं कि शस्त्रों से युद्ध को उत्तेजना प्राप्त होती है। प्रथम विचार के समर्थकों का यह मत है कि मान को पूर्ण रूप से नि शस्त्रीकरण कर भी दिया जाय तो भी जब तक सम्प्रभु राज्य है तब तक शक्ति की समस्या को गौण नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व अनेक होते हैं, केवल सेना ही नहीं होती। सेना और शस्त्रों को मिटा देने के बाद भी आर्थिक एवं अन्य साधनों से एक देश द्वारा दूसरे पर आक्रमण किया जा सकता है। फिर भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि शस्त्रों पर रोक लगाने से सीमित कर न न आक्रमण यदि रोके न भी गये तो भी उनको कम, मर्यादित एवं थोड़ा विध्वंसक बनाया जा सकता है। नि.शस्त्रीकरण द्वारा दो प्रकार से युद्ध रोकने में सहायता की जा सकती है। प्रथम तो इससे कोई भी राष्ट्र तुरन्त एवं अवस्थित रूप से युद्ध छेड़ने में असमर्थ बन जायगा। दूसरे, इससे राष्ट्रीय कक्षीय के परस्पर द्वेषतापूर्ण सम्बन्ध घट जायेंगे तथा राष्ट्रीय हितों के पारस्परिक समायोजन (Adjustment) के अनुकूल वातावरण बन जायगा। प्रोफेसर हार्टमैन (Professor Hartman) के अनुसार 'नि शस्त्रीकरण के प्रयास युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की कल्पनात्मक आशा की पूर्ति के लिए नहीं अपितु अन्धधुंध में डाल देने वाले तथा यथार्थ रूप से होने

घाले आक्रमणों को रोकने के लिए किये जाते हैं।' व आगे कहते हैं कि 'निर्गन्धीकरण का अर्थ आवश्यक रूप से निर्गन्ध बनाना नहीं है। दूध का लक्ष्य तो यह है कि जो भी इच्छित रूप समय उपस्थित है उनके प्रभाव को घटा दिया जाय।'

अन्य विचारकों का विश्वास है कि गन्ध न कारण युद्ध नहीं किया जाता बरन् अन्तः प्रचलित युद्ध का कारण गन्ध का निर्माण किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान शुमा (Schuman) के मतानुसार युद्ध अन्तः प्रचलित युद्ध का एक रूप है जो कि निर्गन्धता सम्भावित हो कि तु अब समय का आग्रा हावी है तो दशरा की दोड़ प्रारम्भ हो जाता है। 'दशरा युद्ध में निकलते हैं तथा युद्ध में योगदान से उनको बढ़ावा मिलता है। जो लोग यह मानते हैं कि गन्ध का कारण युद्ध लगे जाते हैं व शुमा के शब्दों में गांधी को धर्म में पहले रखने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि धर्म को अवहलना का जो सकती है और उस पर इतना प्रभाव भी नहीं होता जबकि गांधी का इच्छानुसार गोता जा सकता है चाहे उस माहल का कोई प्रभाव ही न हो।

(२) शांति की हानि और यह विश्वास कि
दशरा का कारण युद्ध लगे जाते हैं

यह सही है कि वि. व. क. अफ्रीका लोगों का अश्वों की हानि रोकने की ओर ध्यान इस कारण गया है कि आज का अश्व युद्ध एवं सम्पूर्ण युद्ध (Total War) का परिणाम मानव शांति का, उसकी आज तक अविश्व सम्पत्ति और सम्पत्ति का विनाश है किन्तु इसका माप ही यह भी नहीं मूलाया जा सकता कि शांति प्रतीति न समुदाय दूध प्रारम्भ से ही दशरा को कम करने का उद्योग करता रहा है क्योंकि उसका विश्वास है कि गन्ध का कारण ही युद्ध लगे हैं। अमेरिकन मित्र सेवा समिति (American Friends Service Committee) का दृष्टिकोण था कि गन्धीकरण देश की सुरक्षा की मजबूती नहीं करता बरन् युद्ध का तथा विश्व का अश्वानुत्पन्न बनाता है। एक दशरा केवल सुरक्षा की दृष्टि से ही दशरा बना रहा है किन्तु इसका उद्योग पड़ोसी का रक्तचाप बढ़ जायगा उस सदह हानि नयगा कि इसका तत्त्व क्या है। आज यदि भारत अश्वों का जारों से निर्माण प्रारम्भ कर दे तो पाकिस्तान का इसका आशय होगा, इसी प्रकार पाकिस्तान भारत में भय पैदा कर सकता है। दोनों के भय विश्व का दशरा की दोड़ का सायादार बना देगा कि हिंसा की सुरक्षा करने में सफल नहीं हो सकता। एक दशरा द्वारा अश्वों का निर्माण तथा उसकी प्रतिक्रिया अश्व दूध द्वारा दशरा का निर्माण यद्यपि सुरक्षा का नाम पर किया जायगा किन्तु

अब मे, हमसे हाँ में हो देश अपने आप ही अंतरांगिन समझने लगेंगे । यदि प्रत्येक देश यह समझने लगे कि दूसरे देश के पास इतने शस्त्र नहीं कि वह तुरन्त ही कोई भयकर आक्रमण कर सकेगा तो अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की प्रवृत्ति में एकात्म परिवर्तन आ जायगा । कोहन (Cohen) के शब्दों में सम्बन्धों राष्ट्रीय के बीच भय और मन-मुटावों की स्थिति पैदा करता है । निष्पत्तीकरण द्वारा भय और मन मुटावों को कम करके शान्तिपूर्ण समझौतों की प्रवृत्ति को सुविधापूर्ण एवं शक्तिशाली बनाया जा सकता है ।

कुछ विचारकों का यह मत है कि शस्त्रों द्वारा युद्ध की प्रेरणा मिलती है । हो सकता है कि भूतकाल में जबकि विश्व का स्वरूप साम्राज्य था, हथियार युद्ध का फल बन जाते थे किन्तु आज की परिस्थितियों में निरुत्पत्त हो हथियारों के कारण विश्व के देशों के बीच मन-मुटाव, झगड़े और भय पैदा होते हैं । किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि वे ही युद्ध के एकमात्र कारण हैं तथा उनको मिटा देने पर लड़ाईयां समाप्त हो जायेंगी । इसके विपरीत अनेक लोगों की यह मान्यता है कि यदि शस्त्रों को पूरी तरह से नष्ट भी कर दिया जाय तो भी लोग लड़ेगे । वे लाठी, छड़ी, कील और नाखूनों से ही लड़ेंगे । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शस्त्र लड़ाई का साधन हैं, चाटना नहीं और साधनों का परिवर्तन भी किया जा सकता है किन्तु किसी कार्य को मिटाने के लिए उनके कारणों पर आघात करना होता न कि उनके नामों पर, मुर्गों को मारने की अनेक झगड़े पर ही बार करना होगा ।

कुछ राष्ट्रीय शास्त्री यह मानते हैं कि पूर्ण निष्पत्तीकरण न तो सम्भव है और न ही उपयोगी । राष्ट्रीय राज्यों से पूर्ण समाज की ही बात ही क्या है यदि अन्तराष्ट्रीय समाज में विश्व सरकार की स्थापना हो जाय तो भी शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए वायुन और शक्ति प्रयोग की आवश्यकता रहेगी । किन्तु इन विचार का अर्थ भी यह कदापि नहीं है कि शस्त्रों की बीड़ को ज्यों की त्यों बचने दिया जाय । दोनों स्थितियों के बीच का मार्ग करना होता है उनको एक व्यावहारिक रखा । यदि पूर्ण निष्पत्तीकरण दिया जाय तो उसी लागू करना कठिन होगा क्योंकि कोई भी देश अपने चालीस वर्षों में मे बीम को नष्ट कर दे तथा बीम को पुनः के ता उसे कोई देल नहीं सकता । इन धोखेबाजी से वे देश मुक्तकाल में रहेंगे जिन्होंने ईमानदारी के साथ सभी शस्त्रों को नष्ट कर दिया है । इन जटिलताओं को देख कर ही यह सुझाया जाता है कि सीमित निष्पत्तीकरण करना चाहिए ताकि एक देश यदि निरिच्छता सोमा से कुछ अधिक-व्यवहार किया रहे तो भी कोई

परेशानी पैदा न हो सके। इस प्रकार निशस्त्रीकरण सीमित हो अथवा पूर्ण इस सम्बन्ध में विश्व के राष्ट्रों एवं विचारकों के बीच भारी मतभेद है।

निशस्त्रीकरण के रूप (The Types of Disarmament)

निशस्त्रीकरण के अभिप्राय और उसकी आवश्यकता तथा महत्व आदि को समझने के उपरान्त निशस्त्रीकरण प्रयासों का इतिहास या परिचय जान लेना आवश्यक है, किन्तु इसके पूर्व निशस्त्रीकरण के कुछ प्रमुख रूपों को भी जान लेना चाहिये जो निम्नलिखित हैं—

(१) सामान्य निशस्त्रीकरण (General Disarmament)—
निशस्त्रीकरण के इस प्रयास में भाग लेने वाले सभी सम्बन्धित राष्ट्र होते हैं। उदाहरणार्थ १९३२ के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन का नाम लिया जा सकता है।

(२) स्थानीय निशस्त्रीकरण (Local Disarmament)—इस रूप में केवल कुछ सीमित राष्ट्र ही भाग लेते तथा प्रभावित होते हैं। कनाडा व अमेरिका के बीच १८१७ का रसबेगोट (Rush bagot) समझौता इसका उदाहरण है।

(३) मात्रात्मक निशस्त्रीकरण (Quantitative Disarmament)—
इस रूप में हर तरह के सभी शस्त्रों की कमी की जाती है। १९३२ के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन के अधिकांश राष्ट्रों का यही उद्देश्य था।

(४) गुणात्मक निशस्त्रीकरण (Qualitative Disarmament) —
इसके अनुसार विशेष प्रकार के शस्त्रों को कम करने या समाप्त करने की गिकारित की जाती है। जैसे सशस्त्र राष्ट्रों का अणु शक्ति की रोक व समाप्ति पर विचार करना रहा है।

निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों का इतिहास

(The History of Disarmament Measures)

विश्व इतिहास या अन्तर्ग्रहण करने पर निशस्त्रीकरण के प्रयासों को दो श्रेणियाँ दीर्घाई देती हैं। एक ओर तो वे प्रयास हैं जो कुछ देशों द्वारा दूसरे देश पर जबरदस्ती निशस्त्रीकरण लागू करने के लिए किये गये हैं तथा दूसरी ओर वे प्रयास हैं जिनमें देश अपनी इच्छानुसार समान शर्तों और सहयोगपूर्ण वातावरण के अनुसार भाग लें रहे हैं। जबरदस्ती के निशस्त्रीकरण (Enforced Disarmament) के अन्तर्गत उदाहरण अतीत के गर्भ से निवाले जा सकते हैं। इतिहास में कई बार जीने हुए राष्ट्र द्वारा हारे हुए राष्ट्र को शस्त्रों रहित होने के लिए बाध्य किया गया है। ऐसे निशस्त्रीकरण

के उदाहरण हमें १८०६ में नेपोलियन द्वारा प्रुशिया (Prussia) की हार के समय, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद वारसा की सन्धि में और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली के साथ शांति सन्धि में प्राप्त होते हैं। निःशस्त्रीकरण के इस प्रकार के प्रमाण कोई स्थायी प्रभाव रखने में असमर्थ रहते हैं। इसके दो कारण हैं प्रथम तो विदेशी राष्ट्र द्वारा कोई प्रमाणशील एवं निरन्तर निरीक्षण (Supervision) रखने की चेष्टा नहीं की जाती, दूसरे यदि इन प्रकार के निःशस्त्रीकरण के उन्मूलन किये जायें तो आवश्यक रूप से उनका विरोध नहीं किया जाता। जब विदेशी राष्ट्रों का सम्बन्ध इन टूट जाता है तो विविध राष्ट्र की यह दृष्टि नहीं रहता कि मैसिको की मर्तों तथा सम्पत्ति-निर्माण को पुनः प्रारम्भ कर दें। आधुनिक युग में एक देश को पूरी तरह सम्पत्ति-विहीन करने के लिए उसकी औद्योगिक शक्त को नष्ट करना आवश्यक है। जब तक औद्योगिक आधार रहता है तब तक पुनः शस्त्रीकरण की शक्ती एवं सम्भावना भी रहती है। इसके अलावा कोई भी देश सुन्मन्त्रित इन समाज में निःसम्पत्ति रहकर अपने आपको रक्षित नहीं समझता, चाहे उसके हितों की रक्षा के लिये कितने ही आश्वासन क्यों नहीं दे दिये जायें।

निःशस्त्रीकरण का अन्य रूप ऐच्छिक (Voluntary) है जिनमें भाग लेने वाले राष्ट्र स्वैच्छा से ही अपने शस्त्रों को सीमित करने के लिये वातचीत और समझौतों द्वारा प्रयत्न करते हैं। निःशस्त्रीकरण, जैसा कि मार्गेन्थो (Morgenthau) का कहना है, "शस्त्रों की दौड़ के समाप्त करने के लिए युद्ध या सभी देशों को कम उपद्रव मनाउ कर देना है।" इस नर्तक-विहित अर्थ में निःशस्त्रीकरण की दृष्टि में आज तक अनेक प्रयास किये गये हैं, यद्यपि ये प्रयास असफलता की कहानी मात्र ही हैं।

निःशस्त्रीकरण के प्रयासों के इतिहास का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में कर सकते हैं—

- (१) समुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व किये गये प्रयास, एवं
- (२) समुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद किये गये प्रयास।

समुक्त राष्ट्रसंघ से पूर्व निःशस्त्रीकरण के प्रयास
(Disarmament Measures before U. N. O.)

मार्गेन्थो के शब्दों में "निःशस्त्रीकरण के प्रयासों का इतिहास अनेक अक्षर-पत्रों और अनेक मन्त्रालयों की कहानी है।" समुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना से पूर्व ही इन कहानियों का विपन्न विन्मोहित शीर्षकों के जटिलत किया जा सकता है—

(१) हेग सम्मेलन (Hague Conferences)—वैसे तो १८१७ में रूस के जार ने, १८३१ में फ्रांस ने तथा कई बार नेपोलियन तृतीय ने और १८७० में ब्रिटेन ने सामान्य निःशस्त्रीकरण के प्रस्ताव दूसरे देशों के सम्मुख

रहे थे। किन्तु इस प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रथम सम्मेलन १८६६ में हीग में बुलाया गया। इस सम्मेलन में सभी बड़ी शक्तियों सहित २८ राष्ट्रों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य शस्त्रों तथा सैनिक बजट का सीमित करना था। इसने सभी सदस्य राष्ट्र इस बात पर सहमत थे कि मानवता के नैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए शस्त्रों पर बड़े हुए सख्तों को कम करना जरूरी है। फिर भी तकनीकी कठिनाइयों के कारण यह संभव नहीं हो सका और पुनः मिलन की आशा में प्रसिद्धि मिल गई।

अमरीका ने चाहा कि १९०४ में इस सम्मेलन को बुलाया जाय। किन्तु रूस व जापान ने झगड़े के कारण ऐसा न किया जा सका। दूसरा हीग सम्मेलन १९०७ में हुआ। इसमें भाग लेने वाले ४४ राष्ट्र थे। इस सम्मेलन में १८६६ के सम्मेलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा तब से सैनिक बजट अब और भी अधिक हो गया था इसलिए यह कहा गया कि देशों को इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यह सम्मेलन भी अपने अवसर्जन की भाँति असफल रहा। सम्मेलन के अध्यक्ष ने बताया कि निःशस्त्रीकरण का प्रश्न १८६६ की भाँति इस सम्मेलन में भी अधिक गम्भीरता से न देखा जा सका। ऐसी स्थिति में पहले भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सका था अतः इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगले आठ वर्षों में सम्मेलन की पुनः बैठक बुलाने का फैसला किया गया किन्तु उन दिनों विश्व युद्ध का ज्वार अपनी पूरी तेजी पर था।

(२) राष्ट्रमंडल द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयास और जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन (League of Nations Geneva Disarmament Conference)—प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के बाद पुनः निःशस्त्रीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार हुआ और राष्ट्रमंडल की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। राष्ट्रमंडल के संधि (Covenant) के आठवें अनुच्छेद में निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी निम्न लक्ष्य व्यवस्था दी गई—

‘इस अनुच्छेद के प्रथम प्रकरण में यह व्यवस्था थी कि ‘सब के सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि सैनिकी स्थापना के लिए राष्ट्रों की सुरक्षा के अनुकूल न्यूनतम बिंदु तक राष्ट्रों की शक्ति का कमो अल्प सामान्य कार्य द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के दृष्टिकोण को आवश्यकता है।’

दूसरे प्रकरण में यह वर्णित था कि ‘प्रत्येक राष्ट्र को भौतिक शक्तों एवं परिस्थितियों का लेवा स्वरूप परिपक्व विचार करने से द्वारा विचार और कार्यवाही के निम्न प्रस्तावना में बना सम्बन्ध को बनाए रखा जाये।’

चौथे प्रकरण में यह व्यक्ति था कि "जब बहुत सी सरकारें इन योजनाओं को अपना लेंगी तो उसके बाद उसी निश्चित शस्त्रों की सीमाएँ परिपक्व की सहमति के बिना नहीं हो सकेंगी।"

पाचवें प्रकरण में लिखा गया कि "सभ के सदस्य सहमत हैं कि व्यक्तिगत साहस द्वारा युद्ध सामग्री के निर्माण के लिये स्पष्ट रूप से गम्भीर हस्तक्षेप किये जा सकते हैं। परिपक्व यह परामर्श देगी कि ऐसे निर्माण से सम्बद्ध कुटिल प्रभाव किस प्रकार हटाये जा सकते हैं।"

छठे प्रकरण में सभ के सदस्यों को "अनेक शस्त्रों के परिमाण, अपने सामूहिक एवं वायु सम्बन्धी कार्यक्रम तथा युद्ध जैने उद्देश्यों के लिये उपयुक्त उनके उपयोगों की अवस्था की पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना के पारस्परिक परिवर्तन के लिये उत्तरदायी ठहराया।"

आठवें अनुच्छेद के अतिरिक्त २३वें अनुच्छेद के 'द' प्रकरण में यह व्यवस्था की कि 'सभ के सदस्य सभ को उन देशों के साथ शस्त्र एवं युद्ध-सामग्री के व्यापार का निरोधन चाहे सौन दोगे जिनमें कि सामान्य हित के लिये इस व्यापार पर नियन्त्रण आवश्यक है।'

जनवरी, १९२० में राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत एक स्थायी परामर्शदाता (Permanent Advisory Commission) आयोजन गठित किया गया जिसमें सैनिक विशेषज्ञ ही सदस्य थे। नवम्बर, १९२० में आमोद में ६ अस्थायी व्यक्ति बढ़ाकर उसे अस्थायी मिश्रित आयोग (Temporary Mixed Commission) के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। इस मिश्रित आयोग को निःशस्त्रीकरण की सन्धि का मसविदा तैयार करने का काम सौंपा गया। अनेक असफलताओं के बाद आयोग ने पारस्परिक सहायता सन्धि का प्रारूप तैयार किया जिसमें निःशस्त्रीकरण को सामूहिक सुरक्षा का मूलधार बताया गया। अस्थायी मिश्रित आयोग एवं स्थायी परामर्शदाता आयोग ने निःशस्त्रीकरण समस्या के हल के लिये चार सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें १९२२ में सभ की तीसरी असेम्बली ने स्वीकार कर लिया वे सिद्धांत इस प्रकार थे -

(१) निःशस्त्रीकरण को कोई भी योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि वह व्यापक रूप से सब पर लागू न हो।

(२) अनेक राज्य अपने शस्त्रास्त्रों में कमी करने की स्थिति में तब तक नहीं जा सकते जब तक उन्हें सुरक्षा के लिये पर्याप्त आश्वासन न मिल जाय।

(३) ऐसे आश्वासन की व्यवस्था एक ऐसी प्रतिरक्षात्मक सन्धि द्वारा की जा सकती है जिसमें प्रत्येक राज्य एक दूसरे को सुरक्षा का आश्वासन तो

दे ही लेकिन यह आश्वासन भी दे कि आनमण की स्थिति में प्रत्येक राज्य आन्तान देश की रक्षा के लिये युद्ध करेगा।

(४) इस आश्वासन की श्रित्यान्विति बबल सभी सम्भव है जबकि सामान्य योजनानुसार शस्त्रास्त्रा में कमी की जा चुकी है।

पारस्परिक सहायता सन्धि क प्रारूप (Draft Treaty of Mutual Assistance) की अमफलता के बाद मध्यस्थता (Arbitration) के उपाय में सुरक्षा की समस्या हल करने का प्रयत्न किया गया। शूमेन के शब्दों में मध्यस्थता से सुरक्षा और सुरक्षा र नि शस्त्रीकरण का नया मार्ग ढूँढा न गया।

नि शस्त्रीकरण के सामान्य उपायों के विफल होने पर अक्टूबर, १९२४ के बाद से अन्वयो मिथिन आयोग ने काम करना बन्द कर दिया। अब नि शस्त्रीकरण सम्मेलन के लिये सज्जीकरण आयोग (Preparatory Commission for the Disarmament Conference) का गठन हुआ। इस आयोग की प्रथम बैठक मई, १९२६ में हुई और दिसम्बर, १९३० तक यह अस्तित्व में रहा। ६ दिसम्बर, १९३० को आयोग ने नि शस्त्रीकरण की योजना का एक स्थायी प्रारूप प्रस्ताव (Dummy Draft Convention) पास करने में सफलता अर्जित की जिसकी मुख्य व्यवस्थाएँ थी—

(१) वजट द्वारा स्थल युद्ध की रण-सामग्री पर नियन्त्रण किया जाय।

(२) सैनिकों की सरया बिना किसी भेद भाव के नियन्त्रित की जाय और प्रशिक्षित सुरक्षित सैनिकों (Trained Reserves) का विचार न किया जाय।

(३) अनिवार्य सैनिक सेवा के वर्गों की अवधि घटायी जाय।

(४) नौ-सैनिक जहाजों पर १९२२ के वाशिगटन सम्मेलन की तथा १९३० के लन्दन सम्मन्तन की व्यवस्थाओं को लागू किया जाय।

(५) हवाई अस्त्रों का नियन्त्रण अश्व शक्ति (Horse Power) के आधार पर हो।

(६) रासायनिक एवं जीवाणु फैलाने वाले (Bacteriological) युद्धों को रोक जाय।

(७) एक स्थायी नि शस्त्रीकरण आयोग की रचना की जाय तो नि शस्त्रीकरण की प्रगति के बारे में समय-समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहे।

सज्जीकरण आयोग के इस प्रस्ताव का व्यावहारिक मूल्य बहुत कम था और फरवरी, १९३२ में हान वाले नि शस्त्रीकरण सम्मेलन ने इसका

जर्मनी में हिटलर द्वारा शासन सत्ता संभालने के बाद यह योजना कारगर न हो सकी। १४ अक्टूबर, १९३३ को जर्मनी ने सम्मेलन छोड़ने की घोषणा कर दी। उसके एक सप्ताह बाद ही उसने राष्ट्र सघ की भी छोड़ दिया। १६ मार्च, १९३५ को जर्मनी ने वारसा की सन्धि के निरस्तरीकरण से सम्बन्धित उपबन्धों को खोलने रूप से अप्रभावकारी घोषित कर दिया। इस घोषणा के साथ ही युद्ध के नवीन दृश्यो का प्रदर्शन करने के लिए रणमय का पर्दा उठा। शूमा का यह विचार सत्य ही है कि अमफल निरस्तरीकरण सम्मेलन से तो कोई सम्मेलन न होता ही अच्छा है क्योंकि इसकी सफलता से मन मुटाव और गलतफहमी बढ़ती है। पुन शूमा के ही शब्दों में— '१६ वर्ष तक उपरोक्त पराजय का घेरा बन्द कर दिया गया। राष्ट्रसघ के द्वारा समार के निरस्तरीकरण के प्रयत्नों का आरम्भ जर्मनी के एक पक्षीय निरस्तरीकरण से शुरू हुआ था और जर्मनी के एक पक्षीय पुनः शस्तरीकरण से इन प्रयत्नों का अन्त हो गया। यूरोप की सामूहिक वृद्धि सुरक्षा की प्राप्ति में अमफल हो जाने के उपरान्त आत्मघात की तैयारियों में लग गये।'

राष्ट्रसघ के बाहर निरस्तरीकरण के प्रयास—राष्ट्रसघ के बाहर भी निरस्तरीकरण के लिए अनेक प्रयत्न किये गये। यहाँ भी अन्य अनेक प्रयत्नों की ही भाँति महा सन्धियों में विभिन्न मतभेद अपना प्रभाव जमावे रह। राष्ट्रसघ के बाहर निरस्तरीकरण के लिए मुख्य प्रयास निम्नलिखित हुए—

- (१) वाशिंगटन सम्मेलन (Washington Conference), १९२१-२२ ।
- (२) जेनेवा नौ सैनिक सम्मेलन (Geneva Naval Conference) १९२७ ।
- (३) लन्दन नौ सैनिक सम्मेलन (London Naval Conference) १९३० ।
- (४) द्वितीय लन्दन नौ सैनिक सम्मेलन (London Naval Conference), १९३५ ।

वाशिंगटन सम्मेलन (१९२१-२२)—राष्ट्रसघ ने जिस समय अपना निरस्तरीकरण कार्य आरम्भ किया, उस समय वाशिंगटन में राष्ट्रसघ से सर्वथा पृथक् एक नौ सेना निरस्तरीकरण सम्बन्धी सम्मेलन नवम्बर, १९२१ में आयोजित किया गया। इसमें ६ राष्ट्रों ने भाग लिया। जिनके सुदूरपूर्व में हित निहित थे। इसकी अध्यक्षता राज्य सचिव ह्यूजेस (Hughes) द्वारा की गई थी। ह्यूजेस ने अपन उद्घाटन भाषण में जल सेना की शक्ति को सीमित रखने के लिए एक सूत्र (Formula) रखा जिसके अनुसार

अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस व इटली की शक्ति को क्रमशः ५ ५ ३ १ ६७ : और १ : ६७ के अनुपात के रख दिया जाना था। किन्तु यह अनुपात केवल लड़ाई के जहाजों तथा लड़ाई के क्रूजर्स पर ही लागू होता था। हवाई जहाजों की लाने वाले पोतों (Aircraft-Carrier Tonnage) को किसी अन्य आधार पर सीमित करते हुए इनकी मात्रा को ३५,००० टन अमेरिका एवं ब्रिटेन के लिए, ८१,००० जापान के लिए तथा ६०,००० फ्रांस के लिए तथा इतना ही इटली के लिए निश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त दस वर्ष तक कोई बड़ा जहाज (Capital Ship) नहीं बनाया जा सकता था, केवल भरभरात हो जा सकती थी। वाशिंगटन सन्धि के अनुच्छेद XIX के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन व जापान इस बात पर सहमत हो गये कि कुछ अपवादों के अतिरिक्त प्रशान्त महासागर में जो यथास्थिति (Status quo) थी उसे यों का यों बनाये रखा जाए। वाशिंगटन सन्धि के रूप एवं व्यवहार पर विचार करने के बाद यह कहा जाता है कि यह एक आंशिक सफलता रही है। इसने निःसस्त्रीकरण के स्थान पर स्वायत्तत्व की स्थापना की तथा शस्त्रों की दौड़ को रोकने में कुछ कार्य किया किन्तु यह इस दौड़ को न तो समाप्त हो कर सकी और न ही इसने दौड़ को पीछे की ओर हो डकेला। क्रूजर पनडुब्बी तथा विध्वंसकों (Destroyers) को सीमित करने की समस्या पर यह पूरी तरह से असफल रही। इस सन्धि द्वारा जल सेना के वज्र में थोड़ी बनी की गई किन्तु बाद में जल-सेना शक्ति की प्रतिद्वन्द्विता उन विषयों पर केन्द्रित हो गई जिनको कि सन्धि द्वारा मर्यादित नहीं किया गया था।

जेनेवा नौ समझौता १९२७ :—सोप विचारों पर भी सीमा लगाने के लिए १९२७ में जेनेवा जल-सेना सम्मेलन बुलाया गया। फ्रांस तथा इटली ने इस सम्मेलन में यह कह कर उपस्थित होना अस्वीकार कर दिया कि जल-सेना तो एक भाग मात्र है, इस पर सम्पूर्ण शस्त्र समस्या की इकाई के रूप में विचार करना चाहिए। ब्रिटेन, जापान व अमेरिका ने इसमें भाग लिया। क्रूजर्स के बारे में अमेरिका व ब्रिटेन के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और यह सम्मेलन असफल हो गया।

लन्दन नौ सैनिक समझौता :—इस समस्या पर पुनर्विचार के लिए १९३० में लन्दन में जल-सेना सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में अमेरिका व ब्रिटेन मुख्य-पोतों, विध्वंसकों एवं पनडुब्बियों की अधिक से अधिक संख्या के बारे में एकरात हो गये। किन्तु जापानी पाँच वर्षों तक ये दोनों ही देश अपनी जल सेना को स्वोच्छेद सीमा तक रखने में असमर्थ रहे और १९३५ में दूसरा लन्दन सम्मेलन बुलाया गया।

द्वितीय लन्दन नौ समझौता — द्वितीय लन्दन सम्मेलन के समय तक जापान १९२२ की सन्धि को तोड़ने की घोषणा कर चुका था और ब्रिटेन ने नावो जमनी के साथ जल सेना के सम्बन्ध में एक सन्धि कर ली थी । इस सम्मेलन में जापान की उम मांग पर विचार किया गया जिसमें उमने जल-सेना के सभी प्रकार के शस्त्रों में बराबरी के स्तर की मांग की थी । अपनी मांग के अस्वीकृत हो जाने पर जापान ने सम्मेलन को छोड़ दिया । यह सम्मेलन प्रथम सम्मेलन की भांति स्थायित्व बनाये रखने में भी सफलता प्राप्त न कर सका । १९३७ में जर्मनी व रूस ने स्वीकृत सीमा पार कर दी और १९३८ में एक अफवाह के आधार पर सन्धि के तीन मूल हस्ताक्षर-कर्त्ताओं ने लडाकू जहाजों की सीमा ४०००० टन कर दी और इस प्रकार जल सेना नि शस्त्रीकरण का अन्त कर दिया गया ।

निष्कर्षतः १९१९ से १९३५ के मध्य नि शस्त्रीकरण की समस्या को हल करने व लिये राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत और इसके बाहर जो भी प्रयत्न किये गये, वे असफल रहे और अन्ततः गत्वा संसार की दूसरा महायुद्ध लड़ना पड़ा । शूमा के शब्दों में नि शस्त्रीकरण केवल एक याद रह गया । बारसा के बाद दो दशान्विधों में परम्परागत नि शस्त्रीकरण सम्मेलन के द्वारों पर बड़े अक्षरों में अंकित 'असफलता' के अक्षर पड़िबसो संसार के आगामी विनाश के अक्षर हो गये ।

नि शस्त्रीकरण के प्रयासों की विफलता के कारण—प्रथम महायुद्ध के बाद नि शस्त्रीकरण के प्रयास मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से असफल हुए—

(१) संसार के विभिन्न राष्ट्रों की वास्तविक शान्ति में कोई आस्था न थी । हर राष्ट्र अपने शस्त्रास्त्रों के उत्पादन को "राष्ट्रीय सुरक्षा" का बाना पहनाना था और जब दूसरा राष्ट्र शस्त्रों की वृद्धि करता तो उसे युद्ध लिपेसु कहता था ।

(२) विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोणों में उग्र मतभेद थे । उदाहरणार्थ, फ्रांस नि शस्त्रीकरण से पहले सुरक्षा की स्थापना आवश्यक मानता था और राष्ट्र संघ की अल्पशक्ती में शान्ति एवं सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सेना का पक्षपाती था । इसके विपरीत फ्रेड्रिच ब्रिटेन का कहना था कि शस्त्रास्त्रों की उपस्थिति में सुरक्षा का वातावरण कभी सम्भव नहीं हो सकता, अतः पहले नि शस्त्रीकरण की समस्या का समाधान होना चाहिए और तब सुरक्षा का प्रश्न उठना चाहिए ।

(३) महाशक्तियों ने नि शस्त्रीकरण के सिद्धान्त में अविश्वास और पक्षपातपूर्ण व्यवहार का नाम प्रदर्शन किया । उदाहरणार्थ "प्रथम महायुद्ध के विजेताओं ने जर्मनी का नि शस्त्रीकरण तो बलपूर्वक कर दिया, किन्तु

पचनरुद्ध होने पर भी वे अपने निःशस्त्रीकरण को बराबर टालते रहे। जब उन्हें स्वयं को निःशस्त्रीकरण में विश्वास था तो फिर वे उसे सफल भी कैसे बना सकते थे।

(४) शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने वाली कम्पनियों ने निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों का विकृत बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया।

(५) शस्त्रीकरण की यथार्थ व्याख्या और स्वतंत्र निर्धारण के बारे में विभिन्न राष्ट्रों में मतभेद नहीं था। राष्ट्रों में इस प्रश्न पर गम्भीर मतभेद था कि रक्षात्मक अथवा आक्रमणकारी शस्त्रों के बीच क्या विभेद है।

(६) विभिन्न राष्ट्रों को युद्ध सम्बन्धी मनोवृत्ति में मौलिक मतभेद था। कुछ राष्ट्र युद्ध का सहारा लेने को उत्सुक थे तो कुछ गति के रूपासक। कुछ लोग ऐसे भी थे जो सत्ता हड़पने के लिए अपने देश के नागरिकों का ध्यान विदेश नीति में ही उनशाना चाहते थे ताकि उन्हें अपने देश की आन्तरिक वस्तुस्थिति का पता न लग सके। ऐसे नेताओं का तर्क था कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शान्तिमय तरीकों से करने की बात सोचना निरी बेवकूफी है। फासिस्ट इटली और नाज़ी जर्मनी के नेता युद्ध को मानव जाति के लिए न केवल आवश्यक अपितु गौरवपूर्ण मानते हुए उसे शौर्य, साहस, वीरता, त्याग और बलिदान आदि धौंठ गुणों को विकसित करने वाला समझते थे।

(७) शान्तिप्रेमियों की सुरक्षा का प्रश्न निःशस्त्रीकरण प्रयासों के मार्ग में बाधा रहा।

(८) निःशस्त्रीकरण-प्रयासों एवं सम्मेलनों की गति का आठवां प्रमुख कारण यह था कि समस्या को सुमझाने का प्रयत्न मौलिक रूप से नहीं, बरन् ऊपरी तौर से तथा प्राविधिक रूप से किया गया था।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के बाद निःशस्त्रीकरण के प्रयास

(Disarmament Attempts after U. N. O.)

द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ जो विश्व में शान्ति और राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना का विकास करने में सफल हो गया। दो महायुद्धों के बाद मानवता इतनी प्रसन्न हो चुकी थी कि महायुद्ध की पुनरावृत्ति करके अपना अस्तित्व खोने को वह तैयार न थी। फलतः निःशस्त्रीकरण की समस्या एक बार फिर गम्भीर विचार का विषय बन गई। इस बार अलग-अलग के आविष्कार ने इस समस्या को अधिक जटिल किन्तु महत्वपूर्ण रूप प्रदान कर दिया। दुर्भाग्यवश समय बीतने के साथ-साथ निःशस्त्रीकरण की समस्या अधिक जटिल होती गई और आज तो यह

जटिलतम रूप लिये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि अबतक जो भी प्रयास इस समस्या को सुलझाने के लिए किये गये हैं वे अत्रिकाशित असफलता का इतिहास बोहराने हैं। यदि कुछ सफलता मिली भी है तो उस नगण्य हो कहना चाहिए।

द्वितीय महायुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जो वार्ताएँ सम्पन्न हुई उनके इतिहास को हम मोटे रूपा में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—प्रथम भाग के अन्तर्गत उस समय तक की वार्ताएँ सम्मिलित हैं जब केवल अमेरिका ही अणु-बम का स्वामी था, द्वितीय भाग का आरम्भ तब से माना जा सकता है जब सोवियत संघ ने भी अणु बम का निर्माण कर लिया। निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में ए.जी.वादी और मार्क्सवादी दोनों ही खेमों में विरोधी दृष्टिकोण मिलता है और इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघ भी है तथा निजी वार्ताएँ भी। द्वितीय महायुद्ध के बाद निःशस्त्रीकरण की दिशा में जो भी प्रयास किये गये हैं उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों में प्रकट करना उपयुक्त होगा—

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण की व्यवस्था—यद्यपि राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत निःशस्त्रीकरण के प्रयास असफल रहें थे, किन्तु विश्व के राजनीतिज्ञों ने निःशस्त्रीकरण की आशा न त्यागते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निःशस्त्रीकरण के प्रयास जारी रखे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाएँ की गई हैं जो आज भी यथापूर्व प्रभावी हैं। संघ का चार्टर निःशस्त्रीकरण को महामत्त और सुरक्षा परिषद दोनों ही की कर्तव्य सूची में सम्मिलित करता है। अनुच्छेद ११ में कहा गया है—“महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग के सामान्य सिद्धान्तों पर विचार कर सकती है, इनमें निःशस्त्रीकरण और शस्त्र-नियन्त्रण के सिद्धान्त भी शामिल होंगे।” अनुच्छेद २६ में उल्लिखित है—“अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की ऐसी ढंग से स्थापना करने और ऐसे ढंग से उसे बनाये रखने के लिए कि जिसमें सभार की जन शक्ति और आर्थिक साधनों की कम से कम मात्रा शस्त्रों पर खर्च हो, सुरक्षा परिषद पर यह भार होगा कि वह अनुच्छेद ४७ में बताई सैनिक हमला समिति की सहायता से ऐसी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्रसंघ के सदस्यों के सामने रखे, जिनसे शस्त्र नियन्त्रण की एक पद्धति स्थापित हो सके।”

आगे चल कर चार्टर का अनुच्छेद ४७ इस बात की व्यवस्था करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना और अभिवृद्धि के लिए सुरक्षा परिषद सेना स्टाफ समिति की सहायता से ऐसी सेनाएँ बनाने के लिए उत्तरदायी होगी, जिसमें सभार के मनुष्यों के आर्थिक साधनों का उपयोग

राष्ट्रीयकरण के लिए कम से कम हो। ये योजनाएं समुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के सामने पेश की जाएंगी जिससे कि वे शस्त्रों के नियम को समुचित व्यवस्था स्थापित कर सकें।

समुक्त राष्ट्रसभ ने प्रारम्भ में ही निराश्रयीकरण की समस्या पर ध्यान देना शुरू कर दिया। २४ जनवरी, १९४५ को सत्र द्वारा परमाणु शक्ति आयोग (Atomic Energy Commission) की स्थापना की गई जिसका प्रधान उद्देश्य था—

“एक ऐसी योजना का निर्माण जिसके अन्तर्गत राष्ट्र परमाणु शक्ति के उत्पादन को अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण के अन्तर्गत रखने को तैयार हो जाय, ताकि केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग की निश्चित व्यवस्था की जा सके और आणविक तथा सामूहिक विनाश के अन्य सभी शस्त्रों का पूर्ण निषेध किया जा सके।”

अणु शक्ति आयोग कार्य करता रहा, किन्तु इसे वांछित सफलता प्राप्त नहीं हुई। १४ दिसम्बर, १९४६ की महासभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अणुशक्ति आयोग के कार्य को बढ़ाने तथा सुरक्षा परिषद् को शस्त्रों की सीमित एवं मर्यादित करने की सिफारिश की गयी। हमारे शब्दों में इस प्रस्ताव का आशय था कि अणुशक्ति आयोग अपने कार्य में तीव्रता लाये तथा सुरक्षा परिषद् शीघ्रता पूर्वक शस्त्रों के पटाने और उनका निदमन करने की व्यावहारिक योजनाएं बनाये। इस प्रस्ताव के पारित होने के लगभग तीन मास बाद सुरक्षा परिषद् ने ‘परम्परागत हथियारों के आयोग’ (The Commission for Conventional Armaments) की रचना की। इस आयोग में सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्य थे। इन आयोग का कार्य केवल परम्परागत शस्त्रों को सीमित एवं नियमित करने के प्रस्ताव रखना ही था, अणु शस्त्रों एवं विनाश के व्यापक साधनों से इसका सम्बन्ध न था। इस कार्य के लिए परिषद् द्वारा अणु शक्ति आयोग की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी, जिसका उत्तर दे दिया जा चुका है।

निराश्रयीकरण समुक्त राष्ट्रसभ द्वारा उपरोक्त दो आयोगों की स्थापना भी हो गई और महा शक्तियों द्वारा विविध प्रस्ताव भी रखे गये लेकिन इन सब प्रयासों का नतीजा कुछ मिला कर दृश्य रहा। शान्ति की दिशा में हमारे विपरीत चलते इन प्रयासों ने शीत-युद्ध को प्रोत्साहन दिया। इन निराश्रयीकरण-बातालाप में कोई प्रगति नहीं हो सकी। महा शक्तियां अपने प्रस्ताव-प्रति प्रस्ताव रखती रही और विश्व-शान्ति का भविष्य अन्धकार में डालता रहा।”

१६ नवम्बर, १९५१ को पश्चिमी देशों ने राष्ट्रपति ट्रूमैन के इस सुझाव को अपने प्रसन व द्वारा नमस्तेन दिया कि "अणु शक्ति आयोग" और "परम्परागत हथियारों के आयोग" को मिलाकर उनके स्थान पर "मनुष्यन नि शस्त्रीकरण आयोग" (Disarmament Commission) की स्थापना की जाय और उसे यह काम सौंपा जाय कि वह एक ऐसी स्मिथ का प्राण्य तैयार करे जिसमें समस्त मनुष्य मेलानो और शस्त्रास्त्रों के इस दृष्टि में नियमन हो, जिसमें प्रत्येक देश के पास सुरक्षा के लिए तो पर्याप्त साधन रह जाय परन्तु वे साधन आक्रमण की दृष्टि से पर्याप्त न हों। इस प्रस्ताव में यह भी उल्लिखित था कि आयोग विभिन्न देशों के पास शस्त्रास्त्रों का पना लगाने के लिए प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की व्यवस्था की योजना बनये। १६ दिसम्बर, १९५१ को महासभा की राजनीतिज्ञ और सुरक्षा समिति ने पश्चिमी देशों के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। यद्यपि अणु शक्ति आयोग की स्थापना हो सकी किन्तु सोवियत विरोध के कारण आयोग द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

८ दिसम्बर १९५३ को मनुष्य राष्ट्र मधीय महासभा के समक्ष अपने भाषण में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति आर्जजन होवर ने कृत्यागकारी कार्यों के लिए अणु सामग्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय मग्रह स्थापित करने की अशील नीति जिसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी (International Atomic Energy Agency) अस्तित्व में आई।

अप्रैल १९५४ में नि शस्त्रीकरण समस्या पर विचार करने के लिए नि स्वीकरण आयोग की एक पक्ष राष्ट्रीय उस समिति की स्थापना की गई। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पनामा और रूस इसके सदस्य बन। नि शस्त्रीकरण के कार्य में प्रगति के लिए इस उस समिति की अनेक बैठकें हुई किन्तु कोई नतीजा नहीं निकल पाया। १९५४ तक पूरी तरह यह स्थिति ही चाली रही कि एक पक्ष की ओर से नि शस्त्रीकरण के जो प्रस्ताव आते, दूसरे पक्ष की ओर से टकरा दिये जाते।

जेनेवा-सम्मेलन, १९५५ तथा उन्मुख आकाश योजना—जुलाई, १९५५ में जेनेवा में अमेरिका के राष्ट्रपति तथा रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस के प्रधान मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति आर्जजन होवर द्वारा मुक्त आकाश की योजना (Open Skies Plan) प्रस्तुत की गई। इस योजना के अनुसार यह प्रस्ताव रखा गया कि रूस व अमेरिका एक दूसरे को अपनी सैनिक गतिविधियों से अवगत बनायें रहें और एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाये। इस प्रकार

से निःशस्त्रीकरण को सम्भव बनाने के लिए प्रभावशाली निरीक्षण पद्धति को गृह किया जा सकता है। सोवियत : घान मन्त्री द्वारा इस योजना की कड़ी आलोचना की गई। यह उनको कियो भी प्रकार स्वीकार्य न था। कारण यह था कि अमरीका के सैनिक अन्धे सारे विश्व में तिरहित हो रहे थे जबकि सोवियत रूस के उसके अपने ही देश में थे। इस हालत में अमरीका तो इस का सारा भेद जान जाता किन्तु सोवियत संघ अमरीका की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता। इसलिये सोवियत प्रधानमन्त्री कुर्गानिन ने एक दूसरा ही प्रस्ताव सम्मेलन के सामने रखा वह यह कि निःशस्त्रीकरण को प्रियान्वित करने के लिए अन्तराष्ट्रीय नियन्त्रण अभिकरण की स्थापना की जाय जिसमें अन्तराष्ट्रीय आधार पर निरीक्षकों की नियुक्ति की जाये— सभी देशों से विदेशी अड़्डों को खत्म कर दिया जाये—आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर पाबन्दी लगा दी जाय और परम्परागत शस्त्रों की बर्ती भी जाय। यह प्रस्ताव पश्चिम को मान्य न हुआ। शिंघर सम्मेलन में मतभेद बन रहे और इन मतभेदों के कारण ही अक्टूबर, १९५५ में हान वाला विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन भी इसी प्रकार असफल हो गया। दिसम्बर, १९५५ में भारत ने आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर पाबन्दी लगाने की माग की तथा शस्त्रों से सम्बन्धित एक अन्तराष्ट्रीय सन्धि का मुतावा दिया किन्तु अमरीका को यह स्वीकार न हो सका।

लन्दन सम्मेलन, १९५६ (London Conference)—निःशस्त्रीकरण उपसमिति की बैठकों में पैदा हुए मतभेदों को मिटाने के लिये १४ जून १९५६ को लन्दन में निःशस्त्रीकरण आयोग की उपसमिति की बैठक हुई। इस द्वारा इस सम्मेलन में त्रिसूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार था—

- (१) दो वर्षों के लिये आणविक परीक्षण बन्द कर दिया जाय।
- (२) आणविक परीक्षण की इस पाबन्दी को प्रियान्वित करने के लिए अन्तराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाय।

(३) उपयुक्त वैज्ञानिक शस्त्रों के सहित अमरीका, रूस तथा ब्रिटेन को मिलाकर प्रशान्त महासागर में नियन्त्रण चौकिया स्थापित की जायें ताकि इस समझौते के प्रियान्वित रूप पर निगरानी रखी जा सक। ये प्रस्ताव पश्चिम को मान्य नहीं हुए। इसके स्थान पर दूसरे प्रस्ताव रहे गये। आइजनहोवर ने मुझे आश्वासन वाला अपना प्रस्ताव दुहराया। सोवियत प्रतिनिधि जेरिन ने अपने पक्ष के समर्थन में बहुत कुछ कहा किन्तु सब कुछ अरण्य-रोदन की भांति बेकार गया। ६ सितम्बर १९५७ को उपसमिति ने सम्मेलन की असफलता घोषित कर दी। तत्पश्चात् इसकी बैठक बन्द हो गई।

नि शस्त्रीकरण आयोग का विस्तार एवं स्तूननिक कूटनीति—नि शस्त्रीकरण उा समिति को असफलता के बाद महासभा के बारहवें अधिवेशन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नि शस्त्रीकरण की दिशा में मोमित किन्तु सख्त कदम उठाने पर अधिक बल दिया। द्वार सोवियत सघ नि शस्त्रीकरण आयोग की सदस्य सख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा था। उसका कहना था कि महासभा के सभी सदस्य राष्ट्रों को उसमें स्थान दिया जाय। २६ मितम्बर, १९५३ को भारत द्वारा महासभा में एक प्रस्ताव पत्र करके यह माग की गयी कि नि शस्त्रीकरण आयोग और उसकी उा समिति में सदस्यों की सख्या बड़ाई जाय। इस प्रस्ताव में और भी कई सुझाव दिये गये थे जिनमें आणविक शस्त्रास्त्रों को सत्प करने पर अधिक जोर दिया गया। सोवियत सघ ने भारत का समर्थन करते हुए आयोग के सदस्यों को बढ़ाने का जोरदार आग्रह किया। वही इस बात की लेकर नि शस्त्रीकरण वातां हो न टूट जाय, इसलिए आयोग के सदस्यों की नवम्बर, १९५७ में सख्या बड़ा कर २५ कर दी गयी किन्तु इस इतने में ही संस्तुष्ट न हुआ उसने सख्त कह दिया कि जब तक नि शस्त्रीकरण आयोग में उनकी माग के अनुसार विस्तार नहीं किया जायगा, वह आयोग की किसी बैठक में शामिल नहीं होगा। वास्तव में सोवियत सघ को इस हठ के पीछे उस समय उसकी स्तूननिक कूटनीति काम कर रही थी। २६ अगस्त, १९५७ को रूस ने यह दावा करके पश्चिमी राष्ट्रों में भय और सन्देह जागृत कर दिया था कि उसने अन्तर-महाद्वीप प्रक्षेपणस्त्र (Inter Continental Ballistic Missile—ICBM) का सफल परीक्षण कर लिया है और इससे विश्वसक बम के गोले का दुनिया के किसी भी हिस्से में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में पंका जा सकता है। पश्चिम को पहले तो रूस की इस घोषणा पर विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब ४ अक्टूबर, १९५७ को रूस ने पृथ्वी के चारों ओर घूमन वाला एक कृत्रिम उपग्रह (Sputnik) छोट दिया तो सम्पूर्ण पश्चिमी जगत् रूस की इस वैज्ञानिक प्रगति से स्तब्ध रह गये और नि शस्त्रीकरण की आवश्यकता तीव्रता से अनुभूत की जाने लगी। चू कि इस समय शस्त्रों की दौड़ में सोवियत सघ का पत्रडा भारी हो चुका था, अतः नि शस्त्रीकरण के प्रति वह कड़े रथ का अवलम्बन करने लगा।

सुलगानिन योजना—यद्यपि दानो हो पक्षों की ओर से प्रस्तावों को प्रस्तुत एवं अस्वीकृत किये जाने का क्रम जारी रहा तो भी प्रस्तावकों न द्वार न मानी। ३ फरवरी १९५८ को रूसी प्रधानमन्त्री बुलगानिन द्वारा राष्ट्रपति आइज़नहोवर के सम्मुख नि शस्त्रीकरण की एक विस्तृत योजना रखी गई। इस योजना के मुख्य पहलू निम्न प्रकार थे—

(१) अगु ययों के परीक्षणों को दन्द दिया जाये।

- (२) अमरीका, रूस व ब्रिटेन आणविक सस्त्रों का परित्याग कर दें ।
- (३) जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देशों में विदेशी सेनाओं को घटाना जाए ।
- (४) नाटो तथा वारसावैकट के देशों में अनामन्यता समझौता हो ।
- (५) आणविक आक्रमणों को रोकना जाए ।

१५ मार्च, १९५८ को इन्हीं प्रस्तावों के आधार पर सोवियत विदेश मन्त्रालय द्वारा कुछ अन्य प्रस्ताव भी रखे गये । जैसे सैनिक प्रयोजनों के लिए बाह्य आकाश (Outer Space) के प्रयोग का नियंत्रण तथा समुचित राष्ट्रसंघ की देखरेख में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपरोक्त नियंत्रण के पालन का निरीक्षण किया जाये । अमरीकी गुट द्वारा इसका भी कोई संतोषजनक जवाब न दिया गया ।

रापाकी योजना (Rapaki Plan)—इसी समय पोलैंड के विदेश-मन्त्री ने एक योजना प्रस्तुत की । इस योजना में यूरोप में सुरक्षा और शान्ति बनाने रखने के लिए पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी को अणुबिहीन क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया गया था अर्थात् इन देशों में आणविक अस्त्रों का निर्माण, संचयण एवं उपयोग न किया जाए । सोवियत संघ द्वारा इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया किन्तु अमरीका की कोई सन्तोषजनक प्रतिक्रिया न हुई ।

सोवियत संघ के विविध प्रस्तावों की इस तरह अवहेलना होती रहने पर ३१ मार्च, १९५८ को उसने एकतरफा बान किया जिसे उस समय अप्रत्यक्ष-सहाय्यीय माना गया । उस दिन सुप्रीम सोवियत ने सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें यह कहा गया कि सोवियत संघ ने इस आशा से सभी प्रकार के आणविक परीक्षण बन्द कर दिए हैं कि अन्य देश भी उसका अनुसरण करेंगे । किन्तु यदि दूसरे देशों द्वारा आणविक परीक्षण बन्द न किये गए तो वह भी उनकी पुनः प्रारम्भ कर सकता है ।

आइजनहावर की प्रतिक्रिया—अमरीकी प्रशासन सोवियत संघ के स्तुतिपूर्ण कूटनीति से तग आ गया था अतः २ अप्रैल, १९५८ को राष्ट्रपति आइजनहावर ने रूस को इन प्रस्तावों का जवाब भेजा । उन्होंने कहा गया कि सोवियत संघ के सभी प्रस्ताव एवं आणविक परीक्षण का स्थान आदि प्रचारात्मक कार्य हैं । राष्ट्रपति द्वारा रूस के उन कार्यों का वर्णन किया गया जिनके कारण निःसस्त्रीकरण के बदले तक के प्रयास संभव नहीं हो सके थे । बाद में यह घोषणा की गई कि 'एनी बी टोक' में चल रहे अमरीकी आणविक परीक्षण

के समाप्त होने पर अमरीका को यह निश्चित हो गया कि रूस ने सबमुक्त परीक्षण बन्द कर दिये हैं तो अमरीका भी उनको बन्द करने की बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा।

जेनेवा सम्मेलन १९५८ (Geneva Conference)—३१ अक्टूबर, १९५८ से जेनेवा में नि शस्त्रीकरण पर अनेक प्रस्ताव पास किये गये। रूस का कहना था कि ये परीक्षण सदा के लिए बन्द कर दिये जायें, किन्तु अमरीका व ब्रिटेन प्रारम्भ में इनको एक वर्ष के लिये बन्द करने के पक्ष में थे। कुछ बातों पर दोनों पक्ष सहमत थे किन्तु फिर भी मतभेद की खाई इतनी चौड़ी थी कि दोनों किनारे मिल न पाये। इससे कोई उपयोगी समझौता न किया जा सका।

खुश्चेव का प्रस्ताव—सन् १९५९ में सोवियत रूस के प्रधानमंत्री द्वारा समुक्त राष्ट्र मध्य की महासभा में पूर्ण नि शस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि चार वर्ष की अवधि में सभी राज्यों को पूर्ण नि शस्त्रीकरण कर लेना चाहिए ताकि किसी राज्य के पास गुप्त करने का कोई साधन न रह जाए। राज्यों को सब प्रकार की सशस्त्र सेना का परित्याग करना था केवल शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए कुछ पुलिस शक्ति रखी जा सकती थी। खुश्चेव को इस पूर्ण नि शस्त्रीकरण की योजना को शायद दूसरे गुट वाले स्वीकार नहीं करते, इसी कारण उन्होंने आशिक नि शस्त्रीकरण की योजना भी प्रस्तुत की जिसमें निम्न सूत्र थे—

- (१) नाटो संगठन के सदस्य एवं पश्चिमी राज्यों के साथ वारसा पैक्ट के राज्यों की अनाक्रमण संधि हो,
- (२) एक राज्य दूसरे राज्य पर आकस्मिक आक्रमण रोकने के विषय में समझौता करे,
- (३) यूरोपीय राज्यों से सभी विदेशी सेनाएं हटाई जायें,
- (४) मध्य यूरोप में आणविक आयुधों से रहित क्षेत्र (Nuclear Free Zone) कायम किया जाए,
- (५) आकस्मिक आक्रमणों को रोक जा जाए।

खुश्चेव का विचार था कि नि शस्त्रीकरण का समझौता हो जाने के बाद उसे कार्यान्वित करने के लिए कठोर नियन्त्रण रखा जाय किन्तु नि शस्त्रीकरण के बिना नियन्त्रण का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसी प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव का सब देशों द्वारा स्वागत किया गया किन्तु पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसे मजाक का विषय बना दिया गया और इस प्रकार गतिरोध बना ही रहा।

जेनेवा सम्मेलन (Geneva Conference), १९६० — निःशस्त्रीकरण आयोग पर विचार करने के लिए पुनः १९६० में जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस बार एक ही समय दो सम्मेलन चल रहे थे एक तो दस राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन और दूसरा था आणविक क्लब के तीन सदस्यों की वार्ता जिसका लक्ष्य था आणविक परीक्षणों को रोक देना। ये दोनों ही सम्मेलन आसन्नक रूप से सफलता प्राप्त न कर सके। २६ जून, १९६० को दस राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन भी हो गया।

जुलाई १९६० से मई १९६३ तक का काल (The period between 1960 to 1963) — निःशस्त्रीकरण से सम्बन्धित प्रश्न पर रूसी एवं अमरीकी गुट के बीच कई बातों पर मतभेद है। उदाहरण के लिए आणविक परीक्षण, नियन्त्रण, आणविक आयुध, सैनिकों की सहाय, खुला आकाश, बाह्य अन्तरिक्ष आदि। दिसम्बर, १९६० में १० राष्ट्रों के निःशस्त्रीकरण आयोग का रुस ने इस आधार पर बहिष्कार किया कि वह संधि के सभी सदस्यों का एक आयोग बनाने की मांग कर रहा था। १९६१ में १८ सदस्यों का एक आयोग स्थापित किया गया किन्तु फ्रान्स ने इसका प्रारम्भ से बहिष्कार किया और केवल १७ सदस्य शेष रह गये। १९६१ में महासभा के मत करने पर भी सोवियत रुस द्वारा ५० मेगाटन बम का परीक्षण किया गया। नवम्बर ३, १९६१ को महासभा की राजनैतिक समिति में पांच अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि आणविक परीक्षणों पर जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता है तब तक इनको बन्द हो रखा जाय। ब्रिटेन, फ्रान्स, अमरीका व रुस चारों ही शक्तियों ने इसका विरोध किया किन्तु यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। बाद में साधारण सभा ने भी इसे स्वीकार कर लिया। साधारण सभा द्वारा एक और अन्य प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया जिसमें यह कहा गया था कि यदि किसी देश द्वारा आणुशस्त्रों का प्रयोग किया गया तो इसे संधि के चार्टर का खुला उल्लंघन माना जायगा। प्रस्ताव ने अमरीका में आणविक परीक्षण न करने की बात कही। रुस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि पश्चिमी शक्तियों का मत इसके विरोध में था।

मार्च १९६२ में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ किन्तु यह अधिक सफल न रहा। इसी समय जेनेवा में निःशस्त्रीकरण आयोग का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। भारत का यह प्रस्ताव था कि आणविक परीक्षणों का पता लगाने के लिए सदस्य राष्ट्रों के स्टेशन कायम किये जायें। अग्रेज में अमरीका द्वारा आणविक परीक्षण किया गया तथा जुलाई में सोवियत संघ द्वारा भी

ऐसा ही किया गया। इन सबके कारण निःशस्त्रीकरण की सारी आशाएँ लुप्त हो गयीं। १२ फरवरी, १९६३ को जेनेवा में निःशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारम्भ होने पर इस ने यह प्रस्ताव रखा कि दोनों ही पक्ष यह समझौता कर लें कि दूसरे देशों की भूमि में तीन महान् आणविक शक्तियाँ आणविक अड्डे कायम नहीं करेंगी। इस प्रस्ताव को पश्चिमी गुट द्वारा ठुकरा दिया गया।

अणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि १९६३ — कैंनेडी और खुश्नेव के प्रयत्नों से निःशस्त्रीकरण वार्ता में और प्रगति हुई। १४ जुलाई, १९६३ को मास्को में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ और २५ जुलाई, १९६३ को तीनों देशों ने "सीमित परमाणु प्रतिबन्ध सन्धि" पर हस्ताक्षर कर दिये।

वाशिंगटन, लन्दन तथा मास्को में सपुष्टि-पत्रों के आदान प्रदान के साथ १० अक्टूबर, १९६३ को यह संधि लागू हो गयी। उस समय तक लग-भग १०० राष्ट्र इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर चुके थे।

इस सन्धि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाह्य आकाश, जल और वायु-मण्डल में अणु-परीक्षण करने पर रोक लग गयी। १९५५ की आस्ट्रिया की शान्ति सन्धि के बाद पूर्व और पश्चिम का यह सबसे बड़ा समझौता था। इसका विश्व में सर्वत्र स्वागत हुआ। भारत ने इस संधि पर अन्य राष्ट्रों में प्रथम हस्ताक्षर किये। फ्रांस ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और माय्कादी चीन इस सन्धि का विरोधी रहा है।

अणु-परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि ५ धाराओं की छोटी सी, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में असाधारण महत्त्व रखने वाली सन्धि है। इसकी प्रस्तावना में तीनों देशों (ब्रिटेन, रूस व अमेरिका) ने यह घोषणा की है कि उनका प्रधान उद्देश्य—

"शयुक्त राष्ट्र सभ के सत्रों के अनुसार बढते अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में एक सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण का समझौता यथा सम्भव शीघ्र ही कराना है ताकि शस्त्रों के उत्पादन और निर्माण की प्रतिस्पर्धा बन्द हो सके।"

सन्धि की पाँचों धाराओं कााराश रूप में इस प्रकार है—

पहली धारा में तीनों देशों द्वारा यह निश्चय किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र और नियन्त्रण में विद्यमान किसी भी प्रदेश के वायु-मण्डल में, इसकी सीमाओं में, बाह्य अन्तरिक्ष में, प्रादेशिक अथवा महासमुद्रों के जल में कोई भी आणविक विस्फोट नहीं करेंगे और इस प्रकार के आणविक विस्फोटों को रोक देंगे।

दूसरी धारा में सन्धि के संशोधन की व्यवस्था है। सन्धि में संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सरकार द्वारा रखा जा सकता है और हस्ताक्षरकर्ता राज्यों में से यदि एक-तिहाई प्रस्ताव के पक्ष में हों तो संशोधनो पर विचार हो सकता है।

तीसरी धारा के अनुसार इस सन्धि पर सब देश हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह व्यवस्था है कि हस्ताक्षरकर्ता देश इस पर अपनी ससद अपना राष्ट्रीय परिषद् से इसकी पुष्टि करेंगे और इन पुष्टियों या सपुष्टियों को उन्हें हस, अमेरिका एव फ्रेट ब्रिटेन के पास जमा कराना पड़ेगा।

चौथी धारा में उल्लिखित है कि यह सन्धि असीमित अवधि (Unlimited duration) के लिए है, हालांकि हस्ताक्षरकर्ता प्रत्येक देश को यह अधिकार होगा कि वह अपनी राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए उस समय स्वयं को इस सन्धि की बाध्यताओं से मुक्त कर ले, जब वह यह निर्णय करे कि इस सन्धि से सम्बन्धित ऐसी असामान्य घटना घटित हुई है कि उससे उस देश का सर्वोच्च हित सफट में पड़ गया है। इस धारा में कहा गया है कि उपरोक्त अवस्था में सन्धि से हटने की इच्छा करने वाले देश सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य देशों को तीन महीने पहले अपने पुष्क होने का नोटिस दे देगा।

पाचवी धारा में यह कहा गया है कि इस सन्धि के उसी भाषा के तथा अंग्रेजी के दोनों रूप समान रूप से प्रामाणिक समझ जायेंगे।

अगु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि का सत्कार के अधिकांशतः सभी छोटे बड़े राष्ट्रों ने पूर्ण स्वागत किया। यह सन्धि केवल निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ही एक महान् घटना नहीं थी, बरन् यह शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में भी एक प्रभावशाली सुसंवात थी जिसके कारण विश्व इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारम्भ हुआ।

नि शस्त्रीकरण की दिशा में १९६३ के उपरान्त किये गये प्रयास— १९६३ में राष्ट्रपति कर्नेडी की हत्या हो गई। नये अमेरिकन राष्ट्रपति लिन्डन बी. जॉनसन की घुम-कामना सन्देश भेजते हुए उसी प्रधानमंत्री खू र्खेव ने इस बात पर बल दिया कि नि शस्त्रीकरण सम्बन्धी प्रयासों के साथ-साथ संघर्षों के कारणों को दूर करने के और सीमा संघर्षों के कारण को मिटाने के तथा सीमा शिवाशों को हल करने के लिए बल-प्रयोग न करने की प्रभाव-शाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जाय। थी खू र्खेव ने सुझाया कि एक ऐसी सन्धि की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत सीमा संघर्षों के समाधान के लिए बल-प्रयोग करना वर्जित कर दिया जाय।

माचं, १९६४ में जेनेवा में नि शस्त्रीकरण सम्मेलन पुन प्रारम्भ हुआ जिसमें अमेरिका और रूस की तरफ से प्रस्ताव प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। किन्तु इन प्रयत्नों का कोई मसुर फल नहीं निकला। सितम्बर में नि शस्त्रीकरण सम्मेलन कुछ काल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसी के कुछ दिनों बाद ५ अक्टूबर, १९६४ को काहिरा में तत्सम राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री और मिश्र व राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने संयुक्त विज्ञप्ति में पूर्ण नि शस्त्रीकरण पर बल दिया।

कुछ ही दिनों बाद चीन ने अपने प्रथम अणुबम का परीक्षण कर लिया। १९६३ के जेनेवा समझौते का यह प्रथम उल्लंघन था। सारे सप्ताह में इसकी बड़ी आलोचना हुई। २६ नवम्बर, १९६४ को संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके नि शस्त्रीकरण आयोग से आग्रह किया कि परमाणुबम आयुधों के सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्वक किसी प्रकार का समझौता अवश्य होना चाहिए।

२७ जुलाई, १९६५ को जेनेवा में नि शस्त्रीकरण के आयोग की बैठक फिर बुलाई गई। सम्मेलन के आरम्भ होने के समय ही रूसी और अमेरिकन मतभेद तेजी से उभर आये। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने ऐसे ऐसे भाषण दिये कि सम्मेलन के भाग्य का पैमला हो गया। यद्यपि दोनों ही पक्षों में आणविक आयुधों की भयानकता के सम्बन्ध में कोई मतभेद न था, लेकिन इन आयुधों की नियन्त्रण करने के तरीकों के बीच हाट-तीव्र मौलिक मतभेद थे।

तत्सम राष्ट्रों के प्रयत्नों से १७ राष्ट्रों का (भारत सहित) नि शस्त्रीकरण सम्मेलन पुन जेनेवा में प्रारम्भ हुआ जो जनवरी, १९६६ से अगस्त तक पूरे ७ महिने चलता रहा। सम्मेलन में दोनों ही शक्तियाँ अपनी हठवादी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती रही जिसका स्वाभाविक परिणाम यह निकला कि यह सम्मेलन भी बिना किसी प्रकार महत्वपूर्ण निर्णय के ही समाप्त हो गया।

१९६८ की परमाणु अस्त्र विरोधी संधि (The Non-Proliferation Treaty, 1968)—नि शस्त्रीकरण की दिशा में तथा परमाणु अस्त्रों पर रोक लगाने के लिए प्रयासों का प्रथम चलावा रहा और १९६६ में जेनेवा में पुन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन भी ऊपटे ऊपटे लगभग सा चला ही था कि अगस्त के अन्तिम सप्ताह में अमेरिकन और रूसी प्रतिनिधियों ने यह घोषणा की कि परमाणु अस्त्र संधि के मसविदे के बारे में दोनों महा शक्तियों में मोटे तौर पर एक समझौता हो गया है।

इस प्रस्तावित संधि अथवा समझौते का मसविदा बड़ा लम्बा चौड़ा था तथापि साराशत उसकी मूल दाने निम्नानुसार थी —

मसविदे के पहले अनुच्छेद में यह कहा गया है कि परमाणु-अस्त्र सम्पन्न राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता न देगा।

दूसरे अनुच्छेद में कहा गया था कि हस्ताक्षर करने वाले परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे।

तीसरा अनुच्छेद परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में था। इस अनुच्छेद में कुछ एक पवित्र है। अभी इस विषय में कोई समझौता नहीं हो सकता है।

चौथा अनुच्छेद उन राष्ट्रों को आश्वस्त करने के लिए रखा गया है जिन्होंने अपने यहां का एंथ्रैक उद्योग का काको विकास कर लिया है। इसमें कहा गया है कि हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों को अर्पणिक कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का विकास करने में पूरी छूट रहेगी।

पाचवें, छठे और सातवें अनुच्छेद में कार्यान्वि-सम्बन्धी व्याख्याएँ थीं—लेकिन सन्धि में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि अगर किसी परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र पर कोई परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र हमला करता है तो हस्ताक्षर करने वाले देश उसके वधवाक्य की क्या व्यवस्था करेंगे? तीसरे अनुच्छेद के बारे में कोई समझौता न हो सकने के कारण किन्हाल किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की परिकल्पना भी नहीं हो सकी है जो किसी परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र का परमाणु-अस्त्र बनाने से रोक न करे, जो विभिन्न देशों के परमाणु-शक्ति के विकास के कार्यक्रमों का निरोधन और नियन्त्रण करके यह गारन्टी दे सके कि अर्पणिक उपयोग के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सैनिक उपयोग में नहीं आयेगा और जो हस्ताक्षर करने वाले परमाणु शक्ति-विहीन राष्ट्रों की शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों में परमाणु शक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी और सामग्री दिया सके।

स्पष्ट है कि जगत्-व्यापक व्यवस्थाओं के जन्म में प्रस्तावित संधि का कोई महत्व नहीं रह गया और इसीलिए परमाणु अस्त्र-विहीन राष्ट्रों ने मसविदे की जमकर आलोचना की। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और भारत ने संधि पर बहुत अधिक आपत्ति की। पश्चिमी जर्मनी, इटली और फ्रांस ने यह महसूस किया कि परमाणु अस्त्र सम्पन्न सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन के सामने वे यूरोप में बौने होकर रह जायेंगे। भारत को परमाणु-अस्त्र सम्पन्न

चीन से अपरदस्त खतरा है और प्रस्तावित सन्धि हम खतरे को दूर नहीं कर सकती।

अनक राष्ट्रो द्वारा विभिन्न त्रापस्थितियों के बावजूद भी २४ अप्रैल, १९६८ को संयुक्त राष्ट्रमण की महासभा के विशेष अधिवेशन में इस प्रस्तावित सन्धि पर विचार प्रारम्भ हुआ और राजनीति समिति में काफी विचार-विमर्श होने के उपरान्त १३ जून, १९६८ को महा-सभा ने प्रबल सहमति से सन्धि पर अपनी स्वीकृति दे दी। विपक्ष में प्राप्त न मतदान में भाग नहीं लिया और भारत भी मतदान में भाग लेने वाले २१ सदस्यों में से एक था। साम्यवादी चीन भी इस सन्धि से बाध्य नहीं होगा। अल्बानिया ने, जो साम्यवादी चीन का समर्थक है, सन्धि के विरोध में वोट दिया। क्यूबा, रमानिया और जाम्बा के भी विपक्ष में वोट पड़े।

जो भी हो यह निःसंदिग्ध है कि निःशस्त्रीकरण की दिशा में यह परमाणविक आयुध प्रसार प्रतिबन्ध सन्धि अगस्त, १९६३ की परमाणविक प्रतिबन्ध सन्धि के बाद एक दूसरा ऐतिहासिक कदम है। पूर्वापेक्षा निःशस्त्रीकरण के अन्य पहलुओं के समाधान की सम्भावना अब अधिक बढ़ गई है। यह सन्धि इस दृष्टिकोण को बल प्रदान करती है कि यदि महा-शक्तियां परस्पर मिल जुलकर प्रयास करें तो संसार की सभी समस्याय सुगमतापूर्वक सुलझ सकती हैं। वैसे यह सन्धि कुछ दृष्टियों से बड़ी दोषपूर्ण है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि एक ओर तो यह प्रतिबन्ध घोषा गया है कि जो राष्ट्र अब तक परमाणु धर्म नहीं बना पाये हैं वे भविष्य में भी इस आर उदम नहीं बढ़ायेंगे और दूसरी ओर उन्हें परमाणु आश्रमण से बचाने के लिए यह आश्वासन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्रमण के माध्यम से उनको अणु आयुधों से सहायता की जायेगी और यह सहायता देने का नियम रक्षा परिषद् करेगी। स्पष्ट है कि सुरक्षा-परिषद् महा शक्तियों के हाथ का खिलौना है। फिर इस आश्वासन का तब कोई महत्व नहीं रह जाता है जब सुरक्षा परिषद् के किसी भी स्थायी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रमण ने 'आश्रमण' शब्द की व्याख्या नहीं की है। अतः यह भ्रम बने रहने की सम्भावना है कि परिषद् किंग हालत में जिसको आश्रमणकारी समझेगी।

निःशस्त्रीकरण की समस्याएँ

(Problems of disarmament)

निःशस्त्रीकरण के इतिहास के इन पृष्ठों को पढ़ने से यह ज्ञात हो पाता है कि इनमें से बहुत थोड़े से सफल हो सके थे तथा अधिकांश की असफल होना पड़ा। इस निरन्तर असफलता के पीछे अनेक कारण छिपे हैं। अनेक

ऐसी समस्याएँ हैं जो किसी भी समय को संबंधीय नहीं बनने देती। मॉर्गेन्थो (Morgenthau) महोदय ने निःशस्त्रीकरण की चार समस्याओं का वर्णन किया है।¹ वे निम्न प्रकार हैं—

- (१) विभिन्न राष्ट्रों के शस्त्रों के बीच परिमाण सम्बन्ध (Ratio) कितना रहेगा?
- (२) वह मापदण्ड क्या है जिसके अनुसार इस परिमाण सम्बन्ध के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार एवं गुणों के शस्त्र विभिन्न देशों के लिए निर्धारित किये जायेंगे?
- (३) जब उक्त दो प्रश्नों का जवाब दे दिया जाता है तो देखना यह है कि इन दो उत्तरों का हथियारों की संख्या में कमी पर वास्तविक प्रभाव क्या पड़ेगा?
- (४) निःशस्त्रीकरण का अन्तर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था के विषयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मॉर्गेन्थो का कहना है कि निःशस्त्रीकरण के किसी भी प्रयास की सफलता जांचने के लिए हमें इन चार प्रश्नों पर ही उसकी कसौटी चाहिए। इन प्रश्नों के जैसे उत्तर दिये जायेंगे उन्हींसे यह जाना जा सकता है कि उनमें सफलता एवं असफलता की मात्रा कितनी-कितनी थी।

निःशस्त्रीकरण के मार्ग को कठिनाइयाँ

(The difficulties in the way of disarmament)

निःशस्त्रीकरण सफल होने के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं जिनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) अणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों का निर्माण अनेक आन्तरिक एवं बाह्य तत्वों से प्रभावित होता है। एक देश पहले अपन राष्ट्रीय पन की ओर दृष्टि डालता है तथा बाद में यह अन्तर्राष्ट्रीय शांति व हित को देखता है। इसी आधार पर फ्रांस ने परीक्षण प्रतिरोध सन्धि का समर्थन न किया। दो या अधिक राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध आज इतने अस्थिर हैं कि कल का मित्र आज का दुश्मन बन जाता है। इन परिस्थितियों में अणु-आयुधों के रहने से माफ़गणकारी पर प्रतिबन्ध लग जाता है और वह तुरन्त युद्ध छेड़ने का साहस नहीं कर पाता क्योंकि दूसरे देश की शक्ति उसका भी विनाश कर सकती है। अस्थिर सम्बन्धों का भय तथा इसमें निहित खतरे और सातवज्र की भावनाएँ शस्त्रों को सीमित करने के मार्ग में बाधक बन जाती हैं। आजकल सैनिक तकनीकी का इतना विकास हो चुका है कि

नि शस्त्रीकरण का नाम लेकर किसी को भी आप धोखा दे सकते हैं। शक्तिशाली शस्त्रों को छुटाकर, ऊपरी सेना घटाकर नि शस्त्रीकरण का दिखावा किया जा सकता है। जब तक यह भय दोनों पक्षों के मन में रहेगा तब तक नि शस्त्रीकरण का भविष्य उज्ज्वल नहीं है।

(२) राष्ट्रवाद एवं सम्प्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसको नि शस्त्रीकरण को क्रियान्वित की जाच के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय सस्था बनाई जाये। इस प्रकार के निरीक्षण द्वारा एक देश की स्वतन्त्रता पर जो अंकुश लगता है उसे स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं होता। यही कारण है कि नि शस्त्रीकरण योजना की सफलता से पूर्व विश्व सरकार की स्थापना का समर्थन किया जाता है।

(३) नि शस्त्रीकरण के कारण एक देश की अर्थ व्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। शस्त्रों के निर्माण पर व्यय होने वाली भारी राशि का शस्त्र निर्माण बन्द कर देने पर रचनात्मक कार्यों में कैसे उपयोग किया जायगा, उससे अर्थ व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायगी आदि भय रहते हैं तथा यह आश भी रहती है कि इसे अर्थ-विकसित देशों के विकास के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। यह भी सम्भव है कि नि शस्त्रीकरण के आर्थिक परिणामों का भय एव आशा अवास्तविक है। इस आशा एवं भय का पश्चिमी सम्पन्न समाज पर क्या असर होता है यह भी अनुमान का विषय है।

(४) नि शस्त्रीकरण करते समय देशों के लिए शस्त्रों का जो अनुपात निर्धारित किया जाता है उसके कारण देशों के बीच मत-मुटाव अविश्वास की भावना पैदा होती है। शस्त्रों की सीमा निर्धारण के समय प्रत्येक देश को दूसरे देश की प्रति यह शक्य रहनी है कि शायद वह अपनी शक्ति को बढ़ाने तथा विरोधी पक्ष की शक्ति घटाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रत्येक देश उस शक्ति को कम करना चाहता है जो उसके लिए घातक है। १९४६ में आगुशस्त्रों की मिटाने के लिए रूस एवं अमरीका दोनों ही देशों द्वारा किए गए प्रस्ताव एक पक्षीय थे। तकनीकी रूप से यह बड़ा कठिन काम है कि एक देश की सैनिक आवश्यकता को देखा जाय तथा उसी अनुपात में उसकी सैनिक शक्ति को घटाया जाय। जान फोस्टर टनेस के मतानुसार इसी समस्या के कारण आज तक अमरीका द्वारा नि शस्त्रीकरण की योजनाओं का समर्थन सच्चे दिल से न किया जा सका। इन समस्या के दो मुद्दाय प्रस्तुत किये जाते हैं—(१) पूर्ण रूप से नि शस्त्रीकरण कर दिया जाये। (२) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस शक्ति द्वारा देशों की सैन्यिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। विन्तु ये मुद्दाय भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि पक्षे शस्त्रों का कम न किया जाये इन अज्ञान का भयना मूल है।

(५) यह कहा जाता है कि अविश्वासपूर्ण वातावरण में निःशस्त्रीकरण और शस्त्रों का नियन्त्रण तथा अन्य राजनैतिक समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। यदि देशों के बीच विश्वास रहे तो शस्त्रों की आवश्यकता ही न रहे और निःशस्त्रीकरण की समस्या भी पैदा न हो। किन्तु पूर्ण अविश्वास का रहना भी अराजकता एवं पूर्ण तानाशाही में से एक को स्थापित कर देगा। यह आशा की जाती है कि निःशस्त्रीकरण की समस्या के सुलझने के बाद दोनों गुटों में विश्वास की भावना भा सकती है। अविश्वास के कारण कोई समझौता नहीं हो पाता, होता भी है तो मच्चे रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाता।

(६) समस्या यह उठ खड़ी होती है कि पहले राजनैतिक समस्याओं को हल किया जाये या निःशस्त्रीकरण किया जाये। ये दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं और एक के हल हो जाने पर दूसरे का हल हो जाना सुगम है। यह सोचा जाता है कि शस्त्र जगड़ों का कारण है और इनको घटाने से अन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी। किन्तु यह प्रयास एकपक्षीय होगा। होना यह चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास एवं प्रतिद्वन्द्विता को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास करना चाहिए। मडरियागा के शब्दों में निःशस्त्रीकरण की समस्या का समाधान इस समस्या में ही नहीं खोजा जा सकता किन्तु इसके बाहर ही खोजा जा सकता है। अमल में निःशस्त्रीकरण की समस्या निःशस्त्रीकरण की समस्या नहीं है। यह वास्तव में विश्व समुदाय के संगठन की समस्या है।¹

राष्ट्रीय शक्ति की कुछ अन्य सीमायें

(Some Other Limitations of National Power)

राष्ट्र की शक्ति को विनाश और विघ्न की अपेक्षा कल्याण एवं निर्माण में लगाने की व्यवस्था करने हेतु अब तक अनेक उपाय किए गए। इन उपायों में से प्रमुख अर्थात् शक्ति सन्तुलन, सामूहिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, विश्व सरकार एवं निःशस्त्रीकरण का अध्ययन हम कर चुके हैं। इन सीमाओं के अतिरिक्त देश को बाह्य एवं आन्तरिक परिस्थितियों के कारण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जो उस राष्ट्र की शक्ति का उचित प्रयोग करने के मार्ग में बाधाएँ उपस्थित कर देती हैं। इस दृष्टि से एक राष्ट्र के व्यक्तित्व तथा उसके व्यवहारों की तुलना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा व्यवहारों में की जा सकती है। जिस प्रकार व्यवहार करते समय एक व्यक्ति अपने पुनः के नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओं में प्रभावित होता है उसी

प्रकार राष्ट्रीय व्यवहार की भी एक नैतिकता होती है। यदि एक राष्ट्र द्वारा उसका उल्लङ्घन किया गया तो अन्तर्राष्ट्रीय जगत के अन्य सदस्यों का उस पर से विश्वास उठ जायेगा तथा सम्बन्ध अच्छे न रह पायेंगे। इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में समाज के रीति-रिवाजों, परम्पराओं तथा तत्कालीन समाज के मूलों का बड़ा प्रभाव रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी एक देश के व्यवहार की बागडोर पर विश्व के लोकमत का भारी प्रभाव रहना है। इस प्रकार एक राष्ट्र की शक्ति को सीमित करने में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं विश्व लोकमत का जो प्रभाव रहता है वह भी भुलाया नहीं जा सकता।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता

(International Morality)

समाज के हित एवं उसके सदस्यों की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि शक्ति को मर्यादित रखा जाए। ये मर्यादाएँ शक्ति के लिए सघर्ष का ही एक भाग नहीं होतीं किन्तु ये तो उन सघर्ष पर व्यक्तिगत सदस्यों की इच्छा से उनके आदर्शों या व्यवहार के नियमों द्वारा ऊपर से लादे जाते हैं। नैतिकता प्रायः सही व्यवहार को मना जाता है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में 'सही व्यवहार' क्या है यह जानना कठिन है। कुछ विचारकों के मतानुसार नैतिकता सार्वभौमिक होती है, यह पूर्ण होती है। एक राष्ट्र का कार्य नैतिक स्तर के जितना समीप होता है वह उतना ही अधिक नैतिक होता है तथा जितना दूर होता है उतना ही वह अनैतिक होता है। मनुष्य को इस स्तर का पालन करना चाहिए। यह स्तर सत्य के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण पर आधारित न होकर सत्य पर ही आधारित होता है। इस दृष्टिकोण वाले विचारकों के मतानुसार नैतिकता का केवल एक ही मापदण्ड होता है। प्रत्येक मनुष्य यह जान सकता है कि नैतिक-नियम शास्त्र किस प्रकार के व्यवहार को नैतिक कहता है। इस नियम-शास्त्र के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य अनैतिक समझा जाएगा। नैतिक मान्यताएँ प्रत्येक परिस्थिति में एक सी रहती हैं। हरषा को अनैतिक माना जाता है तो कोई भी परिस्थिति या घात उसे नैतिक नहीं बना सकती। मनुष्य चाहे किसी भी समय, स्थान एवं स्थिति में कार्य कर रहा हो, नैतिक नियम उस पर समान रूप से लागू होंगे। यदि एक व्यक्ति अपने परिवार में पत्नी के साथ असत्य व्यवहार करता है तो वह उतना ही अनैतिक माना जाएगा जितना कि वह अपने शत्रु राष्ट्र के सिपाहियों के साथ झूठ बोलते समय होता है।

नैतिकता से सम्बन्धित उचित विचार का अन्य विचारकों द्वारा खण्डन या जाड़ा है। उनके अनुसार नैतिकता का मापदण्ड केवल एक ही नहीं

होता है। आत्मा की आवाज तथा 'सही विचार' भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक अनुभवों एवं सभृतिमों के साथ-साथ बदलते रहते हैं। एक जंगली जानि अपने शत्रु को खा जाता ठीक माननी है। उच्च विचारों एवं बुद्धि से सम्पन्न हम यह किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते कि उन लोगों के मूल्य हमसे निम्न स्तर के हैं। इन विचारकों के मतानुसार एक व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार करते समय समान नैतिक नियमों से प्रशासित होता है यह भी सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार करता है उसी प्रकार यदि वह अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ भी करने लगे तो उसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि नैतिकता का रूप तथा मापदण्ड समय, परिस्थिति एवं स्थान के साथ-साथ बदलता रहता है। इस प्रकार नैतिकता उन विचारों को कहा जाता है जो कि उसकी संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परम्परा एवं रीति-रिवाज आदि के आधार पर निर्मित तथा मान्यता प्राप्त होनी है। एक देश की नैतिक मान्यताओं पर अन्य देशों की सम्यता के सम्पर्क का तथा बदली हुई राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी भारी प्रभाव रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जब एक राष्ट्र कदम उठाता है तो दूसरे देशों द्वारा उस कदम का प्रोत्साहन एवं नैतिकता परखी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता के कुछ मापदण्ड तथा व्यवहार के कुछ नियम हैं जिनके आधार पर एक देश के व्यवहार के प्रति दूसरे देशों में प्रतिक्रिया होती है तथा दृष्टिकोण बनता है। विभिन्न लेखकों के द्वारा इन नैतिक मान्यताओं का वर्णन किया गया है जिनका आवरण करके राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ राज्यों के परस्पर सम्बन्धों को शांतिपूर्ण एवं कम अराजकतापूर्ण बना सकते हैं। ये नियम हैं, जैसे—अपने वायदों को पूरा करना, दूसरे के शब्दों पर विश्वास करना, स्वायत्त कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय मानून का आदर करना, अंतरसंघर्षों को रक्षा करना, राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध का बहिष्कार करना आदि-आदि। इन नैतिक नियमों का सुविधा में अधिक सम्बन्ध नहीं रहता। एक कार्य सुविधाजनक नहीं होता तो भी वह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता द्वारा नहीं ठहराया जाता है; दूसरी ओर अनेक कार्य सुविधाजनक होते हुए भी अनैतिक माने जाते हैं। दन्तानुसार अपने देश के सहोप राष्ट्रीय हित के अनुसार कार्य करना संकीर्ण सावैभौमिक सत्य का पालन करने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित तथा अधिक नैतिक है।

नैतिकता की व्याख्या समय-समय बदलती रहती है। प्रत्येक देश अपने व्यवहार को नैतिक सिद्ध करने की काजिग करता है। 'शक्ति ही अधिकार है' वाली कहावत के अनुसार विजय एवं सफलता प्रत्येक राष्ट्र के किसी भी

व्यवहार को नैतिक बना देती है। आक्रमणकारी राष्ट्र भी अपने आपको उचित ठहराता है। चीन द्वारा किया गया अणु परीक्षण कमल में मानवता व विश्व शान्ति के विरुद्ध है किन्तु जब यह किया गया तो चीन ने बताया था कि ऐसा वह अमरीकी साम्राज्यवाद को रोकने तथा विश्व में स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिए कर रहा है और इसलिए यह कार्य नैतिक है। इसी प्रकार अन्य देशों द्वारा भी कुनक प्रस्तुत किये जाते हैं। फिर भी विश्व-को भूत बनाना, उससे सन्तुष्टता का उठाना कोई सरल काम नहीं है। इन बातों को चीन भी समझता है कि उसकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं हो सकता और वह एक अनैतिक कार्य कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता शान्ति एवं युद्ध दोनों ही समयों में मनुष्य के जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहती है। शान्ति काल में न केवल प्रमुख जनों को बल्कि समस्त देश-वासियों की रक्षा करना एक नैतिक कर्तव्य होता है। हो सकता है कि यह कर्तव्य उसके नुकसानदायक परिणाम से लगे। अत्यधिक जनसंख्या से पीड़ित रहते हुए भी देश अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। युद्ध के समय भी मानवीय जीवन की रक्षा करना अन्तर्राष्ट्रीय नीति का एक अङ्ग माना जाता है। विजेता राष्ट्र द्वारा हारे हुए राष्ट्र के नागरिकों का बर्ष नहीं करना चाहिये और न ही उनको दास बनाना चाहिए। विजेता राष्ट्र द्वारा अविजित राष्ट्र के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। युद्ध के समय नागरिकों एवं सामान्य वस्तुओं पर बमबारी न करके केवल सैनिक महत्व के अङ्गों पर ही करना चाहिए। भारत-पाक संघर्ष के समय जब पाकिस्तान द्वारा नागरिक हत्याओं पर बमबारी की गई तो यह अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन ही था।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का जो बिज हमने सोचा है, वह निम्नांकित छोरों से अधिक स्पष्ट हो सकेगा।

शान्ति काल में मानव जीवन की रक्षा

(Protection of Human life in peace)

राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अमानुषिक व्यवहारों व प्रयोगों का अनुचित समझा जाता है। सत्ता की होड़ में लगे हुए देश भी नैतिकता को सामाज्य में आबद्ध है और आज सभी सरकारों का कर्तव्य है कि न केवल विभिन्न व्यक्तियों, अपितु सामान्य जनता की भी सुरक्षा की जाय। प्रा० हम मार्ग-यो न लिखता है—

“वही विदेश नीति, जो अरने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन-सहार को प्रोत्साहित नहीं करती, राजनीतिक समयानुकूलता के कारण इस सीमा को

अपने ऊपर धोती नहीं है। इसके विपरीत, इसका लाभ पूर्ण तथा प्रभावशाली कार्य निधि में होता है। इस सीमा का उद्गम नैतिक सिद्धान्त में निहित है और इसका पालन राष्ट्रीय हितों की रक्षा परनाह किये हुए भी किया जाना अनिवार्य है। ऐसी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों का भी त्याग उस समय कर देती है, जब राष्ट्रीय हितों के लिए नैतिक सिद्धान्त को, जैसे कि शांति काल में जन-मनूह की हत्या का निषेध, तोड़ दिया जाना आवश्यक हो जाता है।

श्री मार्गोपो का मत है कि अनावश्यक घातनाएँ और हत्यायें न करने के उत्तम्य शासन के कारण ही पृथ्वी पर मानव जीवन विरहित हो रहा है। विकास का लक्ष्य किसी ऊँचे ध्येय की प्राप्ति हेतु जिसके लिए याचना अथवा जीवन सहार का होना आवश्यक नहीं है, और इस ऊँचे लक्ष्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित भी पूर्ण सम्भव है।

यदि व्यवहारतः देखा जाय तो आज के युग में शान्तिकाल में मानव जीवन की रक्षा के नैतिक दायित्व को बहुत कुछ निभाया जाता है। आज एक निरनुस शासन के लिए भी यह कठिन है कि वह जनता को आवश्यक सुरक्षा न दे।

युद्ध-काल में मानव जीवन की सुरक्षा

(Protection of Human life in war)

अन्तराष्ट्रीय नैतिकता का यह भी तत्वाज्ञा है कि युद्ध-काल में जन-साधारण के जीवन की सुरक्षा प्रदान की जाय। इसी मानवतावादी उद्देश्य ने अनेक अन्तराष्ट्रीय अभिमतयों (International Conventions) को प्रेरित किया है जिनका अनुमान करते युद्ध के समय जन-साधारण के विनाश को टाला जाता है। इतिहास का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि समय समय पर युद्ध सम्बन्धी विभिन्न घोषणायें जन-जीवन को युद्ध विमोचिका में बचाने के लिए की जाती रही हैं। १८५६ की पेरिस घोषणा (The Declaration of Paris of 1856) ने समुद्रीय अथवा समुद्रतट स्थित युद्ध (Maritime warfare) को सीमित कर दिया था। १८६४ की सेंट-पीटर्स बर्ग घोषणा ने ऐसे हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध ठहरा दिया था जिनसे अनावश्यक रूप से अपंग और असमर्थ व्यक्तियों के बन्ध बड़े। इस घोषणा ने ऐसे प्रक्षेपण बस्तुओं के प्रयोग को भी निषिद्ध ठहरा दिया था जिसका वजन ४०० ग्राम से कम हो और जिन्हें किसी विस्फोटक पदार्थ से चलाया जाता हो। १८६४ की हेग घोषणा (The Hague Declaration of 1899) ने उन दमटम कारतूतों (Dum Dum Bullets) के प्रयोग को निषिद्ध किया था जो मानव शरीर में प्रवेश करके रुक जाते थे या बाँटे हो जाते थे। १९०७ के हेग सम्मेलन (The Hague Convention of 1907) ने विष अथवा

विपात हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध ठहराया। इस कन्वेंशन ने यह भी निषिद्ध ठहराया कि विरोधी राष्ट्र के वाणिज्य को घेरा-घड़ी और क्रूरता से घायल किया जाय या मारा जाय। आज भी अनेक ऐसे प्रयत्न किये जा रहे हैं जिससे आणविक युद्ध सीमित हो जाये। युद्ध बन्धियों के सम्बन्ध में भी, अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की दृष्टि से, अनेक प्रयत्न किये गये हैं। १८६६ और १९०७ के हेग कन्वेंशनों और १९२९ व १९४६ के जेनेवा कन्वेंशनों में इस बारे में विस्तार से व्यवस्था की गई है कि युद्ध बन्धियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाय।

शासक वर्ग की नैतिकता

(Morality of the Ruling Elite)

प्राचीन काल से शासक वर्ग की नैतिकता के विषय में विशद रहा है। उनके व्यवहारों के प्रति उत्तम शाकाओं का तीन रूपों में निरूपण किया गया है—उनकी प्रशंसा गाकर, अथवा उनकी निन्दा कर, अथवा उनके व्यवहारों का शासक तथा शासित के दोहरे मापदण्ड को अनाकर। प्रशंसा गाने वालों की यह मान्यता रही है कि “राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता,” वह सामान्य व्यवस्था के नियमों से परे है, उसकी इच्छा ही नियम है। वर्तमान शासनतन्त्र में शासक जन नेता होता है। वह जनता का प्रतिनिधि होता है। अब उसका व्यवहार स्तुत्य होता है। यह सिद्धान्त किन्हीं थोथी मान्यताओं पर आधारित है। सोरकिन तथा लन्देन के अनुसार “इन तर्कों को कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सका है और अब भी यह सम्भव नहीं है।” कोई भी सिद्धान्त वैज्ञानिक तथा तार्किक रूप से शासक वर्ग के सदैव श्रेष्ठ ‘व्यवहार’ को सिद्ध नहीं कर पाता। इन सिद्धान्तों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। केवल सामाजिक अथवा ऐतिहासिक आधार ही वैज्ञानिक आधार में बन जावे, ऐसा आवश्यक नहीं है।

शासक वर्ग के व्यवहार की निन्दा करने वाले शासक वर्ग पर घेरा-घड़ी झूठ, ढोंग, आर्थिक लोपण तथा सत्ता के प्रति मोह के आरोप लगाते हैं। सैनिक शासन में व्यक्ति का कोई महत्त्व नहीं होता। उस पर सभी प्रकार के आदेश ऊपर से आरोपित होते हैं जिन्हें मानने के लिये वह विवश होता है। सैनिक समाज में विद्यमान सहकारिता एक अनिवार्यता होती है। शासन पद्धति का कोई भी स्वरूप क्यों न हो शासक अथवा शासक वर्ग समाज का उपयोग अपने लाभ के लिये करता है जिसमें व्यक्ति अथवा समाज की एक दास जैसी स्थिति होती है। अपने-से राजनिहीन देशों को अपने आधीन करने वाले शासकों ने प्रजा के सुखों का भी ध्यान रखा हो, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं रही है। विक्टर ह्यूग्स, मशरलेमैन फ्रेडरिक तथा पीटर महान इस धोखे की शोषण रहे हैं।

ऐसा भी हुआ है कि देश के किसी भाग के किसी व्यक्ति ने अपनी कुटुम्बता के द्वारा अधिक प्रभावशाली वन स्वतन्त्र व्यक्तियों को अपने आधीन रखने का प्रयास किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सत्ता आने पर उन्होंने अपने हितों तथा लाभों को सामान्य जनता के मुँहों से अधिक महत्व दिया। लार्ड एस्टन के अनुसार "सत्ता मनुष्य को मदान्ध बना देती है। राजनैतिक दृष्टि से सभी महान व्यक्ति विभिन्न चरित्र के व्यक्ति रहे हैं। यदि जनता उनके चरित्र को जान पाती तो उन सबको निश्चिन्त हो फाँसी पर चढ़ा देनी।" पर इन लाएनों को लगाने पर भी यह सिद्धान्त अपने पक्ष में कोई निश्चित दृढ़ तथा तथ्यपूर्ण आधार उपस्थित नहीं कर पाता।

दोहरे मापदण्ड को मानने वाले, नैतिक तथा राजनैतिक कार्यों में द्वैत के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। अतः किसी राजनैतिक कार्य के धुण-बोवों का विवेचन नैतिकता के आधार पर नहीं किया जा सकता, ऐसी उनकी मान्यता होती है। राष्ट्र हित में किया गया कोई निन्दनीय कार्य भी नैतिकता के आधार पर निन्दनीय नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन के दो स्वरूप हैं—(i) व्यक्तिगत (ii) राष्ट्रीय। दोनों में कोई समता नहीं होती। सम्भवतः इन्हीं कारणों से प्राचीन शासकों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में किसी भी बलि देने में संकोच नहीं किया। मिथ के फराऊन ओमेन हातेग के शासन सूत्र उपरोक्त कथन पर भली भाँति प्रकाश डालते हैं—“मैं तुम न कहता हूँ तुम चाहे धरती के सम्राट हो अथवा देश देशान्त के तुम अपनी प्रजा के प्रति कठार बनो। प्रजा उसी शासन का सम्मान करती है जो उसे मयभीत रखता है। जबी उसके निकट अकेले मत जाओ। अपने हृदय के निरट भाई, मित्र अथवा जन्म किसी को मत आने दो। निद्रित स्थिति में भी अपनी भावनाओं को बाध कर रनो क्योंकि पाप के दिनों में कोई साथ नहीं देना।” कोसिमो-दि मेडिसी (Cosimo di medici) के अनुसार भी 'अपनी श्रुति के द्वारा शासन अपनी शक्ति का पुनः संवय करना है। उसके शूर कुटुम्बों से अच्छे समाज की व्युत्पत्ति होती है।'

नैतिकता के दोहरे मापदण्ड के सिद्धान्त को भिन्न भिन्न युगों में विभिन्न व्यक्तियों ने बल प्रदान करने का प्रयास किया है। मैकियावेली ने इसे स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास किया है। उसके अनुसार "उन शासक के लिये जो अपनी सत्ता बनाये रखना चाहता है, अच्छे न बनने की कला का मर्मज्ञ होना आवश्यक है। उसे आवश्यकतानुसार अपने ज्ञान का उपयोग करना जाना चाहिए।" इसकी और स्पष्ट करते हुए उसने लिखा है, "किसी शासक में समस्त सद्गुणों का होना प्रशंसनीय है, किन्तु मानवीय सीमाओं के कारण यह सम्भव नहीं है। अतः शासक में उन दुर्गुणों का होना भी आवश्यक है,

जिनके अभाव में राज्य-रक्षा सम्भव न हो पाये। अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कार्यों से घृणा जन्म लेती है। कभी कभी राज्यतन्त्र की भली-भाँति चल्न के लिए शासक का भ्रष्ट होना आवश्यक हो जाता है। उन शक्तियों के भ्रष्ट हो जाने पर, जिनके अभाव में शासन सम्भव नहीं है, शासक को भी उनका अनुसरण करना होता है। ऐसा स्थिति में सरकारों का किया जाना शासन के लिए घातु उत्पन्न करता है।'

विभिन्न विचार-धाराय अपने पक्ष तथा अन्य सिद्धांतों के विरोध में विभिन्न तर्क उपस्थित करती हैं। इनमें से किसी एक का अछूटा होना विवादास्पद है।

अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता का मूल्यांकन

निष्कर्ष रूप में यह कहना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के विषय में विचारकों में मतभेद है। यथायथवादी विचारकों के अनुसार राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध शक्ति पर आधारित होने हैं। इनमें नैतिकता को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत कल्पना को महत्व देने वाले अवास्तविक विचारकों के अनुसार नैतिकता के नियमों का व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों द्वारा समान रूप से व्यवहार होता है।

यथायथवादी विचारधारा के अनुसार प्राचीन भारत में कौटिल्य के समय से मेकियावेली और हेगल के समय तक विभिन्न राष्ट्रों के माध्यम से नैतिकता का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं रहा है। हीगल (Hegel) के अनुसार "प्रत्येक राष्ट्र अपने में एक पूर्ण दर्शाई है। राष्ट्रों के मध्य सम्भाव्य अथवा विरोध उनके निजी स्वार्थों की ध्यान में रख कर होता है।" केंनेथ थोम्पसन (Kenneth W. Thompson) के अनुसार, "राष्ट्रीय नैतिकता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान, नैतिकतापूर्ण दृष्टिकोण की दुर्लभताएँ हैं जिनके मूल में दिखावापन अथवा घोर अहम है।" राष्ट्र द्वारा की गई घोषणाओं तथा स्वीकृत नीतियों के अनुसार राष्ट्र के नैतिक मूल्यों का निर्धारण होता है। इससे स्पष्ट है अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में नैतिकता की कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

हमारे विपरीत कल्पना प्रधान विचारकों के अनुसार नैतिक नियमों का मूल्य केवल व्यक्ति के लिये ही नहीं अस्तित्व में राष्ट्रों के लिए भी है। व्यक्ति तथा राष्ट्र में वैचारिक-एकता स्थापना के लिये, दोनों द्वारा समान नैतिक मूल्यों का स्वीकार किया जाना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय व्यवहार में समान सम्मानित नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिये। प्रेजिडेंट बिन्सन के शब्दों में, "हम ऐसे युग के प्रारम्भ पर हैं जिसमें राष्ट्रों द्वारा उन्हीं व्यवहारों, विचारों तथा मूल्यों को महत्व दिया जावेगा, जिनकी

अपेक्षा सम्म वेना अपने नागरिकों से करते हैं।' प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के अनुसार राष्ट्रीय नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता की तरह नितान्त आवश्यक है।

कसौटी पर जाचने पर उपरोक्त दोनों ही विचार धारयें खरी नहीं उतरती। वास्तविक रूप में अन्तराष्ट्रीय नैतिकता का अपना विशिष्ट नैतिक स्वरूप है। प्रत्येक निरपेक्ष शासक के भी अन्य देशों के प्रति अपने निश्चित नैतिक भावधर्म रहते हैं। प्रोफेसर क्लाड (Claude) के अनुसार समस्त राष्ट्र-सभ की सभा एक सामान्य मूनिस्त्रिल सभा के अनुसार है जिसमें अन्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यों तथा आवश्यकताओं को स्वीकार किया जाता है। उनके विचारानुसार अन्तराष्ट्रीय नैतिकता पर प्रभावशाली अनुसंधानों का मूल कारण अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सहायगत अन्य समस्याओं का होना है जो अपने धर्म स्वार्थों की पूर्ति हेतु नैतिकता के मूल्यों को छोड़ देती है।

अन्त में यह स्वीकार करना अनुचित न होगा कि आज की बदली हुई परिस्थितियों में अन्तराष्ट्रीय नैतिकता का महत्व निरन्तर घटता जा रहा है। कारण यह है कि प्रजातन्त्र के इस युग में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जैसा कि अठारहवीं तथा उन्नीसवीं शताब्दियों के राजतन्त्रों के समय सम्भव था। गोम्पतन के मतानुसार "अन्तराष्ट्रीय नैतिकता उसी दिन समाप्त हो गई जबकि राष्ट्रीय उद्देश्यों की वांछी सहायता द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए शुद्ध लक्ष्य माना गया।"

विश्व जनमत

(World Public opinion)

प्रजातन्त्र के इस युग में राष्ट्रीय स्तर की भांति अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी लोकमत का महत्वपूर्ण स्थान है। कूले के मतानुसार जनमत एक सावधानी प्रविष्टा है, यह एक विशेष समय में एक विशेष प्रश्न पर सहमति मात्र नहीं है। अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों पर विश्व जनमत का प्रभाव बहुत समय पहले से ही पड़ना आ रहा है। राष्ट्रमन्त्र, वित्तमन्त्रियों सन्धि आदि का आधार विश्व लोकमत ही था। २१ जुलाई १९१६ को लार्ड रोबर्ट सेसिल (Lord Robert Cecil) द्वारा हाउस आफ कॉमन्स में कहा गया था कि - "हमारा प्रमुख अस्त्र जिस पर हम विश्वास करते हैं लोकमत है यदि हम इसके चार में गलत हैं तो सारी खोज हो गलत हो जाती है।" १७ अप्रैल १९२६ को कार्डेल हल (Cardell Hull) ने कहा था कि "लोकमत शान्ति के लिए सबसे प्रमुख शक्ति है। यह अधिक जोर-जोर से सारे विश्व में विकसित होती आ रही है।" समुक्त राष्ट्रसंघ का महत्व बताते हुए यह कहा जाता है कि

इस संध्या द्वारा विश्व जनमत अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर अपना प्रभाव डालने में सफल होता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ भी अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो पाता है जबकि विश्व लोकमत की वह अपने साथ कर ले। इसमें जो भी निर्णय लिये जाते हैं वे विश्व जनमत से प्रभावित रहते हैं।

विश्व लोकमत का अर्थ बताते हुए मार्गेंथो (Margenthau) महोदय कहते हैं कि "विश्व जनमत स्पष्ट रूप से लोकमत है जो कि राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है तथा कम से कम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मौलिक प्रश्नों पर विभिन्न देशों के सदस्यों का एकमत में संगठित करता है।" विश्व जनमत का प्रभाव राष्ट्रीय व्यवहार पर सच्चे अर्थों में एक वास्तविक सीमा निर्धारित करता है। यह एक देश के स्वेच्छापूर्ण उच्छल व्यवहार पर पाबन्दी लगाना है। आज कोई भी देश बिना हमारे राष्ट्रों के सहयोग के जीवित नहीं रह सकता। चाहे कितना भी सम्पन्न एवं शक्तिशाली देश हो, उसे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिये आवश्यक रूप से हमारे देशों के साथ सम्बन्ध बनाये रखने होंगे, लेन-देन का व्यवहार (Give and take Policy) बनानी होगी और ऐसा तभी हो सकता है जबकि देशों के बीच परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्ध हों, उनके बीच शांति, सहोदर्य एवं मैत्री के भाव वर्तमान हों। हमारे शब्दों में वे अधिकांश विषयों पर एकमत हो तथा अधिक भिन्नता न रखते हों। वे परस्पर एक दूसरे की नीतियों एवं व्यवहारों को अच्छी तरह से समझते तथा उसका समर्थन करते हो या कम से कम उसका विरोध न करने हों। इस प्रकार की स्थिति को संशेष में प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है कि एक देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सभी दृष्टियों से विकास तभी सम्भव है जबकि विश्व का जनमत उस देश की नीतियों का सक्रिय या निष्क्रिय रूप से समर्थन करता हो। विश्व जनमत के महत्व को समझने के बाद ही प्रत्येक देश द्वारा प्रसार के साधनों पर इतना अधिक व्यय किया जाता है।

वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लोकमत है अथवा नहीं या उसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव होता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में विचारकों के बीच मतभेद नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार विश्व जनमत वास्तविक रूप से राष्ट्रों के व्यवहार पर प्रभाव डालता है तथा वह उसकी स्वेच्छाकारी अंगों से रोकता है। इन विचारकों का कहना है कि यदि यह मान भी लिया जाय कि एक राष्ट्र विश्व लोकमत के अनुसार काम करने का जितना दावा करता है उतना वह वास्तव में व्यवहार नहीं करता है। तो भी इसके यह सिद्ध हो ही जाता है कि वह देश विश्व जनमत के महत्व की अवहेलना चाहते हुये भी, कम से कम सिद्धांत रूप में तो नहीं कर पा रहा है। जो

विश्व जनमत एक राष्ट्र को उसकी इच्छा के विपरीत मत बनाने के लिये बाध्य कर दे उसके अस्तित्व पर तो शका की ही नहीं जा सकती। इससे भिन्न मार्गेन्थो (Morgenthau) आदि विचारकों का मत है कि विश्व जनमत जैसी कोई चीज विश्व में नहीं है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर प्रभाव डालती हो। उनका कहना है कि एक देश अब अपनी नीति को विश्व जनमत या मानव-जाति की चेतना के अनुकूल बनाने की चेष्टा करता है तो इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता। यह तो सभी देशों का एक सामान्य दृष्टिकोण सा बन गया है। मार्गेन्थो के मतानुसार दो कारणों से लोग विश्व-जनमत के अस्तित्व को मानने की भूल करते हैं—

(१) विश्व की मनोवैज्ञानिक एकता (Psychological Unity of the World)—अज्ञ सत्तार में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति और व्यवस्था चाहते हैं। ये बातें ऐसी हैं जिन्हें सभी व्यक्ति चाहते हैं और इस प्रकार ये आज एक प्रकार की विश्व जनमत हैं। इनमें से किसी का भी उत्थ-पन विश्व-जनमत का उत्थपन है और यह निश्चित है कि विश्व-जनमत उत्थपन-कर्त्ता के प्रतिकूल अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। मूल रूप में अनुप्य मात्र की इच्छा का दमन विश्व जनमत को स्वीकार नहीं होगा।

(२) विश्व का तकनीकी एकीकरण (Technological Unification)—तकनीकी विकास के कारण अब विश्व का जन-मानस एक दूसरे के कान्ची निगट आ गया है। अन्तर्राष्ट्रीय संपार साधनों ने विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों को एक दूसरे की मज्जी-भांति समझने और सूचित होने का अवसर प्रदान किया है, अतः पारस्परिक मतभेदों को सुगमतापूर्वक दूर करना संभव हो सता है। तकनीकी विकास ने, इस प्रकार, विश्व जनमत को पधार्थ के निगट ला दिया है और उसमें निकटता जटाप्त की है।

यद्यपि उपरोक्त दो तत्वों ने कारण सत्तार के लोगों में सामिप्य-भावना का विराम हुआ है लेकिन इनके आधार पर यह मानना भ्रामक होगा कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय घटना पर विश्व-जनमत सदैव एक रूप रहता है या रहेगा। विश्व-जनमत में विश्वास करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि विश्व में हर वही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में जनमत को राष्ट्रीय नीतियों के अभिकरणों द्वारा मोड दिया गया है। विश्व-जनमत का प्रभाव राष्ट्रीयता और संप्रमुता की आग पर पड़कर जल की भांति भाप बन जाता है।

प्रस्तुत अध्याय के सम्पूर्ण विवरण के उपरांत निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र की शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाएँ लगाई गई हैं। इन सीमाओं के कारण विश्व में व्यवस्था बाधम रहती है। यद्यपि यह

व्ययम्पा अनेक बार भग हो जाती है तथा विश्व शांति के लिये गम्भीर खतरे पैदा हो जाते हैं किन्तु शक्ति को विभिन्न मोमाओं में नै किसी एक अथवा एक से अधिक के सहयोग से विश्व को विनाश से बचा लिया जाता है। व्यस्तित्व जीवन की भांति अन्तर्राष्ट्रीय जीवन पर भी इकाइयों का व्यवहार विश्व समाज की परम्पराओं, हृदियों, मूल्यों एवं विश्वामो के द्वारा पर्याप्त प्रभावित होता है। विश्व-शांति के लिये यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय शक्ति की इन सीमाओं को सक्रिय एवं प्रभावशील बनाया जाये।

PART V

Contemporary Emerging Trends, Resurgence of Asia, Africa and Latin America, Rise of Soviet Union and USA, Cold War, Rebuilding and reorganization of Western Europe, Impact of Nuclear weapons, Non alignment, its elements and changing patterns, Bipolarity and polycentrism, Sino Soviet conflict, U.N's impact on International Politics, Problems of Vietnam and West Asia.

अध्याय १३ समकालीन उभरती हुई प्रवृत्तियाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जागृति

अध्याय १४ (Contemporary Emerging Trends : Resurgence of Asia, Africa and Latin America)

अध्याय १५ सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति (Rise of Soviet Union and her Foreign Policy)

अध्याय १६ संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और उसकी विदेश नीति (Rise of U S A and her Foreign Policy)

अध्याय १४ शीत-युद्ध

(Cold War)

अध्याय १५ पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनर्संयोजन (Re building and Reorganisation of Western Europe)

अध्याय १६ अणु-सामग्रियों का प्रभाव

(Impact of Nuclear Weapons)

अध्याय १७ असंलग्नता—इसके तत्व और परिवर्तित होते हुए रूप (Non alignment : Its elements and changing Patterns)

अध्याय १८

(Bipolarity and Polycentrism)

अध्याय १९ चीनी-रूसी संबंध

(Sino Soviet Conflict)

अध्याय २० अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव (U. N 's Impact on International Politics)

अध्याय २१ विद्यमान और पश्चिमी एशिया की समस्याएँ (Problems of Vietnam and West Asia)

PART V

Contemporary Emerging Trends; Resurgence of Asia, Africa and Latin America; Rise of Soviet Union and USA; Cold War; Rebuilding and reorganization of Western Europe; Impact of Nuclear weapons; Non alignment; its elements and changing patterns; Bipolarity and polycentrism; Sino Soviet conflict; U N's impact on International Politics; Problems of Vietnam and West Asia.

अध्याय ११ समकालीन उभरती हुई प्रवृत्तियाँ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जागृति

11 ✓ (Contemporary Emerging Trends : Resurgence of Asia, Africa and Latin America)

अध्याय १२ सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति
(Rise of Soviet Union and her Foreign Policy)

अध्याय १३ संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और उसकी विदेश नीति
(Rise of U S A and her Foreign Policy)

अध्याय १४ शीत-युद्ध
(Cold War) ✓

अध्याय १५ पश्चिमी यूरोप का पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन
(Re building and Reorganisation of Western Europe)

अध्याय १६ अणु-आयुधों का प्रभाव ✓ 10.0
(Impact of Nuclear Weapons)

अध्याय १७ असंलग्नता—इसके तत्व और परिवर्तित होते हुए रूप
(Non alignment Its elements and changing Patterns)

अध्याय १८
(Bipolarity and Polycentrism)

अध्याय १९ चीनी-रूसी संघर्ष
(Sino Soviet Conflict) —

अध्याय २० अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव
(U. N 's Impact on International Politics)

अध्याय २१ विप्रतनाम और पश्चिमी एशिया की समस्याएँ
(Problems of Vletham and West Asia)

(१) दूसरा महत्वपूर्ण कारण मनुष्य के विश्वासों और आचार-विचारों में होने वाला परिवर्तन है। आज मनुष्य भाग्यवाद और प्राकृतिक शक्तियों के भय से बहुत कुछ मुक्त हो चुके है। प्राकृतिक भयों, धार्मिक अंध-विश्वासों, भाग्यवाद आदि के स्थान पर तर्क, बुद्धि और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित निर्णयों को महत्व दिया जाने लगा है। स्वतन्त्रता, प्रेम और नवीन जागृति के अङ्कुरों का आरोपण हुआ है तथा सम्पूर्ण जीवन दर्शन ही बदल गया है। आध्यात्मवाद की कल्पनाओं और विवेचनाओं से भरे भौतिकवाद को प्राथमिकता दी जाने लगी है। पहले यह विकास और जागरण केवल यूरोप तक ही सीमित था किन्तु अब एशिया और अफ्रीका जैसे अन्धकार के गर्त में पड़े हुए महाद्वीपों में भी जागरण और विकास की क्रान्तिकारी लहर व्याप्त हो चुकी है। पराधीन देशों की जनता में स्वाधीनता के भाव घर कर गये हैं और राष्ट्रवादी शक्तियाँ प्रबल हो गई हैं।

(२) तीसरा महत्वपूर्ण कारण वर्ग-भेद की भावनाओं को माना जा सकता है। साम्यवाद के उदय के बाद से वर्ग-भेद के विचार में जो राजनीतिक रंग लिया, उसके कारण वर्तमान सलाबरी की चतुर्थ दशाब्दी तक विश्व स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित हो गया। एक ओर शक्ति और सामर्थ्य से पूर्ण साम्राज्यवादी देश थे तथा दूसरी ओर पराधीनता की बेडियों में जकड़े हुए शक्तिहीन शोषित राष्ट्र। इन दोनों ही गुटों के हित परस्पर विरोधी थे। पहले गुट में जागरणता गुरु से हो थी जब कि दूसरे गुट में जागरणता बाद में आयी। जागरणता आने के बाद दूसरे गुट के राष्ट्र भी अगड़ाई लेकर उठ खड़े हुए और तब साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी समुल से निकल पड़ने की एक प्रक्रिया गुरु हुई जो आज तक जारी है। आज पहले गुट के सामने समस्या है अपने प्रभाव क्षेत्रों को येन-केन प्रकारेण बनाये रखने की जब कि दूसरे गुट के देशों की समस्या है सामाजिक, राजनीतिक और भाषिक दृष्टि से अपना विकास करके अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सम्मानपूर्ण स्थान पाने की। दूसरे गुट के राष्ट्रों की भावनाएँ साम्यवादी तेषों के साथ विशेषकर रूस के साथ अधिक जुड़ी हैं, पर उसे यह ध्यान रखना होगा कि रूसी शिकजा भी उसी ढंग से खतरनाक हो सकता है जिस ढंग से पश्चिम का पूँजीवादी शिकजा हुआ था।

(४) चौथा मुख्य कारण विश्व-मुद्द है। मार्गम्बो ने ठीक ही लिखा है कि मुद्द सदैव घमा-स्फिति को बदलने का साधन रखते हैं। मुद्दों के कारण छोटे राष्ट्र बड़े बन जाते हैं और बड़े राष्ट्रों का पतन हो जाता है। वर्तमान सलाबरी के दो महामुद्द विश्व-राजनीति के विभिन्न आदर्शों और व्यवहारों

को झटका दे चुके हैं। इनके कारण अनेक राजनीतिक व्यवहार असामाजिक बन चुके हैं और बहुत सी नयी व्यवस्थाएँ आविष्कृत हो चुकी हैं।

(५) विश्व स्थितियों में परिवर्तन का पाँचवाँ उल्लेखनीय आधार विश्व संस्था को माना जा सकता है। राष्ट्रसंघ अपनी कमजोरियों और सदस्य-राष्ट्रों की स्वायत्त लक्ष्मियों व अमहयोग के कारण अपने उद्देश्य में असफल रहा था। द्वितीय महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का संयुक्त राष्ट्रसंघ के रूप में पुनर्जन्म हुआ। इस बार राष्ट्रसंघ की असफलताओं और अनुभवों से लाभ उठा कर विश्व संस्था को अधिक दृढ़ और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्व के राष्ट्रों में स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व की भावना का प्रसार करके उनके बीच परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना करना चाहता है। इस दृष्टि से साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी मनोवृत्तियों का विनाश आवश्यक समझा जाने लगा है और सभी देशों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान अनिवार्य माना जाने लगा है। विश्व के दो गुटों में विभाजित हो जाने के कारण अविकसित और अर्द्ध विकसित देशों के विकास की ओर ध्यान दिया जाना अधिकाधिक महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है। प्रत्येक गुट अपना प्रभाव बढ़ाने और दूसरे गुट के प्रभाव को कम करने की दृष्टि से अर्द्धविकसित तथा अविकसित देशों को यथासम्भव आर्थिक सहायता और अन्य सहयोग देने के लिए प्रयत्नशील है।

परिवर्तित विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाले तत्व

(The Influential Elements of Changed World Politics)

आज विश्व राजनीति व केवल आधार ही नहीं परिवर्तित हो रहे हैं, बल्कि नवीन राजनीतिक रूपों तथा सम्बन्धों की भी धीरे-धीरे सृष्टि होती जा रही है। अमल में हम जिस युग में रह रहे हैं वह प्रान्तिषो तथा युद्धो का युग है जिसमें सामाजिक सुधार बड़ी तेजी से हो रहे हैं, नई-नई सन्धियाँ की जा रही हैं तथा विश्व का राजनैतिक एवं आर्थिक नक्शा बदलता जा रहा है। टी वी कालिजार्वी (T V Kalijarvi) ने वर्तमान विश्व के इन परिवर्तनों की व्याख्या बड़े स्पष्ट शब्दों में की है। उनका कहना है कि 'वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें कि पहले की राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे-धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में बदलती जा रही है। साम्राज्यों का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतन्त्रता प्राप्त कर रहे जा रहे हैं। राष्ट्र राज्य एक बड़े सच में विघीन होते जा रहे हैं।' विश्व का यह रूप-परिवर्तन, कल्पना की ओर है, जहाँ विनाश की दिशा में, इससे सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में आज अणु-शक्ति के रूप में मनुष्य के पाद बड़ी मारी शक्ति केन्द्रित हो चुकी

है किन्तु उसमें आत्म-नियन्त्रण का विकास अभी तक नहीं हो पाया है और इसीलिए इस शक्ति का दुरुपयोग करने का मय सदैव ही बना हुआ है। तथ्य यह है कि विश्व के आपुनिक परिवर्तन इतने अनिश्चित प्रवाह में बह रहे हैं कि आनावादी और निराशावादी दोनों ही प्रकार की सम्भावनाएँ की जा रही हैं। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा सम्बन्धों पर इन दोनों दृष्टिकोणों का प्रभाव है तथा दोनों ही पक्षों ने विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाले वर्तमान तथ्यों का प्रभावित करने में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले ये तथ्य अनेक प्रकार के हैं। इनमें में विश्व राजनीति पर समस्यात्मक रूप में छाये हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं।

(१) राष्ट्रवाद—राष्ट्रवाद की भावना निश्चय ही आज के विश्व की सबसे बड़ी विशेषता है। पेरू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की राजनीति राष्ट्रवाद के प्रभाव से पूरी तरह आक्रान्त है। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रवाद का मूल्य इस दृष्टि में अधिक बढ़ गया है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के बल पर आज राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का अपहरण करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं रह गयी है। राष्ट्रवाद एक देश की स्वतन्त्रता की रक्षा में श्रम का काम करता है। इसके नीचे एक ही हाथर सम्पूर्ण राष्ट्रवाद की जनता अपनी स्वतन्त्रता के अपहरण-कर्ता का विरोध करने लगती है। इसी प्रकार यदि किसी देश की स्वतन्त्रता का गटने ही अपहरण हो चुका हो तो भी इस भावना के आधार पर उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रवाद एक देश को कुछ करने की शक्ति देता है, उसे प्रेरणा देता और उन एकता के सूत्र में गाँझता है किन्तु शत्रु शक्ति की भाँति राष्ट्रवाद का रचनात्मक और विध्वनात्मक दोनों ही रूप हैं। विध्वनात्मक रूप में यह एक देश को दूसरे देश पर आक्रमण के लिए उत्तमाता है और उसे साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की ओर अप्रसर करता है। अति राष्ट्रीयता का अन्तिम परिणाम साम्राज्यवाद तथा महा विनाशक महायुद्ध होता है। अपने रचनात्मक रूप में राष्ट्रवाद देशभक्ति की भावना है, देशवासियों की एक करने वाला सयोजक तत्व है तथा अन्तर्राष्ट्रीयतावाद का विनाश करने वाला यह देश को स्वतन्त्रता प्राप्त करने, उसे बनाये रखने और देश का विकास करने की नयी प्रेरणाओं का प्रतीक है। राष्ट्रवाद की भावना का रचनात्मक विनाश एशिया और अफ्रीका को बदलने वाला प्रमुख मंत्र रहा, क्योंकि साम्प्रदायी चीन जैसे देशों में यह सूत्रनात्मक रूप विश्वनात्मक रूप में परिणत हो गया है।

(२) आत्म निर्णय का अधिकार — प्रथम महायुद्ध के बाद से ही राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को मान्यता मिली है जिसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह अधिकार है कि वह स्वयं उस धान का निर्णय करे कि क्या उस दूसरी राष्ट्रीयता के अधिकार में रहना है अथवा स्वयं को सरकार बनाकर उसके अधीन रहना है। इस अधिकार के सहारे अनेक पराधीन राष्ट्रों के स्वाधीनता आन्दोलन को एक हट आवाज प्राप्त हुआ है और आज यह अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी समय की अवस्था अधिक संशयन स्थान प्रदान किये हुए है।

(३) साम्यवाद और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया — १९१७ की बोलशेविक क्रान्ति के बाद हम में आ साम्यवाद पनपा, वह आज विश्व राजनीति पर प्रभाव डालने वाला एक अत्यन्त सक्रियतालो तत्त्व है। मजदूरों और किसानों का समर्थन तथा पूँजीपतियों के शोषण का विरोध आदि साम्यवाद के कुछ ऐसे धारणाएँ तरीके हैं जिनकी ओर साधारण जनता का ध्यान जाये बिना नहीं रह पाता। विश्व के पराधीन राष्ट्रों को स्वाधीनता का आश्वासन देकर और उनमें साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रचार करके साम्यवाद ने राष्ट्रीयता की भावना को बल दिया और आज यह विचार घाटा एशिया और अफ्रीका में अपना विशेष प्रभाव जमा चुकी है। साम्यवाद के बढते हुए प्रभाव के प्रतिक्रिया स्वरूप पश्चिमी शक्तिशाली अपने प्रभाव की रक्षा के लिए तेजी से सन्नद्ध हुई हैं जिसका यह स्वाभाविक परिणाम है कि एशिया और अफ्रीका साम्यवादी और पूँजीवादी खेमों के विभिन्न संघर्षों का रंग भव बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का समर्थन कोई भी क्षेत्र इन दोनों खेमों की क्रिया-प्रतिक्रिया से बच हुआ नहीं है। यह क्रिया प्रतिक्रिया विशेषतः तीन रूपों में अधिक प्रभावशाली है—

(१) पश्चिमी शक्ति और उनके साथियों द्वारा अनेक ऐसी सन्धियों और सगठनों का विकास किया गया है जिसका मुख्य लक्ष्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। इन सगठनों के जवाब में साम्यवादी खेम द्वारा बारम्बार पेंकट आदि अन्य गुरक्षामक सगठन कायम किये गये हैं।

(२) गरीब और हीन देशों को जाना साम्यवाद की ओर तुरन्त आकर्षित होती है—यह समय लेने के बाद पश्चात्प शक्तियाँ अर्ध विहसित देशों को हर प्रकार से सहायता देने लगी हैं ताकि उनका जीवन स्तर और मजबूत ऊँचा उठे। पश्चिमी शक्तियों के प्रयासों के जवाब में साम्यवादी देश भी एशिया और अफ्रीका के पिछड़े राष्ट्रों की आर्थिक व मैनिक मदद पर उत्तर आये हैं। इनमें रूस का स्थान सर्वोपरि है।

(३) शीत युद्ध और सन्निकर्षण का प्रसार हुआ है। लेकिन साथ ही सहअस्तित्व की विचारधारा भी पनपी है—विशेषकर इस अनुभूति के बाद कि दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे को नष्ट करने में सक्षम हैं। जत महायुद्ध का अर्थ होगा महाविनाश।

(४) शीतयुद्ध —द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व शीत युद्ध (Cold War) है। इस पर सविस्तार प्रकाश आगे "शीत युद्ध" नामक अध्याय में डाला गया है।

(५) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व —अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में पूँजीवादी और साम्यवादी क्षेत्र का जो विरोध चला है और उसमें शीत-युद्ध के ज्वार और फलस्वरूप युद्ध आगका का जो विस्तार हुआ है, उसमें कारण शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की विचारधारा पनपी है। यह विचारधारा आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना एक विशय स्थान बना चुकी है। महायुद्ध की सम्भावना से आतंकित होकर दोनों ही क्षेत्रों के राजन तज यह सोचने का मजबूर हो गये हैं कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। भावित जैसे-असलान राष्ट्रों ने शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के विचार को सबसे अधिक पविष्ट-पल्लवित किया है।

सोवियत रूस में स्टालिन और स्टालिनवाद की समाप्ति के बाद जो नया सदारवाद आधिक रूप में उभरा है, उसने असलान देशों के प्रति मैत्री प्रदर्शित की है तथा सहअस्तित्व की विचारधारा में विश्वास प्रकट किया है। दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। वह युद्ध और शान्ति की अनिवार्यता में विश्वास करता है। सोवियत रूस से, मुख्यतः सहअस्तित्व के प्रश्न को लेकर ही, सैद्धांतिक संघर्ष छिड़ गया है और उसने वर्तमान सोवियत नेताओं को संशोधनवादी (Revisionist) तथा पूँजीवाद का समर्थक बताकर उन्हें विदेश साम्यवादी शान्ति का नकार करने के अपयोग्य ठहरा दिया है। साम्यवादों में ही यह फट अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की नयी दिशा में प्रभावित करने लगी है। इसने रूस का पश्चिम के निकट आने की विषय किया है और दूसरी ओर पश्चिमो राष्ट्र भी युद्ध विनाशू चीन की तुलना में सोवियत रूस को अधिक तरजीह देने लगे हैं। विचारकों का मत है कि साम्यवादी समार में यह सैद्धांतिक दरार अस्थाई है तथा सोवियत रूस के मूलभूत लक्ष्यों में कोई अन्तर नहीं आया है। श्री एट-ज़िनी (Amatai Et Ziona) इन बात पर बल देना चाहते हैं कि "सोवियत रूस को घेरे-बन्धी और विरोधियों द्वारा मजबूर किया गया है कि वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को छोड़कर सन्न-विहीन प्रयत्नों की ओर अधिक ध्यान दे।"

(६) विश्व सरकार—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों में विश्व-सरकार की धारणा ने भी बड़ी हलचल मचा रखी है। यह कहा जाना है कि यदि विश्व में स्थाई शांति से शांति कायम करनी है और तृतीय महायुद्ध में अणुशक्ति के प्रकोप से मानवता को बचाना है तो विश्व के सभी राष्ट्रों को मिलाकर एक विश्व-संघ का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संघ की कल्पना एक संघामय विश्व सरकार (World Government) की कल्पना है, जिसमें यह बात निहित है कि एक विश्व संघ सारे ससार की एक केन्द्रीय सरकार की तरह कार्य करे और वर्तमान राष्ट्रीय सरकारें राज्य सरकारों की तरह कुछ विषयों में—विशेषकर वैदेशिक क्षेत्र में—विश्व सरकार के अधीन बन जाएं। विश्व सरकार के समर्थकों का कहना है कि वर्तमान विश्व में संघर्षों और युद्धों का मुख्य कारण राष्ट्रवाद है और जब तक सम्प्रभु राष्ट्र विश्व में रहेंगे तब तक यह कारण भी बसा रहेगा, जब अच्छा नहीं है कि इस विपरीत दात को ही समाप्त कर दिया जाए। विचारकों का दूसरा पक्ष इसे श्रुतिपूर्ण और अव्यावहारिक सुझाव मानना मानता है। विश्व सरकार के आदर्श के पक्षधरियों की धारणा है कि विभिन्न क्षेत्रीय संगठन विश्व सरकार की आरंभिक प्रयास माने जा सकते हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व सरकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और आज समुक्त राष्ट्र संघ यदि अपनी 'ब्लॉक पॉलिटिक्स' (Block Politics) को छोड़कर अधिक निष्पक्षता और सत्तरता से कार्य करने लगे तो यह स्वल्प बहुत शीघ्र ही ग्यारहवां में बदला जा सकता है।

(७) निःशस्त्रीकरण—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की निःशस्त्रीकरण की समस्या कितनी अधिक प्रभावित कर रही है, यह कल्पने की आवश्यकता नहीं। सभी दिग्दर्शनवान यह है कि एक आरंभिक मंथन यह मानते हैं कि विश्व शांति के हित में शस्त्रों को समाप्त या सीमित कर दिया जाना चाहिए, और दूसरी ओर सभी शस्त्रों के अधिनाशिक संग्रह में लगे हैं। निःशस्त्रीकरण की समस्या ने शीत युद्ध को और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव आदि पर सविस्तार प्रकाश दिखले 'निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी' पृष्ठों में डाला जा चुका है।

निष्कर्षतः यह सभी तथ्य और इनके साथ जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के घटना चक्र को पूरी तरह प्रभावित किये हुए हैं। इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को अस्थिर और अनिश्चित बना रखा है।

एशिया की प्रजाति (Resurgence of Asia)

एशिया, पूर्व में प्रशान्त महासागर से पश्चिम में भूमध्यसागर तक तथा

दुनियाँ में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में हिन्द महासागर के मध्य बसा हुआ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनियाँ की आधी से अधिक जनसंख्या इस महाद्वीप पर निवास करती है। सभी प्रकार के धर्मों और सभी सभ्यताओं तथा भाषाओं का यह महाद्वीप घर है। इस महाद्वीप पर विभिन्न प्रकार के खनिज, भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु पाई जाती है। महा के अधिकांश देश अति जनसंख्या और आपस में विद्वेष के कारण पीड़ित हैं। इन देशों का राजनीतिक जीवन जनता के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से प्रभावित है। लोग भ्रष्टाचार, हठिबाजी हैं, अतः प्रजातांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना और उनका सफल संचालन बड़ा कठिन है। शासन व्यवस्था के रूप में चाहे जो भी परिवर्तन कर दिया जाए, शासन-सत्ता प्राप्त उन्हीं लोगों के हाथ में बनी रहती है जो पहले से वहाँ शासन करते आये हैं। अन्धकार इन देशों में कोई अपवाद नहीं है वरन् एक सामान्य नियम के रूप में पर पर चुका है।

एशिया महाद्वीप और पश्चिमी उत्तर अफ्रीका पूर्व और पश्चिम के बीच भारी अन्तर यह है कि जहाँ एक ओर तो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए भी तरलते रहते हैं वहाँ दूसरी ओर वे लोग हैं जो अतिरिक्त दानि-संपन्न में लगे हुए हैं। यह पूर्व और अफ्रीका के बीच का अन्तर है। एशिया के लोगों की शिक्षा के लिए जाति और सहयोग की आवश्यकता है। उनकी बुद्धि और कर्म से बितना पत्रा है उतना अन्य किशो को नहीं है।

एशिया का यह पिछड़ापन अतीत से विरासत में मिला है। हुआ यह कि १८ वीं व १९ वीं सतादियों में जब यूरोप तथाकथित 'औद्योगिक क्रांति' (Industrial Revolution) के प्रभाव से मनुष्यानीन अवस्था त्याग कर आधुनिक अवस्था में पहुँच रहा था तो ऐसे समय एशिया ने अपनी अर्थ-व्यवस्था, सभ्यता एवं राजनैतिक-संरचना सम्बन्धी प्राचीन प्रथाओं का परिपालन करने से इनकार कर दिया जिसका स्थानाधिक परिवर्तन यह गिनता कि यूरोप प्रगति करता चला गया और एशिया पिछड़ता गया।

एशिया आर्थिक दृष्टि से ही नहीं पिछड़ा वरन् वह राजनीतिक दृष्टि से भी पश्चिम के हाथों धनः धनः पूरी तरह पराजित हो गया। पश्चिम ने एशिया को पराजित करते उसके स्वतन्त्र अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया। धनः धनः जापान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल और चीन को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण एशिया पश्चात्त्य राष्ट्रों के शासित्व में आ गया। अंग्रेज भारत, बर्मा, श्री लंका, मलाया, सिंगापुर और हावकांग में जन्म गये, फ्रांसिसियों ने हिन्दोचन में डेरा जमा लिया, डचों ने ईस्ट इंडोच में पैर रोखा दिया। रूसियों ने चीन के आन्तर प्रान्त सहित माइकोरिया का बाह्य मंगोलिया में और तुर्किको-स्तान (बाद में सोवियतों ने) सिन्किन्ग में अपने अङ्ग जमा लिये। महा तब कि पुनः

गाल जैसे छोटे से राज्य ने भी अपने उपनिवेश कायम कर लिये। वे देश भी, जो जाहिरा तौर स्वतन्त्र थे, व्यावहारिक दृष्टि से विदेशी राष्ट्रों के आधिक और राजनैतिक प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके। पश्चिमी एशिया अथवा मध्य-पूर्व के राष्ट्र, जो प्रथम महायुद्ध से पहले 'ओटोमन साम्राज्य' के अधीन थे, १९१९ के पेरिस शान्ति सम्मेलन द्वारा अन्वेषित एक नवीन व्यवस्था-संरक्षण पद्धति (Mandate System) के अन्तर्गत अब यूरोप के शोषक शासकों के नियन्त्रण में आ गये। केवल जापान ही एक ऐसा राष्ट्र रहा जिसने पाश्चात्य आधुनिकवाद से पूर्ण शिक्षा लेते हुये स्वयं को औद्योगीकृत किया, अपने पिछड़े-पन के सभी बिन्दुओं को मिटाया और शीघ्र एशियाई राष्ट्रों के दुर्भाग्य से अपने आपको बचाने में सफल हो गया। यही नहीं वह कालांतर में औद्योगिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में पश्चिम का एक घोर प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध हुआ।

एशिया पश्चिम की चक्की में घिसता रहा, लेकिन आखिर उसने भी करबट ली। एशिया के सभी देशों पर पाश्चात्य विचारों और व्यवहारों का प्रभाव पड़ा। पश्चिमी देशों ने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, प्रशासन, अर्थ व्यवस्था आदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन किये। यद्यपि इन परिवर्तनों का प्रारम्भ में विरोध किया गया क्योंकि ये एशियावासियों की परम्पराओं और विश्वासों से मेल नहीं खाने थे, किन्तु धीरे-धीरे जाने या अनजाने इन परिवर्तनों का प्रभाव एशियायी समाज पर पड़ने लगा। 'जिसका जूता उसी का सिर' वाली कहावत चरितार्थ करने हुए एशिया के लोगों ने पाश्चात्य प्रभावों का प्रयोग उनके साम्राज्य को उखाड़ने को किया और इस कथन में कोई अतिशयोक्ति न होगी कि वर्तमान एशियायी शान्ति की जड़ में पश्चिमी विचारों का प्रभाव निहित है। मर्मप्रथम एशियायी देशों में राष्ट्रवाद की एक लहर आयी और तब ऐसे स्वातन्त्र्य आन्दोलन का सूत्रपात हो गया कि जिस उपनिवेशवादी एशिया के जागरण के मदर्भ में यह देखना रोचक और आवश्यक होगा कि एशिया में किस तरह स्वातन्त्र्य आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, किस तरह एशिया जागृति के पथ पर आगे बढ़ा और अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुँच सका।

एशिया में स्वातन्त्र्य आन्दोलनों का सूत्रपात और उपनिवेशवाद का ढहना

एशिया के राष्ट्र पहले से ही आर्थिक दृष्टि से अविकसित अवस्था में थे। पाश्चात्य शक्तिशाली ने उन पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद उनके आर्थिक शोषण की नीति अपनाई। इस नीति ने प्रथम इतना भयावह रूप ले लिया कि एशिया के अनेक समृद्ध राज्यों को भी भुखमरी पीटा और विभिन्न कष्टों का शिकार होना पड़ा। जब तक एशियावासियों ने विदेशी शक्ती के वास्तविक स्वरूप और प्रकृति को नहीं पहचाना तब तक वे चुपचाप और

निश्चय रहे, लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का भाव हुआ अपने बढ़ते हुए कष्टों को विचलित कर देने वाली अनुभूति हुई तो चीत्र ही वे यह निराकरण समझ गये कि उनकी इन सब कठिनाइयों का तमो सम्भव हो सकेगा जब वे विदेशी शासन से मुक्तिपत्र समझेंगे। इस प्रकार की चेतना बहुत कुछ पश्चिमी ज्ञान, छाहिय, कानूनों और सस्याओं के कारण पैदा हुई। पूर्व की 'पश्चिम' के राष्ट्रवादी विचारों और समस्त उच्च जीवन स्तर ने सर्वाधिक प्रभावित किया। प्रो. शुमन (Schuman) के शब्दों में—“इन पिछड़े हुए राष्ट्रों के नये बुद्धि-जीवियों ने विज्ञान, युद्धकला तथा राजनीति में पश्चिमी राष्ट्रों की दक्षता तथा निपुणता का जोही एक आशिक भाग प्राप्त किया क्योंकि उनमें इस बात की माग करने वाले नताग्र भी पैदा हो गये कि उन्हें अपना भविष्य स्वयं निश्चित करने का अधिकार मिलना चाहिये।”

प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता, राष्ट्रियता और लोकतन्त्र की पहली लहर आई। एशियावासी 'पश्चिम' की सम्पन्नता और अपनी निर्धनता तथा दीन-हीन अवस्था से परिचित होने के बाद 'आत्म निर्णय' की माग करने लगे। 'भारत भारतीयों के लिए,' 'चीन चीनियों के लिए,' आदि आवाज बुलन्द होने लगी। एशिया करघट लेकर 'विश्व में अपने उच्च स्थान' की माग करने लगा। सम्पूर्ण महाद्वीप में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पादचार्य प्रवृत्ति से छुटकारा पाने की एक उदात्त लानसा जादत हो गई जिसने एक सभ्य स्वातन्त्र्य आन्दोलन और सभ्य का रूप धारण कर लिया। यद्यपि विभिन्न एशियाई राज्यों के इन राष्ट्रवादी आन्दोलनों का स्वस्व एकसा नहीं था, तथापि उनका उद्देश्य अवश्य एकसा था—पश्चिम के उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और जाति-भेदभाव का विरोध करना। कटस्थल एशिया के लगभग सभी पराधीन राज्यों ने, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी स्थिति पर आन्तरिक पुनर्विचार की माग की। एशियाई राष्ट्रों की इन नवीन भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति अगस्त १९२६ में यूरोप में बायरविले (Bierwile) नामक स्थान पर आयोजित यानि, के लिये 'अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन' में एशियाई प्रतिनिधियों के उस माग-पत्र में हुई जिसमें यह घोषणा की गई कि—

“यूरोपियन विचारों के अनुसार विश्व सम्भवतः उन्ही क्षेत्रों तक सीमित है जिनमें यूरोपियन जातियाँ निवास करती हैं। मानव सभ्यता के बहुमूल्य तथा अपनी सर्वाधिक प्राचीन सम्पत्तियों वाला एशिया महाद्वीप यूरोपियन विचारकों के अनुसार विश्व का भाग नहीं है। हमारा यह नम्र निवेदन है कि यह दृष्टिकोण गलत है। यदि विश्व स्थाई शांति का इच्छुक है तो वहाँ स्थानीय या क्षेत्रीय यानि नहीं होने चाहिये—यदि आप

शांति चाहते हैं तो पहले आपको उन कारणों को दूर करना चाहिये जिनसे एशिया में यूरोप के प्रति विरोध पैदा हुआ है—यदि आप एशिया व यूरोप में एक सहयोगी बन्धुत्व की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं तो आप विश्व-शांति की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठा लगे। जो चीज इस सहयोग के मार्ग को अवरोध कर चुके हैं वह एशिया के शोषण तथा अधिक से अधिक राज्यों को अधीनस्थ बनाने के पश्चिमी राष्ट्रों की गुटबन्दी है।” ✓

एशियाई प्रतिनिधियों द्वारा ~~अभिव्यक्त~~ किया गया उन्नीस विचार सम्पूर्ण विश्व को इस बात का निर्दिष्ट ^{निर्देश} करत था कि एशिया अब जागने लगा है और अपनी महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अब वह हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने को मन स्थिति में नहीं है। एशिया के तेजी से होने वाले नव जागरण ने एशिया के इस निश्चय को शीघ्र ही प्रकट कर दिया। द्वितीय महायुद्ध ने, जिसमें यूरोपियन राष्ट्रों के दो गुट परस्पर मरणाक सघर्ष में जुझ रहे थे, सदियों में उल्लिखित और शोषित एशिया महाद्वीप को अपना उद्देश्य प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया। सैनिक और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध व अपनी जानान ने हिन्दचीन से फ्रांसियों को निकाल फेंका, डच ईस्ट इंडीज को कब्जे में कर लिया, ब्रिटेन के ‘अजय’ सिंगापुर का जोत लिया और फिलीपाइन्स में अमेरिका जैसी महा शक्ति को पछाड़ दिया। दूसरी ओर १९४२ के ‘भारत छोड़ो आन्दोलन’ ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। ऐसा लगने लगा कि श्वेत जातियों का सिनारा अब डूबने को है। परन्तु दुर्भाग्यवश एशिया महाद्वीप को अभी कुछ वर्षों तक साम्राज्यवादी दुर्दिन और देखने थे। १९४५ में पश्चिमी शक्तियों की विजय के पश्चात् साम्राज्यवाद की पुरानी व्यवस्था पुनः उसी का स्थान स्थापित रह गई।

लेकिन अब यह स्थिति अधिक समय तक जारी रहने वाली नहीं थी। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर आई हुई स्वतन्त्रता, राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र की लहर ने द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रबल बाढ़ का रूप धारण करके समस्त एशिया और अफ्रीका को आप्लावित कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में श्वेत जातियों की जिन शारभमक गहरी पराजयों का सामना करना पड़ा था उससे एशियाई जनता को यह विश्वास हो गया कि पश्चिमी राष्ट्र अथवा ‘गोरी-चमडी’ अंग्रेज नहीं है। इस अनुभूति के फलस्वरूप स्वातन्त्र्य आन्दोलनों में नये प्राण फूले गये। पहले हुए यूरोप के लिये उनकी दबाना मुश्किल हो गया और आजादी की लहर चली कि एक के बाद एक सभी राष्ट्रों ने स्वतन्त्र पुरे होने चने गये। वास्तव में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि १९१९ के बाद एशिया और अफ्रीका ने महाद्वीपों में साम्राज्यवाद की पराजय आरम्भ

हुई और १९४५ के बाद इनका सुरू सुरू होने लगा। पश्चिम की प्रगति और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एशिया के इस विद्रोह को अमेरिकन पत्रकार गॉरेट पेन (R. Payne) ने वर्णनरत युग की सबसे बड़ी घटना बताते हुए लिखा है कि एशिया को अब अपने महत्व का ज्ञान हो गया है और 'एशिया की शताब्दी' आरम्भ हो गई है। एशिया के इस नवजागरण को देखते हुए ही विख्यात इतिहासकार अर्नाल्ड टॉयबेक (A. Toynbee) ने यह भविष्यवाणी की है कि "माजरात हम (पश्चिमी देश) साम्यवाद की चुनौती को अधिक महत्व दे रहे हैं। किन्तु जब भारत और चीन की अधिक शक्तिशाली सम्मिताएँ पश्चिमी जगत की चुनौती का उत्तर देने सँगे तो साम्यवाद का महत्व कम हो जायेगा। अन्ततोगत्वा ये सम्मिताएँ हमारे पारिचायक जीवन पर उससे बड़ी अधिक गहरा प्रभाव डालेंगी जितना प्रभाव रुस अपने साम्यवाद द्वारा हमारी सम्मिता पर डाल सकता है।" एशिया की जागृति को स्वर्गीय श्री नेहरू ने १९४७ में प्रथम 'एशियाई-सम्मन्त्र सम्मेलन' (Asian Relations Conference) में घोषणा की थी कि "एक परिवर्तन हो रहा है, एशिया अपने स्वयं को पुनः पहिचान रहा है। हम परिवर्तन के महामुग में रह रहे हैं और इसमें नवयुग तब आएगा जब एशिया अन्य महाद्वीपों के साथ अपना सचिन स्थान ग्रहण करे। विश्व इतिहास के इस सङ्कट में एशिया अवश्य महत्वपूर्ण भूमिका खेद करेगा।"

भविष्य ने इन सभी भविष्यवाणियों को सच कर दिखाया। आज एशिया के अधिकांश भू-भाग स्वतंत्र वातावरण में साँस ले रहे हैं। पश्चिमी देशों की प्रगति की बराबरी करने की बलवती भावना है। वे अपने की औद्योगिक एवं यांत्रिक दृष्टि से इतना विश्वसित कर लेना चाहते हैं कि इनके और औद्योगिक विकास के शिखर पर लौटने पर पश्चिमी देशों के बीच कोई अन्तर न रह जाये। इस भावना को अधिक तीव्र बनाने में राष्ट्रवाद और भी अधिक समर्थ होता जा रहा है। परिणामतः आज उपनिवेशवाद या पश्चिमी देशों के दबाव से मुक्त होने की भावना प्रबल नहीं है बल्कि उससे भी अधिक अपने पुराने ढंग के रहन-सहन को बदलने के लिए प्रगति विरोधी शक्तियों से पल्ला छुड़ाने की भी वे तत्पर हैं। सदियों की दासता और सामन्तवादी व्यवस्था के कुप्रभावों से झुकी हुई अपनी रीढ़ को पुनः सदा करके आज का एशिया अपना साम्राज्य करने को तत्पर है। आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री श्री पी० सी० हॉडर के शब्दों में—“एक अरब से अधिक जनता एशिया में राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन करने में लगी हुई है। सर्वेभर नई राजनीतिक और आर्थिक नीतियों और नई संस्थाओं का विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और यह विकास राष्ट्रीय विचार की प्रेरणा

से तथा आर्थिक और सामाजिक सुधार की मांग के कारण भविष्य में भी चल्ता रहेगा।

आज एशिया राष्ट्रवाद की लहरों से व्याप्त है। इसके देश अपने को आर्थिक दृष्टि से विकसित करने में प्राणपण से सलग्न हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिये तेज कदमों के आकांक्षी हैं। परन्तु आकांक्षाओं के अनुरूप बनने में जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रथम दिया गया है उससे तनाव पैदा हो गया है। एक तरफ एशिया का विशाल जनमत लोकतन्त्रवाद के मार्ग का अनुगामी बनने के लिए सचेष्ट है और दूसरी तरफ साम्यवाद भी अपनी सत्ता जमाने की होड़ में व्यस्त है। यदि एशिया में औद्योगिक शान्ति एवं आर्थिक विकास के कदम स्वतन्त्रता के आगमन के पूर्व ही हो गये होते, तो विशेष परेशानी नहीं होती किन्तु आज विडम्बना यह है कि एक तरफ तो राजनीतिक स्वतन्त्रता मिलती जा रही है और दूसरी तरफ लोगों का जीवन स्तर अब भी मध्यकालीन है। परिणामतः आज का एशिया विभिन्नवादों के संघर्ष का क्रीड़ा स्थल बन गया है। साम्यवाद अपनी नवीन किन्तु नान भूमिका में अवतरित हुआ है और समग्र एशिया को अपने में समाविष्ट कर लेना चाहता है। पश्चिमी पूँजीवाद लोकतन्त्र में अधिक विकास के कदम सहम सहम कर उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण सफलता की दौड़ में साम्यवाद से पिछड़ा रहा है। रूस की तरक्की का उदाहरण तो विश्व के सामने है ही, किन्तु उसमें भी अधिक एशिया में साम्यवादी चीन का बेहतर उदाहरण है। यदि पश्चिम के शक्तिशाली और समर्थ लोकतन्त्रात्मक राष्ट्र चाहते हैं कि एशिया पूरा लाल रंग में न रंग जाय तो यह अपक्षिप्त है कि उन्हें भारत जैसे लोकतन्त्रात्मक राष्ट्रों की प्रत्येक सम्भव सहायता जी खोल कर करनी चाहिये ताकि वे लोकतन्त्र के अजेय स्तम्भ बन कर एशिया में बढ़ते हुए साम्यवाद पर प्रभावी अंकुश लगा सकें।

एशियायी व्यक्तित्व का विकास

मित्र मित्र सांस्कृतिक भूमिकाओं, धार्मिक दृष्टिकोणों और राजनीतिक अनुभवों वाले लोगों का महाद्वीप एशिया, जब स्वतन्त्रता की झँगड़ाइयाँ लेने लगा तो स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार की अविवेककारी शक्तिशास्त्रात्मक स्वदेशी शासकों को चुनौती देने लगी। जाति वैमनस्य और जातुओं ने, साम्प्रदायिकता व स्वार्थ लिप्सा ने, पूँजीवाद और साम्यवाद आदि ने अपना सिर उठाया। कुछ राज्यों में गृह युद्ध हुए, वही साम्प्रदायिक दंगे और विद्रोह हुए तो वही भूख और निर्धनता से तप्य और पीड़ित जनता के प्रदर्शन हुए। राष्ट्रीय नेताओं को, जिन्होंने “विदेशी शक्तों से लोहा लिया या अब स्वदेशी शक्तों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने अपने इदं-गिदं के विद्वत् पर

दृष्टि डाली तो उन्हें एक दूसरे को पराजित करने पर तुले हुए दो 'शक्ति-गुटों' का संघर्ष दिखाई दिया। यह संघर्ष एशियावासियों के लिए खतरनाक था क्योंकि उनकी भयावह समस्याओं के समाधान के लिए आन्तरिक स्थिरता और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को अनिवार्य आवश्यकता थी। जाने को इन खतरनाक परिस्थितियों में पाकर एशियायी राष्ट्रों में एक प्रकार के सामुदायिक हस्तिकोण से जुझ कर विजय पाने के लिए उन्हें पारस्परिक एकता, संगठन और सहयोग का परिचय देना होगा।

इस प्रकार की एकात्मकता की नवीन धेतना की अभिव्यक्ति मार्च, १९४७ में नई दिल्ली में आयोजित 'एशियायी मंत्री सम्मेलन' (Asian Relations Conference) में हुई। इस सम्मेलन में एक 'एशियायी मंत्री मण्डल' (Asian Relations Organisation) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई—

(१) एशियायी समस्याओं और सम्बन्धों के महाद्वीपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं के अध्ययन और ज्ञान को प्रेरणाहित करना,

(२) एशियायी राष्ट्रों में और एशिया तथा विश्व के अन्य राष्ट्रों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देना, एवं

(३) एशियायी जनता की प्रगति और हितों में वृद्धि करना।

एशिया में जागरण और एकता की जो यह चेतना उदित हुई वह तेजी से विकसित होती गई और यह कहना अनिश्चयपूर्ण न होगा कि अप्रैल, १९५१ में होने वाले बाडुंग सम्मेलन में सबसे पहले विश्व के सामने एशियायी व्यक्तित्व बड़े तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ। इन 'अफ्री एशियायी सम्मेलन' में भारत सहित २६ राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए और पहली बार एशिया का महान साम्यवादो राष्ट्र चीन भी उपस्थित हुआ। 'बाडुंग-सम्मेलन' में विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया और 'वास्तविक स्वतन्त्रता' की अभिप्राय की खोज की गई। 'अफ्री एशियायी' राष्ट्रों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक स्वतन्त्रता सभी है जब अपने निम्नलिखित तत्वों का समावेश हो—

(१) विदेशी प्रभाव से मुक्ति एवं पूर्ण लोकतन्त्रात्मक स्व शासन,

(२) जाति, समुदाय और रंग का किसी प्रकार भेदभाव किये बिना मानव प्रतिष्ठा की मान्यता,

(३) तीव्र आर्थिक समृद्धि जिसका लाभ अधिकाधिक जनता को सुलभ हो, एवं

(४) पुद्ग का उन्मूलन तथा सद्भावना का प्रसार।

बाहु ग सम्मेलन में उपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध किया गया और बाफ़ी विचार विमर्श के बाद सम्मेलन ने यह विचार प्रस्थापित किया कि जनता की इच्छा के विरुद्ध शक्ति और विध्वंस द्वारा स्थापित शासन भी उपनिवेशवाद ही है। बाहु ग सम्मेलन ने सह अस्तित्व और अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धान्तों में विश्वास प्रकट किया।

२७ अप्रैल, १९५५ को बाहु ग सम्मेलन की समाप्ति पर लगभग सम्पूर्ण विश्व को यह विश्वास हो गया कि सोया हुआ एशिया और अफ्रीका अब जाग उठा है, एक नयी आवाज और एक नये संदेश के साथ। यह आवाज विद्रोह और सशस्त्र क्रांति की नहीं थी, यह आवाज शीत-युद्ध की नहीं थी, बरन् यह आवाज तो शान्ति, मैत्री, सद्भावना और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की थी। अफ्रीका एशियायी राष्ट्रों के इस महान सम्मेलन के महत्व को इंगित करते हुए सुबिरयात विद्वान बार्नेट ने लिखा है—“बाहु ग सम्मेलन एशिया और अफ्रीका के पुनर्स्थान का प्रतीक था। यह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसमें एशिया और अफ्रीका के प्रमुख नेता पश्चिमी शक्तियों के प्रभाव में मुक्त बंटक में मग्न रह चुके थे। यह इस बात का ज्वलन्त उदाहरण था कि विश्व के मामलों में अब एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों का प्रभाव बढ़ रहा है।”

एशिया महाद्वीप कुछ विशेषताएँ—एशिया महाद्वीप के उपयुक्त वर्णन से प्रकट है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से यहाँ अनेक झुकावों और दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है। पामर और पकिन्स ने इन्हें अनेक शीर्षकों में विभाजित किया है। उनके मतानुसार एशिया में शान्ति अभी तक चल रही है। पहले दुस्का विरोध केवल विदेशी साम्राज्यवाद के प्रति था, किन्तु आज यह विरोध पुराने विचारों, विश्वासों, गरीबी, अज्ञानता, अशिक्षा एवं ऐसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध सन्तुलित किया जा रहा है। राष्ट्रवाद एशिया में सर्वत्र प्रभावपूर्ण बनता जा रहा है तथापि साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने प्रभाव जमाये रखने की प्रयत्नशील हैं। सोवियत साम्यवाद का अधिकार अब भी विशेष रूप से प्रभावशील है। पामर और पकिन्स के अनुसार सोवियत रूस ने साम्राज्यवाद का विरोध कर एशिया-वासियों की भावनाओं को अपने पक्ष में प्रभावित कर लिया है और अब जब कि पश्चिमी शक्तियों का प्रभाव वहाँ से हट रहा है, वह अपना प्रभाव दिनोदिन फैलाता जा रहा है। एशिया के लगभग सभी देश आर्थिक और सामाजिक न्याय चाहते हैं। वे राजनीतिक स्वतन्त्रता के पक्षपाती और साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। इसी मूलभूत एकता के प्रभाव से वहाँ की कोई भी बड़ी शक्ति एशिया-वासियों और एशियायी नेताओं के दृष्टिकोणों की उपेक्षा नहीं कर पाती। दो

ग्रुटो के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी एशिया के अधिकांश देशों का मत है कि साम्यवादी व्यवस्था और पूँजीवादी प्रजातन्त्रों के बीच में भी एक रास्ता है। काथिक दृष्टि से इसे मिश्रित अर्ध-व्यवस्था एवं विदेश नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से असलग्नता की नीति, (Policy of Non-alignment) कह सकते हैं।

पामर और पर्सिन्स ने एशिया के प्रमुख देशों की विदेश नीति को अथवा उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ५ भागों में विभाजित किया है—

- (१) साम्यवादी चीन का दृष्टिकोण,
- (२) राष्ट्रवादी चीन और कोरिया का दृष्टिकोण,
- (३) पश्चिम पक्षपाती दृष्टिकोण,
- (४) ईरान अरब का दृष्टिकोण, एवं
- (५) असलग्न राष्ट्रों का दृष्टिकोण।

विदेश नीति सम्बन्धी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उपर्युक्त ५ भाग उपयुक्त हैं तथापि इन्हें तीन मुख्य भागों में बांटना हो पर्याप्त होगा अर्थात् साम्यवाद समर्थक दृष्टिकोण, पूँजीवाद समर्थक दृष्टिकोण तथा असलग्नता का दृष्टिकोण। असलग्नता के दृष्टिकोण का अपना विशेष महत्व है। इस पर आगे यथा स्थान प्रकाश डाला गया है। साम्यवाद का प्रभाव एशिया में बढ़ रहा है। एशिया का महानतम राष्ट्र चीन पूरी तरह लाल बन चुका है और एशिया व अफ्रीका के विभिन्न देशों पर अपना आतंक फैलाने की प्रयत्नशील है। ताकि यह देश उसका प्रभुत्व स्वीकार करले और उसके बताये हुए तरीके पर चलकर साम्यवाद की स्थापना करले। इस दिशा में उसकी दृष्टि से सोवियत साम्यवाद से है सोवियत रुख भी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की प्राणपण से सचेष्ट है, जिसमें उसे उत्कृष्टनीय सफलता हासिल हो रही है। साम्यवादी चीन की विस्तारवादी और साम्यवादी नीतियों ने एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को जगा दिया है। यह स्थिति भारत पर चीन के अकारण आक्रमण के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। साम्यवादी एशिया पर न छा जाए, इसलिए पश्चिमी शक्तियाँ भी एशिया के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बनाये रखने की सचेष्ट हैं। मुख्य बात यह है कि इस दिशा में नेतृत्व ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों से खिसक कर समुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में आ गया है। यह कहना उपयुक्त होगा कि एशिया विश्व की दो महा शक्तियों का त्रीक्षास्थल बना हुआ है और एशिया की भलाई इसी बात में है कि वह दोनों महा शक्तियों को अपना मित्र मानते हुए किसी प्रभुत्व में न जाए, वरन् अपना स्वतन्त्र मार्ग अपनाय और अपने भाग्य का निर्णायक स्वयं बने। यह तभी सम्भव है जब एशिया आपसी पूँट और मतभेदों से ऊपर उठ जाए, अपनी काथिक उन्नति करले और परिपक्व राजनीतिक सजगता का परिचय दे।

किया। किन्तु इस प्रकार का दमन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को समाप्त करने की बजाय मजबूत करने में ही सहायक रहा। उन्होंने ने वहाँ के निवासियों की राष्ट्रवादी भावनाओं को पूरी तरह से समझा नहीं तथा वे उनका बराबर दमन करते रहे। १७ अगस्त, १९४५ को स्वतन्त्र इन्डोनेशियन गणतन्त्र की स्थापना हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति हाटा ने ७ अक्टूबर, १९४५ को गणतन्त्र के ५ सिद्धान्तों की व्याख्या की जो ये थे— (i) ईश्वर में विश्वास (Belief in God), (ii) राष्ट्रवाद (Nationalism) (iii) सार्वभौमवाद (Universalism), (iv) प्रजातन्त्र (Democracy) और (v) सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

भारत में राष्ट्रवाद के उदय के पीछे अनेक कारण थे। जैसे तो कुछ विद्वान १८५७ की क्रांति को भी स्वतन्त्रता संग्राम मानते हैं जिसमें राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर विदेशी शक्तियों को भारत से निकालने का असफल प्रयास किया गया था। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का संगठित रूप से प्रारम्भ १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से माना जाता है। कांग्रेस का इतिहास भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का इतिहास है। कांग्रेस धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रवाद की अधिकाधिक अभिव्यक्ति करने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीयता स्वतन्त्रता प्राप्ति के अपने प्रयास में सफल हो गई किन्तु यह सफलता उस देश के विभाजन के बाद मिली।

टर्की में मुस्तफा कमालपाशा या अतातुर्क का वहाँ का हीरो माना जाता है। उसने टर्की में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। उसका मूल उद्देश्य साम्राज्यवाद का निर्माण करना अथवा विस्तारवादी नीतियों पर चलना नहीं था बल्कि वह तो टर्की के भीतर राष्ट्रवाद का प्रसार करना चाहता था। “तुर्की के लिये तुर्की” (Turkey for the Turks) यह उनका एक प्रसिद्ध नारा था।

सारारा यह है कि एशिया के प्रायः सभी देशों में अब राष्ट्रवाद का प्रसार हो चुका है। इस महाद्वीप का राष्ट्रवाद पश्चिमी देशों के राष्ट्रवाद से कुछ अर्थों में भिन्न रहा है। एशिया में पश्चिमी राष्ट्रवाद को इस प्रकार अपनाया गया कि वह वहाँ की परम्पराओं तथा रीति रिवाजों का विरोध न करे। एशिया में राष्ट्रवाद का रूप मुख्य रूप से निषेधात्मक रहा है। यहाँ इसका लक्ष्य विदेशी शासन को हटाना था। इसमें धर्म, भाषा, अक्षिधा, गरीबी, अन्ध विश्वास, स्थानीयता आदि के भेदभावों के होते हुये भी एकता प्राप्ति का प्रयास किया गया है। पारवात्य राष्ट्रवाद में साम्राज्यवाद, जातिवाद तथा युद्ध की प्रवृत्तियाँ पाई जाती थीं किन्तु एशिया महाद्वीप में राष्ट्रवाद

ने इन सभी प्रवृत्तियों को छोड़ दिया। एशिया में राष्ट्रीयता की भावना को न केवल राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिये ही प्रयुक्त किया गया बल्कि इसका प्रयोग आर्थिक तथा सामाजिक सुधार आन्दोलनों में भी किया गया। एशिया के राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीयवाद, शान्ति, सहयोग एवं मानवता का सहायक है। जवाहरलाल नेहरू का विचार था कि अन्तर्राष्ट्रीयवाद प्रभावपूर्ण रूप से केवल तभी विकसित हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद ने उन देशों में अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हों जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं। पण्डित नेहरू का यह विचार था कि राष्ट्रवाद का प्रत्येक देश में स्थान है तथा इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए किन्तु यह आत्मपणकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास में बाधक नहीं बने।

एशिया में साम्यवाद—राष्ट्रवाद की भावना के बाद एशिया के देशों पर जिस अन्य तत्व का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वह है साम्यवाद। एशिया के देशों में व्याप्त गरीबी, अज्ञानता, भुखमरी, बीमारी, ओद्योगिक पिछड़ाव तथा अन्य ऐसी ही समस्याएँ साम्यवाद के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती हैं। एशिया महाद्वीप पर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने की मासका इस कारण भी है कि इस विचारधारा का प्रधान केन्द्र तथा शक्ति का स्रोत मास्को है। यद्यपि यह योरोप का एक भाग है किन्तु एशिया से भी दूर नहीं है। इसको अर्ध-योरोपियन तथा अर्ध-एशियन स्वीकार किया जाता है। इस के अतिरिक्त साम्यवाद का दूसरा बड़ा गढ़ साम्यवादी चीन है। यह देश तो पूरी तरह से एशिया महाद्वीप में स्थित है। एक ओर तो साम्यवादी विचारधारा के विस्तार की इतनी सुविधा है कि इसके प्रचारक इसी क्षेत्र में हैं साथ ही यहाँ की समस्याएँ एवं वातावरण भी अनुकूल ही हैं और दूसरी ओर साम्यवाद का विरोध करने वाली शक्तियाँ एशिया से दूर पड़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त इनके साथ एशिया के देशों का अतीत अनुभव अधिक अच्छा नहीं है। इस प्रकार विधेयात्मक एवं नियेष्ठात्मक दोनों ही दृष्टियों से एशिया में साम्यवाद के प्रसार का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता है। एशिया के अधिकांश देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों में साम्यवादी दल द्वारा सत्रिय सहयोग प्रदान किया गया था।

एशिया में साम्यवादी चीन ने विस्तारवादी नीति को अपनाया तथा साम्यवाद के प्रचार की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए बड़े जोर-शोर से वह एशिया के देशों को लाल रंग में रंगने लग गया है। चालू, चालाकी या युद्ध किसी भी साधन द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह तैयार हो गया। उसका विचार है कि पूँजीवाद को समाप्त करने के शुभ लक्ष्य में यदि

युद्ध भी करना पड़े तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि चीन की जनसंख्या इतनी अधिक है कि युद्ध में सत्तार के समान हो जाने के बाद भी जो लोग बचेंगे वे साम्यवादी चीन के ही नागरिक होंगे। उस समय सारे संसार पर लाल झण्डा फहराया जायेगा। इस प्रकार क कथनों तथा उन पर किए गए व्यवहारों को देख कर पश्चिमी राष्ट्र चिन्तित हो गये हैं। अब उनकी समझ में आ गया है कि उनका प्रमुख शत्रु साम्यवाद रूस नहीं बल्कि साम्यवादी चीन है अब चीन की घरेबन्दों की जाने लगी। अमरीका ने दक्षिण कोरिया, फारमोसा तथा फिलीपाइन देशों के माध्यम से जापान से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक सैनिक अड्डे तथा सैनिक सन्धियों द्वारा घेराबन्दी डाल दी और चीन की प्रसारवादी नीतियों को रोका। संयुक्त राज्य अमरीका ने अभी तक चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता नहीं दी है। वह राष्ट्रवादी सरकार को चीन का वास्तविक शासन मान रहा है और इसी कारण वह संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य है।

साम्यवादी शक्तियों द्वारा लाओस, तिब्बत तथा भारत के विरुद्ध जो कदम उठाए गए उनका पश्चिमी देशों ने दृढ़ता के साथ विरोध किया। इसी प्रकार पश्चिमी शक्तियों द्वारा जापान, इण्डोनेशिया, लाओस तथा फारमोसा में जो किया गया, साम्यवादियों द्वारा उसका घोर विरोध किया गया। कोरिया का युद्ध साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी शक्तियों के बीच की लड़ाई का प्रमुख उदाहरण था। किन्तु इन दोनों शक्तियों के बीच वियतनाम में होने वाले सशस्त्र संघर्ष ने उन यादों को फिर से ताजा कर दिया कि विश्व के दो गुटों की तरह एशिया में अपने स्वयं के दो गुट नहीं हैं। इस महाद्वीप में साम्यवादी गुट तो इसी क्षेत्र का है किन्तु साम्यवाद का विरोध करने वाली शक्तियाँ इस महाद्वीप की स्वयं की नहीं हैं। पश्चिमी देशों द्वारा एशिया के देशों के हितों को उकसा कर उन्हें साम्यवाद का विरोध करने का साधन बनाया गया है। विश्व-प्राप्ति शीत युद्ध का प्रभाव एशिया महाद्वीप को भी सहन करना पड़ा है और अब जबकि संसार शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व की नीतियों में विश्वास करने लगा है, एशिया में स्थित शीत युद्ध ने कई बार गर्म युद्ध का रूप धारण कर लिया है। साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी शक्तियों के बीच एशिया की भूमि पर अब एशिया के देशों के सन्धिय सहायोग द्वारा विश्व-शान्ति को अंग करने वाली विभिन्न समस्याएँ आज विशेष चिन्ता की विषय हैं।

एशिया में असलग्नता — एशिया महाद्वीप बवल पूँजीवादी और साम्यवादी गुटों से ही प्रभावित नहीं है बल्कि वहाँ असलग्नता (Non alignment) की विचारधारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान लिये है। यहाँ के अनेक देश असलग्नता की विश्व नीति में विश्वास रखते हैं जिनमें भारत का सर्वोपदि

स्थान है। कोलम्बो शक्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली यह देश अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैद्धान्तिक स्थिति के कारण अपनी आवाज प्रभुत्व पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्य विश्व सम्मेलनों में भारतीय नेताओं ने सदा ही एशिया की एकता के लिये कार्य किया है और यहां के लोगों के हितों के अनुरूप अपना दृष्टिकोण अपनाया है। असलमेंता की नीति के सम्बन्ध में अगले एक अध्याय में विस्तार से विचार प्रकट किया गया है और भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की इस नीति की बसोटी पर परखा गया है। अतः यहां विस्तार में न जाकर इतना ही लिखना पर्याप्त है कि एशिया और अफ्रीका में असलग्न विदेश नीति के समर्थक राष्ट्रों का अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व है और वे विश्व के पूँजीवादी व साम्यवादी खेमों में सतुलनकारी भूमिका अदा कर रहे हैं। असलग्न राष्ट्र अपना कोई गुट बनाकर संसार में एक तृतीय शक्ति के रूप में उदित होने का लक्ष्य नहीं रखते, वे उनका ध्येय यह है कि वे किसी भी राष्ट्र विशेष या गुट विशेष से न बंधकर अपनी स्वतंत्र नीति पर चलते हुए अपनी इच्छानुसार अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की गुटबन्दी को वे अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। किन्तु असलग्नों की यह नीति निष्क्रियता की नीति नहीं है। यह एक सक्रिय और प्रभावशाली नीति है जो न्याय का पक्ष लेने से नहीं बचती और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह से पीछे नहीं हटती। एशिया के प्रमुख राष्ट्रों में जागरण और उनके द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति

इस दृष्टिकोण के उपरान्त अब हमें सांकेतिक रूप में यह भी परिचय देना चाहिये कि एशिया के प्रमुख राष्ट्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चंगुल से कब और कैसे मुक्त हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में उनका वर्तमान दृष्टिकोण क्या है। अध्ययन की दृष्टि से हम एशिया को चार भागों में बांट सकते हैं और उनमें सम्मिलित प्रमुख-प्रमुख राष्ट्रों को ले सकते हैं। ये भाग और प्रमुख राष्ट्र इस प्रकार हैं—

- (i) पूर्वी एशिया—चीन, जापान ।
- (ii) दक्षिण एशिया—भारत, पाकिस्तान, लद्दाख ।
- (iii) दक्षिण पूर्वी एशिया—दर्मा, इण्डोनेशिया, हिन्द-चीन, मलाया, फिलीपाइन्स, थाईलैण्ड ।
- (iv) पश्चिम एशिया—अफगानिस्तान, अरब राष्ट्र, इजरायल, टर्की, साइप्रस ।

पूर्वी एशिया (चीन एवं जापान)—पूर्वी एशिया में चीन और जापान सबसे प्रमुख राष्ट्र हैं। १९४९ से पूर्व वेबल राष्ट्रवादी चीन का अस्तित्व था,

किन्तु चीन के लम्बे गृह-युद्ध में चांगकाई शेक के राष्ट्रवादी दल को पराजित होना पड़ा और साम्यवादी नेता माओत्से-तुंग को न्यायिक विजय मिली। सोवियत संघ की अपेक्षा और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रबल विरोध के बावजूद लगभग २२ वर्ष के निरन्तर संघर्ष के बाद साम्यवादियों ने चीन में अपने राज्य की स्थापना करली। चांगकाई शेक ने भागकर फारमूसा द्वीप में शरण ली और वहाँ चीन की 'निर्वासित सरकार' की स्थापना करली जिसे आज भी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्रसंघ की वास्तविक सरकार माने हुए है।

चीन की साम्यवादी प्रान्ति ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर दिया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऐसा देश जो कुछ समय पूर्व तक साम्राज्यवादी लिप्सा, दमन, अत्याचार और शोषण का शिकार बना हुआ था, आज स्वयं एक क्रूर साम्यवाद का बाग पहरित कर अपने मित्रों और शत्रुओं को समान रूप से धमका रहा है, युद्ध का नारा ध्वलन्द कर रहा है और आज के आणविक युग में भी युद्ध को मनुष्य जाति के बन्धन का एक मान्य साधन बता रहा है। चीन की साम्यवादी प्रान्ति ने एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी शक्तियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है किन्तु साथ ही चीन की विस्तारवादी आकांक्षा ने कमजोर अथवा एशियाई राष्ट्रों में आतंक भी पैदा कर दिया है और उन्हें भय बता रहा है कि कहीं वे चीन के हाथों न चूड़ जाय। चीन ने युद्ध और हिंसा, लम्बे संघर्ष, साम्यवादी प्रचार, सैनिक सहायता कार्यक्रम और दौंगपूर्ण सह-अस्तित्व को अपनी विदेश नीति के साधन माना है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन अपनी विदेश नीति के इतने आधारभूत लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्राणपण से सचेष्ट है --

(१) सम्पूर्ण एशिया में साम्यवाद का प्रसार आज के इसी ढंग का नहीं हो, बल्कि विशुद्ध मार्क्सवाद लेनिनवाद ढंग का शुद्ध साम्यवाद हो।

(२) हिंसा, छल बल और कौशल द्वारा साम्यवादी चीन की सीमाओं का अधिकाधिक विस्तार किया जाय।

(३) एशिया के समस्त देशों पर प्रभावशाली राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक नियन्त्रण स्थापित किया जाय।

(४) सम्पूर्ण एशिया और सुदूर पूर्व में पश्चिम के विशेषकर अमेरिका के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाय ताकि उसकी (चीन की) सैनिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े।

(५) एशिया ही नहीं अपितु समस्त विश्व का एक छत्र साम्यवादी नेता बनने की दिशा में हर उपाय से आगे बढ़ा जाय चाहे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों व जाति से हो संघर्ष क्यों न मोल लेना पड़े।

(६) रोना की आधुनिकतम और आणविक शास्त्राचारों तथा सैनिक उपकरणों से सुसज्जित करके और चीन की राष्ट्रीय शक्ति का सैनिक आधार पर पूर्ण गठन करके उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त किया जाय ।

— चीन के अन्तर्राष्ट्रीय और वैदेशिक दृष्टिकोण का ज्वलन्त प्रमाण उसका भारत जैसे निष्पट मित्र पर किया गया, निर्लज्ज आक्रमण है । वास्तव में यह एशिया का दुर्भाग्य है कि चीन और भारत जैसे दो महान् राष्ट्र परस्पर सलवारें खींचे हुए हैं । चीन ऐसी नीति पर चल रहा है जो न केवल एशिया के लिए ही घातक है बल्कि स्वयं चीन के लिए भी आत्म-घातक है और विश्व शान्ति को पलीता लगाने वाली है ।

पूर्वी एशिया में साम्यवादी चीन को छोड़कर जापान ही ऐसी प्रमुख शक्ति है जो अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करने में सक्षम है । इस छोटे से एशियायी देश में उत्थान और पतन का इतिहास खूब बड़ा है । इस देश ने १९वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में न केवल सैनिक शक्ति और राजनीति के क्षेत्र में पश्चिम की अजेयता के दावे की घृज्जियाँ उड़ा दी थी, बल्कि सम्पूर्ण यूरोप को जचड़ी तरह बता दिया था कि पूर्व (East) निष्प्राप नहीं है, इसमें साहस, शौर्य, धैर्य, दूर-दक्षिता, लगन और धमता है । १९वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में आक्रमणकारी राष्ट्र के रूप में जापान ने साम्राज्यवादी शराब का स्वाद चख लिया । जापान निरन्तर शक्तिशाली होता गया । १९३२ से ही जापान की शासन सत्ता सैनिकवादियों के हाथ में आ गई और वह चीन जैसे विशाल भू-खण्ड पर अपना अधिकार करने तथा समस्त एशिया महाद्वीप का एकदम शासक बनने का स्वप्न देखने लगा । चीन पर जोर शोर से हमले हुए, किन्तु मित्र राष्ट्रों, विशेषकर अमेरिका द्वारा चीन की आर्थिक और सैनिक सहायता करने के कारण जापान अपने दुरादे में सफल नहीं हो सका । द्वितीय महायुद्ध में जापान ने चारों ओर अपनी विजयों की धूम मचा दी, पर अन्त में अणु बमों की प्रलयकारी शक्ति के सामने घुटने टेकते हुए दो सितम्बर, १९४५ को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्म समर्पण की अन्तिम शर्तों पर हथ्या-हार कर दिये ।

आत्म-समर्पण करने के बाद जापान पूरी तरह 'पश्चिम के', विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे में आ गया । जापान की गृह और विदेश नीति पर वैदिक दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण किन्तु व्यावहारिक रूप में अमेरिकन नियन्त्रण स्थापित हो गया । अमेरिकन सैनिक शासन के आधीनत्व बाल में ही जापानी सम्राट की निरंकुश सत्ता समाप्त हो गई, जापानी सम्राट् वैधानिक शासक मात्र रह गया और मई, १९४७ में जापानी जनता

ने एव नया संविधान स्वीकार कर लिया। जापान में उत्तरदायी प्रति-
निध्यात्मक सरकार की स्थापना की गई। जापान अपनी दीन-हीन व्यवस्था
से ऊपर उठने की जी तोड़ कोशिश करने लगा जापान का शासन
अमेरिका के लिए अत्यधिक व्ययसाध्य हो गया और हमरी ओर एशिया
में साम्यवाद के प्रसार के साथ साथ जापानी छात्रों और भूमिकों
में भी साम्यवाद फैलने लगा। इन सभी घटना चक्रों से प्रभावित होकर
अमेरिका ने यही उचित समझा कि जापान को पुनः स्वतन्त्रता और सम्मानपूर्ण
स्तर प्रदान किया जाय ताकि वह पुनस्त्यान की दिशा में अग्रसर होकर पूर्वी
और दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवाद के प्रभाव का मुकाबला कर सके। यह
निश्चय करने के बाद अमेरिकन प्रशासन ने जापान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का
स्तर प्रदान करने की नीति पर विशेष सख्तिगता से चयना शुरू कर दिया।
१९५२ में शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद जापान पुनः स्वतन्त्र हो
गया। अपनी स्वाधीनता के उपरान्त जापान तेजी से प्रगति पथ पर बढ़ता
गया और आज स्थिति यह है कि एशिया का यह छोटासा राष्ट्र विश्व की
आर्थिक शक्तियों में अपना एक विशेष स्थान बना चुका है। अब जापान यह
सोचने लगा है कि बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को सुरक्षित करने के लिये उसके
पास पर्याप्त सैनिक शक्ति भी होनी चाहिये। जापान के पास साधन हैं,
तकनीक है, वेबक समय का इन्तजार है। जिस दिन पुनर्संस्त्रीकरण के
प्रतिरन्धों से मुक्त होकर जापान सम्प्रभ-मंच की होड़ में कूद पड़ेगा, उस दिन
कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पायेगी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान नष्ट-भ्रष्ट
जापान आज अमेरिका और सोवियत संघ के बाद बड़ी ताकतों में नाम लिखाने
का हकदार बन चुका है और आशा की जाती है कि शीघ्र ही वह रूस और
अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सन्नत दश बन जायेगा।

दक्षिण-एशिया (भारत, पाकिस्तान व तमिल)—दक्षिण एशिया के
राष्ट्रों में भारत, पाकिस्तान व तमिल प्रमुख हैं। पाकिस्तान एक नव निर्मित
राष्ट्र है जो अखण्ड भारत का विभाजन करके बनाया गया है। १५ अगस्त,
१९४७ से पहले अखण्ड भारत अंग्रेजों के प्रभुत्व में था। भारत में विदेशी
हुकूमत व शोषण एक लम्बा स्वातन्त्र्य संघर्ष चला। इन स्वाधीनता संघर्षों
की परिणति देश के विभाजन में हुई। १५ अगस्त, १९४७ को अखण्ड भारत
को दो नये राष्ट्र, पाकिस्तान और भारत में विभाजित करके अंग्रेज विदा
हूए।

अपनी दासता से मुक्त होने के बाद नये भारत ने स्वतन्त्र राष्ट्रों की
मण्डली में प्रवेश किया और उसे अपनी आन्तरिक तथा विदेश नीति के

निर्धारण का पूरा पूरा अधिकार मिला। भारत ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और विदेश नीति की रूप रेखा का निर्धारण तो स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही कर लिया था, लेकिन इस पर नियामक रूप से चलने का अवसर स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भारत ने अपने निम्नलिखित आदर्श निर्धारित किये—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुशांति के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाये जाने की नीति को प्रत्येक सम्भव तरीके से प्रोत्साहन देना।

(३) सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना।

(४) अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के परस्परिक सम्बन्धों में सन्धियों के पालन के प्रति आस्था बनाये रखना।

(५) सैनिक गुट-बन्धियों और सैनिक समझौतों से अपने आपको मुक्त रखना तथा ऐसी गुटबन्दी को निरुत्साही करना।

(६) उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध करना।

(७) प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साही करना।

(८) उन देशों की जनता की सश्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हों।

अपने इन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय आदर्शों और राष्ट्रीय हितों में परस्पर मेल बँटाते हुए भारत ने विदेश नीति का निर्धारण किया। सह-अस्तित्व और साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हुए भारत ने असलगन्ता और नान्तिवाद की नीति पर चलना ही श्रेयस्कर समझा। भारत की असलगन्ता की नीति (Policy of Non-alignment) के महत्व और उसकी प्रभावशीलता का विवेचन "असलगन्ता" (Non-alignment) के अगले अध्याय में विस्तार से किया गया है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि भारत ने एशिया के जागरण में विशेष और सबसे प्रभावशाली भूमिका अदा की है। भारत की प्रेरणा से अनेक एशियाई और अफ्रीकन राष्ट्रों के स्वाधीनता आन्दोलनों को बल मिला है। स्वतन्त्र भारत का इतिहास बताता है कि इस महान् देश ने इण्डोनेशिया, मलाया, लीबिया, ट्यूनीशिया, मोल्डोविया, साईप्रस, अल्जीरिया आदि राष्ट्रों को स्वतन्त्रता प्राप्ति में जितना सहयोग दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने इतने सक्रिय रूप से भाग लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को मुलकाने में इतने उत्साह से अपना सहयोग दिया कि यह कहना आम्र है कि वह विश्व राजनीति में प्रयत्न करने की नीति पर चल रहा है। भारत की असलगतता एक विधेयात्मक, सभिय और रचनात्मक नीति है। भारत की विचारधारा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में पश्चिमी तथा साम्यवादी गुटों के बीच है। अतः यह आवश्यक और स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में वह दोनों के बीच के मार्ग का ही अवलम्बन करे। भारत साम्यवाद की समानता, वर्ग-भेद की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा, शोषण का अन्त आदि धारणाओं से सहमत है किन्तु उसमें पाई जाने वाली असहिष्णुता, हिंसा, स्वतन्त्रता के अभाव, दमन आदि दोषों को घृणित दृष्टि से देखता है। एशिया में भारत प्रजातन्त्र का गढ़ है जिसके उत्थान और पतन पर न केवल एशिया के वरन् विश्व के प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर है। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान और चीन जैसे दो पड़ोसी राज्य भारत की सद्भावना और मैत्रीपूर्ण नीति को दुर्बलता का चिन्ह माने हुए हैं और भारत को दबाकर उसके क्षेत्र हड़पने की नीति अपनाये हुए हैं। हमें आशा करनी चाहिये कि अन्ततोगत्वा ये दोनों राष्ट्र एशिया और विश्व में इस महान् प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के स्तम्भ की भूमिका का आदर करेंगे और उसके प्रति सहयोग का हाथ बढ़ावेंगे।

भारत उपमहाद्वीप के विभाजन की कीमत पर जिस पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वह भी एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर दो भू भागों को मिलाकर बनाया गया—एक पश्चिमी पाकिस्तान जिसमें पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त, बिलूचिस्तान तथा कुछ देशी रियासतें हैं और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान जिसमें बंगाल का पूर्वी भाग तथा आसाम का कुछ भाग सम्मिलित है। अपने जन्म के शीघ्र बाद ही अर्थात् १९४७-४८ में पाकिस्तान को संयुक्त राज्य संघ की सदस्यता प्राप्त हो गई। प्रारम्भ में पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में स्वतन्त्र नीति का अनुसरण किया और वह किसी देश अथवा गुट विशेष की ओर नहीं झुका। लेकिन भारत के प्रति जन्मजात वैमनस्य और शत्रुता की भावना शीघ्र ही इतनी प्रबल हो गई कि उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और परराष्ट्र नीति का मूल उद्देश्य ही यह बन गया कि भारत के विरुद्ध मित्रों की खोज की जाए और सैनिक बल पर भारत को दबाया जाए तथा उससे अनुचित रियासतें प्राप्त की जाएँ व उसके क्षेत्रों पर अनुचित रूप से कब्जा जमाया जाए।

भारत विरोध की उग्र भावना के कारण पाकिस्तान ने तटस्थता की नीति को तिलाजलि देकर स्वयं को 'एक हो दिया में' मोड़ दिया। एशिया के

इस महत्वपूर्ण राष्ट्र ने पश्चिमी देशों के साथ मैनिंग गठबंधन में बन्ध जाने का निर्णय किया ताकि उसके दो उद्देश्य — भारत को नीचा दिखाना और इस्लामी जगत का नेतृत्व करना — पूरी पूर्ति हो सके। पश्चिम, विशेषकर अमेरिका के साथ सैनिक दृष्टि से आवद्ध हो जाने के मूल में साम्यवाद का होना दिखाया गया, लेकिन इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस नीति का वास्तविक कारण पाकिस्तान का साम्यवाद के प्रति भय या विरोध न कभी था और न है। भारत चीन के मध्य सीमा प्रश्न को लेकर मुड़ खड़े और पाकिस्तान द्वारा चीन के साथ साठसाठ करने से यह तथ्य भली प्रकार स्पष्ट है।

यह हमारा लक्ष्य पाकिस्तान की विदेश नीति की भीमामा करना नहीं है, लेकिन उसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण और वैदेशिक नीति सम्बन्धी दृष्टिकोण को मोटे रूप में इस तरह प्रस्तुत करना है कि जिससे एशिया के नव-जागरण में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट हो सके। एशिया का नव-जागरण यह मान करता है कि एशिया के राष्ट्र आपस में एकता के सूत्र में बँधें और एकजुट होकर अपना आर्थिक व सामाजिक उत्थान इस तरह करें कि वे विश्व की अन्य शक्तियों के समक्ष खड़े हो सकें, लेकिन दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन और पाकिस्तान के रूप में एशिया की इन आशाओं को विशेष बाधात लगा है और यह भी कम दुःखपूर्ण बात नहीं है कि अरब राष्ट्र भी भारत में घुरी तरह फूट के चिकार हो। पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्यतः भारत के साथ विरोध पर आधारित है। उसकी विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य सदा ये ही रहे हैं—

(१) भारत के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होकर काश्मीर समस्या को अपने अनुकूल हल कराने के लिये भारत को बाध्य करना,

(२) सैनिक दृष्टि से अपने को इतना सबल बनाना कि भारत किसी भी हालत में उससे सैनिक दृष्टि से श्रेष्ठ न होने पावे,

(३) भारत के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करना,

(४) पश्चिम समर्थक अरब इस्लामी राज्यों को धरने साथ मिलाकर अरब राष्ट्रीयता के अग्रदूत और एशियाई एकता के समर्थक मिथ के राष्ट्रपति नासिर के नेतृत्व को घुनीती देना तथा पाकिस्तानी खडे के नीचे एक इस्लामी जगत का निर्माण करना,

(५) पश्चिमी देशों और अन्य देशों के साथ सैनिक गठबंधनों से बँधकर भारत को जाचकिन करना।

एशिया के लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत को अपना प्रमुख शत्रु मानना पाकिस्तान की विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक आधार-

भूत अंग है जिसके लिये आवश्यकता पटने पर वह न मित्रों को बदलने में सकोच करता है और न किसी भी गुट से गठजघन करने में उसे कोई हिचक होती है। पाकिस्तान के रबंये का यह एक अनिवार्य परिणाम है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूरी तरह शीतयुद्ध का ज्वाला बन चुका है। यदि एशिया को आगे बढ़ना है और विश्व राजनीति में पाश्चात्य शक्ति जैसा साम्यवादी, रूस के समक्ष निर्वल स्थिति में नहीं रहना है तो यह आनन्दपक है कि पाकिस्तान और भारत जने दो महान् एशियाई राष्ट्र आपस में सद्भावना और मैत्री का परिचय द तथा चीन अपने को एक पृथक् ज़ानि का राष्ट्र न मानकर एशिया का एक अंग समझते हुए अपनी विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का परित्याग करे।

दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्र श्री लंका है जो भारत के दक्षिणी धलविन्दु के समीप एक छोटे आकार का द्वीप है और भारत के साथ सांस्कृतिक आधारों पर अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। हिन्द महासागर में भारत की समीपता के कारण इसका सैनिक महत्व बहुत पहले से ही स्वीकार किया जाता रहा है। सामरिक महत्व का ठिकाना होने से भारतीय महाद्वीप पर अधिकार करने वाली अथवा आक्रमण करने वाली किसी भी महावाक्शी शक्ति की मुछ दृष्टि से यह द्वीप अलोल में नहीं बच पाया। बाहरी देशों के आक्रमण का शिकार बनते बनते अत में यह ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में इसका पूर्ण शोषण हुआ, क्योंकि ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति यहां भी वैसे ही थी जैसी कि अन्य देशों में। फिर भी यहां की राजनीति व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, शासन व्यवस्था की कुशल परम्परा आदि ने महा स्वशासन का वातावरण बना दिया और प्रथम महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन के १४ मूत्रीय सिद्धन्त तथा भारत की राष्ट्रीयता की लहर ने महा राष्ट्रीय आन्दोलन का बीजारोपण कर दिया। भारत की ही भांति लंका में भी गवैधानिक और सुधारवादी आन्दोलन जोर पकड़ता गया। १९१९ में श्री लंका में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई जिसके नेतृत्व में स्वाधीनता सघर्ष चलने लगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति तक विभिन्न सवैधानिक सुधार किये गये, लेकिन श्री लंका का जनमत तो आने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिये बेताब था। अत में १३ नवम्बर, १९४७ को ब्रिटिश संसद में श्रीलंका की स्वतन्त्रता प्रदान करने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया और लगभग १३३ वर्षों के अंग्रेजी राज्य के उपरान्त श्रीलंका ने अपनी छोई हुई स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त कर ली। ४ फरवरी, १९४८ को ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे पूर्ण 'डोमिनियन स्टेटस' प्रदान कर दिया गया। जुलाई १९५६ में श्री लंका

हमारे समय की ज़रूरतों हुई प्रवृत्तियाँ

ने राष्ट्रमण्डल में एक गणराज्य के रूप में शामिल होने की इच्छा प्रकट की और ब्रिटिश सरकार द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

अपनी राजनीतिक परिस्थितियों, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक विकास की आवश्यकता के कारण दक्षिण एशिया के इस महत्वपूर्ण राष्ट्र ने प्रारम्भ से ही तटस्थतावादी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण ग्रहण किया और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में अपनी आस्था प्रकट की। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा विदेशनीति के क्षेत्र में थोल्का के ये प्रमुख तथ्य निर्धारित किये गये—

(i) थोल्का की नवजात स्वतन्त्रता की रक्षा,

(ii) एक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य के रूप में राष्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार करना,

(iii) दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी देशों, विशेषकर भारत से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना,

(iv) औपचारिक रूप से किसी शक्ति युद्ध के साथ सम्बद्ध न होना और शीतयुद्ध से अलग रहना, एवम्

(v) मित्र देशों के साथ सहयोग करने हुए शांति और आर्थिक विकास के लिये प्रयत्नशील रहना।

यह एक उत्साहजनक बात है कि थोल्का न एशिया और अफ्रीका के देशों के प्रति सदैव सहयोग भावना रखी है और साम्यवाद, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया है। इस देश के नेताओं द्वारा सभी की स्वाधीनता और व्यापक मार्गों को हमेशा समर्थन दिया जाता रहा है। एशिया व्यक्तिगत विकास में थोल्का की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

दक्षिण पूर्वी एशिया (बर्मा, इण्डोनेशिया, हिंद चीन, मलाया, फिलिपाइन्स, थाइलैंड) — अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विश्व शांति के दृष्टिकोण से दक्षिण पूर्वी एशिया संसार के सर्वाधिक विस्फोटक और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। एशिया का साम्राज्यवाद के निरुद्ध विरोध वही भी इतना स्पष्ट और सफ़ल न रहा जितना दक्षिण पूर्वी एशिया में। २०वीं शताब्दी के प्रारम्भ में साम्राज्यवाद के चहुँपे में फँसा हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया आज स्वतन्त्र और मुक्त होकर विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इस क्षेत्र के अधिकांश देशों का बनना कोई व्यवस्थित इतिहास नहीं रहा और न ही बहा किन्हीं ऐसी स्थायी प्रणालियों और संस्थाओं का विकास हो पाया जिन पर शक्ति प्राप्त करने और पथ प्रदर्शन के लिये निर्भर रहा जा सके, लेकिन भारत से उठने वाली स्वतन्त्रता की लहर बर्मा होती हुई दक्षिण पूर्वी

एशिया के अन्य राज्यों की सीमाओं से टकराई और तब ओपनिवेशिक शासकों की स्वेच्छा से अथवा रक्त-रजित सघर्ष के उपरान्त विवश होकर इस क्षेत्र से अपना बोरिया बिस्तार लादना पड़ा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त इस क्षेत्र के अधिकांश देशों को इस बात का कोई स्पष्ट अभास नहीं था कि भविष्य के लिये उन्हें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिये और कौन सी प्रणाली उनके लिये उन्मुख होगी ? स्वतन्त्रता इन देशों की अवस्था मिल गई, पर उस स्वतन्त्रता की सुरक्षित व सुदृढ़ करने तथा उसे आधार बनाकर शक्तिशाली और प्रगतिशील राष्ट्र बनने के लिये उचित पथ-प्रदर्शन और साधन उन्हें नहीं मिल सके। पोरणाम यह हुआ कि आज भी अधिकांश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश विभिन्न विचारधाराओं, प्रणालियों और गुट बन्धियों के सिक्कार बने हुए हैं तथा विश्व की महा-शक्तियाँ उन्हें अपने हाथों का खिलौना बनाए हुए हैं।

यह कहना अनिश्चयितपूर्ण न होगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय युग में सघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और सम्बन्धों में इस क्षेत्र का प्रधान महत्त्व दो कारणों से है—(i) आर्थिक दृष्टि से, एवं (ii) सामरिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र अनेक ऐसे बच्चे मालों का प्रधान उत्पादन है जिनकी वैश्वीय ससार में अत्यधिक मांग है। सामरिक दृष्टि अथवा युद्ध नीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व के प्रधान वायु और समुद्री मार्गों पर स्थित है तथा साम्यवादी चीन व समुन्नत राज्य अमेरिका के मध्य सघर्ष का प्रधान केंद्र है। चूंकि शीतयुद्ध के समय में इस प्रदेश के अधिकांश राज्यों ने एक तत्पक्षनायी नीति अपनाई है, अतः दोनों ही गुटों की दृष्टि से इसका विशेष महत्त्व है।

दक्षिण पूर्वी एशिया के देश जान जाग उठे हैं और विद्वत्मानों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भाग ले रहे हैं। इनमें मुख्य राष्ट्रों का सांकेतिक परिचय जान लेना उन्मुख होगा—

भारत की पूर्वी सरहद पर स्थित बर्मा एन प्रमुख दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्य है। बौद्ध धर्माभ्यासियों के इस देश पर १९१२ में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया। यह प्रभुत्व बढ़ता गया और १८८५ से १९२७ तक बर्मा का सामन ब्रिटिश अधीनस्थ भारत के एन अग के रूप में हो रहा। १ अप्रैल, १९२७ से इसे भारत से पृथक् कर दिया गया और इसके लिये एक अलग प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था की गई। द्वितीय महायुद्ध काल में कुछ समय यह जापानियों के अधिकार में रहा। महायुद्ध समाप्त होने पर पहा पुन ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। लेकिन बर्मा जनता के पटले से चले

आ रहे राष्ट्रवादी आन्दोलन ने अतः मे ब्रिटिश सरकार को विवश कर दिया कि वह बर्मा को स्वाधीन कर दे। ४ जनवरी, १९४८ को बर्मा ने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की और इस प्रकार वर्तमान बर्मा संघ (Union of Burmas) अस्तित्व में आया। बर्मा ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति-के क्षेत्र में अमलगत तथा छातिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति पर चलना शुरू किया। भारत के ही समान एशियाई व्यक्तित्व के विकास में बर्मा की यह नीति आज भी सक्रिय है। बर्मा आज भी सैनिक गठबन्धनों से दूर है और एशिया की स्वाधीनता का समर्थक है। दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन बर्मा के साथ भी अपनी छेड़छानियों से बाज नहीं आता।

दक्षिण पूर्वी एशिया में थाइलैण्ड भी एक महत्वपूर्ण देश है जिसका नाम पहले स्याम था। थाइलैण्ड ने दो साम्राज्यवादी राष्ट्रों बर्मा और मलाया में ब्रिटेन तथा हिन्द चीन फ्रांस के मध्य एक बफर स्टेट के रूप में काम किया। यद्यपि यह देश अपनी स्वाधीनता को सुरक्षित रखने में सफल रहा, लेकिन फिर भी इसे अपनी भूमि के कुछ महत्वपूर्ण भाग फ्रांस और ब्रिटेन को देने पड़े। आर्थिक अपनुकून के कारण यहां के राजनैतिक जीवन में मदा जल-नुशल होती रही। द्वितीय महायुद्ध के दौरान प्रारम्भ में थाइलैण्ड ने पूरी राष्ट्रों का पक्ष निभाया, किन्तु बाद में वह मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद थाइलैण्ड ने अमेरिका से गहरी आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त की क्योंकि उसे साम्यवादी खतरा पैदा हो गया। आज भी थाई-देश दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेरिका के सर्वाधिक विद्यमान सहचर राष्ट्रों में से है। चूंकि थाई-देश में साम्यवादी छापाकारों की ताड़ फोड़ की कार्यशालियाँ तेजी से जारी हैं, अतः अमेरिका की आर्थिक और सैनिक सहायता निरन्तर बढ़ती जा रही है। यदि परिस्थितियों में सुधार न हुआ तो यह आशंका करना निर्मूल न होगा कि थाई देश में अमेरिका की एक दूसरी 'विपतनाम' का सामना करना पड़ सकता है।

दक्षिण पूर्वी एशिया का एक अन्य प्रमुख देश लाओस हिन्द चीन प्रायद्वीप का एक देश है। सामरिक दृष्टि से इस क्षेत्र में लाओस की भौगोलिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है लाओस में तीन बड़े शक्तियाँ हैं— साम्यवादी पाथेट लाओ (Pathet Lao), राज सत्तावादी (Royalists) और तटस्थतावादी (Neutralists)। इनके आपसी संघर्ष के कारण लाओस में गृहयुद्ध की सी स्थिति बनी रहती है। लाओस पर पहले फ्रांस का अधिकार था, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद यह एक सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राष्ट्र बन गया। मई, १९४७ से लाओस में एक संवैधानिक राजतन्त्र की स्थापना हुई। जुलाई १९४९ में लाओस को फ्रांसीसी संघ के अन्तर्गत संघानिक रूप से

स्वतन्त्र देश बना दिया गया। लेकिन साम्यवादी दल ने इस व्यवस्था को मानने से इन्कार कर दिया और सहस्त्र गृह-युद्ध शुरू हो गये। अन्त में ३१ जुलाई, १९५४ को जेनेवा में हुए सम्मेलन के अन्तर्गत लाओस राज्य की सर्वोच्च प्रभुत्व सम्पन्न स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान कर दी गयी। पूर्ण स्वतन्त्रता के बाद भी लाओस का आन्तरिक संपर्क अभी तक बिटा नहीं है। वियतनाम में वियतनाम की तरह महा पर साम्यवादियों के नेतृत्व में पापेट लाओ दल की सैनिक सफलता से समुन्नत राज्य अमेरिका पूरी तरह चिन्तित है। लाओस की स्थिति भी निकट भविष्य में वियतनाम जैसी ही हो जाए ता कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमेरिका की मुख्य चिन्ता यह है कि यदि लाओस व दक्षिणी वियतनाम साम्यवादो शिकार में कस गया तो घोर-भीरे सम्पूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया ही साम्यवादी बन सकता है।

दक्षिण पूर्वी एशिया का कम्बोडिया नामक देश लामेर सम्राटों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। १३ वीं शताब्दी के मध्य खानेर वंश के पतन के बाद स्याम (अब थाइलैण्ड) के राजा ने कम्बोडिया पर अधिकार कर लिया। लगभग २०० वर्षों तक प्रत्यक्ष या पराक्ष रूप से कम्बोडिया स्याम की अधीनता में रहा। १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में फ्रांस ने इन्डोचीन में प्रवेश किया और कम्बोडिया ने पड़ोसियों के आक्रमणों से बचने के लिए फ्रांस का संरक्षण स्वीकार कर लिया। १८८४ में कम्बोडिया को फ्रांस द्वारा सगटिन इण्डोचीन या हिन्द चीन में शामिल कर लिया गया। फ्रांस के संरक्षण में देश की जनता पश्चिमी आधार विचारों से प्रभावित हुई और इस प्रकार कम्बोडियन राष्ट्रियता का प्रादुर्भाव हुआ। द्वितीय महायुद्ध के दौरान इन पर जापान का अधिकार हो गया। अन्तिम अवस्था में अपनी पराजय निश्चित ज्ञान कर ज्ञान ने जय हिन्द चीन को स्वतन्त्र घोषित कर दिया तो मार्च १९४५ में कम्बोडियन प्रधानमन्त्री ने अपने देश की स्वतन्त्रता घोषित कर दी। १९४७ में कम्बोडिया का एक राष्ट्रीय संविधान बनाया गया। नवम्बर १९४९ में कम्बोडियन असेम्बली ने फ्रेंच यूनियन के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में रहना स्वीकार कर लिया और अ-ज में ९ नवम्बर १९५३ का कम्बोडिया पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित हुआ। स्वतन्त्रता के बाद से ही कम्बोडियन विदेश तांडि प्रायः भारत का तरह अवगमना की हो रही है और वह पश्चिम के अतिरिक्त साम्यवादी देशों के साथ भी अच्छे सम्बन्ध रखने के लिए सचेत है।

मलाया प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया के एक छोर पर स्थित है। पहले इस क्षेत्र में अनेक मुसलमानों का वासन था जो परस्पर लड़ने रहने थे। बालान्तर में अंग्रेज लग ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से यहां आये।

धीरे धीरे सन् १९०६ तक अंग्रेजों ने इस सम्पूर्ण प्रदेश पर नियन्त्रण स्थापित कर लिया और राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से इसे तीन असमान भागों में विभाजित कर दिया। द्वितीय महायुद्ध में सिंगापुर सहित सम्पूर्ण मलाया प्रायद्वीप पर जापानियों ने कब्जा कर लिया। उनके घोषण ने मलायी राष्ट्रवाद को जगृत किया। युद्ध की समाप्ति के बाद मलाया प्रायद्वीप पुनः ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत आ गया लेकिन स्वाधीनता के लिए वहाँ का राष्ट्रवादी आन्दोलन और भी सक्रिय हो उठा। स्वाधीनता प्रेमी मलाया वासियों ने स्वाधीनता के अड्डा बना कर कोई समझौता पसन्द नहीं किया और अन्त में विद्रोह होकर ३१ अगस्त, १९५७ को मलाया संघ की स्वतन्त्रता घोषित कर दी गयी। मलाया स्वतन्त्र तो हो गया लेकिन साम्यवादी चीनी वहाँ के राजनीतिक जीवन पर छाते लगे। अतः साम्यवादी चीन की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए १९६१ में मलाया के प्रधानमंत्री श्री टू कू अब्दुल रहमान ने मलान्ग, सिंगापुर, उत्तरी बोर्नियो, ब्रुनो और सारावाक को मिलाकर 'बृहत् मलेशिया' अथवा मलेशिया संघ की स्थापना की योजना प्रस्तुत की। इण्डोनेशिया ने इस योजना का घोर विरोध किया। अन्त में अनेक विवाद बाधाओं के बाद १५ दिसम्बर १९६३ को मलेशिया संघ की स्थापना हो गयी जिसमें सिंगापुर, उत्तरी बोर्नियो और सारावाक सम्मिलित हुए। इण्डोनेशिया का विरोध जारी रहा। सोमाप्यवश १९६६ में इण्डोनेशिया और मलेशिया संघ ने सहअस्तित्व की नीति को स्वीकार कर लिया। दोनों राष्ट्रों के सम्मेलन से दक्षिणी पूर्वी एशिया के एक बड़े क्षेत्र में शांति स्थापित हो गयी।

दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य इण्डोनेशिया है जो सैकड़ों द्वीपों का एक विशाल समूह है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इसके अधिकांश भू भागों पर डच लोगों (हालैंडवासियों) का अधिकार था। महायुद्ध के दौरान इस सम्पूर्ण क्षेत्र पर जापान का अधिकार हो गया। जापान के आत्मसमर्पण के तुरन्त बाद १७ अगस्त, १९४५ को इण्डोनेशियायी जनता के एक समूह ने डा० सुकार्णो को राष्ट्रपति और जकार्ता को राजधानी बनाकर 'स्वतन्त्र इण्डोनेशियायी गणराज्य' की स्थापना की घोषणा कर दी। लेकिन एर्षों की स्थिति के लिए मित्रराष्ट्रीय सेनाएँ इण्डोनेशियायी भू क्षेत्र में उतर आयीं। जब इण्डोनेशियायी जनता का राष्ट्रवाद और भी अधिक भड़क उठा तथा मित्र राष्ट्रीय ब्रिटिश सेनाओं से इण्डोनेशियायी राष्ट्रवादियों की लड़पे होने लगी। इण्डोनेशिया में डचों से मुक्ति का आन्दोलन और पकड़ता गया। इण्डोनेशियायी राष्ट्रवादियों और डच सेनाओं में निरन्तर छोटे-मोटे संघर्ष होते रहे और यह युद्ध की सी स्थिति बनी रही। आखिर

इन्डोनेशियायी राष्ट्रवाद की जीत हुई। २७ दिसम्बर, १९४९ को डचों ने इन्डोनेशिया की प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कर दी। २५ दिसम्बर, १९५० को इन्डोनेशिया संयुक्तराष्ट्रसंघ का भी सदस्य बन गया। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में स्वयं इन्डोनेशिया ने प्रारम्भ में तटस्थतावादो नीति ही अपनायी। किन्तु सान्यवादी चीन का प्रभाव बढ़ने से इन्डोनेशियायी सरकार व्यवहार में तटस्थतावादी नहीं रह सकी। चीन प्रभावित मुक्तार्थ शासन के समाप्त हो जाने के बाद जनरल सुहार्तो के नेतृत्व में गया इन्डोनेशियायी शासन पुनः तटस्थतावाद और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विश्व समस्या के प्रति अपनाने लगा है।

दक्षिण प्रशान्त महासागर में स्थित हजारों छोटे बड़े द्वीपों वाला फिलीपाइन्स लगभग ३०० वर्षों तक स्पेन के और इसके बाद लगभग ५० वर्षों तक अमेरिका के अधीन रहा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह द्वीप समूह अमेरिका के ही अधीनस्थ था। लेकिन जहाँ स्पेन ने इस प्रदेश का घोषण किया वहाँ अमेरिका न यहाँ के निवासियों की स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए तैयार किया। द्वितीय महायुद्ध में फिलीपाइन्स पर जापानियों ने अधिकार कर लिया। महायुद्ध के बाद ४ जुलाई १९४७ को अमेरिका ने फिलीपाइन्स को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। राजनीतिक मूलमूल्य और शासन काल में कुछना के कारण फिलीपाइन्स अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली भूमिका बढ़ा कर रहा है। एशिया की राजनीति में भी फिलीपाइन्स की प्रारम्भ से ही यही रुचि रही है। अपने बाहुग सम्मेलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पश्चिमी (मध्यपूर्व) एशिया

पश्चिमी एशिया अथवा मध्यपूर्व का क्षेत्र तीन महाद्वीपों का सम्मिश्र क्षेत्र है—यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसने अनेक साम्राज्यों का उत्थान पतन देखा है। इस क्षेत्र में वर्तमान में अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, जोर्डन, मित्र (संयुक्त अरब गणराज्य), इजरायल, टर्की, यमन आदि राष्ट्र हैं। यहाँ पर बहुतायत में इस्लाम धर्म है, परन्तु इजरायल में यहूदी और लेबनान में ईसाई धर्म प्रमुख है।

पश्चिमी एशिया अथवा मध्यपूर्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रथम संनिव और सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आन्तरिकारी तीन दिशाओं—तीन महाद्वीपों की ओर एक साथ अग्रसर हो सकता है। दूसरे, इस क्षेत्र की विशाल तेल सम्पदा विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों के लिए इतना प्रबल आकर्षण है कि यहाँ की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को 'तेल नीति' (Oil Diplomacy) कहा जाने लगा है। तीसरे, इस

प्रदेश में अरब का उग्र राष्ट्रवाद और यहूदियों के प्रति उनकी घोर घृणा ने इसे अन्तराष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। चौथे, प्रगतिशील और सामान्यवादी तत्वों के मध्य का संघर्ष भी यहाँ की एक प्रमुख समस्या है।

पश्चिमी एशिया अथवा मध्य पूर्व के जागरण में जिस तत्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग रहा है वह है—अरब राष्ट्रियता और यहूदीवाद से उत्पन्न विरोध। यदि हम पिछले इतिहास पर दृष्टि डालें तो पता है कि प्रथम महायुद्ध के बाद से ही मध्यपूर्व में राष्ट्रियता का उदय आरम्भ हुआ। सबसे पहले टर्की ने धार्मिक बहुदलता का परित्याग करके पश्चात्य जीवन प्रणाली और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को ग्रहण किया। अरबियों का यह राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता के लक्ष्य तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक और आर्थिक फाति का भी वाहक बना। यह राष्ट्रवाद प्रथम महायुद्ध के बाद मध्यपूर्व के देशों पर थोपी गई नयी राजनीतिक और आर्थिक पराधीनता के कारण जोर भी अधिक उग्र हो उठा। २५ दिसम्बर, १९४५ को सिक्न्दरिया में 'अरब-लीग' की स्थापना के द्वारा इस क्षेत्र के लोगों ने अपनी अरब-एकता की महत्वाकांक्षा को अभिव्यक्त किया। अरब-लीग सम्मेलन मध्यपूर्व के विकास और स्वतन्त्रता की प्रतीक बन गई।

द्वितीय महायुद्ध के बाद मध्यपूर्व के देशों में जहाँ राजनीतिक चेतना ने स्वतन्त्रता को लहर को फैलाया, वहाँ आर्थिक चेतना के फलस्वरूप उन्होंने विदेशी के आर्थिक शोषण के विरुद्ध उठ खड़े होने का संकल्प कर लिया। यह संकल्प विदेशी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के रूप में अभिव्यक्त हुआ—ईरान द्वारा तेल-उद्योग का, मिस्र द्वारा स्वेज का, और तुर्की द्वारा भी अपने तेल-उद्योग का। राजनीतिक स्वतन्त्रता का लेने के बाद अरब-राष्ट्रवाद का एक रंग अपने देशों में स्थित विदेशी फौजी अड्डों की सनाथि के रूप में प्रकट हुआ। ये फौजी अड्डे विदेशी दासता के मूर्तिमान् प्रतीक थे और इनका बना रहना राष्ट्रीय गौरव के लिए घोर कलक था, जा मिस्र और ईरान ने अपने देशों से विदेशी फौजी व सैनिक अड्डों को हटाने का प्रबल अभियान छेड़ा। जुलाई १९५८ में जब अमेरिकन व ब्रिटिश फौजें लेबनान और जोर्डन में उतरी तो मध्यपूर्व अरब जगत ने निन्दा और विरोध का एक तूफान खड़ा कर दिया और जल्द ही इन फौजों को शीघ्र ही यहाँ से हटना पड़ा।

अरब-राष्ट्रवाद का एक अन्य रूप यहूदियों के साथ अपने परराष्ट्रिक संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ। यद्यपि इस्लाम यहूदी सभ्यता बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा था, किन्तु द्वितीय महायुद्ध के बाद यहूदियों के एक पृथक् राज्य इजरायल की स्थापना हो जाने से द्वेष और संघर्ष की एक नवीन राजनीति का उदय हुआ जिसने संयुक्त अरब गणराज्य अरब-राष्ट्र का अग्रगण्य

बना। आज अरब-यूद्धों सर्वप्रथम मध्यपूर्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व बना हुआ है। यद्यपि अरब-राष्ट्रों और इजरायल के मध्य हुए विद्रोह युद्धों और जून, १९६७ के युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न तो अरब राज्य इजरायल को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं और न ही इजरायल अरब राष्ट्रों से और अधिक प्रदेश छीनने की स्थिति में है, फिर भी दोनों पारस्परिक शान्ति को त्याग करने को प्रस्तुत नहीं हैं।

मध्यपूर्व की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक शतरंज का प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण चाल अरब राज्यों के एकीकरण की है। अरब लीग का यह प्रयास रहा है कि उत्तरी अफ्रीका और मध्यपूर्व के सब अरबी-भाषी राज्यों का एक सघ बने। वास्तव में यह मुस्लिम-प्रभुता के सर्वाधिक अतीत को पुनः साकार बनाने की योजना है। मिश्र के महान नेता फर्नल नासिर अरब एकता के इस स्वप्न को साकार करना चाहते हैं। उन्होंने १ फरवरी, १९५८ की मिश्र तथा सीरिया को संयुक्त करके 'संयुक्त अरब गणराज्य' की स्थापना करके अरब-राज्यों की एकता की दिशा में पहला पग उठाया। इन दोनों देशों का एक शासनाध्यक्ष, एक विधान सभा, एक संयुक्त सेना और एक झण्डा निश्चित हुआ। ६ मार्च, १९५८ को, अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखने हुए, यमन राज्य भी इसमें सम्मिलित हुआ और 'संयुक्त अरब गणराज्यों' (United Arab Nations) का निर्माण हुआ। श्री नासिर की आकांक्षा थी कि इसमें शनैः शनैः ईराक, अल्जोरिया, जोर्डन, सऊदी अरब, लेबनान, कुवैत, मारोको, लीबिया, ट्यूनिशिया, मारीटानिया, चाड, सूडान, अदन, मस्कत ओमन, बहरीन और कातार के प्रदेश भी सम्मिलित हो तथा इन सब के सहयोग से सब अरब राज्यों का एकीकरण हो।

परन्तु श्री नासिर का अरब राज्यों के एकीकरण का यह स्वप्न कुछ अने वजहों के पहिले ही भग हो गया। १ फरवरी, १९५८ में स्थापित हुआ मिश्र और सीरिया का संयुक्त राज्य भी अधिक समय तक नहीं चल सका। २६ २८ सितम्बर, १९६१ को सीरिया में आगि हुई और वह इस राज्य से पृथक् हो गया। पर श्री नासिर ने अपने देश का नाम मिश्र के स्थान पर 'संयुक्त अरब गणराज्य' ही रहने दिया। २६ दिसम्बर, १९६१ को मिश्र ने यमन के साथ अपने सघ को समाप्त कर दिया। परन्तु ८ मार्च, १९६३ को सीरिया में पुनः एक नासिर समर्थक क्रांति हुई और अग्रेल में मिश्र, सीरिया तथा ईराक ने मित्र कर पुनः अरब सघ का निर्माण किया। यह सघ भी आगे चल कर भग हो गया।

भविष्य ही यह बतायेगा कि अरब राज्यों की एकता का प्रयास कहा तक सफल होता है। अरब राज्यों में एकता का एवमात्र आशीर इजरायल

का उग्र विरोध ही प्रतीत होता है, किन्तु जून १९६७ में इजरायल के साथ संधि में बुरी तरह पराजित होने के बाद एकता के इस आधार की आधारत पहुँचा है और कतिपय अरबराष्ट्र इजरायल के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार आवश्यक समझने लगे हैं।

यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक चेतना के बावजूद राजनीतिक दृष्टि से मध्यपूर्व के क्षेत्र में अभी तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आई है। १९५२ की शान्ति से पहले दस वर्षों में मिस्र में १७ सरकारें बदलती रही और अब भी दहा वानाशाही तरह का ही शासन है और कोई नहीं कह सकता कि वर्तमान में नासिर के नेतृत्व को कम उठा दिया जाय। १९४५ से १९५४ तक सीरिया में २४ सरकारें बदली और आज भी वहा की राजनीतिक दशा अस्थिर है। मध्य पूर्व सैनिक पड़यंत्रों और धमनात्मकों की हत्याओं का घर कहा जा सकता है। यहा के अधिकांश देशों में सरकारों का बाना-बाना चलता ही रहता है।

मध्य पूर्व अथवा पश्चिमी एशिया के राज्यों, उनके स्वातन्त्र्य दिवसों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का चित्र अग्रिम सूची से एक ही निगाह में स्पष्ट हो सकेगा—

Country	Area (1,000 Sq Km)	Population (Min) 1967	Capital	Date of Independence	Political System
1. Afghanistan	655 0	15 75	Kabul	28 2 1919	Constitutional Monarchy
2 Burmes Union	678 0	26 25	Rangoon	4 1 1948	Federal Republic
3 Viet Nam Democratic Republic of Viet-Nam	328 0 about 158	36 0 19 5	Hanoi	2.9 1945	Socialist Republic
4. Israel	14 0**	2 67	Tel Aviv	State set up in 1948	Republic
5 India	3,269	511 0	Delhi	15 1 1947	-do-
6. Indonesia	1,904 4	107 0	Jakarta	1 8 1945	-do-
7. Jordon	96 6	2 04	Amman	25 5 1946	Constitutional Monarchy
8 Iraq	44 4	8 34	Baghdad	3 10 1932	Republic
9. Iran	1,648 0	26 3	Tehran	—	Constitutional Monarchy

	195.0	about 5	San'a	1918	Republic
10. Yemeni Arab Republic					
11. People's Republic of South Yemen	about 500	about 10	Ash Shaab	29.11.1967	Republic
12. Cambodia	172.5	6.32	Phnom-Penh	9.11.1953	Constitutional Monarchy
13. Republic of Cyprus	9.3	0.61	Nicosia	16.8.1960	Republic.
14. Chinese People's Republic	9,5970***	723.14	Peking	—	Socialist Republic
15. Korea	238.8	42.18		On 15.8.1945 liberated by the Soviet Army	—do—
Korean Democratic People's Republic	127 2	12 40	Pyongyang	Proclaimed in Sept. 48 The South	
South Korea	96.6	29.78	Seoul	Korean "republic was proclaimed in May, 1948	—do—

16	Kuwait	207	0 57	Kuwait	19 6 1961	Constitutional Monarchy
17	Laos	236 8	2 7	Vientiane	19 7 1949	Constitutional Monarchy
18	Republic of Labanon	10 4	2 46	Beirut	22 11 1943	Republic
19	Malaysia	332 6	9 7	Kuala Lumpur	Independence of Malaya proclaimed on 31 8 1957 On 16 9 1963 it entered the Fede- ration Malaysia	Federal State
20	Maldiva Island	0 3	0 1	Male	26 7 1965	Monarchy (Sultanate)
21	Mangolian People's Republic	1 565 0	1 2	Ulan Bator	11 7 1921	Socialist Republic
22	Nepal	140 8	10 29	Kathmandu	—	Constitutional Monarchy
23	Pakistan	946 7	107 26	Rawalpindi	14 8 1947	Republic

		—	Entered Malaysian Federation Sept 16, 1963, seceded August 9, 1965	Monarchy
24. Saudi Arabia	1,000, 2,400 about 8.0 Riyadh	1 96	Singapore	Republic
25. Singapore	0 6			Republic
26 Syrian Arab Republic	185 2	5.7	Damascus	Republic
27 Thailand	514.0	32 68	Bangkok	Monarchy
28. Turkey	767.1*	33 83	Ankara	
29. Philippines	299 4	34 66	Quezon City (Actually Manila)	Republic
30. Ceylon	65.6	11 49	Colombo	Republic in British Commonwealth Constitutional
31. Japan	372.1	99 92	Tokyo	Monarchy

*Including the European part (23,500 Sq Km)

अफ्रीका की जागृति (Resurgence of Africa)

अफ्रीका कोई एक देश नहीं है, अपितु एक महाद्वीप है जिसमें अनेक देश हैं। उत्तरी अफ्रीका विशेषतः अल्जीरिया, समुन्त अरब गणराज्य और लीबिया के निवासी गोरे हैं, किन्तु द्वीप अफ्रीका के मूल निवासी काले हैं। लेकिन इन गोरो और कालो के बीच पर्याप्त मात्रा में एकता और प्रेम विद्यमान है।

अफ्रीका महाद्वीप में आज से हजारों वर्ष पूर्व नील नदी की घाटी और कापेंज की महान् सम्पदाओं का विकास हुआ, फिर भी केवल एक शताब्दी पूर्व तक इसका बाह्य सत्कार से अत्यन्त थोड़ा सम्पर्क रहा और इसलिए इसे अथ महाद्वीप (Dark Continent) की संज्ञा दी जाती थी। १९ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक यूरोप और एशियावासी इस महाद्वीप के उत्तर तटवर्ती प्रदेशों और मिस्र से ही थोड़े बहुत परिचित थे। सहारा के विशाल मरुस्थल और भूमध्यरेखा के दक्षिण में स्थित प्रदेश से वे लगभग अपरिचित ही थे। इस समय तक अफ्रीका उनके लिए 'एक महाद्वीप न होकर एक तट मात्र था' और इस प्रदेश में उनकी रुचि केवल इतनी ही थी कि वे वहाँ कुछ ऐसे बन्दरगाहों की स्थापना कर सकें जो भारत जाने वाले जहाजों के लिए विश्राम स्थल बन सकें, जहाँ से वे जहाज ईंधन ले सकें और साथ ही अमेरिका के गन्ने और जपान के बगानों में काम करने के लिए उन्हें गुलाम भी मिल सकें।

लेकिन सन् १८७० के बाद से ही यूरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका में उपनिवेशों की प्राप्ति की होड़ लग गई। १८८० से १८९० के बीच उन्होंने सम्पूर्ण अफ्रीका के विविध प्रदेशों को आपस में बाँट लिया। १८७० के बाद के केवल २० वर्ष की अवधि में ही यूरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका के लगभग ९/१० भाग को आपस में विभाजित कर लिया। १८८० में उनके पास १ लाख वर्गमील का प्रदेश था जो १० वर्ष बाद ६ लाख वर्गमील का प्रदेश हो गया। अफ्रीका महाद्वीप के समस्त देशों में से, जिनकी संख्या इस समय कुल मिलाकर ५० के लगभग है, प्रथम महायुद्ध से पूर्व केवल एबीसी-निया (अथवा इथोपिया) ही स्वतन्त्र राज्य रह गया था, किन्तु १९३६ में इसकी स्वतन्त्रता भी इटली द्वारा समाप्त कर दी गई हालांकि द्वितीय महायुद्ध में यह राष्ट्र पुनः स्वतन्त्र हो गया था।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर १९४५ में अफ्रीका महाद्वीप में केवल ४ राज्य स्वतन्त्र थे। एबीसीनिया, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रीका का सघ और

मिस्र । महायुद्धोत्तरकाल में सम्पूर्ण अफ्रीका में स्वतन्त्र होने की इच्छा दलबली होती गई और अफ्रीका 'अफ्रीकियों का हो' की भावना अँगड़ाई ले ली । स्वतन्त्रता से पूर्व सामान्य तौर पर अधिकांश अफ्रीका महाद्वीप विभिन्न शक्तिशाली देशों के मध्य इस प्रकार विभाजित था—

क्र० सं०	नाम	क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ के अनुसार जनसंख्या
१.	फ्रांसीसी अफ्रीका	४०,२२,१५०	४,४१,५२,६००
२.	ब्रिटिश अफ्रीका	२०,२५,७१६	६,२४,३३,६४५
३.	बेल्जियम अफ्रीका	६२४,३००	१,२०,००,०००
४.	पुर्तगाल अफ्रीका	७,८५,०००	६५,००,०००
५.	स्पेनिश अफ्रीका	१,३४,२००	१४,६५,०००

द्वितीय महायुद्ध के बाद यह अज्ञान अथवा अंधा महाद्वीप स्वतन्त्रता की आकांक्षा के इतने तीव्र प्रभाव से आक्रान्त हो उठा कि सम्पूर्ण क्षेत्र में यूरोपियन साम्राज्यों का उसी तीव्रता से अंत हो गया जिस तीव्रता से उनका निर्माण हुआ था । २० वर्ष के अल्पकाल में ही अफ्रीका के ६१० देश स्वतन्त्र हो गए । जाति, भाषा, इतिहास, परम्परा और धर्म आदि का विभिन्नताओं के विद्यमान होते हुए भी अफ्रीका में राष्ट्रवाद की यह अँगड़ाई विलक्षण थी । वस्तुतः इस राष्ट्रवाद का प्रधान कारण यह था कि यूरोपियन लोग अपने जातीय सिद्धान्त के आधार पर अफ्रीका के अनेक लोगों को अपने से विभक्त करके मानते थे । इस सिद्धान्त की तीव्र प्रतिविया ने अफ्रीका के दुर्दमनीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया । अफ्रीकन राष्ट्रवाद की मुख्य प्रेरणा जातीय समानता की आकांक्षा की प्राप्ति से मिली और राजनीतिक स्वतन्त्रता उनके लिये जातीय समानता की प्राप्ति का साधन बन गई । ई० हक्सले (E. Huxley) के शब्दों में "समानों के रूप में, स्वीकृति के अर्थों में अभिमान (Identity) की मांग वस्तुतः अफ्रीका की राष्ट्रियता का आधार है ।"^१ अफ्रीका में राष्ट्रवाद और स्वतन्त्रता के जागरण के उदय का दूसरा प्रमुख कारण यह रहा कि युद्धोपरान्त भारत की स्वतन्त्रता के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों में भी स्वतन्त्रता की सहर व्याप्त हो गई । विदेशी दासता

1. Quoted in International Relations, P. 565 (by Palmer and Perkins)

से मुक्त हो कर एक-एक कर एशिया के राष्ट्र स्वतन्त्र होने लगे। अरब महासागर से लेकर हिन्द महासागर और प्रशांत के तटवर्ती देशों में स्वतन्त्रता के पारिजात बिल उठे। समय और बदलती हुई हवा के रव के साथ साथ इन पुष्पों की मुराबि हिन्द महासागर और अरब सागर की सहरो पर बसे हुए अफ्रीकन महाद्वीप के तटों में आ टकराई और तब इन महाद्वीप के करोड़ों हाथ स्वतन्त्रता देखी का वरण करने के लिए उठ गये। उका दो प्रमुख कारणों के अतिरिक्त पाश्चात्य शिशा के प्रभाव, महायुद्ध के दौरान स्वातन्त्र्य प्रिय अमेरिकनो के सम्पर्क और राष्ट्रसंघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ आदि में उपनिवेशवाद के विरोध ने भी अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलन के विरास में उत्प्रेक्षणीय भूमिका अदा की। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी अफ्रीका के देशों को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में बहुत सहायता दी। द्वितीय महायुद्ध ने उपनिवेशवादी शक्तियों को असमर्थ दुर्बल बना दिया और फ्रांस, ब्रिटेन आदि विजयी राष्ट्र इतने दुर्बल हो गये कि उनमें अपने उपनिवेशों की प्रबल स्वतन्त्रता की अकांक्षा का दमन करने की शक्ति नहीं रह गई। इस तरह उनके एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश तेजी से इसके हाथ से निकल गये। पहले एशिया के उपनिवेश तेजी से स्वतन्त्र हुए जिससे अफ्रीकी राष्ट्रवादियों में प्रबल आत्म-विश्वास जागृत हुआ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका महाद्वीप में एक-एक करके स्वतन्त्रता की तीग उतारोतर जबर्दस्त लहर आई। जैसा कि कहा जा चुका है, महायुद्ध की समाप्ति पर अफ्रीका में केवल ४ राज्य स्वतन्त्र थे—एल्जीरिया, लाईबीरिया, दक्षिण अफ्रीका का संघ और मिस्र। यह १३० लाख वर्गमील का क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल का केवल ११ प्रतिशत था और इसकी २८ करोड़ की आबादी अफ्रीका की कुल जनसंख्या का २६ प्रतिशत थी। इसके बाद स्वतन्त्रता की पहली लहर आई। इस लहर में केवल अल्जीरिया के अपवाद को छोड़कर अरबों द्वारा आवासित उत्तरी अफ्रीका से उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों का सफाया किया। इस पहली लहर द्वारा स्वतन्त्र होने वाले राष्ट्रों में १९५१ में स्वतन्त्र होने वाला लीबिया और १९५६ में स्वाधीनता पाने वाले मरुआव, मोरक्को तथा ट्यूनीशिया थे। इसके बाद स्वतन्त्रता की दूसरी लहर आई जिसने काले अरबों नोरो लोगों द्वारा आश्रित अफ्रीका पर प्रभाव डाला। १९५७ में ब्रिटेन द्वारा पाना को स्वतन्त्रता प्रदान की गई और १९५८ में गिनी पंचम फ्रेंच गणराज्य से पृथक हो गया। १९५९ तक अफ्रीका में भारी-भरकम स्वाधीन हो गये किन्तु अभी तक सहारा के दक्षिण का और जम्बेजी नदी के उत्तर का मध्य अफ्रीका पराधीन था। १९६० में स्वतन्त्रता की तीसरी जबरदस्त लहर आई जिसने

इस प्रदेश के अधिकांश गुलाम देशों को आजाद कर दिया। यह वर्ष अफ्रीका के स्वतन्त्रता का वर्ष कहा जाता है जिसमें १७ देश स्वतन्त्र हो गये। इसके बाद एक एक करके अफ्रीका के शेष देश भी स्वतन्त्र हो गये। १९६६ के अन्त तक केवल इनेगिने प्रदेशों को छोड़ कर सम्पूर्ण अफ्रीका महाद्वीप आजाद हो गया। इस समय तक जो विभिन्न अफ्रीकन देश स्वतन्त्र हो गये, उनका व्योम इस प्रकार से है—

क्र.सं.	नाम प्रदेश	स्वतन्त्रता पूर्व क्षेत्रफल प्रशासकीय (वर्गमील) देश	१९६१ के अनुसार जनसंख्या	स्वतन्त्र होने की तिथि
१	साइबेरिया	अमेरिका ४३,०००	२७,५०,०००	१८४७
२.	इथियोपिया	—	२ करोड	१९४१
३	लीबिया	— ६,७६,३५८	१२,००,०००	२४ नवम्बर १९४१
४.	इरिट्रिया	इटली —	—	सितम्बर १९५२
५	सूडान	ब्रिटेन ६,६७,५००	१० करोड	जनवरी १९५६
६	मोरक्को	फ्रांस —	—	मार्च १९५६
७.	ट्यूनीशिया	फ्रांस ४८,३१३	३६,२५,०००	मार्च १९५६
८.	गाना	ब्रिटेन ६१,८४३	४८ लाख	मार्च १९५७
९	गिनी	फ्रांस १,०५,२००	३,००,०००	अक्टूबर १९५८
१०.	सयुक्त अरब गणराज्य	— ३,८६,१६८	३ करोड	१९५६
११	नैजर	फ्रांस १,९६,४८६	३२,९५,०००	जनवरी १९६०
१२.	मोरक्को (कुछ अंश) स्पेन	— —	—	मार्च १९६०
१३	टोंगा	फ्रांस ४,२१,८६३	१२ लाख	थ्रेल १९६०
१४	मालीसिया	फ्रांस —	—	जुलाई १९६०
१५	कांगोली गणराज्य बेल्जियम	६,४३,०००	१,३० करोड	जुलाई १९६०
१६.	सीमांतिया	ब्रिटेन व इटली —	—	जुलाई १९६०
१७.	मालागासी गणराज्य	फ्रांस २,२८,०००	५१,७४,५२३	जुलाई १९६०
१८.	छाद	गाना ४,६६,०००	२५,८०,०००	अगस्त १९६०
१९.	नाइजर	फ्रांस ४६,४५,०००	२४ लाख	अगस्त १९६०

क्र.सं.	नाम प्रदेश	स्वतन्त्रता पूर्व प्रशासकीय देश	क्षेत्रफल (वर्गमील)	१९६१ के अनुसार जनसंख्या	स्वतन्त्र होने की तिथि
२०	आइवरी कोस्ट	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
२१	बोल्टाई गणराज्य	फ्रांस	—	—	अगस्त १९६०
२२	बेनेन	फ्रांस	१,०३,०००	४,१२,५००	अगस्त १९६०
२३	होमी	फ्रांस	४५,६००	१७,११,०००	अगस्त १९६०
२४	वागो गणराज्य	—	—	—	अगस्त १९६०
२५	मध्यवर्ती अफ्रीका	—	—	—	अगस्त १९६०
२६	नाइजीरिया	ब्रिटेन	३,७३,२५०	३५ करोड़	अक्टूबर १९६०
२७	मारितेनिया	फ्रांस	४,१५,६००	५ लाख	नवम्बर १९६०
२८	सियरालियोन	फ्रांस	—	—	अप्रैल १९६१
२९	रुआंडा उरुंडी	बेल्जियम	२०,५४०	४६,००,०००	६ जुलाई १९६२
३०	अ-जीरिया	फ्रांस	५८,२६,०००	१,०२,६५,०००	सितम्बर १९६२
३१	युगोडा	ब्रिटेन	६३,६८१	७५,१७,०००	अक्टूबर १९६२
३२	तगानिका	ब्रिटेन	३,६२,६८८	६० लाख	दिसम्बर १९६२
३३	बेनिया	ब्रिटेन	—	—	दिसम्बर १९६३
३४	जजीवार	ब्रिटेन	—	—	१० दिसम्बर १९६३
३५	(मलावी) न्यासलैंड	ब्रिटेन	—	—	१९६४
३६	जेम्बिया (उत्तरी रोडेसिया)	ब्रिटेन	—	—	१९६४
३७	गैम्बिया	ब्रिटेन	—	—	१९६५
३८	ब्रिटिश गियाना (नया नाम गुयाना)	ब्रिटेन	८६,०००	६,५०,०००	२६ मई १९६६
३९	बोत्सवाना (बेचुआनालैंड)	ब्रिटेन	२७,५००	३,३७,०००	३० सितम्बर १९६६
४०	लेसोथो (बसुतोलैंड)	ब्रिटेन	११,७१६	१,२४,०००	३ अक्टूबर १९६६
४१	बारबाडोस	ब्रिटेन	१६६	२,५०,०००	३० नवम्बर १९६६
४२	मारिशस	ब्रिटेन	—	—	मार्च १९६८

यह स्मरणीय है कि अफ्रीका महाद्वीप की राजनीतिक परम्परायें प्रारम्भ से ही अधिनायकवादी और सर्वसत्तावादी रही हैं। औपनिवेशिक युग के सुरु होने से पहले अफ्रीका महाद्वीप में एकतन्त्रात्मक शासन का बोलबाला था। क्वीलो के सरदार स्वेच्छाचारी ढंग से शासन करते थे। जब औपनिवेशिक युग प्रारम्भ हुआ तब भी इस स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं आया और इस महाद्वीप की मोलीमानी प्रजा साम्राज्यवादी शक्तियों के निरंकुश शासन से प्रताड़ित रही। इस राजनीतिक अवस्था का परिणाम यह हुआ कि अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश में स्वस्थ लोकतन्त्रीय परम्पराओं का विकास नहीं हो सका, यद्यपि अब भूतपूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों में सत्तात्मक लोकतन्त्र की स्थापना की गई है तथापि वहाँ भी उदार लोकतन्त्र बहुत सीमा तक सफल नहीं हुआ है। अल्जीरिया या घाना या इथोपिया अथवा मिस्र किसी भी देश को ल, हमें सर्वत्र यही दिखलाई पड़ेगा कि इन सभी देशों में निर्वाचित एकतन्त्र की स्थापना की गई है।

अफ्रीका में साम्यवादी प्रभाव अभी तक विशेष रूप से उग्र नहीं हो पाया है तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि साम्यवादी देशों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध अफ्रीकावासियों के संघर्ष को नैतिक बल पहुचाने में सत्रिय सहायता की है। इनमें अग्रगण्य सोवियत संघ रहा है। वह समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसके बाहर अफ्रीकन जनता की स्वाधीनता का समर्थन करता रहा है। कांगो के प्रथम प्रधानमंत्री पेट्रिस लुमुम्बा की मृत्यु पर मास्को में एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी जिसमें आज भी अफ्रीका के विभिन्न देशों के विद्यार्थी वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह सोवियत संघ अफ्रीका में साम्यवाद का प्रचार-प्रसार करने हेतु सचेष्ट है। यही नहीं उसने स्वयं को अफ्रीका के धर्म आन्दोलनों के साथ जोड़ने की चेष्टा की है और अफ्रीका के गरीब देशों को आर्थिक सहायता देकर उनकी पर्याप्त सहानुभूति अर्जित कर ली है। फिर भी अफ्रीका के राष्ट्र इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि साम्यवादी देश उनके प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि अफ्रीका में साम्यवाद की स्थापना हो। अफ्रीका महाद्वीप में भी चीन सोवियत संघ का प्रतिद्वन्द्वी है। सोवियत संघ और चीन दोनों ही अफ्रीका के देशों को अपने-अपने साम्यवादी ढंग से प्रभाव में लाना चाहते हैं। इसी दृष्टि से दोनों देशों के उच्च नेताएँ अफ्रीका के विभिन्न देशों के घेरे परते रहे हैं।

अफ्रीका की समस्या न केवल राजनीतिक, अपितु एक बहुत बड़ी सीमा तक आर्थिक और औद्योगिक भी है। आर्थिक दृष्टि से अफ्रीका के देश

बहुन अधिक पिछड़े हुए हैं यद्यपि प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अफ्रीका सत्तार का एक सीमाश्रयशाली देश है। अब तक साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी शक्तियाँ अफ्रीका महाद्वीप के विशाल प्राकृतिक साधनों का शोषण अपने लिए करती रही थी, परन्तु अब इनका उपयोग राष्ट्रीय हितों में होना है। अफ्रीका के देश इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि विकसित देश उन्हें वांछित आर्थिक और प्राविधिक सहायता दें, किन्तु साथ ही उनकी सम्प्रभुता और स्वतन्त्रता पर भी किसी प्रकार की आचमन आ पाये। अब यह सम्भव नहीं है कि अफ्रीका महाद्वीप के देश पारिवाह्य औद्योगिक-उत्पादन के लिए बाजार बन कर रह जाए।

अफ्रीका के विभिन्न देशों की एक गम्भीर राजनीतिक समस्या स्वतः यूरेशियनो की है, जिनके पूर्वज यूरेशियन देशों से आकर अफ्रीका में बस गये थे। यद्यपि अफ्रीका की जनता की तुलना में ये लोग अत्यन्त अल्प संख्या में हैं, लेकिन द घंटा तक अफ्रीकावासियों पर शासन करने के कारण उनके मन में उच्चतम की भावना घर बिये हुए है। साथ ही उनके अपने विशिष्ट आर्थिक स्वार्थ भी हैं। अफ्रीका के मूल निवासी इन गोरों उपनिवेशकारियों को घृणा और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की रणभेदनीति ने सम्पूर्ण सत्तार के समक्ष निर्लेख्य रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ के गोर उपनिवेशकारी मानवीय न्याय और सज्जनता की समस्त मर्यादाओं को लाप कर अपने विशिष्ट आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए शासन के बल पर अपने आरको अफ्रीका महाद्वीप में बनाये रखना चाहते हैं।

कुछ प्रमुख अफ्रीकन देश

(Some Important African Countries)

अफ्रीका महाद्वीप के जागरण के इस सक्षिप्त विवेचन के उपरान्त महा के कुछ प्रमुख राष्ट्रों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी है—

लीबिया—लीबिया नामक सघातमक राज्य की स्थापना २४ दिसम्बर, १९५१ को इटली के तीन उपनिवेशों त्रिपोलीतानिया, मायरेनिका तथा फेजान को मिलाकर की गई। यह एक राजन्यात्मक राज्य है जिसकी जनता अधिकांशतः मुस्लिम मतावलम्बी है। लीबिया अरब लीग का एक प्रमुख सदस्य है। दिसम्बर १९५५ से वह संयुक्त राष्ट्रमण्डल का सदस्य है और अफ्रीकन देशों की स्वतन्त्रता के लिये अफ्रीकाई देशों का साथ दे रहा है।

ट्यूनीसिया—यह प्राचीन देश अफ्रीका के भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। पारिवाह्य सम्बन्धों से गम्भीर रूप में प्रभावित इस देश का राष्ट्रवाद शक्ति सङ्कीर्णता और सामन्तवाद से मुक्त रहा है। २० मार्च, १९५६ को

फ्रांस द्वारा द्यूनीसिया की स्वतन्त्रता स्वीकार करने के बाद नवम्बर, १९५६ से ही वह संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य है। द्यूनीसिया के नेता अफ्रीकन देशों की एकता के विशेष रूप से समर्थक हैं। दुर्भाग्यवश अरब राष्ट्रों के साथ इस देश के सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। संयुक्त राष्ट्रसभ के सदस्य के रूप में उसने अफ्रीकी एशियाई देशों का साथ दिया है।

मोरक्को—अरब देशों में मोरक्को ही एक ऐसा देश है जो लगभग पिछले १२०० वर्षों तक एक स्वाधीन देश बना रहा, १९१२ में पहली बार उसे फ्रांस का संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। यह स्थिति १९१२ से १९५६ तक रही। १९३० से ही वहाँ स्वतन्त्रता का आन्दोलन शुरू हो गया और फ्रांस के लिये मोरक्को को गुलाम बनाये रखना सम्भव न रहा। अन्त में २ मार्च, १९५६ को मोरक्को की जनता ने पुनः स्वाधीनता की सास ली। दिसम्बर, १९५६ में मोरक्को संयुक्त राष्ट्रसभ का सदस्य बना लिया गया।

इथोपिया—इसे एथियोपिया भी कहा जाता था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह स्वतन्त्र हो गया और १९३० से चले आ रहे इथोपियन सम्राट हैल-सेलामी ने पुनः शासन का भार सम्हाल लिया। इथोपिया अफ्रीका के सर्वाधिक प्रगतिशील राष्ट्रों में से एक है और आर्थिक दृष्टि से उसने स्वयं को काफी सुदृढ़ कर लिया है। यह देश अफ्रीका राष्ट्रों की एकता का प्रतीक है।

कांगो (ब्रेजेवेल एवं लियोपोल्डविले)—अफ्रीका में दो कांगो हैं जिनमें से एक फ्रांस के अधीन था और दूसरा बेल्जियम के। १९६० में दोनों ही कांगो की स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई और दोनों ही में गणतन्त्रात्मक शासन की स्थापना की गई।

नाइजीरिया—यह ब्रिटिश उपनिवेश एक अक्टूबर, १९६० को स्वतन्त्र हो गया। इसका क्षेत्रफल ३,१६,१६८ वर्गमील और जनसंख्या लगभग ३,४०,००,००० है। यह जनसंख्या अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक है। नाइजीरिया अफ्रीका का समृद्धतम और महत्वपूर्ण देश है।

यहाँ लोकतन्त्रात्मक परम्परायें पर्याप्त रूप से दृढ़ हैं। यह देश तीव्रता से आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्रसभ में नाइजीरिया ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और रंगभेद की नीति के विरुद्ध अन्य अफ्रीकी-एशियाई देशों के साथ मिलकर सघर्ष किया है।

यूगाण्डा—लगभग ६८ वर्षों तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत रहने के पश्चात् यूगाण्डा भी ८ अक्टूबर, १९६२ को स्वतन्त्र हो गया। अपनी स्वतन्त्रता के समय ही यह राष्ट्र मडक का सदस्य बन गया। यूगाण्डा एक सघातक राज्य है। आर्थिक दृष्टि से यह एक समृद्ध देश है। यह राष्ट्र

भी अन्य अफ्रीकन राज्यों की भांति रंगभेद नीति और पश्चिमी राष्ट्रों के साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है।

केनिया—यह यूगाण्डा के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग २ लाख २५ हजार वर्गमील और आबादी लगभग ६५ लाख है। द्वितीय महायुद्ध के बाद केनिया में, जो उस समय ब्रिटिश उपनिवेश था, स्वातन्त्र्य आन्दोलन बहुत तीव्र हो गया। १२ दिसम्बर १९६३ को यह एक स्वतन्त्र देश बन गया और उसे सर्वे सम्मति से राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना लिया गया। इसके शीघ्र बाद ही केनिया ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त कर ली।

केनिया अफ्रीका में चीनी साम्राज्यवाद का प्रबल विरोधी और स्वतन्त्र, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादी और संगठित अफ्रीका का समर्थक है।

घाना—पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटेन का एक उपनिवेश गोल्ड-कोस्ट था। वहाँ की जनता औपनिवेशिक दासता से छुटकारा पाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रही। जुलाई १९५३ में ब्रिटेन की सहमति से गोल्ड कोस्ट एक स्वतन्त्र प्रभुता सम्पन्न राज्य के रूप में प्रादुर्भूत हुआ। बाद में ब्रिटिश टोगोलैंड ने साथ मिल कर १९५७ में गोल्ड-कोस्ट घाना के नाम से एक गणतन्त्रात्मक संघ बन गया और वहाँ अध्यक्षतात्मक शासन की स्थापना हो गई। संयुक्त राष्ट्रसंघ में घाना उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध बोलता रहा है।

अल्जीरिया—भूमध्य सागर के तट पर ही अफ्रीका का एक अन्य अरब देश अल्जीरिया है। १९वीं शताब्दी के आरम्भ में यह एक फ्रेंच उपनिवेश था।

अल्जीरिया की जनता ने फ्रेंच शासन को कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं किया। अल्जीरिया का राष्ट्रीय आन्दोलन सन् १९२५ में मुखरित हुआ जब उसने अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए सशस्त्र लड़ने में मांग की। स्वाधीनता के लक्ष्य को पूर्ति के लिए जुलाई, १९५१ को एक राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया गया जो 'राष्ट्रीय स्वाधीनता का मोर्चा' (Front of National Liberation, F N L) के नाम से प्रख्यात हुआ।

राष्ट्रीय स्वाधीनता मोर्चे के नेतृत्व में १ नवम्बर, १९५४ को फ्रेंच शासन के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम आरम्भ हो गया, जो १९६२ तक लगातार चलता रहा जिसमें दोनों ही पक्षों के लोग लाखों की संख्या में कीड़े मकड़ों की तरह मारे गये।

भीषण रक्त रजित संग्राम और कठोरतम दमनकारी उपायों के उपरान्त भी जब अल्जीरिया के राष्ट्रवादियों को आत्म-समर्पण के लिए झुकाया न जा सका तो फ्रेंच साम्राज्यवादियों ने यह निश्चय किया कि अल्जीरिया की स्वतन्त्रता के प्रश्न पर वहाँ जनमत संग्रह कराया जाय। फ्रेंच राष्ट्रपति डिगाल ने आत्म निर्णय और जनमत के आधार पर अल्जीरिया की स्वतन्त्रता देने का आश्वासन दिया। जनवरी १९६१ में जनमत संग्रह का कार्य हुआ जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ लोगों ने अल्जीरिया में स्थायित्व आनन्द स्थापित होने के पक्ष में और पचास लाख लोगों ने इसके विपक्ष में मत दिये। परन्तु डिगाल द्वारा प्रस्तावित स्वायत्त शासन प्राप्त करने पर भी अल्जीरिया पूर्ण स्वतन्त्र नहीं होता था क्योंकि किसी न किसी रूप में उस पर फ्रांस का अधिकार बना ही रहता।

कुछ दिनों बाद अल्जीरिया की समानान्तर सरकार ने वार्तालाप का रुत अपनाया। इसी बीच डिगाल की अल्जीरिया-नीति से असन्तुष्ट कुछ फ्रेंच सैनिक अधिकारियों ने २२ अप्रेल १९६१ को सहमा अल्जीरिया पर आक्रमण करके उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। किन्तु डिगाल द्वारा इस सैनिक विद्रोह को कुबल दिया गया। अतः १ जुलाई १९६२ को अल्जीरिया की स्वतन्त्रता दे दी गई और इस प्रकार एक महान् स्वतन्त्रता संग्राम का अन्त हुआ। अक्टूबर, १९६२ को अल्जीरिया संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया और तब से वह अफ्रीका में विकासशील राष्ट्र का प्रतीक बना हुआ है।

स्वतन्त्र अफ्रीका महाद्वीप की समस्याएँ

(Problems of Independent African Continent)

नवोदित अफ्रीका के राज्यों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें से अफ्रीका समस्याएँ तो यहाँ की पिछड़ी हुई आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति से उत्पन्न होती हैं। यहाँ के देशों के सामने विश्व के अन्य देशों के उदाहरण बाने के लिए पार करने की एक लम्बा रास्ता पड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यहाँ के कुछ देशों में आन्तरिक हिंस्र गृह युद्ध तथा जातीय भेद भाव के आधार पर अनेको उपद्रव किए गए। महाद्वीप के देशों में विकास के लिए आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता का मुखपान हुआ। उनका हित राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रश्नों को लेकर परस्पर टकराने लगे। अन्तर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तरों पर सर्वोच्चता पाने के लिए यहाँ के विभिन्न देशों के बीच शक्ति का संघर्ष छिड़ गया। इस प्रकार स्वतन्त्र अफ्रीका में अनेकता, संघर्ष और प्रतिद्वन्द्विता का वातावरण जोर पकड़ने लगा। यहाँ के राष्ट्रों के विकास के लिए परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों

की आवश्यकता प्रमुख है किन्तु यहाँ इस आवश्यकता के विपरीत प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। विश्व को दूसरी शक्तियों के द्वारा इस फूट का लाभ उठाया जा रहा है। साम्यवादी गुट तथा पश्चिमी देश दोनों ही अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास में सञ्चलन है। योरोप के जिन देशों ने अफ्रीका के अपन उपनिवेशों का आजादी प्रदान कर दी है वे भी यहाँ किसी न किन्हीं रूप में अपना प्रभाव जमय रखना चाहते हैं। उनका हित इस बात में रहता है कि इस देशों पर गारी जाति का ही प्रभुत्व बना रहे। स्वतन्त्र अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख समस्याय निम्न हैं—

१ अफ्रीका महाद्वीप में मिली-जुली समस्याओं तथा विचारों के सहारे नातिन को मकड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे एक नवीन अफ्रीका की सम्भावना निहित है। किन्तु नवीन विचारों एवं समस्याओं का यह प्रयोग अफ्रीका के पुराने रीति रिवाजों तथा परम्पराओं से भिन्न पड़ता है तथा इसके प्रति यहाँ के लोगों में विरोध की भावनाएँ हैं। समाज के परम्परावादी रूप के विध्वंस से जो असुरक्षा की भावना पैदा होती है वह इन देशों के विकास कार्यों की सफलता में मुख्य रूप से बाधक है।

२ विकास कार्यक्रमों को फलदायक बनाने के लिये अफ्रीका महाद्वीप में पहले सामाजिक तथा सांस्कृतिक श्रान्ति का लाना परम आवश्यक है। यहाँ के धार्मिक नियम राजनैतिक विचार अनुशासनहीनता की प्रवृत्तियाँ आदि में मूलभूत परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। हो सकता है कि इस परिवर्तन काल में यहाँ के देशों को जबरन हिंसात्मक तथा नृसंहारपूर्ण अनुभव भी करने पड़ जाय।

नौकर स्लामी

३ अफ्रीका के नव दिन राष्ट्रों का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्व जानना से पूर्व यह समझना उपयोगी है कि यहाँ की श्रान्ति का लोगों के जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। स्वतन्त्रता से पूर्व यहाँ के लोगों पर हजारों मील दूर बँटे शासकों की आज्ञाय शासन करती थी। उपनिवेशवादी शक्तियों के प्रतिनिधि ही यहाँ के सब कुछ थे। उनके साथ अफ्रीकावासियों का संबंध नौकर और स्वामी का सम्बन्ध था किन्तु आज यह स्थिति नहीं रही है तो भी जातीय उच्चता के आधार पर योरोप के देश इन देशों पर अपने पूर्ण प्रभाव का बनाए हुए है।

४ गोरे और काले का भेद प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य-वृत्त नहीं है और न ही मनुष्य इस परिवर्तित कर सकता है, किन्तु यह शारीरिक भेद अफ्रीका के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को प्रभावित करने वाला सच्चे अर्थ में प्रभावशाली तरंग है। गन्थर (Gunter) महोदय

के अनुसार "सब चीजों से ऊपर रग-भेद ही है जो अफ्रीका में अमनोप तथा विद्वेप उत्पन्न करता है। यह अफ्रीकी हीनता का प्रधान कारण है जिससे उन्मत्त और विद्रोह पैदा होते हैं। यह गोरे तथा काले दोनों ही प्रकार के लोगों के मस्तिष्क को विगाड़ देता है।" घोर विषम सामन्यता में जानीय तथा रग पर आधारित भेद मान की नीति का पर्याप्त बटावा दिया गया था। रग भेद के कारण पूरे महाद्वीप में ही एक प्रकार का गहरी खाई १७ गई थी तथा जिन देशों में गैररहितता समाप्त नहीं रहने बहा के काले लोग भी अपने आपको गोरो से हीन मानते हैं। यह खाई तब तक बनी रहेगी जब तक बमती के रोरपन के आधार पर अधिकांश जन समुदाय के विरुद्ध छोटे से लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होने रहने। जान हच (John Hatch) के शब्दों में "अफ्रीका के लोग आत्म विद्रोह को, जो सहिष्णुता के लिए आवश्यक होता है तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वे रग के आधार पर किये जाने वाले भेद-भाव से अपने आन्तरी स्वतन्त्र नहीं कर लेते।" गोरे गोरे अफ्रीका के देशों में अब राजीकियों की सरकारें स्थापित होती आ रही हैं तथा अब गोरे लोगों के विरुद्ध काले लोगों को कुछ विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति मर करती आ रही है।

५ केवल रग-भेद तथा जाति-भेद को समाप्त कर देना ही पर्याप्त नहीं है। अफ्रीका के देशों में योरोपीय देशों द्वारा भेरे मूलभूत परिवर्तनों की स्थापना करके सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन को बढा दिया गया था। अफ्रीका में क्रान्ति को पूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इस क्रान्ति को सामाजिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लाया जाय। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद इन देशों में जो सरकारें स्थापित की गई हैं, यद्यपि उनका संचालन देश के निवासियों द्वारा ही किया जाता है किन्तु फिर भी वे इतनी अधिक सत्ता एवं अधिकार का प्रयोग करती हैं जिससे कि विदेशियों द्वारा किया जाता था।

अनेक अफ्रीकी देशों में एक दलीय व्यवस्था को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। इस मान्यता पर अफ्रीका के आदिवासी जीवन का प्रभाव है। आदिवासी जीवन की सामान्य परम्परा के अनुसार समूहित विरोधी का होना अनुचित है क्योंकि यह अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न करता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर सभी व्यक्तियों के मत का प्रभाव रहता है। आज एक सामान्य अफ्रीकी अपने जीवन में यह शायद कि उसके ऊपर सत्ता की जिस मात्रा का स्वतन्त्रता के बाद में प्रयोग किया जा रहा है वह स्वतन्त्रता के पूर्व प्रयोग की जाने वाली मात्रा से कहीं अधिक है। सत्ता की इस मात्रा

का भी महा के लोग अपनी सुरक्षा के नाम पर स्वीकार कर लेते हैं। इन प्रकार प्रायः पूरे अफ्रीका में ही सरकार के नियन्त्रण तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बीच बड़ा असन्तुलन होते हुए भी कोई हमका विरोध नहीं करता और न ही किसी को इससे अछूतोप होता है।

६ राष्ट्रवाद की भावना ने अफ्रीका के देशों में एकता का सूझवात किया और इसी एकता के आधार पर वे विदेशी शक्तियों से अपने आपको छुड़ा सके हैं। महाद्वीप के अफ्रीका भाग पर राष्ट्रवाद का भारी प्रभाव है। हेच (Hatch) के शब्दों में स्वतन्त्रता एकता की मांग करती है और राष्ट्रीयता की तेज मानसिक शराब ने सारे देश का साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एकीकृत करने में महत्वपूर्ण काम किया है। शिक्षा, सम्पत्ता एवं विज्ञान में पिछड़े होने के कारण यहाँ के देशों में राष्ट्रवाद उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि यह एशिया महाद्वीप में रहा है। यद्यपि राष्ट्रवाद की जागृति को रोका नहीं जा सकता तो भी अफ्रीका के बड़े क्षेत्र अभी तक राष्ट्रवाद के प्रभावशाली व्यवहार के लिए तैयार नहीं हैं अर्थात् महा पर स्वशासन की स्थापना के अनुकूल वातावरण अभी तक नहीं बना है।

७ अफ्रीका के देशों में नवीन जीवन के प्रति, स्वशासन के प्रति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रति, पारस्परिक सहयोग के प्रति तथा जातीय एकता के प्रति अवस्था की भावनाएँ हैं। अफ्रीका अपने इस रूप में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में आया है। अब यह स्वाभाविक है कि अन्तर्राष्ट्रीय महामेदों का, घटनाओं का तथा मनमुटावों का प्रभाव इस महाद्वीप के देशों पर भी पड़े। किन्तु ये देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं इसलिए किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर अपना स्वतन्त्र विचार नहीं रख सकते। अफ्रीका का आर्थिक जीवन अब भी बहुत कुछ शेष समार पर निर्भर करता है। इस आर्थिक परनिर्भरता की अवस्था में जब ये देश उपनिवेशवाद से स्वतन्त्रता की स्थिति में आये तो उनके समस्याएँ उत्पन्न होगीं। नये राज्यों का निर्माण उन प्रदेशों में से किया गया है जिनका यूरोपीय शक्तियों ने विभाजन कर रखा था। ये राज्य आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए महयोगपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखते।

८ प्रायः पूरे अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीकान की भावना का प्रभाव है। सभी अफ्रीकी यह निर्णय कर चुके हैं कि सम्पूर्ण अफ्रीका पर भविष्य में केवल अफ्रीकियों का ही राज्य रहेगा। इस दृष्टिकोण के कारण अफ्रीका में विभिन्न सभ तथा उपसभ बनाने के प्रस्तावों पर समय समय पर विचार किया जाता रहा है। आपा, सभार साधन तथा आर्थिक विकास जैसी कुछ बाधाएँ

इस प्रकार के संपन्न निर्माण के मार्ग में हैं जिनको दूर करने के बाद यहाँ के लोगों में सुरक्षा की भावना आवेगी तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों में भी विकास होगा।

६. अफ्रीका महाद्वीप शीत युद्ध के प्रसार को रोकने के लिए प्रयत्नशील है और इसी उद्देश्य से इसने अन्तर्राष्ट्रीय समाज में परापूर्व विभा है। यद्यपि अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक कार्यों की आयोजना करते हैं तो भी यह उनके लिए एक आशा का प्रतीक है जो उनके आर्थिक तथा राजनैतिक विकास में सहायता देकर उन्हें विश्व राजनीति को प्रभावित करने योग्य बना सकता है तथा पूर्व और पश्चिम के झगड़े से दूर रख सकता है। अफ्रीका के देश यह चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्रसंघ साम्यवादी भ्रमवा पूँजीवादी शक्तियों के हाथ की कठपुतली न रहकर पूर्व, पश्चिम और निम्नो का बराबर प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बन जाय। उनके मतानुसार यह संस्था उपनिवेशवाद, नवीन उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के नये तरीकों से बहूता है। वे चाहते हैं कि यह उनके अपने आर्थिक विकास में सहायता करे, उनकी राजनैतिक परेशानियों में सहायक बने तथा यही एकमात्र ऐसा अभिकरण है जो विश्व युद्ध को रोकने की सामर्थ्य रखता है।

अफ्रीका में साम्यवाद

साम्यवाद की प्रवृत्तियों का प्रभाव अफ्रीका महाद्वीप पर एशिया महाद्वीप की अपेक्षा कम है। अफ्रीका की राजनीति में यह एक प्रकार का विरोधाभास सा लक्षित होता है। एक ओर तो इस महाद्वीप में साम्यवाद के लिए प्रायः सभी आवश्यक परिस्थितियाँ उपस्थित हैं जिनके कारण इस विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि यहाँ के लोग आर्थिक शोषण तथा साम्राज्यवाद के दपन एवं बातों के कटु अनुभव कर चुके हैं, इन देशों के प्रति यहाँ पर प्रबल विरोध की भावना वर्तमान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पश्चिमी दग का प्रजातन्त्र, जो स्वतन्त्रता के ऊपर इतना अधिक जोर देता है और समानता के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करा सकता है, इन महाद्वीप के लोगों की आशाओं और महत्वाकांक्षाओं से मेल नहीं खाता। वे तो शीघ्र ही बीमारी से छुटकारा पाकर अपने लिए यथेष्ट भोजन की प्राप्ति में रूचि रखते हैं, अन्य अमूर्त आदर्शों में उनकी कोई रूचि नहीं है। इन सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के साधन साम्यवाद के पास मौजूद हैं तथा उसके द्वारा दिये गये आश्वासनों के प्रति इस महाद्वीप के लोगों की रूचि रहना स्वाभाविक है। राय ही साम्यवादी देशों द्वारा साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध,

आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाना तथा पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके शोषण का अन्त करना, व्यक्तियों के बीच समानता की स्थापना करना और जाति भेदभाव की नीति के किसी भी रूप में प्रयोग की निंदा आदि साम्यवादी नीतियों के कुछ उदाहरण हैं जो अफ्रीका निवासियों का ध्यान अपनी आरंभिक नीतियों के लिए पर्याप्त में भी अधिक है। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य है कि सन्त्रियन रूप और साम्यवादी चीन द्वारा इस महाद्वीप के अनेक देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों में सन्त्रिय सहयोग प्रदान किया गया था। इस सहयोग को ये देश कभी भी नहीं भुला सकते। इन सबके होने के बाद अफ्रीका महाद्वीप पर साम्यवादी गुट की पूरी नजर है तथा यहाँ से हटते हुए पश्चिमी प्रभाव के स्थान को वे स्वयं ग्रहण करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न करने को तैयार रहते हैं। आर्थिक असमानता के प्रति यहाँ के लोगों का दृष्टिकोण स्पष्ट है तथा इसके परिणामों से वे भली भाँति परिचित हैं।

सूडान गणतन्त्र के राष्ट्रपति इब्राहिम अबूद (Ibrahim Abboud) ने संयुक्त राष्ट्रमण्डल में बोलते हुए कहा था कि "अन्तर्राष्ट्रीय समूह पर स्थित असहयोग तथा अशांति का कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में असमानता है जो हमारे समय की एक विशेषता है तथा जो विश्व की अति घबराहट और अति गरीबी में विभाजित करती है। आर्थिक विकास के ये असंतुलित स्तर ही असंतोष तथा ईर्ष्या के बाज बोल रहे हैं।" इन सब अनुकूल परिस्थितियों तथा वातावरण के रहने पर भी अफ्रीका में साम्यवाद का प्रभाव इतना कम है। इसका कारण विश्व की स्थिति को माना जा सकता है। अफ्रीका महाद्वीप का देशों से स्वतन्त्रता प्राप्त करने का एक बड़ा लाभ यह प्राप्त हुआ कि अब यहाँ के देशों ने अन्तर्राष्ट्रीय समूह पर पाब रखा तो इनके सामने दो विरोधी तथा प्रतिसाधापूण गुट स्रष्टत आ गये थे। उनके बीच शीत युद्ध एवं उसके भयानक परिणामों की कल्पना करने में भी ये देश समर्थ थे। साथ ही दोनों गुटों से अलग रहने की असममता की नीति का भारत के नेतृत्व में अनेक देशों ने पालन करना प्रारम्भ कर दिया था। ऐसी स्थिति में सदियों के बाद प्राप्त की गई अपनी स्वतन्त्रता को बचाये रखने के उद्देश्य से इन देशों ने भारत का अनुगमन करना ही उपयुक्त समझा। शीत युद्ध की शान्त लपटों से यहाँ के नेता अपने प्रदेशों को बचाने के पक्ष में थे। दक्षिणोपसा के कार्यवाहक राज्य मंत्री कटेमा दिफू (Katsma Yifru) ने संयुक्त राष्ट्रमण्डल में कहा था कि "शीत युद्ध का प्रसार एशिया और अफ्रीका के लिए विशेष खतरा का निर्माण करता है तथा यह उनके सामाजिक तथा आर्थिक रूप से शान्तिपूर्ण एवं बौद्धिक विकास के लिए चुनौतियों का निर्माण करता है।" इसी प्रकार के विचार नाईजीरिया के

प्रधानमंत्री सर अबुबकर बलेवा (Sir Abubaker Balewa) ने कांगो की समस्या पर बोलते हुए प्रकट किये थे। उनका कहना था कि “अफ्रीका को सैद्धांतिक मधुपर्ग की कुछ भूमि नहीं बनने देना चाहिए और इस कारण कांगो की स्थिति पर अफ्रीकी राज्यों को राजनैतिक स्तर पर विचार करने देना चाहिए।”

इन समस्या उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के देशों में साम्यवाद की विरोधी प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं तथा ये किसी भी दाद से अपने आपको बाधना नहीं चाहते। कुछ विचारकों का मत है कि साम्यवाद का इस महाद्वीप के राष्ट्रों में आन्दोलनों पर अधिक प्रभाव नहीं था। अफ्रीका के कई देशों में साम्यवादियों की बूटनीतिक चोकिमा बनी हुई है जैसे कंबो, आदिगजवावा, प्रोटेरिया, मोनराबिया आदि तथा अल्जेरिया, ट्यूनीसिया, फ्रांसीसी पश्चिमी अफ्रीका में स्पानीय साम्यवादियों का प्रभाव है। अफ्रीका के नेताओं में ये बहुत कम ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। किन्तु यहां के विभिन्न देशों के लिए साम्यवाद का प्रचार एवं प्रसार करने के उद्देश्य से एजेंट भेजे जाते हैं तथा यह सम्भावना है कि यहां के कुछ देश साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुक जायें।

अफ्रीकी एकता आन्दोलन

(African Unity Movement)

अफ्रीका के विभिन्न देशों ने जब से स्वतन्त्रता प्राप्त की है तभी से उसके एकीकरण के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। अफ्रीका के राज्यों की समस्याएँ समान हैं तथा स्वतन्त्रता के बाद इनमें परस्पर-निर्भरता की भावना की वृद्धि हुई है। समय-समय पर इस महाद्वीप के दो या दो से अधिक देशों का किसी निश्चित लक्ष्य के लिए संधि बन जाता है। किन्तु समस्या यह है कि इस एकता को किस प्रकार प्राप्त किया जाय, इसी प्रश्न को लेकर अफ्रीका के राज्यों का विभाजन हो गया है। अफ्रीकी राज्यों का एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। यहां के स्वतन्त्र राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय नवीन युग की देन है। राष्ट्रवाद से प्रभावित अनेक नेताओं ने अफ्रीका के विभिन्न राज्यों के बीच जिन मन-मुटावों की स्थापना की थी उनको अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। अतीसवीं शताब्दी में योरोपियन शक्तियों ने अफ्रीका का जो विभाजन किया था उसके कारण एक उपनिवेश दूसरे से घृणित हो गया तथा उनमें उपनिवेशी एकता के भाव आ गए। वर्तमान समय में इन उपनिवेशी संधियों को नवीन अन्तर्अफ्रीकी राध में परिवर्तित करना बड़ा कठिन है। योरोपियन शक्तियों ने अफ्रीकी संधि के महत्व को पहले से नहीं पहचाना तथा इस ओर कोई महत्वपूर्ण कार्य न किया।

अफ्रीकी भ्रातृत्व (Pan Africanism) का आन्दोलन महाद्वीप के एकीकरण के प्राचीनतम आन्दोलन में से एक है। इसके समर्थक प्रायः 'मयूक्त राज्य अफ्रीका' के लक्ष्य का प्रस्ताव रखते हैं। उनके मतानुसार एक सघ के निर्माण के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वे सभी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती हैं। किन्तु जैसा कि रूपर्ट ईमर्सन (Rupert Emerson) ने लिखा है— 'एक यथार्थवादी तो यह चाहेगा कि अफ्रीकी भ्रातृत्ववाद को एक आदर्श तथा रंगीन स्वप्न मानकर अस्वीकार कर दिया जाय क्योंकि यह राज्य सम्प्रभुता की उन ठोस दीवारों का उपयोगी उल्लंघन करने में असमर्थ है जिनको बनाने में अफ्रीकी लगे हुए हैं।' अफ्रीका में अमरीका के नमूने पर सघ का निर्माण करना असम्भव है क्योंकि अमरीका के १३ तरनिवेशों के सामने जो समस्याएँ थी आज का अफ्रीका उनसे भिन्न तथा सलिल्ट समस्याओं का सामना कर रहा है। यहाँ एकता के प्रतीक कम हैं तथा यह राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि में एक सघ बनने के लिए उपयुक्त नहीं है।

अफ्रीका के देश अपने आपको बाह्य शक्तियों के प्रभाव से बचाने में असमर्थ हैं। अफ्रीका के देश प्रायः यह चाहते हैं कि वे शीतयुद्ध के प्रभावों से बचकर रहें किन्तु शीत युद्ध की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि ससार का कोई भी महत्वपूर्ण भाग इस समय से अछूना नहीं रह सकता। अफ्रीका जैसा क्षेत्र, जिसका आर्थिक तथा सैनिक महत्व है तथा जहाँ अशान्ति एवं अस्थिरता की भारी सम्भावनाएँ हैं, वह दोनों गुटों की छाया से दूर नहीं रह सकता। अफ्रीकी एकता के सम्बन्ध में यहाँ के राज्यों के बीच जो मतभेद हैं तथा अलग अलग विचारधाराएँ हैं उन पर शीत युद्ध का प्रभाव दृष्टि रूप से झलकता है। अफ्रीका के अनेक नेता मानसंबाद की खुलकर आलोचना नहीं करते, इसे एक बुराई नहीं कहते। इसके विपरीत यहाँ के अनेक देश अपनी समस्याओं को सुलझान में साम्यवादी देशों के अनुभवों से लाभ उठाना चाहते हैं और कुछ इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। अफ्रीका के सभी राष्ट्र निष्पक्षता अथवा असलपक्षता की नीति में विश्वास करते हैं किन्तु जब ये राज्य अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आते हैं तो इनके व्यवहारों, विचारों एवं व्यापारों में भारी अन्तर आ जाता है। कुछ देशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा सद्भावनाएँ पहले की उपनिवेशवादी शक्तियों एवं पश्चिमी देशों के साथ प्रमुख रूप से जुड़ी हुई हैं, किन्तु कुछ दूसरे अफ्रीकी देशों का झुकाव साम्यवादी देशों के साथ गहरे सम्बन्ध बनाने की ओर होता जा रहा है।

इस प्रकार इस महाद्वीप में अनेकों भिन्नताएँ तथा मतभेद चल रहे हैं तो भी यहाँ के राष्ट्रवादी नेता अफ्रीका का सघ बनाने के पक्ष में हैं। इन

सभी का लक्ष्य यह घोषित किया जाता है कि ये अफ्रीकी लोगों का जीवन-स्तर सुधारना चाहते हैं ; विश्व राजनीति में अफ्रीका का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, शीत युद्ध संधि में अफ्रीका को निष्पक्ष रखना चाहते हैं, सैन्य पराधीन अफ्रीकी राज्यों को स्वतंत्र कराना चाहते हैं तथा अफ्रीका के सभी राष्ट्रों के बीच एकता की स्थापना करना चाहते हैं । ये लक्ष्य कुछ सामान्य प्रकृति के से हैं तथा इनको पूरा नहीं किया जा सकता इसी कारण वर्तमान अफ्रीका के सम्बन्धों पर इनका अधिक प्रभाव नहीं है । तो भी इन लक्ष्यों के कारण अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलनों को पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई है । राष्ट्रपति एनक्रूमा (N. Krumah) को घाना के बाहर प्रायः अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता था किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसने यह आन्दोलन चलाकर इस महाद्वीप के लोगों में जागरण की लहर पैदा कर दी है । इस प्रकार की एकता की प्रेरक शक्तियों में प्रथम तो महाद्वीपव्यापी सामान्य हित है दूसरा क्षेत्रवाद के प्रति आकर्षण है जो अफ्रीकी गुटों को पुनः रूप देने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है । अफ्रीका के देश कभी-कभी प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोतों को मिलाने का मार्ग ढूँढते हैं तथा कभी उपनिवेशवादियों द्वारा स्थापित स्वेच्छाचारी विभाजन रेखा से होने वाले नुकसानों को कम करने की सोचते हैं । आजकल चल रहे समन्वय आन्दोलनों की परिवर्तन का साधन भी माना जा सकता है और इसका प्रतीक भी । इन आन्दोलनों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. Ghana-Guinea-Mali (Union of African States)
2. The Casablanca Powers
3. All-African People's Conferences
4. Conferences of Independent African States
5. All-African Trade Union Federation (AATUF)
6. African Trade Union Confederation (ATUC)
7. The Brazzaville Powers (African-Malagasy Organisation for Economic Co-operation)
8. Conseil de l'Entente
9. The Monrovia Powers
10. The Lagos Meeting of African Heads of State
11. East African Common Services Organisation (Formerly East Africa High Commission)
12. Pan-African Freedom Movement of East, Central, and South Africa (PAFMECSA)
13. Economic and Technical Assistance Organisations.

अफ्रीका के विभिन्न देशों, गुटों एवं समुदायों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है। स्थायी एकता की स्थापना की दिशा में अर्थपूर्ण प्रगति बहुत कठिन है। यहाँ के कुछ देश साम्यवादी शक्तियों का विरोध करने हैं तो दूसरे पश्चिमी देशों को अपने म मलो में हस्तक्षेप करने से रोकते रहते हैं। इस महाद्वीप में दोनों ही गुटों का प्रभाव है किन्तु स्पष्ट रूप से इस प्रभाव को यहाँ का कोई भी देश स्वीकार नहीं करता। इनमें से अधिकांश का कहना यह है कि "वे न तो पश्चिम के समर्थक हैं और न साम्यवाद के ही समर्थक किन्तु वे तो अफ्रीकियों के समर्थक हैं।" यह विश्व के हित में होगा कि वहाँ की राजनैतिक समस्याओं पर बाह्य शक्तियों का अनुचित हस्तक्षेप न रहे और उन पर अफ्रीका के लोगों को ही विचार करने का अवसर दिया जाय। अफ्रीका महाद्वीप की विकास योजनाओं में संयुक्त राष्ट्र सच महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है तथा यहाँ के देश धीरे-धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्व शान्ति इस बात की मांग करती है कि इस महाद्वीप को शस्त्रों की दौड़ में न पटका जाय तथा यहाँ बाहु-शस्त्रों के परीक्षणों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न दिया जाय।

लेटिन अमेरिका का जागरण

(*Resurgence of Latin America*)

लेटिन अमेरिका एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अनेक पिछाईयें देखने को मिलती हैं। यहाँ के समाज में आर्थिक असमानता बहुत है। एक ओर तो बहुत धनवान व्यक्ति हैं तथा दूसरी ओर बहुत गरीब परिवार। इसी प्रकार राजनैतिक दृष्टि से कुछ लोग तो प्रजातन्त्र का गुण गाँव करते हैं किन्तु दूसरे सैनिक तानाशाही में सुन्दर भविष्य की कल्पना करते हैं। इस प्रदेश के देशों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष चला ही रहता है, ये परस्पर झगड़ते रहते हैं फिर भी किसी बाहर के शत्रु से मुकाबला करने के लिये सभी एक हो जाते हैं। यहाँ के राज्यों में कुछ समानतायें भी हैं, वे इन सभी को स्पेन में समान वसोती में प्राप्त हुई है। सभी एक चर्च की पूजा करते हैं। सभी की अपरिहार्य प्राकृतिक बाधाओं का समान रूप से सामना करना होता है। सभी स्वतन्त्रता के पक्षपाती हैं। सभी उत्तरी अमेरिका की भारी शक्ति से परिचिन हैं तथा अधिकांश को तो इस शक्ति का आधिपत्य भी बनना पड़ता है।

'लेटिन अमेरिका' शब्द का अर्थ पश्चिमी गोलार्द्ध के प्रायः उन राज्यों के लिए किया जाता है जो कि लेटिन सभ्यता की समान पृष्ठभूमि रखते हैं। लेटिन अमेरिका को प्रायः तीन मुख्य भागों में बाटा जाता है वे हैं मध्य

अमरीका, इसमें सान गणतन्त्र है, दूसरा कैरीबियन (Caribbean) इसमें तीन गणतन्त्र हैं और तीसरा है दक्षिणी अमरीका, इसमें दस गणतन्त्र हैं । इस प्रकार हम सारे प्रदेश में बीस गणतन्त्र हैं । बाह्य सन्धियों द्वारा प्रशासित द्वीपों को लैटिन अमरीका को परिधि में समाहित नहीं किया जाता है । लैटिन अमेरिका को केवल दक्षिणी अमरीका कहना भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसकी सीमाएँ केवल दक्षिण तक पर्याप्तित न रह कर उत्तर में भी प्रवेश कर जाती हैं । इस प्रदेश की भूमि का क्षेत्रफल समुक्त राज्य अमरीका का लगभग तिगुना है तथा अफीका का तीन चौथाई भाग है । यहाँ की जनसंख्या लगभग डेढ़ करोड़ है और समुक्त राज्य अमरीका की तुलना में करीब एक करोड़ अधिक है । यह जनसंख्या बहुत तीव्रगति से बढ़ती जा रही है और यह अनुमान लगाया जाता है कि १९७५ तक यह बढ़ कर लगभग तीस करोड़ हो जायेगी । यहाँ रहने वालों में भारतीय, स्पेनिश, पुर्तगाली, इटालियन तथा आपानी लोग भी हैं । लैटिन अमेरिका के इतिहास पर दृष्टिगत करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदेश पर स्पेन तथा पुर्तगाल का भारी प्रभाव पड़ा है । इन राज्यों की उपनिवेशवादी सन्धियों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था । राजनैतिक एवं आर्थिक स्वतन्त्रता पाने के पक्षपाती यहाँ के राजनीतिज्ञों पर अमेरिकन प्रान्ति के साहित्य का भारी प्रभाव पड़ा जिसमें स्वतन्त्रता, समानता और मानव अधिकारों पर जोर दिया गया है ।

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद समुक्त राज्य अमेरीका के विचारों एवं राजनैतिक सत्ताओं से इन राज्यों ने प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन ग्रहण किया किन्तु यहाँ के राजनैतिक विचारकों की यह गलती रही कि उन्होंने सत्तरी अमरीका के स्थित लिखित सविधान सरकार का गणतन्त्रात्मक रूप आदि सत्ताओं के सकल संचालन को तो देखा और यह आशा भी की कि इनके अपनाने पर स्थिरता एवं सम्पन्नता प्राप्त की जा सकती है किन्तु उन्होंने यह नहीं देखा कि क्या उनके देश में इन सत्ताओं को अपनाने योग्य अनुकूल परिस्थितियाँ हैं । हमारा परिणाम यह हुआ कि गृह युद्ध छिड़ गया तथा अनेक लैटिन अमरीकी राज्यों को स्वतन्त्रता, तानाशाही और गरीबी आदि अभिशापों की सामना करना पड़ा । बीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक ब्राजील, चिली और अर्जेन्टाइना (Brazil, Chile and Argentina) ही तीन ऐसे राज्य थे जहाँ राजनैतिक स्थिरता एवं प्रजातन्त्रात्मक सत्ताओं ने विकास की आशाएँ की जाने लगी । बाद में कोलम्बिया (Colombia), कोस्टारिका (Costa-rica), मैक्सिको (Mexico), यूराग्वे (Uruguay) आदि राज्य भी इस श्रेणी में आ गये । अर्जेन्टाइना तथा ब्राजील में तानाशाही शासन था गया किन्तु १९५६ में वहाँ पुनः प्रजातन्त्रात्मक सत्ताओं का जन्म होने लगा ।

मैक्सिको में एक दलीय व्यवस्था के साथ विशेषीकृत प्रजातन्त्र (Qualified Democracy) को अपनाया गया। यूरुग्वे (Uruguay) को लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथा विकासशील प्रजातन्त्र वाला देश माना जाता है।

लेटिन अमेरिका से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

(Latin America at Home)

लेटिन अमेरिका के राज्यों की स्थित भिन्नताय तथा अन्य प्राकृतिक बाधाये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनको प्रभावशाली होने से रोकती हैं। इस प्रदेश के राज्यों में आपस में झगडा बना ही रहना है। अधिक झगडे सीमाओं के प्रश्न को लेकर होते हैं। इनक अतिरिक्त रबर, तेल आदि प्राकृतिक साधन भी सघर्ष का कारण बन जाते हैं। इन राज्यों ने अब तक आपस में तीन बड़ी लडाइया लड़ी हैं —

(१) पैरागुआयन युद्ध (Paraguayan war 1865—1870)

(२) प्रशान्त का युद्ध (The war of Pacific 1879—1883)

(३) चाको युद्ध (The Chaco War 1932 — 1935)

ब्राजील की सीमाओं से आठ राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। इन सभी के साथ ब्राजील का नामा सम्बन्धी विवाद था किन्तु उसने युद्ध की अपेक्षा इसको धीरज तथा कूटनीति से सुलझा लिया। सैद्धान्तिक आधार पर इन राज्यों के बीच मतभेद प्रायः नहीं होते। व्यापारिक मतभेदों के परिणाम-स्वरूप परस्पर सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना कर ली जाती है। दक्षिण अमेरिका की दो बड़ी शक्तियां अर्जेन्टाइना तथा ब्राजील के बीच कोई प्रतिस्पर्धापूर्ण अर्थ व्यवस्था नहीं है तथा इन दोनों के सम्बन्ध सामान्य हैं। वैसे कुल मिलाकर लेटिन अमेरिकी राज्यों के आपसी सम्बन्ध अधिक सख्त नहीं रहे हैं। उनका अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध प्रायः शान्तिपूर्ण रहे हैं। इन राज्यों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध नहीं हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लेटिन अमेरिका

(Latin America in International Field)

संसार के अन्य राष्ट्रों में लेटिन अमेरिका का सबसे अधिक तथा गहरा सम्बन्ध अद्यतन राज्य अमेरिका से है। यहां के राज्यों की दृष्टि में अमेरिकन दुनिया की एक शान्तिकारी शक्ति एवं स्वतन्त्रता का प्रतीक था और इसलिए यह तत्कालीन उपनिवेशवादी शक्तियों के लिए एक भारी खतरा था। लेटिन

अमरीका के राज्यों का उनके स्वतन्त्रता आन्दोलनों में यू० एस० ए० द्वारा पूरा समर्थन प्रदान किया गया। इस समर्थन के पीछे उसका हित निहित था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इन राज्यों की मान्यता प्रदान करने वाला सर्वप्रथम देश संयुक्त राज्य अमरीका था। १८२२ में मुनरो सिद्धान्त द्वारा पवित्र सन्धि (Holy Alliance) की सन्धियों को नई दुनिया में उन्मिवेश बनाने के विरुद्ध चेतावनी दे दी गई तथा अमरीकी राज्यों के मामले में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप को सहन न करने की बात कही गई। लेटिन अमेरिका के राज्यों में इस सिद्धान्त के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया हुई।

औपचारिक रूप से निष्पक्ष रहते हुए भी संयुक्त राज्य अमेरिका इन नवीन राष्ट्रों का सबसे प्रमुख बाहरी मित्र (Outside Friend) था। १९०४ में यू०एस०ए० ने पनामा के साथ हे-बुनाउ-वरीला (Hay-Bunau-Varilla) की संधि की जिसके अनुसार नहर की रक्षा के लिए वह देश राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता था। इस प्रकार संरक्षित राज्यों (Protectorates) का समय प्रारम्भ हुआ। डोमोनिकन गणराज्यों को १९०५ से १९२४ तक अधिकार में रखा गया। निकारा गुजा, हैटी (Haiti) आदि पर यू०एस०ए० का भरपूर प्रभाव बना रहा। यू०एस० ने अमरीकी सहयोग से स्वतन्त्रता प्राप्त की थी अतः उसे भी स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की अनुमति न दी गई। इन चार राज्यों पर अमरीका का सैनिक प्रभाव रहा। बुडरो विलसन के समय अमरीकन भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ तथा संरक्षित अमरीकन साम्राज्यवाद का पतन होने लगा और अच्छे पड़ोसियों के से सम्बन्धों की सृष्टि हुई। फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट (Franklin D. Roosevelt) के राष्ट्रपति बाल में लेटिन अमरीका के राज्य हैटी (Haiti) पर से अमरीका के अन्तिम प्रभाव को भी हटा लिया गया। इसके बाद इन दोनों के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का जन्म होने लगा। रूजवेल्ट के राष्ट्रपति काल में पश्चिमी गोलार्द्ध की सुरक्षा, सम्पन्नता एवं सद्भावना की दृष्टि से अनेक कार्य किये गये। अमरीका में भ्रातृत्व के भाव विकसित करने के लिए अनेक सम्मेलन हुए। स्टुअर्ट (Graham N. Stuart) के शब्दों में "राजनैतिक क्षेत्र में पूर्ति करने के लिए अमेरिकन भ्रातृत्व के सम्मेलनों का इक्कीस गणतन्त्रों के बीच उपयोग के अभिकरणों के रूप में उपयोग किया गया।"

आईजनहावर (Eisenhower) प्रशासन में यू० एस० ए० द्वारा लेटिन अमेरिका के राज्यों को काफी तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। संयुक्त राज्य अमरीका के निकटतम पड़ोसी तथा घनिष्ठ सम्बन्धी होने के कारण लेटिन अमेरिका के राज्यों का इसके लिए बहुत महत्व है। इन राज्यों

मे साम्यवाद का प्रसार स्वयं यू० एस० ए० की सुरक्षा के लिए एक चुनौती बन जायेगा। इसी आधार पर राष्ट्रपति केनेडी द्वारा क्यूबा के प्रश्न पर दृढ़ निर्णय लिया गया था। क्यूबा में साम्यवादो सैनिक चौकिया स्थापित हो जाना अमरीका के हिन्ने एव सुरक्षा पर एक गहरा आघात था, इसका विरोध करने के लिए अणु दस्तों के प्रयोग तक की चुनौती दे दी गई।

जहाँ तक लेटिन अमरीका के राज्यों तथा योरोप के देशों के सम्बन्ध का प्रश्न है इस पर यह कहा जाना है कि प्रारम्भ से ही योरोप के देशों ने यहाँ उपनिवेश बना रखे थे। इन राज्यों ने स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने के बाद योरोप की शक्ति राजनीति में बहुत कम भाग लिया किन्तु रिगत दोनों ही महायुद्धों में इनका सश्रिय सहयोग रहा है। यहाँ के अधिकांश राज्यों पर स्पेन की सत्कृति का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है अतः स्वतन्त्रता के बाद स्पेन के साथ इनके सम्बन्ध गहरे हो गये। स्पेन में फ्रांको शासन के प्रति लेटिन अमेरिका के राज्यों में मतभेद था इससे ये सम्बन्ध कुछ कमजोर पड़े। ब्राजील तथा पुर्तगाल से इनके सम्बन्ध सदा ही मित्रतापूर्ण रहे हैं। यहाँ के राज्यों के फ्रांस के साथ प्रारम्भ से ही अच्छे सम्बन्ध नहीं रहे हैं किन्तु फ्रांस की सत्कृति का प्रभाव यहाँ बहुत अधिक है। यहाँ की भाषा, साहित्य, कला, फैशन, पहनाव आदि पर फ्रांस का प्रभाव स्पष्ट है। जर्मनी के साथ लेटिन अमरीका के सम्बन्ध प्रायः आधिक्य रहे हैं। हिटलर के साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद इन देशों पर नुरा प्रभाव पड़ा।

निम्न भविष्य में लेटिन अमरीका के राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बढ़ जायेगा। इस सम्भावना के पीछे अनेक कारण हैं, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं—

- (१) इस क्षेत्र की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है।
- (२) यहाँ अच्छे मात्रा का मन्ने अधिक उत्पादन होता है।
- (३) यह अमेरिकन राज्यों के संगठन (OAS) का एक बड़ा भाग है।
- (४) इस प्रदेश के राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सम्था में जो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं वे अत्यन्त कुशल तथा तीव्र बुद्धि के राजनीतिज्ञ होते हैं।
- (५) ये राज्य समुक्त राष्ट्र मण, अमरीकी राज्यों के संगठन तथा अमेरिका के संयोग में ओद्योगीकरण एवं मशीनीकरण करने में लगे हुए हैं।

लेटिन अमेरिका की प्रगति में उक्त आशा के विन्हो के अतिरिक्त मार्ग की अनेक बाधाएँ भी हैं जो इस क्षेत्र के विकास की राह को घीसा बनाती हैं। ये निम्नलिखित हैं—

(१) इन राज्यों की भौगोलिक बनावट के कारण एक दूसरे के बीच आवागमन के साधन स्थापित करना तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाना मुश्किल है।

(२) इस प्रदेश के अधिकांश राज्यों में बहुत समय से राजनैतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार तथा अप्रजातान्त्रिक व्यवहारों का बोलबाला है।

(३) इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के साथ मेल ही नहीं हो पाता। व्यक्ति की स्वतन्त्रता तथा आर्थिक विकास दोनों से युक्त अर्थ व्यवस्था का इन राज्यों में अभाव है।

(४) इन राज्यों में लोगों की सामाजिक स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है, अधिकांश लोग गरीबी तथा अशिक्षा में ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रंग भेद की नीति के कारण व्यक्ति की समानता का सिद्धांत नियाँवित नहीं हो पाता।

(५) रोमन कैथोलिक चर्च के महत्व के सम्बन्ध में इन देशों में भारी बाध-विवाद है। कुछ कहते हैं कि चर्च को राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये किन्तु दूसरों का विपरीत मत है। दक्षिण अमेरिका में जब स्वतन्त्रता के लिए युद्ध किया गया था तो चर्च ने स्पेन का समर्थन किया था। यह बात अभी तक इन राज्यों को याद है किन्तु फिर भी चर्च के समर्थक वर्ग के अनुयायी प्रतिशियावादी प्रवृत्तियाँ रखते हैं।

(६) इन राज्यों पर समुक्त राज्य अमेरिका का भारी प्रभाव रहता है और यही प्रभाव के कारण इस क्षेत्र के राजनैतिक एवं आर्थिक जीवन पर अनेक नुकसानदायक प्रभाव पड़ते रहते हैं।

(७) साम्यवाद का प्रभाव इन राज्यों पर धीरे-धीरे बढ़ना जा रहा है। इसके पूर्व यहाँ फासीवादी प्रवृत्तियों का जोर था किन्तु साम्यवाद ने आसानी से उसके स्थान को ग्रहण कर लिया क्योंकि—

(i) महा प्रजातन्त्र का बोना पहने हुए फासीवाद है, (ii) यह एक जाति की सर्वोच्चता पर जोर नहीं देता, (iii) यह वर्ग पर आधारित नहीं है। स्टुअर्ट का कहना है कि “लेटिन अमेरिका के गणतन्त्र में प्रजातन्त्र की अपेक्षा साम्यवाद के शास्त्रात्मक अर्थ प्रभावपूर्ण हैं क्योंकि महा विदेशी पूँजीपतियों अथवा राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों द्वारा जनता का शोषण एक सामान्य बात हो गई है।” लेटिन अमेरिका के साम्यवादी नेताओं पर सन् १९३० से

कॉमिन्टर्न (Comintern) का प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हो गया । ब्राजील, चिली (Chile), अर्जेन्टाइना, मेक्सिको, क्यूबा आदि राज्यों में साम्यवादों ने ज़ात शक्ति प्राप्त करने लगे । ग्वाटेमाला (Guatemala) की विजय लेटिन अमेरिका में साम्यवादियों की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है । इन सभी सफलताओं के बाद भी लेटिन अमेरिका में साम्यवाद का महा-उहा योड़ा बहुत प्रभाव है, किन्तु इसको पश्चिमी देशों द्वारा कोई गम्भीर चुनौती नहीं समझी जाती । समुक्त राज्य अमेरिका ने अनेक बहुपक्षीय सन्धियों द्वारा लेटिन अमेरिका के राज्यों को हथियार तथा सैनिक मिशन भेजे हैं । सभी सदस्यों की सहमति से अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) ने यहा साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए अनेक कदम उठाये हैं ।

(८) लेटिन अमेरिका के विकास की सबसे बड़ी बाधा यह मानी जाती है कि यहा के लोगों में सामाजिक चेतना नहीं पाई जाती । इस प्रदेश में अभी तक किसी ऐसे नेतृत्व का जन्म नहीं हुआ है जो सारे प्रदेश का मत अपने साथ कर विश्व राजनीति में उसका प्रयोग कर सके ।

यूरोप के लिए चुनौती

(The Challenge to Europe)

एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के देशों का उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना तथा वहा एक नवीन जागरण की उपस्थिति यूरोप के अविकास देशों के लिए एक चुनौती बन गया है जिसका सामना करने के लिए इन्हें बाध्य होना पड़ेगा । जैसे माला का सूत्र टूट जाने के बाद उसके मोतियों की एकबद्धता समाप्त हो जाती है उसी प्रकार इन महाद्वीपों एवं प्रदेशों में से साम्राज्यवाद के विस्तार वध जाने के बाद इनके बीच अनेक प्रकार के झगड़े तथा उपद्रव पैदा हुए हैं । उपनिवेशवादी शक्तियाँ जब उनके विस्तार की सीमा पर पहुँच गईं तभी उनकी महानता की भी सीमा रेखा आ गई । ठीक उसी प्रकार जैसे कि जब समुद्र में ज्वार आता है और वह बहुत ऊँचा उठ जाता है तब उसमें भाटा आना प्रारम्भ होता है । मॉर्गेन्थौ (Morgenthau) का कहना है कि 'यूरोपीय राष्ट्रों का राजनैतिक एवं आर्थिक क्षय ही उपनिवेशी शक्ति का कारण तथा बहुत कुछ इसका परिणाम रहा है ।' यूरोप की शक्तियों का पतन उपनिवेशों के लिए शक्ति और प्रेरणा का एक स्रोत बन गया । द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने यूरोप की प्रमुख शक्ति को हरा दिया तो उपनिवेशों में आत्मविश्वास की चिनगारी सुलगी और यह चिनगारी बढ़ते-बढ़ते एक सफल अवकाश प्रभावशील शक्ति के रूप में बदल गई । ग्रेट ब्रिटेन ने स्वेच्छा से ही बर्मा, लद्दा, पाकिस्तान, भारत और

भिन्न की आजाद कर दिया। फ्रांस ने इन्डोनाइया में तथा ब्रिटेन ने मलाया में कब्जाई लड़ी थी। इसका कारण यह नहीं है कि वे वहाँ की सत्ता अपने पास रखना चाहते थे वरन् यह है कि वे सत्ता को मनचाहे हाथों में सौंपना चाहते थे। उपनिवेशी शान्ति वे, जो योरोप की कमजोरी की उपज है, योरोप और भी अधिक कमजोर बना दिया। आधुनिक काल तक योरोप को एक बड़ी शक्ति माना जा रहा है इसका प्रमुख कारण यह है कि इसने रणयुक्त जातिपों पर आधिपत्य जमा रखा था। तकनीकी, आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों से भिन्न था और इसी आधार पर उसने यहाँ शासन किया। किन्तु आज यह अन्तर न के बराबर रहता जा रहा है तथा अब योरोप की शक्ति का सैनिक, आर्थिक, राजनैतिक स्रोत सूखता जा रहा है जिसके कारण वे सस्या, स्थान तथा प्राकृतिक साधनों की कमी से उत्पन्न हीनता की भावना को दबा सकते थे।

जैसा कि अन्य सभी शान्तियों द्वारा किया जाता है उपनिवेशों की इस शान्ति का आधार नैतिक है तथा यह पश्चिमी राष्ट्रों के सामने एक नैतिक चुनौती प्रस्तुत करती है। एशिया के द्वारा जो नैतिक चुनौती दी गई है वह एक प्रकार से पश्चिमी विचारों की विजय है। यह दो नैतिक सिद्धान्तों के मधीन आगे बढ़ती है; ये हैं—राष्ट्रीय आत्म-निर्णय तथा सामाजिक न्याय। योरोप के देशों में जब एशिया के देशों में पदार्पण किया तो वे अपने साथ केवल तकनीकी ज्ञान तथा राजनैतिक सस्या ही लेकर नहीं आये थे वरन् राजनैतिक नैतिकता के सिद्धान्त भी उनके साथ थे। पश्चिम ने ही अपने उदाहरण प्रस्तुत करके एशिया के लोगों को स्वतन्त्रता के लिए लड़ना सिखाया। पश्चिम ने यहाँ एक मंत्र फूँका कि गरीबी तथा दुःख ईश्वर प्रदत्त नहीं है किन्तु मनुष्यकृत है तथा इनको प्रयास करके दूर किया जा सकता है। आज एशिया तथा अफ्रीका के देश पश्चिमी नैतिक मापदण्डों के आधार पर ही उनकी वर्तमान राजनैतिक एवं आर्थिक नीतियों के विरुद्ध शान्ति कर रहे हैं तथा इनको दुरा-मला कह रहे हैं।

एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका के नव जागरण से पश्चिमी देशों को जो चुनौतियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण साम्यवाद के प्रसार को माना जाता है। इन महाद्वीपों में साम्यवाद के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है तथा ये देश इसके सुभावने आश्वासनों की ओर बड़ी शीघ्रता से आकर्षित होते तथा हो सकते हैं। इन देशों का आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक विकास करने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए पश्चिमी शक्तियों को यथाशक्ति

सहयोग देना होगा, ऐसा करके ही वे इन क्षेत्रों से साम्यवाद को अलग रख सकते हैं। इस प्रकार एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में परिचयी राज्यों के हित अटक रहे हैं। इन महाद्वीपों में विकासशील देशों की आवाज का महत्व एवं प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। मधुन राष्ट्र सभ में इनकी दूतनी अधिक सग्या है कि उनके मत की अवज्ञा नहीं की जा सकती। परिवर्तन के देशों के इन महाद्वीपों के निवासियों ३ प्रति अपने पूर्वं दृष्टिकोणों में एक क्रान्तिवारी परिवर्तन करना है। आवश्यकता यह है कि वे इन देशों के विकास कार्यों में मयासम्भव हर प्रकार की सहायता करें, इनके साथ समानता का व्यवहार करें तथा अपनी सर्वोच्चता की भावना का परिष्कार करके महा के लोगों के मत, आशा एवं महत्वाकांक्षाओं का आदर करना सीखें।

सोवियत संघ का उदय और उसकी विदेश नीति

(RISE OF SOVIET UNION AND ITS FOREIGN POLICY)

१९१७ की क्रान्ति के फलस्वरूप जो सोवियत व्यवस्था स्थापित हुई उसके कुछ ही महीनों बाद सत्कार के पूजोवादी राज्यों ने मिल कर रुस के नवीन शासन का गला घोटने और उनका नामोनिशान मिटाने के विपुल प्रयास किये। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में यह एक अद्वितीय घटना थी। यदि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना पूजोवादी राज्यों की ओर से नहीं हुई होती तो सम्भवतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत संघ की नीति आज कुछ दूसरी ही होती। इनमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत व्यवस्था की तथा-नूतन गठोरता और सोवियत परराष्ट्र नीति में सकल तथा सम्यक् के सर्वो के लिए पूजोवादी राष्ट्र ही एक बहुत बड़े अड़सत उतरावापी हैं। पर प्रश्न यह उठता है कि जातिपर पश्चिमी पूजोवादी राष्ट्रों ने इस प्रकार की नीति का माध्यम क्यों लिया? इन नीति का माध्यम उन्होंने इसलिए लिया कि १९१७ की क्रान्ति राज्य प्रभुता के सिद्धान्त को एक शाकेनशाही चुनौती थी, क्योंकि सोवियत संघ की नई व्यवस्था प्रवृत्ति और उद्देश्यों में अन्तर्राष्ट्रीय थी जिसका उद्देश्य सत्ताज्वाद के एक ऐसे नये युग का प्रारम्भ करना था जो पूजोवादी राष्ट्रों की जड़ पर अपना अध्यमूल गढ़ा कर सके। पश्चिमी राष्ट्रों के लिये इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य एक सुली चुनौती थी जिसका मुकाबला करना वे अग्रे हित के लिए आवश्यक समझते थे।

स्पष्ट है कि नवोदित सोवियत सरकार चारों तरफ से आन्तरिक और बाह्य खतरों से घिरी हुई थी। रुस के तत्कालीन साम्यवादी शासन की सबसे

बड़ी कामना यही थी कि सत्तार के अन्य राज्य सोवियत रूस को अपनी नीति के अनुसार अपने देश का निर्माण करने और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिये स्वच्छन्द छोड़ द। किन्तु जब साम्यवादी शासकों ने पाया कि पूँजीवादी राज्यों को जब भी मौका मिलेगा वे परस्पर मिल कर या अकेले ही सोवियत सघ का सर्वनाश करने से बाज न आयेंगे तो उन्होंने एक ऐसा मार्ग ग्रहण किया कि रूसी सकटापन्न विकास के पुराने सिद्धान्तों अर्थात् आत्मरक्षा और सुरक्षा की नीति को और बापिस लौटा जाए और पश्चिमी प्रभाव से मुक्त देशों के साथ संधिया की जाए।

अपने उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोवियत शासन ने इस कहावत को सिद्ध किया कि "राजनीति वैश्या की तरह अनेक रूप बदलने वाली होती है।" सोवियत शासकों ने साम्यवादी क्रान्ति से लेकर द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सोवियत कूटनीति को अनेक रूप दिये।

७ नवम्बर, १९१७ की बोलशेविक क्रान्ति के बाद सोवियत कूटनीति द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने तक विभिन्न अवस्थाओं में से होकर गुजरी।

प्रथम अवस्था (१९१७-१९२१) पश्चिमी राष्ट्रों के साथ उग्र विरोध और समस्त विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार करने की थी। सोवियत शासन के प्रारम्भिक ४ वर्ष केवल अपने अस्तित्व को कायम रखने के उस सघर्ष में व्यतीत हुए जो रूसी इतिहास का सम्भवतः समाज से अधिक निराशापूर्ण सघर्ष था जिसमें मन्तव्य ट्रॉट्स्की द्वारा सगठित लाल सेना साम्यवादी शासन को स्थायित्व प्रदान करने में सफल हुई।

द्वितीय अवस्था (१९२१-१९३४) रक्षात्मक पार्श्वक (Defensive Isolation) की थी। इस काल में रूस ने आत्मरक्षा की दृष्टि से विभिन्न शक्तियों के साथ संधिया सम्पन्न की, उनसे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाये और दूसरे देशों में साम्यवादी प्रचार करना कम कर दिया। इस अवस्था में वह सामान्यतः पश्चिमी देशों की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहा और राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी उसने ग्रहण न की। इस अवधि में यद्यपि रूस ने पूँजीवादी राज्यों से समझौते करने की नीति का अनुसरण किया, परन्तु कोमिन्टर्न द्वारा अन्य देशों में साम्यवादी क्रान्ति फैलाने के प्रयत्नों के कारण पश्चिमी राज्य रूस को अविश्वास और सन्देह की दृष्टि से देखते रहे। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका १९३३ से पूर्व रूस को वैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए उद्यत नहीं हुआ। किन्तु रूस की अधिक समय तक उपेक्षा करना सम्भव न था। रूस अब कोई सामान्य शक्ति नहीं रह गया

था। वह अन्तर्राष्ट्रीय सन्निहित में एक महान् शक्ति के रूप में उदित हो चुका था। अब जब रूस ने अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो उसने सोवियत संघ की मान्यता प्रदान करने की दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिये। नवम्बर में विश्व-अर्थ-सम्मेलन (१९३३) के अवसर पर सर्वप्रथम अमेरिकन प्रतिनिधि विलियम बुन्डि और रूसी प्रतिनिधि लिटविनोव को मुलाकात हुई। इनके बाद दोनों देशों के मध्य एक सन्धि सम्पन्न हुई जिसके द्वारा दोनों सरकारी ने एक दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा का और विरोधी प्रचार करने वाले दलों के दमन का बयन दिया। रूस ने अमेरिका की यह बात मान ली कि अपने देश में आने वाले अमेरिकन यात्रियों को वह धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करेगा। इस सन्धि का यह अनिवार्य परिणाम हुआ कि रूस की साम्यवादी सरकार को संसार की सभी महान् शक्तियों ने स्वीकार कर लिया।

तीसरी अवस्था (१९३४-१९३८) के काल में रूप राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना और साथ ही उसने पश्चिम के साथ सहयोग करने की नीति का आश्रय लिया। राष्ट्रसंघ में प्रवेश के बाद मई, १९३५ में रूस ने अपने पिछले सभी मतभेदों एवं सगठनों को भुलाते हुए फ्रांस के साथ पारस्परिक सहायता का १८६४ जैसा सैनिक समझौता किया। इसके बाद पोलैण्ड तथा बाल्टिक राज्यों के साथ भी रूसो ने अनाकण्ठ समझौते किये तथा टर्की और ग्रेट ब्रिटेन से घनिष्ठता बढ़ाई। १६ मई, १९३५ को बंकोस्लोवाकिया के साथ भी उसकी सन्धि हुई। इस तरह रूस ने फ्रांस एवं बंकोस्लोवाकिया के सहयोग से नाजी आक्रमण के विरुद्ध संघ का संगठन सुदृढ़ किया। मार्च, १९३६ में ब्राह्म मंगोलिया के साथ एक पारस्परिक सहायता सन्धि की गई जिसका उद्देश्य आन्तरिक मंगोलिया में जापान के प्रवेश को रोकना था। इस समय तक रूस पश्चिम एक विशाल शक्ति सम्पन्न देश बन चुका था।

इन सभी समझौतों और सन्धियों से रूस की स्थिति पर्याप्त रूप से दृढ़ हो गई। इस समय रूसी साम्यवादी नीति ने एक और भी नया क्रान्तिकारी मोड़ लिया। देश तथा विदेश दोनों में १९३४-३५ में "कॉमिन्टर्न" (Comintern) में यथायक एक उबाल उठा। विश्व क्रान्ति की नीति के प्रतिकूल रूस ने पारंपरिक लोकतन्त्रीय राज्यों में साम्यवादियों को फासिस्ट घातन का विरोध करने वाले बुजुर्गों, दलों-उदारवादी, समाजवादी आदि के साथ मिल कर संयुक्त मोर्चा (United Front) बनाने को कहा। फलस्वरूप अब प्रत्येक देश के साम्यवादी दलों ने अन्य प्रगतिशील तत्वों के साथ फासिस्टवाद के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा स्थापित किया। वास्तव में रूसी विदेश नीति में यह एक बिल्कुल नया परिवर्तन था क्योंकि जो समाजवादी, उदारवादी आदि उपरोक्त सभी दल "पूजोवाद" के विरुद्ध "कहे जाते थे, वे १९३४ के

वाद जब "साम्राज्यवाद के विरुद्ध किये जाने वाले अभियान में बहुमूल्य सहयोगी" समझे जाने लगे ।

१९३४ से १९३८ तक सोवियत रूस ने पश्चिमात्य देशों के साथ सहयोग और मैत्री की नीति तो अपनाई, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से रूस और पश्चिम के मध्य कोई वास्तविक मित्रता स्थापित न हो सकी । हा, पश्चिमी जनतन्त्र अवश्य ही फासिज्म को साम्यवाद के विरुद्ध तथा साम्यवाद को फासिज्म के विरुद्ध करने की अपनी युक्तियों में सफल हुआ और फासिज्म का हर स्थान पर विरोध करना रूसी नीति का एक मुख्य विषय बन गया । रूस अब पश्चिमी देशों के मैत्री सम्बन्धों पर टिप्पणी करत हुए शुमन (Schuman) ने ठीक ही लिखा है "इस उद्देश्यपूर्ण मैत्री भाव में पारस्परिक विश्वास का अभाव था ।" वास्तव में पश्चिमी राष्ट्रों का विश्वास था कि रूस का उद्देश्य अन्तिम रूप में पूँजीवाद का विनाश करना है । इसलिए उसकी मित्रता केवल एक दिखावा मात्र है । परिणामतः वे फासिस्ट शक्तियों को साम्यवाद विरोधी तत्त्व समझकर दबावा देने की नीति पर चलते रहे । ऐसे तीन प्रमुख अवसर आये जब पश्चिमी राष्ट्रों की नीति से स्पष्ट हो गया कि वे आगे वक़्त में रूस का साथ देने को तैयार नहीं हैं, उन्हें रूस पर विश्वास नहीं है और फासिस्ट आक्रमणों को रोकने की अपेक्षा उन्हें रूसी साम्यवाद को रोकने में अधिक दिव्यता है । पहला अवसर इटली-एथियोपिया युद्ध था । इसमें रूस ने राष्ट्रमण्डल के माध्यम से मुसोलिनी के वर्चस्व आक्रमणों में अहिंसक अवरोध की रक्षा का भरसक प्रयास किया लेकिन ब्रिटन और फ्रांस ने एथियोपिया तथा राष्ट्रमण्डल की बलि देकर भी मुसोलिनी की रक्षा की । दूसरा अवसर स्पेनिश गृहयुद्ध का था । इस अवसर पर रूस ने स्पेन की जनतन्त्रीय सरकार को सहायता भेजी और एंग्लो—फ्रांसीसी सरकारों से भी फासिस्टवादी फूँकों को सहायता ली । स्टालिन ने अपने वक्ताव्यों से इस बात का स्पष्ट आभास दे दिया कि रूस को पश्चिमी शक्तियों से सहयोग की आशा करना पूरी भ्रम-मरीचिका थी ।

चौथी अवस्था (१९३८-१९३९) में रूस ने पश्चिमी राष्ट्रों से दूर रहने एवं सकटपूर्ण पार्श्वक (Dangerous Isolation) की नीति अपनायी । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि पश्चिमी शक्तियों के राजनीतिज्ञों ने इस समय तक रूस को न केवल अपने कंधे से निकाल बाहर किया था, बल्कि पश्चिम की ओर की सोवियत कूटनीतिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को बिल्कुल से उखाड़ दिया था, सितम्बर, १९३८ के म्यूनिख के समझौते के बाद ही रूस ने बर्लिन अपने आस-पास सफाई करने में पाया । रूस का कोई विश्वासपात्र मित्र नहीं था । फ्रांस पर अब कोई विश्वास नहीं किया जा सकता था और ब्रिटन

का मास्को की अपेक्षा बर्लिन की ओर अधिक झुकाव था। इस इस बात की मजबूत भावना थी कि पश्चिमी सक्तिवादी जर्मनी को इस पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब इस पश्चिमी की तरफ से निराशा हो गया तो उसने अपनी आत्म-रक्षा के घुरी राष्ट्रों की मंत्री के प्रयास से कर दिये और अगस्त, १९३६ में जर्मन सोवियत अनाक्रमण समझौता हो गया। पश्चिमी राष्ट्रों के लिए सोवियत अक्रमण समझौता एक चक्रपात के समान था। उन्होंने यह आरोप लगाया कि "यह समझौता पश्चात्य लोकतन्त्रों के साथ उनके मंत्री का विश्वासपात, शांति के मोर्चे का विघटक और सोवियत कूटनीति के दुरूपेण का परिचायक है। उसने यह समझौता इसलिए किया है कि इसके परिणामस्वरूप पश्चिम और जर्मनी प्राणान्तक संघर्ष में जुटकर खीन हो जाए तथा संसार में साम्यवाद की प्रभुता स्थापित हो सके, इस को पोलैण्ड के तथा बाल्टिक राज्यों के प्रदेश प्राप्त हो सकें। परन्तु इस प्रकार के आरोप लगाते समय पश्चिमी राष्ट्र यह भूल गये थे कि वास्तव में ऐसे किसी भी समझौते के लिए वे स्वयं उत्तरदायी थे। वे बार-बार जर्मनी को एक साम्यवाद विरोधी शक्ति मान कर प्रोत्साहित कर रहे थे और उसे सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। विश्वासपात का आरम्भ उन्होंने के द्वारा हुआ था।

यद्यपि इस ने जर्मनी के साथ अनाक्रमण समझौता कर लिया, तथापि यह जर्मनी के इरादों को भाप कर उसके विरुद्ध अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए निरन्तर तैयारी करता रहा। सितम्बर, १९३६ में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। इस महायुद्ध के आरम्भ में तटस्थ बना रहा किन्तु अपनी सम्पूर्ण कूटनीतिक सावधानियों के बाद भी वह जून, १९४१ में अपने ऊपर जर्मनी के आक्रमण की नहीं रोक सका। इस आक्रमण में समस्त घुरी राष्ट्रों की मानव शक्ति और स्रोत कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय के अग्निप्रेतों के रूप में सोवियत नेताओं ने अपनी पोशाक बदली और अब वे नाजो जर्मनी के सहायक न होकर राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ बन गए तथा प्रजातन्त्रात्मक ब्रिटेन का समर्थन करने लगे। १३ जुलाई १९४१ को सोवियत संघ और ब्रिटेन ने एक पारस्परिक सहायता समझौता किया जो मई, १९४२ में औपचारिक आल-सोवियत संधि के रूप में परिणत हो गया। २४ सितम्बर, १९४१ को सोवियत संघ ने अटलांटिक चार्टर को स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि सोवियत संघ अपनी विदेश नीति को राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के सिद्धान्त द्वारा निर्देशित करता था और करता है। यह प्रत्येक देश की स्वतन्त्रता व प्रादेशिक अखण्डता के अधिकार की रक्षा करता है तथा उसके इस अधिकार को मानता है कि यह अपने उपयुक्त सामाजिक

व्यवस्था एवं सरकार का रूप निश्चित कर ले। १ जनवरी, १९४२ को सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करके धुरी राष्ट्र विरोधी संधि में औपचारिक रूप से अपने आपको मिलाया।

जर्मन प्रचार न रूसी आक्रमण को बोल्शेविज्म के विरुद्ध समस्त यूरोप का संघर्ष बताया। अधिष्ठित रूस एवं पूर्वी यूरोप में जर्मनी की नीति केवल साम्यवाद विरोधी नहीं थी बरन वह रूस विरोधी भी थी। इसके कारण साक्षित नवाभो का साम्यवाद एवं रूसी राष्ट्रवाद में एकता स्थापित करनी पनी। रूस ने मार्क्सवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रचार को घटा कर रूसी तथा राष्ट्रवादी प्रचार की मात्रा को बढ़ा दिया। इस प्रकार द्वितीय साम्राज्यवादी युद्ध को सोवियत रूस ने प्रचार द्वारा महान् देशभक्तिपूर्ण युद्ध के रूप में परिणत कर दिया। युद्ध की दशभक्तिपूर्ण प्रकृति को सिद्ध करने के लिए औपचारिक रूप से कमिन्टर्न को मई १९४३ में समाप्त कर दिया गया और इसके कर्तव्य सोवियत साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति के विदेशी विभाग को सौंप दिए गए। युद्ध के समय संधि ने भी साम्यवादी सरकार को राष्ट्रवाद के नाम पर समर्थन प्रदान किया। इन सब घटनाओं से सोवियत सरकार की नीति और तकनीकी ने क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिए और यह समझा जाने लगा कि अब यह नाति अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन की अपेक्षा राष्ट्रवादी आन्दोलन की ओर मुड़ गई है।

युद्ध के सोवियत लक्ष्य (The Soviet War Aims)

सोवियत संधि द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता था और उसे क्या मिला, इन दोनों के बीच सम्बन्ध देखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सोवियत राजनीति में उसका उद्देश्यों का पता लगाना अत्यन्त प्रायः है। युद्ध के दौरान सोवियत सरकार द्वारा प्रचार के लिए कोई निश्चित कार्यक्रम अपनाया गया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। साक्षित संधि के युद्ध के लक्ष्यों की इस संनिध और कूटनीतिक कार्यों द्वारा ही जाना जा सकता है। कई एक पयवश्यों का कहना है कि सोवियत नेता जारगाही साम्राज्यवादी लक्ष्यों से प्रेरित थे। इसका जर्म यह नहीं है कि वे उनके पद चिन्हों पर हो चल रहे हों। किन्तु फिर भी जारगाही के द्वारा सोवियत रूस के हितों का और जनता की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता था, इसलिए उसे अपनाया जाना उपयोगी था। रूस ने युद्ध के द्वारा पहले तो उन प्रदेशों को पान का प्रयास किया जो जारगाही के समय दूसरे देशों द्वारा ले लिए गए थे। मुद्दर पूर्व में रूसी आपापी युद्ध में हार के कारण

जर्मनी ने अनेक प्रदेशों से अधिकार छोड़ दिया था। एत प्रसारवादी उद्देश्यों के साथ-साथ सोवियत सरकार ने युद्ध से कुछ एक ऐसे लक्ष्य प्राप्त करने की भी चेष्टा की जो जर्मनी सरकार द्वारा रूसी साम्राज्य के हित में नियोजित किए गए थे किन्तु प्राप्त नहीं किए जा सके। इन उद्देश्यों में पहला यह था कि यूरोप में प्रभाव का क्षेत्र इतना अधिक बढ़ाया जाए कि वह सोवियत विराटी और कूटनीति में सुरक्षित रह सके। दूसरे, काते धागर के दर पर नियंत्रण किया जाए और तीसरे, निकट मध्य एश भुद्ध पूर्व में तथा विश्व में हर जगह सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ाया जाए, जब भी पभी ऐसा करने के लिए अवसर प्राप्त हों।

प्रत्येक विदेशी साम्यवादी का यह कर्तव्य माना गया कि वह अपने पूरे प्रभाव से प्रत्येक सोवियत सैनिक एवं कूटनीतिक का समर्थन करे। ऐसा करते समय यदि उसे अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की अवहलना भी करनी पड़े तो वह पीछे न हटे क्योंकि सोवियत सरकार के लक्ष्य एवं उद्देश्य सर्वोच्च हैं और वह विश्व साम्यवादी आन्दोलन की आत्मा है। वैसे सोवियत नेताओं की विदेशी साम्यवादियों के प्रयासों का अधिक भरोसा एवं विश्वास नहीं था किन्तु फिर भी वे प्रसारवादी कूटनीति को अपनाये रखना चाहते थे। उनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए एक युद्ध नहीं था बल्कि यह तो एक ऐतिहासिक सोनान था जिससे कि दुनिया साम्यवाद की ओर मुड़ सके। स्टालिन ने युद्ध की प्रवृत्ति पर अपना विचार प्रकट करने हुए कहा कि यह युद्ध अन्तर्जातीय युद्धों की भांति नहीं है। इसमें जो कोई भी जिस प्रदेश पर अधिकार कर ले उस पर अरब स्वयं की सामाजिक व्यवस्था की लाद देगा। जहां तक उनकी सेनाएं पहुँच सक्ती हैं वहां तक वह अपनी सामाजिक व्यवस्था लागू कर सक्ती है। स्टालिन का कहना था कि “अब युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और हम पन्द्रह-बीस वर्षों में क्षतिपूर्ति कर पाएंगे और इसके बाद पुन संपर्क स्तिडेगा।” इस प्रकार सोवियत नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में यद्यपि विश्व साम्यवाद का प्रचार किया किन्तु उनका मुख्य ध्यान सोवियत संघ की राजनैतिक शक्ति पर था। उन्होंने सवर्गता के साथ अपने सैनिक एवं कूटनीतिक कार्यों को समन्वित किया।

युद्धकालीन सोवियत कूटनीति

(Soviet War time Diplomacy)

दिसम्बर सन् १९४१ में ग्रेट ब्रिटेन के विदेश सचिव एम्पनी ईडन मारको गए और इस प्रकार सोवियत नेताओं की परिचामी मित्रों के साथ उच्च स्तर के सम्मेलन का प्रथम तबसर प्राप्त हुआ। इस समय साल सेना ने जर्मनी

के सैनिकों को मास्को के दरवाजों पर रोका ही था किन्तु सोवियत सत्ता का अस्तित्व अब भी सदिग्ध था। फिर भी इस सम्मेलन के दौरान स्टालिन अपनी अन्तिम विजय के प्रति आश्वस्त था। स्टालिन ने इस सम्मेलन में युद्ध के बाद की स्थिति पर विचार करने पर जोर दिया किन्तु यहाँ ईडन ने यह बताया कि ग्रैंट ब्रिटेन सीमा सम्बन्धी प्रश्नों पर युद्ध के बाद ही विचार करने के अवसरों की विचार से सहमत है। मई, १९४२ में जब मोस्तोवोव आन्ध्र-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए लंदन गए तो उन्होंने पुनः सोवियत भाग को दोहराया किन्तु ग्रैंट ब्रिटेन वाली ने पुनः इसे छानने से मना कर दिया।

सोवियत संधि को यूरोप में बड़ी महत्वाकांक्षायें थी और ग्रैंट ब्रिटेन इनसे पारचित था। स्टालिनशाह के युद्ध के बाद सोवियत सेना पूर्वी क्षेत्र में निधिय बन गई और अब सोवियत सरकार को सफलता का महान् आश्वासन मिला। उसे विश्वास हो गया कि वह सन् १९४१ की सीमानों को सुरक्षित रख सकता है, चाहे इसे पश्चिमी शक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाए अथवा न किया जाए। पश्चिमी शक्तियों की परवाह किए बिना ही पूर्व केन्द्रीय यूरोप में उसने अपने प्रभाव का क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। वैसे वह बराबर यह कहता रहा कि उसकी इच्छा यह है कि पूर्व केन्द्रीय यूरोप के राष्ट्र युद्ध के बाद अपनी स्वतन्त्रता और सम्प्रभुता को बनाए रख सकेंगे। सोवियत महत्वाकांक्षों से प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होने वाला देश पोलैण्ड था। पोलैण्ड की निष्कापित सरकार ग्रैंट ब्रिटेन में रह रही थी। उसका सोवियत संधि के प्रति पर्याप्त कटु अनुभव था क्योंकि इसने सन् १९३९ में पोलैण्ड को नष्ट करने में भाग लिया था। सोवियत संधि ने यह प्रदर्शित किया कि वह युद्ध के बाद पोलैण्ड के समूह में अपना हाथ रखता है और इसके बाद उसने सोवियत सेना के आधीन पोलिश संधि के देशभक्तों को मास्को में जमा किया जो साम्यवादी पोलिश सरकार की नामि का काम कर सकें। इसके अतिरिक्त सोवियत संधि ने चेकोस्लाव, यूगोस्लाव और रमानिया की रिग्रेड भी बताई जिसमें अधिष्ठित सिपाहियों को भर्ती किया गया। मास्को ने लंदन में किंग पीटर II के आधीन यूगोस्लाव सरकार से संधि जारी रखी। इनके पैसे में जाऊँ द्वितीय के आधीन ग्रीकानी सरकार से भी सम्पर्क बनाए रखा। सोवियत संधि ने लंदन स्थित राष्ट्रपति एडवर्ड वीनस (Edward Venis) के आधीन यूगोस्लाव सरकार से भी मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखे। जुलाई और सितम्बर १९४३ में स्वतन्त्र जर्मनी के लिए राष्ट्रीय समिति और जर्मन अधिकारियों का संधि माहरो में निर्मित किया गया। इसका निर्देशन निष्ठापित जर्मनों द्वारा किया जाता था किन्तु इनमें जर्मन अधिकारी भी शामिल थे। उस समय सम्पूर्ण

जर्मनी या उसके किसी भाग पर सोवियत सच के अधिकार के आसार दूर दिखाई दे रहे थे। किन्तु उस समय मास्को में स्थित जर्मन समूहों का तात्कालिक कार्य तो यह था कि जर्मन सिपाहियों को आत्मसमर्पण के लिए समझा कर उनका युद्ध क्षमता एवं प्रयासों को कम किया जाये। अक्सर आने पर इनका उपयोग नवना पर सोवियत प्रभाव बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता था।

पश्चिमी मित्र एवं सोवियत नीति

सोवियत नीति के जनतुलन ने पश्चिमी शक्तियों को भ्रम में डाल दिया तथा वे सोवियत लक्ष्यों के वास्तविक रूप का अनुमान नहीं लगा सकी। सोवियत सच द्वारा जो भी आश्वासन दिये जाते थे उनको प्रारम्भ में अमरीका द्वारा ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता था किन्तु ग्रेट ब्रिटेन के लोगों को उनके बारे में विश्वास कम था। सोवियत सच का प्रसार योरोप में होता जा रहा था कि तुल्य स्तर के अमरीकी कूटनीतिज्ञों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। अमरीकी सरकार एवं जनता यह मान कर चल रही थी कि युद्ध के बाद पूर्व-केन्द्रीय योरोप में सोवियत सच का प्रभाव होना ही चाहिए। उन्होंने सोवियत प्रभाव को इन क्षेत्रों में प्रजातन्त्र की स्थापना के विरोध नहीं माना। उनका तर्क था कि यदि ऐसा कुछ होता तो सोवियत सच द्वारा अटलाण्टिक चार्टर एवं समुक्त राष्ट्रों की घोषणा में विश्वास ही क्यों लिया जाता। उस समय समुक्त राज्य अमरीका में साम्यवाद एवं सोवियत मामलों के कुछ ही ऐसे जानकार थे जो सोवियत सच के इरादों को सदेह की नजर से देखते थे। उनका विचार था कि सोवियत सच द्वारा पश्चिमीयों के मित्र होने पर चार दिने जाने के पीछे कुछ रहस्य है और वह सम्भवतः यह है कि उसका पड़ोसी भी साम्यवादी देश ही होने चाहिए, क्योंकि लेनिन की दो गुप्त की विचारधारा के अनुसार पूँजीवादी एवं समाजवादी युद्ध तो कभी मित्र हो ही नहीं सकते और इसलिए एक राष्ट्र सोवियत सच का दोस्त तभी बन सकता है जबकि वह लाल झंडे के नीचे आ जाय। सामान्य अमरीकी सरकार एवं जनता को सोवियत मैत्री में कोई शक नहीं था और पश्चिमी सामान्य हित के विरुद्ध उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को सौंन दिये।

मित्र राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का प्रथम सम्मेलन मास्को में अक्टूबर, १९४३ में हुआ। इस समय अमरीकी राज्य सचिव कॉर्डेल हल (Cordell Hull) एवं ब्रिटिश विदेश मंत्री ईडन (Eden) ने सोवियत एवं पश्चिम सरकारों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया किन्तु कोई सफलता न

मिली। अमरीकी दृष्टिकोण पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसका अतिरिक्त स्टालिन ने काटेल हल को यह कहा कि जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त हो जाने पर यदि सोवियत संघ जापान के विरुद्ध युद्ध में हस्तक्षेप करेगा। सोवियत संघ ने अगस्त १९४१ में जापान के साथ अनाक्रमण सन्धि की थी और इस प्रकार का कोई इरादा इस सन्धि का स्पष्ट उल्लंघन था। अर्न्तनिर्भर होने हुए भी यह आश्चर्यजनक बात अमरीकी सैनिक नेताओं को पसंद आयी जो जापान के विरुद्ध युद्ध में रत थे। किंतु युद्ध के अन्तिम दिनों तक भी जनरल माइकल प्रशान्त युद्ध में सोवियत सहायता के वायदे को भुलता रहा, साथ ही योरोप में सोवियत प्रसारवादी नीतियों से भी वह निश्चित ही रहा।

तेहरान सम्मेलन

(The Teheran Conference)

तेहरान में २८ नवम्बर से १ दिसम्बर, १९४३ तक तीन बड़े राष्ट्र-अध्यक्षों का प्रथम सम्मेलन हुआ। चर्चिल, रूजवेल्ट एवं स्टालिन ने ईरान की राजधानी में पारस्परिक हित के विषयों पर विचार किया। यह तय किया गया कि ब्रिटेन, अमरीका मिल कर सन् १९४८ में फ्रांस पर आक्रमण करेंगे और जर्मनी के साथ अपना युद्ध समाप्त करके सोवियत संघ प्रशान्त महासागर के युद्ध में शामिल हो जायेगा। इस विचार विमर्श में पोलैण्ड का प्रश्न मुख्य बात रहा। चर्चिल ने यह सोचा कि शायद सोवियत संघ और पोलैण्ड की सरकारों के बीच समझौता होने में मुख्य बाधा मोन्टियस पोलिश सीमा का प्रश्न है। अब उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि १९८१ की सीमा को स्वीकार कर लिया जाये और पोलैण्ड को पूर्व में जो क्षति होगी उस परिधि में जर्मनी के भागों में पूरा कर दिया जाये। यद्यपि यह प्रस्ताव अटलांटिक चार्टर का उल्लंघन था किन्तु पारस्परिक मुविधा के लिए इस अपनाया गया। स्टालिन ने मीमांसा ही इस विचार को अपना लिया किन्तु पोलिश सरकार से मनमुटाव बनाये ही रहा। रूजवेल्ट इस सम्मन्ध में लुप्त ही रहे। चर्चिल ने एक अन्य कार्यक्रम रखा जिसका अनुसार जर्मनी के लोगों को एगीन द्वीपों (Aegean islands) से निष्कात कर युद्ध की भूमध्यसागर में बढ़ा दिया गया, किन्तु यह कार्यक्रम रूजवेल्ट तथा स्टालिन दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया। यह कार्यक्रम अमल में नहीं आया क्योंकि यह टर्की के सहयोग पर निर्भर करता था। जब परिचर्चा नतीजा कैरे में राष्ट्रपति इस्मैल इनोन् (Ismet Inonu) से मिले तो इनका टर्की को युद्ध तक सहयोग देने में, यहाँ पर निर्णय जब तक कि युद्ध का फैसला नहीं हो जाये।

राष्ट्रपति बेनेस (Bececs) तेहरान हात हुए माइका गये और ब्रिटिश परामर्श के विरुद्ध भी १३ अक्टूबर, १९४३ को सोवियत चरित्रोन्माद सधि

समझौता कर लिया। वेनस मूल रूप से प्रजातन्त्र का समर्थक एवं पश्चिमी राजनीति की ओर झुका हुआ था किन्तु ग्युनिव समझौते में ब्रिटेन व फ्रांस के योगदान से वह नाराज था। इसके अतिरिक्त उसे यह विश्वास हो गया था कि पश्चिमी शक्तियों ने पूर्व-केन्द्रीय योरोप से अपना हाथ खींच लिया है अतः उसने सोवियत संघ के साथ सन्धि करना उपयुक्त समझा। चेकस्लोवाक विदेश मंत्री जान मसेरिका (Jan Masaryk) ने लन्दन में अपने साधियों के सम्मुख इसी भाव को प्रकट करते हुए कहा था कि—“हम आइजनाहॉवर के नक्शे में ही नहीं हैं।”

जब चर्चिल ने लन्दन लौटने पर पोलिश सरकार की १९४१ की सीमा का बलिदान करके सोवियत संघ से समझौता करने की बात कही तो पोलिश सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस पर पश्चिमी शक्तियों को यह विश्वास हो गया कि पोलिश सरकार की अशुद्धिमत्ता के कारण ही सोवियत संघ से उसका समझौता नहीं हो पा रहा है। किन्तु सन् १९४८ में घटने वाली घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि वेनस की बुद्धिमत्ता भी उसकी सरकार की बचाने में रफ़्तक नहीं हो सकी।

पूर्व केन्द्रीय योरोप पर सोवियत विजय

(The Soviet Conquest of East Central Europe)

जून, १९४४ में मिम राष्ट्री न फ्रांस पर आक्रमण किया। इस अवसर पर सोवियत सेना १९४१ की सीमा पर पहुँच गई तथा बर्ला से उसने पोलैण्ड, रुमानिया तथा बाल्टिक राज्यों पर आक्रमण करने का नार्थक्रम बनाया। २२ जून, १९४४ को इसने पूर्वी शक्ति के साथ आक्रमण किया जिसके परिणाम-स्वरूप यह लुसाई के अन्त तक विस्टुला (Vistula) तक पहुँच गया। १ अगस्त, १९४४ को सोवियत सेना वार्सा (Warsaw) पहुँच गई तथा बर्ला सोवियत संघ के रेडियो प्रसारण द्वारा जकसाने पर पोलिश भूमिगत सेना जर्मनी के विरुद्ध लड़ खड़ी हुई। फिर भी सोवियत सेना विस्टुला के पूर्वी किनारे पर ही रक गई तथा विद्रोहियों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया किन्तु पोलिस तथा पश्चिमी सरकारों के प्रयास भी निरर्थक गये। ब्रिटिश तथा अमरीकी जहाज जब आन्तर्गत वार्सा को सामग्री पहुँचाने के लिए जाते थे तो उन्हें सोवियत सेना द्वारा अघिकृत भूमि पर नहीं रकने दिया जाता था। यदि वे रकते भी थे तो रूसी वायुयान भेदी बन्दूकों के निशाने बन जाते थे।

इस व्यवहार के स्पष्टीकरण के रूप में सोवियत सरकार द्वारा यह तर्क दिया जाता था कि सोवियत हाई कमान्ड ने स्प-कोडल की

दृष्टि से यह निर्णय लिया है कि कुछ समय तक विस्टुला से आगे न बढ़ा जाये। विचारको का कहना है कि यह व्यवहार युद्ध रूप से एक राजनैतिक चाल थी। पार्सा में जो नेतृत्व उभर रहा था वह साम्यवादी नहीं था और ग्रेट ब्रिटेन स्थित पोलिश सरकार को मान्यता दे रहा था। सोवियत संघ ने मई, १९४४ में ही मास्को में प्राविधिक पोलिश सरकार की रचना कर दी थी। अब वह वार्सा में पूंजीवादी प्रतिपक्षियों की सहायता करने में कोई रुचि नहीं लेता था। दो माह की अमानवीय लड़ाई के बाद २ अक्टूबर, १९४४ को जर्मनों द्वारा उपद्रवियों को दबा दिया गया।

जब सोवियत सेना पोलैण्ड के विरुद्ध लड़ी थी तो उसने बाल्टिक एवं बलकान्स की ओर भी अपनी टुकड़ियां भेजना प्रारम्भ किया। जर्मनी के पूर्वी प्रदेश विजयी मित्र राष्ट्रों की ओर मिलने के लिए तैयार हो बैठे थे। वे सम्भवतः पश्चिमी देशों को आरम्भसमर्पण करने की प्राथमिकता देते किन्तु जब सोवियत सेनायें उनके ऊपर आ लदी तो उनके सामने कोई विकल्प ही नहीं था। २५ अगस्त, १९४४ को फिनलैण्ड ने हथियार डाल दिये और दस दिन बाद सोवियत फिनिश युद्ध बन्दी समझौता क्रियान्वित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुसार युद्धबन्दी समझौता मुख्य रूप से एक सैनिक परिपत्र होता है जिसका अर्थ यह है कि जब तत्काल शांति-वार्ता के बाद समझौता नहीं हो जाता तब तक कोई लड़ाई नहीं होगी। किन्तु सोवियत संघ ने किसी शांति सम्मेलन की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा और उसने तुरन्त ही फिनलैण्ड तथा जर्मनी के अन्तर्गत्त उपराज्यों के साथ सम्बन्ध निश्चित करना उचित समझा।

इसी समय रूमानिया ने भी मित्रराष्ट्रों की ओर मिलने का निर्णय किया। रूमानिया की सरकार ने, यह कहा जाता है कि, पश्चिमी शक्तियों से गुप्त समझौता करने का प्रयास किया था किन्तु उन्होंने इसे सोवियत रूस के ही हवाले कर दिया। रूमानिया का प्रतिनिधि मण्डल मास्को गया तथा उसने १२ सितम्बर १९४४ को युद्धबन्दी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। रूमानिया को महं योद्धा का स्तर प्रदान कर दिया गया तथा रूमानिया की सेनाएं मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध के अन्त तक लड़ती रही।

रूमानिया के झुकने के कारण सोवियत सेना दक्षिण में डन्यूबी (Danube) तथा बलगारिया की ओर तेजी से बढ़ सकती थी तथा बाल्कन पर्वतमाला को पार करके पश्चिम में हंगरी की ओर बढ़ सकती थी। बलगारिया ही एकाग्र ऐसा पश्चिमी उपराज्य था जिसने सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी बल्कि केवल पश्चिमी मित्र देशों के विरुद्ध

ही युद्ध की घोषणा की थी। कुछ समय तक तो बल्गारिया की सरकार पश्चिमी देशों के साथ आत्मसमर्पण के लिए गुप्त-वार्ता करती रही किन्तु बल्गारिया में मित्र राष्ट्रों की सेना नहीं थी अतः वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ५ सितम्बर, १९४४ को बल्गारिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके सोवियत संघ ने इस समस्या का समाधान कर दिया। सोवियत सेना ने हनुवी को पार करके बिना किसी विरोध का सामना किये ही देश पर अधिकार कर लिया। २५ अक्टूबर, १९४४ को युद्धबन्दी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बल्गारिया का प्रतिनिधि मण्डल साफ़ हो गया। बल्गारिया को भी सह योद्धा का स्तर प्राप्त हो गया तथा उसकी सेनाएं मित्र राष्ट्रों के पक्ष में बिन गई।

हंगरी इस दृष्टि में कम सौभाग्यशाली था। रुमानिया, स्लोवाकिया एवं युगोस्लाविया की रीढ़ों के बाव सोवियत सेनाएं हंगरी पर चढ़ गईं। हंगरी की सरकार एडमिरल मिखैल होर्षी के शासन में पश्चिमी मित्रों से सन्धि करना चाहती थी किन्तु उसे भी सोवियत रूस के हवाले कर दिया गया। १५ अक्टूबर को हंगरी ने जर्मनी से अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की तथा समर्पण समझौते की बात रही किन्तु जर्मनी वालों ने हंगरी के इस निर्णय को ठुकरा दिया। उन्होंने बुडापेस्ट को घेर लिया तथा होर्षी को बन्दी बनाकर जर्मनी भेज दिया। इसके अतिरिक्त डेनुवे के निकट सुरक्षा की पवित्र तैयार की। अप्रसन्न हंगरी को इटली जैसे भाग्य का सामना करना पड़ा व इसका विभाजन कर दिया गया। जर्मनी की सरकार ने हंगरी के फ़ासीवादी नेता फ़रेन्ज साफ़ासी (Ferencz Szalasi) के नेतृत्व में बुडापेस्ट में एक कठुनवादी सरकार की स्थापना की। दूसरी ओर सोवियत संघ ने जमरल बेला मिक्लोस (Bela Miklos) के आधीन डेबेरेसन (Debrecen) में अन्य सरकार की स्थापना की।

बाद में जनवरी २०, १९५० को हंगरी ने मान्को के साथ युद्धबन्दी समझौता किया जिसके अनुसार हंगरी को म्यूनिख में पूर्व की सीमाएं प्रदान की गईं तथा उसे क्षतिपूर्ति के रूप में लगभग तीन सौ मिलियन डालर सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया एवं युगोस्लाविया को देने थे।

सोवियत संघ ने जब इन उपराज्यों के साथ सन्धि सन्धिया की तो पश्चिम से नहीं पूछा गया। यह एक प्रकार से उनकी चेतकनी की एवं घबरा तथा उत्तरे गर्व के लिए गहरी चोट थी। इतने पर भी इन देशों ने मित्र राष्ट्रों की एकता की खातिर इन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार इन सन्धियों को सभी मित्र राष्ट्रों द्वारा किया हुआ मान लिया गया।

उस समय यह कल्पना की गई थी कि ये समझौते केवल अस्थायी प्रकृति के हैं जिनको भावी शान्ति सम्मेलन में परिवर्तित किया जा सकता है। पश्चिमी देशों ने इन उपराज्यों में सोवियत गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था की। यह वाय उन्होंने हल्सिंकी, मुस्कोव, सोफिया एवं बुडापेस्ट में रखे गये अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया। इन प्रतिनिधियों को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सोवियत प्रतिनिधियों से वे पूछ रहे हैं तथा उनकी अवहेलना की जा रही है। सोवियत प्रतिनिधियों को मित्र राष्ट्र युद्धरत आयोगों का सभापति बनाया गया क्योंकि सामान्यतः स्वीडन सिद्धान्त के अनुसार प्रमुख वाशित्व उसी देश का माना जाता है जिसने कि एक प्रदत्त क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है।

ज्यों ज्यों सोवियत सेना पूर्व-केन्द्रीय योरोप में बढ़ती चली गई त्यों त्यों उस हत्या, अत्याचार, बलात्कार एवं अमानवीय व्यवहार की चर्चा बढ़न लगी जो सोवियत सेना द्वारा विजित क्षेत्र की जनता पर किया जाता था। इस सम्बन्ध में एवं उल्लेखनीय बात यह थी कि सोवियत सेना के सहारे देशों साम्यवादी या तो मास्को से लौटकर अथवा भूमिगत क्षेत्रों से निकाल कर सत्ताधारी बनने लगे। सोवियत शक्ति द्वारा इस काम में इनकी पूरी सहायता की जाती थी। अमरीका अभी तक भी इन घटनाओं से एचेज नहीं हुआ था किन्तु थोड़े दिनों पर्यन्त उन्मुख बन गया। चर्चिल ने पहले भूमध्य-सागर से योरोप पर आक्रमण का समर्थन किया किन्तु अब वह बाल्कन में एड्रियाटिक सागर के शीर्ष पर मित्र राष्ट्रों की, सेना रखने पर जोर देने लगा ताकि पूर्व-केन्द्रीय योरोप में सोवियत शक्ति को मर्यादित रखा जा सके। किन्तु जो अमरीकी जनरल भूमध्यसागर में कार्यवाही करने में रूचि नहीं लेते थे उन्होंने इस वायक्रम को रण-नीति की दृष्टि से अनुपयुक्त एवं हल्का बताया। तब यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इस क्षेत्र में इटली की सेना न केवल आगे बढ़ सकी थी वरन् उसे चुरी तरह भार भी सन्नी पड़ी थी। अब चर्चिल ने आइजनाहॉवर के मुख्यालय में जाकर यह बात कही तथा इसके पक्ष में तर्क प्रदान किये तो इके (Ike) ने कहा "नहीं, वह दोषहर बाद तक नहीं बढ़ता गया और अन्त में भी उसने अग्रणी भाषा के प्रत्येक रूप में नहीं ही बढ़ा।"

चर्चिल का प्रतिशत सिद्धान्त

(Churchill's Percentage Deal)

चर्चिल आसानी से ही हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने सितम्बर १९४४ में द्वितीय क्वेबेक सम्मेलन (Quebec Conference) में राजपेस्ट के

सामने भी इस बात को रखा। इस समय राष्ट्रपति चुनाव की कलहनी में ज्वलन था। माप ही वह साम्यवादी खतरे की अपेक्षा नाजीवाद के सम्भावित खतरे से अधिक परेशान हो रहा था। किन्तु फिर भी उसने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया कि चर्चिल अकेला ही स्टालिन के साथ समझौता कर ले। अक्टूबर १९४४ में चर्चिल तथा ईडन मान्यो गये। यहाँ उन्होंने पुन पोलैंड के प्रश्न को मुद्दा ने की बात नहीं। किन्तु तानाशाह अधिक से अधिक केवल हम बान पर राजी था कि मन्त्र के पोलों की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए पोलिश सन्निधि में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। स्टालिन ने अन्य ब्रिटिश मुयावों के प्रति अधिक अच्छा रख अपनाया। इस अवसर पर चर्चिल ने स्टालिन को प्रतिशत का विचार सुझाया जिसके अनुसार बल्शान में उत्तरदायित्व को प्रतिशत के आधार पर बांटना था। उदाहरण के लिए रूमानिया पर ६० प्रतिशत सोवियत और १० प्रतिशत पश्चिमी प्रभाव रहे, इसी तरह बल्गारिया पर ७५ प्रतिशत सोवियत और २५ प्रतिशत पश्चिमी। यूनान पर ६० प्रतिशत पश्चिमी और १० प्रतिशत सोवियत, यूगोस्लाव पर ५० प्रतिशत पश्चिमी और ५० प्रतिशत सोवियत तथा हंगरी पर भी ५० प्रतिशत सोवियत एवं ५० प्रतिशत पश्चिमी प्रभाव रहे। स्टालिन ने यह प्रस्ताव बिना किसी आपत्ति के ही स्वीकार कर लिया। उत्तरी आट्टिमाटिक में ब्रिटिश के रहने की योजना को भी उसने इसी प्रकार स्वीकार कर लिया।

पर लौगने पर चर्चिल ने पाया कि उसके स्वयं के जनरल पूरी अमंगीरी सहायता के बिना इन कार्यवाही के करने में उत्सुक नहीं थे। उन्होंने यह भी सुझाया कि यह क्रम फरवरी, १९४५ में पूर्ण चटाना प्रभावनीय नहीं रहेगा। दिसम्बर, १९४५ में उसने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। हम तेज देन का एकम न फायदा चर्चिल को यह हुआ कि वह यूनान में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हो सका। अक्टूबर में ब्रिटेन को मैनिंक टुकड़िया यूनान तथा उनके आगे तक पहुँच गई। दिसम्बर की भारी लड़ाई में यूनानी साम्यवादियों ने एयन का अधिकार में कर लिया। यद्यपि राजधानी में इनकी हालत गराव कर दी गई किन्तु देहाती क्षेत्रों में साम्यवादियों को नहीं दखाया जा सका और यहाँ गृह संघर्ष क्यों तक चलता रहा। सोवियत सरकार ग्रेट ब्रिटेन के साथ समझौते के परिणामस्वरूप इतनी सीमित रहों कि उसने बाल्कन क्षेत्र में बागे बड़ना रोक दिया। २१ अक्टूबर, १९४४ को बेलग्रेड की अधिकार में करने के बाद सोवियत नेता बूडापेस्ट की ओर उत्तर में मुड़ गई। जर्मन के लौगो ने हंगरी की राजधानी को अपने अधिकार में करने के लिए भरमरु प्रयत्न किए। दूसरी ओर सोवियत सेना १७ जनवरी, १९४५ को

वार्सा पर अधिकार कर लिया। वार्सा और वुडापेस्ट पर अधिकार १२ जनवरी, १९४५ को किए गए अन्तिम सोवियत आक्रमण के भाग थे। बेलग्रेड, वुडापेस्ट और वार्सा होती हुई सोवियत सेनाएँ पश्चिम विमाना, प्राग, बर्लिन की ओर आगे बढ़ी।

याल्टा सम्मेलन

(The Yalta Conference)

सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति पर याल्टा सम्मेलन ने एक रोक लगा दी जो 'तीन बड़ों' का द्वितीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में सामान्य सोवियत नेताओं ने उन विजयों की रक्षा का प्रयास किया जो सोवियत सेना प्राप्त कर चुकी थी और उन विजयों के लिए गारन्टी चाही जिन्हें सोवियत सेना प्राप्त कर सकती थी। सोवियत रूस पूर्व-केन्द्रीय यूरोप पर तो अधिकार कर ही चुका था। याल्टा में सोवियत नेताओं की समस्या यह थी कि वे इस प्रदेश में अपने अधिकार पर पश्चिम की मान्यता प्राप्त कर सकें। जहाँ तक अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का सवाल है वह पूर्व-केन्द्रीय यूरोप के भाग्य की ओर से उदासीन थे और इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत आगा पीछा करके बात मान ली। किन्तु चर्चित ने कई कठिनाइयाँ उत्पन्न कीं। सबसे बड़ा प्रश्न तो पोलैंड की समस्या थी जिसे याल्टा में इन 'तीन बड़ों' का ध्यान केन्द्रित रखा। पोलैंड की सीमाओं के सम्बन्ध में चर्चित सेहरान सम्मेलन में पहले ही यह सुझाव दे चुके थे कि पोलैंड रूस की शक्तियों को पूर्वी भाग में चुकाएगा और पश्चिम में जर्मनी के प्रदेश से इसका भरोसा कर लेगा। अब प्रश्न यह था कि क्षतिपूर्ति की माग क्या हो? सोवियत नेताओं का प्रस्ताव था कि वे आडर-निसी पक्ति (Oder-Neisse Line) और पूर्वी प्रगा के उत्तरी भाग को अपने लिए सुरक्षित रखेंगे जिसमें कि कोनिसबर्ग भी सम्मिलित है। पश्चिमी नेताओं के मतानुसार कोनिसबर्ग से युक्त पूर्वी प्रगा के उत्तरी भाग तक तो बात ठीक थी किन्तु इसके अतिरिक्त और कुछ मागना बहुत अधिक हो जाता। इस प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका। ब्रिटेन वालों ने पोलिस सरकार और सोवियत सरकार के बीच समझौता करने वाले प्रयासों को ठुकरा दिया और अब वे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पोलिस समिति को मान्यता देने के लिए तैयार थे। यह समिति मास्को में पोलैंड की प्राविधिक सरकार के रूप में मानी गई। ग्रेट ब्रिटेन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस सीमांत में रुढ़न में रहने वाले पोलों के कुछ प्रतिनिधि होने चाहिए। सोवियत नेताओं ने सिद्धान्त रूप से यह बात मान ली। किन्तु ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के नेता यह समझौता करने

मे अतमयं रहे कि सिद्धान्त को कैसे विशान्वित किया जाए ? इस प्रश्न को आगे अध्ययन के लिए एक विशेष आयोग को सौंप दिया गया जिसमें सोवियत विदेश बमीस्तर एव मास्को स्थित ग्रेट ब्रिटेन के ओर अमरीकी राजदूत थे ।

पूर्व केन्द्रीय यूरोप में श्रांति निराशा का एक अन्य कारण यह था कि वह लन्दन स्थित युगोस्लाव सरकार को समर्थन दे रहा था । इस प्रश्न पर मास्को सम्मेलन में सोवियन नेताओं ने इसे सुझाया और ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार किया तथा इसके आधार पर मार्शल टोटोव और लन्दन स्थित युगोस्लाव प्रधानमन्त्री ईवान सुबासिक (Ivan Subasic) ने समझौता किया जिसमें नई युगोस्लाव सरकार में विभिन्न प्रजातन्त्रात्मक दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व (Token Representation) देने की व्यवस्था की गई । यह सरकार टोटोव के अधीन कार्य करेगी और वहां राजतन्त्र की स्थापना की जाए अथवा गणराज्य की स्थापना की जाए—यह बात जनमत के आधार पर तय की जाएगी ।

सामान्य रूप से पूर्व केन्द्रीय यूरोप में स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की गारन्टी के सम्बन्ध में अमरीका द्वारा यह प्रस्ताव किया गया कि स्वतन्त्र यूरोप के सम्बन्ध में एक घोषणा जारी की जाए जिसके अन्तर्गत मिन राष्ट्रों द्वारा यूरोप के स्वतन्त्र लोगों को उनकी मर्जी की प्रजातन्त्रात्मक सत्ता बनाने में सहायता की जाए । यह अटलांटिक चार्टर के अनुरूप होगा । सोवियत नेता इस प्रस्ताव से सहमत हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास था कि यूरोप की जनता किस प्रकार की प्रजातन्त्रात्मक सत्ता चाहती है । यही सब ध्यान में रख कर सोवियत नेता बिना कुछ आना-पीछा किए इस बात को स्वीकार कर गए । कहा जाता है कि उन्होंने स्वतन्त्र यूरोप पर घोषणा को उसी प्रकार बिना किसी परेशानी के स्वीकार किया जिस प्रकार कि बाद में बिना किसी परेशानी के तोड़ दिया ।

सोवियत रशिया का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जर्मनी था । सितम्बर, १९४४ में लन्दन में यूरोपीय परामर्शदाता परिषद् (European Advisory Council) में जर्मनी के भावी क्षेत्रों पर सहमति हो चुकी थी । अमरीकी सैनिक प्रतिनिधि इस परिषद् में जर्मनी के भागों को हस्तगत करने के लिए अमरीकी सेना को उलझाने के पक्ष में नहीं थे । उनका विचार था कि अमरीका जापान के साथ युद्ध में उलझा हुआ है अतः जर्मनी में उसे अधिक नहीं उलझना चाहिए । सन् १९२७ के जर्मनी के क्षेत्र का ५२ प्रतिशत भाग जिसमें कि ४८ प्रतिशत जनता रहती थी, सोवियत क्षेत्र माना गया । यह क्षेत्र

उस क्षेत्र की अपेक्षा अधिक था जो मोविपत सेना ने अधिभूत किया था। जर्मनी का प्रशासन विषय राष्ट्रों द्वारा मित्र कर करतल था और इसके लिए बर्लिन में मित्र राष्ट्रों की नियन्त्रण परिषद स्थापित की गई। बर्लिन का अधिकांश भाग सोवियत क्षेत्र में आता था, इनको भी अनेक भागों में बांटा जाना था किन्तु प्रशासन मित्र कर दिया जाना था। बर्लिन तक पहुँचने के तरीका पर यूरोपीय परामशदाता परिषद में कोई विचार नहीं किया गया क्योंकि अमरीकी सैनिक अधिकारियों के मतानुसार जर्मन संचार व्यवस्था के बारे में भरोसा नहीं जान बिना यह सब सोचना गड़बड़ होगा। याटा में 'तीन बड़ों' ने यूरोपीय परामशदाता परिषद की सिफारिशों को स्वीकार किया। इसमें केवल एक परिवर्तन किया गया वह यह कि प्रान्स के लिए एक भाग और दिया जाए जो ब्रिटिश तथा अमरीकी भागों में से बनाया जाए।

जर्मनी के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्षतिपूर्ति की थी। सोवियत रूस का कहना था कि इसके बिना उसका युद्धांतर रचना कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता। याटा सम्मेलन में रूस ने यह प्रस्तावित किया कि जर्मनी को सामान और सेवा के रूप में २० मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति देनी चाहिए और इससे से आगे पर सोवियत रूस का अधिकार हो। पश्चिमी देश इस बात पर सहमत थे कि जर्मनी को क्षतिपूर्ति देनी चाहिए किन्तु इस क्षतिपूर्ति की मात्रा कितनी हो इसके सम्बन्ध में सहमति नहीं थी। सोवियत नेता स्टालिन द्वारा मुझाए गए गत विहीन आत्ममर्मांग के मून को मान रहे थे किन्तु जर्मनी के अधिकार के सम्बन्ध में कोई सामाजिक समझौता न कर सक। याटा में 'तीन बड़ों' ने केवल इस बात पर सहमति प्रकट की कि वे जर्मनी की सैनिक शक्ति तथा साम्य शक्ति को घटा सकें तथा इन समस्याओं को आगे अध्ययन के लिए आयोग को सौंप सकें।

याटा सम्मेलन में उस समय जर्मनी के साथ युद्ध समाप्त होने को था इसलिए तहरान की अवस्था महा मुद्र पूर्व की समस्याओं पर अति ध्यान दिया गया। मोविपत नेता यह चाहते थे कि आसारन पर विषय के बाद उनको क्या हिस्सा दिया जाएगा, इस बात को पहले ही तय कर दिया जाए। त्रिम समय यूरोपीय मामलों पर सोझाजी हो रही थी उस समय पश्चिमी हिस्सों की रक्षा का उत्तरदायित्व ग्रेट ब्रिटेन पर छोड़ा गया। किन्तु जब मुद्र पूर्व के मामलों पर सोझे-बाजी हुई तो यह उत्तरदायित्व मोविपत रूप पर आता गया। सोवियत नेताओं ने अपने इस आकांक्ष को दोहराया कि जर्मनी के साथ अपना युद्ध समाप्त करने के बाद दो या तीन महीने के अन्दर-अन्दर आसारन के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाएगा। किन्तु इस समय उन्होंने इसके लिए

कीमत मागी और वह यह थी कि सन् १९०४ में जापान के शांतिमण द्वारा जो सोवियत अधिकार चीन लिए गए हैं वे उसको वापस मिल जाए। इस प्रकार साम्यवादी सोवियत राष भी जारशाही साम्राज्यवाद के अवशेषों एवं निशानियों को बनाए रखने में पूरी रुचि ले रहा था।

सोवियत राष के इन दावों ने चीन के हितों को बहुत प्रभावित किया, किन्तु चीन यास्ता सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने इस सत पर स्वीकार कर लिया कि वे चांगकाई शैक की स्वीकृति प्राप्त कर लें। यह स्वीकृति प्राप्ति करने का उन्हें विश्वास था। इसके बदले सोवियत नेताओं ने चीन की राष्ट्रवादी सरकार का समर्थन करने का आश्वासन दिया जिससे कि अमरीकी नेता बहुत प्रसन्न हुए। अमरीका को संतोषजनक लगने वाला एक अन्य सोवियत वायदा यह था कि संयुक्त राज्य अमरीका की वायु सेना उस समय सोवियत सुदूरपूर्व के अड्डों का प्रयोग कर सकती है जब कि सोवियत रूस प्रशान्त युद्ध में सम्मिलित हो जाए। यह वायदा बाद में महत्वहीन प्रतीत हुआ।

सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र संघ (Soviet Russia and U. N. O)

यास्ता सम्मेलन में स्वीकार को गई दूसरी योजना संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर का प्रादप थी। इसकी अगस्त अक्टूबर १९४४ में उनके प्रतिनिधियों द्वारा डम्बर्टन ओक्स (Dumbarton Oaks) सम्मेलन में कार्य एवं प्रदान किया गया। सोवियत नेताओं को इस प्रकार के संगठन के मूल्य के सम्बन्ध में पर्याप्त शक था। वे इसे केवल अपने प्रचार के साधन के रूप में देखते थे। किन्तु फिर भी सोवियत नेताओं ने यह निर्णय किया कि वे अब विश्व राजनीति से पृथक रहने की नीति नहीं अपनाएंगे और प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। किन्तु सत यह है कि उसका प्रयोग राष्ट्र संघ की भांति सोवियत राष के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

सोवियत राष की अदेसा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका अल्पमत हमेशा रहेगा और इसलिए उन्होंने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान की विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। इसके अनुसार प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्णयों के अतिरिक्त निर्णयों को इसे ११ सदस्यों में से ७ के द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। इन ७ में इसके सभी स्थायी सदस्य अर्थात् बड़ी शक्तियां होनी चाहिए। इस एकमत सम्मन्धी धारा ने महाशक्तियों को सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर निषेधाधिकार प्रदान किया। इस प्रक्रिया में पश्चिमी शक्तियां सोवियत रूस के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर पायेंगी। इसी

प्रकार सोवियत नेताओं ने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी मत शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से यह मांग की कि सोवियत संघ के १६ गणराज्यों को इसमें अलग से मताधिकार प्रदान किया जाए। उनका तर्क था कि ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्यों को भी महामहान में पृथक् से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार उसके मत बढ़ जायेंगे। सोवियत संघ के इस तर्क का जवाब इस रूप में दिया गया कि इस आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका भी अपने ४८ राज्यों के लिए ४८ मतों की मांग कर सकता है। ऐसी स्थिति में सोवियत संघ को दो अतिरिक्त मतों से ही संतोष करना पड़ा—रुक यूक्रेन (Ukraine) के लोगों के लिए तथा दूसरा सफेद रूसियों के लिए।

याल्टा सम्मेलन की भग करने से पूर्व 'तीन बड़ों' ने सभी मित्र राष्ट्रों को तथा धुरी राष्ट्रों पर आक्रमण करने वाले राष्ट्रों को १ मार्च १९४५ को सान फ्रान्सिस्को में एक महाम सम्मेलन के लिए आमन्त्रित किया जिसमें कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के प्राकल्प पर विचार किया जा सके।

जर्मन का आत्मसमर्पण

(The German Surrender)

सान फ्रान्सिस्को सम्मेलन (San Francisco Conference) २५ अप्रैल से २६ जून, १९४५ तक चला। इस समय तक युद्ध भी समाप्त होने को आ रहा था। युद्ध के अन्तिम समय में सोवियत सेना तथा पश्चिमी सेनाओं के बीच जर्मनी पर हावी होने की दौड़ लगी हुई थी। मार्च के प्रारम्भ में सोवियत सेना कुस्ट्रिन (Kuestrin) पर पहुँच गई जहाँ से बर्लिन केवल ५० मील दूर रह गया था। किन्तु उसी समय जर्मनों का विरोध कड़ा हो गया और सोवियत सेनाओं का बढ़ना १६ अप्रैल तक ठे लिए रुक गया। इस बीच अमरीकी सेनाएँ राइन नदी को पार कर चुकी थी तथा ११ अप्रैल को वे एल्वे पहुँच गई। यहाँ से बर्लिन केवल सठ मील पूर्व में था। बर्लिन सोवियत एवं अमरीकी सेनाओं के बीच में आ गया। इसकी हस्तगत करना एक मूल्यवान राजनैतिक खात बन गई। सोवियत संघ को गिरन्तर यह भयकर स्वप्न आ रहा था कि जर्मनी पश्चिमी शक्तियों के साथ सन्धि वार्ता करेगा अथवा पश्चिमी सेना को खोल देगा और पूर्वी सेना पर कड़ा रुख अपनायेगा। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सेनाएँ जर्मनी पर छा जायेंगी। यह बात कुछ नाज़ी जनरलों एवं नेताओं के मस्तिष्क में भी बनाई जाती थी। किन्तु यह सब नहीं हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों ने अपने सोवियत मित्र पर पूरा विश्वास रखा तथा युद्धबन्दी समझौते से लड़ने इस बात पर ज़ार दिया कि जर्मनी एक साथ सभी मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करे।

बर्लिन के पूरे प्रयाशों के बावजूद भी जनरल आइज़नहाइमर ने अमरीकी सेनाओं को एलबी (Elbe) पर रोक दिया तथा जानबूझ कर बर्लिन के आधिपत्य का अवसर छोड़ दिया। सोवियत सेनाओं ने १२ अप्रैल को बिस्पा पर अधिकार कर लिया और २ मई को बर्लिन उसके नीचे आ गया। अब देखा जा रहा था कि अमरीकी सेनाएँ चैकस्लोवाकिया में आगे बढ़ीं; उधर बाद ५ मई, १९४५ को प्राग भी जर्मनों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। इसी समय जनरल आइज़नहाइमर ने सेना को पिल्सेन (Pilsen) पर ही रोक दिया। चैकस्लोवाकिया के साम्यवादियों के मतानुसार यह कदम इसलिए उठाया गया था ताकि जर्मनों के लोगों को विद्रोह दबाने के लिए समय मिल सके। सम्भवतः ऐसा ही सोवियत सेनाओं द्वारा बार्सा में किया गया था। सोवियत सेना ने प्राग को ६ मई, १९४५ को स्वतन्त्र कराया। सोवियत रुब ने राजधानियों पर कब्जा करने में तथा युद्ध को समाप्त करने में पर्याप्त रुचि ली। जब जर्मनों ने आइज़नहाइमर के हेडक्वार्टर में ७ मई, १९४५ को बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया तो सोवियत सेना ने इस बात पर जोर दिया कि यही प्रक्रिया मार्शल जार्ज स्टीव के सामने भी दूसरे दिन बर्लिन में दोहरायी जाये।

पूर्व-केन्द्रीय योरोप में प्रादेशिक समझौते

(Territorial Settlement in East Central Europe)

तीन बलों के बीच की एकता में दाररे जर्मन आत्मसमर्पण से पूर्व ही पड़ गई थी। सोवियत सरकार का मत था कि उसकी सेनाओं द्वारा विजित प्रदेशों के साथ वह जी-वाहा व्यवहार करेगी। ऐसी स्थिति में उन्ने पश्चिमी शक्तियों के मत की ओर ध्यान दिने बिना ही पूर्व-केन्द्रीय योरोप के क्षेत्रीय प्रश्नों की मुलझाना प्रारम्भ किया। फिनलैण्ड तथा रमानिया में रुब ने सन् १९४४ की सन्धि में ही वांछित प्रदेश के लिए किया था। २५ जुलाई, १९४४ को ही मास्को में राष्ट्रीय सहज्यता की पोलिश समिति के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा पोलिश-सोवियत सीमा विवाद की मुलझाना गया। बाद में सोवियत सेना के साथ पोलिश समिति को 'पोलैण्ड' भेजा गया। मई, १९४५ में इन्ने पश्चिमी शक्तियों को पूरे बिना ही फिनलैण्ड की ओडरनिची पक्ति का जर्मन-क्षेत्र देकर उसकी शक्तिवृद्धि कर दी।

इसके साथ ही सोवियत संध कोनिसर्गों तथा पूर्वी प्रया के भाग की ओर बढ़ने लगा। चैकस्लोवाकिया भी बीचे तो फिनलैण्ड की भांति एक मित्र राष्ट्र था किन्तु उससे कहा गया कि वह स्वेडन से ही अपने बड़े 'स्टाव' आईसों की प्रदेश प्रदान करे। २६ जून, १९४५ को मास्को में एक सन्धि पर

हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार चैकोस्लोवाकिया ने सोवियत संघ को रुथेनिया (Ruthenia) सौंप दिया जो पहले अभी भी सोवियत साम्राज्य का भाग नहीं रहा था। इसके फलस्वरूप सोवियत रूस और हंगरी सीमायें सामान्य बन गई तथा डनुबियन के मैदान पर उसकी शक्ति बढ गई। सोवियत संघ ने अपने इन पड़ोसी राज्यों को, चाहे वे औपचारिक रूप से मित्र थे अथवा शत्रु, अब अपना उपराज्य बना लिया।

सोवियत संघ ने अपनी प्रदेशों की भूख मिटाने के बाद पोलैण्ड की क्षतिपूर्ति की तथा बल्गारिया को छोटी सी प्राप्ति कराई और रोप के लिए उसने युद्ध पूर्व की सीमाओं को बनाये रखा। कहा जाता है कि इससे सोवियत रूस को लगभग दो लाख वर्ग मील प्रदेश का लाभ हुआ जिसमें २२ मिलियन निवासी रहते थे। पूर्व केन्द्रीय योरोप के राज्यों में यदि असमानता एवं समस्याएँ बनी रही तो उसने इसके लिए पेरिस के शान्ति समझौता करने वालों को उत्तरदायी ठहराया।

युद्ध के अन्तिम दिनों में यूगोस्लाव के सैनिकों ने उस समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया जिसके बारे में प्रथम विश्व युद्ध से ही संघर्ष चल रहा था। उन्होंने आस्ट्रिया में भी ट्रीस्टे (Trieste) तथा क्लगेनफर्ट (Klagenfurt) पर भी अधिकार कर लिया। ग्रेट-ब्रिटेन यह मान चुका था कि यूगोस्लाविया उसके प्रभाव से गया। अब उसे इटली की बचाने की अधिक चिन्ता थी क्योंकि यहाँ साम्यवादी आन्दोलन प्रखर होता जा रहा था। ब्रिटेन के प्रोत्साहन पर अमरीका ने शक्ति प्रयोग के आधार पर इन बन्दरगाहों से यूगोस्लाविया को पीछे हटाने का उपक्रम किया। हॉपकिन्स तथा स्टालिन की वार्ता के बाद ६ जून, १९४५ को वेलब्रेड में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। इसके अनुसार एक विभाजक रेखा 'मॉर्गन लाइन' बना दी गई जो कि आंग्ल-अमरीकी तथा यूगोस्लाव सेनाओं के बीच रखी गई। इसका अन्तिम निर्णय शान्ति सम्मेलन के लिए छोड़ दिया गया। इस लाइन के अनुसार ट्रीस्टे तथा आस्ट्रिया के उत्तर में एक रैलरोड तो आंग्ल-अमरीकी नियन्त्रण में रखी गई तथा पहले के अन्य इटालियन क्षेत्र यूगोस्लाविया के पास रहे।

पोट्सडाम सम्मेलन

(The Potsdam Conference)

यह सम्मेलन 'बड़े तीन' का अन्तिम सम्मेलन माना जाता है जो १७ जुलाई, १९४५ से २ अगस्त १९४५ तक पोट्सडाम में चलता रहा। इस सम्मेलन में सोवियत नेताओं के लिए मुख्य प्रश्न जर्मनी तथा क्षतिपूर्ति,

से सम्बन्धित थे। स्वतन्त्र दोरीय पर माया घोषणा-पत्र द्वारा कमरेका ने यह प्रमाण दिया कि पूर्व केन्द्रीय दोरीय का साम्यवादिकरण होने से रोका जाये। किन्तु सोवियत नेताओं ने इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा था तथा इसके सम्बन्ध में पश्चिमी नेताओं को कुछ भी हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। पश्चिमी राजनीतिज्ञों ने बोसिववर्ग पर सोवियत अधिकार दुरुस्त स्वीकार कर लिया किन्तु पोलैण्ड को दी जान वाली क्षतिपूर्ति का आकार कम करने पर जोर डाला। पर्लमैट अगले के बाद वे इस बात पर सहमत हुए कि क्षेत्रीय प्रश्नों को शान्ति समझौते के अन्तिम निर्णय के लिए रखा जाये तथा तब तक इस प्रदेश पर पोलिश राज्य का प्रशासन रहे।

जब तक क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध है, सोवियत सरकार उन भागों को दोहतायी रही जो उठने माया में प्रथम बार रखी थी। वह १० मिलियन डॉलर की कीमत की क्षतिपूर्ति चाहता था किन्तु पश्चिमी सरकारों ने पुनः इस भाग को दुहरा दिया। सोवियत संघ ने मित्र राष्ट्रों के क्षति पूति आयोग के बैठक की प्रतीक्षा नहीं की तथा जर्मनी पहुँचते ही उन्ने अपने क्षेत्र की समस्त चल सम्पत्ति से वधित करने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। दुर्भाग्य से कभी क्षेत्र वृषि प्रधान था जबकि उने औद्योगिक सामान तथा मशीनों की जरूरत थी। किन्तु वे चीजें जर्मनी के पश्चिमी भाग में थी, विशेषतः उच्च मात्र में जो इटली के अधिकार में था। इतने पर भी सोवियत संघ सोवियती करने की स्थिति में था क्योंकि जर्मनी के पश्चिमी भागों की सोवियत भाग से हो अनाज आपाज करना जरूरी था। यदि ऐसा नहीं करने तो बिदेसों से अन्न मगाना होगा और इसका खर्चा उनकी स्वयं पुनर्मा पड़ता। उक्त समय जर्मनी के आयात का भण्डार अधिक नहीं था। इसकी अर्थव्यवस्था पर कुछ का बुरा चकर पड़ा तथा सत्ताधारों शक्तियों की मात्रा का खोना और था। ऐसी स्थिति में जर्मनी क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ था। पर्लमैट बाद-विवाद के बाद तीन बड़े एक जटिल रूप पर सहमत हुए। इसकी मूल बात यह थी कि जर्मनी को एक आर्थिक इकाई (Economic Unit) बनना जाये। सोवियत संघ को उनके क्षेत्र में जो भी प्राप्त हुआ उसके अनिवार्य पश्चिमी क्षेत्र की सामान्य आवश्यकताओं से ऊपर के औद्योगिक सामान में से एक प्रतिशत दिया जाता था। जब पश्चिमी क्षेत्र सोवियत क्षेत्र से साथ सामग्री तथा अन्य चीजें लेते तो इसके लिए वे १५ प्रतिशत और देते। इसपर पोलैण्ड को अपनी क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा था। उने अनुष्ट करने के लिए सोवियत संघ को जर्मनी के एन्-विहाई व्यापारिक पीछे एवं मुद्रा-पीछे दिखे जाते थे। इतने अतिरिक्त जर्मनी की पूर्व-केन्द्रीय दोरीय में स्थित सम्पत्ति पर सोवियत संघ का अधिकार हो गया।

जर्मनी के राजनैतिक भविष्य के बारे में सोवियत संघ एवं पश्चिमी राजनीतिज्ञ स्पष्ट नहीं थे। पोद्सटाम सम्मेलन में इस बात पर विचार ही नहीं किया गया। वे जर्मनी के राजनैतिक रूप का विकेन्द्रीकरण करते ही सन्तुष्ट हो गये। किसी केंद्रीय सरकार की स्थापना नहीं की गई। कुछ समय तक मित्र राष्ट्रों की नियंत्रण परिषद यह कार्य करती रही। स्थानीय एवं राज्य स्तर पर प्रजातन्त्रात्मक मिद्धान्तों पर आधारित स्वायत्त सरकार को बनाये रखा गया। प्रशास्य को पहले तो अनेक राज्यों में विभाजित कर दिया गया और बाद में उसे समाप्त कर दिया गया। तीन बड़े जर्मनी का विसैन्यीकरण करने पर राजी हो गये तथा जर्मन गुट अपराधियों पर शुक्रदमा चलाने पर भी सहमत हो गये।

अप्रैल, १९४५ में पश्चिमी शक्तियों को पूरे बिना ही सोवियत अधिकारियों ने समाजवादी नेता कार्ल रेनर (Karl Renner) के नेतृत्व में आस्ट्रियन सरकार बनाने के लिए कदम उठाये। कार्ल रेनर १९१८ में आस्ट्रियन गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष था। सोवियत संघ का यह चयन आश्चर्यजनक था क्योंकि रेनर लेनिन के साथ सैद्धान्तिक मतभेद रखता था तथा उसे साम्यवाद विरोधी माना जाता था। यह कहा जाता है कि उस समय आस्ट्रिया में अन्य कोई साम्यवादी ही नहीं था। आस्ट्रियन मन्त्रीमण्डल के १२ पदों में से केवल तीन पदों पर ही साम्यवादी थे। इनमें से एक को अन्तरंग का मन्त्री बनाया गया तथा मुद्रित उसने हाथ में सौंने गई।

सोवियत संघ के इस एक तरफा कार्य से पश्चिमी शक्तियां नाराज हुयीं तथा आस्ट्रिया की सरकार को पोद्सटाम सम्मेलन तक मायता प्रदान नहीं की। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि विषया में मित्र राष्ट्रों की एक नियंत्रण परिषद बनाई जाये तथा नगर और शहर को कार्यकारी क्षेत्रों (Occupation Zones) में बांट दिया जाये। इस प्रकार आस्ट्रिया में भी जर्मनी की सी स्थिति पैदा हो गई। रेनर ने इसकी तुलना करने हुए बताया कि यह ऐसा लगता है जैसे कि चार बड़े हाथी किसी छोटी नाव डोंगी में चढ़ गये हैं। आस्ट्रिया की शक्तिपूर्ति के भार से मुक्त कर दिया गया।

तेहरान तथा पाल्टा सम्मेलनों में शालिन ने कालासागर स्ट्रेट का प्रश्न उठाया किन्तु उन पर अधिक जोर नहीं दिया। उसने स्ट्रेट में अड्डों की मांग इस आधार पर की कि इन पर अधिकार करके ही टर्की रूस के गले को पकड़ने में सक्षम हो जायेगा। पाल्टा सम्मेलन के बाद टर्की ने घुरी राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार वह एक मित्र राष्ट्र बन गया। २० मार्च को सोवियत सरकार ने सन् १९२५ की सोवियत-तुर्क शान्ति की

रद्द कर दिया। टर्की ने इसकी प्रतिनिधित्वरूप अपनी सेना को सन्धि रखने हुए पश्चिमी शक्तिशाली से जपान की। पोर्टस्मथ सम्मेलन में सोवियत अधिकारियों ने स्ट्रेट के सोवियत रुढ़ी पर पश्चिमी स्वोक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ट्रुमैन ने इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह सुझाव कि स्ट्रेट का विमोचन तथा अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। १९५१ बाद-विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि १९२६ की मान्डीआक्स सम्मेलन का सशोधन किया जाये क्योंकि यह समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इस सम्मेलन के अनुसार टर्की को स्ट्रेट का सरलक बनाया गया था।

जापान की हार

(The Defeat of Japan)

पोर्टस्मथ सम्मेलन में तीन बलों ने इस बात पर विचार किया कि जापान को किस प्रकार हराया जाये। अमरीकियों की भांति सोवियत राष का भी यह विचार था कि जापान जापानियों के साथ युद्ध कुछ समय तक चलाना पड़ेगा। याल्टा सम्मेलन में रुस ने यह वायदा किया था कि पाश्चिमी युद्ध के समाप्त होने के तीन माह बाद ही यह प्रशान्त-युद्ध में शामिल हो जायेगा। अग्रेल १९४५ में रुस ने १९४१ में दिये गये सोवियत-जापान समझौते को रद्द कर दिया। स्टालिन ने मर्दे-बून में जब हॉन्किंग से बातचीत किया तो यह शिकायत की कि चीन युद्ध में शामिल होने की उन सोवियत शर्तों पर सहमत नहीं है जो तीन बलों द्वारा याल्टा सम्मेलन में मानी गई थी। जब तक चीन इनकी नहीं मानेगा तब तक रुस भी प्रशान्त युद्ध में शामिल नहीं होगा।

चीन की सरकार ने याल्टा सम्मेलन के निर्णयों का बहिष्कार कर दिया था क्योंकि इनमें चीन के हितों का ध्यान नहीं रखा गया था तथा इससे बातचीत भी नहीं की गई थी। चीन का प्रतिनिधि मण्डल जुलाई में नास्को आया। सभी छहों बात चल रही थी कि सोवियत नेताओं को पोर्टस्मथ जाना पड़ा। जाने के कुछ समय पूर्व ही उनकी जापान का यह प्रार्थनापत्र मिला जिसमें उनसे शान्ति के लिए मध्यस्थता करने को कहा गया था। इससे यह लगने लगा कि युद्ध सम्भवतः सोवियत राष से पूर्व ही समाप्त हो जायेगा।

बता जाता है कि पोर्टस्मथ में राष्ट्रपति ट्रुमैन ने प्रथम अनुभव के समक्ष परीक्षण की सूचना दी थी किन्तु सोवियत तानाशाह पर इस सूचना का बहुत कम प्रभाव हुआ। यह परीक्षण १६ जुलाई, १९४५ को आलाभागीडों

(Alamagordo) में किया गया था। सम्मेलन में स्टालिन के दृष्टिकोण पर इस परीक्षण का कोई प्रभाव न हुआ।

पोट्सडाम से लौटने के बाद सोवियत नेताओं ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सोवियत सेना ने ८ अगस्त, १९४५ को मंचूरिया पर आक्रमण किया। इस दिन जर्मनी के आत्मसमर्पण की ठीक तीन माह हुए थे। इसके एक सप्ताह बाद अर्थात् १४ अगस्त, १९४५ को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस एक सप्ताह के युद्ध के लिए सोवियत सभ ने प्रचुर पुरस्कार प्राप्त किया।

१४ अगस्त, १९४५ को ही चीन के विदेशमन्त्री ने मास्को में एक सन्धि समझौते पर दस्तखत किये। इससे छ सहायक समझौते भी संयुक्त थे। इनके अनुसार ये दोनों देश जापान के विरुद्ध तीस वर्षों के लिए सन्धि समझौते में बंधे। दोनों देशों ने एक दूसरे के सम्मान एवं सम्प्रभुता का आदर करने का तथा एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। सोवियत सरकार ने चीन की राष्ट्रीय सरकार को नैतिक एवं भौतिक समर्थन देने का वायदा किया। रूस ने सिन्कियांग तथा मंचूरिया में चीन के अधिकार को मान्यता दी तथा युद्ध के तीन माह बाद इन प्रदेशों को खाली करने का आश्वासन दिया। आर्थर श्वन्दरगाह चीन तथा सोवियत सभ का संयुक्त रूप से नौसैनिक अड्डा बन गया। डैरन (Dairen) को स्वतन्त्र बंदरगाह घोषित कर दिया गया। चीनी चान्गुंग रेलवे को सोवियत सभ व चीन के सम्मिलित स्वामित्व एवं प्रबन्ध के अधीन रखा गया। चीन ने बाहरी मंगोलिया की स्वतन्त्रता को मान्यता दे दी किन्तु इसके लिए यहाँ जनमत संग्रह किया जाना जरूरी था। २ अक्टूबर, १९४५ को प्रसारित शान्ति के घोषणा पत्र में स्टालिन ने कहा कि पुरानी पीढ़ी के लोग चालीस वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे।

जापान में सोवियत सभ को पर्याप्त लाभ रहा। इसके अतिरिक्त योरोप तथा अन्य प्रदेशों में उसकी प्राप्ति का पर्याप्त थोड़ा। पूर्व एशिया में जापान की सरकार ने जो छोड़ा था उसे सोवियत सभ ने पा लिया। इसके साथ ही योरोप में भी उसने नये प्रदेशों को जोड़ लिया। इस सबको मिलाकर सोवियत सभ की लगभग ४६०००० वर्ग मील भूमि प्राप्त हो गई जिस पर लगभग दस करोड़ लोग रहते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही जो शान्ति स्थापित हुई वह शीत युद्ध की भूमिका बन गई। क्लासविज (Clausewitz) के मतानुसार सोवियत नेताओं के लिए सन्धि व अन्य साधनों से युद्ध को जारी रखना था।

द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत रूस अथवा

द्वितीय महायुद्धोत्तर सोवियत विदेश नीति

द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सोवियत रूस ने जो भूमिका उदा की अथवा उसकी जो वैदेशिक नीति रही, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं—

(१) उपग्रवादी नीति का स्टालिन काल (१९४५-५३), एवं

(२) स्थातिपूर्ण प्रतियोगिता का स्टालिनोत्तर काल (१९५३-१९६६)

उपग्रवादी नीति का स्टालिन काल, १९४५-१९५३

(Stalin Period, 1945-1953)

सोवियत रूस के इस काल में सोवियत नीति का नियामक मार्शल स्टालिन था। जहाँ द्वितीय महायुद्ध के समय स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों को पूर्ण सहयोग दिया वहाँ युद्ध की समाप्ति के पश्चात् उनकी नीति उपग्रवादी, कठोर एवं कालू हो गई। युद्धोत्तर उसकी नीति ने उसके इस विश्वास को प्रकट कर दिया कि पूँजीवादी पश्चिमी जगत सोवियत रूस के विनाश का पथचर च रहा है और उसके साथ मंत्री असम्भव है। पूर्वी यूरोप में स्टालिन की सैनिक एवं राजनीतिक साम्राज्यवादी नीतियाँ और देश-विदेश में मार्क्स, लेनिन के सिद्धांतों के पूर्ण पालन पर जोर देना, तथा कभी समझौता न होने योग्य मन मुटावों को बनाये रखना आदि स्टालिन के कार्य शीत-युद्ध की सत्यागत रूप देने के कारण बन गये।

परन्तु इस प्रकार के वातावरण और शीतयुद्ध के विकास के लिये अवैला रूस ही जिम्मेदार नहीं था। पश्चिमी राष्ट्रों ने द्वितीय महायुद्ध के दौरान ही प्रचंड-वप्रचंड रूप से और द्वितीय महायुद्ध के बाद भयावह रूप से साम्यवाद का हौवा उठा करना आरम्भ कर दिया था। उनके इस व्यवहार ने सोवियत रूस के हृदय में प्रस्फुटित हुई सहयोग और सौहार्द की कलियों को खिलने के पहले ही नष्ट कर दिया और स्टालिन ने महायुद्ध के उपरान्त एक उग्रतावादी और हठधर्मी का रूप अपनाया जिसने शीतयुद्ध को उसकी मृत्यु तक चरम सीमा पर पहुँचा दिया।

स्टालिन द्वारा इस दुराग्रही मनोवृत्ति एवं व्यवहार पर आगे बढ़ते जाने का एक प्रधान कारण यह था कि युद्ध समाप्त होने पर सोवियत संघ की स्थिति कई दृष्टियों से पूर्वापेक्षा अधिक अच्छी हो गई थी। पश्चिम में उसकी काल सेनाएं मध्य यूरोप तक के प्रदेश पर अधिकार जमा रही थी। पश्चिम और पूर्व में उसके दो बड़े सन्, जर्मनी और जापान शून्यतः पराधाही हो

सुके थे। पश्चिमी यूरोप की भीषण आपिण इदेश से चल जनता साम्यवाद की आम-जन दे रही थी वहा मन्वारें अस्थिर थी और साम्यवाद के प्रसार की दली सम्भावना विद्यमान थी। एशिया और अफ्रीका म यूरोपियन साम्राज्यवाद क विरुध प्रयत्न विद्रुह और अस्-रोप का सागर सहारा रहा था। ब्रिटिश फ्रेंच और डच साम्राज्य अपन विनाश की अन्तिम कहानी सुनाने को थे। मही साम्यवाद क धोर सन् पादचात्य पूजीपति राष्ट्र युद्ध से विध्वस्त और आन्दि दृष्टि स अस्त-व्यस्त अवस्था म थे, और नी नाना प्रकार की परल समस्याए उन्हें निर्वल एव क्षीण बनाये हुई थी। इस तरह द्वितीय महायुद्धोत्तर स्थिति लगभग सब ओर इस प्रकार की थी कि जहा साम्यवाद अपन पर रोपने मे हर दिशा मे न्यूनाधिक रूप से सफल हो सके। विश्व का यह वातावरण साम्यवाद के प्रसार के अनुकूल था और इस के लिये अपना प्रभाव बढ़ाने का यह स्वर्ण अवसर था। स्टालिन जैसा पाप राजनीतिज्ञ इस अवसर का प्रत्येक लाभ प्रत्येक तरीके से उठाना चाहता था, और इसके लिये सबसे उपयुक्त मार्ग यही था कि पश्चिम की अतीत की कहानी को बुरेदा जाय। आरोपो-प्रत्यारोपो की गोली वर्षा मे चीनयुद्ध को बढ़ावा दिया जाय और पश्चिम के प्रत्येक प्रस्ताव के प्रति अड़गोशानी की नीति अपनाई जाय। चारो ओर क साम्यवाद के लिये अनुकूल वातावरण से लाभ उठान का लोभ सवरण कर पाना स्टालिन क लिये मुश्किल था और स्थिति ऐसी थी कि यदि पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति शिफायन क कुछ जायज कारण वास्तव मे न हो ता नी सोविशत रूप द्वारा बन्ध पैदा किया जाता। मोल्ोटोव न ६ नवम्बर, १९४७ को इस की उपयोगत भावना का व्यक्त करत हुए ही, ये श द बहे थे—“हम ऐसे युग म रह रह हैं जिसम सब मडक साम्यवाद की ओर ले जाने वाली हैं।”

स्टालिन का दिक्वास था कि इस समय पश्चिमी देशों पर डाला गया प्रबल दबाव साम्यवाद क प्रसार म सहायक होगा और इसीलिए उसने सर्वथ उग्र, आक्रमणात्मक एव अग्रगामी नीति का अनुसरण किया। उसके शासन काल में मध्यपूर्व मे टर्की और ईरान पर दबाव डालने की घटनायें हुई, यूनान के गृहयुद्ध मे भाग लेने, कामिनिफोर्म बनाने, बल्कन का घेरा डालने, संयुक्त राष्ट्र सभ म अमेरिका के साथ संघर्ष करने, साम्यवादी चीन मे समझौता करने और कोरिया के युद्ध में उलशने आदि की दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई जिन सब पर पहले यथाम्यान प्रकाश डाला जा चुका है। स्टालिन काल मे मय की विदेश नीति की जो प्रकृति रही, उसे निम्नानुसार प्रकट करना सुविधाजनक होगा—

(१) पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुता का विस्तार

पूर्वी यूरोप में रूसी प्रभुता की स्थापना पीटर महान् क काल से ही रूसी विदेश नीति का एक प्रधान लक्ष्य रहा है । द्वितीय महायुद्ध ने सोवियत संघ को अपने इस प्राचीन स्वप्न को पूरा करने का एक स्वर्ण अवसर प्रदान कर दिया । युद्ध का अनन्त से लाभान्वित होकर रूस न यह हट निश्चय कर लिया कि उसकी विदेश नीति का संचालन इस प्रकार होना चाहिये जिससे उसके पश्चिम में स्थित पड़ोसी राज्य उसके साथ हमेशा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखें । चूंकि साम्यवाद पूर्वी यूरोप के सभी देशों को जर्मनी की दासता से लाल सेना ने ही मुक्ति दिलाई थी, अतः इन देशों में सोवियत संघ के प्रति अपार सहायभूति थी । रूसी प्रभाव इन देशों में पहले ही से इसलिए भी व्याप्त था कि युद्धकाल में इन देशों की साम्यवादी पार्टियों ने ही जर्मनी के विरुद्ध लड़े जान वाले छापामार सपनों का नेतृत्व किया था । इन परिस्थितियों में युद्धोपरान्त इन देशों की साम्यवादियों के हाथ में ही राजनीतिक सत्ता आयी । इस सत्ता स्थापना में रूसियों की लाल सेना से बड़ी सहायता मिली जिसने अदभुत रूप से युद्धकाल में ही मध्य और पूर्वी यूरोप के बड़े भाग पर अधिकार कर रखा था । १९२६ से सोवियत संघ ने अपने क्षेत्रफल में २७ करोड़ ४० लाख वर्गमील की वृद्धि कर ली थी, और अब चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, अल्बानिया, बल्गेरिया तथा यूगोस्लाविया के लगभग ३६ करोड़ वर्गमील के क्षेत्र के ७ राज्य मास्को क कृपणोपक वन गये यद्यपि युगोस्लाविया कुछ समय तक सोवियत गुट में रहने के बाद सोवियत प्रभाव से काफी दूर हट गया । इन देशों के अतिरिक्त अधिष्ठान पूर्वी जर्मनी भी रूसी संरक्षण में ही था और यहाँ जिस दासता प्रणाली को कायम किया गया वह समाजवाद के सिद्धान्तों के ऊपर आधारित थी ।

रूस की वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक सफलता थी कि अपने युद्धोपरान्त १९४८ तक की तीन वर्ष की अल्पवधि में पूर्वी यूरोप के सात देशों को पूरी तरह लाल बना दिया था । स्वभावतः पश्चिमी देश सोवियत संघ के प्रभाव को इस तरह बटता हुआ नहीं देख सकते थे । फरवरी, १९४५ के याल्टा सम्मेलन में पश्चिमी शक्तियों ने पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभुत्व के विकास को रोकने का जो प्रयास किया था उसकी यह पूरा हत्या थी । इस सम्मेलन में ट्रुवेल्स, स्टालिन और चर्चिल ने “मुक्त यूरोप सम्बन्धी घोषणा” (Declaration on Liberated Europe) पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों के लिए यह वचन दिया गया था कि उनमें से प्रत्येक में “जनता के लोकतान्त्रिक सत्ता का विस्तृत रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी

अन्तरिम सरकार स्थापित की जायगी जो यथाशीघ्र स्वतन्त्र चुनावों के जरिये जनता की इच्छा के अनुसार एक नयी सरकार स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हो। परन्तु पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करने सम्बन्धी कार्य 'बाल्टा भावना' का परित्याग था। स्टालिन द्वारा अपने वचन को पूरा नहीं किया गया था और यह स्थिति पश्चिमी देशों को क्रुद्ध करने वाली थी।

स्टालिन पिनरैंण्ड को भी अपने वशीभूत करने से नहीं चूका। फरवरी, १९४७ में फिनलैंड के साथ अपने शांति संधि की और अप्रैल, १९४८ में मैत्री की संधि। इस संधि द्वारा स्टालिन ने फिनलैंड की स्वतन्त्रता को बने रहने दिया, परन्तु फिनलैंड से यह वचन भी ले लिया कि वह रूस विरोधी विदेश नीति नहीं अपनायेगा।

सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करके अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लक्ष्य में निश्चित रूप से उत्साहपूर्वक सफलता प्राप्त की। सोवियत संघ ने इन देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु बहुत से समझौते किये। इनके अन्तर्गत उसने इन्हीं निश्चित अवधि के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री देना स्वीकार किया। १९४७ की 'मोलोटोव योजना' ने इन देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए इनके औद्योगिक-परण पर बल दिया। लोक गणतन्त्रों की स्थापना अथवा दूसरे शब्दों में साम्यवादी शासन सत्ता की स्थापना के बाद इन देशों का पश्चिम के साथ व्यापार पूर्वापेक्षा बहुत कम हो गया। जहाँ १९३८ में पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप की ३४ करोड़ डॉलर का सामान भेजने थे वहाँ १९५० में यह राशि गिरकर केवल १४ करोड़ डॉलर पर आ गयी। इसके विपरीत जहाँ १९३८ में सोवियत संघ का इन देशों के साथ व्यापार कुल २ प्रतिशत था, वहाँ १९५२ में यह बढ़कर ८० प्रतिशत हो गया।

६ मार्च, १९४१ को सोवियत संघ और पोलैंड के मध्य हुए एक समझौते के अन्तर्गत रूस ने पोलैंड को ३, ७८, ७५, ००० डॉलर विदेशों से खाद्यान्न, मशीनरी और कच्चा माल खरीदने के लिए उधार दिये। १२ जुलाई, १९४७ को चैकोस्लोवाकिया के साथ एक व्यापारिक संधि की गयी जिसके अनुसार सावित्रत संघ ने चार मशीनरी एवं मशीनों द्वारा उत्पादित सामग्री के बदले में चैकोस्लोवाकिया को खाद्यान्न, रुई, खाद और धातुएँ देना स्वीकार किया। चैकोस्लोवाकिया के साथ ही १९४८ में एक अन्य समझौता हुआ जिसके द्वारा रूस ने उसे श्रृंग के रूप में एक बड़ी राशि देना मंजूर किया। १९४८ में हंगरी के साथ भी दो व्यापारिक संधियाँ की गयीं जिनके अनुसार कपड़ा, तेल और धातुमाइट के बदले में रूस ने उसे कच्चा

मात देना स्वीकार किया। इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी स्टालिन काल में सोवियत संघ द्वारा इसी प्रकार की संधियाँ सम्पन्न की गयीं।

सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को और भी घनिष्ठ बनाने के लिए १९४६ में 'आर्थिक क्षेत्र में पारस्परिक सहायता के लिए कोमिल' (Council for Economic Mutual Assistance, Com Con) की स्थापना की गयी। इस 'कोम कोन' को पश्चिम द्वारा स्थापित 'यूरोपियन पुनर्निर्माण कार्यक्रम' (European Recovery Programme, E R P) का प्रत्युत्तर कहा जा सकता है।

राजनीतिक क्षेत्र में पूर्वी यूरोप पर सोवियत प्रभाव स्थापित होने का आघात तो पश्चिमी शक्तियों को लगा ही था, आर्थिक क्षेत्र में भी रूस के व्यापक प्रभुत्व से पश्चिमी देशों और रूस के तनावों में अभिवृद्धि हुई। पूर्वी यूरोप परम्परा से पश्चिमी देशों को खाद्यान्न एवं अन्य माल का निर्यात करता था। पश्चिम के कुछ देश तो अपनी अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के लिए पूर्वी यूरोप पर आश्रित थे, उदाहरणार्थ इमारती लकड़ों और निकेल (Nickel) पश्चिम को अधिकांशतः पूर्वी यूरोपियन देशों से ही प्राप्त होती थी। ये देश सोवियत प्रभाव क्षेत्र में चले जाने से पश्चिम के लिए 'निर्यातक' देश नहीं रहे जिससे पश्चिम के कुछ देशों की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। साथ ही पूर्वी यूरोप में बेरोज़गारी, कानूनानुषंग और वयोग्रन्थों के राष्ट्रीयकरण हो जाने से पश्चिमी देशों को जो पूँजी इन देशों में लगी हुई थी, उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ा। इन सब बातों का परिणाम यही निकला कि पश्चिमी देशों में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन तंत्रों के प्रति पूर्ण कटुता पैदा हो गयी। स्टालिन की नीति ने शीत युद्ध को तेज किया।

सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच मंत्री और पारस्परिक सहायता की अनेक सैनिक संधियाँ भी हुईं। पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया तथा युगोस्लाविया के साथ तो सैनिक संधियाँ युद्धकाल में ही की जा चुकी थी। इसके बाद १५ मार्च, १९४६ से १६ अप्रैल, १९४६ तक १७ द्विपक्षीय संधियाँ (Bilateral Treaties) की गयीं। इन संधियों को किन्हीं भी समावित जर्मन आक्रमणों को रोकने के लिए किया गया। बाद में १४ मई, १९५५ को इन देशों ने वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर करके सोवियत संघ के साथ अपने को और भी घनिष्ठ मंत्री में बाँध कर लिया।

स्टालिन काल में सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के पारस्परिक सम्बन्धों में जहाँ हर प्रकार से सफलता का पलड़ा रूस के पक्ष में भारी रहा,

वहाँ रुस को इस क्षेत्र में कुछ अवसरनाओं का सामना भी निश्चित रूप से करना पड़ा। यूनान में एक साम्यवादी शासन की स्थापना के रुखी प्रयास असफल रहे। ट्रूमैन सिद्धान्त के कारण रुस वाले सागर में टर्की से मनोवाञ्छित रियायत और अधिकार पाने में सफल नहीं हो सका। परन्तु इनमें सबसे अधिक साधार्तिक असफलता रुस को युगोस्लाविया के मामले में हाथ लगी, क्योंकि कुछ समय तक रुसी गुट में बने रहने के बाद युगोस्लावियन राष्ट्रपति टीटो ने रुस के प्रभुत्व को स्वीकार करने से मना कर दिया और जून, १९४८ में युगोस्लाविया रुसी गुट से पृथक् हो गया। मार्शल टीटो ने, जो स्वतन्त्र विचारों वाले एक कटुतर राष्ट्रवादी हैं, स्टालिन को इस नीति को पसन्द नहीं किया कि सोवियत रुस पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासन तन्त्रों पर या युगोस्लाविया पर अपनी निगरानी रखे और उन्हें 'लौह आवरण' (Iron Curtain) के भीतर छिपाये रखे। मार्शल टीटो ने जर्मन दामना से अपने राष्ट्र को मुक्त करने के लिए घोर छानामार सर्प किया था, रुसी सहायता से उन्हें बहुत बाद में जाकर मिल पायी। अतः टीटो की लोक-प्रियता युगोस्लाविया में आकाश छूती थी और वह इस बात को पसन्द नहीं करते थे कि उन्हें 'स्टालिन का अनुचर' माना जाय, अथवा उनके राष्ट्र को 'सोवियत रुस का पिछलग्गु' कहा जाय। अतः युद्ध समाप्त होने के उपरान्त जर्मन-शर्म मार्शल टीटो ने स्टालिन के शिक्षण से बचने का प्रयास किया और मास्को के नियन्त्रण में रहने के प्रति अनिच्छा जाहिर की तो रुस की साम्यवादी पार्टी ने मार्शल टीटो की दल विरोधी एवं हन-विरोधी नीतियों को मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के विरुद्ध बताया और कहा कि यह राष्ट्रवाद से प्रभावित एवं पूँजीवाद की ओर झुका हुआ कृत्य है जिससे विश्व के मजदूर आन्दोलन पर गहरा एवं विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मार्शल टीटो पर स्टालिन ने हर प्रकार से दबाव डालने की चेष्टा की किन्तु वह टीटो की अपने कर्ज से म नहीं ला सका। टीटो को यह कतई पसन्द न था कि युगोस्लाविया स्थित लाल सेना युगोस्लाविया के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करे, अतः उसने सोवियत नागरिक और सैनिक अफसरों पर कड़ी निगरानी रखते हुए स्टालिन से स्पष्ट शर्तों में माग की कि रुसी फौजें युगोस्लावियन क्षेत्र से हटा ली जाय।

स्टालिन और टीटो के मतभेद बढ़ते गये। फरवरी २८ जून, १९४८ को 'कॉमिन्फोर्म' (Communist Information Bureau, *Совинформбюро*) ने युगोस्लाव साम्यवादी पार्टी पर यह आरोप लगाया कि उसने अपनी सरस्यता से बिध्वस्त कर दिया कि उसकी नीतियाँ मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के सिद्धान्तों के प्रतिवृत्त हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि

युगोस्लाविया की सरकार सोवियत संघ के प्रति अमेरिका की नीति का अनुसरण कर रही है और कृपणों के प्रति अपनी नीति की निर्धारित करते समय वह बड़े विदेशों की अहंता करने भावमूलक के सुस्थापित मार्ग से हट गयी है। प्रस्ताव में यह आरोप भी लगाया गया कि युगोस्लाविया की साम्यवादी पार्टी न उसके विरुद्ध की गयी आलोचनाओं को आत्म-आलोचना की कसौटी पर नहीं कमा है और इस प्रकार साम्यवादी पार्टी सगठनात्मक सिद्धान्तों के विपरीत आचरण करने की दोषी है। २२ जून को युगोस्लाव नेताओं ने कोमिनफोर्म द्वारा लगाये गये आरोपों को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सोवियत संघ और युगोस्लाविया के बीच गीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गयी जो स्टालिन की मृत्यु पर्यन्त (मार्च १९५३) चलती रही। वास्तव में स्टालिन ने टीटो को अपने समकक्ष मानने से इन्कार कर दिया और उसके प्रति पूर्ण विरोध की नीति पर आचरण किया। रोबिन्सटोन (Alvin Y Rubinstein) के शब्दों में 'टीटोवाद' सोवियत प्रभाव की प्रतिक्रिया से कुछ अधिक था। इसमें राष्ट्रवाद तथा साम्यवाद को एक ऐसी विचारधारा व आन्दोलन में मिला दिया गया जिसके विभिन्न रूप में स्वतन्त्रता की वृत्ति जो मास्को को स्वीकार नहीं थी।¹

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के 'भाईचारे' के विरुद्ध किये गये टीटो के इस विद्रोह का पश्चिमी देशों ने स्वाभाविक मुकदमों से स्वागत किया। इस विद्रोह को 'सोवियत साम्राज्यवाद' के विरुद्ध पूर्वी यूरोप के विद्रोह का सूचक बताया गया। जुलाई, १९४८ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने युगोस्लाविया की ६ करोड़ डॉलर की सम्पत्ति उसे लौटा दी। युगोस्लाविया व भी अमेरिका को १ करोड़ ७० लाख डॉलर का भुगतान दिया। अन्य पश्चिमी देशों के साथ भी इसी तरह के सद्भावपूर्ण और ले-दे की भावना के समझौते किये। मार्शल टीटो ने, सोवियत रुम से क्षुब्ध होकर, पूर्वी यूरोप के देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की अपेक्षा पश्चिमी देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध वापस करना शुरू कर दिया, किन्तु यह सदैव ध्यान रखा कि उनका राष्ट्र पूर्णतः एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहे जो सोवियत या पश्चिमी प्रभाव से उन्मुक्त अवस्था का आनन्दोपभोग करे।

(२) विश्व में साम्यवादी क्रान्ति का प्रसार

साम्यवाद का एक मौलिक सिद्धान्त सम्पूर्ण विश्व में साम्यवादी सिद्धान्तों का प्रसार व पूँजीवाद का उन्मूलन है। द्वितीय महायुद्ध के बाद

1. Alvin Z. Rubinstein, *The Foreign Policy of the Soviet Union*, P. 245.

विश्व की परिस्थितियों को सोवियत संघ के अनुकूल पाकर मास्को ने साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार की नीति पर घटना शुरू किया। साम्यवादी क्रान्ति को दूसरे देशों में फैलाने के लिए स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ द्वारा सभी प्रकार के उपायों का अवलम्बन किया गया। मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध में यूनानी साम्यवादियों को पड़ोसी साम्यवादी देशों अल्बानिया, बल्गेरिया और यूगोस्लाविया द्वारा सहायता पहुँचाई गई। तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय (Third International) के विश्व पाँचो क्रान्ति के कार्यों को करने के लिए १९४७ में वारसा में एकत्रित यूगोस्लाविया, बल्गेरिया, रूमानिया, हंगरी, पोलैण्ड, रूस, पूरुब, चेकोस्लोवाकिया और इटली की साम्यवादी पार्टियों के नेताओं ने 'बेल्ग्रेड' में साम्यवादी सूचना संस्थान या कमिनिफार्म (Communist Information Bureau Cominform) की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना के घोषणा पत्र में कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पिछला युद्ध "विश्व की मण्डियों में प्रतियोगिता को समाप्ति के लिए लड़ा गया था।" सेकिन रूस ने यह युद्ध यूरोप में लोकतन्त्र के पुनर्निर्माण और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए लड़ा था। कमिनिफार्म का उद्देश्य विश्वव्यापी साम्यवादी आन्दोलन का नेतृत्व करना था।

विश्व में साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार के मौलिक सिद्धान्त की पूर्ति के हेतु द्वितीय महायुद्ध के बाद रूस ने ऐसी नीति का अनुसरण किया कि जिससे पूर्व और पश्चिम में रूसी साम्राज्य का विस्तार हो, रूसी सीमाओं पर रूस समर्थक राज्यों की सरकार स्थापित हों, पुराने बूजुर्बा साम्राज्यों का विघ्न हो और इस सम्पूर्ण नवीन सोवियत साम्राज्य का साम्यवादी विचारधारा के आधार पर निर्माण हो। अपने इसी उद्देश्यों को पाने के लिए स्टालिन ने युद्धोत्तर विश्व समझौतों का समाधान करने में शीघ्रता प्रदर्शित नहीं की। वह अडगेवाजी करके शांति व्यवस्था में विलम्ब करना चाहता था ताकि सत्ता की स्थिति सोवियत संघ के लिए और भी अनुकूल हो जाय। मास्को के विदेश मंत्री सम्मेलन में अमेरिकन विदेश मंत्री मार्शल जब सोवियत नीति से व्याकुल हो गया तो स्टालिन ने उसे कहा "धरतरे की कोई बात नहीं है। समय हमारे पक्ष में है, वह स्वयं समझौता करा देगा।"

(३) पश्चिम का विरोध और शीत युद्ध की उत्पत्ति

सोवियत रूस की पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी शासनों की स्थापना के प्रयत्नों और पश्चिमी घटितियों द्वारा रूसी प्रभाव के प्रसार को रोकने की चेष्टाओं के कारण सोवियत संघ और पश्चिम की 'अनोखी मंत्री' का अन्त हो गया तथा युद्ध समाप्त होने के तीन वर्ष के अन्दर ही दोनों गुटों में गम्भीर

शीत युद्ध प्रारम्भ हो गया। जर्मनी, आस्ट्रिया, इटली आदि शत्रु राज्यों के साथ संधियों की शर्तें इटली के उपनिवेशों का तथा राष्ट्रमण्डल के मेम्ब्रेट वाले प्रदेशों का विभाजन, जर्मनी के निःशस्त्रीकरण और एकीकरण की समस्या, पश्चिमी देशों तथा रूस के स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र सम्बन्धी विचारों का मौलिक अन्तर, क्षतिपूर्ति, मध्यपूर्व में प्रभुता पाने के लिये तीव्र प्रतियोगिता आदि ऐसी घटनाएँ या बातें उपस्थित हुईं कि जिन पर दोनों पक्षों में उग्र मनभेद प्रकट हुए और फलस्वरूप शीत युद्ध की उग्रता बढ़ी। जहाँ पश्चिमी राष्ट्र कामिनिफोर्म की गतिविधियों और रूसी प्रभाव के प्रयासों व स्टालिन की अद्भुत कूटनीतिक चालों व हठधर्मों आदि से आशंकित और बस्त हो गये वहाँ सोवियत संघ के इस विरिक्त को सम्बन्ध मिला कि पश्चिमी राष्ट्र उनके सम्मेलन का पडगमन करने में लगे हुए हैं। रूस की दृष्टि में द्रुमैत सिद्धान्त, मार्शल योजना बर्लिन के घेरे के समय दी गई हवाई महायता, आपान व जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण, यूनेन एव प्लेवन योजनाएँ, कोरिया युद्ध आदि पश्चिमी राष्ट्रों के ऐसे कार्य थे जो रूस के प्रति पश्चिम के विशेष कर अमेरिका के घोर विरोध और उनकी उग्र शत्रुता के प्रमाण कहे जा सकते थे। आणविक क्षति से सम्पन्न समुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी गुट को इन कार्यवाहियों से स्टांलिन को आग्रहाएँ उत्तरोत्तर बढ़ती गईं और वह पश्चिम की प्रत्येक कार्यवाही तथा गतिविधि का विरोध करने लगा।

यद्यपि स्टालिन पश्चिम के प्रति अपनी नीति को शांतिपूर्ण सहप्रस्तित्व, (Peaceful Coexistence) का जाया पहनाता था, परन्तु उसके कार्य-कलापों से यह स्पष्ट हो गया कि 'शांतिपूर्ण सहप्रस्तित्व' की इस नीति से उसका अभिप्राय केवल इतना था कि दोनों पक्षों में महायुद्ध नहीं होता चाहिए। एक प्रचारात्मक वाक् युद्ध और कोरिया जैसे स्थानीय युद्धों को वह इस नीति के विरुद्ध नहीं समझता था। स्टालिन की इस नीति का एक अनिवार्य परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे पश्चिम और साम्यवादी क्षत्रियों का शीत युद्ध उग्रतर होता चला गया। स्टालिन ने अपने समय में जो चीजें की दिये और उसके फलस्वरूप पश्चिमी राष्ट्रों की जो प्रतिक्रियाएँ हुईं तथा उन प्रतिक्रियाओं के कारण रूस में जो अन्य प्रतिक्रियाएँ हुईं और इस प्रकार क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का जो चक्कर चला उसके फलस्वरूप जर्मनी से अब तक और आस्ट्रिया से १९५५ तक शांति संधि नहीं हो सकी। रूस और उसके साथी देशों ने जापानी शांति संधि पर हस्ताक्षर करने से भी इन्कार कर दिया। यद्युतः स्टालिन युग में जो नौ कार्य किये गये उन सभी से न्यूनाधिक रूप में शीत युद्ध की अभिवृद्धि ही हुई।

(४) लौह आवरण की नीति

द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त सावियत सघ ने एक ओर तो विश्व में साम्यवादी क्रान्ति के प्रसार के उद्देश्य से एक उग्र नीति को अनायास तथा दूसरी ओर पूर्वी यूरोप में स्थापित साम्यवादी व्यवस्थाओं और स्वयं सोवियत रुम को मजबूत प्रसार के पश्चिमी प्रभावों से अछूता रखने के उद्देश्य से लौह आवरण (Iron Curtain) की नीति का प्रथम लिपि । महायुद्ध के तुरन्त बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी राज्य साम्यवादी प्रसार को सीमित करने (Policy of Containment of Communism) की नीति का अनुसरण करने लगे जिसके अन्तर्गत साम्यवादी देशों की जनता को साम्यवादी व्यवस्था के विरुद्ध भड़का कर विद्रोह करने का कार्यक्रम भी रखा गया । साम्यवादी देशों के इन्हें निर्दिष्ट अन्तरेडियो स्टेशन स्थापित किये गये जिनका नाम 'आजाद हंगरी रेडियो' 'आजाद पोलैण्ड रेडियो' आदि रखा गया और इनके माध्यम से साम्यवाद के विरुद्ध घनघोर जहरीला प्रचार कार्य शुरू हो गया । स्टालिन को यह समझने देर न लगी कि पश्चिमी राज्य साम्यवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न जोर शोर से शुरू कर चुके हैं । उसे भय लगा कि कहीं पश्चिमी शक्तियाँ इस या पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन को दुबल न बना दें । इस भय से बहुत कुछ मुक्ति का अथवा पश्चिमी शक्तियों के उद्देश्य को विकल बनाने का एक ही उपाय था कि साम्यवादी जगत के चारों ओर ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाय कि उसके भीतर अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी राष्ट्रों का प्रचार प्रवेश न कर सके । स्टालिन ने इसी उपाय को अपनाने हुए यह निर्णय कर लिया कि वह रुम एवं पूर्वी यूरोप के साम्यवादी जगत को मजबूत साम्यवादी देशों के सम्पर्क से पृथक रखेगा ताकि यह क्षेत्र पश्चिमी प्रभावों से अछूता रह सके । स्टालिन इस बात को समझता था कि रूसियों तथा विदेशियों के पारस्परिक सम्पर्क साम्यवादी व्यवस्था पर प्रतिशूल प्रभाव डालने वाले सिद्ध हो सकते हैं ।

पश्चिम के प्रचार को निरस्त करने और साम्यवाद की उनमें 'दूषित' होने से बचाने के लिए १९४५ से ही ऐसे कानून बनाये जाने लगे कि जिनमें बाह्य जगत के साथ रूसियों का सम्पर्क रूक जाय । ऐसे ही एक कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि युद्ध के समय रुम में आये हुए विदेशी सैनिकों के साथ जिन रुसी स्त्रियों ने विवाह किया था वे अपने पतियों के साथ विदेश नहीं जा सकेंगी । एक अन्य कानून के द्वारा विदेशियों के साथ मोदिप्रान नागरिकों के विवाहों को निषिद्ध बना दिया गया । इनका ही नहीं, विदेशी राजदूतों तथा पत्र प्रतिनिधियों के साथ भी बड़ी कड़ाई का व्यवहार किया

गया। विदेशों में स्थित सोवियत राजदूतों पर भी कठोर अनुशासनात्मक प्रविष्टि लगाये गये। सभी प्रेस पर भी कठोर नियन्त्रण लगा दिया गया।

(५) अफ्रीका तथा एशिया के प्रति सोवियत नीति एवं शान्तिवादी आन्दोलन

अफ्रीका एवं एशिया के प्रति स्टालिन की नीति कीशतपूर्ण किन्तु अनुशार थी। उसने मध्यपूर्व में साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाने की चेष्टा की और दक्षिण कोरिया को साम्यवादी बनाने के लिए कोरिया-युद्ध की प्रेरणा दी। यद्यपि इन दोनों ही प्रयासों में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई, तथापि कोरिया युद्ध ने चीन की सोवियत सभ पर निर्भरता को स्पष्ट कर इस बात का सबूत दे दिया कि तत्कालीन समय में सम्पूर्ण साम्यवादी जगत पर सोवियत नियन्त्रण भली प्रकार स्थापित करने में स्टालिन को पर्याप्त सफलता मिली है।

इसके अनिश्चित, आपत्तिक आयुधों एवं अणुबमों के आतंक से पीड़ित मानवता के परित्राण के लिए सोवियत सभ ने "शांति आन्दोलन" (Peace-Offensive) आरम्भ किया और युज्जोवादी परिचम को युद्ध-लोभुष (War-monger) कहकर बदनाम करने की प्रत्येक चेष्टा की। स्टालिन का "शांतिवादी-आन्दोलन" एक अत्यन्त चानुर्यपूर्ण और सफूर्त चाल सिद्ध हुई। इस आन्दोलन की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना मार्च, १९५० तक स्टारहोम में हुई विश्वशांति समिति की आणविक आयुधों पर बिना शर्त प्रविष्टि लगाने की अपील थी।

इस अपील पर कुछ समय ही में लगभग ५० करोड़ व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये। इस शांति-आन्दोलन ने एशिया और अफ्रीका की विशाल जनसंख्या को बड़ा प्रभावित किया। वे साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए तथा सोवियत रूस की पश्चिम की अपेक्षा अधिक शान्तिप्रिय और जननिवेशवाद विरोधी मानने लगे। साम्यवादियों ने इस आन्दोलन में सब देशों के मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों से सहयोग मांगा। इन्होंने जहाज से सामान उतारने वाले थमिकों में यह प्रचार किया कि अमेरिका से शस्त्रास्त्रों को लाने वाले जहाजों से माल न उतारा जाए और हड़ताल कर दी जाए।

प्रचार की दृष्टि से शांतिवादी आन्दोलन की प्रारम्भ में बड़ी सफलता मिली और न केवल एशिया तथा अफ्रीका बल्कि पश्चिमी राष्ट्रों की सामान्य जनता ने भी इसका स्वागत किया। परन्तु स्टालिन के अनुसार दृष्टिकोण के कारण रूस इस आन्दोलन में प्राप्त लोकप्रियता का पूरा लाभ नहीं उठा सका। वह तटस्थ राष्ट्रों की भावनाओं की ठीक प्रकार से न समझकर उन्हें अपना शत्रु मानता रहा। पश्चिमी राष्ट्रों ने इस के शांतिवादी आन्दोलन

को एक 'निरे ढोंग' की सजा दी और कहा कि यह तटस्थ एवं गैर साम्यवादी देशों को अपनी ओर आकृष्ट करने तथा अपना समर्थक बनाने का सोवियत कूटनीतिक जाल है।

(६) संयुक्त राष्ट्र सच के प्रति सोवियत नीति

स्टालिन के नतुत्व में सोवियत सच ने संयुक्त राष्ट्र सच के निर्माण में सक्रिय भाग लिया। वह संयुक्त राष्ट्र इसी विश्वास पर आधारित था (और है) कि महाशक्तियाँ, विशेषतः सोवियत सच और संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगपूर्वक कार्य करते हुए सच के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक बनेंगी। परन्तु दुर्भाग्यवश यह आशा पूरी न हो सकी और अपने जन्म काल के कुछ ही समय उपरान्त सच शीतयुद्ध का प्रधान अखाड़ा बन गया। लगभग प्रत्येक समस्या पर दोनों राष्ट्र अथवा दोनों गुट दो विरोधी दृष्टिकोण लेकर सच के मंच पर उदस्थित हुए। चूँकि सच में पश्चिमी शक्तियों और उनके समर्थकों का स्पष्ट बहुमत था, अतः सोवियत रूस ने अपने को एक स्थाई एवं निरन्तर अल्पमत में पाया। ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने के लिए उसके पास इसके अतिरिक्त कोई उपाय न था कि वह सुरक्षा परिषद में खुल कर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करे जिससे संयुक्त राष्ट्र सच पश्चिमी शक्तियों के इंगारों पर नाचता हुआ उनके पक्ष में कोई प्रभावशाली कार्य न कर सके। कोरिया युद्ध के समय अल्पकाल के लिए रूस ने संयुक्त राष्ट्र सच की बैठकों का बहिष्कार कर दिया। लेकिन यह बहिष्कार उसके लिए धाटे का सोदा सिद्ध हुआ, क्योंकि इस बहिष्कार के कारण ही संयुक्त राष्ट्रीय सेनाय दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए भेजी जा सकी। इस घटना से हम न यह समझ लिया कि वह संयुक्त राष्ट्र सच की कार्यवाहियों में भाग लेकर, परिषद की बैठकों में उपस्थित होकर पश्चिमी राष्ट्रों के इरादों को अधिन अच्छी तरह रोक सकता है वनिरूपत हमके कि वह सच से बाहर रः और ऐसी चेष्टा करे। इस अनुभूति के बाद से ही फिर कभी रूस ने सच की बैठकों का बहिष्कार नहीं किया। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सोवियत सच ने सुरक्षा परिषद में अपने निषेधाधिकार के प्रयोग से पश्चिम के अनेक अन्धायपूर्ण प्रस्तावों को, जिनमें काश्मीर प्रस्ताव भी शामिल है, धराशायी किया।

स्टालिन की विदेश नीति का मूल्यांकन

यद्यपि स्टालिन ने १९४५ से १९४८ के बीच पूर्वी युरोप पर सोवियत प्रभुत्व स्थापित करने एवं बड़ी सीमा तक पीटर महान् के बाल से चली आ रही रूसी महावाफादारों को पूरा कर लिया, परन्तु उसके बाद स्टालिन

के गर्व, अहंकार और हठधर्मिता से भरी हुई उष नीति सोवियत संघ के लिए अलामकारी ही सिद्ध हुई। दरअसल मे स्टालिन ने मृत्यु पर्यन्त एक आक्रमणकारी, गतिशील, अउपेक्षाशी और लौह आवरण की तथा समझौता विरोधी नीति का अनुसरण किया। पूर्वी यूरोप में अपने बचनों को झुठला कर सोवियत प्रभुत्व का विस्तार किया गया, यूनान के गृह युद्ध ने साम्यवादियों की सहायता की गई टर्की पर वास्कोरस तथा दूर दानियाल के जलडमरूमध्यों के सम्बन्ध में माण्ट्रेक्स (Montreux) के समझौते को बदलने के लिए दबाव डाला गया, मार्शल योजना की सहायता लेना अस्वीकार कर दिया गया, ईरान से साविष्य सेनाओं के हटाने में देर लगाई गई, टीटो को मास्को के गुट से निष्काशित किया गया, कोरिया व हिन्द चीन में युद्ध हुए। स्टालिन को इस आनामक नीति से पश्चिमी शक्तियां सशक्त हो गई और उन्होंने बढ़ते हुए सोवियत प्रभाव को रोकने तथा साम्यवाद के प्रसार के विरोध के लिए अनेक उपाय किए। दृढ़ निश्चय, मार्शल योजना, डक्क, प्रसेल्स संधियां, नाटो, पश्चिम यूरोप की एकता के लिये बनाए गए विभिन्न संगठन आदि स्टालिन की कठोर नीति के प्रभावशाली प्रत्युत्तर थे। १९४५-४७ तक यूरोप की स्थिति स्टालिन के लिए बड़ी अनुकूल थी, लेकिन १९५३ तक यह स्थिति ऐसी नहीं रही। १९४९ में चीन में साम्यवादी विजय तथा १९५० में कोरिया-युद्ध के प्रारम्भ में पश्चिमी शक्तियों को कोरिया, जापान, फारमोसा और दक्षिणी पूर्वी एशिया में साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए कटिबद्ध कर दिया। मध्यपूर्व में टर्की और यूनान में हस्तक्षेप के कारण सोवियत रुख को चेंसी हो बदनामी मिली जंसी बाद में आइजन्हावर सिद्धान्त के प्रयोग से अमेरिका को मिली। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों के प्रति भी स्टालिन की नीति अनुदार रही। अपनी हठधर्मिता के कारण वह इन राष्ट्रों की, स्वयं को दोनों शक्ति गुटों के प्रभाव से बचने की इच्छा जोर नीति को नहीं समझ सका, उन्हें साम्यवाद का शत्रु मानने लगा। इससे उसने एक बड़ी सीमा तक इन राष्ट्रों का समर्थन छो दिया। तदस्य देशों के प्रति स्टालिन ने विरोधी नीति का अनुसरण किया। उदाहरणार्थ, भारत को उसकी तदस्यता के कारण ही स्टालिन रुग्ण विरोधी समझता रहा था। इसीलिए स्टालिन काल के इसी विम्वक्रोप में भारत के स्वाधीनता संग्राम को और महात्मा गांधी को पुञ्जीवाद का समर्थक बताया गया था।

स्टालिन की उपवादी कठोर नीति ने स्वयं साम्यवादी गुट में काफी दोष उत्पन्न कर दिया। जब यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो ने सोवियत संघ का अनुकरण करने से इन्कार कर दिया तो स्टालिन के निकट से निकल पड़ने के लिए अन्य साम्यवादी देशों में भी राष्ट्रवादी साम्यवाद की प्रवृत्तियों

को अधिक समर्थन मिलने लगा। इसकी अभिवृत्ति बाद में १९५६-५७ में पोलैण्ड तथा हंगरी के उपद्रवों में हुई। स्टालिन की 'लोह आवरण' की नीति से अन्य देशों में रूढ़िवादी प्रतिपक्ष और अतिराष्ट्रवादी धारणाओं की बल मिला। जार्ज एफ केनन (George F. Kennan) का मत है कि १९५२ तक सोवियत नीति अनुसर हो गई थी और १९५३ में स्टालिन के उत्तराधिकारियों के लिए उसमें परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया।

बृहत् लाभ स्टालिन की विदेश नीति में रूढ़िवाद (Conservatism) की शक्ति पात्र हैं। उनके अनुसार वह पश्चिम पर शक्ति के बल पर हावी नहीं होना चाहता। उसने पश्चिमी शक्ति एवं सम्मान को नीचे गिराने तथा अपने साम्राज्य की शक्ति एवं स्थायित्व देने के प्रयत्न किये। अधिराज्यों में व्याप्त असन्तोष के प्रति वह सजग था तो भी सोवियत शक्ति के विस्तार के प्रत्येक अवसर का उसने लाभ उठाया। सन् १९५३ की पश्चिमी विचारकों द्वारा सोमार्थसाती माना जाना है जबकि स्टालिन अपने नाम को छोट कर इस विश्व में सिधार गये। कहा जाता है कि स्टालिन ने इस जैसे पिछड़े व अविश्वसित देश को दुनिया की महान् औद्योगिक एवं सैनिक शक्ति बना दिया तथा चगेरखान और तैमूरलंग जैसा साम्राज्य स्थापित कर दिया।

शांतिपूर्ण प्रतियोगिता का स्टालिनोत्तर काल

(१९५३-१९६७)

स्टालिन की मृत्यु तक सोवियत विदेशी नीति में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किन्तु बाद में उसकी नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह फिर से विकासमुखी बनी। स्टालिन के बाद तीन मुख्य विकासों ने सोवियत संघ की नीति को उठा दिया। प्रथम विचार यह था कि पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्राज्य में स्थापित आ गया। दूसरे सोवियत संघ की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। तीसरे, रूस के दक्षिणी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ने लगा। मध्यपूर्व, दक्षिणी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देश उनका प्रभाव के क्षेत्र बन गये। विश्व का मतलब एक प्रकार से साम्यवाद की ओर झुक गया। स्टालिन के बाद यद्यपि सोवियत साम्राज्य नहीं बढ़ा किन्तु सोवियत संघ की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी बढ़ गयी जितनी कि पूरे धर्म नहीं थी। स्टालिन के उत्तराधिकारियों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा वे थे—सोवियत साम्राज्य की रक्षा करना, पूर्वी यूरोप में सोवियत साम्य के स्थापित व पारध, व स्थायित्व प्राप्त करना, तथा जहाँ सम्भव हो उसे बढ़ा देना सोवियत सुरक्षा का मतलब है शक्ति देश की शक्ति का विस्तार करना, साम्राज्य की रक्षा करना, उसे प्राप्त करने से अधिक

कठिन होता है इसलिए उन्होंने इनकी स्थानीय स्वायत्तता प्रदान की, आर्थिक सम्बन्धों को कम शोषणयुक्त बनाया तथा जीवन स्तर के आधुनिक विकास को प्रोत्साहन दिया। स्टालिन के बाद नवियत रुस को चलित समस्या का सामना करना पड़ा, साम्यवादी चीन के साथ इसका रणनीतिक विवाद बढ़ा, माशेल टीटो के साथ मतभेदों का उतार चढ़ाव आया, पोलैण्ड और हंगरी में भ्रष्टाचार हुई तथा एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों में बड़े नातिकारी परिवर्तन एवं सघर्ष हुए और इन सबके कारण सोवियत सघ की विदेश नीति के चक्र की गति काफी तेज हो गई।

मोस्कोव-वाल

स्टालिन की उप्रतावादी कठोर वैदेशिक नीति के जो परिणाम निकले और पश्चात्य देशों एवं तटस्थ देशों में उसकी जो प्रतिप्रिया हुई, उनके फलस्वरूप अब सोवियत नीति का एक नवीन दिशा में उन्मुख होना स्वाभाविक तथा अनिवार्य था। इसीलिए स्टालिन के अविलम्ब उत्तराधिकारी मालेन्कोव ने दिवंगत नेता के अन्त्येष्टि सत्कार में ही घोषणा की कि—
“लेनिन और स्टालिन की शिक्षाओं के अनुसार साम्यवादी तथा पूँजीपति देशों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाएगा।” मालेन्कोव का यह आश्वासन स्पष्टतः इस बात का संकेत था कि स्टालिन के उत्तराधिकारी पश्चिमी एवं गैर साम्यवादी देशों के प्रति स्टालिन-कालीन विरोध की उप्रता और कठोरता में कमी लाना चाहते थे। इसके तुरन्त बाद ही १५ मार्च, १९५३ को सुप्रीम सोवियत ने अपने देश की वैदेशिक नीति का उल्लेख करते हुए सोवियत प्रधानमन्त्री ने जोरदार शब्दों में कहा—“अब सोवियत विदेश नीति का मंचालन आधार की वृद्धि और शांति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से किया जाएगा। कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे शांतिपूर्वक हल न किया जा सकता हो। यह मिद्धान्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित विश्व के सब देशों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू होता है।” सोवियत रुस की नीति में परिवर्तन का संकेत करने वाले इन विभिन्न घोषणाओं के कारण अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों में रुस के विरुद्ध प्रचार में कमी आयी। इसी के परिणामस्वरूप, अब तक पश्चिम के विरुद्ध जाग बरसाने वाले रुसी विदेश मन्त्री विस्सिस्की ने संयुक्त राष्ट्र सभा की एक बैठक में भाषण देते हुए पश्चिम को निमन्त्रण दिया कि “आप मित्रता की सुरंग में आये रास्ते तक आगे बढ़कर हमसे मिलें।” इससे साथ ही पश्चिमी देशों के विरुद्ध रुस द्वारा किये जाने वाले विरोधी प्रचार की उप्रता में भी कमी आ गई।

रूस की इस नई विदेशी नीति के सुखद परिणाम भी शीघ्र ही निकलने प्रारम्भ हो गए। अक्टूबर, १९५२ से चले आने वाले कोरियाई युद्ध का गति-रोध खत्म हो गया और १० अप्रैल, १९५३ को पानमुनजोन में ऋण एवं घायल युद्ध बन्धियों का समझौता होने पर युद्ध भी समाप्त हो गया। रूस द्वारा टर्की और जर्मनी के प्रति मृदु नीति अपनाई गई। १५ मई, १९५५ को वास्तिट्वा के सम्बन्ध में शांति संधि हो गई। फ़िनलैण्ड के सैनिक अड़्डे सोवियत सैनिकों द्वारा खाली कर दिये गये। सोवियत सेना में १ लाख ८० हजार सैनिकों की कमी की गई। १९५४ में जेनेवा सम्मेलन द्वारा हिन्दचीन की समस्या का शांतिपूर्ण हल निकाला गया। सोवियत संघ ने यूनान और इजरायल के साथ पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये। यूगोस्लाविया के साथ मतभेदों को दूर करके उसे पुनः साम्यवादी परिवार में लाने की चेष्टा की गई। २६ अप्रैल, १९५३ को मोलोटोव ने यूगोस्लाव प्रतिनिधि से कूटनीतिक सम्बन्धों की पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में बातचीत की और मई, १९५३ में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक सम्बन्ध फिर से कायम हो गए। इसके उपरान्त सोवियत नेताओं ने यूगोस्लाव साम्यवादी पार्टी के साथ भी अपने सैद्धान्तिक मतभेदों को दूर करने के प्रयत्न किए।

मालेन्कोव के नेतृत्व में सोवियत रूस की लौह आवरण की नीति में भी शिथिलता का वर्तव किया जाने लगा। बाह्य दुनिया से निकट सम्पर्क कायम करने का प्रयास किया गया ताकि सोवियत संघ छोड़े की दीवार में बन्द नहीं समझे जायें। स्टालिन विन्ध को दो विरोधी गुटों में विभाजित मानता था, लेकिन नई नीति के अनुसार इसको शक्ति सतुलन की प्रक्रिया माना गया और इसको अपने पक्ष में करने के लिए तटस्थ राष्ट्रों की सहिच्छा प्राप्त करने की चेष्टा की गई।

खुश्चेव युग

इस समय सोवियत संघ में भीतर ही भीतर नेतृत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। श्री मालेन्कोव इस संघर्ष में पराजित हुए, फलतः ८ फरवरी, १९५५ को उन्हें प्रमानमन्त्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अब मार्शल बुल्गानिन नये सोवियत प्रधानमन्त्री बने तथा श्री खुश्चेव पार्टी के महा सचिव नियुक्त हुए।

१९५५ से १९६३ तक की सोवियत विदेश नीति का युग खुश्चेव युग है क्योंकि फरवरी, ५५ से मार्च १९५८ तक के बुल्गानिन के प्रधान मन्त्रीत्व काल में भी वास्तविक प्रभाव एक प्रकार से श्री खुश्चेव का ही था। इस युग में सोवियत विदेश नीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उसका जिस प्रकार

संचालन हुआ, इन सबका अध्ययन पृथक्-पृथक् शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न रूप से किया जा सकता है—

(१) लौह आवरण में शिथिलता, यात्राओं की कूटनीति—इस युग में सोवियत लौह आवरण की नीति में पर्याप्त शिथिलता आई और 'यात्रा-कूटनीति' का महत्व बढ़ा। सोवियत संघ के विभिन्न सांस्कृतिक, राजकीय शिष्ट मण्डल विदेशों में जाने लगे और विदेशों के ऐसे ही शिष्ट मण्डल साम्यवादी जगत में आमन्त्रित किए जाने लगे। स्टालिन बाह्य देशों के साथ सम्पर्क का घोर विरोधी था और सम्भवतः केवल एक बार तेहरान सम्मेलन के समय अपने देश से बाहर गया था अथवा युद्ध सम्मेलनों में ही चर्चिल और रुजवेल्ट से उसकी मुलाकात हुई। लेकिन अब श्री ख्रुश्चेव, बुल्गानिन आदि उच्चतम स्तर के सोवियत नेता दूसरे देशों का सङ्भाव पाने और उनकी मैत्री अर्जित करने के लिए विभिन्न देशों की यात्रायें करने लगे और उन देशों के नेताओं को अपने महा निमन्त्रित करने लगे।

जून, १९५५ में भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नेहरू सोवियत रूस द्वारा आमन्त्रित किए गए और नवम्बर, १९५५ में श्री ख्रुश्चेव तथा बुल्गानिन ने भारत यात्रा की। इससे दोनों देशों में सङ्भाव और मैत्री की वृद्धि हुई तथा सोवियत नेताओं की भारत की असलानता की नीति के प्रति स्टालिन काल से जो सन्देह बना हुआ था, वह दूर हो गया। अग्रेल, १९५६ में दोनों नेता ग्रेट ब्रिटेन गए। १९५६ के आरम्भ में प्रथम सोवियत उपप्रधानमन्त्री श्री निकोयान ने १५ दिन तक अपने प्रबल विरोधी समझे जाने वाले अमेरिका की यात्रा की और १७ जनवरी को राष्ट्रपति ओडजनहॉवर द्वारा अमेरिका में १९४५ में मोलोटोव के बाद पहली बार व्हाइट हाउस में किसी रूसी राजनीतिज्ञ का स्वागत किया। सोवियत उपप्रधानमन्त्री ने दोनों देशों में व्यापार की वृद्धि की आवश्यक बताया और इस बात पर ध्यान दिया कि 'शीत-युद्ध' (Cold-war) का स्थान 'शांतिपूर्ण प्रतियोगिता' (Peaceful competition) को लेना चाहिए। स्वदेश वापस लौटने पर श्री निकोयान ने ३१ जनवरी, १९५६ को सोवियत साम्यवादी पार्टी के २१ वें अधिवेशन में मास्को में कहा कि उन्होंने अमेरिकन राजनीतिज्ञों और नेताओं के साथ जो भी वार्तालाप किया उसमें उन्होंने कहीं सोवियत साम्यवाद के 'निरोध' (Containment), 'पीछे धकेलने' (Roll back) तथा "साम्यवाद की दासता से मुक्ति" (Liberation) की कोई चर्चा नहीं सुनाई दी। निकोयान द्वारा अमेरिका की अपनी यात्रा से उपयुक्त दावावरण तैयार कर दिए जाने के उपरान्त सितम्बर १९५६ में सोवियत प्रधानमन्त्री श्री ख्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। फरवरी-मार्च,

१९६० में श्री ख़ुश्चेव ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों-भारत, वर्मा इण्डोनेशिया अफगानिस्तान आदि की यात्रा की।

सोवियत नेताओं द्वारा लोह आवरण में सिधिलता किए जाने और विश्व के विभिन्न दशा की यात्रा करने से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में निश्चित कमी हुई और दोना विरावी पक्ष एक दूसरे के प्रति उतने जबरदस्त रादेहनील न रहे जितने स्टालिन काल में थे।

अपनी इन यात्राओं में रूसी नेताओं ने शासनाध्यक्षों के निस्तर सम्मेलन बुलाने पर बारम्बार बल दिया। ऐसा एक सम्मेलन जुलाई, १९५५ में जेनेवा में हुआ जिसने हिंदी की समस्या को बल दिया। दूसरा सम्मेलन मई १९६० में हुआ जो दुर्भाग्यवश सू २ विमानकांड से उत्पन्न वातावरण का शिकार बनकर असफल हो गया।

(२) शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की ओर विचारों का शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा करने की नीति—स्टालिन की मृत्यु के बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का शुभारम्भ मालेम्कोव के प्रधानमन्त्रित्व काल में ही हो चुका था, किन्तु इसे निखार ख़ुश्चेव युग में और बाद में वर्तमान कोसीगिन युग में मिला। फरवरी १९५६ में रूसी साम्यवादी दल की जो २०वीं कांग्रेस हुई उसमें स्टालिन तथा उसकी नीतियों की कटु आलोचना की गई और साम्राज्यवादी देशों से युद्ध की अनिवार्यता के लेनिन सिद्धांत को संशोधित कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सोवियत विदेश नीति का आधार बना दिया। कांग्रेस की विशेष रिपोर्ट में श्री ख़ुश्चेव ने स्टालिन युग में किए गए अनराधा का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि स्टालिन हम प्रकार से व्यवहार करता था मानों वह सब कुछ जानता है सब कुछ दखता है सब के लिये मोक्षता है सब कुछ कर सकता है और गलती भी भा नहीं करता है। वह अपना आपको ईश्वर मान कर चलता था। उसका व्यवहार अमानवीय एवं हिमात्मक था। श्री ख़ुश्चेव ने कहा कि यदि उन्हें और दुश्मानिन की कभी स्टालिन बुलाता था तो उन्हें यह विद्वाम नहीं होता था कि वे सकुशल अपने घर लौट सकेंगे। 'स्टालिन कभी भी समस्या बुझाकर काम नहीं लेता था किन्तु वह अपनी मान्यताओं की लादता था तथा अपने मतों पर पूर्ण अर्पण की मांग करता था। स्टालिन ने एक बार ख़ुश्चेव से मार्गन टीटा के प्रति श्रेष्ठ प्रकट करत हुए कहा था कि—' मैं अपनी छोटी अगुली उठा दूंगा और टीटा नहीं रहगा, वह गिर जायेगा। '

श्री ख़ुश्चेव की प्रेरणा से इनके समय को विराम नीति अंगीकृत की गई उसकी ५ प्रमुख विशेषतायें थी—

प्रथम, जहाँ स्थापित के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अर्थ केवल युद्ध का न होना माना था, वहाँ श्री खुद्देव ने इसका अर्थ यह माना कि सभी गैर साम्यवादी राष्ट्र (विशेषतः एशिया और अफ्रीका के तटस्थ राष्ट्र) सोवियत संघ के साथ नहीं हैं ।

दूसरे, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर दल दिया गया ।

तीसरे, यात्राओं की कूटनीति स्वीकार की गई और यह माना गया कि दूसरे देशों से अच्छे सम्बन्धों की स्थापना करने के लिए सोवियत नेताओं को अन्य देशों की यात्रायें करनी चाहिये तथा लोह आवरण को सिद्धि कर साम्यवादी एवं गैर-साम्यवादी देशों के मध्य सम्पर्कों की स्थापना को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

चौथे, सोवियत संघ द्वारा विश्व के अल्प-विकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता अनुभव की गई ।

पाचवें, पश्चिमी शक्तिशाली को साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी बता कर उनकी निन्दा करते हुए भी उनके साथ लुले संघर्ष की नीति का परित्याग किया गया । खुद्देव के शब्दों में "सोवियत संघ शांति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को मालता है । " हम सद्गुण राज्य अमेरिका या अन्य किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध करने की नहीं सोच रहे हैं " हम शांतिपूर्ण निर्माण में, रचनात्मक कार्य में प्रतिबद्धता करना चाहते हैं ।"

शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नई सोवियत नीति के अनुसार गैर साम्यवादी देशों को एक नहीं, अनेक चीजें बर्णों में बांटा गया है—(१) सद्गुण राज्य अमेरिका (२) अमेरिका के समर्थक और सहयोगी, एवं (३) तटस्थ देश, जैसे भारत, इण्डोनेशिया, इराक, मिस्र, सीरिया, यूगोस्लाविया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड । दूसरे दो दो में पहले दस दुनिया में दो ही रंग के फूल देखता था—लाल और सफ़ेद । अब वह इसमें लाल, पीले, नीले, हरे, सन्नी प्रकार के फूल देखने लगा । पहले उसकी नीति लाल रंग के फूलों के सिद्धांत पर धारण से फूलों के समुच्चय की थी, अब वह उसके साथ-साथ रंग के 'शांतिपूर्ण सहअस्तित्व' की बात करने लगा था । १२ अक्टूबर, १९५४ को सोवियत संघ और चीन की सरकारों की एक सद्गुण घोषणा में स्पष्टतः कहा गया कि वे समस्त देशों के साथ पंचशील के सिद्धान्तों के आधार पर मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति ने सोवियत

संघ में किसी प्रकार का घरेलू परिवर्तन नहीं किया है। हा इस सिद्धान्त के आधारे रूसी विदेश नीति में एक निश्चित लचीलापन (Flexibility) अवश्य प्रविष्ट कर सका है। इण्डरमेशनल र्यूज सर्विस एजेंसी के मुख्य सम्पादक टर्नर आर हर्स्ट (W R Hearst) को एक इन्टरव्यू में थो खुरशेव ने स्पष्ट किया था कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका वा शांति के पक्ष में इसी अराजक तन्त्र को स्वीकार कर ले कि विश्व में एक समाजवाद की दुनिया कायम है जो अपने आदर्शों के अनुरूप जनता के मार्ग पर अग्रसर है एवं इस समाजवादी दुनिया के अतिरिक्त एक पूँजीवाद का संसार भी है तो वह (सोवियत रूस) इन दो विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच सह-अस्तित्व की सम्भावनाओं को स्वीकार कर ले। अपने इसी इन्टरव्यू में थो खुरशेव ने दृढ़ शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि रूस इस बात को किसी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकता कि संसार के प्रत्येक देश पर संयुक्त राज्य अमेरिका हावी होने की चेष्टा करे। यदि अमेरिका पूँजीवादी दृष्टिकोण से विश्व का सर्वाधिक विकसित और और शक्तिशाली देश है तो सोवियत संघ भी सबसे अधिक शक्तिशाली समाजवादी देश है। अतः उचित यही है कि दोनों देश अपने विवादों का हल शस्त्रीकरण की शीट में भाग लेकर के और युद्ध सामग्री एकत्रित करके नहीं करें बल्कि इन्हें हल करने के लिए अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को समुन्नत बनाने और अपनी जनता के सांस्कृतिक विकास व कल्याण को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। थो खुरशेव ने सम्पूर्ण शब्दों में बताया कि कौनसी व्यवस्था अच्छी है—इसका निर्णय हमियारों द्वारा नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो विवेक की आवश्यकता है।

स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को मानने व निश्चित प्रमाण भी सोवियत रूस ने प्रस्तुत किये। उदाहरणार्थ, जुलाई, १९५३ को कोरिया युद्ध की समाप्ति में रूसी सहयोग मित्रा, जनवरी-फरवरी १९५४ में बार बडों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें किये गये निरवय के अनुसार अप्रैल में जो जेनेवा सम्मेलन हुआ उसमें विषयनाम की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया। १५ मई, १९५५ को आस्ट्रिया के साथ शांति संधि हुई। जुलाई, १९५५ में चार बडों का शिखर सम्मेलन हुआ जो १९४५ के पोद्सडम सम्मेलन के बाद चार बडों की पहली बैठक थी। इसमें हिन्दचीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण निबटारा हुआ। इसी मध्य १५, जून १९५५ को सोवियत संघ ने बालेमागरीय प्रदेश में टर्की के विरुद्ध अपनी प्रादेशिक मार्गों का परित्याग करने की घोषणा की।

सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव को नियुक्ति पर अपने पहले के दुराग्रही रथ को छोड़कर श्री डाग हैमरशोल्ड को महासचिव के रूप में स्वीकार कर लिया। जुलाई, १९५५ में भारत के प्रयत्नों और रूस के समर्थन से साम्यवादी चीन ने ११ बंदी अमेरिकन विमान चालकों को रिहा कर दिया। रूस द्वारा अपनायी गयी इस सहयोगपूर्ण और उदार नीति का संयुक्त राष्ट्रसंघ पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ा। रूसी सहयोग पावर अब वह अधिक प्रभावशाली रूप में कार्य करने लगा। नवम्बर-दिसम्बर १९५५ में एक तरफ सोवियत रूस ने और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह निश्चय किया कि वे एक दूसरे के द्वारा प्रभावित राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के प्रस्तावों का विरोध नहीं करेंगे। इस निश्चय के परिणामस्वरूप ८ दिसम्बर, १९५५ को १८ राज्यों की संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान की गई। सोवियत नेताओं ने दूसरे देशों की सद्भावना बनाए रखना शुरू किया। १८ अप्रैल, १९५६ को कामिनफोर्म को भंग कर दिया। जुलाई-अगस्त १९६३ में अणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि सम्पन्न की गई जिसे १९२२ की वाशिंगटन संधियों के पश्चात् निःशस्त्रीकरण के प्रयत्नों की प्रथम सफलता कहा जा सकता है। अगस्त में ही मास्को और वाशिंगटन के मध्य सीधा टेलिफोन तथा रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U. S. Soviet Hot Line Agreement) किया गया जिसका उद्देश्य यह था किसी भी सकलकालीन स्थिति में दोनों राष्ट्रों के अध्यक्ष एक-दूसरे से सीधी वार्ता के द्वारा विवाद को आणविक तिकार होने से रक्षा करें।

सुदृष्ट काल में 'पूर्व' और 'पश्चिम' के सम्बन्धों में निश्चित रूप से सुधार हुआ, किन्तु इसका यह आशय नहीं है कि शीतयुद्ध समाप्त हो गया अथवा रूस और पश्चिमी शक्तियां परस्पर मित्र बन गये। इसके विपरीत राजनीतिक सन्धु के रूप में दोनों की स्थिति यथा पूर्वं रही और कूटनीतिक दाघ पेशों के जरिये अपना-अपना प्रभाव-क्षेत्र बढ़ाने में दोनों ही पक्ष अग्रसर रहे। मूल अन्तर केवल यही हुआ कि स्टालिनवादी उपवादी नीति का स्थान चानुर्प-पूर्ण और सहन कूटनीतिक उदार नीति ने ले लिया जिसमें प्रत्येक अनुकूल अवसर ने प्रत्येक लाभ उठाने की चेष्टा जारी रही। मोरे-बमोके ऐसे अवसर उपस्थित हो रहे और ऐसी घटनाएँ घटीं जिनमें समय-समय पर शीत युद्ध को तीव्रता मिली और दोनों पक्षों में कटुता का व्यापक प्रसार हुआ; उदाहरणार्थ, १९५६ में स्वेज नहर और हंगरी के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में अत्यधिक कटुता उत्पन्न हो गई, मई १९६० में यू-२ विमान की घटना ने दोनों पक्षों में शीत युद्ध का अवसर ला दिया और १९६२ में क्यूबा के संकट

ने दोनों महाशक्तियों को सघर्ष के इतने निकट ला दिया कि तृतीय महायुद्ध के विस्फोट की सम्भावना से विश्व की सम्पूर्ण शांतिवादी जनता प्रसन्न हो उठी। फिर भी इससे इन्वार नहीं किया जा सकता है कि सबूट के प्रत्येक अवसर को ढालने में न्यूनाधिक रूप से दोनों ही पक्षों ने विवेक और धर्म का महारा लिया तथा रूसी को इतना नहीं खिंचने दिया कि वह टूट जाय। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों महाशक्तियों में इस अनुभूति को बल मिला कि सैनिक शक्ति अथवा युद्ध के द्वारा एक-दूसरे को समाप्त करने की नीति न केवल अव्यावहारिक वरन् आत्मघाती होगी और यदि सह अस्तित्व को नहीं अपनाया जायगा तो उसका एक मात्र विकल्प सह-विनाश रोग।

(३) अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता—जैसा कि कहा जा चुका है, मार्लेन्कोव और खुश्चेव के युग में सोवियत संघ ने भी अल्प-विकसित देशों को आर्थिक, प्राविधिक और सैनिक सहायता की नीति अपनायी जो आज तक सोवियत विदेश नीति का एक प्रमुख अंग बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा १९८० से ही ट्रुमैन सिद्धान्त और मार्शेल योजना के अन्तर्गत अल्प-विकसित देशों के लिये आर्थिक सहायता का कार्यक्रम अपनाया गया था ताकि उन देशों में बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव को रोका जा सके। इसके प्रत्युत्तर में स्टालिन युग में सोवियत रूस ने अल्प विकसित देशों को विकसित करने की अपेक्षा उनमें साम्यवाद के प्रचार और तोड़फोड़ के सिद्धांत को अपनाया। परन्तु स्टालिनोत्तर युग में नवीन नीति का समारम्भ हुआ जिसके अनुसार रूस द्वारा अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास पर बल दिया जाने लगा। इसके परिणामस्वरूप जनवरी १९५४ से जनवरी १९६३ तक दोनों ही देशों द्वारा अल्प विकसित एवं अविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने की एक प्रतियोगिता सी प्रारम्भ हो गई।

सोवियत संघ द्वारा अविकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति का प्रभावशाली रूप में अनुकरण करने में ही वाल्टर लिपमन (Walter Lippmann) को यह लिखने पर विवश कर दिया कि "पहले रूस ने आणविक आयुधों पर पश्चिम के एकाधिकार को भंग किया और अब वह अल्प-विकसित देशों का आर्थिक महत्त्व ग्रहण करने में पश्चिम के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ने लगा है।"

अविकसित देशों को आर्थिक सहायता देने की नीति का अवतारम्भ करने के साथ सोवियत रूस ने उत्पादन और सैनिक शक्ति में अपने को पश्चिमी देशों से श्रेष्ठतर सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया। श्री खुश्चेव का

स्पष्ट मत था कि, "अब सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है ? यह है पूँजीवाद को पराजित करना । जो बड़े पैमाने पर उत्पादन के द्वारा अधिक पैसा करेगा वह विजयी होगा ।" इस नीति के फलस्वरूप रूस के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई सैनिक शक्ति में भी सोवियत संघ तेजी से आगे बढ़ा । १९५७ में स्पूतनिक और १९५९ में ५० मेगाटन बम का निर्माण करके वह राकेट तथा आणविक शस्त्रों की दौड़ में संयुक्त राज्य में भी आगे निकल गया ।

(४) उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध—श्री ख्रुश्चेव ने एशिया और अफ्रीका के देशों तथा अमलगम विश्व (Uncommitted World) की महानुभूति प्राप्त करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद विरोधी प्रचार को और भी तीव्र कर दिया । संयुक्तराष्ट्र संघ में और अन्यत्र वह साम्राज्यवादी शक्तियों की घोर निन्दा करने लगा और उपनिवेशों तथा गुलाम राष्ट्रों को स्वतन्त्र बनाने के सभी प्रस्तावों और आन्दोलनों को प्रबल समर्थन देने लगा । उसी नेताओं की मान्यता थी कि इस नीति से उन्हें दोहरा लाभ मिलना है । पहला तो यह कि एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवाद से पीड़ित जनता की महानुभूति उसे प्राप्त होगी है और दूसरे साम्राज्यवाद के विघटन में रूस के प्रबल एवं कट्टर शत्रु पूँजीपति पश्चिम की प्रभुता क्षीण होगी है ।

वास्तव में स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही, विशेषकर श्री ख्रुश्चेव के प्रभाव में आने के उपरान्त से एशिया और अफ्रीका के अल्प विकसित या अविकसित देशों और उपनिवेशों के प्रति सोवियत नीति के निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य रहे—

(i) भूतपूर्व उपनिवेशी अथवा अर्ध-उपनिवेशी देशों के सदेह एवं राष्ट्रीय सम्मान का अच्छी प्रकार ध्यान रखने हुए उनके प्रति पूरी तरह मित्रता एवं मौहार्द दिखाना,

(ii) इन देशों के पश्चिम के साथ अतीत के बटु सम्बन्धों का फायदा उठाते हुए इन्हें पश्चिम से और भी विमुक्त बना देना;

(iii) न केवल उपनिवेशवाद विरोधी बरन जातिवाद विरोधी प्रवृत्तियों को भी उगाड़ना;

(iv) राजनीतिक सहम्यता की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना;

(v) औद्योगीकरण के द्वारा उनकी अपनी अर्थ-व्यवस्था को विकसित करने की महत्वाकांक्षा को सहारा देना; हो सके तो सोवियत सहम्यता एवं पारस्परिक व्यापारों के सम्बन्धों को और उनकी श्रुताना,

(vi) प्रत्येक झगड़े को उकसाना जो वे पश्चिम के साथ रख सकते हैं,

(vii) विदेशी पूँजी या सहायता को उनकी स्वतन्त्रता एवं सम्मान के विरुद्ध बना कर सन्देह की भावना फैलाना,

(viii) उनकी आँखों के सामने सोवियत रुम के तीव्र औद्योगीकरण की आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना ताकि स्थानीय लोग यह समझ सकें कि केवल साम्यवाद ही बहुत कम समय में ऐसी उपलब्धियाँ को साकार कर सकता है ।

सोवियत राष्ट्र के शक्ति एवं प्रभाव के विस्तार के मुख्य आकर्षण केन्द्र तीन हैं, अफ्रीका, एशिया एवं लेटिन अमेरिका । शेपिलोव (Shepilov) ने पूर्व के सम्बन्ध में कहा था कि सोवियत जनता पूर्वी राष्ट्रों के समाप्त होते हुए उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वायत्तीन सघर्षों को प्रेम तथा सहानुभूति से सम्मान प्रदान करती है । उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा विश्वास है कि प्रत्येक जनता (People) को उसकी राष्ट्रीय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता तथा आत्म निर्णय का कभी न छोना जाने वाला अधिकार है ।

ख़ुश्चेव का पतन, उसकी नीति का मूल्यांकन—ख़ुश्चेव के समय सोवियत नीति में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में वह जिन नई दिशाओं की ओर उन्मुख हुई, उसका समीक्षात्मक वर्णन हम कर चुके हैं ।

ख़ुश्चेव की नीति का मूल्यांकन करते समय प्रमुख प्रश्न यह उठता है कि क्या उसके समय की विदेश नीति की नई विशेषतायें मौलिक परिवर्तनों की सूचक हैं ? स्टालिन द्वारा प्रतिपादित नीतियों का विरोध और नि-स्टालिनीकरण (De Stalinization) स्याई है अथवा अस्याई । और क्या यह एक स्याई तथ्य है कि रुस में विश्व शान्ति का उत्साह वास्तव में सिथिक हो गया है तथा उसमें उदारवाद की प्रवृत्तियाँ स्याई रूप से प्रबल हो गई हैं । इन सब प्रश्नों का यथार्थ उत्तर तो भविष्य ही देगा । यद्यपि श्री ख़ुश्चेव के बाद से (अक्टूबर १९६४ के बाद से अभी तक) (अगस्त १९६६ तक) सोवियत नेताओं की नीति ख़ुश्चेववादी ही रही है और सोवियत प्रधानमंत्री श्री कोसीगिन एवं राष्ट्रपति ब्रेज्नेव रुस की सह अस्तित्व एवं शान्तिवादी नीति को जारी रखने के लिए कटिबद्ध प्रतीत होते हैं, तथापि इतने अल्पकाल में एवं राष्ट्र की परिवर्तित विदेश नीति का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, हाँ कुछ वर्षों के इतिहास से इसी बात की आशा बनती है कि सोवियत रुस अपनी उदार नीति पर चलता रहेगा ।

इस सदर्म में यह सल्लेखनीय है कि कुछ विद्वानों ने सोवियत विदेश नीति के बारे में अनेक मनोरंजक कल्पनाएँ की हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार टायनबी ने इसी सह अस्तित्व एवं उदारवाद की नीति की व्याख्या के लिए साम्यवाद की इस्लाम के साथ तुलना की है। उनका कहना है कि साम्यवाद इस्लाम की भाँति उग्र प्रचारक, सैनिकवादी आंदोलन है। जिस तरह दूसरे देशों को जीतने और बड़ा की जनताओं को मुसलमान बनाने के बाद इस्लाम का उत्साह छिपित हो गया था और उसने अन्य धर्मों के साथ समझौता कर लिया था वही प्रकार साम्यवादियों का जोश मन्द पड़ रहा है और उन्होंने भी अन्य देशों के साथ मित्रता पूर्वक रहने के लिए शक्तिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति ग्रहण की है।

लेविन थी रॉबर्ट स्ट्राउज-हुपे (Robert Strausz-Hupe) ने टायनबी के मत का खंडन किया है। उनका कहना है कि "इस्लाम के उत्साह में मंदी या नमी कई शताब्दियों बाद लाखों व्यक्तियों को मुसलमान बनाने और मारने के बाद विरोधी शक्तियों के प्रबल होने से आई थी। साम्यवाद में वही ऐसी कोई अवस्था दृष्टिगोचर नहीं होती।" थी हुपे और तर्कों के समान कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि उदारवाद रुक की अत्यन्तान्तिक नीति है अन्यथा उसकी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्टालिन के समय बुद्धि-आंदोलनों में अनेक बड़े नेताओं की पदावनति होती थी जो आज भी वही की वही है। उदाहरण के लिए स्टालिन के बाद उसके विश्वास-पात्र बेरिया को मौत की सजा मिली। स्टालिन के उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री मालेन्कोव कजाखस्तान के एक बिजली घर के संचालक बनाकर राजनीति से दूर पटक दिये गये, प्रधानमंत्री बुल्गानिन को स्टाइपोल प्रदेस की आर्थिक परिषद का अध्यक्ष बना कर निकाल फेंका गया और उसके बाद, स्टालिन ही की तरह उस पर छा जाने वाले भी खुरशेव तक को अक्टूबर १९६४ में अपदस्थ कर दिया गया और १५ अक्टूबर, १९६४ को वास एजेन्सी ने घोषणा की कि, "अधिक आयु तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण थी खुरशेव को साम्यवादी पार्टी के मंत्री तथा प्रधानमंत्री के पद से मुक्त किया गया है। केन्द्रीय समिति ने १४ तारीख को इन दोनों पदों से खुरशेव का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है तथा कोसीगिन को प्रधानमंत्री और खुरशेव को साम्यवादी पार्टी का सचिव बनाया गया है।" रुस के मामलों में विदेश रूप से सिद्धहस्त पारचात्य कूटनीतिज्ञों की मान्यता है कि इसी विदेश नीति का प्रमुख ध्येय पूँजीवादी समाज और दातावरण का उन्मूलन है, इसमें कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं है।

खुश्चेव के पतन के बाद सोवियत विदेश नीति तथा सोवियन कूटनीति की नयी दिशाएँ

खुश्चेव के पतन के बाद अक्टूबर, १९२४ में सोवियत संघ का नेतृत्व दो नये व्यक्ति—कोमिगिन और ब्रेजनेव के हाथों में आया। अनेक क्षेत्रों में यह आगमन व्यक्त की गई कि नया नेतृत्व स्टालिनवादी होगा तथा सोवियत विदेश नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आयेगा। किन्तु इस प्रकार की आशंकाओं का समाधान करते हुए नये सोवियत नेताओं ने घोषणा की कि नयी विदेश नीति के क्षेत्र में खुश्चेववादी परम्परा ही अरनायी जायेगी। नये नेताओं ने कहा कि पहले की विदेश नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तथा सोवियत संघ शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करता रहेगा। यह भी कहा गया कि परमाणुविक परीक्षण को बन्द कराने और निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास जारी रहेंगे, शीत युद्ध में तीव्रता नहीं आने दी जायेगी तथा समार के पिछड़े राष्ट्रों की विकास योजनाओं में रुचि तथा सहायता देता रहेगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि १९६४ के अन्त से लेकर अब तक अर्थात् १९६६ की समाप्ति तक सोवियत विदेश नीति में अधिकांशतः खुश्चेववादी परम्परा का ही निर्वाह किया गया है और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की सम्भावनाओं को पहले से अधिक सकल बनाया गया है, किन्तु साथ ही यह भी सच है कि सोवियत कूटनीति ने कुछ नये पैतरे भी बसले हैं—विशेषकर भारत व पाकिस्तान के सम्बन्ध में। अग्रिम पत्रिकों में हम खुश्चेवोत्तर युग में सोवियत विदेश नीति और कूटनीति के क्षेत्र में उसके नये पैतरो का उल्लेख करेंगे।

अमेरिका व पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति रुझान रचना—पश्चिमी राष्ट्रों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति सोवियत विदेश नीति का रुझान बहुत कुछ खुश्चेववादी है। हमी नेताओं का विश्वास है कि अमेरिका से उन्हें कोई तार्कालिक सैनिक या राजनीतिक खतरा नहीं है। खुश्चेव के बाद की सोवियत विदेश नीति में पश्चिम के प्रति किसी विशेष परिवर्तन का संकेत नहीं मिला है। अमेरिका के साथ उलझने और शीत युद्ध को पुनः चालू करने के बड़े खतरा आये हैं, लेकिन सोवियत नेताओं ने स्थिति को बिगड़ने देने का प्रयास नहीं किया है। उत्तरी कोरिया में जॉनसन प्रशासन और निसन प्रशासन के समय हुए अमेरिकी जासूमी वाण्डों के दौरान भी सोवियत संघ ने सयम् ही प्रदर्शन किया और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे आपसी तनाव बढ़े तथा शीत युद्ध का प्रसार हो। वियतनाम की समस्या पर भी संघ का यही

रहा रहा है कि वार्ता द्वारा समस्या का समाधान हो जाय । उत्तरी विषयनाम को विशाल सैनिक सहायता देते हुए भी सोवियत नेताओं ने ऐसा मान बण पैदा नहीं किया है जिससे अमेरिका के साथ समझौता वाता के द्वार ही बन्द हो जाय ।

खुशखबरीयान् यात्राओं की हूटनीति भी जारी रखी गई है । अक्टूबर, १९६६ में सोवियत विदेश मंत्री शोमिको ने राष्ट्रपति जानसन से मुलाकात करके निःशस्त्रीकरण और विषयनाम के प्रश्न पर बातचीत की थी । तब राष्ट्रपति द्वारा सोवियत प्रधान मंत्री कोसिगिन को अपने देश जाने का निमन्त्रण दिया गया और यह भी मकैत किया गया कि वदने में वह हम की यात्रा के निमन्त्रण का स्वागत करने । सौभाग्यवश इन दो महान् राष्ट्रों के सर्वोच्च नेताओं का शिगर सम्मेलन जून, १९६७ में सम्भव हो सका । जून १९६७ में हुए अरब-इजराइल सघर्ष के फलस्वरूप दोनों देशों के सुधरने हुए सम्बन्धों में कुछ कटुता आ गई । सन्तुवन राज्य अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों ने इजराइल का और सोवियत रूस ने अरब राष्ट्रों का पक्ष लिया । अरब-इजरायल सघर्ष के फलस्वरूप सन्तुवन हुए पश्चिमी एशियायी सकट पर समुक्त राष्ट्र सघ की महा-सभा का जो अधिवेशन जून, १९६७ में हुआ उसने भाग लेने के लिए सोवियत प्रधान मंत्री कोसिगिन स्वयं उपस्थित हुए । प्रारम्भ में ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो दिली इच्छा होने के बावजूद जानसन और कोसिगिन में से कोई भी सितार वार्ता के लिए उमसुकता नहीं दिखाया चाहता था । किन्तु घाद में अचानक ही प्लासबरो में दोनों नेताओं ने घटी एवान्त मन्त्रणा की और फिर अपने परामर्शदाताओं के साथ की गई बातचीत अपने दिन रविवार, २५ जून, १९६७ को भी जारी रखी । वार्तालाप में विषयनाम और पश्चिमी एशिया पर मुख्य रूप से वैचारिक आदान-प्रदान हुआ और निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु शक्ति के विस्तार के सवाल भी बहने नहीं रहे । परमाणु अस्त्रों के विस्तार पर जहुश लगाने के बारे में दोनों पक्षों की ओर से अनुकूल वाता-वरण बनाने की बात कही गई ।

विश्व की दोनों महा शक्तियों द्वारा एक दूसरे के प्रति समय बरतने की कूट नीति से यही सकेत मिलता है कि आधुनिक विश्व शान्ति में ये दोनों महान् राष्ट्र पहले की अपेक्षा अब एक दूसरे के अधिक नजदीक आने लगे हैं । साम्यवादी चीन के साथ सोवियत रूस के सम्बन्ध कटु से कटुतर होने जा रहे हैं और सीमा क्षेत्रों पर दोनों देशों में सैनिक झड़पें भी हुई हैं । अतः अनेक राजनीतिज्ञों की धारणा है कि पश्चिमी, विशेषकर समुक्त रा-य अमेरिका के प्रति सोवियत संघ में इन प्रकार का परिवर्तन परिस्थितियों से विशय

हो कर किया गया है। चीन से उलझने की भावी आशंका को ध्यान में रखते हुए ही सोवियत नेताओं ने पश्चिम के प्रति कुछ अधिक समझपूर्ण और साम्य नीति ग्रहण की। लेकिन यह स्थिति आगे जब तक बनी रहेगी, यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। जून, १९६७ में यूरोप के साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों की कोंग्रेस में जो बैठक हुई थी उसमें सोवियत नेताओं की इस बात के लिए कटु आलोचना की गई थी कि वे अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति उदार नीति का अनुसरण कर रहे हैं। साम्यवादी जगत के इस प्रकार के प्रभाव का सामना सोवियत नेता जब तक कर सकेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। समय समय पर अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ऐसे तूफान उठते रहते हैं जिनसे रूस और अमेरिका के सम्बन्धों में पुनः जबरदस्त बिगाड़ आ जाने और शीत-युद्ध भड़क उठने का खतरा पैदा हो जाता है। अगस्त १९६८ में चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण की घटना के समय इसी प्रकार का खतरा पैदा हो गया था। यह स्वाभाविक था कि समुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र सोवियत रूस के इस अन्यायपूर्ण कदम का विरोध करते। चेकोस्लोवाकिया में सोवियत सेनाओं और वारसा पैक्ट के अन्य साम्यवादी राज्यों की सेनाओं का प्रवेश एक प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप था। यह एक शक्तिशाली राष्ट्र का छोटे राष्ट्र पर आक्रमण था। रूस की इस कार्यवाही ने शीत-युद्ध के महारक्षियों को एक नया अवसर प्रदान किया। पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका ने 'चैंक जनता के मुक्ति सशस्त्र' का समर्थन किया और तुरन्त ही इस मामले की सुरक्षा परिषद् में उठाया गया। सुरक्षा-परिषद् में एक प्रस्ताव पेश करके सोवियत रूस और उसके साथी देशों की इस कार्यवाही की निन्दा की गई। बहुमत होने पर भी यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका क्योंकि रूस ने १०५वीं बार अपने विधेयविचार का प्रयोग करते हुए इसे रद्द कर दिया। बाद में चेकोस्लोवाकिया और रूस में परस्पर समझौता हो गया और धीरे धीरे चेकोस्लोवाकिया की स्थिति सामान्य होती गई।

जर्मनी के प्रश्न पर यद्यपि रूस और अमेरिका में मतभेद समापूर्व बाधक है, किन्तु कोंग्रेस में साम्यवादी देशों के प्रतिनिधियों की जून, १९६७ में हुई बैठक के बाद जारी की गई समुक्त विज्ञप्ति से इस बात की पुष्टि होती है कि सोवियत संघ पश्चिमी जर्मनी से अपने सम्बन्ध सुधारना चाहता है। पर इसके लिए शर्तें बड़ी दोहरी जा रही हैं जिनकी रट सोवियत संघ आरम्भ से ही लगाये हुए है। इतने पहली प्रमुख शर्त यह है कि पश्चिमी जर्मनी समूचे जर्मनी का प्रतिनिधित्व करने का अपना दावा छोड़ दे और दूसरी प्रमुख शर्त यह है कि पूर्व जर्मनी को वह अपनी मान्यता प्रदान करे।

सोवियत संघ की कुछ इस प्रकार का विद्वान हो गया है कि पश्चिमी जर्मनी में ऐसे तारों का विकास हो रहा है जो उसकी नीति में बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं और सोवियत संघ की इन तरकों के विरुद्ध होने में सहायक बनना चाहिए।

ताशकन्द सोवियत कूटनीति में एक नया मोड़—सितम्बर, १९६५ में सोवियत कूटनीति के क्षेत्र में एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। सितम्बर में भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर की लेकर जो भयंकर युद्ध हुआ उसकी बन्द कराने में सोवियत नताश्वों ने प्रत्यक्ष प्रयास किये। सोवियत प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खा और भारत के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पक्ष छिन्न कर तत्काल युद्ध बन्द करने का अनुरोध किया और यह सुझाव दिया कि यदि दोनों पक्ष समझौता बातों को तैयार हो तो सोवियत संघ अपनी भूमि पर शान्तिपूर्ण वातावरण में शर्तिलाप करने की सुविधा प्रदान कर सकता है और दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए अपनी सेवाएँ प्रविष्ट कर सकता है। सोवियत संघ का यह सुझाव वास्तव में सोवियत कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शान्तिकारी परिवर्तन था। सोवियत संघ ने अभी तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया था। अतः जब उसने भारत और पाकिस्तान के शत्रुता को सुलझाने में मध्यस्थता का प्रस्ताव किया तो समूचा राजनीतिक विद्वत् स्तब्ध रह गया।

रूसी प्रयत्नों में ४ जनवरी, १९६६ को सोवियत संघ के प्राचीन नगर ताशकन्द में भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति के बीच समझौता बातों प्रारम्भ हुईं। १० जनवरी को प्रातः काल यह निश्चित हो गया कि ताशकन्द बातों का कोई परिणाम नहीं निकल सकेगा लेकिन सोवियत कूटनीति अत्यन्त सज्जिव रही। ताशकन्द में सोवियत संघ के शीर्षस्थ नेता मौजूद थे। १० जनवरी को उनके अदक प्रयासों के फलस्वरूप गतिरोध टूट गया। रात्रि को ६ बजे सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन की उपस्थिति में श्री अयूब खा और श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। ताशकन्द समझौता बन्धुत तर्कों कूटनीति का एक महान सफलता थी।

यदि ध्यान से देखा जाय तो ताशकन्द समझौते के मूल में सोवियत संघ की भारत और पाकिस्तान के प्रति परिवर्तित होती हुई नयी नीति के बीच निहित थे। सोवियत संघ के नये नेताओं ने भारत और पाकिस्तान के प्रति सुस्नेहवादी नीति को जारी न रखने का निश्चय कर लिया था। सुस्नेह के पत्र के कुछ काल बाद से लेकर अब तक का इतिहास बताता

है कि भारत के प्रति सोवियत रूस उतना मैत्रीपूर्ण नहीं रहा है जितना खुश्चेव के समय था। काश्मीर के प्रश्न पर सोवियत रूस ने पाकिस्तान के पक्ष में निश्चित रूप में कुछ नरमी आयी है। १९६५ में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय संयुक्त राष्ट्रसंघ में और उसके बाहर सोवियत रूस ने भारत तथा पाकिस्तान को समान स्तर पर माना और दोनों ही को युद्ध बन्दी तथा बाग़-द्वारा समझौता करने को कहा। इसके बाद दोनों देशों के नेताओं का अपना भूमि पर आमन्त्रित कर बराबरी के स्तर पर तात्कालिक समझौता करवाया। रूसी रूस इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि रूस के नये नेताओं ने भारत को वह समर्थन देने से इंकार कर दिया है जिसका आशवासन खुश्चेव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान काश्मीर पर खड़े हो कर इन शब्दों में दिया था—“आप हमें यहां खड़े होकर आवाज दीजिए, हम आपकी मदद को दौड़े आयेगे।”

सोवियत नेताओं का मन और मस्तिष्क भारत राष्ट्र के प्रति कितना निष्कण्ठ, उदार और मैत्रीपूर्ण है, इसे अब भविष्य ही सिद्ध करेगा। वर्तमान में तो भारत की आशाओं को उनकी तरफ से आघात ही पहुँच रहा है। जुलाई १९६८ में उसके द्वारा पाकिस्तान को फौजी सहायता देने का निर्णय भारत की मंत्री पर एक समाचार ही कहा जायेगा। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को रूसी सस्त्रास्त्रों की सप्लाई बढ़ती जा रही है। जनवरी १९७० में रूस द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में सस्त्रास्त्र दिये जाने के समानांतर पर सरकार सहित सभी राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी है। पाकिस्तान के पिछले व्यवहार को देखते हुए इस प्रकार के आशवासन कोई महत्व नहीं रखते कि रूसी सस्त्रों का प्रयोग पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ नहीं किमे जायेगे।

पाकिस्तान के प्रति नवीन दृष्टिकोण—जैसा कि कहा जा चुका है, खुश्चेव युग तक रूस का दृष्टिकोण पाकिस्तान के प्रति सख्ती का था। लेकिन नये नेतृत्व के रूस में शान्ति शान्ति नर्मा आने लगी जो भारत-पाक युद्ध, तात्कालिक समझौते, पारस्परिक यात्राओं और विभिन्न व्यापारिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समझौतों के रूप में स्पष्ट रूप से प्रकट हो गयी। अप्रैल, १९६५ में ही दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक समझौते हुए। सितम्बर १९६५ में भारत-पाक संघर्ष और तत्पश्चात् तात्कालिक सम्मेलन के समय सोवियत रूस ने भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर माना। अप्रैल, १९६८ में सोवियत प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की और जुलाई में रूस ने पाकिस्तान को फौजी सहायता देने का

दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किया। सोवियत संघ की यह नीति तो अक्सरवादी होती है, अतः भारत को रूस या किसी अन्य राष्ट्र की अटूट मैत्री के घोखे में न रह कर यथासौध हर क्षण में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन जाना चाहिए।

वियतनाम के सम्बन्ध में सोवियत नीति युद्ध के समय से ही वियतनाम के सम्बन्ध में सोवियत नीति प्रायः तटस्थता की थी। लेकिन १९६४ में जब वियतनाम में अमेरिकन सैनिक हस्तक्षेप भयंकर रूप में बढ़ता गया तो रूस ने वियतनाम के प्रति अपनी नीति बदलते हुए उत्तरी वियतनाम को आवश्यक सैनिक सहायता देने की घोषणा की। अप्रैल १९६७ में हुए एक सम्मेलन के अनुसार उत्तरी वियतनाम को सोवियत संघ से निरन्तर सैनिक सहायता दिया जाना तय हुआ। २१ मार्च, १९६८ को जब राष्ट्रपति जॉन्सन ने वियतनाम में बमबारी को सीमित करने की घोषणा की तो रूस ने इसे 'पहली अप्रैल का भजाक' बताया। सोमाम्यवाद ज्ञानस्रव प्रशासन ने बाद में युद्ध को तीव्र नहीं किया और निवृत्त प्रशासन तो युद्ध को समाप्त करने की दिशा में पूरी तरह सज्जित है। अमरीका की इस परिचित नीति को देखते हुए सोवियत रूस का भी यही प्रयत्न है कि बातचीत द्वारा समस्या का समाधान निकल आवे और वियतनाम में युद्ध की लपटें बुझ जाएं।

चेकोस्लोवाकिया पर रूसी आक्रमण और उदारवाद का बमन—युद्ध के समय से शक्तिपूर्ण सहस्रस्थित्व और राष्ट्रों में पारस्परिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले रूस ने अगस्त १९६८ में चेकोस्लोवाकिया पर जिस दम से आक्रमण किया, उसने रूस के नेक इरादों में एक बार फिर सन्देह पैदा कर दिया। चेकोस्लोवाकिया रूसी कायबाही का शिकार इसलिए बना क्योंकि १९६७ के मध्य से ही वहाँ उदारवादी प्रवृत्ति जोर पकड़ती गयी। उदारवादियों का प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्टालिनवादी नीति पर चलने वाले अनेक अधिकाधिक को पद त्याग करना पड़ा। जनवरी १९६८ में अलेक्जेंडर दुबचेक साम्यवादी दल के महामंत्री बने जिनके नेतृत्व में चेकोस्लोवाकिया के साम्यवादी दल ने समाजवादी लोकतंत्रीकरण के सिद्धान्त को स्वीकार किया और उदारवाद के पक्ष में अनेक सुधार प्रस्तावित किये जो सोवियत समाजवादी व्यवस्था से मेल नहीं खाते थे।

सोवियत रूस को चेकोस्लोवाकिया में उदारवाद की यह प्रवृत्ति पसन्द नहीं आयी। उसने पहले तो इस प्रवृत्ति का धीरे धीरे विरोध किया, किन्तु बाद में उत्तका रूस बढोर होता गया। जब चेकोस्लोवाकिया के सुधारवादी नेताओं ने रूसी नाराओं की कोई परवाह नहीं की और एक पूर्ण प्रभुत्व,

सम्पन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतन्त्र नीति पर चलने का निश्चय किया तो सोवियत रूस ने चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप करने का दुर्भाग्यपूर्ण निश्चय कर लिया। रूस ने वारसा पेक्ट के अन्तर्गत सदस्यो हंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड और बलगेरिया के साथ २१ अगस्त, १९६८ को रात्रि को अचानक ही चेको-स्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही घंटों में राजधानी प्राग सहित सभी बड़े नगरों पर अधिकार कर लिया गया। चेकोस्लोवाकिया ने रूसी सैनिक शक्ति से न टकराने में ही भला समझा। पारस्परिक वार्ता चलती रही और अन्त में रूसी दबाव के समक्ष चेकोस्लोवाकिया को झुकना पड़ा। चेक नेताओं ने यह मान लिया कि चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने पर ११-१२ सितम्बर १९६८ तक राजधानी प्राग से सोवियत टैंक सैन्याँ लौट गयीं। लेकिन इस वापसी को भारी कीमत चेक जनता को चुकानी पड़ी। प्रेस की स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लग गया, नये राजनीतिक दलों के निर्माण पर अकुश लगा दिया गया और सैसरक्षिण स्थापित कर दी गयी। अप्रैल, १९६९ में दुबचेक को चेक साम्यवादी दल के प्रथम सचिव के पद से हटाना पड़ा और उनका स्थान रूसी विचारधारा के प्रबल समर्थक डा० गुस्ताव हसाक ने लिया। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया में पुनः ऐसा शस्त्रीय यन्त्र और शासन यन्त्र स्थापित कर दिया गया जो रूस का विश्वलम्बू बना रहे। चेकोस्लोवाकिया काण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् में भी गुंजा और सोवियत संघ की इस कार्यवाही के प्रति परिचयी देशों ने निंदा प्रस्ताव रखा जिसे रूस ने १०५वीं बार अपने वीटो का प्रयोग करके रद्द कर दिया।

अरब इजरायल युद्ध और सोवियत संघ—प्रारम्भ में रूस का रवैया इजरायल समर्थक था लेकिन बाद में अरब समर्थक बन गया क्योंकि रूस ने अनुभव किया कि मध्यपूर्व के अरब राज्यों में समाजवादी प्रगति लायी जा सकती है और रूसी प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। रूस ने पहले तो अरबों को नैतिक समर्थन देना शुरू किया और बाद में सैनिक सहायता के द्वार भी खोल दिये। १९५५ के बाद से ही अरब राज्यों को भारी मात्रा में सोवियत सैनिक सामग्री पहुँचने लगी। १९५६ के स्वेज सङ्कट के समय सोवियत संघ ने अरबों को पूर्ण समर्थन दिया।

जून १९६७ में पुनः अरब इजरायल संघर्ष भड़क उठा। इस बार भी सोवियत संघ ने अरब राज्यों का खूबकर समर्थन किया। सोवियत रूस अरबों के पक्ष में विश्व युद्ध का खतरा उठाने तक के लिए तैयार हो गया, बशर्ते कि अमरीका उसके साथी इजरायल का पक्ष लेकर युद्ध में जुड़ पड़े। पर

पूँछि पश्चिमी राष्ट्र सैनिक हस्तक्षेप से दूर रहे, अतः इजरायल के हाथों अरब राष्ट्रों को पिटने देखाकर भी रुस ने सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया।

सोवियत संघ ने यद्यपि मुझ क्षेत्र में अरबों को सक्रिय सहयोग नहीं दिया, लेकिन उनके असंतोष को दूर करने के लिए एक ओर तो सुरक्षा परिषद् में और बाहर भी इजरायल के विरुद्ध जबरदस्त कूटनीतिक मुझ छेड़ दिया और दूसरी ओर अरबों को विपुल सैनिक सहायता दी। उसने इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध भी तोड़ लिये। अरब राज्यों में अपनी साख बनाये रखने के लिए जून १९६७ में सोवियत राष्ट्रपति स्वयं काहिरा गये और बाद में संयुक्त अरब गणराज्य को आधुनिकतम रूसी सस्त्रास्त्र मिलने लगे। सितम्बर १९६८ में रुस ने अपनी एक शक्ति योजना रखी जिसमें निम्नलिखित बातें प्रस्तावित की गयीं :—

(i) शांति कायम रखने के लिए सीमाओं पर सुदृढ़ संयुक्त राष्ट्रीय व्यवस्था की जाए।

(ii) इजरायली सेनाएं जून १९६७ से पहले की सीमाओं पर लौट जाएं।

(iii) दोनों पक्षों के चार बड़े देश (अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, और सोवियत संघ) दोनों पक्षों के बीच मुझ को पुनः प्रारम्भ न होने दें।

(iv) अरब राष्ट्र भी इजरायल के विरुद्ध मुझ की स्थिति समाप्त करें।

सोवियत संघ का यह उचित प्रस्ताव इजरायल और उसके समर्थक देशों को मान्य नहीं हुआ। ३ अप्रैल १९६६ को पश्चिमी एशिया के लिए न्यूयार्क में अमेरिका, फ्रांस और रुस का सम्मेलन हुआ जिसमें रुस ने अरब राज्यों का पूर्ण पक्ष लिया। सम्मेलन का कोई परिणाम न निकल सका। पश्चिमी एशिया का यह संकट आज भी जारी है। सोवियत संघ को पूर्ण सहानुभूति अरब राज्यों के साथ है। कूटनीतिक स्तर पर वह उन्हें पूर्ण समर्थन दे रहा है और सैनिक स्तर पर उन्हें सस्त्रास्त्र की भारी मदद दे रहा है। रूसी सहायता के बल पर ही अरब राज्य न केवल मुझ में विनष्ट अपनी शक्ति को ही पुनः प्राप्त कर सके हैं बल्कि वे पहले से भी अधिक सैनिक शक्ति सम्पन्न हो गये हैं।

सोवियत संघ और चीन

साम्यवादी जगत के इन दो महारथियों के आपसी सम्बन्धों का उल्लेख 'रूसी चीनी संघर्ष' नामक एक अगले अध्याय में विस्तार किया है। यहां केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि प्रारम्भ में इन दोनों महान् राष्ट्रों

मे घटे मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे लेकिन आज विश्व नेतृत्व के लिए दोनों में भारी होड़ लगी हुई है। दोनों दलों में सैन्य-शक्ति सघर्ष तो छिटा हुआ है ही, लेकिन सीमा विवाद भी बड़ा गहरा है और कभी कभी सैनिक संघर्ष भी होने लगे हैं।

सोवियत विदेशी नीति का मूलमार्ग

सोवियत संघ के द्वितीय महायुद्ध के बाद के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भी उतार चढ़ाव कर रहे हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में सोवियत संघ की नीति समय समय पर बदलती रहती है। अनन्तता सोवियत विदेश नीति के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी हो की जा सकती है और न निश्चित अनुमान ही लगाया जा सकता है। सोवियत विदेश नीति के कुछ सैनिक दृष्टि हैं जो सम्भवतः किसी समय से बचे हुए नहीं हैं। स्टालिन काल के बाद रूस ने शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग चुन लिया है, लेकिन उसके इरादों की नेक नियती पर विश्वास करने के सम्बन्ध में विद्वानों और कुशल प्रेक्षकों के बीच घोर मतभेद है। अनेक आलोचकों का कहना है कि सोवियत चालबाजी और इसके हथियार बदलते रहते हैं। रूस का सह-अस्तित्व का मार्ग भी एक खोप है जो तटस्थ राष्ट्रों को अपना समर्थक बनने के लिए रचा गया है। रूस की विदेश नीति में एक प्रकार का लचीलापन रहता है और इसके व्यवहार पर कोई एक मात्र कठोर व्याख्या नहीं दी जा सकती। आलोचक अपने पक्ष में उदाहरण देते हैं कि जो रूस प्रारम्भ में इजराइल का समर्थक था वही अरब राज्यों में अपने प्रभाव को बढ़ाने की दृष्टि से और साम्यवाद का प्रसार करने के लिए इजराइल का विरोधी बन गया है। इसी तरह भारत और पाकिस्तान के प्रति भी रूसी रवैया बहुत बदल गया है। पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा कौड़ी सहायता देने के विरोध में जो रूस कभी तूफान खड़ा करता था वही अब स्वयं उसे सैनिक सहायता देने को तत्पर है। अपने पुराने और विद्वस्त मित्र भारत की आशाओं का महत्त्व उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा है। चेकोस्लोवाकिया जैसे निर्मल और असहाय देश पर अपना नग्न आक्रमण करके रूस ने सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का जो निरूपण दिया है वह कुछ अभीष्ट है।

इस प्रकार की आलोचनाओं के प्रत्युत्तर में कुछ अन्य समीक्षक यह विश्वास प्रकट करते हैं कि विश्व शांति में रूस का उत्साह भ्रम पड़ गया है। सोवियत संघ में उदारवादी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सोवियत रूस अपनी विदेश नीति का निर्धारण कठोर साम्यवादी सिद्धांत के आधार पर नहीं बल्कि वर्तमान स्थिति पर आधारित करता जा रहा है। रूस अब व्यापक-हारित दृष्टि में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करने और सोचने लगा है।

यह समझना है कि कोई भी महापुंड्र विदेश और विजित के लिए समान रूप से विनाशकारी सिद्ध होगा।

सोवियत विदेश नीति के सम्बन्ध में बहने हुए स्वतन्त्रों के कारण कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। राशनब ने जान रेसेलर (John Reshekar) का यह निष्कर्ष डीढ़ ही है कि सोवियत नेता अब ऐसा व्यवहार कर बैठेंगे इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केवल यही कहा जा सकता है कि वे अपने लाभों को पश्चिम से अधिक बनाना चाहेंगे और उनके लिए कम से कम ज्योतिम उठाना पसन्द करेंगे। सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन की सम्भावनाओं और सोवियत का एक नूतनान विरुद्ध एलेक्स इन्ग्लेस (Alex Inglees) ने किया है। उनके अनुसार सोवियत विदेश नीति में यदि कोई परिवर्तन आया तो वह तीन मुख्य चीजों से आ सकता है—

पहली सम्भावना तो यह है कि सोवियत रूस में उत्तराधिकार के स्रष्ट की समस्या कभी भी नहीं सुलझायी जा सकती। जब कभी भी गोप्य पर पश्चिम के लिए खुले रूप से स्रष्ट होना है तो यह सम्भावना बनी रहती है कि नया नेतृत्व पुरानों व्यवस्था को समाप्त कर देगा। इस प्रकार के स्रष्टों के जो अब तक परिणाम निकलने रहे हैं उनसे यह आशा की जाती है कि रूस प्रजातन्त्र की दिशा में कुछ आगे बढ़े।

दूसरी सम्भावना यह है कि सोवियत अधिराज्यों का साम्राज्य सम्बन्ध स्रष्ट जाए। हंगरी में गानि हो चुकी है, यूगोस्लाविया रूसी दबे से निरल रहा है और अब बल्गेरिया में उदारतावाद ने फिर उठाया है। इन चीजों से यह आशा की जाती है कि सोवियत स्रष्ट प्रजातन्त्र की दिशा में जाने की अपेक्षा अधिकार सम्पूर्णतावाद या सर्वाधिकार की ओर अग्रसर होगा।

तीसरी सम्भावना यह है कि औद्योगिक दृष्टि से परिपक्व सोवियत रूस का सामाजिक ढांचा अब तनामाही में नहीं रह सरेगा। रूस के सामाजिक जीवन में परिवर्तन होगा। वे परिवर्तन सोवियत समाज के प्रजातन्त्रोकरण और सोवियत विदेश नीति में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह कहा जाता है कि महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हो जाने पर भी रूस में तनामाही बनी हुई है। किन्तु इनका कारण यही है कि वहा के नेता वर्तमान परिस्थितियों से पुराने स्रष्टों का साम्राज्य कर लेते हैं। फिर भी एक स्थिति ऐसी आयेगी जब इस प्रकार का साम्राज्य पूरी तरह से असम्भव बन आयेगा।

यह निष्कर्ष निराला अनुचित न होगा कि उन्मुख तीनो ही चीजों और सम्बन्धों पर सोवियत स्रष्ट की विदेशी नीति का भारी रूप बहूत कुछ अवलम्बित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय और उसकी विदेश नीति

(RISE OF U S A AND ITS FOREIGN POLICY)

संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का एक महानतम प्रजातान्त्रिक राष्ट्र है जिसकी विदेश नीति की प्रवृत्ति एवं व्यवहार का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आरम्भिक विदेश नीति के मुख्य आधार दो थे—पायेंक्य (Isolation) और मुनरो सिद्धान्त (Munroe Doctrine)।

पायेंक्य की नीति—संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राष्ट्र के रूप में जन्म १७७६ के अमेरिकन स्वातन्त्र्य संग्राम के फलस्वरूप हुआ था। अपने पन्महाल की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से मजबूर हो कर अमेरिका के इस नये गणतन्त्र को तटस्थता और पायेंक्यवाद की नीति का सहारा लेना पड़ा। १७६७ में प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने विचार-मापण में पायेंक्य नीति का स्वष्टीकरण करते हुए कहा—“विदेशों के सम्बन्ध में हमारे व्यवहार का महान् नियम यह है कि हम उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखें किन्तु राजनीतिक सम्बन्ध यथासम्भव कम से कम रखें। हमारी सच्ची नीति यह है कि हम विदेशी जगत के किसी भी अंग के साथ स्थायी संबंधों न करें।” चूंकि अमेरिका यूरोप के झगड़ों से बिल्कुल पृथक् और तटस्थ रह कर अपनी उन्नति करना चाहता था, इसीलिए उसकी नीति को पायेंक्य-वादी कह कर सम्बोधित किया गया। इस सन्दर्भ में यह ध्यान देने योग्य

सात है कि अमेरिका का यह पार्थक्य केवल यूरोप के मामलों तक ही था उसने पश्चिमी गोलार्द्ध के अन्य अमेरिकन राज्यों के बारे में पार्थक्य की नीति का कभी अनुसरण नहीं किया, और न ही एशिया के सम्बन्ध में वह इस नीति को व्यवहार में लाया। उदाहरण के लिए, १८१४ में अमेरिकन नौसेना ने जापान को अपनी परम्परागत पार्थक्यवादी नीति का परित्याग करने को बाध्य किया तो १९०० में चीन के बाक्सर विद्रोह में अमेरिकन सेनाओं का हस्तक्षेप हुआ तथा सुदूरपूर्व के मामलों में अमेरिका ने पहली दिलचस्पी प्रकट की। इस दृष्टि से शर्मन का यह लिखना ठीक ही है कि "वास्तविक राजनीति की परिभाषा में पार्थक्यवाद तथा इस पर आधारित अहस्तक्षेप और सघर्षों में न उलझने द्वारा सुरक्षा पाने की नीति का वस्तुतः कभी अस्तित्व नहीं रहा।"

तटस्थता और पार्थक्य की अमेरिकन नीति को सिद्धान्त रूप में राष्ट्रपति जेफरसन (Jefferson) ने १८०१ में इस प्रकार किया—“शान्तिपूर्ण व्यापार सब के साथ, पर दखल देना करने वाली सन्धिवा किसी के साथ भी नहीं।” इसका आशय यही था कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करे लेकिन यूरोपीय राजनीति के फन्दे में नहीं फसे।

मुनरो सिद्धान्त—१८२३ में मुनरो सिद्धान्त के प्रतिपादन से अमेरिकन विदेश नीति के इतिहास में एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ। १८२३ में जब प्रशिया, अस्ट्रिया और रूस के “पवित्र सन्धि” ने स्पेन में निरंकुश शासन के विरुद्ध हुई नान्ति को कुचलने के बाद स्पेन के दक्षिण-अफ्रीका के उपनिवेशों में मंड्रिड के विरुद्ध हुए स्वातन्त्र्य आन्दोलनों को दबाना चाहा तो २ दिसम्बर, १८२३ को तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति मुनरो ने यूरोपीय राज्यों को अमेरिकन महाद्वीप के मामलों में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देते हुए यह ऐतिहासिक घोषणा की कि—

१. “हम यह जता देना चाहते हैं कि यूरोपियन शक्तियों के युद्धों में हमने कभी कोई भाग नहीं लिया और न कभी भाग लेने का हमारा विचार है, हम इनसे सर्वथा दूर रह रहे हैं,”

२. “हम अपनी शान्ति और सुख की दृष्टि से अमेरिका के किसी भी भाग में यूरोपीय शक्तियों की राजनीतिक सत्ता का विस्तार नहीं होने देते और दक्षिणी अमेरिका के गणराज्यों की स्वतन्त्रता में किसी हस्तक्षेप की सहन नहीं करेंगे,” एवं,

३. “अमेरिकन महाद्वीप का प्रदेश भविष्य में यूरोपियन शक्तियों द्वारा उपनिवेश (Colonisation) का क्षेत्र नहीं बनाया जा सकेगा।”

राष्ट्रपति मुनरो ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि किसी यूरोपीय राष्ट्र द्वारा अपनी प्रगल्भी को अमेरिकन गोलाबर्द में फँसाने का प्रयत्न किया गया तो सयुक्त राज्य अमेरिका उसे पूरन अमैत्रीपूर्ण कार्यवाही समझेगा। स्पष्टतः मुनरो सिद्धान्त यूरोपियन राज्यों को एक चेतावनी थी कि वे अमेरिकन महाद्वीप में सात्ताज्यवादी चेष्टाओं से दूर रहें। साथ ही यह एक आश्वासन भी था कि अमेरिका नी यूरोपीय झगड़ों से अलग रहेगा। हमारे राज्यों में, मुनरो सिद्धान्त का जय था "तुम पृथक् रहो, हम भी पृथक् रहेंगे।"

मुनरो सिद्धान्त १८२३ में अपने प्रतिपादन से लेकर प्रथम महायुद्ध तक पाश्चात्यवादी नीति के साथ साथ मुत्तारूप रूप से चलता रहा। परन्तु, १९१४ में प्रथम महायुद्ध का समारम्भ हो जाने पर सयुक्त राज्य अमेरिका के लिए परम्परागत पाश्चात्यवादी नीति पर चलते रहना सम्भव न रहा। ४ सितम्बर, १९१४ को विल्सन ने कांग्रेस के समक्ष कहा, "हमारा हम युद्ध में कोई भाग नहीं, किन्तु इसके बिल की अदायगी हमें करनी पड़ेगी।" विल्सन का यह वक्तव्य एकदम सत्य और सन्तो की चेतावनी जैसा प्रमाणित हुआ। अमेरिका महायुद्ध से किसी भी रूप में अप्रभावित नहीं रहे सक्ता था। "अमेरिकन जन सभ्यता में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, उनके देश युद्ध से ग्रस्त थे, उन उनके उद्देश्य स्वाभाविक रूप से उत्तेजित हुए। इसके अतिरिक्त अमेरिका का व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र से था और विशेष रूप से वह जर्मनी की अपेक्षा सम्बन्धित था।"

महायुद्ध में अमेरिका प्रारम्भ में तो किसी प्रकार तटस्थ बना रहा, लेकिन शीघ्र ही १९१५ के मध्य उसे युद्ध क्षेत्र में बँदना पड़ गया। हुआ यह कि मित्र राष्ट्रों के आर्थिक तटरोध (Economic Blockade) को तोड़ने के लिए जर्मन पनडुब्बियों ने मित्र राष्ट्रों के जहाजों को डुबोना शुरू किया। मई में एक अमेरिकन तेलवाहक जहाज पर आक्रमण हुआ और इसके ६ दिन बाद ही एक निरक्षर जहाज जो न्यूयॉर्क में सैनिक सामग्री ला रहा था, डुबो दिया गया जिससे फलस्वरूप १२८ अमेरिकनों सहित लगभग १२०० व्यक्तियों की हत्या हुई। २४ मार्च १९१६ को एक सैन्य रॉकेट में चैनल स्टोमर पर बिना चेतावनी के जर्मन पनडुब्बी द्वारा प्रहार किया गया और फितने ही अमेरिकनों के जीवन की क्षति पहुँच गई। इन काल में अमेरिका समुद्रों की स्वतन्त्रता (Freedom of Seas) तथा तटस्थ देशों के अधिकारों (Neutral Rights) पर बड़ा बल देता रहा।

जर्मनी द्वारा समुद्री आक्रमण की इन हरकतों ने अमेरिकन राष्ट्र को एक बारगी हो साक्षर दिया और अमेरिकन सरकार कोई हद्द स्वीकार करने

के निरवय की ओर अपसर होने लगी। इस समय अमेरिकन पूँजीपति मित्र राष्ट्रों की सरकारों को भारी कर्ज दे रहे थे तथा बहुत बड़े मुनाफे के साथ लम्हे राष्ट्रान्तर एव उन्नत उपयोगी सामग्री बेच रहे थे। मित्र राष्ट्रों की पराजय का अर्थ इनका दिवालिया होना था, अतः इस स्थिति से भी अमेरिकन सरकार और जनता विक्षेप चिंतित होने लगी। अमेरिका का हित मित्रराष्ट्रों की विजय में सन्निहित था। जर्मनी की विजय से अमेरिका को न केवल भीषण आर्थिक क्षति होती अपितु इससे यूरोप का शक्ति सन्तुलन बिगड़ने की तथा यूरोपियन महाद्वीप सहित सम्पूर्ण विश्व में जर्मनी के हावी होने की ओर अमेरिकन सुरक्षा की भयानक उत्पन्न होने की आशंका थी। इन सब राष्ट्रीय स्वार्थों ने अमेरिका में इस निश्चय की परिपक्व किया कि मित्र राष्ट्रों की विजय होनी ही चाहिए। अतः इस पक्ष की व्यापपूर्ण सिद्ध करने के लिए जनता से यह कहा जाने लगा कि जर्मनी में निरक्षर शासन है और मित्र राष्ट्र लोकतन्त्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं तथा उनकी सहायता करना अमेरिकन लोकतन्त्र का पवित्र बर्तव्य है।

इसी समय २१ जनवरी १९१७ को जर्मनी ने घोषणा की कि ब्रिटिश नौ शक्ति को समूह नष्ट कर देने के लिए ब्रिटिश द्वीप समूह, फ्रांस और इटली के निरुद्ध आने वाले प्रत्येक जहाज को जर्मनी 'बिना किसी चेतावनी के' सब उपायों में डुबो देगा। इस घोषणा ने सम्पूर्ण अमेरिकन राष्ट्र को धुन्ध कर दिया। १ फरवरी १९१७ को राष्ट्रपति विल्सन ने जर्मनी से कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छिन्न कर लिये। १ अप्रैल १९१७ तक ८ अमेरिकन जहाज डूबो दिये गये। अमेरिकावासियों का जोष अपनी सीमा लाघ गया और ६ अप्रैल १९१७ को अमेरिकाने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार १७२३ में चलती आ रही पार्थिववादी एवं तटस्थतावादी अमेरिकन नीति का पहली बार सम्पूर्ण रूप में परित्याग हुआ।

अमेरिका ने बड़े ही सकटपथ काल में मित्र राष्ट्रों के पक्ष में युद्ध-प्रवेश किया। अमेरिकन सैन्य शक्ति ने युद्ध का पासा पलट कर जर्मनी की भीषण पराजय को निश्चित बना दिया। "तटस्थता की नीति अमेरिकन रवायों की रक्षा में असमर्थ सिद्ध हुई थी, अतः पार्थिव के स्थान पर यूरोपीय महापटल में भाग लेने की नीति अपनाई गई" जिसके फलस्वरूप विजयी जर्मनी पराजित जर्मनी में दहल गया और ११ नवम्बर १९१८ को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण करते हुए विश्व सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये।

दो महायुद्धों के बीच अमेरिका

(America between Two World Wars)

द्वितीयकी सहायता के बल पर प्रथम महा युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने विजय

पायी जिससे अमेरिका की प्रतिष्ठा में चार चाद लग गये। राष्ट्रपति बिन्सन ने मत प्रकट किया कि महायुद्ध में उजड़ने के बाद जब अमेरिका की पारंपर-वाद की नीति समाप्त हो गयी है तथा अमेरिका की नीति के इस मूलभूत परिवर्तन का कोई विकल्प नहीं है। ६ सितम्बर १९१६ को अपने एक भाषण में उन्होंने बताया कि 'संयुक्त राज्य अमेरिका के पारंपर्य का केवल इसीलिए अन्त नहीं हुआ है कि हमने विश्व राजनीति में भाग लेना पसन्द किया है बल्कि इसलिए हुआ है कि अमेरिकी जनता की योग्यता और हमारी शक्ति के विकास के कारण हम मानव जाति के इतिहास में निर्णायक तत्व बन गये हैं। ऐसी स्थिति में आप चाहे या न चाहें, छूटक नहीं रह सकते।'

अमरीकी जनता की प्रतिक्रिया को देखकर राष्ट्रपति विलसन को यह पूरा-पूरा भरोसा हो चला था कि वाशिंगटन की सन्धि की तथा राष्ट्रसंघ की सदस्यता की उक्त बात स्वीकार कर लेता। किन्तु जब रिपब्लिकन पार्टी के प्रभावित सीनेट ने विनसन-विरोधी रक्त बगनाया तो न केवल राष्ट्रसंघ का ही बहिष्कार किया गया बल्कि जर्मनी की हार में उत्पन्न किसी भी राजनैतिक एवं आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए किये जाने वाले सामूहिक प्रयास का भी विरोध किया गया। जब अमरीका की सदस्यता पर राष्ट्रसंघ में विचार किया जा रहा था अविनाश सदस्यों का विचार यह था कि कुछ समान हो जाने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका को १९१३-१४ की स्थिति में ही आ जाना चाहिए जहाँ से कि वह बना है। उक्त अपनी पहले वाली पारंपर्य नीति को अपना लेना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी इस प्रक्रिया पर प्रभाव डाला। सन् १९१६ का वर्ष संयुक्त राज्य अमरीका के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धातुक आर्थिक मशीन आदि, हिंसक तथा अव्यवस्थापूर्ण औद्योगिक आन्दोलन किये गये, आर्थिक दबन के करीब राज्यों में जाति के आधार पर रक्तपूर्ण दंगे हुए। इन सबके कारण उत्पन्न अस्थिर एवं अव्यवस्था में यह दर होने लगा था कि कहीं बोलशेविक क्रान्ति महा भी न दुहरा दी जाये। इन सभी समस्याओं को समाचार पत्रों में मुख्य स्थान दिया गया तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का महत्व कम हो गया। राष्ट्रसंघ की सदस्यता के समर्थक आमतौर पर इन समस्याओं द्वारा उलट दिया गया।

मुद्रकालीन आर्थिकवाद का किला टूट चुका था तथा यह आशंका की जाती थी कि यदि संयुक्त राज्य अमरीका राष्ट्रसंघ का सदस्य बन भी गया तो बना फायदा होगा। सशस्त्र से लड़ने वाले सैनिकों को जो अनुभव प्राप्त हुए उनका वाकिफ़ लक्ष्य से बहुत कम सम्बन्ध था। उत्तरी भाग के रक्तपूर्ण क्षेत्रों पर जो ध्यानकेंद्रित हुआ उसे स्वतन्त्रता एवं प्रजातन्त्र के

लिए किये जाने वाले युद्ध की मान्यता से नहीं जोड़ा जा सकता था। इन कनेक्शनियों के कारण युद्ध से लौटने वाले का यह विचार था कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका को युद्ध में फँसने से बचासम्भव बचना चाहिए। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का सदस्य बन गया तो निश्चय ही वह शायं करने की पूर्ण स्वतन्त्रता की परम्परागत नीति से वंचित हो जायेगा। वाशिंग्टन की सन्धि को स्वीकार करने के लिए कुछ शर्तों की व्यवस्था का लॉज (Lodge) द्वारा समर्थन किया गया। किन्तु बोरा (Borah) का मत था कि राष्ट्रसंघ में अमेरिकी सदस्यता जैसे विषय पर कोई शर्त लगाना महत्वहीन है। इन प्रचार का बदम या तो मौलिक रूप से सही है बथवा गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रसंघ की सदस्यता का या तो पूरा उत्तरदायित्व सम्भालना चाहिए अथवा इन प्रकार के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देना चाहिए।

राष्ट्रपति विलसन ने अपने अनेक भाषणों द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्ण योगदान से युक्त प्रभाव पूर्ण राष्ट्रसंघ के विकासकार पुनः एक बार युद्ध के गर्त में गिर जायेगा। उसके शत्रु का रूप अब भी आदर्शवादो था, वह राष्ट्रसंघ की सदस्यता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि एक नयी विश्व व्यवस्था की दृष्टि से चाहता था। विलसन ने जो भी तर्क एवं विचार प्रस्तुत किये वे आदर्श के रूप में तो प्रशस्तनीय थे किन्तु उनके द्वारा व्यावहारिक, सजीव, स्वार्थी एवं कठोर पार्थक्यवादियों के विरोध का जवाब न दिया जा सका। फोस्टर डलेस का कहना है कि "वह अपने शत्रुओं से उनके आगे स्तर पर ही बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वह उनसे बहुत ऊँचा उठ चुका था।"

अन्त में वाशिंग्टन की सन्धि को अस्वीकार कर दिया गया। रिपब्लिकन मतदाताओं ने हार्डिंग (Harding) को अपना राष्ट्रपति चुना। हार्डिंग ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे राष्ट्रों के साथ विचार करने के लिए तदा सम्मेलन करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। वह विश्व में निःशर्मीकरण की स्थापना का प्रयास करेगा तथा पक्ष-कैमले एवं मध्यस्थता की प्रोत्साहन देगा। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी समझौते किये जायेंगे वे राष्ट्रीय सम्प्रभुता की ध्यान में रख कर किये जायेंगे न कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय विश्व संस्था द्वारा। हार्डिंग ने यह स्वीकार किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व में एक नया स्थान प्राप्त हुआ है किन्तु उसके मतानुसार राष्ट्रवाद की ताक पर रख कर अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की नीतिमग्नता उचित नहीं है। वाशिंग्टन की सन्धि पर स्वीकृति प्राप्त न

करने का कारण विलसन को सम्भीर आघात लगा और निराशा भरे शब्दों में उसने यह कहा कि अमरीकी जनता अपने कड़े अनुभवों का बावजूद सीखेगी जो उसने अभी खो दिया है। हमें विश्व का नक्सबंद करने का अवसर प्राप्त हुआ था कि नु हमने उसे खो दिया तथा ग्रीक ही हम। इन सबका दुष्परिणाम नात हो जायेगा।

यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध का बावजूद सयुक्त राज्य अमरीका ने पाश्चात्य की नीति को ग्रहण कर लिया किन्तु तो भी इसके कारण उसका प्रभाव विश्व राजनीति में अधिक कम न हुआ। यह जटिल है कि यदि उसने सक्रिय रूप में भाग लिया होता तो सम्भवतः उसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता। राष्ट्रपति विल्सन द्वारा यद्यपि आत्मवादों भाषा में बात की जाती थी किन्तु वह भी राष्ट्रीय प्रभाव की भौतिक उपस्थितियों के प्रति अचल न था। पेरिस के शान्ति सम्मेलन में उन यह विश्वास था कि अब योरोप के देश उसने नतान्व की स्वीकार कर लगे। राष्ट्रपति में अमरीका को वह एक बरिष्ठ भागीदार के रूप में शामिल करना चाहता था। विलसन के कथनानुसार वित्तीय नेतृत्व हमारा होगा औद्योगिक प्रधानता हमारी होगी व व्यापारिक लाभ भी हमको ही प्राप्त होगा। दुनिया के दूसरे देश हमारे ओर निदग्न तथा नेतृत्व के लिए दब रहे हैं। सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इस समय शान्ति सन्तुलन बर्तों का काय किया जा रहा था।

अमरीका की शक्ति अनेक तर्कों पर आधारित थी जसे प्राकृतिक साधन औद्योगिक तकनीकी के तरीके उत्तमो एवं साहसी जनता की गणसमक प्रवृत्ति आदि। केवल यही सब कुछ नहीं था। युद्ध के समय की मांग के कारण उत्पादन एवं व्यापार की गति पर्याप्त तेज हो गई थी। विश्व व्यापी व्यापार की व्यवस्था के कारण अमरीकी वाणिज्य को नये विदेशी बाजार स्थापित करने का अवसर एवं क्षमता मिली। विश्व की वित्तीय राजधानी लंदन की अपना वाणिज्य बन गयी। रेमण्ड माइंसल का विचार है कि बहुत कम लोग ही इसी जल्दी आर्थिक प्रगति प्राप्त करते हैं कि अमरीका ने १९१८ व १९१९ के बीच प्राप्त कर ली। सयुक्त राज्य अमरीका एक ऐसा देश था जिसने युद्ध में हुए अपने नुकसान की पूर्ति की ओर साथ ही आर्थिक प्रगति को भी आगे बढ़ाया। इसका मूल स्रोतों की मात्रा का अनमान लगाया जा सकता है। सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दुनिया के बाजार का ४० प्रतिशत उत्पादन किया गया। यह मात्रा उसके निर्यात प्रतिद्वंद्वी यंत्र विदेश में दो गुनी थी। यह देश समस्त पेट्रोल का लगभग ७० प्रतिशत उत्पादन करता था। अथवा चूना माल की हार्ड सैल्फा उत्पादन अत्यंत व्यापक था। कुछ एवं चीजों का उत्पादन

समुक्त राज्य अमेरिका का उदय

महा नहीं होता था, जैसे रबर, मुद्र के लिए आवश्यक कुछ घातुयें, कॉफी, चीनी और चाय, आदि। इनके लिए वह अन्य देशों पर अवलम्बित था। सन् १६२० तक अमेरिका के व्यापार और वित्त की स्थिति पर्याप्त एकीकृत बन गई। दुनिया का लगभग १५ प्रतिशत निर्यात इसके द्वारा किया जाता था। इसका औद्योगिक उत्पादन इससे भी अधिक व्यापक था।

इन सभी विवासों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि समुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के आर्थिक और वित्तीय मामलों में एक प्रभावशाली योगदान कर रहा था। वह यूरोप के पुनर्निर्माण में कर्ज और भट्टे कर योगदान कर रहा था। व्यक्तिगत एवं सरकारी अभिकरणों की राहट के लिए एवं पुनर्रचना के लिए बहुत बड़ा धन खर्च किया जा रहा था। अमेरिका द्वारा जर्मनी, फ्रान्स और इटली को उनकी शाखा बनाए रखने के लिए पर्याप्त मदद की गई। इसके साथ ही स्थानीय सरकार की इकाइयों को, सामंजसिक उपयोगिताओं को एवं व्यक्तिगत निगमों को कर्ज देने के लिए व्यवस्था की गई। इस देश ने पोलैण्ड में रेल रचना के लिए, यूगोस्लाविया में बदरगाह की रचना के लिए, आस्ट्रिया में गृह रचना के लिए सहायता की। मध्यपूर्व में तेल के नए कुयों खोदने के लिए, बम्बा में चीनी के नए उद्यम स्थापित करने के लिए और टोकियो तथा शंघाई में सामंजसिक उपयोगिताओं के विकास के लिए पर्याप्त खर्च किया गया।

समुक्त राज्य अमेरिका का सोवियत रूप से भी पर्याप्त आर्थिक लेन-देन रहा। वैसे अमेरिका ने १९३३ तक सोवियत रूस को कूटनीतिक मान्यता प्रदान नहीं की किन्तु फिर भी व्यापार को नए बाजार खोजने से नहीं रोका जा सका। जनरल इलेक्ट्रिक ने सोवियतों को लाखों रुपये का बिजली का सामान दिया। यहां की तेल कम्पनियों ने रूस के साथ समझौते किए। कई कम्पनियों ने सोवियत स्वचालित उद्योगों की स्थापना में सहायता की। अमेरिकी तकनीकी सहायकों ने सोवियत बान्धों की रचना में सहयोग दिया।

समुक्त राज्य अमेरिका ने यद्यपि बार्ता की सधि और राष्ट्र संधि की सदस्यता को अस्वीकार किया किन्तु फिर भी उसने विश्व राजनीति से सम्बन्ध नहीं लिया और मार्च १९३३ में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने के बाद ही अमेरिकन विदेशनीति स्पष्ट रूप से पर्यव्यवाद से सैन-दान अन्तर्राष्ट्रीयतावाद की ओर उन्मुख होने लगी। यथावत शुद्ध से अनेक कारणों वश अमेरिका की शक्ति और महत्ता बढ़ती चली गयी। इनमें से कुछ का वर्णन उल्लेखनीय है—

(१) अमरीका के उपनिवेश (The American Colonies)

अमरीका का क्षेत्र केवल अमरीका महाद्वीप तक ही सीमित नहीं था । अंग्रेजों में अमरीका का एक साम्राज्य था अन्य क्षेत्रों पर इसका राजनैतिक प्रभाव था और वहाँ पर स्वयं का शासन भी । इससे विश्व में उसका स्थान महत्वपूर्ण बना । संयुक्त राज्य अमरीका का लैटिन अमरीका के राज्यों पर दक्षिण की दिशा में और एशिया के किनारों पर पश्चिमी दिशाओं में पर्याप्त प्रभाव था । यह इस महाद्वीप में सर्वोच्च स्थिति रखता था तथा प्रशांत महासागर तक इसका प्रभाव था । पोर्टो रिको (Puerto Rico) संयुक्त राज्य अमरीका का प्रथम समुद्र-गार का उपनिवेश था । इसे जब से स्पेन से प्राप्त किया गया था तब से यहाँ स्वायत्त सरकार का विकास प्राप्त हो चुका था । व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व्यापक कर दी गईं और सन् १९१७ के नए अधिनियम के अनुसार एक नियुक्त परिषद की जगह निर्वाचित उच्च सदन स्थापित किया गया । यहाँ के नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक बना दिया गया और उनको अधिकार-पत्र सौंप दिया गया । सन् १९५० में यहाँ का नया संविधान बना और इस प्रकार इस द्वीप को पूर्णतः स्वायत्त सामन्य प्रदान कर दिया गया । इसके दो वर्ष बाद इसका स्तर एक स्वतन्त्र सलग्न राष्ट्र मण्डल का हो गया ।

इस प्रदेश से अधिक महत्वपूर्ण वर्जिन द्वीपों (Virgin Islands) एवं पनामा नहर क्षेत्र को माना गया । वर्जिन द्वीपों को लेने के लिए अनेक व्यक्त सपत्तीना-जातियों की गयीं और अन्त में उन्हें डेनमार्क से खरीद लिया गया । प्रारम्भ में उन्हें नौसेना-आयोग के आधीन रखा गया और सन् १९२१ में उन्हें अन्तरग विभाग को सौंप दिया गया । पनामा नहर क्षेत्र पर सन् १९०३ में अमेरिका का नियन्त्रण था और इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विभाग के माध्यम से दिया जाता था । इन प्रवेष्टों पर अधिकार के द्वारा रीरिविजन पर अमेरिका के नियन्त्रण ने उसकी शक्तियों को और व्यापक बना दिया । संयुक्त राज्य अमेरिका का क्यूबा में एक महत्वपूर्ण सैनिक-अड्डा था तथा बट् बट् भी इस देश के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता था । पनामा गणराज्य, निकारागुआ, हैटी तथा डोमिनिकन गणराज्य भी कुछ-कुछ सरसकट राज्य की स्थिति में थे । संयुक्त राज्य अमेरिका सन् १९२० के अन्तिम काल तक इन राज्यों पर से अपने अधिकार को स्थापन के लिए तैयार हो गया ।

प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी रक्षा के लिए एल्यूमिनियम महाद्वीपों से हवाई होते हुए पनामा नहर क्षेत्र तक एक शक्ति की

रचना की। बाद में एलास्का (Alaska) और एल्यूसियन द्वीपों का महत्व बढ़ गया। प्रिगेडियर-जनरल विलियम मिचेल (William Mitchell) ने सन् १८२५ में यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया था कि वायु शक्ति एलास्का को धरती पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण रणनीति का स्थान बना देगी। उनके विचारानुसार जो कोई भी एलास्का पर अधिकार रखेगा वह सारी दुनिया पर शासन करेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशान्त क्षेत्र के उपनिवेशों में हवाई का सम्बन्ध निम्न का और गहरा था। जब ये द्वीप स्पेन-अमेरिका के युद्ध में लिये गए थे तब से इसको रणनीति सम्बन्धी एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। अमेरिका से दूर स्थित सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कष्टदायक समुद्र-गार के प्रदेशों में फिलिपाइन द्वीप समूह था। यह आशा की गई थी कि इनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशान्त महासागर में नौसैनिक एवं व्यापारिक सर्वोच्चता प्राप्त हो जाएगी किन्तु बाद में यह भावना जोर पकड़ने लगी कि आक्रमण की दशा में उनकी रक्षा नहीं की जा सकती। अनुभव ने यह प्रदर्शित किया कि पूर्वी एशिया में व्यापार के विकास की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं था। बहुत समय से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना यह उद्देश्य जाहिर किया कि फिलिपाइन के लोगों को यथा सम्भव स्वायत्त सरकार प्रदान करेगा और अन्त में उनको पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान कर देगा। सन् १८०२ के कानून के अनुसार वहाँ निर्वाचन व्यवस्थानिकाओं की स्थापना की गई तथा आने वाले वर्षों में स्वायत्त सरकार की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई। सन् १८१६ के जॉन्स अधिनियम में यह बताया गया कि स्थायी सरकार की स्थापना होते ही यहाँ स्वतन्त्रता प्रदान कर दी जाएगी। फिलिपाइन के लोगों की बढ़ती हुई स्वतन्त्रता की मांग को अधिक समय तक दबाए रखना सम्भव नहीं था। हुबेर प्रशासन ने फिलिपाइन को स्वतन्त्रता देने का विरोध किया क्योंकि उसके मतानुसार ये प्रदेश पूर्ण स्वायत्त सरकार के लिये तैयार नहीं थे तथा दूसरे, उनको ठीकाल स्वतन्त्रता दे दी गई तो प्रशान्त महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर खतरनाक रूप से प्रभाव पड़ेगा। फिलिपाइन के सम्बन्ध में अमेरिकी नीति विरोधाभासपूर्ण थी क्योंकि एक ओर तो यहाँ के लोगों को स्वायत्त सरकार प्रदान करके स्वतन्त्रता प्राप्ति के हेतु प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर इसके प्रति जो आर्थिक नीति अपनाई गई उसके परिणामस्वरूप यह प्रदेश अधिक से अधिक आश्रित होता गया। वैसे अमेरिका इस प्रदेश पर नियन्त्रण रखने में रुचि नहीं ले रहा था किन्तु वह नियन्त्रण को हटाना भी नहीं चाहता था। रहने का अर्थ यह है कि

यहाँ से पुराना राजनैतिक साम्राज्यवाद तो हट रहा था किन्तु नए प्रकार का आर्थिक साम्राज्यवाद छा रहा था।

(२) नौसेना का विकास (Growth of the Navy)

संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति के विकास में प्रभाव डालने वाला अन्य तत्व उसकी नौसेना का विकास था। समुद्रों पर नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष की दुनिया में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास यहाँ तक होना जरूरी था कि वह ग्रेट ब्रिटेन की नौसैनिक सर्वोच्चता को चुनौती दे सके। जब अमेरिका ने आर्थिक शक्ति को अपने प्रभाव का मौलिक आधार बना लिया तो यह जरूरी था कि उसकी स्पष्ट अभिप्रेति के लिए अमेरिकी नौसेना का विकास किया जाता। थ्योडोर रूजवेल्ट ने सन् १९०० में ही जो नौसेना शक्ति का विकास किया उसके कारण अमेरिका हवाई और बग़दाद आदि में अपने नौसैनिक अड्डे खोल सका तथा कैरिबियन और पूर्वी प्रशान्त महासागर पर अपना अधिकार रख सका। किन्तु दो महायुद्धों के बीच जो अमेरिकी नौसेना की स्थिति थी उसके कारण विश्व राजनीति में उसे प्रभावशील नहीं कहा जा सकता था। प्रथम विश्व युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका को नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की ओर प्रेरित किया। सन् १९१६ के नौसेना विनियोग कानून में यह उद्देश्य बनाया गया कि नौसैनिक शक्ति का इतना विकास किया जाए जिसकी कोई प्रतिযোগिता न कर सके। राष्ट्रपति विल्सन को यद्यपि नौसेना में अधिक रुचि नहीं थी किन्तु फिर भी उन्होंने उन योजनाओं को स्वीकार किया। विल्सन के परामर्शदाताओं ने भी अमेरिकी नौसैनिक शक्ति पर पर्याप्त ध्यान दिया। राज्य सचिव डेनियल्स (Daniels) के कथनानुसार यदि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रजातन्त्रात्मक भावना के नेता के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है तो उसे आक्रमण के विरुद्ध रक्षा के लिए अद्वितीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए और अत्याचारियों के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए सशस्त्र होना चाहिए।

अमेरिकी जनता का यह मत नहीं था कि जर्मन पत्तीट को नष्ट करने वाली नौसेना के देश को अपनी सुरक्षा के लिए सशस्त्र होना चाहिए। यद्यपि प्रशान्त में जापान की शक्ति का उदय इस बात का द्योतक था कि अमेरिका अपनी शक्ति को कम नहीं कर सकता। कुल मिला कर अमेरिकी जनता का यह विश्वास नहीं था कि अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से अधिक शक्तिशाली

नीसेना रखनी चाहिये। अनेक लोगों ने सरकारी धन को खर्च के लिए तथा सार्वजनिक नीति का अन्तर्गत के लिए भी इन कार्रवायों का विरोध किया। ऐसी स्थिति में नीतिगत प्रकार की योजनाएँ तब तभी और हाईज प्रशासन को सही से प्रचार रखने के लिए वाणिज्यिक सम्बन्धन सुचारु पड़ा।

कुछ समय बाद यह अनुभव किया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अनेक दृष्टियों से एक सर्वोच्च शक्ति बन गया है और इसीसे तब नीसेना के क्षेत्र में भी प्राथमिकता प्राप्त करने चाहिये।

(३) अमेरिकी निर्यात

(The American Exports)

सन् १९२० के दौरान अमेरिकी निर्यात को बड़ा धक्का देते वाले तत्वों में इसके द्वारा किये जाने वाला सामान, शक्कर, सेबीकॉ और विद्युत का निर्यात था। यूरोप में तथा एशिया के अनेक भागों में मनुष्य राज्य अमेरिका की अनेक सामाजिक संस्थाओं ने और सांस्कृतिक मूल्यों ने विदेशों की सम्पदा एवं खन-खन के तरीके पर प्रभाव डाला। अमेरिका का विदेशी व्यापार बहुत बड़ा था तथा और उनके ही उत्पादकों को फायदा अधिक होती था। सम्पूर्ण यूरोप में और मध्यपूर्व, जापान, चीन, सेंट्रल अमेरिका तथा एशिया और अफ्रीका के अनेक भागों में अमेरिका द्वारा निर्मित अनेक चीजें जाने लगीं। इन वैश्विक सम्बन्धों की वस्तुओं ने विभिन्न देशों के खन-खन एवं सोवने विचारों के दूर पर प्रभाव डाला। जब यूरोपीय उत्पादकों को इन चीजों के आभाव से प्रतिस्पर्द्धा हुई तो उन्होंने भी उत्पादन के तरीकों को मनुष्य राज्य अमेरिका के अनुसार रखा। जापान अमेरिकी उत्पादन में प्रभाव प्रभावित हुआ। सोवियत रुब और अन्य देशों के लोगों ने भी इसी बहुत सी विदेशीयताओं को अपनाया। इन क्षेत्र में अमेरिका द्वारा जो धन दिया गया वह वैश्विक व्यापार की अनेक अधिक मूल्यपूर्ण था।

(४) अमेरिकी पर्यटक

(The American Tourists)

सन् १९२० के दौरान विश्व तरह अमेरिकी सामान और धन अन्य देशों में फैल का गया जहाँ तरह अमेरिकी नागरिकों की सेवाएँ भी अनेक देशों में हो गयीं। यूरोप के प्रायः प्रत्येक भाग में उनका प्रवेश हो गया। दुनियाँ के दूसरे भागों में भी वे पर्यटन करने में जाने लगे। इन नागरिकों के द्वारा दूसरे राज्य की भी काफी लाभ होता था उनके कारण वह इन्हें कुछ सुविधाएँ उपलब्ध करने का प्रभाव करने लगा। अमेरिकी व्यापारियों,

विद्यादियो तथा अवकाश प्रसीत करने वालों, आदि के द्वारा अमरीकी सङ्कृति का प्रसार किया गया। इन्होंने अमरीकी विचारों एवं परम्पराओं के प्रसार द्वारा विदेशों में संयुक्त राज्य अमरीका का सम्मान और प्रभाव बढ़ाया।

(५) अमरीकी चलचित्र

(The American Films)

विदेशों में अमरीकी संस्कृति का जो प्रभाव बढ़ा उसमें अमरीकी चलचित्रों ने पर्याप्त योगदान किया। हालीवुड को पश्चिम यूरोप के देशों में भी वैसा ही सर्वोच्च माना जाता था जैसा कि यह अपने स्वयं के देशों में था। जो लोग अमरीकी चलचित्र देखते थे उनकी यह इच्छा होती थी कि उस देश का वास्तविक जीवन भी देखा जाए जो उन्होंने पर्दे पर देखा है। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि अमरीकी फ़िल्मों ने किस मात्रा में अपना प्रभाव डाला किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि यह प्रभाव पर्याप्त महत्वपूर्ण रूप से हुआ जिसे कि गम्भीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए। चलचित्रों के माध्यम से अमरीका, पेरिस और रोम, ओसलो और बर्लिन, लन्दन और मेड्रिड के मध्यम वर्गों के फैशन तथा आचार विचारों को प्रभावित करने में प्रभावशाली रहा।

सन् १९२० में अपनाई गई विदेश नीति की प्रशासकीय सुविधाओं तथा विदेशी मामलों को राष्ट्रीय शक्ति के तत्त्व नहीं माना जा सकता। वाणिज्य सचिव हूवर ने व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए पर्याप्त कोशिशें की व राज्य विभाग को पुनर्गठित किया गया। संयुक्त राज्य अमरीका की शक्ति एवं धनता को देखते हुए बादरीनहोल्ड नेबर (Reinhold Niebuhr) ने यह कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका आधुनिक सभ्यता का वास्तविक साम्राज्य बन गया है किन्तु यह शस्त्र शक्ति के आधार पर नहीं बरन् डालर के आधार पर। कुछ अमरीकी लेखकों को अपने देश के सद्गुणों पर अभिमान है। उनके कथनानुसार अमरीका की शक्ति की अपेक्षा वहाँ के सद्गुणों से अन्य देशों को ईर्ष्या होती है।

सन् १९२० के मध्य में संयुक्त राज्य अमरीका के सामने एक विरोधाभास पैदा हुआ। राष्ट्रपति वूड्रो विल्सन ने कांग्रेस को अपने वाणिज्य सदेश में कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका शान्ति एवं युद्ध की समस्याओं पर नैतिक दृष्टि से देखता है। कैलाशप्रिया सन्धि द्वारा जो पूरा कार्यक्रम स्थापित किया गया था उसे अनुचित माना गया। इस बात के बड़े देश तत्काल के कानून को ही महत्व देने लगे थे और इस प्रकार उनके विश्वास की गति

विपरीत दिशा में जा रही थी। ऐसी स्थिति में सभी अन्तर्राष्ट्रीय जगहों का शान्तिपूर्ण निरन्तर कठिन बन गया। समस्या यह थी कि क्या संयुक्तराज्य अमेरिका को शान्तिप्रिय एवं युद्ध मित्र राष्ट्रों के बीच एक समझौते पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापना के कार्य से अपना हाथ पीछे करके स्वयं की सुरक्षा एवं शान्ति के लिए प्रयास करना चाहिए? क्या उसे अन्य राष्ट्रों के विवादों में एक तटस्थ दर्शक का ही काम करना चाहिए?

एक अन्य विकास ने इस समस्या को और भी अधिक गम्भीर बना दिया। सन् १९२० की दुनिया में जो परिस्थितियाँ थी उनमें प्रजातन्त्र अपमानित सुरक्षित था। उस समय तक फासीवाद एक गम्भीर चुनौती का रूप धारण नहीं कर पाया था। गांधी साम्यवाद के पीछे भी इतनी सैनिक शक्ति नहीं थी। इस वातावरण में रह कर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता अपनी विदेश नीति के शान्तिवाद पर जोर देते थे और वहाँ की जनता को यह विश्वास हो गया था कि इस देश को अब कभी भी हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किन्तु सन् १९३० के समय में फासीवाद को कई एक जगह विजय प्राप्त हो चुकी थी तथा अन्य प्रदेशों में तानाशाही शासनो का विकास हो गया था। इससे वहाँ के विचारों में पर्याप्त परिवर्तन आया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अपनी नीति के व्यापक रूपों पर विचार करना पड़ा। अब समार सम्पूर्णतावाद के खतरे में पड़ चुका था और यह सम्भव था कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस विकास से आलू भूद ले।

संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं का अब यह विश्वास हो चला था कि तटस्थता एवं पार्थक्य का अर्थ कोई महात्वा नहीं रह गया है। राज्य सचिव हल (Hull) का कहना था कि पार्थक्यवाद कभी भी सुरक्षा का साधन नहीं बन सकता वरन् यह तो अनुरक्षा का एक फलदायक स्रोत है।¹ इधर योराप की घटनायें बढ़ से बढ़तर होती जा रही थी। हिटलर जर्मनी को एकीकृत एवं शक्तिशाली बनाने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रहा था। वह सैनिक साधन भी अपनाने में नहीं झिझक रहा था। मार्च, १९३५ में जर्मनी ने आस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया तथा छ महीने बाद वह चेकोस्लोवाकिया से यह मांग करने लगा कि जर्मन जनसंख्या वाले सूडेटनलैण्ड को समर्पित कर दे। इंग्लैण्ड तथा फ्रांस आस्ट्रिया के जर्मनी के साथ विलय को देखते रहे किन्तु चेकोस्लोवाकिया के समर्थन में उन्होंने कदम उठाना उपयुक्त समझा। ऐसी स्थिति में योरोप में सम्भावित युद्ध के लक्षण दिखाई देने लगे। अग्नि, प्राय,

1 Peace and War, PP 57, 418, Vital Speeches, VI (April 1, 1938), 368-372

पेरिस, रोम और लन्दन में इस सघर्ष को दूर करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किये गये। अनेक प्रारम्भिक वाद विवादों के बाद हिटलर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तथा इटली के राज्य अन्वयशो क साथ वानवैत करने को तैयार हो गया। म्यूनिख समझौता किया गया किन्तु यह समझौता हिटलर को मार्च, १९३९ में शक्ति के आधार पर चेकोस्लोवाकिया को लेने से नहीं रोक सका। इसमें प्रोत्साहित होकर मुमोन्टनी ने अन्वयानिया को घर दबोचा। समस्त योरोपीय शक्ति विषय की दिशा में बढ़ती गई।

द्वितीय विश्व युद्ध और अमरीका

(Second World War and U S A)

मार्च १९३८ को चार्ल्स म राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक के बाद एक करके अनेक संदेश विदेशों को प्रसारित किये तथा अमरीका की यह आशा व्यक्त की कि शान्ति स्थापित करने के लिए कोई तरीका मिल सकेगा। जनवरी, १९३९ में कांग्रेस को भेजे गये अन्त संदेश में राष्ट्रपति ने विदेशी समस्याओं पर हो आधार प्रकाश डाला। उनका मत था कि म्यूनिख समझौते ने अन्तिम सकट को मुलझाया नहीं है यरन् टाल दिया है।

१ सितम्बर १९३९ को यह बात सत्य साबित हो गई जब कि हिटलर ने अपनी सेनायें पोलैण्ड को आक्रमण करने के लिए भेज दी। समस्त राज्य अमरीका की जनता अभी भी तटस्थता एवं पार्थक्य के विचारों से प्रभावित थी। उसका मत था कि यारोप में चाहे कुछ भी हो रहा तो हमको इससे कोई मन्लब नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने यह वायदा किया कि वह अपनी पूरी शक्ति से यह प्रयास करेगा कि अमरीका की शान्ति भंग न हो। वाद की घटनाओं ने यह निश्चय कर दिया कि अमरीका अग्निक समय तक पार्थक्यवाद की नीति को नहीं अपना सक्ता है और इसलिए मानव जाति को अस्तव्यस्त सम्पत्ता, सस्कृति, व्यापार एवं शान्ति में उसे हस्तक्षेप करना जरूरी है।

राष्ट्रपति एवं राज्य सचिव यद्यपि कुछ करने के लिए उद्यत थे किन्तु अमरीकी वानावरण को देखते हुए कुछ भी न किया जा सका। वे जनता की अमरीका के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में केवल कुछ भाषण एवं संदेश देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाये किन्तु जर्मनी के आगे बढ़ते हुए बंदरों ने परिस्थिति में ढेर बदल किया। अप्रैल, १९४० में हिटलर ने मोर्र तथा डेनमार्क पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। मई में इन देशों को जीत लिया गया। जून के मध्य में फ्रांस का पतन हो गया तथा युद्ध में रत ग्रेट ब्रिटेन को भी घमड़ी दे दी गई। इस सबको देख कर अमरीका की जनता की आंखें खुल गयीं। पश्चिमी योरोप पर जर्मनी की विजयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की

भाग को बढ़ा दिया तथा देश का जनमन रातों रात कुछ करने के विचार का समर्थक बन गया। उन देशों को तुरन्त सहायता देने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो आक्रान्ता एवं अमरीका के किनारों के बीच स्थित थे। रूजवेल्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि यदि ब्रिटिश और धूम्राना के देवताओं ने चल सेना एवं नौ सेना के द्वारा ही विजय प्राप्त करली तो पश्चिमी दुनिया में प्रजातन्त्र की समस्याएँ खतरे में पड़ जायेंगी।

संकट की गम्भीरता को देख कर संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी नौसेना एवं चल सेना को बढ़ाया। १९४० के अन्त तक इन कार्यों पर किये जाने वाले व्यय की मात्रा १७ बिलियन डॉलर तक पहुँच गई। जब रूजवेल्ट ने दो समुद्री नौसेना बनायी तथा आन्तिकालीन प्रबन्ध किये तो उसे किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जुलाई १९४० के हवाना सम्मेलन में कुछ समझौते किये गये जिनमें कि अमरीकी गणराज्यों ने यह मत प्रकट किया कि पश्चिमी गोलार्ध में यथास्थिति को तोड़ने वाले किसी भी कार्य का विरोध किया जायगा और नई दुनिया में किया गया कोई भी आक्रमण इन सबके द्वारा उनके अपने विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा। कुछ समय बाद ही ओगडेंसबर्ग (Ogdensburg) में कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमरीका की सम्मिलित सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई। हिटलर के विरुद्ध योगोपीय देशों को अब भी सहायता दी जा रही थी।

संयुक्त राज्य अमरीका मित्र राष्ट्रों की विजय में पूरी तरह से रुचि लेने लगा क्योंकि यदि पूरे योरोप पर हिटलर की विजय हो जाती है तो उस पर भारी संकट आ जाता। इस सम्बन्ध में किसी को कोई सदेह नहीं था किन्तु समस्या यह थी कि क्या इन राष्ट्रों के निवारणार्थ अमरीका को प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में आना चाहिये अथवा उसे अपने स्वयं के स्रोतों पर भरोसा करके केवल महाद्वीपीय सुरक्षा का ही प्रबन्ध करना चाहिए। दूसरे विकल्प को मानने वालों का कहना था कि धुरी राष्ट्रों के जीत जाने पर भी संयुक्त राज्य अमरीका अपने साधन स्रोतों के आधार पर अपनी रक्षा करने में समर्थ है। यद्यपि पश्चिमी प्रजातन्त्रों को दबाना जरूरी था किन्तु फिर भी यह आवश्यक था कि देश में शांति रहे। युद्ध और शांति के इस द्वन्द्व में फँस कर अमरीका यह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।

११ मार्च, १९४१ को संयुक्त राज्य अमरीका ने लेन्डलीज अधिनियम को कानून का रूप दिया। इसका समर्थन करते हुए रूजवेल्ट ने बताया कि मैं जान लीजिए मेरे मित्र के घर में आग लग जाती है और मेरे पास बगीचे की एक बंदी टंकी है। यदि वह पड़ोसी उस टंकी का प्रयोग करके आग फैला

सकता है तो मैं इस कार्य में उनकी सहायता करूँगा। १५ मार्च, १९४१ को एजवेल्ट ने यह बताया कि संयुक्त राज्य अमरीका प्रजातन्त्र के लिए सन्नागर का काम करेगा। उसके बयानानुसार 'यदि ब्रिटिश जनता तथा उसके मित्रों को जहाजों की जरूरत है तो अमरीका से वे जहाज प्राप्त करेंगे। यदि उनकी हवाई जहाजों की आवश्यकता है तो उनको प्रदान किया जायेगा। उनको साध की आवश्यकता है अमरीका इस पूर्ण करेगा। उनको टक, यन्त्र, दस्त्र एवं अन्य साधनों की आवश्यकता है, उनको यह सब दिया जायेगा।' 'अमरीका' यहाँ के लोगों की घोषणा के अनुसार प्रजातन्त्र का सन्नागर होता जा रहा था।

जब एजवेल्ट प्रशासन ने मित्र राष्ट्रों को प्रत्येक प्रकार की सहायता देने का विचार सामने रखा तब वह युद्ध में नदी उलझ रहा था वरन् वह अतन्त्र साधनों को रचना कर प्रजातन्त्र विरोधी तात्त्वों व विचारों को रोकने का प्रयास कर रहा था। कई एक अमरीकी लेखकों का मत है कि संयुक्त राज्य अमरीका युद्ध को बढ़ाना नहीं चाह रहा था और मित्र राष्ट्रों को दिया गया उसका आश्वासन इस बात पर आधारित था कि हिटलर द्वारा प्रभावित विश्व से संयुक्त राज्य अमरीका की सुरक्षा नहीं रह सकती तथा पार्थक्यवाद के आधार पर सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती।

संयुक्त राज्य अमरीका की इन नीतियों ने उसे युद्ध की ओर प्रेरित किया किन्तु फिर भी यह कहा जाना है कि वह धुरी राष्ट्रों के साथ आने अन्तिम क्षणों का रोक ही नहीं सकता था। संयुक्त राज्य अमरीका ने युद्ध में प्रविष्ट होने से ही नाजीवादी और फासीवादी शक्ति पराजित हो सकी। जब जापान और जर्मनी को अन्तिम रास्ते से हारने के लिए अमरीका को अपने जल, धूल, नौसैनिकों का पूरा पूरा प्रयोग करना पड़ा तो यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा न किया जाना तो वह इनको हरा नहीं सकता था। यह कहा जाता है कि धुरी राष्ट्रों के हारने के बाद भी विश्वव्यापी शांति जैसी कोई चीज स्थापित नहीं हुई क्योंकि साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव और पूँजीवाद से उसका संघर्ष गम्भीर रूप धारण कर चुका था। किन्तु फिर भी सन् १९४१ के जापान और जर्मनी के आक्रमण ने जो समस्या उत्पन्न की उसमें और कोई विकल्प नहीं रह गया था।

जून १९४० में जय फ्रांस का पतन हुआ और दिसम्बर १९४१ में पहले शर्जर पर जो सन्त्र जर्मनी आक्रमण हुआ उसके बीच, शांति, गन्ध, युद्ध की प्रभावशाली विदेशी नीति बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की जनता में भेदभाव चला रहा। यहाँ राष्ट्रपति रूजवेल्ट की जनता के पूरे

समर्थन की जरूरत थी। उसके बाद ही यह राष्ट्रीय सुरक्षा और लेंडलीज (Lend lease) सहायता के कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकता था। प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए अमरीकी जनता को यह समझना जरूरी हो गया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की जानिर आवश्यक बलिदान करे।

जब १० अप्रैल १९४१ को अमरीका के राज्य विभाग ने यह घोषणा की कि जर्मन नियन्त्रण के डेनिस प्रभाव को सम्भावित प्रसार से रोकने के लिए चीन ईपंड पर कब्जा करना जरूरी है तो इस दिशा में कार्यवाही की गई और तीन महीने बाद राष्ट्रपति ने यह कहा कि इस डीप के लोगों से समझौता हो गया है जिसके आधार पर यह सुरक्षा की दृष्टि से अमरीकी सैनिक टुकटिया रस्तों जा सकते हैं। रूजवेल्ट ने कांग्रेस को बताया कि संयुक्त राज्य अमरीका अटलांटिक में जर्मनी को रणकौशल के लिए महत्वपूर्ण ऐसी चालियों पर अधिकार नहीं करने देगा जिनको पश्चिमी गोलार्ध पर आक्रमण करने के लिए जल सेना या वायु सेना के अड्डे के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। कुछ दिनों बाद जर्मनी की सेनाओं ने यूगोस्लाविया और ग्रीस का पतन कर दिया। सोवियत रूस की ओर विजय के उत्साह में भरी हुई वे बढ़ने लगी।

जापान और संयुक्त-राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका अटलांटिक महासागर की घटनाओं को अधिक महत्व दे रहा था और उसने मतानुसार प्रतान्त की घटनाओं से साति को अधिक उतरा था। जापान चीन में लगातार आक्रमण कर रहा था। सन् १९४० की शरद ऋतु में उसने घुरी राष्ट्रों से सन्धि कर ली। उत्तरी इण्डोचीन पर उसने सोग्र ही अधिकार कर लिया। जब पूर्वी एशिया में युद्ध के प्रसार का खतरा स्पष्ट हो गया। अमेरिका की नीति यह रही कि कूटनीतिक और आर्थिक दबावों के आधार पर जापान को रोकने के लिए कुछ किया जाए तथा राष्ट्रवादी की सहायता दी जाए। फलस्वरूप जापान को भेजे जाने वाले माल के जहाजों पर नियंत्रण निगमन बढोर कर दिया गया और जब जापान ने इन्डो चीन और चीन में हटना अस्वीकार कर दिया तो २५ जुलाई, १९४१ को जापान-अमेरिकी व्यापार समाप्त हो गया। जापान और अमेरिका के सम्बन्ध बिगड़ते गये और ७ दिसम्बर १९४१ को एकदम आचस्मिक रूप से जापान ने पर्न हार्बर पर प्रत्यक्षारी बम बर्षा करदी। अमेरिका में कोई भी यह आशा नहीं कर रहा था कि साफ्ट इतना जल्दी उपस्थित हो जायेगा।

७ दिसम्बर को पर्न हार्बर पर जापानी बम बर्षा ने सम्पूर्ण अमेरिकी राष्ट्र को एकबारगी ही क्षयक्षोर दिया। ८ दिसम्बर को जापान के विरुद्ध

अमेरिकी कांग्रेस ने युद्ध की घोषणा कर दो और ३ दिन बाद ही अमेरिका को जर्मनी और इटली के साथ भी उलझ जना पड़ा। राष्ट्र के नाम जाने एक रेडियो प्रसारण में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अमेरिकी जनता को संकट का मुकाबला करने के लिए आह्वान दिया और कहा कि "हम अब युद्ध के बीच में हैं, विजय के लिए नहीं, बदले के लिए नहीं वरन् एक ऐसी दुनिया के लिए जिसमें कि यह राष्ट्र और इसके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली सारी चीजें इसके बन्धों के लिए सुरक्षित रहेंगी। हम आशा करने हैं कि जापान से उत्पन्न खतरे को समाप्त कर लगे किन्तु यह भी हमारे विरुद्ध होगा कि सौंप दुनिया पर हिटलर और मुसोलिनी का अधिकार हो जाए। हम युद्ध जीतने जा रहे हैं और उसके बाद आने वाली सन्ति को जीतने जा रहे हैं।" प्लं हाबेंर की घटना से अमेरिका पर एक बहुत बड़ा भावात्मक असर हुआ और रातों रात अमेरिका की जनता यह समझ गई कि उनका देश विश्व समाज का एक अंग है और इसका भाग उसी के साथ जुटा हुआ है। युद्ध में उसके प्रत्यक्ष संघर्षों को भौगोलिक स्थिति के कारण रोका नहीं जा सकता।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में परिस्थितियों के कारण उलझा और अब धुरी राष्ट्रों पर विजय प्राप्त करती गई तो उसे कुछ आत्म-संतोष हुआ। मई १९४५ में जोसेफ स्टालिन ने बताया कि "जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों का संबंध है यह युद्ध एक उद्देश्य प्राप्त करना था और वह यह है कि जर्मनी और जापान के सैनिक प्रसार से रक्षा। इस उद्देश्य के लिए हमको लड़ना पड़ा। यदि हम न लड़ते तो हमारा राष्ट्र प्रत्यक्ष रूप से खतरे में पड़ जाता। जहां तक हमारे स्वयं के हितों का सम्बन्ध है, युद्ध युद्ध रूप में आत्मरक्षा के लिए युद्ध था जो हम पर घोसा गया।"

द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अमेरिका

अथवा

द्वितीय महायुद्धोत्तर अमेरिकी विदेश नीति

**(America in the Field of International Politics
after the Second World War)**

१९३९ में द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाथक्वैदाद की नीति को निलजलि दे दी और अपने अतीत के अनुभवों से लाभ उठाकर फिर कभी इस नीति का अनुसरण नहीं किया। पाथक्वैदाद की नीति का परित्याग होने से अमेरिका की महायुद्धोत्तर वैदेशिक नीति में बहुत एक बड़ा नातिकारी मूखपात हुआ। अब संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को अवर्द्ध करने के लिए सब देगों से

समुक्त राज्य अमेरिका का उदय

सैनिक समझौते करने और उन्हें लगभग सभी प्रकार की सैनिक एवं आर्थिक सहायता देने की नीति का अनुसरण करने लगा। तथापि, माइकेल डोनेलन (Michael Donelan) के अनुसार युद्धोपरान्त अमेरिकन वैदेशिक नीति की आत्मा सुरक्षात्मक ही बनी रही और इस ही कारणवश जहाँ उसे जनक लाभ हुए वहाँ अनेक हानियाँ भी उठानी पड़ी। किन्तु यह सुरक्षात्मक नीति सैनिकरण कोशल (Military Strategy) से कहीं अधिक विस्तृत थी और केवल अमेरिका की सुरक्षा से इसका क्षेत्र कहीं अधिक चौड़ा था। युद्धोपरान्त अमेरिकन विदेश नीति द्वारा मानव कल्याण की भावना भी रचालित का गई थी, यह केवल अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक नये प्रकार की अवसरवादिता नहीं थी।

वास्तव में द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद की अमेरिकन विदेश नीति मुख्य रूप से साम्यवादी देशों के साथ उसके विरोध, समझौते, प्रति-द्वन्द्विता एवं संघर्ष की कहानी है जिसमें कभी व पुनः अपनी पारंपरिकवादी नीति पर आ गए और कभी अपने विचार के आदर्श समाज की रचना में भी बूढ़ पड़े। आखिर उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया जो असतोषजनक परिस्थितियों में रहना था। यह आशा की गई कि समय के साथ-साथ या तो ये समस्याएँ सुलझ जायेंगी अथवा स्वतः ही मिट जायगी और इस प्रकार संपूर्ण युद्ध के सतरे को टाला जा सकेगा। युद्धोपरान्त वर्षों में अमेरिकन विदेश नीति ने विश्व के आकार को कल्पनात्मीय एवं तीव्र गति से विस्तृत कर लिया। पश्चिमी यूरोप की साम्राज्यवादी एवं व्यापारिक शक्ति तथा शताब्दियों से विश्व में अपनी क्रियाओं को बढ़ाती जा रही थी किन्तु समुक्त राज्य ने दो दशान्दियों में ही अपने शान्तिकालीन उत्तरदायित्वों को यूरोप, मध्यपूर्व, दक्षिणी एशिया तथा अफ्रीका में बड़ा लिया। माइकेल डोनेलन (Michael Donelan) के शब्दों में युद्धोपरान्त अमेरिकन विदेश नीति का विषय 'गोलाड' सम्बन्धी मान्यताओं का समय विश्व के रूप में विस्तार कर लेना था। युद्धोत्तरकालीन अमेरिकन कार्यरत्नावली से स्पष्ट है कि युद्ध के बाद अमेरिका ने न केवल यूरोप के मामलों में सक्रियता ली है, बल्कि सुदूरपूर्व, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के मामलों में भी सक्रिय भाग लिया है।

महायुद्ध के बाद अमेरिकी विदेश नीति अनेक परिवर्तनों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर प्रकट होती रही है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका ने स्वयं को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। सुविधा की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अमेरिका के युद्धोत्तर स्वरूप को निम्नलिखित ५ भागों में बांटना अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी होगा—

- १ मधु-रात्रि का काल (The Honeymoon Period)—मई १९४५ से अगस्त १९४६ तक,
- २ नवीन दिशान्तेषण का काल (Period of New Departure)—अगस्त १९४६ से जून १९५० तक,
- ३ खुले मघर्ष का काल (Period of Open Conflict)—जून १९५० से जुलाई १९५३ तक,
- ४ नवीन दृष्टि का काल (Period of New Look)—जुलाई १९५३ से जनवरी १९६१ तक,
- ५ सह अस्तित्व का काल (Period of Co-existence)—जनवरी १९६१ के उपरान्त ।

मधु-रात्रि का काल (मई १९४५ से अगस्त १९४६ तक)

द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिका को लगभग एक डेढ़ वर्ष तक यह विश्वास बना रहा कि युद्ध काठ में अमेरिका और रूस की जिम मित्रता का विकास हुआ है, वह युद्धोत्तर शांतिकाल में भी बनी रहेगी। अमेरिका और रूस का युद्धकालीन सहोदर फरवरी १९४५ के याट्टा सम्मेलन में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था और तभी से सामान्यतः यह विश्वास किया जाने लगा था कि याट्टा की भावना युद्धोत्तर काल की भी अनुप्राणित करती रहेगी। इसी विश्वास के आधार पर अगस्त-जून १९४५ के मान-ग्लास्विरो सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र मघ का चार्टर तैयार किया गया तथा जुलाई-अगस्त में पोर्ट्म-डम सम्मेलन में जर्मनी व जपान से शांति-मघियों एवं भुक्तोत्तर व्यवस्थाओं के बारे में विभिन्न समझौते किये गये।

युद्धकालीन सहयोग और मैत्री की युद्ध के बाद इनकी सुमारी छापी रही कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'सहयोग और अनुकूलन की नीति' (Policy of Co-operation and Accommodation) का अनुसरण करते हुए युद्ध से विध्वस्त देशों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण का कार्य आरम्भ किया, अगु शांति के नियंत्रण की योजनाएँ बनायीं, यूरोप से जपान से जपान से सेनाओं को हटाया, चीन में साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों के मन्त्र समझौता कराने के प्रयास किये, जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों के साथ यथामन्य सीमातिनिष्ठ शांति संधियाँ करने का आग्रह और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। २८ अक्टूबर, १९४५ को तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रुमैन ने सहयोग और अनुकूलन की तत्कालीन अमेरिकन विदेशी नीति के 'बारह सूत्री

(Twelve Point) उद्देश्यों की घोषणा की। ये उद्देश्य सा- रूप में इस प्रकार थे—

(i) अमेरिका प्रादेशिक विस्तार अथवा स्वार्थपूर्ण लाभ नहीं चाहता, यह किसी छोटे या बड़े देश पर आक्रमण नहीं करेगा।

(ii) अमेरिका का मत है कि जिन देशों से सर्वोच्च प्रभुसत्ता के अधिकार बलपूर्वक छीने गये थे, वे उन्हें वापिस दिये जाने चाहिए।

(iii) अमेरिका किसी भी देश में स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवस्था की गयी जनता की सहमति के बिना दिये गये किसी प्रादेशिक परिवर्तन की स्वीकार नहीं करेगा।

(iv) अमेरिका का यह विश्वास है कि स्वशासन के लिए समर्थ और उद्यत देशों की विदेशी हस्तक्षेप के बिना अपने शासन का स्वरूप चुनने में स्वाधीनता होनी चाहिए। यह सिद्धान्त यूरोप, एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी गोलार्द्ध में समान रूप से लागू होता है।

(v) अमेरिका का लक्ष्य अपने साथियों के साथ सहयोग करत हुए पराजित देशों में शांतिपूर्ण लोकतन्त्रीय शासन स्थापित करना है।

(vi) संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी शक्ति द्वारा किसी देश में बलपूर्वक थोपी गयी सरकार की मान्यता प्रदान नहीं करेगा।

(vii) अनेक देशों में ये होकर गुजरने वाली नदियों में तथा समुद्रों में शान्तिपूर्ण निर्विघ्न स्वतन्त्रता सब देशों की होनी चाहिए।

(viii) विश्व में कच्चे माल की प्राप्ति तथा व्यापार में सब देशों की स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

(ix) अमेरिका का यह मत है कि पश्चिमी गोलार्द्ध के राज्यों को इस गोलार्द्ध के बाहर से किसी शक्ति के हस्तक्षेप के बिना, उत्तम पद्धतियों की भांति अपनी सामान्य समस्याओं का समाधान करना चाहिये।

(x) अमेरिका चाहता है कि समूचे विश्व में शान्ति को दूर करने तथा जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए सब देशों में पूर्ण आर्थिक सहयोग होना चाहिए।

(xi) संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अभिव्यक्ति तथा धर्म की स्वतन्त्रता की बढान के लिए प्रयत्न करेगा।

(xii) अमेरिका का यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्यों में शांति बनाये रखने के लिए ऐसे संयुक्त राष्ट्र सघ की आवश्यकता है, जिसके सदस्य शांति-प्रेमी हों, तथा शांति बनाये रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्य-वाही करने के लिए भी तैयार हों।

युद्धोत्तरकाल में, युद्धकाल की भांति ही, रूसी सहयोग के प्राप्ति होते रहने की अमेरिकन आशा इनकी बड़ी बड़ी थी कि अमेरिका ने अपनी सशस्त्र सहाय्य लगभग दो वर्ष के भीतर १ करोड़ २० लाख सैनिकों से घटा कर १५ लाख सैनिक कर दिये। परन्तु शीघ्र ही इस आशा का खोखलापन सिद्ध होने लगा। अनेक क्षत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए भी अमेरिका विश्व राजनीति में दो महत्वपूर्ण विकासों के प्रति चूक कर बैठा—सोवियत संघ की धानमणकारी चाल और एशिया महाद्वीप में शक्ति। लगभग सभी क्षेत्रों में शीघ्र ही यह प्रकट हो गया कि रूस एवं अमेरिका परस्पर एक दूसरे के पूर्ण विरोधी हैं और विश्व के प्रत्येक भाग की प्रत्येक सम्भव समस्या पर उन दोनों में मतभेद है। स्पष्टता की दृष्टि से यह कहना होगा कि विशेषतः ५ क्षेत्रों में उनके मतभेद विशेष रूप से उग्र हो गये—

(i) जर्मनी के समीकरण का प्रश्न,

(ii) पोलैण्ड में रूस द्वारा याल्टा सम्मेलन में दिये गये वचनों के उल्लंघन की अमेरिकी शिकायत,

(iii) इटली, हंगरी, रमानिया, बल्गेरिया तथा फिनलैण्ड के साथ शान्ति संधियों का प्रश्न,

(iv) संयुक्त राष्ट्र सत्र तथा उसमें रूस द्वारा निषेधाधिकार के प्रयोग का प्रश्न, तथा

(v) ईरान, टर्की और यूनान में रूसी महत्वाकांक्षाओं का प्रश्न।

इन सभी मतभेदों के कारण और अन्य विभिन्न असहमतियों के फलस्वरूप शनैः शनैः पश्चिम और पूर्व की युद्धकालीन अगोष्ठी मैत्री (Strange Alliance) एक 'शीतयुद्ध' (Cold War) में परिणतित हो गयी। रूस के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण से अमेरिका में आशावादी नेताओं को बड़ा धक्का लगा। एशिया महाद्वीप में जो शान्ति हो रही थी उसका साम्यवादी देशों ने लाभ उठाया तथा पश्चिम विरोधी, उपनिवेश विरोधी और साम्राज्य विरोधी भावनाओं का प्रचार कर यहां के देशों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तथा विश्व की नजरों में अमेरिका को प्रतिनिध्यावादी तथा पूँजीवादी बना दिया।

नयीन दिशावेषण का काल

(अगस्त १९४६ से जून १९५०)

१९४६ के मध्य तक "अगोष्ठी मैत्री" की असफलता अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक बड़ी यथार्थता बन गयी। साम्यवादी देशों के रूस को दसहस्त राष्ट्रपति रुजवेट और ट्रुमैन के प्रधान परामशदाता एथरिड हैरीमन

तथा विदेश विभाग के रुसी विशेषज्ञ जार्ज केनन (Kennan) ने क्रैमलिन के साथ सहयोग की नीति में सदेह प्रकट किया। रूस के साथ सहयोग करने की नीति को अविवेकपूर्ण बताया हुआ यह मत प्रकट किया गया कि 'रूस केवल हड़ता की नीति को ही समझ सकता है और उसी का सम्मान भी कर सकता है, किसी दूसरी नीति को तो वह दुर्बलता और निधिलता की ही निशानी समझता है।' दिसम्बर १९४६ में विदेश मंत्री बर्नार्ड एव अगले वर्ष उमरु उत्तराधिकारी विदेश मंत्री मार्शल भी मास्को के विदेश-मन्त्री-सम्मेलनों से ऐसे ही विचार लेकर लौटे। दोनों का यह विश्वास हो गया कि रूस के साथ सहयोग की नीति सफल होने की कोई संभावना नहीं है।

उपरोक्त अनुभूति होने के फलस्वरूप अमेरिकन विदेश नीति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए और उसे सहयोग की अपनी प्रारम्भिक नीति का परित्याग करना पड़ा। यह समझा जाने लगा कि रूस, चीन एवं पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है, अतः अमेरिका को सुरक्षित ही ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप से अविलम्ब 'अवरुद्ध' कर दिया जाय। इस प्रकार अमेरिका "सहयोग और आनुकूल्य" (Co-operation and Accommodation) की नीति के स्थान पर "अवरोध की नीति" (Policy of Containment) पर आया। सोवियत खुनीती के प्रति जागरूक होकर अमेरिका ने कठोर नीति को अपनाना आरम्भ किया किन्तु फिर भी राष्ट्रपति ट्रुमैन का मत इस धारणा में बना रहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मूल हित इसी बात में निहित हैं कि शांति बनायी रखी जाय ताकि विश्व ने सभी देश उत्पादन और पुनर्निर्माण के अपने मूल कार्यों की ओर लौट सके। उपराष्ट्रपति हेनरी वॉलेस (Henry Wallace) का विश्वास था कि सोवियत सत्र भयभीत है और परिचयी आक्रमण के विपक्ष आस्थातन चाहता है।

जो भी हो, साम्यवाद की संश्लिष्ट या अवरुद्ध करने की नीति राष्ट्रपति ट्रुमैन के युग में प्रारम्भ हो गई और इसकी निश्चित अभिव्यक्ति 'ट्रुमैन सिद्धांत' (Truman Doctrine) में हुई जिसकी पूर्ण आधिकारिक व्याख्या स्वयं राष्ट्रपति ट्रुमैन ने १२ मार्च, १९४७ को आने एक भाषण में कांग्रेस के समक्ष की।

ट्रुमैन सिद्धांत का विवरण देने से पूर्व उन तीन मुख्य घटनाओं को संक्षेप में जान लेना चाहिए जिनके वशीभूत होकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अमेरिका ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से यही प्रकट किया कि

यूनान, टर्की और ईरान पर बढ़ते हुए साम्यवादी दबाव के कारण ही “विपुल आर्थिक सहायता द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति” कार्यान्वित की गई। इन तीनों देशों की समस्याएँ इस प्रकार थी—

(क) यूनान की समस्या—यूनान में दो राजनीतिक दल थे—एक साम्यवादी समर्थक (E.A.M.) और दूसरा राजतन्त्रवादी (E.D.E.S.)। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश फौज ने यहाँ प्रवेश किया। अक्टूबर, १९४४ में एक समझौते के अनुसार रूस ने यूनान को ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र स्वीकार कर लिया। ब्रिटेन यूनान को अपने प्रभाव क्षेत्र में इसलिए रखना चाहता था कि उसके साम्राज्य के पूर्वी हिस्से को जाने वाला मार्ग सुरक्षित रह सके।

यूनान में प्रवेश के बाद ब्रिटेन ने यूनान के साम्यवादी दल (E.A.M.) का विरोध किया। इसके समर्थन से मार्च, १९४५ के चुनावों में राज-सत्ता-वादियों की विजय हुई और यूनान में राजतन्त्र की स्थापना हो गई। साम्यवादियों ने यूनानी सरकार के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। दिसम्बर, १९४६ में सुरक्षा परिषद् में यूनान में विद्रोही दलों को विदेशों से सहायता दिये जान की शिकायत पेश की। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोग की रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई।

इस समय ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति ऐसा नहीं थी कि वह अपनी सेना बढ़ा कर अकेला विद्रोहियों का मुकाबला करता। इसलिए ब्रिटेन ने घोषणा की कि बड़ा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ५ सप्ताह के भीतर अपनी फौजें यूनान से हटा लेगा। अमेरिका के सामने यह चिन्ता सही हो गई कि ब्रिटिश फौजों को हटते ही यूनान पूरी तरह साम्यवादी प्रभाव में चला जायेगा। राष्ट्रपति ट्रुमैन के सहायकों—एवगेन और मासेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा—“यदि यूनान ह्राय में निरल गया तो टर्की के टापू की रक्षा असम्भव हो जायेगी” (२६ फरवरी, १९४७)। फरवरी, १९४७ में निर्णय कर लिया कि यूनान को आर्थिक सहायता दी जाय।

(ख) टर्की की समस्या—महायुद्ध के बाद भूमध्य सागर और कृष्ण सागर का जोड़ने वाली बासबोरस और दरदनियाल जल-डमरू मध्य पर जो टर्की के अधिकार में था, सोवियत रूस कब्जा करना चाहता था। इस क्षेत्र पर कौन से बड़े बृहत् सागर के तटवर्ती देशों का व्यापार दमद कर सकता था और कृष्ण सागर एवं भूमध्य सागर से नौसैनिक आक्रमण भी कर सकता था। अतः ७ अगस्त, १९४६ को रूस ने टर्की के समक्ष जल-डमरू-मध्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किये—

(१) वे युद्ध और शान्तिकाल में सब देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए खुले रहेंगे।

(२) कृष्ण सागर की शक्तियों के युद्ध पोतों के लिए वे सदैव खुले रहेंगे।

(३) विदेश अवस्थाओं को छोड़ कर कृष्ण सागर में भिन्न शक्तियों के युद्धपोत इनमें से गुजरें।

(४) इनका शासन प्रबन्ध टर्की व कृष्ण सागर की अन्य सभी शक्तियों के हाथ में हो, तथा

(५) इनकी रक्षा टर्की और रूस दोनों के सामान्य साधनों से हो।

काफ़ी भारोपों प्रत्यारोपों के बाद और अन्त में वाशिंगटन की मलाह के आधार पर टर्की ने मास्को के सभी प्रस्तावों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। साथ ही अमेरिका ने भी रूस को चेतावनी दे दी कि यदि टर्की पर आक्रमण किया गया तो मामला सुरक्षा परिषद में उठाया जायेगा। टर्की ने भी अपनी सुरक्षात्मक तैयारियाँ आरम्भ कर दी। चूँकि आवश्यक सैन्य शक्ति जुटाने के लिए उसके पास समुचित आर्थिक साधन न थे, अतः उसने अमेरिका से सहायता की प्रार्थना की और राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यूनान की भाँति टर्की को भी सहायता देने का निश्चय कर लिया।

(ग) ईरान की समस्या—द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन और रूस की सेनायें अफगानिस्तान, उत्तरी यूनान और दक्षिणी यूनान में प्रवेश कर गईं। जर्मनी के पराजित होने के बाद २ मार्च, १९४६ के दिन ईरानी क्षेत्रों में सभी सेनाओं का हट जाना निश्चित हुआ। वस्तुस्थितियों से रूस ने ईरानी क्षेत्र से हटना अस्वीकार कर दिया। सुरक्षा परिषद के प्रयासों का कोई फल नहीं निकला। अन्त में अप्रैल, १९४६ में रूस और ईरान के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार मई, १९४६ में रूसी फौजें ईरान से हट गईं। ईरान में घटी इस घटना से राष्ट्रपति ट्रूमैन को रूसी महत्वानाक्षाओं के बारे में कोई सन्देह नहीं रहा।

टर्की, यूनान और ईरान की घटनाओं के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने निश्चय कर लिया कि मध्य-पूर्वी क्षेत्र में रूस की शिष्टता देने के लिए इन देशों की सहायता देने की नीति पर चला जाय। यह नीति उस समय के राष्ट्रपति ट्रूमैन के नाम पर 'ट्रूमैन विधान' (Truman Doctrine) कहलाती है।

ट्रूमैन विधान

(Truman Doctrine)

मार्च १९४७ को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपने मन्त्रिमण्डल को बैठक में

बताया कि उन्होंने कांग्रेस से यह सिफारिश की है कि यूनान को २५ करोड़ डॉलर की तथा टर्की को १५ करोड़ डॉलर की सहायता दी जाय। १२ मार्च, १९४७ को कांग्रेस स राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अपील की कि साम्यवाद का प्रसार रोकने के लिए यूनान और टर्की को आर्थिक सहायता स्वीकार की जाय। उन्होंने घोषणा की कि स्वतन्त्र देशों की बाह्य प्रभाव से रक्षा करना समुक्त राज्य की नीति होनी चाहिए। श्री ट्रूमैन की इस ऐतिहासिक भाषण की, जिसमें 'ट्रूमैन सिद्धांत' की धारणा निहित है, मुख्य बातें इस प्रकार थी—

'आज यूनान राज्य की सत्ता सिकट में है। इसका कारण कम्युनिस्टों के, सरकार को चुनौती देने वाले कई हजार सशस्त्र व्यक्तिमों के आतंकवादी कार्य हैं। यूनान सरकार इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ है। उसको सहायता की आवश्यकता है, समुक्त राज्य अमेरिका को उसे सहायता देनी चाहिए। टर्की की भी यही स्थिति है, अभी हाल में दुनिया के कई देशों ने सर्वाधिकारवादी शासन बहा की जनता की इच्छा के विरुद्ध स्थापित कर दिये गये हैं। समुक्त राज्य अमेरिका ने पान्टा समझौते को भंग करते हुए पोलैंड, रूमानिया, बल्गेरिया में धमकी और दबाव से स्थापित शासनों के विरुद्ध प्रतिवाद किया है।

मेरा विश्वास है कि समुक्त राज्य अमेरिका की यह नीति होनी चाहिए कि वह बाह्य दबाव से या सशस्त्र अल्प सख्या द्वारा स्थापित किये जाने वाले शासनों का प्रतिरोध करने वाली स्वतन्त्र जनताओं का समर्थन करे। मेरा विश्वास है कि हमें स्वतन्त्र जनताओं को अपने तरीके से अपना भाग्य निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि हमारी सहायता प्रधानतः आर्थिक और वित्तीय सहायता के द्वारा होनी चाहिए, जो कि आर्थिक स्थायित्व और मुख्यस्थित राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए अनिवार्य है। यदि यूनान सशस्त्र अल्पसंख्या के हाथ में आ जाता है तो इसका उत्कांक्षित और भीषण प्रभाव हमारे पड़ोसों पर पड़ेगा। समस्त मध्य-पूर्व में गड़बड़ और अव्यवस्था का साम्राज्य हो जायगा। इसका प्रभाव यूरोप में स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने वाली जनता पर पड़ेगा। स्वतन्त्र संस्थाओं का विध्वंस और स्वाधीनता का अपहरण न केवल उनके लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए घातक होगा।

सर्वाधिकारवादी शासनों के बीज दुःख और दरिद्रता में पनपने हैं। उनका विनाश और वृद्धि निर्धनता तथा संघर्ष में होता है। जब जनता में उत्कृष्ट जीवन के लिए आशा नष्ट हो जाती है तो इसका पूर्ण विनाश होता है, हमें यह आशा नष्ट नहीं होने देनी चाहिए।

जगत की स्वतन्त्र जनता अपनी अपनी स्वाधीनता बनाये रखने के लिए हमारी ओर निहार रही है। यदि हमने नैतृत्व में चूक की तो समस्त विश्व की शान्ति रुकट में पड़ जायगी। हम अपने राष्ट्र के कल्याण को संकटपूर्ण बना देगे। समय तथा परिस्थिति के परिवर्तन के कारण हमारे ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस उन समस्त उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से निभायेगी।”

मई के प्रारम्भ में अमेरिकन कांग्रेस ने यूनान और टर्की को ४० करोड़ डालर की सहायता देने का राष्ट्रपति ट्रूमैन का बिल स्वीकार कर लिया और इस पर २९ मई, १९४८ को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गये।

‘ट्रूमैन सिद्धान्त’ के अन्तर्गत प्राप्त विपुल सहायता के चल पर १९५० के अन्त तक यूनान और टर्की ने साम्यवादी दबाव से सफलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर ली। वास्तव में ट्रूमैन सिद्धान्त ने अमेरिकन वैदेशिक नीति के इतिहास में असाधारण महत्व के कीर्ति-स्तम्भ की स्थापना की। जिन दृष्टियों अथवा कारणों से इसका इतना महत्व है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं—

(i) यह अमेरिकन विदेश नीति में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और अमेरिकन परम्पराओं में मौलिक शान्ति का प्रणेता था। इस सिद्धान्त के मान्य होने के समय से ही विश्व की यह ज्ञात हो गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अब घृण्यतावादी नीति का परित्याग करके संपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत की समस्याओं के सम्बन्ध में सक्रिय बनता जा रहा है।

(ii) ट्रूमैन के ‘सर्वाधिकारवादी’ और “स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले राज्य” भाषि शब्द निःसन्देह रूप में उस को एक स्पष्ट चेतावनी थी, उस के साथ शीत युद्ध की घोषणा थी और रजिमेंट की मास्को के साथ सहयोग करने वाली नीति का परित्याग था।

(iii) ट्रूमैन सिद्धान्त ‘अवरोध’ की नीति में विकास का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण था। यह सोवियत रूस को स्पष्ट संकेत था कि उसकी अपने प्रभाव का विस्तार करने की महत्वाकांक्षाओं को सहन नहीं किया जायगा।

(iv) ट्रूमैन सिद्धान्त से अमेरिका की यह धारणा पुष्ट हो गई कि विश्व की विचारधारा दो मार्गों में विभक्त है—एक तो स्वतन्त्रता का अपहरण करने वाले राष्ट्रों की विचारधारा और दूसरी ‘उत्तरी रक्षा करने वाली विचारधारा’। ट्रूमैन के अनुसार उस पहली विचारधारा का प्रवर्तक या जबकि अमेरिका दूसरी का।

(v) यह सिद्धान्त 'मुनरो सिद्धान्त' का बृहत् और विद्वद्भाषी रूप था। मुनरो सिद्धान्त में वाशिंगटन ने घोषणा की थी कि पश्चिमी गोलार्द्ध के किसी राज्य में अमेरिका से बाहर की कोई शक्ति हस्तक्षेप न करे। इसी नीति को व्यापक बनाते हुए ट्रूमैन सिद्धान्त में कहा गया था कि अमेरिका द्वारा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्द्ध में स्वतन्त्रता की आकांक्षी जनता को उसके स्वाधीनता सघर्ष में सहायता दी जायगी।

(vi) ट्रूमैन सिद्धान्त इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकृति थी कि ब्रिटेन अपनी आर्थिक दुर्बलता के कारण पूर्वी भूमध्यसागर और मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बनाये रखने में असमर्थ है अतः ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुए 'शक्तिशून्य' का साम्यवादी रुझान द्वारा लाभ उठाये जाने से पूर्व अमेरिका द्वारा लाभ उठा लिया जाना चाहिए।

(vii) टर्की और यूनान को 'स्वतन्त्रता की रक्षा' के नाम पर सहायता देना अमेरिकन वास्तविक उद्देश्यों को मनमोहक शब्दों के जाल में छिपाना था। ट्रूमैन सिद्धान्त का मूल उद्देश्य तो यूनान एवं टर्की को, बाल्कन प्रायद्वीप में रूसी अधिकार को रोकने के लिए और साथ ही रूस को घेरने के लिए मटत्वपूर्ण सैनिक अड्डे के रूप में सुरक्षित रखना तथा मध्य पूर्व के विशाल तेल गण्डार को अपने अधिकार में बनाये रखना था।

(viii) ट्रूमैन सिद्धान्त से यह स्पष्ट होता है कि समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन रूस के प्रति अपने मन मुटाव, घृणा, वैमनस्य, अविश्वास आदि के परिणामस्वरूप ही किया गया था। ट्रूमैन सिद्धान्त रूस के प्रति अमेरिकन वैमनस्य की स्थूल अभिव्यक्ति थी।

ट्रूमैन सिद्धान्त को जहाँ इतना असाधारण महत्त्व मिला है वहाँ अनेक दिसाओं से इसे बटु आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा—

प्रथम, साम्यवादियों ने अमेरिका की आर्थिक और सामरिक सहायता देने की नीति को साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का एक नवीन रूप बताया। सोवियत संघ ने आराध लगाया कि अमरीका मध्य पूर्व के अल्प विकसित देशों की आर्थिक कठिनाइयों का अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाता है, "सहायता के नाम पर इन देशों के साथ ऐसे समझौते होते हैं जिनसे अमरीकन अर्थ-व्यवस्था इन पर हावी हो जाती है। वह इन देशों के कच्चे माल पर अधिकार कर लेता है, नैतिक अड्डों और सामरिक महत्त्व के मार्गों को अपने बाबू में कर लेता है।"

दूमरे, इस सिद्धान्त को सर्वाधिकारवाद के निरुद्ध लोकतन्त्र का रक्षक कहना विश्व की भ्रम में डालना है क्योंकि यूनान अथवा टर्की को इस सिद्धान्त

की आठ में जब सहायता दी गई तो दोनों में से एक का भी शासन लोक-
तान्त्रिक नहीं था। इस सिद्धांत का उद्देश्य तो पश्चिमी और मध्य एशिया के
ऐसे मण्डलों की रूसी प्रभाव से बचाना था।

तीसरे, इस सिद्धांत से संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थिति दुर्बल हो गई क्योंकि
यूनान और टर्की को संयुक्त राष्ट्रसंघ के माध्यम से नहीं, बल्कि पृथक् रूप से
सहायता प्रदान की गई।

चौथे, स्वयं अमेरिकनो की दृष्टि में दूरगम सिद्धांत मुनरो सिद्धांत का
ही विस्तृत रूप है।

युद्धोपरान्त की प्रारम्भिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के फल-
स्वरूप अब यह भली-भांति स्पष्ट हो गया कि अमेरिकन विदेश नीति का
मौलिक उद्देश्य साम्यवाद और सोवियत प्रसार को रोकना बन गया। इस
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने अपनी विदेश नीति में तीन तत्वों को स्थापित
दिया—प्रथम, आर्थिक, द्वितीय राजनीतिक, एवं तृतीय सैनिक। आर्थिक तत्व
में आर्थिक सहायता और आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम अपनाये गये, राज-
नीतिक नीति को सम्पादित करने के लिए पश्चिमी यूरोपियन संघ की स्थापना
की दिशा में आगे बढ़ा गया और सैनिक नीति के अन्तर्गत सैन्य संगठनों की
स्थापना पर बल दिया जाने लगा।

मार्शल योजना

(Marshall Plan)

“अवरोध” की नीति (Policy of Containment) का दूसरा
धरण मार्शल योजना थी जिसका उद्देश्य युद्ध विध्वस्त यूरोप का आर्थिक
पुनर्निर्माण करके उसे साम्यवाद से बचाना था। यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण
आले अगले एक अध्याय में इस योजना पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है।
यहां इतना ही लिखना पर्याप्त है कि मार्शल योजना सभ सामयिक कूटनीतिक
दतिहस की सर्वाधिक दिलचस्प और युग-प्रवर्तक घटनाओं में से एक थी जिससे
रूस और पश्चिम का विरोध पहले की अपेक्षा और भी अधिक उग्र हुआ।
इस योजना के अन्तर्गत चार वर्षों (१९४७-१९५१) में अमेरिका ने यूरोप
को लगभग ११ मिलियन डॉलर की सहायता दी। इस योजना के बल पर एक
ओर तो पश्चिमी यूरोप आर्थिक वृद्धि और साम्यवाद आधिपत्य से बच गया
तथा दूसरे ओर संयुक्त राज्य अमेरिका पाश्चात्य जगत का सर्वमान्य नेता बन
गया। अमेरिका ने यूरोपीयन देशों की आर्थिक सहायता देते हुए यह सर्व
समाई कि वे अपनी सरकारों में साम्यवादी तत्वों का उन्मूलन करेंगे। १९४६-
४७ तक ढोच शासन में साम्यवादी थे, लेकिन १९४८ में जब ब्लूम फास के

लिए ऋण प्राप्त करने हेतु वांछित न गया तो उस पर दबाव डाला गया कि ऋण प्राप्ति के लिए फ्रेंच सरकार से साम्यवादियों का निवाला जाना आवश्यक है। इसी प्रकार इटली में मार्शल सहायता पाने वाली सरकार को मन्त्री-मण्डल में से साम्यवादियों को निकालना पड़ा।

मार्शल योजना एक प्रकार से ट्रुमैन सिद्धान्त का एक ही चित्रित रूप थी। इसने ट्रुमैन सिद्धान्त में प्रतिपादित अवरोध की नीति को तीन प्रकार से आगे बढ़ाया—

(१) ट्रुमैन सिद्धान्त में अलग अलग राज्यों की सहायता देने की व्यवस्था की गई थी, मार्शल योजना में यूरोप को समग्र रूप से सहायता देने की व्यवस्था की गई।

(२) मार्शल योजना की 'अवरोध की नीति' में आर्थिक तत्वों के महत्त्व को मंजूर प्रकार स्पष्ट कर दिया गया।

(३) इसके द्वारा पहली बार अमेरिकन आर्थिक सहायता की एक सहयोगी एवं योजना बद्ध रूप दिया गया।

यह बतलानेवाला है कि आर्थिक स्तर पर साम्यवाद के अवरोध की नीति के अनुसार अमेरिका ने जर्मन अर्थव्यवस्था को भी पुनर्गठित करने का प्रयास किया। जून, १९४८ में पश्चिमी शक्तियों द्वारा जर्मनी के अपने क्षेत्रों में उन्होंने कुछ मुद्रा सम्बन्धी सुधार किये, जिसके विरोध में रूस द्वारा बर्लिन की 'कुत्खात नाकेबन्दी' की गयी जो अतत असफल सिद्ध हुई। पश्चिमी शक्तियों के मोद्रिक सुधारों और बर्लिन संकट पर उनकी हठता ने जर्मन जनता को यह विश्वास दिला दिया कि पश्चिमी शक्तियां उनके हितों की रक्षा करने के लिए उत्सुक और समर्थ हैं।

चार सूत्री कार्यक्रम

(Four Point Programme)

मार्शल योजना का उद्देश्य केवल यूरोप की आर्थिक अस्त-व्यवस्था को पुनः दृढ़ करना था, लेकिन चीन में साम्यवादियों की महान् विजय से अमेरिकन और अन्य पश्चिमी राजनवा हम दाज में चिन्तित हो गये कि विश्व के अल्प विकसित देश साम्यवादी प्रसार के उत्तम क्षेत्र सिद्ध हो सकते हैं। अतः राष्ट्रपति ट्रुमैन ने, ऐसे प्रदेशों में साम्यवादी प्रसार का अवरोध के लिए, अमेरिकन विदेश नीति का 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा करत हुए २० जनवरी, १९४९ का कृता कि—

“आगामी वर्षों में शांति और स्थिरता का वायनम में चार प्रधान बातों पर बल दिया जायेगा—

- (i) संयुक्त राष्ट्रमण्डल का पूर्ण समर्थन,
- (ii) विश्व के आर्थिक पुनरुत्थार के कार्य को करते रहना,
- (iii) आत्मरक्षण के विरुद्ध स्वतन्त्रता प्रेमी राष्ट्रों का सुदृढ़ बनाना, एवं
- (iv) अल्पविकसित देशों के उत्थान के लिए प्राविधिक (Technical) सहायता देना ।¹

कांग्रेस ने १९५० के 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास अधिनियम' (Act for International Development) के द्वारा इस कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया । रिचर्ड स्टीबिन्स (Richard P. Stebbins) के शब्दों में "यह कानून अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था ।"² इस योजना द्वारा प्रथम बार तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता धीरे-धीरे बढ़ने लगी क्योंकि अर्ध-विकसित देशों की आवश्यकताएँ बहुत अधिक थी तथा अमेरिका के राष्ट्रीय हित की इसके द्वारा साधना होती थी । आलोचकों द्वारा चार सूत्री कार्यक्रम को कीतपुष्ट का ही एक अस्त्र माना गया और कहा गया कि यह अर्ध-विकसित देशों का समर्थन प्राप्त करने तथा उनसे आवश्यक रणनीति का सामान प्राप्त करने का एक तरीका है न कि अर्ध-विकसित देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर अपने पावों पर सटे होने तथा अन्य स्वतन्त्र देशों के साथ अपना सामान्य सम्बन्ध बनाने की सुविधा देने का प्रयास ।

नाटो अवरोध की रण विधि

(NATO . The Strategy of Containment)

राजनीतिक तथा आर्थिक स्तर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैनिक स्तर पर भी साम्यवादी प्रसार के अवरोध का प्रयत्न किया । उसने दूसरे देशों के साथ सैनिक रुद्धि और पारस्परिक प्रतिरक्षा महासन्धि कार्यक्रम (Mutual Defence Assistance Programme) का तरीका प्रारम्भ किया जो अमेरिकन विदेश नीति का एक नवीन प्रयोग था । वैसे इस दिशा में प्रथम पण १७ मार्च, १९४८ की ब्रुसेल्स सन्धि थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लक्जमबर्ग ने यूरोप से सशस्त्र आक्रमण होने की दिशा में परस्पर सहायता देने का वचन दिया । किन्तु यह सन्धि, वस्तु स्थिति का दृष्टि से, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की वचनबद्ध सशस्त्र सहायता के अभाव में कुछ भी प्रभावशाली नहीं थी । अतः सैनिक अवरोध की व्यवस्था को विशेष प्रभावशाली बनाने के लिए अमेरिका द्वारा

1. Richard P. Stebbins, The U. S. in World Affairs, 1950 P. 96.

नाटो का आयोजन किया गया और ४ अप्रैल, १९४९ को यह प्रथम सैनिक सन्धि समुक्त राज्य, कनाडा, इटली, आइसलैंड, नार्वे, डेनमार्क और पुर्तगाल के बीच हो गई। यह उत्तरी अटलांटिक संधि अनेक तरह से एक 'नवाचार' (Innovation) थी। यह प्रथम सन्धि थी जिसके प्रति अमेरिका ने स्वयं को बचनबद्ध किया। इसी के साथ यूरोपीयन देशों की रणशक्ति बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा कार्यक्रम भी अपनाया गया।

समुक्त राज्य अमेरिका को तेजी से सैनिक सधियों के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी एक और महत्वपूर्ण घटना यह थी कि सोवियत रूस ने १९४९ में ही एटम बम (Atom Bomb) के रहस्यों को खोज निकाला था जिन्हें कि समुक्त राज्य अमेरिका ने सावधान रूस से सर्वथा गुप्त रखा था। रूस की खोज से अणुबम पर समुक्त राज्य अमेरिका का अणुशक्ति पर एकाधिकार (Monopoly) का अन्त हो गया और उसकी सर्वोच्च शक्ति को खतरा पैदा हो गया। इस घटना के परिणामस्वरूप अमेरिका के लिए साम्यवाद का आतंक बढ़ गया। इसलिए समुक्त राज्य अमेरिका ने कोरिया (Korea) में साम्यवाद के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का भी नेतृत्व किया।

खुले संघर्ष का काल

(जून १९५० से जुलाई १९५३)

वास्तव में साम्यवाद का खतरा ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा था, अमेरिकन प्रतिक्रिया उसी के अनुरूप हो रही थी और इसी प्रतिक्रिया का एक स्वरूप यह था कि समुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण सैनिक सधियों व प्रतिरक्षा संगठनों की स्थापना की दिशा में झुका। जून १९५० में दक्षिणी कोरिया पर उत्तरी कोरिया का आक्रमण हो जाने से, जिसमें समुक्त राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत अमेरिकन सेनाओं ने लगभग पूर्ण युद्ध किया, अमेरिकन विदेश नीति में सैनिक शक्ति का महत्व दृढ़ीकृत हो गया। श्लेचर (Schleicher) महोदय के शब्दों में "अमेरिकी सैनिक शक्ति के लिए विनियोग तिगुने से भी अधिक हो गया, यूरोप को दिये जाने वाले सहयोग में सैनिक शक्ति पर जोर दिया जाने लगा, तथा मार्शल योजना की मदद 'सुरक्षा समर्पण की मदद' बन गयी।"¹

कोरिया युद्ध जून, १९५० से जुलाई १९५३ तक चला और यह अवधि चीन युद्ध की जगह खुले संघर्ष अवस्था सन्धि युद्ध की रही। इसलिए अमेरिकन युद्धोत्तर वैदेशिक नीति व इतिहास में यह एक प्रकार का 'खुले संघर्ष का काल' (Period of Open Conflict) रहा। इस अवधि में, अवरोध नीति के राजनीतिक और आर्थिक पक्ष की अपेक्षा सैनिक पक्ष को विशेष -

महत्व देते हुए ३० अगस्त, १९५१ को अमेरिका ने फिलिपाइन्स के साथ एक प्रतिरक्षा समझौता किया, १ सितम्बर १९५१ को आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के साथ एन्जस समझौता किया और इसी तरह ८ सितम्बर, १९५१ को जापान के साथ एक प्रतिरक्षा समझौता सम्पन्न हुआ।

स्पष्ट है कि अमेरिकन प्रशासन में सैनिक सन्तति के उपयोग एवं सैनिक तथा प्रतिरक्षा समझौतों ने महत्व की विचारधारा बलवती हुई। इस तरह अमेरिका अपनी विदेशी नीति में अब आर्थिक और सैनिक दोनों ही तत्वों को प्रधानता देने लगा। ये दोनों ही तत्व आज भी अमेरिकन विदेशी नीति के प्रधान अंग बने हुए हैं और यदि देखा जाय तो द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद के कुछ काल को छोड़कर अमेरिकन विदेश नीति का अब तक सम्पूर्ण इतिहास इन दोनों तत्वों की प्रधानता ग्रहण किये हुए है।

नवीन दृष्टि का काल

(जुलाई १९५३ से जनवरी १९६१ तक)

जनवरी १९५३ में २४ वर्षों में प्रथम बार एक रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में जनरल आइजन होवर ने ह्वाइट हाउस में प्रवेश किया। उन्होंने अपने निर्वाचन अभियान में कोरिया युद्ध की समाप्ति करने का वचन दिया था और जुलाई १९५३ में कोरिया युद्ध समाप्त हो गया। इसके पूर्व ही मार्च, १९५३ में रूस के कठोर और लोह पुरुष स्टालिन की मृत्यु हो चुकी थी। १९५३ के वर्ष की इन सब घटनाओं के सम्मिलित परिणामस्वरूप शीतयुद्ध की गर्मी में कुछ समय के लिए कमी आई, अमेरिकन विदेश नीति में इस स्थिति से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा।

वई कारणों से अमेरिका की इस नवीन सरकार, नवीन राष्ट्राध्यक्ष और नवीन सचिव के प्रति लोग सदेह भरी दृष्टि से, देखते हुए आशंका कर रहे थे कि संभवतः वे अपने पहले कालों से अधिक सैनिकवादी एवं युद्ध-प्रिय रहेंगे। किन्तु जेम्स वि. पामर तथा परकिन्स (Palmer and Perkins) का कहना है, कि आइजन होवर ने किसी विदेश नीति की रूपरेखा नहीं रखी बल्कि 'कुछ निश्चित सिद्धान्त' रखे जो उनके प्रशासन का संरक्षण करने का थे।^१ विदेश नीति के सिद्धान्त मुख्य रूप से इस प्रकार थे—युद्ध का दहिप्रार, अमेरिकन शक्ति का विकास दूसरे देशों के साथ सहयोग की इच्छा, सुप्रीमरी का अभाव, अमेरिकन शक्ति का दुरुपयोग नहीं, दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए समर्थन, विश्व के उत्पादन तथा साम पूर्ण

1. Palmer and Perkins, op. cit. P. 710.

व्यापार को प्रोत्साहन देना, समुक्त राष्ट्र सत्र के प्रति भक्ति भावना, पश्चिमी गोलार्द्ध के देशों के साथ सहयोग, यूरोपीय एकता को बढ़ावा देना, सभी लोगों एवं जातियों को समानता तथा समुक्त राज्य को शान्ति के लिए एक प्रभावशाली शक्ति बना देना ।

वाम्पक्ष में रुस द्वारा परमाणु बम के निर्माण, विपुल अमेरिकन सहायता व बावजूद चीन में साम्यवाद की विजय और सबसे बाद में कोरिया व युद्ध में समुक्त राज्य अमेरिका की अरती विदेश नीति पर एक नई दृष्टि (New look) डालने पर विचार कर दिया । अतः रुस के साथ सहयोग के साथ ही अमेरिका का इच्छा व्यक्त की कि अमेरिका के स्वीकार करना आवश्यक हो गया । साम्यवादी चीन की बढ़ती हुई शक्ति ने भी यह जता दिया कि रुस का अवरोधन केवल यूरोप में नहीं सुदूर पूर्व में भी किया जाना आवश्यक है । फिर कोरिया युद्ध से यह आशंका और भी दृढ़ हो गई कि यूरोप और पूर्वी एशिया में अवरोध हो जाने के बाद रुस मध्यपूर्व में बढ़ने का प्रयत्न करेगा । इस आशंका के फलस्वरूप मध्यपूर्व का प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका की दिलचस्पी का प्रधान केन्द्र बन गया ।

राष्ट्रपति आइज़नहोवर के शासन काल में घटना चक्र कुछ ऐसा घूमता कि जिससे शीत युद्ध में कुछ समय के लिए स्थिरता आ गई और अन्तर्राष्ट्रीय मनमुटाव मिटने की आशाओं की जाने लगी । मार्च १९५३ में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में आया उन्होंने भी पूर्वाशा कुछ खोती और समझौतापूर्ण नीतियाँ अपनायीं चाहे । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति में कुछ सुधार हुआ । १६ अगस्त, १९५३ को राष्ट्रपति आइज़नहोवर ने यात्रा के पक्ष में दा दशैंल दी जिन्हें सुन कर लोगों का यह भ्रम बहुत कुछ दूर हो गया कि यह सैनिक जनरल अमेरिका की पूरी तरह से निष्ठा की ओर दृष्टि देता । ११ मई को पब्लिक द्वारा फ्राम, ब्रिटन, रुस और अमेरिका का सितार सम्मेलन बुलाया गया । पश्चिमी यूरोप की अधिष्ठापिका एकीकृत करने के प्रयत्न किये गये । जुलाई १९५३ में ३ साल में भी अधिष्ठापक समय में चलने वाला कालिबर्न युद्ध बन्द हो गया । अगस्त में सोवियत रुस ने घोषणा की कि उनका आइज़नहोवर बम का विपणन कर लिया है । इसके तुरन्त बाद दिसम्बर में समुक्त राष्ट्र सत्र की महासभा में आइज़नहोवर ने अणु शक्ति पर नियंत्रण रखने और उनका शान्ति के लिये उपयोग करने का प्रस्ताव रखा ।

सन् १९५४ में इस अधिष्ठापक सम्मेलन हुए कि जॉन फोस्टर डलैस की यात्री राज्य सचिव की संज्ञा दी जाने लगी । पश्चिमी यूरोप की एकीकृत

वरने के बयानों के फलस्वरूप इसी वर्ष पश्चिमी यूरोपियन संघ (Western European Union) की स्थापना की गई और जर्मनी को नाटो का सदस्य बना लिया गया। १९५४ में ही साम्यवादी चीन की सहायता से साम्यवादी छाप मारो द्वारा हिन्द चीन में गम्भीर स्थिति उत्पन्न कर दी गई जिसके फलस्वरूप जुलाई में हिन्द चीन, फ्रांस, साम्यवादी चीन, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने जेनवा सम्मेलन में हिन्द चीन को विभाजित करने का निर्णय लिया। इसके उत्तरी भाग में वियतमिन्ह (बाद में उत्तरी वियतनाम) का साम्यवादी राज्य स्थापन किया गया और दक्षिणी भाग को लाओस, कम्बोडिया तथा दक्षिणी वियतनाम के तीन गैर-साम्यवादी राज्यों में विभाजित कर दिया गया। इस घटना-वक्र ने संयुक्त राज्य अमेरिका को साम्यवादी चीनी प्रसार को अवरोध करने के लिए कृत-संकल्प बना दिया, और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सितम्बर १९५४ में थाइलैंड, फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, ब्रिटेन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के साथ 'दक्षिणी-पूर्वी एशिया सामूहिक सुरक्षा संधि' (South East Asia Collective Defence Treaty) पर हस्ताक्षर करके सोटा (SEATO) की स्थापना की गई।

मध्यपूर्व आइजनहोवर सिद्धान्त

(Middle East Eisenhower Doctrine)

यूरोप और सुदूरपूर्व में साम्यवादी प्रसार के अवरोध के लिए सैन्य समर्थन व प्रशिक्षण संधियों आदि की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य-पूर्व की ओर मुड़ा। इस क्षेत्र में साम्यवाद के प्रसार पर अकुशल लगाने के लिए आइजनहोवर प्रशामन न टर्की, ईरान, पाकिस्तान और ब्रिटेन आदि की प्रेरित वर के १९५६ में बगदाद पॅक्ट (जिसे १९५६ में सेप्टो कहा जाने लगा) की रचना कराई। यद्यपि मध्यपूर्व में अमेरिका का यह प्रयास प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुआ परन्तु इस क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने का उसे एक अन्य सुत्रवस्तर मिल गया। हुआ यह कि १९५६ में स्वेज नहर के प्रश्न को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल ने संयुक्त रूप से मिस्र पर आक्रमण कर दिया। सीमासम्बन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को इस कार्य-वाही को अपना समर्थन प्रदान नहुा किया प्र त्रु उ-हैं यही इजरायल को दिया कि वे अपना आक्रमण खत्म कर दें। अन्य में, अमेरिका सहित विश्व-जनमत के विरोध पर, विदेशी जायागताओं को स्वेज से हटना पड़ा। स्वेज वाद में पराजय का परिणाम यह निकला कि एक लम्बे समय में मध्यपूर्व की राजनीति पर नियंत्रण करने वाले ब्रिटेन और फ्रांस इस क्षेत्र में अपना प्रभाव खो बैठे और मध्यपूर्व में इस क्षेत्र की शून्यता से यह आसता ही गई कि रूस इस क्षेत्र में

अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा। इन समारंभों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में कूद पड़ा। उसने यहाँ शांति बनाये रखने तथा साम्यवादियों का प्रसार रोकने के लिए सुप्रसिद्ध 'आइजनहावर सिद्धान्त' प्रतिपादित किया।

"आइजनहावर सिद्धान्त" की घोषणा ५ जनवरी, १९५७ को राष्ट्रपति आइजनहावर द्वारा कांग्रेस को भेजे गये एक संदेश में की गयी। यह संदेश मध्यपूर्व के सम्बन्ध में अमेरिका की नीति की घोषणा थी। इस संदेश के अनुसार कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा मधुक्क रूप में पास किये गये कानून पर राष्ट्रपति ने ६ मार्च १९५७ को हस्ताक्षर कर दिये। इस कानून के अन्तर्गत राष्ट्रपति को मध्यपूर्व के किसी भी देश में अपनी विवेक बुद्धि से साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए कौजें भेजने तथा सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार मिल गया।

कांग्रेस ने आइजनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकन सहायता के इच्छुक मध्यपूर्व के देशों की सहायता के लिए २०० मिलियन डालर की धनराशि की स्वीकृति दी।

आइजनहावर सिद्धान्त की प्रतिक्रियाएँ और सिद्धान्त का विश्लेषण—आइजनहावर सिद्धान्त और कानून की प्रतिक्रियाएँ मिश्रित हुईं। मध्यपूर्व में जोर्डन, लेबनान, ईरान, ईराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान आदि ने इसका स्वागत किया। परन्तु मिस्र और सीरिया आदि ने इसे एक साम्राज्यवादी चाल बताया। सोवियत रूस ने इसका घोर विरोध करते हुए इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की आक्रामक नीति की शृंखला की एक और कड़ी कहा। स्वर्गीय श्री नेहरू ने शक्ति शून्य के सिद्धान्त की आलोचना करते हुए कहा—“यदि पश्चिमी एशिया में एक शून्य है तो यह स्वयं उस क्षेत्र के देशों के द्वारा भरा जाना चाहिए। यदि दूसरे गोल आने का प्रयत्न करते हैं तो विपत्ति प्रारम्भ हो जाती है और सुरक्षा के स्थान पर हम उसका उल्टा पाने हैं।”

आइजनहावर सिद्धान्त का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह सिद्धान्त स्पष्ट, दृढ़ सिद्धान्त का एक विकसित रूप था—

प्रथम, दृढ़ सिद्धान्त में सहायता का क्षेत्र विस्तृत गुनिश्चित—टर्की और यूनान था, जबकि आइजनहावर सिद्धान्त के अन्तर्गत अमेरिकन राष्ट्रपति मध्यपूर्व के विशाल प्रदेश में किसी भी देश की सहायता दे सकता था।

दूसरे, इसके अन्तर्गत दो जाने वाली सहायता का क्षेत्र भी अधिक व्यापक था। जहाँ दृढ़ सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रधानतः आर्थिक सहायता की

मध्यम राज्य अमेरिका का उदय

व्यवस्था की गई थी वहा आइजनहोवर सिद्धान्त के अन्तर्गत आर्थिक और सैनिक दोनों प्रकार की सहायता की व्यवस्था थी ।

दूसरे, इस सिद्धान्त ने राष्ट्रपति को ट्रूमैन सिद्धान्त की अपेक्षा सेनायें भेजने व लड़ाई छेड़ने के अधिक विस्तृत अधिकार प्रदान किये ।

चौथे, इस सिद्धान्त में आक्रमण की प्रवृत्ति की भी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई । यह स्पष्ट कर दिया गया कि सहायता वाला साम्यवादी आक्रमण भयवा उसकी आशका पर सम्बन्धित देशों की प्रार्थना और इच्छा पर ही भेजी जायगी ।

पाचवें, ट्रूमैन सिद्धान्त की भांति इस सिद्धान्त का घोषित लक्ष्य भी मध्यपूर्व के देशों में स्थिरता और स्वतन्त्रता की रक्षा करना था, जबकि इसका वास्तविक लक्ष्य मध्यपूर्व के तेल भण्डारों को पश्चिमी गुट के लिए सुरक्षित रखना था । दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि ट्रूमैन सिद्धान्त की भांति आइजनहोवर सिद्धान्त भी अमेरिका के नवीन साम्राज्यवाद का सूचक था ।

आइजनहोवर सिद्धान्त का प्रयोग—इस सिद्धान्त के प्रचार और प्रसार के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत जेम्स बी रिचर्ड्स को मध्यपूर्व के देशों का दौरा करने के लिए भेजा गया । इस समय इन देशों में दो बड़े वर्ग थे—पश्चिम ने समर्थक, एवं पश्चिमो विरोधी किन्तु सोवियत पक्षपाती । पश्चिम समर्थक टर्की, ईरान, ईराक और पाकिस्तान (बगदाद पैक्ट के सदस्य राज्य) ने २१ जनवरी को इस सिद्धान्त का समर्थन कर दिया । इन राज्यों के अलावा लेबनान, सीरिया और इजरायल ने भी इसके प्रति अपनी सहमति प्रकट की । किन्तु पश्चिम विरोधी सीरिया और यमन ने इस सिद्धान्त की अस्वीकार कर दिया, गूडहान ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया और मिस्र ने मौन साथ देना उचित समझा ।

शीघ्र ही ऐसा अवसर भी उपस्थित हो गया जबकि दो देशों में अमेरिका को 'आइजनहोवर सिद्धान्त' का प्रयोग करने का मौका मिला । ये देश थे—लेबनान और जोर्डन । लेबनान में अमेरिका ने स्वयमेव इस सिद्धान्त का प्रयोग किया जबकि जोर्डन में ब्रिटेन की सहायता से । परन्तु इन दोनों देशों में ही यह सिद्धान्त व्यावहारिक दृष्टि से सफल न हो सका ।

(१) लेबनान में अमेरिकी सेना का प्रवेश—ईसाई और मुसलमानों के प्रदेश लेबनान के तत्कालीन राष्ट्रपति चामो और प्रधानमंत्री सामी सोलह के विच्छेद ६ मई, १९५५ को विद्रोह हो गया । यह सरकार अमेरिका समर्थित थी जिसने आइजनहोवर सिद्धान्त की स्वीकार कर लिया था । लेबनान

ने सुरक्षा-परिपद में निष्कासन की कि इस विद्रोह को मिस्र और सीरिया में भड़काया है तथा वे विद्रोहियों की सहायता कर रहे हैं।

राष्ट्रपति राष्ट्रमन्त्रीय जांच आयोग ने लेबनानी आरोपों को गलत बताया, लेकिन लेबनानी सरकार ने आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए मनुष्य राज्य अमेरिका से सैनिक सहायता की मांग की। १५ जुलाई, १९५८ को राष्ट्रपति आइज़नहावर द्वारा घोषणा की गई कि लेबनानी राष्ट्रपति की अत्यावश्यक अग्रील पर अमेरिकन सेनाएं बहा भेजी जा रही हैं। इसी दिन अमेरिकी सैनिक लेबनान की राजधानी बेरूत उतर गये और २० जुलाई तक अमेरिकन सैनिकों की संख्या १० हजार तक पहुँच गई। अमेरिकन फौजा ने विद्रोह को तो दबा दिया लेकिन लेबनानी जनता ने अपनी भूमि पर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति को पसन्द नहीं किया।

सोवियत संघ ने सुरक्षा परिपद में २५ जुलाई को यह प्रस्ताव रखा कि लेबनान से अमेरिकी सेना वापस बुला ली जाए। बिन्तु अमेरिकन ग्रुट से नियन्त्रित परिपद ने इस प्रस्ताव को नामजूर कर दिया। १३ अगस्त को प्रश्न महसभा में पेश हुआ और २३ अगस्त को यहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अमेरिका से अपनी सेनाएं वापस बुलाने की मांग की गई। अमेरिका ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया।

इस बीच लेबनान में गृह-युद्ध जारी रहा। ३१ जुलाई, १९५८ को राष्ट्रपति बामा के स्थान पर चह्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गये। चूंकि विरोधी दलों की पश्चिमो-समर्थक बामो को हटाने की मुख्य मांग पूरी हो गई अब लेबनान का गृह-युद्ध भी शांत हो गया। नयी सरकार ने अमेरिका से तुरन्त अपनी फौजें लेबनान से हटा लेने का मांग की। अतः विवाद हो कर उसे अपनी फौज लेबनान से हटानी पड़ी। २६ अक्टूबर, १९५८ तक अमेरिकन फौजों ने लेबनान छोड़ी कर दिया।

(॥) जोर्डन में हस्तक्षेप—१४ जुलाई, १९५८ को ईराक पश्चिम-पश्चात्तों सरकार ने बिन्तु एक सैनिक विद्रोह हो गया। अतः यह आशंका की जाने लगी कि वहाँ जोर्डन भी ऐसी शान्ति का शिकार न हो जाए। फरवरी १० जुलाई को जोर्डन के शाह हुसैन ने रेडिया से घोषणा की कि ईराक शान्ति से उत्पन्न स्थिति में जोर्डन भी रक्षा के लिए मित्र राज्यों से प्रभावशाली सैनिक सहायता की मांग की गई है। शाह हुसैन ने ब्रिटेन और अमेरिका में अविलम्ब से नए सहायता दान की अग्रील की। ब्रिटेन ने भी इस ही अग्रील सेनाएं जोर्डन में भेज दी और अमेरिका ने शाह हुसैन को ७५ लाख डॉलर की नयी आर्थिक सहायता दी। इस अनिश्चित अमेरिका की

वायु-मण्डल ने जोर्डन में उतारन हुई पैट्रोन की जमीन का करने के लिए बहरीन से तेल टोना घुमा कर दिया।

जोर्डन के मामले में भी अमेरिका को काबूकारी जमानती रही। संयुक्त राज्य का ही महासभा के २३ अक्टूबर, १९५८ के एक प्रस्ताव के अनुसार ज़िन्दन को पानी सेनाएँ जोर्डन से बाहर धुगनी पड़ी। इस तरह ज़िन्दन की सहायता से आइबनहोवर विद्वान का सैनिक प्रयोग जोर्डन में किया गया, यह जन्म में निरंकुश हुआ।

आइबनहोवर विद्वान का मूल्यांकन—देशान्त और जोर्डन इन दोनों देशों में आइबनहोवर विद्वान का जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयोग किया गया, उससे इस विद्वान के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकलने हैं—

(i) आइबनहोवर विद्वान को मध्य-पूर्व में साम्यवादी एवं सोवियत प्रभाव को रोकने में सफलता नहीं मिली और न ही वह इस क्षेत्र में शक्ति स्थापित करने अपना अन्तर्राष्ट्रीय सनाव दूर करने में सफल हुआ। इसके विपरीत लेबनान और जोर्डन में सैनिक हस्तक्षेप का उल्टा प्रभाव यह हुआ कि इन देशों में पश्चिमी विरोधी एवं साम्यवादी तत्वों की पुष्टि मिली तथा दोनों राज्यों में पश्चिमी प्रभाव का प्रतिरोध करने वाली सरकारों की स्थापना हुई।

(ii) यह स्पष्ट हो गया कि दूमरे विद्वान की तरह आइबनहोवर विद्वान भी संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्बल बनाने वाला था क्योंकि इसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम की करने हाथ में लेने का प्रयास किया गया था।

(iii) राष्ट्रपति आइबनहोवर ने मध्य पूर्व में नवीन राष्ट्रीयता के जगमगाते उदारा की। वह भूल गये कि मध्य पूर्व अब विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध है। इस विद्वान की अनकम्पत्ता का एक अन्य कारण मध्य-पूर्व में बर्लेन नाविक का व्यक्तित्व भी था जिसकी अनुरोध द्वारा भारत-उत्तरी ही कर दी गयी थी।

निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहिए कि व्यावहारिक दृष्टि से आइबनहोवर विद्वान एक सफल गुरुता रही। इसके अन्तर्गत १९५८ में लेबनान में भेजी गयी अमेरिकन सेनाओं के द्वारा शक्ति अवसर स्थापित की गयी, किन्तु पश्चिम के कट्टर समर्थक राष्ट्रपति काको पुनर्निर्वाचित नहीं हो सके और बाद में अमेरिकन फौजों की लेबनान से हटना पड़ा। इसी प्रकार जोर्डन में भी अमेरिकन सहायता से साहू हुसैन के विरुद्ध विद्रोह की दवा दिया गया, परन्तु इसके बादभूत सीरिया, ईराक और विश्व में साम्यवादी प्रभाव में वृद्धि हुई तथा ईराक बादशाह समझौते से अलग हो गया।

शीत-युद्ध में निश्चितता (१९५६-६०)—आइजन होवर सिद्धांत के कारण शीत-युद्ध तीव्र हो गया और आइजन होवर प्रशासन की विश्व के अधिकांश भाग में कटु-आलोचना होने लगी। लेकिन सितम्बर, १९५६ में जब अमेरिकन राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने अमेरिका की राजकीय यात्रा की, तो वातावरण में सुधार हुआ। दोनों महान् नेताओं के मध्य वार्ता से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में बड़ी कमी आयी। दोनों नेताओं ने यह निर्णय किया कि पारस्परिक मतभेदों के प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए मधुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन और फ्रांस इन चार बड़े राष्ट्रों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाय। अमेरिकन राष्ट्रपति ने १९६० के वसन्त काल में रूस की यात्रा के निमन्त्रण को भी स्वीकार किया।

शिखर-सम्मेलन की अमफलता—काफी विचार-विमर्श के बाद १६ मई, १९६० को प्रस्ताविन शिखर सम्मेलन होना निश्चित हुआ। दुर्भाग्यवश सम्मेलन के पूर्व ही कुछ ऐसे अपशकुन हो गये जिन्होंने पहले तो सम्मेलन के होने में ही संदेह उत्पन्न कर दिया और बाद में जत्र सम्मेलन हुआ तो उसे असफल बना दिया। मुख्य रूप से ये अपशकुन दो हुए—

(i) जर्मनी से सम्बन्धित विवाद, एवं

(ii) यू-२ विमान काण्ड।

(i) जर्मनी से सम्बन्धित विवाद—पहला अपशकुन जर्मनी पर हुआ। १४ जनवरी, १९६० को पश्चिमी जर्मनी के चान्सलर आडेनौर ने आरोप लगाया कि रूसी वर्गिन पर हमला कर रहे हैं तथा शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय जर्मनी नहीं बरन् निगरानीकरण का प्रश्न होना चाहिए। खुश्चेव ने घमकी दी कि "यदि पूर्वे और पश्चिम की दार्ता ने बर्लिन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया तो वह पूर्वी जर्मनी से पृथक् सम्पि कर लेगा और पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया के साथ उसकी सीमा का निर्धारण करेगा।"

फरवरी, १९६० में रूस ने बर्लिन में एक नया सत्र पेंदा कर दिया। पूर्वी जर्मनी में विद्यमान पश्चिमी देशों के सैनिक विधानों को दिये जाने वाले पाम पूर्वी जर्मन सरकार के नाम से जारी कर दिय गये जत्र कि अतएव ये पूर्वी जर्मनी के सोवियत अधिकारियों द्वारा जारी किये जाते थे। इस नयी व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि रूस इस प्रकार पश्चिमी देशों से पूर्वी जर्मनी की सरकार को 'तथ्यानुसार मान्यता' (De facto recognition) दिलवाना चाहता था। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के दृढ़

विरोध के उपरान्त अन्त में १४ मार्च, १९६० को सोवियत रुस इस बात पर राजी हो गया कि पश्चिमी देशों के सैनिक अधिकारियों को पूर्वी जर्मनी में यात्रा के लिए जो पास दिये जायेंगे उन पर सोवियत अधिकार का क्षेत्र (Zone of Soviet Occupation) लिखा रहेगा।

इसके बाद फिर तनाव पैदा हुआ। १६ मार्च को पश्चिमी जर्मन-कान्सलर ने घोषणा की कि १६ मई को गिबेर सम्मेलन होने से पहले ही पश्चिमी बर्लिन में इस बात पर जनमत संग्रह लिया जाय कि लोग बर्लिन में वर्तमान स्थिति बनाये रखने के पक्ष में हैं अथवा नहीं। इसके विरोध में दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि इस प्रकार का जनमत संग्रह बर्लिन के दोनों भागों में हो।

स्पष्ट ही, ऐसे वातावरण में, दोनों पक्षों में एक दूसरे के प्रति मन्देह पूर्वापेक्षा अधिक बढ़ गया जिसका कुप्रभाव गिबेर-सम्मेलन पर पड़ा।

(ii) यू-२ विमान-काण्ड—गिबेर सम्मेलन के मार्ग में दूसरा सबसे बड़ा अपसृान यू-२ विमान काट हुआ। ५ मई, १९६० को सोवियत प्रधानमंत्री ने रोपपूर्ण शब्दों में घोषणा की कि रुस के हवाई अड्डों की जामूसी करते हुए एक यू-२ अमेरिकन विमान को १ मई, १९६० को राकेट द्वारा नीचे गिरा दिया गया है। रुस ने अमेरिका पर चट्ट-प्रहार किये और बाद में राष्ट्रपति थाइजन होवर की इस घोषणा ने आग में घी का काम किया कि अमेरिका की हवाई जामूसी उड़ाने न्यायसंगत हैं और 'पंचंहार्वर की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठ न भावश्यक है।' सोवियत रुस ने आइजन होवर के इन चुनौती भरे शब्दों को अपना राष्ट्रीय अवमान समझा।

यू-२ विमान काण्ड से दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुँच गया और गिबेर सम्मेलन की सफलता की आशा धूमिल हो गई, लेकिन ज़ुइचेव की इन घोषणाओं से फिर भी आशा बनी रही कि 'अन्तर्राष्ट्रीय दबाव कम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए' और 'गिबेर सम्मेलन में यू-२ का विषय नहीं उठाया जायेगा।'

लेकिन जब १६ मई को गिबेर सम्मेलन प्रारम्भ हुआ तो सोवियत प्रधानमंत्री ने अज्ञान ही यू-२ काण्ड के लिए अमेरिका की निन्दा करते हुए निम्नलिखित मार्ग पेश कर दी—

- (१) अमेरिका को अपने उत्तरेजनात्मक मार्ग की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए धमा मागनी चाहिए, इन मार्ग को बन्द करना चाहिए और दस काण्ड के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्डित करना चाहिए।

(ख) यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रुस की दृष्टि में शितर सम्मेलन में जमेगिना के साथ बातचीत करना व्यर्थ है और वह इसमें भाग नहीं ले सकता।

खुश्चेव ने यह भी कहा कि सम्मेलन को दिया न महीने के लिए स्थगित कर दिया जाय ताकि अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनावों के बाद जनवरी, १९६१ में यह आयोजित हो सके। आइज़न होवर द्वारा जानूसी उठानों को भविष्य में स्थगित कर देने के आश्वासनों के बावजूद खुश्चेव अपनी मांग पर बड़े रहे। १७ मई को सम्मेलन आरम्भ होने पर खुश्चेव जब नहीं आये तो यह घोषणा कर दी गई कि 'खुश्चेव द्वारा अपनाय गये रुस के कारण शितर सम्मेलन की बातों आरम्भ करना सम्भव नहीं है।' अमेरिकन राष्ट्रपति आइज़न होवर, ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मैकमिलन तथा फ्रेंच राष्ट्रपति डिगॉल के सम्मिलित प्रयास भी सम्मेलन को निष्फल होने से नहीं बचा सके।

सहप्रस्तित्व का काल (जनवरी, १९६१ के उपरान्त)

बैनेडी युग

जानूसी विमान-कांडों को लेकर रुस और अमेरिका के मध्य सम्बन्धों में कुछ रिगोश अवसर का गया लेकिन अक्टूबर, १९६० में श्री खुश्चेव ने अपने एक उत्साहजनक और शान्तिवादी भाषण में दोनों देशों के बीच सुधार की आशा को पुनः जगृत कर दिया। इसका बाद ही नवम्बर, १९६० को अमेरिकी राष्ट्रपति कनिडिचन में सैन्टर जॉन पिटर्बैरग्ट बैनेडी की सफलता से शीत युद्ध की समाप्ति की और सह-अस्तित्व के विचार की अभिवृद्धि की आशा दृढ़ गई। बैनेडी-प्रशासन ने विदेश नीति के मूल सिद्धांतों को लगभग अपरिवर्तनीय ही रखा, लेकिन उन्हें इतना सजीव और सश्रिय अवश्य बना दिया कि ऐसा लगने लगा मानो अमेरिकन विदेश नीति में नई जान आ गई हो। श्री बैनेडी ने १९५६ की "बैम्प डेपिड भावना" में विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि महा शक्तियों के हित स्पष्ट हैं और उन्हें अधिक दिन तक अपने पारस्परिक सम्बन्धों को ढीला या बिगड़ा हुआ नहीं रखना चाहिये। जून, १९६१ में वियना में बैनेडी और खुश्चेव की मुलाकात हुई और बैनेडी का यहाँ यह मत पुष्ट हुआ कि दोनों दलों के बीच अस्पष्टता, सन्देह, गलत पहचानों के कारण अनेक राकट पेंदा हो जाते हैं किन्तु विचारों के स्पष्ट आदान प्रदान के द्वारा उन्हें मिटाया जा सकता है।

बैनेडी प्रशासन ने विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण विचार यह किया कि साम्यवाद को सीमित करने के लिए पूरे विश्व को यहाँ तक कि सोवियत

दीवार के पीछे के प्रदेशों को भी राजनीतिक और आर्थिक विचारों का क्षेत्र बना लिया। कनेडी ने अमेरिकन विदेश नीति को एक नया निखार दिया। उनकी विदेश नीति का विश्लेषण निम्नलिखित तत्त्वों में किया जाना उपयुक्त होगा—

(क) मानवीय अधिकारों के सम्बन्ध में कनेडी की विदेश नीति—श्री कनेडी ने मानवीय अधिकारों के प्रति दृढ़ निष्ठा प्रकट की और कहा कि उनका देश मानव अधिकारों के प्रातिवर्ती विचारों की मशाल को बुझाने नहीं देगा तथा स्वतन्त्रता की सुरक्षा और सफलता के लिए किसी भी मित्र की सहायता करने या किसी भी शत्रु का अवरोध करने के लिए तैयार रहेगा। २० सितम्बर, १९६२ को उन्होंने नागरिक अधिकारों के प्रश्न पर समुन्नत राष्ट्रसंघ में विचार विमर्श और स्पष्ट शब्दों में कहा कि “ऐसी महान् रास्ता इस समय आगे मूँढ़े नहीं रही रह सकती जब किसी सदस्य राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों का दुरुपयोग और हनन किया जा रहा हो।” उनका शक्तिशाली दक्षिण अफ्रीका में होने वाले अन्याय की ओर था।

(ख) समुन्नत राष्ट्रसंघ, शान्ति एवं युद्ध तथा सह-अस्तित्व के प्रति कनेडी की विदेश नीति—श्री कनेडी ने समुन्नत राष्ट्रसंघ के पूर्ण समर्थन की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका सत्ताशक्तों द्वारा घोंघी हुई नहीं जान् ऐसी शान्ति की कामना करता है जिनसे पृथ्वी पर जीवन जीने योग्य रहे और राष्ट्रो तथा व्यक्तियों को विनाश के चक्कर में न लें। उन्होंने शान्ति और निःस्त्रीकरण के प्रश्नों पर मन को मोड़ा नहीं बल्कि उनके उद्देश्यों को विचारपूर्ण दृष्टांतों द्वारा शान्ति के लिए उसके प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने विदेश नीति के क्षेत्र में यह वाक्यांश प्रकट किया कि—“सामाजिक शान्ति के समान विरल शान्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने पड़ोसी को धार करे। इसके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि वे एक दूसरे को बरदाश्त करते रहे और कोई झगड़े तक नहीं लें तो उनके उपयुक्त एवं शान्तिपूर्ण निपटारे के लिए प्रस्तुत रहें।”

सह-अस्तित्व की धारणा में विश्वास रखते हुए श्री कनेडी ने सोवियत संघ और साम्यवादी प्रणाली के प्रति अमेरिकियों की घृणा के प्रसार को उचित नहीं माना। उन्होंने कहा कि दूसरे पक्ष का विघटन और निराशापूर्ण क्षेत्र मत देखो और न ही हारण को अवश्यमावी मानो।

(ग) पुराने मित्रों के प्रति वफादारी का वचन—राष्ट्रपति कनेडी ने कहा सोवियत संघ और साम्यवादी व्यवस्था के प्रति सह-अस्तित्व का नारा बुलन्द किया वहीं “वफादार मित्रों के प्रति निष्ठा” रखने का वाक्य भी

किया और उसे निभाया भी। उन्होंने नाटो (NATO) का आधिकार और राजनीतिक आधार मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये तथा जर्मनी के प्रश्न पर झुकने से इनकार कर दिया। जून १९६१ में ख्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक धृष्टक सन्धि पर हस्ताक्षर करने की घमकी दी और कहा कि इससे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रान्स के लिए पश्चिमी बर्लिन में जाने के अधिकार समाप्त हो जायेंगे। लेकिन कैंनेडी ने सोवियत घमकी का जवाब विवेकपूर्ण अस्वीकृति में दिया। उनके नेतृत्व में पश्चिमी शक्तियों ने रूस को स्पष्ट संदेशों में बताया कि रूस की एक पक्षीय कार्यवाही उन्हें किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों की इस दृढ़ता का परिणाम यह हुआ कि रूस ने अपनी घमकी को कार्यान्वित नहीं किया।

(घ) क्यूबा का संकट और कैंनेडी की विदेश नीति—राष्ट्राति कैंनेडी के कार्य-काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्यूबा की घटना थी जिसने केवल सम्पूर्ण अमेरिकन राष्ट्र को ही नहीं बल्कि समूचे विश्व को झकझोर दिया। इस घटना में कैंनेडी की विदेश नीति की दृढ़ता स्पष्ट रूप से प्रकट हुई।

क्यूबा का टापू समुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्व में बंस्ट-इन्डो ज का सबसे बड़ा टापू है। प्रारम्भ में क्यूबा काफी समय तक अमेरिका की नीति का समर्थक था, लेकिन २ जून, १९५९ को फिडेलकास्ट्रो के नेतृत्व में एक क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप वह साम्यवादी रूप का समर्थक और अमेरिका का विरोधी बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कास्ट्रो सरकार साम्यवादी रूस की ओर झुकती गई।

अक्टूबर, १९६२ में क्यूबा पर एक ऐसा महान संकट उत्पन्न हुआ जिससे रूस और अमेरिका के बीच खुले सघर्ष की समावना हो गई। इस घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई—२ सितम्बर, १९६२ को रूस ने घोषणा की कि वह क्यूबा को साम्राज्यवादियों से अपनी रक्षा के लिए सशस्त्रों की पूर्ण सहायता प्रदान करेगा। उधर राष्ट्रानि कैंनेडी ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया कि सोवियत रूस ने क्यूबा को प्रशेषणास्त्रों, पन्डुब्धियों तथा राकेट आदि से सज्जित किया है जिनसे अमेरिका की सुरक्षा को भारी खतरा पैदा हो गया है। ७ सितम्बर को अमेरिकन कांग्रेस ने राष्ट्रानि की अधिकार दे दिया कि आवश्यकता पड़ने पर वह डेढ़ लाख रिजर्व सैनिकों की सैनिक सेवा के लिए बुला सकते हैं।

क्यूबा में रूसी शस्त्रास्त्र पहुँचते रहे और १६ अक्टूबर, १९६२ को कैंनेडी ने क्यूबा की पूरी तरह हवाई जांच हटाने का आदेश दे दिया जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि क्यूबा में प्रशेषणास्त्रों का भारी संचय हो रहा

है। २२ अक्टूबर को बलूचा सरुट पर राष्ट्रपति कैंनेडी ने अपने कार्य काल का सबसे महत्वपूर्ण भाषण दिया, जिसमें भली प्रकार जता दिया गया कि अमेरिका की विदेश नीति में सुरक्षा का तत्व कितना जबरदस्त है और मंत्री तथा सहयोग का हाथ बढाने हुए भी अमेरिका विदेश नीति में किस हद तक सैनिक कार्यवाही का आश्रय ले सकता है।

२२ अक्टूबर की अपनी चेतावनी के बाद २३ अक्टूबर को ही कैंनेडी ने बलूचा को ताकेबन्दी की घोषणा कर दी। इसका स्पष्ट अर्थ था कि अमेरिका के सैनिक जहाज बलूचा के बन्दरगाहों को घेर लगे और वहाँ साक्षिपत शम्शान्को से सुसज्जित जहाज नहीं पहुँच सकेंगे। राष्ट्रपति कैंनेडी का यह आदेश रूप की एक स्पष्ट चेतावनी थी कि वह बलूचा को सैनिक सहायता देना बन्द कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाय।

सोवियतसोवियत प्रधानमन्त्री कुश्चेव ने दूर-दर्शिता से काम लिया। २२ अक्टूबर को कुश्चेव द्वारा घोषणा की गई कि इस बलूचा से अपने प्रक्षेपणास्त्र वापस मगाने की माँग दे रहा है और वह उस द्वीप पर स्थित सभी प्रक्षेपणास्त्र अड्डों को संयुक्त राष्ट्र संधि की देखरेख में तुड़वा देने को सहमत है। सोवियत प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की स मधी बलूचा नहीं भेजने का भी रुत आश्वासन देता है। राष्ट्रपति कैंनेडी ने कुश्चेव की घोषणा का तुरन्त उत्तर दिया कि "यह एक सच्चे नेता सरीखा निर्णय है।"

इस प्रकार कैंनेडी की दृढ़ता और तत्परता तथा कुश्चेव का विवेक और संयम के फलस्वरूप बलूचा का सरुट तनावन हो गया तथा अणु-युद्ध की आशंका से भयभीत मानव जाति ने सम्शोध की साक्षली।

(६) निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रगति अणुपरीक्षण प्रतिबंध संधि-बेनेडी प्रशासन ने निरस्त्रीकरण के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए—

(i) सभी राष्ट्रों द्वारा परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की संधि पर हस्ताक्षर करना, जो तुरन्त किया जा सकता है। परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की घर्ता शुरू करने के लिए आम निरस्त्रीकरण होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है और न करना चाहिए।

(ii) संस्थाओं में प्रचुर होने वाले विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन बंद किया जाए और इन समय जिन राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है, उन्हें इन विस्फोटक पदार्थों को हस्तांतरण न किया जाए।

(iii) परमाणु अस्त्रों पर उठा राष्ट्रों को नियन्त्रण हस्तांतरित करने से रोकना, जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं हो।

(iv) परमाणु अस्त्रों को अन्तरिक्ष में नये मुख्य क्षेत्रों के बीच ओने से रोकना।

(v) इस समय तक जो परमाणु अस्त्र बन चुके हैं उन्हें धीरे-धीरे नष्ट करना और उनमें लगी सामग्री को शांतिपूर्ण कामों में प्रयुक्त करना।

(vi) परमाणु अस्त्रों को नये जाने वाले सामरिक महत्व के वाहनो के उत्पादन और असीमित परीक्षण पर रोक लगाना व धीरे-धीरे उन्हें भी नष्ट करना।

राष्ट्रपति केनेडी और प्रधानमन्त्री जूइन्चेव इन दोनों दूरदर्शी नेताओं के सहयोगपूर्ण रख के कारण अन्त में २५ जुलाई, १९६३ को तीन प्रमुख परमाणु शक्तियों—संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच एक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर हस्ताक्षर हुए। बाद में फ्रांस और जनवादी चीन को छोड़कर विश्व के लगभग अन्य सभी राष्ट्रों द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए। इस संधि का विस्तार से वर्णन 'निःशस्त्रीकरण' वाले अध्याय में किया जा चुका है। इस संधि में कुछ ही दिन पूर्व १५ अग्रेल, १९६३ को संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ ने सीधा टेलीफोन और रेडियो सम्पर्क स्थापित करने का समझौता (U.S.—Soviet Hot Line Agreement) हुआ जिसका उद्देश्य बयाना लेना संकट के समय दोनों देशों में सीधा सम्पर्क स्थापित करके गलती से या आह्वित घटना से छिटकने वाले युद्ध व संकट का निवारण करना था।

राष्ट्रपति केनेडी ने समय उपरोक्त दोनों ही महत्वपूर्ण समझौतों से छीतदुष्ट क मतलब हैं यही वर्ष हुई। दुर्भाग्यवश इस प्रतिभावान् नेता को २२ नवम्बर, १९६३ को हत्या हो जाने से विश्व की भावी शांति की आशाओं को बड़ा आघात पहुँचा।

(घ) केनेडी की लेटिन अमेरिका के प्रति नीति प्रगति के लिए मंत्री—लेटिन अमेरिका के प्रति राष्ट्रपति केनेडी ने अव्यक्त उदार और मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। बड़े द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और लेटिन अमेरिका के देशों के पारस्परिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए १९४८ में अमेरिकन राज्यों के 'संगठन' (O.A.S.) की स्थापना की जा चुकी थी, परन्तु जहाँ केनेडी से पूर्व इस संगठन में सैनिक तथा कूटनीतिक सहयोग पर अधिक बल दिया जाता था, वहाँ केनेडी ने आर्थिक सहयोग पर अधिक बल देना शुरू किया। १३ मार्च, १९६१ में उन्होंने औपचारिक रूप से

अमेरिकन गणराज्यों के राजनयिक प्रतिनिधियों के समक्ष 'प्रगति के-ब मेम्ब्रो' (Alliance for Progress) का प्रस्ताव रखा। इससे अन्तर्गत न गया कि अन्य स्वतन्त्र देशों, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तिगत पूँजीपतियों के साथ समुक्त राज्य अमेरिका, सेंटिन अमेरिका के आर्थिक विकास एवं जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए २० हजार मिलियन डॉलर की सहायता तथा ऋण देगा। अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति कनेडी ने पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रीय के प्रति एक विशेष प्रतिज्ञा ली कि वे समुक्त राज्य अमेरिका के 'अष्टमै सद्यों के प्रगति के लिए मेम्ब्रो के रूप में, अच्छे कामों में परिणत करेंगे जिससे स्वतन्त्र लोगों तथा स्वतन्त्र सरकारों की निर्धनता की धज्जियाँ तोड़ फेंकने में सहायता दी जा सके।'

कनेडी ने प्रगति के लिए मेम्ब्रो प्रस्ताव रखते हुए अपने भाषण में सेंटिन अमेरिका के प्रति समुक्त राज्य की उदार नीति पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समुक्त राज्य अमेरिका इस गोलार्ध के देशों को हर सम्भव सहायता देने को उत्तम है। प्रत्येक दक्षिण अमेरिकी योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे दक्षिणी अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ बने, मुद्रा सम्बन्धी स्थिरता आये, गृहल करने की भावना को प्रोत्साहन मिले, अधिकतम राष्ट्रीय प्रयास सम्भव हो और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास सम्भव हो सके।

राष्ट्रपति कनेडी न दक्षिणी अमेरिका के देशों के प्रति जो सहायता नीति अपनायी, उसका सुपरिणाम निकला। दक्षिणी अमेरिका के देश अन्तः-कात्त में ही आर्थिक और सामाजिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगे।

अन्त में यही कहना होगा कि राष्ट्रपति कनेडी के प्रधानमन्त्र-काल में यद्यपि अमेरिका की वैदेशिक नीति के आधारभूत सिद्धान्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन उन सिद्धान्तों में कनेडी ने रचनात्मक रंग भर दिये और उन्हें एक नया निखार दे दिया।

जानसन युग

२२ नवम्बर, १९६३ को राष्ट्रपति कनेडी की हत्या के बाद सरकारीन उप-राष्ट्रपति लिन्डन जानसन समुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और बाद में १९६४ के निर्वाचन में विजय प्राप्त करके पुन राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तुरन्त बाद ही श्री जानसन ने घोषणा की कि वे विदेश नीति के क्षेत्र में दिग्गज राष्ट्रपति कनेडी का अनुसरण करेंगे और अमेरिका की विदेश नीति के मूल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

घोषणा प्रारम्भ में तो बहुत कुछ यथायं सी वायुमाल के इतिहास में उनकी घोषणा की गई। जानसन ने एक ओर तो चीत युद्ध के कमा और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सामंजस्य अपनाये। जानसन प्रशासन की विदेश नीति अन्तर्गत प्रसन्न पहलुओं के सार में देखा जा सकता है —

(क) जर्मनी और बर्लिन के एकीकरण का प्रश्न

जर्मनी और बर्लिन के प्रश्न पर अभी तक दोनों पक्षों (अमेरिका एवं रूस) के मतभेद यथापूर्व हैं। युद्ध के बाद से ही जर्मनी दो राज्यों में तथा बर्लिन चार भागों में बँटा हुआ चला आ रहा है। तब से लेकर अब तक जर्मनी के बर्लिन के एकीकरण के सम्बन्ध में अनेक बार अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वादबोलत हो चुकी है। सम्झौता का निराकरण करने के लिए दोनों पक्षों ने आने अने सुनाव पेश किये हैं परन्तु इनमें वास्तविक भी सम्झौता अभी तक हुआ नहीं हो पाया है। इस समय बर्लिन से ८०-१०० मील पश्चिम में उत्तर से दक्षिण की ओर साँची जाने वाली एक रेखा से दोनों जर्मन राज्य विभक्त होते हैं। इस रेखा के पश्चिम में पश्चिमी जर्मनी का 'जर्मन संघीय गणराज्य' (German Federal Republic) है और पूर्व में पूर्वी जर्मनी का 'जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य' (German Democratic Republic) है। पश्चिम जर्मनी पश्चिम का प्रबल पक्षगती है जबकि पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र है। दोनों ही राज्यों में आर्थिक उन्नति, उद्योगों, सम्पत्तियों तथा जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी राज्य बड़ा चढ़ा है।

१९५४ में २५ जनवरी से १८ फरवरी तक दोनों भागों के एकीकरण के लिए बर्लिन में विदेश मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें पश्चिमी शक्तियों ने निम्न बातों पर बल दिया—

(i) जर्मनी के दोनों भागों में तथा बर्लिन में स्वतन्त्र मतदान द्वारा सश्रित परिषद का निर्वाचन किया जाय।

(ii) यह परिषद एक के श्रेष्ठ जर्मन सरकार को स्थापना करे।

(iii) यह सरकार विज्ञेता शक्तियों के साथ मंत्रि करे और यह पौंडित्य तथा रूप द्वारा हथियारों जमे जर्मनी प्रदेशों का अन्तिम बटवारा करे।

(iv) यह सरकार आति मध्य में सम्मिलित शक्तों के अनुसार आने अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्वयं निर्दिष्ट करे।

पश्चिमी शक्तियों के प्रस्तावों से असहमत होते हुए सोवियत संघ ने एकीकरण के लिए इन बातों पर बल दिया—

(i) पश्चिमी देश पूर्वी जर्मनी के 'जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य' को सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न राज्य स्वीकार कर लें।

(ii) पश्चिमी देश साविद्यत रूस की यह बात मान लें कि जर्मनी पर अधिकार करने वाले देश अब जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(iii) पूर्वी और पश्चिमी दोनों गणराज्य एकीकरण के लिए आपस में सीधी बातचीत करें।

(iv) यह बातचीत कुछ निश्चित दलों या माम्यताओं के आधार पर हो जो इस प्रकार होंगी—दोनों राज्यों की सरकारों का मत। पहला, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट सहयोगियों की सुझाव, बीन के मधीय जर्मन गणराज्य को नाटो से वृषक होना तथा पश्चिमी देशों की सेनाओं का जर्मनी के प्रदेश से हट जाना।

दोनों पक्षों की दलों की तुलना से स्पष्ट है कि पश्चिमी शक्तियों का बल दोनों क्षेत्रों के सम्मिलित चुनाव बरान पर था क्योंकि पश्चिमी राज्य की आवादी पूर्वी क्षेत्र से तिहुनी हों के कारण उन्हें वांछित परिणाम निकालने के विषय में लगभग कोई संदेह नहीं है। पश्चिमी शक्तियों का विश्वास है कि संयुक्त जर्मनी निश्चित रूप से पश्चिम का समर्थक होगा और इसका अर्थ होगा यूरोप में सोवियत सीमांत का २०० मील पूर्व में चला जाना, पूर्वी जर्मनी में विद्यमान रूस के २२ डिबिजनों का पूर्वी पोलैण्ड से हट जाना, पश्चिम पर आक्रमण के लिए प्रक्षेपणार्थ पेंकने के छद्मों का पीछे हटना और साथ ही पूर्वी यूरोप में रूसी समर्थक राज्यों पर बुरा प्रभाव पड़ना। साफ जाहिर है कि ऐसे परिणामों का जन्म देने वाले पश्चिमी प्रस्ताव को मास्को स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर रूस की एकीकरण की दलों पश्चिम को इसलिए मान्य नहीं हुई क्योंकि यदि इसके आधार पर मधि हो जाम तो जर्मनी का एकीकरण करन पर सारा देश साम्यवादी हो जायगा, पश्चिमी देशों की सीमा राइन नदी पर आ जायगी, पश्चिमी जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक बेस्ड सोवियत रूस के हाथ में चले जायेंगे और सोवियत संघ के नेतृत्व में उसकी शक्तिशाली सेना हिटलर की नाजी सेना की भांति पश्चिम के लिए खड़ा बन जायगी।

रूस और पश्चिमी शक्तियां दोनों ही के प्रस्तावों के परस्पर टकराने के कारण जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका।

जहाँ तम बर्लिन का प्रश्न है, पश्चिमी यूरियन यथास्थिति को स्थापित रखने के पक्ष में रहा है जबकि सोवियत रुस का सुझाव रहा है कि जहाँ तक जर्मन समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक उसे स्वतन्त्र नगर सोवियत करने उसका विमोक्षोत्तरण कर दिया जाय। चूँकि दाना पक्ष एक दूसरे की शर्तों को मानने को तैयार नहीं हैं अतः यह समस्या भी अभी तक लटकती हुई है।

जर्मनी के प्रश्न पर सोवियत रुस और अमेरिका के मौलिक मतभेद तब अधिक उग्र हो गये जब मई, १९५५ में पश्चिमी जर्मनी को नाटो का सदस्य बना लिया गया और मार्च १९५८ में अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी को आणविक आयुधों तथा प्रक्षेपणास्त्रों से सुसज्जित करने का फैसला लिया। कुपित होकर मई, १९५८ में खुश्चेव ने घोषणा की कि—“पश्चिमी जर्मनी के आणविक शस्त्रों से सुसज्जित होने से जर्मन राष्ट्रीय एकता सम्पन्न करने का क्या हुआ एकमात्र खुला दरवाजा भी बन्द कर बन्द कर दिया गया है।”

१० नवम्बर १९५८ को श्री खुश्चेव ने यह घोषणा की कि—“सम्पूर्ण बर्लिन जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के प्रदेश है, इस क्षेत्र पर इस गणराज्य की सर्वोच्च प्रभुता है। इसके पश्चिमी भाग पर पश्चिमी शक्तियों के अधिभार का कोई कानूनी आधार नहीं है। अतएव सोवियत सरकार ने यह निश्चय किया है कि बर्लिन में विदेशी शासन को समाप्त कर दिया जाय। सोवियत सरकार पश्चिम के साथ इस विषय पर वार्तालाप करने को तैयार है। सोवियत सच चाहता है कि पश्चिमी बर्लिन को निरस्त्र (Demilitarized) स्वतन्त्र नगर बना दिया जाय और यह परिवर्तन ६ महीने के भीतर सम्पन्न हो जाय ताकि इस नगर का सोवियत विरोधी जामूबी के लिए प्रयोग बहुत अधिक दिनांक लिए न किया जा सके।” सोवियत रुस ने यह भी घोषणा की कि यदि पश्चिमी देशों ने पश्चिमी बर्लिन में बने रहने के लिए सैनिक शक्ति का प्रयोग किया तो सोवियत सच को भी युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। २७ नवम्बर को रुस ने इस विषय में निश्चित प्रस्ताव पश्चिमी देशों के सामने रखा, किन्तु सोवियत घमकी से सर्वथा अग्रमाविन रहते हुए उन्होंने कहा कि बर्लिन में उनकी वर्तमान स्थिति ५ जून, १९४५ के पोद्सहम के तथा ४ मई, १९४६ को बर्लिन-घेरे की समाप्ति पर हुए समझौते के अनुसार है।

* १ दिसम्बर, १९५८ को पश्चिमी देशों (फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका) ने बर्लिन के प्रश्न पर जर्मनी और यूरोपीयन सुरक्षा की व्यापक बैठक में विचार करना स्वीकार कर लिया। १० जनवरी, १९५९ को सोवियत रुस

द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि समस्या पर विचारार्थ सामनाव्यवस्था का एक विश्व सम्मेलन आयोजित हो। किन्तु पश्चिमी देशों ने आग्रह किया कि विश्व सम्मेलन से पूर्व परराष्ट्रमन्त्रियों का सम्मेलन होना चाहिए। १६ मार्च, १९१६ को सावित्रा नगर में इस परिवर्तित प्रस्ताव के प्रति अपनी सन्मति दी।

११ मई, १९१६ को संयुक्त राष्ट्र सभ के तत्वावधान में चारों देशों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन आरम्भ हुआ। अमेरिका की तरफ से निरिचयन हर्टर नाम की लफ स टाट्रेई प्रोमिस्को, ब्रिटन की तरफ से सेल्मिन लायड तथा फ्रांस की ओर से जुवद मरवीय (Couvred Marville) इस जेनेवा सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के आरम्भ में पश्चिमी देशों ने संयुक्त रूप से जर्मन एकीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव रखे जिन्हें अस्वीकार करते हुए प्रोमिस्को ने कहा कि पहले शांति संधि की जानी चाहिए क्योंकि ऐसी संधि के अभाव में ही पश्चिमी जर्मनी आणविक आयुधों से सुसज्जित होकर और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बन कर यूरोप में तनाव उत्पन्न कर रहा है। ६ जून को बर्लिन विपरीत रूसी प्रस्तावों पर बातचीत में गतिराध पैदा हो गया। ये प्रस्ताव इस प्रकार थे—

(i) एक वर्ष के बाद पश्चिमी बर्लिन से पश्चिमी देशों का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए। एक वर्ष की अवधि तक वे कुछ सीमित अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) इस बीच में (इस एक वर्ष की अवधि में) पश्चिमी देश यहां अपनी मैत्रियों रूस वरें, कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार पर प्रतिबन्ध लगावें और कम्युनिस्ट विरोधी जासूसों और तोड़-फोड़ करने वाली गश्तालों को समाप्त कर दें तथा वहां आणविक अवस्था राकेट अड्डे नहीं बनावें।

(iii) एक वर्ष के भीतर पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन को एक अखिल जर्मन समिति बनाया जाए इसमें दोनों जर्मन राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या समान हो यह दोनों राज्यों में समर्क बढ़ाया तथा एकीकरण एवं शांति के प्रस्ताव तैयार करें। श्री प्रोमिस्को ने कहा कि यदि पश्चिम दो वर्ष के भीतर इन शर्तों के आधार पर समझौता करने में अडरन ड लेगा तो सावित्रा नगर संधि जर्मनी के साथ शांति संधि कर लेगा।

पश्चिमी राष्ट्रों ने नावियन प्रस्तावों को ठुकराते हुए उन्हें (पश्चिमी देशों को) अस्टोमेटम को सलाह दी। अमेरिका ने प्रस्तावों का "पूर्णतया अस्वीकार" कहा। सावित्रा प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में पश्चिमी देशों ने बर्लिन के सम्मेलन में

ये प्रस्ताव रहे—

(i) पश्चिमी देश बर्लिन में विद्यमान अपनी ११ हजार सेना में वृद्धि नहीं करेंगे। यदि स्थिति अनुकूल रही तो इसमें कमी करने का विचार किया जा सकता है। इन सेनाओं का साधारण शस्त्र ही दिये जायेंगे।

(ii) रुस द्वारा पश्चिमी बर्लिन को आने वाले स्थलीय, जलीय और वायु शीय मार्गों को खुला रखने की गारन्टी दी जाय।

(iii) पश्चिमी देश पारस्परिक आधार पर इस बात के प्रति सहमत हैं कि वे विरोधी प्रचार अथवा तोड़फोड़ की कार्यवाहियों की जाच करेंगे।

चूँकि दोनों ही पक्षों की जर्मनी व बर्लिन के सम्बन्ध में रहे गये एक दूसरे के प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुए अतः ११ जून को यह सम्मेलन १३ जुलाई १९५६ तक के लिए स्थगित हो गया। १३ जुलाई से ५ अगस्त १९५६ तक विदेश मंत्रियों का पुनः सम्मेलन हुआ, किन्तु बर्लिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका और फलस्वरूप सम्मेलन विफल हो गया। तत्पश्चात् मई, १९६० के शिखर सम्मेलन में इस समस्या पर विचार किया जाना निश्चित हुआ किन्तु दू-२ विमानकाण्ड हो जाने के फलस्वरूप शिखर सम्मेलन की भ्रूण हत्या हो गई और उसमें किसी प्रकार का विचार-विमर्श नहीं हो सका।

तब से लेकर अभी तक जर्मनी और बर्लिन का प्रश्न समाधान के लिए अटका हुआ है। राष्ट्रपति जॉनसन के प्रशासन काल में भी संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति लगभग वही रही जो पहले थी। २० जनवरी, १९६६ से चलने वाले निक्सन-प्रशासन की नीति में भी पहले से कोई भिन्नता इस मामले पर नजर नहीं आती है। वास्तव में अमेरिका चाहता है कि जर्मनी के दोनों भागों में और बर्लिन में स्वतन्त्र मतदान द्वारा विधान निर्मात्री सभा चुनी जाय और यह सभा एक केन्द्रीय जर्मन सरकार की स्थापना करे। यही सरकार विदेशी शक्तियों के साथ संधि करे और इसमें पोलैण्ड एवं रूस द्वारा हथियाने गये प्रदेशों का आन्तर्गत बंधारा हो। इसके विपरीत सोवियत रूस भी पहले ही के समान यही है कि पश्चिमी देश पूर्वी जर्मनी को एक प्रभुत्व सम्पन्न राज्य स्वीकार कर लें और फिर पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दोनों गणराज्य अपने एकीकरण के लिए परस्पर प्रत्यक्ष बातचीत करें। दोनों ही पक्षों की ओर से जर्मन एकीकरण के लिए रचनात्मक उपाय अपनाये जाने की अपेक्षा कूटनीतिक दावपेचों से उलझे हुए मुझाब पेन किये जाते हैं जिनसे समस्या का समाधान निकट भविष्य में होता दिखाई नहीं पड़ता।

(स) साम्यवादी चीन की माय्यता का प्रश्न

जॉनसन प्रशासन यह मानता रहा कि जिम लाल चीन ने आज तक हिंसा और युद्ध का सहारा लिया है, संयुक्त राष्ट्र संधि से युद्ध किया है,

तिब्बत की स्वतन्त्रता का बपहरण किया है और जो अमेरिका के विनाश की बात करता है, उसे सध में प्रवेश के योग्य एक शातिप्रिय राष्ट्र नहीं माना जा सकता तथा अमेरिका उसे मान्यता नहीं दे सकता। नव-निर्वाचन राष्ट्र-पति निकसन यद्यपि अधिक समझौतावादी प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं लेकिन लालचीन को मान्यता देने के प्रश्न पर उनके प्रशासन की नीति में अभी तक पूर्ववर्ती प्रशासन की नीति से कोई भिन्नता प्रकट नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र सध की महासभा ने ११ नवम्बर, १९६६ को साम्यवादी चीन को सार का सदस्य बनाने से १६वीं बार इन्कार कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका का मत चीन की सदस्यता के विरोध में पड़ा।

(ग) लैटिन अमेरिका और जानसन प्रशासन

जानसन प्रशासन के अन्तर्गत लैटिन अमेरिका अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बरकरार रखने की 'विवशता' के अभिभाव से ग्रस्त है। स्वर्गीय राष्ट्रपति कैंनेडी ने इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि के लिए मार्च, १९६१ में 'प्रगति के लिए मैत्री' (Alliance for progress) का कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, किन्तु जानसन प्रशासन इस कार्यक्रम को प्रभावशाली रूप में कार्य-न्वित करने में असफल रहा और उसकी मौलिक नीति यही रही कि राज-नीतिक प्रतिद्वन्द्वियों की भौगोलिक दूरी का लाभ उठाने हुए लैटिन अमेरिका को हर तरह से अमेरिकन प्रभाव क्षेत्र में रखा जाये। यह वास्तव में एक दुःखद तथ्य है कि आकार में भारत से चौगुना यह महाद्वीप उन सभी विषम-ताओं से पीड़ित है जिनसे कि अफ्रीका या दक्षिणी एशिया के देश। लगभग २५ करोड़ की आबादी वाले इस महाद्वीप के देशों की आर्थिक प्रगति के लिये अमेरिका के सत्वावधान में संगठित किया गया 'प्रगति के लिये मैत्री कार्यक्रम' अपने उद्देश्य को पाने में असफल ही रहा है। कई अरब डॉलर की आर्थिक सहायता इस रूप में प्रदान की गई है या इस सहायता कार्यक्रम को इस तरह लागू किया गया है कि इस महाद्वीप की आर्थिक समृद्धि बढ़ने की बजाय घटी ही है। अमेरिका के साथे में पलती तरीकी का हाल यह है कि इस महाद्वीप के ५-६ देशों में वामपंथी छाशमार गतिशील रहते हैं, हालांकि लैटिन अमेरिका रूस और चीन से हजारों मील दूर है। उधर अमेरिका चाहता है कि इन देशों के बाजार तो उसे मिलें लेकिन उसरी कम से कम कीमत चुकानी पड़े। इसने लिये राष्ट्रपति जानसन सैनिक प्रशासनों को भी उतना ही महत्व देने हैं जितना कि अनुदार अर्धनिक प्रशासनों को। स्वर्गीय श्री कैंनेडी क्यूबा से घोट टाकर नहीं चाहते थे कि लैटिन अमेरिका में साम्यवाद पनपे, लेकिन उनसे उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जानसन ने उदार नीति छोड़ कर सख्त रवैया

अपनाया। लेटिन अमेरिका के प्रति उनकी नीति “कथनी और करनी” के अन्तर की रही।

वियतनाम के सम्बन्ध में जानसन प्रशासन की नीति—वियतनाम पर आक्रामक रुख अपनाने का निर्णय राष्ट्रपति कैंनेडी के समय ही ले लिया गया था और जानसन के शासन काल में यह नीति उत्तरोत्तर उग्र होनी गई। वियतनाम युद्ध पर विस्तार से प्रकाश ‘वियतनाम युद्ध एवं पश्चिमी एशिया का संकट’ नामक अगले अध्याय में डाला गया है। महा इतना ही जान लेना काफी है कि अगस्त, १९६४ से ही अमेरिका अपनी विशाल सैनिक शक्ति के साथ वियतनाम युद्ध में कूद पड़ा और यह युद्ध हनोई तथा वाशिंगटन का युद्ध बन गया। युद्ध में अमेरिका को प्रारम्भिक सफलता भले ही मिली हो, किन्तु बाद में उसे अनेक भीषण और अपमानजनक पराजयों का सामना करना पड़ा। वियतनाम युद्ध के प्रति अमेरिकी जनता का आक्रोश और विश्व जनमत का दबाव बढ़ गया। २१ मार्च, १९६१ को जानसन ने राष्ट्र के नाम अपने एक सन्देश में घोषणा की कि वियतनाम में शान्ति-वार्ता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्तरी वियतनाम पर बम बारी सीमित करने के आदेश दे दिये गये। राष्ट्रपति ने साथ ही यह भी घोषणा की कि वह आगामी चुनावों में राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी नहीं बनेंगे। सीमित बम-बारी का उनका निर्णय वियतनाम से अमेरिका को समाविष्ट वापसी का पहला लक्षण था जो वर्तमान निरन्तर प्रशासन में स्पष्ट है साकार रूप में प्रकट होगा। जानसन ने अपने शासन के शेष काल में वियतनाम के प्रति सहिष्णुता की नीति से काम लिया।

(४) कोरिया और प्सेवलो संकट—राष्ट्रपति आइज़नहोवर के समय की ‘अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदारी’ की नीति को जानसन ने न केवल जारी रखा बल्कि उसका कार्य क्षेत्र और भी बढ़ा दिया। इस नीति ने शीघ्र ही एक ऐसा संकट पैदा कर दिया जिसमें अमेरिका को बड़ा अपमानित होना पड़ा। अमेरिका के एक जासूसी पोत प्सेवलो को २३ जनवरी, १९६८ को उत्तरी कोरिया ने अपनी प्रादेशिक जल-सीमा में पकड़ लिया और जहाज पर स्वार ८३ व्यक्तिओं को हिरासत में ले लिया। अमेरिका जैसी महाशक्ति के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पोत को हिरासत में ले लेना अमेरिका का अपमान था और उसकी विदेश नीति पर एक करारी चोट थी। उत्तरी कोरिया ने यह निश्चय भी प्रकट कर दिया कि पोत पर पकड़े हुए अमेरिकी जासूसों पर मुकदमा चला जायेगा। जानसन प्रशासन ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि प्सेवलो ‘गुप्तना समुद्र का सहायक पोत’ था जिसे जापान सागर में समुद्र

सट से २५ मील दूर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पकड़ा गया है। जानसन प्रशासन ने चुनौती दी कि उत्तरी कोरिया की सरकार अवैध रूप से पकड़े गये पोत को छोड़ दे। इतना ही नहीं अमेरिका ने उत्तरी कोरिया को मयमोत करने के लिए विशाल पैमाने पर मैनिक संधारिया की ओर दक्षिण कोरिया में अमेरिका के लगभग ५५ हजार मैनिक युद्ध के लिए तैयार हो गये। अमेरिकन वायु सेना और नौ-सेना को भी युद्ध पर जाने के लिए आदेश दे दिये गये। उत्तरी कोरिया इन कार्यवाहियों से मयमोत नहीं हुआ। उसने जामूसी पोत वापस करने से इनकार कर दिया और यह भी कह दिया कि संयुक्त राष्ट्रमण्डल का कोई भी प्रस्ताव उसे मान्य नहीं होगा।

अब अमेरिका के सामने दो ही मार्ग रहे—युद्ध या समझौता। सोभायवरा जानसन प्रशासन ने दूसरा मार्ग ही अपनाया। सोवियत प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया कि यदि अमेरिका अपनी गलती के लिए माफी माग लेता तब वेबलों को रिहा किया जा सकता है, और तब अमेरिकन विदेश सचिव डीन रस्क ने कूट-नीतिक भाषण में अपनी गलती कबूल करते हुए कहा कि अमेरिकन पोत 'मूल से उत्तरी कोरिया के प्रादेशिक जल में भटक गया था।' इस स्वीकारोक्ति के बाद उत्तरी कोरिया ने वेबलों को छोड़ दिया।

(घ) जानसन प्रशासन और पश्चिमी एशिया का संकट—जून, १९६७ में पश्चिम एशिया में जो महान संकट उत्पन्न हुआ उसके प्रति जानसन प्रशासन की नीति बड़ी अदूर-दर्शितापूर्ण रही। इस संकट का सविस्तार उल्लेख हमले एक अध्याय में किया गया है। जानसन प्रशासन ने पूर्णतः अरब विरोधी रणनीति अपनायी और इजरायली आक्रमण की योजना तैयार करने में भी सहायता दी। वास्तव में जानसन प्रशासन की नीति ने पश्चिमी एशिया के संकट को तीव्र किया। यदि अमेरिका दूर-दर्शिता से काम लेता तो इजरायल और अरब राज्यों के बीच घनघोर युद्ध नहीं छिड़ता।

जब अरब इजरायल संधि छिड़ गया तो पहले तो जानसन इस बात से अनभिज्ञता प्रकट करता रहा कि आक्रमणकारी कौन है। बाद में उसने सुरक्षा-परिषद् में तथा बाहर पूर्णतः पक्षपातपूर्ण रवैया अपनायी और इस बात का विरोध किया कि आक्रमणकारी इजरायली सेनाएँ वापस लौटें। अरब-इजरायल संधि में जानसन प्रशासन की नीति स्वयं अमेरिकी हिन्दी के भी अनुकूल नहीं थी। अमेरिका ने अरब राज्यों की नाराजगी मोत ले ली। अरब देशों ने अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये और अपने देश में रहने वाले अमेरिकन नागरिकों का वापस चने जाने के आदेश

दे दिये। जानसन प्रशासन ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इजरायल को इतना प्रोत्साहन दिया कि वह पूर्णतः स्वेच्छाचारी आचरण पर उतर आया और अन्त में जानसन प्रशासन के लिए भी उसे वास्तव में बर्बाद कर समर्पण देना कठिन हो गया। २५ दिसम्बर, १९६८ को बेरुत हवाई अड्डे पर इजरायली वायु आक्रमण की सम्पूर्ण विश्व में निन्दा की गई। विश्व जनमत के रवये से बाध्य हो कर जानसन प्रशासन को भी इजरायली कार्यवाही की कटु आलोचना करनी पड़ी।

यद्यपि सोवियत रूस का रवैया भी पूरी तरह अरब पक्षपाती रहा, लेकिन सकट का समाधान करने के लिए उसका रुख इतना अडिग नहीं था जितना जानसन प्रशासन का। इसके अतिरिक्त इजरायल को मुद्द के लिए उक्साने में भी जानसन की नीति अधिक बजनी सिद्ध हुई।

राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की विदेश नीति

राष्ट्रपति जानसन अपने वायदे के अनुसार दुबारा राष्ट्रपति पद के लिए लड़े नहीं हुए और रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। २० जनवरी, १९६९ को वह समुक्त राज्य अमेरिका के ३७वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपने उद्घाटन-भाषण में अपनी शानि प्रियता की दुहाई दी। उन्होंने विश्व को विश्वास दिलाने की चेष्टा की कि उनके नेतृत्व में समुक्त राज्य अमेरिका विश्व शांति स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करेगा और इन प्रयासों में अन्य राष्ट्रों से सान्नेदारी के लिए तैयार रहेगा। नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमें प्रत्येक से मैत्रीभाव विकसित करने चाहिए। यद्यपि हम हर एक को अपना मित्र नहीं बना सकते, लेकिन हम यह प्रयत्न जरूर कर सकते हैं कि हमारा कोई शत्रु भी न हो।

राष्ट्रपति निक्सन ने पद ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही यूरोप की सद्भावना यात्रा की तैयारी की।

(क) यूरोप की सद्भावना यात्रा—२३ फरवरी, १९६९ को वह यूरोप की आठ दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। निक्सन विद्यमान और पश्चिमी एशिया के सबूट के बारे में तथा विश्व की अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में यूरोप के देशों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते थे। ब्रिटेन में राष्ट्रपति निक्सन और प्रधानमंत्री विंस्टन में ब्रिटेन अमेरिका सम्बन्धी, पूर्वी पश्चिमी समस्याओं, नाटो, साक्षात् बाजारों आदि के बारे में सम्वी बातचीत हुई। फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और रोम में राष्ट्रपति निक्सन की यात्रा पर कोई विशेष उत्साह प्रदर्शित नहीं हुआ। पश्चिमी जर्मनी में

संगु प्रसार विरोध सन्धि पर चासलर कीसिन्जर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुए। वास्तव में यूरोप की इस यात्रा के दौरान बेल्जियम की छोड़कर राष्ट्रपति निरमन जहाँ भी गए, अमेरिका विरोधी नारे भी उनके पीछे लगे रहे।

यद्यपि यूरोप की सम्भावना यात्रा का कोई विशेष महत्व नहीं निकला लेकिन राष्ट्रपति निरमन को यूरोपीय समस्याओं के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त हुई और उन्हें यह पता चल गया कि शीत युद्ध की उभारने में पश्चिमी यूरोपीय राज्यों का संयुक्त राज्य अमेरिका को अब पूरा-पूरा समर्थन नहीं मिल सकेगा। राष्ट्रपति निरमन को यह अहसास हो गया कि पश्चिमी यूरोप के राज्य अब पूरी तरह अमेरिका के पिछलग्गू नहीं रहना चाहते।

(ख) वियतनाम समस्या के प्रति दृष्टि—राष्ट्रपति 'निरमन ने वियतनाम समस्या के प्रति व्यावहारिक रुख अपनाते हुए प्रारम्भ से ही ऐसे प्रयास शुरू कर दिये कि पेरिस में चल रही शांति-व्यवस्था में प्रगति हो सके और वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो सके। धीरे धीरे किन्तु दृढ़ता से उन्होंने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिये कि अन्ततः वियतनाम युद्ध टूट-पड़ने-पड़ने समाप्त हो जाए। निरमन ने न केवल बम-बारिश को बंद कर दिया बल्कि बड़ी संख्या में समयांतर से अमेरिकन सैनिकों को भी स्वदेश लौटा लिया और साथ ही वियतनाम में अमेरिका की तकनीकी सामरिक सक्ति को भी इस ढंग से बनाये रखा कि उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पर हावी न हो सके। मई, १९६९ में वियतनाम से ५० हजार अमेरिकन सैनिक वापस बुलाने का निर्णय किया गया। शांति स्थापना के लिए एक सात मूखीय प्रस्ताव भी रखा गया जिसे हनोई ने स्वीकार नहीं किया। १९६९ के वर्ष के अन्त तक इस बात की पर्याप्त सम्भावना प्रबल हो गई और निरमन प्रशासन ने बड़ी संख्या में अमेरिकन सैनिकों को वारिष्ठ स्वदेश बुलाना शुरू कर दिया।

निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहिये कि निरमन प्रशासन के व्यावहारिक और समझौतावादी रुख तथा हनोई की अनुकूल प्रतिक्रिया के कारण वियतनाम युद्ध के समाप्त होने की आशा बलवती हो गई है। यद्यपि पूर्ण सफलता-असफलता का निर्णय तो भविष्य ही करेगा लेकिन रतमान आसार यही है कि निरमन भविष्य में ही यह सूनी हवाकाण्ड बन्द हो जायेगा।

(ग) पश्चिमी एशिया के संकट के प्रति निरमन की नीति—निरमन

प्रशासन की पश्चिमी एशिया के सकट के प्रति नीति अभी तक जानसन्-प्रशासन के एक पक्षीय रुख से कोई अधिक भिन्न नहीं है। ३ अप्रैल, १९६६ को चार बड़े राष्ट्रों की जो बातें न्यूयार्क में हुई, उसे सफलता विरोधतः इसी कारण नहीं मिल सकी कि निक्सन प्रशासन का रुख एकदम अरब विरोधी और इजरायली समर्थक रहा। यह वास्तव में दुख की बात थी कि निक्सन प्रशासन ने उस सीमा-रेखा को भी मानने से इन्कार कर दिया जहाँ तक इजरायली सेना को हटाने के लिये कहा जा रहा था। इतना ही नहीं, मिस्री इलाके में तो विसंन्याकरण की बात बही गई लेकिन इजरायली इलाके के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

पश्चिमी एशिया का यह सकट, जिस पर सविस्तार अगले एक अध्याय में प्रकाश डाला गया है, तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस जैसी महाशक्तियाँ समस्या के प्रति निष्पक्ष होकर ईमानदारी से शांति स्थापना का प्रयत्न नहीं करेंगी।

(घ) उत्तरी कोरिया में अमेरिकी जामूसी-‘अन्तर्राष्ट्रीय चौकीदार’ की हिमायत निक्सन प्रशासन ने पहले ही की भाँति जारी रखी है। निक्सन प्रशासन के समय भी अप्रैल, १९६६ में एक भयंकर जामूसी काण्ड हुआ। उत्तरी कोरिया ने अमेरिका के एक जामूसी विमान ई सी १२१ को मार गिराया। यह जहाज उत्तरी कोरिया की सीमा में घुसकर जामूसी कर रहा था। अमेरिका ने पहले तो कहा कि विमान उत्तरी कोरिया की सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ था और बाद में यह घोषणा करके अपनी असलियत दिवा दी कि दक्षिण कोरिया और प्रशान्त महासागर में अमेरिकन हितों की रक्षा के लिए तथा उत्तरी कोरिया की सैनिक तैयारी को जानने रहने के लिए यह आवश्यक है कि अमेरिका इस प्रकार की जामूसी कार्यवाहियाँ करे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने विशाल नौ सैनिक बड़े को भी उत्तरी कोरिया के निकटवर्ती समुद्र में एकत्र कर लिया ताकि भविष्य में जामूसी हवाई उड़ानों को निषिद्ध जारी रखा जा सके। एक स्वतन्त्र राष्ट्र के प्रति निक्सन प्रशासन का यह रुख निश्चित रूप से आश्रामक कहा जाएगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का मूल्यांकन

संयुक्त राज्य अमेरिका की द्वितीय महायुद्धोत्तर विदेश नीति का उपरोक्त विस्तृत वर्णन हमारे समक्ष अमेरिकन विदेश नीति के मूल तत्वों का स्पष्टीकरण देता है। इस विवेचना से कुछ स्पष्ट निष्कर्ष निकलने हैं। प्रमुख बात तो यही है कि अमेरिकन विदेश नीति में उपनिवेश विरोधी

अथवा साम्राज्य विरोधी तत्वों को कभी विशेष महत्व नहीं दिया गया है बल्कि स्वयं अमेरिका ने आर्थिक व सैनिक सहायता की नीति द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया है। लंडन अमेरिकन देश और सुदूरपूर्व स्पष्टतः ऐसे ही क्षेत्र हैं जहाँ अमेरिकन साम्राज्यवादी आकांक्षाओं ने अपना खेल खेला। यही कारण है कि स्वर्गीय पटित नेहरू अमेरिकन विदेश नीति को 'अदृश्य साम्राज्य बनाने की नीति' कह कर उसकी आलोचना करते थे। यह ठीक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में कहीं कोई उपनिवेश नहीं है और उसने युद्धोपरान्त अपने उपनिवेश फिलिपाइन्स को भी मुक्त कर दिया है, किन्तु विश्व भर में फंसे हुए अमेरिका के सैनिक बड़े और उसके असमान व्यापारिक सम्बन्ध ये प्रबल साधन हैं जिनके माध्यम से उसने विभिन्न देशों की आर्थिक व्यवस्था को अपने नियन्त्रण में कर रखा है। अमेरिका से असमान आर्थिक और सैनिक संधियां होने के कारण सम्बन्धित देशों को वही काम करना पड़ता है जो अमेरिकन प्रशासन को मंजूर होता है।

मध्यपूर्व के तेल को अपने अधिकार में रखने के लिए ही अमेरिका ने वहाँ की राजनीति में सुलुकर हस्तक्षेप किया है। दृढ़तः सिद्धान्त, आइज़नहोवर सिद्धान्त आदि तो इस हस्तक्षेप को उचित ठहराने के आवरण या प्रयास मान हैं। सुदूरपूर्व और दक्षिणी-पूर्वी एशिया में अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिए ही उसने चीन में च्यांगकाई-जेक, दक्षिणी कोरिया में सिङ्गमन-री और दक्षिणी वियतनाम में दायोसाई के भ्रष्ट शासन को सुलासमर्थन दिया है। लंडन अमेरिका ने फासिस्ट और अर्द्ध फासिस्ट शासनतन्त्र उसी के समर्थन से आज तक कायम हैं। विश्व में स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व लेने वाले अमेरिका ने स्पेन में फ्रांको तथा पाकिस्तान में अयूब के तानाशाही शासनो के साथ पूर्ण सहायुभूति दर्शायी है जबकि स्वतन्त्रता और शांति प्रेमी भारत के प्रति कटुता चालबाजी और पक्षपातपूर्ण रवैया रखा है। काश्मीर पर उसका दब और पाकिस्तान को दिये जाने वाले पैटन डेक और सैंडर जेट इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी जर्मनी का पश्चिमीकरण करके और उसे आणविक आयुधों से सुसज्जित करके अमेरिका ने सोट्सडम निर्णयों के प्रतिकूल आचरण किया है। वियतनाम युद्ध में अपनी दानवी पक्षि का प्रयोग कर के विश्व शांति को उसने खंड में डाल रखा है। सधार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रादेशिक सैनिक सफ़टनों की स्थापना उसने यह कह कर की है कि इनसे अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सकेगा। परन्तु इन सैनिक सफ़टनों की स्थापना के कारण साम्यवाद की लोकप्रियता को तो कोई विशेष आपात नहीं पहुँचा, उल्टे अमेरिका की प्रतिष्ठा ही समूचे संसार

में और विशेषकर एशिया तथा अफ्रीका के महाद्वीपों में पूर्वदिशा कहीं अधिक कम हुई है। और हो और, उसके पुराने छापी भी उसकी नीति से ऊब कर उसके चंगुल से निरलने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रान्स इसका ज्वरित प्रमाण है। एशिया में अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा जाघात लगा है। स्वयं एक अमेरिकन लेखक ने लिखा है कि "आज एशिया में सभ्यत राज्‍य अमेरिका की पहचान स्वतन्त्रता के प्रतीक के रूप में नहीं अपितु बन्दूकी से होती है।"

आज लगभग सम्पूर्ण ससार इन दोनों पक्ष या गुटों में विभक्त है और इनके 'शीत-युद्ध' ने विश्व को एक तृतीय महायुद्ध के विस्फोट के निकट ला दिया। यदि समय रहते इस पर नियन्त्रण न हुआ तो यह एक न एक दिन 'व्यावहारिक युद्ध' को जन्म दे डालेगा। यह (शीत-युद्ध) एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों पक्ष परस्पर शान्तिकालीन कूटनीतिक सम्बन्ध बनाये रखते हुए भी परस्पर शत्रुभाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति को दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह एक कूटनीतिक युद्ध है, जो व्यावहारिक युद्ध का जनक हो सकता है।

इस 'शीत युद्ध' में अमेरिका साम्यवाद को स्वतन्त्रता और विश्व शांति का शत्रु बताते हुए रूस के प्रभाव के विस्तार को रोकने का प्रयत्न करता है और हमरी ओर पूर्वो यूरोपीय देशों में हुए राष्ट्रीय विद्रोहों के आधार पर रूस को एक साम्राज्यवादी शक्ति बताता है तो रूस पश्चिमी शक्तियों को उपनिवेशवादी घोषित करते हुए साम्यवाद को एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों के लिए तथा विश्व की दीन हीन जनता के लिए एक रामघाण औषधि के रूप में प्रस्तुत करता है। दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रभाव के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए अपनी अपनी सैद्धांतिक मान्यताओं पर बल देते हैं तथा आर्थिक सहायता, प्रचार, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक गुटबंदियों, प्रादेशिक संगठनों, समुदाय राष्ट्र, सघ, सस्त्रीकरण, वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति का प्रदर्शन आदि सभी सम्भव साधनों का प्रयोग करते हैं। अपने प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे जाति और वर्गगत द्वेष को भड़काने, राष्ट्रीय भावनाओं का दुरुपयोग करने, औद्योगिक असंतोष व स्थानीय सघर्षों को प्राप्ताह्न देने आदि के सभी हीन उपायों का आश्रय लेते हैं। वे दरिद्रता, भुखमरी आदि मानवीय दुर्भाग्यों का लाभ उठाने में भी नहीं हिचकिचाते।

शीत-युद्ध का प्रारम्भ, कारण और इतिहास

महायुद्धोत्तर स्थिति ने दोनों महाशक्तियों के मध्य जिस शीत युद्ध को जन्म दिया, उसने याल्टा-सम्मेलन से लौटने वाले प्रतिनिधियों के विचारों को व्यक्त करने वाले हैरी हॉपकिंस (Harry Hopkins) के इन शब्दों को झूटला दिया कि—“हम वस्तुतः अपने हृदय में यह विश्वास था कि यह एक नूतन दिवस का नया दृश्य था जिसके लिए हम इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहे थे। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि हमने शान्ति की प्रथम-चिन्म प्राप्त कर ली है।” रूस वासियों ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे युक्ति-युक्त और दूरदर्शी हो सकते हैं तथा हम भविष्य में जहाँ तक सोच सकते हैं

यहाँ तक उनके साथ शान्तिपूर्वक रह सकते हैं और चल सकते हैं।¹ अब अमेरिका के नेतृत्व में पाश्चात्य राष्ट्रों ने रूस पर गालियों और आरोपों की बौछार करना शुरू किया और उधर रूस ने उन पर आलोचना एवं प्रत्या-रोपण की झड़ी लगा दी। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे को शत्रुतापूर्ण मनो-भावना और सदेहपूर्ण प्रवृत्तियों से भरा सिद्ध करने के लिए अपने-अपने तर्क पेश किये। यहाँ हम, शीत युद्ध के कारणों को बताते हुए, दोनों ही पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों का पृथक्-पृथक् रूप से वर्णन करेंगे।

(क) 'पश्चिम' की 'पूर्व' के विरुद्ध शिकायतें

अमेरिका के नेतृत्व में पाश्चात्य शक्तियों ने सोवियत मध्य के विरुद्ध महत्वपूर्ण शिकायतें प्रस्तुत की अथवा उरा पर जो विभिन्न प्रमुख आरोप लगाए, वे इस प्रकार हैं—

(१) रूस द्वारा पाल्टा समझौतों की अवहेलना—ब्रिटेन और अमेरिका की रूस के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिकायत यह थी कि उसने पाल्टा-समझौतों का पूर्ण उल्लंघन किया है। फरवरी १९४५ में रूजवेल्ट, चर्चित और स्टालिन ने कुछ समझौते किये थे, उदाहरणार्थ जर्मनी को चार 'आधिपत्य क्षेत्रों' (Occupation Zones) में विभाजित किया जायगा, 'पोलैण्ड में सोवियत मध्य द्वारा सुरक्षित 'लुबलिन सरकार' और पश्चिमी देशों द्वारा सुरक्षित 'लन्दन सरकार' के स्थान पर स्वतन्त्र चुनाव किये जाकर एक प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना की जायगी, नये पोलैण्ड से उसके पूर्व में स्थित रूसी भाषा-भाषी प्रदेश वर्जिन-रेखा के आधार पर पृथक् कर दिये जायेंगे, परन्तु पश्चिम में उसे मुआवजे के रूप में कुछ जर्मन-भूमि दी जायेगी। सोवियत रूस द्वारा यह भी वचन दिया गया था कि वह "बाह्य मंगोलिया" में 'पूर्व स्थिति' (Status quo), दक्षिणी सुस्तालिन तथा कुराईत द्वीपों पर रूसी स्वामित्व, दारैन का अन्तर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of Dairen), पोर्ट आर्थर में एक रूसी नौसैनिक बड्ढे की स्थापना तथा एक चीनी-रूसी कम्पनी द्वारा मन्चूरियन रेलवे के समुक्त-संचालन की शर्तों के साथ जर्मनी के आत्म समर्पण के दो तीन महीने बाद जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाएगा। स्टालिन ने यह भी कहा था कि वह चीन की 'राष्ट्रवादी' सरकार को ही वैध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

1. Sherwood, Robert. Roosevelt and Hopkins Vol II, P. 516.

लेकिन रुस द्वारा याहटा-समझौते की उपेक्षा की गई। राष्ट्रपति रुजवेल्ट की मृत्यु के बाद अप्रैल, १९४५ में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने हैरो होपकिंस को माहको यह सूचित करने के लिए भेजा कि उसका राष्ट्र (अमेरिका) रुजवेल्ट की नीतियों को निर्यान्वित करने पर कटिबद्ध है। प्रत्युत्तर में स्टालिन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि सोवियत नव भी याहटा-समझौते के पालन से पीछे नहीं हटेगा।

रुस ने उपरोक्त आश्वासन भले ही दे दिया, परन्तु उसकी नीति याहटा-समझौते का पालन करने की न थी। उसने अनेक ऐसी कार्यवाहियाँ की जिनसे पश्चिमी राष्ट्रों को यह स्पष्ट हो गया कि रुसी दृष्टिकोण में याहटा-समझौता रद्दी कागजों के ढेर के अलावा कुछ नहीं है—

(i) रुस ने पोलैण्ड में स्वतन्त्र चुनावों पर आधारित एक प्रतिनिधिक सरकार की स्थापना करने की अपेक्षा पोलिश जनता पर अग्ने द्वारा मरक्षित 'लुबनिन-सरकार' (Lublin Government) को लादने का प्रयत्न किया। इस कठगुल्लो 'लुबनिन सरकार' अथवा 'Polish Committee of National Liberation' की स्थापना दिसम्बर, १९४१ में रुसी भूमि पर की गई थी और २५ अप्रैल, १९४३ को रुस ने प्रजासत्ता पोलिश सरकार से सम्बन्ध तोड़ कर २६ जुलाई, १९४४ को लुबनिन सरकार से जोड़ दिये थे।

रुस ने न केवल लुबनिन सरकार को पोलिश जनता पर लादा ही बल्कि देश के अन्य प्रजातन्त्रीय दलों को गिरफ्तार भी कर लिया। पोलैण्ड के कैटिन (Katyn) वन हत्याकांड में ४ हजार गैर साम्यवादी पोलों का लाल सेना द्वारा सकाया कर दिया गया। यह आशंका भी की जाती है कि संभवतः ११ हजार अन्य लापता पोलों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया होगा।^१ जब अमेरिकन और ब्रिटिश प्रेसकी ने पोलैण्ड में प्रवेश करना चाहा तो इसकी उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

रुस की लाल सेना द्वारा पूर्वी यूरोप में साम्यवादी दलों के प्रावधान और विरोधी तात्वों के विध्वंस ने मित राष्ट्रों को बड़ा चिन्तित बना दिया और रुस के प्रति गहरी आशंका व सन्देह का वातावरण उनके मन-मानस में पुष्ट हो गया।

(ii) हंगरी, बल्गेरिया, रूमानिया और चोस्कोवाकिया में भी रुस द्वारा युद्ध विराम समझौतों तथा सन्धि व पाश्चात्य गुप्तचरों का उन्मूलन

किया गया। रूस द्वारा मित्र राष्ट्रों के साथ पहले यह निश्चय किया गया था कि — “नाज़ियों से मुक्त किए गए राष्ट्र अपनी इच्छानुसार सौनतन्त्रीय मस्या चुनें और इसके लिए मित्र राष्ट्रों के बीच सम्मिलित विचार-विनिमय किया जायगा।” परन्तु रूस ने इस पूर्व निश्चय को ठुकराते हुए पूर्वी यूरोप के इन सभी देशों में प्रजातन्त्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इन्कार कर दिया और इन देशों के जनमत तथा पश्चिमी राष्ट्रों के विरोध की पूर्ण अवहेलना करते हुए वहाँ रूस समर्थक सरकारें स्थापित कर दीं।

रूस द्वारा गाल्डा और पोर्ट्समथ समझौतों को इन सुली अवहेलना और उसके बड़ो हुए प्रभाव ने पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति सन्देह भावना को और भी बढ़ाया।

(111) सन् १९४४ के मध्य साम्यवादी सेना बाल्कन प्रदेश में प्रविष्ट हो गई। इस पर चर्चिल को आशंका हुई कि रूस सामरिक महत्व के इस सम्पूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेगा। अतः १९४४ में ही उसने स्टालिन के साथ पूर्वी यूरोप के विभाजन के प्रश्न पर यह निर्णय किया कि रूस को बल्गेरिया व रमानिया पर छाये रहने की अनुमति होगी और ब्रिटेन को ग्रीस में इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। यह निश्चय किया गया कि हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों ही देशों का समान प्रभाव माना जायगा। चार्ल्स स्पीयर के कथनानुसार, चर्चिल के मत में यह व्यवस्था “तत्कालीन युद्ध-साम्यन्धी परिस्थिति का नियोजन थी और इसमें पूर्ण समझौते की कोई आशा उन्हें प्रतीत नहीं होती थी।”¹ पश्चिमी देशों के लिए यह स्थिति बड़ी चिन्ता जनक और भय तथा आशंका से परिपूर्ण बन गई कि जर्मनी द्वारा आत्म-समर्पण किये जाने से पूर्व ही रूसी फौजों ने ग्रीस के उत्तर में अधिकांश पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर अपना नियन्त्रण जमा लिया, जनता पर साम्यवादी सरकार घोष की और कुछ ही वर्षों में ग्रीस और बाल्टिक सागर के बीच गुरुद धमिल तानाशाही राज्य स्थापित हो गये।

(112) सोवियत रूस की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्रराष्ट्रों को साइबेरिया-अङ्ग्रेजी की सुरक्षा प्रदान करने में हिचकिचाहट ने भी पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति सन्देह और शंका को बढ़ाया। रूस ने जापान के विरुद्ध युद्ध-घोषणा तभी की जब अमेरिका द्वारा प्रथम अणुबम के प्रहार से जापान की पूर्ण पराजय एतदग मुनिश्चित व सन्निकट हो गई। साइबेरियाई अङ्ग्रेजी की सुरक्षा मित्रराष्ट्रों में इसलिए चाही थी कि इससे प्रभावित सागरीय युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाने में सहायता मिलेगी।

(113) पश्चिमी देश रूस की इस चाल से भी बड़े दुःख हुए कि जब

ब्रिटिश अमेरिकन अधिकारी इटली में जर्मन सेनाओं के आत्मसमर्पण के बारे में एक जर्मन सेना से बातें कर रहे थे तभी स्टालिन ने रुजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन पर और चर्चिल पर इस प्रकार का आरोप लगाया कि ब्रिटिश-अमेरिकन अधिकारियों का जर्मन सेनापति से वार्ता का आशय यह है कि रूसी सेनाओं के बर्लिन पहुँचने से पूर्व ही आर्य प्रमरोकी सेनाएं उस पर कब्जा कर लें।

(vi) सोवियत रूस द्वारा चीन में भी याल्टा-समझौते की गंभीर अवहेलना की गई। मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने सन् १९४६ के प्रारम्भ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहाँ प्रवेश कर नष्ट करने दिया जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश-सम्बन्धी सभी सुविधाएँ देते हुए वह सम्पूर्ण युद्ध सामग्री भी सौंप दी, जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी।

(२) रूसी सेनाओं का ईरान से न हटाया जाना—१९४२ में एक समझौते द्वारा यह निश्चित हुआ था कि युद्ध के दौरान जिन विदेशी सेनाओं ने ईरानी प्रदेश में प्रवेश किया था उन्हें जर्मनों द्वारा आत्मसमर्पण के अधिकतम ६ माह बाद वहाँ से हटा लिया जायगा। युद्ध के उपरान्त एंग्लो-अमेरिकन फौजें दक्षिणी ईरान से हटा ली गयीं, लेकिन रूसी फौजें उत्तरी ईरान में ज्यों की त्यों जमी रही। इतना ही नहीं, रूस ने इस उत्तरी क्षेत्र में साम्यवादी पार्टी को समर्थन देकर जाति करवाने का प्रयत्न भी किया। यद्यपि बाद में, काफी प्रयासों और संयुक्त राष्ट्र सचोय हस्तक्षेप के बाद, रूसी फौज ईरान से हटा ली गयी, किन्तु यह घटना पारस्वत्य राष्ट्रों के सन्देह और अविश्वास को पनपाने में सहायक हुई।

(३) टर्की पर रूसी दबाव—युद्ध की समाप्ति के तुरन्त बाद रूस ने टर्की से कुछ भू-प्रदेश एवं बस्फोरस (Bosphorus) में सैनिक अड्डे निर्मित करने के अधिकार की मांग की। इन प्रदेशों पर प्रभुत्व पाने के लिए वह टर्की पर प्रभाव डालने और उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा। पश्चिमी राष्ट्रों ने रूस के इस कदम को सर्वथा अनुचित बताते हुए अपनी नाराजगी प्रकट की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे यह चेतावनी दी कि यदि उसने टर्की पर आक्रमण किया तो यह विषय सुरक्षा परिषद् में देश किया जायगा। मूनान और टर्की की घटनाओं के कारण ही अमेरिका ने इन देशों को अपनी सुरक्षा हेतु जापिक सहायता देना प्रारम्भ किया।

(४) रूस का अमेरिका-विरोधी 'प्रचार-अभियान'—साम्यवादी पत्रों ने युद्ध समाप्त होने के कुछ समय पूर्व से ही, अमेरिकन नीतियों और नीति-निर्माताओं के विरुद्ध विषममन करना शुरू कर दिया। साम्यवादी पत्रों 'प्रावदा' और 'इजवेस्तिया' में अमेरिका के प्रति घोर आलोचनात्मक

लेख प्रकाशित होने लगे। इस 'प्रचार-अभियान' से अमेरिका के सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बड़ा विशोभ फैला। यद्यपि यह प्रमाणित नहीं हो सका कि इस आलोचना को प्रोत्साहन देने के पीछे हेमलिन का हाथ था, किन्तु इसने भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि यदि किसी अधिकारी चाहें तो ऐसी अवांछित आलोचनाओं को रक्वा सकते थे। अमेरिकन राष्ट्र इस बात को भली भाँति समझता था कि इस प्रचार का उद्देश्य एतिया एव अफ्रीका की जनता की दृष्टि में अमेरिका को बदनाम करना था।

(५) रूस द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना—युद्ध काल में जर्मनी के हाथों सर्वाधिक जन घन की हानि रूस को उठानी पड़ी। याल्टा-सम्मेलन में स्टालिन ने माग की कि जर्मनी से क्षति-पूर्ति स्वरूप रूस को १० बिलियन डॉलर दिलाये जायें। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रूस की माग को 'अग्रिम वार्ता के आधार के रूप में' स्वीकार कर लिया। परन्तु स्टालिन ने इसका अर्थ यह लगाया कि उसकी माग अन्तिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। अतः यद्योपरान्त उसने जर्मनी उद्योग को खण्डित विखण्डित करते हुए मूल्यवान् मशीनों का स्थानान्तरण रूस में करना शुरू कर दिया। रूस के इस कार्य से पहले ही से अस्त-व्यस्त जर्मनी आर्थिक व्यवस्था पर अतिरिक्त रूप से भारी बोझ पड़ा। ब्रिटेन और अमेरिका में रूस की इस कार्यवाही से काफी विशोभ फैला गया और साथ ही उन्हें विवश होकर जर्मन अर्थ व्यवस्था की सहायतायें प्रदान करना पड़ा।

रूस ने जर्मनी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के भी अनेक गम्भीर उल्लंघन किये—

(i) १ अगस्त १९४५ के पोर्टस्मथ समझौते तथा मित्र राष्ट्रीय नियन्त्रण परिषद् (Allied Control Council) के वाद के निर्णयों में यह निर्दिष्ट हुआ था कि जर्मनी जनता को कुछ आधारभूत व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतन्त्रताओं से वंचित नहीं किया जायगा। लेकिन सोवियत संघ ने अपने द्वारा अधिभूत जर्मनी क्षेत्र के हजारों व्यक्तियों को कंठ बरके रूस भेज दिया या बन्दी शिवरों में डाल दिया।

(ii) पूर्वी जर्मनी की जनता को पश्चिमी जर्मनी की जनता से एकरूप प्रयत्न कर दिया गया।

(iii) अप्रैल, १९४६ में रूसियों ने जर्मनी समाजवादी दल की बल-पूर्वक साम्यवादी दल में दसलिये मिला दिया कि बर्लिन और पूर्वी क्षेत्र के समाजवादी मन्त्रालयों को अपने काबू में रखा जा सके।

(iv) पोद्सडम संधि में यह निर्दिष्ट हुआ था कि जर्मनी को एक पृथक् वार्षिक इकाई माना जायगा और सभी आवश्यक पदार्थों का विविध क्षेत्रों में समान वितरण किया जायगा। लेकिन रूस ने अप्रैल, १९४६ में स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि प्रत्येक क्षेत्र अपना व्यापार स्वयं करे। इसके अतिरिक्त फिनलैंड, पूर्वी आस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और रूमानिया में जर्मनी की जो सम्पत्ति 'German External Property Commission' के अधिकार में रखी गई थी उसका रूस ने स्वयं उपयोग किया।

(v) २६ नवम्बर, १९४४ का प्रकाशित लंदन-प्रोटोकॉल नामक समझौते में युद्धोत्तर बर्लिन की प्रशासन व्यवस्था के बारे में कहा गया था कि बर्लिन पर अस्थाई रूप से अधिकार करने वाली शक्तियों को बर्लिन-प्रवेश का मार्ग प्राप्त होगा। परन्तु जून १९४८ में सोवियत संघ ने बर्लिन की कुख्यात नाके-बंदी का दौर चलाया और पश्चिमी बर्लिन तथा पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जन यातायात की बंद कर दिया। यही नहीं, रूस ने हजारों जर्मन-युद्ध बंदियों और नागरिकों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया।

(vi) याल्टा समझौते और पोद्सडम-प्रोटोकॉल दोनों में ही यह तय किया गया था कि जर्मनी-पोलैंड सीमा का निर्णय जर्मनी के साथ पूर्ण निपटारे तक ठठा रखा जाये। लेकिन रूस ने इस समझौते का कोई परवाह न करते हुए ओडर-नीसे (Oder-Niesse) रेखा को जर्मन-पोलिश-सीमा के रूप में मान लिया और लुब्लिन सरकार को यह अनुमति प्रदान कर दी गई कि वह उस भूमि पर कब्जा करके वहां वैसे जर्मन नागरिकों को बाहर निवाले दे। ६ जुलाई, १९५० को पोलैंड और पूर्वी जर्मनी (रूस-संरक्षित) ने एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर दिये जिसके अनुसार ओडर-नीसे रेखा को मान्यता प्रदान कर दी गई।

(६) रूस द्वारा समुक्त राष्ट्र संघ में निषेधाधिकार का बारम्बार प्रयोग—पश्चिमी राष्ट्र और विशेषकर समुक्त राज्य अमेरिका को यह बात बहुत प्यारी कि समुक्त राष्ट्र संघ ने अपना काम ठीक प्रकार से शुरू भी नहीं किया था कि सोवियत रूस ने अपने निषेधाधिकार के अनियंत्रित प्रयोग द्वारा उनके मार्ग में बाधाएँ डालना आरम्भ कर दी। सोवियत संघ ने समुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका और पश्चिमी गणियों की विदेशी नीति का एक अंग समझ कर, निषेधाधिकार के यह पर, गुराहा परिपक्व में, उनके (पश्चिमी राष्ट्रों व अमेरिका के) लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। इसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि पश्चिम ने यह धारणा बना ली कि सोवियत रूस एवं ऐसे संगठन को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है

त्रिसुकी स्थापना विश्व-शांति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिए हुई है। इस सदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि जहाँ अगस्त १९६१ तक अमेरिका ने एक बार भी निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं किया था वहाँ रुस ६५ बार इसका प्रयोग कर चुका था। इंग्लैंड ने दो बार, फ्रांस ने चार बार और चीन (राष्ट्रवादी) ने एक बार इस अधिकार का प्रयोग किया था।

(७) रुस द्वारा शांति-स्थवस्था में बिघ्न—महामुद्र की समाप्ति के उपरान्त शांति-स्थवस्था की पुनर्स्थापना के मार्ग में रुस द्वारा इटली-अइंगेराजी की गई कि उससे पश्चिमी शक्तियों के हृदय में रुस के प्रति वैहद शकाएँ पैदा हो गयीं। इटली के साथ शांति भविष्य करने के लिए लंदन में जो विदेश मन्त्रियों की परिषद बुलाई गई उसमें रुसी विदेश मन्त्री मोलोतोव ने अपनी ऐसी मांगें प्रस्तुत की कि पश्चिमी राष्ट्र स्तब्ध हो गये। परिणाम यह निकला कि विदेश मन्त्री परिषद की बैठकें शांति की समस्याएँ सुलझाने के स्थान पर उन्हें उलझा कर नये विवाद उत्पन्न करने लगीं।

(८) अमेरिका में साम्यवादी गतिविवियाँ—सोवियत रुस ने न केवल अन्य देशों में बल्कि स्वयं समुक्त राज्य अमेरिका में भी साम्यवादियों को विभिन्न प्रकार से प्रेरित किया। सन् १९४५ के प्रारम्भ में 'स्ट्रेटेजिक सर्विस' (Strategic Services) के अधिकारियों को पता चला कि उनकी संस्था के बहुत से गुप्त दस्तावेज (Secret Documents) साम्यवादी सरक्षण में चलने वाले 'अमेरेशिया' (Amerasia) नामक मासिक पत्र के सम्पादक के हाथ में पहुँच गए हैं। इसके अतिरिक्त १९४६ में 'कनाडियन राही आयोग' (Canadian Royal Commission) की रिपोर्ट ने यह प्रमाणित किया कि कनाडा का साम्यवादी दल 'सोवियत सघ की एक भुजा' (An arm of the Soviet Government) है। इस आयोग ने अनेक सोवियत जासूसों गिराफ्तों का पता लगाया और यह रहस्योद्घाटन किया कि विश्वस्तरीय पदों पर आसीन अनेक कनाडी व्यक्ति (Canadians) जिनमें एक सत्त सदस्य व एक प्रमुख अगु बंगाली भी शामिल हैं, साम्यवादी गुट के एजेंट हैं और उन्होंने माफ़ी की आणुबिक भेद तथा यूरैनियम धातु के नमूने भेजे हैं। इस रिपोर्ट से अमेरिकन सरकार साम्यवादियों के प्रति पूरी तरह से सतर्क हो गई और एम्पूमें अमेरिकन राष्ट्र तथा अन्य पश्चिमी शक्तियों में रुस के प्रति विश्वास की गहरी छहर फैल गई। दूसरी ओर मास्को रेडियो ने प्रकाशना यह सरकारी के विपक्ष धरना प्रचार-अभियान तेजी से चालू रखा।

पश्चिमी राज्यों ने उन्नोक्त गिराफ्तों करते हुए और विभिन्न आरोप लगाते हुए सोवियत सघ के प्रति अपना पूर्ण अविश्वास व्यक्त कर दिया।

अगस्त १९४५ में अमेरिका के राज्य सचिव बर्नेस और ब्रिटिश विदेश मंत्री बेविन ने इस बान पर अत्यन्त शोक प्रकट किया कि सोवियत संघ ने किसी भी रूप में अपने पवित्र वचन का पालन नहीं किया है। पूर्वी यूरोप के सोवियत नियन्त्रण को चुनौती देन हुए उन्होंने घोषणा की—

हमें तानाशाही के एक स्वल्प के स्थान पर उनके दूमेरे स्वरूप के समर्थन का शरणा चाहिए।'

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री चर्चिल ने अमेरिकन राष्ट्रपति थ्रो ट्रूमैन की उपस्थिति में साम्यवाद के विरोध की एक नई नीति का निर्देश ५ मार्च, १९४६ को अपनी सुप्रसिद्ध "फुल्टन वक्ता" (फुल्टन नामक स्थान पर चर्चिल ने यह वक्तव्य दिया था) में किया। इस भाषण में चर्चिल ने यूरोप के द्वार पार सोवियत "लोह आवरण" (Iron Curtain) की निन्दा की तथा "स्वतन्त्रता की दीपशिखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए" एक एंग्लो-अमेरिकन गठबंधन की मांग की। सन् १९४६ के अप्रैल मास के बाद से ही दोनों पक्षों (पश्चिमी व पूर्वी गुट) ने अपने मनभेदों का खुलेआम उगटना शुरू कर दिया। १२ मार्च, १९४७ को यूनानी गुट युद्ध के सम्बन्ध में कांग्रेस ने यूनान एवं तुर्की को ४०० मिलियन डालर की सहायता देने का अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने विरासत "ट्रूमैन सिद्धान्त" (Truman Doctrine) का प्रतिपादन किया। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत उन्होंने उन सभी स्वतन्त्र देशों की सहायता देने की नीति पर बल दिया जो मंगस्त अन्तरमहको अथवा बाह्य शक्तियों के द्वारा आघात स्थिति बनने व प्रयत्नों का विरोध कर रहे थे। ५ जून १९४७ को 'मार्शल योजना' की घोषणा की गई जिसका उद्देश्य यूरोप की अन्तःस्थित आर्थिक दशा को सुधारने का था। जहां पाश्चात्य यूरोपियन राष्ट्रों ने इस योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत किया वहां कम ने इसे अपने लिए गम्भीर चुनौती समझा। ३ जुलाई, १९४७ को ब्रिटेन और फ्रांस ने यूरोपियन आर्थिक पुनरुत्थान की समस्या पर विचार करने के लिए पेरिस में २२ देशों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें प्रारम्भ में तो पोलैंड और चेकोस्लावाकिया ने भाग लेने की इच्छा प्रकट की, परन्तु बाद में सोवियत संघ के विरोध के कारण इस नियन्त्रण का ठुकरा दिया। एटली (Attlee) के शब्दों में—“जब पोलैंड और चेकोस्लावाकिया ने मानसल गठायता के विचार का स्वीकार कर लिया तब पूर्वी ओर पश्चिमी यूरोप, एक एकाकरण की उसकी (उचित की) आशाओं को उठ गया। परन्तु नेपोलिन के आदेश पर ही स्वायत्तियों के परावर्तन ने इस आशा को नष्ट कर दिया। परन्तु यह 'शीत युद्ध' की एक घोषणा थी।”

(ख) पूर्व की (रूस की) पश्चिम के विरुद्ध सिकायतें

पश्चिमी राज्यों द्वारा रूस के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए, उनमें यह नहीं गमना चाहिए कि शीत-युद्ध के नाटक का एतन्मात्र सल्लाहक सोवियत रूस ही था। जहां पश्चिमी शक्तियों ने अपने विभिन्न आरोपों द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि पूरी तरह से गुप्तज्ञात केन्द्र सोवियत संघ ने ही की है और सभी ने सारे पूर्ववर्ती समझौतों व निश्चयों का उल्लंघन किया है, वहां 'पूर्व' न अर्थात् सोवियत संघ और उसके समर्थक राष्ट्रों ने अपने आरोपों में यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि युद्धोत्तर काल के तनाव और अस्थिरता का नारा दोष पश्चिमी राष्ट्रों का है। जहां पश्चिमी शक्तियों ने साम्यवादियों को "गुण्डों का निकुण्टतम गिरोह" (Worst scoundrels) कहा, वहां रूसियों ने उन्हें "लुटेरों तथा डाकुओं के गुट" (A den of robbers) की संज्ञा दी। रूस और उसके समर्थक राष्ट्रों द्वारा पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध जा सिकायतें की गयीं—वे इस प्रकार थीं—

(1) युद्धकाल में पश्चिम द्वारा 'द्वितीय मोर्चा' खोले जाने में देरी—
रूस की पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध एवं नवने बड़ी सिकायत यह थी कि जर्मनी द्वारा पूरी तरह से दबे रहने की स्थिति में स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से बार-बार अनुरोध किया था कि पश्चिमो यूरोप में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मार्चा खोला जाय ताकि सोवियत रूस पर किए जाने वाले जर्मन आक्रमण में बर्बाद हो सके। पल्टु स्मॉल्ट और चाबिल ने रूस की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा रूसी सुझाव को यह कह कर अस्वीकार कर दिया गया कि उनकी तैयारी अभी अधूरी है। दूसरा मोर्चा खोले जाने में पर्याप्त विलम्ब किये जाने का परिणाम यह हुआ कि सोवियत रूस को जर्मनी के हाथों जन-घन की भयंकर क्षति उठानी पड़ी। इस हानि की ओर संकेत करते हुए स्वयं आइज़नहोवर ने लिखा है—“१९४१ में जब हम हमारे जहाज से रूस गये तो हमने इसकी पश्चिमी सीमा से मारवो लैंड के विशाल प्रदेश में एक भी मकान खड़ा नहीं देखा।” सैगसम के लेखानुसार, 'विश्व और दिनांक के इस ताण्डव में रूस द्वारा उठाई गई असीम जन-घन की क्षति का सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है किन्तु यह बात ज्ञात है कि रणचण्डी का संपूर्ण देश करोड़ शक्तियों के विलक्षण ने जबरन भरा होगा।’ इसी अपितु माया में जो घन की हानि के कारण रूस में मित्र राष्ट्रों की नैतिकता पर तथा उल्लंघन हो गई। सोवियत नेताओं और इतिहासकारों ने यह मान्यता प्रकट की कि अमेरिका और ब्रिटेन ने पूर्व सोवियत-मनन कर तथा आन-बूम पर दूसरा मोर्चा खोलने में देर ली थी ताकि जर्मनी किसी

तरह रूस की साम्यवादी व्यवस्था का नाश कर दे। वास्तव में रूस के मन में सदेह के बीज तो तभी पड़ गये थे जब मित्र राष्ट्रों ने अघूरी तैयारी के बहाने पर दूसरे मोर्चे को खोलने की सोचियत प्रार्थना डाल दी थी। बैली (Bailey) के शब्दों में, “इससे ज़ेमेलिन में यह सन्देह जड़ पकड़ गया कि पश्चिमी राष्ट्र, जो युद्धोत्तर वर्षों में एक शक्तिशाली सोवियत संघ के उत्थान की सम्भावना से भयभीत हैं, युद्ध के अखाड़े में कूदने से पूर्व रूस को पूर्णतया ‘आहत तथा शक्तिहीन’ होते देखना चाहते हैं।”¹

(ii) पश्चिमी देशों की फासिस्ट देशों से साठगांठ—रूस ने इस बात पर बड़ा विशोभ प्रकट किया कि सैनिक व्यावहारिकता की आड़ में अमेरिका ने इटली और फ्रांस के फासिस्ट तत्वों से सम्पर्क स्थापित किया है और फिनलैंड द्वारा रूस के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने तथा लेनिनग्राड पर आक्रमण करने के काफी समय बाद तक वाशिगटन से उसने अपने कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये।

(iii) युद्धकाल में पश्चिम की अपर्याप्त सहायता—सोवियत संघ ने यह आरोप लगाया कि युद्धकाल में, जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने जो भी सैनिक सहायता सोवियत रूस को दी, वह रूस द्वारा उत्थान की गई युद्ध सामग्री का अत्यल्प अंश केवल ४ प्रतिशत था। वास्तव में मित्र राष्ट्रों की आन्तरिक इच्छा यही थी कि रूस जर्मनी के साथ संघर्ष में विलुप्त क्षीण हो जाय। इसीलिये उन्होंने प्रथम तो बहुत विलम्ब से और दूसरे अत्यल्प मात्रा में केवल दिखावे के लिए सहायता दी। फिर जो कुछ भी सहायता दी गई वह भी इसीलिये कि पश्चिमी राष्ट्र समझ गए कि जर्मनी द्वारा रूस को पूर्ण रूप से नष्ट किया जाना तब सत्तार के लिए फलक सिद्ध होगा।

(iv) अमेरिका द्वारा अणुबम के रहस्य को रूस से गुप्त रखना—अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार की सोवियत रूस से सर्वथा गुप्त रखा जबकि ब्रिटेन और कनाडा की इस बात का पता था। जब इस अणुबम का प्रयोग जापान पर किया गया तो उससे केवल हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं हुआ अपितु मित्र राष्ट्रों की मंत्री भी द्रुत गई। स्टालिन ने अमेरिका द्वारा अणुबम का रहस्य को रूस से गुप्त रखने की बात को परस्पर विरोधाभास माना। इससे उसे व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा दुःख हुआ। परिणामस्वरूप रूस और अमेरिका में परस्पर तनाव उत्पन्न हो गया और दोनों ही

देश युद्ध रूप से वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कार की होड़ में लग गए। रूस ने युद्ध-समाप्ति के बाद ४ वर्षों में ही अणुबम के रहस्य का पता लगा लिया और अक्टूबर १९५० में तो स्पूतनिक छोड़ कर वैज्ञानिक क्षेत्र में अमेरिका की गाँठ दे दी।

(९) सोवियत संघ की 'लैंडलीज' सहायता बन्द किया जाना—अमेरिका द्वारा 'लैंडलीज अधिनियम' (Land Lease Act) के अन्तर्गत सोवियत संघ की जो आर्थिक सहायता दी जा रही थी, उससे वह (रूस) पहले से ही असंतुष्ट था, क्योंकि सहायता एकदम ना-काफी थी। किन्तु यूरोप में विजय के उपरान्त राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अब यह आर्थिक सहायता भी एकाएक बन्द कर दी तो सोवियत रूस इससे बहुत उछा। अमेरिका द्वारा इस सहायता को रोकने और पश्चिमी शक्तियों द्वारा स्टालिन की सति प्रीति की माँगों के विरोध ने मास्को का यह सन्देह विस्वास्त में परिणत कर दिया कि पाश्चात्य राष्ट्र साम्यवादी रूस के शत्रु हैं और उसे फटते फूलते नहीं देखना चाहते।

(१०) सोवियत विरोधी प्रचार अभियान—रूस पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति इस बात में भी बहुत असंतुष्ट था कि युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार अपनी सेनाओं में निरन्तर सोवियत विरोधी साहित्य का प्रचार करती रही है। युद्धोपरान्त जहाँ पश्चिमी शक्तियों ने रूस पर पश्चिम के विरुद्ध विष-बमन का आरोप लगाया वहाँ रूस ने भी पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध यही गिनायत की। पश्चिमी प्रेस जुले आम साम्यवादी देश के प्रति घृणा प्रचार में सलग्न हो गई। साम्यवादी स्वतंत्र को सूत्र बजा चढ़ा कर पेश किया जाने लगा और ऐसा घातावरण पैदा करने की गरज से चेष्टा की जान लगी कि जनता में मास्को के भावी इरादों के प्रति नय और आशंका की भावनाएँ व्याप्त हो जायें। सोवियत सेनाओं के बर्तन के निरुद्ध पहुँचते ही अमेरिकन समाचार पत्रों में इस प्रकार के शीर्षक छपने शुरू हो गए—“साम्यवादी प्रसार से ईसाई सम्प्रदाय के टूटने का खतरा”, “सोवियत मर विश्व का एकमात्र आशामक राज्य” आदि। जिस सोवियत संघ ने अस्त्र हानि सह कर अद्वयन शीर्ष के साथ दुर्दमनीय नाशों का शत्रु को पछाड़ा था और जिसके वलिदानों ने मित्र राष्ट्रों की विजय को सरल बना दिया था, उसी के विरुद्ध इन प्रकार का अन्तर्गत प्रचार मास्को की एकदम शरणा पर देने वाला था।

(११) ५ मार्च, १९४६ की जनरल ने प्रेषित 'फुल्टन बयान' ने सोवियत रूस की एकदम बोधला दिया। इसमें इस बात का स्पष्ट निर्देश था कि “हमें तानाशाही के एक स्वयं के समय पर उनके दूसरे स्वयं के संस्थापन को रोकना चाहिए।” यह दूसरा स्वयं साम्यवादी साम्राज्यवाद के

के इतिहास में 'शीत-युद्ध' का जन्म एक इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विकास था कि इसने सम्पूर्ण विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, यद्यपि इसके प्रधान केन्द्र कुछ देश ही थे।

१९४७ से वर्तमान समय तक के शीत युद्ध पर एक दृष्टि

१९४५ से १९८७ तक का काल 'शीत-युद्ध' के प्रारम्भ का काल था जिस पर पूर्ववर्ती विवरण में प्रकाश टाँका जा चुका है। अब हम १९४७ के बाद के 'शीत युद्ध' के इतिहास की प्रमुख बातों की चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्धोत्तर काल की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ही 'शीत-युद्ध' की सन्तान है और इस अवधि में अरब तक जो भी घटनाएँ घटी हैं, उनका प्रभाव कारण अधिकारित, 'शीत-युद्ध' ही रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के जिस इतिहास का अध्ययन हम प्रस्तुत पुरस्वक में कर रहे हैं वह सम्पूर्ण इतिहास ही अपने आप में इस 'शीत-युद्ध' का इतिहास है। इसलिए प्रस्तुत सत्र में कुछ प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त विश्लेषण कराते हुए 'शीत युद्ध' के उत्तर-चक्रों को बताया जाएगा।

— (१) १९४७ से १९५३ तक शीत युद्ध—१९४५ से १९४३ तक पश्चिमी देशों और रूस में समुक्त राष्ट्र सच के भीतर और बाहर अणुशक्ति के नियंत्रण व नियमीकरण, निस्स्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ सन्धि-संधियों, जर्मनी, बर्लिन, यूरोपियन सुरक्षा समस्याओं, एशिया एवं अफ्रीका के अल्प विकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी प्रश्नों पर तीव्र वाद विवाद तथा कूटनीतिक संघर्ष चला। रूस द्वारा मार्शल योजना के प्रत्युत्तर में अक्टूबर १९४७ में यूरोप के नौ-साम्यवादी देशों के 'कॉमिन फॉर्म' (Cominform or Communist Information Bureau) की स्थापना के बाद से ही शीत युद्ध की उग्रता बढ़ती गई। रूस ने पूर्वी यूरोप पर अपने नियंत्रण की ओर भी अधिक कठोर बना दिया। शक्ति के दो घटे अथवा गूट या खेमे बन गये और उनमें अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों के विकास के लिए जो-सोड स्वार्थी हान लगी। रूसी दबाव के कारण फिनलैंड को मार्शल सहायता ने प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा। परन्तु एक साम्यवादी देश यूगोस्लाविया ने ही, अपने नेता मार्शल टिटो के नेतृत्व में, स्टालिन के प्रभुत्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मार्शल टिटो का यह कार्य 'शीत-युद्ध' की एक महत्वपूर्ण घटना थी क्योंकि जहाँ इसने एक तरफ गैर साम्यवादी देशों को नवीन चल प्रदान किया, वहाँ दूसरी तरफ रूस के दृष्टिकोण की ओर भी अधिक कठोर बना दिया। १९४८ में रूस ने बर्लिन की नाकेबंदी करके एक नया सफट उद्घाटन कर दिया। इस घटना ने 'शीत युद्ध' को एक

नया मोड़ दिया। बर्लिन के घेरे के समय ही दोनों पक्षों की ताकत आजमाने का पहले पहल वास्तविक मौका मिला और शीत युद्ध में इस बार अमेरिका को सघ पहले बार अत्यधिक कठोर हो गया। यद्यपि रूस की बर्लिन नाके-बंदी असफल सिद्ध हो गई और मई १९४८ में इस नाके-बंदी को समाप्त कर दिया गया, परन्तु इस घटना का एक गम्भीर परिणाम यह निकला कि अब सोवियत सभ का विरोध करने के लिए अमेरिका तरह-तरह के सैनिक-संगठनों की स्थापना करने की दिशा में सधिया हो गया।^१ दूसरी ओर पहले से ही दितन्त्र जर्मनी 'शीत युद्ध' का एक प्रधान केन्द्र बना रहा। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने द्वारा अधिकृत जर्मनी के तीनो पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया और इस तरह २१ सितम्बर, १९४९ को "जर्मनी के संघीय गणतन्त्र" (Federal Republic of Germany) अथवा पश्चिमी जर्मनी का उदय हुआ। मित्रराष्ट्रों अर्थात् उपरोक्त तीनो शक्तियों के इस कार्य के प्रत्युत्तर में ७ अक्टूबर, १९४९ को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में "जर्मन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य" (German Democratic Republic) अथवा 'पूर्वी जर्मनी' की स्थापना कर दी गई। इस तरह पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी के दो जर्मन राष्ट्र अस्तित्व में आये और उनके एकीकरण का प्रश्न अभी तक शीत-युद्ध की अलिवेदी पर पड़ा हुआ है तथा निम्नट अविध्य में जर्मनी के संयुक्त होने की कोई आशा नहीं दिखाई देती।

रूस के कठोर होते गये रूस और साम्यवाद के प्रसार की नीति का उत्तर पश्चिमी शक्तियों ने ४ अप्रैल, १९४९ को 'नाटो' (NATO) की स्थापना करके दिया। शीत युद्ध का क्षेत्र केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा, परन्तु एशिया भी इसकी छपेट में आ गया। रूस ने टर्की और ईरान में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहा, परन्तु पाश्चात्य शक्तियों की सहायता से ये दोनों देश रूसी दबाव का सफलतापूर्वक प्रतिरोध करते रहे। १ अक्टूबर, १९४९ को पोरिकिम में साम्यवादियों का जन गणराज्य स्थापित हो जाने से 'शीत युद्ध' में बड़ी गर्मी आ गई। साम्यवादियों की इस विजय ने रूस के सत्ताह को बहुत बढा दिया। संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थाई सदस्य है। परन्तु जब च्यांगकाई गोक की राष्ट्र-वादी सरकार भाग कर फारमोसा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पाने की माग की। परन्तु पश्चिमी गुट यह नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत सभ का एक और समर्थक हो जाय। परिषद के ५ स्थाई सदस्यों में से २ साम्यवादी

हो जाने के डर से संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन की नई सरकार को मान्यता नहीं दी और साम्यवादी प्रतिनिधि के मध्य में बिटाने का घोर विरोध किया। साम्यवादी चीन की सदस्यता की माग को इस प्रकार ठुकरा दिये जाने का रूस द्वारा तीव्र विरोध किया गया और एक बार तो उसने परिषद की बैठकों तक का बहिष्कार कर दिया। वास्तव में साम्यवादी चीन की मध्य में सदस्यता के प्रश्न को लेकर शीत युद्ध में जिस कटुता और गम्भीर वैमनस्य का समावेश हुआ, उसने आगे वाले वर्षों में शीत युद्ध की भयकरता और पारस्परिक मतभेदों की तीव्रता को हर प्रकार से बढ़ाया। भारत ने भी चीन की सदस्यता के प्रश्न पर सदैव सोवियत गुट का समर्थन किया, यद्यपि जब यह समर्थन उतना सक्रिय प्रतीत नहीं होता जितना कि पहले था। संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के कारण ही साम्यवादी चीन आज तक—संयुक्त—राष्ट्र सभ का सदस्य नहीं बन पाया है और यह प्रश्न आज भी शीत युद्ध-का-एक प्रमाण अङ्ग बना हुआ है। -

बलिन-प्रश्न पर और संयुक्त राष्ट्र सभ में साम्यवादी चीन के प्रवेश की समस्या पर शीतयुद्ध की बड़ी हुई खमारी अभी कम भी न हो पाई थी कि जून १९५० में उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया गया जिससे 'शीतयुद्ध' ने कुछ समय के लिए 'उष्ण अथवा सशस्त्र युद्ध' का रूप धारण कर लिया। प्रत्यक्ष में यह युद्ध दो कोरियाई क्षेत्रों में था, परन्तु वास्तव में यह दोनों शक्ति गुटों के नेताओं रूस एवं अमेरिका के बीच था। संयुक्त राष्ट्र सभ न उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उसके हाड़े के नीचे अनेक देशों की, विशेषतः अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिण कोरिया की सहायता की। परन्तु किसी भी पक्ष को निर्णयात्मक विजय प्राप्त न हो सकी और ८ जून, १९५३ को अन्ततः कोरिया में युद्ध विराम हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की सरकारों ने युद्ध बन्द हो जाने का स्वागत किया किन्तु इन देशों का वास्तविक मन मुटाव का हृदयों में चलने वाला युद्ध समाप्त नहीं हुआ, फलतः शीत युद्ध जारी रहा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कोरिया युद्ध शीतयुद्ध की ही एक महत्वपूर्ण घटना थी। चेस्टर बोल्वेस (Chester Bowles) के शब्दों में, "कोरिया युद्ध ने सभी ओर चीनी नीतियों को एव ही घुंके में एक्कन कर दिया।"¹ चीन के लिए सोवियत सहायता की आवश्यकता स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई और चीन और पश्चिमी राज्यों के सम्बन्ध और भी अमैत्रीपूर्ण हो गये।

1 Chester Bowles • The New Dimensions of Peace,

नित सन्नय कोरिया—'युद्ध चल रहा था, सभी सितम्बर १९५१ में अमेरिका और कई अन्य देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किये। इस को यह बात बहुत चुरी लगी और उसने इस एकपक्षीय कार्यवाही की खुर कर आलोचना की।

(२) १९५३ से १९५८ तक का 'शीतयुद्ध'—मार्च १९५३ में स्टालिन को मृत्यु के बाद शीतयुद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आया। स्टालिन उग्रवादी था और पश्चिम के प्रति कठोर नीति का पक्षपाती भी। उसका दस्त १९५३ ने प्रारम्भ तक शीतयुद्ध का एक प्रधान कारण बना था। सर एलबेरी गैस-कोमने के अनुसार, '१९४७ के बाद यद्यपि स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित रखे परन्तु वह इतना अटक्काबाज और दुसाध्य हो गया कि उसके साथ कार्य करना सहज नहीं था। जो सुझाव भी सामने रखा जाय उसको ही वह अस्वीकार कर देता था।' सोमार्गवश स्टालिन के बाद के उत्तराधिकारी, क्रिश्चियन, खुश्चेव ने समझौतावादी नीति को अपनाने की कोशिश की, यद्यपि शीतयुद्ध निरन्तर जारी रहा और आज भी वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक निर्णायक तथ्य बना हुआ है। अमेरिका के नेतृत्व में भी एक परिवर्तन आया और शीतयुद्ध के उन्नायक राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहोवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगस्त १९५३ में सोवियत संघ का प्रथम आणविक परीक्षण हुआ और हथियारों के क्षेत्र में विद्यमान खाई को धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता दोनों ओर से महसूस की जाने लगी।

परन्तु शीतयुद्ध की यह शिथिलता एब्रहम लिन्कनवादी नहीं रही क्योंकि रूस के विदेश मंत्री मोलोटोव और अमेरिका के विदेश सचिव डेलस दोनों ही शीतयुद्ध के बाँके छडाके थे। एक तरफ तो हिन्द चीन के प्रश्न पर शीतयुद्ध में पुनः तेजी आ गई क्योंकि फ्रेंच साम्राज्यवाद के विरुद्ध वहाँ चलने वाले युद्ध में दोनों ही गुटों ने अलग-अलग पक्षों का पुर-जोर समर्थन किया, और दूसरी तरफ अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सैनिक समझौते तथा सैन्य समझौतों की स्थापना करने की नीति अपना कर शीतयुद्ध को बढावा दिया। अमेरिका ने किस तरह नाटो, सीटो और बगदाद पॅक्ट बनाए और इनके जवाब में किस प्रकार रूस ने वारसा पॅक्ट कायम किया—इन सबका सल्लेख हम प्रादेशिक समझौतों के अव्ययन में कर चुके हैं। वास्तव में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी कार्यवाहियों से एक दूसरे के प्रति सदेह और शकाओं को दृढ़ बनाया तथा अपनी प्रत्येक कार्यवाही से न्यूनाधिक मात्रा में शीतयुद्ध को आगे बढाया। उदाहरणार्थ यदि सितम्बर १९५३ में रूस ने उसके और पश्चिमी देशों के मध्य के एक अनानुमन प्रस्ताव को ठुकरा दिया

तो मार्च १९५४ में जब रूसो विदेश मंत्री मोलोटोव ने रूस के उत्तर अटलांटिक संधि में सम्मिलित होने के प्रश्न पर विचार करने की अपनी तत्परता जताई तो नाटो देशों ने इस सद्भावना का पूर्णतः अवास्तविक और पश्चिमी देशों की प्रशिक्षा व्यवस्था व सुरक्षा के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिबल बता कर इसका तिरस्कार कर दिया। जनवरी १९५६ में रूसी प्रधानमंत्री बुल-गानिन ने राष्ट्रपति आइजन-होवर के सम्मुख एक रूसी अमेरिकन मंत्री व सहयोग संधि का प्रस्ताव रखा, परन्तु वह भी फर्जीभूत नहीं हुआ। ऐसे प्रस्ताव समय-समय पर किए जाने रहे किन्तु पारस्परिक मतभेद व संदेह इतने गहरे थे कि कोई सफलता प्राप्त न हो सकी। संयुक्त राष्ट्र संधि, यूरोप, अफ्रीका, मध्यपूर्व, सुदूरपूर्व, आदि सभी स्थानों में पूर्व और पश्चिम का सख्त बराबर जारी रहा। जापान और जर्मनी व पुनः संयुक्तकरण ने दोनों ही गुटों में काफी तनाव उत्पन्न कर दिया। जर्मनी के भविष्य और वर्तमान के स्तर पर भी मतभेद न मिट सके। अणुसक्ति का निर्माण और नियंत्रण पर कोई समझौता न हो सके। संसार के सबसे प्रमुख प्रश्न निःसंश्लेषण पर दोनों ही गुटों में मतभेद बला—प्रस्ताव व प्रति प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते रहते, किन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रत्येक प्रश्न पर शीत युद्ध के पृष्ठाधार में दोनों गुटों के दृष्टिकोण निर्धारित होने लगे।

१९५६ में हंगरी के प्रश्न ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और शीतयुद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि की। पश्चिमी देशों ने रूस के 'अनाचार' की कटु निंदा की, और उधर रूस ने स्वयं नहर के राष्ट्रीयकरण के फर्म्बवन् मिश्र पर १९५६ में ही होने वाले एडनर फोर्ब्स द्वारा रक्त आक्रमण की तीव्र मत्प्रेक्षा की। जून १९५७ में "आइजनहोवर मिडान्त" की घोषणा की गई जिसके अनुसार अमेरिकन कांग्रेस ने राष्ट्रपति को मध्य-पूर्व व किसी भी देश में अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए फौजें भेजने तथा सैनिक कार्यवाही करने का अधिकार दिया। "आइजनहोवर-मिडान्त" की घोषणा के बाद मध्यपूर्व में 'शीतयुद्ध' में काफी तीव्रता आ गई। रूस ने पश्चिमी एशिया के लिए इस सिद्धान्त को एफ़दम अनुचित बताया तो अमेरिका और इंग्लैंड ने उस क्षेत्र में रूसी घुसपैठ व तोड़-फाड़ की कार्यवाहियों की निंदा की। कहने का अर्थ है कि १९५५ से १९५८ तक पश्चिमी एशिया शीतयुद्ध का भयंकर अखाड़ा बना रहा। वास्तविकता यही थी कि उस क्षेत्र के सम्पत्ति राष्ट्र और तेल-स्रोतों पर प्रभुता कायम रखने के लिए दोनों पक्षों में घोर मर्पट होता रहा। पारस के तेल-विवाद, होज नहर के गड़बड़, मेसोपोटामिया में अमेरिकी फौजों की उतारने, ईरान की प्राप्ति आदि अवसरों पर दोनों ही

पक्ष ताल ठोक कर मैदान में डट गये। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जो शीत युद्ध का परिणाम न हो या उससे प्रभावित न रही हो।

(३) १९५८ से १९७० तक का शीतयुद्ध—इस समय के शीत-युद्ध के इतिहास को निम्न रूप में प्रकट करना सुविधाजनक होगा—

खुश्चेव की अमेरिकी यात्रा तथा यू०-२ विमानकाण्ड—१९५९ में कुछ कारणों से शीत युद्ध में थोड़ी कमी आयी। ३ अगस्त को मास्को और वाशिंगटन से यह घोषणा हुई कि कुछ ही दिनों में सोवियत प्रधानमन्त्री खुश्चेव मधुस्त राज्य अमेरिका और उसके बाद अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहोवर सोवियत सभ का भ्रमण करेंगे। इन समाचारों से प्रतीत होने लगा कि शीत युद्ध या तो समाप्त हो जायेगा या उसका प्रभाव नगण्य रह जायेगा।

दोनों देशों में बढ़ते हुए तनाव में कमी लाने के लिए श्री खुश्चेव ने १५ सितम्बर से २८ सितम्बर, १९५९ तक अमेरिका की यात्रा की। यात्रा के दौरान तीन दिन तक राष्ट्रपति आइजनहोवर और खुश्चेव में मन्त्रीपूर्ण वार्तालाप हुआ। श्री खुश्चेव की यात्रा पर प्रकाशित सधुक्त वक्तव्य में कहा गया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का निर्णय शान्तिपूर्ण साधनों तथा पारस्परिक वार्तालाप के माध्यम से किया जाना चाहिए।

शीत युद्ध के तनाव को कम करने और आपसी मतभेदों को समाप्त करने के लिए चार बड़े देशों (सधुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत सभ, ब्रिट-ब्रिटेन और फ्रांस) के शासनाध्यक्षों का एक शिखर सम्मेलन बुलाया जाना आवश्यक समझा गया। पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरम्भ से पूर्व ही १ मई, १९६० को यू०-२ विमान काण्ड हो गया जिसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि करके अन्ततः शिखर सम्मेलन को असफल बना दिया। बात तब बहुत बढ़ गई जब राष्ट्रपति आइजनहोवर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि सोवियत सभ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहनी हैं, अतः किसी भी आवृष्टिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जामूसी कार्य-वाहिया करता है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में इसकी मनाही नहीं है। इस घोषणा से खुश्चेव आग बबूला हो गया। उसने ऐसी जामूसी उद्घाटनों को राष्ट्रीय अपमान बताने हुए इन्हें भविष्य में बन्द करने की मांग की और साथ ही यह धमकी दी कि भविष्य में इस प्रकार की किसी घटना से यदि युद्ध छिड़ गया तो उत्तका दायित्व मधुक्त राज्य अमेरिका पर होगा। यू०-२ काण्ड ने शीत युद्ध में जो सूफान खड़ा कर दिया उससे रूप ने खूब लाभ उठाया। खुश्चेव ने यह सिद्ध करने में कोई कसर

नहीं छोड़ी कि रूस शांति का सबसे बड़ा प्रेमी और अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के लिए यही एक मात्र उत्तरदायी है।

रूसी चेतावनी के फलस्वरूप अब अमेरिकी अड्डों को इजाजत देने वाले देश यह अनुभव करने लगे कि यू०-२ विमानों को अपने देश में ठहराना भयंकर खतरा का मोड़ लेना होगा।

पेरिस शिखर सम्मेलन—यू०-२ विमान कांड की घटना से १६ मई, १९६० से होने वाले शिखर सम्मेलन को असफलता साफ नज़र आने लगी। लेकिन ११ मई को नुरीम सोवियन में अरने एक भाषण में ख्रुश्चेव ने सम्मेलन की सफलता के प्रति आशाभिन कर दिया। ख्रुश्चेव ने कहा "संयुक्त राज्य अमेरिका के इस उत्तेजनापूर्ण कार्य से हमें अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने के प्रयत्नों में शिथिलता नहीं लानी चाहिए। पेरिस में यू-२ का विषय नहीं उठाया जायेगा।"

लेकिन जब पेरिस में शिखर सम्मेलन शुरू हुआ तो ख्रुश्चेव ने यू-२ का प्रश्न उठाते हुए अमेरिकन जामूसी कार्यवाही की तीव्र निन्दा की। श्री ख्रुश्चेव ने बड़े ही नाटकीय ढंग से माग की कि अमेरिका को अपने जामूसी काम की निन्दा करनी चाहिए, इसके लिए माफ़ी मागनी चाहिए, भविष्य में ऐसे उत्तेजक कार्य बन्द करने चाहिए और इस घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। ख्रुश्चेवने यहां तक कह दिया "यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका के साथ वार्ता करना निरर्थक समझता हूँ और वह उसमें भाग नहीं ले सकता। सम्मेलन को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाय ताकि यह अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जनवरी में हो सके।" ख्रुश्चेव ने शीत युद्ध को तब पराव प्टा पर पहुँचा दिया जब उसने डिगाल और मँकमिलन से तो हाथ मिलाया, लेकिन जब राष्ट्रपति राइजनहोवर ने हाथ बढ़ाया तो ख्रुश्चेव ने इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं ख्रुश्चेव ने अमेरिकन राष्ट्रपति को दिये गये दसो दाना व निमन्त्रण को वापस ले लिया और कहा कि राष्ट्रपति महोदय को अब रुस आने की आवश्यकता नहीं है।

रूसी नेता के इस रुख से शिखर सम्मेलन असफल हो गया। आइजन-होवर के आश्वासन और डिगाल व मँकमिलन के प्रतिरोध को दूर करने के प्रयत्न सम्मेलन को भग होने में सफल न सके। सम्मेलन के दूसरे नज़र में ख्रुश्चेव ने भाग ही नहीं लिया, अतः सम्मेलन की कार्यवाही बन्द कर दी गई।

कैंनेडी का अमेरिकन राष्ट्रपति निर्वाचित होना और बरूया काण्ड—
ख्रुश्चेव ने पेरिस शिखर सम्मेलन की असफल बनाने के बाद अपने विभिन्न

शीत-युद्ध

भाषणों में आश्वासन दिया कि इस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को बिगाड़ने का कोई कार्य नहीं करेगा। ८ नवम्बर, १९६० को अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन में सीनेटर जान फिट्ज़राल्ड कॅनेडी की सफलता के बाद शीत युद्ध में तन्मी की आशा की जाने लगी। ख्रुश्चेव न कॅनेडी को अपनी बर्बाद में और प्रत्युत्तर में कॅनेडी न ख्रुश्चेव को बड़े आशावादी शब्द लिखे।

दोनों नेताओं की आशाओं और उनके आश्वासनों का कुछ समय तक प्रभाव पड़ा और शीत युद्ध में कुछ थना आया लेकिन मई १९६२ में बर्बूबा के संकट ने पुनः एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी। बर्बूबा के प्रश्न पर एक बार फिर विश्व-युद्ध की सम्भावना उत्पन्न हो गई। सोवियतवश कॅनेडी और ख्रुश्चेव की बुद्धिमत्ता के कारण बर्बूबा का संकट समाप्त हो गया। सोवियत रुस ने बर्बूबा संकट पर संधर्ष क्षेत्र से हट जाना का निर्णय करके बड़ी सहनशीलता का परिचय दिया।

शीत युद्ध में शिथिलता—बर्बूबा संकट अन्तिम अवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को सुधारने और शीत युद्ध में शिथिलता लाने की दृष्टि से एक गुप्त बरदान सिद्ध हुआ। अब ख्रुश्चेव और कॅनेडी दोनों ही नेता विश्वसनीय-कारण की दृष्टि में प्रगति के लिए सहानुभूति प्रयास करने लगे। परिणामस्वरूप शीतयुद्ध में काफी समय तक कोई वाद नहीं आया। ५ अगस्त, १९६३ को इस, अमेरिका और इंग्लैंड ने मास्को में आणविक परिक्षण पर रोक सम्बंधी सन्धि पर हस्ताक्षर किये और वाद में चान, फ्रांस आदि कुछ राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के सभी अधिक राष्ट्रों ने सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये। इस सन्धि के फलस्वरूप दोनों गुटों में तनाव कम हुआ और शीतयुद्ध ठण्डा पड़ गया। १९५५ की आस्ट्रिया की शांति सन्धि के बाद पूर्व और पश्चिमी का यह सबसे बड़ा समझौता था।

ख्रुश्चेव और कॅनेडी दोनों ही के प्रयत्नों से शीत युद्ध में शिथिलता आयी और यह आशा की जाने लगी कि दोनों नेता आपसी विश्वास और शांति के बीज बो देंगे, पर दुर्भाग्यवश २२ नवम्बर, १९६३ को कॅनेडी एक हत्यारे की गोली के शिकार बने और १५ अक्टूबर, १९६४ को ख्रुश्चेव अपदस्थ हो गये।

कॅनेडी की मृत्यु के बाद लिम्बन जानसन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जानसन ने आश्वासन दिया कि अमेरिका की ओर से शीत युद्ध को फैलाने की कोई चेष्टा नहीं की जायेगी। नये राष्ट्रपति ने अपने शासन के प्रारम्भिक दिनों में इस दृष्टि का पालन भी किया और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जिससे यह आरोप लगाया जा सके कि अमेरिकी-प्रशासन शीतयुद्ध के फैलाव की चेष्टा कर रहा है।

दूसरी ओर खुश्चेव के पतन के बाद अक्टूबर, १९६४ में रूस का नेतृत्व कोसिगिन और ब्रेज्नेव के हाथों में आया। इन दोनों नेताओं ने भी घोषणा की कि रूस खुश्चेव की विदेश नीति पर चलते हुए शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करता रहेगा, नि घस्त्रोत्करण के लिए प्रयास करेगा और शीत युद्ध को नहीं बढ़ायेगा।

सौभाग्यवश कुछ असें तक शीत युद्ध में शिथिलता आती गई, लेकिन बाद में वियतनाम युद्ध की तीव्रता और अरब इजराइल संघर्ष के फलस्वरूप एक बार फिर शीत युद्ध भटक उठा।

वियतनाम युद्ध, भारत पाक संघर्ष, अरब इजराइल संघर्ष और शीत युद्ध—सन् १९६४ में ही शीत युद्ध के तीव्र होने के आधार पगट होने लग गये। रूस ने कागो आदि में राष्ट्रपति राष्ट्र सभ के शान्ति स्थापना सम्बन्धी कार्यों के व्यय व अपने अश्व की अदायगी से इनकार कर दिया। अमेरिका ने मांग की कि यदि रूस अपना अश्व अदा नहीं करेगा तो चार्टर के उन्नीसवें अनुच्छेद के अन्तर्गत उसे महासभा में मताधिकार से वंचित कर दिया जाय। इस घटना से शीत युद्ध बड़ा उग्र हो गया।

वियतनाम युद्ध में तीव्रता ने शीत युद्ध को और बढ़ावा दिया। अमेरिकन राष्ट्रपति जानसन ने वियतनाम के प्रति अत्यन्त उग्र और आक्रामक नीति का अनुसरण किया। उत्तरी वियतनाम की सीमाओं में घुस कर अमेरिकी वायुयान बम वर्षा करने लगे। वियतनाम युद्ध को अधिकाधिक फैलाने की कोशिश की गई। सोवियत रूस ने इन आक्रामक कार्यवाहियों का बड़ा विरोध किया। अमेरिका की वियतनाम नीति के कारण शीत युद्ध की लहर पहले से अधिक तेज हो गई।

सितम्बर, १९६५ में काश्मीर को लेकर भारत पाक संघर्ष ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि की। पश्चिमी राष्ट्रों ने भारत के विरुद्ध अपना कूटनीतिक युद्ध चलाने में कोई कसर नहीं रखी। सौभाग्यवश उनकी शीत युद्ध कुशलता और कूटनीतिक पैतरेबाजी स्वर्गीय साल बहादुर शास्त्री की दृढ़ता और स्पष्टता के सामने विशेष सफल नहीं हो सकी।

जून, १९६७ में अरब इजराइल संघर्ष के समय शीत युद्ध और संस्र संघर्ष के नाटक गगार को बरग को मिले। सोवियत संघ ने अरब राज्यों का पक्ष लेकर अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह इजराइल को आक्रामक कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बदलाव में अमरीका ने इस संघर्ष के लिए सोवियत कूटनीति का दोषी ठहराया। पश्चिमी एशिया के संकट को लेकर दोनों गुटों में इतना घाक् युद्ध चला कि उनके आपस में टकराने का

सकट पैदा हो गया। दोनों के जहाजी बेड़े भी भू-मध्य सागर में चक्कर काटने लगे और अमेरिका व रूस जैसी महा शक्तियों के प्रत्यक्ष सघर्ष की नींव तैयार हुई। अरब और इजराइली नेताओं द्वारा भी जबरदस्त कूटनीतिक एवं वायुयुद्ध लड़ा गया। यही शीतयुद्ध सशस्त्र युद्ध में परिणत हो गया जिसकी समाप्ति समुन्नत राष्ट्र सघीय हस्तक्षेप और अरब राष्ट्रों की आकस्मिक पराजय में हुई।

अरब इजराइल सघर्ष के समय सुरक्षा परिषद की प्रत्येक बैठक में शीत युद्ध का नजारा देखने को मिला। अमेरिका और सोवियत तब एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते रहे और एक दूसरे को पश्चिम एशिया के सकट के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे। अरब राष्ट्रों की पराजय के बाद सोवियत संघ के प्रति अरबों में सन्देह और अविश्वास व्याप्त हो गया, क्योंकि उसने युद्ध में अरबों की सशस्त्र और प्रत्यक्ष सहायता नहीं की थी जब कि इजराइल को अमेरिका व ब्रिटेन दोनों से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायता मिली थी। इस वातावरण को देखते हुए रूस ने अरब जगत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिये यह भाग का कि अरब इजराइल सघर्ष का मामला समुन्नत राष्ट्र संघ की महासभा में पेश किया जावे। १५ जून, १९६७ को जब महासभा में प्रश्न पर विचार होने लगा तो स्वयं रूसी प्रधान मन्त्री ने कार्यवाही में भाग लिया। कासीजिन ने महासभा में खुद ने एक प्रस्ताव पेश किया जो अरब भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला था। लेकिन पश्चिमी गुट उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अतः १६ जून को बैठक में सोवियत प्रतिनिधि मण्डल ने महासभा से बहिर्गमन करके अरबों की सहानुभूति जीती। सोवियत प्रधान मन्त्री ने अमेरिकन प्रशासन पर कस-कस कर प्रहार किये। अरब इजराइल सघर्ष के सन्दर्भ में इस प्रकार शीत युद्ध आकाश छूने लगा।

ग्लासबरो का शिखर सम्मेलन—सोवियत प्रधान मन्त्री कोसीजिन ने जो महासभा के अधिवेशन में जाये हुए थे, अमेरिकन राष्ट्रपति जॉनसन से ग्लासबरो में भेंट की ताकि शीत युद्ध का गर्म वातावरण कुछ शान्त हो सके। दोनों शासनाध्यक्षों का यह शिखर सम्मेलन ग्लासबरो में २३ जून से २६ जून, १९६७ तक चला। दोनों नेताओं ने विद्यतनाम और पश्चिमी एशिया पर मुख्यतः विचार-विमर्श किया। निराशाचकण एवं परमाणु शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक प्रश्न भी अछूते नहीं रहे। दोनों नेताओं का यह शिखर सम्मेलन चीन द्वारा हार्डडोजन बम का परीक्षण किये जाने के प्रभाव से व्याप्त था। दोनों ही नेता इस बात को भली भाँति समझते थे कि

आणुगतिक से सम्पन्न चीन विश्व के दानों की खेती के लिए सज्ज हो सकता है।

आसुवरा में गई सौदवात्री नहीं हा मुकी लेकिन इस सम्मेलन के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में अवश्य कमी आयी। पश्चिमा एशिया के सफट के सम्बन्ध में दानों महा शक्तियों के बीच सहमति का क्षेत्र कुछ अधिक बढ़ा। इस विश्व सम्मेलन के बाद चीन युद्ध की उपरता कम हो गई और दानों हा महा शक्तियां कुछ अधिक नयमित माया का प्रयोग करने लगी।

वियतनाम युद्ध में शिथिलता और शीत युद्ध में कमी—१९६७-६८ में वियतनाम का प्रश्न शीत युद्ध का भटकाता रहा। सीमाश्रय वियतनाम में अमेरिकी नीति के विरुद्ध विश्व जनमन ने ही नई वरिष्ठ स्वयं अमेरिकियों ने भा प्रवृत्त आक्षेप दिये। उन बाध्य होकर राष्ट्रपति जानसन ने एक आरंभ उतारी वियतनाम पर बम्बारी रोकने की घोषणा की और दूसरी ओर आ मन्त्रालय में पीठित होकर राष्ट्रपति पद के लिए पुन उम्मीदवार न हान का निम्नम व्यक्त किया। फलस्वरूप चीन और वियतनाम युद्ध शिथिल होना गया और शीत युद्ध ठण्ठा पड़ना गया।

वियतनाम में शान्ति समझौता बनावें चले रही हैं और इस बात की पूरी समझना दिखाने दे रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाय और शीत युद्ध का एक महान् कारण लुप्त हो जाय। जानसन के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति रिक्सेन ने अक्टूबर, १९६९ तक हजारों अमेरिकी सैनिक वापस स्वदेश बुला दिये। दूसरी ओर उत्तरी वियतनाम की आक्रामक कार्यवाहियां भी कम होनी जा रही हैं। मितम्बर, १९६९ में उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति हाचामिन्ह की मृत्यु के बाद आ नये नेता प्रभुच में आय हैं, उन्होंने भी अभी तक युद्ध छोड़ करन में कोई व्यावहारिक रुचि नहीं दिखाने है। इस प्रकार वियतनाम युद्ध के शान्त होन के लक्षण प्रवल हैं।

मार्च, १९६९ का बर्लिन संकट और शीत युद्ध—यद् ह्य कि कुछे हैं कि शीत युद्ध उत्तार-चढ़ाव का नाटक रहा है। यद्यपि क्यूबा काण्ड के बाद ही शीत युद्ध में, शिथिलता आता गढ़ है, लेकिन बावजूब में विभिन्न कारणोंवा उपन तावता भी आता रहा है। शीत युद्ध के इतिहास में एक बार सभी तरह आशा अब पश्चिमा जमाना ने निश्चय दिया कि ५ मार्च, १९६९ का सङ्घर्ष जनता के राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिम बर्लिन में सम्पन्न दिया जाय। पूर्वो जमान सरकार ने इस निश्चय का विरोध करते हुए कहा कि पश्चिम बर्लिन अभी तक १९६९ के पाठ्यक्रम समन्वित के अधीन है, अतः पश्चिम बर्लिन की सरकार को इस तरह का समाराह करन इस पश्चिमी

जर्मनी का ही एक भाग सिद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्वी जर्मनी ने यह आरोप लगाया कि पश्चिमी जर्मनी के राष्ट्रपति का चुनाव बर्लिन में कराने का निर्णय पूर्वी जर्मनी के दावे के खण्डन के लिए किया गया है।

पूर्वी जर्मनी ने केवल मौखिक विरोध ही नहीं किया बरन् पश्चिमी बर्लिन जाने वाले मार्गों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया ताकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला निर्वाचक मण्डल बर्लिन न पहुँच सके। लेकिन पश्चिमी जर्मनी भी इस बात पर तुल गया कि राष्ट्रपति का चुनाव पश्चिमी बर्लिन में ही किया जायगा। अतः वायुमार्गों द्वारा (हवाई यातायात प्रतिबन्ध से मुक्त है) निर्वाचक मण्डल अपने दल बल सहित पश्चिमी बर्लिन पहुँचा। पश्चिमी जर्मनी को इस सम्पूर्ण कार्यवाही में पश्चिमी राष्ट्रों का पूरा पूरा समर्थन था। यद्यपि पूर्वी जर्मनी ने, जो रुस समर्थित है, उपर विरोध प्रगट किया और स्वयं रुस ने भी पश्चिमी जर्मनी को स्थिति से बचाने की चेष्टा-कनी की, तथापि राष्ट्रपति का चुनाव कार्य शान्तिपूर्वक सम्पन्न हो गया। इन प्रश्नों को लेकर सोवियत संघ ने कोई बड़ा पूर्व पश्चिम संकट खड़ा नहीं किया क्योंकि इसमें उसका कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता था। उल्टे इसका दो बातों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था—प्रक्षोभास्त्रों के बारे में रुस द्वारा प्रस्तावित वार्ता पर तथा नये अमेरिकन राष्ट्रपति निकसन के साथ सोवियत संघ के शिखर सम्मेलन की योजना पर। सोवियत संघ के समय और पश्चिमी राष्ट्रों की हृदय के फलस्वरूप स्थिति बिगड़ने से बच गई और शीत युद्ध पुनः शुरू होने से रुक गया। यह भी कहा जाता है कि बर्लिन में चुनाव सम्पन्न होने के तीन दिन पहले ही २ मार्च, १९६९ को रूसी-चीनी सैनिकों में एक सैनिक संकट हो गई थी, अतः रुस ने बर्लिन संकट पर अधिक ध्यान नहीं दिया।

शीत युद्ध की वर्तमान स्थिति

यह कहना तो भ्रामक होगा कि शीत युद्ध अब समाप्त हो गया है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि इसकी उग्रता हाल के वर्षों में काफी घटी है। आज स्थिति यह है कि दोनों ही गुट स्पष्ट रूप से महसूस करने लगे हैं कि बिना एक सहारक महायुद्ध के दूसरे गुट का दमन सम्भव नहीं है और यदि ऐसा कोई महायुद्ध छिड़ा तो दोनों ही पक्षों का लगभग पूर्ण विनाश हो जायेगा। अतः शीत युद्ध को अनावश्यक रूप से भड़का कर 'वास्तव-युद्ध' में परिणत कर देने से दोनों ही महाशक्तियाँ हिचक रही हैं। इस अनुभूति ने दोनों ही पक्षों को सहअस्तित्व की अनिवार्यता में विश्वास दिला दिया है जिससे शीत युद्ध की गर्मी एक बड़ी सीमा तक शान्त हो गई है और उतने एक

प्रकार के 'ठण्डे सहअस्तित्व' (Cool Coexistence) का रूप धारण कर लिया है। रूस ने पश्चिम के अस्तित्व को मिटाने का सकल्प स्वप्न समझ लिया है और पश्चिम में भी यह एक आम-विश्वास फैल रहा है कि रूस कुछ विवादों को सुलझाने में तो अवश्य ही निष्कपटता रखता है। फिर भी कुछ निराशावादियों का यही कहना है कि रूस का विश्वास करना पश्चिमी देशों का भोलापन है। यह मत सम्भवतः विश्व के अधिकांश वर्ग और अधिकांश जनता को स्वीकार्य नहीं होगा।

शीतयुद्ध के १९५३ के बाद के इतिहास से, और विशेषकर ब्यूवा-सकट की समाप्ति के बाद से निष्कर्ष यही निकलता है कि यद्यपि समय समय पर ऐसी घटनाएँ होती रही हैं जिनसे मौके-मौके काफी अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न हो जाता है, फिर भी जैमाकि एडवर्ड ब्रेकशा का मत है कि—“ब्यूवा के बाद से ज्वार एक ही दिशा में बह रहा है। वाशिंगटन के साथ एक लगातार और युक्त कथोपकथन के साथ 'उष्ण स्थलों का एक क्रमिक शीतलीकरण' (Damping down) हुआ है।”¹

शीत युद्ध केवल 'पूर्व' और 'पश्चिम' की विशेषता ही नहीं रही है बल्कि स्वयं साम्यवादी दुनिया में भी इसने अपना प्रभाव दिखाया है। साम्यवादी दुनिया में 'शीत युद्ध के नेता सोवियत रूस और साम्यवादी चीन हैं। जहाँ रूसी स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही सहअस्तित्व के प्रति पूर्वापेक्षा अधिक आश्वस्त हुए हैं वहाँ चीन साम्यवादियों का कहना है कि पूँजीवाद के साथ समाजवाद का अस्तित्व एक बेतुकी बात है। स्वयं को ससार का सबसे बुद्धिमान और विवेकशील तथा युद्ध-अनुभवी समझने वाले माओत्सेतुंग का अलाप है कि देवता और दानव एक साथ अगल-बगल में नहीं रह सकते। दानव रूपी पूँजीवाद का विनाश करना प्रत्येक साम्यवादी का परम पुनीत कर्तव्य है। उसका मत है कि जो साम्यवादी शान्तिपूर्ण सहजीवन की बात करते हैं वे असली मार्क्सवादी नहीं हो सकते। इस प्रकार साम्यवादी दुनिया में चलने वाला यह भयंकर सैद्धान्तिक मतभेद 'एक ही घर में शीत युद्ध' वाली बात है। स्वयं इस में इस सैद्धान्तिक मतभेद के कारण अन्दर ही अन्दर दो गुट हैं—स्टालिनवादी गुट, जो पहले से ही विद्यमान है और ख्रुश्चेववादी गुट, जो सहअस्तित्व का पक्ष करते हैं। यद्यपि श्री ख्रुश्चेव का लगभग राजनीतिक सन्ध्या हो चुका है, किन्तु वर्तमान रूसी नेतृत्व अपनी विचारधारा में बहुत कुछ ख्रुश्चेववादी ही है।

साम्यवादी सत्तार के इस सघर्ष का प्रभाव पश्चिम द्वारा चलाये जाने वाले 'शीत युद्ध' पर निश्चित रूप से पड़ा है। पश्चिमी गुट यथासम्भव ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहते कि जिसमें क्रैमलिन में स्टालिनवादी पक्ष को सहारा मिले। स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका को अधिकाधिक विश्वास होता जा रहा है कि पूँजीवादी विद्व के लिए अब साम्यवादी रुत संभवतः इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि साम्यवादी चीन निकट भविष्य में हो सकता है। चीन की आक्रामक नीति से न केवल पश्चिमी राष्ट्र अपितु स्वयं रूस सहित विद्व के अन्य शांतिप्रिय राष्ट्र नरत हैं। सभी इन बात में अपना ओर विश्व का हित समझने लगे हैं कि या तो चीन को सहयोग का हाथ बढ़ाने के लिये विवश कर दिया जाय या फिर उसे अकेला बना दिया जाय। इसके साथ ही अब यह नवीन चर्चा भी चल पड़ी है कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब चीन के विरुद्ध अमेरिका और सोवियत रूस का एक संयुक्त मोर्चा बन जाय।¹ रूस और चीन के सैद्धान्तिक मतभेद खुट-पुट तथा सीमा-सघर्ष शीत युद्ध में निश्चित रूप से शिथिलता लाये है। अब देखना यह है कि ऐसी स्थिति कब तक कायम रहनी है। जहा तक शीत युद्ध की पूर्ण समाप्ति का प्रश्न है; इस बात की आशा निकट भविष्य में नहीं की जा सकती, क्योंकि युद्ध का कुनिभ खातावरण अमेरिकन आर्थिक व्यवस्था को जिन्दा रखने के लिए आवश्यक है और इस हालत में शीत युद्ध की स्थिति कायम रहना भी जरूरी है।

अन्त में, शीत युद्ध के सम्बन्ध में यह बात याद रखी जानी चाहिए कि 'शीत युद्ध के परस्पर विरोधी खेमों में यदा-कदा सेतुबन्ध (Bridge) का काम भारत सहित कुछ तटस्थ राष्ट्रों ने किया है, अन्यथा 'शीत युद्ध' में सलग्न राज्य के बीच कभी भी सघ महायुद्ध हो सकता था। भारत ने 'शीत युद्ध' वाले राज्यों के मध्य सह-अस्तित्व स्थापित करने पर हमेशा बल दिया है और विश्व के सैनिक सगठनों को सदा निरस्त्राहित किया है।

सैद्धान्तिक संघर्ष बनाम शक्ति-राजनीति (Ideological Conflict or Power Politics)

अब हमें 'शीत-युद्ध' के एक दूसरे पक्ष पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए। प्रायः यह कहा जाता है कि 'शीत-युद्ध' एक सैद्धान्तिक सघर्ष (Ideological Conflict) है जिसमें दो विरोधी जीवन-वृद्धतियाँ-उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद—सर्वोच्चता के लिए सघर्ष-रत हैं। वास्तव में इससे इन्कार करना आमक होगा कि शक्ति राजनीति के इस युग में सोवियत सघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य जो एक विशेष प्रकार

की प्रतिद्वन्द्विता है, वह सचमुच सैद्धान्तिक है। इसके पीछे एक गहन सामाजिक दर्शन है जो अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का एक मुख्य कारण बन गया है। समुक्त राज्य अमेरिका सोवियत प्रणाली की एक अन्तर्राष्ट्रीय पटवन्त्र मानता है जिसका उद्देश्य अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अवका एन-केन प्रकारेण अपना प्रभाव डालकर साम्यवाद का प्रसार करना है। दूसरी ओर सोवियत मध्य अपने बहुत अनुभवों के आधार पर पड़िचमी देशों की प्रणालियों की शोषण, आनमण, हीनतर उपायों से भी स्वार्थ लाभ तथा सगठित लूट-खसोट के ऊपर आधारित मानता है। दोनों देशों और उनके पिछलग्गू राष्ट्रों के दृष्टिकोण परस्पर इस तरह विरोधी अथवा प्रतिकूल हैं कि उनका प्रभाव हर क्षेत्र पर पड़ा है और सर्वत्र रूस, अमेरिका के वैचारिक मध्य प्रवेश कर गये हैं। यह वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक मध्य आज विश्व राजनीति का एक आधार बन चुका है और इसी मध्य को जारी रखने एवं इसमें सफलता प्राप्त करने के प्रत्येक संभव उपाय सोचे जा रहे हैं।

दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति इतने सशक्त हैं कि अपनी व्यवस्था के रक्षार्थ उन्होंने गुप्तचरों का एक विश्वव्यापी जाल बिछा रखा है। सैद्धान्तिक मध्य में और एक-दूसरे के दर्शन से अपने दर्शन को अथवा अपनी जीवन-व्यवस्था को थोड़तर सिद्ध करने के लिए प्रचार के सही-गलत माध्यम हैं, उनका निर्भर रूप से अनुसरण किया जाता है, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देकर अविच्छिन्न देशों की मित्रता खरीदी जाती है, सामरिक सामग्रियों पर नियंत्रण किया जाता है और दुर्गल देशों के आर्थिक तन्तुओं पर भी कब्जा जमा लिया जाता है। इतना ही नहीं, अन्य देशों के अन्दर जो राजसत्ता के लिए मध्य होते हैं उनमें भी किसी दल का पक्ष लेकर सैद्धान्तिक मध्य को बढ़ाया जाता है।

इस तरह इस तथ्य में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि वर्तमान शीत-युद्ध का एक तबोपरि आधार सैद्धान्तिक अथवा वैचारिक मध्य (Ideological Conflict) ही है। अर्नोल्ड टायनबी ने शीत-युद्ध को एक सैद्धान्तिक मध्य मानते हुए विश्व-राजनीति की 'दि-ध्रुवी' व्याख्या की है। श्री टायनबी के अनुसार वर्तमान समय में विश्व राजनीति में केवल दो सिद्धांत और केवल दो शक्तियाँ हैं—उदारवादी लोकतन्त्र तथा सर्वाधिकारवादी साम्यवाद और समुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस।

निष्कर्ष यह निकलता है कि शीत युद्ध को एक सैद्धान्तिक मध्य की समा दी जाना गलत नहीं है। हाँ, यह कहना अवश्य भ्रामक है कि १९वीं शताब्दी की शक्ति-मत्तुलन की राजनीति से सर्वथा भिन्न यह केवल एक सैद्धान्तिक

तिक मंघर्ष मान है। कहने का आशय यह हुआ कि शीत युद्ध और सौदागिक सघर्ष परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं बल्कि सौदागिक सघर्ष शीत युद्ध के एक प्रधान कारण के रूप में स्वीकार्य है। इस बात के अनेक प्रमाण हमारे सामने हैं कि सौदागिक मतभेदों पर चल दिये जाने के बावजूद शीत युद्ध शक्ति-राजनीति का २०वीं शताब्दी का संस्करण है। प्रथम, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की 'द्वि ध्रुवी' व्याख्या (Bi-polar interpretation) पूर्णतया सही नहीं है। भारत तथा एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो पाश्चात्य प्रजातन्त्र व्यवस्था सोवियत या चीनी साम्यवाद में से किसी एक को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हुए एकतन्त्रता तथा अमलग्नता की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। दूसरे, दोनों ही गुटों (रूसी व अमेरिकन) द्वारा कुछ ऐसे देशों को सहायता दी जा रही है जो इन सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करते, जिनका संरक्षक होने का ये गुट दावा करते हैं। उदाहरणार्थ लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में अलोकतांत्रिक और फासिस्ट प्रवृत्ति की सरकारें पाई जाती हैं, किन्तु फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं को उनका प्रधान संरक्षक मानता है। तीसरे, प्रत्येक गुट में समान सिद्धान्तों के बावजूद आंतरिक मतभेद विद्यमान हैं। रूसी अथवा अमेरिकन कोई भी गुट मतभेदों तथा नेतृत्व की होड़ से परे नहीं है। साम्यवादी गुट में चीन ने सोवियत संघ के विरुद्ध बगावत का झंडा उठा रखा है तो पश्चिमी गुट में फ्रांस अपने गुट के विरुद्ध विद्रोह के मार्ग पर चल रहा है। चौथे, रूस और अमेरिका के मध्य का तनाव यह बताता है कि शीत युद्ध शक्ति-राजनीति (Power Politics) का ही एक रूप है। इन दोनों राष्ट्रों में सघर्ष और प्रतिस्पर्धा का तीव्र विनाश इसलिए हुआ क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के विघ्वंस से बचे हुए संसार में यह दोनों ही राष्ट्र विघ्न की महाशक्तियों के रूप में उदित हुए और अन्य किसी भी दिशा से चुनौती के अभाव में विश्व नेतृत्व के लिए साघर्षी हो गये और अब तो साम्यवादी चीन के रूप में एक तृतीय महाशक्ति का उदय हो रहा है जिसने इन दोनों बृहत् शक्तियों को सौदागिक सघर्ष के बावजूद परस्पर मंत्री और सहयोग की दिशा में अग्रसर होने को प्रेरित कर दिया है।

यूरोप का पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन

(RE-BUILDING AND RE-ORGANISATION
OF EUROPE)

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति घुरी राष्ट्रों की पराजय और मित्र राष्ट्रों की विजय में हुई। मानव इतिहास के एक अध्याय को इतिथो हो गयी और दूसरे का समारम्भ हुआ। इस महायुद्ध से पूर्व तक यूरोप विश्व इतिहास का निर्माता था, किन्तु अब वह आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व की दृष्टि से अपाहिज बन गया। महायुद्ध ने यूरोपीयन राष्ट्रों की राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया। प्राचीन काळ का 'ससार को अनुशासित करने वाला यूरोप' (World Dominating Europe) महायुद्ध के बाद नवीन 'समस्या प्रधान यूरोप' (Problem Europe) बन गया। १९४५ में यूरोपीयन प्रभुत्व का एक प्रकार से जनाजा ही निकल गया।

युद्ध के समय की उखाड़-पछाड़ों के कारण अनेक राष्ट्रों की सीमायें बदल गयीं और कुछ राष्ट्रों की शक्ति का पूरी तरह विनाश हो गया। द्वितीय महायुद्ध के पहले जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत रूस, इटली आदि यूरोप के कुछ देश बड़ी शक्तियों में गिने जाते थे। लेकिन ६ साल की भयानक लड़ाई के कारण यूरोप का चित्र ही बदल गया। विश्व विजय का स्वप्न देखने वाला और उसे त्रियाम्वित करने की शक्ति और कोशिश वाला जर्मनी पराजित, बर्बाद और विभाजित हो गया। इटली को घातक राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इटली की भाँति ही फ्रांस का भी बुरा हाल था। उद्योग औद्योगिक और कृषि उत्पादन चौंटा हो गया। जर्मनी द्वारा दिये गये विनाश से इसे जो हानियाँ उठानी पड़ी उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उसे

बहुत दिनों तक प्रमत्त करने पड़े। ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था घातक रूप से प्रभावित हुई। एक प्रमुख ऋणदाता राष्ट्र से उसकी स्थिति एक ऋणि या कर्जदार राष्ट्र की हो गयी। सोवियत रूस की जन-जन की भारी हानि हुई, किन्तु फिर भी वह पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन गया। युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि अब सत्तार में दो ही महानतम शक्तिशाली रह गयी हैं— सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों ही देश प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों के रूप में उदित हुए और युद्धोत्तर विश्व स्तरों से इनके प्रभाव क्षेत्रों में बढ़ता गया।

युद्ध-जनित परिवर्तनों के कारण यूरोपीय महाद्वीप के देशों में एकदम अव्यवस्था और अस्थिरता आ गयी। युद्ध में हारे हुए राष्ट्रों के स्वरूप निर्धारण, यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण और पुनर्गठन की समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। शीत युद्ध का शीर्षण हुआ और यूरोप के पुनर्व्यवस्था के प्रश्न पर विजेता शक्तियों में मतभेद खड़े हुए। इन मतभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करने तथा स्थाई शांति का निर्माण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन बुलाये गये और इनमें भारी विचार विमर्श के बाद यूरोप का एक नया रूप सामने आया।

यह कहा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद योरोप की परिस्थितियों में परिवर्तन आये उनका उदाहरण आधुनिक इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता। सोवियत रूस को छोड़कर शेष सारा यूरोप शक्ति राजनीति में इतना पिछड़ गया कि एरिक फिशर (Eric Fischer) आदि इतिहास के अनेक विद्वान 'योरोप का समय गुजर गया' (The passing of the European age) आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। विलियम फॉक्स (William T R Fox) का कहना है कि योरोप का सत्तापूर्ण प्रभाव बदल कर समस्यापूर्ण बन जाना ही हमारे समय की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक केन्द्रीय तथ्य है। योरोप की शक्ति क्षीण होने के कारण इसका स्थान अन्य दूसरे राष्ट्रों द्वारा ग्रहण किया जाने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की महान् शक्ति के रूप में उदित हुआ। योरोप के अधिकांश देश दूसरे या तीसरे नम्बर की शक्ति बन गये। शक्ति-राजनीति में इस उलट-फेर के अनेक कारण बताये जाते हैं। पहला तथा महत्वपूर्ण कारण तो द्वितीय विश्व युद्ध ही है जिसने योरोप के देशों की सैनिक शक्ति को समाप्त प्रायः कर दिया तथा वहाँ की आर्थिक स्थिति को डाबाडोल बना दिया। युद्ध के समय हथियारों तथा युद्ध की अन्य सामग्रियों का भारी मात्रा में निर्माण होने से आवश्यक चीजों के तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन को सटका लगा और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

में योरोप कुछ पिछड़ने लगा। खर्चा बढ़ जाने के कारण एव रक्षा बजट कई गुना हो जाना व कारण यहाँ की जनता पर करो का भार बढ़ गया। इसके अतिरिक्त योरोप व देशों का एशिया तथा अफ्रीका आदि महाद्वीपों में जो साम्राज्य फैला हुआ था वहाँ भी नवजागरण का उदय होना लगा तथा योरोप के देशों की सत्ता वहाँ से सिमटने लगी। इन सब आन्तरिक तथा बाह्य कारणों व परिणामस्वरूप योरोप का जो रूप हमारे सामने आया उसे देख कर हेरल्ड तथा मार्गरेट स्प्राउट (Harold and Margaret Sprout) का कथन तथ्य समत ही प्रतीत होता है। वे कहते हैं कि "अब राजनैतिक शक्ति एव विश्व नेतृत्व में केन्द्रीय तथा पश्चिमी योरोप का एकाधिकार नहीं रहा है।"

कुछ विचारकों के मतानुसार योरोप की शक्ति का ह्रास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्रारम्भ नहीं हुआ था यह बहुत पहले से ही शुरू हो गया था किन्तु फिर भी बाद में अनेक व्यापारिक, प्राकृतिक, राजनैतिक एव आर्थिक कारणों से इस प्रक्रिया की गति तीव्र हो गई। तीसरे युद्ध प्रारम्भ हो जाने के कारण बड़ी शक्तियों के बीच जो मतभेद तथा असहयोगपूर्ण वातावरण तैयार हुआ उसने युद्ध से उत्पन्न धाँति की पूर्ति को कठिन बना दिया। अब सारा विश्व का गुटों में विभाजित हो गया—साम्यवादी तथा असाम्यवादी। इन गुट राजनीति व परिणामस्वरूप जर्मनी का दो भागों में विभाजन कर दिया गया तथा भविष्य में उसका एकीकरण की आशा ही खूब गई। यूरोप की इन परिवर्तित परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया कि यहाँ के करोड़ों निवासियों व कल्याण एव सु-व्यवस्थित जीवन यापन के लिए योरोप का पुनर्निर्माण किया जाय।

शान्ति स्थापना के प्रयास

(Peace Making Attempts)

द्वितीय विश्व युद्ध के भयानक परिणामों तथा अणुशक्ति के आविष्कार के कारण तृतीय विश्व युद्ध की आशंका का हर बीमता पर निवारण करने के लिए मानवता तैयार हो गई। विश्व के प्राय सभी राजनीतिज्ञ दिल से यह चाहते लगे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थायी स्थापना का कोई मार्ग खोज निकाला जाय, किन्तु शान्ति को स्थायी बनाने से पूर्व उसे स्थापित करना आवश्यक था। इसके लिए विजेता राष्ट्रों के नेताओं ने सोचा कि इस बार कोई सामान्य शान्ति सम्मेलन नहीं बुलाया जाये क्योंकि इस प्रकार के प्रयासों की असफलता का अनुभव इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था। इसी कारण ब्रिटेन, अमरीका तथा सोवियत रूस की सरकारों ने पोट्सडाम (बर्लिन)

सम्मेलन, जुलाई-अगस्त, १९४५ में विदेश मन्त्रियों की एक परिपद का निर्माण किया। इसमें तीन बड़े (ब्रिटेन, रूस व अमेरिका) तथा फ्रांस और चीन-इस प्रकार पाच राष्ट्रों के विदेश मन्त्री थे। इस परिपद का कार्य शान्ति समझौते से सम्बन्धित आवश्यक कदम उठाना था। इस परिपद के निर्णय सर्वसम्मति से होने थे अतः इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक था कि सभी बड़ी शक्तियाँ एक मत हों।

इस परिपद की प्रथम बैठक लन्दन में सितम्बर-अक्टूबर, १९४५ में हुई तथा इसके बाद इस परिपद के इटली, रूमानिया, बल्गारिया, हंगरी और फिनलैण्ड आदि देशों के साथ सन्धि करने के लिए सितम्बर १९४५ से दिसम्बर १९४७ तक विभिन्न सम्मेलन बुलाये गये। ये पेरिस, न्यूयार्क, मास्को तथा लन्दन आदि स्थानों पर हुए। टक्क पाचों राष्ट्रों के बारे में शान्ति समझौते इन शर्तों के अनुसार किये जाने थे जो उन्होंने आत्म-समर्पण करते समय लगाई थी। यह व्यवस्था की गई कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस मिल कर इटली के साथ की जाने वाली सन्धि का मसौदा (Draft) तैयार करेंगे। रूस, अमेरिका व ब्रिटेन द्वारा बल्कान क्षेत्रों के लिए सन्धि का मसौदा तैयार किया जायेगा और फिनलैण्ड के लिए मसौदा तैयार करेंगे वहाँ का कार्य ब्रिटेन तथा सोवियत रूस करेंगे। बाद में इन सभी मसौदों पर मित्र राष्ट्रों तथा उनके समर्थक सभी राष्ट्रों के एक सामान्य सम्मेलन में उस पर विचार किया जायेगा। इस सम्मेलन की मित्फारिंगों को ध्यान में रखकर सन्धियों के अन्तिम रूप का निर्धारण विदेश मन्त्रियों की परिपद द्वारा ही किया जाता था। इन पाँच राज्यों के लिए सन्धि का मसौदा तैयार करने के काम का निरीक्षण करने के लिए विदेश मन्त्री परिपद ने पेरिस में दो सम्मेलन किये (१९४६)।

सन्धियों के मसौदे तैयार हो जाने के बाद इन पर विचार करने के लिए पेरिस में एक सामान्य सम्मेलन (General Conference) बुलाया गया। सन्धि मसौदों के लगभग ६० अनुच्छेद ऐसे थे जिन पर विदेश मन्त्री परिपद एकमत न थी। इन मन्त्री को सामान्य सम्मेलन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मई १९४६ की २६ जुलाई से १५ अक्टूबर तक इक्कीस राष्ट्रों के लगभग पन्द्रह सौ प्रतिनिधियों ने सन्धि मसौदों पर अनुच्छेदों के अनुसार विचार किया। कैम्पबेल (Campbell) महोदय का विचार है कि "इस सम्मेलन में विचार विमर्श का जो तरीका अपनाया गया तथा प्रतिनिधियों द्वारा जो दृष्टिकोण रखा गया उसके कारण किसी सर्वमान्य समझौते पर पहुँचने की सम्भावना ही समाप्त हो गई।" अनेक राष्ट्रों ने सम्मेलन पर

बड़ी शक्तियों के अतिशय प्रभाव का विरोध किया तथा इसी प्रश्न पर असंतुष्ट होकर आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने सम्मेलन को ही छोड़ दिया।

सन्धियों की मुख्य मुख्य धाराएँ

(The Main Provisions of Treaties)

पेरिस में होने वाला सामान्य सम्मेलन प्रायः असफल ही माना जाता है किन्तु फिर भी इस सम्मेलन का महत्त्व है क्योंकि इसमें जो मिकारिओं की गई थी उन पर विदेश मंत्री सम्मेलन में बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया तथा उनमें से कुछ को अपनाया भी गया। सन १९४६ में विदेश मंत्रियों की इस परिपद की न्यूयार्क में बैठक हुई। इस बैठक में पाँचों सन्धियों की शर्तों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया। इन सन्धियों की मुख्य मुख्य बातें निम्न प्रकार थी—

(१) इटलियन प्रायद्वीप का अधिकांश भाग, इटली का कुछ सीमा-वर्ती प्रदेश तथा ट्रिस्टे (Trieste) बन्दरगाह को मिलाकर एक स्वतंत्र प्रदेश बना दिया गया तथा इसे संयुक्त राष्ट्र सच को सुरक्षा परिपद के निरोक्षण में रखा गया। इस उपयय को चारों ही बड़ी शक्तियों ने स्वीकार कर लिया किन्तु यथायथं यह मुझाव सभी के लिए असतोषजनक था।

(२) इटली और यूगोस्लाविया के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए अमेरिका तथा रूस दोनों की ओर से सुझाव आये थे। सम्मेलन द्वारा इन दोनों ही सुझावों के बीच का रास्ता अरनाया गया।

(३) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इटली को जहाँ सीमाएँ थीं उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। ब्रिगा टेन्डा (Briga Tenda) तथा उसके अन्य कुछ छोटे क्षेत्र फ्रांस को दे दिए गए।

(४) इटली के उपनिवेशों की व्यवस्था से सम्बन्धित विषयों को आगे के लिए छोड़ दिया गया तथा यह तय किया गया कि यदि विदेश मंत्री परिपद एक वर्ष के भीतर भीतर इस विषय पर कोई निणय न ले सके तो यह मामला संयुक्त राष्ट्र सच की महासभा को सौंप दिया जायेगा और महासभा का निर्णय बाध्य होकर मानना पड़ेगा। फरवरी महासभा ने १९४६ के अन्त काल में इस समस्या पर विचार किया।

(५) यह तय किया गया कि इटली हज़ारों हज़ारों के रूप में ३६ करोड़ डॉलर की राशि अदा करेगा। इस राशि का अधिकांश भाग यूनान तथा यूगोस्लाविया को दिया जाना था। हंगरी, चेकोस्लाविया तथा फिनलैंड में प्रत्येक पर हज़ारों की रकम दान करोड़ डॉलर रखा गई। इनका अधिकांश भाग सावित

रुस को दिया जाना था। बल्गेरिया को दो करोड़ पाच लाख डालर यूगोस्लाविया को देना था तथा चार करोड़ पाच लाख ग्रीनान को देना था।

(६) रूमानिया ने बिसाराबिया तथा बुकोविना पर रुस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया और सारा ट्रान्सिल्वानिया उसके स्वयं के अधिकार में आ गया।

(७) फिनलैण्ड ने पेतसामो प्रान्त सोवियत रुस को सौंप दिया तथा पचास साल के पट्टे पर हेल्सिंकी के पश्चिम की ओर उन्नीस मील दूर पोरकाला उद् (Porkkala-Udd) का क्षेत्र सोवियत रुस को ही नौ-सैनिक बट्ठा बनाने के लिए दे दिया।

(८) सोवियत रुस की सहमति से बलकान सन्धियों द्वारा डनूबे (Danube) में स्वतन्त्र नौ संचालन की गारन्टी दी गई किन्तु बाद में रुस ने इस प्रकार की स्वतन्त्रता को ब्यान्वित होने से रोक दिया। चारों बड़े राष्ट्रों ने यह निश्चय किया कि सन्धियों के प्रभावशाली होने के छ मास बाद डनूबे पर एक अन्तर्राष्ट्रीय नौका संचालन सत्ता की व्यवस्था के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाय। इस प्रकार का एक सम्मेलन सन् १९४८ के जुलाई-अगस्त में बेलग्रेड में बुलाया गया।

इन शांति सन्धियों द्वारा पराजित राष्ट्रों को आक्रमणकारी प्रयासों का समुचित दण्ड मिला और विजयी राष्ट्रों को उनकी क्षतिपूर्णे की व्यवस्था के लिए घन एवं प्रदेश दिलाने का प्रबन्ध किया गया। शांति-सन्धियों ने यूगोस्लाविया को बलकान प्रायद्वीप में सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक लाभ रुस को हुआ। राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से भी पूर्वी यूरोप में रुस का अधिकार स्थापित हो गया। इन शांति-सन्धियों से पश्चिमी राष्ट्रों को आर्थिक अथवा प्रादेशिक दृष्टि से किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ, उल्टे भावी समझौते में रुस की मांगें उत्तरोत्तर बढ़ती गयीं जिनके परिणामस्वरूप मित्र राष्ट्र जर्मनी, जापान और आस्ट्रिया के साथ सामूहिक रूप से शांति सन्धिया करने में असफल रहे।

ये शांति सन्धिया यद्यपि १५ सितम्बर, १९४७ से अन्तिम रूप में लागू कर दी गयीं तथापि इन सन्धियों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इनके अनेक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ अथवा उनकी उपेक्षा की गई।

आस्ट्रिया के साथ सन्धि

(Peace Treaty with Austria)

छोटे-छोटे राज्यों के साथ तो पाचों शान्ति सन्धिया सम्पन्न कर ली गई, लेकिन आस्ट्रिया, जर्मनी और जापान के साथ शान्ति-सन्धि करने में

गम्भीर मतभेद और उग्र-तनाव बढ़ता गया। फिर भी आस्ट्रिया के साथ सन्धि करने की दिशा में कुछ अधिक आशा दिखाई दी।

द्वितीय महायुद्ध काल में १९४३ में मास्को सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि युद्ध के बाद आस्ट्रिया की स्थापना पुनः एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में की जाएगी। लेकिन जुलाई १९४५ के एक अन्य सम्मेलन के अनुसार न केवल आस्ट्रिया को चार क्षेत्रों में बांट दिया गया, बल्कि उसकी राजधानी वियना के भी चार टुकड़े कर दिए गए। फिर भी आस्ट्रिया की इच्छानुसार सरकार स्थापित करने तथा विद्वानों सम्बन्धों का सम्भालन करने का अधिकार दिया गया।

युद्ध समाप्ति के बाद विदेश मंत्रियों की परिषद में आस्ट्रिया और जर्मनी का मामला अनेक बार उठा और गिरा। १९४७ के मास्को सम्मेलन में इस मामले पर पुनः विचार हुआ। पाश्चात्य शक्तिशाली और सोवियत रूस के मध्य मुख्य मतभेद तीन बातों पर था—

(i) दक्षिणी कैरन्थिया में आस्ट्रियन प्रदेश के एक भाग पर युगोस्लाविया का दावा, (ii) युगोस्लाविया द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में १५ करोड़ की घनराशि की मांग, एवम् (iii) जर्मन सम्पत्ति की परिभाषा।

अंतिम विवाद (जर्मन सम्पत्ति की परिभाषा का) अधिक आधारभूत था। सोवियत रूस का तर्क था कि आस्ट्रिया में किसी भी सदन द्वारा अधिकृत की गई जन सम्पत्ति पर उसका स्वयं का अधिकार है जबकि पश्चिमी राष्ट्रों को यह अस्वीकार्य था।

१९५५ के प्रारम्भ तक अनेक बार विचार विमर्श होने पर भी आस्ट्रिया का प्रश्न अधर स्तर में लटका रहा। अप्रैल, १९५५ में आस्ट्रियन चांसलर ने अपने देश की निरपेक्ष नीति (Policy of Neutrality) घोषित की। तत्पश्चात् पर्याप्त सोवियत विचार के बाद, १५ जुलाई, १९५५ को आस्ट्रिया के साथ शांति सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए। सन्धि पर मधुरतः राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और आस्ट्रिया ने हस्ताक्षर किए। यद्यपि आस्ट्रिया एक प्रमुख गम्भीर, स्वतन्त्र और प्रजातन्त्रात्मक राज्य बन गया, लेकिन यह निश्चित कर दिया गया कि वह जर्मनी के साथ कोई राजनीतिक या आर्थिक सम्बन्ध नहीं बनाएगा तथा विस्फोटकारी शस्त्रों की दौड़ में नहीं उल्लेखित।

जर्मनी के साथ सन्धि शर्तें

(Peace Talks with Germany)

युद्ध काल में ही जर्मनी के साथ शांति रचना के मिशनरों को तय कर लिया गया था, लेकिन युद्ध के बाद सम्बन्धित पक्षों में इतना उग्र मतभेद

प्रकट हुए कि आज तक इस सम्बन्ध में विधिवत् कोई सधि सम्पन्न नहीं हो सकी है।

युद्ध की समाप्ति पर स्थिति यह थी चारों महाशक्तियों ने जर्मनी को चार क्षेत्रों में विभक्त कर उन पर अपना अधिकार जमा लिया था और चारों ही क्षेत्रों के प्रधान सेनापतियों को अपने प्रदेश में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। चारों राष्ट्रों की मित्र राष्ट्रों ने नियन्त्रण परिषद बर्लिन में फिर स्थापित हुई जो आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकी और १९४८ में समाप्त हो गयी।

युद्ध के बाद १९४६ में जर्मनी से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर रूस एवं अमेरिका में जबरदस्त खींचातानी होने लगी। रूस की मांग थी कि जर्मनी को शक्तिशाली सघीय राज्य बनाया जाय और वह १८ वर्षों के भीतर दस अरब डालर क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। इसके अतिरिक्त रूस का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया जाय और पूर्वी सीमाओं का नये ढंग से निर्धारण हो। आंग्ल-अमेरिकन गुट चाहता था कि जर्मनी में प्रजातांत्रिक सघीय सरकार की स्थापना की जाय, सेनाओं का पुनर्निर्धारण किया जाय और जर्मनी की हालत आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ बना दी जाय ताकि वह क्षतिपूर्ति आसानी से अदा कर सके।

पेरिस बैठक में अमेरिकन विदेश मन्त्री बर्नेस (Burnes) ने रूसी मंत्रियों को बम करने की दृष्टि से जर्मन निःशस्त्रीकरण और अस्त्रिकीकरण के सबब में एक २५ वर्षीय सधि का सुझाव रखा, परन्तु १ जुलाई, १९४६ को मोलोटोव ने यह कहकर इस सधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि यह अपूर्ण है और इसका उद्देश्य जर्मनी के शक्ति का पुनरुत्थान करना है। इसके अगले ही दिन मोलोटोव ने परिषद में घोषणा की कि जर्मनी के साथ सधि करने से पूर्व एक ऐसी अखिल जर्मन सरकार की स्थापना की जानी चाहिए जो विमुक्त रूप से लोकतान्त्रिक हो और नाज़ी तत्वों को मज्ज कर देने में तथा मित्र राष्ट्रों के प्रति अपने दायित्वों को—विजयकर क्षतिपूर्ति के दायित्वों को पूरा करने में समर्थ हो। रूस के इस रवैये से अमेरिका, जर्मनी की आर्थिक एकता के प्रयत्न में लग गया और उसने घोषणा की कि वह जर्मनी की आर्थिक एकता की दृष्टि से जर्मन अधिकार-क्षेत्रों से सम्बन्धित सरकारों के साथ मिल-जुल कर काम करने को तैयार है। २० जुलाई, १९४६ को ब्रिटेन ने स्पष्टतया रूस को यह बता दिया कि यदि वह (रूस) जर्मनी की आर्थिक एकता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा तो ब्रिटेन अमेरिका के प्रस्ताव को मांग लेगा और ब्रिटेन तथा अमेरिका के जर्मन अधिकार क्षेत्रों को राखवत कर दिया

जायगा। रूस की कटु आलोचनाओं और उसके उग्र विरोध का मित्र राष्ट्रों के निश्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और १ जनवरी, १९४७ को ब्रिटिश-अमेरिकन अधिकार क्षेत्रों को मिला कर एक द्विशेत्र (Bizonia) का निर्माण किया गया। इस द्विशेत्र के प्रशासन हेतु एक संयुक्त बोर्ड, एक संयुक्त आर्थिक नियंत्रण बोर्ड एवं एक जर्मनी कार्यपालिका कमेटी की स्थापना की गयी।

स्पष्टतः उपरोक्त व्यवस्था जर्मन समस्या का कोई समाधान न थी। जनवरी १९४७ से मार्च १९४७ के मध्य जर्मनी और आस्ट्रिया की समस्या को हल करने के लिए विदेश-मन्त्रियों की अनेक बैठकें हुईं। १० मार्च, १९४७ से आरम्भ होने वाली मास्को की विदेश-मन्त्री परिषद की बैठक में जर्मन समस्या के सम्बन्ध में ५० दिन तक लम्बा वाद-विवाद होता रहा। परन्तु इसमें केवल दोनों पक्षों में कटुता और घमनस्थ की वृद्धि ही हुई। तत्कालीन अमेरिकन विदेश-मन्त्री जॉन फास्टर डलंस के मतानुसार दोनों पक्षों में मतभेद के निम्नलिखित कारण थे—

१. अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी का ऐसा पुनर्निर्माण चाहते थे जिससे भविष्य में जर्मनी कभी भी युद्ध न कर सके। जबकि रूस जर्मनी को पुनः मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का आकांक्षी था।

२. पोद्सडम सम्मेलन में तय हुआ था कि जर्मनी में अधिक शक्ति-सम्पन्न केन्द्रीय सरकार न हो, किन्तु रूस शोषित क्षेत्र में पलिन से संचालित होने वाली शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार, शक्तिशाली राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन सब के निर्माण का पक्षपाती था।

३. जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से निर्वहण बनाने के लिए पोद्सडम सम्मेलन ने यह व्यवस्था की थी कि युद्ध-सामग्री का उत्पादन करने वाले जर्मन कारखानों की मशीनों एवं अन्य सामग्री क्षतिपूर्ति के रूप में रूस आदि को दे दी जायगी। रूस ऐसे बहुत से कारखाने व मशीनें अपने देश में ले गया लेकिन इन्हें चलाने में सफल नहीं हो सका। अधिकांश मशीनें रेल्वे स्टेशनों पर पड़ी हुई जंग लाने लगी। अतः अब रूस यह चाहने लगा कि क्षति-पूर्ति के रूप में जर्मन कारखाने न उठाये जायें अपितु उन कारखानों में उत्पादित माल लिया जाय और इसके लिए जर्मनी का औद्योगीकरण हो और वह जर्मनी से १० अरब डालर का हर्जाना वसूल कर सके।

उपरोक्त मतभेदों के अतिरिक्त दोनों ही पक्षों में और भी कुछ मतभेद थे—

(1) पश्चिमी राष्ट्र जर्मनी का नया संविधान संघात्मक (Federal) बनाना चाहते थे जबकि रूस, आरम्भ में सहमत होने पर भी बाद में इसका विरोध करने लगा ।

(11) पश्चिमी देश राइन प्रदेश को जर्मनी से पृथक करना चाहते थे पर रूस इस बात से सहमत न था ।

(111) मित्र राष्ट्र इस पक्ष में थे कि जर्मनी के औद्योगिक व्यापारिक शर्षों तथा बड़ी जमीदारियों को नष्ट किया जाय, जबकि मास्को रूस पर चार शक्तियों के नियन्त्रण का और व्यापारिक संघों (Cartels) तथा जमीदारियों आदि की समाप्ति का पक्षपाती था ।

(1V) जर्मनी की पूर्वी सीमाओं के सम्बन्ध में भी वे एक मत नहीं थे । सोवियत रूस पोट्सडम सम्मेलन द्वारा निर्धारित सीमा को अन्तिम मानता था जबकि पश्चिमी राष्ट्र इसमें संशोधन के पक्षपाती थे ।

(V) सोवियत रूस द्विशेष (Bizonia) के निर्माण से बहुत कोपित हो गया था । इसका अभिप्राय, पश्चिमी जर्मनी को शेष जर्मनी से पृथक करना था और रूर क्षेत्र से (जो खनिज वपदा का भण्डार था) सोवियत रूस को दूर रखना था । रूस की आकांक्षा थी कि "रूर क्षेत्र पर भी चारों राष्ट्रों का नियन्त्रण रहे ।"

(VI) पूर्व और पश्चिम की लोकमान्यताओं में आधारभूत अन्तर था क्योंकि पश्चिम ने निवासियों को विशेषकर अमेरिकन लोगों को—महायुद्ध से उत्पन्न धन जन के विनाश का उतना व्यावहारिक अनुभव नहीं था जितना रूसियों को था । मोलोटोव का कहना था "कनि पूर्ति का प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक भिन्न अर्थ रखता है जोर सोवियत संघ के लिये दूसरा । संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति दूगरी होई । नाज़ा अधिकृत क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये विनाश, घोर दुष्कर्म और लूट पाट आदि का अनुभव करने के उपरांत रूसी नागरिक जो महमूस करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग वैसा महसूस नहीं करते ।"

उपरोक्त सभी मतभेद इतने व्यापक और उग्र थे कि पूर्व और पश्चिम में कोई समझौता हो सकने की सम्भावना मास्को सम्मेलन में नजर नहीं आई और फलतः जर्मनी के साथ कोई संधि नहीं की जा सकी । अब मित्र राष्ट्र (ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस) रूस की उपेक्षा करते हुए अपने द्वारा अधिकृत जर्मन प्रदेशों के बारे में एक पदम और आगे बढ़े । जनवरी १९४७ में ब्रिटेन और अमेरिका द्विशेष (Bizonia) का निर्माण कर ही चुके थे, ३१ मई १९४८ को फ्रांस के साथ मिल कर उन्होंने, अर्थात् अमेरिका ब्रिटेन व फ्रांस

तीनों ने अपने-सीनो क्षेत्रों (Trizonia) के लिए एक केन्द्रीय सरकार बनाना स्वीकार कर लिया। २१ सितम्बर, १९४६ को पश्चिमी जर्मनी में संघीय गणराज्य (Federal Republic of Germany) की स्थापना हुई जो अब तक चला आ रहा है और जिसकी राजधानी बोन (Bonn) है। मित्र राष्ट्रों के सैनिक कमिशन ने पश्चिमी जर्मनी के इस संघीय गणराज्य के प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये। दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में सोवियत संघ ने ७ अक्टूबर १९४६ को जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य (German Democratic Republic) की स्थापना की जिसकी राजधानी सोवियत क्षेत्र के बर्लिन में स्थित है।

बू कि अभी तक जर्मनी के साथ कोई शान्ति संधि सम्पन्न नहीं हो सकी थी, जब वैधानिक दृष्टि से जर्मन और मित्र राष्ट्रों के मध्य युद्ध की अवस्था विद्यमान थी। सन् १९५१ में पाश्चात्य राज्यों ने अपनी तरफ से जर्मनी के साथ युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी और २६ मई, १९५२ को 'Contractual Agreements' के द्वारा पश्चिमी जर्मनी को व्यावहारिक स्वशासन प्रदान कर दिया गया। ५ मई, १९५५ को जर्मन नेताओं की बोन पार्लिमेन्टरी कौंसिल द्वारा 'जर्मनी के संघीय गणराज्य का मौलिक कानून' (Basic Law of the Federal Republic of Germany) तैयार किया गया और उसे पश्चिमी क्षेत्रों के मित्र राष्ट्रीय सैनिक गवर्नरों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस अधिनियम द्वारा पश्चिमी जर्मनी पर से पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने सैनिक अधिकार समाप्त कर दिये और इस प्रकार संघीय गणराज्यों की स्वाधीनता तथा सर्वोच्च प्रभुता प्राप्त हो गयी। सोवियत संघ ने भी २० सितम्बर, १९५५ को एक संधि द्वारा पूर्वी जर्मनी के जनतांत्रिक गणराज्य को पूर्ण स्वाधीनता और प्रभुता प्रदान कर दी जो वास्तव में मात्र सैद्धान्तिक ही थी क्योंकि व्यावहारिक रूप से पूर्वी जर्मन सरकार पर पूरा नियन्त्रण सोवियत संघ का ही है।

जर्मनी की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए अभी तक एक प्रश्न चिन्ह बनाया हुआ है क्योंकि इसके सम्बन्ध में पाश्चात्य शक्तियों और सोवियत संघ के मध्य अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। आज भी जर्मनी में दो सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य-जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य तथा जर्मनी का संघीय गणराज्य मौजूद हैं।

यूरोप का आर्थिक विकास एवं एकीकरण

(Economic development and integration of Europe)

यूरोप का विकास करने के लिए पश्चिमी शक्तियों द्वारा मर्सल योजना आदि का प्रस्ताव किया गया किन्तु इन सभी योजनाओं को सोवियत

रूस तथा उसके गुट के अन्य देशों द्वारा बस्वीकार कर दिया गया। इस मतभेद के कारण कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका जिसके द्वारा योरोप के सभी राष्ट्रों का विकास किया जा सके। हार कर दोनों गुटों द्वारा उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अलग-अलग योजनाएँ बनाई जाने लगी। महाद्वीप विभाजित हो गया तथा क्षेत्रीय आधार पर उसकी हानि पूर्ति करने के प्रयास किये गये। सभी देशों की लगभग समान समस्याएँ थी और उनको दूर करने के मार्ग भी प्रायः एक से ही थे। इन कारणों से इन देशों के बीच एक अभूत-पूर्व सहयोग के वातावरण का जन्म हुआ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिमी योरोप का एकीकरण करने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। पश्चिमी योरोप के देशों की सभी समस्याएँ प्रायः समान थी और इनको सुलझाने के लिए राजनैतिक, नैतिक तथा आर्थिक कदम उठाने परम आवश्यक थे। योरोप ने आर्थिक एकीकरण के लिये जो मुख्य-मुख्य कदम उठाये गये उनमें बेनेलक्स (Benelux), मार्शल योजना (Marshal Plan), यूमेन योजना आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका संक्षेप में परिचयात्मक विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(१) बेनेलक्स

(Benelux)

योरोप के देशों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने का यह प्रथम महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह सन्धि बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स तथा लक्जमबर्ग—इन तीन देशों के बीच सितम्बर, १९४४ में ही कर ली गई थी। जनवरी, १९४८ से इसे संशोधित रूप में स्वीकार किया गया। पामर तथा परकिन्स के शब्दों में इस सन्धि द्वारा इसमें भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों के बीच चुंगी (Custom duty) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा आयात पर एक समान टैरिफ कार्यक्रम की स्थापना की गई। यह बताया जाता है कि इस सन्धि का अन्तिम लक्ष्य पूर्ण आर्थिक-सह का निर्माण करना था। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने १ जनवरी, १९५० को इस प्रकार के संधि प्रारम्भ करने की तिथि निश्चित की और बाद में इस तिथि को कई बार आगे बढ़ा दिया गया क्योंकि इसे क्रियान्वित करने के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएँ थी। बाद में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जब तक कुछ बड़े उद्योगों के विशेष हितों को और यहाँ तक कि राष्ट्रीय हितों को भी अधोन्मुख या शीघ्र नहीं बना दिया जाता तब तक पूरे योरोप के आर्थिक कामों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बेनेलक्स देशों का प्रारम्भिक प्रयास प्रसन्ननीय होते हुए भी पर्याप्त नहीं था तथा उसके क्षेत्र एवं प्रभाव का विस्तार किया जाना आवश्यक था।

मार्शल योजना एवं यूरोपीय आर्थिक सहयोग तथा विकास का संगठन
(Marshall Plan and OECD)

साम्यवाद का खतरा बढ़ता जा रहा था। समुक्त राज्य अमेरिका को यह आशंका होने लगी थी कि यदि योरोप के पिछड़े तथा युद्ध से पीड़ित देशों का उत्थान न किया गया तो वे सम्भवतः साम्यवाद का मार्ग ग्रहण कर लेंगे और इस प्रकार अमेरिका के हित खतरे में पड़ जायेंगे। यह अनुमान लगाया गया कि शायद इसी आशंका में सोवियत रूस योरोप का आर्थिक विकास करने वाली किसी सन्धि में सम्मिलित नहीं हो रहा था। राज्य सचिव जार्ज सी० मार्शल द्वारा ५ जून, १९५७ को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिये गये अपने भाषण में बताया कि योरोप के पुनरुद्धार के लिए प्रयत्न किया जाना परम आवश्यक था। एक ऐसी वर्ध व्यवस्था का पुनरुद्धान किया जाये जिसमें ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो कि जो स्वतन्त्र संस्थाओं का विकास कर सकें। मार्शल द्वारा योरोप को सहायता देने की योजना प्रस्तुत की गई जिसमें यह बताया गया कि योरोप के देश स्वयं यह बतायें कि उनको कैसी तथा किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार पहले योरोप के देशों की ओर से ही होनी चाहिये, समुक्त राज्य अमेरिका तो इस मांग को पूरी करने का प्रयास भर कर सकता है। मार्शल की घोषणा के बाद योरोप के १६ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा पुनरुद्धान के लिए किये जाने वाले सामूहिक कार्यक्रम पर विचार किया गया तथा बाह्य सहायता की मांग एवं महत्व को भी ध्यान में रखा गया। मोलोटोव तथा अन्य रूसी प्रतिनिधियों ने कुछ दिनों तक इस सम्मेलन में भाग लिया तथा बाद में उसे छोड़ कर चले गये। रूस की सरकार द्वारा मार्शल योजना के आधार को ही गलत बताया गया और इसे अमेरिकन साम्राज्यवाद का प्रतीक तथा छिपे हुए स सोवियत सभ के विरुद्ध एक गठबन्धन माना गया। रूस के दृष्टिकोण का अनुगमन करते हुए चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड आदि देशों ने भी योजना में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। हेर्बर्ट ल्यूथी (Herbert Luthy) के मतानुसार इस अवसर पर पश्चिम तथा सोवियत गुट के बीच एक विभाजन रेखा खींची गई जिसके कारण योरोप का आगामी वर्धों का इतिहास प्रभावित रहा।

कठिनाइयों के बावजूद जुलाई १९४७ में १६ यूरोपीय देशों (दक्कैंट, फ्रान्स, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीस, आइसलैंड, इटली, नार्वे, स्वीडन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, नीदरलैंड और टर्की) के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग समिति (Committee of European Economic Co-operation) की स्थापना की गयी और यूरोपीय पुनरुद्धार का चार वर्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम तैयार किया गया।

यूरोपियन आर्थिक सहयोग समिति ने समुक्त राज् अमेरिका को एक रिपोर्ट अर्पित की जिसमें कहा गया कि अमेरिका यदि १६ ३ बिलियन डॉलर धन राशि खर्च करने को तैयार हो तो मन् १९५१ तक एक आत्म-निर्भर यूरोपियन अर्थ व्यवस्था (Economy) की प्राप्ति की जा सकती है। यह रिपोर्ट 'मार्शल योजना' के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिसम्बर १९४७ में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 'मार्शल योजना' से सम्बन्धित व्यय का अनुमान कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें उक्त चार वर्ष की अवधि के लिए १७ अरब डॉलर और १५ महीनों के लिए ६ अरब ८० करोड़ डॉलर के खर्च का अनुमान लगाया गया। इस प्रस्ताव के उद्देश्य (Motive) की व्याख्या करते हुए ट्रूमैन ने कहा—'मेरा प्रस्ताव यह है कि अमेरिका उन १६ राज्यों को जो उसी की तरह स्वतन्त्र सस्थाओं की सुरक्षा एवं राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति के लिए हठ सक्त्प हैं, उनके पुनर्निर्माण कार्यों में सहायता देकर विश्व शांति एवं अपनी सुरक्षा में योगदान करें।'

'मार्शल योजना' की, जो अधिकृत रूप से 'यूरोपियन रिलीफ प्रोग्राम' (European Relief Programme) कहलाई कांग्रेस ने पास कर दिया। ३ अप्रैल, १९४८ को कांग्रेस ने 'विदेशी सहायता अधिनियम' पारित करके मार्शल योजना को मूर्त रूप प्रदान किया और इसको कार्यान्वित करने के लिए 'यूरोपियन आर्थिक सहयोग सगठन' (Organization for European Economic Co-operation) की स्थापना की गयी।

इस नवीन सस्था में अमेरिका और कनाडा पूर्ण सदस्य मान लिये गये। इस प्रकार अब यह केवल मात्र विशुद्ध यूरोपीयन सगठन ही नहीं रहा। १४ दिसम्बर, १९६० को इस सगठन के सम्बन्ध में जो मन्जीने स्वीकार किये गये उनके अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य हैं—

(क) सदस्य देशों को उच्चतम आर्थिक विकास और रोजगार प्रदान करना तथा जीवन-यापन के स्तर को उन्नत बनाता,

(ख) आर्थिक स्थिरता बनाये रखते हुए विश्व की अर्थ-व्यवस्था के विकास में सहायक होना,

(ग) सदस्य देशों को और अन्य देशों में स्वास्थ्य, आर्थिक विस्तार और विकास में सहयोग देना,

(घ) विश्व व्यापार के ऐसे विस्तार में सहयोग देना जो बहुपक्षीय हो तथा विशेष भेदभावन न करने वाला हो।

उपरोक्त उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिए सगठन के अन्तर्गत आर्थिक नीति समिति, व्यापार समिति, विनाश सहायता समिति आदि ना

गठन किया गया है। दिसम्बर १९६१ के एक निर्णय के अनुसार यह लक्ष्य रखा गया है कि संगठन के सदस्य राष्ट्रों के वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में १९६० से १९७० तक की १० वर्षीय अवधि में ५० प्रतिशत वृद्धि की जाए।

सार्वजनिक योजना और उसके फलस्वरूप अस्तित्व में आये अन्य आर्थिक सहयोग संगठन के कारण यूरोप के देशों का औद्योगिक उत्पादन, कृषि की उपज, लोगों का जीवन-स्तर तथा पूरी अर्थ-व्यवस्था सुधर गई। देशों के आपस के व्यापारिक सम्बन्धों में सहयोग की स्थापना हुई तथा इस प्रकार पश्चिमी यूरोप में साम्यवाद की आशंकाओं को अकल्पित बना दिया गया। इसने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओं की प्राप्ति में सहयोग दिया। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के इस प्रयास ने सैनिक क्षेत्र में सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। इसने राष्ट्रवाद की कठोर दीवारों को भेद कर एकीकरण की आशाएँ दिखाई तथा महाद्वीप को एकीकृत, सम्मिश्रित तथा शान्तिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया।

शुमान योजना एवं यूरोपीय कोयला-स्पात समुदाय

(Shuman Plan and European Coal & Steel Community)

पश्चिमी यारोप का आर्थिक एकीकरण करने के लिए 'शुमान प्लान' के रूप में एक अन्य नवीन योजना सम्मुख आई। प्रायः इसे ऐसी आर्थिक योजना कहा जाता है जिसका लक्ष्य राजनैतिक था। जून, १९५० में बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी, ये छ योरोपीय राष्ट्र फ्रांसीसी विदेश मंत्री शुमान के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए। इस प्रस्ताव में यह बात थी कि इन सभी राष्ट्रों का कोयला तथा फोलाद का सारा उत्पादन एक सम्मिलित उच्च सत्ता के अधीन रखा जाय तथा इस प्रकार एक अति राष्ट्रीय राजनैतिक संस्था का निर्माण कर दिया जाय। इस रूप में यह योजना फ्रांस-जर्मनी की समस्या को सुलझाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसके अनुसार एक योरोपीय संघ संसद का निर्माण करना था।

पेरिस की इन मेट के नौ मास बाद अर्थात् १८ अप्रैल, १९५१ को छ देशों के विदेश मंत्रियों ने सन्धि के मसौदे पर हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार एक योरोपीय कोयला एवं फोलाद के समाज (European Coal and Steel Community) की स्थापना की जानी थी। इन सभी देशों ने एक के बाद एक इस मसौदे की स्वीकार कर लिया। १० अगस्त, १९५२ को ६ व्यक्तियों की एक उच्च सत्ता (High Authority) की स्थापना की गई। जोन मोनेट

(Jean Monnet) इसके चेयरमैन बनाये गये। बाद में इन सभी राष्ट्रों द्वारा कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये जिनके कारण न केवल इस समाज को ही ठोस आधार प्रदान किया गया किन्तु योरोपीय एकता की सम्भावनाओं को भी बढ़ाया गया। योजना के लगभग चार वर्ष बाद शूमा प्लान को बार्दे रूप दे दिया गया। अपने जन्म से लेकर आज तक इस योजना ने योरोपीय कोसले तथा फोलाद के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। इसकी उच्च शक्ति (High authority) द्वारा नीति सम्बन्धी अनेक निर्णय लिए गये हैं। योरोपीय एकता का इस समाज को एक नया प्रयोग माना जाता है। मई, १९५५ में सामान्य सभा (Common Assembly) को योरोप के आवागमन का एकीकरण करने के लिए बुलाया गया तथा इस सम्बन्ध में समाज की शक्ति एवं उत्तरदायित्व बढ़ाने के सुझाव माये गये। इन मन्त्रों द्वारा एक या दो अतिराष्ट्रीय सम्मेलनों का सुझाव दिया गया जो कि योरोपीय एकीकरण की सम्भावनाओं पर आगे विचार कर सकें। २० मई को वेनेलक्स देशों की सरकारों के अन्य तीन देशों की सरकारों को एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जिसमें आर्थिक क्षेत्र में एकीकरण बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई थी। बाद में सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों ने एक समिति नियुक्त की जो एकीकरण की योजना से उत्पन्न समस्याओं पर विचार कर सके।

यूरोपीय साक्षा-बाजार

(European Common Market)

शूमा योजना ने ही आगे चलकर यूरोपीय साक्षा बाजार की स्थापना को सम्भव बनाया। इसकी स्थापना शूमा योजना के सदस्यों द्वारा १ जनवरी, १९५८ को की गई। यह योजना आज भी जारी है। यह एक क्षेत्रीय योजना है जिसका उद्देश्य यूरोप के ६ देशों का आर्थिक एकीकरण करना है। ये ६ देश हैं—बेल्जियम, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग। अपनी-अपनी वृद्धि से राष्ट्र इसके छोटी सदस्य हैं। यद्यपि इस समुदाय का अन्तिम अथवा दीर्घवर्षीय लक्ष्य यूरोप के देशों का राज-संघ बनाना है, लेकिन इसके तात्कालिक लक्ष्य आर्थिक हैं। आर्थिक लक्ष्य के रूप में समुदाय बनाने का एक मात्र उद्देश्य उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने की उत्पादन प्रमाणी द्वारा उत्पादन करके वितरितकरण और धन-विभाजन के लाभों को प्राप्त करना है। यह योजना इस आशा का परिणाम है कि ६ देशों के व्यापक क्षेत्रफल में पहले वितरित बाजार में बड़े पैमाने के उद्योगों को अधिक कुशलतापूर्वक चलाया जा सकेगा और इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से सक्रियशील बनाया जा सकेगा।

साक्षात् बाजार की स्थापना न केवल यूरोप वरन् विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस समुदाय या साक्षात् बाजार ने प्रगतनीय प्रगति की है और बड़े पैमाने के विस्तृत आर्थिक लाभ सदस्य राष्ट्रों को प्राप्त हुए हैं। किन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि इस प्रकार की योजनाएँ सच्ची अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता और मुक्त व्यापार के हित के घातक हैं।

यूरोप की सैनिक संधियाँ

(The Military Pacts of Europe)

यूरोप की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ यह भी आवश्यक था कि उसे सैनिक रूप से भी समस्त बनाया जाये। कहा जाता है कि साविजन समझौते के बाद इंग्लिश नहर पर आक्रमण कर सकता है। पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप के बीच प्राकृतिक अवरोध न होने के कारण यह आवश्यक समझा गया कि यूरोप के इन दोनों भागों के बीच समुक्त राज्य अमरीका के समान रखी जाय। आर्थिक क्षेत्र की भाँति यूरोप के देश अब सैनिक दृष्टि से भी एकीकृत होने जा रहे हैं। उत्तर अटलांटिक सन्धि संगठन (NATO) के अधीन यूरोप ने समुक्त राज्य अमरीका तथा स्वतन्त्र विश्व के अन्य सन्निधाली देशों से भी अपना सम्बन्ध बना लिया है। पश्चिमी यूरोप के आठ देशों ने मिल कर एक पश्चिमी यूरोपीय संधि (Western European Union) की रचना की है जिसे नाटो (NATO) के माध्यम से अमेरिका तथा ब्रिटेन का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यूरोपियन सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए जो सैनिक संधियाँ की गई हैं निम्न प्रकार हैं—

डंकर्क संधि

(Dunkirk Treaty)

यह सन्धि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य ४ मार्च, १९४७ को ५० वर्षों के लिये की गई। इसका प्रयोजन सम्भावित वर्तमान आक्रमण के विरुद्ध पारस्परिक सैनिक सहायता है। ब्रिटेन तथा फ्रांस ने यह निश्चय किया कि (क) भयंती के आक्रमण करने पर, (ख) जनता द्वारा आक्रमण का प्रात्याह्वन करने की नीति स्वीकार करने पर, एवं (ग) समुक्त राष्ट्र मंत्रिद्वारा जर्मनों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने पर दाना देना एवं दूसरे का सैनिक तथा अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करेंगे। इस संधि के द्वारा दोनों ही देशों ने एक दूसरे को यह भी आश्वासन दिया है कि वे दाना एवं दूसरे को निरन्तर आर्थिक सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

ब्रुसेल्स-संधि

(Brussels Treaty)

१७ मार्च, १९४८ को ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, लक्जमबर्ग और

हाईण्ड ने अर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग एवं सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य से ५० वर्ष के लिये यह संधि की। यह संधि वेन्जियम के ब्रूसेल्स नगर में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि उपरोक्त राष्ट्रों में किसी पर भी आक्रमण होता तो सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर की धारा ५१ के अनुसार उनका सैनिक सहायता करेंगे। इन संधि के प्रमुख ध्येय इस प्रकार गिनाये जा सकते हैं—मूलभूत अधिकारों में विश्वास की पुष्टि तथा संधि के चार्टर में उल्लिखित अर्थों की पुष्टि, जन तन्त्र एवं स्वतन्त्रता का स्थायित्व, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की स्थापना यूरोपियन धार्मिक पुनर्गठन में सहायता, अन्तरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में सहयोग, युद्ध नीति के विरुद्ध माथा आदि।

उल्लेखनीय है कि १९५४ में पेरिस के सम्मेलन से पश्चिमी जर्मनी और इटली भी यूरोपियन संधि सङ्गठन में सम्मिलित हो गये हैं और अब इस सङ्गठन का नया नाम पश्चिमी यूरोपीय संधि (Western European Union) रखा गया है।

उत्तरी अटलाण्टिक सन्धि सङ्गठन (NATO)

ब्रूसेल्स सन्धि द्वारा सुरक्षा का जो गड तैयार किया गया वह उपयोगी होने पर भी पर्याप्त नहीं था। मनुष्य शक्ति एवं धन के अभाव में इस सङ्गठन के लक्ष्यों को पूरा करना कठिन था, इसी कारण पश्चिमी यूरोप के देशों ने संयुक्त राज्य अमरीका की ओर सहयोग तथा मैत्री का हाथ बढ़ाया। सैनिक, राजनैतिक तथा कूटनीतिक स्तरों पर एक-दूसरे समय तक विचार विमर्श होने के बाद वाशिंगटन में ४ अप्रैल, १९४९ को नाटो (NATO) पर हस्ताक्षर किये गये। हस्ताक्षर करने वालों में ब्रूसेल्स सन्धि के पांच देश तथा कनाडा, डेनमार्क, आइसलैण्ड, इटली, नार्वे, पुर्तगाल और संयुक्त राज्य अमरीका—इस प्रकार कुल बारह देश हैं। नाटो सन्धि के निम्न लक्ष्य बताये जाते हैं—

(१) सदस्य राष्ट्रों को उनकी स्वतन्त्र सत्स्थाओं का विकास करने का अवसर प्राप्त करना,

(२) आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना,

(३) सैनिक आक्रमण का विरोध करने के लिए सदस्य देशों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक सामर्थ्य को बनाना एवं विकसित करना,

(४) यूरोप अथवा उत्तरी अमरीका में किसी एक या सब देशों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण को सभी देशों द्वारा अपने विरुद्ध आक्रमण समझा जाना।

यूनान तथा टर्की १९५२ में इस सन्धि में सम्मिलित हो गये तथा पश्चिमी जर्मनी १९५५ में आकर मिला। इस प्रकार सदस्यों की संख्या बढ़कर १५ हो गई। यह समझौता २० साल तक प्रभावकारी है किन्तु १० साल बाद यदि आवश्यकता हो तो विचार किया जा सकता है। सर्वोच्च सैनिक हंड-क्वार्टर्स को पेरिस में रखा गया है, नाटो के लिए पर्याप्त डिबीजन रखे गये हैं। फ्रांस चाहता है कि ब्रिटेन तथा यू० एल० ए० इस सन्धि से बाहर हो जाय। योरोप में वह स्वयं एक तीसरी शक्ति के रूप में उदित होने की महत्वाकांक्षा रखता है और इस प्रकार इस संगठन की संशक्तता कम पड़ने लगी है।

वारसा पैक्ट या पूर्वो यूरोपियन संधि संगठन
(Warsaw Pact)

पारशात्य राष्ट्रों ने जब पश्चिमी जर्मनी का शस्त्रीकरण करने का निश्चय कर लिया और उसे नाटो संधि संगठन तथा पश्चिमी यूरोपियन संधि का सदस्य बना लिया तो सोवियत रूस ने ११ से १४ मई, १९५५ तक वारसा में "यूरोप में शांति एवं रक्षा की सुरक्षा के लिए यूरोपियन देशों का एक सम्मेलन" आयोजित किया। इस सम्मेलन में सोवियत संधि के अनिवार्य अन्य ७ साम्यवादी देश—पोलंड, रूमानिया, हंगरी, पूर्वो जर्मनी, अल्बानिया, बल्गेरिया और चेकोस्लोवाकिया सम्मिलित हुए।

१४ मई को सोवियत रूस सहित उपरोक्त सातों देश इस बात पर सहमत हो गये कि उनकी सेनाओं की एक संयुक्त कमान बनाई जाए और वे आपस में मैत्री, सहयोग एवं पारस्परिक सहायता की संधि करा करें। इस निश्चय के फलस्वरूप १४ मई, १९५५ का ही उपरोक्त सभी राष्ट्रों ने "सुरक्षा और शांति" के दृढ़ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये।

यह संधि जिसे वारसा संधि या पूर्वो यूरोपियन संधि संगठन के नाम से सम्बोधित किया जाता है, २० वर्ष के लिये की गई। इसका उद्देश्य पारस्परिक शक्ति के प्रयोग से बचे रहना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण उपायों से निपटारा करना है, परन्तु साथ ही इसमें सदस्य राष्ट्रों की बाह्य आक्रमण के समय सामूहिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है।

संधि की प्रस्तावना एवं कुछ प्रमुख धारणों इसके प्रधान स्वरूप व इसकी शक्ति को व्यक्त करती हैं। संधि की भूमिका में यूरोप में सामूहिक सुरक्षा पद्धति स्थापित करने पर बल दते हुए कहा गया है कि पश्चिमी यूरोप के संधि एवं पश्चिमी जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण से यह आवश्यक हो गया है कि हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करें तथा यूरोप में शांति कायम

रखें। इस दृष्टि से इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों में घनिष्ठ सहयोग का वर्णन है।

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय

(The European Defence Community-EDC)

सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप की प्रतिरक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण करने की दृष्टि से काफी लम्बी और जटिल वार्ता के बाद, २७ मई, १९५२ को 'यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की सन्धि' पर पेरिस में हस्ताक्षर हो गये। इस सन्धि के द्वारा ही यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय का जन्म हुआ। इस ५० वर्षीय सन्धि पर फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग इन ५ देशों ने हस्ताक्षर किये।

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय का उद्देश्य एक ऐसे संगठन की स्थापना करना था जिसमें हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र मिल कर अपने सैन्य बल, सैन्य बजट और अपनी सैन्य सस्थाओं का एकीकरण कर सकें। इसके संविधान में यह व्यवस्था थी कि नाटो के सैन्य संगठन में उपरोक्त ६ राज्य अपनी सेनाओं को एक इकाई की तरह शामिल करेंगे।

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय यूरोप के राजनीतिक एकीकरण के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम इस तेजी से घूमा कि समुदाय की व्यावहारिक स्थापना और सफलता संदिग्ध हो गयी। स्टालिन के मरने से रूसी आक्रमण का आतंक घट गया और ग्रेट ब्रिटेन ने इस समुदाय के साथ सहयोग करना अस्वीकार कर दिया। ३० अगस्त, १९५४ को फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद ने भी यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय सन्धि को अस्वीकार कर दिया।

पश्चिमी यूरोपियन संघ

(Western European Union-W E U)

यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय की असफलता के परिणामस्वरूप २८ सितम्बर से ३ अक्टूबर १९५४ तक लन्दन में होने वाले सम्मेलन में पश्चिमी यूरोपियन संघ की स्थापना की गई। ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और बेनीलक्स देश (हालैंड, बेल्जियम तथा लक्जमबर्ग) कम से कम १९६८ तक के लिए परस्पर प्रतिरक्षा और अन्य उद्देश्यों को लेकर संगठित हो गये। इस संघ का एक अन्य उद्देश्य 'यूरोप के एक अन्य संगठन को प्रोत्साहन देना' भी था। संघ की स्थापना के समय यह निश्चय किया गया कि पश्चिमी जर्मनी को भी नाटो में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया जाए। बदले में पश्चिमी जर्मनी ने स्वीकार किया कि वह अपने शस्त्रास्त्रों के उत्पादन पर

स्वेच्छा से नियन्त्रण रहेगा। यह भी तब हुआ कि जब तक पश्चिमी जर्मनी स्वयं अपनी प्रतिरक्षात्मक सेनाओं तैयार न करले तब तक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाय पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की रक्षा के लिए बहा रहें।

पश्चिमी यूरोपियन संघ की सभी सशस्त्र सेनाओं नाटो के सचिव सनापति व अधीन रखी गयी। इस संघ का सचिवालय लन्दन में स्थापित किया गया। सचिवालय न अठावा संघ के कार्य संचालन करने वाले अन्य अंग में बनाय गये—परिषद बना, सैन्य नियन्त्रण एजेन्सी तथा स्थाई सहायक समिति। अपनी स्थापना के समय में लगभग १॥ वर्ष तक यह उचित ढंग में कार्य करता रहा लेकिन शीघ्र ही इसके मध्य दलों में मतभेद प्रकट होने लगे। फरवरी १९५७ में ब्रिटेन ने जर्मन स्थित अपनी सेनाओं में फिर कटौती करने का निश्चय किया और जनवरी १९५८ में संघ की परिषद ने घोषणा की कि उसने ब्रिटेन के १९५८ में यूरोप में अपने ८,५०० सैनिक बाकिस मुलाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी है।

१९५८ में ही पश्चिमी यूरोपियन संघ ने अपने को सुदृढ़ करने के विभिन्न प्रयास किये लेकिन सदस्य राष्ट्रों के मतभेद पूरी तरह मिटे नहीं। फिर भी यह संघ कठिनाइयों से गुजरता हुआ अभी विद्यमान है।

पश्चिमी यूरोप का राजनीतिक एकीकरण

(The Political Integration of Western Europe)

यूरोप की द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए आर्थिक सहयोग की स्थापना करने वाली अनेक योजनाएँ बनाई गईं। इस महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रस्ताव रखे गये। ठीक इसी प्रकार बहा का राजनीतिक एकीकरण करने के लिए भी अनेक प्रस्ताव रखे गये ताकि इस क्षेत्र के देशों के बीच उदयन शमली तथा द्विर्दों के विरोध को सदा के लिए समाप्त किया जा सके। विलियम बुलिट (William Bullitt) का कहना है कि योरोपीय संघ के बिना किसी भी मूलभूत समस्या को नहीं सुलझाया जा सकता। यही विचार क्लेमेंट एटली (Clement Attlee) का भी है। वे कहते हैं कि योरोप को या तो संधीय हो जाता चाहिये अथवा यह नष्ट हो जायगा। योरोप में एक संघ बन जाने का महत्व है फिर भी पूर्व तथा पश्चिम में भारी मतभेद होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार साम्यवादी देश भी योरोप का एकीकरण चाहते हैं किन्तु उनका यह एकीकरण संघ राज्य के रूप में न होगा वरन् वे तो आक्रमण तथा विजय द्वारा ऐसा

करने। यद्यपि पूरे योरोप का सपना का आसंद बहुत दूर है तो भी इसमें सन्देह नहीं कि पश्चिमी योरोप में जो आर्थिक एवं सैनिक सम्बन्ध बढ़े हैं इससे इस क्षेत्र के देश परस्पर निकट आये हैं तथा पश्चिमी योरोप के एकीकरण की ओर भी इन्होंने कुछ कदम बढ़ाये हैं। ६ मार्च, १९५२ को काब्रिज के तान भेजे गये अपने सन्देश में राष्ट्रपति ट्रुमैन ने बताया था कि योरोप एकीकरण की ओर पिछले पाच वर्षों में इतना बढ़ा है जितना यह पहले के ५०० वर्षों में नहीं बढ़ा था।

योरोप के एकीकरण का विचार अतः प्राचीन माना जाता है। रोमन साम्राज्य के पीछे भी यह विचार कार्य कर रहा था। सन् १९२२ से १९३० के बीच का समय योरोपीय संधि के विचार तथा समर्थन का मुख्य समय है। सन् १९४१ में रिचार्ड कुडनहाउ क्लेर्गी (Richard Coudenhove Kalergi) ने पान-योरोप (Pan-Europe) नामक पुस्तक प्रकाशित की तथा योरोप की एकता का महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। राष्ट्र संधि की सभा में बोलते हुए १९२६ में ब्रिया (Briand) ने योरोप के देशों को योरोप का संधि बनाने के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर योरोप का संधि बनाने के अनेकों प्रयास किये गये। मई, १९४८ में होने वाली हेग काब्रिज योरोपीय एकता के लिए किये अनाधिकृत संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें योरोप के पन्द्रह देशों के प्रतिनिधि, संसार के अन्य भागों के दूर-दूर प्रकार कुल लगभग सात सौ लोगो ने भाग लिया। इसमें अन्त्येष्ट पद से बोलते हुए चर्चिल ने कहा था कि हम पूरे योरोप के एक संधि को छोड़ कर अपना कोई दूसरा लक्ष्य नहीं बना सकते। इन काब्रिज में अनेकों प्रस्ताव पाम किये गये तथा योरोपीय एकता के आन्दोलन के लिए एक स्थाई अन्तर्राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया गया जिसका काम यह था कि सरकारों को हेग काब्रिज के प्रस्तावों की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना।

योरोपीय एकता समिति ने एक योरोप की परिषद (Council of Europe) की स्थापना का सुझाव दिया। इस सुझाव को ५ मई, १९४६ को स्वीकार कर लिया गया। यह परिषद एक प्रकार से पश्चिमी योरोप की ससद थी जिन्हु इसके पास किसी प्रकार के सम्प्रभुता के अधिकार न थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले इस परिषद का विचार क्षेत्र में नहीं आते थे। योरोपीय फौलाद तथा कोयला समाज की नामान्य सभा में सितम्बर १९५२, में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। मंत्रियों की परिषद के सुझाव पर सभा ने एक सन्धि तैयार करने का विचार किया जो एक ऐसे योरोपीय राजनैतिक समाज की स्थापना कर सके जिसमें वास्तविक शक्ति रखने वाली एक

समान संसद हो। यह इन छ. राज्यों के बीच संघ स्थापना का प्रयास करेगी और इस प्रकार बाद में दूसरे राष्ट्रों पर भी प्रभाव डालेगी। इस प्रकार योरोपीय एकता प्रयासों के इतिहास में एक नया अध्याय खुला। १९५३ के बाद इस संघात्मक दृष्टिकोण की समाप्ति हो गई। योरोपीय सुरक्षा समाज (E. D. C.) के अस्तित्व हो जाने के बाद योरोप के राजनैतिक एकीकरण की ओर किये जाने वाले सभी प्रयास अतीत की गाथा बन गये। पामर तथा परकिन्स ने लिखा है कि पश्चिमी योरोप एक प्रभावशाली एकता के रास्ते से अर्न्त भी बहुत दूर है तथा पूरे योरोप या अटलाण्टिक समाज के मापदंड पर वास्तविक एकता के आधार नजर नहीं आते।

असंलग्नता-इसका तत्व और बदलते हुए स्वरूप

(NON-ALIGNMENT-ITS ELEMENTS AND CHANGING PATTERNS)

गुट निरपेक्षता या असंलग्नता का सिद्धान्त विश्व राजनीति में पर्याप्त महत्व रखता है। इस सिद्धान्त का समर्थक भारत को ही माना जाता है। वैसे इस सिद्धान्त का अस्तित्व भारत द्वारा इसे अपनाए जाने से पहले भी था एवं इसके सम्बन्ध में पर्याप्त साहित्य की रचना हो चुकी थी। किन्तु भारत को इस सिद्धान्त को लोकप्रिय बनाने का तथा व्यावहारिक रूप में महत्वपूर्ण बनाने का श्रेय दिया जा सकता है। यह कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का कोई भी सिद्धान्त उस समय तक पूरा नहीं होता जब तक कि वह गुट-निरपेक्षता के विकास के उस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण नहीं कर देता। अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा के विद्यार्थी के लिए इस सिद्धान्त का अध्ययन अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसका पहला कारण यह है कि गुट निरपेक्षता की नीति वर्तमान विश्व-प्रवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो शक्ति पर आधारित न हो कर संचार प्रवस्था पर आधारित है। दूसरे, इसके द्वारा आने वाले विश्व-समाज की कुछ विशेषताओं को प्रतिबिम्बित किया जाता है। तीसरे, गुट-निरपेक्षता की नीति ने अनेक ऐसी विशेषताएँ अन्तर्निहित रहीं हैं जो गुट-सापेक्ष-देशों में भी विकसित हो रही हैं और चोथे, गुट-निरपेक्ष के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का एक विकल्प प्रस्तुत किया जाता है और कुछ नए नियम सोचे जाते हैं जो कि अणु-शक्ति के प्रतिरोधात्मक रूप के समाप्त होते ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

हमें देखना चाहिये कि इस असंलग्नता या गूट निरपेक्षता की नीति का अर्थ क्या है ? उसका विचार किस प्रकार हुआ ? विभिन्न राष्ट्रों ने इस नीति को क्यों अपनाया ? शीत युद्ध के काल में इस नीति का क्या योगदान रहा ? इसे विदेश नीति के माधन के रूप में कितना महत्व दिया जा सकता है ? ये सभी प्रश्न अपना विशेष महत्व रखते हैं ।

गूट निरपेक्षता की नीति का अर्थ

(The Meaning of Non-alignment)

गूट निरपेक्षता (Non-alignment) शब्द का प्रयोग प्रायः उन राष्ट्रों की विदेश नीति की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो कि साम्यवादी और पश्चिमी गूट के साथ किसी सेनिक संधि में बद्ध नहीं हैं । इस अर्थ के सम्बन्ध में गूट निरपेक्ष राष्ट्रों ने नेताओं का विचार है कि यह उनकी नीतियों की संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता । गूट निरपेक्षता का कोई सकारात्मक मूल्य या अर्थ नहीं है किन्तु फिर भी अधिकांश राष्ट्र व्याख्या के इस सकारात्मक मूल्य को अविन्यक्त करना चाहते हैं । इस नीति के बेलग्रेड (Belgrade), कैरो (Cairo), दिल्ली आदि विभिन्न बैठकों द्वारा इसे अविन्यक्त करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे, गूटबिहीन (Not Block), असंलग्न (Uncommitted), सक्रिय तटस्थ (Actively Neutral) आदि-आदि । इस नीति के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक शब्द न होने के कारण उत्पन्न असन्तोष को दूर करने के लिए सम्झे लम्बे भाषण दिए जाने हैं । इस सम्बन्ध में एक बाल ध्यान में रखने योग्य यह है कि गूट निरपेक्षता की नीति की तटस्थतावादी प्रान्त देशों द्वारा मुख्यतः सन् १९४५ के बाद लोकप्रिय बन गया है । यह नीति विभिन्न छीना के लिए विभिन्न समर्थों पर विभिन्न अर्थ रखती है । इसीलिए यह कहा जाता है कि गूट निरपेक्ष नीति का अध्ययन देश विदेश के प्रसंग में ही करना चाहिए । जवा, लडा, मिस्र, भारत, इण्डोनेशिया, यूगोस्लाविया और अफ्रीका के देशों में जिस गूट निरपेक्षता की नीति का विकास हुआ है वह महा की ऐतिहासिक परम्पराओं और स्थित राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित रही । ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त होगा कि गूट निरपेक्षता का सही अर्थ जानने के लिए खण्ड प्रयोग तथा व प्रसंग में समर्थ व्यवहार किया जाए । केवल ये राष्ट्रीय सम्प्रदाय ही पर्याप्त नहीं हैं क्योंकि वे जहाँ राष्ट्रीय सम्प्रदाय की अर्थ से नहीं रहते जो कि गूट निरपेक्षता के लिए विशेष है तथा उनसे भिन्न हैं जो निरपेक्षता एवं मापदण्ड दोनों के लिए सामान्य हैं । यूरोपिया के सम्बन्ध में लंदन महामंडल ने यह बताया कि महा राष्ट्रवाद एवं

उपनिवेशवाद का निरोध गुट-निरपेक्ष नीति के कारण रहे। यह तत्व केवल गुट निरपेक्ष राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि जो राष्ट्र गुट निरपेक्ष नहीं हैं वे भी इनमें विश्वास करते हैं।

पश्चिमी लेखकों, विचारकों एवं राजनैतिक नेताओं ने गुट निरपेक्षता की समझने के लिए तटस्थता अथवा तटस्थतावाद शब्द का प्रयोग किया है। नि० पिटर लायन (Peter Lyon), मार्गेन्थो (Hans J Morgenthau), हैमिल्टन फिश आर्मस्ट्रांग (Hamilton Fish Armstrong), राबर्ट ए० स्केलेपिनो (Robert A. Scalapino), फ्रान्सिस लाबीयर (Francis Lowbeer), वार्नर लेवी (Warner Levy) आदि लेखकों ने तटस्थता (Neutrality or Neutralism) शब्द का प्रयोग किया है। यह कहा जाता है कि गुट-निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सम्भवतः नैज्ञानिक अर्थ में जार्ज लिस्का (George Liska) ने किया होगा। उसके बाद तो तटस्थता के स्थान पर अनेक विचारक गुट-निरपेक्षता शब्द का प्रयोग करने लग गए और अब इसे एक सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो गई है। कई एक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता भी अपनी विदेश नीति के लिए वर्मा के यूनु (U Nu) की भांति तटस्थता शब्द का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त समझते हैं। तटस्थता एवं गुट-निरपेक्षता के बीच यह तो सामान्यता है कि वे शीत युद्ध के समय सघर्ष से असलग रहते हैं किन्तु अन्तर यह है कि वास्तविक युद्ध छिड़ने पर तटस्थ राष्ट्र युद्ध से अलग रहता है किन्तु गुट-निरपेक्ष राष्ट्र युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से सलज्ज सकता है। स्वीट्जरलैण्ड तटस्थ देशों का एक उदाहरण है। ऐसे देश के राजनैतिक एवं कानूनी स्तर को युद्ध करने वाले दोनों ही पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। दूसरी ओर असलग्न नीति विरोधी विचारधारकों के बीच स्थित सघर्ष को प्रकट करती है। इस सघर्ष में सम्मन्यित देश किसी भी पक्ष के साथ सलग्न नहीं रहता। स्वारजन्बर्गर (Schwarzenberger) के मतानुसार गुट निरपेक्षता सधियों से दूर रहने की नीति है। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व संयुक्त राज्य अमरीका की विदेश नीति को असलग्न नीति का नाम दिया है। कुछ विचारकों के मतानुसार यह उचित नहीं है क्योंकि असलग्नता या गुट निरपेक्षता (Nonalignment) की नीति के लिए गुटों का तथा उनके बीच सघर्ष का होना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक गुटों से अलग रहने वाली नीति जैसी किसी चीज के होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। गुट निरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करती है, यह शांति की दिशा में एक सक्रिय नीति है, एक सकारात्मक तटस्थता है। इस अर्थ में हम समुक्त राज्य अमरीका की प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व की नीति को पार्यव्यवादी कह सकते हैं,

उसे तटस्थ मान सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय घटना चक्र में कोई रुचि ही नहीं लेती किन्तु उसे गुट-निरपेक्षता की नीति नहीं कहा जा सकता। तटस्थ नीति का महत्त्व केवल तभी तक रहता है जब तक कि युद्धरत राष्ट्रों द्वारा उसे मान्यता दी जाये। १९वीं शताब्दी के दौरान होने वाले युद्धों में तटस्थ नीति को कई देशों द्वारा सफलता के साथ अपनाया गया किन्तु इसके बाद या पहले यह नीति प्रभावशील न रही।

पहले विश्व राजनीति में सक्ति सतुलन का रूप अनेक राष्ट्रों से युक्त था। इसमें प्रत्येक युद्धरत राष्ट्र यह चाहता था कि युद्ध से अलग राष्ट्र को उत्तेजित करके विरोधी पक्ष से साथ शामिल होने के लिए प्रेरित न करे। इसी कारण तटस्थता का सम्मान किया जाता था किन्तु प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तटस्थता की नीति भयानक होती है।

तटस्थता एक प्रकार से कूटनीति का अङ्ग है न कि विदेश नीति का। तटस्थता के सहारे हम एक देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का केवल एक ही पहलू देख पाते हैं और वह यह कि युद्ध के समय उसकी स्थिति क्या रहेगी।¹ किन्तु इससे हम उस देश का विदेश नीति के सामान्य रूप को जानकारी नहीं कर पाते। तटस्थ नीति एक देश की मजबूरी या सुविधा का परिणाम होती है जबकि गुट निरपेक्षता एक सिद्धान्त की बात है।

गुट-निरपेक्षता की नीति की एक मुख्य विशेषता यह होती है कि इस व्यवस्था को मानने वाला देश सैनिक संधियों का विरोध करता है। सैनिक संधियों का विरोध मानव इतिहास के प्रारम्भ से ही एक नीति के रूप में वर्तमान है, यह कोई नया आविष्कार नहीं। किन्तु फिर भी आज का संधि विरोधी दृष्टिकोण पहले के संधि विरोधी दृष्टिकोण से पर्याप्त भिन्न है। पहले किसी एक संधि विशेष में सम्मिलित करने से मना कर दिया जाता था किन्तु ऐसा करने वाला देश सामान्य रूप से सैनिक संधि का विरोध नहीं करता था। एक दूसरे प्रकार की संधि विरोधी नीति यह होनी थी जिसे अपना कर वह देश सभी देशों के साथ सभी प्रकार की संधियों का विरोध कर देता था। यद्यपि वह स्वयं सन्निबद्ध नहीं होता था किन्तु दूसरे देशों द्वारा भी जाने वाली सैनिक संधियों को वह बुरा नहीं मानता था। इस प्रकार के संधि विरोधी देश परिस्थितियों के बदलते ही सन्निबद्ध हो जाते हैं। वे स्थायी रूप से सैनिक संधियों का विरोध नहीं करते। गुट निरपेक्ष नीति के

1. स्व० पण्डित जवाहरलाल नेहरू व मतानुसार भी तटस्थता की मान्यता या सम्मर्थन केवल युद्ध से होता है।

मानने वाले देश स्वयं सैनिक संधियों में बद्ध नहीं होते तथा दूसरों के बद्ध होने की नीति का विरोध करते हैं और यह नीति उनके स्थायी जीवन की विशेषता होती है। इन देशों के मतानुसार सैनिक संधियाँ सहयोग का परिणाम नहीं होती बरन् विरोध का परिणाम होती हैं। इससे एक देश शत्रु की दौड़ में सम्मिलित हो जाता है। इस प्रकार की संधियों को तोड़ने का एकमात्र उपाय युद्ध होता है। संधि विरोधी नवीन दृष्टिकोण के अनुसार संधियों के न होने पर प्रत्येक राष्ट्र अलग रहेगा और इस प्रकार उस पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून की भली प्रकार लागू किया जा सकेगा।

स्व० प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने ७ सितम्बर, १९४५ को अपने एक रेडियो प्रसारण में कहा कि भारत को एक दूसरे के विरुद्ध संधिवद्ध समूहों की दक्षिण राजनीति से अलग रहना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अतीत-काल में दो विश्व युद्ध हुए तथा जो आगे भी और अधिक स्तर के विध्वंस की ओर प्रेरित कर सकती है। स्व० श्री नेहरू के इस कथन में गुट निरपेक्ष नीति का सैनिक संधियों के प्रति विरोध झलकता है। किसी भी देश द्वारा अपनाई जाने वाली गुट निरपेक्षता की नीति उस देश की आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों का परिणाम होती है। कोई देश सैनिक संधियों का विरोध अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर सकता है अपना आन्तरिक स्थायित्व के लिए। किन्तु फिर भी उसकी मुख्य प्रेरणा प्रायः भावात्मक विचारधाराएँ होती हैं और कभी-कभी विदेशी सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने की कामना भी प्रेरणा बन जाती है। गुट-निरपेक्षता की नीति को राष्ट्र-सम्मान का भी प्रतीक माना जाता है। स्व० पंडित नेहरू ने कहा था कि “किसी एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ यह होता है कि किसी एक खास प्रश्न पर आप अपने विचार का परित्याग कर दें और दूसरों को खुश करने तथा उनकी सद्भावना प्राप्त करने के लिए उनके विचार को मान लें।” ऐसे गुट निरपेक्षता की नीति को मानने वाला एक देश अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति अपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण बाँध नहीं होता बरन् वह दोनों पक्षों की स्थिति को समझ कर उचित पक्ष की ओर मिलने का प्रयास करता है। सन् १९४६ में अमरीकी जनता के समक्ष घोषित हुए स्व० प्रधानमन्त्री श्री नेहरू ने कहा कि “जहाँ कहीं स्वतन्त्रता संकट में पड़ती है, न्याय की चुनौती दी जाती है या आक्रमण होता है वहाँ हम सह्य नहीं रह सकते और न रहेंगे।” भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के तत्वों का वर्णन स्व० नेहरू द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले भाषणों के आधार पर जाना जा सकता है। ६ दिसम्बर, १९५८ को उन्होंने लोक सभा में बताया कि “जब हम यह कहते हैं कि हमारी नीति गुट-निरपेक्षता की है तो स्पष्ट रूप में हमारा अर्थ सैनिक गुटों से निरपेक्ष रहने का होता है।”

गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति एक देश को निष्क्रिय नहीं बनाती वरन् जैसा कि मि० एम० एस्० राजन का कहना है "यह एक विधेयात्मक सक्रिय एवं रचनात्मक नीति है जो सामूहिक सुरक्षा की ओर अग्रसर होती है तथा एकमात्र इस पर ही सामूहिक सुरक्षा स्थित रह सकती है।" एक गुट-निरपेक्ष देश सैनिक संधियों में बद्ध न होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर निम्न-निम्न नीतियों, प्रेरणाओं और सिद्धान्त के अनुसार धमक करता है। गुट-निरपेक्षता की नीति एक राष्ट्र को कोई भी एक दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य नहीं करती वरन् उसे राष्ट्रीय हित, विश्व शांति एवं न्याय की दृष्टि से कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्रता देती है।

गुट-निरपेक्षता की नीति का विकास

(The Development of Non alignment)

जिस समय भारत, बर्मा, सीलोन, इण्डोनेशिया द्वारा सर्वप्रथम गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाई गई उस समय अधिकांश राज्य औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस इन दो विरोधी शक्तियों के साथ संधिबद्ध थे। गुट निरपेक्षता की नीति अपना कर विभिन्न देशों ने स्वतन्त्रता के प्रति अपनी इच्छा को अभिव्यक्त किया। गुट निरपेक्षता की नीति के विकास में अनेक तत्वों ने प्रभाव डाला है। इन तत्वों ने मिल कर ही देश को गुटों से अलग रहने की नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। जब हम गुट-निरपेक्षता की नीति के विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके लिए हमें दो रास्तों से आगे बढ़ना होगा प्रथम, यह देखना होगा कि कोई देश अपनी स्वतन्त्रता को दाव पर लगा कर भी सैनिक संधियों में सम्मिलित होना क्यों चाहता है और उसके बाद इस पर विचार करना उपयुक्त रहेगा कि गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए कौनसी प्रेरणायें काम करती हैं।

(A) सैनिक संधि के कारण

(The Causes of Military Alliances)

प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्वतन्त्रता को सम्मान देता है और वह अपनी स्वेच्छा से उन व्यक्तियों को स्वीकार नहीं करना चाहता जो सैनिक संधियों में बद्ध होने के कारण उन पर लग जाते हैं। जो सरकारें सुरक्षित, स्वतन्त्र एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती हैं उनके लिए सैनिक संधि में शामिल होना आवश्यक बन जाता है। प्रत्येक संधिबद्ध देश यह सोचता है कि वर्तमान परिस्थितियों में संधिबद्ध होने का कोई विकल्प नहीं है। यदि शक्तिशाली बलशाली राष्ट्रों के विरुद्ध सैनिक शक्ति के प्रयोग की धमकी दे कर उन संधि में बद्ध होने के लिए मजबूर कर सकता है। उदाहरण के लिए

जर्मनी, कोरिया और वियतनाम के विभाजित भागों को किया जा सकता है। इन देशों में जब एक भाग का समर्थन पश्चिमी शक्तियों ने करना प्रारम्भ किया तो यह स्वाभाविक था कि दूसरा भाग साम्यवाद की ओर झुक जाता। इन देशों के दोनों भागों ने महाशक्तियों के साथ सैनिक संधि में बढ होना उचित समझा। वैसे बाध्यकारी रूप से किसी देश को अधिक दिनों तक संधि में बढ नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार की संधि केवल तभी तक रहती है जब तक कि सम्बन्धित देश पर कोई सक्क हो किन्तु इसके बाद वह देश इस संधि को छोड़ देता है। यदि किसी देश की संधि को दोषकालीन बनाना है तो इसके लिए यह जरूरी होता है कि उस देश में ऐसी सरथाये तथा सरकार स्थापित की जायें जो संधि युक्त नीति का समर्थन करे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्व वैश्वीय यूरोप में जो हस्तक्षेप किया और पश्चिमी शक्तियों ने यूनान, इटली एवं मध्यपूर्व तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में जो हस्तक्षेप किया उसका कारण इन प्रदेशों में ऐसी सरकारें कायम करना था जो सम्बन्धित महाशक्ति के साथ संधि-बद्ध रह सकें। मि० वटन के मतानुसार “अधिकांश मामलों में संधि न तो योपी जाती है और न ही यह बाध्यता का परिणाम होती है वरन् इसके लिए एक राष्ट्र अनेक परिस्थितियों पर विचार करता है और विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर आता है कि अपनी रक्षा के लिए वह दूसरी शक्ति के साथ सम्बद्ध हो जाए।” कोई भी देश बड़ी शक्तियों के साथ अनेक कारणों से संधि में बढ होता है।

① पहला कारण यह है कि परम्परागत रूप से जिस देश से हम आक्रमण की आशा करने हैं उसके विरुद्ध दूसरी शक्ति के साथ संधिबद्ध हो जाते हैं। आक्रमण की समस्याएँ उस समय अधिक स्पष्ट हो जाती हैं जब दो राष्ट्र परस्पर राजनैतिक संपर्क में उत्पन्न जाते हैं। सन् १९५० में पाईलेण्ड, दक्षिण वियतनाम आदि राज्यों की यह विश्वास था कि यदि चेराबन्दी न की गई तो चीन के आक्रमण लगातार होते रहेंगे। दूसरी ओर चीन यह सोच रहा था कि यदि किसी उपनिवेशवादी प्रशासन या सरकार को थोड़ा बहुत भी स्थानीय समर्थन मिला तो यह विदेशी सहायता प्राप्त कर लेगी और इस प्रकार चीन के लिए यह दूसरी चुनौती बन जाएगी। जब कुछ मन-मुटाव हो जाता है तो आक्रमण की सम्भावनाएँ पूरी-पूरी हो जाती हैं और उसके विरुद्ध कोई प्रमाण स्वीकार नहीं किया जाता।

② सैनिक संधि में बढ होने का दूसरा कारण शीत युद्ध है। शीत युद्ध में अनेक देश एक या अन्य महाशक्ति के साथ सैनिक संधिबद्ध हो गए जैसे

कि वे भी विचारधारागत सघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उलझ हुए हों, यद्यपि इन देशों की सधि का केन्द्रीय सघर्ष से अधिक लेना देना नहीं होता। इस प्रकार की सधि में एक देश इस आशा से सम्मिलित होता है कि सकट के समय उससे सहायता प्राप्त होगी। यद्यपि ऐसे देश प्रत्यक्ष रूप से विरोधी महाशक्ति के साथ अथवा उसके मित्रों के साथ सघर्षपूर्ण सम्बन्धों में उलझे नहीं रहते। आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड आदि साम्यवाद के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सन्निवद्ध हैं। किन्तु इनमें से कोई भी देश आन्तरिक रूप से साम्यवादी समस्या नहीं रखता और न ही उनके सामने कोई अन्तर्देशीय या विदेशी साम्यवाद की चुनौती है। आस्ट्रेलिया ने सीएटो तथा एन्जस (ANZUS) की सन्धि को स्वीकार किया है किन्तु उसके लिए यह सधिया साम्यवाद का विरोध नहीं है। शीत युद्ध की सधियों का एक उदाहरण पाकिस्तान है। पाकिस्तान में वे सभी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो एक गुट-निरपेक्ष नीति को अपनाने की प्रेरणायें देती हैं। पाकिस्तान में भी उपनिवेशवाद विरोधी तथा राष्ट्रवादो भावनार्यें पाई जाती हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ पाकिस्तान का इतिहास, परम्परायें तथा धार्मिक बन्धन हैं। इसके अतिरिक्त चीन व रूस के साथ एवं पश्चिमी शक्तियों के साथ पाकिस्तान के जो सम्बन्ध हैं उन सब के देखने से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी गुट निरपेक्षता की नीति का ही अनुसरण करना चाहिए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने १९५४ तथा १९५५ में सीएटो एवं बगदाद-सधि को स्वीकार कर लिया। यद्यपि पाकिस्तान की असेम्बली में इसका पर्याप्त विरोध किया गया किन्तु फिर भी देश की सुरक्षा के नाम पर इसे स्वीकार लिया गया। मोहम्मद अहम चौधरी (Mohammed Ahsen Choudhri) के मतानुसार पाकिस्तान ने यह आशा की कि सीएटो तथा बगदाद सन्धि में शामिल हो जाने के बाद संयुक्त राज्य अमरीका उसे आर्थिक एवं सैनिक सहायता देने के अतिरिक्त काश्मीर के झगड़े को सुलझाने में नैतिक तथा राजनैतिक सहायता प्रदान करेगा।

बाद के अनुभवों से पाकिस्तान को पर्याप्त निराशा हुई क्योंकि अमरीका द्वारा भारत को भी सहायता दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में सीएटो सन्धि को कोई लाभदायक समझौता न मान कर एक भार समझा गया।

सैनिक सधियों को स्वीकार करने का तीसरा कारण एक देश की आन्तरिक राजनैतिक अवस्था होती है। युद्ध के तुरन्त बाद क्लिपाहन्त तथा मलया की आन्तरिक अवस्था ने इन देशों को सैनिक सधि में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों देशों में जापान से लड़ने वाले

छापामारों का शासन था। इस शासन के विरुद्ध देश की प्रतिव्रियावादी शक्तियों ने संगठन बनाया और देशों के बीच विरोध का सूत्रगत हुआ। बाद में पश्चिम की सहायता से आन्तिकारियों को दबाने के बाद इन देशों में पश्चिम समर्थक सरकारों की स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया। किन्तु इण्डोनेशिया तथा इण्डोचीन में राष्ट्रवादी एवं छापामार सत्त्वों को नहीं दबाया जा सका क्योंकि पश्चिमी शक्तियों की सेना वृद्ध से हट चुकी थी। एक देश की सरकार को जब अपने अस्तित्व के लिए खतरा दिखाई देता है तो वह भीघ ही किसी महाशक्ति के साथ सन्धिबद्ध हो जाती है।

सैनिक सन्धि में शामिल होने का चोपा कारण तब उत्पन्न होता है जबकि एक देश की आन्तरिक गड़बड़ी को नीति-गुट का राजनैतिक लाभ उठाने के लिए विदेशी एजेंटों द्वारा प्रेरित या समर्थित किया जाता है। यह कारण पाइलैण्ड तथा ससेलोन द्वीपों, अफ्रीका के अनेक राज्यों, मध्य पूर्व एवं लेटिन अमरीका आदि राज्यों पर बहुत कुछ लागू होता है।

(B) गुट-निरपेक्षता के कारण (The Causes of Non-Alignment)—सैनिक सन्धि को स्वीकार करने के लिए प्रभावित करने वाले कारणों का अध्ययन करने के बाद अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कोई देश गुट-निरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाता है, इसके क्या कारण हैं? ऐसा नहीं होता कि जिस देश पर सन्धि-बद्ध होने के लिए दबाव न डाले जायें, वह स्वतन्त्र ही गुट-निरपेक्षता की नीति को अपना के। सन्धि-बद्ध होने के कारणों का प्रभाव निषेधात्मक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु सकारात्मक रूप से इस दिशा में प्रेरित करने वाले दूसरे ही तत्व होते हैं। विलियम हेन्डर्सन (William Henderson) ने गुट-निरपेक्ष नीति के लिए उत्तरदायी आठ मुख्य प्रेरणाओं का उल्लेख किया है, ये हैं—सांस्वात्पीकरण का विरोध, नव प्राप्त स्वतन्त्रता को बनाये रखने का संकल्प, भावनाओं की अधिकता किन्तु भौतिक कमजोरियाँ, विदेश-ध्यवहार का अज्ञान तथा उदासीनता, भावसंवाद का प्रभाव, साम्यवादी चीन के साथ समाशोषित होने की आवश्यकता, यह विश्वास कि गुट-निरपेक्ष नीति शान्ति को बढ़ावा देती है तथा गुट-निरपेक्षता के द्वारा साम्यवाद को रोक जा सकता है।

गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए एक देश क्यों प्रेरित हुआ? इस प्रश्न का जवाब हमें उन देशों के सामान्य प्रभावों एवं विशेष प्रभावों को देखने पर प्राप्त हो सकेगा जो इस नीति पर चल रहे हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार एवं उन्नि-वेशवाद का विरोध तथा आर्थिक विकास की समस्याओं के दबाव ने निम्न कद-

उन सभी परिस्थितियों को पैदा किया है जिनमें गुट-निरपेक्षता की नीति संचालित होती है। ये विशेषताएँ ऐसी हैं जो प्रायः अफ्रीका और एशिया के सभी देशों में पाई जाती हैं चाहे वे गुट-निरपेक्ष हों अथवा न हों। ये तत्त्व एक गुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए भा उभरना हो बजाब डालते हैं जितना कि सम्भव हो जाने के लिए। इन तत्त्वों का गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने में जितना योगदान रहता है यह एक विवादास्पद प्रश्न है। अधिकांश विचारकों का मत है कि ये सहायक परिस्थितियाँ इन नीति के विकास में सहायता अवश्य देती हैं किन्तु ये आवश्यक पूर्व शर्तें नहीं हैं।

गुट-निरपेक्ष नीति की सहायक परिस्थितियों में प्रथम उल्लेखनीय राष्ट्रवाद की भावना है जो स्वतन्त्रता आन्दोलनों की एक मुख्य विशेषता रही है। सामान्य भाषा एवं सभ्यता न होते हुए भी एशिया, अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के देशों में इस भावना का पर्याप्त प्रसार एवं प्रभाव हुआ। गुट के बाद अफ्रीका के देशों का राष्ट्रवाद एक दृष्टि से अफ्रीकावाद (Africanism) था। यह अतीत के प्रति प्रतिनिधता थी। यह निम्न स्तर के विरुद्ध, जातीयता के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जो भाषा, संस्कृति और जाति की सीमाओं को पार कर गई। नये राज्यों का राष्ट्रवाद उन परिस्थितियों के अनुसार मिश्र-भिन्न होता है जिनमें यह उत्पन्न हुआ। जिन देशों को साम्राज्यवादी शक्तियों ने जातानों से स्वतन्त्रता दे दी उनके बीच बाद में भी सम्ग्रन्थ अच्छे बने रहे तथा जिन देशों को इन्डोनेशिया की तरह स्वतन्त्रता प्राप्त करने में पर्याप्त समय करना पड़ा उनके सम्ग्रन्थ परस्पर विगड़ गये। प्रायः सभी नव स्वतन्त्रता प्राप्त राज्यों के राष्ट्रवाद में राष्ट्रपन को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। राष्ट्रवाद और गुट निरपेक्षता के बीच सहयोग इसलिए है क्योंकि इन देशों के नेताओं ने अपनी गुट-निरपेक्षता की नीति का समर्थन करने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया। एक बार हव० प्रधानमन्त्री नेहरू ने कहा था कि "यदि किसी आन्दोलन को जनता के लिए वास्तविक बनना है तो उसे राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित होना चाहिए। किसी भी एशियाई देश में एक आन्दोलन उसी मात्रा में सफल अथवा असफल होगा जिस मात्रा में कि वह राष्ट्रवाद की गहनतम भावना के साथ संयुक्त है।" जॉन मारकस (John Marcus) का कहना है कि फ्रांस, जर्मनी तथा घेन ब्रिटेन में जब कभी तटस्थता की नीति का प्रभाव आया है तो वह मुख्यतः इन देशों में अल्प राष्ट्रवाद की भावना के कारण आया।

दूसरी सहायक परिस्थिति आनिडेनवाद का विराघ है। एशिया तथा अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवादी एवं आन्तिहारी आन्दोलन बने, उनका मुख्य

प्रेरणा उपनिवेशवाद का विरोध था। सन् १९५५ में हुए वाण्डुज सम्मेलन का यह मुख्य विचार था। यदि एक देश को सैनिक संगठन में शामिल होने को मजबूर करने वाली कोई चीज नहीं है तो उपनिवेश विरोधी भावना उसे गुट-निरपेक्षता की दिशा में प्रभावित करेगी। एशिया और अफ्रीका के देशों का यह विश्वास है कि अतीतकाल में होने वाली सभी लड़ाइयाँ मुख्य रूप से योरोपीय लड़ाइयाँ थीं और इसमें एशिया तथा अफ्रीका के देशों को गतराज के मोहरों की तरह प्रयुक्त किया गया। आज इन शोषित राज्यों को यदि सैनिक सधियों में मिला दिया गया तो वही पुराना इतिहास दोहराया जायेगा। इस व्यासका से वे अपने आपको अलग ही रखना पसन्द करते हैं। उपनिवेश विरोधी भावना के कारण एशिया और अफ्रीका के ये देश पश्चिमी शक्तियों के साथ नहीं मिलना चाहते किन्तु अतीत के सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी एवं प्रशासनिक सम्बन्धों के कारण वे उनका विरोध भी नहीं करना चाहते अतः गुट निरपेक्षता की नीति अपना लेते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे को साम्राज्यवादी कहा जाता है। नये राज्य यह तय नहीं कर पाते कि कौन साम्राज्यवादी है और कौन नहीं, अतः वे दोनों को ही सदेह की नजर से देखते हैं। यही कारण है कि इन देशों में से कोई भी यह नहीं चाहता कि वह किसी भी एक पक्ष से हो आर्थिक या सैनिक सहायता प्राप्त करे। इस प्रकार गुट निरपेक्षता की नीति को पराधीनता के विरुद्ध आत्मरक्षा का एक साधन बनाया गया है।

तीसरी सहायक परिस्थिति इन देशों की अर्द्धविकसित स्थिति है। इनकी गरीबी तथा उच्च जीवन स्तर की मांग ने इन देशों में आर्थिक विकास को पर्याप्त महत्व प्रदान किया है। यह भी गुट-निरपेक्ष नीति की एक प्रेरणा है। ये देश मैनगुटावों तथा लिखावों को कम करके इस बात का प्रयास करते हैं कि शस्त्रों के निर्माण पर अधिक खर्च न करके उत्पादन व विकास पर किया जाये। गुट-निरपेक्षता के समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि इस नीति को अपनाने पर दोनों ही गुटों की पर्याप्त आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है जबकि गुट में शामिल होने पर तो केवल एक ही देश की सहायता प्राप्त होती। कुछ विचारकों के मतानुसार यह तर्क अत्यन्त हल्का है क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से सन्निवृद्ध देशों को अधिक सहायता प्राप्त हुई है। प्रारम्भ में तो असलान देशों की महाशक्तियों द्वारा सहायता ही नहीं दी गई। इनके अतिरिक्त इन देशों की अपनी सुरक्षा योजनाओं पर भी पर्याप्त ध्यान बरतना पड़ा। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का विचार है कि उनको जो भी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है वह उनका अधिकार था न कि कोई बहुशान। राष्ट्रपति नासिर के कथनानुसार अतीत काल में साम्राज्यवादी शक्तियों ने जिस

राष्ट्रीय सम्पत्ति का अपहरण किया वह यदि उनको वापिस प्राप्त होती है तो इसमें किसी का भी क्या अहसान है। सहायता प्रदान करना प्रगतिशील देशों का एक स्वेच्छापूर्ण कर्तव्य है। यह एक प्रकार का कर है जो अतीत के उपनिवेशवादी शोषण कर्त्ताओं द्वारा उनको प्रदान किया जाना चाहिए जो शोषित किये गये हैं। विकसित देशों के प्रति गरीब देशों में एक ईर्ष्या की भावना पैदा हो रही है अतः यह आवश्यक है कि इनके जीवन स्तर में जो असमानताएँ हैं उनको दूर किया जाये।

चीन, गुट निरपेक्षता की नीति का एक जानीय एवं सांस्कृतिक पहलू भी है। इस नीति को मानने वाले देश मुख्यतः अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के रहने वाले हैं। ये देश ऐसे हैं जो योरोप से भिन्न दुनिया में रहते हैं। इन देशों का आर्थिक रूप से शोषण किया गया था तथा इस पर समान रूप से राजनैतिक अधिकार रहा था अतः इनके बीच एक पारस्परिक सहानुभूति रहना स्वाभाविक है। अवसरवश गुट निरपेक्ष देश अद्वैत हैं। इन देशों के बीच परस्पर सांस्कृतिक एकता इतनी अधिक नहीं है किन्तु केवल यही एकता है कि वे समान रूप से एक बड़ी शक्ति के आधीन रहें।

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद का विरोध, आर्थिक सहायता की आवश्यकता एवं सांस्कृतिक एकता आदि तत्वों द्वारा अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करके गुट निरपेक्षतावादी नीति के विकास के लिए एक घुंठभूमि का काम किया गया जैसे ये परिस्थितियाँ कई ऐसे देशों में भी पाई जाती हैं जो सैनिक संगठनों के सदस्य हैं। इन देशों को इन परिस्थितियों ने सन्धि करने की दिशा में प्रेरित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम इन परिस्थितियों को गुट निरपेक्ष नीति के विकास का मुख्य कारण नहीं मान सकते। मुख्य कारण तो अन्य परिस्थितियाँ हैं। इनका निर्धारण भी हम एशिया और अफ्रीका के सभी देशों का निरीक्षण करने के बाद ही कर सकते हैं। गुट निरपेक्षता के ये विशेष लक्षण एशिया व अफ्रीका के सभी देशों में सामान्य रूप से पाये जाते हैं किन्तु इतने पर भी गुट निरपेक्ष देशों में इनका प्रभाव अधिक होता है। इनका सम्बन्ध राजनैतिक दृष्टिकोणों से रहता है तथा इसकी अभिव्यक्ति अनेक आर्थिक एवं राजनैतिक संगठनों में होती है। गुट निरपेक्ष देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संघर्ष किया था। वे स्वाधीनता से पूर्व ऐसी सत्ताओं की मांग कर रहे थे जो उपनिवेशवादी सरकार को मान्य न थी। विश्व राजनीति में भी ये देश स्थित व्यवस्था का समर्थन करने की अपेक्षा पार्श्वकारी आन्दोलन का समर्थन करने लगे।

गुट-निरपेक्षता की दृष्टि से जो तत्व महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव डालते हैं उनमें पहला समाजवाद है। योरोप में तटस्थता की नीति का समर्थन सामपक्षियों द्वारा किया गया था तथा नहा समाजवादी एवं तटस्थतावादी व्यंगों में अधिक भेद नहीं था। अफ्रीका और एशिया के देशों में भी अधिकांश अर्द्धविकसित देश इसी प्रकार समाजवाद एवं तटस्थता की नीति से प्रभावित हैं। इन देशों द्वारा अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए नियोजन, राष्ट्रीयकरण, सरकारी हस्तक्षेप आदि साधनों को अपनाया जा रहा है। इन देशों की प्राप्त अल्प सम्पत्ति प्रायः ऋषि कार्य में केन्द्रीकृत रहती है अतः औद्योगिक विकास का कार्य केवल सरकार की पहल पर ही किया जा सकता है। भारत में कांग्रेस सरकार ने प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया है। जिस किसी देश में गठित भ्रान्ति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की जाती है उस देश की विशेषता केन्द्रीय शक्तियाँ, केन्द्रीय निर्देशन एवं नियोजन बन जाता है।

रगून में सन् १९५३ में एशिया के समाजवादियों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक एसियाई समाजवादी व्यूरो स्थापित किया गया। वर्मा में समाजवादी दल के संस्थापक के शब्दों में "समाजवादी नेताओं के रूप में हमको ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो भ्रष्टता की राजनीति को समाप्त करदे अथवा एक नये स्वतन्त्र विचारधारागत दृष्टिकोण को रोक दे। इस स्वतन्त्र दृष्टिकोण के कारण ही हम इस तीसरी शक्ति का विकास कर सके हैं तथा प्रजातन्त्रात्मक समाजवाद का विचार विकसित कर सके हैं।"

इस प्रकार का मानसिक दृष्टिकोण लोचनील, स्वीकार करने योग्य तथा किसी भी विचारधारा से अलग होता है। किन्तु यह किसी न किसी प्रकार से नियोजन का समर्थन करता है ताकि अपनी कृषक अर्थव्यवस्था को बढ़ा सके। ऐसी स्थिति में ये देश अमरीका और सोवियत संघ के बीच का ही मार्ग अपनाते हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि ये देश दोनों गुटों से अलग अपना अस्तित्व बनायें। सन् १९५० तक समुन्नत राज्य अमरीका द्वारा इन देशों को साम्यवादी माना जाता था और साम्यवादी देश इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वाजीवाद का ही एक रूप कहते थे। समाजवाद गुट निरपेक्ष नीति की पूर्ण आवश्यकता नहीं है, किन्तु यह अर्द्धविकास की समस्याओं के प्रति नए राज्यों की प्रतिनिधिता है। समाजवाद, अर्द्धविकास और गुट निरपेक्षता तीनों एक ही साथ एक ही बालावरण में पाए जाते हैं।

समाजवाद की भांति गुट निरपेक्ष देशों की एक अन्य विशेषता यह है कि वे अपनी घरेलू नीति के प्रति भ्रान्तिवारी दृष्टिकोण रखते हैं। स्वतन्त्रता

प्राप्त करके इन देशों ने स्वतन्त्रता की महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट किया। एक दूसरी शक्ति की आवश्यकता और भी जो इन देशों की भौतिक महत्वाकांक्षाओं को सन्तुष्ट कर सके। इण्डोनेशिया में विदेशी सम्पत्ति और पूंजीगत उद्यमों को समाजीकृत कर दिया गया। एशिया और मध्य-पूर्व के अनेक क्षेत्रों में चीन की भाँति भूमि की व्यवस्था में पर्याप्त परिवर्तन किया गया। अन्य देशों में भी आर्थिक शक्ति प्रारम्भ हो चुकी थी। वहाँ उन संस्थाओं को बदला गया जो इस शक्ति के मार्ग की बाधा थी और उसे आने से रोक रही थी।

समाजवादी शक्तिशाली सरकारें पश्चिम के साथ अपने आपकी सधियद्ध नहीं कर सकती थी। संयुक्त राज्य अमरीका में इस समय समाजवाद का विरोध ज्वर जोरों पर था। जो सरकार जमींदारी, जागीरदारी को दूर करने का प्रयास करती थी उसे अमरीका चीन का हमदम मान लेता था। इस आधार पर इन नये राज्यों के नेताओं के प्रति अमरीका का दृष्टिकोण सन्देहपूर्ण रहा। संयुक्त राज्य अमरीका की नीति इन राज्यों में सामाजिक और राजनैतिक परिवर्तनों को हतोत्साहित करने की रही। यह प्रतिनिध्यावादी सरकारों को खनखन देता रहा ताकि प्रशासनिक अव्यवस्था से लाभ उठा कर साम्यवादी आगे न आ जायें। एशिया और अफ्रीका के देशों ने जो आन्तरिक शक्ति की उमने उनको पश्चिमी देशों के साथ मिलने से रोक दिया। किन्तु जहाँ पश्चिमी दबाव उन पर अधिक पड़े वहाँ इन देशों ने साम्यवादी देशों की सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, उदाहरण के लिए वजूबा को लिया जा सकता है। जहाँ इस शक्ति को मजबूत पश्चिमी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा वे गुट-निरपेक्ष बने रहे, उदाहरण के लिए मिस्र।

इसका अर्थ यह नहीं होता कि सामनवादी सरकारें गुट-निरपेक्ष नहीं होती। बेलग्रड सम्मेलन में इस तथ्य को स्वीकार किया गया, फिर भी यह बताया जाता है कि सामनवादी देशों की जनता आन्तरिक सुधारों की मांग करती है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सरकार विदेशों में अपनी रक्षा की मांग करती है और वे गुट निरपेक्ष नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित है कि गुट निरपेक्ष देश प्रायः वे होते हैं जहाँ तीव्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो चुके हैं या हो रहे हैं।

सीमरे, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का राजनैतिक दृष्टिकोण भिन्न है। वे युद्ध को, रोकने के परम्परागत पद्धतियों, द्वायतों, से दिखाला नहीं करते और हमारे शक्ति-सन्तुलन आदि को मान्यता नहीं देते। नाबिलीय प्रतिरोध के नवीन प्रयोगों को भी वे बहुत कम आदर देते हैं। गुट-निरपेक्ष नीति के

समर्पक युद्ध, शक्ति एवं प्रत्येक शक्ति गुट के दावों का अवमूल्यन करते हैं। स्व० श्री नेहरू ने सन् १९५४ में कांग्रेस समिति को भेजे हुए एक पत्र में लिखा कि शान्ति केवल शान्ति के तरीकों से ही प्राप्त हो सकती है। शान्ति के प्रति युद्ध पूर्ण दृष्टिकोण अपने आप में एक विरोधाभास है। स्व० श्री नेहरू के मतानुसार पहले से ही सुरक्षा का प्रक्रम करना उग गलत प्रवृत्तियों को विनष्टित करना है जो सही प्रवृत्तियों को विकसित होने से रोक देती हैं।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के नेता शीत युद्ध के सभी पहलुओं पर नया दृष्टिकोण रखते हैं। इस दृष्टिकोण के कारण ही वे गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाते के लिए प्रेरित हुए। ये देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विभिन्न समस्याओं के प्रति अपना स्वयं का दृष्टिकोण अपनाते हैं। इन देशों के द्वारा सशदीय व्यवस्था को सरकार का एक मात्र प्रजातन्त्रात्मक रूप कहा जाता है। गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा महाशक्तियों को इस रूप में नहीं देखा जाता है जिस रूप में वे दिखना चाहती हैं बरन् इस रूप में देखा जाता है जैसा कि किसी बाहरी दूरक को प्रतीत हो। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का मत है कि दोनों ही पक्ष विश्व शान्ति के लिए खतरनाक हैं और कोई भी एक पक्ष सदगुरु या बुद्धि पर कोई एकाधिकार नहीं रखता। ये देश शीत युद्ध संपर्प के केवल दर्शन हैं, अभिनेता नहीं हैं इसलिए स्वयं स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। इन देशों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्तिपूर्ण सम्बन्धों के लिए अलग से मार्ग बताया जाता है, उदाहरण के लिए स्व० प्रधानमंत्री श्री नेहरू पंचशील में विश्वास करते थे। उनके कथनानुसार "यदि पंचशील को पूरी तरह और गम्भीरता के साथ सभी देशों के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो प्रत्येक का शान्ति प्राप्त होगी और सहयोग की भावना बढ़ेगी।" स्वतन्त्रता और गुट-निरपेक्षता मुख्य दान हैं। स्वतन्त्रता की प्राप्ति किसी एक बड़ी शक्ति या शक्ति समूह के साथ सधि करने से नहीं हो सकती बरन् प्रत्येक विवादपूर्ण एवं झगड़े वाली स्थिति पर एक स्वतन्त्र दृष्टिकोण रखने से हो सकती है। एक राष्ट्र की पराधीन जनता को स्वतन्त्रता देना, जातीय भेदभाव को समाप्त करना, आवश्यकता, बीमारी और अज्ञान को समाप्त करने, आदि विभिन्न पहलुओं के प्रति स्वतन्त्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

यह कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष देशों के नेताओं के शायों और कथनों में पर्याप्त अन्तर रहता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति मुबारक ने यह घोषणा की थी कि वे पश्चिमी इरियान (West Iran) की समस्या पर ईरान के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। किन्तु सन् १९६१ में उसने

सोवियत सभ से युद्ध प्रमाणन प्राप्त किए जिन्हें परिषदों इरियान के क्षेत्र में रखा गया। शक्ति प्रयोग के अन्य कुछ उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनके पक्ष में यह कहा जाता है कि गुट-निरपेक्ष देशों ने इन्हें आत्मरक्षा और उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनाया। किन्तु यह तर्क अधिक न्यायोचित नहीं है, क्योंकि इसे तो युद्ध करने वाला कोई भी देश दे सकता है; या तो गुट-निरपेक्ष राज्यों को यह स्पष्ट करना होगा कि जिन परिस्थितियों में वे शक्ति के प्रयोग को उचित मानते हैं और क्यों? अपना उन्हें भी इस दोष का भागो बनना पड़ेगा कि वे महाशक्तियों से मौलिक रूप से भिन्न नहीं हैं।

चौथे, अनेक बड़े गुट निरपेक्ष राष्ट्र, जैसे भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया और इण्डोनेशिया अपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा भाग सुरक्षा के कार्यों पर खर्च करते हैं। गुट-निरपेक्ष और गुट-भाषेक्ष देशों के कार्य तो लगभग एक जैसे हैं किन्तु दानों के दृष्टिकोण में अन्तर है। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का विद्वान्त है कि भय को हटा दीजिए, और आत्मभयकारी नीतिषा अपने आग हट जायेगी। दूसरी ओर सशिवद्ध राष्ट्रों का विचार है कि जब तक सम्भावित आक्राता का प्रतिरोध करने के लिए शक्ति का परिचय न दिया जाए उस समय तक युद्ध की नहीं रोका जा सकता। गुट-निरपेक्ष देशों की मान्यता है कि आक्रमण की आशा तथा उसे रोकने के लिए की जाने वाली सधिया ही अन्तिम रूप में ससंपूर्ण स्थिति पैदा कर देती हैं। अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस दृष्टिकोण का समर्थन किया जाता है कि युद्ध का आधार भय है।

पाचव गुट-निरपेक्ष देशों में प्रारम्भ से ही अमाधारण नेतृत्व रहा है। स्व० श्री नेहरू, यूनु, सुकार्ना, नासिर, एनकूमा, टीटो आदि का नाम युद्ध के बाद अफ्रीका और एशिया की घटनाओं में प्रमुख रहा है। अफ्रीका और एशिया के जिन देशों ने पहले की उपनिवेशवादी शक्तियों से सधिया की हुई है उनमें कुछ एक अन्वादी नो छाड़ कर, नेतृत्व का अभाव है। यह एक विनाशपूर्ण विषय है कि क्या इन देशों के नेतृत्व ने गुट-निरपेक्षता की नीति का विकास किया? कई विचारकों का कहना है कि गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावशाली नेतृत्व का परिणाम नहीं है बरन् जिन परिस्थितियों ने प्रभावशाली नेतृत्व को जन्म दिया वे ही गुट-निरपेक्षता की नीति के लिए भी उत्तरदायी हैं। गुट-निरपेक्षता की नीति को अपनाते वाला पहला देश भारत था। भारतीय विदेश नीति के वर्णनार स्व० पंडित नेहरू को राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान ही उदस्यता की शिक्षा प्राप्त हुई। दस वृष्टभूमि के होने हुए भी यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है कि भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद से ही एक स्वतन्त्र विदेश नीति का अपनाया जो कुछ

सकारात्मक विशेषताओं से युक्त तटस्थ नीति थी। स्व० श्री नेहरू ने सन् १९५० में यह कहा था कि "मेरे सदन में यह कहना चाहता हूँ कि जिस नीति को हम अपना रहे हैं वह केवल तटस्थ या निष्क्रिय या निपेक्षात्मक नहीं है वरन् यह एक ऐसी नीति है जो हमारे ऐतिहासिक तथा वर्तमान अतीत से प्राप्त हुई है। यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन और विभिन्न आदर्शों से निकली है जिनकी हम समय-समय पर घोषणा करते रहते थे।

शांति की रक्षा भारतीय विदेश नीति का केन्द्रीय मूल लक्ष्य है। इस नीति की खोज में ही भारत ने किसी सैनिक या अन्य सन्धि में सम्मिलित नहीं हो कर गुट-निरपेक्षता की नीति का मार्ग अपनाया है। गुट-निरपेक्षता का दीर्घ दिमाग और कार्यों की निष्क्रियता नहीं है, यह विश्वास और मान्यताओं की निष्क्रियता नहीं है, इसका अर्थ बुराई के सामने झुक जाना भी नहीं है, वरन् यह विश्व की समस्याओं के प्रति एक सकारात्मक और उत्प्रेरक दृष्टिकोण है। यद्यपि नेतृत्व के कारण गुट-निरपेक्ष नीति के विकास में पर्याप्त सहायता मिली किन्तु नेतृत्व का पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह दिखाई देता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों ने गुट-निरपेक्षता की नीति को जन्म दिया उन्होंने इन नेताओं का भी विकास किया। कारण चाहे कुछ भी हो किन्तु गुट-निरपेक्षता की नीति और प्रभावशाली नेतृत्व दोनों साथ-साथ चले हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुट-निरपेक्षता की नीति एक देश द्वारा उठा सपना बन गई जाती है जब कि उस पर सधि में बचने के लिए अधिक दबाव न डाले जाय। इतने पर भी गुट-निरपेक्षता को एक स्वभाविक चीज नहीं कहा जा सकता जो अपने आप विकसित हो जाती हो, वरन् अनेक विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं जो राष्ट्री को इस नीति की ओर प्रेरित करते हैं। इनमें से कुछ प्रभाव तो ऐसे हैं जो गुट-निरपेक्ष और गुट-मापेक्ष देशों में समान रूप से पाए जाते हैं जब कि अन्य कुछ प्रभाव ऐसे हैं जो केवल गुट-निरपेक्षता की नीति के लिए भी विशेष हैं।

गुट निरपेक्ष नीति का उद्देश्य

(The Object of Non-alignment)

गुट-निरपेक्ष नीति एक देश को मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्रदान करती है। इस नीति को मानने वाले देश किसी भी प्रकार की विदेशी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं यदि वह उनके आन्तरिक विषयों पर हस्तक्षेप करने का प्रयास करे। स्वतन्त्रता की रक्षा इस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है और यदि सहायता देने के माध्यम से विदेशों द्वारा उसकी

स्वतन्त्रता को छोड़ा जाता है तो वह इस सहायता का बलिदान कर देगा। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर जो दृष्टिकोण अपनाया जाता है वह विषय का प्रकृति एवं औचित्य पर आधारित होता है। इन देशों की मान्यता है कि महाशक्तियों द्वारा कही गई बात अन्तिम सत्य नहीं होती, क्योंकि वे अपने स्वार्थ एवं अन्य भावनाओं से प्रभावित होती हैं। शीत युद्ध से अलग रहने के कारण गुट निरपेक्ष देश किसी समस्या को वस्तुगत रूप से देख सकते हैं और दृष्टिकोण की यह स्वतन्त्रता ही गुट-निरपेक्ष नीति का एक मुख्य उद्देश्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक विचारक गुट-निरपेक्षता की नीति को केवल एक साधन मानते हैं तथा उसे विदेशी नीति का स्तर देने को तैयार नहीं हैं। यह सब है कि गुट निरपेक्षता की नीति द्वारा सम्बन्धित देशों ने आर्थिक विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और विदेशों से पर्याप्त सहायता प्राप्त की है किन्तु इस आधार पर गुट निरपेक्षता को कोई नीति न मानना गलत है। लेखकों के मतानुसार विदेश नीति भी एक साधन होती है जिसने सहारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अमल में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में साधन और नीति के बीच कोई महत्वपूर्ण अन्तर स्थापित करना मुश्किल है। गुट निरपेक्षता विदेश नीति का एक मुख्य साधन है।

गुट-निरपेक्षता की नीति के द्वारा एक राष्ट्र अपनी सम्प्रभुता एवं प्रादेशिक अखण्डता को रक्षा का प्रयास करता है। जब भारत को दोनों ही गुटों से सैनिक सहायता प्राप्त हुई तो पाकिस्तान और चीन आदि देशों ने यह दोष लगाया कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का त्याग कर दिया है। सन् १९६२ के चीन आक्रमण से पूर्व भारत द्वारा विदेशों से केवल आर्थिक सहायता प्राप्त की जाती थी किन्तु समय की आवश्यकताओं से प्रभावित हो कर भारत ने अपनी विदेश नीति को समायोजित किया और सैनिक सहायता स्वीकार की। यद्यपि भारत ने सैनिक सहायता ली किन्तु—उसने—अपने प्रदेश पर विदेशी सेनाओं एवं सैनिक अड्डों की स्थापना होने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार विदेशी सहायता, चाहे वह सैनिक हो अथवा आर्थिक, उस समय तक गुट-निरपेक्षता के विरुद्ध नहीं बोझा जाती जब तक कि वह सम्बन्धित देश की विदेश नीति की दृष्टान्तता समाप्त नहीं करती। यदि कोई देश अपनी स्वतन्त्रता एवं प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए विदेशी सहायता की स्वीकार करता है तो एक प्रकार से वह उन्हीं लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो रहा है जिनकी ओर हमें गुट निरपेक्षता की नीति ले जाती है। सैनिक सहायता के माध्यम से गुट निरपेक्ष नीति का मार्ग गुप्त तथा निर्वाचन बन जाता है।

गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का एक अन्य लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना है। इस नीति में विश्वास करने वालों का मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति एक नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य है जो युद्ध की अमानवीय बर्बरताओं से बचा कर सम्यता एवं सस्कृति के प्रसार को आगे बढ़ाता है। गुट-निरपेक्ष देशों द्वारा विश्व शांति का समर्थन केवल इसीलिए नहीं किया जाता कि वह उनके आर्थिक विकास एवं राजनैतिक स्थिरता के लिए जरूरी है बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि आज का युद्ध विध्वंसकारी बन गया है। इसके अतिरिक्त शांति अपने आप में एक अच्छाई है और इसे किसी अन्य कारण के लिए नहीं चरन् इसकी अन्तर्निहित अच्छाई के लिए ही अपना लिया जाना चाहिए। युद्ध के न होने पर ही मानव मात्र द्वारा सम्यता एवं सस्कृति के क्षेत्र में नई प्रगति का कुछ मूल्य होता है। नेहरू के कथनानुसार गुट-निरपेक्ष नीति युद्ध नहीं चाहती है, यह शांति के लिए सकारात्मक रूप में प्रयास करती है तथा सहयोग में विश्वास करती है।

गुट निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन भी है। कुछ लेखकों के अनुसार जब गुट निरपेक्षता के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को साधने का प्रयास किया जाता है तो वह नीति बन जाती है और जब इसे विश्व शांति की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह एक साधन बन जाती है। यदि गुट निरपेक्षता को हम आर्थिक आत्मनिर्भरता, या राजनैतिक स्वायत्तता अथवा उपनिवेशवाद के विरोध का साधन मात्र ही मान लें तो ऐसी स्थिति में इन लक्ष्यों के प्राप्त हो जाने पर गुट निरपेक्षता का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए यह जरूरी है कि इसके साथ किमो स्थायी एवं सर्वनालीन मूल्यों को समुक्त किया जाये। इस मूल्य के साधन के रूप में ही हम इसका मूल्य आंक सकते हैं। विश्व शांति की प्राप्ति को एक ऐसा ही मूल्य बताया गया जिसको प्राप्त करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति को साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। गुटनिरपेक्ष देश विश्व शांति को राष्ट्रीय हित में भी अधिक प्रगुप्तता प्रदान करते हैं। यह कहा जाता है कि अनेक विचारक गुट-निरपेक्षता की नीति में छिपी शक्ति को नहीं पहचान सके जिसके आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का शान्तिपूर्ण निपटारा किया जा सके। यही कारण है कि जार्ज श्वार्ज़ेनबर्गर (George Schwarzenberger) ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आत्म-केन्द्रित नीति बताया है। मार्क्स-यो तथा रीनाल्ड नीबर आदि लेखक इसे केवल विचारधारा मात्र कहते हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन विचारकों का अर्थ यही है कि गुटनिरपेक्षता की नीति विदेशी सहायता प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण होने

क माय माय गठन भी है क्योंकि यह नीति मुख्य रूप से विश्व शांति की स्थापना का प्रयास करती है।

गुटनिरपेक्षता का नीति समुक्त राष्ट्रमन्त्र का तथा निःशस्त्रीकरण को दिया में नियोजन वाले प्रयामो का मनन करती है। यह नानि उन सभी कार्यों का समर्थन करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय शिवाव को दूर करने में सहायन करते हैं। एना स्थिति में समुक्त राष्ट्र सन एव निःशस्त्रीकरण सम्मेलन को सक्राना का गुटनिरपेक्ष राज्यों के लिए अत्यन्त महत्व होता है। गुटनिरपेक्ष नानि का अस्तित्व हो विश्व शांति के अस्तित्व पर निर्भर करता है। युद्ध छिड़ जान पर गुटनिरपेक्षता नाम की कोई चीज न रहेगी। स्वर्गीय आ नहल यह कहा करते थे कि यदि वास्तविक युद्ध छिड़ गया तो गुटनिरपेक्ष अवका अलम्न राज्यों के सामने इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता कि व जिने भी उचित समझें उन पक्ष के साथ व्यापकतया या सावृहिक रूप से युद्ध में शामिल हो जाएँ। इस प्रकार तृतीय विश्व युद्ध की रोकना इस नीति का केवल लक्ष्य ही नहीं है वरन् यह उसके अस्तित्व की आवश्यक मन भी है।

भारत में गुट निरपेक्षता व असंलग्नता की नीति

(Non aligned Policy in India)

भारत न स्वतन्त्रता व वाद से हो अपनी विदेशी नीति का आधार गुट निरपेक्षता या असंलग्नता को बनाया है। भारत की यह नीति है कि वह वनमान दि व राजनीति व दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल नहो होगा। किन्तु अ ग रहते हुए भी उनसे मैत्री सम्बन्ध कायम रखने की चेष्टा करेगा और उनकी मिता गत सहायता में अपनी उन्नति करने में तत्पर रहगा। भारत का विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति में वह महत्वपूर्ण योग सभी दे सकगा जब अपने विवेक की स्वतन्त्रता को वह सुरक्षित रहे। भारत को गुट निरपेक्षता या असंलग्नता की नीति सकारात्मक और गतिशील (Positive and Dynamic) है।

स्वाधीन भारत का इतिहास बताता है कि इस देश ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर सन्धि रूप से भाग लिया है और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुनधान में पूर्ण समाह से अरना सहायन दिया है। भारत की नीति तत्स्थ वही सर है कि तक वह पक्ष में ही किसी पक्ष व साथ अपने को बाधना नहो चाहे, चाहे शांतिविरुद्ध हो, है कि अत्यन्तकरता अपने अर भारत धृष्टकार अटकर समागत दमन बागा नहो है। भारत कभी भी और किसी भी एक पक्ष का समर्थन करने का तयार रहा है जिसकी शांति को उसने

विश्व शांति और सुरक्षा के लिए उपयोगी माना है। इसी तरह वह ऐसे पक्ष का विरोध करता रहा है जिसकी नीति को उसने शांति और सुरक्षा के लिए अहितकारी समझा है।

भारत की असलग्नता की नीति का उद्देश्य किसी तृतीय गुट का निर्माण करके उसका नेतृत्व करना नहीं है। भारत तो दो विरोधी गुटों के बीच सन्तुलन स्थापित करना चाहता है। वह विश्व राजनीति रूपी समुद्र के दो किनारों के बीच एक पुल बनाने का आकांक्षी है। भारत की असलग्नता की नीति उसे छैनिक गुटों से दूर रखे हुए है। लेकिन पड़ोसी और अन्य राष्ट्रों के बीच अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देने में यह नीति बाधक नहीं है। हमारा इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि हमने असलग्नता की नीति पर चलते हुए विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार की राबिया की है किन्तु इन सन्विधों का चिह्नप मैनिक न होकर बाधक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रहा है।

भारत की असलग्नता का अभिप्राय कोय शांतिवाद नहीं है। भारत की असलग्नता, निर्वलता या अशक्ति की छोटक नहीं है। यदि भारत पर आक्रमण होना है तो निश्चय ही हथियारों का जवाब हथियारों से दिया जायेगा। १९६२ में चीनी आक्रमण के समय भी यही हुआ और बाद में १९६५ के पाकिस्तान के आक्रमण ने समय भी यही हुआ। पर भारत के हथियार भारत की रक्षा के लिए हैं, दूसरे देश की सीमाओं का प्रतिरक्षण करने के लिए नहीं।

असलग्नता की नीति के कारण

भारत ने असलग्नता की यह नीति कुछ अल्पसंख्यक कारणों के आधार पर अपनायी है जो संक्षेप में इस प्रकार हैं—

(१) भारत किसी भी देश पर शांता करना नहीं चाहता, अपितु विश्व में शांति बनाये रखने का इच्छुक है। इस दृष्टि से उसके लिये किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना उपयुक्त नहीं है।

(२) भारत युद्ध को दूर रखने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहता है, किन्तु यदि किसी गुट विरोध में सम्मिलित होने की उसने चेष्टा की तो उसका यह प्रभाव निश्चित रूप से क्षीण हो जायगा।

(३) भारत अपनी विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता को बनाये रखना चाहता है। यदि उसने किसी गुट विरोध को अपना लिया तो उसे अनिवार्य रूप से विरोध की समस्याओं पर वही रूप अपनाना पड़ेगा जो उसका गुट अपना रहा है।

(४) असलमन्नता की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। बहुत से विचारक, जो व्यवस्थापिका की विदेश नीति को श्रेष्ठ मानते हैं, वे भी इस प्रकार की नीति से सन्तुष्ट होंगे। स्वतन्त्र वैदेशिक नीति कालान्तर में अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। भारत, अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी याजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहायता एवं सहायता पर बहुत कूट निर्भर है। असलमन्नता की नीति उसके इस लक्ष्य को भली प्रकार सम्भव बना रही है। किसी गुट में शामिल न होने के परिणामस्वरूप ही यह सम्भव हुआ है कि भारत के सम्पूर्ण विश्व के दोनों शक्तिशाली शक्तियों के साथ अच्छे हैं और सावित्र नर तथा अमेरिका दोनों से एक ही साथ उसे सहायता मिल पा रही है। इससे अतिरिक्त किसी एक गुट के हाथों में खेदने की नाति न केवल अर्थात् है वरन् भारत जैसे राष्ट्र के लिये अस्मानजनक भी है।

(५) भारत की भौगोलिक स्थिति भी उसे असलमन्नता की नीति अपनाने को बाध्य करती है। हम पश्चिमी गुट के साथ सैनिक गुटबन्दी नहीं कर सकते क्योंकि विद्वत् के पश्चिम विरोधी दो प्रमुख और अत्यन्त शक्तिशाली साम्यवादी देशों की सीमाएँ भारत की सीमाओं के सन्निकट हैं। दुर्भाग्यवश साम्यवादी चीन से हम संपर्क की स्थिति में हैं और यदि पश्चिमी सैनिक क्षेत्र में शामिल हो कर हमने रुख की सहानुभूति भी खाँदी तो यह हमारे लिये निश्चित रूप से अहितकर होगी। भारत के निकटवर्ती साम्यवादी एवं अन्य देशों में सैन्यपूर्ण सम्बन्धों का होना इसलिए भी आवश्यक है कि उनके आक्रमण की शूरत में पाश्चात्य शक्तियों की सहायता उपयुक्त समय एवं प्रयुक्त मात्रा में प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरी ओर यदि हम साम्यवादी देशों के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं तो इसका स्पष्ट परिणाम अमेरिका एवं हमारे पाश्चात्य राष्ट्रों को अप्रसन्न करना होगा जिससे उनके द्वारा दी जाने वाली सतत विनाश आर्थिक सहायता अवरुद्ध हो जाएगी और भारत का आर्थिक ढाँचा बुरी तरह लज्जित जाएगा। इसके अतिरिक्त साम्यवादी क्षेत्र में हमारी दान-कटौती दाम्नी इसलिए भी नहीं हो सकती कि अपनी अतीत की परम्पराओं के कारण हम साम्यवादी सिद्धान्त को अच्छा नहीं मानते और हिंसात्मक एवं दमनकारी नीतियों तथा व्यवहारों को बुरी निगाह से देखते हैं।

(६) असलमन्नता की नीति भारत की परिस्थितियों और उसकी परम्पराओं में मेल खाती है। ६ दिसम्बर, १९४८ को तत्कालीन प्रधान मंत्री प० नेहरू ने लोकसभा में कहा था कि गुटबन्दी में शामिल न होने की नीति को उन्होंने कबल वाणी दी है, उमरा उगादन नहीं किया है। यह एक ऐसी

नीति है जो भारत की परिस्थितियों में, भारत की प्राचीन विचारधाराओं में और विश्व की वर्तमान आवश्यकताओं में स्वाभाविक है। इस विचारधारा का सार भारत के लोगों के सैनिक और अहिंसक विचारधारा का पालना जाना है। भारतीयों ने इस परम्परा को अपने धर्मग्रन्थों और इतिहास में उत्तराधिकार में पाया है।

(३) भारत की विचारधारा आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तनीयता मान्यताओं का बीज की है और इसलिए यह प्रादेशिक एवं स्थानाधिकार बन जाता है कि उनकी विदेश नीति में ऐसे दोषों के बोध के भाग का हो आवश्यक विचार आए। भारत साम्यवाद की समानता, वा भेद की उपस्थिति सामान्य गुरुत्व, शोध का एक प्रादेशिक विचारों से सहमत है परन्तु उसने पाई जाने वाली अहिंसक विचार, स्वतन्त्रता का प्रभाव एवं दमन प्रादेशिक दोषों को प्रकट इतिहास देता है। इस प्रकार भारत परिवर्तनीय देशों की इस परम्परा ने प्रभावित है कि व्यक्ति के शान्त एवं स्वतन्त्रता का सभी मूल्यमान विचार जाना चाहिए। किन्तु साम्यवाद के व्यक्ति इन दोषों में साम्यवाद की प्रतिनिधि स्वरूप जो प्रकट एवं कटुता का वातावरण बनता है यह भारत के लिए एक उत्पन्न प्रकट प्रतीति है जिससे यह अहिंसक विचारों का प्रतीक मानता है।

प्रकट नेहरू ने यह ठीक ही कहा था "किसी युद्ध के साथ सैनिक सन्धि में वध जान के कारण नया उसका इशारा पर लावता पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतन्त्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अतः चाहें कुछ भी हो जहाँ हम किसी देश के साथ सैनिक सन्धि नहीं करते। अब हम असहयोग (Non-alignment) का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना रास्ता छोड़ कर बढ़ने लगते हैं। किसी देश से अपना आत्म सम्मान सौना है, यह बहुमुख्य निधि का विनाश है।"

भारत की असहयोगता की नीति एक दशकों पर

असहयोगता की भारतीय नीति की व्याख्या करने के उद्देश्य अब हम यह सभ्य में इसका चाहिए कि भारत ने इन नीति का एक तरफ़ केने प्रयोग किया है। इस नीति के इतिहास की गुरुत्व तीन भागों में बाँटा जा सकता है—१९४७ से काबुल के युद्ध (१९५०) तक, कोरिया युद्ध से द्वितीय भारतीय आन विचार (१९५३) तक एवं १९५३ के बाद से अब तक।

(१) सन् १९४७ से १९५० के बीच—१९४७ से १९५० के बीच भारत की असहयोगता की नीति बहुत प्रकट होती है और उसकी प्रकृत अन्तराष्ट्रीय मामलों में परिवर्तनीयता की एक हद तक पता चला रहा।

पश्चिमी गुट की तरफ इस प्रारम्भिक झुकाव के कुछ विशेष कारण थे—
 उदाहरणार्थ मुरक्षा के मामले में भारत उस समय तक पूर्णतः पश्चिमी
 गुट पर आधारित था, भारत के शिक्षित वर्ग पर पश्चात्प देशों का पर्याप्त
 प्रभाव छाया हुआ था और सर्वोपरि आर्थिक दृष्टि से हमारा देश पश्चिमी
 गुट पर बहुत अधिक आश्रित था। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद कुछ काल तक
 भारत का व्यापारिक सम्बन्ध केवल पश्चिमी राष्ट्रों से था और देश के आर्थिक
 पुनर्निर्माण के लिए सहायता मुख्यतः ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से ही
 प्राप्त हो सकती थी। अतः स्वाभाविक था कि इन परिस्थितियों में भारत
 असलगन्ता की नीति के सही रास्ते पर चलते हुए भी एकदम निष्पक्ष नहीं
 रह सका। उदाहरणों द्वारा इस बात को मली प्रकार समझा जा सकता है।
 सर्वप्रथम पूर्वी जर्मनी के प्रति भारत की नीति एकदम निष्पक्ष नहीं रही।
 विभाजित जर्मनी में एक को (पश्चिमी जर्मनी को), जो पश्चिमी गुट से सम्बद्ध
 था, कूटनीतिक मान्यता प्रदान की गई जबकि दूसरे (पूर्व जर्मनी) को यह
 मान्यता नहीं दी गई। भारत का यह तर्क कोई विशेष प्रबल नहीं था कि
 उसने पूर्वी जर्मनी को इसलिए मान्यता नहीं दी है कि ऐसा करना जर्मनी के
 विभाजन को मान लेना होगा। इसी तरह का थोड़ा बहुत पक्षपातपूर्ण रुख
 कोरिया युद्ध के प्रारम्भ में रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी
 राष्ट्रों की तरह भारत ने भी एकदम के शिक्षक उत्तरी कोरिया को आनामक
 घोषित कर दिया जबकि वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिमी देश आज तक भी
 अपन कथन के समर्थन में पूर्णतया विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके
 हैं। यह सम्भावना आज भी वर्तमान है कि स्वयं दक्षिणी कोरिया ने ही
 उत्तरी कोरिया पर आक्रमण किया हो। इस विषय में श्री कश्नाकर गुप्त
 का लिखना है—भारत का निर्णय श्री कोण्डापी (Kondapi) की रिपोर्ट
 पर आधारित था और यह रिपोर्ट उसके व्यक्तिगत विचारों से अत्यधिक
 प्रभावित थी।

(ii) सन् १९५० से १९५७ के बीच—१९५० से १९५७ के काल
 में सोवियत संघ के प्रति भारत के रुख में कुछ परिवर्तन हुआ। इसके कुछ
 विशेष कारण थे। प्रथम तो १९५३ में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत
 व्यवस्था में कुछ उदार तत्वों का समावेश हुआ। दूसरे, सामरिक दृष्टिकोण
 से भी सोवियत संघ अधिक सक्रियशाली बना और उसने अणु राष्ट्र होने का
 गौरव प्राप्त कर लिया। तीसरे, अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों में कुछ
 कटुता आन लगी क्योंकि १९५४ में अमेरिका और पाकिस्तान के मध्य एक
 सैनिक सन्धि हुई जिसके अन्तर्गत, भारत के सीमा विरोध के वाजजूद, अमेरिका
 ने पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर सहायता देने का निर्णय किया। फिर

गोवा की समस्या के प्रति अमेरिकन रक्त ने भी भारतीय जनमत को अमेरिका के विरुद्ध विस्तृत कर दिया। अमेरिका के विदेश मन्त्रि जान फोस्टर डेलैस ने सार्वजनिक तौर पर गोवा में पुर्तगाल का समर्थन किया। इन परिस्थितियों में यह भारतीय विदेश नीति स्वभावतः सोवियत संघ के प्रति, जिन्होंने भारतीय रक्त का हमेशा समर्थन किया, कुछ तदार एवं मैत्रीपूर्ण बनी। इन दोनों देशों के बीच इस बड़ती हुई मित्रता को पण्डित नेहरू और श्री स्ट्रुश्चेव के भ्रमणों ने भी अधिक मजबूत कर दिया। सोवियत संघ के साथ केवल राजनीतिक सम्बन्ध ही प्रगाढ़ नहीं हुए बल्कि व्यापारिक सम्बन्ध में भी काफी वृद्धि हुई और भारत को उससे पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने लगी। इस काल में ही दो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएँ घटी—स्वेज पर ब्रिटेन और फ्रांस का आक्रमण तथा हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। स्वेज पर से पश्चिमी राष्ट्रों के आक्रमण को दूर करने और फिर से आजातता फौजों को हटाने के मामले में भारत ने सोवियत संघ के साथ पूर्ण सहयोग किया। हमरी की समस्या पर भी भारत की नीति प्रारम्भ में सोवियत संघ का समर्थन करती रही।

(iii) सन् १९५७ से १९६६ के अन्त तक—१९५७ में द्वितीय आम निर्वाचन हुए और इसके बाद से ही भारत की नीति पुनः पश्चिमी गुटों की ओर कुछ अधिक झुक गई। इसके भी कुछ कारण थे। प्रथम तो निर्वाचकों ने यह प्रकट कर दिया कि भारत में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरे १९५७ के गम्भीर आर्थिक संकट ने, देश में स्वायत्तता और विदेशी मुद्रा की कमी ने तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भावी अमफलता ने भारत को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह असह्यता की नीति पर चलते हुए भी, यथासम्भव पश्चिमी गुट के साथ अपना मेलजाल बढाये। स्वयं कांग्रेस पार्टी के अन्दर दक्षिण पन्थियों का प्रभाव बढ़ा और नेहरू मन्त्रिमण्डल में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ जिनकी सहानुभूति अमेरिकन गुट के प्रति अधिक थी। भारत की इस नीति में इस परिवर्तन का पहिले स्पष्ट मकेत हंगरी की समस्या में भारतीय रक्त के बदलने से मिला; जहाँ शुरू में इस बारे में भारत ने सोवियत संघ का समर्थन किया था वहाँ बाद में वह अपनी पूर्ण स्थिति से हट कर सोवियत संघ का विरोध करने लगा। अब पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया में पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध भी भारत बहुत बन्द खदान से करने लगा। विपत्तनाम संकट में भारत की अदृष्ट दुःखमुक्त नीति भी परिस्थितियों का परिणाम बनी जा सकती है।

नवम्बर १९६२ में चीन द्वारा भारत पर विशाल पैमाने पर आक्रमण किये जाने पर असह्यता की नीति की अग्नि परीक्षा हुई। अधिकांश क्षेत्रों

से यह मांग की जान लगी कि असह्यता की नीति पूर्णतः असफल हो चुकी है, अतः देश के हित में इसका जल्दी से जल्दी परिवर्तन होना चाहिये, लेकिन राष्ट्र के नाम अपने रेडियो ब्राडकास्ट में श्री नेहरू ने स्पष्ट घोषणा की कि भारत अपनी असह्यता की नीति का अनुसरण करता रहेगा। चीन के आक्रमिक और विनाशकारी आक्रमण के कारण भारत को कुछ गम्भीर सैनिक पराजयों का सामना करना पड़ा और भारत सरकार की अपील पर अमेरिका व ब्रिटन से सहायताएं बहुत बड़ी मात्रा में संस्थाप्य भारत पहुँच। इस अवसर पर विरोधियों को असह्यता की नीति की आलोचना करने का और उस व्यर्थे दान का एक और अवसर मिला। यह कहा जाने लगा कि जब सम्पूर्ण विश्व ही दो विरोधी गुटों में विभक्त है तो भारत द्वारा असह्यता की नीति का अवलम्बन करना पूर्णतः अव्यावहारिक है। भारत का गुटों में से—साम्यवादी गुट के प्रमुख सदस्य चीन के साथ युद्धरत है और उसका सामना करने के लिये अमेरिकन गुट द्वारा सैनिक सहायता ले रहा है। अब इन परिस्थितियों में असह्यता की नीति को कोई बका रहा है और समय आ गया है कि भारत को अब अपनी स्थिति का पुनर्निर्धारण स्पष्ट दिशा में कर लेना चाहिये।

यद्यपि स्वयं पण्डित नेहरू का चीनी आक्रमण से गहरा आघात पहुँचा था, किन्तु फिर भी वे विरोधियों और आलोचकों के तर्कों के सामने परास्त नहीं हुए और उन्होंने यह मानना गम्भीर कर दिया कि असह्यता की नीति ग्राह्य है अथवा दम के लिये अहितकारी है। उन्होंने यहो कहा कि भारत को यह नीति सर्वोत्तम है तथा वे उसका अनुसरण करते रहेंगे। श्री नेहरू का प्रवल तर्क यह था कि आक्रमणकारी का मुकाबला करने के लिये भारत ने जो भी संस्थाप्य की सहायता ली है, उसके साथ किसी प्रकार की राजनीतिक या अन्य दान नहीं लगी है। किन्तु भा अतः सहायता को लेने का अनिष्टाय असह्यता की नीति से दूर हटना नहीं कहा जा सकता। असह्यता की नीति के आलोचकों को इस नीति के समर्थकों ने यह करार देना दिया कि यदि इस नीति का परिष्कार कर दिया गया तो भारत, चीन-सोवियत-मध्यस्थ मुक्त का एक अंग बन जाएगा और तब भारत चीन विवाद १०० वर्षों में भी हल नहीं हो सकेगा। इसके अनिश्चित इतिहास बताता है कि गुटों की नीति कभी भी सही रूप में फलदायक नहीं हो सकी है। अमेरिका के समर्थन के बावजूद भी तो कारिया और जर्मनी का एकीकरण हो सका है और न पाकिस्तान को काश्मीर मिल सका है। इसलिये यह असाध्य निराश्रुति होगी कि यदि भारत पाश्चात्य राष्ट्रों के गुट में या

साम्प्रदायी गुट में मिल गया तो इसे उसके खोये हुए प्रान्त वापस मिल जायेंगे ।

भारत सरकार की ओर से यह एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि देश अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा परन्तु असलमनता की नीति का परित्याग नहीं करेगा । भारत चीन समर्थन के बाद सितम्बर १९६५ में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में असलमनता की नीति की शक्ति को एक बार फिर सही सिद्ध कर दिया गया । पाकिस्तान, सीटों और सेंटों जैसे सैनिकी शक्ति, गुटों का सदस्य—होने पर—भी किसी—से—नोई—प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त नहीं कर सका । टर्की और ईरान ने उसे सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया भी तो अन्य राज्यों के विरोध, जिसमें पश्चिमी राज्य भी सम्मिलित थे, के कारण पाकिस्तान की मदद पर आये नहीं । इस युद्ध में पाक दृष्टिकोण से यह सिद्ध हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गुटों में सम्मिलित होने की नीति गलत है । बात यही तक सीमित नहीं रही । पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक समुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिये और यह घोषणा की कि जब तक दोनों पक्ष युद्ध बन्द नहीं कर देंगे तब तक उन्हें किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता नहीं दी जाएगी । स्पष्ट ही अमेरिका ने अपनी इस घोषणा द्वारा एक साथी राज्य और असलमन राज्य को एक ही कोटि में रखा । जब गुटों में सम्मिलित होने से पाकिस्तान को भी लाभ नहीं पहुँच सका तो फिर भारत को लाभ पहुँचने की क्या आशा की जा सकती थी । वास्तव में देखा जाए तो यह असलमनता की नीति का ही परिणाम था कि सकट की अवस्था में भारत को अनेक क्षेत्रों से पूरा समर्थन मिला और युद्ध के समय उसकी कूटनीतिक स्थिति किसी तरह कमजोर नहीं हुई । सुरक्षा परिषद में युद्ध पर बहस के दौरान भी सोवियत संघ द्वारा उसे पर्याप्त समर्थन दिया गया । भारत पाक युद्ध ने असलमनता की नीति की श्रेष्ठता को फिर सिद्ध कर दिया ।

नेहरू की मृत्यु के बाद असलमनता की नीति को नेहरू युग से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई । साम्प्रदायी जगत और पश्चिमी सत्तार दोनों ही भारत के विचारों की ओर उसके असलमनता की नीति की बद्ध करते रहे । २७ मई, १९६४ को उनकी मृत्यु के उपरान्त यह आश्चर्य व्यक्त की जाने लगी कि भारत अब असलमनता की नीति का अवलम्बन सम्भव नहीं कर पायेगा । किन्तु उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय लाल-बहादुर शास्त्री ने भी स्पष्ट शब्दों में बतला दिया कि भारत के हक में असलमनता की नीति सर्वोत्तम है और वह उसका किसी भी दशा में परित्याग नहीं करेगा । भारत पाक युद्ध के समय और बाद की घटनाओं ने इस मत की पुष्टि कर दी । भारत

की विदेश नीति का मूल्यांकन करते समय इस पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है।

जनवरी, १९६६ में श्री शास्त्री की मृत्यु के बाद जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी तो उन्होंने भी यह घोषणा की कि भारत हर सूरत में असंलग्नता की नीति का अनुसरण करेगा। अभी तक इन्दिरा प्रशासन ने इस नीति का पालन किया है। विभिन्न दवावों के बावजूद भी इन्दिरा-सरकार इस या उस गुट की ओर नहीं झुकी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने समय-समय पर पश्चिमी राष्ट्रों की आलोचना की है और सोवियत रूस के पाकिस्तान के प्रति रुढ़े पर जिन स्पष्ट शब्दों में भारत की नाराजगी प्रकट की है उनमें यह स्पष्ट है कि भारत किसी भी एक गुट से वध कर अपने स्वतन्त्र विचारों को बाध नहीं सनता। शास्त्री और इन्दिरा सरकार ने भारत की विदेशी नीति को असंलग्नता की नीति पर मजबूत प्रकार चलाते हुए भी उसे अधिक यथार्थवादी बनाया है। आज विदेश नीति के क्षेत्र में पहले से अधिक यथार्थता और स्पष्टता दिखाई देती है। अमेरिका की नाराजगी के बावजूद वियतनाम में भारत ने अपनी पहुँचे हो की नीति जारी रखी है और चेकोस्लोवाकिया की घटना पर भारत सभी कार्यवाही के विरुद्ध अपना महाराज्य प्रकट करने से नहीं चूका है। पाकिस्तान को सत्ताशून्य देने के प्रश्न पर भारत मुझे शब्दों में अपना धर्म प्रकट कर चुका है और यह सकेन दे चुका है कि यह कार्यवाही भारतीय हितों के लिए मातृ है।

असंलग्नता के बदलते हुए रूप

(Changing Patterns of Non-alignment)

प्रायः यह देखा गया है कि सिद्धान्त व्यवहार में परिणत होने समय कुछ भिन्न स्वरूप धारण कर लेता है। आज की तेजी से बदलती जटिल परिस्थितियों में व्यावहारिक रूप से असंलग्नता का वह स्वरूप नहीं रहा है जो हम सिद्धान्त रूप में पढ़ते या सुनते हैं। विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक दवावों ने अनेक क्षणकालिक असंलग्न राष्ट्रों की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से गुट-विशेष के साथ बाध दिया है या उनकी नीतियाँ उस पक्ष में झुक गई हैं। ऐसी प्रवृत्तियों और गतिविधियों को खोज निकालना कठिन नहीं है जो इस मत को बहुत कुछ पुष्ट करती हैं कि ये 'असंलग्न' (Non-aligned) राष्ट्र वास्तव में 'संलग्न' (Aligned) होते जा रहे हैं।

हम सर्वप्रथम मयुक्त अरब गणराज्य व सीरिया आदि अरब अरब राष्ट्रों को ले सकते हैं जो अपने को असंलग्नता की नीति के प्रति निष्ठावान मानते हैं और असंलग्न राष्ट्रों की पंक्ति में बंटे हैं। लेकिन 'व्यवहारतः' यह छिपा

नहीं है कि पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा समर्थित इजरायल के हाथों गम्भीर अपमान-जनक पराजयों ने और इजरायल की निरन्तर बढ़ती हुई सैन्य क्षमता ने उन्हें विवश कर दिया है कि वे अपने सहायक सोवियत रूस के पक्ष में श्रुत जाय और उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त करें। फिर भी इस खतरे के प्रति ये राष्ट्र सचेत हैं कि आर्थिक व सैनिक सहायता के माध्यम से कहीं सोवियत संघ इस क्षेत्र को 'लाल' न बनादे। कहने का आशय है कि इस क्षेत्र में एक प्रकार से 'सचेत व सावधान' गुटबन्दी का अखाड़ा है।

भारत के सम्बन्ध में भी, जो असलग्न राष्ट्रों का विरोध है, आलोचकों का कहना है कि इसकी विदेश नीति को स्वतन्त्र व असलग्न कहना एक भ्रान्ति है। महासन्धियों के संपर्क में प्रारम्भ में भारत सरकार, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर झुकती रही तो बाद में सोवियत रूस के पक्ष में। अरब-इजरायल सम्बन्धों के प्रति भी पूरी तरह अरबों का एकतरफा पक्ष लेकर भारत ने असलग्नता की नीति के प्रति अपने विश्वास को प्रकट ही पहुँचाया है। यहाँ हमारा लक्ष्य भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन करना नहीं है, तपानि यह अवश्य कहा जा सकता है कि असमंजस में पड़ कर भारत की विदेश नीति निरपेक्ष रहने से कभी-कभी विपत्ति उत्पन्न हो गई लेकिन अत्यन्तता और मन्देह का कोहरा मिटते ही वह सही मार्ग पर आ गई। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का मूल लक्ष्य अपनी सुरक्षा, समृद्धि और स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए देश के हितों की अभिवृद्धि करना होता है और इसी लक्ष्य के कुछ अवसरों पर कूटनीति का आश्रय लेते हुए कठिन ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनसे लोगों को यह भ्रम पैदा हो सकता है कि विदेश नीति अपनी दिशा बदल रही है। भारत की असलग्नता की नीति कठिन अवसरों पर इसी प्रकार के भ्रम का शिकार बनी है। इसके अतिरिक्त यदि हम किसी राष्ट्र से अत्यंत आर्थिक व सैनिक सहायता लेते हैं तो हमारे असलग्नता की नीति सन्निहित नहीं होती।

वस्तु स्थिति यह है कि 'असलग्नता' का कोई निश्चित मापदण्ड नहीं है और आज के पटिल अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखते हुए यह कहना कठिन है कि कौन राष्ट्र निश्चित रूप से किस सीमा तक असलग्न है। असलग्नता अपने आदर्श रूप में सम्भवतः कहीं भी विद्यमान नहीं है और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते हुए मोहरे भविष्य में असलग्नता की नीति को नहीं बरक सफल व प्रभावी होने देंगे—यह नहीं कहा जा सकता।

चीन और सोवियत रूस का संघर्ष

(SINO SOVIET CONFLICT)

सोवियत रूस और चीन संसार के दो महान् शक्तिशाली देश हैं जिनका पारस्परिक सम्बन्ध विश्व राजनीति को बहुत गहरे रूप में प्रभावित करने की क्षमता रखता है। साम्यवादी जगत के इन दो महान् राष्ट्रों में प्रारम्भ में बड़े मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे लेकिन शीत शीत प्रतिपक्षीय द्वान्द्विक और राजनीतिक कारणों से दोनों के मध्य मन-मुटाव बढ़ते गये और आज इनका पारस्परिक सम्बन्ध अथवा मन मुटाव विश्व राजनीति के लिए गहरे अध्ययन और सूत्र की सामग्री बना हुआ है। हमारे लिए यह अपेक्षित होगा कि हम इन दोनों महान् देशों के पहले के मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सम्बन्धों को जान लें और तब यह देखें कि दोनों के वर्तमान संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है और किन किन समस्याओं पर दोनों के मध्य खींचतान या मन मुटाव है।

चीन में लम्बे गृह युद्ध के बाद १ अक्टूबर, १९४९ को वर्तमान साम्यवादी चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। कम्युनिस्टों की राष्ट्रवादी सरकार ने भागकर फारमोसा में शरण ली। आज भी इन दोनों चीनों—राष्ट्रवादी और साम्यवादी चीन का अस्तित्व है।

साम्यवादी चीन की स्थापना के तुरन्त बाद सोवियत रूस के साथ उसकी मैत्री सेन्ती में फटती फूटती गयी। माओत्सेतुंग ने अपने महान् जाति भाई रूस की यात्रा की और २४ फरवरी, १९५० को दोनों देशों के मध्य तीन संधियाँ हुई—(i) ३० वर्ष के लिए मैत्री और पारस्परिक संधि, (ii) चांग-शुंग रेलवे, पाई आंगर और दान्दरन से सम्बद्ध संधि (iii) जंग सम्बन्धी

सन्धि। प्रथम संधि के द्वारा यह निश्चय किया गया कि आक्रमण की स्थिति में दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। द्वितीय सन्धि द्वारा यह निश्चय हुआ कि सोवियत संघ चांग-चुंग रेलवे को चीन को सौंप देगा एवं पोर्ट आर्थर भी चीन को लौटा दिया जाएगा। तृतीय संधि के द्वारा रूस ने चीन को विशाल मात्रा में ऋण देना स्वीकार किया।

उपरोक्त सन्धियों के सम्पन्न हो जाने के उपरान्त सोवियत रूस और चीन के सम्बन्ध कुछ वर्ष तक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहे। सितम्बर १९५२ में चांग-चुंग रेलवे चीन को लौटा दी गयी। १९५५ में पोर्ट आर्थर चीन को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस अवधि में सोवियत संघ द्वारा चीन को दी जाने वाली वित्तीय, वाणिज्यिक और प्राविधिक सहायता में भी निरन्तर वृद्धि होती गयी। चीन का लगभग ७० प्रतिशत व्यापार रूस के साथ होने लगा जिसमें १९५० के बाद निरन्तर वृद्धि होती चली गई। १९५४ में ही रूस ने चीन को प्रमुख उद्योगों में भी सहायता देना स्वीकार किया परन्तु साथ ही यह निर्णय भी हुआ कि चीन द्वारा अणु-परीक्षण रस की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। इसके अनिश्चित चीनी-रूसी मैत्री संगठन स्थापित किये गये। रूसी साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद करवाना भी आरम्भ हुआ।

राजनीतिक क्षेत्र में भी दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे के सारकारी समय तक सहयोग से काम किया। सोवियत संघ ने चीन को मयूकन राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के लिए निरन्तर प्रयास किया। १९५४-५५ में दोनों ही देशों ने पश्चिमी शक्तियों, विशेषकर अमेरिका द्वारा निर्मित प्रादेशिक सैनिक संगठनों की कटुतम आलोचना की। १९५६-५७ में दोनों ने मिस्र पर ब्रिटेन व फ्रांस के आक्रमण की निन्दा की। हंगरी और पोलैंड में जब दक्षिण पक्षी दंगे हुए तब भी दोनों देशों ने निरन्तर रूप से विचार विमर्श होने रहे। १९५८ में टोटी के समोपनवाद की कटु आलोचना भी दोनों ही देशों के द्वारा की गई। सोवियत संघ की नाति ही अन्य साम्राजवादी देशों के साथ चीन के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्पन्न रहे।

परन्तु चीन और साम्राजवादी देशों के अन्य देश-विशेषकर रूस के पारस्परिक सम्बन्ध अधिक समय तक मैत्रीपूर्ण नहीं रह सके। वास्तव में इनके संबंधों में तनाव का बीजारोपण तो तब ही हो गया जब १९५४ में सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टियों को २०वाँ कांग्रेस की बैठक सम्पन्न हुई। इस कांग्रेस में भाषण करते हुए श्री खुरचेव ने दो बातें ऐसी कही थी जो कठमन्के मार्क्सवादियों की समझ से परे थी और जिनसे साम्यवादी जगत में वैज्ञानिक तथ्य

को अकारण ही जन्म दे दिया। अभी तक समूचा साम्यवादी आन्दोलन यह मानता आया था कि जब तक पूँजीवाद व्यवस्था का अस्तित्व रहेगा तब तक संसार में युद्धों की अनिवार्यता भी बनी रहेगी। साम्यवादी आन्दोलन की यह भी मान्यता थी कि विभिन्न देशों में समाजवाद की स्थापना नाति के द्वारा ही संभव हो सकती है। परन्तु श्री लुश्चेव ने परम्परागत इन दोनों मान्यताओं की उपेक्षा की और आणविक आयुधों के वर्तमान युग के लिए इन्हें असंगत बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सैमा आज इतना अक्षिणशाली है कि किसी भी गैर-साम्यवादी देश को उस दर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं हो सकता, अतः यह कहना अनुचित है कि युद्ध अवश्यमावी है। इसी तरह फ्रांसि रे ब्लिवार्डर के सम्बन्ध में श्री लुश्चेव ने कहा कि आज संसार के सभी देशों में जन-आन्दोलन इतने गहन हो चुके हैं कि कुछ देशों में समाजवाद की स्थापना हिंसात्मक प्राप्ति द्वारा नहीं बल्कि विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा हो और संभवतः संसदीय तरीके से ही सम्पन्न हो सकती है। श्री लुश्चेव की ये दोनों स्थापनाएँ चीनी नेताओं के गले नहीं उतर सकी। कम-स्वरूप चीनी साम्यवादी पार्टी ने सोवियत नेताओं विशेषकर श्री लुश्चेव पर सुनो-सुनानी होने का आरोप लगाया और उनको बटु आलोचना करना शुरू कर दिया।

१ सन् १९५६ के बाद दोनों देशों के बीच शान्ति के लिए संपर्क छिड़ जाने के कारण दोनों के राष्ट्रीय हितों में भी क्लेश पैदा हो गया। साथ ही दोनों का मैकमनिक संपर्क भी पूर्वापेक्षा तीव्रतर हुआ। श्री लुश्चेव द्वारा मास्को में रूसी साम्यवादी दल की सन् १९५३ में आयोजित कांग्रेस और १९६१ की २२वीं कांग्रेस में भी स्टालिन की तीव्र भर्त्सना एवं निन्दा की गई। श्री लुश्चेव के इस स्टालिन विरोधी अभियान को विग्टालिनिकरण की संज्ञा दी गई। पश्चिम की रूस के नये नेताओं का यह व्यवहार बड़ा नागावार गुजरा। इसी तरह जब मास्को युगोस्लाविया को साम्यवादी भ्रातृत्व में वापिस बुलाने के लिए तत्पर हुआ तो चीन को बड़ा बुरा लगा। चीनी विदेश मंत्री श्री चैन यी ने युगोस्लाव पुनर्विचारवाद पर तीव्र आक्रमण आरम्भ कर दिया—तीखा इसलिए क्योंकि चीनियों की दृष्टि में युगोस्लाव राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने अमेरिकावासियों के साथ सहअस्तित्व का इरादा जाहिर करके घोर अपराध किया था।

सोवियत रूस और चीन के मध्य मतभेदों की खाई निरन्तर चौड़ी होती गई। सितम्बर, १९५९ में श्री लुश्चेव की अमेरिका यात्रा को चीन ने बहुत बुरा समझा इसीलिए श्री लुश्चेव को, जब उन्होंने चीन की यात्रा की, पश्चिम में कोई विशेष स्वागत प्राप्त नहीं हुआ। श्री लुश्चेव ने अपनी इस चीन यात्रा (१९५९ ई.) के दौरान रूस जान पर बण दिया कि वह साम्यवादी सिद्ध ही सशक्त क्यों न हो जाए, उन्हें पूँजीपति राष्ट्रों के विरुद्ध गठित का

प्रयोग करन से बचे रहना चाहिये। चीन के मार्क्सवादी नेताओं को श्री खुश्चेव का यह कथन 'प्रतिनिधायवादी शक्तियों की प्रगतिवादी शक्तियों पर मित्र्य के समान प्रतीत हुआ।' श्री खुश्चेव न अमेरिकन राष्ट्रपति आइजनहोवर की राजनयतिज्ञता की जो प्रशंसा की वह भी चीनवासियों के गले न उतर सकी। चीनियों को श्री खुश्चेव की अमेरिका यात्रा एक प्रकार का विश्वास-पात लगी।

चीन और रूस के सम्बन्धों में तब और भी नटुता आई जब १९५६-६० में चीन के भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद पर श्री खुश्चेव ने यह आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपने साम्यवादी लगन का सीध ही कोई शान्तिपूर्ण हल खोज लगे। श्री खुश्चेव ने चीन का कोई पुष्टरोपग न करते हुए, उनकी मित्रता को लगभग वैसा ही दर्जा दिया जो भारत को। माओ, चाऊ और अन्य चीनी नेताओं को यह बड़ा बुरा लगा।

साम्यवादी चीन और सोवियत संघ में १९५० से विभिन्न प्रश्नों पर मैक्रानिक्त मतभेद उत्पन्न होने लगे। साम्यवादी आन्दोलन का सत्तार मर में पैलात के विषय में मतभेद प्रतीत अधिक उत्पन्न हुए। जून, १९६० में बुखारेस्ट में हुए रमानिया नवंबर दश के तृतीय सम्मेलन के अवसर पर श्री खुश्चेव ने अपने इस मत की पुन पुष्टि की कि सेनिन का 'पूजीवाद के अधीन युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत' अब लागू नहीं होना। दूसरी ओर चीनी प्रतिनिधि मण्डल के नेता ने घोषणा की कि जब तक साम्राज्यवाद विद्यमान है युद्धों का खतरा बना रहेगा इसके बाद नवम्बर, १९६० में मास्को में साम्यवादी नेताओं का जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें भी उत्ती-चीनी सिद्धान्तिक मतभेद और भी तेजी से उत्पन्न कर सामने आये। चीन रूस से इस कारण भी बहुत अधिक विड गया कि जुलाई, १९६० का रूस ने चीन की विकास योजनाओं में लगे समस्त सोवियत वैज्ञानिकों को सीा दिन का नोटिस देकर घुला दिया और यह उत्ती कर्मचारी अरब साय विरास योजनाएँ बन्द हो गईं रूस ने चीन को सामर्थ्य और भगीने आदि भजना भी बन्द कर दिया। दोनों देशों के बीच मतभेदों को यह छाई तब और भी अधिक चौड़ी हुई जब १९६१ में सोवियत साम्यवादी पार्टी का कार्यक्रम प्रकाशित हुआ जिसमें २० पय की अवधि में सोवियत संघ में साम्यवाद को स्थापना का नारा दिया गया। इस कार्यक्रम में साम्यवाद का अर्थ वस्तुओं की प्रचुरता बताई गई। चीनी साम्यवाद पार्टी का कार्यक्रम में भी हुई साम्यवाद का यह अर्थ जल्द ही आर्थिक रूप से लया। दोनों देशों के सम्बन्ध तब और भी अधिक कटु हुए जब १९६२ में सोवियत संघ ने भारत को

मित्र-विमान देने तथा उनकी बनाने के कारखानों में सहायता देने का समझौता किया। १९६२ में हा क्यूबा संकट में अपनाई गई रूसी नीति ने भी चीनियों को बहुत हलट किया। चीनी नेताओं ने आरोप लगाया कि क्यूबा के सम्बन्ध में सोवियत नीति आदि से अन्त तक गलत रही है। रूस ने पहले तो क्यूबा में अपने प्रत्येक राष्ट्र भेजे, किन्तु बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा युद्ध की धमकी देने पर उन्हें वापिस मगा लिया। चीन नेताओं ने कहा कि रूस का पहिला दावा 'दुस्साहस' का था और दूसरा कामजी शेर अमेरिकन साम्राज्यवाद के आगे 'पुणित आत्मसमर्पण' करने का। १९६२ में ही भारत पर चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में रूसी नीति ने भी चीन को असन्तुष्ट कर के अग्नि में धीका काम किया। दोनो देशों के मध्य सैद्धान्तिक मतभेदों की यह साई बढ़ती ही गई। १८ नवम्बर, १९६२ की साफिया में हुए वर्ल्डरिपन साम्यवादी दल के सम्मेलन में रूसी प्रतिनिधि ने कहा कि "राष्ट्रपूर्ण महत्प्रसित्व के अतिरिक्त किसी भी नीति को युक्तिमय नहीं माना जा सकता।" चीनी प्रतिनिधि ने सोवियत सरकार के इस दृष्टिकोण को घोर निन्दा की।

जुलाई, १९६३ में रूस और चीन की साम्यवादी पार्टियों में बातें हुईं ताकि परस्पर विचारधारा में मेलमजुदा प्राप्त किया जा सके। किन्तु मास्को में हुई यह बातें पूरी तरह असफल हो गई और दोनों ही देशों के द्वारा एक दूसरे की बटु धारा में निन्दा की गई। रूसी नेताओं ने अपना यह स्वष्ट मत प्रकट किया कि पश्चिम के साथ युद्ध होने पर मानव जाति समूह नष्ट हो जायेगी जिसमें रूसी जनता और उसकी सम्पत्ति भी सम्मिलित है, अतः ऐसे विनाशक युद्ध की बात सोचना सर्वनाशपूर्ण होगा। किन्तु इसके विपरीत चीन नेताओं का यह विचार बना रहा कि साम्राज्यवाद के सम्पूर्ण विनाश के लिए युद्ध सहाय्य है। उनकी (रूसी नेताओं की) विचार प्रणाली कुछ इस प्रकार की थी कि परमाण्विक युद्ध से लड़ा गया तत्पश्चात् महायुद्ध अन्तिम रूप में अमेरिका और रूस को ही समाप्त करेगा, चीन को नहीं। अपनी विशाल सख्या व बल पर, महायुद्ध के बाद भी, चीन संसार की महानतम शक्ति बने रह जाएगा और तब संसार में साम्यवादी शान्ति का प्रदत्त सुगम हो जाएगा।

२१ जुलाई १९६३ का मास्को में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने एक शिष्टाचार परीक्षण निराप मन्त्रि पर हस्ताक्षर कर के आकाश, बाह्य अन्तरिक्ष और पन के नीचे अतु परिणाम पर रोक लगा दी। किन्तु साम्यवादी चीन ने न केवल इस मन्त्रि का बहिष्कार हो किया बल्कि अपने इस कार्य को उचित ठहरात हुए सोवियत संघ पर यह आरोप लगाया कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मित्रवत आगविक शक्तों के क्षेत्रों में अतः एकाधिकार कायम रखना चाहता है।

१९६३ तक दोनों देशों के बीच कटना को एक गहरी और लगभग स्थायी खाई बन गई। फिर भी रूस ने जहाँ संघर्ष से काम लिया वहाँ चीन सोवियत रूस के राजनीतिक व्यवहार, विचारधारा व अन्य नीतियों का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कटुतम रूप में विरोध करने लगा। फलस्वरूप रूस को भी अपने बचाव के लिए खुल कर आगे आना पड़ा और इस तरह इन दोनों महारथियों का धार्म्युद्ध सम्पूर्ण साम्यवादी जगत की एकता को गहरा आघात पहुँचाने लगा।

१९६४-६५ के वर्षों में भी रूस और चीन के सम्बन्धों में और विगाड़ हुए। चीन रूस को पाश्चात्य देशों का अनुचर बताने लगा और उसने यह आरोप लगाया कि वह (रूस) अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर विश्व साम्यवादी आन्दोलन की पीठ में छुरा भोकना चाहता है। अक्टूबर १९६४ में श्री ख़ुश्चेव को अपदस्थ कर दिये जाने पर पकिंग में बड़ी खुशियाँ मनाई गई और यह आशा प्रकट की गई कि रूस के नये नेता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को त्याग कर विश्व साम्यवादी आन्दोलन को बलपूर्वक आगे बढ़ायेंगे। परन्तु जब रूस के नये प्रयागमन्त्री श्री कोसीगिन और राष्ट्रपति ब्रेज्नेव ने पाश्चात्य देशों के साथ सहअस्तित्व की नीति का परित्याग नहीं किया तथा उसके साथ अपने विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के भावों पर चलने का निश्चय किया तो चीनी नेताओं को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने रूस के नये नेतृत्व पर भी उसी प्रकार के लाछन लगाये जिस प्रकार के वे श्री ख़ुश्चेव पर लगाते रहे थे।

रूस और चीन की सनातनी निरन्तर बढ़ती गई। ख़ुश्चेव के पतन के बाद रूस बोरोसेविक शांति के ४७वें वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-साई आरके गये। उन्होंने अपने भाषण में सोवियत नेताओं से अपील की कि अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन की एकता के प्रयासों में रूस को चीन का साथ देना चाहिए। चाऊ-एन-साई ने सोवियत नेताओं को चेतावनी भी दी कि उन्हें पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी चालों से सावधान रहना चाहिए। सोवियत नेताओं ने अपने जवाब में स्पष्ट कर दिया कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में सोवियत रूस का विश्वास है और वह इस सिद्धांत का परित्याग नहीं करेगा। चीनियों की कटनीतिक धार्ता असफल हो गई और चाऊ-एन-साई को निराश होकर पकिंग लौटना पड़ा।

अगले वर्ष अक्टूबर, १९६५ में सोवियत संघ के प्रति वार्षिकोत्सव के समय चीन ने सोवियत संघ के विरुद्ध अजरदस्त प्रचार आन्दोलन शुरू कर दिया। रूस में सिसाक बनेव आरोप लगाये गये। यह भी कहा गया कि

अमेरिका और रूस अन्य देशों को सैनिक दृष्टि से कमजोर बना कर अपना प्रभुत्व पायम करना चाहते हैं।

सीमा संधर्ष—सोवियत सभ और साम्यवादी चीन के सैद्धांतिक मतभेद उग्रतर होने गये। दोनों देशों के बीच इसना मत मुटाव पैदा हो गया कि दोनों के बीच सीमा विवाद ने सीमा संधर्षों का रूप ले लिया। २ मार्च, १९६६ को पूर्वी एशिया में उसूरी नदी के टापू दमिस्क को लेकर दोनों देशों में सीधी सैनिक भिड़न्त हो गई। १५ मार्च को दोनों पक्षों में उसी टापू को लेकर फिर एक सैनिक मुठ-भेड़ हो गई। रूसी सूत्रों के अनुसार पहली झड़प में चीन के लगभग ३०० सैनिक मारे गये जब कि रूसी पक्ष के ३१ सैनिक मरे और १४ घायल हुए। रूस का एक कर्नल भी चीनी गोलीबारी का शिकार बना।

रूस और चीन के बीच होने वाले ये सशस्त्र सीमा संधर्ष इस बात का स्पष्ट सबूत करते हैं कि दोनों के बीच न केवल गहरे सैद्धांतिक मतभेद ही हैं बल्कि गहरे सीमा विवाद भी हैं। दोनों देशों के बीच सैनिक भिड़न्त केवल एक निजन छोटे से द्वीप के लिए नहीं हैं बल्कि मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के विस्तृत भाग के लिए है। रूस और चीन की सामान्य सीमा लगभग ४५०० मील लम्बी है। इस सीमा का अधिकांश भाग मध्य एशिया के ऊँचे पहाड़ों पर मरुस्थलों से गुजरता है। रूसी क्षेत्र में कजाखस्तान, किरगिज और उज्बेक गणराज्य हैं तो चीनी इलाकों में सिक्किम का प्रान्त है। पूर्वी एशिया में दोनों की सीमाओं का निर्माण जापूर और उसरी सहायक नदी उसूरी करती है।

रूस और चीन की वर्तमान सीमाओं का निर्धारण रूस के जारों और चीन के मच् सल्ताटी के बीच हुई सन्धियों द्वारा हुआ था। ये सन्धियाँ १८५८ और १८६० में की गई थी। इन सन्धियों के फलस्वरूप चीन को लगभग ५ लाख वर्ग मील का विस्तृत क्षेत्रफल रूस की देना पड़ा था। साम्यवादी चीन का कहना है कि रूस ने चीन की सत्ताहीन निर्वृत्ता का लाभ उठाते हुए उस पर जबरदस्ती ऐसी सन्धियाँ लाद दी थी जिनके अनुसार उसे अपना विशाल भू-खण्ड देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। दूसरी ओर रूस चीन के दावों को दखौशान करता है। सन् १९५७ में खुशेव ने और बाद में वर्तमान रूसी प्रधान मंत्री ने चीनी दावों को टुकरा दिये हैं। रूस का कहना है कि पुरानी किताबों या पुरानों की हड्डियों के आधार पर इस प्रकार के दावों को नहीं माना जा सकता।

रूस ने कई बार सीमा के प्रश्नों को वार्ता द्वारा दानिपूर्वक हल करने के प्रस्ताव रखे हैं। हाल ही में ३ मई, १९६६ को मास्का द्वारा यह घोषण

की गई थी कि रूस नदियों के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नदी सीमा आयोग बुलाने को तैयार है। लेकिन चीन का रुख बढ़ते वाजी और दबाव का है। चीनी सीमा प्रदेश में रूस का कोई दावा नहीं है। दावा स्वयं चीन का है अतः रूस के अनुसार, भड़काने वाली धाँसेबाहियाँ चीन ही कर रहा है। पहले तिब्बत और तब भारत के प्रति चीन का जिस प्रकार का रवैया रहा है और भारत के साथ चीन ने जोर जबरदस्ती का जो रुख अपनाया है उससे चीन के सीमा दावों के सम्बन्ध में विश्वास न किये जाने की बात स्वभावतः पैदा हो जाती है। फरवरी १९७० तक समय समय पर चीनी सोवियन प्रतिनिधियों की जो मुलाकातें हुई हैं, उनका इस दिशा में कोई उत्साहजनक फल नहीं निकला है।

अनेक राजनीतिक समीक्षकों का यह मत है कि सोवियत संघ से छोटी-मोटी सड़कें करके चीन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। वह पाकिस्तान और उत्तरी वियतनाम को बताना चाहता है कि चीन एक शक्तिशाली देश है और वे अपने हितों की रक्षा के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं। रूस चीन सोझा संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करेगा, लेकिन इस बात में पूरा सन्देह है कि रूस चीन के साथ बड़े पैमाने पर टकराने का साहस कर सकेगा। रूस की अपार सैनिक शक्ति के सामने चीन अपनी निर्बलता को खुद भी अच्छी तरह समझता है।

चीन-सोवियत संघर्ष के कारण

(Causes of Sino-Soviet Conflict)

रूस और चीन दोनों देशों के संघर्ष के सम्बन्ध में विचारकों के अलग-अलग मत हैं। कुछ लोग इसे दृष्टि और पश्चिमी राष्ट्रों की मुलावे में खाने वाला मानते हैं तो कुछ लोग इसे सैद्धांतिक मतभेद न मानकर राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बताते हैं। दूसरे विचारकों का मत है कि संघर्ष का कारण मुख्यतः दोनों देशों का आर्थिक और सामाजिक विकास तथा विश्व राजनीति में दोनों देशों का स्थान है। रोबर्ट ए० स्केलपिनो के मतानुसार इन दोनों महान् साम्यवादी देशों का वर्तमान संघर्ष तीन कारणों का परिणाम है—(१) सगठन, निर्णय प्रणाली और साम्यवादी गुट का नेतृत्व, (२) शान्ति-वारी तरीके तथा बीसवीं शताब्दी के मध्य की विश्व राजनीति, एवं (३) अन्तर्गुट सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता का रूप।

दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्ध में दिन प्रति दिन जो बढ़ता जा रही है, जिन प्रकार दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं और

जिस प्रकार दोनों के मध्य सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस सबसे इसी धारणा को बल मिलता है कि इन दोनों देशों के मतभेद वास्तव में उग्र और गहरे हैं तथा अपने अपने सैद्धान्तिक पक्षों की आड़ में दोनों देश साम्यवादी जगत पर अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। दोनों ही सैद्धान्तिक रूप से अपने अपने पक्ष में मार्क्स और लेनिन के मौलिक सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं और एक दूसरे पर इन सिद्धान्तों से अलग हटने का आरोप लगाते हैं। चीन का विचार है कि सोवियत रूस के वर्तमान नेता मार्क्स के मौलिक सिद्धान्तों में परिवर्तन और संशोधन करने का जघन्य कार्य कर रहे हैं जबकि माओ और उसके सहयोगी विपुल मार्क्सवादी और साम्यवाद के सुदृढ़ समर्थक हैं। दूसरी ओर रूसी नेता यह आवश्यक समझते हैं कि मार्क्सवाद की नवीन परिस्थितियों के यथार्थवादी विश्लेषण पर प्रतिष्ठित करना चाहिये। आज दोनों राष्ट्रों के मध्य सघर्ष के जो प्रधान सैद्धान्तिक और राजनीतिक कारण दृष्टिगत हो रहे हैं वे मक्षेप में ये हैं—

(१) दोनों देशों के मध्य पहला गंभीर सैद्धान्तिक सघर्ष युद्ध की अनिवार्यता पर है। लेनिन की मान्यता थी कि जब तक साम्राज्यवाद है तब तक युद्ध अनिवार्य है और केवल युद्ध से ही पूँजीवाद का विध्वंस किया जा सकता है। चीन का आरोप है कि सोवियत रूस ने लेनिन के इस सिद्धान्त को तिलाजलि दे दी है और वह युद्ध की अनिवार्यता के प्रश्न पर डगमगाने लगा है तो यह अस्तित्व की चर्चा करता है। इसके विपरीत सोवियत रूस का कहना है कि चीन आज के आणविक युग में युद्ध की अनिवार्यता का गीत गाकर पूर्ण विध्वंस को निरुद्ध खाने की बात कर रहा है। रूस का विचार है कि वर्तमान काँट का आणविक युद्ध दोनों ही पक्षों के लिये इतना प्रबल विध्वंसकारी होगा कि इसमें न केवल साम्राज्यवादी बल्कि साम्यवादी भी समाप्त हो जायेंगे। अतः आज की परिवर्तित परिस्थितियों में साम्यवाद का रस्ता व लिये पूँजीवाद के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति वांछनीय है। क्यूबा के प्रश्न पर अमेरिका की बात मानने का कारण दृष्ट करते हुए रूस के प्रधानमन्त्री श्री कुश्चेव ने कहा था कि यदि उस समय पूँजीवादी जगत के साथ सघर्ष किया जाता तो पहले ही दिन सात करोड़ व्यक्ति मर जाते। श्री कुश्चेव और उनके सहयोगी सोवियत नेताओं ने बलपूर्वक यह मन अभिप्रेषण किया कि इस प्रकार के महाविनाश के तथ्य से व्यक्त मूढ़ने वाले ही यह मानना पूर्ण युक्ति दे सकते हैं कि युद्ध समाजवाद के प्रसार में सहयोगी होगा। “मार्क्सवाद का निर्माण अगुवना के विरुद्ध न विध्वस्त भू-मण्डल पर नहीं हो सकता है। रूस के सैद्धान्तिक पक्ष “कम्मुनिस्ट” में इन मत का समर्थन करते हुए बेल्लाकोव और बुरलाखोव ने लिखा था—

“आणविक आयुद्धों का उपयोग करने वाले विद्वद् युद्ध में, संतुष्टि तब्या अर्थनिक जनता में कोई मतभेद नहीं रह जायेगा। इस युद्ध का परिणाम सम्पत्ता के प्रधान केन्द्रों और सम्पूर्ण राष्ट्रों का पूर्ण विध्वंस होगा। यह युद्ध समस्त मानव जाति के लिये महान विपत्ति लात वाला होगा, और केवल उम्मत व्यक्ति ही ऐसी विपत्ति को आमन्त्रित करने की इच्छा कर सकता है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक आणविक युद्ध अपने आप क बायों को और समाजवाद की विजय को अधिक निकट लाने में सहयोगी निम्न नहीं हो सका। इनके विपरीत इस प्रकार का युद्ध तो मानव जाति को सम्पूर्ण प्राप्ति को प्राप्तिकारी धर्मिकों क आन्दोलन के विकास को और साम्यवाद के निर्माण के कार्यों को रीसियों वर्ष पीछे षकेल देगा।”

(२) रूस और चीन के मध्य दूसरा संज्ञानितक लगडा आणविक युद्ध सम्बन्धित है। चीन आणविक क्षतरे से भयभीत होना कायरता समझता है। चीन की मान्यता है कि प्रथम महायुद्ध में रूसी क्रांति की जन्म देना था, उत्तम महायुद्ध में चीनी क्रांति की जन्म दिया और तीसरा महायुद्ध जो आणविक युद्ध होगा, सम्पूर्ण सभार से पूरबीबद का विनाश करके साम्यवाद को सक्तु बनावेगा। युद्धोन्मादी माओ और उनके साथियों का विचार है कि चीन की आणु युद्ध से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें उनके दो तर्क हैं—पहला तर्क यह है कि चीनी जनता रूस और पाश्चात्य देशों की भांति ही विनाश कारखानों वाले कुछ बड़े शहरों में केन्द्रित न होकर देशतो व ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। आणुबम सभन आबादी वाले नगरों को ही अधिक क्षति पहुँचा सकती है। दूसरा तर्क यह है कि चीन सभार की विशालतम जनसंख्या वाला देश है, अत आणविक युद्ध में चीन की सम्पूर्ण जनता नष्ट नहीं हो सकेगी। चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई के वचनानुसार “चीन की ७० करोड जनता में से ३३ करोड वष आएगी और यह आणविक युद्ध के मल्ले से एव सुन्दर समाजवादो समाज का निर्माण करेगी।” हर चीनी नेताओं का यह विचार नम की स्वीकार नहीं है। रूसी नेताओं का यह निश्चित मत है कि आणविक युद्ध से नवीन समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पूर्णतः विध्वसात्मक होगा, इसके अतिरिक्त धर्मिक जनता का सद्देश्य एतदार तरीके से माना नहीं चरन् नया सुखपूर्ण जीवन का निर्माण करना है। सोवियत रूस आणविक युद्ध को टालने में ही समाजवाद का कल्याण देखता है और इसीलिये चीन के युद्धोन्माद को अनुचित और विध्वकारी मानते हैं।

(३) रूस और चीन में तीसरा गम्भीर मतभेद प्राप्ति के सिद्धांत के बारे में है। चीनियों का लेनिन के सिद्धांतों में विश्वास है कि समाजवाद

लाने के लिये क्रान्ति अनिवार्य है तथा क्रान्ति में व सशस्त्र युद्ध में साम्यवादियों को शासन सत्ता बलपूर्वक छीन लेनी चाहिये। चीनियों का यह कहना है कि प्रत्येक तरीके से विश्व में क्रान्ति का प्रसार किया जाना चाहिये। माओ की मान्यता है कि क्रान्ति का प्रसार में चीनी अनुभव विशेष रूप से उपयोगी है और यह यह है कि सशस्त्र संघर्ष तथा छापामार युद्ध का आश्रय लेना चाहिये और बुजुर्गों वर्ग के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं बनानी चाहिये। माओ का सोवियत नेताओं पर यह आरोप है कि उन्होंने क्रान्ति के विचार को विस्मृत कर दिया है और वे क्रान्ति की अपेक्षा शांति और आर्थिक विकास को महत्व देने लगे हैं। माओ के अनुसार क्रान्ति में इस प्रकार का पन्थागत मार्क्सवाद से निनवाद को पीछे हटाना है और साम्यवादी आदर्श को मूलाना है। इसके विपरीत रुम की मान्यता है कि साम्यवाद क्रान्तिपूर्ण साधनों से भी आसता है। सोवियत नेताओं का कहना है कि बीसवीं शताब्दी के मध्य से विश्व राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन आरम्भ हो गये हैं और साम्यवाद की प्रजातन्त्रात्मक तरीकों से लिया जा सकता है। विभिन्न देशों की ससदों के राजनीतिक दलों के साथ गठबन्धन करके भी साम्यवादी शासन स्थापित किया जा सकता है, जैसा कि १९४५ में चेकोस्लावाकिया में हुआ था। रुम का मत है कि क्रान्ति केवल सशस्त्र साधनों से ही हो, यह आवश्यक नहीं है। क्रान्ति शांतिपूर्ण साधनों से भी लाई जा सकती है। मार्क्सवाद से निनवाद की सच्ची शिक्षा यह है कि साम्यवादियों को क्रान्ति लाने के लिये हिंसक और अहिंसक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग समस्त व आवश्यकतानुसार करना चाहिये। अतः आज के परिवर्तित विश्व में, जब कि सम्पूर्ण मानव जाति अणु युद्ध के कगार पर खड़ी है, क्रान्ति के अहिंसक साधनों को ही अपनाया जाना चाहिये।

(४) दोनों देशों में चीन विवाद निःशस्त्रीकरण के बारे में है। सेनिकवाद का पुजारी और युद्ध का घोर समर्थक चीन निःशस्त्रीकरण का विरोधी है। इसीलिये वह रुस द्वारा अमेरिका के साथ की गई अणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि का कटु आलोचक है। लेकिन रुस का कहना है कि अणु शस्त्रों को छोड़ एक दिन सम्पूर्ण मानव जाति को नष्ट कर देगी और साम्यवाद या गैर साम्यवाद कोई भी नहीं बच पायेगा। अतः निःशस्त्रीकरण के मार्ग पर बढ़ना आज की परिस्थितियों की मांग है।

(५) दोनों देशों के मध्य पाचवां शताब्दी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बारे में है। चीन का आरोप है कि सोवियत समाज पूँजीपति बनता जा रहा है, क्योंकि उसमें उत्तम और उच्च जीवन स्तर पर चल दिया जा रहा है। इस प्रकार वह सशस्त्र क्रान्ति का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हो सकता।

आज का रूस सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकता। चीन के आरोप से पूर्णतः असहमति प्रकट करते हुए रूस का कहना है कि नान्ति का संदेश यह नहीं है कि गेट पर पट्टी बाधना अनिवार्य है। यदि मजदूर अच्छा जीवन बिताते हैं तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे पूर्णजीवि बन जाते हैं। आखिर जीवन की दशाओं को उन्नत करना साम्यवाद का उद्देश्य है ही। चीनियों के निम्न जीवनस्तर पर ध्यान करते हुए रूसियों का कहना है कि "रूसियों का बना हुआ जूता पहिनना और एक साधारण प्याले में अत्यन्त पतला घोरवा पीना ही तो साम्यवाद नहीं है।"

(९) मास्को और पेरिस में छठा मतभेद 'व्यक्ति पूजा' का है। ख्रुश्चेव ने स्टालिन द्वारा रूसी जनता पर किये गये अत्याचारों का पर्दाफाश करते हुए बताया था कि उसे देवता तुल्य बनाने से और उसकी पूजा करने से रूस की जनता को कितनी यातनायें और हानियाँ उठानी पड़ी थी। इसीलिये ख्रुश्चेव ने व्यक्ति पूजा के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व पर बल देते हुए स्टालिन की निन्दा का अभिप्राय आरम्भ किया। रूस के वर्तमान नेता भी व्यक्ति पूजा के स्थान पर सामूहिक नेतृत्व का परिचय देते रहे हैं। चीन सोवियत रूस के इस कार्य की लज्जाजनक और अत्यन्त अनुचित बात मानता है। चीन का मत है कि स्टालिन भी माओ के साथ आराध्य देव है। चीन व्यक्ति पूजा के सिद्धान्त में आस्था रखता है और यह स्वाभाविक है क्योंकि माओ अपने भाषकों सत्तार का महान् योग्यतम, महानतम और आदर्शतम महापुरुष मानता है। आज माओ ही चीन का भगवान, उसका आराध्य देव है।

(७) मास्को से पेरिस के संघर्ष का एक बड़ा कारण यह भी है कि चीन की आन्तरिक स्थिति अस्थिर है। माओ रूसी युग की चीन में अपने विरोधियों से अविनाशिकता का संघर्ष करना पड़ रहा है। अतः वह रूस के साथ सीमा-विवाद छेड़ कर और यदा-कदा सैनिक टाठपें करके अपने देशवासियों का ध्यान इस ओर बटाना चाहता है। साम ही सोवियत विरोधी प्रचार के नाम पर उसे अपने आन्तरिक शत्रुओं का सफाया करने का अवसर भी मिला रहा है।

(८) दोनों देशों के बीच संघर्ष का सबसे बड़ा और अपारमूल्य कारण यह है कि साम्यवादी चीन साम्यवादी जगत में रूसी नेतृत्व को पुनर्जीव देना चाहता है। उसका उद्देश्य है कि भवेली रूस साम्यवादी जगत का एकमात्र नेता न रहे अल्बानिया, आदि साम्यवादी देशों को उसने अपने पक्ष में कर लिया

है। उसे साम्यवादी विश्व में फूट की दरार डालने में सफलता मिल चुकी है। सोवियत रूस उसकी इन गतिविधियों से परेशान है।

(६) चीन के सन्तुलापूर्ण रवैये को देख कर रूस इस बात से चिन्तित है कि अणुशक्ति का प्रभावी विकास कर लेने पर रूस के लिये उसकी ओर से जबरदस्त खतरा पैदा हो जायगा। अतः रूस की सुरक्षात्मक तैयारियों और सैनिक व्यूह रचना ने एक नया मोड़ ले लिया है।

इस सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि मास्को और पeking आज एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। पर साम्यवादी चरित्र के विरोधाभास की प्रुष्ट-भूमि में सोवियत रूस का विचार है यह कहना कठिन है कि दोनों के सम्बन्ध भविष्य में निश्चित रूप से क्या मोड़ लेंगे।

१८

आणविक शस्त्रों का प्रभाव, द्वि-ध्रुवीयता और बहुकेन्द्रवाद

(IMPACT OF NUCLEAR WEAPONS, BIPOLARITY
AND POLYCENTRISM)

अणु शस्त्रों का प्रभाव

(Impact of Nuclear Weapons)

द्वितीय महायुद्ध के अन्तिम चरण में अगस्त, १९४५ में समुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणु बम गिराकर सम्पूर्ण विश्व को आणविक शस्त्रों की विनाशकारी शक्ति से दहला दिया। उस समय एकमात्र समुक्त राज्य अमेरिका ही अणु शक्ति का स्वामी था। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रही। विश्व की दूसरी महा-शक्ति सोवियत रूस ने यह समझ लिया कि यदि आणविक शस्त्रों के क्षेत्र में अमेरिका ही एक छत्र स्वामी बना रहा तो उसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव को भविष्य में चुनौती देना असम्भव ही जायेगा। आणविक शक्ति से सम्पन्न अमेरिका का भय विश्व के राष्ट्रों को इतना आतंकित कर रहा होगा कि वे एक-एक सटके सूती तरह अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आते-आयेंगे। इसका ही नहीं, साम्यवाद के प्रसार का मार्ग भी बड़ा अवदल हो जायेगा।

स्वाम्याधिक या कि सखरोक्त परिस्थिति ने सोवियत रूस को विन्तित कर दिया। वह भी प्राणपन से अणु-शक्ति का स्वामी बनने की चेष्टा करने लगा और चीन ही उसने इस क्षेत्र में अमेरिका के एकाधिकार को समाप्त

कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद केवल चार वर्षों में ही उसने अणु-बम के रहस्य का पता लगा लिया, इसके बाद तो आणविक शस्त्रास्त्रों के निर्माण की भयानक होड़ लग गई। ब्रिटेन और फिर फ्रांस भी अणु-शक्ति के स्वामी बन गये। साम्यवादी चीन भी पीछे लगा। प्रारम्भ में बहुत कुछ सोवियत सहायता के बल पर और बाद में अपने प्रयत्नों से उसने अद्भुत आणविक शस्त्र-निर्माण क्षमता पैदा कर ली और आज विश्व की दोनों महा शक्तियाँ इस क्षेत्र में उसकी बढ़ती हुई क्षमता से चिन्तित हैं।

आणविक शस्त्रों ने प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में उथल-पुथल मचाना शुरू कर दिया। इन्हीं के फलस्वरूप विश्व की दो महा शक्तियों के बीच पारस्परिक अविश्वास विकसित हुआ जिससे चौथ-युद्ध (Gold war) को प्रोत्साहन मिला। आणविक शक्ति से सम्पन्न होने की छालसा ने शस्त्रीकरण की ऐसी विनाशकारी प्रतियोगिता को जन्म दिया जो आज सम्पूर्ण मानव जाति के लिए बारूद का ढेर बनी हुई है। विश्व के राजनीतिज्ञ और सैन्य-विचारद्वय इस बात से आतंकित हैं कि तृतीय महायुद्ध यदि छिड़ा तो अणु-आयुधों के प्रयोग से वह इतना विनाशकारी होगा कि युद्ध के बाद विजेता और विजित में कोई फर्क नहीं होगा। इतना ही नहीं सम्पूर्ण मानव जाति का अधिकांश भाग नष्ट और विभिन्न कु-प्रभावों से प्रस्त हो जायेगा।

आणविक शस्त्रों का प्रभाव शुरू से ही राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रभाव डालने लगा और समय के साथ साथ उसने विश्व की महा शक्तियों के लिए राजनीतिक प्रभाव के नये द्वार और कूटनीति के नये आँकड़े खोल दिये। साम्यवादी जगत में भी आणविक शस्त्रों ने सघर्ष के तत्वों को प्रोत्साहित किया। एशिया और अफ्रीका के देश भी आणविक कूटनीति के प्रभाव से न बच सके। विश्व के अनेक देशों को सैनिक व्यूह रचना बदल गई। अन्तर्राष्ट्रीय अय व्यवस्था पर भी आणविक शस्त्रों के विपुल व्यय ने और इससे प्रभावित कूटनीति के नये पैतरी ने प्रभाव डाला।

इस प्रकार आणविक शस्त्र आने जन्म के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और सम्बन्धों को प्रभावित करने लगे, तेजी से यह प्रभाव क्षेत्र बढ़ता गया और आज तो स्थिति यह है कि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक किसी न किसी रूप में आणविक शस्त्रों के प्रभाव से आनन्त है। विस्तार और स्पष्टता के लिए यह उपयुक्त होगा कि हम अणु-आयुधों के प्रभाव का पृथक् पृथक् रूप से विवेचन करें—

(१) आणविक शस्त्रों का सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि विश्व की दो महा शक्तियाँ सम्बन्धित राज्य अमेरिका और सोवियत इस मफूट की जहें

प्रारम्भ से ही निरन्तर गहरी होती गई। अमेरिका ने अणु-बम के आविष्कार को सोवियत रूस से सर्वथा गुप्त रखा जब कि ब्रिटेन और कनाडा को इस बात का पता था। जब अणु-बम का प्रयोग जापान पर किया गया तो उससे केवल हिरोशिमा का ही विनाश नहीं हुआ अपितु रूस और पश्चिमी राष्ट्रों की युद्धकालीन मंत्री भी डूट गईं। स्टालिन ने अमेरिका द्वारा अणु-बम के रहस्य को रूस से गुप्त रखने की बात को परस्पर गम्भीर विश्वासघात माना। उसे इस घटना से व्यक्तिगत रूप में भी बड़ा दुख हुआ। परिणामस्वरूप रूस और अमेरिका में परस्पर तनाव उत्पन्न हो गया और दोनों ही देश एक दूसरे को शका की दृष्टि से देखने लगे।

(२) रूस अणु-शक्ति पर अमेरिका के एकाधिकार को अपने लिए और संपूर्ण साम्यवादी जगत के लिए एक भारी खतरा मानने लगा। अतः उसने अपनी सम्पूर्ण बुद्धि और सामर्थ्य अणु-बम के निर्माण में लगा दी। चार वर्षों के अल्प-काल में ही सन् १९४९ में उसने अणु-बम का रहस्य का पता लगा लिया। अब अमेरिका और रूस दोनों ही देश गुप्त रूप से वैज्ञानिक अस्त्र-शस्त्रों के आविष्कार की होड़ में लग गये। दोनों ही राष्ट्र अणु शक्ति की दृष्टि से अधिकाधिक सम्पन्न हो कर विश्व राजनीति को अपनी ओर मोड़ने के प्रयत्नों में लग गये।

(३) अणु-शक्ति जनित सन्देह और अविश्वास ने द्वितीय महायुद्ध के बाद शीत-युद्ध को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। सम्मेलनों और पारस्परिक विचार-विमर्श पर किसी न किसी रूप में आणविक शस्त्रों का प्रभाव छाया रहा। पश्चिमी देशों और रूस में समुक्त राष्ट्रसंघ के भीतर और बाहर अणु शक्ति के नियन्त्रण के नियमोक्त, नि रक्षोक्त, यूरोपीयन सुरक्षा समस्या आदि प्रश्नों पर शीत युद्ध और कूटनीतिक मध्यम चला जो आज भी यथापूर्व विभिन्न उतार-चढ़ावों के साथ जारी है। नि रक्षोक्त और शीतयुद्ध के क्षेत्र में आणविक शस्त्रास्त्रों का प्रभाव कितना आकाशित रहा और आज भी इन क्षेत्रों में अणु-शक्ति अपना कितना आतंक अमाये हुए है, इसका स्पष्ट चित्र 'शीत युद्ध' और 'नि रक्षोक्त' के विभिन्न अध्यायों में चित्रित किया जा चुका है।

(४) अणु-शस्त्रों की प्रत्यक्षकारी शक्ति और अणु-युद्ध से मानव-सम्यता के विनाश के मय में सह-अस्तित्व की धारणा को आज पूर्वापेक्षा नहीं अधिक व्यावहारिक बना दिया है विश्व की दोनों ही महाशक्तियाँ, पारस्परिक सन्देह और अविश्वास के बावजूद, यह भली प्रकार समझ चुकी हैं कि अणु युद्ध में हार और जीत का कोई महत्त्व नहीं रहेगा क्योंकि विजेता देश भी

सतता ही नष्ट हो जायेगा जितना विजित देश । अतः, अणु-युद्ध की निरर्थकता में सैद्धान्तिक रूप से विश्वास करते हुए दोनों ही देश अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथामुम्भव ऐसा कठोर मार्ग ग्रहण करने से बचने की कोशिश करने लगे हैं जिससे कोई व्यापक युद्ध भड़क उठने की सम्भावना हो । सह-प्रस्थितत्व के महत्व का आज विश्व के राष्ट्र पहले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं । स्टाइन युग के बाद सोवियत विदेश नीति भी इसी तरह संचालित होने लगी है जिससे शान्तिपूर्ण सह-प्रस्थितत्व की सम्भावनाएँ अधिक प्रबल हुई हैं । रूसी और पश्चिमी दोनों ही श्रुत यह मानने लगे हैं कि आज के अणुयुग में साम्यवाद व पूँजीवाद व सह अस्तित्व की बात करना ही विवेकपूर्ण है ।

कोरिया, बर्मा, विपतनाम, स्वेज आदि की घटनाएँ सिद्ध करती हैं कि आणविक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग के मय न महाशक्तियों को जितना नियन्त्रित किया है । कोरियाई युद्ध में अमेरिका ने अणुबम का प्रयोग इसीलिये नहीं किया कि रूस का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो जायगा और अणु-युद्ध का स्फोट न केवल साम्यवादी वरन् पूँजीवादी क्षेत्रों को भी नष्ट-भ्रष्ट कर देगा । अणु-युद्ध के मय ने ही कोरियाई युद्ध को स्थानीय और सीमित क्षेत्रीय युद्ध का रूप दिये रखा ।

स्वेज बाँध के समय ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल की सैनिक-गोजनाएँ इसीलिये मिट्टी में मिल गई कि रूस की ओर से आणविक प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग की धमकी दी गई । अणु-आयुधों के सम्भावित प्रयोग की चेतावनी मात्र ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सलबली भूचादी और ब्रिटेन व फ्रांस को अपने कूटनीतिक व सैनिक बँतरे बदल कर स्वेज से हट जाना पड़ा । इस प्रकार स्वेज का राष्ट्रीयकरण पूरा हुआ और अरब राजनीति अरबों के पक्ष में झुक गई । ब्रिटेन के हट जाने से हुई रिकत-शून्यता को भरने के लिए अमेरिका व रूस में होड़ शुरू हो गई और आज लगभग समूचा मध्यपूर्व इन दोनों महाशक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में बसा हुआ है । इन कूटनीतिक असाहों ने सम्पूर्ण मध्यपूर्व की अराजक बना रखा है ।

बर्मा प्रश्न पर भी आणविक आयुधों के प्रभाव ने अपनी पूरी छाप डाली । अमेरिका की बात मानने का कारण स्पष्ट करते हुए तत्कालीन सोवियत प्रधानमंत्री नुस्चेव ने कहा कि यदि उस समय पूँजीवादी जगत के साथ सघर्ष किया जाता तो पहले ही दिन सारा करोड़ व्यक्ति नष्ट हो जाते । उन्होंने और उनके सहयोगियों ने मध्यपूर्व कहा कि इस प्रकार के महाविनाश के तथ्य से और मूढ़ने वाले ही यह मूर्खतापूर्ण युक्ति दे सकते हैं कि युद्ध समाजवाद के प्रसार में सहायक होगा । साम्यवादी नेताओं ने घोषणा की कि

समाजवाद का निर्माण अणुबमों के विस्फोट से ध्वस्त नू मण्डल पर नहीं हो सकता ।

A वियतनाम युद्ध भी आणविक युद्ध के भय से विश्वव्यापी युद्ध का रूप धारण करने से बचा रहा और सौभाग्यवश अब वह रुने रुने: शिथिल पड़ता जा रहा है ।

(५) आणविक-शक्ति सम्पन्नता के बल पर प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की इच्छा ने ही साम्यवादी जगत के दो महान राष्ट्रों रूस और चीन में मतभेदों का बंमनस्थ की गार्ई को चौड़ा कर दिया । आज चीन साम्यवादी जगत पर सोवियत नेतृत्व की चुनौती दे रहा है और रूस को पूरा भय है कि विशाल जनसत्ता वाला चीनी अजगर आणविक विष से सम्पन्न होकर निकट भविष्य में रूस के लिये एक भारी सतरा बन जायगा । आणविक शक्ति के रूप में चीन के उदय ने और नेतृत्व का प्रभाव के चीनी मन्त्रियों ने दो ध्रुवीयता (Bipolarity) के अन्त को दिला में प्रभावकारी भूमिका अदा की है ।

(६) आणविक शस्त्रास्त्रों के प्रजन ने अनेक एशियाई राष्ट्रों की विदेश नीति और सामरिक नीति को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है । विश्व की अणुशक्ति सम्पन्न शक्तियों का प्रयत्न और आप्रह है कि अणु-शस्त्र विहीन राष्ट्र ऐसे शस्त्र बनाने का प्रयत्न न करें । वे चाहते हैं कि ये राष्ट्र परमाणु शक्ति का विकास केवल असेनिक कार्यों के लिये करें । लेकिन विदम्बना यह है कि परमाणु अस्त्र-विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के आक्रमण की मूर्त में उसके बचाव की व्यवस्था का कोई ठोस आश्वासन या समाधान नहीं है । स्पष्ट है कि इस परिस्थिति ने परमाणु अस्त्रविहीन राष्ट्रों की शक्तियों और सन्देहों को बढ़ा दिया है । इसीलिये कुछ राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था और विदेश नीति को इस तरह मोड़ देने को प्रयत्नशील हैं कि वे या तो स्वयं अणु आयुधों का निर्माण कर सकें या ऐन-बैन-प्रकारण उन्हें प्राप्त कर सकें । भारत यद्यपि अणु आयुधों का निर्माण न करने का निश्चय व्यक्त कर चुना है किन्तु उसने १९६८ की परमाणुविह आयुध प्रसार प्रतिबन्ध सन्धि पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है । अणुशक्ति सम्पन्न चीन के सम्भावित सतरे और पाकिस्तान चीन के नापाक गडझोड़ को देखते हुए इस सम्भावना को ठुकराया नहीं जा सकता कि भारत सरकार अणु-आयुध न बनाने की अन्ती नीति पर पुनर्विचार के लिये तैयार हो जाय । देशों और विदेशी पर्यवेक्षकों की धारणा है कि भारत ने परमाणु अस्त्रों के विनाश की समस्या पर सन्धिय रूप से सोचना शुरू कर दिया है और अधिक समय तक जनमत को उन्देशा करता उसने लिये सम्भव नहीं होगा । मध्यपूर्व की राजनीति

व सामरिक व्यूह-रचना पर भी अणु-आयुधों की काली छाया पड़ रही है। इजरायल द्वारा अणुबम के निर्माण की ओर तेजी से अग्रसर होने की सूचनाएँ मिल रही हैं जिसका प्रभाव अरब राष्ट्रों की सैनिक व कूटनीतिक पेंतरेबाजी पर पड़ना स्वाभाविक है। इजरायल की सैनिक शक्ति का भय समुन्नत अरब गणराज्य, सीरिया आदि को रूस के साथ पहले ही बाँधे हुए है, किन्तु उसकी सम्भावित अणुशक्ति का भय यदि उन्हें सोवियत सेमे में पूरी तरह आ जाने की बाध्य करद तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

(७) आणविक सत्तास्त्रों ने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय जगत में असुरक्षा, अविश्वास, सन्देह और तनाव का वातावरण पैदा किया है जो नाटो, वारसा पैक्ट, आदि अनेक सैनिक संगठनों के जन्म में सहायक हुआ है। एक-दूसरे पर परमाणविक आक्रमण के भय से सोवियत रूस और अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को जन्म दिया है अपने-अपने पक्ष के देशों में अणु-आयुध सम्पन्न सैनिक केन्द्र स्थापित किये हैं। इससे उन देशों की आन्तरिक राजनीति और प्रभुसत्ता भी बड़ी सीमा तक प्रभावित हुई है। पराये देश में अपने आणविक केन्द्र स्थापित करने के लिये शक्तिशाली देशों ने उद्य देश को विशाल आर्थिक और सैनिक सहायता देकर अपना पिछलग्नु बनाने के सफल प्रयास किये हैं। उदाहरणस्वरूप पाकिस्तान में अमेरिका नियन्त्रित गिलगित हवाई अड्डे की और इस आधार पर पाकिस्तान-अमरीकी सम्बन्धों की बहानी उहराना अनावश्यक है।

सारांश यह है कि आणविक सत्तास्त्रों ने आधुनिक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय, राजनीतिक, सैनिक व आर्थिक नीति की प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप में कम या अधिक प्रभावित अवश्य किया है।

द्वि-ध्रुवीयता (द्वि-केन्द्रीयता) एवं बहु केन्द्रवाद (Bipolarity and Polycentrism)

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में द्वि-ध्रुवीयता अथवा द्वि-केन्द्रीयता का सरलतम अर्थ है—विश्व का दो शक्ति-ग्रुटो या केन्द्रों में विभाजित हो जाना। इसी प्रकार बहुकेन्द्रवाद का आशय है—विश्व में शक्ति के केवल मात्र दो केन्द्रों की अपेक्षा शक्ति के अनेक केन्द्रों का उदय हो जाना। द्वितीय महा-युद्ध के तुरन्त बाद विश्व द्वि-ध्रुवीयता (Bipolarity) की ओर बढ़ा और १९६० के आते-आते इस द्वि-ध्रुवीयता के घणन सिद्धिल पड़ने लगे। अब विश्व शन-शन बहु केन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर अग्रसर होने लगा। आज स्थिति यह है कि विश्व में शक्ति के दो से अधिक केन्द्र स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुके हैं, यद्यपि उनका स्वरूप गुनिश्चित नहीं हुआ है। अग्रिम

शक्तियों में हम प्रथम दोनों ही स्थितियों को अर्थात् द्वि-ध्रुवीयता और बहु-केन्द्रीयता को सविस्तार प्रकट करेंगे ।

द्वितीय महायुद्ध का एक अत्यन्त नातिकारी और महत्वपूर्ण परिणाम यह निश्चय है कि प्राचीन शक्ति-सन्तुलन का पूरी तरह विनाश हो गया । युद्ध के उपरान्त दो प्रमुख फासिस्ट शक्तियाँ जर्मनी और इटली पूर्ण पराभव को पहुँच गईं । ब्रिटेन राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से बहुत क्षीण हो गया । यूरोपीय महाद्वीप पर यदि कोई देश युद्धकालीन महान् शक्तियों के बावजूद भी शक्तिशाली होकर निकला तो वह था सोवियत संघ । उसकी विशाल प्रदेशों की उपलब्धि हुई और अनेक पड़ोसी देशों पर उसकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव पड़ा । युद्ध काल में तो उसने अपनी सीमाओं का पश्चिम में विस्तार कर ही लिया, अब उसके सीमान्तों में वे सम्पूर्ण प्रदेश भी शामिल हो गये जो किसी समय जार कालीन रूस में हुआ करते थे । उसका विश्व की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव स्थापित हो गया और साम्यवादी सिद्धान्तों तथा जीवन-दर्शन में मानव की आस्था में वृद्धि हो गई । महायुद्ध से विनष्ट और अस्थिर-संसार में केवल एक ही देश ऐसा बचा जो सोवियत संघ का मुकाबला करने में सक्षम था और लोकतन्त्रवादी शक्तियों को सशक्त गेनुत्व दे सकता था । यह देश था समुक्त राज्य अमेरिका जिसे युद्ध में कोई विशेष क्षति नहीं पहुँची थी, न विनाशकारी बम वर्षा का शिकार होना पड़ा था और न जिसकी भूमि पर रक्त रजित होली ही खेली गई थी । आर्थिक दृष्टि से वह संसार का समृद्धतम देश था । युद्ध के बाद संसार के सभी पूँजीवादी देश अमेरिकन सहायता के बल पर अपनी अर्ध-अवस्था को ठीक रास्ते पर लाने की आशा लगाये बैठे थे ।

महायुद्ध के बाद कुछ काल तक समुक्त राज्य अमेरिका ही अणु रहस्य का एक मात्र स्वामी था । सोवियत रूस के लिए यह एक गम्भीर चुनौती थी । स्वाभाविक था कि वह शक्ति-सन्तुलन को अपने विपक्ष में, जाने से रोकने के लिए अणु-शक्ति व रहस्य का पता लगाने में जुट जाता और अपने देश की सेनाओं को अपने सहयोगी और मित्र-राष्ट्रों से घेरकर सुरक्षित बनाने का प्रयत्न करता ।

महायुद्ध के पश्चात्तरूप उत्पन्न हुई उत्तरोत्तर स्थितियों ने दृष्ट पर दिया कि विश्व में शक्ति के दो ही प्रमुख केन्द्र हैं—सोवियत संघ और समुक्त राज्य अमेरिका । यूँ कि युद्धोत्तर विश्व में प्रारम्भ से ही दोनों महाशक्तियों परस्पर प्रतियोगी बन गईं, अतः दोनों ही के नेतृत्व में दो विरोधी शक्तिशाली गुटों का निर्माण होने लगा । दो गुटों के इस निर्माण को सिद्धान्तों के सपर्य

ने विशेष प्रोत्साहन दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद सिद्धान्तों और आदर्शों पर विशेष आपस किया जाने लगा। सोवियत रूस साम्यवाद के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्नशील हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी राष्ट्र साम्यवाद की अवरोध करने के लिए कटिबद्ध हो गया। रूस और अमेरिका दोनों ही महाशक्तियाँ अपने सिद्धान्तों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गईं और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में वे एक दूसरे के प्रति असहिष्णु बन गईं। साम्यवाद की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की अमेरिकन सुदृढ़ विरोध और सफल से ठन गई।

यद्यपि द्वि-ध्रुवीकरण की प्रक्रिया द्वितीय महायुद्ध के तुरन्त बाद ही शुरू हो गई, तथापि १९४७ तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि विश्व द्वि-ध्रुवीय (Bipolar) बन गया था। इस समय तक रूस का प्रतिरोध मुख्यतः ब्रिटेन के प्रति था अमेरिका के प्रति नहीं। रूसियों को विश्वास था कि अमेरिका शीघ्र ही पुनः अपनी परम्परागत पार्थक्यवादी नीति (Traditional Isolationism) की ओर लौट आयेगी। लेकिन रूसी अनुमान पलट सिद्ध हुआ। महायुद्ध के बाद ब्रिटेन राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक दृष्टि से इतना सक्षम नहीं रहा था कि वह पूँजीवादी विश्व को नेतृत्व दे सकता। ब्रिटेन तो शीघ्र ही आर्थिक दृष्टि से अपने पुनः निर्माण के लिए अमेरिका का मुख्यापेक्षी हो गया। नेतृत्व अमेरिका ने सम्भाल लिया। मार्च १९४७ में ट्रुमैन सिद्धान्त (Truman Doctrine) के अन्तर्गत अमेरिका यूनान और टर्की में ब्रिटिश उत्तरदायित्वों को पूरा करने की सहमति हो गया। अमेरिका ने अपना यह दृढ़ निश्चय व्यक्त कर दिया कि वह उस प्रत्येक देश की सहायता करेगा जो साम्यवाद के विरुद्ध उसकी सहायता मागेगा। अमेरिकन राजनीतिज्ञों को यह विश्वास हो गया कि रूस, चीन और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के प्रसार ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर दिया है। अतः अमेरिका को अविलम्ब ऐसी नीति अपनानी चाहिये जिससे साम्यवादी प्रसार को प्रभावशाली रूप से 'अवरोध' कर दिया जाय।

अमेरिका और रूस एक दूसरे के प्रति अविश्वास और संदेह की धारा में बहते हुए अपने-अपने पक्ष में शक्ति संचय करने लगे। शीत-युद्ध (Cold war) शुरू हो गया जो क्रमशः तेज होता गया। दोनों महाशक्तियों का संघर्ष (Conflict) पहले तो यूरोप तक सीमित रहा, किन्तु धीरे-धीरे यह अन्य महा-क्षेत्रों में भी फैल गया। सबसे पहले एशिया संघर्ष स्थल बना, बाद में मध्य-पूर्व और सब लैटिन अमेरिका व अफ्रीका। दोनों ही महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में लेने का प्रयत्न करने लगे। सोवियत रूस ने आदर्शवादी सीधता से पूर्वी यूरोप में अपनी प्रभुता का विस्तार कर

लिया। युद्धोपरान्त १९४८ तक की केवल तीन वर्ष की अल्पावधि में ही पूर्वी यूरोप के सात देशों को पूरी तरह 'लाल' बना दिया गया। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद की केवल चार वर्ष की अवधि में ही सोवियत रूस ने अणुबम के रहस्य को खोज लिया। अब स्थिति यह थी कि रूस और अमेरिका—ये दोनों महाशक्तियाँ न केवल एक-दूसरे को आणविक हथियारों की धमकी देने लगीं वरन् विश्व के हर भाग में और हर मामले में एक-दूसरे को सींचा-दिखाने का प्रयास करने लगीं। अमेरिकन युद्ध और रूसी युद्ध में संयुक्त राष्ट्र सन के भीतर और बाहर अणु शक्ति के निष्पन्न व नियंत्रीकरण, निःशस्त्रीकरण, पराजित राष्ट्रों के साथ शांति सन्धियों, जर्मनी व बर्लिन के प्रश्नों, यूरोपीयन सुरक्षा-समस्याओं एशिया व अफ्रीका के अल्प-विकसित राष्ट्रों के भविष्य आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी प्रश्नों पर तीव्र वाद-विवाद और कूटनीतिक संघर्ष चलने लगे।

सोवियत प्रभाव और साम्यवाद के प्रसार को अवरोध करने के लिये अमेरिका की मार्शल योजना के अन्तर्गत यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के प्रभावशाली प्रयत्न चले। मार्शल योजना के प्रति-उत्तर में अक्टूबर १९४७ में रूस ने यूरोप के नौ साम्यवादी देशों के 'कोमिन्फार्म' की स्थापना की। रूस ने पूर्वी यूरोप पर अपने नियंत्रण को और भी बढोढ़ बना दिया। शक्ति के दो पड़े अपना युद्ध या सेमे बना गये और उनमें अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों के विकास के लिये जीतोड़ स्पर्धा होने लगी। चीन में साम्यवादियों की महान् विजय ने जहाँ सोवियत युद्ध को बड़ा प्रबल बना दिया वहाँ अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों में यह भय पैदा हो गया कि उपनिवेशों या नव-जागत राज्यों में बसने वाली अविचलित जनता चीन का अनुकरण करके पश्चिमी लोकतन्त्र की अपेक्षा कहीं साम्यवादी व्यवस्था की ही पसन्द न कर ले। अमेरिका व अन्य पश्चिमी राज्यों के राज-नेता इस बात से चिन्तित हो गये कि विश्व के अल्प-विकसित देश साम्यवादी प्रसार के लिये उत्तम क्षेत्र सिद्ध हो सकते हैं। अतः जनवरी १९४९ में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने प्रसिद्ध 'चार सूत्री कार्यक्रम' (Four Point Programme) की घोषणा की।

विश्व का तेजी से दो शक्ति प्रभुओं या शक्ति-केन्द्रों में विभाजन होता गया। १ अक्टूबर, १९४९ को पेरिस में वाक्यांश साम्यवादियों का अन्त-गणराज्य स्थापित हो गया। पश्चिमी शक्तियाँ साम्यवाद के अवरोध के लिये राजनीतिक व आर्थिक स्तर के साथ सैनिक स्तर पर भी उतर आईं। अमेरिका ने अन्य देशों के साथ सैनिक सन्धियों व पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम का तरीका प्रारम्भ किया और अप्रैल १९४९ में नाटो की

स्थापना हुई। चूँकि नाटो-फार्मूला ने यूरोप में अच्छा काम किया, अतः अमेरिका ने इसका प्रयोग अन्य क्षेत्रों में भी किया। इसके अन्तर्गत नाटो-सदस्यों की सैनिक सहायता दी गई, सदस्य देशों में सैनिक बन्दे स्थापित किये गये और विभिन्न सैन्यी सन्धियाँ ब्रियान्वित की गईं। सारा सारा इस प्रकार तेजी से दो भागों में बंटता गया—एक था साम्यवादी भाग (The Communist Part) और दूसरा था अमेरिकनों के शब्दों में 'मुक्त विश्व' (The Free World)।

कुछ समय तक यही प्रतीत हुआ कि विश्व का यह द्वि-ध्रुवीयकरण या द्वि-केन्द्रीयकरण स्थायी बन गया है और भविष्य में यह व्यवस्था अर्थात् द्वि-ध्रुवीयता (Bipolarity) अधिक सुदृढ़ होती जायगी। इस समय जिन तटस्थ राष्ट्रों (Neutrals) का उदय हुआ, उन्हें इस द्वि-ध्रुवीय विश्व (The bipolar world) में कोई स्थान नहीं दिया गया। रूसी और अमरीकी दोनों ही भारत जैसे राष्ट्रों को शक व सन्देह की निगाह से देखते रहे। दोनों ही महाशक्तियों ने इस उचित पर आचरण किया कि "जो हमारे साथ नहीं है, वह हमारे विरुद्ध है" (He who is not with us is against us)। युद्धोत्तर विश्व का द्वि-ध्रुवीय चरित्र इस तरह प्रकट हुआ कि अनेक देश वास्तविकता के अन्य पहलुओं को भुला बैठे और इस बात के प्रति आश्वस्त हो गये कि अन्तर्गतवा सम्पूर्ण विश्व दो परस्पर प्रतिरोधी गुटों में बंट जायगा और द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था पक्की या स्थिर (Fixed) हो जायगी।

पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ने करवट ली, नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, नई विचारधाराएँ पनपी, राष्ट्रीय चरित्र अथवा राष्ट्रीयता को प्रतिष्ठित करने की भावनाएँ बलवती हुईं और धीरे-धीरे द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था बहु-केन्द्रवाद (Polycentrism) की ओर बढ़ने लगी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कठोर रूप में द्वि-केन्द्रीय या द्वि-ध्रुवीय बनने की अपेक्षा एक भिन्न दिशा में प्रभावित होने लगी जिसका स्वरूप अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका।

विश्व के द्वि-ध्रुवीय चरित्र को राखते पढ़ते राष्ट्रियता की शक्तियों (The forces of Nationalism) ने चुनौती देना प्रारम्भ किया। यह चुनौती वास्तव में १९४८ में ही मिल गई जबकि युगोस्लाविया ने सफलतापूर्वक सोवियत प्रभाव क्षेत्र से अपने को मुक्त कर लिया। यद्यपि सोवियत-युगोस्लाव सन्धियों की सैन्यनिरप सन्धियों का याना पहनाया गया तथापि यह एक तथ्य है कि युगोस्लाविया की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ ही सावियन शक्ति के प्रति विद्रोही बना। सोवियत शक्ति-गुट व लिये जून १९४८ में युगोस्लाविया का पृथक् हो जाना एक भारी आघात था। स्वतन्त्र विचारों वाले कट्टर राष्ट्र-

वादी मार्शल टीटो यह बर्दाश्त नहीं कर सके कि सोवियत रूस यूरोप के साम्यवादी शासन तन्त्रों या गुगोस्लाविया पर अपनी कठोर निगरानी रखे और उन्हें 'लोह-आवरण' (Iron Curtain) के मोतर ढिपाये रखे । गुगो-स्लाविया ने इसी प्रभाव से मुक्त होकर अपने को पश्चिमी खेमे के साथ आवद्ध नहीं किया बरन एक स्वतन्त्र और सक्रिय असतन्त्र-नीति पर चलना शुरू कर दिया । विश्व की द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था पर यह पहला आघात था जिसके दूरगामी प्रभाव हुए ।

रूस और अमेरिका के शक्ति-गुटों ने विश्व के जो नवोदित एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्र सम्मिलित नहीं हुए थे, उन्होंने भी दोनों गुटों से प्रयत्न रहने की नीति अपना कर द्वि-केन्द्रीय व्यवस्था को स्थिर बनाया । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका भारत की रही । भारत के प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री स्व० नेहरू ने कहा कि उनके देश का प्रमुख लक्ष्य है दो विरोधी गुटों के विश्व राजनीति के सागर के दो कूलों बीच एक पुल का निर्माण करना—ऐसा पुल जिसके द्वारा दोनों गुटों की दूरियों और मतभेदों को दूर करके उन्हें मिलाया जा सके । यद्यपि भारत की यह आकांक्षा नहीं रही कि वह एक तीसरे गुट का निर्माण करके उसका नेतृत्व करे, तथापि अनेक एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्री ने भारतीय दृष्टिकोण का अनुसरण किया और इस प्रकार विश्व के द्वि-केन्द्रीय चरित्र को घूमिल बनाने में निर्णायक योग दिया । नासिर का मिस्र और एनकूमा का घाना इनमें अग्रणी रहे । धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि लगभग एक तिहाई विश्व ने यही निर्णय किया है कि दोनों शक्ति गुटों में से किसी में भी सम्मिलित न हुआ जाय और सक्रिय तटस्थता अथवा अमलम्नता की नीति पर चला जाय ।

शीघ्र ही दोनों शक्ति गुटों में जोर भी स्थिरता आयी । पश्चिमी यूरोपियन शक्तियों ने अपना आर्थिक पुनर्निर्माण करके और अपने को पुनः शक्ति-सम्पन्न करके यह चाहा कि अब वे अमेरिकन नीतियों का अन्धानुकरण नहीं करें अर्थात् अमेरिका के पिछलग्नु बन कर नहीं रहें । यही कारण था कि १९५६ में ब्रिटेन और फ्रांस ने स्वेज पर आक्रमण किया, यद्यपि रूस की आणविक शस्त्रों के प्रयोग की घमकी और अमेरिका की गाराजगी के कारण उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े, लेकिन इस घटना ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी कि अमेरिका का नेतृत्व अब स्थिर पड़ने लगा है और पश्चिमी खेमे में दरार आने लगी है ।

विरुद्ध फ्रान्स ने, जनरल डिगॉल के नेतृत्व में, विश्व की द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था को विशेष आघात पहुँचाया । राष्ट्रपति डिगॉल की प्रमुख जिज्ञा सदैव यही रही कि फ्रांस किसी न किसी तरह अपने विलुप्त अन्तर्राष्ट्रीय

सम्मान को फिर से प्राप्त करे। इसीलिए शनः शनः वह अपने राष्ट्र को अमेरिकन प्रभाव से मुक्त करने लगा और दूसरी ओर ब्रिटेन के बढ़ते हुए प्रभाव को भी रोकने की चेष्टा में लगा रहा। इसीलिए साम्यवादी देशों के साथ उन्होंने मधुर सम्बन्ध स्थापित किये। साम्यवादी चीन के साथ फ्रांस के मित्रतापूर्ण सम्बन्धों में विकास हुआ। मास्को की अगुा परीक्षण निरोध सन्धि पर हस्ताक्षर न करने वाले केवल दो ही बड़े देश रहे—चीन और फ्रांस और दोनों ही ने यह तर्क दिया कि सन्धि का ध्येय यह है कि सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन अगुा-शस्त्रों के क्षेत्र में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं एवं उनका प्रयोजन यह है कि अन्य देश इस शक्ति का विकास न करने पायें।

फ्रांस ने विपत्तनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यवाही की निन्दा की, यूरोपियन साक्षा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश को रोकने की डिगॉल की नीति ने पश्चिमी खेमे में फूट का संकेत दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बढ़त चाहा कि ब्रिटेन का यूरोपियन साक्षा बाजार की सदस्यता मिल जाये। किन्तु डिगॉल अपने हठ पर दृढ़ रहे। इतना ही नहीं, नि शस्त्रीकरण के प्रश्न पर इनमें मतैक्य नहीं हो सका। जब फ्रांस को संयुक्त राष्ट्र नि शस्त्रीकरण आयोग का सदस्य बनाया गया तो उसने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। इनमें भी बढ़ कर घटना नाटो को पोलरिस यन्त्रों से युक्त करने के प्रस्ताव को ले कर घटी। १९६२ में अमेरिका और ब्रिटेन में एक समझौते द्वारा यह तय हुआ कि नाटो राज्यों की सेनाओं को पोलरिस प्रक्षेपणास्त्रों से लैस किया जाय। परन्तु फ्रांस ने इसमें शामिल होने से इन्कार कर दिया और निर्णय लिया कि वह इस कार्य में साथ नहीं देगा। १९६३ में फ्रेंच सरकार द्वारा चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर देना और दोनों राष्ट्रों के बीच राजदूतों का आदान-प्रदान हो जाने की घटना से यह और भी स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति डिगॉल का अपना अलग ही रास्ता है जो नाटो राज्यों से भिन्न है।

राष्ट्रपति डिगॉल ने साधारण के समक्ष एक और मुद्दा रखा। उन्होंने कहा कि दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीतिक स्थिति अत्यन्त टाढाडोल है, अब इस क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करके सटस्वीकरण (Neutralisation of S. E. Asian Region) कर दिया जाय। समुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी राज्यों ने डिगॉल के मुद्दा का बटु-विरोध किया। वास्तव में फ्रांस की ये सभी कार्यवाहियाँ बटलाष्टिर समुदाय की एकता को भंग करने वाली थी। इस एकता की बढोरतम आघात तो १२ मार्च, १९६६ की

डिगॉल की इस घोषणा से पट्टेडा कि फ्रान्स नाटो संगठन से ही अलग होना चाहता है। फ्रान्स की माग पर ही सयुक्त राज्य अमेरिका को फ्रान्स भूमि पर स्थित नाटो अड्डों को खाली कर देना पडा। फ्रान्स के नाटो के परिपाम के निर्णय से पश्चिमी गुट पर एक महान् शकट आ गया। नाटो में पश्चिमी जर्मन को इस शर्त पर १९५५ में शामिल किया गया था कि वह स्वतन्त्र रूप से अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि नहीं करेगा। इस शर्त के लिए स्वयं फ्रान्स बहुत दृढ था। परन्तु जब फ्रान्स ही नाटो से निकल जाता तो पश्चिमी जर्मनी भी इस शर्त से मुक्त हो जाता और तब वहां सैन्य शक्ति में वृद्धि करने का कार्यक्रम जोर-शोर से चलने की सम्भावना हो जाती। पश्चिमी जर्मनी द्वारा सैनिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास की प्रतिप्रिया सोवियत गुट के देशों में होती और इस तरह हथियारबन्दी की होड का कुचक फिर जोरों से चलना शुरू हो जाता। राष्ट्रपति डिगॉल के इस निर्णय के कारण यूरोप की नूतनीतिक स्थिति खराब हो सकती थी और पश्चिमी जर्मनी को लेकर युद्ध की सम्भावना बढ़ सकती थी।

जनरल डिगॉल ऊपर से विविध दीखने वाले अपने व्यवहार से राजनीतिक जगत को चौंकाते रहे। कुछ लोगो ने इसे 'वृद्धपस्था की सनक' का नाम दिया। मगर जो लोग इन कार्यवाहियों के पीछे उद्देश्य खोजने के पक्ष में थे उनके अनुसार यूरोप और सम्पूर्ण विश्व के प्रति जनरल डिगॉल का अपना विशिष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा था—“अमेरिका विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है और सारभाविक रूप से वह अपनी शक्ति को बढ़ाने पर तुल्य हुआ है।” इस शक्ति विस्तार से बचने के लिए उनके अनुसार दो ही रास्ते थे। पहला मार्ग यह था कि उसी गुट का एक सदस्य बना जाये जहां अमेरिकन शक्ति सर्वोपरि है और यह रास्ता आसान था। दूसरा रास्ता था अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा। इसके लिए यह जरूरी था कि फ्रान्स और जर्मनी एक-दूसरे के निकट आये, अन्यथा अमेरिकन प्रभाव से नहीं बचा जा सकता था। इसीलिए फ्रान्स और जर्मनी में राजनीतिक घनिष्ठता के प्रति सन्धि कदम उठाये जाते रहे। जनरल डिगॉल का विश्वास था कि फ्रान्स ने जिस आर्थिक ढांचे को पिछले ६ वर्षों में खड़ा किया है, उसे नष्ट न होने दे, ताकि उसे अमेरिकन पद्धति द्वारा आत्मसात् न किया जा सके। अपने व्यक्तित्व को धनाये रखने के लिए ही उनकी तीसरी शर्त यह थी कि विश्व में इस बहम को समाप्त कर दिया जाये कि शक्ति के कुल दो ही गुट हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। तीसरे गुट की रचना के लिए उन्होंने फ्रान्स को पूर्वी यूरोपीय देशों के निकट लाना चाहा ताकि ‘विश्व राजनीति में दो गुटों

की पद्धति के अतिरिक्त भी कुछ हो ।' इसी नीति को अपनाकर ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने का उन्होंने विरोध किया ।

जनरल डिगॉल ने अत्यन्त सदिग्ध और विवादास्पद परिस्थितियों में भी फ्रांस की प्रतिष्ठा का निरन्तर विकास किया । डिगॉल ने अपने राष्ट्रपतित्व-काल में फ्रांस को वास्तव में तूफानी माना पर चलाया और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फ्रांस की जहाज की शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बहुत कुछ सफल चेष्टा की । अप्रैल, १९६६ में राष्ट्रपति डिगॉल के शासन काल के समाप्त होने के बाद न केवल फ्रांस के इतिहास में बल्कि वास्तव में समस्त यूरोप के इतिहास में एक युग का अन्त हुआ । पोंम्पिदू नये राष्ट्रपति बने । नयी फ्रेंच सरकार ने डिगॉल शासन की अपेक्षा अपने रवैये में अभी तक कुछ नरमी प्रदर्शित की है और इस बात पर सम्भावना नजर आने लगी है कि फ्रांस अब नाटो का परित्याग नहीं करेगा तथा फ्रांस व मित्र देशों की फौजों में सहयोग की भावना पैदा होगी । जो भी हो यह स्पष्ट है कि फ्रांस ने डिगॉल के नेतृत्व में अपने इस पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को निखारा है, उसकी वह हर सूरत में रक्षा करेगा । फ्रांस यह नहीं चाहेगा कि एक शक्ति-केन्द्र के रूप में उसका जो उदय हो रहा है—वह समाप्त हो जाय ।

विश्व की द्वि ध्रुवीय व्यवस्था को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में इस बात से भी आघात पहुंचा है कि अब अणु-आयुधों का एकाधिकार केवल अमेरिका और रूस के पास ही नहीं रहा है । ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी अणु-शक्ति के स्वामी बन चुके हैं । यद्यपि इनकी अणु-शक्ति अभी इतनी सम्पन्न नहीं है कि वह अमेरिका अथवा सोवियत संघ की अणु शक्ति का मुकाबला कर सके और यद्यपि कुछ समय तक उनके कारण आणविक शक्ति का सन्तुलन अधिक प्रभावित होने की सम्भावना नहीं है, तथापि यह अवश्य है कि ये राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतन्त्र आचरण करते जायेंगे और अमेरिका या रूस के पिछलग्गू कहलाने की स्थिति से बचना चाहेंगे । चीन की महत्वाकांक्षा तो एकदम स्पष्ट हो चुकी है । चीन ने अपने को जिस प्रकार सोवियत संघ से एकदम मुक्त कर लिया है और जिस ढंग से साम्यवादी जगत में सोवियत नेतृत्व को चुनौती दी है, वह आश्चर्यजनक है । साम्यवादी सेना आज दो शक्ति-केन्द्रों में बंट चुका है—एक केन्द्र है रूस तो दूसरा केन्द्र है चीन । इसी शक्ति को हगरी, पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया के व्यवहार से भी भय पैदा हो चुका है । ये राष्ट्र यद्यपि इसी सैनिक बल के कारण अपनी आवाज को दबाए हुए हैं लेकिन रह रह कर प्रस्फुटित होने वाले इनके व्यवहारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में लम्बे समय तक

सम्भवतः इन्हें जबरदस्ती सोवियत-शक्ति-केन्द्र के साथ बाधकर नहीं रखा जा सकेगा अथवा इन पर सोवियत नियन्त्रण आज के समान कठोर नहीं रह पायेगा।

ऐसी से बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हाल ही के कुछ वर्षों से एक नया मोड़ दिखाई देने लगा है और वह है सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य परस्पर सह अस्तित्व की धारणा का विकास होना। दोनों ही राष्ट्र यह समझ चुके हैं कि कोई भी अणु युद्ध विजेता और विजित के लिए समान रूप से विनाशकारी सिद्ध होगा। अतः दोनों यह मानने लगे हैं कि अपने सैद्धान्तिक सधर्षों के बावजूद पूँजीवाद और साम्यवाद का सहअस्तित्व सम्भव है। इसी नेता आज कि परिवर्तित जटिल और विस्फोटक परिस्थितियों में यह मानने लगे हैं कि साम्यवाद का प्रसार अब शान्तिपूर्ण उपायों से ही करना हितकारी होगा—इसके लिए सैनिक शक्ति का आश्रय लेना विनाश को आमन्त्रण देना होगा। दुर्भाग्यवश साम्यवादो चीन का रवैया अभी तक युद्धोन्मादी है। वह आज के युग में भी युद्ध की अनिवार्यता पर बल दे रहा है और सैनिक-शक्ति से पूँजीवाद के विनाश पर चीनी साम्यवाद का महल खड़ा करने के स्वप्न देख रहा है। प्रगुता और नेतृत्व की लालसा में वह सोवियत संघ से भी बुरी तरह उलझ गया है। रूस और अमेरिका दोनों ही यह मलीभाति समझने लगे हैं कि निकट भविष्य में ही प्रबल आणविक शक्ति से सम्पन्न चीन दोनों ही के लिए जबरदस्ती खतरा सिद्ध हो सकता है। इस अनुमति ने भी दोनों को पूर्वापेक्षा कुछ निकट लाने में सहयोग दिया है।

उभरती हुई नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रूप रेखा अभी तक सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि दो शक्ति गुटों अथवा दो सेमों की जगह तीन गुट या सेमे साफ तौर पर उभर आये हैं जिनमें असंलग्न गुट दो की अपेक्षा कम शक्तिशाली है, तथापि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था बहु केन्द्रीय (Poly-centric) है, क्योंकि शक्ति के केन्द्र (Centres of Power) अनेक हैं जिनमें केवल उपरोक्त दोनों सेमे ही शामिल नहीं हैं बल्कि अकेले राष्ट्र और समुक्त राष्ट्र संघ भी सम्मिलित हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रीय राज्य अपने महत्व को खोना पसन्द नहीं करेंगे। आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी है कि मौके पर कमजोर से कमजोर एशियायी और अफ्रीकी राष्ट्रों की आवाज भी अपना महत्व रखती है। ऐसे अनेक अवसर आये हैं जब क्षेत्रीय मामलों (Regional Issues) में इन राष्ट्रों ने दोनों महा शक्तियों का सफलतापूर्वक विरोध किया है। इन राष्ट्रों ने समुक्त राष्ट्रसंघ की महा सभा,

को अपना रंग मच चुना है और सब तेजी से उनका प्रवक्ता बनना जा रहा रहा है। मध्य-पूर्व में इजराइल और समुद्रन अरब गणराज्य शक्ति के ऐसे केन्द्र हैं जो अपने रङ्गों में परिवर्तन द्वारा सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को और महा शक्तियों के आपसी सम्बन्धों को शकशोर सकते हैं। शक्ति सन्तुलन की ऐतिहासिक परम्परा का आज विशेष महत्व नहीं रह गया है और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की बात अव्यावहारिक प्रतीत होने लगी है। आणविक हथियारों की भयकरता ने शक्ति सन्तुलन के स्वरूप को बदल दिया है और सामूहिक रक्षा व्यवस्था की प्रणाली को बहुत कुछ खण्डित कर दिया है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अभी अपनी निर्माणात्मक अवस्था में है और भविष्य में इसमें अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहने की सम्भावना है। वर्तमान आधार यही है कि अभी अनेक महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय होना बाकी है। आधुनिक संसार द्वि-केन्द्रीयवाद से बहु-केन्द्रवाद की ओर अग्रसर है।

१६

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रभाव

(IMPACT OF U. N. O. ON INTERNATIONAL POLITICS)

प्रथम युद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई जो विभिन्न दुर्बलताओं और महाशक्तियों के असहयोग के कारण अपने उद्देश्य में असफल हुआ। १९१९ में द्वितीय महायुद्ध भड़क उठा जो अपार घन-जन के विनाश के बाद १९४५ में समाप्त हुआ। महायुद्ध काल में ही दुनिया के विचारचौल और शान्तिवादी राजनीतिज्ञों तथा विचारकों ने पुनः कोई ऐसा साधन सोचना चाहा जो ऐसे विनाशकारी युद्ध की पुनरावृत्ति को रोक सके। इस आवश्यकता को भूत रूप देने के लिए मित राष्ट्रों में विचार-विमर्श शुरू हो गया और अन्त में विभिन्न मुलाकातों और सम्मेलनों के बाद विश्व-संगठन के चार्टर पर २६ जून, १९४५ के दिन ५० राष्ट्रों के ५५० प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये इस प्रकार संयुक्त राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ और राष्ट्रपति ट्रू मैन ने भाषण देते हुए कहा कि—“यह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए इतिहास आपका सम्मान करेगा।” २४ अक्टूबर, १९४५ से संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर लागू हुआ और १० फरवरी, १९४६ को संघ की प्रथम बैठक हुई।

प्रस्तुत अध्याय में हमारा उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघ के स्वरूप और उसके रूप विधान या ढांचे या संगठन का वर्णन करना नहीं है बल्कि यह देना

है कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर समुक्त राष्ट्र संघ ने क्या प्रभाव डाला है और भविष्य में इस प्रभाव की क्या सीमाएँ हैं ? अतः इस प्रभाव को जानने के प्रसंग में यह भी ज्ञात करना होगा कि समुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों और सिद्धान्तों में ऐसी क्या बातें रखी गई हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को प्रभावित करने वाली हो। यह भी देखना होगा कि संघ के विभिन्न अंगों को ऐसी कौनसी शक्तियाँ दी गई हैं जिनके माध्यम से वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभाव लागू कर सकती हैं अथवा करती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने की दृष्टि से संघ का स्वरूप

समुक्त राष्ट्र संघ का स्वरूप उसके चार्टर या संविधान से स्पष्ट है। चार्टर की प्रस्तावना के आरम्भ में सदस्य राष्ट्रों के विश्व-शान्ति और सुरक्षा सम्बन्धी सकल्यों को प्रकट किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और विश्व-शान्ति और सुरक्षा को प्रभावित करने की दृष्टि से संघ के उद्देश्य यह रहे गये हैं—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करना, शान्ति पर होने वाले आक्रमणों को रोकना और उनके विरुद्ध प्रभावशाली सामूहिक कार्यवाही करना, शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानून भंग करने वाली चेष्टाओं को दबाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से और अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुलझाना।

(२) जनता के आत्म-निर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्रों से मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना तथा सार्वभौम शान्ति को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करना।

(४) उपरोक्त देशों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में सामञ्जस्य स्थापित करने हेतु केन्द्र के रूप में कार्य करना।

समुक्त राष्ट्र संघ का आधार ऐसे सिद्धान्तों पर रखा गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सम्बन्धों को प्रभावित करने की भूमिका तैयार करते हैं। संघ के सदस्य राज्यों को इन बातों या सिद्धान्तों के अन्तर्गत कार्य करना होता है —

(i) सभी राज्य प्रभुत्व सम्पन्न हैं और समान हैं।

(ii) सभी सदस्य चार्टर के अनुसार अपने उत्तरदायित्वों व कर्तव्यों का सम्भावना से पालन करेंगे।

(iii) सभी सदस्य राष्ट्र अपने सगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण ढंग से इस प्रकार करेंगे कि शान्ति, सुरक्षा व न्याय के मंग होने का मय नहीं रहे।

(iv) सदस्य राष्ट्र अपने सम्बन्धों में आक्रमण की धमकी देने या दूसरे राज्यों के प्रति बल प्रयोग करने से दूर रहेंगे।

(v) सदस्य राष्ट्र चार्टर के अनुसार की जाने वाली संधि की प्रत्येक कार्यवाही में सब प्रकार का सहयोग व सहायता देंगे और वे किसी ऐसे देश की मदद नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संधि शान्ति और सुरक्षा के लिए कोई कार्यवाही करेगा।

(vi) शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए यह संधि आवश्यक कार्यवाही करेगा। सब यह भी देखेगा कि गैर-सदस्य राष्ट्र भी यथासम्भव ऐसे कार्य न करें जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाय।

(vii) विश्व-शान्ति और सुरक्षा के अतिरिक्त संधि किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संधि के उद्देश्यों और सिद्धान्तों की रचना इस प्रकार की गई है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की भूमिका बनाते हैं और इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संधि के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखना, विभिन्न राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना और मानव कल्याण के कार्य करना उसका कर्तव्य है। संधि का सदस्य बनने वाला प्रत्येक राष्ट्र इन उद्देश्यों और सिद्धान्तों में अपनी निष्ठा प्रकट करता है। इस प्रकार वह यह स्वीकार करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के क्षेत्र में और इसी प्रकार के अन्य कार्यों में वह संयुक्त राष्ट्र संधि के हस्तक्षेप को स्वीकार करेगा तथा प्रोत्साहन देगा। सदस्य-राष्ट्रों की यह स्वीकृति ही संयुक्त राष्ट्र संधि की इस दृष्टि से सशम बनाती है कि वह शान्ति व सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में, अपनी सीमाओं में रहते हुए हस्तक्षेप कर सके।

अब हम संधि के विभिन्न अंगों को लेते और देखते हैं कि यह अंग अपने किन अधिकारों और कर्तव्यों के बल पर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में समर्थ है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से

संधि के अंगों के अधिकार व कर्तव्य

चार्टर के सातवें अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्रसंधि के ६ प्रमुख अंगों की व्यवस्था की गई है—

- (१) साधारण सभा या महासभा (General Assembly),
- (२) सुरक्षा परिषद् (Security Council),
- (३) आर्थिक व सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council)
- (४) न्याय परिषद् (Trusteeship Council),
- (५) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice), एवं
- (६) सचिवालय (Secretariat)

साधारण सभा या महासभा

महासभा सभ की व्यवस्थापिका सभा कहो जा सकती है जिसमें सभी सदस्य राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। महासभा के कार्यों की प्रकृति मुख्य रूप से निरीक्षणात्मक और अन्वेक्षणात्मक है। इसे विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने की शक्ति है। यह उन प्रयासों को खोज करती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है तथा विश्व के राष्ट्रीय के मध्य पारस्परिक सहयोग की स्थापना की जा सकती है। महासभा शस्त्रों को सीमित करने और निःशस्त्रीकरण के विषयों पर विचार करती है। विश्व में शान्ति स्थापित करना उसका प्रमुख लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह कोई भी सम्भव कदम उठा सकती है।

महासभा की शक्ति और महत्ता आज बहुत उठ गई है। यदि सुरक्षा परिषद अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ पाई जाय तो महासभा को अधिकार है कि वह सम्बन्धित विषय पर फौरन विचार करके सामूहिक उपायों के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए सैनिक कार्यवाही का निर्देश दे। महासभा को यह भी अधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय तनाव वाले क्षेत्रों में स्थिति का निरीक्षण करने और रिपोर्ट देने के लिए एक 'शान्ति निरीक्षण आयोग' की व्यवस्था करे। सदस्य-राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि वे आवश्यकता पडने पर महासभा सुरक्षा परिषद् की सिफारिशों पर सभ के अधीन कार्यवाही करने के लिए सशस्त्र सेना प्रदान करें।

वास्तव में महासभा को हम सम्पूर्ण विश्व का अन्तर्राष्ट्रीय रण-मंच कह सकते हैं। बड़ाका आइन्वर्गरे के मतानुसार महासभा मानव जाति की सभ का एक रूप है जिसमें विश्व के राष्ट्र, राष्ट्रमण्डल, अखण्ड क्षेत्रों, समुदायों पर विचार करने का साधन दृढ़ रहे हैं। कानून व ससदात्मक प्रक्रिया के द्वांचे में महासभा में सदस्य राष्ट्र स्वतन्त्र रूप से अपनी शिकायतें,

प्रस्ताव और सुझाव आदि प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार महासभा विश्व का समुक्त अन्तःकरण (Open Conscience of the World) है। महासभा में अणुबम से लेकर मानवीय कल्याण, भोजन, वस्त्र और आवास साधन तक की सभी समस्याओं पर विचार किया जाता है।

सुरक्षा परिषद

सुरक्षा-परिषद् संधि की कार्य कारणी और उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका निभाता है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की स्थापना की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए सुरक्षा-परिषद् की व्यापक शक्तिवा दी गई हैं और उस पर व्यापक जिम्मेदारिया हैं। चार्टर के अनुच्छेद २४ में स्पष्ट उल्लिखित है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है और उसे यह देखना है कि संधि की ओर से प्रत्येक कार्यवाही जल्दी और प्रभावपूर्ण ढंग से हो सके। अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत समुक्त राष्ट्र संधि के सदस्यों का वक्तव्य है कि वे चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् के फैसलों को मानेंगे और उन पर अमल करेंगे। सुरक्षा परिषद् को जिन अधिकारों व शक्तियों से सम्पन्न बनाया गया है उनका उल्लेख चार्टर के ६, ७, ८ और १२ वें अध्याय में किया गया है। इन अध्यायों के अनुसार शान्ति व सुरक्षा की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से परिषद की शक्तिया निम्नलिखित हैं—

(१) यदि किसी झगड़े से विश्व की शान्ति और सुरक्षा को खतरा हो तो दोनों विवादी पक्ष उस झगड़े को सबसे पहले बातचीत, पृथक्ता, बीच बचाव, मेल, न्यायपूर्ण समझौतों, प्रादेशिक संधियों या व्यवस्थाओं द्वारा या अपनी पक्ष के अन्य शान्तिपूर्ण साधनों से सुलझाने का प्रयास करेंगे, और सुरक्षा परिषद आवश्यकता समझने पर विवादी पक्ष को अपने झगड़े ऐसे साधनों से निपटाने की मांग करेगी। (अनुच्छेद ३३)

(२) सुरक्षा परिषद किसी ऐसे झगड़े अथवा स्थिति की जाच-पड़ताल कर सकती है जो अन्तर्राष्ट्रीय संधि का हट्ट हो सकता हो अथवा जिससे कोई दूसरा झगड़ा उठ सकता हो। सुरक्षा परिषद इस बात का भी निश्चय करेगी कि ये झगड़े अथवा स्थिति जारी रहे तो उनसे विश्व की शान्ति और सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो सकता है अथवा नहीं। ऐसे झगड़े या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा हो जाने पर सुरक्षा परिषद किसी भी समय उसके लिए उचित कार्यवाही करने या सुलझाने के उपायों की सिफारिश कर सकती है। (अनुच्छेद ३४, ३६)

(३) उपरोक्त सिफारिशें करते समय सुरक्षा परिषद को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि सामान्य रूप से कानूनी झगड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय अदालत के विधान के उनबन्धों के अनुसार पेश किया जाये । (अनुच्छेद ३६)

(४) सुरक्षा परिषद ही इस बात का निर्णय करेगी कि कौनसी चेष्टायें शांति को खतरे में डालने वाली, शांति भंग करने वाली और आक्रमण की चेष्टाएँ समझी जा सकती हैं । वही सिफारिश करेगी और तय करेगी कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने अथवा फिर से स्थापित करने के लिए कौनसी कार्यवाही की जानी चाहिए । किसी स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए सुरक्षा परिषद अपनी सिफारिशें करने अथवा किसी कार्यवाही का निश्चय करने से पहिले विवादो पक्षों से ऐसी अस्थायी कार्यवाहियाँ करने की माग करेगी जिन्हें वह उचित या आवश्यक समझे । इन अस्थायी कार्यवाहियों से विवादो पक्षों के अधिकारों, दावों या उनकी हैसियत का कोई अहित न होगा । यदि कोई पक्ष इस प्रकार की अस्थायी कार्यवाहियाँ नहीं करता है तो सुरक्षा परिषद इसका भी विधिवत ध्यान रहेगी । (अनुच्छेद ३६, ४०)

(५) सुरक्षा परिषद अपने फैसलों पर अमल कराने के लिए ऐसी कार्यवाहियाँ भी निश्चित कर सकती है जिनमें सशस्त्र सेना का प्रयोग न हो । वह संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से इस प्रकार की कार्यवाही करने की माग कर सकती है । इन कार्यवाहियों के अनुसार आर्थिक सम्बन्ध पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समाप्त किये जा सकते हैं, समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो और यातायात के अन्त्यान्त्य साधन बन्द किये जा सकते हैं, अथवा राजनीतिक सम्बन्ध विच्छेद किया जा सकता है । (अनुच्छेद ४१)

(६) अनुच्छेद ३१ में बताई गई उपरोक्त कार्यवाहियाँ यदि सुरक्षा परिषद की दृष्टि में नाकाफी हो अथवा नाकाफी शिद्ध हो गई हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने या फिर से स्थापित करने के लिये वह जल, स्थल और वायु सेनाओं की सहायता से आवश्यक कार्यवाही कर सकती है । इस कार्यवाही में संयुक्त राष्ट्रों के सदस्य देशों की जल, पल, वायु सेना विरोध प्रदर्शन कर सकती है, घेरा डाल सकती है अथवा अन्य दूसरे प्रकार की कार्यवाहियाँ कर सकती है । (अनुच्छेद ४२)

(७) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग देने के लिये संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य देशों का यह बर्तव्य बताया गया है कि वे सुरक्षा परिषद के मागने पर और बिना समझौते के अनुसार,

अपनी सशस्त्र सेनाएँ, सहायता और अन्य सुविधाएँ, जिनमें मार्ग अधिकार भी शामिल होंगे, मुहैया करेंगे। सेनाओं की सख्या, उनके प्रकार, उनकी तैयारी और स्थिति आदि के बारे में निश्चय, समझौते या समझौतों से किए जाएंगे और इस प्रकार के समझौतों की बाह्यीत सुरक्षा परिषद को प्रेरणा से जल्दी से जल्दी गुरु को जानी चाहिए। ये समझौते सुरक्षा परिषद और सदस्यों अथवा सुरक्षा परिषद तथा सदस्य दलों के बीच किये जाएंगे और इन पर अमल तब ही किया जा सकेगा जब हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र अपनी अपनी वैधानिक प्रक्रियाओं द्वारा इनकी पुष्टि कर देंगे। चार्टर में यह भी लिखा गया है कि सदस्य सामूहिक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिये अपनी अपनी राष्ट्रीय वायुसेना के दल जल्दी से जल्दी उपलब्ध करायेंगे ताकि संयुक्त राष्ट्र सच सुरक्षित सैनिक कार्यवाही कर सके। इन सैनिक दलों की मस्या और तैयारी आदि के बारे में निश्चय सुरक्षा परिषद अपनी "सैनिक स्टाफ समिति" की मदद से करेगी। सैनिक स्टाफ समिति की मदद से ही सामूहिक कार्यवाही के लिये योजनाएँ बनाई जाएगी। (अनुच्छेद ४३, ४५)

(८) अनुच्छेद ४७ के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि सुरक्षा परिषद को निम्नलिखित प्रश्नों पर स्थगन सलाह देने और सहायता के लिये एक सैनिक स्टाफ समिति बनाई जायगी—(क) अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा परिषद की सैनिक आवश्यकताएँ, (ख) उसके आधीन सेनाओं का प्रयोग और उनकी कमान, (ग) शस्त्रों का नियंत्रण, और (घ) सम्भावित नि शस्त्रीकरण। सैनिक स्टाफ समिति में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के स्टाफ अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि रहेगे। यदि संयुक्त राष्ट्र सच का कोई सदस्य समिति का स्थायी प्रतिनिधि न हो और समिति के दायित्वों को ठीक तरह पूरा करने में उस सदस्य का भाग लेना आवश्यक हो तो समिति उसको अपने साथ काम करने के लिए बुला लेगी। इस अनुच्छेद में यह भी लिखा गया है कि सुरक्षा परिषद के उपयोग के लिए जो सशस्त्र सेनाएँ दी जाएगी, उनका युद्ध सम्बन्धी निर्देशन सैनिक स्टाफ समिति के हाथ में रहेगा और यह समिति सुरक्षा परिषद के अधीन रहेगी। सैनिक स्टाफ समिति उपर्युक्त प्रादेशिक समस्याओं से सलाह लेने के लिए प्रादेशिक उपसमितियों का निर्माण भी कर सकती है। सैनिक स्टाफ समिति को यह अधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(९) जब सुरक्षा परिषद किसी राष्ट्र के विरुद्ध रोकथाम की या अपने निषेधों को अमल कराने की कोई कार्यवाही कर रही हो उस समय यह हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के सामने कुछ विशेष आर्थिक

समस्याएँ उठ खड़ी हों। अतः अनुच्छेद ५० में यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसी सूरत में उस राष्ट्र को, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य हो या नहीं, अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए सुरक्षा परिषद से सलाह लेने का अधिकार होगा।

(१०) यदि संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य पर कोई सशस्त्र आक्रमण होता है तो वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से आत्मरक्षा करने का अधिकारी है। अनुच्छेद ५१ यह व्यवस्था देता है कि उस राष्ट्र पर उस समय तक कोई रोक नहीं होगी जब तक कि सुरक्षा परिषद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्वयं कोई कार्यवाही न करे। आत्मरक्षा के लिए सदस्य जो भी कार्यवाही करेंगे उसकी सूचना तुरन्त ही सुरक्षा परिषद को दी जाएगी। लेकिन इससे सुरक्षा परिषद के अधिकारों और दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने या फिर से स्थापित करने के लिए जब कभी, जो कार्यवाही चाहे, कर सकती है।

(११) स्थानीय सगड़ों और विवादों के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद प्रादेशिक सगठनों और एजेंसियों को माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक सगठन या एजेंसियाँ अपने क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाये रखने की दिशा में जो भी कदम उठाती हैं, उनकी सूचना उन्हें नियमित रूप से सुरक्षा परिषद को देनी पड़ती है।

(१२) सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सभ ने जो दायित्व ग्रहण किया है, उन्हें निभाने का भार भी सुरक्षा परिषद पर ही है। संरक्षित प्रदेशों को किसी भी राष्ट्र के संरक्षण में देते समय संरक्षण सम्बन्धी शर्तें भी सुरक्षा परिषद द्वारा ही तय की जाती हैं। वही इन शर्तों में फेर बदल या संशोधन कर सकती है। यदि ऐसे कुछ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हों जो संयुक्त राष्ट्र सभ के संरक्षण में हों, तो इन क्षेत्रों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के लिए सुरक्षा परिषद आवश्यक कदम उठा सकती है।

सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया और निषेधाधिकार (Voting and Veto power)—अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि में परिषद की शक्तियों के प्रसंग में उसकी मतदान प्रक्रिया और स्थाई सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, व. राश्ट्रवादी, चीन), के निषेधाधिकार का शांति, आन्तरिक, केना आवश्यक है। सभी हम ठीक ढंग से यह गूँथावन कर सकेंगे कि परिषद अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में वहाँ तक सक्षम है।

सुरक्षा परिषद के वर्तमान कुल १५ सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक मत प्राप्त है, लेकिन मतदान की प्रक्रिया बहुत कुछ विभिन्न प्रदेशों के स्वरूप या परिषद् के कार्यों पर निर्भर करती है। परिषद् के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है—(१) साधारण, और (२) असाधारण। साधारण कार्यों में परिषद् के कार्यन्वयन आदि आते हैं। अन्य मामले असाधारण कार्यों में आते हैं, जैसे विवादों के शान्तिपूर्ण समाधान सम्बन्धी मामले, आतंकवादी शक्ति के विरुद्ध प्रतिद्वन्द्व लगाना आदि।

साधारण मामलों पर किन्हीं ९ सदस्यों के स्वीकारात्मक (Affirmative) मत पर्याप्त हैं, लेकिन असाधारण मामलों पर ९ सदस्यों के स्वीकारात्मक मतों में ५ स्थायी सदस्यों के मत शामिल होना आवश्यक है। इन ५ स्थायी सदस्यों में कोई भी सदस्य अपनी असहमति प्रकट करे अथवा प्रस्ताव के विरोध में मतदान करे तो प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं समझा जाता। निषेधाधिकार या विटो (Veto) की यह सुप्रसिद्ध व्यवस्था है।

परिषद का कोई भी सदस्य अथवा अस्थायी सदस्य यदि प्रस्तुत विवाद से सम्बन्धित हो तो उसे भी मतदान करने का अधिकार नहीं रहता। संघ का कोई भी सदस्य-राष्ट्र ऐसे किसी भी प्रश्न पर जो विचारधीन हो सुरक्षा परिषद में हो रहे वाद-विवाद में भाग ले सकता है। सुरक्षा परिषद, यदि उचित समझे तो ऐसे किसी भी राष्ट्र को जो सुरक्षा परिषद अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सदस्य न हो, उससे सम्बन्धित विवाद पर विचार करते समय उसे बैठकों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित कर सकती है। इस प्रकार आमन्त्रित होने वाले राष्ट्र मतदान में भाग नहीं ले सकते।

दोहरा निषेधाधिकार (Double Veto)—जब यह प्रश्न उठता है कि कोई साधारण मामला माना जाये अथवा असाधारण, तब दोहरे निषेधाधिकार (Double Veto) का प्रयोग होता है अर्थात् पहले तो निषेधात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को साधारण विषय ठानने से रोका जाता है और तत्पश्चात् प्रस्ताव के तत्वों (Substance) के विरोध में दोहरा मत दिया जाता है।

निषेधाधिकार की समालोचना—सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया के अध्ययन से स्पष्ट है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में कोई भी किसी भी प्रस्ताव के विरोध में मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। इसके केवल दो ही अपवाद हैं—प्रथम, प्रक्रिया सम्बन्धी मामले, द्वितीय, वे मामले जिनमें स्वयं विरोध में मत देने वाली एक महा शक्ति एक पक्ष हो। आलोचकों का कहना है कि इस निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद अपने सामूहिक सुरक्षा के कार्य में असफल हो गई है। बर्नोल्ड फोर्स्टर (W. Arnold

Foster) के अनुसार "निषेधाधिकार का भय सम्पूर्ण व्यवस्था पर छाया हुआ है। ऐसी व्यवस्था के रक्त में ही पक्षाघात है। यह उस कार के समान है जिसका स्टार्टर (Starter) किसी भी समय उसकी यन्त्र व्यवस्था में गड़बड़ करके उसका इन्जिन को रोक सकता है।"

निषेधाधिकार की उपयोगिता एवं आवश्यकता के बारे में सभी विचारक एक मत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विपक्ष में प्रचलित चार बातें कही जाती हैं—

प्रथम, यह कहा जाता है कि निषेधाधिकार के कारण ही सुरक्षा-परिपद शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था के अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में असमर्थ हो गई है। यह अधिकार ही अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शान्तिपूर्ण हल में सबसे बड़ा बाधक है। ऐसी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, परन्तु निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिपद ऐसा नहीं कर पाती। इस विषय में ट्रिग्वेली (Trygve Lie) ने कहा था कि "संयुक्त राष्ट्रसंघ निषेधाधिकार के कारण नपुंसक है। यह महा शक्तियों के संघर्ष द्वारा पक्षाघातग्रस्त कर दिया गया है।"

दूसरे, निषेधाधिकार विधि के समक्ष समता और राष्ट्रों की सम्प्रमुख-समानता के मौलिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है।

तीसरे, निषेधाधिकार पृष्ठपोषक राज्यों (Client States) की एक ग्यूनाधिक खुली राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। यह हो सकता है कि प्रत्येक म्यामो सदस्य अपने मित्र राष्ट्रों को निषेधाधिकार का संरक्षण प्रदान करे। ऐसी स्थिति में यह भय पैदा होना स्वाभाविक है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य स्थायी सदस्यों के नेतृत्व में गुटों में विभक्त हो जायेंगे। यह भय निराधार नहीं है। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और सोवियत रूस के नेतृत्व में ऐसे दो शक्तिशाली गुट जन्म ले भी चुके हैं।

चौथे, निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिपद में जो गतिरोध उत्पन्न होता रहा है, उसने विश्व के राज्यों की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में आस्था को पूरी तरह डगमगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सच की तरफ से निराश होकर ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए NATO, SEATO जैसे प्रादेशिक सुरक्षा संगठनों का आश्रय लिया है।

निषेधाधिकार की व्यवस्था में नि मन्देह कुछ दोष अवश्य हैं, किन्तु हम व्यवस्था को बिगड़ कराना न तो चाहती हैं और न व्यावहारिक ही। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी संगठन की सफलता सभी मिल सकती है जब उसे विश्व की महान शक्तियों का सहयोग प्राप्त हो परन्तु इन

महान देशों का किसी ऐसे संगठन में भाग लेना सम्भव नहीं है जिसमें अन्य देश केवल अपने बहुमत से इसे किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य कर दें। इसे रोकने का एक मात्र उपाय निषेधाधिकार ही है। शूमन (Shuman) ने लिखा है “इसके निमित्तों ने यह स्पष्ट ही समझा था कि यदि सुरक्षा परिषद किसी महान राज्य के विचार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करती है तो इसका अर्थ विश्व शांति नहीं बरन् युद्ध होगा।

निषेधाधिकार एक अनिवार्यता है। विद्वानों और विधि शास्त्रियों द्वारा व्यक्त विचारों और अब तक की सुरक्षा परिषद की कार्यवाहियों के आधार पर अनेक कारण इस पक्ष में प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

प्रथम, संयुक्त राष्ट्र सभ को सुचारु रूप से चलाने के लिए निषेधाधिकार का होना अत्यावश्यक है। निषेधाधिकार इस सभ की अनुमति पर आधारित है कि बिना महा शक्तियों के सहयोग के सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था सम्भव नहीं है। राष्ट्र सभ की असफलता का एक प्रमुख कारण संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत रुस का उससे दूर रहना था। आज भी रुस और अमरीका निषेधाधिकार के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में रहने को उद्यत नहीं होंगे और उनके बिना संयुक्त राष्ट्रव्यवस्था निरर्थक तथा निष्फल होकर राष्ट्र संघ की कहानी की पुनरावृत्ति कर देगा। इस सम्बन्ध में विशिन्सकी (Vishinsky) का मत है कि “निषेधाधिकार की शक्ति के अन्त का अर्थ होगा संयुक्त राष्ट्र सभ का अन्त, क्योंकि एक महा शक्ति के विरुद्ध प्रयोग का अर्थ है, युद्ध की निश्चित निम्नगण।” निषेध का मूल विचार स्वर्गीय पण्डित नेहरू के शब्दों में “विश्व युद्ध की सम्भावना को हटाने और विवादों को सम्मेलनों द्वारा सुलझाना है।”

दूसरे, यह कहना गलत है कि निषेधाधिकार के फलस्वरूप सुरक्षा परिषद वा काम ठप्प हो गया है। अब तक का अनुभव बताता है कि निषेधाधिकार शक्ति के इतने अधिक प्रयोग होने के कारण किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इसने अधिक बाधा नहीं पहुँचाई है। जिन निर्णयों के लेने में यह बाधक बना है उनके न लेने पर भी विश्व शांति में किसी प्रकार का खतरा नहीं पहुँचा है।

तीसरे कई बार निषेधाधिकार पत्रापातपूर्ण निर्णय लेने में बाधक रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों की शांतिपूर्ण उपायों से सुलझाने में सफल हुआ है। उदाहरणार्थ, जब कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत था तो सोवियत रुस के निषेधाधिकार के प्रयोग ने स्थिति को सम्हालने में और सत्य की रक्षा करने में सहायता प्रदान की। यदि निषेध की व्यवस्था

न होती तो संयुक्त राष्ट्र साथ पूरी तरह एक गुट विशेष का साथ बन जाता और उस गुट विशेष को अपनी मनमानी करने की पूरी छूट मिल जाती।

चौथे सुरक्षा परिषद् की सीमित निषेधाधिकार प्रणाली दोषपूर्ण होते हुए भी राष्ट्र साथ परिषद् की सर्वसम्मति मतदान प्रणाली से कहीं अधिक श्रेष्ठ है।

पाचवें, सुरक्षा परिषद् का अधिकांश कार्य महासभा द्वारा सम्हाल लिया गया है तथा १९५० में 'शांति के लिये एकता' का प्रस्ताव पास होने के बाद से निषेधाधिकार का तथा निषेध (Veto) करने वाली सुरक्षा परिषद् का महत्व घट गया है। अब इसका प्रभाव मुख्य रूप से सदस्यता के सम्बन्ध में ही रह गया है। न तो यह कोई नया अन्तर्राष्ट्रीय संधि उत्पन्न करता है और न इसके आगे ही बढ़ता है। निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र साथ के कार्य को पगु भी नहीं करता। इसके होते हुए भी महासभा द्वारा अनेक कार्य सम्पादित किये जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र साथ की वास्तविक सफलता तो इस बात में निहित है कि वह विभिन्न राज्यों से अपने निर्णयों को न्यायवित्त कर सकने में सफल हो।

छठे, अनेक और भी ऐसे व्यावहारिक पग उठाये जा चुके हैं जिनने निषेधाधिकार के महत्व को पूर्णपेक्षा बहुत कम कर दिया है। अन्तरिम समिति या लघु सभा (Interim Committee or Little Assembly), शांति निरीक्षण आयोग (Peace Observation Commission) तथा सामूहिक उपाय समिति (Collective Measures Committee) आदि की स्थापना के द्वारा महासभा ने सामूहिक सुरक्षा-व्यवस्था को निषेधाधिकार के दुष्प्रभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नई सदस्यता और शांति-पूर्ण समझौतों के सम्बन्ध में तो निषेधाधिकार आशिक है, अतः समाप्त होना चाहिये। परन्तु शांति भंग और आक्रमण की स्थिति में रौनिक कार्यवाही के लिये इस अधिकार का प्रयोग अत्याज्य है, अतः इसे बनाये रखना लाभप्रद है।

आर्थिक व सामाजिक परिषद्

यह साथ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से साथ के अराजनीतिक प्रकृति के लक्ष्यों को पूरा किया जाता है। यह संस्था अपने सहायक अंगों द्वारा विश्व के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करती है। यह संसार से गरीबी और हीनता को मिटा कर एक स्वस्थ, विकसित और समोन्नत विश्व

के निर्माण में प्रयत्नशील है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में उठ खड़े होने वाले वार विवादों को व झगड़ों को भी यह परिपक्व मिटाने का प्रयत्न करती है। इस परिपक्व द्वारा स्थापित विभिन्न आर्थिक व प्रावधिक सहायता योजनाओं के माध्यम से विच्छेद हुई जातियों और जन समुदायों के विकास का प्रयत्न किया जाता है। परिपक्व का मुख्य लक्ष्य मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देना है। इस दायित्व की पूर्ति के लिए परिपक्व ने विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों का अध्ययन किया है और इनके लिए विभिन्न आयोग स्थापित किये हैं। सरणार्थियों व राज्यहीन व्यक्तियों के लिए निरम बनाये गये हैं, ट्रेड-यूनियनों के अधिकारों का, दासता और बेपार का अध्ययन किया गया है।

यद्यपि आर्थिक व सामाजिक परिपक्व के उपरोक्त सभी कार्य अराजनीतिक हैं, तथापि अप्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण तैयार होने में सहायता मिलती है। आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग के कारण राष्ट्रों में जो पारस्परिक सद्भावना और सहयोग की प्रवृत्ति जागृत होती है वह दूषित राजनीतिक वातावरण को सुधारने में अपरोक्ष रूप से सहायन होती है। मानव-अधिकारों में आर्थिक व सामाजिक अधिकारों के अतिरिक्त राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। इन मानव अधिकारों की प्रोत्साहन देने के उत्तरदायित्व के फलस्वरूप आर्थिक व सामाजिक परिपक्व राजनीतिक क्षेत्र में कुछ न कुछ सुधारात्मक अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य डालती है। अर्द्ध विकसित व अल्प विकसित देशों को आर्थिक व प्रावधिक सहयोग दे कर यह परिपक्व उन्हें उन्नत बनाने में और बड़ा आपिज स्थिरता लाने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि आर्थिक स्थिरता अन्तर्गत राजनीतिक स्थिरता को जन्म देती है। जब राष्ट्रों में राजनीतिक स्थिरता की प्रोत्साहन मिलती है तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति इससे अप्रभावित नहीं रह सकती। राजनीतिक स्थायित्व स्वस्थ राजनीतिक दृष्टिकोण के विकास में बड़ा सहायक हुआ है।

न्याय-परिपक्व व न्याय-व्यवस्था

संघ का चौथा महत्वपूर्ण अंग 'न्याय-परिपक्व' (Trusteeship Council) है। चार्टर के अध्याय १२ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था (Trusteeship System) को समझाया गया है और अगले अध्याय में न्याय-परिपक्व पर प्रकाश डाला गया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की न्याय पद्धति (Trusteeship System) राष्ट्रसंघ की संरक्षण-व्यवस्था (Mandate System) का विकसित और उच्चतम रूप है जिसके प्रमुख उद्देश्य, चार्टर अनुच्छेद ७६ के अनुसार ये हैं—

- (१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना,
- (२) न्यास प्रदेशों के निवासियों का स्व शासन की दिशा में विकास करना
- (३) मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ाना और यह भाव जागृत करना कि ससार के सभी लोग अग्योन्या-धित हैं।
- (४) सामाजिक आर्थिक, तथा वाणिज्यिक मामलों में समुक्त राष्ट्र-संघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासक राष्ट्रों व न्यास पद्धति के प्रदेशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं जिसका अतः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव पड़ता है। न्यास पद्धति के अन्तर्गत आने वाले सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेशों को स्वयं सुरक्षा परिषद का संरक्षण मिलता है जब कि सामान्य न्यास प्रदेश महासभा व न्यास परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और उनके शासन संचालन के लिए एक राज्य, अनेक राज्यों अथवा स्वयं समुक्त राष्ट्र संघ को संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। संरक्षण परिषद का काम है कि वह उन राज्यों पर नियन्त्रण रखे जो संरक्षक (Trustees) बनाये गये हैं। इन संरक्षकों को समुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ कार्य सौंपे हैं, जैसे संरक्षक प्रदेशों की राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रयास करना, दुराचार व भ्रष्टाचार को दूर करना, सदैव व्यवहार करना, स्वायत्त शासन का विकास करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्रियात्मक कदम उठाना आदि। न्यास परिषद् शासन कर्ता अथवा संरक्षक देश से न्यास प्रदेश की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करती है। इन हेतु परिषद द्वारा तैयार की गई प्रश्नावली में न्यास प्रदेशों के शासन से सम्बन्धित सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। न्यास परिषद् प्रतिवर्ष अपने निरीक्षक मण्डल पूर्वी अफ्रीका के न्यास प्रदेशों, प्रशान्त महासागर के न्यास प्रदेशों, टागानिका, सीमाजीलैण्ड आदि में इस प्रकार भेजती है कि तीन वर्षों में एक बार प्रत्येक प्रदेश का निरीक्षण हो जाय। ये निरीक्षक मण्डल पराधीन प्रदेशों पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण के अत्यन्त प्रभावशाली साधन हैं। ये परिषद् का 'नेत्र और कान' है क्योंकि एक ओर तो ये निरीक्षक मण्डल परिषद् के सदस्यों को व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष रूप से न्यास परिषद् के निवासियों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करते हैं

और दूसरी ओर ये न्यास-प्रदेशों की जनता को इस बात का सन्तोष प्रदान करते हैं कि परिषद् उनकी स्थिति की वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं है। ये निरीक्षक-मण्डल निष्पक्ष और स्वतन्त्र अन्वेषण करने में सक्षम हैं। ये निरीक्षक मण्डल न्यास प्रदेश में शासन सरकार की विभिन्न नीतियों का अध्ययन ही नहीं करते हैं बल्कि सुधार के लिए आवश्यक सुझाव भी देते हैं।

स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सच न्यास-परिषद् के न्याय व्यवस्था के माध्यम से विश्व के विभिन्न प्रदेशों में शान्ति, सुरक्षा और स्वायत्त-शासन को प्रोत्साहन देता है और इस प्रकार स्वस्थ राजनीतिक-आर्थिक वातावरण बना कर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को उचित दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सच का मुख्य न्यायिक अंग है। सच के सभी सदस्य इस न्यायालय के अधीन हैं। न्यायिक प्रश्नों पर आधारित उनके सभी विवादों का निर्णय इस न्यायालय में अन्तर्राष्ट्रीय विधानों के अनुसार होता है। वह देश भी, जो संयुक्त राष्ट्रसच का सदस्य न हो, सुरक्षा-परिषद् की सिफारिशों के आधार पर महासभा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान का पक्षकार (Party) बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पर अपने मामले न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किये जा सकते, केवल राज्य ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। चार्टर के अनुच्छेद ६४ में यह व्यवस्था है कि यदि कोई पक्षकार या विवादी न्यायालय के निर्णय को न माने तो सुरक्षा परिषद् की सूचित कर दिया जाता है। परिषद् स्थायी सदस्यों की सहमति और ९ सदस्यों के बहुमत से यह निश्चित करती है कि न्यायिक निर्णय का निष्पादन कराया जाय। अनुच्छेद ४१ के अनुसार परिषद् सैनिक बल-प्रयोग की छोट कर ऐसे उपायों का प्रयोग कर सकती है जिनमें आर्थिक सम्बन्ध, रेल, समुद्र, राब, रेडियो, अन्य यातायात के साधनों एवं राजनीतिक सम्बन्धों के अनुच्छेद सम्मिलित हैं इन उपायों के असफल होने पर, अनुच्छेद ४२ के अनुसार, परिषद् जल, स्थल और वायु सेना द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। हेनरी क्लेन्टन ने इस व्यवस्था की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि "इस बात की दृष्टि में रखते हुए कि चार्टर में न्यायालय के निर्णय के अनुपालन न होने की दशा में अपील की प्रक्रिया दी हुई है, यह विचार करना बर्ज़न है कि ऐसे अनुपालन को शान्ति के लिए घमकी अपवा उत्तरा भग कहा जाये।" ओपेनहेम का विचार है कि इस प्रकार का सचीन होना चाहिए जिससे सुरक्षा-परिषद्

का कार्य आदेशात्मक हो जाय और इस विषय में सुरक्षा-परिपद् की कार्यवाही सचिवी सदस्यों के मतव्यवहारे को आवश्यकता के अनुसार ही मुक्त हो जाय ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय विवादों का निर्णय करने के अतिरिक्त, मांग की जाने पर, महासभा व सुरक्षा परिपद् की जयवा सयुक्त राष्ट्र सभ के किसी अन्य अंग को वैधानिक प्रश्न पर परामर्श भी दे सकता है । इसके अनिश्चित वादों पक्ष अपने मनोरथ के अनुसार उत्तम कानूनी राय प्राप्त कर सकता है जिसके औचित्य व अनौचित्य की भली भाँति समझता है । स्टोन ने लिखा है "दोषी राज्य पोल खुलने से बचने के लिए विवाद के सहमतिपूर्ण निरादारे के लिए तैयार हो जाते हैं । न्यायालय के मत का नैतिक बल भी बहुत अधिक होता है और यदि कोई राज्य अडिगलपना करे तो उसे विश्व के जनमत के सम्मुख भर्त्सना सहनी पड़ती है । अतः यह परामर्शदात्री मत चाहे कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, परन्तु राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान है ।

सचिवालय

सयुक्त राष्ट्र सभ के कार्यों के सम्पादन के लिए सचिवालय की व्यवस्था है । महासचिव की अनेक ऐसे अधिकार मिले हैं और उसे अनेक ऐसे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं । चार्टर के अनुच्छेद ९९ के अनुसार यह व्यवस्था है कि "यदि महासचिव यह समझे कि किसी मामले में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है तो वह सुरक्षा परिपद् का ध्यान उस मामले की ओर आकर्षित कर सकता है ।" यह महासचिव का निश्चय ही सभ से बड़ा अधिकार है जिसके चल पर वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर विश्व-शान्ति कायम रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है । इसके अतिरिक्त अनुच्छेद १०० (२) के अनुसार सयुक्त राष्ट्र सभ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि वह महासचिव और उसके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को मानेगा और उन दायित्वों के निर्वाह में किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा ।

महासचिव का सभ में महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण उसके द्वारा शक्ति से दुष्प्रयोग की सम्भावनायें भी बढ़ जाती हैं । इसी कारण भूतपूर्व सोवियत प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने यह गुस्ताव दिया था कि महासचिव के वर्तमान पद को समाप्त कर देना चाहिये तथा इसके स्थान पर ट्रिब्यूनल (Tribunate) की स्थापना कर दी जाये अर्थात् तीन राष्ट्रों की कार्य-कारिणी बना दी जाये जो सोवियत रूस, सयुक्त राज्य अमेरिका तथा अखण्ड देशों का प्रतिनिधित्व करे । तीनों के पास वीटो का अधिकार होना

चाहिये। इस सुझाव को अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अनुपयोगी समझा गया है।

संयुक्त राष्ट्र सभ में महासचिव के पद पर अभी तक तीन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है—ट्रिम्बेली, हैमर शोल्ड तथा ऊ-याण्ट। वर्तमान समय में ऊ-याण्ट ही इस पद पर हैं।

महासचिव का पद बड़ा महत्व का है और उसे न केवल प्रशासनिक अपितु राजनैतिक कार्य भी करने पड़ते हैं। राजनीतिक कार्यों में वह बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। १९५० में चीन के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर रूस द्वारा सभ को कार्यवाहियों में भाग न लेने की घोषणा करने पर, इस एकदम को टालने के लिए महासचिव ट्रिम्बेली ने अथक प्रयास किये और समझौते के लिए योजनाएं प्रस्तुत की। पुनः १९५० में सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव ट्रिम्बेली ने कोरिया समस्या पर सर्वप्रथम उपयुक्त प्रकाश डाला और उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कार्यवाही करने की प्रभावकारी अजील की। इसके बाद परिषद द्वारा जब उत्तरी कोरिया के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने की छूट दे दी गई तो उन सैनिक कार्यवाहियों के लिए सदस्य राज्यों का सहयोग अजित कराने और उनमें समन्वय स्थापित कराने का उत्तरदायित्व भी महासचिव की ही उठाना पड़ा।

इसी प्रकार कांगो में छिड़े गृह-युद्ध के सम्बन्ध में भी महासचिव को बहुत बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ा। गृह-युद्ध को समाप्त करके शांति की स्थापना करने के लिए राष्ट्र सभाय सैन्य कागो में प्रविष्ट हुई और महासचिव हैमरशोल्ड ने अत्यन्त साहस और सूक्ष्मज्ञ के साथ इस सैनिक अभियान का निदेशन किया। वह अपने दायित्वों को निभाते हुए, प्राणों की परवाह न करते हुए भी, अनेक बार कागो गये और इसी क्रम में उन्हें हवाई दुर्घटना में प्राणों से हाथ भी धोना पड़ा।

महासचिव की राजनीतिक जिम्मेदारी का ताजा उदाहरण सन् १९६५ में भारत पाक युद्ध में अंश को गई ऊ-याण्ट की भूमिका से मिलता है। उन्हीं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप दोनों देशों में युद्धबन्दी की अवस्था निवट आई।

वस्तुतः महासचिव की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने के अवसर मिलते हैं। महासचिव का विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों मण्डलों के साथ निरन्तर सम्पर्क रहता है, अतः उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वह संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों को प्रभावित कर सके। उसे यह स्वतन्त्रता होती है कि वह सदस्य राज्यों के विदेश मन्त्रालयों में जा सके और स्वतन्त्रतापूर्वक सलाह मागकर कर सके। उसे सामंजस भाषण देने का भी अधिकार होता है। अपने-भाषणों द्वारा वह विरल जनमत की

प्रभावित कर सकता है । इतना ही नहीं अपनी रिपोर्टों में भी वह इस तरह की सिफारिशें कर सकता है कि सच को कौनसी नीति एवं कार्यक्रम अपनाना चाहिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की विश्व-शान्ति में भूमिका

अथवा

संघ का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव
(The Role of U. N. O. in World Peace)

or

(The Impact of U N O in the field of International Politics)

संयुक्त राष्ट्रसंघ को राष्ट्रों के बीच के राजनीतिक झगड़े सुलझाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । अपने इन महत्वपूर्ण कार्य के माध्यम से संघ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटना-चक्र को बड़ा भारी प्रभावित करता है । चार्टर द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य यद्यपि मुख्यतया सुरक्षा परिषद के कंधों पर डाला गया है तो भी कुछ विशेष परिस्थितियों में महासभा भी इन पर अपना योगदान कर सकती है । इन विवादों को तय करने का सुरक्षा-परिषद के पास कोई विशेष तरीका नहीं है । वह अनेक तरीकों में से समयानुसार किसी को भी अपना सकती है । सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रों के केवल राजनीतिक विवादों पर ही विचार किया जाता है । वैधानिक विवादों पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय विचार करता है । संयुक्त राष्ट्र संघ के मस्युल २५ वें को इसकी अल्पावधि में छोटे बड़े अनेक राजनीतिक विवाद प्रस्तुत हुए हैं । उनका समाधान करने में जहाँ इसे उल्लेखनीय सफलताएँ मिली हैं, वहाँ महा-शक्तियों की अड़नेवाजियों के फलस्वरूप गम्भीर असफलताओं का भुल भी देना पड़ा है । अग्रिम पवित्तियों में हम कुछ प्रमुख विवादों की प्रकृति और उन्हें हल करने में संघ के योगदान का मूल्यांकन सक्षेत्र में कर रहे हैं ।

रूस ईरान विवाद

संयुक्त राष्ट्रसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला यह प्रथम विवाद था । ईरान के एक प्रान्त आजरबाइजान (Azerbaijan) में सोवियत फौजें घुसी हुई थी । १६ जनवरी, १९४६ को ईरान ने सुरक्षा परिषद से शिकायत करते हुए रूस पर ईरान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और ईरानी प्रान्त में रूसी सेनाओं की उपस्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए खतरा बताया । सुरक्षा परिषद में आरोप-प्रत्यारोप चले और रूस ने यह सकेत दिया कि वह ईरानी सरकार के साथ प्रत्यक्ष वार्ता करना पसन्द करेगा । परिषद् ने दोनों पक्षों को सीधे बातचीत करने और वार्ता की प्रगति से सूचित करने का सुझाव दिया । जब वार्ता से कोई परिणाम न निकला तो परिषद् ने सोवियत संघ से प्रार्थना की कि वह ५ मई, १९४६ तक ईरान से अपनी फौजें बुला ले । इसी बीच ईरान और रूस के मध्य समझौता हो गया और महासचिव ने बताया कि परिषद को अब इस प्रश्न

पर विचार करने का अधिकार नहीं रहा है। २२ मई, १९४६ को पैहरान तथा मास्को ने घोषणा की कि सोवियत सेनाएँ ६ मई को ही ईरान खाली कर चुकी हैं।

ईरानी सरकार को मुल्कशाने में यद्यपि सुरक्षा-परिषद द्वारा की गई किसी विशेष कार्यवाही का भाग नहीं था, किन्तु परिषद में हुई बहसों ने समस्या पर प्रबल दल विरोधी लोकमत जागृत कर दिया और रूस ने अपनी सेनाएँ ईरानी भूमि से हटा लेना उचित समझा।

यूनान विवाद

३ जनवरी, १९४६ को रूस ने सुरक्षा परिषद से शिकायत की कि महायुद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी ब्रिटिश फौज यूनानी भू-प्रदेश पर बनी रह कर उस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनाव पैदा कर रही हैं। परिषद में विचार विमर्श के दौरान यूनानी प्रतिनिधि ने कहा कि यूनानी जनता ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति को जन-यवस्था और सुरक्षा के लिए अनिवार्य समझती है। इस स्थिति में यह स्वाभाविक था कि सुरक्षा परिषद ने मामले की सुनवाई समाप्त करने का निश्चय कर लिया। दिसम्बर १९४६ में यूनान ने परिषद से शिकायत की कि पड़ोसी साम्यवादी देश छापामारों को सहायता दे रहे हैं और यूनान के साथ तनाव पैदा कर रहे हैं। परिषद द्वारा नियुक्त आयोग ने मई, १९४७ में इस शिकायत की गृष्टि की। परिषद ने जब आगे जाच-पड़ताल करने का प्रयत्न किया तो सोवियत रूस ने वोटों का प्रयोग कर दिया। इसके बाद महासभा ने जाच-पड़ताल के लिए आयोग नियुक्त किया जिसे अल्बानिया, बल्गेरिया व यूगोस्लाविया ने अपनी सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अन्त में ३ मुख्य कारणों से यूनानी समस्या का समाधान हो गया —

(१) महासभा द्वारा नियुक्त आयोग की उपस्थिति में साम्यवादी देशों द्वारा पूर्वोक्त मान्यता में छापामारों को सहायता नहीं दी जा सकी।

(२) टोटो-स्टालिन-विवाद के कारण यूनानी छापामारों को यूगो-स्लाविया की सहायता बन्द हो गई।

(३) संयुक्त राष्ट्र सभ के निरोधन में अमेरिका द्वारा यूनान को पूरी पूरी आर्थिक व सैनिक सहायता मिली।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सभ के सामयिक और साहजिक हस्तक्षेप से दक्षिणी यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश साम्यवादी नियन्त्रण में जाते जाते बच गया।

बर्लिन की समस्या

१९४५ के पोट्सडम सम्झौते के अनुसार बर्लिन नगर रूस, फ्रांस,

ब्रिटेन और अमेरिका के नियन्त्रण में बांट दिया गया था। पश्चिमी बॉलिन मित्र राष्ट्रों के नियन्त्रण में और पूर्वी बॉलिन रूस के नियन्त्रण में रहा था। तभी से आज तक यह स्थिति चली आ रही है। पोतुसदम सम्मेलन में यह भी तय हुआ था कि दोनों जर्मनी की आर्थिक एकता कायम रखी जायगी। लेकिन चारों देश इस निर्णय को कायम न रख सके। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा नई मुद्रा प्रचलित करने से क्षुब्ध हानर रूस ने १ मार्च, १९४८ को पश्चिमी बॉलिन के जल और रेल मार्ग बन्द कर दिये। इस नाके-बन्दी का प्रत्युत्तर पश्चिमी राष्ट्रों ने हवाई मार्ग का अधिकाधिक प्रयोग करके दिया।

२३ सितम्बर, १९४८ को सुरक्षा-परिपद में रूसी नाके-बन्दी के विरुद्ध शिकायत की गई और इस कार्यवाही को शान्ति के लिए चातक बताया गया। लगभग महाशक्तियों के बीच था, अतः सुरक्षा-परिपद समस्या पर विचार करने के अतिरिक्त और कुछ भी कर सन्ने में असमर्थ थी। इसी मध्य चारों महाशक्तियों के बीच अनौपचारिक रूप से समस्या को सुलझाने की बातचीत चलती रही और ४ मई १९४९ को फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका ने सुरक्षा-परिपद को सूचित किया कि बॉलिन समस्या पर रूस से उनका समझौता हो गया है।

यद्यपि समस्या का हल महाशक्तियों के आपसी समझौते से हुआ, तथापि संयुक्त राष्ट्र सभ ने विचार-विमर्श, पत्र-व्यवहार और सम्पर्क आदि के माध्यम से दोनों पक्षों को परस्पर मिलने के लिए महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी पृष्ठभूमि तैयार की और स्वयं तथा सुविधायें उपलब्ध की।

कोरिया संकट

यह एक ऐसा गम्भीर संकट था जिसमें संयुक्त राष्ट्रसंघ की सामाजिक सुरक्षा और दण्ड व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा थी और जिसके समाधान के लिए सत्र को पहली बार सैनिक कार्यवाही का आसरा लेना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के बाद विभाजित उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में विरोध बढ़ता गया। २५ जून, १९५० को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर विशाल सैनिक आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सभाय जाव-गडनाल से इसकी पुष्टि हो गई। इन दिनों रूस ने संयुक्त राष्ट्र सत्र की बैठकों का बहिष्कार कर रखा था। सुरक्षा-परिपद ने उत्तरी कोरिया की आक्रमणकारी घोषित करके सैनिक हस्तक्षेप का निश्चय किया। जुलाई, १९५० में संयुक्त राष्ट्र सभाय सत्र के अधीन लगभग सोलह राष्ट्रों की एक संयुक्त कमान की रचना हुई जिसका सेनापति जनरल मैकार्थर बनाया गया। पहले तो संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना को सफलता मिली लेकिन जब संधीय फौजों ने ३८ अक्षांश पार करके उत्तरी कोरिया क्षेत्र में लड़ना शुरू किया तो साम्यवादी चीन के सैनिक उत्तरी कोरिया की ओर में लड़ाई में बूढ़ पड़े।

एक ओर तो संयुक्त राष्ट्रसच की सैनिक कार्यवाही जारी रही और दूसरी ओर सच ने शान्तिपूर्ण समझौते के प्रयास जारी रमे। महासभा ने चीन और उत्तरी कोरिया को युद्ध-सामग्री भेजने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया पर इसका कोई फल नहीं निकला। युद्ध की भीषणता से दोनों ही पक्ष तंग आ गये और विराम-सन्धि की चर्चा चलने लगी। अन्त में १० जुलाई, १९५१ को राष्ट्र सघीय संयुक्त कमान और साम्यवादो चीन व उत्तरी कोरिया की संयुक्त कमान के प्रतिनिधियों में अधिकांश विषयों पर समझौता हो गया। शेष मतभेदों और युद्ध बन्धियों के मुसले पर जून, १९५३ में समझौता सम्पन्न हो सका।

संयुक्त राष्ट्र सच के प्रयासों से कोरिया का युद्ध विश्व-युद्ध बनने से रक गया। ए. ई. स्टीवेंसन के शब्दों में—“संयुक्त राष्ट्र सच के इस प्रथम महान सामूहिक सैनिक कार्यवाही ने यह सिद्ध कर दिया कि यह संगठन शक्ति और शान्ति दोनों से काम लेने के रूपों को ग्रहण करने योग्य है।” वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रबल सैनिक शक्ति के बल पर ही सच कोरिया युद्ध में सफल हो सका।

फिलिस्तीन विभाजन की समस्या

प्रथम महायुद्ध के बाद यह प्रदेश संरक्षण प्रदेश (Mandate) के रूप में ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त फरवरी, १९४७ में ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि उसके लिए इस मेण्डेट के शासन-प्रबन्ध को चलाना सम्भव नहीं है। अप्रैल १९४७ में ब्रिटेन ने यह समस्या महासभा के सामने पेश कर दी। महासभा द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने अगस्त, १९४७ में सिफारिश की कि फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया जाय—एक भाग में अरब राज्य की स्थापना हो और दूसरे में यहूदी राज्य की। महासभा ने सिफारिश स्वीकार कर ली। लेकिन फिलिस्तीन विभाजन के प्रश्न पर अरबों और यहूदियों में सघर्ष बढ़ता गया। दोनों पक्षों में प्रभावो युद्ध-विराम के सभी संयुक्त राष्ट्र सघीय प्रयास विफल हो गये। १४ मई, १९४८ को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर से अपना शासन प्रबन्ध हटा लिया (जिसकी घोषणा १५ मई को की गई) और यहूदियों ने फिलिस्तीन में इजराइल राज्य की घोषणा कर दी। यद्यपि में ईराक, लेबनान, ट्रांस-जोर्डन आदि अरब राष्ट्रों ने फिलिस्तीन पर आक्रमण कर दिया। इजराइल के प्रत्याक्रमण की अरब राष्ट्र नहीं सँठ सके। ११ जून, १९४८ को संयुक्त राष्ट्र सघीय प्रतिनिधि बर्नाडोट के प्रयत्नों से दोनों पक्षों में चार सप्ताह के लिए युद्ध विराम हो गया किन्तु उपद्रव चलते रहे और १७ सितम्बर को बर्नाडोट भी गोली के शिकार हुए। सुरक्षा परिषद

ने अब डा० राल्फ जे बन्च को कार्यवाहक मध्यस्थ नियुक्त किया। २६ दिसम्बर को तीसरी बार युद्ध-विराम स्थापित हुआ। इसके बाद महासभा ने एक "मध्युक्त राष्ट्र समझौता आयोग" (U N Conciliation Commission) नियुक्त किया जिसने अनेक विकट प्रश्नों को सुलझाया और इजराइल व पड़ोसी राज्यों में सीमा सम्बन्धी सन्धिया सम्पन्न हुई।

यद्यपि मध्युक्त राष्ट्रमण्डल के प्रयासों से फिलिस्तीन विभाजन की समस्या का समाधान हो कर इजराइल और अरब राष्ट्रों में सन्धिया हो गई लेकिन इस क्षेत्र में स्थायी शान्ति की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अक्टूबर, १९५६ में मिस्र और इजराइल के मध्य पुनः युद्ध छिड़ा तथा रूसी हस्तक्षेप व राष्ट्र-गंभीर प्रयासों से शान्ति स्थापित हुई। इसके बाद १९६७ के मध्य एक बार फिर अरब राष्ट्रों और इजराइल के बीच घन-घोर युद्ध छिड़ा तथा मध्युक्त राष्ट्र संधीय प्रयत्नों से अस्थायी तौर पर शान्ति हो गई। इण्डोनेशिया विवाद

द्वितीय महायुद्ध के पूर्व इण्डोनेशिया पर हालैण्ड का अधिकार था। युद्ध काल में जापान ने अधिकार जमा लिया। जापान की पराजय के बाद इण्डोनेशिया के राष्ट्रवादिशों ने अपने यहां एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर दी। फरवर्ण हालैण्ड और इण्डोनेशिया में युद्ध छिड़ गया। मामला सुरक्षा-परिषद में आया। परिषद द्वारा नियुक्त 'सत्कार्य समिति' (Good Offices Committee) के प्रयत्नों से अगस्त, १९४७ में दोनों पक्षों में युद्ध बन्द हो गया और स्थायी सन्धि की बातें चलने लगी। लेकिन दिसम्बर, १९४८ में हालैण्ड ने इण्डोनेशियन गणराज्य के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड़ दिया तथा इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति व अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिषद ने इस सन कार्य का विरोध करते हुए हालैण्ड से कहा कि इण्डोनेशिया में एक सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न मध्यात्मक गणराज्य की स्थापना की जाय जिसे डच सरकार १ जुलाई, १९४९ तक सप्रभू शक्ति हस्तान्तरित कर दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सत्कार्य समिति' को 'इण्डोनेशिया आयोग' में परिवर्तित कर दिया गया।

जाफ़ी विचार-विमर्श और दबाव के बाद डचों ने इण्डोनेशियाई राजधानी से अपनी फौजें बुताली और यह सहमति प्रकट की कि ३० दिसम्बर, १९४९ तक इण्डोनेशिया के गणराज्य को सर्वोच्च सत्ता हस्तान्तरित कर दी जायगी। बाद में २७ दिसम्बर, १९४९ को ही इण्डोनेशिया को एक स्वतन्त्र सप्रभू गणराज्य मान लिया गया और २८ दिसम्बर, १९५० को उसे मध्युक्त राष्ट्र मण्डल की सदस्यता भी प्रदान कर दी गई। इण्डोनेशियाई विवाद को हट करने में हम प्रकार मध्युक्त राष्ट्र मण्डल की उत्प्रेक्षनीय सफलता मिली।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार का प्रश्न

दक्षिण अफ्रीका सरकार 'वाले-गीरे' में भेद मानने के लिये बहुत समय से बदनाम है। १९४६ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रथम अधिवेशन में ही भारत ने यह प्रश्न उद्घोषित कर दिया और दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर मानवीय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत की शिकायत पर यह सफाई दी कि यह उसका घरेलू मामला है और संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें दखल नहीं देना चाहिये। महासभा ने दक्षिण अफ्रीका के एतद्वाक्य को अमान्य घोषित करते हुए भारतीय प्रस्ताव पास कर दिया। किन्तु दक्षिण अफ्रीका इस प्रस्ताव की चिन्ता न करते हुए अपनी जाति-भेद की अमानवीय नीति पर चलता रहा। १९४८ में यह प्रश्न पुनः महासभा में उठाया गया जिसने एक प्रस्ताव द्वारा सिफारिश की कि भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका एक गोलमेज सम्मेलन करके समस्या का निदान करें। सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका की विरुद्ध के कारण कोई निर्णय न हो सका। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अब तक यह प्रश्न बराबर उठाया गया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अपना रुख नहीं बदला है। महासभा में प्रस्ताव पास होते हैं, पर समस्याओं की रीं बनी हुई है। वास्तव में उस प्रकार की मानवीय व्यवहार की समस्या को न मुजता पाता संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी बिकरता है। ऐसी महान् अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के लिये यह दुर्भाग्यपूर्ण असंगतता है कि समस्या विरल अज्ञान होकर जानता रहे और दक्षिण अफ्रीका में रणभेद अपना गहन मूल्य करता रहे तथा समस्त नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आघात करता रहे।

काश्मीर समस्या

१५ अगस्त, १९४७ को भारत डा-महाद्वीप में दो स्वतंत्र राष्ट्रीय-भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। स्वतंत्रता देने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था की कि दोनों राज्यों अपनी स्थिति का निर्धारण कर सकेंगे और पाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिला सकेंगे। काश्मीर भी इसी तरह का एक देशी राज्य था। इस राज्य ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया।

पाकिस्तान की नियत काश्मीर को अवैधता बताने काय निलाने की थी। अतः २२ अक्टूबर, १९४७ को उसने उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के कश्मीरियों द्वारा काश्मीर पर हमला करवा दिया। पाकिस्तान की एक नियमित सेना के एक बड़े भाग ने भी इस आक्रमण में हिस्सा लिया। राजधानी श्रीनगर का पतन सम्मिलित होने पर काश्मीर के महासभा ने

२६ अक्टूबर, १९४७ को भारत सरकार ने काश्मीर को भारत में शामिल कर अविलम्ब मैनिक सहायता देने का अनुरोध किया। महाराजा ने 'प्रवेश पत्र' (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर कर दिए। तत्पश्चात् भारतीय सेनामें काश्मीर की रक्षा के लिये भेज दी गई। काश्मीर में पाकिस्तान का नान आक्रमण जारी रहा और १ जनवरी, १९४८ को भारत ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि इस आक्रमण से अन्तर्राष्ट्रीय शांति को खतरा है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान का काश्मीर पर आक्रमण स्वयं भारत के विरुद्ध किया गया आक्रमण है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने घोषणा की कि काश्मीर का स्थायी विन्यय भारत में बहा की जनता की मत-गणना (Plebescite) पर होगा।

सुरक्षा परिषद में दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप होते रहे। २० जनवरी, १९४८ को सुरक्षा परिषद ने एक मध्यस्थ आयोग (Mediation Commission) नियुक्त किया जिसे युद्ध बन्द कराने के लिये और जनमत संग्रह का कठिन काम सौंपा गया। आयोग का प्रयत्न से युद्ध विराम हो गया और १/३ काश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। आयोग ने जनमत संग्रह कराने के लिये दोनों देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जिन्हें पाकिस्तान ने भंग कर दिया। काश्मीर में परिस्थितियाँ तेजी से बदलती गईं और भारत व पाकिस्तान में समझौता कराने के समुक्त राष्ट्र सघीय प्रयास कोई सफलता अर्जित न कर सके। पाकिस्तान को पश्चिमी राष्ट्रों का खुला समर्थन मिलता रहा और उनके हाथों में खेलते हुए सुरक्षा परिषद भारत के साथ अग्रिम करती रही। १९५४ में काश्मीर सविधान सभा ने काश्मीर के राजाशाही भारत में विनय का अनुमोदन कर दिया। १९५६ में राज्य के लिये एक नया सविधान स्वीकार किया गया जिसके द्वारा काश्मीर प्रत्येक दृष्टि से भारत का वैध अंग बन गया। इस तरह अब काश्मीर समस्या का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और जनमत संग्रह का कोई मूल्य न रह गया। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकन मैनिक गुट में शामिल हो जाने के कारण और काश्मीर को बलपूर्वक लेने की चान सेवन के कारण जनमत संग्रह की बात बैसे बहुत पहलें ही निरर्थक हो चुकी थी।

पाकिस्तान, पाश्चात्य राष्ट्रों के समर्थन के बल पर रह रहा और काश्मीर के प्रश्न को सुरक्षा परिषद में उठाता रहा, लेकिन भारत के दृढ़ हथ के कारण और न्याय का पक्ष लेते हुए सावित्र मन्त्र के निषेधाधिकार के प्रयोग के कारण उसके कठिन उद्देश्य पूरे न हो सके।

काश्मीर का मामला आज भी सुरक्षा परिषद की विषय सूची में है। दुर्भाग्यवश विश्व महावर्द्धों के कारण सुरक्षा परिषद अभी तक इस विवाद का

हल नहीं कर सकी है। सुरक्षा परिषद में पश्चिमी शक्तियों का बहुमत है, अतः पाकिस्तान परिषद के फैसले को अपने पक्ष में कराने का कोई मौका नहीं चूकता। किन्तु सितम्बर १९६५ के भारत-पाक युद्ध के बाद अब स्थिति इतनी बदल चुकी है कि पाकिस्तान भी यह समझ चुका है कि परिषद के माध्यम से भारत पर कोई भी निर्णय घोषित करने की बात सोचना व्यर्थ होगा।

वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सभ के लिये काश्मीर का विवाद राहू के समान सिद्ध हुआ। मर्यादा इस प्रश्न को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्धों को बह शांत कर सका है, लेकिन पश्चिमी शक्तियों के हाथों में खेलते हुए उसने जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, उससे इस महान् समस्या के गौरव पर आपात ही लगा है। न्याय और निष्पक्षता का तकाशा यही है कि संयुक्त राष्ट्र सभ आक्रामक पाकिस्तान की सेनाओं को काश्मीर की भूमि से हटाने की कार्यवाही करे।

स्वेज नहर विवाद

१८६६ में बनकर पूरी हुई स्वेज नहर का संचालन एक स्वेज नहर कम्पनी करती थी जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकांश शेयर थे। समझौते के अनुसार इसकी रक्षा के लिये ब्रिटिश सरकार अपनी सेना रखती थी। नवम्बर १९५० में मिस्र की सरकार ने यह मांग की कि ब्रिटिश सेना स्वेज नहर क्षेत्र से हट जाए। ब्रिटेन द्वारा यह मांग ठुकरा देने पर दोनों पक्षों के सम्बन्ध कटु होते गए। मिस्र में राष्ट्रीय आन्दोलन जोर पकड़ता गया और अंत में जुलाई १९५४ में एक नये समझौते के अन्तर्गत ब्रिटेन का स्वेज क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेनी पड़ी। इस समय मिस्र में कर्नेल नासिर का शासन था। उपरोक्त समझौते के बाद भी मिस्र और ब्रिटेन व अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के सम्बन्धों में कोई सुधार नहीं हुआ और २६ जुलाई, १९५६ का नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तथा मिस्र में स्वेज नहर कम्पनी को सम्पत्ति जब्त कर ली। ब्रिटेन और फ्रांस ने यह सम्पूर्ण विवाद २६ सितम्बर को सुरक्षा परिषद के समक्ष रख दिया। १३ अक्टूबर, १९५६ को परिषद ने समस्या के हल के लिये ६ सिद्धान्तों का प्रतिपादन एवं प्रस्ताव के रूप में किया जिसमें स्वेज नहर पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखने का भी सुझाव दिया गया, लेकिन सोवियत वीटो से यह प्रस्ताव रद्द हो गया।

आपसी तनातनी इतनी बढ़ गई कि २६ अक्टूबर, १९५६ को ब्रिटेन और फ्रांस को प्रेरणा पर इब्राहिम ने स्वेज नहर क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। इसके दो दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस भी इब्राहिम के साथ युद्ध में पड़ पड़ा। सुरक्षा परिषद में युद्ध बन्द करने का प्रस्ताव फ्रांस और ब्रिटेन के

बीटो के कारण पास न हो सका। संघ के जीवन में यह घोर संकट का समय था जब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य स्वयं संघ के चार्टर का उल्लंघन करके संघ के एक सदस्य राज्य पर हमला कर रहे थे। २ नवम्बर, १९५६ को महासभा के एक विशेष अधिवेशन ने अमेरिका का एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस की सैनिक कार्यवाही की निन्दा करते हुए अविलम्ब युद्ध बन्द करने पर बल दिया गया। ४ नवम्बर को यह प्रस्ताव पास किया गया कि महासचिव श्री डाग हेमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र-मण की एक आपातकालीन सेना तैयार करें जो मित्र म लड़ाई बन्द कराने जाय तथा युद्धबन्दी का कार्य करे। १० राष्ट्रों ने मिलकर लगभग ६ हजार सैनिक दिये जो संयुक्त राष्ट्र मण के नीले और स्वेत ध्वज के नीचे एकत्र हुए। ५ नवम्बर को सोवियत रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि एक निश्चित समय के भीतर मित्र पर हमला बन्द नहीं किया गया तो सोवियत मण नवीनतम शस्त्रों के साथ इस मकट में हस्तक्षेप करेगा। इस चेतावनी से तृतीय महायुद्ध की सम्भावना दिखाई पड़ने लगी और ब्रिटेन और फ्रांस ने भयभीत होकर युद्ध बन्द कर दिया। ७ नवम्बर, १९५६ को महासभा ने अपने एक प्रस्ताव में कहा कि ब्रिटेन, फ्रांस व इजराइल की सेनायें मित्र से हट जाएं तथा स्वेज नहर क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की व्यवस्था की जाए। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप युद्ध पूरी तरह बन्द हो गया और १५ नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र सघीय आपातकालीन सेना का पहला दस्ता मित्र पहुँच गया। मित्र ने संघ की सेनाओं को तभी घुसने की आज्ञा दी जब मित्र की प्रभुसत्ता को हानि न पहुँचने का वचन दे दिया गया। अप्रैल १९५७ में स्वेज नहर से जहाजों का आना जाना पुन प्रारम्भ हो गया।

मित्र में युद्ध बन्द कराने और भिदेसी सेनाओं को हटाने में संयुक्त राष्ट्र सघ की पूरी सफलता मिली और स्वेज पर ब्रिटेन व फ्रांस के पुन आधिपत्य के सपने चूर चूर हो गये।

कांगो समस्या

संयुक्त राष्ट्र मण की सबसे बड़ियाँ परीक्षा कांगो में हुई और सोमाली-शम इस परीक्षा में बड़े सफल हुआ। १९५६ से पहले इस पर बेल्जियम का अधिकार था। रूढ़िवादी आन्दोलन के परिणामस्वरूप ३० जून, १९६० को स्वतन्त्र कांगो गणराज्य की स्थापना हुई। लुमुम्बा प्रधानमन्त्री बन और कासाबुं राष्ट्रपति।

लूजिन कांगो के लिये यह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता महंगी सिद्ध हुई। कांगो के ६ प्रान्त स्वतन्त्र होन का प्रयत्न करने लगे। ६ जुलाई १९६० को

लियोपोल्डविले नामक प्रान्त में सैनिक विद्रोह हो गया और बेल्जियम कागो में पुनः हस्तक्षेप की ताक में था, अतः बेल्जियम की जनता की सुरक्षा के बहाने २ जुलाई, १९६० को उसने कागो में अपनी सेनाएँ भेज दी। बेल्जियम के पड़ोस से ११ जुलाई को कटंगा प्रान्त ने एक पृथक स्वतन्त्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी। १२ जुलाई को प्रधानमंत्री लुमुम्बा ने संयुक्त राष्ट्र संधि से प्रार्थना की कि बेल्जियम के आक्रमण से रक्षा करने के लिये कागो को तुरन्त सैनिक सहायता दी जाए। १४ जुलाई को परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया कि बेल्जियम की सेनाएँ कागो से वापस चली जाएँ और महासचिव कागो को आवश्यक सैनिक सहायता देने की व्यवस्था करे। इस प्रस्ताव के अनुपालन में २८ जुलाई तक संधि की सेनाओं के १० हजार से भी अधिक सैनिक कागो पहुँच गये। संयुक्त राष्ट्र संधीय सैनिकों ने कागो और बेल्जियम के बीच होने वाले संधि को समाप्त कर दिया। शीघ्र ही संधि की सेनाएँ विद्रोही कटंगा प्रान्त को छोड़कर पूरे कागो में फैल गई।

कागो का मामला सुलझने की बजाय उलझता ही गया। अगस्त १९६० के अंत तक स्थिति बहुत बिगड़ गई। कटंगा का अनुसरण करते हुए कागो के अन्य प्रान्तों ने भी पृथक राज्य स्थापित करने की नीति अपनाई। विद्रोहियों को कुचलने के लिये लुमुम्बा ने नैतिक शक्ति का आश्रय लिया। विद्रोहियों को बेल्जियम की खुली मदद मिलती रही। विदेशी हस्तक्षेप से कागो को बचाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संधीय सैनिकों ने कागो के सभी हवाई अड्डों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया, लेकिन कागो के गृह-युद्ध में तटस्थता की नीति स्वीकार की। संयुक्त राष्ट्र संधि का यह कार्य इस दृष्टि से पक्षपातपूर्ण था कि पृथक्तावादियों को तो कागो में पहुँची हुई सेनाओं से खूब मदद मिल रही थी जबकि हवाई अड्डों पर संधीय सेनाओं का बख्ता होने से केन्द्रीय कागोली सरकार को बाहर से सहायता मिलना बन्द हो गया था।

सितम्बर के प्रारम्भ में प्रधानमंत्री लुमुम्बा और राष्ट्रपति कासानुबू में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। दोनों के सत्ता संघर्ष से कागो की सेना परेशान हो गई और १४ सितम्बर को जर्नेल मोबूतू ने सारी शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा कागो में नैतिक शासन की घोषणा कर दी। कागो की हालत बिगड़ती गई। जनवरी १९६१ में लुमुम्बा की हत्या कर दी गई। उसपर कटंगा के शीम्बे ने संयुक्त राष्ट्र संधि की यह धमकी देना शुरू कर दिया कि यदि संधीय सेनाएँ कटंगा भेजी गईं तो उसके विरुद्ध घोर आक्रमण करने का फैसला कर ली जाएगी। कागो की बिगड़ती हुई स्थिति पर विचार करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद् में २१ फरवरी, १९६१ को यह प्रस्ताव पारित किया कि कागो में गृह-युद्ध रोकने के लिये सब उपाय चले जाएँ। इस प्रस्ताव के

अनुपालन में समुक्त राष्ट्र सच की एक सैनिक कमान नियुक्त की गई। २४ नवम्बर, १९६१ को गुरक्षा परिषद् ने अपने एक प्रस्ताव में आदेश दिया कि कांगो से कटंगा के पृथक होने के कार्यों को रोकने का प्रयत्न किया जाए। इसके बाद ही दिसम्बर में समुक्त राष्ट्र सच की फौजों ने कटंगा प्रदेश पर नियन्त्रण रखने और केन्द्रीय कांगोली सरकार के अधिकार में उसे लाने के लिये सामरिक दृष्टि में महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा कर लिया। सितम्बर, १९६२ में महासचिव हेमरसोल्ड कांगो के नेताओं से पृथक बातचीत के लिये स्वयं कांगो गये जब वे शोम्बे से वाता के लिये लियोपोल्डविले से इन्दोला गए तो मार्ग में ही उनका वायुयान गहस्पपूर्ण ढग से दुर्घटना का शिकार हो गया और महासचिव सहित विमान के सभी यात्री जलकर खात्म हो गये। अगस्त १९६२ में नये महासचिव ऊथान्ट ने कांगो के पुन एकीकरण की योजना तैयार की जिसमें कटंगा की केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में लाने के लिये अनेक सैन्यनैतिक, सैनिक, आर्थिक उपायों का निर्देश था। शोम्बे ने समुक्त राष्ट्र सच की प्रयासों की पूर्ण तन्ना की। इतना ही नहीं, कटंगा का सेनापति समुक्त राष्ट्र सच की सेनाओं पर हमला भी करने लगी। अतः में अमेरिका और रूस समर्थित समुक्त राष्ट्र सच की प्रभावशाली सैनिक कार्यवाही के सामने शोम्बे ने घुटने टेक दिये और २५ जनवरी, १९६३ को घोषणा की कि कटंगा का कांगो के साथ पृथक्करण समाप्त होता है तथा वह महासचिव की एकीकरण योजना में पूरा सहयोग देगा।

इस प्रकार कांगो में अन्ततः शांति स्थापित कर दी गई और समुक्त राष्ट्र सच का शांति स्थापना का प्रधान कार्य कांगो व एकीकरण के साथ समाप्त हुआ।

यमन की समस्या

१६ सितम्बर, १९६२ को यमन के शासक इमाम अब्दुल्ला की मृत्यु हो गयी। २९ सितम्बर को एक आन्तिम द्वारा राजतन्त्र की समाप्ति कर दी गयी और आन्तिमकारी परिषद् ने गणराज्य की स्थापना की। दूसरी ओर राजतन्त्रवादियों को अपन पक्ष में करके शाहजादे हमन ने सउदी अरब में जिद्दा नामक स्थान में यमन की निर्वासित सरकार की स्थापना की। दोनों यमनी सरकारें एक दूसरे को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक और सामरिक नीतियाँ अपनाती रही। अक्टूबर के समाप्त होने होते ही राजतन्त्रवादियों और गणतन्त्रवादियों में भीषण संघर्ष शुरू हो गया। सउदी अरब और जाटन ने राजतन्त्रवादियों की सहायता की और मिस्र ने गणतन्त्रवादियों की। गृह युद्ध को व्यापक बनने से रोकने के लिए समुक्त राष्ट्र सच ने हस्तक्षेप किया।

मार्च १९६३ में संधि की ओर से सल्फ वुन्च ने प्रत्यक्ष मुलाकात द्वारा दोनों पक्षों को इस बात के लिए राजी किया कि वे अपने-अपने सैनिकों को वापिस बुला लें और समस्या का शांतिपूर्ण हल खोजें। संयुक्त राष्ट्र संधि के बाद के प्रभावपूर्ण प्रयासों के फलस्वरूप धर्म धर्म बाह्य शक्तियों ने यमन से अपनी सेनाएँ हटा ली और यमन में शांति स्थापित हो गयी।

साइप्रस की समस्या

१३ अगस्त, १९६० को साइप्रस ब्रिटिश प्रभुता से मुक्त होकर स्वतन्त्र गणराज्य बना। साइप्रस का जो सविधान बनाया गया उसमें वहाँ के बहुमतर्यक यूनानियों और अल्पसंख्यक तुर्कों के बीच सामंजस्य और शांति बनाये रखने की व्यवस्था की गयी। स्वतन्त्रता के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति मकारियोस ने सविधान में ऐसा संशोधन प्रस्तावित किया जिनसे दोनों जातियों के मध्य स्थापित किया गया संतुलन और सामंजस्य समाप्त हो जाता। फलस्वरूप दोनों जातियों में राजनीतिक संघर्ष और गृह युद्ध की शुरुआत हो गयी। समस्या पर यूनान, टर्की और साइप्रस के बीच इंग्लैंड में शांति सम्मेलन शुरू हुआ। ब्रिटेन ने साइप्रस में नाटो फौजें भेजने का कुछ चक्कर रखा। राष्ट्रपति मकारियोस ने दिसम्बर १९६३ में सारा मामला सुरक्षा परिषद् के सामने रखते हुए संयुक्त राष्ट्र नवीय पर्यवेक्षक भेजने और स्थिति समालने के लिए संधि के हस्तक्षेप की मांग की। लम्बे विचार विमर्श के बाद मार्च १९६४ में साइप्रस में शांति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र नवीय शांति सेना भेजने का निर्णय किया गया। शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय सेना साइप्रस पहुँच गयी जिसने बड़ा नातून और व्यवस्था बनाये रखने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इसके बाद इस आपातकालीन सेवा का अवधि बढ़ायी जाती रही और आज भी यह सेना साइप्रस के कलहप्रस्त क्षेत्रों में तैनात है।

डोमिनिकन गणराज्य विवाद

लेटिन अमेरिका के इस छोटे से देश में अप्रैल, १९६५ में गृह युद्ध छिड़ गया। अमेरिकन राष्ट्रपति ने अपने पक्ष की सरकार को बचाने के लिए सैनिक हस्तक्षेप किया। बहाना यह दिया गया कि डोमिनिकन गणराज्य में साम्यवादियों ने बचारे के लिए यह राज्य काटो की पकड़ी है। हम ने सुरक्षा परिषद् से अनुरोध किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करे। अन्त में परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव पास किया गया कि युद्धरत दोनों पक्ष युद्ध विराम करें और महासचिव आवश्यक जाच-पड़ताल के लिए अपने प्रतिनिधि डोमिनिकन गणराज्य में भेजें। अमेरिकन राज्यों के मगठन ने भी समस्या के समाधान की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाये। अन्त में अमेरिकन राज्यों के मगठन और

संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रयासों से, ४ माह के गृहयुद्ध के उपरान्त ३१ अगस्त, १९६५ को दोनों पक्षों में समझौता होकर शांति स्थापित हो गयी। महा-सचिव ने अपनी रिपोर्ट में हृदयशून्यता के साथ कहा कि डोमिनिकन गणराज्य में युद्ध बन्द कराने के कार्य में संधि ने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया है।

अरब इजरायल संघर्ष

१९५६ के अरब इजरायल संघर्ष में युद्ध-विराम होने पर संयुक्त राष्ट्र-संघ की अन्तर्राष्ट्रीय सेना गाजा और मिस्र की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हो गयी थी ताकि इजरायल अरबों में पुनः संघर्ष न छिड़ जाए। लेकिन दोनों पक्षों में तनाव बढ़ना गया। १९६७ में जोरों से युद्ध की तैयारियां शुरू हो गयीं। मई में, राष्ट्रपति नासिर के जिद्द करने पर, संयुक्त राष्ट्र संधि सैनिक हटा लिये गये। अब संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सेनाओं धामने सामने हो गयीं। एक दूसरे की कार्यवाहियों से स्थिति में पूरा बिगाड़ आ गया और ५ जून को एकाएक इजरायल ने अरबों पर अपना विनाशकारी आक्रमण कर दिया। जोर्डन, सीरिया, मिस्र, ईराक आदि १० करोड़ वाली जनसंख्या के देश छोटे से इजरायल का आक्रमण न सह सके। केवल ५ दिन की लड़ाई में ही अरब राष्ट्रों की सामरिक क्षमता का विनाश हो गया। इस बीच सुरक्षा परिषद् युद्धविराम के लिए पूरे प्रयास करती रही। ७ जून को परिषद् ने यह आदेशात्मक प्रस्ताव पारित किया कि युद्धरत सभी देश युद्ध बन्द कर दें। चूंकि अरब राष्ट्र युद्ध क्षमता खो चुके थे और इजरायल सामरिक उद्देश्यों को पूरा कर चुका था, अतः ८ जून को इजरायल और मिस्र के बीच युद्ध विराम हो गया और १० जून तक सभी अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच पूरी तरह लड़ाई बन्द हो गयी। संयुक्त अरब गणराज्य स्वेज के किनारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय पर्यवेक्षक रखने में सहमत हो गया। १६ जुलाई से स्वेज नहर क्षेत्र में संधि के पर्यवेक्षकों की देख-रेख में युद्धविराम लागू हो गया। किन्तु फिर भी पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो सकी और आज भी इस क्षेत्र में दोनों पक्षों में सैनिक झड़पें होती रहती हैं। आपसी तनाव पुनः विस्फोट स्थिति में पहुँचता जा रहा है और स्थायी शांति कोसों दूर दिखाई देती है। अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच बारम्बार युद्ध विराम कराने में संधि की सफलता अवसर मिली है, लेकिन इसे समस्या का स्थायी समाधान नहीं कहा जा सका है। इस क्षेत्र में शांति तभी सम्भव हो सकेगी जब विश्व की महाघबिनियां बीच में पड़कर रुचिपूर्वक कोई हल निकालने का प्रयत्न करेंगी।

भारत-पाक संघर्ष

काश्मीर की हड़पने के लिए पाकिस्तान ने १९६५ में पुनः युद्ध का

आश्रय लिया। अगस्त १९६५ में हजारों पाकिस्तानी हमलावर छिप कर युद्ध विराम रेखा पार करके काश्मीर के भारतीय प्रदेश में घुस गये। भारत ने जब इस घुसपैठी आक्रमण को नाकामयाब कर दिया तो १ सितम्बर, १९६५ को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके पाकिस्तान की एक पूरी पैदाश ब्रिगेड और ७० टैंक काश्मीर पर चढ़ आये। मजबूरन भारत को भी अपनी रक्षा के लिए पाकिस्तान के बिरुद्ध पूरी छटाई छेड़ देनी पड़ी। २२ दिनों के घमासान युद्धों में पाकिस्तान पर करारी मार पड़ी और आखिर संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रयासों से २३ सितम्बर १९६५ को प्रातः ३-३० बजे भारत-पाक युद्ध-विराम हो गया तथा पाकिस्तान की रही सही लाज नष्ट होने से बच गयी।

संयुक्त राष्ट्र संधि प्रारम्भ से अन्त तक युद्ध विराम के प्रयत्न करता रहा। स्वयं महासचिव ने देहली और कराची पहुँच कर श्री शास्त्री और अग्रुव से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया। महासचिव ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद् को बताया कि यदि पाकिस्तान राजी हो तो भारत बिना शर्तें युद्ध बन्द करने को प्रस्तुत है, किन्तु पाकिस्तान ने युद्धविराम प्रस्ताव को प्रत्यक्षत ठुकरा दिया। महासचिव ने माग की कि परिषद् दोनों पक्षों को अविलम्ब युद्ध बन्द करने का आदेश दे और युद्ध बन्द न होने पर आवश्यक कार्यवाही करे। भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परिषद् पहले यह निश्चित करे कि आक्रामक कौन है। भारत ने यह भी कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र संधि संधि पर्यावेक्षों की रिपोर्ट ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि काश्मीर में घुसपैठी आक्रमण पाकिस्तान ने शुरू किया और बाद में आश्रयदाता हमला कर दिया। अन्त में काफी उत्तार-चढ़ाव के बाद परिषद् द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि भारत और पाकिस्तान २२ सितम्बर को दोपहर से युद्ध बन्द कर दें और युद्ध-विराम लागू होने के बाद अपनी सेनाओं को ५ अगस्त, १९६५ की स्थिति में लौटा लें। पाकिस्तान द्वारा सहमति की सूचना देने पर युद्ध २३ सितम्बर, १९६५ को प्रातः ३। बजे बन्द हुआ।

सुरक्षा परिषद् का २२ सितम्बर का प्रस्ताव भारत के साथ अग्राय था। इसमें दोनों देशों को युद्ध-बन्द करने का आदेश दिया गया था जब कि यह आदेश केवल आक्रामक पाकिस्तान को ही दिये जाने चाहिये थे, क्योंकि उसने ही परिषद् के युद्ध-बन्दी के पहले वाले प्रस्ताव को ठुकराया था। आक्रमणकारी और आक्रान्त दोनों के साथ एक-का व्यवहार करना न्यायमंगल नहीं था। यह प्रस्ताव और भी अनेक दृष्टियों से अनुचित था, किन्तु भारत ने केवल यही सोचकर इसे स्वीकार कर लिया कि कोई उसकी पातिप्रियता पर थपुली न सठा सके। जो भी हो, दोनों देशों के बीच युद्ध-बन्द करा देने में संयुक्त राष्ट्र संधि और महासचिव के प्रयत्न सराहनीय माने जायेंगे।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले कुछ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का ही हमने उल्लेख किया है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक छोटे-मोटे विवाद सभ के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। सब ने सभी विवादों का समाधान करने के सम्बन्ध में अपनी जागरूकता प्रदर्शित की है तथापि महाशक्तियों की अड़बेबाजी के फलस्वरूप अनेक मामलों की सुलझाने में सब असफल रहा है। काश्मीर के प्रश्न वियतनाम के सघर्ष, राष्ट्रीय चीन व साम्यवादी चीन के भेदभाव, दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद नीति, निःशस्त्रीकरण, अणुशक्ति के प्रयोग पर प्रतिबन्ध आदि विषयों के समाधान में सब को विकलता का पुँह देखना पड़ा है। फिर भी इनमें से कुछ समस्याओं के उग्र रूप को अधिक विस्फोटक बनने से रोकने की दिशा में सब के प्रयास प्रशंसनीय रहे हैं। अनेक अवसरों पर सब के सामयिक हस्तक्षेप के कारण हो स्थिति वि-फोटक बनने से रुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सब के कार्यों का मूल्यांकन प्रस्तुत अध्याय के अन्त में किया गया है। यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है कि यद्यपि सब विश्व शांति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूरी तरह और सन्तोषजनक रूप से सक्षम सिद्ध नहीं हुआ है तथापि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में शांति बनाये रखने के इसने अनेक बार सफल प्रयत्न किये हैं। विश्व के राष्ट्रों और लोगों की सेवा के लिए जो विभिन्न सङ्गठन और आयोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच सब ने समन्वय की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र सभ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय जगत की एक आवश्यक, उपयोगी और अनेकित विशेषता है तथा अगु सगु में अस्तित्व की आवश्यक शक्त है। राजनीतिक और कूटनीतिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में इसने प्रभावशाली भूमिका अदा की ही है, लेकिन अपने गौर राजनीतिक कार्यों द्वारा भी इसने मानव के भौतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में सहयोग देकर शांति और व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सभ की कमजोरियाँ

(The Weak Points of the U. N. O.)

हमें देखना चाहिये कि आखिर ये कौन सी कमजोरियाँ हैं जिनकी वजह से अनेक बार संयुक्त राष्ट्र सभ को बुरी तरह अक्षम होना पड़ा है। वास्तव में महाशक्तियों के बीच इतने अधिक मौलिक मतभेद हैं कि सुरक्षा परिषद का कार्य करना भी कभी कभी असम्भव हो जाता है। इसको इन अपूर्णताओं अथवा कमजोरियों पर ध्यान देना आवश्यक है—

१. सभ की सदस्यता में धार्मिकता का अभाव है। अभी तक विश्व के समस्त राष्ट्र इससे सदस्य नहीं बन पाये हैं। इसके जन्म के लगभग

२३ वर्षों परचाहूँ भी ८० करोड़ की जनसंख्या वाला जनवादी चीन तथा पराजित राष्ट्र जर्मनी (पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी) इसके सदस्य नहीं हैं। पियतनाम, चीतमिन्ह, उत्तरी एव दक्षिणी कोरिया जैसे छोटे-छोटे राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र संधि से बाहर हैं।

२. संयुक्त राष्ट्र संधि का संगठन इस सिद्धान्त पर आधारित है कि क्षेत्रफल अथवा सीमा तथा जनसंख्या की विभिन्नता होते हुए भी सभी सदस्य राष्ट्र समान हैं। वैधानिक समानता की इस मान्यता के कारण महाधिकार की दृष्टि से बड़े राष्ट्र भी छोटे राष्ट्रों के समक्ष आ गये हैं। वस्तुतः यह एक हास्यास्पद बात है कि ४५ करोड़ की विनाल जनसंख्या वाले देश भारत को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो १२ १३ लाख की जनसंख्या वाले लैबनान को हैं।

३. संयुक्त राष्ट्र संधि राष्ट्रों का एक संधि है। इसमें भाग लेने वाले राजनीतिज्ञ अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार संधि राष्ट्रों की सम्प्रभुता के व्यवहार पर ही आधारित रहता है जबकि इसमें सरकारों के स्थान पर जनता के, विश्व के लोगों के प्रतिनिधि होने चाहिये। क्लार्क आइचबर्गर (Clark Eicheberger) के मतानुसार, "संयुक्त राष्ट्र संधि एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है जिसके निर्माताओं ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पार्य करने की शक्ति का बाना पहिनाया है तथा जिसके सदस्यों ने इसके प्रति महावपूर्ण दायित्व सम्भाले हैं, किन्तु यह न तो एक राज्य है और न ही सर्वोच्च राज्य। यह अन्तर्विरोध तो विश्व समाज के विकास में निहित ही रहता है।"^१ संयुक्त राष्ट्र संधि क्षेत्रल चर्चा, वाद-विवाद तथा विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय स्थल माना जाता है। इसके पास अपनी स्वयं की ठोस शक्ति नहीं है, सिवाय उन अधिकारों के जो सदस्य राष्ट्रों ने उसे स्वेच्छा से प्रदान किये हैं। विभिन्न देशों के "घरेलू मामलों" में संधि का कोई अधिकार नहीं है और "घरेलू मामलों" की स्पष्ट परिभाषा घोषणा-पत्र में नहीं दी गई है।

४. संयुक्त राष्ट्र संधि के वाद-विवाद एवं निर्णय पक्षपातपूर्ण होते हैं। सुरक्षा परिषद में भी संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है और इसी कारण सोवियत रूस को अनेक बार वीटो का सहारा लेकर अपनी रक्षा करनी होती है।

५. संयुक्त राष्ट्र संधि निषेधाधिकार के दुरुपयोग का रगमच बना हुआ है। सुरक्षा परिषद में ५ महा शक्तियों ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस

और राष्ट्रवारी चीन को निषेधाधिकार प्राप्त है। इसमें से कोई भी शक्ति किसी भी उचित किन्तु अपने विरोधी दावे को निषेधाधिकार के प्रयोग से अमान्य ठहरा देती है। इस तरह यह निषेध शक्ति विश्व में शांति एवं सुरक्षा को स्थिर करने की दिशा में प्रभावकारी कार्यवाहियों में अवरोध उत्पन्न कर देती है। आलोचकों की मान्यता है कि निषेधाधिकार का अनुभव यह बताता है कि आधार रूप से समुक्त राष्ट्र सघ अपर्याप्त है तथा युद्ध और शांति की समस्या को प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा सकता।

६ सघ के पास अपने निर्णयों को व्यवहृत कराने की शक्ति नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निवारण कर विश्व में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए इसे महा शक्तियों के मुँह की ओर ताकना पड़ता है जिनके सन्निध्य सहयोग के बिना यह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहा जा सकता है कि 'सघ के पास काटने के लिए दात नहीं हैं।'

७ समुक्त राष्ट्र सघ के घोषणा पत्र में आत्मरक्षा एवं आक्रमण के मध्य का भेद स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित नहीं है।

८ सघ के सभी सदस्य राष्ट्र समान रूप से साम्राज्यवादी तथा जातीय भेदभाव के विरोधी नहीं हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जातीय भेदभाव का असर इतना अधिक है कि यह प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता एवं मानव अधिकारों आदि का पूरी तरह से मलौठ करता सा दिखाई देता है।

९ समुक्त राष्ट्र सघ के बाहर की गई सैनिक सधियों के कारण भी इसका महत्व कुछ कम हो गया है।

१० आधुनिक विश्व दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों में बंटा हुआ है और समुक्त राष्ट्र सघ उस और उसके सहयोगी राष्ट्र तथा अमेरिका और उसके साथी राष्ट्रों की पारस्परिक खींचतान का रंगमंच बना हुआ है। विश्व के ये दोनों गुट सघ में और उसके बाहर भी प्रायः प्रत्येक प्रश्न पर एक दूसरे के विरोधी विचार ही व्यक्त करते हैं।

११ समुक्त राष्ट्र सघ की स्थापना के बाद आज भी अनेक पराधीन राष्ट्रों को अपनी स्वतन्त्रता के लिए घोर प्रयत्न करने पड़ रहे हैं तथा वहाँ की जनता को स्वतन्त्रता की मांग करने पर गोलियों का शिंकार बनना पड़ता है। जब तक आधुनिक विश्व में यह साम्राज्यवादी भावना कायम रहेगी तब तक सघ की सफलता में बाधा उपस्थित होना स्वाभाविक बात है।

१२ समुक्त राष्ट्र सघ तब ही सफल हो सकता है जब इसे सदस्यों का सन्निध्य सहयोग प्राप्त होता रहे। क्लार्क आइव' बर्गर के शब्दों में "अन्तिम विश्लेषण में समुक्त राष्ट्र सघ को सफल बनाने का काम इसका

प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों तथा राजनीतिज्ञों पर ही निर्भर है।”^१ किन्तु इन पर राष्ट्रीयता एवं सम्प्रभुता जैसी भावनाओं का प्रभाव पड़ता रहता है, अतः वे मंडल की सफलता में आशाजनक सहयोग प्रदान नहीं कर पाते।

१३. मंडल का एक गम्भीर दोष यह है कि शक्तों के एकीकरण और निर्माण को कम करने के मामलों में इसके सदस्य राष्ट्रों में विशेषकर बड़ी शक्तियों में, ईमानदारी का अभाव है।

कुछ भी हो, दुर्बलताओं के बावजूद भी यह निर्विवाद तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र मंडल अब तक विश्व युद्ध को रोकने और शांति को बनाये रखने में बहुत कुछ सफल हुआ है और इसने अपने आपको राष्ट्र मंडल के समान एक भूतप्राय मंडल नहीं बनने दिया है।

मंडल की शक्तिशाली बनाने के लिये सुझाव (Suggestions for Strengthening the U. N. O.)

मंडल के अनेक उपबन्ध आज समयातीत बन चुके हैं। मंडल के संस्थापकों के सामने जिस सप्ताह का चित्र था वह आज के नवीन विकासों के कारण कई नवीन रंगों से परिपूरित हो गया है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि मंडल के मूल एवं मूलभूत में परिवर्तन किया जाए।

मंडल की शक्तिशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक तो चार्टर में आवश्यक संशोधन किये जाय और दूसरे इस दिशा में कुछ अन्य प्रभावशाली और व्यावहारिक कदम उठाये जायें। ये संशोधन और अन्य पग निम्नलिखित हो सकते हैं—

चार्टर में संशोधन

(१) नवीन राज्यों के साथ में प्रवेश के लिए स्थायी सदस्यों द्वारा विशेषाधिकार के प्रयोग की व्यवस्था हटा दी जानी चाहिये।

(२) चार्टर के दूसरे अनुच्छेद के सातवें पैराग्राफ में यह व्यवस्था दी गयी है कि—“संयुक्त राष्ट्र मंडल किसी भी राज्य के उन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकारी न होगा जो निश्चित रूप से उस राज्य के घरेलू क्षेत्र के भीतर आते हों।” घरेलू क्षेत्र (Domestic Jurisdiction) की इस व्यवस्था ने मंडल की कार्यवाहियों के क्षेत्र को बहुत सीमित बना दिया है। यह व्यवस्था इतनी लचकीली है कि इसके आधार पर राष्ट्रों द्वारा मंडल की कार्यवाहियों में अड़ने लगाये जाते रहे हैं। मंडल अपने उद्देश्यों की दिशा में अधिक

शक्तिशाली व समर्थ बने—इसके लिए घरेलू-क्षेत्र की व्यवस्था में समुचित मसौदा किया जाना चाहिए।

(३) चार्टर के अनुच्छेद ४ में सभ की सदस्यता के लिए दो शर्तें हैं—(१) सभी शांति चाहने वाले राष्ट्र सदस्य बन सकते हैं बशर्ते कि वे चार्टर में दिये हुए दायित्वों को मानें और सभ की सभ में इन दायित्वों को पूरा करने की उनमें इच्छा तथा योग्यता दोनों हो, एवं (२) कोई राष्ट्र सभ का सदस्य सभी बनाया जायगा जब सुरक्षा परिषद सिफारिश करे व महासभा सिफारिश पर अनुकूल निर्णय दे। स्पष्ट है कि सभ की सदस्यता की दूसरी शर्त विवादों को आमंत्रित करने वाली है। सुरक्षा परिषद में महाशक्तिमों को निषेधाधिकार प्राप्त हैं। रूस और परिचयी राष्ट्र स्वयं की स्थिति को मयुक्त राष्ट्र सभ में सुदृढ़ बनाये रखने की दृष्टि से अपने विरोधी नवीन राज्यों के प्रवेश को निषेधाधिकार के बल पर रोक सकते हैं। वस्तुतः सदस्यता के प्रवेश की दूसरी शर्त सभ के दोनों पक्षों में कटुता बढ़ाने वाली है और और इसी वजह से विश्व के कुछ देशों का प्रतिनिधित्व सभ में अभी तक नहीं हो पा रहा है। अतः यह उचित है कि सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश की शर्त हटा देनी चाहिए अथवा उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(४) न्यास पद्धति से सम्बन्धित अनुच्छेद ७६ (ख) बड़ा अस्पष्ट है। उसमें पराधीन देशों की स्वतन्त्र करने की बात अवश्य कही गयी है लेकिन इसके लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की है। इस अनुच्छेद में इस तरह की व्यवस्था जोड़ी जानी चाहिये कि विभिन्न प्रदेशों के विकास को देखते हुए उन्हें कितनी अवधि में स्वाधीनता दे दिया जाना उभयुक्त है।

(५) न्यास पद्धति से सम्बन्धित ७७ (क) में इस तरह का मसौदा किया जाना चाहिए कि राष्ट्र सभ के सभी मेंग्रेट अनिवार्य न्यास परिषद के अग समझे जाए।

(६) अनुच्छेद ५१-५२ में चार्टर द्वारा प्रादेशिक संगठनों को बनाने की अनुमति दी जाने का ही यह परिणाम है कि नाटो (NATO), सीटो (SEATO) जैसे सैनिक संगठन बन गये हैं। इस धारा में ऐसा मसौदा होना चाहिए कि जिससे सैनिक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन न मिल सके।

१७) अनुच्छेद २७ में सुरक्षा परिषद में मतदान की व्यवस्था में 'प्रक्रिया सम्बन्धी' (Procedural Matters) और 'अन्य सभी विषय' (On All Other Matters) शब्द इतने अनिश्चित और अस्पष्ट हैं कि

जिससे निपेधाधिकार का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अतः यह उपयुक्त है कि इन शब्दों को अधिक स्पष्ट किया जाय।

(८) सुरक्षा परिषद में स्याई सदस्यों का प्रतिनिधित्व समुचित एवं समुचित नहीं है। निष्पक्षता और समुचित विचारों की दृष्टि से तथा संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रति अर्पित किये गये महान् सहयोग की ध्यान में रखते हुए भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। सुरक्षा परिषद में एशिया और अफ्रीका के देशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

चाटेंर में उल्लिखित मानवीय अधिकारों की प्राप्ति को वियात्मक बनाने के लिए उपयुक्त संस्थाओं की स्थापना सबंधी प्रावधानों और अन्य व्यवस्थाओं का होना भी आवश्यक है।

महाशक्तियों की चाटेंर में संशोधन की रचि—संयुक्त राष्ट्र संधि के चाटेंर का संशोधन करने के पक्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारम्भ से ही जोर देता रहा है। जनवरी, १९५४ में जॉन फास्टर डलैस ने चाटेंर का संशोधन के मुख्य विषयों का उल्लेख करते हुए कहा था कि संशोधन निम्नलिखित विषयों में अवश्य किये जाने चाहिए (१) सर्वव्यापी सदस्यता (२) सुरक्षा (३) सुरक्षा परिषद् की सदस्यता एवं मतदान प्रणाली (४) महासभा में मतदान प्रणाली (५) शांति की समस्या (६) अन्तर्राष्ट्रीय कानून आदि।

सोवियत रूस पहले चाटेंर में संशोधन का समर्थक नहीं था। किन्तु बाद में (१९६० में) जब सुरक्षा परिषद में रूस द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ प्रस्ताव वीटो के कारण असफल हो गये तो वह चाटेंर की व्यवस्था में परिवर्तन करने का हामी हो गया। सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र संधि के चाटेंर में परिवर्तन करने के अनेक सुझाव समय-समय पर दिये जो संक्षेप में निम्न प्रकार से थे :—

(१) संधि की सभी परिषदों में से अमेरिका का हस्तक्षेप कम किया जाय और इनमें अफ्रीका तथा एशिया के देशों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाय।

(२) साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संधि का सदस्य बना लिया जाय।

(३) एक महासचिव वाली व्यवस्था दोषपूर्ण है क्योंकि वह प्रायः एक पक्ष का ही समर्थक बन जाता है तथा उस पक्ष द्वारा संधि की शक्तियों का अनुचित लाभ उठाया जाता है, अतः एक के स्थान पर तीन महासचिवों की नियुक्ति की जाय—एक साम्यवादी गुट की ओर से, दूसरा पश्चिमी शक्तियों की ओर से तथा तीसरा तटस्थ या अलग-अलग राष्ट्रों की ओर से। ऐसा करने पर कोई भी समस्या जो सुरक्षा परिषद में राजनीतिज्ञों के मतभेद के कारण गति-

रोष उत्पन्न कर देती है वह महासचिवों के स्तर पर विचार विमर्श के बाद एक ऐसा रास्ता निकालकर तय की जा सकेगी जो तीनों पक्षों को स्वीकार हो। इस मुझाव का अधिवाग विचारकों एवं राजनीतिज्ञों द्वारा रादेह एवं आलोचना द्वारा स्वागत किया गया। यह समझा गया कि इस मुझाव को क्रियान्वित करने पर महासचिव स्तर पर राजनीति उतर आयगी तथा सुरक्षा परिषद की भांति यहां भी गतिरोध की समस्या पैदा हो जायगी तथा कोई भी निर्णय लेना अमभव बन जायगा।

(४) मध का प्रधान कार्यालय समुक्त राज्य अमेरिका में न रखकर किसी अन्य देश में रखना चाहिए। वह अन्य देश स्वयं सोवियत मध, स्विट्जरलैण्ड या आस्ट्रिया हो सकते हैं।

यद्यपि इस और अमेरिका के द्वारा चार्टर के संशोधन के धारे में अनेक मुझाव प्रस्तुत किये गये, किन्तु ये मुझाव इस प्रकार के हैं कि वे एक दूसरे को मान्य नहीं होते। ऐसा सोचा जाता है कि चार्टर पर पुनर्विचार करने का समय अभी तक नहीं आ पाया है। इस प्रकार यदि चार्टर का परिवर्तन किया गया तो हो सकता है कि वह अपने मूल स्वरूप की ओर और भी अधिक कठोर बन जाय।

अनौपचारिक मशोधन—उल्लेखनीय है कि यद्यपि औपचारिक रूप से चार्टर में संशोधन नहीं हो पाये हैं, किन्तु अनौपचारिक रूप से व्यवहार में चार्टर के कुछ उपबन्धों को प्रभावी अथवा प्रभावहीन किया जा चुका है, उदाहरणार्थ ३ नवम्बर, १९५० के 'शान्ति के लिए एकता' के प्रस्ताव ने निषेधाधिकार को काफी प्रभावहीन कर दिया है और महासभा को सुरक्षा परिषद से अधिक शक्तिशाली बना दिया है। होता यह है कि सुधार के मुझावों के सम्बन्ध में महासक्तिवा एकरत हो सकती हैं चाहे वे चार्टर के वास्तविक रूप में कोई परिवर्तन करने पर राजी हों या न हों। सुधार के सम्बन्ध में मुझाव तथा उनका मध के चरित्र, रूप एवं संगठन पर प्रभाव यद्यपि चार्टर में परिवर्तन तो नहीं कहा जा सकता किन्तु इससे मध शक्तिशाली बनता है इस मध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पामर तथा परकिन्स ने इसे अनौपचारिक मशोधन की प्रक्रिया (The Process of informal amendment) कहा है। इस तरीके से अनेकों परिवर्तन निय जा चुके हैं तथा निश्चय ही आज का मधुक्त राष्ट्र मध ठीक वही नहीं है जो वह सन् १९४५ में था। इस प्रक्रिया में महासक्तियों की आवश्यक सहमति जरूरी नहीं होती। फ्रान्सिस विल्कोक्स (Francis O. Willcox) का मतानुसार चार्टर निम्न प्रकार से मशोधित किया गया है—

- (१) चार्टर के कुछ उपबन्धों को त्रियान्वित न करके;
- (२) संधि के विभिन्न अंगों तथा सदस्यों द्वारा चार्टर की व्याख्या करके,
- (३) सहायक संघियों एवं समझौतों के निर्णयों के द्वारा;
- (४) विशेष अंगों एवं अभिकरणों की रचना करके ।

अन्य सुझाव

संधि को शक्तिशाली बनाने के लिये अनेक सुझाव समय-समय पर दिये जाते रहे हैं जो प्रमुखतया ये हैं—

१. संधि सम्प्रभु राज्यों की एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है और यदि इसे शक्तिशाली बनाना है तो सदस्य राज्यों को अधिक स्वामी भवित और कल्पनात्मक रूप से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना चाहिये ।

२. चार्टर की व्याख्या करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ।

३. संधि के वर्तमान यन्त्र को विस्तृत बना देना चाहिए ताकि आवश्यकता के अनुरूप नवीन संस्थाओं का निर्माण किया जा सके ।

४. जो क्षेत्र राष्ट्रीय संप्रभुता के अधीन नहीं हैं वहां पर प्रशासकीय सत्ता स्थापित कर लेनी चाहिए, उदाहरण के लिए बाहरी आकाश (Outer Space) ।

५. संधि को सर्वव्यापी बनाने के लिये सभी राष्ट्र इसके सदस्य होने चाहिये ।

६. आय का कोई स्वतन्त्र स्रोत रखना चाहिए । राष्ट्रों के चरश एवं सहयोग पर अवलम्बित रह कर संधि सच्चे अर्थों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रहता है । संधि को चाहिए कि वह विकास कर (Improvement Tax), सेवा कर (Service Tax), यात्री कर (Traveller Tax) आदि लगाये तथा विश्व बैंक की आय तथा बाहरी आकाश की फीस आदि द्वारा अपनी आय को बढ़ाये ।

७. वर्तमान अंगों की बनावट तथा कार्य-प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए ।

८. विश्व कानून की प्रणिया का विकास करना चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रयोग से अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए ।

९. चार्टर का परिवर्तन करना चाहिए ।

महासचिव के सुझाव (Suggestions of Secretary General)—
संधि के प्रथम महा सचिव ट्रिग्वेली (Triggve Lie) ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किये थे जो इस प्रकार हैं—

(1) जर्मनी के भविष्य की समस्या का कोई प्रभावपूर्ण समझौता कर लेना चाहिए ।

(II) सुरक्षा परिषद के पास अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों की सुलझाने तथा शांति को कायम रखने के लिए काफी शक्तियाँ हैं, इनका उपयोग करना चाहिए ।

(III) सुरक्षा परिषद के प्रयोग के लिए अनुच्छेद ४३ के आधीन सदस्यों को सशस्त्र सेना देनी चाहिए ।

(IV) घातक शस्त्रों में उत्पन्न समस्याओं पर नियन्त्रण करने के लिए सच को इसका अध्ययन कराना चाहिए ।

(V) सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को अपनी वीटो शक्ति का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

(VI) सच के सदस्यों को महासभा एवं सुरक्षा परिषद के निर्णयों को यथासम्भव समर्थन देना चाहिए ।

संयुक्त राष्ट्र सच विश्व शांति एवं सुरक्षा का प्रतीक है किन्तु इस प्रतीक का प्रयोग पूरी तरह एवं सतोषजनक रूप में अभी तक नहीं किया गया है । पर यह भी सत्य है कि श्रम्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में इसने शांति बनाये रखने के अनेक बार सफल प्रयास किये हैं । विश्व के राष्ट्रों एवं लोगों की सेवा के लिए जो विभिन्न संगठन तथा आयोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच सच ने समन्वय की स्थापना की है । संयुक्त राष्ट्र सच वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीयता की एक आवश्यक उपयोगी एवं अपेक्षित विशेषता है तथा अगु-युग में अस्तित्व की आवश्यक शर्त ।

संयुक्त राष्ट्र सच की कुछ विशिष्ट उपयोगिताएँ

संयुक्त राष्ट्र सच के समस्त २५ वर्षों की अवधि में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रमुख राजनीतिक विवादों और उनके समाधान के लिए किए गए सच के प्रयासों का वर्णन हम कर चुके हैं । संयुक्त राष्ट्र सच ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपनी अमूल्य सेवाएँ आज तक अर्पित की हैं जिनके महत्व की इतिहास में सदैव स्वर्णशिरो में लिखा जाता रहेगा । इनके अतिरिक्त सच की कुछ विशिष्ट उपयोगिताएँ या विशेषताएँ हैं जिन पर दो पन्च पृष्ठीय से सारांश देना उपयोगी होगा । ये विशेषताएँ या उपयोगिताएँ निम्न हैं—

(१) सच द्वारा अन्तर्राष्ट्रीयता का प्रसार,

(२) सच विश्व शांति की ओर एक कदम,

(३) सच द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर एवं पजीकरण,

(४) सच द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा ।

(१) समुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर
(U. N. O. towards Internationalism)

उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में तप द्वारा जो कार्य किया गया वह सफल रहा अथवा नहीं एवं उससे आशाजनक परिणाम प्राप्त किए जा सके अथवा नहीं, इस प्रश्न पर तथ्यों की व्याख्या करते समय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों के बीच मतभेद रह सकता है। परन्तु यह मतभेद रहते हुए भी निःसन्देह रूप से यह कहा जा सकता है कि संघ ने विश्व-युद्ध को रोकने, विनाश की भीषणता को अवरुद्ध करने, न्याय, कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने में जो योगदान किया है उसे मानव जाति कभी नहीं भूल सकती। ७ जून, १९६३ को संघ की बजट कमेटी में भाषण देते हुए भारतीय प्रतिनिधि श्री बी० एन० चक्रवर्ती ने कहा था कि हम संघ से रहित विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। इसके बिना हम सशस्त्र, युद्ध और विध्वंस की पुरानी स्थिति में लौट जाएंगे। समुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के बीच अपनत्व की भावना का विकास करने की चेष्टा की गई है। इसके विशेष अभिकरणों द्वारा शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति आदि क्षेत्रों में जो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं तथा पिछड़े देशों में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को आगे बढ़ाने के जो प्रयत्न किए जाते हैं उनका प्रभाव यह होता है कि जिन लोगों को इसकी सेवाओं से लाभ प्राप्त हो रहा है उनके दिलों में इसके प्रति सम्मान के भाव जागृत होंगे। समुक्त राष्ट्र संघ जैसे आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक प्रयत्नों का पक्षपाती है उसी प्रकार वह एक राष्ट्र की प्रत्येक समस्या में दूसरों राष्ट्रों के सहभाग्यपूर्ण सहयोग को सम्भव बनाता है। इससे ससार के राष्ट्रों के बीच मिलजुल कर रहने तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की परम्पराओं का सूत्रपात होता है। यह कहा जाता है कि समुक्त राष्ट्र संघ ने आज एक विशेष प्रकार का वातावरण तैयार कर दिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने आपको समग्र विश्व का एक अंग मानने लगा है। एक राष्ट्र की सम्प्रभुता मर्यादित होकर उच्छृंखलताओं एवं मनमानी प्रवृत्तियों से हटकर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं से मर्यादित होने लगी है। यह आक्रमणकारी, विध्वंसक तथा विद्वेषपूर्ण अपने कुरूप चोले को छोड़कर विश्व कल्याण एवं मानव-जीवन के चरम लक्ष्यों की प्राप्ति के भागों का सौन्दर्यपूर्ण याना पहन चुकी है।

समुक्त राष्ट्र संघ में कार्य करने वाले नागरिक सेवा के वर्गचारी हजारों की संख्या में होते हैं, ये बल्य अलग देशों के निवासी होते हुए भी जब हमें विश्व की समस्याओं पर विचार करने तथा उनसे नग्नित हो कार्य

करते रहते हैं तो यह स्वाभाविक है कि उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीयतावाद की सकुचित परिधिओं से ऊपर उठ कर अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से ओतप्रोत हो जाए। प्रत्येक विषय पर सोचते समय उनकी दृष्टि विश्व शांति, सुरक्षा एवं कल्याण पर ही टिकी रहती है। सिविल सेवकों की यह वर्ग दक्षता, क्षमता एवं ईमानदारी बहुत ऊँचे स्तर की होती है। अनेक राष्ट्रों के बहुत से प्रभावशाली व्यक्तियों का इस वर्ग के सदस्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। यह सम्बन्ध जब तब इन राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। दूसरे शब्दों में सच के सिविल सेवकों का बदला हुआ दृष्टिकोण उनके सम्बन्धियों की ओर इस प्रकार देश के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक बनता है। चार्टर की धारा १०० में कहा गया है कि महासचिव और कर्मचारी वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरी तरह से समझ तथा सच के बाहर के किसी राज्य या उसके अधिकारी से परामर्श प्राप्त न करें। उनकी पूरी की पूरी निष्ठा और भक्ति सच के प्रति होनी चाहिये। इसके साथ ही मनुष्य राष्ट्र सच का प्रत्येक सदस्य भी आवश्यक रूप से यह प्रतिज्ञा करता है कि वह महासचिव तथा उसके कर्मचारियों के दायित्वों के पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप को मानेगा और उनके पालन में किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयास न करेगा।

(२) संयुक्त राष्ट्र सच विश्व सरकार की ओर एक कदम
(U N O An Step towards World Govt.)

संयुक्त राष्ट्र सच द्वारा उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिनकी साधना के लिए अनेक विचारक विश्व सरकार की स्थापना की सिफारिश करते हैं। डाग हेमरशोल्ड ने सच के चार्टर में पाये जाने वाले पांच मूल सिद्धांतों को परिभाषित किया या, वे हैं—(i) समान राजनैतिक अधिकारों की एक व्यवस्था (ii) समान आर्थिक अधिकार (iii) विधि का शासन (iv) सामान्य सुरक्षा के अतिरिक्त कभी भी सैनिक शक्ति का प्रयोग न करना (v) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को तथा मनमुटावों को तय करना जो बाद में अन्तर्राष्ट्रीय अशांति का कारण बन सकते हैं। ठीक यही उद्देश्य विश्व सरकार के बढाये जाते हैं। विश्व सरकार की स्थापना एक साधन मात्र है जिसके द्वारा अनेक मान्य राजनीतिक एवं विचारक अनुसार में अशांति, असुरक्षा एवं विनाश को मिटा कर इसके स्थान पर शान्ति, सुरक्षा एवं व्यवस्था पूर्ण विश्व समाज की रचना करना चाहते हैं। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत के विनाश के सभी सम्भव साधन एवं अवसर प्रदान किये जायेंगे।

विश्व सरकार की प्राथमिक आवश्यकता होती है अन्तर्राष्ट्रीय समाज, जिसके अभाव में विश्व सरकार से सम्बन्धित कोई भी योजना सफलता से पांच गज दूर हो रहेगी। इसमें सन्देह नहीं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व सरकार में राष्ट्रों की सम्प्रभुता शक्ति को पूरी तरह समाप्त करके उसे अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के हाथों में सौंप दिया जायेगा। सम्प्रभुता का यह हस्तांतरण विश्व सरकार की स्थापना के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बाधा को दूर करने में भी कुछ कार्य कर रहा है। संघ द्वारा इसके सदस्यों को कुछ दायित्व सौंपे गये हैं जिनको पूरा करना विश्व-शांति एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। एक राष्ट्र द्वारा किसी विश्व संस्था द्वारा लगाये गये इन उत्तरदायित्वों का पालन कुछ सीमा तक उसकी सम्प्रभुता को मर्यादित करना है और इस प्रकार उसे विश्व सरकार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आज तक एक राष्ट्र की सीमित एवं संकुचित समस्याओं पर विचार करने वाले राजनीतिज्ञ विश्व सरकार का एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाज का संभालन तथा व्यवस्था किस प्रकार करेंगे यह भी एक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया है जहाँ विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञ अन्तर्राष्ट्रीय रूप में विचार-विमर्श कर सकें, विश्व की समस्याओं का समाधान ढूँढ सकें। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक प्रशिक्षण केन्द्र है जहाँ विश्व के निवासियों एवं राष्ट्रों के नेताओं को उन सब बातों की शिक्षा दी जाती है जो विश्व सरकार की स्थापना एवं संचालन के लिए अनिवार्य हैं। क्लार्क एडिचबर्गर (Clark Eicheberger) के मतानुसार यदि विश्व शांति प्राप्त करना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक सीमित सरकार के रूप में कार्य करना चाहिये इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर एवं पंजीकरण

(Codification and respect for International Law)

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून को नियमबद्ध (Codified) करने में बहुत कुछ योगदान किया है। इसके चार्टर में इस कार्य पर विशेष जोर दिया गया है। महासभा ने १७ सदस्यों की एक आतंजालिक समिति (Ad-hoc Committee) नियुक्त की है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास तथा पंजीकरण के कार्य को कर सके। चार्टर के अनुच्छेद १३ के अनुसार महासभा का यह उत्तरदायित्व है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास तथा पंजीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करे। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के

साधनों को इस समिति द्वारा खोज की जाती है। सितम्बर, १९४७ के अपने प्रतिवेदन में समिति ने एक अन्तर्राष्ट्रीय कानून-आयोग नियुक्त करने की सलाह दी। इस आयोग को दो प्रकार के काम सौंपे जाने थे। प्रथमतः उस अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विषय का अध्ययन जो अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। दूसरे, उन कानूनों को सक्षिप्त रूप में देना जिनका पहले से ही अभिसमयों, परम्पराओं एवं सिद्धान्तों के रूप में प्रचलन है। समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई कि आयोग को प्रवर्जित अन्तर्राष्ट्रीय कानून (Customary International Law) के विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना चाहिये ताकि पंजीकरण के लिए शीघ्रक छाटे जा सकें। समिति ने बताया कि उसके उत्तरदायित्व से दो कार्य निकलते हैं—(1) नवीन कानून का प्रगतिशील विकास (2) प्रस्तुत कानून का पंजीकरण। इन दोनों कार्यों के बीच भारी अन्तर वर्तमान है। महासभा ने २१ नवम्बर, १९४७ को अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग (ILC) की स्थापना की। इसके १५ सदस्यों को तीन वर्षों के लिये चुना गया।

आयोग ने राज्यों के अधिकार और कर्तव्यों पर एक घोषणा तैयार की तथा न्यूरेम्बर्ग युद्ध अपराधी द्रापन (Nuremberg War Crimes Trials) के आधारभूत कानूनों के सिद्धान्तों में से कुछ को रचनात्मक रूप प्रदान किया। पंजीकरण (Codification) के क्षेत्र में आयोग ने अपना ध्यान मुख्यतः चार विषयों पर ही केन्द्रित रखा।

- (१) सन्धियों के कानून (Law of Treaties)
- (२) न्यायीकरण प्रक्रिया (Arbitral Procedure)
- (३) ऊँचे समुद्रों की शासन पद्धति (Regime of the high Seas)
- (४) प्रादेशिक जल (Territorial Waters)

महासभा ने आयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय कौशदारी न्यायालय स्थापित करने के बारे में राय पूछी। १९५० में आयोग ने रिपोर्ट दी कि इस प्रकार का न्यायालय (Tribunal) अपेक्षित भी है तथा सम्भव भी। महासभा ने १९५१ में आयोग को आक्रमण की परिभाषा का काम सौंपा, किन्तु भारी वाद-विवाद के बाद आयोग इस निर्णय पर आया कि आक्रमण की कोई भी सक्षिप्त परिभाषा अव्यावहारिक है। समुक्त राष्ट्र द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कानून के पंजीकरण का कार्य केवल आयोग ही नहीं करता है, वरन् सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, मानवीय अधिकार आयोग (The Human Rights Commission) आदि भी इस दिशा में कार्य करते हैं। उस द्वारा दशों के राजनैतिक मतभेद दूर करते समय अपना अन्तर्राष्ट्रीय

शान्ति एवं सुरक्षा की स्थापना एवं रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाते समय अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन पूरी तरह किया गया है। इसका हर सम्भव प्रयास यह रहता है कि सभार के विभिन्न राष्ट्रों में इन कानूनों के प्रति आदर-भाव पैदा किया जाय और कहीं भी, किसी भी स्थिति में उनका उल्लंघन न किया जाय। युद्ध के कानून व शान्ति के कानून, समुद्री सीमा सम्बन्धी कानून, व्यापार सम्बन्धी कानून एवं अन्य किसी भी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय कानून यदि किसी भी रूप में तोड़ा गया तो विश्व की शान्ति एवं व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी, इसलिये मंच द्वारा यह पूरा-पूरा ख्याल रखा जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो न होने दी जाय।

(४) संधि द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा

(Protection of Human Rights by the U. N. O.)

संयुक्त राष्ट्र संधि व्यक्ति के मानवीय अधिकारों एवं राष्ट्रों के लिए स्वतन्त्रताओं से पूरी तरह सम्बन्धित है। अनुच्छेद ५५ तथा ५६ में इन विषयों के ऊपर पर्याप्त रूप से विचार किया गया। चर्चित सभा स्जवेल्ड का कहना था कि इनका अर्थ यह है कि सभी प्रदेशों के सभी व्यक्ति आवश्यकता एवं समय से स्वतन्त्र रह कर अपना जीवनयापन कर सकें। महासभा ने पेरिस में १० दिसम्बर, १९४८ को आधी रात को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र दिया। जब यह घोषणा की गई तो महासभा के अध्यक्ष ने कहा कि यह पहला ही अवसर है जबकि राष्ट्रों के संगठित समुदाय ने मनुष्यों के अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रताओं की घोषणा की है। इस घोषणा के पीछे संपूँर्ण संधि की, विश्व के समस्त स्त्री पुरुषों की शक्ति है जो दूरस्थ होने पर भी इस घोषणा को अर्पण करने के लिए सहामता, प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। महासभा के अनेको प्रस्ताव इस घोषणा के सिद्धान्तों पर ही आधारित हैं। इसके बहुत से अनुच्छेद शान्ति सन्धियों में समाहित कर दिये गये हैं तथा नये राज्यों के संविधानों में भी इन्हें लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संधि द्वारा मानव अधिकारों की कई परम्पराएँ स्थापित कर दी गई हैं :—

(i) जाति, नस्लीय एवं धर्म सम्बन्धी (Genocidal Convention)

(ii) महिलाओं के राजनैतिक अधिकार (Political Rights of Women) महासभा द्वारा १९५० में निर्मित परम्परा

(iii) दासता विरोधी परम्परा (Anti-slavery Convention) १९५५

(iv) जबरदस्ती के काम के विरुद्ध परम्परा (Convention Against Forced Labour) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा १९५३ में निर्मित L

सन् १९५३ में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा मानव अधिकारों के सम्बन्ध में जा रूख अपनाया गया था वह इस आन्दोलन के पूरी तरह से विरुद्ध था। किन्तु २२ जुलाई, १९६३ को जान एफ० कनेडी ने इस निषेधात्मक नीति का उलट दिया। इन्होंने अमरीकी सीनेट को संयुक्त राष्ट्र सभ की उन्नत चार परम्पराओं में से तीन को स्वीकार करने को कहा, प्रथम परम्परा (Genocide Convention) का उल्लेख नहीं किया गया था। मानव अधिकार आयोग के अमरीकी प्रतिनिधि ने इस दिशा में अमेरिकन कार्य योजना (American Action Programme) को प्रस्तुत किया। इसका तीन भाग थे—

(i) मानव अधिकारों पर सामयिक प्रतिवेदनों (Periodic Reports) की योजना।

(ii) मानव अधिकारों पर अध्ययन की एक शृंखला (Series)।

(iii) कुछ मानव अधिकारों में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

यह सहायता तीन प्रकार से दी जा सकती है अर्थात् विशेषज्ञों के उपबन्ध द्वारा, बर्जीफा तथा फेलासिप के उपबन्ध द्वारा, सेमिनारों के संगठन द्वारा। विश्व शान्ति तथा मानव अधिकारों के बीच भारी सम्बन्ध है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है तथा ये दोनों परस्पर सहयोगी भी हैं। क्लार्क आइकबर्गर (Clark M Eicheberger) का मत है कि राष्ट्र स्थायी शान्ति की ओर अग्रसर होने हैं तो यह भी अपरिहार्य है कि मानवीय अधिकारों की भी प्रगति होगी तथा वे सुरक्षित हाने।¹

संयुक्त राष्ट्रसंघ-एक मूल्यवान

अथवा

संयुक्त राष्ट्र संघ की देन

संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर, उसके विभिन्न संगठनों और कार्यकलापों आदि से यह भलीभांति स्पष्ट है कि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संस्था है जिसने अनेक अवसरों पर युद्धों का निवारण करके और गंभीरतम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करके विश्व में तृतीय महायुद्ध के भूतपात को भविष्य के लिए टाला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि महासक्तिप्राप्त संस्था के माध्यम से अनेक विवादों को ईमानदारी से सुलझाने का प्रयत्न

1. Clark M Eicheberger, U. N - The first twenty years, 1965, P. 85.

करें और इस समस्या के कार्यों में अपेक्षित सहयोग दें तो भविष्य में तृतीय महायुद्ध की संभावना को भी यह समस्या बहुत कुछ समाप्त कर सकती है।

आलोचकों का यह कहना कि मध्य अपने प्रधान उद्देश्य—युद्धों के निवारण और अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल करने में विफल हुआ है, अनेक समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं कर सका है और न ही शांतिकरण की होड़ को मिटा पाया है, निरगदेह बहुत कुछ सत्य है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मानवीय अधिकारों और अन्तर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सम्भालने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ आज तक दक्षिण अफ्रीकन संघ में भारतीयों और अरब जातियों के साथ दुर्व्यवहार को नहीं रोक सका है, साम्यवादी चीन को न अपना सदस्य बना सका है और न ही उसकी हिंसात्मक पाशविक प्रवृत्ति पर ही किसी तरह का अकुश लगा पाया है, पूर्व और पश्चिम के मनभेदों को नहीं पाट सका है, महाशक्तियों के वैमनस्य और विरोध को नहीं मिटा सका है। इसने वाश्मीर की स्राष्ट और सरल समस्या को जलजाया है तथा महाशक्तियों के हाथों में खेल कर आक्रान्ता व आक्रमणकारी की तराजू के दोनों पलड़ों में बैठाकर बराबर तोलने की चेष्टा की है। इतना ही नहीं, आक्रान्ता पाकिस्तान की आक्रमणकारी प्रवृत्ति पर रचनात्मक नियन्त्रण भी लगाने में यह असफल रहा है, उल्टे इसकी गतिविधियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को अवैधानिक रूप से लिये गये भारतीय प्रदेश में घेर जमाये रखने को प्रोत्साहित ही करती रही हैं। यह महाशक्तियों के शीत युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है और अनेक अवसरों पर इसने अनेक देशों की स्वतन्त्रता व स्वाधीनता के अपहरण को करीब एक मूकदर्शन के समान निहारा है।

मध्य के पास अपनी स्वयं की दण्डकारी शक्ति का अभाव है। इसकी अपनी स्वयं की कोई सेना नहीं है। मध्य शक्ति और आर्थिक दृष्टि से यह अपने सदस्य देशों की श्रृंखला का आकांक्षी है। जहाँ महाशक्तियों के स्वार्थ निहित होते हैं वहाँ मध्य के निर्णय काम नहीं आते बल्कि महाशक्तियों के अपने निर्णय ही महत्व रखते हैं। किन्तु जहाँ छोटे राष्ट्रों का प्रश्न होता है वहाँ मध्य अपने प्रयासों की सफलता की कुछ भी बचाकर अन्तर्राष्ट्रीय शांति का रक्षक होने की माहौल-माहौल रूढ़ता है और वह भी इसीलिए कि महाशक्तियों का उन छोटे राष्ट्रों की दबाकर मध्य का निर्णय मानने को बाध्य कर देती हैं। यदि विभिन्न शांति प्रस्ताव ईमानदारी के साथ और सही भावना से मुरदा परिपक्व में प्रस्तुत होते भी हैं तो महाशक्तियाँ अपने परस्पर विरोधी स्वार्थों के कारण अपने विषेधाधिकार से उन्हें नष्ट कर देती हैं। वस्तुतः मध्य में इतना

विरोध और विवेधाधिकार का प्रयोग देखने को मिलता है कि इसे "संयुक्त राष्ट्र सभ" कहने के स्थापन पर विमर्श तथा विरोधों दोनों में विभाजित राष्ट्र सभ कहना अधिक उपयुक्त लगता है।"

सितम्बर १९६६ में संयुक्त राष्ट्र सभ की २१ वीं महासभा के समय अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सभ के हो महासचिव ऊ पाट ने यह स्वीकार किया था कि सभ अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति को दिशा में बहुत कम प्रगति कर पाया है। उसका मूल कारण उनके मतानुसार यही है कि सभ परस्पर विरोधी महाशक्तियों के संघर्ष का असाध्य बना हुआ है।

महासचिव ने बड़े राष्ट्रों पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि वे पारस्परिक शंका, भय और अविश्वास को भावनाओं से प्रेरित हैं और प्रत्येक समस्या पर मानवीय हित के दृष्टिकोण से विचार नहीं करते। सभ के संगठनात्मक दोषों का उल्लेख करते हुए उ-होने इस बात की सिफारिश की कि जनवादी चीन को सभ का सदस्य बनाया जाना चाहिये ताकि संयुक्त राष्ट्र सभ सच्चे अर्थों में सभी राष्ट्रों का संगठन बना सके।

संयुक्त राष्ट्र सभ के समक्ष तीन आधारभूत समस्याएँ रही हैं—पूर्व और पश्चिम के मध्य संघर्ष, पेट्रोल अधिकार क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र सभ के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न विवाद। इन तीनों आधारभूत समस्याओं पर विजय प्राप्त करने में सभ वस्तुतः समर्थ नहीं हो सकता है। हंगरी और तिब्बत के मामले पर सोवियत रुख तथा चीन पर कोई दबाव डालने में उसकी असमर्थता और असफलता हम बात का प्रमाण है कि सभ सन्निधायी राष्ट्रों के सम्मुख जितनी कमनीय स्थिति रखे हुए हैं।

परन्तु इन सब कमियों, दोषों व दुर्बलताओं के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि संयुक्त राष्ट्र सभ केवल मात्र राष्ट्र सभ की ही एक पुनरावृत्ति है और इसके अस्तित्व का महत्व नगण्य है। वास्तविकता यही है कि अपनी विफलताओं में भी यह निरन्तर सक्रियता की मोडिया चढ़ता रहा है और इसने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को घटा कर शान्ति बनाय रखने की दिशा में सहाय्यीय प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र सभ मरणासन्न नहीं है अपितु प्रगति पथ पर अग्रसर है। इसने न केवल अनेक राजनीतिक विवादों में सफलता पायी है बल्कि नैर राजनीतिक कार्यों में भी महान यश कमाया है। यह कहना अत्यन्तपूर्ण न होगा कि नैर राजनीतिक अर्थात् सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में ही इसने नकार की अन्य किसी भी समस्या की अपेक्षा अधिक दलायनीय कार्य किया है। २५ वर्षों की अल्प अवधि में विश्व के सभी भागों में निवास करने

बाली जनता के जीवन-स्तर को सुधारने के लिए विशाल धन-सधिया व्यय की गयी है। विद्यार्थी, बाढ़-नियन्त्रण, विद्युत-शक्ति, उत्पादन, भूमि की उपज में वृद्धि सम्बन्धी लगभग ६० से भी अधिक योजनाओं पर अमल किया जा रहा है ताकि मानव जाति प्रकाल के खतरे से मुक्त हो सके। स्वास्थ्य, धर्म एवं चिकित्सा के क्षेत्र में इसके प्रभाव स्वर्गांतरों में लिखे जाने योग्य हैं।

राजनैतिक विवादों को हल करने में भी यह सर्वथा असफल नहीं रहा है। १९४८ और बाद में जमी १९६७ में भारत-पाक सपर्ष का अन्त करके मुद्द-बिराम की स्थिति छाने में, १९४८, १९५६ और १९६७ के अरब-इजरायल सपर्षों में हर बार मुद्द रोक कर शांति स्थापित करने में स्वैर नहर को फास और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी नापाक इरादों से बचाने में, दक्षिणी कोरिया को साम्यवाद के लौह सिकने से मुक्त रखने में, ईराक, सीरिया व लेबनान से विदेशी सेनाएँ हटाने में, इन्डोनेशिया में मुद्द बन्द कराने में, बर्लिन के घेरे में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में, कागा के गृहमुद्द को समाप्त कर उसके एकीकरण को बनाये रखने में और ऐसे ही अनेक विवादों में सप ने उत्तेजनीय सफलता अर्जित की है।

समुक्त राष्ट्रमण के अस्तित्व के कारण ही बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों के विरुद्ध, अधिकांशतः शक्ति का प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं, इस तरह मुद्द का भय कुछ कम हुआ है और इस दृष्टि से छोटे राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त महासभा की पनान्त अधिवार होने के कारण छोटे-छोटे सदस्य राष्ट्रों को अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के अवसर प्राप्त हुए हैं और उन्होंने अपने सामाये इन अवसरों का पूरा उपयोग किया भी है। यह निश्चित रूप से एक धूम सशान है कि संभवतः पहली बार छोटे-छोटे राष्ट्रों द्वारा बड़े राष्ट्रों के प्रसारों को निष्कट कर पाता सम्भव हो सका है। उदाहरणार्थ महासभा में एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्रों के सम्मिलित प्रसार के कारण ही सोवियत रूस का 'त्रिमोका' सिद्धान्त कार्यान्वित न हो सका।

समुक्त राष्ट्र सप का प्रभाव राष्ट्रों की सीमाओं से परे व्याप्त शक्तों और शक्तियों पर विमोद रूप से पड़ा है। इसने अन्तर्राष्ट्रीयता के प्रसार में अपने प्रभाव का सम्पूर्णनीय ढंग से उपयोग किया है और अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को अधिक सबल व स्पष्ट बनाया है।

यद्यपि सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से सप एक ध्वस्त और एकीकृत प्रणाली का उपयुक्त विहास नहीं कर पाया है किन्तु फिर भी मानव-जाति की समस्याओं, कठिनाइयों, विपन्नताओं को इसने प्रभावशाली ढंग से मुचरित

किया है। यह विश्व की समस्याओं और वास्तविकताओं का एक सुन्दर दर्पण है।

संयुक्त राष्ट्र सभ ने साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के उन्मूलन में पर्याप्त सफलता पायी है। एबसीनिया, लीबिया, सोमालीलैण्ड, मोरक्को, ज्युनीसिया, टोगोलैण्ड आदि की स्वाधीनता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति क्रूरतापूर्वक अत्याचारों की चर्चा जब सभ के रगमच पर की जाती है तो उसका प्रचार अविलम्ब सम्पूर्ण विश्व में हो जाता है और इसका यह प्रभाव पड़ता है कि नैतिक दबाव अनेक बार सैनिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा पैदा किये गये नैतिक बल और विश्व जनमत के कारण ही रूस को बदनाम होकर ईरान से सेनाएँ हटानी पड़ी, फ्रांस को उत्तरी अफ्रीका के उपनिवेश छोड़ने पड़े और हालैण्ड को इण्डोनेशिया का मोह त्यागना पड़ा।

विश्व युद्ध के मकड़ को टालने के लिये निःशस्त्रीकरण तथा आणविक शक्ति पर प्रतिबन्ध की दिशा में संयुक्त राष्ट्र सभ निरन्तर सक्रिय है और असफलताओं के एक लम्बे इतिहास के बाद अब ऐसी योजनाएँ प्रस्तुत होने लगी हैं जिन पर महाशक्तियों में पूर्वापेक्षा अधिक मतभेद हो सकता है। १९६८ की परमाणविक प्रसार निरोध सन्धि इस दिशा में एक उत्साहवर्धक सफलता है।

इस तरह स्पष्ट है कि अपनी दुर्बलताओं व विफलताओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सभ मानवीय बुद्धि द्वारा परिकल्पित अब तक का श्रेष्ठतम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। यही एकमात्र ऐसी मस्या है जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्थिरता ला सकती है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि सभी क्षेत्रों में संधि की क्षमता और उसके साधनों का उपयोग बुद्धिमत्ता तथा विवेक के साथ किया जाय और मात्र व सदस्य, विशेष कर महान् राष्ट्र, चार्टर के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान रह कर उन पर त्रियात्मक आचरण करें। संयुक्त राष्ट्र सभ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय मस्या अभी जोवित रह सकती है व सफलीभूत हो सकती है जबकि इसके सभी सदस्य राष्ट्र सहअस्तित्व के सिद्धान्त पर चलें और गगठन में विश्व के सभी राष्ट्रों का उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए उद्यत रहें। सदस्य राष्ट्रों ने जिस तरह सभ की विश्व में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने में, विश्व की सामाजिक, शैक्षणिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में, विश्व क्षेत्र में सामाजिक बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने में, एक स्वतन्त्र, स्वस्थ और सुखद जीवन किस प्रकार विश्व में जन-जन को प्राप्त हो, इसका रास्ता

दूढ़ता के प्रयत्नों में प्रशंसनीय सहयोग दिया है और दे रहे हैं, उसी प्रकार वे राजनीतिक क्षेत्र में मानव मन में विश्वास जमाने में सघ के उद्देश्यों में सहयोग दें। इस सम्बन्ध में अन्त में यही कहा जा सकता है कि मानव चाहे तो यह संयुक्त राष्ट्र सघ एक विश्व राज्य बन सकता है बशर्ते कि मनुष्य अपनी इस चेतना के प्रति पूरी तरह जाग उठे कि संकुचित एकदेशीय भावना से ऊपर उठे बिना, समस्त मानव कल्याण की दृष्टि से सोचे बिना उसका प्राण नहीं।

वियतनाम और पश्चिम एशिया की समस्याएं

(PROBLEMS OF VIETNAM AND WEST ASIA)

वियतनाम और पश्चिमी एशिया के सकट लम्बे अर्धों से अन्तर्राष्ट्रीय शांति को भंग किये हुए हैं। ये सकट इतने विस्फोटक हैं कि यदि इन पर शीघ्र ही काबू नहीं पाया गया तो ये कभी भी तृतीय महायुद्ध का कारण बन सकते हैं। अग्रिम पंक्तियों में हम पहले वियतनाम-समस्या को लेंगे और तब पश्चिमी एशिया अथवा मध्य-पूर्व के सकट को।

वियतनाम की समस्या (Problem of Vietnam)

वियतनाम देश का क्षेत्रफल लगभग १,२७,००० वर्गमील और जन संख्या ३ करोड़ से भी अधिक है। वियतनाम कभी हिन्द-चीन का सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम 'वान्गो' साम्राज्य के नाम से हुआ। लगभग २००० वर्षों से भी अधिक लम्बे समय में इस राष्ट्र ने कई नामों से अपना अस्तित्व बनाये रखा। एक समय इस पर चीन का भी अधिकार रहा, किन्तु १९वीं शताब्दी में जब हिन्द-चीन पर फ्रांस का अधिकार हुआ तो वियतनाम भी फ्रांस के कब्जे में चला गया। द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने पर हिन्द-चीन की फौज सेना जापान की बढ़ती हुई सेना का मुकाबला नहीं कर सकी। परन्तु कूटनीति का सहारा लेते हुए जापान ने हिन्द-चीन पर अपने सैन्य बल से अधिकार नहीं किया वरन् सैन्य बल के आतंक की छाया में फ्रांस प्रशासन के साथ २१ जुलाई सन् १९४१ को एक पारस्परिक सुरक्षा समझौता

करके हिन्द-चीन में प्रविष्ट होने की अनुमति प्राप्त कर ली। युद्ध-काल में जापान ने इस देश के प्राकृतिक स्रोतों का अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरा उपयोग किया। मार्च, १९४५ में उसने इस क्षेत्र में फ्रेंच-प्रशासक वर्ग को पदच्युत कर दिया।

जापान के युद्धकालीन शासनकाल के दौरान वियतनाम की राष्ट्रवादी शक्तियाँ विशेष रूप से प्रबल हो गईं। उन्होंने "बीत मिन्ह लीग" नामक एक राष्ट्रवादी आति दल की स्थापना की। इसका नेतृत्व साम्यवादी छापा-मार नेता 'थी हो-ची मिन्ह' को सौंपा गया। वियतनाम के आतिकारी और राष्ट्रवादी तत्वों ने जापान के इस क्षेत्र से हटने के समय इतनी प्रचुर युद्ध सामग्री हस्तगत करली कि वे दीर्घकाल तक छापा-मार युद्ध चला सकने की स्थिति में आ गये। जून अगस्त, १९४५ में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और वियतनामवासियों को जापानी निरंकुश नियन्त्रण से छुटकारा मिला तो बीतमिन्ह राष्ट्रवादियों ने सितम्बर में ही फ्रांस से अपनी स्वतन्त्रता घोषित करके 'वियतनाम गणतन्त्र' का उद्घाटन किया। अगस्त, १९४५ में उन्होंने एक राष्ट्रीय महासभा आयोजित की तथा अपने देश की नूव-स्थापित सरकार के लिए थी हो-ची-मिन्ह को राष्ट्रपति चुना। बाग्रीशई ने (जो अन्तर्गत का प्रतुर्व सन्नाट था और जिसने महायुद्ध के दौरान वियतनाम की स्वाधीनता की घोषणा करते हुए स्वयं को वियतनाम का शासक घोषित कर दिया था) हो-ची-मिन्ह द्वारा हनोई में स्थापित की गई कार्यकारी सरकार के 'सर्वोच्च राजनितिक परामर्शदाता' का पद प्राप्त करके सम्मेलन कर लिया। वियतनाम की हो-ची-मिन्ह सरकार ने राज्य का पूरा नाम 'वियतनाम लोकतन्त्री गणराज्य' रखा और कोचीन-चीन, टोंकिन तथा अन्तर्गत पर अपने प्रभुत्व का दावा किया।

वियतनाम के राष्ट्रवादियों द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही फ्रांस के लिए असह्य थी। जापान के हिन्द चीन से पराजय के बाद जब वियतनाम पुनः फ्रेंच प्रभुत्व के अन्तर्गत आ गया तो फ्रांस ने राष्ट्रवादियों से किसी प्रकार का समझौता करने के बजाय उनका दमन करने का विवेक विमोक्त फलस्वरूप बीतमिन्ह-राष्ट्रवादियों और फ्रेंच साम्राज्यवाद में युद्ध छिड़ गया।

१९४५ से लेकर १९५४ तक फ्रांस और हो-ची मिन्ह के बीच विरन्तर लड़ाई चलती रही। डॉ॰ हो-ची-मिन्ह की स्थानीय साम्यवादियों, कुछ और साम्यवादियों और बाद में चीनी साम्यवादियों की सहायता प्राप्त हुई। उनके अनुयायियों ने देश में आतंक, लूट, छापामार युद्ध और विध्वंस

को वातावरण प्रदा कर दिया तथा इस प्रकार फ्रांस के लिये वियतनाम में व्यवस्था स्थापित करना असम्भव बना दिया ।

सैनिक साधनों द्वारा हो-ची-मिन्ह पर विजय पाने में अपने को नाकामयाब पाकर फ्रांस ने राजनीतिक साधनों का आश्रय लिया । उसने असंतुष्ट बाओदाई को अन्नाम में एक नई कार्यकारी सरकार (Provisional Government) स्थापित करने के लिये उकसाया । ५ जून, १९४८ को बाओदाई ने कोचीन-चीन सहित 'रिपब्लिक ऑफ वियतनाम' के नाम से एक नई सरकार स्थापित कर ली । इस तरह अब वियतनाम में दो सरकारें काम करने लगी—दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की 'रिपब्लिक ऑफ वियतनाम' सरकार और उत्तर में डा० हो-ची-मिन्ह का 'वियतनाम गणतन्त्र' जिसे 'वीतमिन्ह' कहा जाने लगा । मार्च, १९४६ में बाओदाई ने फ्रांस की यात्रा की । फ्रेंच सरकार के साथ कुछ समझौते किये गए जिनके अन्तर्गत वियतनाम (वीतमिन्ह नहीं) 'फ्रेंच संघ का एक उपराज्य' (Associated State of the French Union) बना दिया गया । इसके वैदेशिक मामलों व इसकी सेनाओं पर फ्रेंच शासन का नियन्त्रण स्थापित हो गया । ३० दिसम्बर, १९४६ को बाओदाई ने सैगोन (Saigon) में स्वयं को 'राजाचक्ष' घोषित कर दिया । यह बाओदाई-शासित वियतनाम की राजधानी बनी । डा० हो-ची-मिन्ह द्वारा शासित वियतनाम की राजधानी हनोई ही रही ।

फ्रेंच साम्राज्यवाद की इस प्रकार की कूटनीतिक चालों ने स्पष्टतः वियतनाम में भीषण गृह-युद्ध की गुरुश्रान कर दी क्योंकि एक तरफ तो हनोई की सरकार स्वयं को सम्पूर्ण वियतनाम की वैधानिक सरकार कहने लगी और दूसरी ओर सैगोन सरकार सारे वियतनाम की वैधानिक सरकार होने का दावा करने लगी । नीध हो इस गृह-युद्ध ने एक राष्ट्र-घापी युद्ध का रूप धारण कर लिया । एक तरफ अमेरिकन डालरो, सस्त्रास्त्रों, टैंकों और वायुयानों में सुसज्जित १,५०,००० फ्रेंच सैनिक थे तो दूसरी तरफ साम्यवादी चीन की सहायता प्राप्त डा० हो-ची-मिन्ह के अपेक्षाकृत कम सैन्य में सैनिक । स्थिति तब और भी विषम हो गई जब सन् १९५० में अमेरिका और रूस 'गोल्ड युद्ध' (Cold-War) की भी हिन्दी चीन के द्वार तक खींच लाये । फरवरी, १९५० में सैगोन की 'वियतनाम सरकार' को समस्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, दार्जिलैण्ड एवं 'स्वतन्त्र विश्व' के अधिकांश राज्यों ने कूटनीतिक सन्मति प्रदान कर दी । दूसरी ओर डा० हो-ची-मिन्ह की 'हो-ची-मिन्ह सरकार' को युगालादिया से कूटनीतिक सन्मति मिली । इसके अतिरिक्त रूस, साम्यवादी चीन, 'लोह-आवरण' से सम्बन्धित अन्य देशों और कुछ एशियाई

राष्ट्रों का 'कूटनीतिक समर्थन' प्राप्त हुआ। डा० हो-पी-मिन्ह के राष्ट्रवादी अनुयायी वियतनाम के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अथक श्रम करने लगे। उन्होंने फ्रेंच साम्राज्यवाद द्वारा पोषित, मरक्षित और पूर्ण सहायता प्राप्त सैगोन-सरकार के विरुद्ध अपना अद्भुत छापामार-युद्ध जारी रखा। हनोई की सफलताओं ने वाशिंगटन को इस भय से सशक्त कर दिया कि कहीं सम्पूर्ण वियतनाम भी साम्यवादी शक्तों में न चला जाय। अतः उसने फ्रेंच सेनाओं की अधिराष्ट्रिक सैन्य सहायता देना आरम्भ कर दिया। इधर साम्यवादी चीन और रूस हनोई की 'बीत मिन्ह या वियत मिन्ह सरकार' को पर्याप्तमय हर प्रकार की सहायता प्रदान करने लगे। इस तरह 'उन्नियेशवादी शासकों' और 'उन्नियेशी शासितों' के बीच गुरु होने वाले युद्ध ने अब 'स्वतन्त्र विश्व' तथा 'अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद' के मध्य संघर्ष का रूप धारण कर लिया।

७ मई, १९५४ को 'बीत मिन्ह' सेनाओं ने हीत बीत फ्रेंच सेनाओं को सबसे बड़ी और निर्णायक पराजय दी। फ्रांस के लगभग १५,००० सैनिक बंदी बना लिए गये। इस भीषण पराजय ने हिन्द-चीन में फ्रेंच साम्राज्यवाद की कमर तोड़ दी। फ्रांस ने अमेरिका से और सैनिक सहायता भेजने की अपील की। वाशिंगटन न लन्दन के समक्ष 'समर्थ सैनिक हस्तक्षेप' का प्रस्ताव रखा किन्तु लन्दन ने साफ इन्कार कर दिया। एडमिरल रेडफोर्ड द्वारा एक पक्षीय अमेरिकन हस्तक्षेप और आणविक एस्त्रों के प्रयोग का सुझाव दिया गया, लेकिन युद्ध के विश्व व्यापी बन जाने के भय से राष्ट्रपति आइजनहोवर ने समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का ही निश्चय किया।

जेनेवा में युद्ध विराम संधि और वियतनाम का विभाजन

२६ अप्रैल से २१ जुलाई, १९५४ तक जेनेवा में हिन्द चीन की समस्याओं पर चर्चा चल रही थी और अन्त में २१ जुलाई को दोनों पक्षों में युद्ध विराम संधि हुई। इस सन्धि के अनुसार निम्नलिखित बातें स्वीकार हुई—

(१) यह देश दो भागों में बंट गया—उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम। १७वीं अक्षांश रेखा के उत्तर में हनोई नदी से लगता हुआ सारा उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को मिला और उससे दक्षिण में दक्षिण वियतनाम गणराज्य भी स्थापना हुई।

(२) दोनों भागों के बीच एक बकर क्षेत्र भी स्थापना की गई।

वियतनाम में आम चुनाव हुए और राष्ट्रपति दायम की सरकार ने सारी बहुमत प्राप्त किया। दूसरी ओर १५ जुलाई, १९६० को उत्तरी वियतनाम की राष्ट्रीय मण्ड ने सर्व-सम्मति से ७० वर्षों का होंघोमिन्हू को राज्याध्यक्ष (Head of State) चुन लिया। दोनों ही नेता सत्ता से चिपके रहे और एक-दूसरे पर जेनेवा का छाति समझौता भंग करने का दोष लगाते रहे। उत्तर की प्रेरणा से दक्षिण वियतनाम में साम्यवादियों ने १९६० में 'राष्ट्रीय मुक्ति सेना' (National Liberation Front) की स्थापना की। इन सैनिकों को सरकारी बयानों में वियत-कांग (Viet-Cong-Vietnamese Communists) कहा गया। यह वियतकांग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने लगा।

इससे तो अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा लेने के बाद हनोई सरकार ने दक्षिण के विरुद्ध पुनः तोड़-फोड़, घुसपैठ और छापामार लड़ाई प्रारम्भ कर दी और उधर १९६०-६१ के दौरान वियतकांग छापामार सैनिकों ने अपनी कार्यवाही देश के बहुत से भागों में अत्यधिक बढ़ा दी। १९६१ के अन्त तक लगभग २० हजार साम्यवादी वियतकांग छापामार सैनिक दक्षिण वियतनाम में जहाँ-तहाँ आनकपूर्व कृत्य करने लगे। लावार होकर दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति नो दिन्ह दायम (Ngo Dinh Diem) ने १६ अक्टूबर, १९६१ को सारे वियतनाम में आन्तकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। मई १९६१ में अमेरिकन उपराष्ट्रपति लिम्डन जानसन ने सेंगोन का दौरा किया। उन्होंने वापिस लौटकर अपनी सरकार की यह सिका रिखा की कि दक्षिण वियतनाम को अमेरिकन सहायता में वृद्धि की जाय और इन सहायता की गति को बढ़ाने के उपाय लिये जाय। इस पर राष्ट्रपति जेनेडी ने अक्टूबर १९६१ में जनरल मैक्सवेल टेलर को दक्षिण वियतनाम इसलिए भेजा कि वह साम्यवादी चुनौती का सामना करने के लिये सेंगोन सरकार की आवश्यकताओं को आँके।

१० दिसम्बर को अमेरिकन राज्य-विभाग ने 'शांति की खतरा' (A threat to the peace) के नाम से दो भागों में एक रिपोर्ट निकाला और आरोप लगाया कि वियतकांग 'मुक्ति आन्दोलन' का निर्देशन व संचालन उत्तरी वियतनाम से होता है, साम्यवादियों द्वारा दक्षिण-वियतनाम की विजित कर लिये जाने का मन्त्र है, और यह उद्दिष्ट है, और यदि ऐसा हुआ तो साम्यवादी युद्ध में १,४०,००,००० व्यक्ति और सम्मिलित हो पायेंगे जिससे लाओस की प्रगति का भाग पूरजत बन्द हो जायेगा जहाँ कि साम्यवादियों का पहले से ही आये देश पर प्रभुत्व है। दक्षिण वियतनाम सरकार और अमेरिकन प्रजासत्तन का यह सारा आरोप था कि हनोई सरकार

का यह प्रयास है कि वह दक्षिण वियतनाम की सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले साम्यवादी वियतनाम लोगों को सत्नासनों की सहायता देकर वहाँ की सरकार को नष्ट कर दे और दक्षिण वियतनाम को उत्तरी वियतनाम के साथ मिला ले।

४ जनवरी, १९६२ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम को आर्थिक और सैनिक सहायता देने की योजनाएँ घोषित की। लगभग एक मास बाद अमेरिकन सैनिक कमान स्थापित की गई और लगभग ४ हजार अमेरिकन सैनिक युद्ध कार्य में भाग लेने के लिए भेज गए।

दक्षिण वियतनाम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग (International Control Commission) से शिकायत की गई कि उत्तरी वियतनाम घुसपैठ और विनाश की कार्यवाहियाँ कर रहा है। किन्तु जब शिकायत पर आयोग द्वारा विचार किया जाने लगा तो पोलिश सदस्य ने आपत्ति की कि आयोग को दक्षिण वियतनाम की शिकायत की जाच पड़ताल करने का अधिकार नहीं है। परन्तु आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि उसे जाच करने का पूरा अधिकार है। सावियन सर और चीन ने दक्षिण वियतनाम के आन्तरिक मामलों में अमेरिका के अनुचित हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका द्वारा जो सैनिक कमान नियुक्त की गई है वह दक्षिणी वियतनामी जनता के उस देशमर्ति पूरा मर्त्य का दमन करने के लिए स्थापित की गई है जो अन्धश्रद्धा और साम्राज्यवाद के हाथों की कठपुतली दायम सरकार के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। साम्यवादी चीन द्वारा आपह किया गया कि जेनवा सम्मेलन का सहायक प्रधान आवश्यक परामर्श करके 'दक्षिण वियतनाम' से युद्ध के गम्भीर खतरे दूर करने के उचित उपाय करे। मार्च, १९६२ में रूस द्वारा माग की गई कि अमेरिका दक्षिण वियतनाम में युद्ध सामग्री ले जाना बन्द कर दे और वहाँ से अपने सैनिक अमले को वापस बुला ले। रूस द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के सदस्यों से भी आपह किया गया कि वे दक्षिण वियतनाम में अमेरिकन हस्तक्षेप बन्द करने के लिए दबाव डालें।

२ जून, १९६२ को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के भारतीय और वनाडियन सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया—

(१) उत्तरी वियतनाम आन्तरिक कार्यवाहियों का दोषी है। उसने दक्षिण वियतनाम में अनुत्पापूर्ण कार्यवाहियों को प्रोत्साहन व समर्थन देकर जेनवा समझौते की अवहेलना की है।

(ii) दक्षिण विपतनाम ने संयुक्त राज्य अमेरिका से वास्तविक सैनिक गठबन्धन करके जेनेवा समझौते की १६वीं और १७वीं धारा की अवहेलना की है।

आयोग का निर्णय किसी भी पक्ष की अपनी कार्रवाहियों से निरस्त न कर सका। दोनों विपतनामों के भविष्य और भावी सम्बन्धों का प्रश्न 'शीतयुद्ध' में उलझ कर रह गया। आरोपों-प्रत्यारोपों की धोछारें होने लगीं। रूस व साम्यवादी चीन उत्तरी विपतनाम के खूले समर्थक बने तो ब्रिटेन व कुछ अन्य पश्चिमी राष्ट्र दक्षिण विपतनाम में अमेरिका की स्थिति का समर्थन करने लगे।

दिसम्बर, १९६३ में अमेरिकन प्रतिरक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा (Robert McNamara) ने कुछ अन्य उच्च अधिकारियों के साथ संयोजन का दौरा किया और घोषणा की कि—"दक्षिण विपतनाम को जब तक आवश्यकता होगी, अमेरिकन सैनिक सहायता दी जाएगी।" किन्तु अमेरिका की इस घोषणा से वियतनाम के साहस में कोई कमी नहीं आई बल्कि उसकी आनकपूर्व कार्रवाहियों की भयावहता में वृद्धि होती गई। जनवरी, १९६४ में फ्रांस के राष्ट्रपति डिगाल ने जोर देकर कहा कि विपतनाम का तटस्थीकरण किया जाना चाहिए। मार्च, १९६४ में अमेरिका के राज्य सचिव डीन रस्क द्वारा कहा गया कि यदि वियतनाम अपनी सैनिक कार्रवाही समाप्त कर दें, चीन व उत्तरी विपतनाम दक्षिणी विपतनाम के मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दें और उसे शान्तिपूर्ण रहने दें तो अमेरिका अकेले दक्षिण विपतनाम का तटस्थीकरण भी स्वीकार कर सकेगा है। श्री डीन रस्क द्वारा यह विचार व्यक्त करने के तुरन्त बाद व मार्च की थी मैकनमारा व अन्य सैनिक तथा राजनीतिक अधिकारी पुनः संयोजन गये जहाँ उन्होंने एक प्रेस सम्मेलन में स्पष्ट सूत्रों में घोषणा की कि दक्षिण विपतनाम की आवश्यकता सभी आर्थिक, सैन्य, प्रशिक्षण सम्बन्धी और मानव सामग्री की सहायता अमेरिका देने की संसार है। अमेरिका द्वारा इस सहायता का उद्देश्य दक्षिण विपतनाम की जनता की साम्यवादी विपतनामों की प्रेरणाओं से छुटकारा दिलाना बताया गया। २३ जून, १९६४ को राष्ट्रपति जॉनसन द्वारा सन्तान सेनाध्यक्षों के प्रश्न और अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी श्री मैकसवेल रो. टेलर की दक्षिण विपतनाम में राजदूत नियुक्त किया गया। इस उत्तरी विपतनाम की ओर से १७ वीं मर्शाल रेखा पर दबाव बढ़ता गया, चीनी साम्यवादी सेना उत्तरी विपतनाम से लगती हुई चीन की दक्षिणी सीमा पर बिसाल शब्दा में प्रवेश हो गई और कुछ चीनी सेना को उत्तरी विपतनाम के भीतर तक अग्र

कर बैठ गई। साथ ही लगभग १,५०,००० साम्यवादी सैनिक दक्षिण वियतनाम में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गये।

उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी आक्रमण और सघर्ष में तीव्रता— अगस्त, १९६४ में वियतनाम में और भी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई। अमेरिका द्वारा उत्तरी वियतनाम के विरुद्ध सैनिक हस्तक्षेप करने का निरवधारण कर लेने के फलस्वरूप वियतनाम युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया। ५ अगस्त, १९६४ को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम की पण्डुब्बियों के अड्डों और तेल-पण्डुब्बियों पर ५ घंटे तक भीषण बम-वर्षा की। अमेरिका का आरोप था कि उत्तरी वियतनाम की पण्डुब्बिया टोनकिन (अथवा टोंगकिन) की खाड़ी में अमेरिकन गस्ती जहाजों पर आक्रमण करती रहती हैं और यह स्थिति अमेरिका को असह्य है। अमेरिकी बम वर्षा के बाद ही वियतनाम साम्यवादियों ने विनाल पैमाने पर छापामार-युद्ध आरम्भ कर दिया। सोवियत रूस ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के सैनिक ठिकानों पर बम वर्षा की तो वह उत्तरी वियतनाम को भरपूर सहायता देने को बाध्य हो जायगा। साम्यवादी चीन ने भी घोषणा की कि अभी तक उसने हिन्द-चीन में एक भी सैनिक नहीं भेजा है, लेकिन उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण होने की सूरत में उसकी सन्न का बाध टूट जायेगा।

रूस और चीन की चेतावनिया अप्रभावी रही। परिस्थिति दिन प्रति-दिन विषमतर होती गई। साम्यवादी वियतनाम छापामारों ने दक्षिणी वियतनाम के सैनिक अड्डों को तहस-नहस करने के प्रयत्न शुरू कर दिये। १ नवम्बर, १९६४ को वियतनाम छापा-मारों ने 'विएत-हो-आ' के हवाई अड्डे पर आकस्मिक रूप से भीषण हमला करके २७ विमान नष्ट कर दिये। इस आक्रमण में अनेक अमेरिकन सैनिक मारे गये और घायल हो गये। इस घटना के बाद राष्ट्रपति-जनरल ने सड़क शब्दों में घोषणा कर दी कि अमेरिका उत्तरी वियतनाम द्वारा वियतनाम छापा मारों को दी जाने वाली सैनिक सहायता बन्द करने के लिए सख्त रा प्रयोग करेगा। जनरल ने कहा कि यह सैनिक सहायता लाओस के मार्ग से जा रही है और जैनेवा समझौते के सर्वेष्वा प्रतिकूल है। दिसम्बर, १९६४ में व्हाइट हाउस से प्रकाशित एक विज्ञप्ति में दक्षिण वियतनाम को सैनिक सहायता देने का वचन दिया।

इसके बाद ही ७ फरवरी, १९६५ से उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकी हवाई हमले आरम्भ हुए। २७ फरवरी, १९६५ को वाशिंगटन ने एक द्বেत-पक्ष प्रकाशित किया जिसमें उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिण वियतनाम पर वियतनाम छापामारों द्वारा किये जाने वाले हमलों का विस्तृत विवरण दिया गया। इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि वियतनाम आन्दोलन

दक्षिण वियतनाम का स्वाधीन आन्दोलन नहीं है बल्कि ठहरा वियतनामी सरकार द्वारा प्रेरित और संचालित आन्दोलन है। —

समझौता प्रयासों की असफलता—पार्स से ही अमेरिकी हवाई हमलों की गति में तेजी आने लगी। फ्रांस, रूस, भारत आदि देशों ने उत्तरी और दक्षिण वियतनाम में समझौता कराने के लिए पुनः जेनेवा सम्मेलन बुलाये जाने की अरील की। महासचिव कपाट ने सम्बन्धित देशों के बीच वार्ता का प्रस्ताव दिया और १७ सितम्बर राष्ट्रों ने युद्ध बन्द करने की अरील की।

अप्रैल, १९६५ के आरम्भ में उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति डा० हो चो-मिन्ह ने एक चार मूनीय प्रस्ताव रखा जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त मुख्यतः यह माग की गई कि दक्षिण वियतनाम से अमेरिकी सेनाएँ हटा ली जाय, उत्तरी वियतनाम पर बम-बर्षा बन्द की जाय और मैगोन में वियतनाम के राजनीतिक कामकाज के अनुसर-समस्या तिराई जाय। प्रत्युत्तर में ७ अप्रैल, १९६५ को राष्ट्रपति जानसन ने घोषणा की कि यदि दक्षिणी वियतनाम की रबन्ध रखा जावे और सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना बहा रहे तो अमेरिकन सरकार "बिना सब वार्ता" करने को तैयार है। हनोई द्वारा जानसन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। सोवियत रूस और लाल चीन ने हनोई के दृष्टिकोण का समर्थन दिया। रूस ने हनोई के निकट वायुयान-भेदी प्रक्षेपास्त्रों के अड्डे बनाना शुरू कर दिया और चीन ने उत्तरी वियतनाम को रूसी सैनिक सामग्री ले जाने की सुविधाएँ प्रदान की। दूसरी ओर अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में अपनी नैनिक शक्ति बढ़ा दी। मई, १९६५ में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एक विधेयक पास किया गया जिसमें वियतनाम के लिए ७० करोड़ डॉलर की अतिरिक्त राशि स्वीकार की गई।

समझौता प्रयास चलने रहे। जून, १९६५ में लन्दन में हुए १४ वें राष्ट्र-मण्डलीय प्रधान मन्त्री सम्मेलन में एक "वियतनाम शांति आयोग" स्थापित किया गया, जिसे सोवियत मध्य, चीन और उत्तरी वियतनाम ने अस्वीकार कर दिया। जुलाई १९६५ में जब शास्त्री टीटो ने वियतनाम संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए गुरुवृत्त अरील जारी की तो साम्यवादी चीन ने टीटो और शास्त्री को "अमेरिकन साम्राज्यवाद के ऐजेन्ट" की गजा दी।

वियतनाम के मामले में नैत्र की प्रतिस्पर्धा सोवियत-चीन मामलों की भी उभारने लगी। उपर वियतनाम युद्ध में तीव्रता आती गई। १९६५ के अन्त तक वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा विभाग की घोषणा के अनुसार मयरीकी सैनिकों की संख्या १,८१,२६२ तक पहुँच गई। हिन्दु फिर भी यह समझा

जाता था कि वियतनाम युद्ध को जीतने के लिए ५ लाख तक अमेरिकन सैनिक आवश्यक हैं। वियतनाम युद्ध को शान्ति से निपटाने के लिए इस कूटनीतिक प्रयत्न करता रहा, लेकिन चीन संधय को उकसाने में ही अपना लाभ देखता था। पकिंग ने उत्तरी वियतनाम की सरकार को यह गंकेन भी दिया कि इस से मतभेद दूर करना मार्क्सवाद लेनिनवाद के प्रति विस्वासाघात समझा जायेगा। जब दिसम्बर १९६५ में सोवियत प्रधान मन्त्री ने मार्क्सवादी नेता एलेक्जेंडर श्चेलेपिन को वियतनाम युद्ध शांत कराने के उद्देश्य से हनोई भेजा तो चीनी नेताओं ने पूरा प्रयत्न किया कि उत्तरी वियतनाम में श्चेलेपिन का उद्देश्य पूरा न होने पावे।

१९६६ के समझौता प्रयास और मनीला सम्मेलन—सन् १९६५ में निमनस के अवसर पर कुछ समय के लिए युद्ध-विराम की घोषणा की गई थी। इस अवधि में संधय को निपटाने के कूटनीतिक प्रयत्न किये गये जो सफल नहीं हुए। ३७ दिन हवाई हमले बन्द रखने के बाद ३१ जनवरी, १९६६ को अमेरिका ने पुन बहुत बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिये। १९६६ में वियतनाम संधय के समाधान के अनेक प्रयत्न किये गये, लेकिन उत्तरी वियतनाम अपनी निम्नलिखित चार बातों पर खड़ा रहा—

(i) अमेरिका दक्षिणी वियतनाम से अपनी सारी सेनाएँ तुरन्त हटावे।

(ii) दक्षिणी वियतनाम में सन्धिवर्ती छपा मार वियतनाम सैनिकों के राजनीतिक संगठन 'राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे,' (National Liberation Front) से की जाये क्योंकि वही दक्षिण वियतनामी जनता का एक मात्र प्रतिनिधि है।

(iii) समझौते के लिए उत्तरी वियतनाम की चतुर्गुंथी योजना स्वीकार की जाय।

(iv) उत्तरी वियतनाम पर की जान वाली बनबारी को फौरन बन्द दिया जाये।

डा० हो ची मिन्ह ने ब्रिटेन, कनाडा, भारत आदि अनेक देशों और समाजवादी राष्ट्रों को पत्र भेजे जिनमें उपरोक्त बातों पर बल दिया गया। भारत के राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने प्रत्युत्तर में लिखा कि अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग का अध्ययन होने के लिये भारत १९५४ के जेनेवा समझौते के अनुसार दोनों देशों का एकीकरण करना चाहता है। अमेरिका से उसका अनुरोध है कि बम बर्षा बन्द की जावे और सयुक्त राष्ट्र संध की अध्यक्षता में तटस्थ देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सेना संगठित की जाय जो समस्या का समाधान

होने तक दोनों देशों की सीमाओं पर शान्ति स्थापना का कार्य करे। प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने वियतनाम में युद्ध विराम के लिए जेनेवा सम्मेलन के पुनः आमन्त्रित हिस्से जाने का प्रस्ताव रखा।

भारत के प्रस्ताव महासचिवों को स्वीकार नहीं लगे। अमेरिका बिना शर्त सम-वर्षा बन्द करने को तैयार न था और उस उत्तरी वियतनाम की सहमति के बिना जेनेवा सम्मेलन बुलाने में राजी नहीं था। फ्रेंच राष्ट्र-पति डिगाल ने भी उत्तरी वियतनाम पर अमेरिकन सम-वर्षा और दक्षिणी वियतनाम में उसके हस्तक्षेप का घोर विरोध किया। एशियाई देशों की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि वियतनाम समस्या का समाधान जेनेवा समझौते के अनुसार दोनों भागों का पुनः एकीकरण करके तथा इनकी तटस्थ देस बना कर किया जाना चाहिए। अक्टूबर, १९६६ में दिल्ली में यूगोस्लाविया, मयुक्क अरब-मणराज्य और भारत के शिखर-सम्मेलन के अवसर पर भी यही विचार प्रकट किया गया कि वियतनाम युद्ध बन्द हो, वहाँ से विदेशी सेनाएँ हटा ली जाय कोई बाहरी देस वियतनाम के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और वहाँ की जनता इच्छानुसार अपने राजनीतिक स्वरूप का गठन करे।

नवम्बर, १९६६ में फिलिपाइन्स की राजधानी मनीला में भी एक शिखर-सम्मेलन हुआ जिसमें मयुक्क-राज्य-अमेरिका, फिलिपाइन्स, थाइलैण्ड, आस्ट्रेलिया, दक्षिणी वियतनाम, दक्षिण-कोरिया और न्यूजिलैण्ड के सामना-व्यसों ने भाग लिया। सम्मेलन की विज्ञप्ति में माग की गई कि वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिए सज्जम पहल यह आवश्यक है कि वियतनाम अपनी आन्तरिक कार्यवाहिया समाप्त करे और उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम की प्रदेश में अपनी फौजे हटा दे। ऐसा हो जाने पर ही अमेरिका भी अपने सैनिक हटा लेगा और सम्बन्धित पक्षों में वार्ता हो सकेगी।

१९६७ से १९६८ के अन्त तक वियतनाम समस्या और वैरिष्ठावार्ता—वियतनाम समस्या के समाधान के लिए सयुक्क राष्ट्रमण के महा-सचिव द्वारा भी काफी प्रयत्न किये गये। पोंग ने सुझाव दिया कि सयुक्क राष्ट्र सय तटस्थ देशों को इस विवाद में रुच बनाने पर उनके सम्पर्क का समाधान करावे। महासचिव ऊपाण्ट ने नव वर्ष की १ जनवरी, १९६७ को समस्या के समाधान के लिए एक वि-युक्तीय योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार थी—

(१) उत्तरी वियतनाम पर फौ जाने वाली सम-वर्षा अविलम्ब बन्द की जाए।

एक गोल मेज पर हो तथा सम्बन्धित पक्ष अपनी इच्छानुसार उस पर बैठने का स्थान चुन। लेकिन अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम इस मुझाव को मानने का सहमत न हुए क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चों को मान्यता नहीं देने से और गोल मेज बातों का मुझाव मान लेने पर राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को इनकी मान्यता प्राप्त हो जाती थी। किसी प्रकार, काफी वादविवाद के बाद, इन समस्या का भा सनादान निकाला गया और सम्मेलन को कार्यवाही पुन शुरू होने की भावना बढ गयी।

इसी मध्य अमेरिका में २० जनवरी, १९६६ को नये राष्ट्रपति निक्सन ने ने कार्यभार सम्भाला। उन्होंने पेरिस वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधि हैरीमन की जगह हैनरी केवक लाज को नियुक्त किया। ६ फरवरी, १९६६ को पेरिस वार्ता का तीसरा दौर शुरू हुआ किन्तु कोई प्रगति न हो सकी। ८ मई, १९६६ को राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा एक दस सूत्री योजना पास की गयी जिसमें दक्षिणी वियतनाम से विदेशी सैनिकों की वापसी और वहाँ के लिए अस्थाई संयुक्त सरकार के गठन की बात कही गयी। दक्षिणी वियतनाम इन प्रस्ताव के आधार पर अगे बातचीत की तैयार हो गया, किन्तु मध्यम सरकार की बात के लिए मान्य नहा हुआ। राष्ट्रपति निक्सन ने यह नाति अपनयी कि एक ओर तो परिम स सानिधानों को आगे बढ़ाया जाए और दूसरी ओर वियतनाम से इस तरह अगे सैनिक धीरे-धीरे वापिस लौटाये जाए कि सैनिक हानि प्रथम दक्षिणी वियतनाम व अमेरिका के प्रतिकूल न हो जाए। मई १९६६ में अमेरिका ने वियतनाम में लगभग ५० हजार अमेरिकी सैनिक वापिस बुलाने का निश्चय किया। राष्ट्रपति निक्सन ने गान्धि स्थापना के लिए एक सान सूत्री प्रस्ताव भी रखा।

दुभाग्यवश अभी तक पेरिस वार्ता का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल सका है। फिर भी इस बात के आसार प्रकट हो गये हैं कि सम्भवत निकट भविष्य में वियतनाम युद्ध समाप्त हो जायगा। अमेरिका वियतनाम से सैन. शर्त अपनी सैनिक टुकड़ियाँ वापिस बुला रहा है और उत्तरी वियतनाम को आन्तक कार्यवाहियों भी शिथिल पड़ी है। राष्ट्रपति निक्सन वियतनाम युद्ध को समाप्ति चाहते हुए भी यह संकेत दे चुके हैं कि यदि उत्तरी वियतनाम की हमलावर कार्यवाहियों के फलस्वरूप अमेरिकन सैनिक अधिक सख्या में मारे गये तो अमेरिका पुन कठोर कार्यवाही कर सकता है। उत्तरी वियतनाम का जवाब है कि वह घमकियों से नहीं डरेगा। फिर भी दोनों ही पक्ष युद्ध से उबरता चुके हैं और हमे आशा करनी चाहिये कि वियतनाम समस्या का समाधान शीघ्र ही कूटनीतिक स्तर पर निजाल लिया जायगा।

पश्चिमी एशिया अथवा मध्य पूर्व की समस्या (Problem of West Asia)

पश्चिमी एशिया अथवा मध्य पूर्व एशिया की समस्या अरब-इजरायल संघर्ष की समस्या है जो विश्व-शान्ति के लिये एक ऐसी चुनौती बन गई है जिसका जवाब दू दे दिना हम अपने को तृतीय महायुद्ध की ज्वाला-मुखी के मुख पर बैठे पा रहे हैं। इस संघर्ष की शुरुआत १४ मई, १९४८ को इजरायल नामक नवीन राज्य के उदय के साथ हुई। यहाँ हमें इजरायल राज्य के उदय की पृष्ठभूमि के रूप में इतना ज्ञान लेना चाहिये कि द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने होते फिलस्तीन में अरबी और यहूदियों ने अपने-अपने मंत्रित्व संगठनों की स्थापना कर ली जिसका नतीजा यह हुआ कि फिलस्तीन महायुद्ध की आग में झुलसने लगा। चारों ओर अज्ञाति और अशांति फैल गई। ब्रिटेन ने स्थिति को बाबू से बाहर जाने देना पर १९४६ में सारा मामला संयुक्त राष्ट्र मण की सौंप दिया। संयुक्त राष्ट्र मण ने स्थिति की जाच-पड़ताल के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त किया जिसकी सिफारिश पर १९४७ के अन्त में फिलस्तीन के बंटवारे का फैसला किया गया। अरबों ने संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का विरोध किया और कहा कि यदि उनकी इच्छा व विरुद्ध उनकी पवित्र भूमि का बंटवारा किया गया तो वे उसे रोकने के लिए शस्त्र का प्रयोग करने में भी नहीं हिचकिचायेंगे। किन्तु अरबों का यह विरोध कारगर सिद्ध नहीं हुआ। १४ मई, १९४८ को मध्य एशिया में ब्रिटेन ने फिलस्तीन पर अपना मंडेट (Mandate) समाप्त कर दिया और अभी समय तेलअवीव में यहूदियों ने 'इजरायल' राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी तथा वेन गुरियो उसके प्रथम प्रधान मंत्री बने। पासिगटन ने संवर्द्धित इजरायल राज्य की तुरन्त मान्यता प्रदान की और मास्को तथा लन्दन ने भी इसे स्वीकार कर लिया।

इजरायल-अरब युद्ध, १९४८

अरब राष्ट्र इजरायल के जन्म को वर्धित न कर सके। जिस दिन इस यहूदी राज्य की स्थापना हुई उसी दिन मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया की सेनायें फिलस्तीन में घस पड़ी और इजरायल पर आक्रमण शुरू हो गया। परन्तु इजरायल ने अमेरिकन यहूदियों से विपुल आर्थिक सहायता प्राप्त की, चेकस्लोवाकिया से शस्त्र प्राप्त किये और अरब राज्यों से डट कर मुकाबला किया। इस समय यहूदियों की संख्या साढ़े छ. लाख थी और उनके पास ८००० वर्गमील का प्रदेश था जबकि दूसरी ओर जोर्डन के शाह के नेतृत्व में लड़ने वाले अरब लोग के राज्यों की जनसंख्या ४ करोड़ और क्षेत्रफल २० लाख

वर्गमील था। फिर भी इस संघर्ष में इजरायली अपनी साधन सम्पन्नता, विदेशी सहायता और उत्कृष्ट रण-कौशल के कारण विजयी हुए और लाखों की संख्या में अरबों को इजरायल से बीछ कर भागना पड़ा। समुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थ रॉक बुच के प्रयत्नों से जब १९४९ में दोनों पक्षों में युद्ध बन्द हुआ तो इजरायल के पास संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तैयार की गई विभाजन-योजना से दो हजार वर्गमील अधिक प्रदेश था। समुक्त राष्ट्र संघ ने इजरायल का क्षेत्रफल ५६०० वर्गमील तय किया था जबकि उसके पास ७६०० वर्गमील प्रदेश हो गया। इस युद्ध में मिस्री सेनाओं ने गाजा तथा बोरगवा पर अधिकार कर लिया था और जेरुसलम के उत्तरवर्ती भागों से यहूदियों को भगा दिया था। समुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से जो समझौता हुआ उसके अनुसार मिस्र को गाजा पट्टी मिली जिसमें शरणार्थी अरबों की अगलबेगी व्यवस्था की गई। जेरुसलम नगर दो हिस्सों में बंट गया— लगभग एक लाख की आबादी वाला बड़ा हिस्सा यहूदियों के दब्जों में आया और ५० हजार की अरब आबादी वाला हिस्सा जोर्डन के अधिकार में रहा। इस तरह दोनों राज्यों की सीमा इस नगर में से होकर गुजरती हुई रखी गई। इजरायल ने भागे हुए अरबों की वापस लौटने की अनुमति नहीं दी। उसकी नीति के कारण लगभग १० लाख अरबों को १९४३ तक इजरायली प्रदेश छोड़ कर अन्य अरब देशों में शरणार्थी बनना पड़ा और बदले में यूरोप, अफ्रीका एवं मध्यपूर्व के विभिन्न देशों से ६ लाख यहूदी आकर वहां बस गये। जहां १९४८ में इजरायल राज्य में १३½ लाख अरब और ६½ लाख यहूदी थे वहां १९५८ में लगभग २० लाख की कुल जनसंख्या में यहूदियों की संख्या लगभग १७ लाख हो गई।

समस्याओं का पहाड़

इजरायल राज्य की स्थापना और फिर युद्ध में इजरायल के हाथों पराजय ने सम्पूर्ण अरब जगत में इजरायल-विरोधी आग स्थायी रूप से प्रज्वलित कर दी। अरब राज्यों की, विशेषतः मिस्र, सीरिया, जोर्डन आदि की इस बात से बड़ा आशान पहुँचा कि प्रथम तो वे फिलस्तीन के विभाजन और एक स्वतन्त्र यहूदी राज्य की स्थापना को रोकने में असमर्थ रहे और दूसरे इजरायल के क्षेत्रफल को ग़ुन करने में भी असमर्थ रहे। इन अरब शक्तियों ने, विशेषकर मिस्र ने, अपने इस दुर्भाग्य के लिए पश्चिमी ताकतों को उत्तरदायी ठहराया। अरब राज्यों ने शीतल कर इजरायल को न केवल बाधित व राजनीतिक रूप से लगभग विराना कर दिया बल्कि उन्होंने इजरायली बदरगाहों से सामान लाने तथा वहाँ सामान पहुँचाने वाले जहाजों

के लिए स्वेज नहर का रास्ता भी बन्द कर दिया। अरब लीग की सदस्य-राज्यो से प्रोत्साहन पा कर मिस्र ऐसे जहाजों को रोकने व तसकी जाव करने लगा, और उधर इजरायली-जोर्डनी सीमा पर भी यदा-कदा हिंस्र मुठभेड़ों की घुटझात हो गई। इजरायल के साथ सब अरब देशों ने व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ दिये। ईराक ने इस राज्य के अन्तर्गत हैका बंदरगाह को किरकुक से पाइप लाइन द्वारा पेट्रोल भेजना बन्द कर दिया।

इजरायली सरकार को उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त बाहर से आने वाले निर्वासित इजरायलियों को बसाने की भीषण समस्या का भी सामना करना पड़ा। ये निर्वासित दुनिया के तमाम भागों से आये। इनके पास रोजी-रोटी कमाने के कोई साधन न थे। ऊपर से इजरायल की रेतीली भूमि और पाना की कमी तथा हर क्षण अरबों से तत्पर छिड़ जाने की आशंका। परन्तु इजरायल ने इन सब चुनौतियों को बड़े साहस और विश्वास के साथ स्वीकार किया। यहूदियों ने यूरोपियन देशों के साथ व्यापारिक समझौते करके अमेरिका और वहाँ के सम्पन्न यहूदियों से प्राप्त होने वाली विपुल आर्थिक सहायता से तथा सबसे बड़ कर अपने अदम्य साहस से इन गम्भीरतम समस्याओं पर विजय पा ली। देखते ही देखते मरम्मत में धरे-भरे सेत लहराने लगे, आधुनिक उद्योग धन्ये स्थापित हो गये और लोगों ने रहने के लिए खूबसूरत मकान बन गये। अरबों की चुनौती यहूदियों की प्रगति न रोक सकी और इजरायल मध्यपूर्व का सबसे विकसित और समृद्ध देश बनने के मार्ग पर बढ़ता गया।

इस सबसे अरबों ने चिन्ता व्याप्त हो गई और सभी अरब देश आरसी मतभेद भुला कर इजरायल को सबक सिखाने के लिए एक हो गये। सीमावर्ती अरब राज्यों से इजरायल को छूट-पुट सैनिक हाटने होने लगी। १९५४ तक की अवधि में इजरायली-जोर्डनी सीमा पर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर छोटे-छोटे हमले किये गये। फरवरी, १९५५ में इजरायली प्रवक्ता ने टर्की-ईराक के पत्र को इजरायल विरोधी बताया और कहा कि यह पत्र इजरायल के विरुद्ध अरब राजता को प्रोत्साहित तथा अरबों की आन्तमन्त महत्वकांक्षाओं को उत्तेजित करने वाला है। सितम्बर, १९५४ से इजरायली-मिस्री सीमा पर भी स्थिति विशेष शोचनीय होने लगी। २८ फरवरी, १९५५ को गाजा के निजट दोनों पक्षों में हुई एक सैनिक मुठभेड़ में दोनों तरफ से अनेक सैनिक हताहत हुए। २ नवम्बर, १९५५ को इजरायली प्रधान मंत्री डेविड बेन गुरियो ने अरब-इजरायली समस्याओं के समाधान के लिये मिस्र के प्रधान मंत्री और अन्य अरब राज्यों के शासकों से मेट की

इच्छा प्रकट की, किन्तु अरबों की ओर से इस इजरायली इच्छा को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इजरायल और मिस्र की सीमा और भी अधिक विस्फोटक हो गई। १९४९ में अरबप्रोत्साहक के विरुद्धीकृत क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दोनों पक्षों की अनेक प्राणों में हाथ धोना पड़ा। ११-१२ दिसम्बर १९५५ को अरब-रात्रि में निवेरिम झील के उत्तर पूर्व में सीरियाई मोर्चे पर इजरायल ने एक खूनी मुठभेड़ हुई जिसमें ४० सीरियाईयों और ६ इजरायलियों की जानें गयीं। १३ दिसम्बर को सीरिया ने इजरायल के इस 'शर्मनाक व खुले आक्रमण तथा उत्तनात्मक कुकृत्य' की शिकायत सुरक्षा परिषद से की। २६ मार्च, १९५६ को सुरक्षा परिषद ने मत्र के महासचिव से अरब इजरायली नेताओं से वार्ता करने के लिए पश्चिमी एशिया जाने को कहा। मई में महासचिव की यात्रा से इजरायल व उसके पड़ोसी अरब राष्ट्रों में तनाव कुछ कम हो गया।

अरब इजरायल संधि, १९५६

जुलाई अक्टूबर, १९५६ के दौरान इजरायल जोर्डन और मिस्र की सीमाओं पर स्थिति पुनः गम्भीर हो गई। स्वज नहर के राष्ट्रीयकरण व वाद २६ अक्टूबर को तब एक भारी विस्फोट हुआ जब इजरायली सैनिकों ने सिनाई प्रायद्वीप में मिस्री मोर्चों पर आक्रामक आक्रमण कर दिया। इस हमले का स्पष्ट उद्देश्य फेदायोन अड्डों को नष्ट करना था क्योंकि इन अड्डों से ही भूतकाल में इजरायल पर अक्रामक आक्रमण किये गये थे। ब्रिटेन और फ्रांस की सरकार ने मिस्र और इजरायल के पास मदेश भेजा कि दोनों ही देश तुरन्त युद्ध बन्द कर दें और इस झगड़े में ब्रिटेन व फ्रांस को मध्यस्थ मानें। १२ घण्टों में इसका उत्तर मांगा गया और घमकी दी गई कि ऐसा न होने पर वे दोनों युद्ध में कूद पड़ेंगे। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री ईडन में ३० अक्टूबर को ब्रिटिश लोकमना प कहा कि स्वेज नहर से समस्त देशों के जहाजों के स्वतन्त्रतापूर्वक व्यापार करने व जाने-जाने के लिए हमने मिस्र की सरकार से पूछा है और कहा है कि पोर्ट सईद आदि महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी रूप से ब्रिटेन व फ्रांस की सन्तान रखी जाये तो यातायात की सुविधा के लिए कहीं उत्तम होगा। साथ ही श्री ईडन ने यह भी कहा कि मेरे लिए यह अमम्यव होगा कि मैं यह बता सकू कि ब्रिटेन की ओर से शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सुरक्षा परिषद में इस बात पर विचार न हो जाय। ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद से भी इस बात की मांग की कि मिस्र को सैनिक हस्तक्षेप की घमकी दी जाये।

ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद के निर्णय का इन्तजार न करने हुए ३१ अक्टूबर, १९५६ को पोर्ट सईद पर हमला कर दिया ताकि स्वेज प्रदेश

उनके अधिकार में आ जाय। इस तरह मित्र को अब बकेले ही तीन सन्धियों से जूझना पड़ा—सिनाइ में इजरायल से और स्वेज क्षेत्र में ब्रिटेन व फ्रांस से। पांच दिन की लड़ाई के बाद लगभग सम्पूर्ण सिनाई प्रायद्वीप पर इजरायल का नियन्त्रण स्थापित हो गया। ४ नवम्बर, १९५६ को महासभा ने कनाडा का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि मित्र में युद्ध बन्द करने और युद्ध विराम की देख-भाल के लिये समुक्त राष्ट्र सभ की एक आपान्कालीन सेना की योजना महा-सचिव द्वारा तैयार की जाये। ५ नवम्बर को सोवियत सभ ने फ्रांस व ब्रिटेन की आक्रमण रोकने की चेतावनी दी। इस चेतावनी का फौरन प्रभाव पड़ा और ६-७ नवम्बर को मध्य रात्रि में ब्रिटिश फौज कीजों ने युद्ध बन्द करने की घोषणा कर दी। ७ नवम्बर को ही महासभा द्वारा एशिया-अफ्रीका के देशों का यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि ब्रिटिश फौज और इजरायली सेनाएँ मित्र की भूमि से हट जायें तथा स्वेज नहर के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस स्थापित की जाये। ९ नवम्बर का इजरायल द्वारा घोषणा की गई कि 'अन्तर्राष्ट्रीय सेना' के स्वेज नहर के क्षेत्र में प्रविष्ट होना के बाद वह सिनाई-क्षेत्र में अपनी सेनाएँ हटा लेगा। १५ नवम्बर को समुक्त राष्ट्र मधीय आपान्कालीन सेना का पहला दस्ता मित्र पहुच गया। ब्रिटिश फौज और इजरायली सैनिकों के मित्र प्रदेश से न हटने पर महासभा द्वारा २४ नवम्बर को पुनः यह प्रस्ताव दोहराया गया कि ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल मित्र से अविलम्ब अपनी फौज हटा लें।

समुक्त राष्ट्र सभ के प्रस्ताव के अनुशासन में ब्रिटेन और फ्रांस ने तो २२ दिसम्बर, १९५६ को मित्र से अपनी फौजें हटा ली, किन्तु इजरायल ने गाजापट्टी तथा दार्मल क्षेत्र में अपनी फौजें हटाने से इन्कार कर दिया। १९ जनवरी तथा २ फरवरी, १९५७ का महासभा ने इजरायल द्वारा फौजें हटाने तथा महासचिव के इस प्रस्ताव का विचारविमल करने के दो अग्र्य प्रस्ताव पास किये। इजरायल ने इसका भी पालन नहीं किया तब ६ सन्धियों के एक अग्र्य प्रस्ताव को स्वीकार करके महासभा ने यह निर्णय किया कि इजरायल द्वारा समुक्त राष्ट्र सभ के आदेशों का पालन न करने के कारण सभी देश उसे आर्थिक व वैनिक सहायता देना बन्द कर दें। इस पर १ मार्च, १९५७ का इजरायल ने कुछ शर्तों के साथ सेनाएँ हटाना स्वीकार कर लिया और ७ मार्च को मित्र से सभ सेनाएँ हटा ली गयी। इजरायल की प्रमुख शर्तें ये थी कि अफाका की खाड़ी तथा तिरान (Tiran) जलमल्लमलों में इजरायल सहित सब देशों के लिये भी-चारन की पूरी स्वतन्त्रता होगी और समुक्त राष्ट्र सभ उस समय तक गाजापट्टी पर अपना प्रशासन रखेगा जब तक कि इसके अधिकार के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो जाता।

इजरायल और अरब राष्ट्रों में तनाव कायम रहना

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र मध्य के हस्तक्षेप से मिल और इजरायल के संसन्न सचप की समाप्ति हो गई, किन्तु अरब देशों ने इजरायल के अस्तित्व की स्वीकार करने की तत्परता नहीं दिखाई।

सन् १९५७ में इजरायल और जोर्डन की सीमाओं पर अनेक छूट-मुट घटनाएँ हुई। इनके कारण दोनों देशों के पारस्परिक सम्बन्धों में तनावपूर्ण स्थिति आ गई और संयुक्त राष्ट्र मध्य के महासचिव को इस क्षेत्र का दौरा करना पड़ा। मिस्र और इजरायल के सम्बन्ध भी पुनः तनावपूर्ण होते गये। फरवरी मार्च १९५९ में स्वेज के रास्ते इजरायल से सुदूरपूर्वी देशों की निर्यात किये गये माल व अनेक विदेशी जहाजों को संयुक्त अरब गणराज्य ने रोक लिया। परिणामस्वरूप दोनों देशों में बहुत अधिक तनाव बढ गया। इजरायल द्वारा सुरक्षा परिषद से शिकायत की गई। इजरायली प्रतिनिधि ने परिषद के सदस्यों को लिखे गये एक पत्र में संयुक्त अरब गणराज्य के इस कदम की निंदा की और आरोप लगाया कि यह "स्वेज नहर समझौते व सुरक्षा परिषद व १ नवम्बर, १९५१ के उस प्रस्ताव की, जिसमें मिस्र में किसी भी दिशा में जा रहे माल और जहाजों को स्वेज नहर से गुजरने देने के लिये कहा गया था, नग्न अवहेलना है।" दूसरी ओर काहिरा के सरकारी समाचार पत्र 'अल अहगाम' ने लिखा कि इजरायल की स्वेज नहर से अपने मालवाहक जहाजों को भेजने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इजरायल और अरब देशों के मध्य 'युद्धस्थिति' अभी तक मौजूद है। मई १९५९ में संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा एक हेनिस मालवाहक जहाज को, जो हैफा बन्दरगाह से इजरायली सामान हागकाग तथा जापान से जा रहा था, रोक लिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने इस कार्यवाही को इजरायली हितों तथा संयुक्त राष्ट्र मध्य के चाटर और सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर एक भारी चोट बनाया। अगस्त १९५९ में पुनः ऐसी ही घटनाएँ घटी और इजरायली प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करने हुए संयुक्त अरब गणराज्य की इन कार्यवाहियों की समुद्री डकैती के कार्य बताया।

सीरिया के साथ भी इजरायल के झगड़े चलते रहे। फरवरी १९६० में तावफिक नामक स्थान पर दोनों की सैनिक टुकड़ियों में जबरदस्त मुठ-भेड़ हुई। फरवरी के अन्तिम सप्ताह में इजरायल से लगती हुई सीमा पर संयुक्त अरब गणराज्य की सेनाओं के जमाव से बड़ी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इजरायल ने सुरक्षा परिषद को सूचित किया कि इस क्षेत्र में शांति अभी स्थापित हो सकती है जब कि संयुक्त अरब गणराज्य इजरायल के प्रति

सक्रिय शत्रुता की नीति का परिहास कर दे। मार्च १९६० में इजरायली प्रधानमंत्री बेनगुरियो अमेरिका गये। राष्ट्रपति जॉर्जनहावर ने उन्हें आश्वासन दिया कि अरब-आक्रमण की स्थिति में अमेरिका इजरायल को सहायता देगा। दूसरी ओर कनेट नासिर ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित किया कि इजरायल द्वारा सीरियाई क्षेत्र पर आक्रमण मिल पर आक्रमण समझा जायगा तथा संयुक्त अरब गणराज्य स्थिति के अनुकूल प्रतिरक्षा व्यवस्था करेगा।

अरब राष्ट्रों और इजरायल के सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले गये। मार्च १९६२ में इजरायल सीरिया सीमा पर फिर से दुर्घटनाएँ होने लगी। सुरक्षा परिषद में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि दोनों देशों को युद्ध विराम समझौते पर अमल करना चाहिये। अगस्त १९६२ में सीरिया और इजरायल में पुनः गम्भीर सैनिक मुठ-भेड़ हुई। सुरक्षा परिषद की एक विशेष बैठक में सम्मेलन पर विचार किया गया और महासचिव लुन्पाट ने दोनों देशों से आत्मनिपन्त्रण रखने की अपील की। परिषद् में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीरिया की निन्दा करने का प्रस्ताव रखा, परन्तु सोवियत संघ ने इसे निषेधाधिकार द्वारा समाप्त कर दिया। अगस्त १९६२ में ही इजरायल और जोर्डन की सीमाओं में झड़पें हो गई। लगभग इसी समय इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि संयुक्त अरब गणराज्य ऐसे सैनिक प्रक्षेपणास्त्र तैयार कर रहा है जिससे वह इजरायल को शीघ्र ही पराभूत कर सकता है। इस समाचार से इजरायल में गम्भीर चिन्ता व्याप्त हो गई। उसने इस बात का प्रयत्न किया कि उसके पास इन प्रक्षेपणास्त्रों का निवारण करने के लिये और मिस्र का आक्रमण विफल बनाने के लिये आवश्यक राकेट होने चाहिये। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस मत की पुष्टि की कि इन क्षेत्र में शांति तभी सम्भव है जबकि यहाँ सैनिक शक्ति में सतुल्य बना रहे। अतः उसने मध्यपूर्व के देशों को हथियार न देने की अपनी सामान्य नीति की अपेक्षा करते हुए सितम्बर १९६२ में यह निर्णय किया कि वह अल्प दूरी तक जाने वाले और शत्रु के वायुमानों को मार गिराने वाले रक्षात्मक प्रक्षेपणास्त्र इजरायल को प्रदान करेगा। इजरायल की इच्छा थी कि उसे मिस्र की माति अपने देश की भूमि से ही शत्रु की भूमि के अड्डों को नष्ट करने वाले प्रक्षेपणास्त्र (Ground to Ground Missiles) प्रदान किये जायें। फिर भी उन्हें अमेरिकन सहायता से कुछ सन्तोष अवश्य हुआ। अरब राज्यों ने वाशिंगटन की इस सहायता की अर्धश्रीपूर्ण कार्यवाही की मज्ञा दी।

जोर्डन नदी के पानी के विवाद ने भी अरब इजरायल बलहू को काफी बढ़ाया। इजरायल और जोर्डन राज्यों की सीमा का निर्माण करने वाली

और सीरिया, लेबनान, इजरायल तथा जोर्डन के चार राज्यों में से होकर चहने वाली इस नदी के पानी के उपयोग के बारे में सहमति बढ़ाने पर ऐरिज आसटन की योजना के अनुसार यह निश्चय किया गया कि इसके जल का ६७ प्रतिशत भाग अरब राज्य और ३३ प्रतिशत भाग इजरायल अपने उपयोग में लाये। इजरायल ने अपने जल का उपयोग करने के लिये योजना आरम्भ कर दी। इससे अरब राज्यों को यह चिन्ता हुई कि इजरायल अपने नगेव व मरुस्थल को हरा मरा बना कर अपने को समृद्ध बना लेगा और अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके अपने को शक्तिशाली बनाने में समर्थ होगा तथा अपने राज्य विस्तार के द्वारा अरब राज्यों को हानि पहुँचायेगा। चूंकि अरब राष्ट्र इस स्थिति को सहन करने की मानसिक अवस्था में नहीं थे, अतः १३ अरब राज्यों ने जनवरी १९६४ में काहिरा में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुख्यतः तीन विषयों पर विचार हुआ— (१) जोर्डन नदी व पानी की समस्या, (२) अरब राज्यों की संयुक्त सेना का निर्माण, एवं (३) सब अरब राज्यों द्वारा मिलकर इजरायल को नष्ट करना।

काहिरा के इस शिखर सम्मेलन में स्पष्ट हुआ कि अरब राज्यों में विभिन्न विषयों पर प्रबल मतभेद विद्यमान थे। प्रमुख राष्ट्र—ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिश्र (संयुक्त अरब गणराज्य), सीरिया, लेबनान, जोर्डन, मजदी अरब, यमन, कुवैत, ईराक और मूडान—किसी भी प्रश्न पर सहमत नहीं थे। इजरायल के विरुद्ध अथवा विराध के विषय में भी सब राज्यों में सहमति नहीं थी। ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया को इस प्रश्न से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ट्यूनीशिया ने तो बाद में अप्रैल १९६५ में यह घोषणा भी की कि अरब राज्यों को इजरायल के साथ समझौता कर सेना चाड़िय, क्योंकि ठमे समाप्त नहीं किया जा सकता।

परन्तु अरब राज्यों में मतभेद के बावजूद इजरायल के प्रति विरोध की भावना की ही विजय होती रही और एक नये अरब-इजरायल संधि की भूमिका बनती गई।

अरब इजरायल संधि, जून १९६७ एय बाव की घटनायें

इजरायल और अरब राज्यों द्वारा परस्पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते रहे हैं। विशेषतः संयुक्त अरब गणराज्य और सीरिया के साथ सम्बन्ध अधिनाधिक बिगड़ते गये। दोनों पक्षों में सैनिक तैयारियों की होड़ लग गई। मार्च १९६७ के प्रथम सप्ताह में निवेरियास झील के किनारे हुई एक घटना के फलस्वरूप सीरिया और इजरायल में खूबसे सैनिक भट्ठे हो गई। ७ मार्च को हवाई युद्ध भी हुआ और टैंक तथा भारी तोपघाने का

इस्तेमाल किया गया। सीरिया और इजरायल की सैनिक-मुठभेड़ों ने सब अरब राष्ट्रों में एक बार फिर इजरायल विरोधी जाग भयंकर रूप से प्रज्वलित कर दी। समुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने इजरायल को स्पष्ट चेतावनी दी कि सीरिया पर आक्रमण करने का परिणाम इजरायल का विनाश होगा।

राष्ट्रपति नासिर ने १५ मई को अपनी सशस्त्र सेनाओं को चौकस रहने का आदेश दे दिया। १८ मई को यह माग भी कर दी गई कि समुक्त राष्ट्र मध्य की शान्ति रक्षा सेनायें अरब गणराज्य की सीमा से हट जाए ताकि इजरायल द्वारा आक्रमण हो पर समुक्त अरब गणराज्य की सेनायें सीरिया की सहायता के लिए बेरोकटोक लागे वढ़ सकें। नासिर की हठ माग के सामने महासचिव ऊषाण्ट के सामने सेनाओं को हटाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। फिर भी ऊषाण्ट ने चेतावनी भरे शब्दों में बतला दिया कि "सेनाओं को वहाँ से हटाने का मतलब स्पष्ट रूप से यह होगा कि समुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सेनायें एक दूसरे के आमने-सामने हो जाएंगी तथा आज तक जो पवित्र दोनों के बीच शान्ति बनाये हुए थी, वह हट जाएगी। मुझे इस बात का दुःख है मगर इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं।" लगभग इसी समय समुक्त अरब गणराज्य और इजरायल ने अपने-अपने रिजर्व सैनिकों को ह्यूटी पर वापस आने का आदेश दे दिया और दोनों देशों की १४६ मील लम्बी सीमा पर सैनिक सैन्य हो गये। अरब लीग परिषद ने भी घोषणा कर दी कि किसी भी अरब देश पर इजरायल के आक्रमण को सभी अरब देशों पर आक्रमण समझा जाएगा।

स्थिति को बिस्कोटन होने से बचाने के लिए महा सचिव ऊषाण्ट स्वयं बाहिरा गये। इस अवसर पर इजरायल द्वारा घोषणा की गई कि यदि समुक्त अरब गणराज्य सीमा से अपनी फौजें हटा देगा तो इजरायल भी अपनी फौजों को हटा लेने को तैयार है। ऊषाण्ट के प्रयत्नों की कोई सफलता नहीं मिली। २३ मई को स्थिति तब और भी गम्भीर हो गई जब समुक्त अरब गणराज्य द्वारा अम्नदुआ की खाड़ी की नाकेबन्दी की घोषणा कर दी गई। इस नाकेबन्दी का अर्थ था इजरायल की रक्त प्रवाहिनी नाडियो को काट देना। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि इजरायली या इजरायल के मित्र देशों के जहाज इजरायली बन्दरगाह ऐलात पर न पहुँच जायें। इजरायल और पश्चिमी राष्ट्रों ने इस कदम को नाजायज बताने हुए कहा कि अक्काबा की खाड़ी एक अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग है जिसकी नाकेबन्दी नहीं की जा सकती। इजरायल ने चुनौती दी कि उसे अक्काबा की खाड़ी से आने-जाने में

कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इजरायली प्रधानमन्त्री ने कहा कि संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा जहाजरानी में बाधा पहुँचाने की इस कार्यवाही को उनका राष्ट्र आक्रामक कार्यवाही मानता है।

इसके बाद ही दोनों पक्षों में छोटी-मोटी सैनिक मुठभेड़ होने लगी। २६ मई को सुरक्षा परिषद ने सङ्कट पर विचार किया किन्तु कोई फल न निकला। इस समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस दोनों के युद्ध पोतों ने भी भूमध्य सागर में पहुँच कर मोर्चे सम्हाल लिये। इस तरह पश्चिम एशिया के इस सङ्कट ने दो महाशक्तियों के टकराने की स्थिति पैदा कर दी। २ जून को इजरायली और सीरियाई सैनिकों में मुठभेड़ हुई। ४ जून को काहिरा के समाचार पत्रों ने शक्ति परीक्षण को निश्चित बताया। मिश्री सेनाओं को तैयार रहने के आदेश दे दिये गये। शहर इजरायल के नये राजा भन्त्री मोरी आपान ने घोषणा की कि उनका राष्ट्र अरबों से अकेले ही सभ्य करेगा।

आखिर सोमवार, ५ जून, १९६७ को अकस्मात ही युद्ध ज्वालामुखी फूट पड़ा। आक्रमण की पहल इजरायल ने की। भारतीय समय के अनुसार लगभग ११।। बजे संयुक्त अरब गणराज्य की राजधानी काहिरा पर हवाई हमले हुए। हवाई बड़ों पर एक साथ इतने व्यापक हमले पर बमबारी की गई कि संयुक्त अरब गणराज्य के अधिकांश विमान एक ही चपेट में नष्ट हो गये। संयुक्त अरब गणराज्य की अबीरुष्ट बायु शक्ति ने इजरायल की राजधानी तेलअवीव और अन्य स्थानों पर जवाबो हमले किये। संयुक्त अरब गणराज्य और इजरायल की सीमा पर गाजा पट्टी से लेकर दक्षिण इजरायल के नगेव क्षेत्र तक, जबर्दस्त युद्ध छिड़ गया। घीघ्र ही इजरायल से लगती हुई जोर्डन और सीरिया की सम्पूर्ण सीमा भी भड़क उठी। अकेले ही इजरायल ने समस्त मोर्चों पर अरबों की संयुक्त शक्ति पर कहर ढा दिया।

पश्चिम एशिया का यह युद्ध इजरायल की निर्णायक विजय के साथ केवल ६ दिन में ही समाप्त हो गया। ७ जून को इजरायल ने अकाबा की खाड़ी पर स्थित समलक्षेत्र पर कब्जा कर लिया और बेतलहम तथा जेरिको में भी उसकी सेनायें पहुँच गईं। ८ जून तक इजरायली सेनायें सिनाई प्राय द्वीप को पार करते हुए स्वेज नहर के पूर्वो कोने पर जा पहुँची। इसी बीच ७ जून को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पेश कर मांग की कि युद्धरत सभी देश रात के ८ बजे से (घोनाविव समय) युद्ध बन्द कर दें। परिषद का यह आदेशात्मक प्रस्ताव था। चूँकि संयुक्त अरब गणराज्य का पूरा पलायन हो

गया था और युद्ध जारी रखने पर उसका पूर्ण विनाश सम्भव था, अतः उसने तुरन्त ही युद्ध विराम की मांग स्वीकार कर ली। ८ जून को इजरायल और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच युद्ध बन्द हो गया। यद्यपि सीरिया ने भी अपनी ओर से युद्ध बन्द करने की घोषणा कर दी किन्तु ६ जून को इजरायल ने स्वेज नहर के किनारे और इजरायल सीरिया सीमावर्ती पहाड़ों में भी युद्ध जारी रखा। इजरायल कुछ महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहता था। ९-१० जून को सुरक्षा परिषद ने पुनः एक प्रस्ताव पास करके यह आदेश दिया कि इजरायल और सीरिया दो घंटे में युद्ध बन्द कर दें। चूंकि इजरायल का सामरिक उद्देश्य पूरा हो चुका था और सीरिया की सामरिक क्षमता समाप्त हो चुकी थी, अतः १० जून को दोनों पक्षों में पूर्णतया लड़ाई बन्द हो गई।

इजरायल के हाथों पराजय की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति नासिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अरब जनता की आवाज पर उन्हें यह इस्तीफा वापस लेना पड़ा। अरब जनता को विश्वास था कि नासिर के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति उनका नेतृत्व नहीं कर सकता है और अरब राज्यों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने की क्षमता नासिर में ही है। नासिर ने अमेरिका और ब्रिटेन पर आरोप लगाया कि उनके विमानों ने इजरायल की प्रतीत सहामता की थी और युद्ध में भाग लिया था। यद्यपि अमेरिका और ब्रिटेन ने इस आरोप का खण्डन किया, किन्तु अरब राज्यों ने दोनों राष्ट्रों से अपने कूटनीतिक सम्बन्ध तोड़ लिये और यह आदेश दिये कि सभी अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिक अपने देश लौट जाए।

करिया जा चुका है) रखी गई किन्तु यह योजना इजरायल और उसके सम-
बंधकों देशों को मान्य नहीं हुई। ८ अक्टूबर, १९६८ को इजरायल ने संकट के
हल के लिये एक नौ-सूत्री कार्यक्रम पेश किया जिसे संयुक्त अरब गणराज्य ने
तत्काल ठुकरा दिया।

संयुक्त राष्ट्र सभ की शांति रक्षा सेना होने पर भी दोनों पक्षों में सैनिक
झड़प होती रही। २८ दिसम्बर, १९६८ को बेरुत हवाई अड्डे पर इजरायली
वायु आनमण हुआ जिसकी विश्व भर में आलोचना की गई। १ जनवरी,
१९६९ को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पेश करके इजरायल को गम्भीर
चेतावनी भी दी। फरवरी मार्च १९६९ में अरब इजरायल छापामारों के बीच
अनेक छोटी-मोटी झड़पें हुईं। २४ फरवरी को इजरायल ने सीरिया के कुछ
नगरों पर बम गिराये। ८ मार्च को स्वेज नहर के पास संयुक्त अरब गण-
राज्य के तेल कारखानों पर इजरायल की गोलाबारी हुई। मार्च में ही
जोर्डन के साथ भी इजरायल की झड़पें हुईं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर छोटे
मोटे आक्रमण प्रत्याक्रमण करते रहे। ३ अप्रैल, १९६९ को पश्चिमी एशिया
के संकट पर विचार विमर्श के लिये न्यूयॉर्क में चार बड़े राष्ट्रों का सम्मेलन
हुआ। लेकिन इजरायल ने इस सम्मेलन का विरोध किया। १२ मई, १९६९
को इजरायली प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि पश्चिम एशिया
की समस्या को हल करने के लिये चार बड़े राष्ट्र जो भी प्रस्ताव रखेंगे उन
पर इजरायल दिवार विमर्श तक करने को तैयार नहीं है। इजरायल का
बहना था कि पश्चिमी एशिया से बाहर के राष्ट्र पश्चिम एशिया संकट का
फैसला न करें। अरब राष्ट्रों और इजरायल के बीच आज भी पूरा तनाव
बना हुआ है और कोई नहीं कह सकता कि पुनः कब विस्कट हो जाए।
इजरायल की शर्तें अरब राष्ट्रों को मान्य नहीं हैं और अरब राष्ट्रों की शर्तें
इजरायल को स्वीकार नहीं हैं। इजरायल चाहता है कि—

- (i) अरब राष्ट्र इजरायल की राजनयिक मान्यता दे।
- (ii) स्वेज नहर और अनाबा की खाड़ी में इजरायल को उसी तरह
जहाजरानी के अधिकार मिलें जैसे हमारे देशों को प्राप्त हैं।
- (iii) जेरुसलम इजरायल के कब्जे में रहे।
- (iv) जोर्डन नदी के पश्चिम की तरफ का इलाका फिलिस्तीनी
विस्थापितों के लिये अलग कर दिया जाए।
- (v) सीरियाई सीमान्त का वह पड़ाही इलाका जहा से सीरियाई
सैनिक उत्पात करते रहते हैं, इजरायल के ही कब्जे में रहे।

(vi) इजरायल से खेड़-छाड़ न करने का आश्वासन दिया जाए।

स्पष्ट है कि इजरायल की माँगें महज सोदेवाजी की हैं जो अरब राष्ट्रों को मान्य नहीं हो सकती। राष्ट्रपति नासिर झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने घोषणा की है कि—

- (i) वे एक इंच अरब भूमि भी हाथ से नहीं जाने देंगे,
- (ii) अपनी प्रमुखता में नूई की नोक के बराबर कम नहीं आने देंगे, और
- (iii) इजरायल को युद्ध द्वारा हथियाई गई जमीन का फायदा नहीं उठाने देंगे।

फिर भी राष्ट्रपति नासिर का खत है “यदि पश्चिम एशिया की समस्या का मानवीय ढंग से समाधान हो जाए तो मैं और अरब गणराज्य के लोग इजरायल की हकीकत को स्वीकार कर लेंगे।” अरब इजरायल संघर्ष में भारत की सहानुभूति अरब राष्ट्रों के, विशेषकर मशुक्त अरब गणराज्य के साथ है। ऐसा क्यों है—इसका विवेचन भारत की विदेश नीति के सदर्भ में किया जा चुका है।

EXERCISES

Chapters 1 & 2

1. What do you understand by Internationalism ? Also write the importance and history of internationalism.

अन्तर्राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीयता का महत्व और इतिहास भी लिखिये ।

2. Discuss the present nature and scope of the study of International relations.

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की आधुनिक प्रकृति और क्षेत्र के अध्ययन की विवेचना कीजिये ।

3. "Various types of groups—nations, states, governments, peoples regions, alliances, confidence, international organisations, even individual organisations, cultural organisations, religious organisations—must be dealt with in the study of international relations." (Quincy wright). Discuss.

"विभिन्न प्रकार के समूह—राष्ट्र, राज्य, सरकार, जनता, प्रदेश, मंत्री, गोपनीयता, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, यहां तक कि व्यक्तिगत संगठन, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अध्ययन के अन्तर्गत अवश्य सम्मिलित होने चाहिये ।" विवेचना कीजिये ।

4. What is theory of International politics ? What are relations between International politics and International Relations ?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धान्त क्या है ? अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में क्या सम्बन्ध है ?

5. Discuss the role of ideology in international politics.

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धान्तों के महत्व का वर्णन कीजिए ।

6. Examine the legal and organisational approaches to the study of International Politics. How far do you consider them satisfactory ?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिये वैधानिक तथा संस्थागत दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिये । आपके विचार में ये कहां तक संतोषजनक हैं ?

7. On what grounds can you criticise the realistic theory of International Politics.

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धान्त की किन आधारों पर आलोचना की जा सकती है।

8. To what extent is International Politics a Science.

किस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान है ?

9. Briefly survey the significant current developments in International sphere in modern world.

आधुनिक विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आधुनिक महत्वपूर्ण विकासों का संक्षिप्त सर्वेक्षण कीजिए।

10. What do you understand by the term State System ? Mention its essential features.

राज्य व्यवस्था शब्द से आप क्या समझते हैं ? इसके आवश्यक लक्षण बताइये।

11. Enumerate differences among States and classify states on the basis of power.

राज्यों के अन्तर की परिमणना कीजिये और राज्यों का शक्ति के आधार पर वर्गीकरण कीजिये।

12. What factors have played an important part in the growth of the Western States System ?

पश्चिमी राज्य-व्यवस्था के विकास में किन कारकों का प्रमुख योग रहा है ?

13. Give a brief history of the rise of Western State System in modern world.

आधुनिक विश्व के पश्चिमी राज्य व्यवस्था के उदय का संक्षिप्त इतिहास दीजिए।

14. What do you understand by the term nationalism ? What are its various forms according to Hayes and Quincy Wright ?

राष्ट्रवाद शब्द से आप क्या समझते हैं ? हेन, वीन्सी राइट के अनुसार इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं ?

15. Give a brief history of the origin of various types of nationalism in the different centuries.

विभिन्न शताब्दियों में राष्ट्रवाद के विभिन्न प्रकारों की उत्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास दीजिये।

- 16 What are the instruments and symbols of Nationalism ?
राष्ट्रवाद के साधन और प्रतीक क्या हैं ?
- 17 Discuss the dangers of Nationalism in modern world
आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद के खतरे की विवेचना कीजिये ?
- 18 What do you understand by sovereignty ? Can sovereignty be divided or limited ? What are your views about the source of sovereignty ?
सम्प्रभुता में आप क्या समझते हैं ? क्या सम्प्रभुता विभाजीय अथवा सीमित हो सकती है ? सम्प्रभुता के स्रोत के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?
- 19 Explain the Soviet views on Sovereignty Should the concept of sovereignty be discarded ?
सम्प्रभुता पर रूस के विचारों का वर्णन कीजिये । क्या सम्प्रभुता के विचार पृथक् पृथक् होने चाहिए ?
- 20 What do you understand by the Community of States ? Why do international conflicts and differences arise ? What are the various international political processes to solve them ?
राज्य समाज से क्या अभिप्राय है ? अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े और मतभेद क्यों खड़े होते हैं ? इन्हें निपटाने के लिये क्या अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक विधिया हैं ?
- 21 What do you understand by the following terms used in International Politics or relations—
(a) Nation and Nation State (b) Nationality (c) National self determination
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति या सम्बन्धों में निम्न प्रयुक्त शब्दों से आप क्या समझते हैं ?
(क) राज्य और राष्ट्राय राज्य (ख) राष्ट्रियता (ग) राष्ट्रीय आत्म-निर्धारण ।
- 22 Indicate the major trends in the sphere of nationalist in the last two decades
अन्तिम दो दशकों में राष्ट्रवाद के क्षेत्र में प्रमुख भ्रूकावों का वर्णन कीजिये ।

Chapters 3, 4, 5, & 6 •

- 1 Define National Power and discuss the various forms of it

राष्ट्रीय शक्ति की परिभाषा कीजिये तथा उसके विभिन्न स्वरूपों की विवेचना कीजिये ।

2. International Politics is a struggle for Power Explain

अन्तरराष्ट्रीय राजनीति एक प्रकार से शक्ति के लिए संघर्ष है । इसे स्पष्ट कीजिए ।

3. "Power in a political context means, the power of man over the minds and actions of other man" (Morgenthau). Discuss

राजनीतिक गदर्भ में शक्ति का अर्थ है, मनुष्य की शक्ति जो दूसरे मनुष्यों व मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो । विवेचना कीजिये ।

4. Discuss the basic elements of national power On the basis of these elements, give an estimate of the power of either France or the U S S R

राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिये । इन तत्वों के आधार पर फ्रांस अथवा सोवियत संघ की शक्ति का मूल्यांकन कीजिये ।

5. Examine the elements or ingredients of natural power, with particular attention to those factors which make for the ultimate form of power i.e. military power

शक्ति के अन्तिम स्वरूप जैसे सैनिक शक्ति पर विशेष ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय शक्ति के तत्व या संपादनों की परीक्षा कीजिये ।

6. "If, however, it is utopian to ignore the element of power, it is an unreal kind of realism which ignores the element of morality in any world order" (E H Carr). Comment

7. What are the principal elements of national power? Has the importance of geography declined in recent years?

राष्ट्रीय शक्ति के मुख्य तत्व क्या हैं । क्या हाल ही के वर्षों में भूगोल का महत्व घट गया है ?

8. Discuss the basic elements of national power On the basis of these elements give an estimate of the power of either France or the U S S R

राष्ट्रीय शक्ति के मूल तत्वों की व्याख्या कीजिए । इन तत्वों के आधार पर फ्रांस अथवा सोवियत संघ की शक्ति का मूल्यांकन कीजिए ।

- 9 Explain the importance of economic factors in the formulation of national policy and in international politics.

राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक कारकों का महत्व समझाइये ।

- 10 Why states are so much concerned with power and why the cultivation of national power is a corollary to the national state system

राज्य शक्ति से बहुत अधिक सम्बन्धित क्यों हैं और क्यों राष्ट्रीय शक्ति की वृद्धि का परिणाम राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था है ।

- 11 Comment on the 'Realist' and 'Idealist' views about power politics

शक्ति की राजनीति पर यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण की विवेचना कीजिये ।

- 12 "Physical geography is one of the more constant conditioning factors in world politics and effects the power, the needs, goals and policies that follow in pursuing their respective interests" (Padelford and Lincoln) Discuss

भौतिक भूगोल विश्व राजनीति को अधिक निरन्तर रूप से प्रभावित करने वाला तत्व है । यह उन आवश्यकताओं, लक्ष्यों, नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है जिनको राज्य अपने हितों की दृष्टि से अपनाते हैं ।

- 13 'It would, of course, not be correct to say that the larger the population of a country the greater will be power of that country' (Morgenthau) Comment

यह कहना सही न होगा कि एक देश की जनसंख्या ज्यादा है अतः उस देश की शक्ति भी अधिक होगी । विवेचना कीजिये ।

- 14 'The rapid spread of modern technology will bring power to population now comparatively important' (Frank W. Notestein)

"Although quantity of population is important in war and peace, quality is even more desirable" (Schleicher)
In light of the above statements discuss 'Population' as an element of national power

15. Describe the effect on International Politics of the following elements of Geography—(a) Location and Climate (b) The Factor of Position, (c) Land Form, (d) Size of the State, (e) Raw Materials and (f) Boundaries

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर निम्नलिखित भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है—(क) स्थिति तथा जलवायु, (ख) राज्य की स्थिति का तत्व, (ग) भूमि का रूप, (घ) राज्य का आकार, (ङ) कच्चे माल की उपलब्धता तथा (च) सीमाएँ।

16. How does the population of a state affect International Politics? Illustrate your answer by suitable examples from the countries of the World.

किसी देश की जनसंख्या विश्व राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है? अपने उत्तर के पक्ष में विभिन्न राष्ट्रों की जनसंख्या का उदाहरण देते हुए स्पष्टीकरण कीजिये।

17. Describe the economic needs of nations. How do they create international dependency and rivalry? Discuss.

राष्ट्रों की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिये। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय पराधीनता तथा प्रतिद्वन्द्विता पर कैसे प्रभाव डाला है? समीक्षा कीजिये।

18. What do you mean by Ideology? What is its place in politics? What part does it in the International Relation.

विचारधारा से आप क्या अर्थ निकालते हैं? उसका स्थान राजनीति में क्या है? अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में वह क्या करती है?

19. How much does the moral factor work in International Politics?

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता को मापना कहा तक कार्य करती है?

20. "Really speaking war occurs in the minds of men and not between the armies. Hence to establish permanent peace, it is the minds where peace much prevail." Discuss the statement critically.

“यदि सत्य पथ कहा जाय तो यह ठीक लगता है कि युद्ध नेताओं के मध्य नहीं हुआ बल्कि उसके बीच मानव मस्तिष्क में पैदा होते हैं। अतः स्थाई शानति के लिये, मानव मस्तिष्कों में शानति फैलाई जाये।” इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये।

21. Discuss ‘Technology’ as an element of national power.
राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में ‘तकनीकों’ की विवेचना कीजिये।
22. Comment on the nature and influence of ‘Technology’ as an element of national power
राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में ‘तकनीकी’ की प्रवृत्ति और उसके प्रभाव की समीक्षा कीजिये।
23. “Ideologies, like all ideas, are weapons that may raise the national morale and with it, the power of one nation and in the very act of doing so, may lower the morale of the opponent (Hans J Morgenthau.) Comment.
‘विचारधाराएँ समस्त विचारों की भाँति ऐसे हथियार होती हैं जो राष्ट्रीय मारल को उठा सकते हैं और इसके साथ ही एक राष्ट्र की शक्ति का अंश ख़त्म कर देती हैं। ऐसा करने व अरब विरोधी के मारल को नीचा कर सकते हैं।’ समीक्षा कीजिये।
24. “In short, Communist theory is truly international, on a class basis, whatever concessions it may make to nationalism are wholly strategic and temporary” (Schlicher) Discuss
“संक्षेप में साम्यवाद विचारधारा सच्चा रूप में अन्तर्राष्ट्रीयवादी है, जिसका आधार वर्गवाद है। राष्ट्रवाद के लिए यह जो भी छूट प्रदान करती है वह अस्थायी है तथा इसी राजनीति है।” विवेचना कीजिए।
25. “Moral is a thing of the spirit, made up of loyalty, courage, faith the impulse to the preservation of personality and dignity, sentiment for the known, fear and dislike of the unknown & self-interest” (Palmer & Perkins)
“Morale is composed, not many, variable, is a complex of a few constants and many variables” (Palmer & Perkins). In light of these statements discuss ‘Morale’ as an element of national power.

“मनोवश आत्मा को एक बीज है जो स्वामिमर्शिन, साहस तथा विद्वान् से मिल कर बनती है, यह व्यक्तित्व एवं सम्मान की रक्षा की छात्रा है, ज्ञात के प्रति ‘भावना’ है तथा अज्ञात के प्रति भय एवं अश्वि । यह आ मन्त्राय है ।”

राष्ट्रीय मनोवश (National Morale) कुछ निश्चित तथा बनेक अनिश्चित तत्वों का उल्लेखपूर्ण समवाय है ।

— इन कथनों के प्रकाश में “राष्ट्रीय शक्ति के एक तत्व के रूप में मनोवश” की विवेचना कीजिये ।

26 “ the quality of military leadership has always exerted a decisive influence upon national power ” (Morgenthau) Do you agree with this statement ?

“सैनिक नेतृत्व के गुण न राष्ट्रीय शक्ति पर सदा ही निर्णायक प्रभाव डाला है ।” क्या आप इस प्रश्न में सहमत हैं ?

27. “Diplomacy of high quality will bring the ends and means of foreign policy into harmony with the available resources of national power ” (Morgenthau) Comment.

“उच्च दर्जे की कूटनीति विदेश नीति व साधन और साधनों की उपलब्ध राष्ट्रीय शक्ति के स्रोतों के साथ एकरूप करती है ।” विवेचना कीजिये ।

Chapters 7 & 8

1 “All the instruments and techniques of international intercourse have some application both in friendly and in hostile relations, in peace and in war, even though some are pronouncedly more persuasive whilst others are coercive” (Joseph Frankel). Discuss

अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक व्यवहार के सभी साधन एवं तकनीकें मैत्रीपूर्ण तथा शत्रुतापूर्ण, सम्मिश्रण में, शान्ति एवं युद्ध दोनों ही कालों में प्रयुक्त की जा सकती हैं । यद्यपि इतना आवश्यक है कि इनमें से कुछ की प्रवृत्ति अधिक सममान बुझाने की है जबकि अन्य दबावकारी हैं । • विवेचना कीजिये ।

2 What is the meaning of national interest ? Define it in terms of national power

राष्ट्रीय हित का अर्थ क्या है ? राष्ट्रीय शक्ति के रूप में इसे परिभाषित कीजिये ।

3. "The concept of the national interest, then contains two elements one that is logically required and in that sense necessary and one that is variable and determined by circumstances" (Morgenthau)

Elucidate

"राष्ट्रीय हित में प्रायः दो तत्व निहित होते हैं। एक तो यह है कि यह तार्किक रूप में वाछनीय है और इस प्रकार आवश्यक भी। दूसरे, यह अस्थिर है तथा परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होता है।" व्याख्या कीजिये।

4. What is diplomate ? Explain the qualities and specialities of diplomate with reference to his duties

राजनयज्ञ किसे कहते हैं ? उनके कार्यों का सेक्षा जोक्षा प्रस्तुत करते हुए एक सफल राजनयज्ञ के गुणों तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिये।

5. Write development of diplomacy and explain the forms of recent diplomacy

राजनयिक सिद्धान्त के विकास पर सम्यक् विचार कीजिये तथा आधुनिक राजनय के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत कीजिये।

6. 'Diplomacy in the popular sense means the employment of tact, shrewdness, and skill in any negotiation or transaction. In the more special sense used in international relations it is the art of negotiation, in order to achieve the maximum of group objectives with minimum of costs, within a system of politics in which it is a possibility' (Quincy Wright)

'Diplomacy in the application of intelligence and tact to the conduct of official, relations between the governments of independent states (Ernest Satow)

"Diplomacy, used in relation to international politics, is the art of forwarding one's interests in relation to other countries" (K M Panikkar) Elucidate the above statements.

“लोकप्रिय रूप में कूटनीति का अर्थ है किसी सौदे में या लेन-देन में चातुरी, धोखेबाजी तथा कुशलता का प्रयोग। अपने विशेष अर्थ में जिसमें कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रयुक्त की जाती है यह सौदेबाजी की वह कला है जो राजनीति की उस व्यवस्था में कम मूल्य में अधिक से अधिक सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है जिसमें कि युद्ध एक सम्भावना है।”

“कूटनीति” स्वतन्त्र राष्ट्रों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करने की कहा जाता है।

“अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त ‘कूटनीति’ अपने हितों को दूसरे देशों से अग्रिम रखने की एक कला है।”

उपयुक्त कथनों की व्याख्या कीजिये।

7. “A diplomat's words must have no relation to action otherwise what kind of diplomacy is it? Words are one thing, actions another. Good words are a mask for the concealment of bad needs. Sincere diplomacy is no more possible than dry water or wooden iron.” (Joseph Stalin).

“Diplomacy by trickery seldom helps a country to achieve its objects.” (K. M. Panikkar).

In light of these statements discuss the nature of diplomatic functions.

“एक कूटनीतिज्ञ के शब्दों का उसके वाशों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये वरना यह कूटनीति ही कैसी? कथनी एक चीज है और करनी दूसरी। अच्छे शब्द बुरे कार्यों को छुपाने में ढाल का काम करते हैं। एक निष्कपट कूटनीति उसी तरह असम्भव है जितना कि ‘सूखा पानी’ या ‘नरम लोहा’।”

“चालबाजी पूर्ण कूटनीति एक देश की उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कम सहायता कर पाती है।”

इस कथनों के प्रकाश में कूटनीतिक कार्यों के स्वरूप की विवेचना कीजिये।

8. Describe functions and kinds of diplomacy.

कूटनीति के कार्यों और प्रकारों का वर्णन कीजिये।

9. Define Propaganda and explain the methods and techniques of it.

प्रचार शब्द की व्याख्या कीजिये तथा इसकी पद्धति तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिये।

10. What do you understand by Political Warfare ? Discuss its devices and role during First World War and Second World War and in post war period

राजनीतिक युद्ध से आप क्या समझते हैं ? प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और इसके पूर्व के युद्धों में इसके कार्य और साधनों की विवेचना कीजिये।

11. What do you understand by economic instruments of National Policy. Distinguish between Economic weapons and weapons of economic warfare

राष्ट्रीय नीति के आर्थिक शस्त्रों से आप क्या समझते हैं ? आर्थिक शस्त्र और युद्ध के आर्थिक शस्त्र में अन्तर कीजिये।

12. Explain the importance of economic factors in the formulation of national policy and in international politics.

राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक कारकों के महत्व को समझाइये।

13. What is Imperialism and discuss its relation with nationalism.

साम्राज्यवाद क्या है और राष्ट्रवाद से इसके सम्बन्धों की विवेचना कीजिये।

14. Explain briefly the various economic instruments of National Policy

राष्ट्रीय नीति के विभिन्न आर्थिक साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

15. What is colonialism ? Explain difference between colonialism and Imperialism

उपनिवेशवाद क्या है ? उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में अन्तर बतलाइये।

16. What do you understand by Imperialism ? How is it related to colonialism ? Give the motives of Imperialism and colonialism.
- ✓ आप साम्राज्यवाद से क्या समझते हैं ? इसका सम्बन्ध उपनिवेशवाद से क्या है ? साम्राज्यवाद तथा उपनिवेश के पीछे कौनसी भावनाएँ छिपी रहती हैं ? स्पष्ट कीजिये ।
17. (a) What is war ? What do you understand by the costs of war ?
 (b) Explain briefly the functions of war giving illustrations from communist countries
 (क) युद्ध क्या है ? युद्ध लागत से आप क्या समझते हैं ?
 (ख) युद्ध के कार्यों का साम्यवादी और पूँजीवादी देशों का उदाहरण देकर संक्षिप्त में वर्णन कीजिये ।
18. Discuss the various approaches to the study of war and mention briefly the causes of war.
 युद्ध के अध्ययन के विभिन्न तरीकों का विश्लेषण कीजिये तथा युद्ध के कारणों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिये ।
19. (a) Discuss Dulles false or inadequate solution to war. Are there any other alternatives to war ?
 (b) Explain the future of war as an instrument of National Policy
 (क) डल्लेस की युद्ध की झूठा अथवा अन्यायपूर्ण हल की विवेचना कीजिये । क्या युद्ध के अन्य विकल्प हैं ?
 (ख) राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध के भविष्य का वर्णन कीजिये ।
20. Describe the characteristics of the modern war. How does it differ from the old war ?
 आधुनिक युद्ध की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । यह प्राचीन युद्ध से किस प्रकार भिन्नता रखता है ?
21. Describe the Economic aspects of Modern war. Illustrate your answer with reference to the World Wars I & II. What was the part of U. S. A. towards Economic Reconstruction ?

आधुनिक युद्ध के आर्थिक पहलू का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर में प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धों का उदाहरण दीजिये। विश्व के पुनर्निर्माण में आर्थिक दृष्टि से स० रा० अमेरिका का क्या योगदान है ?

- 22 What are the Social, Political and Psychological consequences of the two World Wars ? Is the nature of war in the present times changing ? If your answer is in the positive describe the factors contributing to such a change ?

दो विश्वयुद्धों के सामाजिक राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या हुए ? क्या आजकल के युद्ध की प्रकृति बदल रही है ? यदि आपका उत्तर इसके पक्ष में है, तो इस परिवर्तन के पीछे कौन कौन से तात्व हैं ?

Chapters 9 & 10

- 1 What are the various meanings of Balance of Power

शक्ति सन्तुलन के क्या क्या विभिन्न अर्थ हैं ?

- 2 Discuss the nature of the Balance of Power and mention its characteristics

शक्ति सन्तुलन की प्रकृति और इसके चरित्र का वर्णन कीजिए।

- 3 Explain the role of balances and show how polarization of power takes place

सन्तुलन के कार्य का वर्णन कीजिए और बतलाइये कि भ्रूव शक्ति का स्थान कैसे लेते हैं ?

- 4 Explain the devices for maintaining the Balance of Power

शक्ति सन्तुलन को स्थिर करने के साधनों का वर्णन कीजिये ?

- 5 What do we mean by Collective Security and assess the true significant possibilities of collective security in international affairs.

सामूहिक सुरक्षा से हम क्या अर्थ लेते हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय कार्य में सामूहिक सुरक्षा की सम्भावना और वास्तविक महत्त्व को निपारित कीजिये।

6. Is collective security a pitfall or bulwark ?
यस सामूहिक सुरक्षा एक सिद्धान्त है ?
7. "The logic of collective security is flawless, provided it can be made to work under the conditions prevailing on the international scene." (Morgenthau)
Comment on this statement and explain the problems connected with collective security."

"सामूहिक सुरक्षा के तर्क में कोई त्रुटि नहीं है, यदि उसको अन्तर्राष्ट्रीय मंच की वर्तमान परिस्थितियों में कार्यान्वित किया जा सकता है।"
(मोरगेन्थौ)

इस कथन की समीक्षा करते हुए, सामूहिक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

8. Discuss the relationship of collective security and balance of power with special reference to Concert of Europe, League of Nations and United Nations
सामूहिक सुरक्षा और शक्ति सन्तुलन के सम्बन्ध का विशेषकर यूरोप शक्ति, राष्ट्र संध और संयुक्त राष्ट्र संध के संदर्भ में विवेचना कीजिये।
9. What are the most promising of all the approaches to peace ? Explain the relationship between collective security and peaceful settlement.
शान्ति के अत्यधिक दृढ़ मार्ग क्या हैं ? सामूहिक सुरक्षा और शान्तिपूर्ण हल के सम्बन्ध का वर्णन कीजिये।
10. "Collective security is in an intermediate position with respect to the criterion of centralization; it refers to a system with a greater degree of managerial centralization than the balance system, but a lesser degree than the world government concept."
(Claude). Elucidate.

"यदि केन्द्रीकरण की दृष्टि से देखा जाय तो हम पायेंगे कि सामूहिक सुरक्षा बीच की व्यवस्था है। इसमें शक्ति-सन्तुलन से अधिक केन्द्रीकृत प्रबन्ध होता है, किन्तु विश्व सरकार की मान्यता से यह कम होता है।" व्याख्या कीजिये।

- 11 " the collective security system should be regarded as simply a revised version of the balance system, not as a drastically different system substituted for the latter " (Claude) Elucdate.

“सामूहिक सुरक्षा को शक्ति सन्तुलन का एक परिवर्धित संस्करण मानना चाहिए न कि पूरी तरह से भिन्न और शक्ति सन्तुलन का विकल्प ।” इस कथन को समझाइये ।

- 12 What is meant by Collective Security and what are its problems ? Is there any alternative to Collective Security ?

सामूहिक सुरक्षा से क्या तात्पर्य है तथा उसकी समस्याएँ क्या हैं ? क्या सामूहिक सुरक्षा का कोई अन्य स्थापनापत्र संभव है ?

- 13 Explain in detail the methods for the Pacific Settlement of international disputes with special reference to regional arrangements and the United Nations

अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का विशेषकर प्रादेशिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र संधि के तहत में शान्तिपूर्ण निराकरण के पद्धतियों का विस्तृत वर्णन कीजिये ।

- 14 Can Regionalism promote world peace ? Illustrate with reference to NATO and SEATO

क्या क्षेत्रीयवाद विश्व शांति को उत्तम बना सकता है ? नाटो और सीटो के तहत में बताइये ।

- 15 Do you agree that regional agreements for international peace and security are, at best, a 'necessary evil' ?

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन, एक आवश्यक बुराई है ?

- 16 Define International law Explain various branches Distinguish between international law and municipal law.

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा दीजिये । विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिये । अन्तर्राष्ट्रीय कानून और म्यूनिसिपल कानून में अन्तर बताइये ।

17. What are the main sources of international law ?
How International law is enforced ?

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुख्य स्रोत क्या हैं ? अन्तर्राष्ट्रीय कानून कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है ?

18. Write short notes on—

(1) World Government, (2) Disarmament, (3) International Morality, (4) World Public Opinion

निम्न पर टिप्पणी लिखिये—

(१) विश्व सरकार, (२) निशस्त्रीकरण, (३) अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता, (४) विश्व जनमत ।

19. Discuss the attitude of Great Powers towards disarmament since the close of Second World War.

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद नि.शस्त्रीकरण के प्रति महा-शक्तियों के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिये ।

20. Discuss the 'progress' of disarmament under the U N. O pointing out specially the basic differences in the points of view of Western Powers and U S. S. R.

पारचाय शक्तियों और सोवियत संघ के महाशक्तियों मौलिक मतभेदों को बताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्संवाधान में निशस्त्रीकरण की दिशा में की गई 'प्रगति' की विवेचना कीजिये ।

21. Give an account of the attempts made after 1945 to tackle the problem of disarmament.

निशस्त्रीकरण की समस्या के समाधान के लिए १९४५ के बाद किये गये प्रयत्नों का विवरण दीजिए ।

22. Discuss the nature of International law. What is the force behind this law ?

अन्तर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति की विवेचना कीजिये । इस कानून के पीछे कौनसी शक्ति होती है ?

23. What is the scope of International Law ? Discuss.

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का क्षेत्र क्या है ? विवेचना कीजिये ।

- 24 Describe the present status of International Law. How do the International Court of Justice and U N O. help in strengthening the International law

आधुनिक समय में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की हैसियत क्या है ? अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा म० रा० संघ किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय कानून को शक्ति बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं ?

Chapters 11 to 20

- 1 "The most significant development of the period following world war II has been the emergence of the struggle of the African people for national self-determination " Comment.

“द्वितीय महायुद्धोत्तर युग में सबसे महत्वपूर्ण विकास राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के लिये अफ्रीकन लोगों के संघर्ष का उदय रहा है।” विवेचना कीजिये।

2. Discuss the emergence of independent states in Africa and its effect on international politics.

अफ्रीका में स्वतन्त्र राज्यों के उदय की ममीक्षा कीजिये और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसके प्रभाव को बताइये।

3. What has been the problems of Africa after the Second World War and how are they affecting the international relations

द्वितीय महायुद्ध के बाद अफ्रीका की क्या समस्याएँ रही हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को वे कैसे प्रभावित कर रही हैं।

Write a note on the resurgence of Africa

अफ्रीका के जागरण पर एक नोट लिखिये।

4. Write an essay on the growth and development of the movements towards continental unity in Africa. What do you think about the prospect of such unity ?

अफ्रीका में महाद्वीपीय एकाता के लिये जो विभिन्न आन्दोलन हुए उनके उदय और विकास पर एक निबन्ध लिखिये। इस एकाता के भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

5. 'Contemporary international relations are going through a reorganisation in which the old national state and the old state system are being slowly moulded into new political forms. Colonies are gaining independence as empires are breaking up. National States are being merged into great federations' (T. V. Kalijarvi) Discuss

“वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें पिछले की राज व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में बदलती जा रही है। साम्राज्यों का पतन हो रहा है और उपनिवेश स्वतंत्रता प्राप्त करने जा रहे हैं। राष्ट्र राज्य एक बड़े मध्य में विलीन होत जा रहे हैं।” (टी वी कालीजार्वी) विवचना कीजिये।

6. How has the Second World War affected the political development of South East Asia?

द्वितीय महायुद्ध ने दक्षिण पूर्वी एशिया के राजनीतिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है?

7. Discuss the importance of South East Asia in International affairs

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्व की विवचना कीजिये।

8. Discuss the Vietnam crisis. Do you think that the Vietnamese crisis can escalate into a world war?

वियतनाम संकट की विवचना कीजिये। क्या आपका ख्याल है कि वियतनाम-संकट विश्व युद्ध के रूप में परिणत हो सकता है?

9. Discuss the importance of Middle East in the diplomacy of Great Powers during year of 1940-56 1940 से 1956 के वर्षों के दौरान महाशक्तियों की कूटनीति में मध्यपूर्व के महत्व की समीक्षा कीजिये।

10. Write a short essay on international politics of the Middle East after World War II.

मध्यपूर्व की द्वितीय महायुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये।

- 11 How the Zionist problem influenced international politics in the Middle East ?
मध्यपूर्व में यहूदीवाद की समस्या ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है ?
- 12 Give a brief history of Anglo Egyptian relations in the period leading to the Suez Crisis
स्वेज पकट के समय पर आंग्ल-मिस्र सम्बन्धों का संक्षिप्त इतिहास लिखिये ।
- 13 Write a note on Arab Nationalism
अरब राष्ट्रवाद पर एक नोट लिखिये ।
- 14 What do you know of the Palestine problem and its settlement after the Second World War
फिलिस्तीन समस्या और द्वितीय महायुद्ध के बाद इसके समाधान के बारे में आप क्या जानते हैं ?
- 15 Critically examine the foreign policy of the U S A since the termination of Second World War
द्वितीय महायुद्ध की उत्तरकालीन अमेरिकन विदेश नीति का आलोचकानात्मक विश्लेषण दीजिए ।
- 16 Sketch briefly the part played by the U S A in International affairs since 1939 What are the international aims of the U S A at present time ?
१९२९ के बाद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो भूमिका अदा की उसका मूल्य में चित्रण कीजिये । वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य क्या हैं ?
- 17 Estimate the strength and influence of the imperialist motive in the policy of the United States to day
संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति में साम्राज्यवादी उद्देश्य के प्रभाव और शक्ति का मूल्यांकन कीजिये ।
- 18 What was the Truman Doctrine ? When and under what circumstances was it enunciated ? Would you agree with the view that the Truman Doctrine is the modern version of the Monroe Doctrine ?

द्रुमैव सिद्धान्त क्या था ? क्या और किन परिस्थितियों में इसे कार्यान्वित किया गया था ? क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि द्रुमैव सिद्धान्त मुनरो सिद्धान्त का आधुनिक रूप है ?

- 19 What do you mean by the Eisenhower Doctrine ? Discuss its workings and the causes of its failure.
आइज़नहोवर सिद्धान्त से आशय क्या अभिप्राय है ? इसकी कार्य प्रणाली और असफलता के कारणों का विवरण कीजिये ।

20. Give a critical sketch of the policy of U S A towards Latin American States since 1945.
१९४५ के बाद से संयुक्त अमेरिकन राज्यों के प्रति मध्यम राज्य अमेरिका की नीति की समीक्षा कीजिये ।

- 21 "The post war world possessed a number of important characteristics but above all, it was overshadowed by the rivalry of the United States and the Soviet Union " Discuss
"महायुद्धोत्तर विश्व की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएँ थीं—किन्तु मध्यम राज्य अमेरिका और सोवियत गण की शक्ति या प्रतिद्वन्द्विता इन सबसे ऊपर गिनी हुई ।" प्रतिद्वन्द्विता और विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिये ।

- 22 Discuss in brief the problem of the reunification of Germany
जर्मनी के एकीकरण की समस्या का गहन में वर्णन कीजिये ।

- 23 Give a critical sketch of the foreign policy of Russia since 1945
१९४५ से रूस की विदेश नीति का आलोचनात्मक विवरण दीजिये ।

- 24 In what respects has the foreign policy of the U S S R. modified in recent years ? Give concrete instances to illustrate your answer.

आधुनिक वर्षों में सोवियत रूस की विदेशी नीति किन रूपों में परिवर्तित हुई या सुधरी है ? उनमें की पुष्टि में दोन उदाहरण दीजिये ।

- 25 "Every manifestation of the Soviet policy during the post war period has made it clear that the Soviet Government of Stalin is pursuing precisely the same

aims that were envisaged by Nicholas I and Alexander II, "Do you agree? Give reasons in support of your answer

‘युद्धोत्तर काल में सोवियत नीति को प्रत्येक घोषणा या उसके प्रत्येक प्रकाशन से यह स्पष्ट हो गया है कि स्टालिन की सोवियत सरकार उन्ही उद्देश्यों का अनुसरण कर रही है जो निकोलस प्रथम और अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा अपनाये गये थे।’ क्या आप सहमत हैं? अपने पक्ष के समर्थन में कारण दीजिये।

- 26 "He (Stalin) ruled in the autocratic tradition of Peter the Great and westernized the economy of the Soviet Union in the realm of Foreign Policy, he followed in the footsteps of the most expansionist of czars. His successors have sought to maintain his tradition" (Alvin Z. Rubinstein) Discuss.

“उसने (स्टालिन ने) पीटर महान की स्वच्छाचारी परम्पराओं में शासन किया और सोवियत संघ की अर्थ व्यवस्था का पाश्चात्यीकरण कर दिया। विदेश नीति के क्षेत्र में उसने मुख्यतः विस्तारवादी जारों के पदचिह्न ही का अनुसार किया। उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी परम्परा को निभाना पड़ेगा।” (अल्विन रबिन्स्टीन) विवेचना कीजिये।

- 27 Give a brief account of the achievements and failures of post Stalin diplomacy of the Soviet Union.

सोवियत संघ की स्टालिनोत्तर कूटनीति की सफलताओं एवं असफलताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

- 28 Discuss in brief Soviet Union's relations with other Communist countries of the world

संसार के अन्य साम्यवादी देशों के साथ सोवियत संघ के सम्बन्धों की संक्षिप्त विवेचना कीजिये।

- 29 Do you think that foreign policy of Soviet Union under Khrushchev was fundamentally different from that of his predecessor?

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सोवियत संघ की कुरुखेव के समय की विदेश नीति उसके पूर्ववर्ती नेता (स्टालिन) से मौलिक या आधारभूत रूप से भिन्न थी?

- 30 What do you mean by the term 'peaceful co existence'? Discuss it in the context of the U S S R Diplomacy.

“शांति पूर्ण सह-अस्तित्व” से आपका क्या आशय है ? सोवियत कूटनीति के सदर्भ में इसकी विवेचना कीजिये ।

31. “The conflict between the two monolithic giants of the modern world is the dominant reality of the contemporary world-politics.” Discuss the main causes of the friction between United States of America and Union of Soviet Socialist Republics in the light of the above statement. How can this friction be made up ?

“आधुनिक वाय की दो भीमानाय शक्तियों के मध्य मध्य ही आधुनिक विश्व राजनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है ।” इस कथन के प्रकाश में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य पारस्परिक तनाव के कारणों की विवेचना कीजिये । इस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है ?

32. Write a short essay on “Rebuilding and Re organization of Western Europe.”

“पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण और पुनर्गठन” पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिये ।

33. What do you understand by ‘Bipolar System’ ? Do you agree that the trend is now towards polycentrism ?

द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं ? क्या आप सहमत हैं कि अब यह प्रवृत्ति बहुध्रुवाद की ओर है ?

34. What do you know about so called Cold War ? Give its short resume 1946 to 1967.

तणावपूर्ण शीतयुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं ? १९४६ से १९६७ के मध्य के शीत युद्ध की संक्षेप में बताइये ।

35. What are the causes of the so-called ‘Cold War’ ? Indicate main fronts on which it is being fought and the main episodes it has witnessed since 1946.

तणावपूर्ण शीतयुद्ध के क्या कारण हैं ? जिन मुख्य बातों को लेकर यह लड़ा जा रहा है और १९४६ से जिन मुख्य घटनाओं के दर्शन हमने किये हैं—उनका वर्णन कीजिये ।

36. ‘The Conflict between two monolithic giants of the modern world is the dominant reality of the contemporary world politics.’ Discuss the principal causes of friction between U. S. A. and the U. S. S. R. and suggest remedies or solution if any.

“आधुनिक विश्व के दो भीमाकाय दानवों के मध्य सघर्ष ही समकालीन विश्व राजनीति की विशेषता है ।” संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य विवाद व मतभेदों के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिये और सम्भाव्य हल बताइये ।

- 37 Trace the origin and growth of the conflict between the United States of America and the U S S R after the Second World War How far is it proper to explain the conflict in terms of the ideological differences between the two great powers ?

द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो संघर्ष रहा है उसकी उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिये । यह कहना कहा तक उचित है कि इन दो महान् शक्तियों के मध्य यह संघर्ष सिद्धान्तिक मतभेदों का है ?

- 38 *Examine the role of ideological as prime factor in International Relations Illustrate your answer by one or two examples*

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में सिद्धान्तों की भूमिका की एक प्रमुख पहलू के रूप में परीक्षा कीजिये । एक भयंकर दो उदाहरणों द्वारा अपना उत्तर स्पष्ट कीजिये ।

- 39 Give some account of the United Nations Organisation and explain the provisions it has made for the prevention of International conflicts

संयुक्त राष्ट्र संघ का कुछ विवरण दीजिये तथा उन प्रावधानों की व्याख्या कीजिये जो उसने अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षों की रोकने के लिए बनाये हैं ।

- 40 Examine the strength and weakness of the U N O for the maintenance of International peace

अन्तर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए सं० रा० संघ की शक्ति एवं निरालता का वर्णन कीजिये ।

41. Write an essay on the working of the U N O as an instrument for the establishment of World Peace.

“विश्व शांति की स्थापना के लिए सं० रा० संध एक साधन के रूप में कार्य करता है।” इस विषय पर एक लेख लिखिये।

42. Describe the mechanism for collective security under the charter of the United Nations and show how it differs from the collective security system under the covenant of the League of Nations.

संयुक्त राष्ट्र संध के चार्टर के अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ? यह भी स्पष्ट करो कि यह सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था राष्ट्र संध के समझौते से कितनी भिन्नता रखती है ?

43. Write an essay on the Security Council of the United Nations Organisation with special reference to the "Veto" power available to its permanent members. Would you advocate the abolition of the Veto as a means of making the United Nation more effective.

संयुक्त राष्ट्र संध की सुरक्षा परिषद् पर एक लेख लिखो जिसमें विशेष-तौर पर विटो शक्ति जो स्थाई सदस्यों की प्राप्त है, उसका उल्लेख हो। क्या आप इस पक्ष में हैं कि विटो की पद्धति को उखाड़ देने पर सं० रा० संध अधिक प्रभावी हो जायेगा ?

44. What are the contributions of the United Nations Organisation towards world peace ?

विश्व-शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संध की क्या देन है ?

45. Describe the failures and weaknesses of the U. N. O. in the maintenance of peace and security.

संयुक्त राष्ट्र संध की शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में जो असफलताएँ प्राप्त हुईं उनका उल्लेख करते हुये उसकी दुर्गुणताओं का वर्णन कीजिये।

46. "... in fact, the U. N. must act as a limited Govt. if the world is to have peace; it has no other choice." Discuss.

“यदि विश्व शांति प्राप्त करना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र संध की एक सीमित सरकार के रूप में कार्य करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं।” विवेचना कीजिए।

47. "Here, then is the U.N.O. and international personality, clothed by its frame with authority to operate on an international plane and whose members have taken important obligations toward it. But it is neither a state nor a super-state. The dilemma is inherent in the development of world society." (Clark M. Eicheberger) Discuss

"संयुक्त राष्ट्र सब एक ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है जिसके निर्माताओं ने इसे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति का बना पहनावा है तथा जिसके सदस्यों ने इसके प्रति महत्वपूर्ण दायित्व समाले हैं। किन्तु यह न तो एक राज्य है और न ही सर्वोच्च राज्य। यह अन्तर्बिरोध तो विश्व समाज के विकास में निहित हो रहता है।" विवेचना कीजिए।

SUGGESTED READINGS

1. B. Cohen : The Political Process and Foreign Policy.
2. Deutch, Karl W : The Nerves of Government.
3. Fox, William T.R. : Theoretical Aspect of International Relations (ed)
4. Nerman Kahn and : Game Theory, Irwin Mann
5. Hoffman, Stanlay : Contemporary Theory in International Relations.
6. Kaplan, Mortan A : System and Process in International Politics.
7. Manning C. A. W : International Relation, Paris.
8. Miller James G, : Towards a General Theory of the Behavioural Sciences
9. Mc Clell and, : Theory the International System. Charles A
10. Snyder, Richard C : H. W. Bruck and Burton Sapin : Foreign policy decision Making.
11. " " : An Approach to the Study of International Politics.
12. Thompson; Ken. : The Study of International Politics, neth W.
13. Herz, Hohn H. : Political Realism and Political Idealism
14. Morgenthau, : In defence of the National Interest, Hens J,
15. Morgenthau, : Politics among Nations, Hans J.
16. Morgenthau, : Scientific Man V.S. Power Politics. Hans J.
17. Palmer & Perkins : International Relations.
18. Lerner, Daniel, and : The policy Scieuces Lasswell, : Recent Developments in Scope and Harold D. eds : Method

- 19 Wright, Quincy The Study of International Relations
- 20 Padelford and Lincoln The Dynamics of International Politics,
- 21 Benno, Wasserman : 'The cultural and Psychological Approach to the study of International Relations.
- Morgenthau, In Defence of the National Interest.
- Hans J.
- Morgenthau, Scientific Man Vs Politics
- Hans J
- 22 Jucker W. Robert ' Professor Morgenthau's Theory of Political Realism ' American Political Science Review
- 23 E H Carr Nationalism and after.
- 24 Earle, Edward M ed Nationalism and Internationalism.
- 25 Gooch, George P Nationalism
- 26 Hayes, C J H The Historical evolution of modern nationalism
- 27 Keeton, George W National Sovereignty and international order
28. Cohn, Hans Nationalism Its meaning and History.
- 29 Cobban, Alfred National Self-determination
30. (a) Shafer Boyd G Nationalism Myth and reality.
- 30 (b) Clark, Grover, : The Balance Sheets of Imperialism.
- 31 Moon, Parker T, Imperialism and World Politics.
- 32 Merriam, Charles E History of the theory of Sovereignty since Rousseau,
- 33 John Drewett Signs of the Times.
- 34 David S Mc Lellan, William C and Fred A. Sonderrmann-
The Theory and Practice of International Relations,
- 35 Charles E Merriam Political Power
36. Harold D Loswell A Study of Power.

- 37 Colby, C C , editor Geographic Aspects of International Relations
- 38 Emeny Brooks, The Strategy of Raw Materials
- 39 Merriam, Charles ' Political Power, in a Study of Power History
- 40 Organski, A F K , World Politics
- 41 Sprout Harold and Margaret, editors, Foundations of National Power
- 42 Staley Eugene, Raw Materials in peace and War, New-York Council of Foreign Relations
- 43 Mead, Margaret, ed , Cultural Patterns and Technical Change
- 44 Kuczynski Robert R ' Population, History and Statistics, Encyclopaedia of the Social Sciences
- 45 Lorimer, Frank . ' Population Factors Relating to the Organization of Peace, International Conciliation, No 369
- 46 Pye, Lucian Aspects of Political Development, 1966
- 47 Kautsky, John H ed Political Changes in Under developed Countries Nationalism and Communism
- 48 Brzezinski, Zbigniew K. Ideology and Power in Soviet Politics, 1962
- 49 Klueberg, Otto The Human Dimension in International Relations, 1964
- 50 Pye, Lucian Politics, Personality and Nation Building, 1962
- 51 Burns, Arthur D Carleton, William G ' Ideology or Balance of Power ' Yale Review
- 52 Hans, Ernest B ' The Balance of Power Prescription Concept, or Propaganda ' World Politics
- 53 Schwarzenberger, George Power Politics
- 54 Briery J L The Law of Nations

- 55 Corbett, P E Law and Society in the Relations of States
- 56 Fenwick Charles G International Law,
- 57 Kelsen, Hans Principles of International Law
- 58 Sir Wiliam Hater The diplomacy of the great powers, 1960
- 59 Harold Nicolson The diplomacy of diplomatic methods
- 60 Panikkar, K M The principles and practice of Diplomacy
- 61 Losswell Harold D Propaganda Technique in the world war
- 62 Line Barger, Paul Psychological Warfare
M A
- 63 Jack, D T Studies in Economic Warfare
- 64 Falls, Cyril A hundred years of War
- 65 Dulles, John War and Peace
Foster
- 66 Cantril Hadley, ed Tensions that causes wars
- 67 Adler, M J How to think about War and Peace
- 68 Eagleton, Clyde Analysis of the Problem of War
- 69 Vannevar Bush Modern Arms and Freeman
- 70 Quincy Wright A Study of War
- 71 Amitai Etzioni Winning Without War
- 72 Bernal J D World Without War
- 73 Madariaga S de Disarmament
- 74 Willard N Hosen International Conflict and Collective Security, 1955
- 75 Seabury, Paul Balance of Power
- 76 Kissinger, Henry A The Necessity for Choice
- 77 Philip C, Jessup A modern Law of Nations, 1949.
- 78 Meyer Cord Peace of Anarchy, 1947.
- 79 Schuman, F L The commonwealth of man : An inquiry into power politics and world Govt , 1952

- 80 Nutting, Anthony Disarmament An outline of the
Negotiations 1959
- 81 Woodward E L Some Political Consequences of the
Atomic Bomb, 1956
- 82 Claude Jr Inis L Power and International Relations,
1964
- 83 John Strachey On the prevention of War, 1962
- 84 Murray Thomas E , Nuclear Policy for War and Peace,
1960
- 85 Haas,Ernst , B Types of Collective Security
An Examination of Operational
Concepts, American Political Sci
ence Review, XLIX, 40-62
- 86 Wolfers, Arnold, "Collective Security and the war in
Korea," The Yale Review XLIII, 481-96
- 87 Johnson, Howard C, Jr and Gerhart Niemeyer, Coll
ective Security The Validity of an Ideal, International
Organization VIII, 19-35
- 88 Webster, Sir Charles, The Art and Practice of Dipol
macy
- 89 Bowles, Chester The New dimensions of peace,
1955
- 90 Holland, William Asian Nationalism and the West,
L ed 1953
- 91 Low, Sir Francis Struggle for Asia, 1956
- 92 Panikkar, K M Asia and western dominance,
1954
- 93 Arciniegas, German The State of Latin America,
1952.
- 94 Daniels, Walter Latin America in the cold war,
M ed 1952
- 95 Macdonald, Austin Latin American Politics and Govt.
F 1954

- 96 Bartlett Varnon Struggle for Africa, 1953
97. Cloete, Stuart The African giant, 1955
- 98 Davidson, Basil The African Awakening, 1955
- 99 Dundas Sir Charles African Cross roads, 1955
- 100 Brzezinski Zbigniew, The Soviet Bloc Unity and
conflict Cambridge Harvard University Press 1960
- 101 Aubrey, Henry G Coexistence Economic Challenge
and Response Washington, D C National Planning
Assn, 1961
- 102 Robert Henry L, Russia and America Dangers and
Prospects New York : Council on Foreign Relations.
Inc, 1956
- 103 Schwartz Harry, The Red Phoenix Russia since
World War II New York Frederick A Praeger, Inc,
1961
- 104 Thomas A Bailey, A Diplomatic History of the Amer-
ican People
- 105 Samuel F Bemis and G G Griffin, Guide to the Dipl-
omatic History of the United States 1775 1921
- 106 Richard W Van Alasyne, American Diplomacy in
Action
- 107 Dexter Perkins The Evolution of American Foreign
Policy
- 108 Haines, C Grove ed The threat of Soviet Imperialism
- 109 Hunt, R N C The Theory and Practice of Commun-
ism
- 110 Schuman Frederick L Soviet Politics at Home and
abroad
111. Tara Covzio T A War and Peace in Soviet Diplomacy.
- 112 Williams. William A American Russian Relations
- 113 Langsome, W C The Strategy of Peace
- 114 Kamath M V, India s Dynamic neutralism Current
History
- 115 Crankshaw, Edward The New Cold War—Moscow
Vs Peking
- 116 Dentsher, I The Great Contest, 1960

- 117 Smith Gordon Connel Pattern of the Post-War World
- 118 Kundra J C Indian Foreign Policy
- 119 Coyle David Cushman The United Nations and how it works
- 120 Karunakaran K P India in World Affairs
- 121 Nehru, Jawaharlal India's Foreign Policy
- 122 Poplai, S L Asia and Africa in the Modern World
- 123 Lequeur, W Z Communism and Nationalism in the Middle East
- 124 Blackett, Patrick, M S Atomic Weapons and East-West Relations.
- 125 King Hall, Sir Stephen Defence in the Nuclear Age
- 126 Russel, Bertrand Commonwealth and Nuclear Warfare Foreign Affairs Vol XXXVIII
- 127 Banerjee, J K The Middle East in World Politics
- 128 Dean, V M Main Trends in post-war American Foreign policy
- 129 Donelon, Michael The Ideas of American Foreign Policy
- 130 Baibey Thomas A America faces Russia Russian American Relations from early times to our day
- 131 Lippman Walter The Cold War A study in U S. Foreign Policy
- 132 Hatch John Africa Today and Tomorrow
- 133 Anton us George The Arab Awakening
- 134 Peter Lyons Neutralism
- 135 Chase Eugene The United Nations in Action McGraw Hill 1950
- 136 Goodrich Leland M, and Simons, Anne P The United Nations and the Maintenance of International Peace and Security The Brookings Institution, 1955
- 137 Haviland, H Field, Jr, The Political Role of the General Assembly Carnegie Endowment for International Peace, 1951

- 138 Wightman, David, Economic Co operation in Europe
Praeger, 1956 A study of the Economic Commission
for Europe
 - 139 Wilcox, Francis O , and Marcy, Carl M Proposals for
Changes in the United Nations The Brookings Insti-
tution, 1956
 - 140 The Times of India
 - 141 The Hindustan Times
 - 142 International Studies
 - 143 Current History
 - 144 Foreign Affairs
 - 145 Pacific Affairs
 - 146 World Politics
 - 147 International Affairs
 - 148 Review of Politics
 - 149 India Quarterly
 - 150 साप्ताहिक दिनमान ।
-